





74





# Punjab Vidhan Sabha

## Debates

15th February, 1966

Vol. I—No. 1

### OFFICIAL REPORT

Chief Reporter  
Punjab Vidhan Sabha  
Chandigarh



### CONTENTS

Tuesday, the 15th February, 1966

	PAGES
Obituary References to the Death of late Shri Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India ..	(1)1
Obituary References to the Deaths of late—	
(1) Shri N.V. Gadgil, Former Governor of Punjab ..	
(2) Rao Bahadur Chaudhri Lal Chand, Ex-Minister, Punjab ..	
(3) Jathedar Udham Singh Nagoke, Ex-M.P. ..	
(4) Shri Mam Chand, Ex-M.L.A. ..	
(5) Shri Ahmed Mohiuddin, Deputy Transport Minister, Union Government ..	
(6) General K.S. Thimayya, former Chief of the Staff, Indian Army ..	
(7) Lt. Gen. Kulwant Singh. ..	
(8) Lt. Gen. D.R. Thapar. ..	
(9) Dr. H.J. Bhabha, Chairman, Atomic Energy Commission. (1)17—	

Price : Rs. 1.70 Paise.



# ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 1, DATED THE  
15TH FEBRUARY, 1966.

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
ऐसा	ऐस	(1)1	22
बायोग्राफी	बायग्राफी	(1)6	4 from below
भुलव	भलव	(1)13	6
रुस	रुप	(1)16	5
House	Aouse	(1)17	28
international	intternational	(1)24	35
politician	poli ician	(1)26	6



## PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 15th February, 1966

*The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.*

### OBITUARY REFERENCES TO THE DEATH OF LATE SHRI LAL BAHADUR SHASTRI, PRIME MINISTER OF INDIA

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, आज हम हिन्दुस्तान के एक महान व्यक्ति, लेट प्राइम मनिस्टर, श्री लाल बहादुर शास्त्री के तर्द अपनी गहरी श्रद्धा का इजहार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 10 जनवरी, 1966 की रात हमारे देश और संसार के लिए एक भयानक रात थी कि जिस रात हमारे हिन्दुस्तान के एक महान व्यक्ति, श्री लाल बहादुर शास्त्री को, जो सिर्फ हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि सारे संसार का एक बिलवड दोस्त और भारत का बिलवड प्राइम मनिस्टर था, जालिम मौत ने हम से हमेशा के लिए छीन लिया। इस से बढ़कर और कोई ऐसी दुःखदाई और शाकिंग खबर नहीं थी जो एक ऐसे वक्त पर सारे संसार को मिली जब कि उन्होंने ताशकन्द के अन्दर न सिर्फ हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों आदमियों को बल्कि सारे संसार को एक शान्ति और अमन का रास्ता दिखाया था। ताशकन्द का यह एग्रीमेंट जो श्री लाल बहादुर शास्त्री और प्रैजिडेंट मार्शल अयूब के दरम्यान श्री कोसीगिन, यू. एस. एस. आर के प्रधान मन्त्री के सहयोग के साथ हुआ था, यह उन का एक ऐसा सुनहरी डाकुमेंट है जो सारे संसार के लिए रहेगा और जो दुनिया की मुख्तलिफ कौमों को, एक एक इनसान को मशाल दिखाता रहेगा। स्पीकर साहिब, शास्त्री जी का हम से इस मौके पर जुदा होना एक ऐसा भारी और नाकाबले तलाफी नुकसान हुआ है कि जिस को आज सारा संसार महसूस करता है। उन्होंने हमारे सामने एक ऐसा शान्ति और अमन का रास्ता दिखाया कि जिस के लिए इन्सान और कौमें लाखों साल तक खोज करती रहती हैं। श्री शास्त्री जी की परसनैलिटी सादगी, सिम्पलिसिटी, मुहब्बत, प्यार, खिदमत और एक तरह से कुरबानी, बलिदान और तप का जीवन थी। उन्होंने अपने जीवन से एक ऐसी दृष्टि और एक ऐसा इतिहास बनाया कि जिस को हमेशा सुनहरी हरूफ के अन्दर लिखा जाएगा। खासकर श्री शास्त्री जी ने जब इस देश का उन्नीस महीने नेतृत्व सम्भाला और यहां के प्रधान मन्त्री बने तो उन्होंने सारी नेशन और सारे राष्ट्र में एक नई स्पिरिट, एक नया जज्बा और एक नई भावना पैदा की थी और उन्होंने अपनी एफर्ट्स से, अपनी मेहनत और परिश्रम से सारे राष्ट्र को इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाया कि उन को हिन्दुस्तान कभी भी भूल नहीं सकता। यह शास्त्री जी का ही कैलेबर था कि मुश्किल से भश्किल सवालों को हल करने की, मुश्किल से गुत्थियों को सुलझाने की उन में शक्ति

[मुख्य मन्त्री]

थी और हिम्मत थी। उन के चेहरे पर हमेशा हंसी और खुशी व्याप्त रहती थी। जहां उन के चेहरे पर हंसी और खुशी रहती थी वहां एक अजीब जलाल उन की आंखों में से टपकता था। वह बहुत ही सिम्पल थे, हम्बल थे और हरेक के साथ प्रेम से पेश आते थे। लेकिन इन सब के साथ साथ उन में फर्मनेस भी थी, सद्गुण थी और एक रैजोल्यूट माइंड था जिस से कि वह मुश्किल से मुश्किल मसाल का भी हल निकाल लिया करते थे। उन्होंने अपनी इन खूबियों से सारे देश को प्यार और मुहब्बत से इस तरह जीत लिया था कि हिन्दुस्तान का हर एक परिवार, हर भाई और बहन यह महसूस करते थे कि श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे परिवार का अपना ही एक मੈम्बर है। स्पीकर साहिब, वह लाल बहादुर शास्त्री सारे हिन्दुस्तान के लोगों पर और बिलखसूस पंजाब पर बड़ा भारी इम्पैक्ट छोड़ गए हैं। वह पंजाब के लोगों की करेज और हिम्मत की और उन के डिसिपलन की हमेशा तारीफ ही किया करते थे पंजाब के लोगों को उन से इन्सपिरेशन मिलती थी, हिम्मत मिलती थी और खास तौर पर जब इस देश के लिए एक आवर आफ ट्रायल आया था, एक बड़ी परीक्षा का मौका आया था उस मौके पर उन्होंने ऐसे मजबूत तरीके से हमारी राहनुमाई की थी कि जिस के लिए सारा हिन्दुस्तान उन का कृतज्ञ है। जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का एक कानफ़लिक्ट हुआ था उसमें अगर श्री शास्त्री जी के मुतअल्लिक यह कहा जाए कि वह फाइटिंग फ़ोरसिज के जर्नल के रूप में हिन्दुस्तान और संसार के सामने पेश हुए तो यह कहना बेजा नहीं होगा। वह एक मजबूत और महान हीरो के रूप में हमारे सामने आए थे और उन्होंने न सिर्फ हिन्दुस्तान के लोगों के मनों को जीत लिया था बल्कि सारे संसार के अन्दर हिन्दुस्तान का प्रैसटिज बढ़ाने में, हिन्दुस्तान की इज्जत को ऊंचा करने में, हिन्दुस्तान को कामिटी आफ नेशंज में सफे अव्वल पर खड़ा करने में उन्होंने एक बड़ा इम्पाटेंट पार्ट प्ले किया था। उन्होंने लोगों के मनों को सिर्फ जीता ही नहीं था बल्कि लोगों के मनों को, उन की नवज को पहचाना भी था लोगों की हालत को देखकर, उसे अनुभव करके उन के दिल में तकलीफ होती थी और इस प्रकार उन्होंने पूरी तरह से देश की सही राहनुमाई की थी। जो पिछले ऐग्रेशन के वक्त हिन्दुस्तान का मन पूरी तरह से यूनाईट हुआ था, जिस विलिंगनेस के साथ, जिस कुरबानी के साथ उन की लीडरशिप के नीचे सारा हिन्दुस्तान इकट्ठा हो गया और सारी दुनिया के सामने पेश हुआ वह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक सुनहरी पन्ने पर लिखा जाएगा।

स्पीकर साहिब, उन्होंने ने हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ तरह से काम किया मगर इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वह संसार में पहले ऐसे प्राईम मिनिस्टर थे कि जिन की मृत्यु के बाद हम ने देखा है कि उन की कोई किसी तरह की लाईफ इन्श्योरेंस नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई प्रापरटी और उन का अपना कोई मकान नहीं था। अगर उन का कोई बैंक बैलेंस और प्रापरटी थी तो वह यह कि उन की मृत्यु के बाद वह अपनी कार के बारे में चार हजार का कर्जा छोड़

गए । वह कर्जा उन्होंने देना था । सारे संसार के अन्दर इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती ।

स्पीकर साहिब, आज सारा हिन्दुस्तान और सारा संसार जानता है कि किस तरह से उन्होंने एक स्कूल मास्टर के घर में पैदायश लेकर किस तरह से पूर्ण सादगी और गरीबी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया था और थोड़ी से स्कूल ऐजुकेशन हासिल करने के बाद महात्मा गांधी की काल आने पर "नान कोआप्रेशन" के सिलसिले में हिन्दुस्तान की आजादी की लहर में पूरी तरह से जुट गए थे । अपनी लाईफ में श्री शास्त्री जी कोई आठ बार जेल गए और कोई नौ और दस साल के दरम्यान उन्होंने सजा काटी और हिन्दुस्तान की आजादी के लिए यह सारा बलिदान उन्होंने किया । नान कोआप्रेशन की लहर के बाद फिर काशी विद्यापीठ के अन्दर दाखिला लिया और हिन्दुस्तान के मशहूर फिलास्फर डाक्टर भगवानदास के नेतृत्व में उन्होंने शिक्षा और विद्या प्राप्त की और फिर वहां से उन्होंने शास्त्री की डिग्री प्राप्त की । उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन कौम के अर्पण कर दिया और उसके बाद हिन्दुस्तान के पालेटिक्स के अन्दर उन्होंने सरगर्मी के साथ हिस्सा लेना शुरू कर दिया । स्पीकर साहिब, वह पच्चीस साल के थे जब कि लाहौर के अन्दर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मुकम्मल आजादी का झंडा अहराया था । उस वक्त वह उन के नेतृत्व के नीचे आए थे लेकिन उस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि यही लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद हिन्दुस्तान का सैकंड प्रधान मन्त्री बनेगा । लेकिन यह उन की क्वालिटीज थीं, उन की सादगी, उन का परिश्रम और इमानदारी थी जिस ने सारे देश को मोह लिया । उन का जीवन ऐसा था जैसे कि कहते हैं 'होनहार बिरवा के होवत चिकने चिकने पात ।'

स्पीकर साहिब, शास्त्री जी सन् 1926 में लाला लाजपत राय जी के कान्ट्रैक्ट में आगे पर सरवेंट्स आफ दी पीपल सोसाईटी के मैम्बर बने । इलाहाबाद में मुख्तलिफ तरह से उन्होंने सेवा की । वह इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के वाईस चेयरमैन बने । इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के सैक्रेटरी रहे । डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सैक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम किया और 1935 के अन्दर वह वहां के जेनरल सैक्रेटरी चुने गए । जब 1937 में प्रोविशियल प्रतानोमो के तहत हिन्दुस्तान के अन्दर जेनरल इलैक्शन हुए तो उस वक्त वह उत्तर प्रदेश की असेम्बली के मैम्बर चुने गए । उस के बाद पार्लियामैंटरी लाईफ में जिस वक्त उन्होंने कदम रखा तो उस वक्त के बाद वह दिन ब दिन चमकते गए । स्पीकर साहब, आप को याद होगा कि 1921 से ले कर 1942 तक के अरसा में उन्होंने किस तरह से देश की आजादी की जंग में हिस्सा लिया । इस अरसा में देश में जितने भी आन्दोलन हुए उन सब में वह हर दशा में सरदार के रूप में सामने आते रहे । जिस वक्त कोई एजीटेशन करनी होती थी तो वह वालंटियरों में सब से आगे सरदार बनकर आ जाते थे । किसी वक्त जब लाठियां खानी होती थीं तो भी वह सब के

[मुख्य मन्त्री]

आगे सरदार बन कर आ जाते थे और सदा ऐसे मौकों पर सब के साथ सब के आगे होते थे।

1946 में वह उत्तर प्रदेश के अन्दर लेजिस्लेचर में रिटर्न हुए और उन्हें वहाँ के चीफ मिनिस्टर का पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी बनने का मौका मिला, जिस पद पर उन्होंने बड़ी सूझ बूझ के साथ काम किया और इस का नतीजा यह हुआ कि वह वहाँ के होम एंड ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर मुक़र्रर किए गए और इस तरह से उन्होंने पांच साल तक यू० पी० की अगवाई और राहुनुमाई की। तो स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि उन में अबिलेटी थी और काम करने की पोटेन्शलेटी थी और उन में हिम्मत थी जिस की वजह से पंडित जवाहर लाल नेहरू उन के मद्दाह थे और इसी का नतीजा था कि 1952 के अन्दर जब आज़ाद हिन्दुस्तान के अन्दर पहले जनरल इलेक्शन हुए तो उस वक्त पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने उन को जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए इनचार्ज मुक़र्रर किया था और उस वक्त उन्होंने सारे देश की अगवाई की और जिस ढंग से उन्होंने सारे इलेक्शन के काम को आरगेनाइज़ किया और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने उन दिनों दिन रात काम किया उस को कोई नहीं भूल सकता। स्पीकर साहिब, वह रात के दो दो तीन तीन बजे तक काम करते थे और फिर सुबह 6 बजे उठ जाते थे। इस तरह से उन्होंने सारे हिन्दुस्तान की अगवाई की थी। तो इस के बाद, स्पीकर साहिब, 1952 की फ़र्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद जब हिन्दुस्तान की पहली पार्लियामेंट बनी तो वह राज्य सभा के मੈम्बर चुने गए और फिर यह हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार के मिनिस्टर फ़ार ट्रांस्पोर्ट एंड रेलवे बने और इस तरह से उन्होंने चार साल तक काम किया जिस के बाद एक ऐसा वाक्या हुआ जो हिन्दुस्तान की पार्लियामेंटरी हिस्टरी के अन्दर एक बड़ा अहम और सुनहरी लफ़्ज़ों में लिखा जाने वाला वाक्या समझा जाता है। 19 नवम्बर, 1956 को जब अयार के स्थान पर साऊथ में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, जिस में 150 के करीब जानें तलफ हुई थीं तो उन्होंने रेलवे मिनिस्टर के पद पर से अस्तीफा दे दिया था। इस तरह रिज़ाइन कर के श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की थी जो हमेशा याद रहेगी। उन के अस्तीफा को मन्ज़ूर करते हुए हमारे लेट प्राईम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने पार्लियामेंट में एक ब्यान दिया था जिस के अन्दर उन्होंने कहा था—

“Mr. Lal Bahadur was a man of the highest integrity with devotion to high ideals. He said that he was accepting Lal Bahadur's resignation because it would set an example in constitutional propriety and not because Lal Bahadur was in any way responsible for what had happened.”

लेकिन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि बतौर रेलवे मिनिस्टर के उस एक्सीडेंट की जिम्मेवारी उन पर जाती है। तो, स्पीकर साहिब, मैं आप से अर्ज करनी चाहता हूँ कि इस मौका पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जनता के सामने इस ऊँचे कैरेक्टर के साथ

आए थे और यह पहला मौका था जिससे लोगों को पता चला था कि यह एक पुष्टा इरादे के इन्सान हैं और उनमें एक तरह की फर्मनैस है जिसकी वजह से उन्होंने उस पद से रिज़ाईन किया था। स्पीकर साहिब, आप को याद होगा कि उस वक्त जब उन्होंने अपना अस्तीफा दिया था और उन के अस्तीफा पर जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही थी तो 27 नवम्बर, 1956 को जब वह उस डिस्कशन का जवाब दे रहे थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था --

"Perhaps due to my being small in size and soft in tongue, people are apt to believe that I am not able to be very firm with them. Though not physically strong, I think I am internally not so weak."

तो इन के उस बयान से पता चलता था कि वह कितने मुसम्मम इरादा के थे, कितनी उन के अन्दर फर्मनैस थी और कितनी शक्ति और स्टैग्थ उन में थी, यह इस वाक्या से पूरी तरह से लोगों को नज़र आ गई थी। इस के बाद वह मार्च, 1958 में कामर्स और इण्डस्ट्रीज़ के मिनिस्टर बने थे और जब वह कामर्स और इण्डस्ट्रीज़ के मिनिस्टर थे तो उनकी तरफ से पहली बार एगरो इण्डस्ट्रियल इन्टेंग्रेसन स्कीम आई थी जिस का मकसद था कि सारे हिन्दुस्तान के एक एक गांव के अन्दर इण्डस्ट्री को ले जाया जाए ताकि हिन्दुस्तान के कामन मैन के अन्दर, पेजेंट्स के अन्दर और रूरल मासिज़ के अन्दर जो अनएम्पलायमेंट है उसको दूर किया जा सके। इस तरह से उन्होंने हिन्दुस्तान के काफी गांवों में इण्डस्ट्री को ले जाने का यत्न किया था। इसके बाद जब पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर का पद संभाला। और उस पद पर रहते हुए उन्होंने साबत कर दिया कि वह एक आला दरजे के नैगोशिएटर हैं और कम्प्रोमाईज़ हैं। वह परसूएशन से और अपनी सिनसैरेटी के ज़ोर से लोगों के दिलों को जीत ले थे और इस बात का उन को होम मिनिस्टर बनने के बाद सबूत देने का मौका मिला ज आसाम में लैंग्वेज कन्ट्रोवर्सी पर बड़ा भारी झगड़ा पैदा हो गया था। उन्होंने बंगाल और आसाम के लोगों की बातें सुन कर इस मसला का एक ऐसा हल ढूँढा जो दोनों पार्टियों को मनज़ूर था। स्पीकर साहिब, सिर्फ यह ही नहीं जब श्री लाल बहादुर शास्त्री हिन्दुस्तान के प्राईम मिनिस्टर बने तो इन की इन्हीं खूबियों की वजह से हमारे पड़ोस देश नेपाल, बर्मा और सिलोन जितने भी मुमालक हैं वह हमारे देश के ज़्यादा नज़दीक आए। श्री लाल बहादुर जी शास्त्री मिसअण्डरस्टैंडिंग को, जो इन मुमालिक के दरमियानी, परसूएशन से और अपनी सिनसैरेटी से दूर कर के इन को अपने देश के नज़दीक लाने में सफल हुए।

अगस्त, 1963 में उन्होंने फिर कामराज प्लान के तहत अस्तीफा दिया लेकिन पि 24 जनवरी, 1964 को यह मिनिस्टर विदाऊट पोर्टफोलियो लिए गए और एज़ मिनिस्टर विदाऊट पोर्टफोलियो जब कश्मीर में मूए मुबारिक की एजीटेशन चली थी तो इन्हें बड़ी बुर्दबारी और सूझबूझ से और हिम्मत से इस मसले को सुलझाया। इसी तरह वह हर ऐसे मसले का हल तलाश करते रहे और खतरनाक से खतरनाक मसले का

[मुख्य मन्त्री]

वह निकाल लेते थे और उन्होंने इस तरह से नेशनल इन्टिग्रेशन के कायम करने में एक नया चेंप्टर कायम किया है। इसी वजह से पंडित नेहरू जी के हम से जुदा हो जाने के बाद वह हमारे प्राईम मिनिस्टर बने थे और जिस तरह प्राईम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने हिन्दुस्तान की अगवाई की और राहुमाई की और जिस शक्ति के साथ उन्होंने देश को सम्भाला है उसको सारा देश अच्छी तरह से जानता है। 19 महीने का थोड़ा सा अरसा है जब कि वह हमारे प्राईम मिनिस्टर रहे लेकिन इस थोड़े अरसे के अन्दर सही मायनों में उन्होंने महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहर लाल जी नेहरू का अपने आप को सही जानशीन साबत कर दिया था। उन्होंने अपने प्यार से और अपनी शक्ति से अपने देश में एकता पैदा की और इस तरह से उन्होंने सही मायनों में देश में इमोशनल इन्टिग्रेशन कायम की थी। प्राईम मिनिस्टर बनने के बाद जो उन्होंने पहला ब्राडकास्ट देश के नाम किया था उससे पता चलता है कि उन के क्या इरादे थे उसमें उन्होंने कहा था—

“Our way is straight and clear—building up of a socialist democracy at home with freedom and prosperity for all, and the maintenance of world peace and friendship with all nations abroad. To that straight road and to these shining ideals, we re-dedicate ourselves today.”

इसी तरह से, स्पीकर साहिब, जहां उन्होंने अपने देश में इतना काम किया है वहां उन्होंने बाहर के मुमालिक में भी बड़ा भारी काम किया है। काहरा में जब नान-एलाईण्ड नेशनल की कानफेंस हुई थी जिसमें तमाम नान-एलाईण्ड नेशनल के नुमायन्दे एकत्रित हुए थे तो इन्होंने दुनिया में से लड़ाई को खत्म करने का एक नारा दिया था कि इस काम में दुनिया के नान-एलाईण्ड नेशनल ने एक बड़ा अहम पार्ट प्ले करना है जिससे तमाम दुनिया आराम से रह सके। उसको सारी दुनिया मानती है। पिछले दिनों वह रंगून में जैनेरल ने विन से मिलने गए, सिलोन में भी गए और इन जगहों पर रहने वाले हिन्दोस्तानियों के मामले को बड़ी खुशअसलूबी से सुलझाया। यह वह बातें हैं जो हमारे ही नहीं सारे संसार के सामने उन की एक जीती जागती तसवीर पेश करती हैं। आप को मालूम है कि किस तरह से कश्मीर के मामले पर भारत का अपमान होने लगा था मगर उन्होंने किस खुशअसलूबी से उस सारे मामले को हल किया और इस मुल्क की शान को बढ़ाया। ना वह और ना हिन्दुस्तान लड़ाई लड़ना चाहता था मगर जब उन पर यह लड़ाई ठोसी गई तो आप जानते हैं कि वह किस तरह से इस का मुकाबला करने के लिये खड़े हो गए और दुश्मन का मुकाबला किया। और जब मौका आया तो जिस तरह से उन्होंने ताशकन्द में अमन कायम करने के लिये कार्यवाही की वह सारी दुनिया के लिये एक मशअल रहेगी। उन सारी खूबियों और कारनामों से उन्होंने हिन्दोस्तानियों के मनो को जीत लिया था। यही नहीं बल्कि संसार के सभी बड़े बड़े आदमियों ने उन को बड़ा ट्रिब्यूट पे किया है। उन्होंने मैडेम क्यूरी की बायग्राफी हिन्दी में लिखी है। उन को जहां और बहुत सा काम था वह उस के साथ स्विमिंग, टेबल टेनिस और बैडमिन्टन वगैरह का शौक भी रखते थे और जब भी मौका मिल पाता था बच्चों से खेलने में भी बड़ी खुशी मनाते थे। उन को बच्चों से बड़ा प्यार था। एक बार उन्होंने कहा था : I am so short that no body

likes to play with me. I, therefore, turn to children. बच्चों से खेलते हुए वह उन से घुल मिल जाते थे। बच्चों से ही नहीं वह सभी से मिलते जुलते थे और बड़े प्यार से बरताव करते थे। जब हम उन के बारे में सोचते हैं तो उन की वह सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह से वह सब को रास्ता दिखाते थे। हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि वह हम सब को शक्ति दे कि हम उन के दिखाये हुए मार्ग पर चल सकें और इस तरह से अपने देश को शक्तिशाली बना सकें और जो देश को मजबूत बनाने का उन की मृत्यु से अधूरा रह गया है उसको पूरा कर सकें। इन अलफाज के साथ मैं अपने इस स्वर्गीय नेता, लेट प्राईम मिनिस्टर को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और यह रैजोल्यूशन मूव करता हूं :

Sir, I beg to move:

That the Punjab Vidhan Sabha places on record its deep sorrow at the passing away of Shri Lal Bahadur Shastri. The Nation was deprived of the brightest jewel of the country on the dreadful night of the 10th January, 1966, when, standing at the pinnacle of success, Shri Lal Bahadur Shastri was snatched away from us by the cruel hands of death.

Shri Shastri's services to the nation were so significant that he could easily be called as the consolidator of Indian freedom.

Shri Lal Bahadur Shastri was a man of peace and goodwill. He symbolised the traditional virtue of humility and greatness of mind ; never was the fusion of these qualities so complete as in the personality of this great leader of the Indian people.

This House has a special reason to be closely attached to Shri Lal Bahadur Shastri as ever since his association with Lala Lajpat Rai, he had been always specially benevolent to Punjab.

This House will indeed honour itself by paying respectful homage to a man whose whole social and political career was a legend of devotion to the interests of the people and sacrifice to the national cause.

The Members of the Punjab Vidhan Sabha convey their heartfelt condolences and sympathies to Shmt. Lalita Shastri, and all other members of the bereaved family.

**Sardar Gurnam Singh (Raj Kot) :** Mr. Speaker, Sir, the interregnum between our meeting today and when we dispersed at the end of last session has been marked by more than one grievous news of passing away of eminent men in our public life. Besides that of our late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri, we had to bear the shock of death of several other eminent men of this country.

The death of Shri Lal Bahadur Shastri has been, in a sense, most grievous for us. During his short period of stewardship of the nation he more than fulfilled the trust we repose in our democratic processes and belied those who associate democratic leadership with chair charisma and exceptional gifts of body and mind. He shone in his full glory in the task of peace at Tashkent as he distinguished himself as a man of determination and decision during the recent Indo-Pakistan conflict. He commanded respect of nations of the world for his effort to solve intricate International disputes by peaceful means.

[Sardar Gurnam Singh]

The late Prime Minister was a man of genial temperament and was an unassuming democrat. He led the nation with ease and confidence and made serious effort to solve our problems with resolute determination. His name will always be associated with justice and integrity—noblest aspects of humanity. He was a wise statesman.

Sir, my people, the Sikhs entertain a sense of special loss in the death of Shri Lal Bahadur Shastri, knowing that the last Prime Minister was firmly disposed in favour of demarcation of a unilingual Punjabi State as a first step towards a sympathetic settlement of the Sikh grievances and problems. My people earnestly hope that the charming and brilliant successor of late lamented Prime Minister will soon bend her energies to the same task.

Sir, I on behalf of my party and also on my own behalf, join with the rest of the House in expressing and conveying condolences to the bereaved family.

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : स्पीकर साहिब, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन के सामने रखा है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहिब, शास्त्री जी ने अपने थोड़े से प्रधान मंत्री पद के अर्से में एक ऐसा चित्र देश के सामने रखा कि जिसे देख कर हम सब का सिर उन के सामने श्रद्धा से झुक जाता है। स्पीकर साहिब, नीतियां के साथ किसी का भी विरोध हो सकता है और प्रजातन्त्र में अलग अलग विचारधाराएं और नीतियां चलती हैं और चलती रहेंगी। परन्तु जहां तक उन को महानता, उन को सच्चाई, निष्ठा और कर्तव्य परायणता का प्रश्न है, कोई भी देशवासी ऐसा न होगा जो शास्त्री जी का नाम पूरी श्रद्धा के साथ न लेता हो। उन्होंने प्रजातन्त्र के अन्दर नई परम्पराएं, नई रवायतें पैदा कीं। उन्होंने अपने 18 महीने के प्रधान मंत्री पद के काल में जिस तरह से सारी आपोजीशन को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि उन का यह प्रयत्न बहुत ही सराहनीय था।

यही प्रजातन्त्र की सही भावना है। मेरी राय और हो सकती है, लेकिन दूसरों की राय क्या है और उस की मांग क्या है, इसके बारे में शास्त्री जी के पास कदर थी। वह लोक राय की कदर करते थे और उन्होंने अपनी नीतियों में उसी के अनुसार परिवर्तन लाने की कोशिश की। उन्होंने सदा इस भावना से और इस नुक्ता से काम किया कि देश के हित में क्या होगा। 18 वर्ष की स्वतन्त्रता प्राप्ति की जो राजनीति थी उस का उन्होंने 18 महीने में अपने शासन काल में परिवर्तन कर दिखाया। यह एक महान परिवर्तन है, जिस को हर देशवासी याद रखेगा और उन के कदमों पर चलने का प्रयत्न करेगा। इस से न केवल देशवासी ही बल्कि आने वाले प्रधान मंत्री और सब पार्टियों के राजनीतिज्ञ उन के बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयत्न करेंगे। इन के जीवन को अपना आदर्श मानेंगे। मैं समझता हूँ कि यही आशा हर देशवासी की होगी और इसी भावना से वह काम करेंगे।

स्पीकर साहिब, इतना ही नहीं, 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो हमें सैनिक दृष्टि से पीछे हटना पड़ा और हमें अपने कुछ इलाके को खाली करना पड़ा।

इस से हमारे देश का अपमान हुआ। संसार में हमारे प्रति बुरी भावना पैदा हो गई। और यह समझा जाने लगा कि भारत जो इतना शक्तिशाली देश है, किसी के हमला हो जाने पर मुकाबला नहीं कर सकता। इसमें इतनी शक्ति और हिम्मत नहीं। इस देश में शायद इनसान नहीं रहते और ऐसे लोग नहीं रहते जो स्वैरभिमानी हों बल्कि इस देश में भेड़ बकरियां रहती हों। इस तरह की भावना बन गई थी लेकिन जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच 18 या 20 दिन का जो युद्ध हुआ उसमें शास्त्री जी के नेतृत्व के अन्दर, उन की लीडरशिप के अन्दर संसार के लोगों के सामने एक नई तसवीर देखने को मिली। और यह सिद्ध कर दिया कि जब देश पर आक्रमण हो तो हमारा देश शांति की मान मर्यादा को छोड़ कर आक्रमण का मुकाबला करने को तैयार हो जाता है और देश की आजादी को कायम रखने में कोई कसर नहीं रखता। शास्त्री जी के नेतृत्व में देश ने जो कदम उठाए उससे सारे संसार पर यह सिद्ध हो गया कि इस देश में बसने वाले 45 करोड़ इनसान भेड़ बकरियां नहीं और लड़ाई में मुकाबिले के लिये खड़े हो सकते हैं। देश न सिर्फ खड़ा ही हो सकता है बल्कि दुश्मन को पीछे धकेल सकता है। दुश्मन के देश में जा कर भी कब्जा कर सकता है। और हमारे जवानों ने अपनी वीरता का झन्डा दुश्मन के देश में जा कर झुलाया। इस तरह की हमारे देश की तसवीर शास्त्री जी ने ही पेश की। और मैं तो यह समझता हूँ कि आधुनिक काल में इस देश के लिए एक नए युग प्रणाली को आरम्भ किया। इससे देश की मान और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी। देश के रहने वालों में हिम्मत बन्ध गई। लोगों का मान बढ़ा, देश का गौरव ऊंचा हुआ और देश की सर्विसों में आत्म विश्वास बढ़ा। हरेक शहरी के अन्दर स्वैरभिमान स्थापित हो गया। यह सब शास्त्री जी की दन थी।

स्पीकर साहब, और अधिक न कहता हुआ मैं केवल एक दो और बातें शास्त्री जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि इन का जीवन कितना सादा था जो आज के युग में सत्ताधारियों के लिए आदर्श माना जा सकता है। आज क्या हालत होती है कि जब कोई व्यक्ति सत्तारूढ़ हो जाए तो दो महीनों में चार महीनों में या छः महीनों में ही अपनी प्रापर्टी बना लेता है। उसकी जायदाद को आप देखें, उसकी परसनल प्रापर्टी को आप देखें और उस के रिश्तेदारों की शान को आप देखें लेकिन शास्त्री जी की मिसाल आप को शायद न मिल सके कि लोगों के सामने उन्होंने किस तरह की भावना कायम की। वह आज से नहीं, शुरू से ही राजनीतिज्ञ रहे हैं, एम. एल. ए. रहे, मन्त्री रहे लेकिन ऊंचे आदर्श को सामने रखा। जन साधारण तो एम. एल. ए. बनने के लिये या कुर्सी को हासिल करने के लिये क्या कुछ नहीं करते और राजनीति की दौड़ में पिछले 18 वर्षों में जो तसवीर सामने आई वह खराब हो चुकी थी और यही समझा जाने लगा था कि राजनीति की दौड़ में जो भी आ गया उसने सब तरह से कुर्सी को कायम रखने की चेष्टा की और आम आदमी के दिल में यह बात घर कर गई थी कि राजनीति के क्षेत्र में सारे ही कुरष्ट होते हैं। इस तरह की घृन्दली तसवीर को शास्त्री जी ने साफ किया और अपने जीवन काल में यह सिद्ध कर दिया कि एक राजनीतिज्ञ का जीवन कितना साधारण हो सकता है। आप प्रधान

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

मन्त्री भी रहे और मन्त्री भी रहे परन्तु जब स्वर्गवास हुए तो इन के परिवार के पास न कोई जायदाद, न रहने को अपना मकान और फिर लोगों को देने वाला कर्जा, यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिये भी रकम नहीं। उन्होंने अपने राजनीति काल में कोई अपनी परसनल जायदाद नहीं बनाई और न ही इसके बारे में कोई ध्यान दिया था। अब सरकार ने कुछ पेंशन उन के बच्चों की पढ़ाई के लिए मुकरर की है और उनकी विधवा धर्म-पतनी के गुजारा के लिए रकम मुकरर की है। राजनीति के अन्दर इतने ऊंचे पद पर रहने पर भी अपने जीवन आदर्श का त्याग नहीं किया बल्कि सेवा की भावना को सामने रखा और आज के राजनीतिज्ञों के सामने एक ऊंचा आदर्श कायम किया जिसकी मिसाल संसार में नहीं मिलती। एक नए आदर्श का निर्माण किया जिस को हम सब को मान कर आगे चलना पड़ेगा।

स्पीकर साहिब, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमें कहीं कहीं पर इन की नीति से विरोध हो सकता है और प्रजातन्त्र में विरोध एक साधन है अपनी राय को प्रकट करने का और इस बात की स्वतन्त्रता है, जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि ताशकंद समझौता इस देश के लिए एक बहुत बड़ी एचीवमेंट है, मैं भी इस बात को मानता हूं। ताशकंद समझौते के बारे में किसी रूप में मुझे या हमारे जनसंघी भाइयों को विरोध हो सकता है लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ताशकंद समझौता में देश के हित को कायम रखने और देश में शान्ति बनाए रखने का एक प्रयत्न शास्त्री जी ने किया। यह जरूरी नहीं कि ताशकंद समझौता से पूरी तरह से हरेक एग्री हो, हरेक की मनो-वृत्ति अलग अलग हो सकती है लेकिन यह जो प्रयत्न शास्त्री जी ने किया इस से हम सब का सिर अत्यन्त श्रद्धा से झुक जाता है। उन्होंने जो प्रयत्न देश की आजादी को कायम रखने के लिए और शान्ति के लिए किया हम सब उस का अभिनन्दन करते हैं। ताशकंद समझौते का विरोध हो सकता है और हमारा है भी लेकिन उस भावना और उस प्रयत्न की जो शास्त्री जी के व्यक्तित्व ने देश की शान्ति को कायम रखने के लिये किया आज सब सराहना करते हैं। इस से देश का मान बढ़ा है। जो व्यक्तित्व शास्त्री जी ने पेश किया वह एक रास्ता है जिस पर आने वाली नसलें मान करेंगी और राजनीतिज्ञों का पथ प्रदर्शक बनेंगी। हम अपनी पार्टी की ओर से इस सोगमई प्रस्ताव में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। इतना कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

**चौधरी देवी लाल (फतेहबाद) :** स्पीकर साहिब, आज जो मुख्य मंत्री महोदय ने देश की एक बहुत बड़ी हस्ती श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया है उस का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधान मन्त्री ही नहीं थे बल्कि अंग्रेज के वक्त में देश की आजादी की लड़ाई में एक वालन्टीयर से लेकर जरनैल तक थे। उन्होंने देश की आजादी हासिल करने के लिए महान कुरबानी की और न केवल कुरबानी की बल्कि आजादी को हासिल करने के बाद देश की हकूमत को किस तरह से चलाना चाहिए, किस ढंग से चलाना चाहिए और देश की हकूमत को चलाने वाले का क्या फर्ज होना चाहिए इस की मिसाल शास्त्री जी ने

कायम की। जो रास्ता इन्होंने अपनाया वह आगे आने वाले लोगों के लिये एक शाहराह बन गया है। दुनिया की किसी भी स्टेट में, किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने बताया है कि एक साधारण ढंग से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने अपनी जिम्मेवारी इसमें समझी और वजारत से अस्तीफा दे दिया।

शास्त्री जी जब हमसे जुदा हुए तो इस कालोगों में क्या रीएक्शन हुआ मैं इस की एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं 10 और 11 तारीख को बम्बई से 20 मील दूर राजेश्री गांव में सुबह छः सात बजे गर्म पानी के चशमे पर नहाने के लिये जा रहा था तो एक साईकल वाला कहता जा रहा था कि हमारे प्रधान मन्त्री लाल बहादुर शास्त्री स्वर्गवास हो गए हैं। लोग इस खबर को सुन कर हैरान थे। छोटी छोटी चाए की दुकानों वालों को इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर जब रेडियो पर लोगों ने खबर सुनी तो यकीन करना पड़ा। जब हम चशमे पर पहुंचे तो वहां पर एक दो औरतें नहा रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश की आन और मान मरयादा को बचा लिया पाकिस्तान से लड़ाई कर के, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हशर होता। उनकी आंखों में आंसू थे। शास्त्री जी ने देश के आम लोगों का दिल जीत लिया था।

जब चीन का हमारे मुल्क पर एग्रेसन हुआ उस का मुकाबला करने के लिये हमें बहुत से आर्मज और ऐम्पूनेशन इकट्ठे करने की जरूरत पड़ी थी जिस के लिये हम ने बाहर के मुल्कों से डिमांड की थी। हमारे मुताल्लिक अमरीका में यह ख्याल किया गया था कि इन्हें कोई जंगी असलाह नहीं देना चाहिये, इस लिये कि यह चीन को दे देंगे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारी फौज का इतना नाम ऊंचा किया कि अमरीका वाले इन दिनों यह महसूस करने लगे थे कि हमें इन को ज्यादा से ज्यादा जंगी इमदाद देनी चाहिये थी। इस बात को अमरीका के लोगों को कहते हुए खुद प्रोफेसर शेर सिंह जी ने सुना जो कि उन दिनों अमरीका में थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि शास्त्री जी के जो असूल थे वह ऐसे थे जिन्होंने इस मुल्क के वकार को बहुत ही ऊंचा किया था, बावजूद इस बात के कि हमारी फौज के जवान बड़ी दलेरी से इस लड़ाई में लड़े मगर जो असूल और रवायात श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इन लड़ाई के दिनों में इस मुल्क को आगे ले जाने के लिये कायम कीं उनसे हमारे देश का और भी वकार ऊंचा हो गया है। यह उनकी राहनु-माई का ही नतीजा है।

जिन हालात में ताशकंद समझौता हुआ वह आप सब जानते ही हैं। हो सकता है कि कोई शख्स इस समझौता के खिलाफ भी हो मगर इस बात को तमाम लोग मानते हैं कि जिस स्पिरिट में ताशकंद समझौता हुआ है उस से यह साफ जाहिर होता है कि उन की आत्मा दोनों मुल्कों का खून खराबा बरदाश्त न कर सकी जिस की वजह से उन्हें अपनी जान की बाजी तक लगानी पड़ी। वह हर कीमत पर इस देश की आजादी और अमन को बरकरार रखना चाहते थे। वापसी का वक्त था जब उन्होंने घर पर टेलीफोन किया; समझौता हो जाने के बाद, जो बात उन्होंने की इस से भी इसी चीज के रीएक्शन की झलक ही नजर आती थी।

[चौधरी देवी लाल]

आज हम उस महान हस्ती का मातम मनाते हुए इस रैजोल्यूशन के जरिये श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। हमें चाहिये कि हम उन के असूलों पर चल कर सच्चे मायनों में श्रद्धांजलि दें। जिन डैमाक्रेसी के असूलों को मद्दे नज़र रखते हुए उन्होंने इस मुलक के झगड़ों को हल करने में हर पार्टी के लीडर्ज़ को कन्सल्ट करने की कोशिश की, वह हमारे लिये बहुत ही शानदार असूल का रास्ता दिखाती है। आज मुलक के सामने ऐसे हजारों मसले हैं जिन को इन रवायात के मुताबिक हल किया जा सकता है। हमारे सामने गिज़ाई मसला है। पंजाब में पंजाबी सूबा और हरियाना प्रान्त के भाषाई सवाल हैं। शास्त्री जी इस मसला को बखूबी समझते थे इस लिये उन्होंने इस को हल करने की पूरी पूरी कोशिश की। मगर मुलक की बदकिस्मती है कि वह इस को दरमयान में ही छोड़ गये। फिर भी मुझे यकीन है कि इस मुआमला के मुताल्लिक जो नीति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इख्तियार की थी अगर उस पर चलें तो इस देश के मसले आसानी से हल हो सकते हैं।

अगर हम सही लफ्जों में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया था, हम उन के दिखाये हुए रास्ता पर चलें। मैं इस मुआमला पर और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मुख्य मंत्री और दूसरे साहिबान भी इस पर बहुत कुछ कह गये हैं। अब हमें चाहिये कि हम उन के दिखाये हुए रास्ता पर चलें।

जो खिदमत आज़ादी को बरकरार रखने में इस मुलक की उन्होंने की इस की कहीं मिसाल नहीं मिलती। जो कुरबानो उन्होंने इस मुलक की खिदमत करते हुए की वह एक नमूना है। 1937 से लेकर 1966 तक वह कभी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर और कभी होम मिनिस्टर और कभी प्रधान मन्त्री रहे। हकूमत के इतने बड़े बड़े अहदों पर रहने के बावजूद भी कितनी हैरानी की बात है कि उनकी अपनी कोई जायदाद न थी। न उन का अपना कोई रहने का मकान था, न कोई और जायदाद। आप देखें कि जिस के पास ज़रा सी भी पुलिटीकल पावर आ जाये वह दिनों के अंदर महल उसार लेता है। मगर वह ऐसे शख्स थे जो आला पुलिटीकल पावर पर होते हुए एक आम आदमी की तरह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ रहे। किसी को भी अपनी पुलिटीकल पावर का नाजायज़ फायदा उठाने नहीं दिया। हमें उन के असूलों से सबक लेना चाहिये।

इन इलफाज़ के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और श्री लाल बहादुर जी शास्त्री को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा उन की रूह को शान्ति दे।

ਕਮਰੇਡ ਜ਼ੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮਤਾ ਏਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਕ ਆਮ ਜਨਤਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਐਮ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਉਚੇ ਪਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਵੀ ਬੇਲਾਗ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਾਏ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਨ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ੀਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚ ਲਿਆ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਲਝਿ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬੀਨਿਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਲਝ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ। ਉਹ ਅਜ ਸਾਡੇ ਉਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

**ਕਾਸਰੇਡ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਾ (ਕਰਨਾਟ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਸਕੀਨ ਕਰਨੇ ਆਰ ਅਪਨੀ ਅਫ਼ਜ਼ਾਇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ ਹੂੰ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਲੂ ਹੈ ਜਿਨ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਯੋਂ ਕਾ ਸੇਰੇ ਸੋ ਪਹਲੇ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਨਾ ਸਾਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਕਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੁਰਾਪਟ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਮ ਕੀਏ ਤਨ ਸੋ ਧਰ ਸਾਕਰ

कामरेड राम प्यारा]

इसका कि पुराना माकूला गलत हो सकता है। बशर्ते कि इन्सान इन्टैग्रिटी वाला बनने की कोशिश करे और यह कहने में मुझे रत्ती भर झिझक नहीं कि इन्सान की बड़ी क्वालिटीज़ हैं जिन पर खूब पाना मुश्किल है। उनमें से मैं एक दो जस्टिस और इन्टैग्रिटी कह सकता हूँ। हिन्दुस्तान ने शास्त्री जी द्वारा वह फखर हासिल किया क्योंकि वह इन दोनों क्वालिटीज़ पर खूब पा चुके थे। उन के बारे में यह ठीक कहा जाता है कि 'शास्त्री बाज़ ए मैन आफ इन्टैग्रिटी एंड जस्टिस'। जब शास्त्री जी प्रधान मन्त्री बने तब उन के सामने दो किसम के चैलेंज जिन को उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल किया। जब चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान का वकार गिरा। जो हिन्दुस्तान में डिमारेलाइजेशन आई और फौज में भी थोड़ी बहुत हल-चल मची थी, लोगों में भी बेचैनी मची थी, शास्त्री जी ने अपनी काबलीयत से, अराम के तूआवन से, फौज की मदद से बड़ी बहादुरी से इस चैलेंज को कबूल किया और उसको कबूल करने में पूरी तरह कामयाब हुए। हिन्दुस्तान के सफ़ेद तहल्ले पर जो बदनूमा दाग था चीन के हमले का उसको अराम के तूआवन और बहादुर पाहियों के हौसले से उन्होंने धो दिया। वह चैलेंज उन्होंने मान कर कामयाबी हासिल की। दूसरा चैलेंज जो उन्होंने कबूल किया वह हिन्दुस्तान की अराम की तरफ से था। हिन्दुस्तान अराम के साथ जो वायदे किये गये थे उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं हुआ था क्योंकि ग़लत तो यह था कि गरीब और अमीर के दरम्यान फर्क कम करना है। पिछले 17 या 18 साल में गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता ही गया। शास्त्री जी ने अराम के साथ किये हुए उस वायदे को भी पूरा किया। हिन्दुस्तान में जो बड़े बड़े मगरमछ कैपटलिस्ट जिन के पास ब्लैक मनी, चोरी का रुपया था, हिन्दुस्तान की कमाई का अक्सर रुपया उनके पास था उसके ऊपर इन्होंने हाथ डालना शुरू किया था। अगर परमात्मा इन्हें जिन्दगी देता तो वह बड़े बड़े मगरमछों जिन के ऊपर हिन्दुस्तान के बड़े बड़े आदमियों को हाथ डालने की हिम्मत न हुई यह उन पर हाथ डालते, उन की ब्लैक की कमाई लेते और उन्हें छोड़ी बहुत सज़ा देते और गरीब अराम का भला कर सकते। जो मसले बहुत देर से नहीं हुए थे वह 18 महीनों में शास्त्री जी ने कर दिखाए। वह एक कामन मैन का प्रिमिनिस्टर था, अराम की तरफ से। कई दफा बड़े बड़े महापुरुष हम से जुदा होते हैं। उनके लिए हड़ताल कराने के लिये बाज़ार में जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही शास्त्री जी की मौत की खबर पहुंची बाज़ार के काम एक सैकन्ड में बन्द हो गए। किसी को आने की ज़रूरत न हुई। उन की छाप अराम के दिल पर थी। हो सकता है कि चन्द बिज़नेस मैग्नेट ऐसे नहीं क्योंकि उनको डर हो रहा था, कोई कैपटलिस्ट ब्यू के आदमी नहीं लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान के अराम का ताल्लुक है उन को दुख हुआ। वह काम छोड़ कर उस दुख में शामिल हुए जिस दुख में हिन्दुस्तान डूबा हुआ था। शास्त्री जी की प्रिमिनिस्टरशिप से एक बात और बाज़े हो गई कि वक्त आने पर हिन्दुस्तान लड़ेगा। इससे साबित हुआ कि एक वक्त में हिन्दुस्तान अमन परस्त भी है। हिन्दुस्तान की आन और शान को बचाने के लिये लड़ाई की ज़रूरत थी तो शास्त्री जी ने लड़ी। जब ज़रूरत थी कि अमन हो तो शास्त्री जी ने अमन के लिए जान दे दी। ज्यादा समय नहीं लेता, बहुत से मੈम्बरों ने ख्यालात कह दिए हैं। मैं इतना ही अर्ज करूंगा

कि उन्होंने त्याग की वह भावना पेश की है जो हिन्दुस्तान की सभ्यता को ऊंचा करती है। अगर हिन्दुस्तान की पुरानी तारीख को देखें तो पता चलता है कि राजाओं महाराजाओं की इतनी पूजा नहीं होती जितनी कि त्यागी महापुरुषों की होती है। अशोक की ग्रेट की पूजा नहीं होती मगर महात्मा बुद्ध की पूजा होती है। अकबर की ग्रेट की पूजा नहीं होती मगर राणा प्रताप की होती है। महाराजा रणजीत सिंह की नहीं होती बल्कि गुरु गोबिन्द सिंह की पूजा होती है जिन्होंने त्याग किया। यह हमारी पुरानी रवायत है। उस को शास्त्री जी अपने त्याग से सिद्ध किया। जब उन की मृत्यु हुई तो उन के पास मकान नहीं था, जमीन नहीं थी, उन का कोई बैंक बैलेन्स नहीं था और न ही उन की कोई इन्शोरेन्स थी। उन्होंने साबित कर दिया कि हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता में जहां राजाओं महाराजाओं की कदर नहीं, कैपटलिस्ट की कदर नहीं, दौलत वालों की कदर नहीं बल्कि त्याग की कदर है तो उस कदर को, जो त्याग की पुरानी कदर थी, आप के सामने रखते हुए शास्त्री जी एक बार फिर अपनी इज्जत को कायम किया। इस लिये शास्त्री जी का त्याग, उनका कुरबानी उन का चैलेंज कबूल करना हिन्दुस्तान की तारीख में सुनहरे शब्दों में लिखा जायगा। यदि हम सही मायनों में उन्हें श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने जो चैलेंज मंजूर करके हिन्दुस्तान की आन और शान को बचाया, अमीर और गरीब दरम्यान फर्क को कम करने की कोशिश की अगर हम तहे दिल से उनके सिद्धान्तों का कायम करने की कोशिश करें तो सही मायनों में श्रद्धांजलि होगी। इन लफ्जों में मैं शास्त्री जी के कदमों में श्रद्धांजलि पेश करता हूं।

**चौधरी नेत राम (हिसार सदर) :** स्पीकर साहिब, हमारे मुख्य मंत्री महोदय जो प्रस्ताव शास्त्री जी की मृत्यु पर पेश किया है उसमें मैं भी अपना फर्ज समझता हूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि पेश करूं और उन के परिवार से सहानुभूति प्रकट करूं। वह देश की आजादी के लिये लड़ते रहे। अंगरेज हुकमरान को यहां निकालने के लिये जद्दो जहद करते रहे और इस काम में जुटे रहे। और देश में से अंगरेजों को निकाल कर जो देश की प्राबलम्ज थी उन को हल करने में जुट गए। देश के लिए जज्बात का ख्याल और भावना रखने वाला इन्सान इस मौका पर देश से उठ गया है। उन से पहले जो कुछ होता रहा उसके कई कारण हैं। एक यह कि कांग्रेस सरकार लगातार 19 साल से भारत पर हुकूमत करती आई है, अपनी सरकार चलाती आ रही है उसकी विदेश नीति जो रही है वह बहुत नुकसान देह रही है, गलत रही है। इस देश की सरहद्दों की रक्षा मजबूती के साथ होनी थी उसमें सरकार की नीति बहुत कमजोर रही जिसका नतीजा यह हुआ कि कहीं चोटें खाईं, कहीं गलत ढंग से काम किया। आज देश के अंदर अनाज का न होना, भुखमरी का फैलना और देश के अंदर इस हालत का पैदा होना सरकार की गलत नीति से हुआ है। जिस का नतीजा यह हुआ कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसी पवित्र आत्मा को ताशकंद के समझौते में बैठ कर इतना सदमा पड़ा कि उन्हें अपने प्राण देने पड़े। स्पीकर साहिब, मैं बताना चाहता हूं अगर इसी तरीके से हमारी सरकार चलती रही तो न जाने कितने ल

चौधरी नेत राम]

हादुर शास्त्री जैसे महान् व्यक्तियों को इस जहान से जाना पड़ेगा। इस सरकार को चाहिए कि यह उन की मृत्यु से सबक सीखे और देश को मजबूत बनाए और यहां जो भुखमरी ड़ रही है उसे दूर करे और अपनी गलत पालिसी को छोड़ कर सही रास्ते पर आए। अगर हमारा देश मजबूत होता और हमारी सरकार की पालिसी सही होती तो रूप, मरीका या कोई और देश हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकता था। हमारे महान् नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कुरबानी नहीं दी बल्कि उन की सदमे की जह से मृत्यु हुई है जिस का कि हमें बहुत दुःख है। हमारे देश को तरक्की की राह पर चलना चाहिए और दूसरे देशों के सहारे चलने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस कांग्रेस सरकार ने अपनी पालिसी न बदली और मुलक कमजोर होता गया तो न जाने कितने लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान् नेताओं को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। बस इतना कह कर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मा को अन्ति बख़्शे और उन के परिवार को सहन शक्ति बख़्शे और हमारा देश उन के खयालात के ढंग से सोच कर अपनी कमजोरियों को दूर कर के मजबूत बने।

**Mr. Speaker :** I also join the Leader of the House and the other hon. Members in paying my humble homage to the great departed leader the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri. Shri Shastri was a great fighter for freedom. He was an uncompromising defender of the security of the country and he was a determined seeker of peace both national and international. He was very anxious to make the country at peace with all the neighbouring countries. He tried to solve the problems—the pending disputes with Ceylon, with Nepal and other countries. When he became the Prime Minister, the country was faced with a number of problems. He solved some of them and made a determined effort to solve the others. He set new conventions—very healthy conventions in democracy. He was very anxious to associate the Leaders of opposition with the country with him before taking any decision on any important problem. He was a man of humble origin. He came from the poorest family in India and by sheer dint of his sense of service and sacrifice, he rose to the highest position in the country. But throughout, he resisted all temptations for personal power and wealth. During his short regime, the nation was re-built. He was able to restore confidence, give back determination and develop a sense of pride in the nation. The nation had all confidence in him and he also had faith in the destination of the country. I am confident that if he were given more time by fate, he would have solved all problems with which the country was faced. The present-day India and the generations to come will always get inspiration from his life and from his deeds.

Now, we shall pass this resolution by standing in silence for two minutes in the memory of the departed leader.

*The House then stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of late Shri Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India.)*

**Mr. Speaker :** The House has agreed with the resolution. Copies of this Resolution will be sent to the President of India, the Prime Minister of India and Shrimati Lalita Shastri.

**Voices: Yes.**

दे  
र  
उ  
प  
व  
इ

## OBITUARY REFERENCES TO THE DEATHS OF LATE

- (1) Shri N.V. Gadgil, Former Governor of Punjab.
- (2) Rao Bahadur Chaudhri Lal Chand, Ex-Minister, Punjab.
- (3) Jathedar Udham Singh Nagoke, Ex-M.P.
- (4) Shri Mam Chand, Ex- M.L.A.
- (5) Shri Ahmed Mohiuddin, Deputy Transport Minister, Union Government.
- (6) General K.S. Thimayya, former Chief of the Staff, Indian Army.
- (7) Lt. Gen. Kulwant Singh.
- (8) Lt. Gen. D.R. Thapar.
- (9) Dr. H.J. Bhabha, Chairman, Atomic Energy Commission.

**Chief Minister (Shri Ram Kishan) :** Sir, I beg to move —

The Punjab Vidhan Sabha places on record its deep sense of sorrow on the passing away of Shri Nar Hari Vishnu Gadgil, former Governor of Punjab.

Shri Gadgil was a dedicated freedom fighter, an eminent legislator and Parliamentarian and a public leader of fame all through his political career. He served people of Punjab by completely identifying himself with the aspiration of the people. His death has removed from the national scene a great scholar and a senior statesman. The House wishes to convey its heartfelt condolences and sympathies to the bereaved family.

The Punjab Vidhan Sabha places on record its deep sense of sorrow on the passing away of Rao Bahadur Lal Chand, the grand old man of Haryana and a former Agriculture Minister of Punjab. Jathedar Udham Singh Nagoke, the selfless patriot who spent nearly twenty years of his life in prison in the cause of Indian freedom and was later closely associated with this House as a Member from 1946 to 1952, and Shri Mam Chand, also a Member of this House, who rendered outstanding service for the cause of the uplift of Harijans.

This House also mourns the death of Shri Ahmad Mohiuddin, Deputy Minister, Government of India, who was a staunch nationalist, General K. S. Thimayya the distinguished Indian soldier who died in Cyprus in the case of peace, serving under the United Nations; Lt. General Kulwant Singh, who won a place of honour in the annals of Military history on account of his meritorious service in the Kashmir operations in 1947-48; Lt. General D. R. Thapar who played an important role in the building up of armed forces medical services and Doctor Homi Jahangir Bhabha, Chairman, Indian Atomic Energy Commission, who had made notable contribution to nuclear physics and had brought India to the threshold of the Atom era when nuclear energy was to be harnessed for peaceful use. The House expresses its deep sense of sorrow at the passing away of these eminent Indians and conveys its profound sympathies to the bereaved families.

स्पीकर साहिब, पिछली दफा जो विधान सभा का सेशन हुआ था उस के बाद पिछले डेढ़ महीने में दिसम्बर के आखिर में और जनवरी में हमारे बहुत से साथी और भारत सपूत हम से सदा के लिए जुदा हो गए हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता और आप सब जानते हैं कि श्री गाडगिल साहिब, जो हमारे पंजाब के गवर्नर रहे हैं, 12 जनवरी, 1966 को हम से जुदा हो गए हैं। गाडगिल साहिब एक निहायत अच्छे आला पाया के ओरेटर, सियास्तदान, पैट्रियाट और इंडीपेंडेंट थिंकर थे और उन्होंने अपनी काबलियत और खिदमत से देश में नाम पैदा किया है। बतौर एक दलेर पार्लियामेंटेरियन और काबिल स्टेट्समैन के उनका नाम हमेशा जिन्दा रहेगा। उन्होंने अपने वक़्त में जो

[मुख्य मन्त्री]

देश की सेवा की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जब से पब्लिक लाइफ में कदम रखा हिन्दुस्तान की आजादी की हर तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1935 से लेकर 1947 तक वह सेंट्रल असैम्बली के मੈम्बर रहे और फिर 1947 से 1952 तक पार्लियामेंट के मੈम्बर रहे और भारत के मंत्री भी रहे। जब वह सेंट्रल असैम्बली के मੈम्बर थे तो वहां उन्होंने बतौर सैक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के भी निहायत शानदार काम किया। उसके बाद उन्होंने आजाद भारत की कांस्टीचुएंट असैम्बली के मੈम्बर के तौर पर भारत का विधान बनाने में काफी कंट्रीब्यूशन की। वह महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रधान और सैक्रेटरी भी रहे और इन ओहदों पर बड़ी काबलियत से काम किया। वह सेंट्रल पे कमीशन के मੈम्बर भी रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि बतौर स्टेट बैंक आफ इंडिया के वाइस चेयरमैन के उन्होंने हिन्दुस्तान की इकानोमी को उभारने में बड़ा काम किया। 1958 में वह पंजाब के गवर्नर बने और 1962 तक उन्होंने इस ओहदा पर रह कर पंजाब की सेवा की और उन की शानदार खिदमात के लिये उन्हें डाक्टर आफ ला की डिग्री दी गई। इन दिनों वह पूना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था और वह एक माने हुए लिखारी, ओरेटर और स्कालर थे। उन्होंने पंजाब की एक बड़ी सेवा यह भी की कि जपजी साहिब का मराठी में तरजमा किया। उन्हें पुलोटीकल साइंस, कांस्टीट्यूशनल ला, फिक्शन वगैरा पर काफी अबूर हासिल था उन्होंने कई किताबें लिखीं और वह माने हुए आथर थे। उन्हें लोग बड़े प्यार से काका साहिब के नाम से पुकारते थे। उन्होंने जो देश की सेवा मुख्तलिफ शोभों में की है वह हमेशा याद रहेगी और देश हमेशा उनका आभारी रहेगा।

स्पीकर साहिब, राओ साहिब चौधरी लाल चंद हमारे पंजाब के बहुत पुराने पार-लीमेंटेरियन थे और उन्होंने जो इस राज्य की खिदमात की है वह किसी से छुपी हुई नहीं है वह 26 जनवरी, 1966 को हम से जुदा हो गए हैं। राओ साहिब ने पंजाब की और खास तौर पर हरियाणा की जो खिदमात की है उन के लिये उन का नाम हमेशा रौशन रहेगा। वह 1915 में पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसल के, मिंटो मारले स्कीम के तहत मੈम्बर चुने गए थे। उसके बाद वह तीन बार मੈम्बर चुने गए। इसके साथ साथ सर फजल हुसैन के साथ पंजाब के एग्रीकलचर मिनिस्टर भी रहे। सेंट्रल असैम्बली के मੈम्बर के तौर पर भी उन्होंने काफी खिदमात की। वह पब्लिक सर्विस कमिशन के मੈम्बर भी रहे और रोहतक का जाट कालिज उनकी कोशिशों की ज़िन्दा मिसाल है। उन्होंने चौधरी छोटू राम के साथ प्रैक्टिस भी की और इस तरह काफी नाम पैदा किया। वह सैकुलरिज़्म के पक्के हामी थे और युनाइटेड पंजाब में युनियनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखने वालों में से थे। रोहतक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बाग डोर काफी अर्सातक उन के हाथ में रही। पंजाब में मिनिस्टर रहने के बाद वह फिर भरतपुर स्टेट के दीवान रहे। वहां वह बतौर वजीर माल और चेयरमैन स्टेट कौंसल भी रहे। उन्होंने रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का भी बहुत काम किया और वह दिहाती कामों और तरक्की में बड़ी दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने दूसरी जंगे अज़ीम में रिक्रूटिंग का बहुत काम किया जिस की वजह से गवर्नर और सी. इन. सी. उन की

दम से तक बर । त र न के । व श्री । र ग ग । ग । न । 5

हर बात मानते थे और उनकी कदर करते थे। उन के दिल में दिहाती जनता के लिये बड़ा दर्द था और आखरी वक्त तक वह दिहात की भलाई की बात सोचते रहे। वह फौजी जवानों की बहबूदी का भी बहुत ख्याल रखते थे। वह मशहूरोंमारेफ इन्कलाबी नेता लाला हरदयाल एम० ए० के क्लासफेलो थे। उन्होंने पंजाब की जो खिदमात की हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल के मैम्बर के तौर पर जो पार्ट उन्होंने प्ले किया वह आप सब जानते हैं। हमें उन के चले जाने से अफसोस है।

हमारे एक और साथी जो हमारी आजादी की जंग के जरनैल थे, सरदार ऊधम सिंह जी नागोके, वह भी 11 जनवरी को हमसे जुदा हो गए हैं। उन्होंने देश की आजादी के लिए भारी कुरबानियां दीं। वह 29 दफा जेल में गए और अपनी उमर का 20 साल का अरसा उन्होंने जेल में गुजारा। उन्होंने सारी उमर सल्फलैस सर्विस की और उन्होंने देश आजाद कराने में जो तकलीफें उठाई और जो खिदमात कीं उन्हें सारा मुल्क जानता है। उन को इन्टीगरिटी और सिन्सैरिटी मुसल्लमा थी। उन्होंने किसान मोर्चा और गुरुद्वारा मूवमेंट में जिस तरह हिस्सा लिया वह पंजाब की तारीख का एक सुनहरी पन्ना है। वह 15/20 साल तक नागोके ग्रुप के तौर पर पंजाब पालेटिक्स पर छाए रहे। वह सबसे पहले नान-कोप्रेशन मूवमेंट के वक्त कांग्रेस में शामिल हुए और उस के बाद देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते रहे।

जय्येदार ऊधम सिंह नागोके ने तीन बड़े मोर्चों में हिस्सा लिया। पहला मोर्चा गोल्डन मंदिर, अमृतसर की चाबियों की रैस्टोरेशन के बारे में था। उन्होंने यह मोर्चा 1922 में लगाया था। उस के बाद उन्होंने 1923-24 में जैतो (नाभा) में मोर्चे में हिस्सा लिया। उस मोर्चे में स्वर्गीय प्रधानमंत्री रंडित जवाहर लाल नेहरू ने भाग लिया था। इस मोर्चे में स्वर्गीय ऊधम सिंह नागोके ने हिस्सा लिया और अपना नाम पैदा किया। उन्होंने गुरु के बाग अमृतसर के आन्दोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने इन मोर्चों में नुमायां पार्ट प्ले किया।

वह 1926 से 1952 तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के मैम्बर रहे। उन्होंने अकाली दल के प्रधान के रूप में 8 वर्ष तक काम किया। उन्होंने इस दल में काफी सेवा की।

उन के दिल में किसानों के लिये दर्द था। उन के हकूकों की रक्षा करने के लिये मोर्चे लगाए और सरकार के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिविल डिस-ओबीडीएंस मूवमेंट में सक्रिय पार्ट प्ले किया। उन्होंने 1932 में किसान मूवमेंट चलाई। उन्होंने 1938 में भी बड़ा किसान मोर्चा आर्गेनाइज किया और दफा 144 का उलंघन किया। उन्होंने पंजाब के अन्दर "क्विट इंडिया" मूवमेंट में हिस्सा लिया और नुमायां पार्ट प्ले किया।

स्पोकर साहिब, वह कांग्रेस को छोड़ कर स्वतन्त्रता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उस पार्टी में शामिल होने के बाद जहां तक उन की देश के प्रति हुब्वल वतनी का सम्बन्ध है, उन की कुरबानी का सम्बन्ध है, सफरिगज का सम्बन्ध है, और देश के हित में जो जो भी कदम उठाए, वह सब चीजें किसी भी देश वासी से भूली हुई नहीं हैं। वह निडर व्यक्ति थे। वह बहादुर व्यक्ति थे और दृढ़ निश्चय वाले थे। उन्होंने देश को ऊपर ले जाने

[मुख्य मन्त्री]

के लिये बहुत ही काम किया। उन्होंने पंजाब असैम्बली में 1946 से ले कर 1952 तक इस मुद्दे की खिदमत की और 1953 से 1960 तक राज्य सभा के मੈम्बर रहे और वहाँ पर देश के लिए काफी सेवा की। उन के निधन से देश को हानि हुई। उन के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजली पेश करता हूँ।

स्पीकर साहिब, चौधरी माम चन्द रोहतक के रहने वाले थे। वह कई सालों तक जिला कांग्रेस कमेटी रोहतक के मੈम्बर रहे। वह विधान सभा के मੈम्बर रहे। उन के दिल में हरिजनों के लिए और गरीब जनता के लिए बहुत दर्द था। वह यहाँ पर उन लोगों की तकलीफों को बताया करते थे और उन की हालत को सुधारने के लिये प्रयत्न किया करते थे। उन के निधन होने पर हमें बहुत अफसोस है।

स्पीकर साहिब, श्री अहमद मोहियुद्दीन, डिप्टी मिनिस्टर ट्रांस्पोर्ट, गवर्नमेंट आफ इंडिया भी हमारे से जुदा हो गए। वह बड़े नैशनलिस्ट विचारधारा वाले थे। वह हिन्दू मुस्लिम यूनियन में यकीन रखते थे। वह सोशल वर्कर थे। उन का निधन होने से हमें बहुत अफसोस हुआ है।

स्पीकर साहिब, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमारे बड़े से बड़े और बेहतरीन से बेहतरीन आदमी देश को अनाथ कर के चले गए। इन महान व्यक्तियों की इस देश को बहुत ही जरूरत थी। इस रैजोल्यूशन में जनरल के. एस. थमैया का जिक्र किया गया है। वह 18 दिसम्बर, 1965 को इस दुनिया से चले गए। उन के चले जाने से सारा देश और सारी दुनिया उन की सेवाओं से महरूम हो गये हैं। वह बहादुर जनरल थे। उन की मृत्यु उन के निवास स्थान निकोसिया में हुई। वह वहाँ पर यूनाइटेड नेशन्स पीस फोर्स को कमांड कर रहे थे। उस कमांड में 6,000 फौजी काम करते थे। इस कमांड में ब्रिटेन, आयरलैंड, कैनैडा, स्वीडन और डेनमार्क के व्यक्ति काम करते थे और वह उस फोर्स के कमांडर लगे हुए थे।

वह 59 वर्ष के थे। उन्होंने मिलिटरी सर्विस में अहम पार्ट प्ले किया था। वह मिलिटरी और आफिशियल सर्कल में जनरल टिम्पो के नाम से मशहूर थे। उन्होंने भारत के अन्दर और बाहिर जो सेवाएं कीं, वह किसी से छुपी हुई नहीं हैं। उन्होंने 1948 में सबसे बड़ा कारनुमायां काम किया जोकि दुनिया की अखबारों ने हैड लाइन्ज में छापा था। उस वक्त उन्होंने न होने वाली बात को होने वाली बात में करके दिखा दिया था। यह बहुत ही कठिन काम था। कश्मीर में जो जी ला पास है जिस की ऊंचाई 12,000 फुट है और वहाँ पर टैंक पहुंचाना बहुत ही कठिन बात थी और इस बहादुर सेनानी ने अपने दिमाग और भरसक प्रयत्नों से वहाँ पर टैंक पहुंचाए। यह काम उन्होंने 1948 में किया जब पाकिस्तान ने काश्मीर पर जारहाना हमला किया था। जो कुछ उसने किया वह बहुत ही हैरानी वाली बात थी और उसने उस वक्त भारतीय फौज की राहनुमाई की और देश की रक्षा के लिये जो जो कदम उठाए, वह हर एक को भली भांति याद हैं।

स्पीकर साहिब, उन्होंने यूनाइटेड नेशन्स की मुख्तलफ रूप में जिस तरह से सदा की, उस को सभी जानते हैं। 1953 में चीन ने नार्थ कोरिया की मदद की। इस तरह से

नार्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका और दूसरे एलाइड कंट्रीज थे। वहां पर उन्होंने यू. एन. फ्लैग अधीन जो काम किया और जो वहां पर ख्याति प्राप्त की, उस से उन की शान नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने देश की शान को भी चार चांद लगाए। मैं इस समय उन शिक्षा के बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता लेकिन उन्होंने फौज में मुख्तियार रैंक पर जो जो काम किया, उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। अपने शुरू के कैरियर में उन की पोस्टिंग फोर्ट सैंडेमान में हुई। यह नार्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविन्स में टिफी पोस्ट थी। वहां पर उन्होंने मुख्तियार पोस्टों पर काम किया। उन्होंने वहां पर वैल्यूएबल तजर्बा हासल किया। उसके बाद उन्होंने फ्रंटियर में उनीसवीं हैदराबाद रेजमेंट काम किया। उन्होंने इराक में भी अहम काम किया। उन के कामों से हर एक वाकिफ उन को पाँववीं बटालियन यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर हमेशा याद किया करेगी। वहां पर उन्हें एडजुटेंट के तौर पर 4 साल काम किया। वह सैल्फ रिस्पेक्टिड और हाई इंटेलिजेंस के थे।

वह 1936 में 4/9 हैदराबाद रेजमेंट में वापस चले गए। उसके बाद मलाया चले गए। वह 1944 में अरकान में नियुक्त हुए और वहां पर उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। उन्होंने सैकंड वर्ल्ड वार में अहम पार्ट प्ले किया और उन्होंने, अपने आप को बहादुर कमान साबित किया। यह भारतीय इतिहास में पहली बात थी जब भारतीय अफसर को इंग्लिश ब्रिगेड की कमान दी गई और जिसने लड़ाई में हिस्सा लिया। वह बहुत काबल जनरल थे। उन्होंने अपनी काबलीयत के कारण ही साउथ ईस्ट एशिया कमांड में लार्ड लुइस माउन्टबैटन, जनरल स्टिलवेल और फील्ड मार्शल के साथ काम किया।

स्पीकर साहिब, जनरल थमैय्या 1957 में चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए। वह इस पद पर चार साल तक रहे। उन्होंने इस पोस्ट पर बड़ी खुशअसलूबी से काम किया। उन्होंने इस असें में भारतीय फौज की जिस तरह से रहनुमाई की और सेवा की वह किसी से छुपी हुई नहीं है। वह इस असें में अपनी काबलीयत से और दलेरी की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मुख्तियार जगहों पर मुख्तियार रैंक में सेवा की। इस तरह अपना नाम ही ऊंचा नहीं किया बल्कि देश के नाम को ऊंचा करने में भरसक प्रयत्न किया।

स्पीकर साहिब, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की, जनरल थमैय्या ने 1948 में सर्दिय मौसम में दर्रा जोजीला सम्भाले रखा और लड़ाई में पाकिस्तानी रेडर्ज के दांत खट्टे किए। उस वक्त वह कश्मीर आप्रेशन के इंचार्ज थे। उसके पश्चात् 1953 में फिर ख्याति प्राप्त की। उन्होंने कोरिया के झगड़े को बड़ी संजीदगी से और दूरदर्शिता से तथा दलेरी से हल किया। वह फाइव नेशन न्यूट्रल नेशन्स रीपैटरीएशन कमीशन के चेयरमैन रहे। उन्होंने वहां पर नुमायां पार्ट प्ले किया और उन की सेवा को समझते हुए देखते हुए पदम विभूषण दिया गया।

स्पीकर साहिब, लेफ्टीनेंट जनरल कुलवन्त सिंह देश के बहादुर जनरल थे और उन देश की भरसक सेवा की। वह हमारे से 2 जनवरी, 1966 को जुदा हो गए। उन्हें

मुख्य मन्त्री]

श की और पंजाब की जो सेवा की, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। वह ऐसे मौके पर हमसे जुदा हुए, जब कि उन की मैजिस्टर सलाह की बहुत जरूरत थी। यह कहना कोई व्यक्ति न होगी कि उन के निधन से हमारी स्टेट को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने चीन के हमले के समय और इंडो-पाक कंफ्लिक्ट के समय बहुत ही कीमती सलाहें और सलाह दिए। उन के निधन से पंजाब सरकार और गवर्नमेंट आफ इंडिया उन कीमती तथा योग्य सुझावों से वंचित हो गई है और अपने आप को अनाथ समझती है।

जनरल कुलवन्त सिंह 1959 में रिटायर हुए। उन्होंने 34 वर्ष सर्विस की। देश विभाजन के समय वह आर्मी हैड क्वार्टर में चीफ आफ दी जनरल स्टाफ लगे हुए थे और बाद में जम्मू और कश्मीर में फौज की कमान की। उन्होंने वहां पर देश की भरसक सेवा की। उन्होंने दुश्मन का मुकाबला बड़ी दलेरी से किया और देश की इज्जत को उंचा किया। उन्हें कश्मीर की पहाड़ियों का बहुत ज्ञान था और यह बात उन की उंगलियों पर थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया और उन के दांत खट्टे किए। वह रिटायर होने के बाद भी हर चीज का हिम्मत के साथ मुकाबला करने की सलाह देता करता था। उन्होंने 1938-41 के दरमियान कैप्टन के तौर पर काम किया। उस के बाद ब्रिगेड-मेजर, और थल विप्रेडियर बने। 1941 में वह स्टाफ कालिज, कोयटा में इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए गए और वहां पर दो साल तक काम किया। उन्होंने बाद में असिस्टेंट मास्टर-जनरल (प्लैन्ज) इंडियन ऐक्सपीडीशनरी फोर्स के पद पर काम किया। ऐसा कि पहले मैंने अर्ज की वह बहादुर जनरल थे और हमेशा नेक मशिवरा दिया करते थे। हम उन की नेक सलाहों के कारण उन्हें हमेशा याद किया करेंगे। वह हमेशा साहसी और साहस से काम करते थे। उन्होंने फौज में मुखलिफ रैंक्स पर काम किया। उन्होंने 1943-45 में सातवीं बटालियन जो कि पंजाब की पहली रेजिमेंट थी, की कमान संभाली। वह बर्मा में 114 ब्रिगेड के सैकंड इंचार्ज थे और बाद में बैकाल ब्रिगेड की कमान संभाली। उन्होंने आर्मी हैडक्वार्टर में डिप्टी डायरेक्टर आफ रीसेटलमेंट की पोस्ट पर भी काम किया।

जून 1947 में वह ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ, नार्दन कमांड मुकर्रर हुए तो वे पहल हिन्दोस्तानी थे जो कि इस पोस्ट पर लगे। जब हिन्दोस्तानी आजाद हुए तो जनरल कुलवन्त सिंह डायरेक्टर आफ मिलिटरी ट्रेनिंग, आरमी हैडक्वार्टर्स मुकर्रर हुए। अक्टूबर 1947 में जनरल प्रमोट हुए और उन्होंने काश्मीर ओपरेशन की कमांड संभाली। मई 1948 में वे चीफ आफ दी जनरल स्टाफ अप्वायंट हुए और जो काम उन्होंने इस ओहदे पर किया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम उन को भी खराजेतहसीन पेश करते हैं।

स्पीकर साहिब, मैंने रेजोल्यूशन में जनरल थापर साहिब का भी जिक्र किया था। उन्होंने हिन्दोस्तान की आरमी में मुद्दत तक काम किया। वे 15 दिसम्बर, 1965 को 71 साल की आयु में हमसे जुदा हो गए। छोटी सी उम्र में ही वे इंग्लैंड चले गए थे और वहां पर उन्होंने तालीम हासिल की। वहीं से उन्होंने इंडियन मैडिकल सर्विस ज्वाइन किया और बड़े लम्बे अर्से तक नार्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सर्व किया। आरमी के अंदर उन्होंने कई पोस्ट संभालीं। 1950 में वे आरमी फोरसिज मैडिकल सर्विसिज के डायरेक्टर

जनरल अप्पायंट हुए और 1954 में वे रिटायर हुए। आरमी मैडिकल कोर जनरल के 1943 से 1950 तक फाउंडर एडिटर रहे। उसके बाद उन्होंने चेंबरमैन आफ दी मैडिकल हिस्टरी एडवाइजरी कमेटी आफ दी डीफेंस मिनिस्ट्री के तौर पर काम किया जिस वल्ड वार सैकंड की इंडियन आरमी फोरसिज की हिस्टरी 6 वॉल्यूम्स में शायी की उन्होंने यूरोप, एशिया और अमरीका में वाईडली ट्रेवल किया और एनशेंट इंडियन स्कलप्ट और पेंटिंग में बड़ी दिलचस्पी ली। उन की बहुत सी खिदमात हैं जो कि किसी से छि हुई नहीं हैं। हमें उन के जुदा होने का भी भारी दुख हुआ है।

स्पीकर साहिब, एक महान व्यक्ति डाक्टर एच. जे. भाभा की जिन्होंने हिन्दोस्तान एटामिक एज के मैप पर लाकर खड़ा कर दिया उस हवाई हादसे में जो कि 24 जनव को हुआ ट्रेजिक डैथ हो जाने से सारे हिन्दोस्तान को बहुत शोक हुआ है। उन की मृत्यु का समाचार सुन कर सारे देश में गम और दुख की लहर दौड़ गई। एक बड़ा जबरदस्त साइंटिस्ट जालिम मौत ने हम से छीन लिया और हमारा ऐसा नुकसान किया है जो कि पुनर् नहीं हो सकता। जब आप उन के सब कामों को देखें जो कि अधूरे रह गए हैं तो पता चले कि किस किस फील्ड में उन्होंने काम किया है।

उन्होंने बतौर सेक्रेटरी आफ दी गवर्नमेंट आफ इंडिया, डीपार्टमेंट आफ अटॉमिक इनर्जी और बतौर चेंबरमैन आफ दी इंडियन अटॉमिक इनर्जी कमिशन के काम किया जो काम उन्होंने हिन्दोस्तान के अटॉमिक इनर्जी प्रोग्राम के आर्कीटेक्ट के तौर पर किया हमारा देश उस के लिये कृतज्ञ है। आज हमारे देश को उन की खिदमात की सब ज्यादा जरूरत थी लेकिन बड़े दुख की बात है कि वे हम से जुदा हो गए। डाक्टर भाबु बम्बई में पैदा हुए थे। उन्होंने बम्बई और इंग्लैंड में तालीम हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन्होंने राउज बाल ट्रेवलिंग स्टूडेंटशिप इन मैथेमैटिक्स 1932 से 1934 हासिल किया। उन्होंने रोम के अन्दर बड़ा अच्छा काम किया और वैज्ञानिक क्षेत्र का नाम पैदा किया। जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1942 से 1948 होपकिन्स प्राइज आफ दी कैम्ब्रिज फिलोसोफिकल सोसायटी प्राप्त किया। 1951 से 1954 तक वे इंडियन साइंस कांग्रेस के इलैक्टड प्रेजीडेंट रहे और देश की साइंस के क्षेत्र का राहुनुमाई की। उन की खिदमात के सिले में हिन्दोस्तान के प्रेजीडेंट ने उन्हें पद्मविभूषण प्रदान किया। 1957 में वे आनरेरी फेलो आफ गानविले एंड केयस कालिज कैम्ब्रिज के आनरेरी फेलो आफ दी रायल सोसायटी आफ एडम्बरा रहे। उन्होंने न सिर्फ हिन्दोस्तान ही बल्कि सारी दुनिया की साइंस के क्षेत्र में खिदमात की। 1959 में वे आनरेरी फेलो आफ दी अमरीकन एकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइंस एलैक्ट हुए थे।

स्पीकर साहिब, इस के अलावा वे 1962 में फेलो मैम्बर आफ दी वल्ड एकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइंस चुने गए थे। 1963 में वे फारिन एसोशिएट आफ दी यूनाइटेड स्टेट्स नैशनल एकेडमी आफ साइंसिज और आनरेरी मैम्बर आफ दी न्यू यार्क एकेडमी आफ साइंसिज इलैक्ट हुए। 1964 में वे फारिन कारेसपांडिंग एकेडमीशन आफ दी अमरीकन एकेडमी आफ साइंस आफ मैडरिड के तौर पर चुने गए।

स्पीकर साहिब, इस से पता चलता है कि सारी दुनिया के अंदर उन्होंने कितना पैदा किया। आज उन के जुदा होने से हमारे देश को बड़ा धक्का लगा है। पीर

[स्वयं मन्त्री]

पॉइंट आफ व्यू से और वर्ल्ड की डिवैलपमेंट में जो काम उन्होंने किया है वह किसी से पा हुआ नहीं है। हिन्दोस्तान में अटॉमिक इनर्जी को डिवैलप करने के लिये उन्होंने जो रमी दिखाई वह काबले दाद है। हमारे बेहतरीन साथी जिन्होंने हमारे देश की साइंस क्षेत्र में और डीफेंस के प्वायंट आफ व्यू से और कंस्ट्रक्शन के प्वायंट आफ व्यू से अनुमाई की उन के आज जुदा होने से हमारे देश को महान दुख हुआ है।

आज जब हम उन के लिये शोक प्रकट कर रहे हैं हम आशा रखते हैं कि जो काम उन प्रधूरे रह गए हैं, परमात्मा हममें शक्ति देगा कि हम उन को पूरा कर सकें। इन अल्फाज साथ हम उन को खराजे तहसीन अदा करते हैं।

**Sardar Gurnam Singh (Raikot) :** Mr. Speaker, Sir, we have met to mourn the loss to this country of several eminent public men. In it, it seems as if we are almost meeting under the shadow of death.

Sir, Shri N. V. Gadgil provided the State with a wide awake and a new Governor and now that he is no more with us we feel all the more only his loss to the country as an experienced public man.

Jathedar, Sardar Uddham Singh Nagoke was not only a veteran freedom fighter but also a leader of political vision who clearly perceived the intricate relationship between a just solution of the sikh problem and the problem of national integrity and progress. In him the country has lost not only a liberal Swatantra leader but also a sincere friend of the down-trodden man. He was a man of strong convictions. He did not hesitate to quit Congress Party which he had devotedly served for quite a long time when he could not be persuaded to agree with its policies.

Sir, we are also mourning the loss of Rao Bahadur Chaudhri Lal Chand who belonged to a distinguished jat family of Rohtak District. He served the people of Punjab in various capacities with distinction, as a legislator, a public man, as a Minister and as a member of the Public Service Commission. His death at this critical juncture of our political life is a great loss to the people of the State. To many of us, in fact, the loss is also personal.

General Thimaya, former Chief of the Indian Army Staff was a soldier of great attainments. He served under U.N.O. on various assignments and showed considerable professional skill. He loved his men and his men, in return, loved and respected him. India is left poorer by his death.

Lt. General Kulwant Singh was a soldier of international renown for his improved tactical abilities. The fact that while he lived his talents did not receive due recognition, is only matched by the dark tragedy that overtook his family after his death in the shape of the tragic fate of his only son in the recent Air India jetliner 'Kanchenjunga' disaster. Our hearts go out to the bereaved family left behind to mourn the loss.

Lt. General D. R. Thapar of the Indian Army Medical Corps was a very competent and kind-hearted soldier Doctor. He achieved the highest distinction in his profession in the Army Medical Corps.

Dr. Bhaba, Chairman, Atomic Energy Commission was a scientist of world renown. Sir, he had received the highest distinction in the field of science. During my last visit to Bombay in connection with the Administrative Reforms Commission I was lucky to have an opportunity to visit his Organisation. I must say without any fear of contradiction that he made a marvellous job of it. In his death, Sir, India has lost a priceless asset whose loss it is difficult to replace.

We have also suffered a great loss in the death of two other public men ; namely, Shri Ahmed Mohiuddin, Deputy Transport Minister, Government of India and Shri Mam Chand, ex-M.L.A.

Sir, on behalf of the Opposition and on my own behalf I join the Leader of the House in the expression of regret and in conveying the condolences to the bereaved families of these illustrious men.

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) :** ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਵੀ. ਗਾਡਗਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਵੀ. ਗਾਡਗਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਆਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਪੀਪਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਰਤੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਡਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਸੰਨ 1933-34 ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਰਤੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਵੀ. ਗਾਡਗਿਲ ਹੀ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਰਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚਾ ਉਚਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਰਾਏ ਰਖਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਸੰਨ 1947-48 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਾੜਵਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਨੇਤਾ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

**Mr. Speaker :** I also associate myself with the sentiments expressed here by the Leader of the House and other hon. Members for the various eminent personalities we have lost. In fact the cruel fate staged a

[Mr. Speaker]

human tragedy during the last month. Shri Gadgil who had been Governor of Punjab for a number of years was a public spirited man of eminence with a high sense of integrity. His was a voice of revolt against any act of injustice anywhere in the country. Even as a Governor he had been an active politician. Throughout his life he had made great contribution in the public cause.

Jathedar Udham Singh Nagoke had been a great freedom fighter and a public man of eminence. He has left his mark in the public life.

The three military Generals we have lost had been great personalities in their respective fields and our Province especially has been left poorer by the tragic death of Lt. General Kulwant Singh's son. On the day when the country received the holy relics of Guru Gobind Singh, the 1st January, 1966, I met Lt. General Kulwant Singh at the Palam Airport. He seemed to be quite hale and hearty and the next morning we heard the news that he had collapsed. In every situation when we were faced with the enemy his advice was sought and he was a source of inspiration and strength in any military situation.

Dr. Bhabha ushered in a new era in the nuclear energy. He was a scientist of great eminence and also a very shrewd and a great administrator. We had the great rare combination in him of a scientist and an administrator.

Similarly, Rao Bahadur Chaudhri Lal Chand has also left his mark in the public service.

Shri Ahmed Mohiuddin was also a great dedicated soul and was an embodiment of Hindu Muslim unity.

Shri Mam Chand also led a dedicated public life.

In all these eminent personalities we have lost a great asset. Their services to the nation and to the Province will be remembered for a long time to come. Now we shall pass this Resolution by standing and observing silence for two minutes.

*The House then stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased).*

**Mr. Speaker :** If the House agrees copies of this Resolution may be sent to the members of the bereaved families.

**Voices :** Yes.

**Chief Minister (Shri Ram Kishan) :** Mr. Speaker, Sir, I beg to move :—

That the House be adjourned as a mark of respect to the memory of the late Shri Lal Bahadur Shastri, Prime Minister of India.

**Mr. Speaker :** The House stands adjourned as a mark of respect to the memory of the departed leader Shri Lal Bahadur Shastri.

53 a.m. *(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 16th February 1966).*

or  
ce  
of  
n  
n

d

s  
y  
e  
,

;

© (1965)

Published under the authority of the Punjab Vidhan Parishad and printed  
by the Controller, Printing and Stationery, Punjab, Chandigarh.

# PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES

*16th February, 1966*

**Vol. I—No. 2**

## OFFICIAL REPORT



### CONTENTS

	<i>Page</i>
<b>Wednesday, the 16th February, 1966</b>	
Starred Questions and Answers	... (2) 1
Written answers to starred questions laid on the Table of the House under rule 45	.. (2) 53
Unstarred Questions and Answers	.. (2) 63
Question of Privilege	(2) 169
Adjournment Motions/Call Attention Notices	(2) 169
Walk-out	.. (2) 183
Governor's Address (Copy laid on the Table of the House)	.. (2) 183
Announcements by the Speaker	.. (2) 203
Panel of Chairmen	.. (2) 204
Announcement by the Secretary	.. (2) 204
Leave of absence	.. (2) 205
Papers Laid on the Table	.. (2) 205
Legislative Business (Presentation of Reports)	.. (2) 205
Reference of Punjab Cattle Preservation Bill, 1964, to the Regional Committees	.. (2) 206
Discussion on Governor's Address	(2) 206—239
Appendix	i—xxiv

**Price: Rs. 13.55 Paise.**



# ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES Vol. I—No. 2, DATED  
THE 16TH FEBRUARY, 1966

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>page</i>	<i>Line</i>
Jullundur	ullundur	(2)3	8
visited	visitedd	(2)12	17
Ferozepur Cantt	Feroz Cantt	(2)16	last
Hoshiarpur	Hoshirapur	(2)19	5
Chief Minister	Cheif Minister	(2)24	1
places visited	laces vis	(2)26	1
मिलिटरी	मिलेटरी	(2)33	18
एबडकट	अबडकट	(2)34	21
पोस्टपोन	पोस्टयोन	(2)52	17 from below
Justice	Justice	(2)134	1
Transport and	Transpor tand	(2)139	6 from below
School	Scho 1	(2)147	Sr. No. 1, Col. 4
for	or	(2)154	16 from below
3120	*3120	(2)156	24
3121	*3121	(2)157	16
Sardar Trilochan Singh Riasti	Sardar Trilocahan Singh Riasti	(2)157	16
applications	appliations	(2)157	6 from below
meeting	meetjng	(2)169	13
ਗਕਰੰਸੋਟ ਨੇ	ਗਕਰੰਸੋਟ	(2)169	12 from below
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ	ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ	(2)172	15

P. T. O.

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
Addressing	Add-essing	(2)175	11-12 from below
ਕਾਮਰੇਡ	ਕਾਮਰੇਡ	(2)176	1
ਆਡਰ	ਆਡਰ	(2)178	4
ਅਧਿਕ	ਅਧਿਕ	(2)179	3 from below
ਸਕੇਟਰੀ	ਸਕੇਟਰੀ	(2)180	14
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ	ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਨਾਥ	(2)181	6 from below
ਸੇਰਾ	ਸੇਰਾ	(2)181	6 from below
Teacher's	Teachr's	(2)211	16
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ	ਇਤ ਸਰ੍ਹਾਂ	(2)218	18
ਪਾਲਦੀ	ਪਾਲਦੀ	(2)234	last
brought	rought	(2)237	17 from below
ਬੰਦ	ਬੰਦ	(2)238	3
He should	Hes hould	(2)238	14
but continue	bu tcontinue	(2)239	3
adjourned	adjonrned	(2)239	last but one
Debate	Debates	(i)	last
of	{ or	{ (iii)	{ 1
	{ o	{ v	{ 12
Legislators	Legisators	(iii)	2

below

# PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 16th February, 1966

low

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhavan Sector 1, Chandigarh. at 9—30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

OW

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

OW

### Tours of Ministers, etc.

\*3825. Comrade Ram Chandra : Will the Chief Minister be pleased to state—

OW

(a) the total number of days for which each Minister, Minister of State and Deputy Minister remained on tour during the period from 1st April, 1965 to date ;

(b) the number of days spent by each on tour district-wise and month-wise, together with the names of places visited, district-wise, during the said period ;

(c) the number of days spent by each in Delhi, Rohtak and Gurgaon with night stay at Delhi during the said period ?

Shri Ram Kishan : (a) and (c) A statement is laid on the table of the House as Annexure I.

(b) A statement is laid on the table of the House as Annexure II.

### ANNEXURE I

(a) & (c)

Serial No.	Name of Minister	Total No. of days of tour during April, 1965 to December 1965	No. of days spent		
			In Delhi with night stay at Delhi	In Gurgaon with night stay at Delhi	In Rohtak with night stay at Delhi
1	2	3	4	5	6
1	Comrade Ram Kishan, Chief Minister	140	35	9	4
2	Shri Darbara Singh, Home and Development Minister	114½	49½	2	..
3	Shri Prabodh Chandra, Education Minister	79½	18	1	3

[ Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
4	Shri Kapoor Singh, Finance Minister	98	24	1	2
5	Shri Gurdial Singh Dhillon, Transport and Election Minister ..	62	12	..	..
6	Ch. Ranbir Singh, Public Works Minister ..	104½	15	..	..
7	Shri Ajmer Singh, Planning and Local Government Minister ..	91½	11	1	1
8	Shri Harinder Singh, Revenue Minister	Details not received from the Minister. He does not draw any Travelling Allowance for the journeys on tours performed by him			
9	Shri Rizak Ram, Irrigation and Power Minister	89½	20	..	..
10	Shri Prem Singh Prem, Capital and Housing Minister ..	63½	12	..	..
11	Shri Chand Ram, Welfare and Justice Minister ..	86	8	2	3
12	Shmt. Om Prabha Jain, Health Minister	90¾	29	3	6
13	Ch. Sunder Singh, MEPL ..	94½	15	6	..
14	Capt. Rattan Singh MAHA ..	114½	9½	..	..
15	Shmt. Chandra Vati, Deputy Minister, Food and Supply ..	90	21	1	1
16	Shri Gurmit Singh DMDI ..	87	1	..	..
17	Shri Gian Chand DMIH ..	81	10	..	..

## ANNEXURE II

Name of the District	No. of days spent on tour in							Names of places visited during 1st April, 1965 to 31st December, 1965	
	April, 1965	May, 1965	June, 1965	July, 1965	August, 1965	September 1965	October 1965		
								Novem-ber, 1965	Decem-ber, 1965

April, 1965 to 31st December, 1965

April, 1965    May, 1965    June, 1965    July, 1965    August, 1965    September, 1965    October, 1965    November, 1965    December, 1965

*Sardar Darbara Singh, Home and Development Minister*

Jullundur	..	2½	2	1	½	1	2	1	1	1	1	1	1	1	Goraya, Jullundur, Phillaur, Pasala, Baba Bakala, Adampur, Nakodar, Apra, Ajnala, Roorika Kalan
Hoshiarpur	..	½	6½	1	..	..	..	..	½	..	..	..	2	2	Nangal, Hoshiarpur, Chabewal, Rattewal, Nari, Dera Baba Rudrandudji Amar Jogi, Garhshankar, Takhtgarh, Barsar, Nadaun
Bhatinda	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Faridkot, Uchana
Gurdaspur	..	1	..	..	½	..	½	½	..	..	..	..	..	..	Pathankot, Mangewal, Dera Baba Nanak Batala
Ludhiana	..	½	½	1	..	1	1	1	..	1	1	1	..	..	Chakkar, Ludhiana, Dehlon, Pakhewal, Sudhar, Jagraon, Adampur, Hussainiwala, Rajowana
Kangra	..	½	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Kangra
Amritsar	..	1	1½	½	1	½	4	½	1½	1½	1½	1½	½	½	Amritsar, Basarke, Khadoor Sahib, Chheharta, Patti, Rajoke, Bhikhiwind, Sursing, Attari, Chola Sahib, Tarn Taran, Ajnala, Jandiala
Sangrur	..	..	..	½	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	Uchana Mandi, Sangrur
Mahendragarh	..	½	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Narnaul, Daderi, Satnauli
Patiala	..	1	½	1	..	½	½	½	..	1	1	1	..	..	Patiala, Pinjore, Amloh

Kapurthala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Kapurthala, Damdama Sahab, Sultanpur Lodhi, Phagwara
Ferozepore	..	..	2	1	1	2½	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ferozepore, Abohar, Fazilka, Moga, Malout, Abohar, Sulemanke
Gurgaon	..	..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Faridabad, Badarpur
Karnal	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	Pehowa, Pai, Nilokheri, Rajaund, Karnal Kaithal, Jagadhri
Ambala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	Ambala City
Hissar	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Sirsa, Mandi Adampur
Rohtak	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	Rohtak
<i>Shri Prabodh Chandra, Education Minister</i>																
Gurgaon	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Palwal
Ambala	..	1½	1	1	5½	1½	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bichari, Ambala Cantt., Kalka, Ambala City
Jullundur	..	1½	1½	1½	..	1½	..	2	1½	..	..	..	..	..	..	Jullundur City, Phillaur
Gurdaspur	..	3	..	4	6½	3½	9½	3	..	..	..	..	..	..	..	Gurdaspur, Gurdiala Guru, Batala, Dera Baba Nanak, Qadian, Pathankot, Fatehgarh Churian, Dina Nagar, Dalhousie, Sathiala, Chakki, Madhopur Mukerian, Sirhind, Patiala, Nabha
Patiala	..	..	1	1	..	1½	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
Hoshiarpur	..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	Hoshiarpur, Nandpur, Pong Dam, Nangal
Kangra	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Dharamsala, Noorpur
Simla	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	Simla

Names of places visited during  
April, 1965 to 31st December, 1965

Name of District April, 1965 May, 1965 June, 1965 July, 1965 August, 1965 September, 1965 October, 1965 November, 1965 December, 1965

Amritsar	..	1	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	..	3	..	1	..	Amritsar Kawan, Chherta
Kapurthala	..	..	..	1	$1\frac{1}{2}$	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	Phagwara, Kapurthala
Ludhiana	..	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	..	..	..	..	1	$\frac{1}{2}$	..	Rasulpur, Ludhiana, Jartauli, Sudhar
Sangrur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Sangrur, Ahemad Garh
Rohtak	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	..	..	Chulkana, Rohtak, Uralana
Karnal	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	Nillan Kheri, Karnal
Bhatinda	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	..	..	..	..	..	Rampura Phul, Bhiwani, Jhumer
Hissar	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	Sirsa, Hissar, Hansi
Ferozepore	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	Ferozepur
Shri Kapoor Singh. Finance Minister											
Patiala	..	1	$\frac{1}{2}$	..	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	..	Patiala, Doraha, Dhamot, Payal, Kadon
Jullundur	..	..	$5\frac{1}{2}$	..	..	..	..	..	..	..	Jullundur
Ambala	..	1	..	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	..	Ambala Cantt., Kurali, Yamuna Nagar, Pinjore, Bahadurgarh, Kharkheda
Hissar	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	..	..	..	..	..	Dabwali
Ferozepore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Ferozepore, Hussaniwala

Note.—The information regarding Education Minister is up to November, 1965

Hoshiarpur	..	1	..	..	..	1	..	Tanda Urmur, Bhakra Nangal
Gurdaspur	..	1	..	..	..	..	..	Gohkal Daliwal
Gurgaon	..	..	..	..	..	..	..	Faridabad
Amritsar	..	1	..	1	..	1	..	Amritsar, Waga, Chheharta
Karnal	..	..	..	..	..	..	..	Nilokheri
Kapurthala	..	1	..	..	..	..	..	Kapurthala
Simla	..	..	14	2 1/2	..	..	..	Tara Devi, Simla, Sabathu, Kasauli, Dagshai, Kandaghat, Chail,
Sangrur	..	..	..	..	..	..	..	Malerkotla, Ahmedgarh
Ludhiana	..	3	3 1/2	2	1 1/2	3	8 1/2	7 1/2
								Ludhiana, Phillaur, Khanna, Samrala, Shamashpur, Sidhwan Khurd, Dehru Halwara, Jagraon, Pakhowal, Kailey, Lita and Saraba, Burj Lita, Noorpur and Sudher, Dholon, Chachrari Hans, Sujapur, Baraich, Kolar, Pabian, Machhiwara, Abowal Tusa, Rattowal Sadher, Hissowal, Boparai Kalan, Rakha, Teggai, Ikolaha, Jalaian, Jandali, Raikot, Chhappar, Raipur, Kaind, Lalton, Sarabax
Sardar Gurdial Singh Dhillon, Transport and Elections Minister								
Amritsar	..	..	..	1	7 1/2	17 1/2	6	3
Jullundur	..	..	..	..	1	..	..	1
Patiala	..	..	..	..	1	..	..	1
Gurdaspur	..	..	..	..	..	2 1/2	..	..
Simla	..	..	..	..	1	..	..	..
								Batala, Qadian, Madhopur, Pathankot, Dehra Baba Nanak Simla

Note—The information regarding Finance Minister is upto November, 1965

[Chief Minister]

Name of the District	Number of days spent on tour in					Names of places visited during 2nd July, 1965 to 30th November, 1965	
	April, 1965	May, 1965	June, 1965	July, 1965	August, 1965	Septem-ber, 1965	October Novem-ber, 1965
Ferozepore	..	..	..	..	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ Ferozepore, Fazilka, Abohar, Moga
Ludhiana	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	$\frac{1}{2}$ Dakhā
Ambala	..	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ Kalka, Ambala
Hissar	..	..	..	..	..	1	.. Hissar
Kulu	..	..	..	..	..	..	.. Mināli
Gurgaon	..	..	..	..	..	..	.. Bahadurgarh
Kangra	..	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	.. Dehragopipur
Hoshiarpur	..	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..
Chaudhri Ranbir Singh, Public Works Minister							
Patiala	..	..	2	1	1	..	1 Patiala, Budhanli
Ambala	..	..	1	$\frac{1}{2}$	..	$\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$ Ambala, Rupar, Jamuna Nagar, Raiwāli Chamkaur Sahib Gopal Mechan, Kurukshetra
Sangrur	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	1 Kalyat, Narwana, Surja Khera, Marchar
Karnal	..	..	1 $\frac{1}{2}$	1	2	$2\frac{1}{2}$	1 2 .. Nilokheri, Pipli, Panipat, Alupur, Karnal, Kurukshetra, Kaithal, Neesing and Babain-Jathlana

Note.—The information regarding Transport and Elections Minister is up to November, 1965.



(2)

PUNJAB VIDHAN SABHA [16TH FEBRUARY, 1966]

Chief Minister]

Name of District	Number of days spent on tour in						Names of places visited during 1st April, 1965 to 31st December, 1965
	April, 1965	May, 1965	June, 1965	July, 1965	August, 1965	September, 1965	
Gurdaspur	..	..	..	..	2	4	1 Madhopur, Batala, Dera Baba Nanak, Pathankot-Gurdaspur
Ferozepore	..	..	..	..	..	1½	.. Sarai Naga, Ferozepur, Jalalabad, Fazilka, Abohar, Malaut, Moga
Jullundur	..	..	..	..	..	½	.. Narot Jamial Singh, Adampur Doaba, Nawana Shehar, Awan, Jullundur
Kangra	..	..	..	..	..	..	4 Jawala Mukhi, Palampur, Chabin, Khera Chakki
Kapurthala	..	..	..	..	..	2	.. Kapurthala-Lohian Khas-Sultanpur
<i>Sardar Ajmer Singh, Planning and Local Government Minister</i>							
Bhatinda	..	..	..	..	..	..	.. Mahal Kalan
Ludhiana	..	..	2½	3½	4½	2	3½ Samrala, Khanna, Ludhiana, Sidhwan Khurd, Bhanni Sahib, Halwara, Lalton, Rajciana, Lall Kalan, V. Dhobran, Behlolpur, Shergur, Kotala, Hambowal, Jodhwal, Panj Graian, Machhiwara, Kutani Kalan, Jagraon, Kamalpura, V. Ghamana
Ambala	..	..	..	½	1½	½	1½ Ambala City, Kurali, Rupar, Yamuna Nagar, Manimajra, Chamkaur Sahib, Ambala Cantt.

Hoshiarpur	..	..	..	1	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	..	Una, Nangal, Anandpur, Manji Sahib, Ganguwal
Jullundur	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	..	1	$\frac{1}{2}$	1	2	Jullundur, Nawansher, Kartarpur
Amritsar	..	..	..	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	2	..	2	1	$2\frac{1}{2}$	Amritsar, Harika, Bhikiwind, Khalsa, Baba Bakala
Kapurthala	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	Kapurthala, Phagwara
Simla	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	Simla
Patiala	..	..	..	..	..	..	$3\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	Patiala, Doraha, Bassi Pathana, Sirhind
Sangrur	..	..	..	..	..	1	$3\frac{1}{2}$	..	1	..	Sangrur, Jhar Sahib, Bhawanigarh, Jhar Sahib, Sherpur, Malerkotla, Narwana, Uchana, Jind, Dhuri, Barnala
Ferozepore	..	..	..	..	..	$1\frac{1}{2}$	1	1	$\frac{1}{2}$	..	Ferozepur, Moga, Abohar, Fazilka
Karnal	..	..	..	..	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	Gharaunda
Hissar	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	Hissar, Bhiwani, Hansi, V. Bhora,
Rohtak	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Rohtak, Faridabad
Gurgaon	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

*Chaudhri Rizak Ram, Irrigation and Power Minister*

Simla	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	Simla
Ludhiana	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	..	..	..	Ludhiana
Rohtak	..	..	6	$3\frac{1}{2}$	5	4	$3\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	2	1	Rohtak, Bunjol, Sonapat, Jhajjar, Sohana, Idajana
Hissar	..	..	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	..	2 $\frac{1}{2}$	4	..	..	$\frac{1}{2}$	Hissar, Kaithal, Tohana and Tosham
Jullundur	..	..	$1\frac{1}{2}$	..	..	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	2	2	Jullundur

[Chief Minister]

Name of District	Number of days spent on tour in						Names of places visited during April, 1965 to December, 1965			
	April, 1965	May, 1965	June, 1965	July, 1965	August, 1965	September, 1965				
Gurdaspur	..	..	1	..	..	1	1	..	..	Madhopur, Gurdaspur
Hoshiarpur	..	..	1	..	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	Hoshiarpur, Nangal, Jogindergarh
Sangrur	..	..	..	1 $\frac{1}{2}$	..	1	..	..	..	Jind, Narwana, Sorken and Safidon
Gurgaon	..	..	..	2	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	Hodel and Rewari
Karnal	..	..	..	2	..	..	..	..	..	Karnal
Bhatinda	..	..	..	..	2 $\frac{1}{2}$	..	..	..	..	Bhatinda and Faridkot
Amritsar	..	..	..	..	..	1	..	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	Amritsar
Ferozepur	..	..	..	..	..	..	..	1	..	Ferozepur

*Sardar Prem Singh Prem, Capital and Housing Minister*

Name of the District	Number of days spent on tour in						Names of places visited during 1st June, 1965 to 31st December, 1965
	June, 1965	July, 1965	August, 1965	September, 1965	October, 1965	November, 1965	
Kulu	..	..	..	1	..	..	Mandi, Kulku, V. Sehel, Bhagaru
Patiala	..	..	..	..	..	3½	Rajpura, Patiala, Gobindgarh, Sirhind, Nabha
Ambala	..	..	½	3½	1½	2	Yamuna Nagar, Dera Bassi, Lalru, Chinathal, Kalan, Mani Majra, Kalka, Kulu Majra and Dera Bassi, Ghanaur, Alluan, Kala Majra, Chiwind, Ambala
apur thala	..	..	..	..	..	..	Kapurthala
udhiana	..	..	..	2	..	1	Jagraon, Ludhiana
mrtsar	..	..	..	..	..	..	Amritsar

Original with;  
Punjab Vidhan Sabha  
Digitized by;  
Panjab Digital Library

[Chief Minister]

Names of places visited during June, 1965 to  
31st December, 1965Name of  
DistrictJune, 1965  
July, 1965  
August 1965  
September, 1965  
October, 1965  
November, 1965  
December, 1965

Gurgaon	..	1½	2	4½	1	1	1	Gurgaon, Chandu Badhera, Mehchana, Rewari, Puthrawas, Nuh, Nagina, Bahadur, Ferozepur Jhirka, Rewli, Kohri, shsh choohke, Palwal Farmbhnagar, Dhani, Shamaspur, Saidpur and Sisana
Ludhiana	..	1	1	..	1½	2	2	Phillaur, Ludhiana, Sahnewal, Jagraon Khanna, Kher Nand Singh
Hoshiarpur	..	..	½	..	..	..	..	Piplanwala, Nara, Dasuya
Mohindergarh	..	..	1	..	..	..	..	Narnauh, Garbi, Mahasa, Dadri
Bhatinda	..	..	1	..	..	..	..	Bhatinda
Amritsar	..	..	..	..	1½	..	..	Amritsar, Dograi, Bhikiwind
Gurdaspur	..	..	..	..	2	..	..	Madhopur, Dera Baba Nanak, Pathan kot, Bhagwanpur.
Karnal	..	2½	2	1	2½	2½	1½	Kaithal, Karnal, Gharanda, Asandh, V. Chandaha Kurukshetra, Thanesar, Pundri V. Kheri Saraf Ali Samalkha, V. Mattanda, V. Ballab, V. Kaenla, V. Bapolf V. Siswah, V. Patti, Kalyane Shabad, Ladwa, Pehowa,, Ghula, Gumthala, Keouk, Sisla, Sismore, V. Kaul
Jullundur	..	3	2½	1½	½	½	..	Jullundur

Shrimati Om Prabha Jain,  
Health Minister

	Simla, Kanda Ghat	Simla	Patiala	Rohtak	Gurgaon	Ludhiana	Hoshiarpur	Sangrur	Ambala	Ferozepur	Amritsar	Gurdaspur	Kulu
Simla	3½	2½	1	1	1	1	1½	1½	1½	1	1	1	3½
Patiala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rohtak	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gurgaon	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ludhiana	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Hoshiarpur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Sangrur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ambala	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ferozepur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Amritsar	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gurdaspur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kulu	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Chaudhri Sunder Singh, Minister of State for Excise, Printing and Labour

District	Number of days spent on tour in				Names of places visited during the period	
	April, 1965	May, 1965	June, 1965	July, 1965	August, 1965	September, 1965
Gurgaon	1½	1	1	1	1	1
Ambala	..	2	..	..	..	1
Jullundur	..	2½	2	1½	1	1
Gurdaspur	..	3½	7	2	6½	1½

Names of places visited during the period  
April 1965 to 31st December, 1965

Gurgaon, Hodel, Palwal, Dhulhola, Gurgaon, Doboda  
Suraj Pur, Rupar, Gopal Mochan, Malla quary, Haodi, Kalan, Majri  
Sharif, Chand and Saidipur, Kaithi, Bhogpur, Banga  
Bhanota, Madhopur, Bani Lodhi, Malokpur and Batala, Dathuri, Nanga Bhur, Mangowal, Sultanpur, Hayti-chack, Basaubaan, Sorna, Jundra Baloon, Behrampur, Indora, Dina Nagar, Panjar, Kotli Maglan-Bharoli

## Name of District

## Names of Places visited during 1st

April, 1965 to 31st December, 1965

April, 1965    May, 1965    June, 1965    July, 1965    August, 1965    Septem-ber, 1965    October, 1965    Novem-ber, 1965    Decem-ber, 1965

Patiala	..	..	..	1	..	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	Rajpura, Sirhand, Jalwanti
Hoshiarpur	..	$\frac{1}{2}$	..	..	$\frac{1}{2}$	2	..	..	Hoshiarpur, Khurd, Bharwain, Mithian, Lehri, Mahalpur
Kangra	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	..	..	..	Joginder Nagar, Hamirpur, Palampur, Dharamsala
Simla	..	..	..	..	..	..	..	..	Dharampur
Amritsar	..	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	..	2	1	$1\frac{1}{2}$	Amritsar, Derababa Nanak, Khasa, Ajnala, Chheratta, Burki, Dograi Mo Mhega
Kapurthala	..	..	..	..	..	..	..	..	Kapurthala, Phagwara
Ludhiana	..	..	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	..	1	$\frac{1}{2}$	Ludhiana, Phillaur, Jagraon, Sahnewal Dhadian
Sangrur	..	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	..	..	Sangrur
Rohtak	..	..	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	Rasoi, Sampla
Karnal	..	1	..	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	..	..	..	PaniPat Karnal Maduda, Ladwa, Ganur
Bnatinda	..	..	..	..	..	..	..	..	Ranupra Phul
Hissar	..	..	..	..	$1\frac{1}{2}$	..	..	$1\frac{1}{2}$	Dabwali, Odhan, Sirsa, Hansi Hissar
Ferozepur	..	..	..	..	..	..	1	..	Feroz Cantt

*Captain Rattan Singh, Minister of State for  
Animal Husbandry and Agriculture*

Hoshiarpur	..	..	3	1	4½	8½	3½	4½	3½	3½	Chanda, Khurd, Sakila, Mehl Grenia Udhanwala, Raorika, Mughlan, Migher Garhshankar, Balachaur, Bihala, Mole wal, Jadli, Una, Nangal, Kahnuan Miani, Chinipuri, Gegretpur, Dasuya Kumhi Dev, Ramgarh, Kot Phatuahia, Matpur
Ludhiana	..	..	7½	½	1½	4½	5	2	7	7	Gogiana, Halwara, Samundra, Sidhwan, Khurd, Shahkot, Sahnewala, Choga Kalan, Bhaini Sahib, Adampur, Khanna Kaulgarh, Jagraon Karnal
Karnal	..	..	½	..	..	..	..	½	..	..	Sangrur, Mastuana
Sangrur	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Moga, Abohar
Ferozepore	..	..	2	..	½	½	..	..	..	..	Nabha, Patiala, Pinjore
Patiala	..	..	½	..	1½	..	..	..	½	1½	Rupar, Morinda, Jagadhri, Kharar, Kasuli, Chamkaur Sahib, Nalagarh
Ambala	..	..	..	2½	½	1	..	..	½	½	Nawanshaher Daulatpur, Kenge Pat, Nikodar, Bhogpur, Banga, Adoana
Jullundur	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	Kandaghat, Simla, Saproc
Simla	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	Hissar, Sardulgarh, Sirsa, Hissar, Rewari
Hissar	..	..	..	½	..	..	..	..	2	..	Phagwara, Nadalon
Kapurthala	..	..	..	..	1½	..	1½	..	..	..	Narnaul
Mohindergharh	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	Rampuraphul, Behman Diwana, Sadhe- wala, Mansa
Bhatinda	..	..	..	..	1½	1	..	..	..	..	Amritsar
Amritsar	..	..	..	..	..	..	1½	1½	1½	1½	

Name of District	No. of days spent on tour in							Names of places visited during 1st June, 1965 to 31st December, 1965
	June, 1965	July, 1965	August 1965	Septem-ber, 1965	October 1965	Novem-ber, 1965	Decem-ber, 1965	
Sardar Gurmit Singh Deputy Minister, Development Irrigation and Power								
Ferozepore	..	1	6	4½	8½	5½	6	5½
								Muktsar, Malout, Moga, Bagha Purana, Rupana, Ferozepur, Sherewala, Bhullar, Jallalabad, Bani, Khanianwali, Talwandi Bhaj, Kasoana, Zira, Abohar, Dharankot, Ferozeshah, Gidderbaga, Karam Patti, Kot Bhaj, Dandhar Qalawala, Ghollia Khurd, Mamdot, Sayanwali, Chibranwali, Tahliwala Jattan, Fazilka, Burj Sidhwan, Baruwali, Ghattianwali, Jattan, Mundhir, Patto Hira Singh, Ratia, Kattanwali, Chur Chak, Dina, Deon Khora, Misriwala, Lande Janer, Nihal Singh Wala, Bombika Bhaj Khara, Paniwala, Mohallen, Dhandri Kalan, Masi Mustafa
Patiala	..	½	..	½	1	½	1½	1½
								Patiala, Sirhind, Kandaghat, Dumna, Talania, Amloh Nabha, Rajpura, Nasirpur
Jullundur	..	½	..	..	..	..	..	½
								Jullundur
Ludhiana	..	½	½	..	..	..	½	..
								Ludhiana, Latala
Sangrur	..	½	..	..	..	..	1½	½
								Sangrur, Dhuri, Barnala, Jind, Gangoli, Dningana, Mirchpur, Kuthala, Sheerpur
Bhatinda	..	1	2	1	½	½	1½	..
								Bhatinda, Faridkot, Kot Kapur, Jhunir, Rampura Phul, Mansal, Bhikhi, Hingna
Ambala	..	½	1½	½	½	½	1½	..
								Ambala, Rupar, Jagadhari, Sulhar, Charn Kaur Sahib, Dharampur, Kalka, Gulab Garh, Yamuna Nagar
Amritsar	..	..	½	..	..	..	1	..
								Amritsar, Khadur Sahib

Gurdaspur	..	..	1½	1	..	..	1	½	Puthankot, Malakpur, Thain Dam, Madhopur, Udhampur, Dera Baba Nanak, Fatehgarh Churian, Sri Har Gobind pur
Kapnal	..	..	1	½	..	..	1	2	Kaithal, Karnal, Taraori, Nisang, Panchhi Gujran
Hoshiarpur	..	..	..	1	½	..	..	½	Nangal, Anandpur, Bhakra, Thanupali
Hissar	..	..	..	..	..	..	½	..	Hansi, Badaka, Dabwali
Simla	..	..	..	..	..	..	1	..	Simla
Rohtak	..	..	..	..	..	..	..	1	Gohana, Khanpur, Rohtak
<i>Shri Gian Chand, Deputy Minister, Industries and Hill Areas</i>									
Simla	..	3½	4½	2	1½	4½	2½	3	Dharampur, Simla, Chail and Kasauli, Dagsheer, Sarpoo Sabathu, Ochhat, Totu, Mamlig, Rugra, Kohbagn, Beon, Domehar, Kandaghat, Ratti, Bawri, Koti
Kulu	..	4	..	..	½	4	3½	..	Manali, Ranla, Pelli, Kuml, Bhuntar, Jari, Manikala Kulu, Bahang, Naggarr, Bhuthi, Larjit, Banjar, Sharla Khannag, Anni, Chawai, Dalgh, Luhri, Bawri
Ambala	..	½	2	1	½	..	½	1	Mahsul, Khana, Surajpur, Ambala, Jagadhri, Chachrauli, Maulana, Rupar, Kalka, Naraingarh, Beddi, Nulagarh Ram Shenar, Rawalsar, Tharoon, Toola
Patiala	..	..	½	..	..	½	..	1	Patiala-Banur, Rajpur
Sangrur	..	..	..	..	..	..	..	..	Malekotta
Jullundur	..	..	½	..	..	..	..	..	Jullundur
Amritsar	..	..	1	..	..	½	..	..	Amritsar
Gurdaspur	..	..	1	..	..	..	..	..	Batala
Ludhiana	..	..	..	½	..	..	..	..	Ludhiana
Gurgaon	..	..	..	½	½	..	..	..	Faridabad

[Chief Minister]

Name of District	Number of days spent on tour in					Names of places visited during 1st June, 1965 to 31st December, 1965
	June, 1965	July, 1965	August, 1965	September, 1965	October, 1965	
Kangra	..	..	3	2½	1½	..
Karnal	..	..	..	..	..	½ Kaithal, Panipat, Smalkha
Hoshiarpur	..	..	..	½	..	..
Hissar	..	..	..	1½	..	..
Kapurthala	..	..	..	..	½	..
Hissar	1½	1½	1	3	3½	1½ Bhiwani, Hissar Laharu, Kakroli, Sardawan, Kirhana, Behal, Pahari, Phertia
Simla	3	..	..	..	..	Simla, Chail
Gurgaon	½	½	..	..	½	..
Ferozepore	..	..	..	..	..	Village Sagar pur, Faridabad, Chancwas, Gurgaon, Hotel Moga
Karnal	..	..	..	..	..	Karnal
Ludhiana	..	..	..	..	½	..
Rohtak	..	..	1	1	..	1 Sandawa, Toshani, Bhadani

Shmt. Chandrawati, Deputy Minister, Food and Supplies

Bhatinda	..	..	..	1	..	..	$\frac{1}{2}$	..	Budhlada, Faridkot
Ambala	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	..	..	Ambala
Amritsar	..	..	..	..	..	..	..	..	Amritsar
Patiala	..	..	..	$1\frac{1}{2}$	..	..	..	..	Patiala
Sangrur	..	..	..	$1\frac{1}{2}$	..	$\frac{1}{2}$	1	..	Sangrur, Sunam
Jullundur	..	..	..	..	..	$\frac{1}{2}$	..	..	Jullundur City
Mahendragarh	..	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	2	$8\frac{1}{2}$	4	5	9	Charkhi Dadri Bond, Britni Kalan, Najand, Barda, Dnanauda, Pandwan, Bassian, Rania, Satnali, Kagna Arya Nagar, Chhgoa, Khatod, Mohindergarh, Nastauga- bad, Dhani, V, Heri, Khulari, Salawas, Mirchpur, Sighani, Khera, Pali

**कामरेड राम चन्द्र :** स्पीकर साहिब, मुझे जो लिस्ट दी गई है उस में बताया गया है कि मिनिस्टर आम तौर पर अपने ही जिला का दौरा करते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस की क्या वजह है ?

**मुख्य मंत्री :** ऐसी बात नहीं है। (विघ्न) आखिर जिले भी तो पंजाब में ही हैं, उन में भी जाना ही पड़ता है।

**श्री जगन्नाथ :** स्पीकर साहिब, यह जो लिस्ट है इस में बताया गया है कि कुछ मिनिस्टर्स एक ही हलके का टूर करते रहे हैं, जैसे कि श्रीमती चन्द्रावती हैं या यह अलग अलग टाइम पे एक ही हलके में लोहारू, सांडवा, तोशम, बगौरह गांव में दौरे पर जाती रही हैं, एक ही हलके में 15 गांव का दौरा कर चुकी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह टूर अपनी इलैक्शन की तैयारी के लिये किये जा रहे हैं ?

**मुख्य मंत्री :** वक्तन फवक्तन जब दौरे पर जाते हैं तो अपने हलके का भी ख्याल रखते हैं।

**सरदार गुरचरण सिंह :** इस लिस्ट मुताबिक सरदार गुरमीत सिंह ने एक ही हलके, मल्लेट का 9 दिन दौरा किया जस कि ऐसे कौड़ी धास इंसान ही नहीं सी। उन की यह सरकारी धरत उ अगली आं एलैक्शन की आं तैयारी आं हो रही आं हन ?

**मुख्य मंत्री :** वह वहां पर किसी प्राबलम के सिलसिले में गए होंगे, इलैक्शन के प्वायंट आफ व्यू से नहीं जाते, हां अगर आनरेबल मैबर के नोटिस में कोई खास बात है तो वह चैक की जा सकती है।

**श्री रूप सिंह फूल :** क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जिला कांगड़ा जो कि ज्यादा तबज्जुह का मुस्तहिक है वजीर साहिबान वहां पर क्यों कम दौरे पर जाते हैं ?

**मुख्य मंत्री :** जिला कांगड़ा हमारी तबज्जुह का ज्यादा मुस्तहिक है और वजीर साहिबान वहां पर जाते रहे हैं। वहां पर और ज्यादा दौरे रखे जायेंगे।

**कामरेड राम प्यारा :** यह जो लिस्ट दी गई है इस के मुताबिक श्रीमती ओम प्रभा दिल्ली में 29 दिन रहीं और होम मिनिस्टर साहिब वहां पर 49 दिन रहे। तो क्या वह बताएं कि होम मिनिस्टर साहिब के इतने दिन दिल्ली में रहने का क्या मतलब है ?

**मुख्य मंत्री :** किसी सरकारी प्रोग्राम के सिलसिले में गए होंगे। (विघ्न)

**सरदार गुरनभ सिंह :** On a point of order, Sir. चीफ मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया 'गुटे रेंगे'। Sir, we want information and not guess work.

**मुख्य मंत्री :** इस बारे में चैकिंग की जा सकती है आम तौर पर सरकारी काम पर ही जाते हैं।

**श्री मंगल सैन :** यह जो लिस्ट दी गई है, इस में बताया गया है कि आप दिल्ली में 35 दिन ठहरे जबकि होम मिनिस्टर साहिब वहां पर 49 दिन ठहरे। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आप को पलटने का बन्दोबस्त हो रहा हो ?

**Mr Speaker..** Order please.

**श्री अमर सिंह :** यह जो लिस्ट है इस के देखने से पता चलता है कि वजीर साहिबान हिमार ज़िले के दौरे पर बहुत कम गए हैं । क्या इस का यह कारण है कि वहां का कोई मिनिस्टर नहीं है ?

**मुख्य मंत्री :** ऐसी कोई बात नहीं है । जब जरूरी होता है तो हिमार का दौरा भी करते हैं ।

**कामरेड राम प्यारा :** उन्होंने बताया है कि वह दिल्ली सरकारी काम पर गए होंगे । तो क्या ऐसा कोई इन्तजाम है कि दिल्ली ठहरने पर सरकारी काम होने के बारे में कोई पूछ पड़ताल होती है ?

**मुख्य मंत्री :** मिनिस्ट्रों को हक है कि अगर वह सरकारी काम पर दौरे पर जाएं तो और काम भी कर सकते हैं । अगर वह प्राइवेट दौरे पर जाते हैं तो उस का टी. ए. वगैरह नहीं मिलता ।

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** इस में बताया गया है कि होम मिनिस्टर साहिब दिल्ली में 49 दिन रहे । तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब सरकार का सरकारी काम वहां पर दिल्ली में क्या होता है ?

**मुख्य मंत्री :** आप जानते हैं कि दिल्ली में कई तरह की मीटिंग्स और कान्फ्रेंसिंग होती रहती है, होम मिनिस्टर्स कांफ्रेंस, चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस, फूड मिनिस्टर्स कांफ्रेंस, प्लेनिंग और ला एंड आर्डर के बारे में भी मीटिंग्स होती रहती हैं ।

**श्रीमती सरला देवी :** यह जो जिले हैं जिन में मन्त्रियों के ज्यादा दौरे रहते हैं वहीं पर ही उन के डिस्ट्रिक्शनरी फंड भी जाते हैं । तो क्या इस से कोई फर्क नहीं पड़ता ?

**मुख्य मंत्री :** इस के लिये नोटिस दें ।

#### Tours of Deputy Commissioner, Kangra

**\*8827. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased, to state—

- (a) the names of places visited by the Deputy Commissioner, Kangra months-wise from the 1st April, 1965 to date together with the purpose of each visit and the total amount of T.A. paid or payable to him on this account ;
- (b) whether the said officer travelled by his own car during the said tours or used block jeeps for the purpose; if the latter, the names of Block whose Jeeps were used together with the number of days for which each was used ;
- (c) the Head of account to which the cost of petrol used in the said jeeps was debited ?

**Shri Ram Kishan :** (a) The requisite information is given in annexure "A".

(b) No. The Government jeep of the D.C., Kangra, having gone out of order, some of this touring had to be done in Block jeeps in the interest of Government work, particularly in the fields of agricultural production and development. The requisite information regarding use of block jeeps is given in annexure "B".

(c) The cost of petrol used in the block jeeps for these tours was debited to the head "19 General Administration. E-District Establishment-Contact Contingencies."

[Chief Minister]

## ANNEXURE 'A'

Name of month	Places visited	Purpose of visit	Amount of T.A. paid/to be paid
			Rs.
April, 1965	.. Mangwal-Daroka	.. Accompanied the Home Minister, Punjab, in his tour in Hal- doon area, made enquiries into complaints made by the people to the Home Minister, Punjab, on the spot under his directions (regarding demand of Pong Dam Oustees) and Deve opment work	216.00
	Chandigarh	.. Meeting with the Secretary to Government, Punjab, regarding demand of Pong Dam Oustees	
	Ludhiana	2. Meeting with the Home Minister, Punjab, Health Depart- ment regarding Biological Research Institute proposed for Kangra District	
	Mandi	.. Attended a course for training in Agriculture meant for Deputy Commissioners	
	Barsar	.. Visit to the Package Programme and meeting with the Deputy Commissioner, Mandi, and other Project authorities under instructions of Dr. M.S. Randhawa, Special Secretary to the Government of India	
	Bharoli	.. Village touring for Development work, meeting of the D.S.S.A. Board, Crop inspection and enquiries into complaints	
	.. Kangra	.. Inspection of Flood Protection work in Mann Khad near Nadaun	
May, 1965	Palampur	.. General Administration and Development work	285.00
		.. Ditto	

Bajinath	...	1. General Administration and Development work	
		2. Visit to Jogindernagar, Palampur, Maranda along with Chief Minister, Punjab	
Nurpur	...	General Administration and Development work, Departmental enquiries	
Simla	...	Attendance of meeting of a Agricultural Sub-Committee and Communication Sub-Committee under orders of the Development Commissioner, Hill Areas	
June, 1965	.. Tyara Lang, Mangwala and Hamirpur	Along with Chief Minister, Punjab	186.00
	2. Palampur	Ditto	
	3. Jogindernagar	Discussions with the officers of the Punjab State Electricity Board regarding compensation to be paid to the Chhota Bhagal right holders for the Ban imposed in their area over keeping of sheep and goats	
	4. Chandigarh	Attended meeting at the State Headquarters in connection with the State Quarry, Ghuniara as ordered by the Chief Minister, Punjab	
	5. Palampur	Village touring, General Administration, enquiries and development work	
July, 1965	.. Nurpur, Phadwar, Jawali, Gnea, Jassur and Panjhara	1. Inspection of the S.D.O's, Sub-Registrar and B.D. & P.O's offices at Nurpur	210.00
		2. Visit to villages Phadwar, Jawali, Gona, Jassur and Panjhara. Heard the grievances of the public there and checked the development work of these villages also	
		3. General Administration	

[Chief Minister]

Name of month	Places visited	Purpose of visit	Amount of T.A. paid/to be paid
August, 1965	Chandigarh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meeting with Mrs. Ram Kishan at the residence of Chief Minister regarding social and moral Hygiene and social welfare work in Kangra District</li> <li>2. Meeting at the Directorate Food Supply regarding measures to be taken to stop export of rice from Kangra to Non-Zone Areas through Himachal Pradesh and opening of P. R. Centres in connection with the distribution of wheat, rice, etc.</li> <li>3. Meeting with the Registrar, Co-operative Societies and Secretary, Marketing and Supply Federation regarding supply of fertilizers</li> <li>4. Meeting in connection with the Resettlement of Tibetan Refugees called by the C.M., Punjab, at the instance of Director, Tibetan Rehabilitation</li> </ol>	219.00
	Palampur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. General administration and development work</li> <li>2. Inspection of the road under construction and other sites</li> </ol>	
	Palampur and Bir	To see the sites and damage caused by landslides which destroyed houses and human beings in village Bir	
	Palampur-Panchrukhi	Inspection of S.D.O's and Panchrukhi Block Offices	
	Chandigarh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meeting with Mrs. Ram Kishan at the residence of Chief Minister regarding social and moral Hygiene and social welfare work in Kangra District</li> <li>2. Meeting at the Directorate Food Supply regarding measures to be taken to stop export of rice from Kangra to Non-Zone Areas through Himachal Pradesh and opening of P. R. Centres in connection with the distribution of wheat, rice, etc.</li> <li>3. Meeting with the Registrar, Co-operative Societies and Secretary, Marketing and Supply Federation regarding supply of fertilizers</li> <li>4. Meeting in connection with the Resettlement of Tibetan Refugees called by the C.M., Punjab, at the instance of Director, Tibetan Rehabilitation</li> </ol>	219.00
	Palampur	General Administration, Development work and inspections of S.D.O's Office, Palampur	
	Nurpur-Jawali	Enquiry into the dispute between Municipal Committee and Public Health Department over the payment of dues as well as to study the position of fertilizers in the Nurpur Sub-	

Division, etc. Settlement of dispute between Public Health Department and Irrigation Department regarding a site at Jawali

Kangra, Yol, Sera-Thana and Pathiar

1. General Administration and Development work

2. Inspection of Development work in the villages of Yol, Sera-Thana and Pathiar

3. Inspection of the S.D.O.'s office at Kangra

September, 1965 .. Chandigarh .. To attend the Deputy Commissioner's and Commissioner's Conference at Chandigarh 167.50

.. Nurpur .. In connection with Civil Defence work arrangements for refugees from Jammu and Kashmir, etc.

.. Palampur .. Defence work and meeting with S.D.O. (Civil), Palampur and other local leaders

October, 1965 .. Hamirpur .. War and Defence work 225.00

.. Dehra .. Defence Rally at Dhaliara

Lathiani-Bijhr and Uhal .. Defence Rallies

Dehra .. Defence Rally at Dehra

Kangra .. Defence work

Nurpur .. Ditto

Indora .. Defence Rally

Kangra .. Ditto

Nagrota .. Ditto

November, 1965 .. Kangra .. Inspection of the S.D.O.'s office, Kangra ..

Pait-Bhadiara .. Inspection of Development work at Bhadiara

217.50  
(yet to be drawn)

[Chief Minister]

Name of month	Places visited	Purpose of visit	Amount of T. A. paid/to be paid
	Palampur	.. Enquiries	
	Kangra	.. Finalized the inspection of S.D.O's office, Kangra	
	Jogindernagar Simla	.. Procurement of Potato Seeds for cultivators of this district in compliance with the orders of the Development Commissioner, Hill Areas	
	Chandigarh	.. Discussion of cases with the Director, Food and Supplies regarding supply of cement, kerosene oil and rice to this district. Discussion with the Secretary State Marketing and Supply Federation for fertilizer, etc.	
	Nangal	.. Attended meeting of Bhakra Dam Sub-Committee	
	Palampur	.. Visit to Primary Health Centre, Palampur, in connection with selection of site for Children's Ward	
December, 1965	.. Barsar	.. Implementation of the decision of Bhakra Dam Committee regarding Govind Sagar Lake and held meeting of Block officials and members of the Samiti	285.00 (yet to be drawn)
	Dehra-Kangra	.. Tour with Chief Minister, Punjab, and attended Defence Rallies at Dehra and Kangra	
	Chobin and Khaira	.. Attended Defence Rallies at Chobin and Khaira	
	Sapri-Dehra-Galore	.. Inspection of S.D.O's office, Dehra. Attended Defence Rally at Galore. Presided over by the Home Minister, Punjab. General administration and Development work	
	Palampur	.. General Administration and Development work	
	Jogindernagar-Barot, Kothi Kohar, Kothi Sower Loharli,	Touring in the interior of Kothi Kohar and Kothi Sower areas in Chhota Bhangal	

## ANNEXURE 'B'

Name of the month	Name of Block whose jeep was used on tour	No. of days for which used on tour
April, 1965	.. Panchrukhi Block	<p>The necessary information is not readily available. It is being collected and will be supplied to the Honourable Member, on receipt</p>
May, 1965	.. 1. Nurpur Block 2. Panchrukhi Block	
June, 1965	.. 1. Panchrukhi Block 2. Bhoranj Block 3. Baijnath	
July, 1965	.. 1. Nurpur Block 2. Bhawarna Block	
August, 1965	.. 1. Kangra Block 2. Panchrukhi Block 3. Bhawarna Block	
September, 1965	.. 1. Kangra Block 2. Baijnath Block	
October, 1965	.. Nil	
November, 1965	.. 1. Panchrukhi Block 2. Kangra Block	
December, 1965	.. Nil	
		.. As against April to September, 1965

**कामरेड राम चन्द्र :** स्पीकर साहिब, मेरे दो तीन सवालों का जवाब जो कि बड़ा डिटेल्ड है मुझे अभी अभी मिला है और मैं उन को सरसरी निगाह से ही देख पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस और अगले सवाल के बारे में मुझे इजाजत दी जाए कि मैं कल सवाल कर सकूँ।

**श्री अध्यक्ष :** आप को यहां पहले आना चाहिए था। (The hon. Member should have come here a bit earlier.)

**कामरेड राम चन्द्र :** मुझे इन को देखने का मौका नहीं मिल सका।

**Mr. Speaker :** Not possible now. You should have come in time

**Staff working in the Chief Minister's Office**

**\*8830. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number and names of Private Secretaries or aides, Personal Assistants, Stenographers, etc., attached with him at present ;
- (b) the number and names of such personnel, categorywise, attached with S. Partap Singh Kairon when he was the Chief Minister ?

**Shri Ram Kishan :** (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

## Statement

*Private Secretaries or aides, etc., with the present Chief Minister*      *Private Secretaries or aides, etc., with late Chief Minister, S. Partap Singh Kairon*

Serial No.	Designation of the post	Number	Name of incumbent	Serial Designation of the post No.	Number	Name of the incumbent	
1	Private Secretary	..	(1) Shri Madan Mohan Sud, Private Secretary (Office) (2) Shri Khem Chand, Private Secretary (Public)	1	3	(1) Shri Harbans Singh Sahney, Private Secretary (Office) (2) Shri Narinder Nath, Private Secretary (Public) (3) Shri Mohinder Singh Pannu, Private Secretary (Political)	
2	Personal Assistant	..	1 Shri Dharminder Singh, P.A. (Residence) to C.M.	2	1	Shri Dharminder Singh, P.A. (Residence) to C.M.	
3	Senior Scale Stenographer	1	Shri Om Parkash Kashyap, Steno to C.M.	3	1	Shri R.C. Mehtani, Steno to C.M.	
4	Hindi Stenographer	..	1 Shri Ravinder Nath	4	1	Shri Ravinder Nath	
5	Steno-typist	..	(1) Shri Surrinder Singh Batra, Steno-typist/P.S.(P) to C.M. (2) Shri Raj Kumar Kalia, Stenotypist/P.S.(O)to C.M.	5	2	(1) Shri Alla Singh, Steno- typist/P.S.(P) to C.M. (2) Shri Pritam Singh Sabharwal, Steno-typist/ P.S.(Pol.) to C.M.	
Total		..	7	Total		..	8

**Decorations for Civil Servants posted in Border Districts**

**\*8921. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government for awarding some kind of decorations to the Civil Servants posted in the border districts for their work during the Indo-Pakistan conflict ; if so, the steps so far taken to implement the same ;

(b) the names of the officers (Civil Servants) who are proposed to be awarded such decorations ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes, there is a proposal to issue appreciation letters to Civil Government Servants, belonging to all Government Departments, who have done very good work in the recent Indo-Pak conflict on the basis of the recommendations made by the Commissioners of the Divisions. The recommendations from the concerned quarters are being collected, and would further be scrutinised at Government level.

(b) Since the case has not yet been finalized, it is not possible to furnish the list of such Government employees at this stage.

**श्री बलरामजी दास टंडन :** क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिन सिविल सर्वेंट्स को डेकोरेट किया जाता है उन के लिये अलग प्रोसीजर है और जिन को पंजाब सरकार की तरफ से डेकोरेट किया जाता है उस के लिये अलग प्रोसीजर है ? क्या आप बाद में ऐनाउंस करेंगे जबकि राष्ट्रपति की तरफ से डेकोरेशन का ऐलान हो चुका है ?

**मुख्य मंत्री :** जी हां। होम मिनिस्टरी ने हम से रिक्मैण्डेशन मांगी थीं वह चली गईं। स्टेट लेवल पर जो कार्रवाई होनी है उस के बारे में इन्फरमेशन कुलैक्ट की जा रही है। इस को सीनियर आफिसर्स की एक कमेटी स्कुटेनाइज करेगी और जिन अफसरों ने जिला या डिवाइजनल लेवल पर अच्छा काम किया है उस को रैकगनाइज और एप्रिशियेट किया जायेगा।

**श्री बलरामजी दास टंडन :** यह तो हुई एप्रिशियेशन के बारे में एक कमेटी बनाने की बात मगर जिन अफसरों ने इस लड़ाई के दौरान अपने काम में कोताही दिखाई क्या उन के खिलाफ किसी कार्यवाही या उन के खिलाफ रिमावर्स देने का भी कोई प्रोसीजर बनाया गया है ?

**मुख्य मंत्री :** अगर ऐसा कोई केस नोटिस में आया तो कायदे के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी।

**श्री मंगल सैन :** क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह पदम विभूषण इत्यादि देने के लिये प्रोसीजर क्या है ?

**मुख्य मंत्री :** इस का प्रोसीजर हिन्द सरकार का है हम से जो सूचना मांगते हैं वह हम दे देते हैं।

**ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸ਼ਟਰੋ ਕਿ ਇਸ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

**Mr. Speaker :** I am sorry.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਜਦ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨ ਦੀ ਫਲੌਰ ਆਫ ਇਸ ਹਾਊਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨ ਦੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਖਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਖਤਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ?

**ਮੁਖਯ ਮੰਤਰੀ:** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਸੋਂ ਹਾਊਸ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਡੀ. ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਦੀ ਵਹ ਠੀਕ ਥੀ ਐਂਦਰ ਜੋ ਇਤਲਾਹ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੀ ਥੀ ਵਹ ਗਲਤ ਥੀ। ਜਹਾਂ ਤਕ ਇਸ ਡੀ. ਸੀ. ਕੇ ਕਾਮ ਕਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਮੈਂ ਤਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ ਐਂਦਰ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਤਸ ਕੇ ਕਾਮ ਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਤਕ ਲੜਕੀਓਂ ਕਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਪਹਲੇ ਭੀ ਕਹਾ ਥਾ ਐਂਦਰ ਅਬ ਦੋਹਰਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਝਗੜਾ ਮੈਂ 3 ਸਿਤੰਬਰ ਕੋ ਪਕਕਾ ਚਿਸ਼ੀ ਐਂਦਰ ਜ਼ਿੰਗਰ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਤੋ ਜੋ ਭਾਈ ਐਂਦਰ ਬਹਨ ਵਹਾਂ ਰਹ ਗਏ ਤਨ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੀ ਓਨਬੀਨ ਕੇ ਲਿਏ ਏਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਈ ਗਈ ਥੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਮਿਲੇਟਰੀ ਕੇ ਆਫੀਸਰ ਐਂਦਰ ਵਹਾਂ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਭੀ ਥੇ ਤਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋ ਹਮ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਪਹਲੇ ਇਤਲਾਹ ਥੀ ਤਸ ਕੋ ਭੀ ਏਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਿਆ ਗਿਆ ਐਂਦਰ ਤਸ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਐਂਦਰ ਬਹਨੋਂ ਤਸ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਰਹ ਗਈ ਥੀ ਵਹ ਅਬ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਿਸ ਆਗਈ ਹੈ ਐਂਦਰ ਤਨ੍ਹੇ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ ਏਕਡਕਟ ਨਹੀ ਕਿਆ ਗਿਆ ਥਾ ਕੁਓ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋ ਗਲਤ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਥੀ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਨਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।  
The hon. Member has not heard the complete answer.  
There is no contradiction in the reply.

**ਡਾ॰ ਬਲਵੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਖੜਾ ਹੁਆ ਹੂੰ। ਆਪ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏਮ. ਸਾਹਿਬ ਕੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ

[डा० बलदेव प्रकाश]

फैक्ट यह है कि सी. एम. साहिब, फिरोज़पुर के डी. सी. साहिब को आऊट आफ दी बे जा कर भी ट्रिब्यूनल पे करते हैं तो अगर वह इतना लायक आफिसर है और अगर सी. एम. साहिब यह समझते हैं कि तमाम बार्डर के ज़िलों के डिप्टी कमिश्नरों में से सब से ज्यादा काम, फिरोज़पुर ज़िला के डी. सी. ने किया है तो इन्हें सिरफ पद्म श्री का खिताब देने के लिए ही क्यों रिकमेंड किया गया भारत रत्न क्यों न दिलवाया गया ?

मेरा तो स्पैसिफिक सवाल है कि जो नाम पंजाब सरकार रिकमेंड करती है वह किसी खास डेकोरेशन के लिये या जैनरल तौर पर और अगर किसी खास डेकोरेशन के लिए रिकमेंड करती है तो क्या वजह थी कि डी. सी. फिरोज़पुर का नाम पद्म श्री के लिए रिकमेंड किया गया और भारत रत्न के लिए नहीं।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** On a point of Order, Sir. Mr. Speaker, the hon. Chief Minister has just now stated that some brothers and sisters, have come from Pakistan, but they were not abducted. May I know, Sir, if those brothers and sisters who have returned from Pakistan went of their own accord ?

**मुख्य मंत्री :** मैं ने आगे भी अर्ज किया है कि 6 सितम्बर को फिरोज़पुर-फाज़िल्का बैकटर पर जत्र पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया तो कुछ भाई और बहनें वहां से निकल न सके वहां पर ही रह गए और पाकिस्तान वाले उन्हें इन्टरनीज़ के तौर पर ले गए जिस तरह कि हमारे पंजाब में रहने वाले पाकिस्तानियों को इन्टरनी बनाया गया था और अब वह सारे के सारे वापिस आ गए हैं और किसी भाई और बहन ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि उन्हें अबडकट किया गया था। हालात के मुताबिक जिस तरह की लड़ाई हुई उसका यह नतीजा था।

**कामरेड बाबू सिंघ मासटर :** ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਬਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੀ, ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ?

**Mr. Speaker :** Reply to this has already come.

**श्री राम प्यारा :** जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि कमिश्नरों की सिफारिशों पर डेकोरेट किया जाता है तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या कमिश्नर इन्डी-पेंडेंटली सिफारिशें करते हैं या डी. सी. की मारफित की जाती है और क्या जिस की सिफारिश की जाए उस के सिरफ गुड एक्शन को ही सामने रखा जाता है या उस के गुड और बंद एक्शन को सामने रखा जाता है ?

**मुख्य मंत्री :** मैंने यह नहीं कहा कि कमिशनरों को सिफारिश पर डेकोरेट किया जाता है। कमिशनर उन लोगों का नाम सुबुलिक ज़िनों से ले कर जिन्होंने अच्छा काम किया हो सरकार को भेज देते हैं और उन नामों को स्टेट लैबल पर जो कमेटी बनी हुई है उसे एग्जामिन करती है कि किस तरह से किसी की सर्विस को एग्जिश्यूट करना है और पूरा गौर किया जाता है। जहाँ तक सैट्रज गवर्नमेंट का तालुक है पंजाब गवर्नमेंट सिफारिश करती है।

**सरदार अजयिब सिंघ सैयू :** मुँह मँतरी साहिब ने दसिआ है कि जिनुं अफसरों ने चंगा कर्म कीता है उनुं दीआं सिफारिश ज़िहज़ीआं कमिशनरों तें आਈआं हन उनुं ते सरकार गौर कर रही है तां कि उनुं अफसरों नुं सजा देठ घरे वी कौड़ी कायिदा बठा दिता गिआ है जिनुं ने अमरसैसी दे दैरान सरकार दी कौड़ी मँदें नही कीती।

**सरदार गुरबखस सिंघ गुरदासपुरी :** की चीफ मनिस्टर साहिब ऐंघ दसठ दी घेचल करनगे कि जद घारडर दे ज़िल्लिआं दे डिपटी कमिशनरों ने इस अमरसैसी दे दैरान चंगा कर्म कीता है जिवे कि ऐंघ आप मनदे हन तां की कारन है कि गुरदासपुर दे डिपटी कमिशनर नुं कौड़ी डैक्लरेसन देठ तें अकैसकलूड कीता गिआ है अते उस नाल इस उरुं दा वितकरे भरिआ वरताव करन दे की कारन हन। की ऐंघ ठीक नही कि डेहरा घाघा नानक ते जद हँला हँऐआ तां इसे डिपटी कमिशनर ने इलाके नुं बचाऐआ अते सलआ घरिआ कर्म कीता सी। नेकर ठीक है तां इस नाल इस उरुं दी पध-पात किउं कीती जा रही है ?

**मुख्य मंत्री :** पंजाब गवर्नमेंट डी० सी०, गुरदासपुर के काम की पूरी तरह से एग्जिश्यूट करती है और सराहना करती है कि उस ने बहुत अच्छा काम किया है। सिफारिशपर बारडर के आर्मी कमान्डरों की तरफ से आई थीं उन को मद्देनज़र रख कर सारी चीज़ पर गौर किया जा रहा है और मैं हाऊस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि डी. सी. ज़िला गुरदासपुर की जहाँ तक सर्विसिज़ का तालुक है हम उन को एग्जिश्यूट करते हैं। इस बात के लिये जो भी हम रिवाइ दे सके वह देने की कोशिश करेंगे।

**श्री बलरामजी दास टंडन :** मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पदम श्री के पाने वाले आया यह वही डिप्टी कमिशनर ज़िला फिरोज़पुर हैं जिन के लड़के को रैड क्रॉस में से 470 की दवाइयां दी गई थीं जो कि गरीब लोगों के लिये हैं ?

**मुख्य मंत्री :** यह बात बिल्कुल गलत है। डी. सी. के लड़के ने बीमारी की हालत में भी दिन रात काम किया है। इस की सेवा की पंजाब सरकार सराहना करती है।

#### Awards granted to Military personnel from Punjab

**\*8905. Shri Rup Singh Phul :** Will the Chief Minister be pleased to state the names, ranks and home addresses of the Military personnel from Punjab, who have been granted awards, categorywise, for displaying gallantry during the recent Indo-Pak conflict, tehsil and districtwise ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister) :** A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

[Transport and Elections Minister]

## LIST OF GALLANTRY AWARDEES

During Indo-Pakistan Conflict

Number, rank and name	Permanent home address
<b>Maha Vir Chakra</b>	
IC—801 Lt. Col. Salim Caleb. 3rd Cav.	AMRITSAR DISTRICT
	TEHSIL AMRITSAR C/o Maj S. Caleb (Retired), Bishops Office, Taylor Road, Amritsar
<b>JULLUNDUR DISTRICT</b>	
JC No. 18340 Subedar Ajit Singh, 4th Bn., The Sikh Regt. (Posthumous)	Village Sobhana, Post Office, Jullundur Cantt., Jullundur
IC—2990 Lt. Col., Gurbans Singh Sangha, 3rd Bn., The Garhwal Rifles (Posthumous)	Village and Post Office Jandu Singha, Tahsil and District Jullundur
<b>HOSHIARPUR DISTRICT</b>	
IC—4004 Maj. Ranjit Singh Dayal 1st Bn., The Parachute Regt.	Village Kante, post office Paluckwah, Tehsil Una, District Hoshiarpur
<b>KANGRA DISTRICT</b>	
IC—12701 Capt. Chander Narain Singh, 22nd Bn., The Garhwal Rifles (Posthumous)	TEHSIL DHARAMSALA Ram Nagar, Dharamsala, district Kangra
<b>FEROZEPUR DISTRICT</b>	
Wg. Cdr. P. P. Singh (3871) CD (P)	TESIL MOGA C/o S. Sucha Singh, Assistant Director of Agriculture, G. T. Road, Moga, district Ferozepore
<b>LUDHIANA DISTRICT</b>	
IC—4466 Maj Bhupinder Singh 4th Hudson Horse (Posthumous)	TEHSIL LUDHIANA Harnampura, Ludhiana

AMRITSAR DISTRICT

Vir Chakra

Flt. Lt. D. N. Rathore (5780) GD (P)

TEHSIL AMRITSAR No. 3-A., The Mall, Amritsar

JULLUNDUR DISTRICT

IC—1351 Lt. Col. Chajju Ram

TEHSIL JULLUNDUR Village Daroli Khurd, Tahsil and District Julundur

EC—55428-2/Lt. Bhupinder Kumar Vaid, Regiment of Artillery

TEHSIL NAKODAR Village and Post Office Shankar, Tahsil Nakodar, District Julundur

HOSHIARPUR DISTRICT

IC—13651 Lt., Teja Singh 9th Bn. The Jammu and Kashmir Rifles

TEHSIL HOSHIARPUR Village and Post Office Kukanate, district Hoshiarpur

KANGRA DISTRICT

IC—14602 Capt. Bhikham Singh, 7th Bn, The Punjab Regiment

TEHSIL HAMIRPUR Village and Post Office Sujampur Tira, Tahsil Hamirpur, District Kangra

IC-6725 Maj Sarvjit Singh Ratra, The Regiment of Artillery

TEHSIL KULU Dhal Pur Bazar, Kulu, District Kangra

9065621 L/Hav Fidoo Ram, Regiment of Artillery

TEHSIL PALAMPUR Village Nora, District Kangra

IC-2807 Naib Risaldar Jagdish Singh, Central India Horse

TEHSIL NURPUR Village Trithipur Tika Gangth, Tahsil Nurpur, District Kangra

Flt. Lt. V. S. Pathania (5198) GD(P)

—do— Village and Post Office Re, Tahsil Nurpur, District Kangra

FEROZEPUR DISTRICT

Flt. Lt. H.S. Mangat (5226) GD(N)

TEHSIL MUKTSAR

Village Kermangat, Post Office Muktsar, District Ferozepore

[Transport and Elections Minister]

Number, rank and name

Perma

## LUDHIANA DISTRICT

## Vir Chakra

JC-5234-Risaldar Achhar Singh Daccan Horse 9th Horse

Tahsil Ludhiana

Village Kaile, district Ludhiana

IC-8041, Lt. Col. Sampuran Singh, 16 Bn., The Punjab Regt.

Tahsil Jagraon

Village Bassian, police-station Raikot, tahsil Jagraon, district Ludhiana

## AMBALA DISTRICT

IC-14376, 2/Lt. Ravinder Singh Bedi, The Sindh Horse

Tahsil Ambala

C/o Kanwar Surinder Singh Bedi, Deputy Commissioner, Ambala

3339173, Naib-Subedar Ajmer Singh, 4th Bn., The Sikh Regt.

Tahsil Ambala

Village and post-office Boh, tahsil and district Ambala

Sqn. Ldr. S. Handa (4816) GD (P)

Tahsil Kharar

C/o Prof. D. R. Handa, E-49, Sector 14, Chandigarh

IC-10082, Major Surinder Mohan Sharma, 8th Bn., The J. &amp; K. Rifles (Posthumous)

Tahsil Kharar

29—J, Sector 21-A, Chandigarh

IC-8519, Major Jatinder Kumar, 15th Bn., The Dogra Regt.

Tahsil Kharar

C/o Jessa Ram, Tahsildar Kharar, district Ambala

## HISSAR DISTRICT

2851209, Rifleman Mathan Singh, 2nd Bn., The Rajputana Rifle (Posthumous)

Tahsil Bhiwani

Village and post-office Bapora, tahsil Bhiwani, district Hissar

Sqn. Ldr. A. J. S. Sandhu (4705) GD (P)

Tahsil Sirsa

Village and post office Moriwala, district Hissar

## GURGAON DISTRICT

2853735 Rifleman Mahi Lal Singh, 4th Bn., The Rajputana Rifle

Tahsil Palwal

Village and post-office Banchari, tahsil Palwal, district Gurgaon

SANGRUR DISTRICT

IC-13986, 2/Lt. Surinder Pal Singh Sekhon, Rajputana Rifles (Posthumous)	Tahsil Sangrur	Village Ubha, post-office Sangrur, district Sangrur
3348906, L/Nk. Pritam Singh, 4th Bn., The Sikh Regt. Posthumous	Tahsil Malerkotla	Village Niamatpur, post-office Amargarh, tahsil Malerkotla, district Sangrur
3341107, Naik Chand Singh, 2nd Bn., The Sikh Regt.	Tahsil Malerkotla	Village Manki Khurd, post-office Manki Kalan, tahsil Malerkotla, district Sangrur

BHATINDA DISTRICT

3342155 L/Hav. Gurdev Singh 1st Bn., The Sikh Regt.	Tahsil Faridkot	Village and post-office Jaitu, tahsil Faridkot, district Bhatinda
---	-----------------	---

NARNAUL (MOHINDER GARH) DISTRICT

4139233, L/Hav. Umrao Singh, 1st Bn., The Para Regt. (Posthumous)	Tahsil Narnaul	Village Surjanwas, post-office Mohindergarh, tahsil Narnaul, district Mohindergarh
---	----------------	--

**Shri Rup Singh Phul :** From the statement given to me it is evident that Kangra is the district which has given the highest number of recipients of gallantry awards. May I know from the Government whether they would propose any special allocation of funds for this district in view of its superb performance during Indo-Pakistan and Chinese aggression ?

**Minister :** Well, the hon. Member should know that the Government does not make any discrimination. But we do appreciate the services rendered by the Kangra district and I think if the hon. Member makes some personal contact in this behalf the Government certainly should look into it.

**श्रीमती सरला देवी :** ट्रांसपोर्ट मन्त्री जी ने यह कहा है कि गवर्नमेंट के सामने किसी एक या दूसरे जिले के लिये भेद भाव रखने का कोई सवाल नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जिला कांगड़ा में जंग हटने के बाद किसी शहीद के घर उसके परिवार को मिलने गये हैं। यह भेद भाव नहीं तो और क्या है ?

**मंत्री :** जहाँ बहन जी ले जाना चाहें हम जाने को तैयार हैं। किसी खास जिला से डिस्ट्रिक्तीनेटरी टरीटमेंट का यह सवाल नहीं है।

**श्री मंगल सेन :** अभी अभी ट्रांसपोर्ट मन्त्री ने कहा है कि वह वहाँ जाने को तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह कांगड़ा जिले में जायेंगे या कहीं और भी ? (हंसी)

**मंत्री :** डाक्टर मंगल सेन जो भी बात कहें हमें उस से कोई एतराज नहीं है। हम तो बुरे दिनों में भी उन के साथ रहे हैं अब तो वजीर हैं। (हंसी)

#### Visits paid by Chief Minister to the Families of Killed Army Personnel

**\*8906. Shri Rup Singh Phul :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of visits so far paid by him to meet the families of the jawans and officers of the Armed Forces killed during the India-Pak conflict, district-wise ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister) :** Chief Minister did not specifically visit any village only for this purpose, but used to visit the families of Jawans, whenever he visited any district. In some cases he asked the Deputy Commissioners/Superintendents of Police concerned to call on the family of a Jawan, whenever needed.

**श्री रूप सिंह फूल :** क्या वजीर साहिब यह बतायेंगे कि दूसरे जिलों में ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि दूसरे वुजरा साहिबान भी गये मगर जिला कांगड़ा में कोई भी मंत्री नहीं गया ? May I know the reason for this gross neglect on the part of the State Government?

**मंत्री :** दरअसल बात यह है कि हम ने इस बात को कभी भी महसूस नहीं किया कि वहाँ जाना है और वहाँ नहीं जाना। मिनिस्टर्स की तादाद 7-8 है। डिप्टी मिनिस्टर्स को शुमार भी अगर किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 12-14 है। मगर सब जगह पहुँचने के लिये कम से कम 50 होने चाहिये। जहाँ भी हम पहुँच सकते थे हम ने पहुँचने की फिर

भी कोशिश की है। प्रोग्राम के मुताबिक जहां पहुंच सकते थे पहुंचे हैं अभी बहुत सी नैमिलीज को विजिट करना बाकी है। इस लिये जो जगह रह गई हैं वहां भी जरूर जायेंगे।

**श्री रूप सिंह फूल :** मैं पूछना चाहता हूं वजीर साहिब से कि :—

यूं तो हर बज्रम में मेरा जिकरे कलाम आता है।

भूल जाता है साकी जब जाम पे जाम आता है।

बतायेंगे क्या वजह है, जनाब ?

**श्री अध्यक्ष :** इस के जवाब की इजाजत दी जा सकती है अगर शेर का जवाब शेर में दिया जाये। (Permission to reply to this supplementary can be given only if the answer is also given in verse.)

**मंत्री :** स्पीकर साहिब आप जानते ही हैं कि फिलबदीह तो कहना बड़ा मुश्किल है। यह तो इन ती पुरानी यादें हैं जो अब ताज़ा हो गई हैं।

(चोधरी रणबीर सिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

**महोदय लल्लम सिंह गिल :** On a point of order, Sir. मैं वजीर साहिब उं पुढा चहुंदा ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਖਾਵਿੰਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

**श्री अध्यक्ष :** आप हमेशा होली और सैंकरिड माहौल में ऐसा एटमासफियर पैदा करने की कोशिश करते हैं। This is not proper for you. (The hon. Member always tries to disturb this holy and sacred atmosphere. This is not proper for him.)

**लोक कर्म मंत्री :** स्पीकर साहिब, गुस्ताखी माफ हो। मैं इन शब्दों की तबक्को उन माननीय सदस्यों से तो कर सकता हूं जो सामने बेंचों पर बैठे हैं मगर मैं  
10.00 a.m. | आप की बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे दोस्तों को अपनी जगह रखा जाए मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा में खेड़ा गांव है जहां के कश्मीर की लड़ाई में लड़ने वाले लेफ्टीनैंट जनरल कटोच हैं। उस गांव के कई भाई शहीद भी हुए हैं। वह काफी बड़ा गांव है। वहां चीफ मिनिस्टर साहिब और मैं गए थे।

**परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री :** जो थोड़ा वक्त मिला उस में मैंने यह लिखा है :

रह कर कांग्रेस में साकी व मैं का जिक्र करते हैं।

न यहां साकी न मैं है सिर्फ कामराज का फिकर करते हैं।

**काभरेड जंगीर सिंह नेगा :** कौ वजीर साहिब एह दमटगे कि जिनुं नुं वीर चक्र अउ पदम वीर चक्र मिले हन एह उनुं ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

मंत्री : मैं इसका जवाब नहीं दे सकता । कोशिश तो करते हैं हर जगह जाने की ।

श्री मंगल सैन : आन. ए. प्वायंट आफ आर्डर, सर। अभी २ हाउस में ट्रांसपोर्ट मनिस्टर साहिब कह रहे थे कि कांगड़ा जिला में नहीं गए लेकिन चौधरी रणबीर सिंह ने कह दिया है कि हम गए थे । हम किस को ठीक मानें और किसको गलत मानें ।

**Ex-gratia grants for Army Personnel killed or wounded during India-Pak Conflict**

\*8907. **Shri Rup Singh Phul :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount of ex-gratia grants so far given tehsil-wise, by the State Government to (i) the Jawans/Officers of the Armed Forces wounded during the recent India-Pak conflict and (ii) the relatives of those Jawans/Officers who were killed during the said conflict ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon** (Transport and Elections Minister) :  
(i) Nil.

(ii) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Name of Tehsil	Amount of ex-gratia grant paid to Officers/ Jawans
<b>Ambala District</b>	
	Rs,
Ambala	7,500
Jagadhri	3,000
Naraingarh	5,500
Kharar	10,500
Rupar	8,500
Nalagarh	500
<b>Rohtak District</b>	
Rohtak	12,000
Jhajjar	22,500
Sonepat	5,500
Gohana	5,000
<b>Kapurthala District</b>	
Kapurthala	7,500
Sultanpur	1,500
Phagwara	500
<b>Karnal District</b>	
Karnal	11,000
Panipat	9,000

Nxme of Tehsil		Amount of <i>ex-gratia</i> grant paid to Officers/ Jawans	
Thanesar	Karnal District concld	..	2,250
Kaithal		..	10,500
	<b>Bhatinda District</b>		
Bhatinda		..	4,500
Mansa		..	7,500
Faridkot		..	3,500
	<b>Mohindergarh District</b>		
Mohindergarh		..	13,750
Dadri		..	14,500
Narnaul		..	7,500
	<b>Hoshiarpur District</b>		
Hoshiarpur		..	18,000
Garhshankar		..	30,000
Dasuya		..	16,000
Una		..	13,500
	<b>Gurgaon District</b>		
Gurgaon		..	5,500
Rewari		..	10,500
Palwal		..	3,000
Ballabgarh		..	2,500
Nuh		..	2,500
Ferozepore Jhirka		..	500
	<b>Sangrur District</b>		
Sangrur		..	3,000
Malerkotla		..	3,500
Barnala		..	4,000
Narwana		..	2,000
Jind		..	1,500
	<b>Ferozepore District</b>		
Ferozepore		..	1,000
Fazilka		..	1,000
Zira		..	4,500
Moga		..	11,500
Muktsar		..	1,500
	<b>Patiala District</b>		
Patiala		..	4,000
Sirhind		..	3,000
Nabha		..	2,500
Rajpura		..	6,000
	<b>Simla District</b>		
Kandaghat		..	1,000
	<b>Hissar District</b>		
Hissar		..	1,000
Hansi		..	5,000

## [Transport and Elections Minister]

## Hissar district—CONCLD

Bhiwani	..	9,000
Fatehabad	..	1,000
Sirsa	..	1,500

## Amritsar district

Amritsar	..	8,280
Patti	..	1,500
Ajnala	..	15,740
Tarn Taran	..	20,000

## Jullundur district

Jullundur	..	32,500
Nawanshahr	..	28,000
Phillaur	..	2,000
Nikodar	..	14,000

## Kangra district

Dehra	..	14,000
Palampur	..	18,000
Hamirpur	..	29,500
Nurpur	..	13,500
Kangra	..	15,000

## Kulu district

Kulu	..	4,000
------	----	-------

## Ludhiana district

Ludhiana	..	11,720
Jagraon	..	9,050
Samrala	..	9,490

## Gurdaspur district

Gurdaspur	..	25,000
Batala	..	16,500
Pathankot	..	14,000

श्री रूप सिंह फूल : क्या माननीय मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि जब एक्सप्रेसिया ग्रांट देने की बारी आती है तो मैदानी इलाका में एक दम शुरू हो जाती है लेकिन जिला कांगड़ा में देर से दी जाती है, इस की क्या वजह है ?

मन्त्री : सब जगह ठीक है, इन को गलती लग गई है। सब जगह एक वक्त काम शुरू हुआ था।

**Relief to Jawans/Officers belonging to Una Tehsil killed during  
India-Pak Conflict**

**\*9048. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number and names of Jawans and military officers belonging to tehsil Una, district Hoshiarpur, who were killed during the recent India-Pak conflict, block-wise ;

- (b) the nature of relief so far granted by the State Government to the family of each martyr mentioned in (a) above ;
- (c) whether the Government has received any representation from the representatives of the people requesting the Government to raise memorials in each of the villages to which more than two martyrs belonged; if so, the action taken or intended to be taken in this connection ;
- (d) whether the Government intend to start some permanent institutions for the benefit of the (i) families of the martyrs, and (ii) the injured and other military personnel in this backward hilly area of the Dogras ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon** (Transport and Elections Minister):

- (a) It is not in public interest to disclose the information asked for.
- (b) A statement showing the details of relief admissible to families of armed forces personnel killed during the Indo-Pak. conflict is laid on the Table of the House.
- (c) No.
- (d) No.

#### STATEMENT

##### (1) EX-GRATIA GRANTS :—

	Rs.	
(i) Officer	.. 5,000	Rs. 500 is paid in cash and the balance in the form of National Savings Certificates. In hard cases, the whole or a part of the balance may also be paid in cash.
(ii) J.C.O.	.. 3,000	
(iii) Other rank	.. 2,000	

#### EDUCATIONAL CONCESSIONS

The Children of the afore-said personnel will be entitled to free education i.e., no fees will be charged from the children in schools and colleges, including professional institutions. In addition to it, such children will be given allowance at the following rates beyond the period of 7 years, as the Government of India has enhanced the family pension rates to 2/3rd of the pay last drawn for a period of 7 years :—

	Rs. per month
(i) At the Primary stage	.. 10
(ii) At the Secondary stage	.. 25
(iii) During the College/Arts and Science	.. 50
(iv) In the case of Technical and Professional Education	.. 75
(v) For higher education in foreign countries	.. 250

**पंडित मोहन लाल दत्त:** तहसील ऊना में कुछ देहात ऐसे हैं जहां के दो या तीन एक एक गांव के शहीद हुए हैं। तो क्या देश-भक्तों को प्रेरना देने के लिए और देहात की होसला अफजाई के लिए सरकार उन शहीदों की यादगार के सिलसिले में कोई मेमोरियल बनाने के लिये तैयार है या नहीं या अगर लोग बनाएं तो उस में सरकार इम्दाद देने के लिये तैयार है ?

**मन्त्री :** अभी तक तो किसी गांव की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई लेकिन ऐसी जरूर आइ है कि किसी स्कूल या किसी लाइब्रेरी का नाम उन शहीदों के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन अभी कुछ तजवीजें ऐसी हैं जिन पर गौर किया जा रहा है कि उन के नाम को किस बेहतरीन तरीके से कायम रखा जा सकता है।

**Salaries to the Staff in the Office of the Assistant Registrar,  
Industries, Malerkotla**

**\*8835. Comrade Bhan Singh Bhaurya :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the staff working at present in the Office of the Assistant Registrar, Industries, Malerkotla, have not been paid their salaries for the last six months ; if so, reasons therefor ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister):** No. The salaries of the staff have since been disbursed upto 31st December, 1965.

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ :** ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 31 ਮਈ, 1965 ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

**ਮੰਤਰੀ:** ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੁਛ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਗ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੌਸ਼ :** ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਗੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੋਬਾਰਾ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ।

**Opening of Industrial Training Institute at Amb in Tehsil Una,  
District Hoshiarpur**

**\*8869. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister with reference to the reply to Starred Question No. 6887, included in the list of Starred Questions for 5th March, 1965 be pleased to state—

- (a) whether a final decision to start an Industrial Training Institute at Amb in tehsil Una, a backward hilly area, has since been taken ; if so, the time by which it is likely to be opened there ;
- (b) whether the Government is aware of the fact that no such facility is available in the vast hilly areas of Gagret and Amb Blocks in Una Tehsil and there is a great demand for the same ;
- (c) whether it is a fact that the Hilly Area Organisation in its report had recommended the opening of such an Institute at Amb or Gagret?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister) :**

(a) No.

(b) At present, three Industrial Training Institutes are already functioning at Talwara, Nangal and Hoshiarpur, which cater to the needs of hilly areas of Gagret and Amb blocks in Una Tehsil.

(c) Yes, at Amb.

**ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ :** यह जो हिल्ली एरिया आर्गनाइज़ेशन ने रिफ रिश की है कि अम्ब में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट खोला जाये, क्या उन की रिफ रिश पर सरकार गौर करेगी या नहीं ?

**मन्त्री :** उन्होंने अम्ब में नया आई. टी. आई. खोलने को मान लिया है।

This was discussed at the meeting with the Chief Minister on 13th May, 1965 where the Development Commissioner was also present. In this meeting the setting up of I.T.I. at Amb was dropped due to the fact that consequent upon the reduction of seats from 21,000 to 10,000 the number of I.T.Is. to be opened in the Fourth Plan was also reduced to 25. However, final sanction of the Government for opening 11 new I.T.Is is still awaited.

उन्होंने आर्गेनाइजेशन की सिफारिश को मान लिया था, लेकिन इस का यह टैक्नीकल पहलू था।

#### **Industrial concerns in which Government have invested in Shares**

**\*8897. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister with reference to the reply to Unstarred Question No. 2874 included in the List of Questions for 11th October, 1965, be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that some of the Directors of different concerns appearing at numbers 1 to 7 mentioned in Part (b) of the said reply have been on the black-list of the Industries Department/Punjab Government ; if so, their names, the names of the concerns of which they are Directors at present and the date/dates when their names were brought on the black-list together with the date of removal of their names from the black-list ;
- (b) the circumstances under which names were brought on the black-list ;
- (c) whether the statement, black-listing the said persons was circulated to the different offices of the Industries Department or other Government Departments concerned, ; if so, when; if not, the reasons therefor ; ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon** (Transport and Elections Minister)

(a) No. (b) and (c) Does not arise.

**कामरेड राम प्यारा :** क्या मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूँ कि उन्होंने इस में कोई भी तरीका अख्तियार नहीं किया तो मैं किस तरह मान लूँ कि यह जो आईटम नम्बर 5 पर सरदार रौनक सिंह का नाम है जो भारत ट्यूब फैक्टरी को रिप्रिजेंट करते हैं। क्या वह ब्लैक लिस्ट पर नहीं रहे ?

**उद्योग तथा पहाड़ी क्षेत्र उप मन्त्री :** जो ऐसी फर्म होती है उन के खिलाफ 4 किस्म का एक्शन लिया जाता है। एक तो यह कि उसे एपर्बुड फर्मों की लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है दूसरे उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तीसरे उस के खिलाफ इन्क्वायरी के दौरान माल लेना सस्पेंड कर दिया जाता है चौथे उस फर्म से बिजनेस खत्म कर दिया जाता है। जहां तक रौनक सिंह एण्ड कम्पनी का ताल्लुक है इस को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सन् 1962 में सस्पेंड किया और उन के खिलाफ इन्क्वायरी शुरू की उस वक्त हम को उन्होंने इत्तलाह दे दी। मगर गवर्नमेंट के बेसिक एग्रीमेंट्स हैं उन के मुताबिक जब फर्म के खिलाफ एक्शन लेते हैं तब उस को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। 1964 में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक्शन लिया। जो लिस्ट शाया की उस में रौनक सिंह एंड कम्पनी का नाम

[उप मन्त्री]

फिर शामिल करके की गई। जो इन्क्वायरी की गई उसमें फर्म के खिलाफ कोई बात नहीं आती इसलिये उस फर्म का नाम दुबारा आया और पंजाब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया।

**कामरेड राम प्यारा :** मन्त्री महोदय ने बताया था कि 1963 में सस्पेंड किया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि आया उस वक्त कोई मयाद मुक़र्र की गई थी कि वह कितने अरसे तक ब्लैक लिस्टड रहेंगे और क्या उस पीरियड के गुज़र जाने के बाद उन का नाम इनक्लूड किया गया था।

**उप-मन्त्री :** 1963 में उन्हें सस्पेंड किया गया था ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था। इस लिए पीरियड वगैरा फिक्स नहीं किया गया था।

**श्री मंगल सेन :** मन्त्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया था। मगर 1964 में उन का नाम फिर आ गया है। मैं सपैसिफिकली पूछना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उन को निर्दोश करार दिया था और उस के बाद उन का नाम इनक्लूड किया है।

**Minister for Transport and Elections :** The order, dated 17th February, 1963 was for suspension and not for black-listing.

**श्री मंगल सेन :** मन्त्री महोदय ने गोल सा जवाब दिया है। मैंने सपैसिफिकली पूछा था कि क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उस फर्म को निर्दोश करार दे दिया था।

**उद्योग तथा पहाड़ी क्षेत्र उप-मन्त्री :** उन को सस्पेंड पंजाब सरकार ने नहीं किया था बल्कि हिन्द सरकार ने किया था और चूँकि हिन्द सरकार ने बाद में इंटीमेट कर दिया था इस लिए पंजाब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लेना था।

**कामरेड राम प्यारा :** क्या यह हकीकत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार को लिखा था कि रौनक सिंह एंड कम्पनी के साथ पंजाब सरकार डीलिंग न रखे। पंजाब सरकार ने इस के बावजूद भी उन को रुपया ऐडवांस किया जब कि फाईनेंस डिपार्टमेंट ने रोका था कि उन को रुपया मत ऐडवांस करो।

**परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री :** इस सवाल के लिये अलहदा नोटिस दीजिये।

#### Allocation of Controlled Commodities to a certain Firm at Chandigarh

\*8898. **Comrade Ram Piara .** Will the Chief Minister with reference to the reply to Starred Question No. 8526 included in the list of Questions for 11th October, 1965 be pleased to state—

(a) whether the enquiry report which was being processed and examined as stated in reply to part (c) of the said question has since been finally processed and examined ; if so, when together with the result thereof, if not, finally processed or examined, the reasons therefor ;

(b) whether as a result of checking by the Deputy Director, Industrial, Technical Expert Mechanical Engineering and A. D. I. Chandigarh referred to in part (f) of the said reply, it was found that the controlled commodities allotted to M/s Rakesh Industries, Chandigarh, mentioned in reply to part (b) of the

said question, had not been utilised properly, if so, the action taken in the matter ;

- (c) the allocation, if any, made to -M/s Rakesh Industries, Chandigarh over and above those indicated in Annexure I referred to in part (d) of the said reply together with the details of the quantity and its cost or value of Essentiality Certificate etc.

**Sardar Gurdial Singh Dhillon** (Transport and Elections Minister) :

- (a) The detailed investigations by the police are in progress.  
(b) The question of taking action will be considered after the completion of the investigations.  
(c) Nil.

**कामरेड राम प्यारा :** क्या वजीर साहिब बताएंगे कि डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ की इन्क्वायरी के बाद केस पुलिस के हवाले किया गया है।

**मन्त्री :** हां जी, उन की रिपोर्ट चली गई है और पुलिस के पास है।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** पिछले सेशन में बताया गया था कि डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ इन्क्वायरी कर रहे हैं मगर अब कहा गया है कि पुलिस इन्क्वायरी कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ की इन्क्वायरी जारी है या बन्द कर दी गई है।

**मन्त्री :** जो डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज़ ने रिपोर्ट दी थी उस की बिना पर जो बात थी वह **D. I. G., Police** को इन्वैस्टीगेशन के लिए भेज दी गई है।

**श्री मंगल सेन :** क्या मन्त्री सहोदय बताएंगे कि राकेश इंडस्ट्रीज़ चंडीगढ़ जिस के मालिक श्री हंस राज शर्मा हैं उस की इन्क्वायरी पुलिस में कब दी गई थी और वह कब तक पूरी होने की आशा है।

**मन्त्री :** कोशिश तो यह है कि जल्दी से जल्दी हो जाए।

**कामरेड राम प्यारा :** क्या मन्त्री सहोदय बताएंगे कि डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ ने यह रिपोर्ट की थी कि यह केस पुलिस इन्वैस्टीगेशन के काबल है क्योंकि प्राइमा फेसाई केस एस्टैबलिश होता है।

**मन्त्री :** हां जी, तभी तो पुलिस के हवाले करने की ज़रूरत पड़ी थी।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੰਸ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹੋ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਮਗਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਗਿੱਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਡਨੋਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਸਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ncu

ਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬਾਲ :** ਅਗਰ ਆਪ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੋਨਾ ਫਾਇਡੀਜ਼ ਪਰ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲਕੀ ਆਪ ਦੀ ਬੋਨਾ ਫਾਇਡੀਜ਼ ਪਰ ਵੀ ਕਵੈਸ਼ਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰੁ ਹਾਊਸ ਇਸ ਪਰੀਯੋਪਸ਼ਨ ਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਂ ਇਸ ਪਰ ਫਰਦਰ ਕਵੈਸ਼ਚਨ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਰ ਜੋ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਵਰੁ ਸਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਰਾਧਰਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ।

(If the hon. Member doubts the bona fides of the hon. Minister, then next time his own bona fides can also be questioned. This House proceeds on the presumption that whatever information is supplied by the Minister in reply to his question is correct and it is not proper to question its veracity. Whatever the hon. Member says and whatever information the hon. Minister supplies, become the property of the House).

**ਸੰਤ੍ਰੀ :** ਮੈਂ ਇਸ ਸੇ ਝਯਾਦਾ ਆਨੇਸਟ ਆਰ ਕਯਾ ਜਵਾਬ ਦੂਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਧਰੁ ਪੈਂਡ ਆਪ ਕੀ ਦੇਂਦਾ ਹੂੰ ਆਰ ਆਪ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਿਖਾ ਲੇਂ।

**ਡਾ॰ ਕਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਕਯਾ ਕਜੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਆਰ ਚੌਠ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬੀਚ ਜੋ ਲੇਟਿਸਟ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਏਂ ਹੈਂ ਉਸ ਕੀ ਧਯਾਨ ਮੇਂ ਰਖਤੇ ਹੁਏਂ ਸਰਕਾਰ ਧਰੁ ਇਨਕਵਾਰੀ ਕਬ ਤਕ ਵਿਦਫ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਹ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸੇ ਨਾਮ ਵਿਦਫ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾ?

**ਚੌਧਰੀ ਇਨਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਿਕ :** ਕਯਾ ਧਰੁ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇਤਲਾਹ ਇਸ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਯੋਂਕਿ ਵਰੁ ਕੈਰੀਂ ਗੁਪ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁਏਂ ਆਰ ਵਰੁ ਅਬ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲੇ ਹੁਏਂ ਹੈਂ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** It is a serious thing. The gentleman who has been referred to by the honourable Member is not present in the House. He is being brought into the picture unnecessarily. That is bad.

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਧਿਆਰ :** ਧਰੁ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਧਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਨਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਜੋ ਅਬ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਨ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਏਂ ਜਾਹਿਰ ਹੋਤੇ ਹੈਂ?

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਸੋਰ)

**Mr. Speaker :** Will you please withdraw your remarks? You have made an insinuation against an organisation which is not desirable. This has nothing to do with the Question. He may be a General Secretary or anything else.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ .....

**Mr. Speaker :** Please withdraw your remarks. You have made some insinuations against an organisation.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਚੰਗਾ ਜੀ, ਵਿਦਤਰਾ ਕੀਤਾ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਗੁਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਨੂੰ ਲਕੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

**Mr. Speaker :** This is no point of order.

**ਭੀ ਸ਼ੋਸ਼ ਰਜ਼ਾਜ਼ ਅਖਿਰਹੋਤੀ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਕਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂ ਉਸ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਂਡ ਕਵੈਸ਼ਚਨ ਨੰ 0. 8526 ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀ ਲਿਖਾ ਥਾ ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

**ਕਮਰੇਡ ਰਾਮ ਧਾਰਾ :** ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਕਵਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਨ ਕਿਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਡ ਦੇ ਪੈਡ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਐਂਡ ਧੰਨਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡ ਨੋਟ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਿਪਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਏਗੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੰਕਵਾਇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

**ਕਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇੰਟ ਰਿਸਪਾਂਸੇਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗੁਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਲੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸੇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

### Foreign Industrial Collaborations

**\*9174. Sardar Bulwant Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number and names of the foreign industrial collaborations which the Liaison Officer, Industries and the State Agent in Delhi has procured for the State during the year 1965-66 and expects to procure during 1966-67 ;
- (b) the number and names of new industrial projects which the department formulated and decided to execute during the last two years ?

**Sardar Gardial Singh Dhillon** (Transport and Elections Minister) : (a) The Liaison Organisation in Delhi has been contacting Embassies, Economic Consuls, Trade Representatives of foreign countries as well as representatives of foreign collaborates in India in regard to collaboration for a various projects sponsored by the State Government e.g., pig iron, power tillers, heavy electricals, steel castings etc., Out of these, the case of Pig Iron Project along has reached the final stage, while others including the selection of collaborators, are under consideration :

(b) A list of public sector and State sponsored industrial projects the industries Department has had in hand for the last two years is enclosed. A preliminary start to sponsor these projects for licencing, except the power tillers and Oscilloucope projects, was made in 1963, but the detailed planning for setting up all the various projects under taken during the years 1964 and 1965 is still in progress.

**List showing the public sector and State Sponsored Industrial Projects—**

1. Pig Iron.
2. Seamless Tubes.
3. Machine Tools.
4. Steel Forgings.
5. Heavy Electricals
6. Power Till rs.
7. Oscilloscope.
8. Steel Castings.

**Sardar Balwant Singh** : I would like to know specifically as to what are the hurdles before the Government for the completion of these Projects and also the total expenditure which the Punjab Government is incurring for the maintenance of the Liaison Officer.

श्री अध्यक्ष : अगला स्ताल श्री फतेह चन्द का है। इसके बारे में मेरे पास सरदार अजमेर सिंह जी से रिकवैस्ट आई है कि यह स्वाल चीफ मिनिस्टर साहिब को रिफ्रेट नहीं करता यह उनका है और चूकि जवाब देने के लिये आज उन का दिन नहीं है। इस लिए अगले दिन के लिए जब उनकी टर्न हो पोस्टयोन कर दिया जाए।

So this Question will be taken up on the proper day.

(The next question is by Shri Fateh Chand Vij. In this connection I have received a request from Sardar Ajmer Singh that since that question relates to him and not to be Chief Minister and that today was not his turn to answer questions that question be postponed till his turn to answer questions comes. So this question would be taken up on the proper day).

**Sardar Balwant Singh** : May I know, Sir, whether my Question has been postponed ?

**Mr. Speaker** : No, please.

**Sardar Balwant Singh** : May I know whether my question has also been postponed ?

**Mr. Speaker** : I am sorry, not.

**Pandit Chiranji Lal Sharma** : You had been pleased to call Shri Fateh Chand Vij to put his question. Has his question been postponed ?

**Mr. Chairman** : His question will be taken up on the appropriate date.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON  
THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Officials working on deputation to the Pepsu Road Transport Corporation,  
Patiala

**\*8834. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the total number and names of the employees of other departments working on deputation at present in the administrative section of the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala ;
- (b) the grade of pay of each of the said employees in his parent department together with his present grade of pay ;
- (c) the date from which each of the said employees has been working in the said administrative section, and the reasons for keeping them on deputation?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a), (b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

ANNEXURE 'A'

STATEMENT

- (a) (1) Shri Raj Krishan Khanna, General Manager.
- (2) Shri Om Parkash Bhardwaj, Chief Accounts Officer.
- (3) Shri Siri Ram, Resident Auditor.
- (4) Shri Wishan Dass Bhatia, Office Superintendent.
- (5) Shri Om Parkash Dhundia, Assistant Accountant.
- (6) Shri Om Parkash Moudgil, Assistant Accountant.
- (7) Shri Jagdish Ram, Record Lifter.

(b) *Grade.—*

*In parent Department*

*Present*

- |   |   |
|---|---|
| 1. Rs 600—40—800—40—920—40—1000—50—1200   | Rs 600—40—800—40—920—40—1000—50—1200 plus 20 percent deputation pay   |
| 2. Rs 250—25—500/30—650                   | .. Rs 250—25—750  |
| 3. (i) Rs 175—15—295/15—400 (Substantive) | The Corporation scale for S.A.S. is 200—15—380/20—500 but the present incumbent has been allowed substantive scale of Rs 175—15—295/15—400 plus 20 per cent deputation allowance as per terms of deputation |
| (ii) Rs 200—15—380/20—500 (Officiating)   |   |
| 4. Rs 300—20—400                          | .. Rs 300—20—400 plus 20 per cent deputation allowance on substantive pay i.e., Rs 250.   |
| 5. Rs 80—5—150                            | .. Rs 100—10—250  |
| 6. Rs 60—4—80/5—120/5—175                 | .. Rs 100—10—250  |
| 7. Rs 30— $\frac{1}{2}$ —35               | .. Rs 30— $\frac{1}{2}$ —35   |

- (c) (1) 2nd February, 1963 (Now under orders of transfer)
- (2) 14th November, 1963.
- (3) 31st October, 1962.
- (4) 15th December, 1965.
- (5) 16th October, 1956.
- (6) 31st October, 1956.
- (7) 21st November, 1957.

Their retention is in the interest of the Corporation.

**Complaint against the Samundri Transport Co., Private,  
Ferozepore**

**\*8866. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state whether he has received any intimation from the Sub-Divisional Magistrate, Faridkot, district Bhatinda, regarding complaints made to him about over-charging of fares by the New Samundri Transport Company (P) Ltd., Ferozepur during the India-Pakistan conflict ; if so, the action so far taken thereon ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (i) No.

(ii) Does not arise.

**Punjab Roadways Bus Stand, Amritsar**

**\*8919. Shri Balramji Das Tandon :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred on the Punjab Roadways Bus Stand Amritsar and the income derived therefrom upto date, under different heads separately ;

(b) whether it is a fact that Rickshaws and Tongas have to pay for entry into the premises of the said Bus Stand in spite of the fact that rickshaws and tongas in Amritsar ply after paying a licence fee, if so, the reasons for charging a fee for entering into the premises of the Bus Stand ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) Rupees 9,19,600 *plus* the cost of the land which is still to be determined.

(b) The rickshaws and tongas do not have to pay for entry into the premises of the bus stand. To exercise proper control, the rickshaws/tongas stand was leased-out, and a fee of 5 paise per trip or 25 paise per day per rickshaw and 10 paise per trip or 50 paise per day per tonga is charged per loaded out going rickshaw/tonga by the leasee of the rickshaws/tongas stand.

**Income And Expenditure of Punjab Roadways etc.**

**\*8920. Shri Balramji Das Tandon :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the total income and expenditure of the Punjab Roadways, Pepsu Road Transport Corporation and the Kulu-Mandi Transport Corporation for the last three Financial Years ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** A statement is laid on the Table of the House

**STATEMENT**

**PUNJAB ROADWAYS**

Year		Income	Expenditure
1962-63	..	4,20,84,495	2,83,30,071
1963-64	..	5,54,06,423	3,71,27,437
1964-65	..	5,54,06,423	4,46,58,423

**PEPSU ROAD TRANSPORT CORPORATION**

1962-63	..	87,04,930	65,35,845
1963-64	..	1,03,03,273	88,88,978
1964-65	..	1,21,53,225	1,19,85,266

**MANDI KULU ROAD TRANSPORT CORPORATION**

1962-63	..	28,40,416	28,29,910
1963-64	..	40,86,985	38,52,240
1964-65	..	52,24,401	51,58,886

**Applications for Energising Tubewells**

**\*8838. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the total number of applications for energising tubewells received by the authorities during the period from 1st April, 1965 to 31st December, 1965 in the State, districtwise ;
- (b) the total number of applications for energising of tubewells in respect of which electric connections were not given up to 31st March, 1965 ;
- (c) the total number of tubewells energised from 1st April, 1965 to 31st December, 1965 district-wise ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) District-wise information is not maintained.

However Division-wise information is laid on the Table of the House.

(b) 14,923.

(c) Statement is laid on the table of the House.

**The Division-wise split up of applications for Agricultural Connections received during the period from 1st April, 1965 to 31st December, 1965**

Serial No.	Name of Division	Number of applications received
1	Amritsar	380
2	Tarn Taran	378
3	Batala	538
4	Dharamsala	2
5	Gurdaspur	335
6	Joginder Nagar	..
7	Jullundur/East	311
8	Jullundur/West	968
9	Phagwara	859
10	Hoshiarpur	667
11	Ferozepur	598
12	Ludhiana City -1	338
13	Ludhiana Suburban-2	393
14	Moga	660
15	Muktsar	175
16	Ganguwal	46
17	Dhulkot-2	740

## [Transport and Elections Minister]

Serial No.	Name of Division	Number of applications received
18	Ambala-I	.. 1,393
19	Chandigarh	.. 30
20	Solan	.. 11
21	Karnal	.. 1,333
22	Hissar	.. 733
23	Bhiwani	.. 472
24	Panipat	.. 697
25	Delhi	.. 262
26	Faridabad	.. 169
27	Gurgaon	.. 1,017
28	Rohtak	.. 265
29	Patiala	.. 364
30	Rajpura	.. 362
31	Nabha	.. 560
32	Khanna	.. 598
33	Sangrur	.. 671
Total		.. 16,295

## ANNEXURE 'B'

## STATEMENT

TUBEWELLS ENERGISED FROM 1.4.65 to 31.12.65

District-wise

Serial No.	Name of District	Tubewell connections given from 1-4-65 to 31-12-65
1	Patiala	.. 357
2	Sangrur	.. 370
3	Ambala	.. 550
4	Karnal	.. 1,188

Serial No.	Name of District	Tub well connections given from 1-4-65 to 31-12-65
5	Rohtak	328
6	Hissar	211
7	Gurgaon	559
8	Mohindergarh	254
9	Ludhiana	626
10	Ferozepur	3 1
11	Bhatinda	1 0
12	Amritsar	599
13	Gurdaspur	427
14	Kangra	3
15	Kulu	2
16	Jullundur	639
17	Kapurthala	294
18	Hoshiarpur	348
Total		7,236

**Tubewell connections applied for up to 31st October, 1964**

**\*8839. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state —

- whether it is a fact that the Government had announced that electric connections would be provided by 31st March, 1965 to those tubewells applications in respect of which had been received up to 31st October, 1964 ;
- whether all the tubewells mentioned in part (a) above have been energised, if not, the total number of applications with the authorities as on 31st October, 1964 and the number of such applicants who have been given tubewell connections ;
- whether the Government has taken any action against the officials of the Punjab State Electricity Board who have not given connections to the tubewells in accordance with the announcement referred to in part (a) above, if no action has been taken the reasons therefor ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

**Electrification of Village Nihal Singhwala, district Ferozepur**

**\*8864. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state whether he received any application for the electrification of village Nihal Singhwala a pocket village in district Ferozepur, if so, the steps so far taken by the authorities for the electrification of the said village?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** No such application has been received. Apart from this, Nihal Singhwala is not a pocket village in the sense that no 11 kV line connecting other villages passes by or around it.

**Electric Connection for Tube-wells**

**\*8959. Sardar Balwant Singh :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state —

- (a) the total number of tubewells where motors have been fitted and pumps have been bored but which are not working due to lack of electric connections in the State ;
- (b) the proposal, in detail, if any, of the Electricity Board to energise the said tube-wells and the period within which these are proposed to be energized ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) 3,923.

(b) The Board has fixed a target to energise as many as 11,000 Tube-wells during 1965-66 and the connections are being given in turn subject to availability of material and funds.

**Villages in Tehsil Zira, district Ferozepore affected by Indo-Pakistan Conflict**

**\*8954. Sardar Balwant Singh :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state —

- (a) whether Government has recently received a representation from the residents of Bharan, Kohala, Hamidwala and Borawali of Tahsil Zira, district Ferozepore, stating *inter alia* that these villages are within a distance of 10 miles from the International border with Pakistan ; if so, the details of the said representation ;
- (b) whether Government have in view of the fact that the said villages are within a radius of 10 miles from the International border taken steps to provide relief and rehabilitation facilities to the residents of the said villages in accordance with the policy enunciated by it after the Indo-Pakistan hostilities ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) Yes, a copy of the representation, dated the 13th January, 1966 is placed on the Table of the House.

(b) Yes, relief in the form of full remission of land revenue and abiana has been granted in respect of these four villages and the recovery of Government dues, e.g. taccavi loans has also been stayed till further orders.

To

The Hon'ble Minister for Relief and Rehabilitation, Government of Punjab, Chandigarh.

**Subject.**—Application for remission of land revenue and abiana and stay of the realisation of the same in villages of (1) Bharana, (2) Kohala, (3) Hamidwala Uttarh, and (4) Borawali, tehsil Zira, district Ferozepur.

It is most respectfully submitted as under :—

1. That the applicants are residents of Tehsil Zira in Ferozepore District and represent the villages of (i) Bharana, (ii) Kohala, (iii) Hamidwala Uttarh, and (iv) Borawali.

2. That all the four villages stated above are situated within a distance of less than 8 miles from the international border between India and Pakistan.

3. That the whole of this area has been seriously affected by the recent war between the two countries. Crops have been damaged considerably due to action of the enemy, movement of troops and lack of irrigation water.

4. That, the State Government,—vide its notification No. 7125-26 W 65 dated 1st October, 1965 has issued instructions to the Deputy Commissioner, concerned that in the case of villages situated within a distance of 10 miles from the international border in the districts of Ferozepore and Amritsar, full remission of land revenue and abiana is to be sanctioned.

5. That in the case of all the villages situated within a distance of 10 miles from the border in tehsil Ferozepore, the authorities have included these villages in the list of villages prepared for sanctioning full remission of land revenue and abiana. Some of the villages in Ferozepore Tehsil, which have been included in this 10 miles belt of operational villages are more distant from the international border than the villages of the applicant, e.g. village Ratta Khera Gulab Singh is situated at a distance of about 10 miles whereas the distance of Bharana from the border is only 8 miles. Similar is the case with village Sur Singh Wala and Faridwala.

6. That all the villages of Ferozepore tehsil falling within this 10 miles belt of operational villages have been included in the list for the purpose of sanctioning full remission of land revenue and abiana without any exception, whereas no village from Zira Tehsil has been included in this list inspite of the fact that villages of Zira tehsil stated above are similarly situated within 10 miles belt of operational villages.

7. That the applicants have approached the Deputy Commissioner, Ferozepore more than once for the said purpose but he has, without any reason flatly declined to give the relief prayed for.

8. That this treatment being meted out to the applicants at the hands of the Deputy Commissioner, Ferozepur, is purely arbitrary and discriminatory. There is absolutely no justification in denying the same relief to the applicants villages which have been already granted to other similarly situated villages in the Ferozepore Tehsil. Instead thereof, the authorities are compelling the people of these villages to immediately pay all these dues on account of land revenue and abiana, and are being harassed by the authorities.

9. That in addition to the loss caused to the crops in these villages due to the recent war and lack of irrigation water, the crops have been further damaged considerably due to the absolute failure of rain fall in the district, and under the circumstances, the agriculturists residents of these villages, have been rendered penniless and they have no provisions to live upon and to feed their dependents and cattle.

10. That in view of the above circumstances, the residents of these villages cannot survive unless the State Government help them effectively by sanctioning the full remission of land revenue and abiana and granting them loan facilities at easy terms.

It is, therefore, respectfully prayed, that the above stated villages of Zira Tehsil, i.e., Bharana, Kohala, Hamidwala, Uttarh and Borawali may kindly be ordered to be included in the list of operational villages situated within a distance of 10 miles from the border and full remission of land revenue and abiana may kindly be granted. The realisation of the dues on account of land revenue and abiana may kindly be stayed with immediate effect.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Sd.)- Autar Singh.

Dated 13th January, 1966.

(Sd.)- Balwant Singh.

**Nihalsinghwala-Ramgarh Road in district Ferozepore**

**\*8862. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the time by which the Nihalsinghwala Ramgarh road in district Ferozepore is scheduled to be completed ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** The road is likely to be completed in the Fourth Plan subject to availability of funds.

**Roads proposed to be constructed in Hoshiarpur District during the Fourth Five-Year Plan Period**

**\*8891. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

- (a) the names of the roads proposed/decided to be constructed in Hoshiarpur District during the Fourth Five-Year Plan period ;
- (b) the names of the village approach roads intended to be taken up in the said district during the said period ;
- (c) whether the hilly area of tehsil Una, at present having inadequate and unsatisfactory means of communication, has been given special and preferential treatment in this respect in the said Plan ; if so, the details of the allocation of funds made for this purpose ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** (a) and (b) Fourth Plan proposals for Roads have not yet been finalised.

(c) Allocation of funds are not made tehsilwise. Hill Areas as a whole are being given due weightage.

**Karnal-Kachhwa-Sambhali Kaul Road**

**\*8894. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

- (a) whether it is a fact that the construction of the Karnal Kachhwa-Sambhali Kaul Road was sanctioned in the year 1964 ; if so, the total amount so far sanctioned for its construction ;
- (b) whether any request or communication from any Legislator of Karnal District for allotment of more funds for the construction of the said road has been received by the Public Works Minister ; if so, the contents thereof ;
- (c) the total estimated cost of construction of the said road together with the mileage to be constructed according to the present sanction ;
- (d) the progress of work so far made on the said road together with the approximate amount so far spent thereon ;
- (e) the number of miles on which construction work is now being done and the mileage expected to be completed by the end of financial year 1965-66 ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** (a) Yes. Total amount sanctioned for the years 1964-65 and 1965-66 is Rs 10,000 and Rs 17,000 respectively.

(b) Yes. A copy of the communication is laid on the table of the House.

(c) Estimated cost of the Road is Rs 20,00,000 with a total mileage of 20 miles.

(d) Earthwork in mile 1.5 is in progress. Bridges and culverts in first two miles are nearing completion. Stone metal is also being collected in first two miles. A sum of Rs 45,500 has been spent by diverting funds from other works.

(e) Work in first five miles is in progress. Earthwork and collection of bricks completed in first five miles during the current financial year. Bridges and culverts and collection of stone metal is likely to be completed in first two miles during the current financial year.

*Copy of letter dated the 2nd December, 1965, from Shri Ram Piara Comrade, M.L.A., addressed to Ch. Ranbir Singh, Public Works Minister, Punjab, Chandigarh*

**Subject.**—Allocation of funds for Karnal-Kachhwa-Sambhli-Kaul Road.

The Karnal-Kachhwa-Sambhli-Kaul Road was budgetted in the Budget Session of 1964. The amount was sanctioned only Rs 10,000 though the total cut for the road was twenty lakhs. Again in the current year an amount of Rs 17,000 was budgetted. I had requested the Government and Chief Engineer, Punjab and I was assured that some more money shall be spent on it. I presume that the same must have been done as people of the area have started feeling that some work has been started on this road. This road is very important. This is an old one as the road used to be maintained by the District Board, but the same was a kacha one. The people of this area and myself along with some others have laboured hard for this road and now it is for you to get some good amount not less than five six lakhs in the next budget.

You fully know that Haryana has been and perhaps now is being not given proper share though it deserves more so as to bring it at par with other more advanced and developed districts and hence this road remained neglected for years together. Now the Department is with the Minister who belongs to Haryana. Besides any favourable consideration, even on merit this road deserves at least five six lakhs in the coming budget. Hope that you shall be good enough to do your best as your little effort shall help a thickly populated area.

Hoping to be favoured with a line in reply.

**Construction of Bypass in Amargarh on Nabha-Malerkotla Road**

**\*3928. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to construct a Bypass in Amargarh on the Nabha-Malerkotla road ; if so, the time by which the construction thereof is likely to be completed ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** No, Sir.

**Construction of Ganaur-Shahpur Road in Sonapat and Gohana Tehsils**

**\*9122. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for public Works be pleased to state—

- (a) the year in which the construction of the Ganaur-Shahpur Road in tehsil Sonapat and Gohana was approved ;
- (b) the total amount originally sanctioned for the construction of the said road together with the total amount spent thereon up to 31st January, 1966 ;
- (c) the reasons for which the construction of the said road has not yet been completed, together with the approximate date by which it is likely to be completed ;
- (d) the time by which the bridge on the Western Jamuna Canal near Khubru Fall is likely to be constructed for regular traffic on this road ;
- (e) whether the said bridge is to be constructed by the Buildings and Roads Branch or the Irrigation Branch ;
- (f) whether the estimate for the construction of the said bridge has since been sanctioned ;
- (g) the total length of the bridge and how much of it has since been completed ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** (a) In the year 1956.

(b) Total amount sanctioned for the work is Rs 4,47,500 and the amount spent thereon up to 31st January, 1966 is Rs 4.25 lakhs.

[Public Works Minister]

(c) The road has since been completed except for the bridges on the Western Jamuna Canal, Delhi Branch and parallel Delhi Branch.

(d) The bridge on Western Jamuna Canal is likely to be completed by 1967-68.

(e) By the Buildings and Roads Branch.

(f) Previously there was one canal for which an estimate amounting to Rs 85,900 was sanctioned. Later on a parallel Delhi Branch was constructed by the Irrigation Branch and the total estimate for both the bridges which run side by side is under preparation in B&R Branch.

(g) The total length of each bridge is about 100'. The work has not yet been started.

**Metalling of Gohana-Khanpur Kalan Road in tehsil Gohana  
district Rohtak**

**\*9123. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to metal the Gohana-Khanpur Kalan Road in tehsil Gohana, district Rohtak ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the metalling of the said road has been included in the Fourth Five-Year Plan ;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether the work on the above-mentioned road is likely to be taken in hand in the 1st year of the said Plan ;

(d) whether any estimate of the total cost to be incurred on the said road has since been prepared, if so, the details thereof ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** (a) Yes.

(b) It is proposed to be included in the tentative proposal of the Fourth Five Year-Plan .

(c) Efforts will be made to take up the works of tarring the roads at the earliest as Kankar soling was done by the Zila Parishad several years ago .

(d) The estimates are under preparation.

**Proposed construction of Ganaur-Datauli Road in Khadar Area of  
tehsil Sonapat**

**\*9124. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a provision had been made for the construction of the Ganaur-Datauli road in the Khadar Area of tehsil Sonapat under the scheme of relief works taken up in tehsil Sonapat last year ;

(b) whether it is also a fact that a sum of Rs 20,000 was originally earmarked for the said Road but the scheme was subsequently changed or completely dropped, if so, the reasons for the same ;

(c) whether there is still any proposal to construct the said road in the backward area of Khadar ;

(d) whether the Government propose to undertake the construction of the road from Ganaur to village Bega via Datauli if the residents of these two villages do the earth work on the road or otherwise make a contribution of Rs 5,000 per mile ;

(e) the length of the said road and the total cost likely to be incurred thereon ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** (a) No. The Road from Ganaur to Datauli does not stand provided in the III Five-Year Plan under any scheme. However, a Road from G.T. Road to Datauli measuring 2.5 miles was included in the original proposals of various flood relief works during the year 1964-65.

(b) Yes. A sum of Rs 20,000 was provided during 1964-65 but it was later on dropped during that year.

(c) There is no proposal to include this road in the IV Five-Year Plan.

(d) If the residents of the area contribute 25 per cent of the cost of the road, it can be considered for inclusion in IV Plan under the Village Road Co-operative Development Scheme.

(e) The length of the road will be 4.50 miles and is likely to cost Rs 2.70 lakhs, and villagers share will be Rs 67,500.

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### Enquiry into certain allegations levelled by 'Dastak' fortnightly

**3062. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Home and Development with reference to the reply to Unstarred Question No. 2334 printed in the list of Unstarred Questions for 8th March, 1965 be pleased to state—

(a) the details of specific issue or issues mentioned in the communications laid on the Table of the House in reply to part (a) of the said question which were looked into by Shri Piara Lal, S.I. (Security), Shri G. S. Bhullar, D.S.P. and Shri Joginder Singh, S.I. (CID) referred to in part (c) of the said reply ;

(b) whether it is a fact that all the three enquiry officers mentioned above reported that the allegations levelled by the 'Dastak' fortnightly were incorrect ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) A statement of issues mentioned in the communications laid on the Table of the House in reply to part (a) of Unstarred Question No. 2334 printed in the list of Unstarred Questions for 8th March, 1965 is laid on the Table of the House.

(b) Yes.

Comrade Ram Piara, M.L.A. raised the following issues in his letter dated 10th December, 1964:—

- (i) News item in the Dastak, dated 6th December, 1964, had alleged that some Goondas who enjoyed the patronage of Shri Ram Piara, M.L.A. had threatened the Editor of Dastak (Shri Tarlochan Singh) in case he did not stop writing against Shri Ram Piara. He asserted that the allegations though attributed to him, mainly concerned the law and order situation.
- (ii) Shri Tarlochan Singh, Editor, has levelled the allegation to gain importance and for using it as Peshbandi against any future trouble.
- (iii) He asserted that the allegations published in the said issue of the paper were false. He demanded an enquiry into the matter.
- (iv) Sarvshri Tarlochan Singh, Kirpal Singh, M.C. and President, City Congress, Karnal, were getting financial help from certain Satta-Darra Gamblers.
- (v) Shri Kirpal Singh appeared as a defence witness in a Satta-Darra Gambling case for Hukam Chand Kuki in the Court which rejected his evidence. with the remarks that such evidences were available every-where at any time. Shri Kirpal Singh again made a statement in another court saying that he did not know Hukam Chand Kuki at all.

## [Home and Development Minister]

(vi) About a month back Shri Kirpal Singh threatend a Satta- Darra Gambler in Sadar Bazar Area when Shri Tarlochan Singh was also with him. There was a good hue and cry . He understood that the Police held enquiries into the matter.

(vii) They have got no known soruces of income . They are seldom seen attending to their professions if they had any. If Shri Kirpal Singh had anything with him he would have paid the Government tax of his truck which was taken into possession by the Sales Tax Department. The Truck has been got released by him now. Some financiers must have paid the dues in respect thereto.

(viii) He requested for necessary action against the persons found guilty.

2. As regards specific issues mentioned in the communication sent by Comrade Ram Piara, M.L.A., on 16th January, 1965 the following points (Issues) were mentioned therein relating to paper Dastak , dated 10th January, 1965:—

(i) Ali Baba Ram Piara's son and his Goonda associates threatened to kill the Editor', 'Dastak'.

(ii) Every body in Karnal very much regrets the assault on the students of Amritsar during last month . But Ram Piara is inflaming this incident to such an extent that he may get an opportunity to throw mud on the local officials

(iii) It may be remembered that during the past few days a capitalist who is a previous bad character on Bundle 'B' indulged in heavy smuggling along with his companion who is an owner of a flour mill, under their patronage. The information about this incident reached the authorities . The Civil Supply Officials raided the flour mill to seize the stock registers and other documents. But Ali Baba interferred and the Civil Supply officials became helpless. They also sought police help but Ram Piara interferred and prevented the police from discharging their duties by mentioning the name of Sardar Darbara Singh, Home Minister.

### Stay of officers /officials of Industries Department at Canal Rest House, Delhi

3063. **Comrade Ram Piara:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether any officers/officials of the Industries Department stayed in the P.W.D. Canal Rest House, Delhi (Alipur Road) during the period from 1st October, 1960 to date; if so, their names together with the dates in each case when they stayed ;
- (b) the amount of Rent/Electricity charges paid by each of the said officers/officials during the period of their stay at the said Rest House ;
- (c) whether the visits by the said officers/officials were shown by them as official or private visits , stating the details of each visit ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** Yes. The following officers/officials stayed in the P.W.D. Canal Rest House, Delhi during the period noted against each . The visitors register for the period 1st October, 1960 to August, 1961 seems to have been lost, and information for this period can not be supplied.

(b) The statement regarding the amount paid by the officers/officials is given below:.

(c) On duty . The details of their visit were not indicated.

## STATEMENT

(b) Name of visitor	Designation	Date		Amount paid by the officers/officials
		From	To	
Shri A. C. Kohli	Joint Director, Industries	12-9-61	15-9-61	Rs 14.25
		18-1-62	21-1-62	6.37
		5-2-62	6-2-62	2.12
		25-3-62	26-3-62	2.12
		29-3-62	30-3-62	4.25
		22-4-62	23-4-62	3.37
		17-6-62	18-6-62	3.37
		20-6-62	21-6-62	3.37
		27-6-62	29-6-62	6.75
		18-8-62	20-8-62	10.12
		24-8-62	25-8-62	6.75
		11-9-62	13-9-62	6.75
		24-10-62	26-10-62	4.27
		30-10-62	31-10-62	2.37
		17-11-62	17-11-62	2.37
		26-11-62	26-11-62	2.37
		20-12-62	20-12-62	2.37
		23-12-62	27-12-62	26.00
		4-5-63	7-2-63	7.75
		10-11-63	10-11-63	2.37
Shri G. R. Bhai	Ditto	17-9-61	18-9-61	3.37
Shri G. R. Bhai with Shri A. C. Kohli	Ditto	5-1-62	6-1-62	2.12
		6-1-62	7-1-62	4.25
Shri G. R. Bhai	Ditto	19-2-62	23-2-62	8.50
		19-3-62	20-3-62	2.12
		31-3-62	1-4-62	2.12
		14-6-62	15-6-62	3.37
		17-6-62	18-6-62	3.37

## [Irrigation and Power Minister]

Name of visitor	Designation	Date		Amount paid by the officers./ officials
		From	To	
				Rs
		12-9-62	13-9-62	6.75
Shri S. P. Jain	Joint Director, Industries	11-7-62	13-7-62	6.75
		8-8-62	9-8-62	3.37
		30-8-62	31-8-62	3.37
		9-11-62	10-11-62	2.37
		22-3-63	23-3-63	2.37
		23-4-63	25-4-63	6.75
		26-7-63	28-7-63	7.25
		18-8-63	21-8-63	10.87
		1-9-63	3-9-63	7.25
		24-9-63	25-9-63	3.62
Shri S.P. Jain with Shri Baldev Kapur	Ditto	3-10-63	3-10-63	10.50
Shri S. P. Jain	Ditto	6-12-63	7-12-63	2.37
Shri S. P. Jain with Shri Sukh Dev	Ditto	14-12-63	15-12-63	4.75
Shri S. P. Jain	Ditto	27-12-63	28-12-63	2.37
		8-1-64	10-1-64	4.75
		7-2-64	11-2-64	9.50
		14-2-64	18-2-64	9.50
		17-6-64	18-6-64	3.62
Shri P. N. Sahni	Director, Industries	11-7-62	13-7-62	6.75
		10-2-63	11-2-63	3.75
Shri Baldev Kapur	Joint Director, Industries	7-10-62	8-10-62	3.62
		16-1-63	16-1-63	2.37
		10-2-63	12-2-63	4.75
		7-3-63	9-3-63	4.75
		3-6-63	4-6-63	3.62

Name of visitor	Designation	Date		Amount paid by the officers/officials
		From	To	
				Rs
		26-7-63	30-7-63	14.50
		1-8-63	3-8-63	10.50
		24-9-63	25-9-63	3.62
		28-11-63	29-11-63	4.75
		15-1-64	16-1-64	4.75
		20-3-64	22-3-64	4.75
		30-3-64	31-3-64	2.37
		10-6-64	11-6-64	3.62
		13-6-64	14-6-64	3.62
Shri L. R. Mago	.. Joint Director, Industries	25-2-63	26-2-63	3.75
		7-3-63	9-3-63	4.75
		15-3-63	18-3-63	7.12
		4-4-63	6-4-63	4.75
Shri L. R. Mago with Shri Ravinder Nath Adviser State Export Corporation	Ditto	25-4-63	28-4-63	14.25
		18-5-63	20-5-63	10.50
		1-11-63	3-11-63	9.50
Shri S. S. Gill	.. Technical Expert, Industries	23-3-63	24-3-63	2.37
Shri S. S. Gill with Shri A. C. Kohli Joint, Director, Industries	Ditto	2-5-63	3-5-63	5.25
Shri I. E. N. Chauhan	.. Director, Industrial Training	23-6-65	25-6-65	7.25
		26-7-65	29-7-65	10.87
		3-11-65	7-11-65	9.50
		18-11-65	21-11-65	7.12
		6-12-65	7-12-65	2.37
		23-1-66	24-1-66	2.37

**Cases against Sarpanch of Panchayat Nighdu, District Karnal**

**3064. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Home and Development with reference to the reply to Unstarred Question No. 2888 included in the list of questions for 11th October, 1965 be pleased to state—

- (a) whether the investigation of the case F.I.R. No. 230 under section 409, I.P.C., Police Station Nisang, registered on 27th April, 1965, referred to in part (a) of the said reply has since been completed; if so, when, if not, the reasons for the same ;
- (b) whether the challan of the said case has been put up in the court; if so, when, if not, the reasons for the delay ;
- (c) in case the challan has been put up in the court, the names of the witnesses cited therein ;
- (d) whether the hearing of the said case has been started ;
- (e) the amount involved, as indicated by the B.D. & P.O., Nilotkheri ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes. On 21st December, 1965.

(b) On investigation the case was found to be false and sent up for cancellation. The question of putting the case in court, therefore, does not arise.

(c & d) Does not arise in view of part (b) above.

(e) Rs 907.37 nP.

**Rice exported out of the State**

**3065. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total number of wagons of rice exported from the State during the period from 1st August, 1964 to 31st July, 1965, and 1st August, 1965 to date, district-wise ;
- (b) whether any samples were taken from the said wagons of rice and analysed; if so, the names of the Laboratories where such analysis were held ;
- (c) whether any allowance is charged/levied on the basis of the analysis of rice samples; if so, the formula for charging the allowance ;
- (d) the total number of wagons the rice samples of which were got analysed in each Laboratory, laboratory-wise, during period mentioned in part (a) above ;
- (e) the total amount of allowance levied/recovered/charged by each D.F.C. Office on the basis of the result of the analysis done by each laboratory of the respective district during the period mentioned in part (a) above district-wise/laboratory-wise.?

**Shri Ram Kishan :** A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

## Statement showing the quantity of Rice exported out of the State

(a)

Name of District	Number of wagons despatched from 1st August, 1964 to 31st July, 1965	Number of Wagons despatched from 1st August, 1965 to 31st January, 1966	Total
Ambala	.. 1,283	505	1,788
Karnal	.. 3,662	2,194	5,856
Hissar	.. 1,043	..	1,043
Patiala	.. 1,372	602	1,974
Hoshiarpur	.. 404	337	741
Amritsar	.. 1,390	1,086	2,476
Jullundur	.. 993	674	1,667
Feroze Pur	.. 1,160	822	1,982
Gurdaspur	.. 1,250	1,075	2,325
Sangrur	.. ..	109	109

(b) Representative samples are taken out from each wagon and are analysed in the Laboratory of the district concerned.

(c) Yes. The specifications are prescribed in the Punjab Rice Control Order, 1964.

(d)

Name of District	Number of wagons despatched from 1st August, 1964 to 31st July, 1965	Number of wagons despatched from 1st August, 1965 to 31st January, 1966	Total
Ambala	.. 1,788	..	1,788
Karnal	.. 3,799	2,203	6,002
Hissar	.. 1,125	} For both the periods	1,125
Patiala	.. 2,057		2,05
Hoshiarpur	.. 741		74
Amritsar	.. 665	1,290	

[ Chief Minister]

Name of District	Number of wagons despatched from 1st August, 1965 to 31st July 1965	Number of wagons despatched from 1st August, 1965 to 31st Jan- uary, 1966	Total
Jullundur	993	674	1,667
Ferozepur	1,190	829	2,019
Gurdaspur	1,312	1,210	2,522
Sangrur	..	109	109

(e) Total amount of allowance levied:—

	Rs	Rs
Ambala	2,21,327.95	83,082.02
Karnal	41,15,243.58	3,14,491.19
Hissar	1,03,068.55	} For both the periods
Patiala	2,62,612.59	
Hoshiarpur	1,66,798.15	
Amritsar	2,02,054.68	1,32,497.96
Jullundur	1,47,133.21	53,902.60
Ferozepur	1,33,907.93	1,14,741.13
Gurdaspur	3,86,314.29	2,24,414.53
Sangrur	..	15,480.00

**Crime Cases registered in the State**

**3066. Shri Balramji Das Tandon :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- the total number of cases of crime, heinous or otherwise registered by the Police in the State in years 1962, 1963, 1964 and 1965, district-wise ;
- the total number of the said cases in which challans were put up in the courts together with the number of those which resulted in conviction of the accused ; ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

Crime Chart of heinous crimes registered during 1962 to 1965 (District-wise) in Punjab State

District	Heinous cases of crime registered					No. of cases in which challans were put up in the courts					No. of cases which resulted in the conviction of the accused				
	1962	1963	1964	1965	1966	1962	1963	1964	1965	1966	1962	1963	1964	1965	1966
Hissar	..	2,585	2,945	3,442	36,72	2,173	2,513	2,927	2,765	1,336	1,587	1,857	1,857	1,001	
Rotak	..	1,873	2,372	2,610	2,764	1,858	1,579	1,709	1,699	906	1,056	950	950	842	
Gurgaon	..	1,651	1,492	1,550	1,449	1,025	1,019	1,061	1,090	576	671	760	760	690	
Karnal	..	2,978	3,227	3,669	4,135	2,232	2,288	2,835	2,776	1,416	1,587	1,847	1,847	1,775	
Ambala	..	3,102	3,752	4,058	4,312	2,047	2,543	2,916	2,862	1,395	1,576	1,786	1,786	1,879	
Simla	..	186	259	250	257	127	163	197	185	96	101	145	145	116	
Kulu	..	226	188	229	182	207	177	217	154	188	145	178	178	73	
Kangra	..	871	807	645	692	654	614	544	435	359	282	246	246	170	
Hoshiarpur	..	1,816	2,072	2,255	2,400	1,487	1,661	1,820	1,976	788	909	1,103	1,103	1,167	
Jullundur	..	3,951	4,141	4,191	4,547	2,981	2,587	2,758	3,612	1,943	1,870	1,692	1,692	2,172	
Lahaul and Spiti	..	9	15	34	25	5	11	30	20	3	3	24	24	12	
Ludhiana	..	3,573	3,878	4,277	4,488	2,342	3,310	2,764	2,921	1,430	2,214	1,664	1,664	1,758	
Ferozepur	..	6,109	6,000	5,095	5,619	5,293	5,205	4,325	3,752	3,951	3,929	3,057	3,057	1,047	
Amritsar	..	6,202	7,051	7,316	7,743	5,651	6,376	6,685	6,656	4,817	4,977	5,128	5,128	4,881	
Gurdaspur	..	2,578	2,672	2,517	2,826	2,280	2,150	2,215	2,124	1,803	1,702	1,541	1,541	1,515	
Patiala	..	949	1,001	997	904	745	772	874	798	338	307	326	326	277	
Sangrur	..	2,782	2,925	3,146	2,790	2,381	2,522	2,468	2,720	1,623	1,476	1,575	1,575	2,000	
Bhatinda	..	2,590	3,080	3,830	3,913	2,322	2,691	3,146	3,301	1,491	1,974	2,357	2,357	2,193	
Narnaul	..	406	462	535	561	399	392	524	546	256	222	324	324	341	
Kapurthala	..	1,045	1,473	1,280	1,380	792	1,260	1,088	1,248	459	548	709	709	574	

**Family Allowance granted to certain Communist Detenus**

**3067. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the names of the Communist detenus in the State who applied for family allowance for maintenance of their dependents during the year 1965 together with the names of those who were granted such allowance and the amount of allowance given in each case ;
- (b) whether before granting the maintenance allowance the properties of the concerned detenus were got verified through the Police and the revenue agencies; if so, the details of such properties, movable and immovable belonging to (1) Shri Darshan Singh Jhabal, ex-M.L.A., detenu, Sangrur Jail, (2) Comrade Katar Singh Gujapeer, detenu, Hissar Jail, (3) Comrade Prem Chand Bhardwaj, detenu, Hissar Jail, (4) Comrade Dhanpat Rai Nahar, detenu, Sangrur Jail, (5) Comrade Bishan Singh, detenu, Hoshiarpur Jail, (6) Comrade Solukhan Singh, detenu, Patiala Jail, (7) Comrade Kesar Singh, detenu, Amritsar Jail, (8) Comrade Satya Mandan, detenu, Sangrur Jail, (9) Comrade Daya Singh Prem, detenu, Nabha Jail ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) List of names of communist detenus who applied for family allowance during 1965 is placed on the Table of the House. Family allowance has not been granted to any detenu so far.

(b) Yes. Through the Police. A list of movable and immovable properties belonging to each detenus referred to in the Assembly Question is placed on the Table of the House.

(a) List of names of Communist Detenus who applied for Family Allowance during 1965

Sarvshri—

1. Raghbir Singh
2. Ude Singh.
3. Gian Singh
4. Dharam Singh.
5. Isher Singh.
6. Gurbax Singh.
7. Mehar Singh.
8. K. R. Palta.
9. Ram Kishan Bharolian.
10. Gurcharan Singh Randhawa.
11. Dhanpat Rai Nahar.
12. Kesar Singh.
13. Rachhpal Singh.
14. Bhajan Singh.
15. Chanan Singh Brar.
16. Daya Singh Prem.
17. Darshan Singh Jhabal.
18. Kartar Singh Gujapir.
19. Bishan Singh.
20. Solakhan Singh.
21. Prem Chand Bhardwaj.
22. Vidya Dev Longowal.
23. Ghuman Singh Ugrahan.
24. Janak Singh Bhathal.
25. Ganda Singh.
26. Devki Nandan.
27. Satya Mandan.
28. Ram Singh of Bhatinda.
29. Harkishan Singh Surjeet.
30. Fauja Singh.
31. Dalip Singh Bhatiwala of Sangrur.
32. Dharam Singh Kasni.

## (b) List of moveable and immovable properties belonging to each detenu

Serial No.	Name of detenu	Details of moveable and immovable properties
Sarvshri—		
1	Darshan Singh	.. One kacha house
2	Kartar Singh Gujapir	.. One Kacha house in village Gujapir, One Kacha house in village Parewal, Ten Kilas of land out of which 8½ Kilas mortgaged and the rest one and half kila under cultivation
3	Prem Chand	.. One Semi-kacha house
4	Dhanpat Rai	.. Nil
5	Bishan Singh	.. Nil
6	Sulakhan Singh	.. Nil
7	Kesar Singh	.. One house and a buffalow
8	Satya Mandan	.. Nil
9	Daya Singh Prem	.. One Kacha house

**Jail Advisory Committee**

**3068. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- whether the Government has constituted any Jail Advisory Committee consisting of M.Ps., M.L.As. and officials to suggest reforms in Jails; if so, the names of the members of the said Committee;
- whether any member of the said Committee had undergone any imprisonment during the National Independence Movement; if so, the details thereof in respect of each;
- whether any recommendations have so far been made by the said Committee to the State Government; if so, the details thereof;
- whether the recommendations referred to in part (c) above were considered by the Government; if so, the action so far taken in this behalf?

**Shri Chand Ram :** (a) Yes. The names of the members of the Committee are as under :—

*Chairman*

Minister-in-Charge, Jails.

*Non-official Members*

- Shri Narain Singh Shahbazpuri, M.L.A.
- Chaudhri Chuhar Singh, M.L.A.
- Shri Dev Raj Anand, M.L.A.
- Shri Mohan Singh (General, I.N.A.), M.P.
- Shri Amar Nath Vidyalkar, M.P.
- Shri Jaswant Singh Sodhi, M.L.A.
- Shri Pritam Singh Sahoke, M.L.A.

[Minister for Welfare Justice]

*Departmental Officers*

1. Home Secretary to Government, Punjab.
  2. Inspector-General of Prisons, Punjab.
- (b) This information is not available.
- (c) & (d) The details of the recommendations made by such committees to the State Government from time to time along with the action taken against them is given in the enclosed statement.

**STATEMENT**

Recommendations of the Jail Advisory Committees	Action taken by Government
(1) Clerical staff should be considered for promotion on the Executive side as was done in the case of some other Departments	Rules already permit such appointments through Competitive Examinations
(2) Junior Executive staff be allowed to keep milch cattle at jail premises	Not accepted
(3) Normal working hours in the Jail Department should be reduced to give adequate relief to the serving personnel	Not accepted
(4) Modern farming including the use of improved methods of agriculture should be adopted	Acced
(5) All non-official members of the Jail Advisory Committee be made <i>exofficio</i> jail visitors	Accepted
(6) Some industrialists from Ludhiana, Amritsar and Panipat should be allowed to start small industries inside the jails and allowed to employ jail labour on payment of reasonable wages	Not accepted
(7) Non-official jail visitors should be impressed upon to pay maximum number of visits to Jails	Accepted
(8) Liberalization of facilities for writing letters and interviews to convicted and un-convicted prisoners recommended	Accepted
(9) Punjab University may be approached to give general permission to all convicts to sit in examinations, conducted by them	Accepted to the extent that each case is examined by the University authorities on merits
(10) Grant of remission to prisoners on account of good behaviour during Punjabi Suba agitation	Accepted
(11) Pay scales of technical hands in jails should be revised	Accepted
(12) Revision of pay scales of Warder Establishment should be expedited and their grades suitably revised	Accepted
(13) In all the jails improved mechanized and scientific methods of cultivation should be adopted wherever there was such a scope with the advice and assistance of Agriculture Department specialists from the Agriculture Department might be called to demonstrate in the Jails Farms the use of new	Accepted

Recommendations of the Jail Advisory Committees	Action taken by Government
and improved instruments, seeds, chemical fertilizers and manures. If need be tractors should be purchased and the Jails as far as possible should have their own tube-wells. Additional agricultural lands should be purchased either through direct negotiation or by requisitions	
(14) Instructions should be issued to all Superintendents of jails for developing agriculture and industrial resources of the jail to fullest extent	Since implemented
(15) Jails should be self-sufficient in blankets and other such like articles	Implemented as far as practicable
(16) Arrangements for exhibition of industrial products be made	Accepted
(17) Recommendations of non-official visitors for grant of remission to deserving prisoners should be considered	Not accepted
(18) Wage-earning scheme should be introduced in Jails	Accepted
(19) Small cotton ginning machines and crushers should be installed in Jails	Accepted so far as installation of crushers is concerned
(20) The Department should take steps to secure more land contiguous to jail farms. The possibility for the transfer of Government land adjoining jail farms be examined. The possibility of starting a camp agriculture jail at about 100 acres of good land be examined	Accepted
(21) Poultry Farming should be extended to other jails on the basis of experiment of District Jail, Gurdaspur	Accepted
(22) Disciplined and well-behaved prisoners be granted a clearance certificate at the time of their release to save them from harassment at the hand of Police	Accepted
(23) Vine yards should be established at selected jails	Accepted
(24) Present Poultry Farms should be expanded and incubators and feed mixers provided	Accepted
(25) The powers of Superintendents of Jails to meet contingent expenditure for the purchase of raw material for the Jail Factories should be enhanced	Government had delegated enhanced powers to the I.G., Prisons, Punjab, to sanction non-recurring expenditure for effecting purchases through the Controller of Stores from Rs 25,000 to Rs 50,000 on any one item. The question of enhancing the powers of A.I. G. (Industries) and Superintendents of Jails for the purchase of material is under consideration of Government

## [Minister for Welfare and Justice]

Recommendations of the Jail Advisory Committees	Action taken by Government
(26) Arrangements should be made to provide meat to non-vegetarians and sweets to other prisoners on special occasions	Government has sanctioned the issue of sweet dish of rice, Halva or Khir on four occasions, namely, Republic Day, Baisakhi, Independence Day and Diwali
(27) Training should be imparted to prisoners engaged in poultry farming on the lines of training centres at Gurdaspur, etc.	Accepted

**Income from Jail Gardens/Industries**

**069. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the details of the income which accrued to the Government from the Jail Gardens and Jail Industries in each of the Central and District Jails in the State, Jail-wise, during the years 1964-65 and 1965-66 to date ;

(b) the details of expenditure incurred on (1) pay of the staff, etc., (2) Food, clothing and medical facilities supplied/provided to the prisoners jail-wise, during the period mentioned in part (a) above ?

**Shri Chand Ram :** (a) (i) *Income from Jail Garden.*—As in Annexure A.

(Note.—As agricultural statistics are maintained on the calendar year basis, the information in this regard is also for the calendar year instead of financial year).

(2) *Income from Jail Industries.*—As in Annexure B.

(b) As in Annexures C and D for the years 1964-65 and 1965-66 respectively.

**ANNEXURE A****Income accrued to Government during the Calendar years 1964 and 1965**

Name of Jail	Production in 1964	Production in 1965
(In Rupees)		
1. Central Jail, Patiala	.. 1,33,114.17	1,40,969.79
2. District Jail, Amritsar	.. 88,884.31	89,840.60
3. Central Jail, Ambala	.. 1,24,406.29	1,06,410.09
4. B.I. & J. Jail, Faridkot	.. 61,028.88	71,673.63

Name of Jail	Production in 1964 (In Rupees)	Production in 1965 (In Rupees)
5. Central Jail, Hissar	1,06,049.83	1,22,155.29
6. Central Jail, Ferozepur	1,36,222.31	1,25,547.40
7. District Jail, Gurdaspur	49,426.78	49,439.68
8. District Jail, Bhatinda	32,162.28	34,407.29
9. District Jail, Ludhiana	67,638.63	47,523.69
10. District Jail, Jullundur	40,697.79	38,779.05
11. District Jail, Rohtak	18,626.74	18,496.46
12. District Jail, Sangrur	26,134.32	33,745.46
13. District Jail, Nabha	33,678.35	38,691.66

## ANNEXURE 'B'

*Income that accrued to the Government from the Jails Industries in each Central and District Jail in the State Jail-wise, during the years 1964-65 and 1965-66*

Name of the Jail	Income during	
	1964-65	1965 (up to 31st December, 1965, i.e. months)
	(In Rupees)	(In Rupees)
Ambala	5,01,593	4,57,783
Patiala	6,88,284	4,09,498
Ferozepur	7,07,713	3,29,561
Hissar	3,09,308	1,93,948
Ludhiana	2,99,388	1,68,526
Faridkot	3,37,217	2,98,833
Amritsar	2,17,025	1,47,139
Jullundur	1,82,154	95,073
Nabha	86,072	77,066
Sangrur	1,38,684	75,096
Rohtak	86,750	78,487
Gurdaspur	74,661	61,187
Bhatinda	1,16,129	77,014
Total	37,44,968	24,69,211

[Minister for Welfare and Justice]

## ANNEXURE C

## Part (b) Information for 1964-65

Name of Jail	(i) Expendi- ture on Pay of Staff, etc. (in rupees)	(ii) Expenditure on		
		Food	Medical facilities (in rupees)	Clothing and bedding
Ambala	.. 2,54,725	1,21,274	31,640	61,930
Ferozepur	.. 2,27,599	2,00,395	48,186	68,788
Patiala	.. 2,46,476	1,60,171	38,628	47,951
Hissar	.. 1,72,157	89,010	26,266	14,324
Ludhiana	.. 1,48,349	1,00,349	17,547	8,446
Jullundur	.. 1,03,417	66,958	20,300	6,602
Amritsar	.. 1,40,566	1,12,812	13,527	29,864
Rohtak	.. 86,727	35,452	8,032	25,146
Nabha	.. 73,404	35,524	17,839	8,177
Bhatinda	.. 86,979	70,469	11,699	7,281
Sangrur	.. 79,762	47,104	12,989	1,893
Gurdaspur	.. 90,747	52,372	7,307	8,124
B.I. & J., Faridkot	.. 1,54,502	80,510	8,833	23,578

## ANNEXURE D

Part (b) Information for 1965-66 (i.e. 1st April, 1965 to 31st December, 1965)

Name of Jail	(i)		(ii)	
	<i>Expenditure on</i>		<i>Expenditure on</i>	
	Pay of staff, etc. (In rupees)	Food	Medical facilities and bedding (In rupees)	
Ambala	.. 2,30,533	1,92,330	30,674	69,382
Ferozepur	.. 1,92,125	1,91,373	61,573	31,874
Patiala	.. 1,97,217	1,50,804	39,640	51,325
Hissar	.. 1,49,158	1,20,145	58,203	21,787
Ludhiana	.. 1,30,115	1,08,072	13,357	13,164
Jullundur	.. 87,238	78,478	10,842	13,819
Amritsar	.. 1,27,305	1,36,579	16,334	1,882
Rohtak	.. 77,375	50,024	7,646	8,896
Nabha	.. 61,674	39,646	15,552	18,352
Bhatinda	.. 66,057	70,245	14,146	6,347
Sangrur	.. 74,089	55,143	3,834	10,850
Gurdaspur	.. 75,582	51,490	10,185	7,119
B.L. & J. Jail, Ferozkot	.. 1,31,040	80,753	8,289	8,675

## Jails visited by the Minister in 1965

70. Comrade Makhan Singh Tarsikka :—Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- (a) whether he visited any jail in the State during the year 1965. if so, the names of such jails together with the details of the inspection reports or remarks, etc., made by him regarding the working of such jails, jail-wise :
- (b) whether the work of any jail officer official was appreciated by him during the said visits, if so, the details thereof and the action, if any, taken by the Jail Department thereon ?

Shri Chand Ram : (a) Names of the Jails visited by the Minister for Welfare and Justice, Punjab, during 1965 are given in the enclosed statement.

**[Minister for Welfare and Justice]**

No inspection report or remarks were recorded by him. During his addresses to the gatherings of prisoners and Jail staff, however, he has been exhorting them to raise jail production, both in industries and agriculture. He has also been advising the prisoners to be good citizens when they go out.

(b) No.

**Statement regarding the names of Jails visited by the Minister for Welfare and Justice during the year 1965**

Serial No.	Name of Jail
------------	--------------

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 1  | Central Jail, Ambala      |
| 2  | Central Jail, Delhi       |
| 3  | Central Jail, Hissar      |
| 4  | Central Jail Ferozepur    |
| 5  | Special Jail, Hissar      |
| 6  | District Jail, Gurgaon    |
| 7  | District Jail, Jullundur  |
| 8  | District Jail, Amritsar   |
| 9  | District Jail, Bhatinda   |
| 10 | District Jail, Ludhiana   |
| 11 | District Jail, Hoshiarpur |
| 12 | District Jail, Gurdaspur  |
| 13 | District Jail Rohtak      |

**Instructions regarding Treatment of Communist Detenus in State Jails**

**3071. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the Government received any instructions or note from the Union Home Ministry during the month of December, 1965 or January, 1966 regarding the treatment and amenities to be given to the communist detenus in the State Jails and for making uniform All-India Political Detenus Rules; if so, the details of such instructions/note and the action, if any, taken thereon.

**Shri Chand Ram :** Yes, a communication in this behalf was received from the Government of India, Ministry of Home Affairs, in January, 1966, which is under consideration of the State Government. It is, however, not in the public interest to disclose its contents.

**Special Certificates for Certain Untrained Teachers**

**3072. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education with reference to the reply to Unstarred Questions No. 2439 included in the list of questions for 24th March, 1965 be pleased to state—

- the date on which the decision for giving special certificates to the teachers mentioned in Annexure 'A' appended to the said reply was taken and the date on which they were actually given such certificates in each case ;
- the names of the teachers mentioned in Annexure 'B' appended to said reply who have not so far been given the special certificates together with the reasons for not giving them these certificates in each case ;

- (c) the names of the teachers as mentioned in part (a) above who have been given increments up to date together with the details thereof in each case ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) and (c) The information is being collected and will be supplied at the earliest.

(b) A statement marked at Annexure 'B' giving the requisite information is laid on the Table of the House.

#### ANNEXURE 'B'

**List of teachers who have not been awarded Special Certificates so far giving reasons thereof**

Serial No.	Name of the teacher with School where working	Reasons for not awarding Special Certificate or reason for delay
1	Smt. Nirmal Kanta, teacher, Government Primary School, Lachmansar	Case rejected since the teacher did not fulfil the conditions for its award
2	Shri Gyan Singh, teacher, Government Primary School, Udhoke	The teacher has not submitted the case despite many reminders
3	Shri Harbans Singh, teacher, Government Primary School, Majjupur	The teacher has been asked to supply certain wanted documents which are still awaited from him. He is being reminded constantly
4	Shri Kundan Lal, teacher, Government Primary School, Behola	Ditto
5	Shri Dev Dutt, teacher, Government Primary School, Marrikala	The teacher having been taken from the District Board the break in his service is being regularised from the District Board
6	Shri Hardip Singh, teacher, Government Primary School, Vadala Virum	Special Certificate has been awarded to the teacher
7	Smt. Harbans Kaur, teacher, Government Primary School, Lachmansar	The teacher is being asked to give the reason for break in her service
8	Shri Gajjan Singh, teacher, Government Primary School, Jabbowal	The teacher has not submitted his case despite many reminders
9	Shri Bhagwan Dass, Bal Vidyalaya, Amritsar	Certificate has been awarded to the teacher
10	Shri Hari Sharn Sharma, Bal Vidyalaya, Amritsar	The teacher has been asked to supply certain documents which are still awaited from him. He is being reminded constantly
11	Smt. Jagjit Kaur, Cantt. Board, Amritsar	Her case has been rejected since she was not found eligible for the award of Special Certificate
12	Shri Jaswant Rai, Government High School, Butala	Case rejected by Department as not recommended by the Headmaster (returned to the D.E.O.)

[Education Minister]

Serial No.	Name of the teacher with School where working	Reasons for not awarding Special certificate or reason for delay
13	Shri Gurcharan Singh, Government High School, Vadali Guru	The teacher has been asked to supply certain wanted documents which are still awaited. He is being reminded constantly
14	Smt. Satya Sethi, Government Girls Middle School, Sultanwind	Her case has been rejected, she being not eligible under rules
15	Smt. Raj Wans Kumari Shahjadanad School, Amritsar	She has since been awarded a Special Certificate
16	Shri Natha Singh, Government Primary School, Bhakna	The teacher has been asked to supply certain wanted documents which are still awaited. He is being reminded constantly
17	Shri Faqir Chand, teacher, Government Primary School, Sohawa	Ditto

#### Property of Shri Ganpat Singh, Communist Detenu attached by the Government

**3073. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- whether Government has received any representation from Shri Ganpat Singh, Communist detenu in Hissar Jail for releasing his property attached during the period when he absconded; if so, the action so far taken thereon;
- the detailed list of the property referred to in part (a) above attached by the Government and also the date on which it was attached?

**Sardar Darbara Singh :** (a) No. However, Shri Hardit Singh Bhattal, M.L.A. represented for the release of property of Shri Ganpat Singh who is under consideration of Government.

(b) (i) House in village Rattan Kalan attached on 12th May, 1965.

(ii) Agricultural Land measuring 25 kanals and 16 Marlas attached on 13th May, 1965.

The above properties have been given on superdari to Bir Singh Lambar-dar of the same village.

#### Winter Uniform for Officers/Officials of the Jail Department

**3074. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state whether the Jail Department Officers/Officials are provided with any kind of winter uniform; if so, the details of the Uniform as given in each case, if not provided, the reasons for not supplying the same to them?

**Shri Chand Ram :** The requisite information is given in the enclosed statement, which is laid on the table of the House.

**Statement showing Information regarding Uniform for Officers/Officials of the Jail Department**

Serial No.	Name and designation of the post	Details of winter uniform provided
1	Deputy Superintendents, Senior Assistant Superintendent and Assistant Superintendents	(i) Brown Buckskin gloves (to be worn on parade) (ii) Great Coat (Warm)
2	Warders	<p>(i) Blouse-Khaki drill made loosely in length to reach to the tip of wearer's forefinger to have collar 1 inch high, hooking in front with one hook, two breast pockets with plain flaps fastening with jail pattern buttons of brass (letters P.J. in Brass) across shoulder straps which will fasten at top with one button, three small size jail buttons (brass) down the front</p> <p>(ii) Knicker bockers Khaki drill made loosely</p> <p>(iii) Great Coat—Police pattern</p> <p>(iv) Jerseys-Woollen to be worn under the blouse</p> <p>(v) Head-dress Khaki muslin pugree 5 yds. long, one inch of the cloth at either end to be knotted and made into a fringe and khaki kullah or khaki muslin cloth 4 yds. long and 11 inches wide to be worn under the pugree</p> <p>(vi) Shoe— Plain country brown leather</p> <p>(vii) Waist belt—Brown leather brass clasp with the letters P.J. and the word "Warder" embossed thereon to be worn over blouse</p> <p>(viii) Patti—Khaki Cotton</p> <p><i>Note.</i>—(1) Khaki Kullah shall be worn by non-Sikh Warders and khaki muslin cloth by Sikh Warders</p>
3	Head Warders	<p>.. The Uniform of a Head Warder shall be the same as prescribed for warders above with the following additions :—</p> <p>(i) Three chevrons on right sleeve above elbow</p> <p>(ii) Waist belt to have the words "Head Warder" embossed on the clasp</p>
4	Matron or a Female Warder	.. A chaddar and kurta of garah cloth with red border 1 inch wide, pyjama of plain blue garah cloth, shoes of plain brown country leather and woollen jersey for cold weather wear

The Deputy Superintendent, Senior Assistant Superintendents, Assistant Superintendents have got to equip themselves with such uniform at their own expense as provided under para 357 of Punjab Jail Manual.

[Welfare and Justice Minister]

The Warders' staff is issued winter uniform free of charge according to their rank and grade as provided under paragraph 358 of Punjab Jail Manual.

**Winter Uniform for the Employees of the Police Department**

**3075. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister of Home and Development be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that Gazetted Officers in the Police Department are supplied with woollen coats and woollen pants during the winter season at Government expense ;
- (b) whether it is also a fact that all Non-Gazetted Officers of the Police Department (Inspectors, Sub-Inspectors, Assistant Sub-Inspectors, Head Constables and Constables) are not provided with winter uniforms by Government ; if so, the reasons therefor ;
- (c) whether Government intend to remove the above-mentioned disparity, ; if so, when ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Gazetted Officers (Deputy Superintendents of Police) are given initial grant of Rs 250 on their first appointment and Rs 250 at the time of their confirmation and another Rs 250 after completing 5 years service in the rank of Deputy Superintendent of Police. They are required to purchase uniforms out of the above-mentioned grant which hardly covers cost of woollen uniforms except Great Coat.

(b) Non-Gazetted Officers and other Ranks of the Punjab Armed Police are provided woollen uniforms. NGOs. and ORs of the District Police get woollen uniforms in Hilly Areas only, while in the plains NGOs. get great coats and ORs get great coats and woollen jersies. The existing Police Rules which were framed in 1934 do not provide for woollen uniforms in the plains.

(c) A proposal for providing winter uniforms to all NGOs/ORs in the plains also is under the consideration of the State Government. It is not possible at this stage, to indicate the time by which it will be finalized, but efforts are being made to finalize it as early as possible.

**Assessment of Surplus Area in Village Shamgarh, Tahsil and District Karnal**

**3076. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Revenue with reference to the reply to Unstarred Question No. 2870 included in the list of Questions for 11th October, 1965 be pleased to state whether the case regarding the assessment of surplus area referred to in part (a) (i) of the said reply which was in the Court of the Financial Commissioner, Revenue for review has since been finalised or reviewed ; if so, when and with what result ?

**Sardar Harinder Singh Major :** (i) Yes.

(ii) On 31st January, 1966.

(iii) The orders passed by the Collector, Karnal, have been set aside by the Financial Commissioner, Revenue, and the cases have been remanded to the Special Collector, Punjab, for a fresh determination of all the surplus area cases after hearing all the parties.

## Iron and Steel Quota Holders in Karnal District

3077. Comrade Ram Piara : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number and names of iron and steel quota holders at present in the district of Karnal together with the place of business of each ;
- (b) whether any quota certificates for iron and steel were issued to the quota-holders in district Karnal during the period from 1st November, 1965 to-date together with the quantity of iron and steel including G.P. Sheets and B.P. Sheets, issued to each quota-holders;
- (c) the purpose for which the said quota has been given as mentioned in each of the said quota certificates issued together with the nature of trade or industry which each quota-holder was carrying on before the issue of the certificates and is carrying on at present separately;
- (d) the nature of trade/industry shown by each of the said quota holders in their applications submitted to the Industries Department when they applied for the grant of the said quota ;
- (e) whether it is a fact that certain quota-holders had been supplied with such material of iron and steel which is normally not used in the industry approved by the Department and being carried on at present by the quota-holders ; if so, the reasons for the same ;
- (f) whether any previous record of the said quota holders prior to the issue of the said quota certificates had been looked into by the department ; if so, by whom, if not, the reasons therefor ;
- (g) whether it is a fact that if a quota-holder is given quota of iron and steel which is different in type or quality from that to which he is entitled or which he requires for the industry approved by the department, that material goes or is likely to go to the black market ; if so, the reasons for not giving the material of requisite quality or type to the quota-holders ?

**Shri Ram Kishan :** (a) and (b). A statement giving the requisite information is enclosed.

(c) The time and labour involved in collecting the requisite information will not be commensurate with the benefit sought to be derived therefrom.

(d) Fabrication.

(e) No.

(f) Yes. By the district staff.

(g) Yes. As far as possible those categories of material are issued to the quota-holders which can be used for some type of fabrication.

## S.S.C.I. QUOTA HOLDERS

Serial No.	Name and address of the party	Location
1	2	3
1	M/s. Dev Dutt Vij, G.T. Road	.. Karnal
2	M/s. Gujranwala Metal Works, G.T. Road	.. Karnal
3	M/s. Asiatic Industries, Novelty Road	.. Karnal
4	M/s. Chinot Trunk House	.. Karnal
5	M/s. Girdhari Lal-Lal Chand	.. Karnal
6	M/s. Lyallpur Steel Works	.. Karnal
7	M/s. Bharat Steel Works	.. Karnal
8	M/s. Zamindara Trunk House	.. Karnal
9	M/s. Munshi Ram-Kewal Ram	.. Karnal
10	M/s. Chawla Trunk House	.. Karnal
11	M/s. Tilak Raj Steel Fabricator	.. Nilokheri
12	M/s. Chaman Lal Steel Fabricator	.. Nilokheri
13	M/s. Ram Kishan Soni, Steel Fabricator	.. Nilokheri
14	M/s. Kanshi Ram, Railway Road	.. Nilokheri
15	M/s. Hari Chand, Steel Fabricator	.. Nilokheri
16	M/s. Sangat Ram, Steel Fabricator	.. Nilokheri
17	M/s. National Nail Industries	.. Nilokheri
18	M/s. Pharya Lal-Jiwan Dass	.. Panipat
19	M/s. Channu Ram-Wazir Chand	.. Panipat
20	M/s. Surrender Metal Industries	.. Panipat
21	M/s. Ravi Safe Works, Railway Road	.. Panipat
22	M/s. Hargopal Dass Bhatia & Sons, Railway Road	.. Panipat
23	M/s. Ram Piara Mal	.. Panipat
24	M/s. Chaman Lal-Kharaiti Lal	.. Panipat
25	M/s. Vir Bhan-Aishi Lal	.. Panipat
26	M/s. Sita Ram-Ram Sarup	.. Panipat
27	M/s. Basdeo Mal-Kashmiri Lal	.. Panipat
28	M/s. Lila Dhar-Karam Chand	.. Panipat

Serial No.	Name and address of the party	Location
1	2	3
29	M/s. Chandan Lal Chattar Sain, G.T. Road	.. Panipat
30	M/s. Kundan Lal-Jita Ram	.. Panipat
31	M/s. Devki Nandan Mittal	.. Samalkha
64	M/s. Mohan Lal-Shiv Nath	.. Samalkha
65	M/s. Dharam Chand Steel Fabricator	.. Thanesar
66	M/s. Banarsi Lal-Ashok Kumar, Model Town	.. Panipat
67	M/s. Jai Bharat Auto Industries	.. Karnal
68	M/s. Sethi Trunk House, Railway Road	.. Karnal
69	M/s. Krishanpura Iron Store, Rajputana Bazar	.. Panipat
70	M/s. Hari Chand-Gulshan Rai, 24/2	.. Panipat
71	M/s. Seema Industrial Corporation	.. Niawal
72	M/s. Puran Chand-Sharwan Kumar, Railway Road	.. Kaithal
73	M/s. Rashtrya Trunk House, Sadar Bazar	.. Karnal
74	M/s. J.P. Dhiman & Sons, Industrial Area	.. Panipat
75	M/s. The Punjab General Manufacturers	.. Kaithal
76	M/s. Surjan Singh & Sons, E-49, Industrial Area	.. Panipat
77	M/s. Batra Cycle Industries, O-37, Industrial Area	.. Panipat
78	M/s. Mohan Lal-Sukhan Lal	.. Samalkha
79	M/s. Batra Steel Works, 0/15, Industrial Area	.. Panipat
80	M/s. Jawahar Industrial & General Corporation M-10, Industrial Area	Panipat
81	M/s. Hem Overseas Auto Industries, Timber Market	.. Kaithal
82	M/s. Hari Ram-Gian Chand, Trunk Manufacturers, Pansarian Street	Kaithal
83	M/s. Setia Iron and Steel Industries	.. Pasina Kalan
84	M/s. True Tempo Auto Industries, M-7, Industrial Area	.. Panipat
85	M/s. Gupta Trunk House	.. Kaithal
86	M/s. Nico Iron and Steel Works	.. Kaithal
87	M/s. New India Tin Bucket and General Manufacturers old College Building	Kaithal
88	M/s. The Superintendent Rural Artisan Training Centre	.. Kaithal
89	M/s. Jain Agrico Industries, Shed No. 11-B	.. Nilokheri
90	M/s. Shiv Shanker Metal Production Co-operative Industrial Society Ltd., 6-B, Industrial Estate	Nilokheri

[Chief Minister]

## ANNEXURE I

## NUMBERS AND NAME OF S.P.I. QUOTA HOLDERS OF KARNAL DISTRICT

Serial No.	Name and Address of the party	Location
1	2	3
1	M/s. Jai Hind Iron Foundry and Engineering Works	.. Samalkha
2	M/s. Mittal Iron Foundry and Engineering Works	.. Samalkha
3	M/s. Bharat Iron Foundry, G.T. Road	.. Panipat
4	M/s. Indian Conduit Industries, G.T. Road	.. Panipat
5	M/s. Krishna Engineering Works, Railway Road	.. Panipat
6	M/s. Ahuja Mechanical and Engineering Works, Railway Road	Panipat
7	M/s. Mathura Dass Bhatia and Bros. Railway Road	.. Panipat
8	M/s. Satya Engineering Corporation, Industrial Area	.. Panipat
9	M/s. Bajaj Metal Works, Industrial Area	.. Panipat
10	M/s. General Engineering and Foundry Works, work Centre	Panipat
11	M/s. Himalya Cycle Works, Industrial Area	.. Panipat
12	M/s. Haryana Progressive Industrial Works, Industrial Area	Panipat
13	M/s. Romesh Safe and Carding Works, Railway Road	.. Panipat
14	M/s. Vishwakarma Industries	.. Kaithal
15	M/s. O.K. Engineering & General Works	.. Kaithal
16	M/s. Kaithal Expellers Workshop	.. Kaithal
17	M/s. Telu Ram-Lekh Ram	.. Kaithal
18	M/s. Jai Bharat Hardware Co., Industrial Area	.. Panipat
19	M/s. The American Industries, G.T. Road	.. Karnal
20	M/s. Aggarwal Iron Foundry	.. Samalkha
21	M/s. Steel Fabs & Co., G.T. Road	.. Panipat
22	M/s. Steel Krafts, G.T. Road	.. Panipat
23	M/s. United Engineering Works, G.T. Road	.. Panipat
24	M/s. Hindustan Industrial Works, Industrial Area	.. Panipat
25	M/s. Aggarwal Metal Industries	.. Kaithal
26	M/s. United Steel products E 11 Industrial Area	.. Panipat

## ANNEXURE II

## THE QUOTA CERTIFICATE ISSUED TO QUOTA HOLDERS OF KARNAL DISTRICT FROM 1ST NOVEMBER, 1965 TO 4TH DECEMBER, 1966

Serial No.	Name and Address	Category in M. Tons						Total	Purpose
		G.P. Sheets	B. P. Sheets						
			10—14 G	16—20 G	above 20 G				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	M/s. Lal Chand-Lakhmi Chand, Kaithal	0.535	..	..	0.860	1.395	Manufacture of Trunk Balties		
2	M/s. Jai Hind Iron and Steel Manufacturing Works, Kaithal	0.535	..	..	1.720	2.255	Manufacture of Trunks, Suit Cases		
3	M/s. Janta Trunk House, Kaithal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
4	M/s. Hari Chand-Dharam Chand, Kaithal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
5	M/s. Gupta Trunk House, Kaithal	0.535	..	..	1.720	2.255	Ditto		
6	M/s. Nico Iron and Steel Works, Kaithal	0.535	..	..	1.720	2.255	Ditto		
7	M/s. Punjab General Manufacturers, Kaithal	0.535	..	..	1.720	2.255	Ditto		
8	M/s. Paul Trunk House, Assandh	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
9	M/s. Hans Trunk House, Indri	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
10	M/s. Chawla Trunk House, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		

[Chief Minister]

Serial No	Name and Address	Category in M. Tons					Total	Purpose
		G.P. Sheets			B. P. Sheets			
		10—14 G.	16—20 G.	above 20 G				
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	M/s. Gujr anwala Metal Works, Karnal	0.535	..	..	0.860	2 255	Manufacture of Trunk Suit Case	
12	M/s. Multani Trunk House, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto	
13	M/s. Munshi Ram-Kewal Ram, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto	
14	M/s. Lyallpur Steel Works, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto	
15	M/s. Chinot Trunk House, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto	
16	M/s. Zamindara Trunk House, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto	
17	M/s. Bharat Steel Industries, Karnal	0.535	..	..	0.800	1.395	Ditto	
18	M/s. Rashtriya Trunk Hcuse, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto	
19	M/s Girdhari Lal-Lal Chand, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto	
20	M/s. Dev Datt Vij, Karnal	0.535	..	..	2.580	3.115	Ditto	
21	M/s. Hukam Chand, son of Dhoola Ram, Purani Mandi, Karnal	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto	
22	M/s. Asiatic Industries, Karnal	0.535	..	..	1.720	2.255	Ditto	

23	M/s. Ram Parshad Trunk Maker, Ladwa	0.535	..	..	0.860	1.395	Manufacture of Trunk suit case
24	M/s. Hari Chand Steel Fabricator, Nilokheri	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
25	M/s. Sangat Ram Steel Fabricator, Nilokheri	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
26	M/s. Chaman Lal Steel Fabricator, Nilokheri	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
27	M/s. Ram Kishan Soni, Steel Fabricator Nilokheri	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
28	M/s. Kanshi Ram Steel Fabricator, Nilokheri	0.535	10.000	15.750	1.720	28.005	Manufacture of trunks, suit cases Taslas etc.
29	M/s. National Nail Industries, Nilokheri	0.535	6.000	6.000	0.860	13.395	Manufacture of trunks suit cases and Agricultural implements
30	M/s. Tilak Raj Steel Fabricator, Nilokheri	0.535	..	..	0.860	1.395	For the manufacture of Trunks, suit cases etc.
31	M/s. Lal Chand, Madan Steel Fabricator, Nilokheri	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
32	M/s. Sujan Singh, Steel Fabricator, Nilokheri	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
33	M/s. Khurana Trunk House, Pehowa	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
34	M/s. Sharma Trunk House, Thanesar	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
35	M/s. Dharam Chand Steel Fabricator, Thanesar	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
36	M/s. Kishanpura Iron Store, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
37	M/s. Bharat Trunk House, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto
38	M/s. Sita Ram-Ram Sarup, Panipat	0.535	..	6.000	0.860	7.395	For the manufacture of Trunks suit cases etc. and taslas

[Chief Minister]

[Chief Minister]

Serial No.	Name and address	Categories in M. Tons						Total	Purpose
		B. P. Sheets							
		G. P. Sheets	10-14 G.	16-20 G	above 20 G				
1	2	3	4	5	6	7	8		
39	M/s. Kundan Lal-Jita Ram, Panipat	0.535	..	6.000	0.860	7.395	For the manufacture of suit-cases etc.		
40	M/s. Surinder Metal Industries, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Manufacture of Trunks/suit cases		
41	M/s. Maghiana Trunk House, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
42	M/s. Phraya Lal-Jiwan Dass, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
43	M/s. Chaman Lal-Kharaiti Lal, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
44	M/s. Vir Bhan-Aishi Lal, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
45	M/s. Ram Piara Mal, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
46	M/s. Krishna Coop. (I&S) Workers Industrial Workers Society, Panipat	0.535	..	..	1.290	1.825	Ditto		
47	M/s. Channu Ram-Wazir Chand, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
48	M/s. Lila Dhar-Karam Chand, Panipat	0.535	..	..	1.720	2.255	Ditto		
49	M/s. Banarsi Lal-Ashok Kumar, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
50	M/s. Bhoj Raj-raj Bhagwan, Panipat	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
51	M/s. Nirankar Industries, Samalkha	0.535	..	..	1.720	2.255	Manufacture of trunks/suit-cases and Agricultural implements		
52	M/s. Mohan Lal-Shiv Nath, Samalkha	0.535	..	..	0.860	1.395	Ditto		
53	M/s. Mohan Lal-Sukhan Lal, Samalkha	0.535	2.000	..	0.860	3.395	Ditto		
54	M/s. Chandan Lal-Chattar Sain, Panipat	0.535	..	6.000	0.860	7.395	Manufacture of trunks/suit cases and taslas		

55	M/s. Supdt., Rural Artisan Training Centre, Kaithal	0.535	..	5.000	0.860	6.435	For the purpose of General Engineering Machinery parts and training purposes
56	M/s. Sheet Metal Workshop, Nilokheri	0.535	..	..	1.720	2.255	For the manufacture of trunks and machinery parts
57	M/s. B.L. Engineering Works, Kaithal ..	..	..	15.750	1.720	17.470	For the manufacture of machinery parts etc.
58	M/s. Jai Bharat Auto Industries, Karnal ..	..	..	15.750	1.720	17.470	For the manufacture of automobile parts
59	M/s. Agro Engineering and Production Co-operative Industrial Society Ltd., Karnal	..	10.000	30.000	6.610	46.610	For the manufacture of Agricultural implements
60	M/s. Setia Iron and Steel Industries, Village Posiana Kalan, tehsil Panipat	..	..	5.000	..	5.000	For the manufacture of motor parts
61	M/s. Guru Nanak Industries and Workshop, Ladwa	..	10.000	15.750	1.720	27.470	For the manufacture of Agricultural implements
62	M/s. Basdeo Mal-Kashmiri Lal, Panipat	..	3.000	10.000	1.720	14.720	For the manufacture of taslas and Agricultural Implements
63	M/s. Hargopal Dass Bhatia and Sons, Railway Road, Panipat	..	10.000	15.750	1.720	27.470	For the manufacture of steel furniture
64	M/s. Ravi Safe Works, Panipat	..	10.000	15.750	1.720	27.470	Ditto
65	M/s. Bhatia Engineering Works, Panipat	..	5.000	15.750	1.720	22.470	Ditto
66	M/s. Batra Cycle Industries, Panipat	..	..	12.000	1.720	13.720	For the manufacture of cycle parts
67	M/s. Batra Steel Works, Panipat	..	8.000	15.750	1.720	25.470	For the manufacture of steel furniture and cycle parts
68	M/s. J.P. Dhiman and Sons, Panipat	..	..	12.000	..	12.000	For the manufacture of machine parts
69	M/s. Surjan Singh and Sons, Panipat	..	..	12.000	..	212.000	Ditto

**Upgraded Primary School at village Ispur, tehsil Una, district Hoshiarpur**

**3078. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Education be pleased to state —

- (a) whether it is a fact that the Government upgraded the Primary School at village Ispur in tehsil Una, district Hoshiarpur to the middle standard ;
- (b) the shortest distance between the main abadi in the village and the said school and the D.A.V. Higher Secondary School at Khad, a neighbouring village ;
- (c) the rules, if any, framed by the Department for opening new middle schools or upgrading of the Primary Schools to the middle standard ;
- (d) whether it is a fact that a considerable number of students migrated from the Secondary School at Khad to Ispur School resulting in a considerable loss of income to the management of the School at Khad ;
- (e) whether he is aware of the fact that the Khad school was the oldest in the locality and it had suffered enormously on account of opening of new schools in its neighbour-hood ; if so, whether the Government intend to take over the school at Khad in view of the backwardness of the area and its weak financial position ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) Yes.

(b) Distance between the village abadi and the upgraded school at Ispur—1/2 mile.

Distance between the upgraded school at Ispur and D.A.V. Higher Secondary School at Khad—5 miles.

(c) No Middle schools are opened straightaway . The following factors are kept in view for upgrading of primary school to the Middle Standard : Khad

- (1) Availability of sufficient accommodation for housing the new classes and adequate playground etc.
- (2) Availability of sufficient land for further expansion.
- (3) Population likely to be benefited.
- (4) Existing enrolment of the School.
- (5) Distance from the nearest School.
- (6) Amount of contribution by the local community.
- (7) Nature of illaqa—Hilly and Backward.

(d) Yes.

(e) Yes. D.A.V. Higher Secondary School, Khad is an old school. It has suffered some loss on account of migration of students. The school is not proposed to be taken over during the current financial year because it has still to fulfil some conditions laid down by Government for taking over of privately managed schools.

**Electrification of villages in Amritsar District**

**3079. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the total number of applications with names and addresses of the applicants for electric connections for tubewells at present pending in the Jandiala Guru and Butari Sub-Divisions of the Electricity Board and the number and names of the applicants among them who have since submitted their test reports alongwith the dates of submission thereof ;

(b) the number and names of the villages in Amritsar district electrified during the period from 31st March, 1965 up-to-the 31st December, 1965.

(c) the names of villages in Jandiala Guru and Butari Sub-Divisions which are still to be electrified ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon** : (a) (i) 293. Statement attached (Annexure 'A').

(ii) 48. Statement attached ( Annexure 'B')

(b) 10. Statement attached ( Annexure 'C')

(c) 53. Statement attached ( Annexure 'D')

#### STATEMENT ANNEXURE 'A'

State ment of pending applications for Tubewell connections Jandiala Guru and Butari Sub-Divisions as it stood on 31st January, 1966

Serial No.	Name and address of the applicant
1	Hazara Singh .. Ravidaspura
2	Hazara Singh .. Do
3	Chanchal Singh .. Timmoval
4	Atma Singh .. Ekal Gadda
5	Dalip Singh .. Do
6	Sohan Singh .. Jandial Guru
	Bhan Singh
7	Dalip Singh .. Do
8	Kalai Singh .. Do
9	Harbans Singh .. Do
10	Mohan Singh .. Dharar
11	Lekha Ram .. Jandiala
12	Sarain Singh .. Moharbanpura
13	Baldev Singh .. Jandiala
14	Sant Singh .. Do
15	Kesar Singh .. Do
	Mala Singh .. Moharbanpura
15A	Bhan Singh .. Do
16	Amar Singh .. Jandiala
17	Sunder Singh .. Talwandi
18	Budha Singh .. Jandiala
19	Tara Singh .. Dhera Kot
20	Dara Singh .. Do
21	Gurnam Singh .. Do
22	Sangat Singh .. Jandiala
23	Shan Singh .. Do
24	Sadhu Singh .. Do
25	Ujagar Singh .. Do
26	Sadhya Singh .. Khabe Dogran
27	Rattan Singh .. Pakhoke
28	Boota Singh .. Jandialan
29	Kirpa Ram .. Do
30	Thakar Singh .. Do
31	Joginder Singh .. Rakhjita
32	Gian Singh .. Kishan Pura
33	Gurbaz Singh .. Bhut
34	Teja Singh .. Chhajjalwadi
35	Harnam Singh .. Do
36	Avtar Singh .. Do
37	Karam Singh .. Michhal
38	Teja Singh Karam .. Chohan
39	Boota Singh .. Timmoval
40	Chanda Singh .. Talwandi
41	Ganga Singh .. Do
42	Ujagar Singh .. Do
43	Pritam Singh .. Shahpur

## [Minister for Transport and Election]

1	2	3
44	Thakar Singh	.. Shahpur
45	Harnam Singh	.. Do
46	Capt. Kartar Singh	.. Do
47	Baghar Singh	.. Do
48	Ujagar Singh	.. Do
49	Capt. Kartar Singh	.. Taragarh
50	Surain Singh	.. Do
51	Gurdial Singh	.. Do
52	Surat Singh	.. Do
53	Gurdial Singh	.. Do
54	Tara Singh	.. Do
55	Ujar Singh	.. Do
56	Hazara Singh	.. Do
57	Balwant Singh	.. Do
58	Utam Singh Jagat Singh etc.	.. Sansara
59	Inder Singh	.. Malian
60	Gopal Singh	.. Do
61	Balbir Singh	.. Do
62	Balwant Singh	.. Chhajal Wai
63	Teja Singh	.. Ditto
64	Jhanda Singh	.. Chohan
65	Labh Singh	.. Takhtu Chak
66	Ganga Singh	.. Chhajal Wadi
67	Gurdial Singh	.. Saidpur
68	Dewan Singh	.. Dhadded
69	Sohan Singh	.. Do
70	Ajit Singh	.. Bhitte
71	Surta Singh	.. Do
72	H.S. Randhawa	.. Chanake
73	Dasunda Singh	.. Do
74	Inder Singh	.. Takkapur
75	Gurcharan Singh	.. Meharbanpura
76	Hazara Singh	.. Do
77	Charan Singh	.. Mehta
78	Durdial Singh	.. Dhardoe
79	Darshan Singh	.. Do
80	Sahel Singh	.. Do
81	Santa Singh	.. Do
82	Shangara Singh	.. Saidpur
83	Banta Singh	.. Mehta
84	Kishan Singh	.. Khabe Rajputan
85	Gurbaz Singh	.. Takkapur
86	Kashmir Singh	.. Khabe Rajputan
87	Ajaib Singh	.. Takkapur
88	Basant Singh	.. Chung
89	Munsha Singh	.. Do
90	Pritam Singh	.. Khabe
91	Surat Singh	.. Dharmu Chak
92	Mahi Dass	.. Do
93	Kundan Singh	.. Jallal Usman
94	Mansha Ram	.. Khhatwind
95	Sohan Singh	.. Do
96	Kundan Singh	.. Mehta
97	Achhar Siogh	.. Khabe Rajputan
98	Ganda Singh	.. Dharmu Chak
99	Sardul Singh	.. Takkapur
100	Delar Singh	.. Tanel
101	Kanwal Singh	.. Do
102	Amrik Singh	.. Dharmu Chak
103	Fauja Singh	.. Do
104	Kundan Singh	.. Bhutter
105	Harbans Singh	.. Do
106	Chur Singh	.. Mehta
107	Pritam Singh	.. Mehsum Pur

1

2

3

108	Kartar Singh	..	Dharmu chak
109	Darshan Singh	..	Do
110	Bawa Singh	..	Jallal Usman
111	Puran Singh	..	Ditto
112	Banta Singh	..	Ditto
113	Santa Singh	..	Mangali
114	Pritam Singh	..	Udho Nangal
115	Dalip Singh	..	Khadew Rajputan
116	Hazara Singh	..	Udho Nangal
117	Jassa Singh	..	Do
118	Sucha Singh	..	Do
119	Harnam Singh	..	Bhutter
120	Ujagar Singh	..	Khabe Rajputan
121	Harnam Singh	..	Bhowal
122	Kartar Singh	..	Bhowal
123	Harnam Singh	..	Do
124	Jagir Singh	..	Bhowewal
125	Jagir Singh	..	Do
126	Dalip Singh	..	Mangli
127	Rattan Singh	..	Chhajjal
128	Gurmaj Singh	..	Rakh Devidaspura
129	Sadhu Singh	..	Talwandi
130	Durdial Singh	..	Janian
131	Tara Singh	..	Michhal
132	Teja Singh	..	Do
133	Makhan Singh	..	Do
134	Arjan Singh	..	Khalchian
135	Inder Singh	..	Banian
136	Swaran Singh	..	Dhulka
137	Udhan Singh	..	Michhal
138	Suman Singh	..	Banian
139	Assa Singh	..	Michhal
140	Fauja Singh	..	Do
141	Samand Singh	..	Banian
142	Harnam Singh	..	Sodhewa
143	Bishan Singh	..	Muchhal
144	Ram Kaur	..	Bodhewal
145	Ajib Singh - Bhan Singh	..	Do
146	Jarnail Singh	..	Sudhar
147	Sarpanch	..	Kaleke
148	Surain Singh	..	Bhorchi Rajputan
149	Santa Singh	..	Do
150	Harnam Singh	..	Do
151	Santa Singh	..	Do
152	Teja Singh	..	Jallowal
153	Sandhu Singh	..	Bhorchi Rajputan
154	Bahadur Singh	..	Dhulka
155	Inder Singh	..	Jharunnangal
156	Narinder Singh	..	Dhulka
157	Kartar Singh	..	Bhorchi Rajputan
158	Mohan Singh	..	Do
159	Inder Singh	..	Dhulka
160	Ralla Singh	..	Kaleke
161	Balwant Singh	..	Bhallipur
162	Harnam Singh	..	Do
163	Narinjan Singh	..	Do
164	Lakha Singh	..	Sudhar
165	Karnal Singh	..	Dhulka
166	Jaswant Singh	..	Sudhar
167	Partap Singh	..	Do
168	Lakha Singh	..	Do
169	Dharam Singh	..	Kaleke
170	Chhattar Singh	..	Bhalaipur
171	Mana Singh	..	Kaleke

## [Minister for Transport and Elections]

1	2	3
172	Joginder Singh	.. Bhalaipur
173	Prem Singh	.. Kalek e
174	Makhan Singh	.. Dhulka
175	Bagat Singh	.. Jaspal
176	Dhana Singh	.. Bhorehi Rajputan
177	Jawand Singh	.. Wadala Kalan
178	Narain Singh	.. Dhorahi Rajputan
179	Sawaran Singh	.. Wedala Kalan
180	Piara Singh	.. Rattan Garh
181	Shmt. Jeewo	.. Sudhar
182	Pritam Singh	.. Dheriwal
183	Jalla Singh	.. Bhinder
184	Gurbax Singh	.. Narinjanpur
185	Hazara Singh	.. Kaleke
186	Darshan Singh	.. Sudhar
187	Garib Singh	.. Jallowal
188	Pritam Singh	.. Dhulka
189	Balkar Singh	.. Do
190	Bhinder Singh	.. Do
191	Massa Singh	.. Do
192	Mohan Singh	.. Do
193	Noor Singh	.. Wadala Khurd
194	Gurdial Singh	.. Sadhar
195	Pasahra Singh	.. Bhhinder
196	Chanan Singh	.. Do
197	Roor Singh	.. Sarja
198	Hazara Singh	.. Do
199	Kartar Singh	.. Do
200	Misra Singh	.. Do
201	Bhadur Singh	.. Bhorchi Frahman
202	Chanan Singh	.. Sudhar
203	Karam Singh	.. Blolla
204	Harbhajan Singh	.. Bahadurpur
205	Bela Singh	.. Cheam Bath
206	Dashan Singh, Santokh Sing	.. Do
207	Jarnail Singh, Ghasit Singh	.. Bhalaipur
208	Gurmit Singh	.. Pattuwal
209	Mala Singh, son of Ishar Singh	.. Do
210	Bachan Singh, son of Mela Singh	.. Do
211	Inder Singh, son of Jiwan Singh	.. Cheema Bath
212	Joginder Singh	.. Fattuwal
213	Joginder Singh	.. Gaggerewal
214	Ganta Singh	.. Cheema Bath
215	Labh Singh	.. Balojia
216	Surat Singh	.. Bhule Mangal
217	Sohan Singh	.. Bhule Mangal
217A	Pritam Singh	
218	Smear Singh, son of Sohan Singh	.. Bhule Nangal
219	Harbhajan Singh	.. Bahadurpur
220	Teja Singh	.. Gaggerewal
221	Bhan Singh	.. Bhalaipur
222	Bishan Singh	.. Baba Bakala
223	Bhan Singh	.. Do
224	Hukam Singh	.. Jama!pur
225	Bahadur Singh	.. Do
226	Paul Singh	.. Do
227	Partap Singh	.. Butala
228	Basant Singh	.. Jaggar
229	Sewa Singh	.. Baba Bakala
230	Sant Singh	.. Do
231	Sohan Singh	.. Do
232	S.D.E. Phealth	.. Do
233	S.D.E. Phealth	.. Do
234	Biant Singh	.. Butala
235	Beota Singh	.. Do
236	Pal Singh	.. Do
237	Bagwan Singh	.. Do

Serial No.	Name and address of applicant
238	Bela Singh .. Kartarpur
239	Bahadur Singh .. Do
240	Tej Kaur .. Sathiala
241	Gopal Singh .. Lakuwal
242	Bachan Singh .. Do
243	Puran Singh .. Cheema Bath
244	Inder Singh .. Bal Sarai
245	Ajaib Singh .. Jallual
246	Sohan Singh .. Chhappian Wali
247	Talbir Singh .. Jalluwal
248	Lachhman Singh .. Do
249	Gurdip Singh .. Do
250	Mohan Singh .. Chhappian Wali
251	Teja Singh .. Bal Sarai
252	Brij Lal .. Jalalabad
253	Chanan Singh .. Bodhewal
254	Jassa Singh .. Rampur
255	Boor Singh .. Do
256	Gurmit Singh .. Do
257	Bahadur Singh .. Do
258	Sarain Singh .. Sanghar
259	Kartar Singh .. Khadur Sahib
260	Singh .. Do
261	Ajit Singh .. Kallah
262	Avtar Singh .. Jallalabad
263	Samunda .. Sanghar
264	Pritam Singh .. Alia
265	Gurdip Singh .. Rampur
266	Gurcharan Singh .. Ghasitpur
267	Gurmukh Singh .. Kallah
268	Boor Singh .. Do
269	Natha Singh .. Do
270	Reja Singh .. Do
271	Ajaib Singh .. Banian
272	Bahjan Singh .. kallah
273	Inder Singh .. Do
274	Hazara Singh .. Ghasirpur
275	Ajit Singh .. Sanghar
276	Hakam Singh .. Veroval
277	Hari Singh .. Dinawal
278	Jagir Singh .. Nagoke
279	Didar Singh .. Mughlani
280	Banta Singh Ki .. Kiri Bodhal
281	Mesar Singh .. Do
282	Mangal Singh .. Do
283	Kirpa Singh .. Do
284	Ajit Singh .. Do
285	Lekh Singh .. Khadur Sahib
286	Amar Singh .. Do
287	Paul Singh .. Dinawal
288	Banta Singh .. Banian
289	Amar Kaur .. Sarai Talwandi
290	Sant Ram .. Dhota
291	Ajaib Singh .. Nagoke
292	Mukhtiar Singh .. Dinawal
293	Hardit Singh .. Nagoke

\*Illegible in Reply supplied by the Govt.

## [Minister for Transport and Elections]

## ANNEXURE B ]

Statement of applicants of Jandiala Guru and Butari Sub-Divisions who have since submitted the Test Reports

Serial No.	Name of Applicant	Date of submission of test Report
1	Mohan Singh	.. 29th January, 1966
2	Raja Singh	.. 29th January, 1966
3	Harnam Singh	.. 25th January, 1966
4	Avtar Singh	.. 25th January, 1966
5	Karam Singh	.. 29th January, 1966
6	Teja Singh	.. 29th January, 1966
	Karam Singh	.. 21st January, 1966
	Jagir Kaur	.. 31st January, 1966
7	Balwant Singh	.. 10th January, 1966
8	Gurdial Singh	.. 11th January, 1966
9	Ajit Singh	.. 11th January, 1966
10	Surta Singh	.. 28th January, 1966
11	Rattan Singh	.. 21st January, 1966
12	Sadhu Singh	.. 17th January, 1966
13	Gurdial Singh	.. 13th December, 1965
14	Tara Singh	.. 13th December, 1965
15	Teja Singh	.. 13th December, 1965
16	Makhan Singh	.. 13th December, 1965
17	Arjan Singh	.. 13th December, 1965
18	Inder Singh	.. 13th December, 1965
19	Swarn Singh	.. 13th December, 1965
20	Udham Singh	.. 15th December, 1965
21	Sarn Singh	.. 15th December, 1965
22	Assa Singh	.. 15th December, 1965
23	Fauza Singh	.. 15th December, 1965
24	Samand Singh	.. 15th December, 1965
25	Harnam Singh	.. 14th December, 1965
26	Bishan Singh	.. 15th December, 1965
27	Ram Kaur	.. 17th December, 1965
28	Ajaib Singh	.. 17th December, 1965
29	Chattar Singh	.. 17th January, 1966
30	Narain Singh	.. 17th January, 1966
31	Pritam Singh	.. 28th January, 1966
32	Labh Singh	.. 28th January, 1966
33	Surat Singh	.. 5th January, 1966
34	Sohan Singh -Pritam Singh	.. 15th January, 1966
35	Smear Singh	.. 18th January, 1966
36	Harbhajan Singh	.. 17th January, 1966
37	Teja Singh	.. 30th November, 1965
38	Bhan Singh	.. 30th November, 1965
39	Bela Singh	.. 30th December, 1965
40	Bahadur Singh	.. 30th December, 1965
41	Tej Kaur	.. 3rd September, 1965
42	Gopal Singh	.. 18th January, 1965
43	Bahan Singh	.. 20th January, 1966
44	Amar Kaur	.. 6th January, 1966
45	Sant Ram	.. 19th January, 1966
46	Ajaib Singh	.. 17th January, 1966
47	Shri Mukhtiar Singh	.. 18th January, 1966
48	Shri Hardit Singh	.. 21st January, 1966

## ANNEXURE 'C'

Statement showing the number of villages in Amritsar District electrified during the period 31st March, 1965 to 31st December, 1965

Serial No.	Name of village	Serial No.	Name of village
1	Balhet	6	Ramuwal
2	Balia	7	Chakwalia
3	Jharu	8	Chuslewar
4	Nangal	9	Mehoka
4-A	Rattoke	10	Tarpai
5	Burj		

## ANNEXURE 'D'

Statement showing the names of villages in Jandiala Guru and Butari Sub- Divisions which are still to be electrified

1	Kotla	28	Malchak
2	Naraingarh	29	Alia
3	Rana Kalan	30	Fatehpur Bedeshian
4	Shahpur	31	Jallowal
5	Nallowal	32	Padee
6	Chung	33	Mudh
7	Dalara	34	Rayya khurd
8	Banjarwal	35	Mijiar
9	Teharpur ]	36	Bhotangarh
10	Tanel	37	Dhande
11	Bopara	38	Saria
12	Saropada	39	Mohamdpur
13	Rajdhan	40	Jala Ipur Sheron
14	Kot Hayat	41	Bhaini Ram Dayal
15	Loharaka	42	Sheron lania
16	Logharh	43	Sheron
17	Banian	44	Ahluwal
18	Mahadepur	45	Talwandi Bodewal
19	Singhaura	46	Uppal
20	Thotihian	47	Gill Kaler
21	Kammoke	48	Garibwal
22	Khera	49	Bhatike
23	Thanewal	50	Talwandi
24	Gajiwal	51	Bhaguan Shian
25	Dulchipur	52	Gadli
26	Devlawala	53	Rajdhewal ]
27	Ahmedpur		

### Loss of Property due to India-Pakistan Conflict in Khem Karan Sector

**3080. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state :

(a) the approximate loss of the movable and immovable property, village-wisely separately that occurred in the recent India-Pakistan conflict on the Khem Karan Sector (Amritsar District) ;

(b) the total number of population affected in the said Sector, village-wise ;

(c) the details of the help given by the Government in the above-mentioned villages in cash and kind, village-wise; and

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

(d) the names of persons who died during the said conflict as a result of Military firing and by shells and mines in the above mentioned villages, village-wise ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) An assessment of the loss to property has yet to be made. The work will be taken in hand as soon as the area is declared safe and accessible to civilians by the Indian Army Authorities.

(b), (c) and (d) A statement is laid on the Table of the House. As joint payment registers are being maintained, village-wise, break-up of the expenditure is not practicable.

(b) Statement showing total number of population affected in the Khem Karan Sector, Village-wise

Serial No.	Name of village	Population affected	REMARKS
1	Khem Karan	7,354	
2	Kalia	575	
3	Sankatra	742	
4	Mastgarh	964	
5	Kals	362	
6	Dhaul Nau	72	
7	Mehdipur	2,325	
8	Machhike	572	
9	Rattoke	2,972	
10	Nurwala	59	
11	Chak Ladheke	..	Be-Chiragh
12	Mai Wala Autar	..	Do
13	Mohammadiwala	..	Do
14	Bhure Kohna	2,284	
15	Bhure Karimpura	860	
16	Manawan	840	
17	Dhool Kohna	835	
18	Thathi Jaimal Singh	740	
19	Dholan	825	
20	Asal Autar	3,320	
21	Serai Valtoha	235	

Serial No.	Name of village	Population affected	Remarks
22	Kotli Wasawa Singh	1,012	
23	Gajjal	737	
24	Valtoha	6,092	
25	Amirke	432	
26	Chima	975	
27	Kalanjar Autar	705	
28	Lakhana	1,205	
29	Dhodhipura	..	
30	Ballianwala	405	
31	Mehmoodpura	1,332	
32	Dibbipura	1,092	
33	Badhal	742	
34	Keshopura	..	
35	Rajoke	4,469	
36	Daudpura	138	
37	Wan	3,093	
38	Bangala	843	
	Total	49,208	

(c) Statement showing the details of help given by Government in the villages of Khem Karan Sector in cash and kind

1.	Cash Doles	..	Rs 13,29,816.00
2.	Cash in lieu of cloth	..	2,10,454.00
3.	Fodder Subsidy	..	5,546.50
4.	Wheat	..	Qls. Kgs. 14,035.50
5.	Quilts	..	11,945
6.	Darris	..	8,993

(d) Statement showing villagewise names of persons who died during the conflict as a result of military firing, and by shells, and mines in Khem Karan Sector

(i) Persons died due to military firing—Nil

## [Minister for Transport and Elections]

## (ii) Persons killed due to shelling—

Serial No.	Name of village	Name of persons died with parentage
1	Bhure Kohna	.. (1) Virsa Singh, son of Bhan Singh (2) Sadhu Singh, son of Inder Singh (3) Joginder Singh, son of Santa Singh (4) Mohinder Singh, son of Banta Singh (5) Gurdip Singh, son of Bhagwan Singh (6) Bahal Singh, son of Hakim Singh (7) Gurdit Singh, son of Gehal Singh (8) Beesa Singh, son of Gehal Singh (9) Smt. Hukmi, widow of Nikka Singh (10) Smt. Bisso, widow of Lal Singh (11) Smt. Santo, widow of Bishan Singh (12) Smt. Mutab Kaur, widow of Tega Singh (13) Naranjan Singh, son of Jagat Singh
2	Varnala	.. (14) Smt. Surjit Kaur, wife of Ajaib Singh (15) Smt. Harbans Kaur, wife of Shebeg Singh (16) Gurdev Singh, son of Shebag Singh (17) Mukhtar Singh, son of Shangara Singh (18) Smt. Jeo, widow of Mohan Singh
3	Valtoha	.. (19) Atma Singh, son of Sunder Singh (20) Sujinder Singh, son of Chanchal Singh (21) Major Singh, son of Sujinder Singh (22) Smt. Kulwant Kaur, widow of Sujinder Singh (23) Baljit Kaur, daughter of of Kulwant Kaur (24) Man Kaur, widow of Bahadur Singh
4	Mehdipur	.. (25) Jiwan Singh, son of Ishar Singh (26) Smt. Summon, wife of Bhagtoo
5	Rattoke	.. (27) Harnam Kaur, wife of Hari Singh
6	Bhura Karimpura	.. (28) Basant Kaur, wife of Mehar Singh
7	Assal Autar	.. (29) Smt. Jasso, widow of Sunder Singh
8	Mastgarh	.. (30) Nihaloo, widow of Mehnga (31) Sajjan Singh, son of Wadhawa Singh

Serial No.	Name of village	Name of persons died with parentage
9	Kalla	.. (32) Chanchal Singh, son of Kundan Singh (33) Mahna Singh, son of Santa Singh (34) Gehna Singh, adopted son of Sher Singh (35) Surjan Singh, son of Bhan Singh (36) Udham Singh, son of Ghasita Singh (37) Shangara Singh, son of Arbal Singh
10	Thathi Jaimal Singh	.. (38) Sohan Singh, son of Sunder Singh (39) Jaimiat Singh, son of Sangat Singh
11	Dassuwal	.. (40) Gajjan Singh, son of Wadhawa Singh
12	Khem Karan	.. (41) Santa Singh, son of Iqbal Singh (42) Booramal, son of Mian (43) Nihal Singh, son of Bir Singh
13	Narla	.. (44) Chanan Singh, son of Surain Singh
14	Bhikhiwind	.. (45) Balkar Singh, son of Budhu
15	Algon	... (46) Des Raj, son of Sant Ram (47) Balkar Singh, son of Budh Singh
16	Mari Gaur Singh	.. (48) Sadha Singh, son of Ujjagar Singh
17	Kalsian Khurd	.. (49) Mukha Singh, son of Piara
18	Kalia	.. (50) Ganga Singh, son of Hardit Singh (51) Amrik Singh, son of Chattar Singh
19	Tattle	.. (52) Jhanda Singh, son of Keshar Singh
20	Balher	.. (53) Sampuran Singh, son of Teja Singh
21	Lakhna	.. (54) Kapur Singh, son of Kesar Singh (55) Chanan Singh, son of Lal Singh (56) Santa Singh
22	Mamoodpura	.. (57) Kabal Singh, son of Santa Singh (58) Mota Singh, son of Inder Singh (59) Tara Singh, son of Atma Singh
23	Cheema Khurd	.. (60) Gura Singh, son of Bur Singh (61) Ujagar Singh, son of Gurdit Singh (62) Hakim Singh, son of Wadhawa Singh (63) Sajjan Singh, son of Ganda Singh (64) Piara Singh, son of Gulab Singh

## [Transport and Election Minister]

Serial No.	Name of village	Name of persons died with parentage
(iii) Persons died due to the explosion of our own Mines		
24	Assal Auttar ..	(65) Bachan Singh, son of Teja Singh (66) Bakhshish Singh, son of Bishan Singh (67) Jassa Singh, son of Kartar Singh
25	Cheema near Valtoha	(68) Kashmira Singh, son of Sunder Singh (69) Piara Singh, son of Teja Singh
26	Valtoha ..	(70) Balbir Singh, son of Arjan Singh (71) Raj Singh, son of Ganga Singh (72) Smt. Karmon, daughter of Saudagar Singh
27	Baura Kohna ...	(73) Chainchal Singh
28	Thaker Koura ..	(74) Mohan Singh, son of Bhola Singh
29	Lakhna ..	(75) Jagir Singh, son of Suraina (76) Milkha Singh, son of Udham Singh
30	Mehdipur ..	(77) Anant Ram, son of Salgram
31	Kalanjer ..	(78) Jagir Singh, son of Ganga Singh
32	Rasulpur ..	(79) Balwant Singh, son of Karnail Singh (80) Sher Singh, son of Karnail Singh (81) Kashmir Singh, son of Gajjan Singh

**Staff in X Ray Departments of Government Medical Colleges and Hospitals at Amritsar, Patiala and Rohtak**

**3081. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Health be pleased to state :—

- (a) the details of the staff working in the X-Ray Departments of the Government Medical Colleges and Hospitals at Amritsar, Patiala and Rohtak and the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, separately, together with their qualifications and pay scales as at present ;
- (b) the detail of the income that accrued to the X-Ray departments of the said colleges / hospitals / institute from:
  - (i) X-ray ;
  - (ii) deep X-ray ;
  - (iii) diaoothermy ; and
  - (iv) cancer therapy etc. ;
 monthwise from Ist January, 1965 to date ; and
- (c) the different kinds of fees charged from the patients in the said department of the said Colleges / Hospitals / Institute during the period mentioned in part (b) above, and the criteria kept in view while charging fees from them ?

**Shrimati Om Prabha Jain** (a), (o) and (c) Statements I (a), I(b), II and III containing the requisite information are attached.

## STATEMENT No. 1(a)

**Details of the staff working in the X-Ray Departments of the Government Medical Colleges and Hospitals, Amritsar, Patiala and Rohiak together with their qualifications and pay-scales**

Name	Designation	Qualification	Pay-scale
<b>Medical College, Amritsar and its attached V.J. Hospital, Amritsar</b>			
Dr. M.L. Aggarwal	.. Professor	.. M.B., B.S. (Punjab), D.M.R. (London), F.A.M.S.	Rs 1,000—75—1,600
Dr. Y.P. Bhandari	.. Assistant Radiologist	.. M.B., B.S. (Punjab), D.M.R. (Bombay), M.D. (Punjab)	250—25—375/25—500/25—750
Dr. S.K. Gupta	.. Assistant Radiologist	.. M.B., B.S. (Punjab), D.M.R. (Punjab)	250—25—375/25—500/25—750
Dr. S. Khanna	.. Registrar	.. M.B., B.S. (Punjab)	.. 250—25—375/25—500/25—750
Dr. Birinder Singh	.. Do	.. M.B., B.S. (Punjab)	.. 250—25—375/25—500/25—750
Dr. N.K. Sarin	.. Senior Medical Officer	.. M.B., B.S. (Punjab)	.. Rs 200 per mensem
Shri M.K. Joshi	.. Senior Radiographer	.. C.R.T	.. 150—10—250
Shri Om Parkash	.. Do	.. Do	.. 150—10—250
Shri Harbans Singh	.. Radiographer.	.. Do	.. 70—4—90/5—120
Shri Tilak Raj	.. Do	.. Do	.. 70—4—90/5—120
Shri Harnam Dass	.. Do	.. Do	.. 70 4—90'5—120
Shri Kewal Krishan	.. Assistant Radiographer	.. Matric	.. 75—5—125

[Health Minister]

Name	Designation	Qualification	Pay-scale
Shri Chhotu Ram	... Laboratory Assistant	.. Matric	.. 50—3—80/4—100
Shri Natinder Kumar	.. Laboratory Attendant	.. Higher Secondary	.. 39½—1—49½/2—59½
Shri Ram Sarup	... Ditto	.. Matric	.. 39½—1—49½/2—59½
Shri Hira Lal	.. Ditto	.. Do	.. 39½—1—49½/2—59½
Shri Lal Singh	.. Radiographer	T.B. Sanatorium, Amritsar .. Under-matric, Trained locally	70—4—90/5—120
Shri Gopal Singh	... X-Ray Assistant	.. Matric	.. 50—3—80/4—100
Shri Siri Ram	.. X-Ray Assistant-cum-Operation Theatre	.. Do	.. 60—100
Medical College, Patiala and its attached Rajendra Hospital, Patiala			
Dr. A.L. Jain	.. Assistant Professor	.. M.B., B.S. (Bombay)	.. 750—50—1,000/50—1,250
Dr. S.S. Sandhu	.. Senior Lecturer	.. M.B., B.S., D.M.R.D.	.. 450—30—600/40—800/50—950
Dr. K.C. Jain	.. Assistant Radiologist	.. M.B., B.S., D.M.R.E.	.. 250—25—375/25—500/25—750
Dr. Gurnam Singh	.. Ditto	.. M.B., B.S., M.D., Part I	.. 250—25—375/25—500/25—750
Dr. Raj Chopra	.. Registrar	.. M.B., B.S.	.. 250—25—375/25—500/25—750
Dr. Tejinder Kaur	.. House Physician	.. M.B., B.S.	.. Rs 200
Shri Ranbir Singh	.. Electrician	.. Matric, Trained Electrician	.. 70—4—90/5—120
Shri Khushi Ram	.. Radiographer	.. Ditto	.. 70—4—90/5—120
Shri Sufesh Kumar	.. Do	.. Ditto	.. 70—4—90/5—120

70-4-90/5-120	Ditto	70-4-90/5-120
Shri Vidya Sagar Sharma	.. Radiographer	.. Matric, Trained Electrician .. 70-4-90/5-120
Shri Mohan Lal Gupta	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Miss Nirmal Bhatnagar	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri Bishambar Nath	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri Raj Kumar Jain	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri Gurmail Singh Sindhu	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri Baldev Singh Kohli	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri Naubat Rai Sharma	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri Des Raj	.. Dark Room Assistant	.. Higher Secondary .. 47½-2-57½/4-77½
Shri Shiv Kumar	.. Ditto	.. Matric .. 47½-2-57½/4-77½
<b>T.B. Centre, Patiala</b>		
Shri Shashi Bhushan	.. Radiographer	.. Matric with Science, Diploma in Radiography 70-4-90/5-120
Shri Ram Singh	.. X-Ray Bearer	.. Knowledge of English, Punjabi 30-½-35
Dr. V.P. Lakhan Pal	.. Medical College, Rohtak, and its attached Hospital Assistant Professor	.. M.D. (Punjab), D.M.R.E. (Bombay) 750-50-1,000/50-1,200
Dr. K.C. Marwaha	.. Assistant Radiologist	.. M.B., B.S., P.C.M.S. 250-25-375/25-500/25-750
Shri Gurcharan Singh	.. Senior Radiographer	.. Matric with Science, Diploma in Radiography 150-250
Shri Ram Narain Arya	.. Radiographer	.. Matric with Science, one year Radiography Course 70-4-90/5-120
Shri Satjit Singh Grewal	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri H. Massey	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri Shri Niwas Sharma	.. Do	.. Ditto .. 70-4-90/5-120
Shri Tersem Nath	.. Do	.. F.A., Radiographer's Diploma 70-4-90/5-120
Shri R.K. Gupta	.. Do	.. Matric with Science, Diploma in Radiography 70-4-90/5-120
Shri Vijay Singh	.. Do	.. F.Sc., one year's Course in Radiography 70-4-90/5-120

[Health Minister]

## STATEMENT No. I(b)

(b) The following staff has been appointed in the X-Ray Department of Institute of Post-Graduate -Medical Education and Research, Chandigarh.

Serial No.	Name and Designation	Qualifications	Scale of Pay
			Rs
1	Dr. K. Lal, Associate Professor, Radiotherapy	M.B., B.S., D.M.R.T.	1,500—50—1,800/75—2,100
2	Dr. J.S. Sodhi, Assistant Professor, Radiology	M.B., B.S., D.M.R., D.M.R.D.	1,000—50—1,400
3	Dr. Brij Bala Gupta, Senior Lecturer in Radiology	M.B., B.S., D.M.R.D.	800—40—1,000
4	Dr. (Mrs). M. Saini, Lecturer in Radiology	M.B., B.S., D.R.M.E.	650—30—950
5	Dr. V.P. Sharma, Tutor in Radiology	M.B., B.S., D.M.R.E.	450—30—600
6	Dr. G.S. Lamba, Tutor in Radiology	M.B., B.S.	450—30—600
7	Dr. (Mrs.) P. Wahi, Tutor in Radiology	M.B., B.S.	450—30—600

## Non-Gazetted Staff

1	Shri Tejinder Singh, Senior Technician Radiology	Matric with Science got 3 months training in Lady Linlithgow Sanatorium	150—5—160/8—240/8—280/10—300
2	Shri Jasbir Singh, Senior Technician Radiology	Matric with Science, passed Radiographer Course	150—5—160/8—240/8—280/10—300
3	Shri Raghbir Singh, Senior Technician Radiology	Ditto	150—5—160/8—240/8—280/10—300
4	Shri Joginder Singh, Senior Technician Radiology	Ditto	150—5—160/8—140/8—280/10—300
5	Shri Sampat Kumar Dhillon, Junior Technician Radiology	Matric with Science, hold certificate of Radiological	80—5—120/5—175
6	Shri Megh Raj Garj, Junior Technician Radiology	Matric with Science, passed Radiographer Course	80—5—120/5—175
7	Shri M.P. Vasudeva, Junior Technician Radiology	Matric with Science, passed C.M.A., Diploma examination of Radiographer training	80—5—120/5—175
8	Shri Uday Singh, Junior Technician Radiology	Matric with Science, got X-Ray training	80—5—120/5—175
9	Shri Benarsi Dass, Junior Technician Radiology	Matric with Science, qualified Radiographer	80—5—120/5—175

## STATEMENT No. II

(b) The details of income accrued to the X-Ray Departments of the Medical Colleges and Hospitals at Amritsar/Patiala/Rohtak

X-Ray    Deep X-Ray    Diapharmy    Cancer Therapy

**Medical College, Amritsar and its attached V.J. Hospital, Amritsar**

		Rs	nP.	Rs	nP.	Rs	nP.
January, 1965	..	3,584.32		9.80		20.00	..
February, 1965	..	4,287.69		16.80		22.00	..
March, 1965	..	5,183.71		11.20		52.00	..
April, 1965	..	4,802.76		113.60		46.00	..
May, 1965	..	5,501.46		59.20		58.00	..
June, 1965	..	4,130.68		189.20		8.00	..
July, 1965	..	5,026.44		58.40		2.00	..
August, 1965	..	5,073.56		116.40		150.80	..
September, 1965	..	1,290.69		8.40		8.40	..
October, 1965	..	3,396.56		83.40		10.00	..
November, 1965	..	3,325.20		32.80		10.00	..
December, 1965	..	3,025.18		10.80		39.20	..

**T.B. Sanatorium, Amritsar**

January, 1965	..	..	..	..	..
February, 1965	..	14.00	..	..	..
March, 1965	..	28.00	..	..	..
April, 1965	..	28.00	..	..	..
May, 1965	..	..	..	..	..
June, 1965	..	..	..	..	..
July, 1965	..	10.00	..	..	..
August, 1965	..	..	..	..	..
September, 1965	..	..	..	..	..
October, 1965	..	..	..	..	..
November, 1965	..	..	..	..	..
December, 1965	..	20.00	..	..	..
January, 1966	..	7.00	..	..	..

**Medical College, Patiala and its attached Rajindra Hospital, Patiala**

January, 1965	..	2,467.00	..	191.00	..
February, 1965	..	2,421.00	..	18.00	..
March, 1965	..	1,545.00	..	70.00	..

## [Health Minister]

	X-Ray	Deep X-Ray	Diatharmy	Cancer Therapy
April, 1965 ..	3,298.00	..	128.00	..
May, 1965 ..	2,472.00	24.00	88.00	..
June, 1965 ..	3,998.00	3.00	112.00	..
July, 1965 ..	3,444.00	4.00	189.00	..
August, 1965 ..	3,492.00	62.00	92.00	..
September, 1965 ..	1,070.00	..	20.00	..
October, 1965 and November, 1965 ..	3,569.00	..	10.00 — 148.00	..
December, 1965 ..	1,542.00	14.00	80.00	..
January, 1966 ..	2,206.00	..	160.00	..
<b>T.B. Centre, Patiala</b>				
January, 1965 ..	14.00	..	..	..
February, 1965 ..	..	..	..	..
March, 1965 ..	..	..	..	..
April, 1965 ..	14.00	..	..	..
May, 1965 ..	14.00	..	..	..
June, 1965 ..	..	..	..	..
July, 1965 ..	..	..	..	..
August, 1965 ..	28.00	..	..	..
September, 1965 ..	10.00	..	..	..
October, 1965 ..	14.00	..	..	..
November, 1965 ..	14.00	..	..	..
December, 1965 ..	..	..	..	..
January, 1966 ..	14.00	..	..	..
<b>Medical College, Rohtak and its attached Hospital</b>				
January, 1965 ..	1,147.32	..	28.00	..
February, 1965 ..	1,197.42	..	33.00	..
March, 1965 ..	878.33	..	18.00	..
April, 1965 ..	1,277.86	..	35.00	..
May, 1965 ..	1,171.31	..	25.00	..
June, 1965 ..	738.21	..	..	..
July, 1965 ..	1,254.46	..	..	..
August, 1965 ..	1,441.39	..	..	..
September, 1965 ..	1,164.07	..	75.00	..
October, 1965 ..	1,189.1	..	..	..
November, 1965 ..	1,242.92	..	9.00	..
December, 1965 ..	1,432.80	..	195.00	..
January, 1966 ..	1,160.98	..	8.00	..

(b) Income from X-ray Department from 1st January, 1965 to 31st December, 1965 in P.G.I., Chandigarh :—

	X-Ray	Diatharmy	Deep X-Ray and Cancer Therapy
	Rs		Rs
January, 1965	2,654.77	..	5.00
February, 1965	3,204.75	..	105.00
March, 1965	3,021.12	..	..
April, 1965	5,798.00	..	45.00
May, 1965	4,811.35	..	75.00
June, 1965	3,045.90	..	13.00
July, 1965	3,787.09	..	170.00
August, 1965	2,615.28	..	2.00
September, 1965	3,324.31	..	4.00
October, 1965	3,719.20	..	24.00
November 1965	2,409.21	..	14.00
December, 1965	2,392.06	..	113.00
Total	40,783.04	..	570.00

## STATEMENT III

(c) The different kinds of fees charged from the patients.

1. No X-Ray fee is charged from the patients having income not exceeding Rs 30.

The Charges are made for the following kinds/types of X-Rays according to the income group :—

Income per patient	X-Ray	Super- ficial X-Ray and light elec- trical treat- ment Rs	Deep X-Ray Treat- ment Rs	Screen- ing charges Rs
Exceeding Rs 30 per mensem but not exceeding Rs 150 per mensem	2	Free	Free	2
Exceeding Rs 150 per mensem but not exceeding Rs 250 per mensem	5	2	4	5
Exceeding Rs 250 per mensem but not exceeding Rs 350 per mensem	7	3	5	7
Exceeding Rs 350 per mensem but not exceeding Rs 500 per mensem	10	5	7.50	10
Exceeding Rs 500 per mensem, but not exceeding Rs 1,000 per mensem	10	6	9.00	10
Exceeding Rs 1,000 per mensem	10	7	10.00	10

Besides above a fee of Rs 16 is charged for per mounted-electro-cardio-gram from patients irrespective of income group if they wish to take away the same. A fee of Rs 14 is levied per film from patients who wish to take away their Skiagram irrespective of the income group.

**Persons insured under Employees State Insurance Scheme in Amritsar  
and certain other places**

**3082. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of persons insured under the Employees' State Insurance Scheme in Amritsar, Chheherta, Batala and Dhariwal separately up to 31st December, 1965 ?

**Chaudhri Rizaq Ram :—**

Amritsar (including Verka)	..	12,570
Chheharta (including Kharsa)	..	7,620
Batala	..	3,700
Dhariwal	..	3,000

**Unions recognised under the Code of Discipline in Amritsar and  
Gurdaspur Districts**

**3083. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to lay on the Table of the House a list of Unions in Amritsar and Gurdaspur Districts which have so far been recognised under the Code of Discipline by the employers ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** The names of the Unions in Amritsar and Gurdaspur Districts which have been recognised under the Code of Discipline are given as under :—

Amritsar	..	1. Textile Mazdoor Ekta Union, Amritsar
		2. Municipal Labour Union, Amritsar
		3. Municipal Mazdoor Sabha, Amritsar
		4. Textile Labour Association, Amritsar

Gurdaspur .. Nil

**B.T./B.ED. Teachers/Teachresses of Provincialised High Schools**

**3084. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- the names of B.T. and B.Ed. teachers and teachresses of the privately managed high schools which were provincialised during the year 1963-64 and thereafter up-to-date district-wise, together with the dates when they were taken into Government service ;
- the criteria kept in view by the Subordinate Services Selection Board while approving the services of the said teachers ;
- whether the record of service of the said teachers in the privately-managed schools was taken into consideration ; if so, the details thereof ; if not, the reasons therefor ;
- whether the length of service of the said teachers with the privately-managed schools will also be counted towards their service and seniority ; if not, the reasons thereof ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) Statement is laid on the Table of the House.

(b) The Board keeps in view the necessary educational qualifications prescribed for recruitment to a post as in the case of fresh entrants.

(c) No. No service record is usually maintained in privately-managed schools.

(d) Since they are fresh entrants, their services under the managements will not be counted for the purpose of seniority in the State Cadre. It will, however, be considered by the Subordinate Services Selection Board, Punjab while drawing up their *inter-se*-seniority.

## STATEMENT

(a)—

District	Serial No.	Name (Shri./Shrimati)	Date of taking over (to be treated as the date of entry into Government service after the approval of the Board)
Amritsar	1	Sukhdevjit Singh	5-12-63
	2	Sarbjit Singh	15-5-64
	3	Sukhdev Singh	15-5-64
	4	Jagjit Kaur	5-12-63
Hoshiarpur	1	Kanwar Sewa Singh	18-2-65
	2	Kanwar Pancham Singh	18-2-65
Ludhiana	1	Amarjit Kaur	5-12-63
	2	Gurwant Kaur	5-12-63
	3	Joginder Kaur	5-12-63
Karnal	1	Amar Nath Kaul	1-9-64
	2	Shiv Lal	1-9-64
	3	Sher Singh	1-9-64
Kangra	1	Narotam Chand Austi	6-7-64
	2	Tilak Raj Dogra	6-7-64
	3	Puran Chand Joshi	7-2-64
	4	Sat Dev Sharma	7-2-64
Patiala	1	Sarwan Singh	5-11-63
	2	Randhir Singh	5-11-63
	3	Ajaib Singh	5-11-63
	4	Ajit Singh	5-11-63
	5	Joginder Singh	5-11-63
	6	Shashi Kaushal	4-4-64

**Government Ayurvedic/Unani Dispensaries in Amritsar District**

**3085. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Health be pleased to state the number and names of places, tehsilwise in district Amritsar, where Government Ayurvedic and Unani Dispensaries are functioning at present together with the names, qualifications and the home addresses of the staff working therein ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** A statement containing the requisite information is enclosed.

[Health Minister]

## Statement showing the number of Ayurvedic/Unani Dispensaries, Medical Personnel along with their Home Addresses

Serial No.	Name of place	Ayurvedic/Unani	Tehsil	Name of Vaidya	Qualifications Academic	Professional	Home Address
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manochahal	.. Ayurvedic	Tarn Taran	Shri Nitya Nand	Middle	Vaidya Vachaspati (4 years), D.A.V. College, Jullundur	Village and post Gaglehara, tehsil Una, district Hoshiarpur
2	Kang	.. Do	Do	Shri Gopal	..	A.M.B.S. (5 years) from Guru Kul Kangri, Haridwar	63-A 'Laxmi Niwas, Lawrance Road, Amritsar
3	Dera Sahib	.. Do	Do	Shri Manmohan Sharma	Hindi Rattan	Bishgharcharya from Banwari Lal Ayurved Vidyalaya, Delhi	Sanjiwani Ayurvedic Rasin Shala, Roag Shanti Bhawan, Panipat
4	Ekal Gadha	.. Do	Do	Shri Raj Paul Sindhu	Matric	G.A.M.S. (5 years) from Faculty of Indian Medicine, Punjab, Amritsar	Village and post office Atari, district Amritsar
5	Pandori Sidhwan	Unani ..	Do	Shri Amar Nath	Matric	Kamil-i-Tibbozarhat (4 years) from Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi	Village and post office Bugga Kalan, district Patiala
6	Nagoke	.. Do	Do	Shri Om Parkash, Agnihotri	B.A.	Ditto	3/180, Mander Lane, Mandi Phool, district Bhatinda
7	Bhangali Kalan	.. Ayurvedic	Amritsar	Shri Harbhajan Singh	Matric	Vaidya Vachaspati (4 years) from D.A.V. College, Jullundur	Village and post office Khilchian, tehsil and district Amritsar
	Ekalgarh Dhappian	Do	Do	Shri Jagmohan Bawa	Matric	Ditto	Village and post office Attari, district Amritsar

9	Jalalasman	..	Do	Do	Shri Krishan	Sanskrit Prathama	Ayurvedacharya (4 years) from Government Ayur- vedic College, Patiala	Village Khandu, post office Momad Khara, tehsil Kaithal, district Karnal
10	Daoka	..	Do	Do	Shri Jagdish Chander	Sanskrit (Shastri)	Ayurvedacharya (6 years) from Vidya Peeth, Delhi	Village and post office Bhikhi, tehsil Mansa, district Bhatinda
11	Tabli Sahib	..	Unani	Amritsar	Shri M. S. Kukreja	Matric/Inter.	B.I.M.S. (Delhi)	M. S. Kukreja, son of Shri Kesar Singh, Sarai Guru Ram Dass, Amritsar
12	Kakkar	..	Ayurvedic	Ajnala	Shri Ram Sarup	Matric	Bishgaracharya Dhan- wantri (4 years) from Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi	Village and post office Naudan, district Hoshia- pur
13	Chamyari	..	Do	Do	Shri Baldev Raj	Matric	B.A.M.S. (5 years) from D.A.V. College, Jallundur	Village and post office Lopoke, district Amritsar
14	Gago Mahal	..	Unani	Do	Shri Gurdeep Singh	Middle	Hazikul Tibbia (3 years) Vedic and Unani Tibbia College, Amritsar	Village Chhajalwadi, tehsil and district Amritsar
15	Valtoha	..	Ayurvedic	Patti	Shri Sansar Chand	..	Vaidya Shastri from S.D.P.G. Ay. College, Lahore, 2 Ay. Bhishak, 3, Ayurvedacharya	Village and post office Shakhopur, tehsil and district Kapurthala
16	Makhi Khurd	..	Do	Do	Shri Kishori Lal	..	Vaidya Shastri (3 years) Ayurvedic Vidayala, Patiala	Patiala
17	Bhangala	..	Do	Do	Shri Kishori Lal	..	Ayurvedic Rattan (4 years) from Hindi Sahi- tya Sammelan, Allah- abad	Village and post office Tiwari, tehsil Kharar, district Ambala

## [Health Minister]

Serial No.	Name of place	Ayurvedic/Unani	Tehsil	Name of Dispenser	Registered in Part III	Qualification	Home Address
1	2	3	4	5	6	7	
1	Manochahal	Ayurvedic	Tarn Taran	Shri Sain Dass Joshi	Registered in Part III		Village and post office Kang tehsil Tarn Taran, district Amritsar
2	Kang	Do	Do	Shri Banwari Lal	Enlisted		Son of Shri Devi Ram Jogi, c/o Shri Nihal Singh, Veterinary Stock Assistant, Civil Veterinary Hospital, Gurgaon Cantt.
3	Dera Sahib	Do	Do	Shri Ram Niwas (Resigned on 4th January 1966)	Up-vaidya from the Faculty		Son of Shri Singh Ram, village and post office Karora, tehsil Kaithal (Karnal)
4	Ekalgadha	Do	Do	Shri Balbir Singh	Up-vaidya from Secretary Faculty		Son of Shri Partap Singh, village Doodian (Sangrur)
5	Pandori Sidhwan	Unani	Do	Shri Gurcharan Singh	Enlisted under section 34 of the East Punjab Ayurvedic/Unani Practitioner Act, 1949		Care of Inqualabi Pharmacy, Nurdhi Bazar, Tarn Taran (Amritsar)
6	Nagoke	Do	Do	Shri Murari Lal	Experience of compounding with different practitioners		Son of Shri Telu Ram, Nawanshahar Doaba, Mchalla Buehram (Jullundur)
7	Bhangali Kalan..	Ayurvedic	Amritsar	Shri Des Raj	M.A., M.S.		Village and post office Narote Mehra, tehsil Pathankot (Gurdaspur)
8	Ekalgarh Dhapien	Do	Do	Vacant	..		..
9	Jalalusman	Do	Do	Shri Baij Nath	Up-vaidya from recognised Inst.,		Care of Joshi Kalu Ram, Mohalla Jand Gali (Patiala)

10	Dhulha	..	Do	Do	Shri Krishan Kumar	Up-vaidya from recognised Inst.	Village and post office Chhatae via Panipat (Karnal)
11	Tahli Sahib Holla Mohalla	Unani	Amritsar	Shri Rattan Chand	Practical experience of Unani compounding	Son of Shri Reloo Ram, village and post office Talabpur Pandori (Gurdaspur)	
12	Kakkar	..	Ajnal	Shri Bhoj Dutt	Studied in Gurukul	Care of Prophari Ayurvedic Aushdhalayas, Guru Kul, Raikot (Ludhiana)	
13	Changai	..	Do	Shri Bal Kishan	Up-vaidya from recognised Inst.	Care of Desh Raj, village and post office Samana (Patiala)	
14	Gagomahal	..	Do	Shri Om Parkash	Studied under up to the 6th class	Son of Shri Hans Raj, Doraha Mandi (Patiala)	
15	Valtoha	..	Patti	Shri Amar Chand	Up-vaidya from recognised Inst.	Son of Shri Hardwari Lal, Ghurani Kalan	
16	Makhi Khurd	..	Do	Shri Ram Gopal	Up-vaidya from Faculty	Son of Shri Pala Ram s/o Shri Jagan Nath-Nand Lal, Samana	
17	Bhangala	..	Do	Shri Tara Chand	Ayurvedic Bhishak	Son of Shri Ram Gopal, village and post office Mugatwali, tehsil Jagadhri (Ambala)	
DAIS							
1	Manochahal	..	Ayurvedic	Tarn Taran	Shrimati Prem Kumari	Trained Dai	T. B. Hospital, Ghatdan Kothi, Sangrur
2	Bhangali Kalan..	..	Do	Amritsar	Shrimati Satya Vati	Do	Wife of Shri Gurbachan Singh, village and post office Lohsimbly, tehsil Rajpura, district Patiala
3	Valtoha	..	Do	Patti	Shrimati Bhagwant Kaur	Do	Care of Shri Jaswant Singh Sethi, Havaldar, R.P.F. House No.5/4, Railway Colony, B. Block, Amritsar

**Upgraded Government Primary/Middle Schools in Amritsar District**

**3086. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the number of Government Primary and Middle Schools upgraded to Middle and High Schools, respectively, during the year 1965-66 to date in Amritsar District ;
- (b) the number of class-rooms in each of the said upgraded Middle and High Schools excluding the Headmaster's office, etc. ;
- (c) the area provided in each such school for playgrounds ;
- (d) the number of teaching posts sanctioned for each of the schools mentioned in part (a) above ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a)—

*Primary to Middle*

*Middle to High*

16

8

(b) and (c) Information\* is being collected and will be supplied to the Member later on.

(d) For each school upgraded to  
Middle Standard

For each school upgraded to  
High Standard

- |   |   |
|---|---|
| 1. One post of Master/Mistress in<br>in Rs 110/250 grade                                    | 1. One Headmaster/Headmistress<br>in Rs 250/350 grade |
| 2. Two posts of Language<br>Teachers in Rs 60/120 grade with<br>a start of Rs 72 per mensem | 2. Four Masters/Mistresses in<br>Rs 110/250 grade     |
| 3. One J.B.T. in Rs 60/175 grade  | 3. One P.T.I. in Rs 60/120 grade                      |

### Rural Industrial Estates

**3087. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the name of the Rural Industrial Estates so far built in the State, districtwise and blockwise ; and their location in each case ;
- (b) the total expenses incurred on the buildings and the machinery installed therein in each such Estate ;
- (c) the details of the industries being run at present in each of the said estates ?

**Shri Ram Kishan :** (a), (b) and (c) The requisite information is given in the attached statement. The information given in respect of expenditure incurred on machinery items is approximate only as the machinery is installed by the allottees.

**\*Note.**—For information in reply to parts (b) and (c) of this question please see Appendix to this Debate

## STATEMENT

Serial No.	Name of Rural Industrial Estate	Name of Block	District	Expenditure incurred on building	Approximate expenditure incurred by the parties on machinery	Details of the industries - being run at present
				Rs	Rs	
1	Jawali	.. Nurpur	.. Kangra	.. 1,52,000	..	No application received for allotment of shed from the parties. All sheds are lying vacant
2	Dehragopipur	.. Dehragopipur	.. Do	.. 79,890	..	..
3	Nakodar	.. Nakodar	.. Jullundur	.. 1,41,000	..	..
4	Rurka Kalan	.. Goraya	.. Do	.. 1,29,900	28,000	Autoparts, Electrical accessories, Sanitary Fittings, Wire Drawing, etc.
5	Fatehgarh Churian	.. Fatehgarh Churian	.. Gurdaspur	.. 88,500	..	—
6	Pinjore	.. Manimajra	.. Ambala	.. 1,06,000	18,500	Steel Fabrication, Auto-parts, Shoe Tingles, Surgical goods
7	Morinda	.. Morinda	.. Do	.. 98,755	..	—
8	Dharampur	.. Dharampur	.. Simla	.. 2,21,710	10,000	Brass decoration, cutlery goods and sanitary fittings
9	Otalon	.. Samrala	.. Ludhiana	.. 2,13,400	19,800	Auto-parts

[Chief Minister]

Serial No.	Name of Rural Industrial Estate	Name of Block	District	Expenditure incurred on building		Approximate expenditure incurred by the parties on machinery	Details of the industries being run at present
				Rs	Rs		
10	Ramgarh Sardaran	.. Dehlon	.. Ludhiana	.. 10,600	..	..	..
11	Mohindergarh	.. Mohindergarh	.. Mohindergarh	.. 1,54,000	..	..	..
12	Kaithal	.. Kaithal	.. Karnal	.. 1,28,700	.. 22,000	..	.. Metal casting, auto-parts, cycle parts, gun metal, surgical instruments
13	Haryana	.. Bhunga	.. Hoshiarpur	.. 1,24,000	..	..	..
14	Sunam	.. Sunam	.. Sangrur	.. 86,700	.. 12,800	..	.. Radio assembling, auto-parts, etc.
15	Kathunangal	.. Majitha	.. Amritsar	.. 95,000	..	..	..
16	Talwandi Chaudhrian	.. Sultanpur	.. Kapurthala	.. 1,12,200	..	..	..
17	Sohna	.. Sohna	.. Gurgaon	.. 13,300	.. 1,57,850	..	.. Stove Manufacturing, auto parts
18	Barwala	.. Barwala	.. Hissar	.. 1,00,800	.. 25,300	..	.. Malleable pipe fitting and brass pipe fittings
19	Rai	.. Rai	.. Rohtak	.. 75,600	.. 24,800	..	.. Optical frames manufacturing, auto-parts, cycle parts, etc.
20	Panjgrain	.. Kotkapura	.. Bhatinda	.. 91,000	.. 18,000	..	.. Cement fallays and files, circular saw
21	Sarai Nagal	.. Muktsar	.. Ferozepore	.. 95,000	..	..	..
22	Dhudike	.. Moga	.. Do	.. 1,21,100	.. 1,45,000	..	.. Enamalled goods, tin soda, auto-parts, electrical goods, fruit preservation
23	Banur	.. Rajpura	.. Patiala	.. 2,20,000	.. 38,600	..	.. Auto-parts, steel furniture, Tumbler, locks, wire drawings, etc.

### Arrest of certain persons by Saddar Police Station, Karnal

**3089. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Home and Development with reference to the reply to unstarred Question No. 2934, included in the list of questions for 18th October, 1965, be pleased to state—

- (a) the names of the prosecution witnesses referred to in part (b) of the said reply who have since been examined together with the dates when they were examined and the reasons for not producing them during the period from 25th October, 1964 to 28th October, 1965 ;
- (b) whether the said case has since been decided by the Court ; if so, when ; if not, the total number of dates so far fixed by the Court for hearing and the names of prosecution witnesses referred to in part (b) of the said reply, who appeared on each date ;
- (c) the name and designation of the Police official who had been deputed to pursue the said case ;
- (d) whether the summons were served on the said Prosecution witnesses in respect of each appearance in the Court ?

**Sardar Darbara Singh :** (a)—

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (1) Shri Umra         | .. 9th December, 1965                            |
| (2) Shri Sadhu        | .. 9th December, 1965                            |
| (3) Shri Bharat Singh | .. Given up as unnecessary on 9th December, 1965 |
| (4) H. C. Ram Parkash | .. 7th February, 1966                            |

During the period from 25th October, 1964 to 28th October, 1965, they were produced but they could not be examined by the court.

(b) The case is still pending trial. 23 dates of hearing were fixed by the court in this case.

P.W. Umra attended the court on 14th December, 1964, 18th February, 1965, 31st March, 1965, 28th October, 1965 and 9th December, 1965.

P.W. Bharat Singh attended the court on 14th December, 1964, 8th January, 1965 and 18th February, 1965.

P.W. Sadhu attended the court on 14th December, 1964, 18th February, 1965, 31st March, 1965, 28th October, 1965 and 9th December, 1965.

P.W. Ram Parkash, Head Constable, attended the court on 14th December, 1964, 8th January, 1965, 18th February, 1965 and 7th February, 1966.

(c) P.S.Is. Ranjit Singh, Inder Singh and Baldev Singh have been conducting the prosecution of the case.

(d) There have been in all 23 dates of hearings in this case. Out of these prosecution evidence had been summoned for 11 days of hearings. Service on all the witnesses was effected for 3 dates of hearings. The witnesses were partly served on 6 dates of hearings while no service could be effected on 2 hearings.

### Industrial Licences

**3090. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total number of industrial licences granted, yearwise, from 1961-62 to 1965-66 by the Punjab Government and Government of India for (i) districts in the Punjabi Region ;

[Comrade Ram Chandra]

(ii) the Hindi Region Districts and (iii) Kangra, Simla, Kulu, Lahaul and Spiti Districts of the Hindi Region respectively :

(b) the total amount allocated for and spent by Government on the Industrial Development of the (i) Punjabi Region, (ii) Hindi Region as a whole and (iii) Kangra, Simla, Kulu, Lahaul and Spiti Districts of the Hindi Region, separately, during the period from 1st April, 1961 to date?

**Shri Ram Kishan :** (a) and (b) Statements I and II giving the requisite information are enclosed.

## STATEMENT I

Year	No. of Licences issued in Punjabi Region including Chandigarh	No. of Licences issued in Hindi Region	No. of Licences issued in Kangra, Simla, Kulu, Lahaul and Spiti Districts of Hindi Region	Total
1	2	3	4	5
1961-62	37	41	..	78
1962-63	33	28	..	61
1963-64	38	24	1 (for Kangra District only)	63
1964-65	14	12	..	26
1965-66	12	14	..	26

## STATEMENT II

(Rs in lakhs)

Seral No.	Name of Region/ Districts	Allocations						Actuals			
		1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Punjab Region	61.90	76.69	94.75	1,09.20	1,08.50	44.97	1,45.87	71.84	86.84	
2	Hindi Region	41.96	1,62.62	1,02.11	1,67.37	1,10.57	28.16	41.54	88.77	1,01.94	
	Kangra Simla, Kulu, Lahaul and	15.15	1,20.13	21.81	19.79	21.20	10.92	17.07	13.47	15.68	

Besides the above, an amount of Rs. 330.52 lakhs during the period 1961-66 was provided out of which a sum of Rs. 119.92 Lakhs was utilized during 1961-65 for industrial development in the State, which cannot be split up district-wise.

**Military Officers and other Ranks Awarded Maha Vir Chakra, etc.**

**3092. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased, to state the number of military officers and other ranks belonging to Punjab districtwise, and if possible, tehsilwise who were/have been awarded Vir Chakra, Maha Vir Chakra, Param Vir Chakra and other decorations for displaying gallantry during the Chinese invasion in 1962 and the recent India-Pakistan Conflict ?

**Shri Ram Kishan :** Statements containing the information regarding gallantry decorations, i.e., Param Vir Chakra, Maha Vir Chakra and Vir Chakra awarded to the military personnel belonging to Punjab during Chinese aggression and during the operations against Pakistan are enclosed. State Government do not receive information regarding other Military decorations.

**LIST OF DECOREES WHO WERE AWARDED THE DECORATIONS  
DURING THE CHINESE AGGRESSION.**

(Number, name and rank)  
Particulars of the decoree.

Decoration won

(1)	(2)
<b>DISTRICT ROHTAK.</b>	
IC-8164 Major M. S. Chaudhry V. Maira, District Rohtak.	Maha Vir Chakra.
3132623 Nk. Munshi Ram, V. Bhadana P. O. Kharkhoda, Tehsil Sonipat, District Rohtak.	Vir Chakra
3946 GD (T) Sqn. Ldr. J. M. Nath. V, Barkatabad, tehsil Bahadurgarh, district Rohtak.	Maha Vir Chakra
3138184 Hav. Dharam Singh, village Gubhan Majri, tahsil Jhajjar, district Rohtak	Vir Chakra
Sqn. Ldr. A. S. William, district Rohtak	Vir Chakra
4136414 Jem. Surja, village Bethampur, tahsil Jhajjar, district Rohtak	Vir Chakra
Sep. Nursing Dharampal Singh, village Nirdhan, tahsil Sonapat, district Rohtak	Vir Chakra
<b>DISTRICT LAHAUL AND SPITI</b>	
9100170 Hav. Stanzia Phunchok, village Keylong, district Lahaul and Spiti	Maha Vir Chakra
<b>DISTRICT FEROZEPURE</b>	
JC-4547 Subedar Joginder Singh, village Mahia, post office Daroli Bhaiki, tahsil Moga, district Ferozepore	Param Vir Chakra
Sqn. Ldr. S. K. Badhwar (3973) GD(P), Ferozepore City	Vir Chakra
IC Major Gurdial Singh, village Dhonkat Kalan, tahsil Moga, district Ferozepore	Maha Vir Chakra
<b>DISTRICT AMRITSAR</b>	
M.R. 6455 Capt. B. C. Chopra, Kucha Badha Balb Dhab Khatikan (Amritsar)	Vir Chakra
1155599 T.A. Gurdeep Singh	Vir Chakra

1

2

## DISTRICT GURDASPUR

- 2nd Lt. Pardeep Singh Bhandari (Gurdaspur) .. Vir Chakra
- Nk. Chain Singh, village Bhaini Bangar, post office Qadian, district Gurdaspur .. Maha Vir Chakra

## DISTRICT LUDHIANA

- IC-3275 Major Ajit Singh, village Kotha Shamshawala, post station Jagraon (Ludhiana) .. Maha Vir Chakra
- IC-12920, 2nd Lt. Harish Chander Gujral (Ludhiana) .. Vir Chakra

## DISTRICT SIMLA

- IC-7990 Major Dhan Singh Thapa (Simla) .. Param Vir Chakra

## DISTRICT JULLUNDUR

- 3349770 Sep. Kewal Singh village Kotli Dhan (Jullundur) .. Maha Vir Chakra
- IC-11811 Lt. Hari Pal Kaushik (Jullundur) .. Vir Chakra
- No. 2436723 Hav. Malkiat Singh, village Khurd (Jullundur) .. Vir Chakra
- 3330962 Hav. Kirpa Ram, village Birring, post office Cantt. (Jullundur) .. Vir Chakra
- Sqn. Ldr. K. K. Saini (Jullundur) .. Vir Chakra

## DISTRICT AMBALA

- IC-2651 Major S. S. Randhawa (Ambala), village Adhoi Tolanwali, Barara Co-operative Society .. Maha Vir Chakra
- Wing Commander P. L. Dhawan (Ambala) .. Bar to Vir Chakra
- Captain Gurcharan Singh Bhatia, Yamna Nagar (Ambala) .. Vir Chakra
- IC-6405 Capt. Parshotam Lal Kher, 8-F/27/11C, Chandigarh .. Vir Chakra

## DISTRICT KANGRA

- Hav. Bhag Singh (3941391), village Harnchara, post office Chakmoh, tahsil Hamirpur (Kangra) .. Vir Chakra

## DISTRICT HOSHIARPUR

- 2nd Lt. IC-13176 Bhagwan Dass Dogra, village Dheowan, tahsil Una, district Hoshiarpur .. Maha Vir Chakra

## DISTRICT HISSAR

- JC-6022 Sub. Nihal Singh, village Shi, post office Bhawani, district Hissar .. Vir Chakra

## DISTRICT GURGAON

- IC-7077 Capt. Prem Nath Bhatia 137-B, New Colony, Gurgaon .. Vir Chakra

1

2

4132072 Jem. Ram Chandra, village and post office Mandola, tahsil and district Gurgaon	Vir Chakra
4140476 Nk. Hukam Chand, village Nakhrola, tahsil and district Gurgaon	Vir Chakra
Nk. Dharam Chand Dhillon, village Babroli, tahsil Rewari, district Gurgaon	Vir Chakra
Nk. Ram Kumar, village Gothra, post office Khurd, tahsil Rewari (Gurgaon)	Vir Chakra
Nk. Gulab Singh, village Manthi, post office Khund, tahsil Rewari, district Gurgaon	Vir Chakra
Nk. Singh Ram, village Dhawana, tahsil Rewari (Gurgaon)	Vir Chakra
IC-12681, 2nd Lt. Surrinder Nath Tandon, village Rajpur Kalan, tahsil Balabgarh (Gurgaon)	Vir Chakra

**List of Gallantry Awardees during the Indo-Pak. Conflict**

Number, rank and name

Permanent home address

**AMRITSAR DISTRICT**

**Tahsil Amritsar**

Maha Vir Chakra—

IC-801 Lt. Col. Salim Caleb 3rd Cav. .. C/o Maj. S. Caleb (Retired) Bishops Office,  
Taylor Road, Amritsar

**JULLUNDUR DISTRICT**

**Tahsil Jullundur**

JC No. 18340 Subedar Ajit Singh 4th Bn., Village Sobhana, post office Jullundur  
The Sikh Regt. (Posthumous) Cantt., Jullundur

IC-2990 Lt. Col. Gurbans Singh Sangha Village and post office Jandu Singha,  
3rd Bn., the Garhwal Rifles (Posthumous) tahsil and district Jullundur

**HOSHIARPUR DISTRICT**

**Tahsil Una**

\*IC-4004 Maj. Ranjit Singh Dayal, 1st Bn., Village Kante, post office Paluckwah, tahsil  
The Parachute Regt. Una, district Hoshiarpur

**KANGRA DISTRICT**

**Tahsil Dharamsala**

IC-12701 Capt. Chandar Narain Singh, 22nd Ram Nagar, Dharamsala, district Kangra  
Bn., The Garhwal Rifles (Posthumous)

Number, rank and name

Permanent home address

## FEROZEPORE DISTRICT

## Tahsil Moga

Mahavir Chakra—

Wg. Cdr. P.P. Singh (3871), GD(P)

C/o S. Sucha Singh, Assistant Director of  
Agriculture, G. T. Road, Moga, district  
Ferozepore

## LUDHIANA DISTRICT

## Tahsil Ludhiana

IC-4466 Maj. Bhupinder Singh, 4th Budson Horse (Posthumous) Harnampura, Ludhiana

## AMRITSAR DISTRICT

## Tahsil Amritsar

Vir Chakra—

Flt. Lt. D. N. Rathore (5780) GD(P)

No. 3-A, The Mall, Amritsar

## JULLUNDUR DISTRICT

## Tahsil Jullundur

IC-1351 Lt. Col. Chajju Ram, Regt. of  
ArtilleryV. Daroli Khurd, tahsil and district  
Jullundur

## Tahsil Nakodar

EC-55428 2nd/Lt. Bhupinder Kumar Vaid  
Regiment of ArtilleryVillage and post office Shankar, tahsil  
Nakodar, district Jullundur

## HOSHIARPUR DISTRICT

## Tahsil Hoshiarpur

IC-13651 Lt. Teja Singh, 9th Bn.,  
The J. & K. RiflesVillage and post office Kukanate, district  
Hoshiarpur

## KANGRA DISTRICT

## Tahsil Hamirpur

IC-14602 Capt. Bhikham Singh, 7th Bn.,  
The Punjab RegimentVillage and post office Sujampur Tira,  
tahsil Hamirpur, district Kangra

## Tahsil Kulu

IC-6725 Maj. Sarvjit Singh Ratra,  
The Regiment of Artillery

Dhal Pur Bazar, Kulu, district Kangra

## Tahsil Palampur

9065621 L/Hav Fidoo Ram Regt. of  
Artillery

Village Nora, district Kangra

## Tahsil Nurpur

JC-2807 Niab Risaldar Jagdish Singh Central  
India HorseVillage Prithipur Tika Gangth, tahsil  
Nurpur, district Kangra

## Tahsil Nurpur

Flt. Lt. V. S. Pathania (5198) GD(P)

Village and post office Re. Tahsil Nurpur,  
district Kangra

[Chief Minister]

Number, rank and name	Permanent home address
<b>Vir Chakra—</b>	
<b>FEROZEPORE DISTRICT</b>	
<b>Tahsil Muktsar</b>	
Flt. Lt. H. S. Mangat (5226) GD(N)	Village Kermangat, post office Muktsar, district Ferozepore
<b>LUDHIANA DISTRICT</b>	
<b>Tahsil Ludhiana</b>	
JC-5234 Risaldar Achhar Singh 9th Deccan Horse	Village Kaile, district Ludhiana
<b>Tahsil Jagraon</b>	
IC-8041 Lt. Col. Sampuran Singh 16 Bn., The Punjab Regt.	Village Bassian, P.S. Raikot, tahsil Jagraon, district Ludhiana
<b>AMBALA DISTRICT</b>	
<b>Tahsil Ambala</b>	
IC-14376 2/Lt. Ravinder Singh Bedi, The Sindh Horse	C/o Kanwar Surinder Singh Bedi, Deputy Commissioner, Ambala
3339173 Naib Subedar Ajmer Singh 4th Bn., The Sikh Regt.	Village and post office Boh, tahsil and district Ambala
<b>Tahsil Kharar</b>	
Sqn. Ldr. S. Handa (4816) GD(P)	C/o Prof. D. R. Handa, E-49, Sector 14, Chandigarh
IC-10082 Major Surinder Mohan Sharma, 8th Bn., The J. & K. Rifles (Posthumous)	29-J, Sector 21-A, Chandigarh
IC-8519 Maj. Jatinder Kumar, 15th Bn., The Dogra Regt.	C/o Jessa Ram, Tahsildar Kharar, district Ambala
<b>HISSAR DISTRICT</b>	
<b>Tahsil Bhiwani</b>	
2851209 Rifleman Mathari Singh, 2nd Bn., The Rajputana Rifle (Posthumous)	Village and post office Bapora, tahsil Bhiwani, district Hissar
<b>Tahsil Sirsa</b>	
Sqn. Ldr. A.J.S. Sandhu (4705) GD(P)	Village and post office Moriwala, district Hissar
<b>GURGAON DISTRICT</b>	
<b>Tahsil Palwal</b>	
2853735 Rifleman Mahi Lal Singh, 4th Bn., The Rajputana Rifle	Village and post office Banohari, tahsil Pal- wal, district Gurgaon

Number, rank and name

Permanent home address

Vir Chakra—

## SANGRUR DISTRICT

## Tahsil Sangrur

IC-13986 2/Lt. Surinder Pal Singh Sekhon, Village Ubha, post office Sangrur, district  
Raiputana Rifles (Posthumous) Sangrur

## Tahsil Malerkotla

3348906 L/Nk. Pritam Singh, 4th Bn., Village Niamatpur, post office Amargarh,  
The Sikh Regt. (Posthumous) tahsil Malerkotla, district Sangrur

3341107 Naik Chand Singh, 2nd Bn., The Village Manki Khurd, P. C. Manki Kalan  
Sikh Regt. tahsil Malerkotla, district Sangrur

## BHATINDA DISTRICT

## Tahsil Faridkot

3342135 L/Hav. Gurdev Singh, 1st Bn., Village and post office Jaitu, tahsil Faridkot  
The Sikh Regt. district Bhatinda

## NARNAUL (MOHINDERGARH) DISTRICT

## Tahsil Narnaul

4139233 L/Hav. Umrao Singh, 1st Bn., Village Surjanwas, post office Mohinder-  
The Para Regt. (Posthumous) garh, tahsil Narnaul, district Mohindergarh,

## Treatment given to Comrade Kesar Singh, a Communist Detenu

**3093. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that Comrade Kesar Singh, a communist detenu, has been suffering from serious mental trouble for the last one year and is under treatment in the Mental Hospital, Amritsar, if so, the report of Rajindra Hospital authorities, Patiala on the basis of which he was transferred from Nabha Jail to the Amritsar Hospital for treatment, be laid on the Table of the House ;
- (b) the date since when he is under treatment in the Mental Hospital, Amritsar and the first diagnosis and examination report about his trouble by Dr. Vidya Sagar, Mental Specialist be laid on the Table ;
- (c) the present condition of illness of the said detenu and the nature of treatment being given to him ;
- (d) whether the Government has considered his release on medical grounds, if not, the reasons therefor ?

**Shri Chand Ram :** (a) It is a fact that communist detenu Kesar Singh is suffering from some mental trouble. He is at present detained in District Jail, Amritsar, for treatment in the Mental Hospital, Amritsar.

A copy of the report of the authorities of the Rajindra Hospital, Patiala, is at annexure 'A'.

[Minister for welfare and Justice]

(b) Shri Kesar Singh is under treatment in the Mental Hospital, Amritsar, since 17th August, 1965.

A copy of the report by Dr. Vidya Sagar, Mental Specialist is at Annexure 'B'.

(c) Shri Kesar Singh is now very much improved. He sleeps about 5-6 hours with a small dose of drug with minor interruptions and is relieved of palpitation, night starts and heaviness of head. He had a few Electric treatments in September last, and a few intravenous injections of Penthol Sodium (for harcoanalysis) in October, last. Since then he has been taking medicines by mouth.

(d) The matter is under the consideration of Government.

(a)

#### ANNEXURE 'A'

No. 2011-Pay.

The C.M.O. has mentioned his complaints of sleeplessness etc. The case has been interviewed and C.M.O. note mentioned his complaints and treatment seen. In my opinion he requires close observation and treatment. Arrangements for it may be made appropriately with Punjab Mental Hospital, Amritsar immediately. In the meantime C.M.O., Nabha may treat him for his mental symptoms, as indicated by his note and look after his management. Appropriately for Sedatives and Hypnotics as necessary.

The Professor has been consulted by me about this case

Sd/-  
Registrar Psychiatry,  
Department C.M.C.

Patiala  
Dated 21-7-65.

Sd/- (S.P. Mittal).

#### ANNEXURE 'B'

(b) He has been under treatment at the out-patient clinic of Punjab Mental Hospital, Amritsar, since 17th August, 1965 (Register No. 771-BK-65). He was first seen by Dr. Baldev Kishore P.C.M.S. (I) Psychiatrist, as the undersigned was away on leave. He was diagnosed to have anxiety State. I saw him in September, 1965 and agreed with the diagnosis of Dr. Kishore, and started treating him. No report about the patient's condition was asked from me, but on 15th November, 1965, I wrote the following remarks on the application of the said detenu, for leave on parole :—

"Shri Kesar Singh, has been taking treatment at the out patient clinic of his hospital, since 17th August, 1965 (Register No. 771-BK-65) for chronic Anxiety Neurosis, with Hysterical and depressive features. The only cause is his feeling of unease, due to the fact of his being a detenu, and that he thinks his disease to be dangerous, which it is not. He keeps preoccupied with his illness. Treatment has not had any satisfying result to the patient. He is otherwise, in perfect health."

His only complaint was sleeplessness, palpitation/heaviness in the head, and waking up with a start, several times during the night.

#### Health condition of certain Communist Detenus

3094. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state the present condition of Health of the Communist detenus (1) Comrade Pt. Kishori Lal, Hissar Jail (2) Comrade Fauja Singh Bhullar, Sangrur Jail (3) Comrade Dr. Bhag Singh, ex-M.L.A., Nabha jail (4) Comrade Harnam Singh Chamak, ex-M.L.A., Central Jail, Patiala (5) Comrade Gurbax Singh Ata, Central Jail, Patiala (6) Comrade Kartar Singh Gujapeer, Hissar Jail, together with the detailed reports of the

Jail Medical Officers, and of the Specialists about the condition of each and the nature of treatment being given to each be laid on the Table of the House ?

**Shri Chand Ram:** A statement containing information in respect of each detenu is laid on the table of the House.

Statement containing information in respect of each detenu

1. Pt. Kishori Lal .. Case of chronic Bronchitis with bronchial asthma, loose artificial denture, refractory error,  
Treatment :  
Inj. Stepto Penclin. 1 Cm. O.D.  
Mixture No. 16.  
Tab. Millicortim as required.  
Tab. Aminophylim I.T.D.S.  
  
His case for examination and treatment in the Rajindra Hospital, Patiala, as recommended by the Medical Officer, Central Jail, Hissar is under consideration.
2. Shri Kartar Singh Gujjapir Case of ventral hernia.  
His case for operative treatment in the Civil Hospital, Hissar has recommended by the Medical Officer, Central Jail, Hissar, is under consideration
3. Shri Fauja Singh Bhullar .. On examination :—The Patient is moderately built and nourished. No Jaundice. Throat not congested. Nose showing signs of allergic Rhinitis.  
  
Pulse. 90 per minute with 3-4 extrasystoles coming irregularly volume good.  
  
Blood pressure: 145/95 mm.  
  
Heart, Both sounds heard normally with 2-4 extra-systoles coming irregularly.  
Chest breath sounds are harsh in nature and slightly diminished in intensity. No crepitations or Rhinch heard, Chest appears emphysematous.  
  
Abdomen There is tenderness in Rt. hypochondrium especially in gall bladder area and in epigastrium. No mass palpable. Spleen not palpable.  
  
Gonorrhea, Normal.  
The patient had an attack of myocardial infection in 1955 and he was treated for the same. The patient appears to have cholelithiasis and hyperacidity. For the same the patient needs full investigation. The patient should be referred to some hospital where all facilities are available.
4. Comrade Dr. Bhag Singh He is suffering from enlarged prostate and is being given the following treatment—  
  
1. Tablets Stilbisterol. 1. Tablet TDS.  
2. Alkasol 1 Tea spoonful TDS.  
3. No. 20 20 Oz. 1 TDS.  
  
He has also been advised for operation for the enlarged prostate.

## 5. Harnam Singh Chamak

He was examined on 13th January, 1966 last by the Senior Lecturer in Medicine, at the Medical College, Patiala and was found to be responding favourably to treatment. His blood sugar curve and urine show almost complete control of diabetes. His blood pressure is 155/100

Previously also he had undergone a thorough check-up and after an X-Ray and B.C.G. was diagnosed as a case of Ischaemia of the heart 26th November, 1965, and old case and not a new one.

Earlier still when he was seen by the specialist all the treatment advised by him was given to him.

Lately by ones and twos his 18 teeth have been extracted. He developed sepsis which is being successfully treated

Since he was admitted to the Jail his health has been satisfactory and this weight steady.

Weight on admission 69 Kg. his weight was on 10th February, 1966 was 70 Kg.

## 7. Gurbux Singh Atta

He was admitted to Rajindra Hospital on 16th August, 1965 and was discharged on 2nd September, 1965. He was thoroughly examined and his urine stool and blood etc. was tested and an E.C.G. was taken. After a thorough check up he was found to be case of hypertension (essential) and angina pectoris by the Medical Specialist

The E.N.T. specialist examined him and found that he had a polypus of the nose and allergic rhinitis

The Eye Specialist tested his vision and found that he had a conical cornea and ultimately advised contact glasses for which correspondence is going on.

The Dental specialist provided him with a new denture after extracting the undesirable teeth.

Throughout his stay here he has maintained satisfactory health and weight. His weight on admission was 56 Kg. and on 10th February, 1966 was 56 Kg.

His blood pressure varies between 170/105—175/195.

He had no attacks of angina pectoris since he was discharged from the hospital.

The condition of his nose is satisfactory. He was provided with all the medicines that were prescribed by the Specialists from time to time

**Complaints of Cuts of Rajbahas etc. received by S.D.O.,  
Jandiala Canal Bungalow**

**0095. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the S.D.O., Jandiala Canal Bungalow, Rayya and Athwal of U.B.D.C. received any complaints of cuts of Rajbahas

- and of Bunds near the outlets during the year 1964-65 ; if so, the details of such complaints along with the names of those persons with their addresses who were involved or challaned as a result of the said complaints ;
- (b) whether any Tawans were imposed on the said persons, if so, the details thereof in each case ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) No.

(b) Does not arise.

**Privately-Managed High Schools provincialized in Amritsar District during 1965**

**3096. Comrade Makhan Singh Tarsikka:** Will the Minister for Education be pleased to state —

- (a) the names of the privately-managed High Schools in Amritsar District which were proposed to be provincialized during the year 1965 together with the details of the conditions if any, imposed in each case;
- (b) the names of such schools which were actually taken over during the said period ;
- (c) whether the Education department has received any representations from the managing Committee, Khalsa High School, Tarsikka, for relaxing the conditions mentioned in part (a) above due to its location in the flood affected area since 1955 onward ; if so, copies of these representations and the action taken thereon be also laid on the Table of the House ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) Following seven schools of Amritsar District were proposed to be taken over during the current financial year 1965-66 on the conditions as shown in the enclosed statement :—

- (1) G.N. Khalsa High School, Dehra Sahib ;
- (2) Janta High School, Khilchian ;
- (3) S.I.S. Trust Higher Secondary School, Verka ;
- (4) S.G.A.D. Khalsa Higher Secondary School, Valtoha ;
- (5) National High School, Bhikhiwind ;
- (6) G.T.B. Khalsa High School, Tarsikka.

The condition of payment of 3 years estimated deficit in full has, however, been relaxed by Government in the case of the schools at Serial No. 1 to 4 above. They are required to deposit atleast 5 per cent of three years deficit. The management of G.B.T. Khalsa High School, Tarsikka has committed to pay Rs-7,045 towards deficit and Rs 23,000 towards other shortages. It has been asked to honour its commitment. The management of National High School, Bhikhiwind has already deposited Rs 8,000.

(b) No school has actually been taken over so far. However, orders regarding taking over of school at Valtoha have been issued.

(c) Yes. A copy of the representation is laid on the Table of the House. This representation is under the consideration of the Department.

[Education Minister]

**Conditions laid Down by Government for taking over of Privately Managed Schools (Relevant to part (a) of un-Starred Question No. 3096)**

- (a) The institution is needed in the area on educational grounds.
  - (b) It has got adequate buildings, furniture, equipment and play fields.
  - (c) The management is prepared to hand over all its assets in the shape of buildings, equipment, furniture, library books, science apparatus, play-grounds, etc. to Government.
  - (d) The management is prepared to pay the running cost of the school equal to the deficit in income over expenditure for three years in advance.
  - (e) Government will not be bound to recruit the members of the staff in Government service. Such of them as are considered suitable may be taken over on the Government scales of pay.
  - (f) All deficiencies in the matter of furniture, equipment, science apparatus, library books, etc. will be made good by the management before the school is taken over.
  - (g) Government will take no liability of any kind whatsoever on behalf of the management of the school to be taken over.
  - (h) All the assets of the school as they existed on the 4th May, 1960 and those acquired thereafter will be completely handed over to Government.
  - (i) Only trained hands with satisfactory record of service will be taken over. No untrained teacher or any one whose record of service is found to be unsatisfactory will be taken over.
  - (j) The teachers will be treated as fresh entrants and they will be placed at the bottom of the old Government Teachers' cadre. No credit whatsoever of the previous service will be given.
  - (k) The staff will be given Government grades and their pay will be fixed according to rules. In no case, they would be granted better scales of pay than their counterparts in Government service.
  - (l) Any other condition as may be imposed by Government.
- (c) *Copy of letter, dated nil, from Shri Satwant Singh, Manager, G.T.B. Khalsa High School, Tarsikka (Amritsar) to the Chief Minister, Punjab, Chandigarh*

**Subject.**—Taking over of G.T.B. Khalsa High School, Tarsikka, District Amritsar.

Kindly refer to Memo No. 842-Pr(G)-17/430-65, dated 16th August, 1965 addressed to the District Education Officer, Amritsar. It has been communicated in this Memo. that the Government has decided to take over along with others, G.T.B. Khalsa High School, Tarsikka, District Amritsar, on the condition that the management of the school concerned deposit at least 5 per cent of the three years deficit 'into the Government Treasury. Accordingly the management of the school have deposited Rs 3,150 plus Rs 353 in the treasury at Amritsar vide Chalan No. S/30, dated 4th September, 1965 and No. 5/14, dated 31st August, 1965.

The management has received a subsequent communication from the department enquiring viz. if it has deposited Rs 7,045 plus Rs 23,000 in the treasury. The first amount related to three years deficit and the second related to shortage in the school building and furniture.

In this connection it is stated that the committee under took to pay Government a sum of Rs 23,000 in the year 1962. The Committee could easily have paid this amount if the school could have been taken over in the years 1961 or 1962

With introduction of free education and setting up of new schools in the surrounding villages, the school has been running in deficit. The position of the committee has become

so weak that it can not run the school any longer and contemplate to close it immediately. It is in the fitness of the things to mention here that this village is inhabited by 195 families of military personnel and it is not desirable to collect any contribution from the families of military personnels. The other families are too poor to make any contribution. More over half the population of this village belongs to the scheduled and backward classes communities and the rest residents of this village are also very poor and helpless to make any contribution, as the village is located in flood affected area.

The most glaring example of sacrifice of this village in the present Pak aggression is that shaheed Sardar Harbans Singh, A.S.I. P.A.P., son of Shri Banta Singh Tarsikka had laid down his life at Mhor Choki in Udhampur Tehsil in Jammu sector and has thus raised the head of this village in defending the mother land.

The amount of Rs 3,000 was assessed on account of the cost of construction of one drawing room, one store room, and one clerk room, furniture and equipment. The above deficiency of accommodation has been wrongly assessed as the building of the school is sufficient for a high school. It appears that the accommodation provided on the upper storey had not been taken into account as it was not shown in the plan of the school building. The rooms built on the upper floor can be utilized for the accommodation considered to be deficient. Thus the amount of Rs 23,000 need not be recovered from the committee.

As already stated the committee has deposited Rs 3,503 in the treasury at Amritsar and an additional sum of Rs 8,000 on account of reserve fund of the school will also be transferred to Government. Thus committee will be actually paying more than three years deficit of the school. Since the committee can not run the school any longer it has decided to close it. You are requested to order that should be taken over with immediate effect so that the education of the children especially those of military personnel should not be neglected.

Thanking you.

### **Agricultural and Livestock Farm, Hissar**

**3037. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state—

- (a) the total area of land in acres with the Agricultural and Livestock Farm, Hissar ;
- (b) the total amount spent on the (i) entire staff, (ii) feed of the animals, (iii) agricultural activities and (iv) other items at the said farm together with the income of all kinds derived from the farm, during the period from 1960-61 to 1965-66 yearwise ;
- (c) the total number of cattle heads and the expenses incurred on their maintenance, year-wise, during the period mentioned in (b) above ;
- (d) the income derived from the agricultural activities during year 1965-66 ;
- (e) the profit earned or loss incurred by the said farm during the period referred to in part (a) above, year-wise together with the reasons for the loss, if any ?

**Captain Rattan Singh :** (a) 28,860 acres.

(b) to (e) A statement is attached.

## [Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture]

## Statement containing information about Government Livestock Farm Hissar

Year	Amount spent on				Other items (b)(iv)	Income of all kinds (b) (v) and Sahiwal (c)(i)	Amount spent on maintenance of animals (c)(ii)	Income from Agri-cultural activities for 1965-66 to January, 1966 (d)	Profit or loss (e)	
	Entire staff (b)(i)	Feed of animals (b)(ii)	Agri-cultural activities (b) (iii)							
1960-61	..	1,85,057	2,78,736	1,66,582	1,24,329	7,82,942	6,944	2,78,736	7,55,983	3,22,820 Profit
1961-62	..	1,86,511	2,79,963	2,12,046	91,608	8,25,538	6,830	2,79,963	..	2,60,291 Profit
1962-63	..	2,65,719	2,05,628	2,32,535	1,26,089	11,15,242	6,711	2,05,628	..	1,74,140 profit
1963-64	..	4,32,425	85,932	5,90,639	79,629	13,96,084	5,682	85,932	..	4,86,172 profit
1964-65	..	4,99,540	1,04,631	4,87,338	2,26,328	14,08,391	4,975	1,04,631	..	1,13,018 profit
1965-66 (upto December, 1965)	..	3,41,683	77,928	2,75,758	1,86,617	14,03,946	4,912	77,928	..	The profit or loss will be worked out at the close of the financial year when the Proforma accounts are prepared

**Decontrol of Cement in Punjab**

**3099. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to lay on the Table of the House statements showing :—

- (a) the date from which control on the distribution of cement in Punjab was lifted ;
- (b) the date on which intimation in regard to (a) above was sent to the Cement Dealers and a copy of the detailed instructions sent to the cement dealers in this connection, be laid on the Table ;
- (c) the actual stock in hand with the dealers on the date of decontrol ;
- (d) the date by which the stock referred to in part (a) above was to be disposed of ?

**Shri Ram Kishan :** A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) 1st January, 1966

(b) All the District Magistrates in the State were advised on the 23rd December, 1965, to clear the existing stocks of cement lying with the stockists in their respective districts. They, in turn, asked all the permit issuing authorities to arrange for clearance of stocks by the 31st December, 1965. They did not issue any instructions in writing to the cement stockists in this connection

(c) 3673 tonnes

(d) No such date was fixed. There was no price and distribution control after 31st December, 1965.

**Government Aid to Privately-managed Schools in the State**

**3100. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the details of the offer of Government aid made to the managements of the private schools in the State to enable them to bring the scales of pay of the teachers employed by them at par with those of Government teachers ;

(b) the number of institutions, the managements of which have accepted and utilized the offer along with the amount of grant asked for or demanded, to date ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) Nil.

(b) Question does not arise.

**Deaths due to explosion of mines planted by Pakistanis in Border Areas of the State**

**3101. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the total number of people who have died on account of explosion of mines, planted by Pakistanis in the border areas of Punjab during or after the recent Indo-Pakistan conflict ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister) :** None.

**Bhakra Canals**

**3102. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total length of the Bhakra Canals in the State, district-wise ;

[Comrade Ram Chandra]

(b) whether the said canals have created any water logging problem if so, the acreage of the land affected by it districtwise;

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) The total length of the Bhakra Canals in the State districtwise is as under :—

	Miles
Ambala ..	90.25
Patiala ..	692.34
Ludhiana ..	297.28
Sangrur ..	464.96
Hissar ..	1,844.00
Karnal ..	647.00
Jullundur ..	428.25
Hoshiarpur ..	71.19
Kapurthala ..	53.06
Ferozepur ..	626.51
Bhatinda ..	215.21

(b) As a large number of factors are responsible for water logging, e.g., heavy rainfall, floods, obstruction or absence of drainage and geological strata of the soil in a particular terrain, it is not possible to indicate the affect by the Bhakra Canals alone.

#### Share due from Municipalities in respect of Schools provincialized since 1958

**3103. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the names of the Municipalities in the State which have not paid their share of expenses for running the provincialized schools since 1958 ;

(b) the total amount due from each of the said Committee up-to-date ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) & (b) A statement showing the names of the Municipal Committees with amount due from each, as it stood on 30th November, 1965, is placed on the Table of the House.

#### STATEMENT

(a) and (b)—

District	Serial No.	Name of the Municipal Committee	Amount
			Rs
Jullundur ..	1	Jullundur	18,57,703.00
	2	Alawalpur	33,661.00
	3	Nawanshahr	2,40,551.00
	4	Phillaur	80,326.00
	5	Banga	58,709.00

District	Serial No.	Name of the Municipal Committee	Amount
			Rs
Ludhiana	6	Nakodar	72,157.00
	7	Ludhiana	10,16,671.00
	8	Khanna	6,13,449.00
	9	Samrala	66,363.00
	10	Raikot	71,285.00
	11	Jagraon	3,57,634.00
Gurdaspur	12	Gurdaspur	2,05,723.00
	13	Batala	6,48,170.00
	14	Pathankot	5,42,650.00
	15	Sujjanpur	78,704.00
	16	Dhariwal	82,411.00
	17	Dinanagar	2,76,665.00
Hoshiarpur	18	Hoshiarpur	1,27,019.00
Kangra	19	Kangra	49,099.00
	20	Dharmasala	7,693.00
	21	Palampur	78,387.00
Ferozepore	22	Ferozepore	3,99,927.00
	23	Guru Har Sahai	2,86,179.00
	24	Tankawali	42,350.00
	25	Moga	4,29,650.00
	26	Giddarbaha	3,71,434.00
	27	Abohar	5,15,865.00
	28	Zira	1,42,058.00
	29	Muktsar	4,33,254.53
	30	Jalalabad	52,285.00
	31	Fazilka	2,44,420.00
Amritsar	32	Amritsar	61,68,447.00
	33	Tarn Taran	8,12,843.00
	34	Ram Dass	30,115.00
	35	Patti	2,28,881.00
	36	Chhehartta	2,17,341.00

District	Serial No.	Name of the Municipal Committee	Amount
			Rs
	37	Jandiala Guru	.. 6,62,865.00
	38	Khem Karan	.. 1,02,843.00
Ambala	.. 39	Ambala	.. 4,85,227.00
	40	Chhachhrauli	.. 56,061.00
	41	Kalka	.. 4,35,960.00
	42	Rupar	.. 2,75,643.57
	43	Kharar	.. 92,700.00
	44	Yamuna Nagar	.. 7,87,318.00
	45	Jagadhri	.. 2,21,100.00
	46	Sadhaura	.. 44,199.00
Simla	.. 47	Simla	.. 1,27,527.41
Rohtak	.. 48	Rohtak	.. 6,45,167.00
	49	Beri	.. 2,30,284.00
	50	Jhajjar	.. 4,59,956.00
	51	Gohana	.. 60,630.00
	52	Sonepat	.. 1,49,968.00
	53	Bahadurgarh	.. 1,58,308.00
	54	Karnal	.. 5,73,432.00
	55	Kaithal	.. Nil
	56	Shahabad	.. 93,792.00
	57	Panipat	.. 1,66,865.27
	58	Thanesar	.. 78,525.26
	59	Ladwa	.. 1,30,159.00
Hissar	.. 60	Hissar	.. 1,53,022.00
	61	Loharu	.. 80,276.00
	62	Tohana	.. 26,775.00
	63	Kalanwali	.. 1,22,233.00
	64	Fatehabad	.. 1,76,428.00
	65	Jakhal	.. 20,086.00
	66	Dabwali	.. 6,85,192.00

District	Serial No.	Name of the Municipal Committee	Amount Rs.
	67	Bhiwani	.. 1,93,984.00
	68	Sirsa	.. 4,84,858.00
Gurgaon	.. 69	Gurgaon	.. 2,11,148.00
	70	Faridabad	.. 1,24,368.00
	71	Balabgarh	.. 1,49,168.00
	72	Palwal	.. 2,15,142.00
	73	Rewari	.. 2,40,147.00
	74	Hodel	.. 1,30,760.00
	75	Ferozepur-Jhirka	.. 1,01,365.00
	76	Haily Mandi	.. 60,909.00
Patiala	.. 77	Gobindgarh	.. 62,465.36
Bhatinda	.. 78	Bhucho Mandi	.. 2,88,832.00
	79	Kot Kapura	.. 83,339.00
	80	Sangat	.. 10,045.00
	81	Budhladda	.. 29,152.00
	82	Maur Mandi	.. 93,678.00
Sangrur	.. 83	Jind	.. 54,887.00
	84	Barnala	.. 22,013.00
	85	Safidon	.. 28,486.00
Mohindergarh	.. 86	Charkhi Dadri	.. 65,204.00
Hissar	.. 87	Hansi (Hissar)	.. 3,11,897.00

### Schools Upgraded in District Rohtak

**3105. Pandit Charanji Lal Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- the names of the Primary, Middle and High Schools upgraded in Rohtak District from April, 1962, to January, 1966, with the year of their upgradation ;
- the number of the said schools, category-wise, which were upgraded in tehsil Sonapat during the said period together with the names of the villages in which these were upgraded ;
- the total number of schools, category-wise, upgraded in Punjab during the said period ;

**Shri Prabodh Chandra :** (a), (b) & (c) A statement showing the requisite information is enclosed.

[Education Minister]

## STATEMENT

	Primary to Middle	Middle to High	Middle to Higher Secondary	High to Higher Secondary
1962-63 .. Nil	.. Nil	.. Nil	..	..
		(1) Government Middle School, Nona Majra	(1) Government High School, Bahu Jholri	
		(2) Government Middle School, Lakhan Majra	(2) Government High School, Berl	
		(3) Government Middle School, Jehazgarh	(3) Government High School, Badli	
		(4) Government Girls Middle School, Badli	(4) Government High School, Bahadurgarh (G)	
		(5) Government Girls Middle School, Kerhanli Pahladpur	(5) Government High School, Sonapat (G)	
1963-64 .. (1) Deepalpur	.. Nil	.. Nil	.. Government High School, Murthal	
(2) Sankhol				
(3) Khanda				
(4) Rurkee				
(5) Khatiwar				
(6) Nadana Kalan				
1964-65 .. Peepli Khera	.. Nil	.. Nil	..	Nil
1965-66 .. (1) Jauli		(1) Bhali Anandpur		

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| (2) Kharak Kalan    | (2) Bega         |
| (3) Ajaib           | (3) Chulkana     |
| (4) Rindhana        | (4) Bhawar       |
| (5) Dehkora         | (5) Assandhe (G) |
| (6) Bhambhewa       | (6) Beri (G)     |
| (7) Chuliana        | (7) Nihri (G)    |
| (8) Seria           | (8) Bhalaut      |
| (9) Mundaheer       | (9) Talao        |
| (10) Gorya          | (10) Ritauli     |
| (11) Chiri          | (11) Bidhlan     |
| (12) Kheri Khumar   | (12) Juan        |
| (13) Bhainsru Khurd | (13) Purkhas     |
| (14) Makioli Kalan  | (14) Pinana      |
| (15) Nanond         | (15) Jaram Kheri |
| (16) Sheikhupura    | (16) Kharakra    |
| (17) Boupania       | (17) Silini      |
| (18) Dhakla         | (18) Machroli    |
| (19) Dnamar         | (19) Barhana     |
| (20) Saman          | (20) Deepalpur   |
| (21) Ahluana        | (21) Ahluana     |
| (22) Perawas        | (22) Kosli (G)   |
| (23) Banwasa        |                  |

[Education Minister]

(a) Primary to Middle	Middle to High	Middle to Higher Secondary	High to Higher Secondary
(24) Kheora			
25) Kharar			
(26) Kherda			
(27) Chhichrana			
(28) Bhainswan Khurd			
(29) Bir Barkatabad			
(30) Bera-i Kalan			
(31) Gochhi			
(32) Gumer			
(33) Gandhi Nagar, Rohtak			
(34) Kulasi			
(35) Khuddan			
(36) Meham			
(37) Tajpur			
(38) Bhadana			
(39) Bahu Jholri			
(40) Sampla			
(41) Bhindawas			
(42) Anwali			
(43) Anwal			

		PART (B)		
1962-63 ..	Nil	Nil	Nil	(1) Government Girls High School, Sonapat
1963-64 ..	Deepalpur	Nil	Nil	(2) Government Girls High School, Murthal
1964-65 ..	Peeply Khera	Nil	Nil	Nil
1965-66 ..	(1) Sheikhpura	(1) Bega	Nil	
	(2) Ahluana	(2) Chulkana		
	(3) Gummar	(3) Nahri (G)		
	(4) Tajpur	(4) Juan		
	(5) Bhadaur	(5) Purkhas		
	(6) Kheora	(6) Deepalpur		
		(7) Pinana		
PART (C)				
1962-63 ..	1	..	13	62
1963-64 ..	78	1	3	24
1964-65 ..	16	6	..	..
1965-66 ..	325	158	1	..
	(including 4 Lower Middle Schools)			

**Villages Electrified in the State**

**3106. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the total number of villages electrified in the State during the period from March, 1962 to January 31, 1966 ;
- (b) the total number and names of the villages electrified during the said period in Rohtak district stating the years in which they were electrified ;
- (c) the total number and names of the villages electrified during the said period in tehsil Sonapat, district Rohtak ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) to (c) Time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

**Tubewell energised in tehsil Sonapat, district Rohtak**

**3107. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the total number of tubewell energised in tehsil Sonapat, district Rohtak during the period from April, 1962 to January, 1966 alongwith the names of the villages where they are situated ;
- (b) the total number of applications made in the said period for energising tubewells and the number of such applications still pending with the authorities ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) & (b) Time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

**Rajbahas irrigating villages in tehsil Sonapat, district Rohtak**

**3108. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the names of the Rajbahas (distributaries) irrigating villages in tehsil Sonapat, district Rohtak, which have their heads on the Eastern Jumna Canal ;
- (b) the total area commanded by such distributaries ;
- (c) whether it is a fact that the said distributaries were a non-perennial previously ;
- (d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, whether all such Rajbahas have now been made perennial, if so, since when and to what effect ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) (1) Bajana Distributary.

- (2) Dobetta Distributary.
- (3) Sargthal Minor.
- (4) Bhainswal Distributary.
- (5) Mohana Minor.
- (6) Guhna Minor.
- (7) Hulana Distributary.
- (8) Naraina Distributary.
- (9) Sardana Distributary.
- (10) Smalkha Distributary.
- (11) Ganaur Distributary.
- (12) Sonapat Distributary.
- (13) Jua Distributary.
- (14) Kakroi Distributary.
- (15) Pai Distributary.
- (16) Harsana Distributary.

- (17) Ladpur Distributary.
- (18) Rajpura Distributary.
- (19) Nahri Major Distributary.
- (20) Nahra Distributary.
- (21) Bowana Distributary.
- (b) 1,64,687 acres.

(c) & (d) No. Except the following :—

*Dates when the Distributary made perennial channels*

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| (1) Smalkha Distributary     | .. 15th October, 1962 |
| (2) Ganaur Distributary      | .. 15th October, 1962 |
| (3) Harsana Distributary     | .. 1955-56            |
| (4) Rajpura Distributary     | .. 15th October, 1962 |
| (5) Nahri Major Distributary | .. 15th October, 1963 |
| (6) Nahri Distributary       | .. Rabi, 1955-56      |

#### **Cases registered in Border Police Stations in Amritsar District**

**3100. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

- (a) whether any cases were registered at the Border Police Stations of Amritsar District in regard to rioting, smuggling, security reasons and disturbing the peace, during the months of September and October, 1965 ; if so, the details thereof, Police Station-wise ;
- (b) the names and addresses of those persons against whom the cases referred to in part (a) above were registered and with what result in each case ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) and (b) No case of rioting, smuggling or disturbing the peace was registered in the Border Police Stations of Amritsar District during the months of September and October, 1965. The following three cases against the persons noted against them were registered at P. S. Bhikhiwind for spreading false rumours regarding Indo-Pak War :—

(i) F.I.R. No. 214, dated 8th September, 1965 Under Rule 35/41 Defence of India Rules.

Hazara Singh, son of Narain Singh, r/o Kale, P. S. Bhikhiwind.

The case is pending in court.

(ii) F.I.R. No. 215, dated 18th September, 1965 U/Rule 35/41 Defence of India Rules.

(1) Lakhwinder Singh, son of Gurdit Singh, r/o Akbarpura, P. S. Bhikhiwind.

(2) Kashmira Singh, son of Bhan Singh, r/o Kacha Pacca, P. S. Bhikhiwind.

(3) Balwant Singh, son of Fauja Singh, r/o Ahmedpura, P. S. Bhikhiwind.

(4) Virsa Singh, son of Tara Singh, r/o Makhi Kalan, P. S. Bhikhiwind.

(5) Mahoorat Singh, son of Banta Singh, r/o Kacha Pacca, P. S. Bhikhiwind.

(6) Ajit Singh, son of Teja Singh, r/o Pohuwind, P. S. Bhikhiwind.

(7) Gurcharan Singh, son of Gujjar Singh, r/o Bhikhiwind.

(8) Gujjar Singh, son of Mangal Singh, r/o Bhikhiwind. The case is pending investigation.

[Home and Development Minister]

(iii) F.I.R. No. 216, dated 22nd September, 1965 U/Rule 35/41 Defence of India Rules.

(1) Piara Singh, son of Amar Singh, r/o Sur Singh, P. S. Bhikhiwind.

(2) Piara Singh, son of Boota Singh, r/o Sur Singh, P. S. Bhikhiwind.

(3) Angrez Singh, son of Ganga Singh, r/o Padhiri Kalan, P. S. Jhabal.

The case is pending investigation.

### **Compensation to the Survivors of late Shri Karnail Singh of Pepsu Road Transport Corporation**

**3110. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

(a) whether it is a fact that one Shri Karnail Singh working as helper in the Pepsu Road Transport Corporation, Paitala died due to an accident while repairing a bus at the Bhatinda Depot ; if so, the amount of compensation, if any, paid to his wife Shrimati Raj Kumari ; if no compensation have been paid, the reasons for the same ;

(b) whether the arrears of pay of the deceased have since been paid to his wife by the General Manager of the said Corporation if so, the total amount so paid, and the details of final decision taken regarding the payment of compensation referred to in part (a) above ;

(c) whether it is a fact that a cheque for Rs 4,200 on account of compensation was handed over to Shrimati Raj Kumari, wife of the deceased, but it was subsequently cancelled ; if so, the reasons for doing so ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) Yes. An amount of Rs 4,200 as compensation had been deposited with the Patiala Treasury on 22nd January, 1965 for payment to the widow of the deceased.

(b) Yes. An amount of Rs 73.87 p. as arrears of pay has been paid to Smt. Raj Kumari on 16th July, 1964.

(c) No. The cheque in fact was presented to the court of the Commissioner, Patiala for payment under the Workmen Compensation Act on 11th August, 1964. Under advice from that office it was subsequently cancelled and the amount was deposited in cash with the Patiala Treasury on 22nd January, 1965 for payment to Shrimati Raj Kumari wife of the deceased .

### **Schools upgraded in Amritsar District**

**3111. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number and names of the Government Primary, Middle and High Schools which were proposed to be upgraded to Middle, High and Higher Secondary standards respectively, in Amritsar District, during the years 1962-63, 1964 and 1965, separately and the names of those schools, category-wise, actually upgraded ?

**Shri Prabodh Chandra :** It is not in public interest to disclose the names of the schools proposed for upgrading during these years. A statement showing the number of schools actually upgraded category-wise is enclosed.

**Schools upgraded in Amritsar District**

Period	Primary to Middle	Middle to High	Middle to Higher Secondary	High to Higher Secondary
1962-63	Nil	Nil	1. Rajoke 2. Diamganj 3. Rata Guda 4. Tur 5. Katra Karam Singh, Amritsar 6. Nawan Kot, Amritsar 7. Mehra Singh Road, Amritsar Nil	1. Mehta Nangal 2. Kang 1. Chola Sahib 2. Patti
1963-64	1. Bundala 2. Jharu 3. Kiampur 4. Kotla Gujran 5. Brahmpur	Nil	Nil	Nil
1964-65	Nil	Nil	Nil	Nil
1965-66	1. Sakhira 2. Pakkarpura 3. Jakhowal 4. Tarsikka 5. Javinda Kalan 6. Bhore Kanah 7. Gumanpur 8. Lauke 9. Bhalaipur 10. Buttar 11. Beas 12. Voin Poin 13. Bath 14. Pandori Sidhwan 15. Preet Nagar 16. Panjavar	1. Lalpura 2. Bhindi Saydan 3. Bachhiwind 4. Ghariala 5. Shahbazpur 6. Gago Majra 7. Akal Gada 8. Dial Bharang	Nil	Nil

2-50  
0-65  
0-08  
3-  
0-25  
207/145-48  
7-48

2-50  
3-00  
0-25  
0-65  
0-08

**Evacuee Land purchased by the Harijans**

**3112. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- (a) the total acreage of evacuee land purchased by the Harijans in auctions during the period from 1st January, 1964 to date, region-wise and district-wise ;
- (b) the total amount of grant, if any, given by the Government in the State to the Harijans for the purchase of the said evacuee land during the said period, district-wise ;
- (c) the total number of families settled by the Government on the said evacuee land during the above mentioned period, district-wise ;
- (d) the names and addresses of those Harijans who have been settled on evacuee land in the Amritsar District up to date with the location of the land and the acreage of land given to each ?

**Sardar Harinder Singh Major :** (a) and (c) A statement showing the total acreage of evacuee land purchased by the Harijans during the period from 1st January, 1964 to 30th November, 1965, along with the Harijan families settled thereon, district-wise in both Punjabi and Hindi regions, is enclosed.

(b) No grant had been given to Harijans for the purchase of evacuee land.

(d) The information is not readily available and the time and labour involved in its collection from the district offices will not be commensurate with the possible benefits to be derived.

**Statement**

(a) and (b)

Serial No.	Name of the District		Area purchased by the Harijans in auction and by transfer from 1st January, 1964 to 30th November, 1965			No. of families benefi- ted
			Cultivated in S.A.	Banjar in O.A.	Ghar- mumkin in O.A.	
1	Amritsar	Punjabi Region	1,101	1,098	444	676
2	Ludhiana		447	863	63	651
3	Patiala		568	193	21	242
4	Sangrur		600	272	27	272
5	Ferozepore		3,020	1,264	23	1,388
6	Gurdaspur		673	581	713	512
7	Hoshiarpur		653	1,837	691	1,001
8	Jullundur		1,607	1,008	747	631
9	Kapurthala		1,864	1,166	293	756
10	Bhatinda		1,006	..	...	353
Total for Punjabi Region			11,539	8,282	3,022	6,482

S. No.	Name of the District	Area purchased by the Harijans in auction and by transfer from 1st January, 64 to 30th November, 1965		No. of families benefited	
		Cultivated in S.A.	Banjar in O.A.	Ghairmumkin in O.A.	
<b>Hindi Region</b>					
1	Ambala	1,400	746	653	995
2	Kangra	31	89	26	169
3	Hissar and	2,532	154	85	933
4	Mohindergarh				
5	Karnal	817	325	..	530
6	Rohtak	404	249	630	253
7	Gurgaon	500	267	298	500
8	Simla	Nil	Nil	Nil	Nil
Total for Hindi Region		5,684	1,830	1,692	3,380

Figures of Mohindergarh District are included in Hissar District

Grand Total	17,223	10,112	4,714	9,862
-------------	--------	--------	-------	-------

### Allotment of Quotas of Zinc, Copper and Tin

**3115. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state the names with addresses of persons and firms who were allotted quotas of zinc, copper and tin during the years 1964 and 1965 at Jandiala Guru, Batala, Jagadhri and Amritsar with the details of the quantity of quota allotted to each, metal-wise ?

**Shri Ram Kishan :** The time and labour involved in collecting the requisite information will not be commensurate with the benefit sought to be derived therefrom.

### Allotment of Quotas of Anode

**3116. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- the names and addresses of those who were allotted quotas of Anode during the years 1964 and 1965 ;
- the names and addresses of those who applied but were not given the said quota during the said period ;

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

- (c) whether the Government while sanctioning the quotas of the said metal, gave preference to those Gold-smiths who took to electro-plating work after the enforcement of the Gold Control Order. If so, the details of such Ex-gold smiths who applied for and were given quotas of this metal during the said period ;
- (d) the names and addresses of Goldsmiths at Ludhiana who applied for Anode quota during 1965 and the details of the action taken by the Government on their application?

**Shri Ram Kishan :** (a) and (b) the time and labour involved in collecting the requisite information would not be commensurate with the results desired to be achieved.

(c) No

(d) M/s G.S. Electroplating Works, Ludhiana and M/s Nirmal Plators, Ludhiana

The case of M/s G.S. Electroplating Works, Ludhiana was covered under the policy and the allotment of Nickel was made to them. The case of M/s Nirmal Plators, Ludhiana, was not covered by the approved policy.

#### **Allotment of Plots in Industrial Area at Amritsar**

**3117. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state the names and addresses of persons who have so far been allotted plots in the Industrial Areas at Amritsar with the measurements of each such plot and the purpose for which it was allotted ?

**Shri Ram Kishan :** No plot has so far been allotted in the Industrial Area, Amritsar. The question of supplying information on other points does not arise.

#### **Villages electrified in Amritsar Tehsil**

**3119. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister or Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the names of the villages so far electrified in the Amritsar tehsil ;
- (b) the names of the villages in the said Tehsil which are within one mile of the electric lines but have not been electrified ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) List attached. (Annexure 'A')

(b) List attached. (Annexure 'B')

#### **ANNEXURE 'A'**

**Statement of villages so far electrified in Amritsar Tehsil**

(a) Nos.—

- (1) Jandiala, (2) Nawankot, (3) Nijjarpura, (4) Henawala, (5) Gehri, (6) Dhirkote, (7) Mebatbunpura, (8) Wadali Legran, (9) Bishamberpur, (10) Devidaspur, (11) Amarkote, (12) Bundala, (13) Janian, (14) Nawanpind, (15) Bhut (16) Thathian, (17) Nangal Guru, (18) Kishanpura, (19) Rakh Jita, (20) Tangra, (21) Chohan, (22) Malian, (23) Timmowal, (24) Kot Khera, (25)

Muchhal, (26) Balia, (27) Rasulpur, (28) Udhonangal, (29) Mehta, (30) Khaba Dogran, (31) Takkapur, (32) Bhutter Sewian, (33) Khardeo, (34) Chananke, (35) Jallal and Usman, (36) Dharmuchak, (37) Saidpur, (38) Nangli, (39) Mehsumpur Kalan, (40) Mehsumpur Khurd, (41) Ghansyampur, (42) Rayya, (43) Bhinder, (44) Jallupur, (45) Lidher, (46) Tong, (47) Pheruman, (48) Dinapur, (49) Kot Mehtab, (50) Chima Bath, (51) Fattuwal, (52) Hamanpur, (53) Umra Nangal, (54) Danial, (55) Baba Bakala, (58) Thathian, (59) Bedadpur, (60) Sathiala, (61) Palia, (62) Gaggar Bhana, (63) Buta'a, (64) Jalari, (65) Khanpur, (66) Jamalpur, (69) Kartarpur, (70) Devidaspura, (71) Beas, (72) Budha Theh, (73) Nazir Bhullar, (74) Daula, (75) Lakhowal, (76) Chapianwali, (77) Jodhe, (78) Balsarai, (79) Dera Radha Swami, (80) Waraich, (81) Bulari, (82) Khalchian, (83) Bhorchi Rajputan, (84) Bhorchi Brahman, (85) Wadala Khurd, (86) Wadala Kalan, (87) Sudhar, (88) Kaleke, (89) Jabhowal, (90) Jodha Nagri, (91) Raraikka, (92) Jaspal, (93) Dhulka, (94) Bamna Chak, (95) Dheriwal, (96) Berianwala, (97) Sarja, (98) Raipur, (99) Rattangarh, (100) Maranjapur, (101) Bhaini, (102) Jharunangal, (103) Sangra, (104) Badeshian Tara Singh, (105) Gunnowal, (106) Chhajjalwadi, (107) Talwandi Bogroan, (108) Rah Mangawala, (109) Bhoiwal, (110) Gaughatwind, (111) Arjan Mangha Hinnan, (112) Verpal, (113) Thathian, (114) Verka, (115) Tung Bala, (116) Mana Wala, (117) Khankot, (118) Chatiwind, (119) Mandiala, (120) Gilwali, (121) Chhaba, (122) Mula Chak, (123) Iban Khurd, (124) Jhand, (125) Kotla Jiwan Singh, (126) Ballaha, (127) Talwandi Dogra, (128) Chittan Kalan, (129) Ram Pura Jitha, (130) Sanag rana Sahib, (131) Mahian, (132) Bhagtipur, (133) Daburji, (133) Nangal Dayal Singh, (134) Mailakpur, (135) Mehoka, (136) Fatehpur Rajputana, (137) Niazampura, (138) Nawanpind, (139) Tirathpura, (140) Akalgarh, (141) Rusalpur, (142) Wadala Khohal, (143) Raipur, (144) Makhan windi, (145) Mabipur, (146) Lothina, (147) Matewal, (148) Chugwan, (149) Gillan, (150) Lola, (151) Bhilowal, (152) Chhapa, (153) Khujala, (154) Chatiwind, (155) Saidolail, (156) Tarsikka, (157) Mukandpur, (158) Niberwind, (159) Khidowali, (160) Mehinian, (161) Meranchuck, (162) Dhada, (163) F.garh Sukar Chuck, (164) Ada Kathunangal, (165) Udokey, (166) Sialka, (167) Bagga, (168) Kathu-Nangal, (169) Gopalpura, (172) Hadyatpura, (173) Ajaibwali, (174) Kalar Mangar, (175) Ludhar, (176) Khushpura, (177) Matuwal, (178) Manga Saria, (179) Dhadiala, (180) Talwandi Dasunda Singh, (181) Hans Bhupalar, (182) Rapuwali Brahmana, (183) Shahzada, (184) Ram Dewali Hinduan, (185) Karion Nangal, (186) Quarlian, (187) Ram Dewali Muslmana, (188) Bala Chuck, (189) Bthu Chuck, (190) Main Bander, (191) Kaly, (192) Chunupur, (193) Khosa, (194) Mahal, (195) Kot Khalsa, (196) Hamdipura, (197) Fatehpur, (198) Bharari ual, (199) Gurukiwadali, (200) Kathiania, (201) Khaper Kheri, (202) Dhaul Kalan, (203) Chamanpura, (204) Rampura, (205) Basarkey, (206) Dhapai, (207) Kotla Dal Singh, (208) Iban Kalan, (209) Tkanda, (210) Wadala Phitewad, (211) Khumania, (212) Kotlinasir Khan, (213) Ghusabad, (214) Mulla Beham, (215) Bhangali Kalan, (216) Bhangali Khurd, (217) Gujarpura, (218) Chachowali, (219) Jaintipura, (220) Pakhapura, (221) Hardo Putili, (222) Viram, (223) Dhoma, (224) Wadala, (225) Sangatpura, (226) Machhi-Nangal, (227) Kotli Gujran, (228) Nawanpind Biriari, (229) Modhipura, (230) Bhandar, (231) Budha Teheh, (232) Umarpura, (233) Bosal Afgana, (234) Bhalowali, (235) Nizampura, (236) Majitha, (237) Harian, (238) Bagewal, (239) Targir, (240) Jalalpura, (241) Chande, (242) Dhignangal, (243) Duppariwind, (244) Bhaini Lidder, (245) Gosal, (246) Burj, (247) Rarpai, (248) Kotla Sultansingh, (249) Kotla Majha Singh, (250) Jaurian, (251) Romanchak, (252) ShamNagar, (253) Burewal Kang, (254) Tharrewal, (255) Marrere Kalan, (256) Marrere Khurd, (257) Rangilpura, (258) Mago Sohian, (259) Ralwandi Khuman, (260) Dadopura, (261) Hamja, (262) Sohiankalan, (263) Birbulpura, (264) Bal Khurd, (265) Bal Khurd, (266) Bal Kalan, (267) Nag Khurd, (268) Nag Naur, (269) Mangli, (270) Bhaini Gill, (271) Muradpura, (272) Pandori, (273) Naushehra Chhote, (274) Naushehra Dharamsala Wala, (275) Verka, (276) Raja Sansi, (277) Adliwala, (278) Balischander, (279) Heir, (280) Kambo, (281) Rudala, (282) Gumtala, (283) Palah Shahib, (284) Kherabad, (285) Mehlanwali, (286) Sansera, (287) Tanewala, (288) Jagdev Kalan, (289) Guru Ka Bagh, (290) Gakhawal, (291) Sangutu Nangal, (292) Daburji, (293) Mammupura, (294) Chetanpura, (295) Kandowali, (296) Pathan Nangal, (297) Harsha Chhina Colony and Scho, (298) Rampura, (299) Bhagwan.

## [Transport and Elections Minister]

## ANNEXURE 'B'

The names of the villages in Amritsar Tehsil which are within one mile of the electric lines but have not been electrified

(b)

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 1. Kotla      | 18. Nijjar               |
| 2. Naraingarh | 19. Rayya Khurd          |
| 3. Rana Kalan | 20. Padde                |
| 4. Shahpur    | 21. Khera Thanewal       |
| 5. Malowal    | 22. Gajawal              |
| 6. Chung      | 23. Rajdhewal            |
| 7. Balera     | 24. Jamalpur             |
| 8. Bangarwal  | 25. Bothangarh Sheron    |
| 9. Teharpur   | 26. Athwal near Matjitha |
| 10. Tanel     | 27. Sekhwan              |
| 11. Bopara    | 28. Budala               |
| 12. Saropada  | 29. Lakhu Kalan          |
| 13. Loharka   | 30. Bhoewali             |
| 14. Lohgarh   | 31. Bua Nangali          |
| 15. Mudhepur  | 32. Babowal              |
| 16. Banian    | 33. Rampur               |
| 17. Kammoke   | 34. Jiwan Bhamer         |

### Issue of Arms Licences

**\*3120. Sardar Trilochan Singh Riasti :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether Government intend to grant licences for Arms (Revolvers/Pistols/Rifles) to all desirable persons in the State, if so, the details of instructions, if any, issued to the District Magistrates in the State in this connection, be placed on the Table of the House ;
- (b) whether there is also any proposal under the consideration of the Government to issue permits to the deserving persons for the purchase of the said weapons at the reserved price, from the Government Ammunition Depots or from Government Malkhanas (under police custody) in the State, if so, the details of the instructions if any, issued on the subject be laid on the Table of the House. if no instructions have yet been issued, the time by which a decision is likely to be taken in this behalf ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes. A copy of Government instructions issued in this behalf is placed on the Table of the House ; and

(b) District Magistrates in the State have been allowed to dispose of, by public auction, non-prohibited bore confiscated ammunition to arms dealers

and other arms licensees, we are authorised to possess such ammunition. Disposal of arms from District Malkhanas is not permissible under the existing rules. Government are, however, considering a scheme to issue non-prohibited bore confiscated arms, lying at the State Fire Arms Bureau, Phillaur, to deserving persons at assessed prices and orders, will issue when the proposal is finalised.

Copy of Memo No. 14413-3H—65/, dated the 17th September, 1965, from the Secretary to Government, Punjab Home Department to all the District Magistrates in the state.

Subject :—Issue of arms licences.

In view of the present emergency the State Government have decided that the issue of arms licences should be liberalised. Applications received for the grant of arms licences may therefore, be considered in the light of the above decision.

### **Sugar/Atta Depots at Chandigarh**

**\*3121. Sardar Trilochan Singh Riasti :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number of sugar/atta depots at Chandigarh, sector-wise as on 1st January, 1966 together with the names of the depot-holders ;
- (b) the names of the depot-holders amongst those mentioned in part (a) above belonging to the Scheduled Castes ;
- (c) if there is no Scheduled Caste depot holder, the reasons why due representation has not been given to persons belonging to Scheduled Castes and the steps Government propose to take to make up their number ;
- (d) whether the Civil Supplies authorities received any applications from persons belonging to the Scheduled Castes and others for allotment of sugar/atta depots at Chandigarh from 1st November, 1965 to todate ; if so, when, together with the names of the applicants with their addresses ;
- (e) the action, if any, taken or proposed to be taken on the applications mentioned in part (d) above ?

**Shri Ram Kishan :** (a) The required information is given in the statement at annexure I.

(b) No sugar/atta depot holder from amongst those mentioned at (a) above, belongs to the Scheduled Castes.

(c) Allotment of sugar/atta depots is made on merits irrespective of the caste considerations.

(d) 24 applications were received after 1st November, 1965 for allotment of depots. The names and addresses of the applicants alongwith the dates when their applications were received, are given in the statement at annexure II. Except Shri Pal Sing Johal, mentioned at serial No. 24 of the statement, no applicant belongs to Scheduled Castes.

e) All the applications have been kept pending for consideration on merits for allotment of depots, as soon as any vacancy/ need arises for the same.

—

[Chief Minister]

## ANNEXURE I

## List of Sugar/ Atta Depots at Chandigarh as on 1st January, 1966

Serial No.	Name of the Depot Holder	Sector	Remarks
1	M/s Ram Tirath Dogra	7	
2	M/s Aggarwal Karyana Store	7	
3	Government Fair Price Shop	7	
4	Shri Sharda Ram Sharma	8	
5	M/s Gupta General Store	9	
6	M/s Kewal Store	9	
7	M/s Happy Store	10	
8	M/s Punjab University Employees Stores	14	
9	M/s Bushan General Store	11	
10	M/s Chet Ram Maini	14	
11	Shri Om Parkash	Labour Colony-14	Atta only
12	M/s Mohan Singh Sons	15	
13	M/s Prem Store	15	65
14	Government Fair Price Shop	16	
15	Government Fair Price Shop	17	
17	Shri Sunder Singh	18	
17	Amritsar Karyana Store	18	
18	M/s Madan Lal-Gian Parkash	19	
19	M/s Patiala Provision Store	19	
20	M/s Sardar Singh-Kulwant Singh	19	
21	M/s Patiala Karyana Store	19	
22	M/s Singla Flour Mill	19	
23	Government Fair Price Shop	19	
24	M/s Radhey Shyam -Shiv Charan Dass	20	
25	M/s Raj Store	20	
26	M/s Kasauli Provisison Store	20	
27	M/s Jamna Dass and Sons	20	
28	M/s New Patiala Provision Store	20	
29	Government Fair Price Shop	20	
30	Shri Surinder Nath	20	Atta only
31	M/s Gopal Singh-Dharam Pal	21	
32	M/s Rulia Ram-Hari Chand	22	
33	M/s Weeran Di Hatti	22	
34	M/s Anant Ram-Jagdish Lall	22	
35	Government Fair Price Shop	22	
36	-M/s Ganpat Rai	23	
37	Mahavir Parshad	23	
38	M/s Bhujai Store	23	
39	M/s Tilak Raj -Chuni Lal	23	
40	Government Fair Price Shop	23	
41	M/s Chaudhry General Store	24	
42	M/s Haryana Laxmi Co-operative Society	Labour Colony, Sector 26	
43	M/s Narsi Ram-Sudesh Kumar	24	
44	M/s Chadha Provision Store	27	
45	M/s Karam Singh and Co.	27	
46	Government Fair Price Shop	27	
47	Goyal Provision Store	28	
48	Shri Gurnam Singh	Labour Colony Industrial Area	
49	M/s Dev Raj-Parshotam Dass	30	
50	Shri Ram Syrup	Labour Colony, Sector--30	Atta only
51	Shri Madan Lal	Ditto	Atta only
52	Shri Sat Paul	Ditto	Ditto

Serial No.	Name of the Depot Holder	Sector	Remarks
53	Shri Churia Ram .. Labour Colony Sector--26	Atta only	
54	Shri Mangat Ram .. Bajwara	Ditto	
55	Shri Parshotam Lal .. Do	Ditto	
56	Shri Lalit Kumar .. Do	Ditto	

## ANNEXURE II

(d) List of applications received after 1st November 1965 for the allotment of Sugar/Atta Depots at Chandigarh

Serial No.	Name of the applicant	Address	Whether Scheduled caste or not	Date of receipt of application
1	Shri Lakhpatt Rai Jain ..	Shop No. 3, 20-C	No	1-11-65
2	Shri Dhan Puj Sethia ..	S.C.F. 5 ..	No	1-11-65
3	Shri Manohar Singh, son of Chattar Singh	House No. 3442, Sector 27	No	3-11-65
4	M/s Gopi Chand and Bros.	S.C.F. No. 44, Sector 28	No	4-11-65
5	Shri Nanak Chand Uppal ..	H. No. 3204, 23-D	No	8-11-65
6	Shri Tilak Raj ..	H. No. 523, 20-A	No	10-11-65
7	Shri Shankar Dass ..	H. No. 1368-A, 20-B	No	11-11-65
8	Shri Tara Chand Gupta ..... M/s ESS TEE Provision Store	Booth No. 52, Sector 14	No	15-12-65
9	Shri Kundan Lal Jain ..	H. No. 24-D, Sector 21	No	15-12-65
10	Shri Krishan Kumar ..	S.C.F. 34, 28-C	No	29-12-65
11	Shri Prem Dutt Verma ..	S.C.F. 35, 28-C	No	5-1-66
12	Shri H.D. Ahuja ..	Cheap Booth-20 ..	No	14-1-66
13	Shri D.S. Singh—M/s. Batra Stores	S.C.F. 15, 10-D	No	19-1-66
14	Shri Gurbux Singh ..	H. No. 2126, 22-C	No	18-1-66
15	Shri Kuldeep Singh ..	S.C.F.37, Sector-18D	No	27-1-66
16	Shri Ram Gopal, Gopal Flour Mills	Sector-15	No	27-1-66
17	M/s. Harnam Singh & Co. ..	101-Grain Market	No	28-1-66
18	Shri Ved Parkash Mahajan ..	Karyana Store, Bajwara Market	No	28-1-66
19	Shri Bal Kishan ...	S.C.F.-4, Sector 19D	No	28-1-66

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the Applicant	Address	Whether Scheduled caste of or not	Date of receipt of application
20	Shri Amar Nath Kohli	.. S.C.F.-38, Sector-23	No	29-1-66
21	Shri Tirlok Chand Mahajan	.. H. No. 2326, 22-C	No	8-2-66
22	Shri Puran Chand	.. H. No. 3013, 23-D	No	31-1-66
23	Shri Bishan Dass	.. H. No. 2253, 19-C	No	8-2-66
24	Shri Pal Singh Johal	.. Booth No. 73, 8-B	Scheduled Caste	18-12-65

### Class I posts in Directorate of Agriculture, Punjab

**3122. Sardar Trilochan Singh Riasti :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- the number and names of class I Officers, seniority-wise in the Directorate of Agriculture, Punjab, as on 1st January, 1966 ;
- the academic qualifications with experiences, of each of the officers mentioned in part (a) above ;
- the number with designations of class I posts in the said Directorate which are vacant at present together with the reasons for not filling them and the time by which the same are likely to be filled up ?

**Sardar Darbara Singh :** Parts (a) and (b)—A statement is laid on the table of the House.

Part (c) —Only one post of Deputy Director of Agriculture (Seeds) is lying vacant . Shri Kharak Singh Mann, Cotton Development Officer in P.A.S. I Class I, is holding the current charge of the duties of this post in addition to his own. It has been decided to fill up this post by direct recruitment and a requisition to this effect has since been placed with the Punjab Public Service Commission. The post will be filled up on receipt of the recommendations of the Commission . However, no time limit can be specified.

## STATEMENT

S. No.	Name of Officer	Designation	Academic qualifications	Experience
1	2	3	4	5
1	Dr. Amrik Singh Cheema	Director of Agriculture	M.Sc. (Agri.) & D.Ed. in Extension Methods (U.S.A.)	Assistant Director of Agriculture, Faridkot State from 7th June, 1945 to January, 1947  Director of Agriculture, Faridkot State from January, 1947 to 31st August, 1948  Assistant Director of Agriculture, Pepsu, from 1st September, 1948 to 13th February, 1950 Deputy Director of Agriculture (Food)/ Joint Director Extension, Pepsu, from 14th February, 1950 to 2nd December, 1955 Director, National Extension Service Pepsu, from 3rd December, 1955 to 31st October, 1956 Deputy Director of Agriculture, Punjab, from 1st November, 1956 to 31st August, 1959 Joint Director (Community Development), Punjab, from 1st September, 1959 to 31st March, 1960 Joint Director, Agriculture (Extension), Punjab, from 1st April 1960 to 28th February, 1963 Additional Director of Agriculture, Punjab, from 1st March, 1963 to 11th December, 1963 Director of Agriculture, Punjab, from 12th December, 1963 onwards
2	Shri Rajinder Singh Kahlon	Joint Director (Soil Conservation and Engineering)	B.Sc. (Agri.) and B.Sc. (Civil Engineering)	From 1st September, 1948 to August, 1949 as Agricultural Officer (Government of India) August, 1949 to February, 1953 as Incharge Land Reclamation Unit (Punjab Government) August, 1956 to December, 1956 as Junior Highway Engineer at Washington under the Government U.S.A

1	2	3	4	5
				January, 1957 May, 1958 as S.D.O., P.W.D. Punjab (Irrigation Branch) (May, 1958 to 6th November 1961 as Assistant Engineer (Government of India) 7th November, 1961 to 4th July, 1963 as Divisional Soil Conservation Officer, Punjab 5th July, 1963 onwards as Joint Director (Soil Conservation and Engineering)
3	Shri P.N. Pangotra	.. Agricultural Engineer (Implementations)	B. Sc. Agri., Section A&B (A.M.I.E. (India) (equivalent to the degree of Mechanical Engineering)	December, 1947 to December, 1953 in private firms. January, 1954 to September, 1954 as Inspector, Agriculture Engineering, Extension Training Centre, Nilkheri. October, 1954 to August, 1961 as Chief Instructor Works, Extension Education Institute, Nilkheri August, 1961 to August, 1962 as Agricultural Engineer, Nahar Foundry Ltd., Government of India Undertaking September, 1962 to March, 1964 as Agricultural Engineer, I.A.D.P., Ludhiana April, 1964 onwards as Agricultural Engineer (Implementations)
4	Shri K.L. Mehra	.. Officer on Special Duty (Minor Irrigation)	B.Sc. (Engineering)	From 1948 to 1955 as Assistant Engineer, Government of India October, 1955 to February, 1965 as Executive Engineer, P.W.D. (Irrigation Branch), Pepsu / Punjab March, 1965 onwards on deputation to the Agriculture Department, Punjab, as Officer on Special Duty, (Minor Irrigation)
5	Shri G.S. Kalkat	.. Deputy Director of Agriculture	M.Sc. (Agri.) and Ph.D. (U.S.A. in Agri. Zoology-Entomology)	From 9th April, 1949 to 31st March, 1960 as Agricultural Inspector/ Locust Control and Warning Officer 1st April, 1960 onwards as Deputy Director of Agriculture

*Note.*—Besides the above mentioned Class I Officers, Sarvshri M.S.V. Ramarao and B.M. Pansare have been re-employed as Soil Conservation Adviser and Grape Extension Adviser respectively in the Agriculture Department. The present term of re-employment of these Officers expires on 28th February, 1966 and 10th June, 1966 respectively.

**Stainless Steel**

**3123. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total quantity of stainless steel imported into the State through the Punjab State Small Industries Corporation during the years 1964 and 1965, for utensil and non-utensil purposes separately ;
- (b) whether Government had formulated any definite policy for the distribution of the said steel before it was actually distributed ; if so, the details thereof be laid on the Table of the House ;
- (c) the names and addresses of the parties who were allotted quotas of stainless steel during the years 1964 and 1965 and the quantity of quota allotted in each case ;
- (d) whether it was ensured that the parties who were allotted the quota mentioned in part (c) above had the necessary machines installed for the manufacture of non-utensil articles ?

**Shri Ram Kishan :** (a)

Year	For the manufacture of utensils	For the manufacture of items other than utensils
1964	..	14 Metric Tonnes
1965	.. 67	221.53 Metric Tonnes

- (b) & (c) The requisite information is enclosed  
(d) Yes.

**Policy for distribution of 14 M.T. Stainless Steel during the year 1964.**

The parties who were issued Essentiality Certificates for the import of S.S. Sheets for the manufacture of Surgical Instruments during the Licensing Period October, 1963—March 1964 and had set up their works and were in a position to utilize the material were made eligible for the allotment of the material out of the allocation of 14 M.T. S.S. during 1964.

2. Keeping in view the meagre quantity of material a maximum ceiling of 0.80 M.T. and minimum allotment of 0.1 M.T. was fixed.

3. The term Surgical instruments used in this location also included manufacture include d manufacture of Surgical equipment and hospital wares.

4. Where the party was engaged both in Surgical Instruments and Cutlery the entitlement for surgical instrument was worked out on 50 per cent basis.

**Statement showing the distribution of stainless steel sheets during 1964**

Serial No.	Name of the Party	Allotment in M. Tons
1	M/s Associated Industries, Jagadhri	.. 0.8
2	M/s Punjab Wire Netting Industries, Narnaul	.. 0.8
3	M/s West end Machinery Mart Ltd., Faridabad	.. 0.8
4	M/s Sharaf Industries, Bahadurgarh	.. 0.8
5	M/s National Steel Industries, Industrial Area, Bahadurgarh	.. 0.8

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the Party	Allotment in M. Tons
6	M/s Rakesh Industries, Chandigarh	.. 0.8
7	M/s Silara Industries, Dhuri Distt. Sangrur	.. 0.1
8	M/s United Iron Industries, Bhiwani	.. 0.4
9	M/s Amrit Metal Industries, Jagadhri	.. 0.1
10	M/s Jainko Industries, Ambala City	.. 0.4
11	M/s Kuldip Industrial Corporation, Chandigarh	.. 0.3
12	M/s T. R. Metal & Engg. Works, Rewari	.. 0.1
13	M/s Data Ram-Ashok Kumar, Kaithal	.. 0.3
14	M/s Bali Ram Chowdhry & Sons, Kaithal	.. 0.1
15	M/s Hem Overseas Auto Industries, Kaithal	.. 0.3
16	M/s Bharat General Mills, Kaithal	.. 0.3
17	M/s Punjab General Manufacturers, Kaithal	.. 0.2
18	M/s Hindustan Chemical & Glass Products, Panipat	.. 0.2
19	M/s Jai Bharat Hardware Co., Industrial Area, Panipat	.. 0.1
20	M/s Jai Industries, Karnal	.. 0.4
21	M/s Setia Iron & Steel Industries, Village Pasina Kalan, Tehsil Panipat District Karnal	0.1
22	M/s Surjan Singh & Sons, Panipat	.. 0.1
23	M/s Free India Surgical Industries, Jullundur	.. 0.3
24	M/s Standard Mechanical Works, Jullundur	.. 0.4
25	M/s Speedway Surgical Co., Ludhiana	.. 0.1
26	M/s J. L. Sumair Chand, Jhajjar Road, Rohtak	.. 0.2
27	M/s Kuldip Industries, Village Mamnoan, Tehsil Pathankot, District Gurdaspur	0.1
28	M/s Sekhri Brothers, Industrial Estate, Batala	0.8
29	M/s Bali Singh Bhagwan Singh Ghee Mandi Amritsar	... 0.8
30	M/s Inderjit & Co., Ludhiana	.. 0.1
31	M/s Jiwan Engineering Works, Ludhiana	.. 0.5
32	M/s New India Engineering Works, Ludhiana	.. 0.4
33	M/s T. F. Industrial Corporation, Ludhiana	.. 0.2
34	M/s Aero Engg. Works, Ludhiana	.. 0.5
35	M/s Rumpas Industries, Ludhiana	.. 0.1
36	M/s Adarsh Metal Works Industries, Jagadhri	.. 0.8
37	M/s Surjit Industries, Malerkotla	.. 0.2
38	M/s Puran Chand-Sharwan Kumar, Kaithal	.. 0.2

**Policy for distribution of Stainless Steel for Non-utensil purposes (1965)**

1. Stainless steel of different gauges was imported from Czechoslovakia and Japan at different prices. It was decided to allot stainless steel sheets to parties in proportionate of 40 per cent from Czechoslovakia (18, 19 & 20G) 40 per cent from Japan (18, 19 & 20 G) and 20 percent 26G from Japan
  2. The Department had recommended the Essentiality Certificates for Import of Stainless Steel for the period October, 1964—March, 1965. These recommendations were withdrawn and the parties were allotted material in proportion to the recommendations made to import authorities for stainless steel in the Government of India.
  3. Material was allotted to parties in whose favour it was decided to meet arrear claims.
  4. Allotment was made taking into consideration the highest value of Essentiality Certificate for stainless steel sheets issued during the last three licensing periods of 6 months each, subject to maximum of 6 M.T. and with a minimum standard of half M.T.
  5. The new parties who had not been given Essentiality Certificate during the last three periods were allotted imported stainless steel sheets equal to the entitlement as worked out by the field officers for issue of Essentiality Certificates for stainless steel sheets for the period 1965-66.
- In case where the entitlement of the party for issue of Essentiality Certificate for stainless steel for the year 1965-66 was more than this share on the basis of Essentiality Certificates for the last three periods, the party was given material equal to the entitlement as worked out for the period 1964-65.
- ..
6. The Department is considering to encourage the parties and made allotment of stainless steel sheets for export purposes and also for production of defence articles.

---

**Statement showing the names and addresses of the parties allocated stainless steel sheets for Non-Utensil purposes, 1965**

---

Serial No.	Name of the party	M.T.
1	M/s Bali Singh-Bhagwan Singh, Out side Ghee Mandi Gate, Amritsar	4
2	M/s Indian Weighing Machine, Hide Market, Amritsar	.. 2
3	M/s Kartar Industries, Out side Ram Bagh Gate, Amritsar	.. 0.50
4	M/s Akali Kirpan Factory Malvai Bunga Amritsar	.. 3
5	M/s Rumpas Industries, Industrial Estate, Ludhiana	.. 1
6	M/s Speedway Surgical Co., 583 Pindi Street, Ludhiana	.. 2.50
7	M/s Sigma Steel Industries, A-2, Industrial Estate, Ludhiana	.. 1.50
8	M/s Sat Kartar Cycle Industries, Industrial Estate, Ludhiana	.. 1
9	M/s T. F. Industrial Corporation. Industrial Estate, Ludhiana	.. 3

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the party	M.T.
10	M/s Sant Singh Mehta & Co. 17-B, Industrial Estate, Ludhiana	.. 0.50
11	M/s Dua Brothers, Industrial Estate, Ludhiana	.. 4
12	M/s B. S. Engineering Works, Gil' Road, Miller Ganj, Ludhiana	.. 1
13	M/s Aero Engineering Works, 489, Karim Pura Road, Ludhiana	.. 6
14	M/s Jiwan Engg. Works, Industrial Estate, Ludhiana	.. 6
15	M/s Rama Fancy Works, Ganji Chapari, Ludhiana	.. 1
16	M/s Silara Industries, 455, Emerson Road, Ludhiana	.. 3.50
17	M/s New India Engineering Industries, Industrial Estate, Ludhiana	2.50
18	M/s Gupta Loom Industry, Industrial Estate, Ludhiana	.. 0.50
19	M/s New Shangar electroplating Works, Industrial Area, Ludhiana	1
20	M/s Ravi Industries 8-R, Industrial Area, 'B' Ludhiana	.. 1.50
21	M/s Mahabir Metal Works Kapurthala	0.50
22	M/s Surjit Industries, Industrial Estate, Malerkotla	.. 2.50
23	M/s Narendra Stainless Steel Industries, Industrial Estate, Malerkotla	2.50
24	M/s Sukhri Brothers, 12-A, Industrial Estate, Batala	.. 1.50
25	M/s Kuldeep Industries, Village Mamoon Tehsil, Pathankot District Gurdaspur	.. 6
26	M/s United Iron Industries, Serai Chopta, Bhiwani	.. 3
27	M/s Punjab Wire Netting Industries, Railway Road, Narnaul	.. 6
28	M/s Adarsh Metal Industries, Jagadhri	.. 6
29	M/s Amrit Metal Industries, Jagadhri	.. 1.50
30	M/s Associated Industries, Jagadhri	.. 6
31	M/s Jainko Industries, Spatu Road, Ambala City	.. 1
32	M/s Kuldeep Industrial Corporation, Industrial Area, Chandigarh	.. 1
33	M/s Kiran Industries, Industrial Area, Chandigarh	.. 4.50
34	M/s Raj & Co. Railway Road, Bhatinda	.. 1 50
35	M/s J. L. Sumar Chand Jain, Jhajjar Road, Rohtak	.. 3
36	M/s Punjab Iron & Steel Industries, Butana Road, Gohana	.. 4
37	M/s Pokhar Dass & Co., Delhi Road, Rohtak	.. 5
38	M/s National Metal Industries, Industrial Area, Bahadurgarh	.. 6
39	M/s Trade Industrial Corporation, Industrial Area, Bahadurgarh	1
40	M/s Hindustan Rolling & Wire Products, Sonapat	.. 3

Serial No.	Name of the party	M.T.
41	M/s Saraj Industries, Industrial Area, Bahadurgarh	.. 6
42	M/s National Manufacturers & Traders, Kaithal	.. 1
43	M/s India Auto Industries Kaithal	.. 1
44	M/s Datta Ram-Ashok Kumar, Kaithal	.. 4
45	M/s Seema Industries' Corporation, Kaithal	.. 1
46	M/s Relan General Mills Kaithal	.. 2
47	M/s New India Tin Bucket & General Manufacturers, Kaithal	.. 3
48	M/s Puran Chand-Sharwan Kumar, Kaithal	.. 3
49	M/s Setia Iron & Steel Industries Factory, village Pasina Kalan, 320-L, Model Town, Panipat	.. 1
50	M/s Bharat General Mills, Kaithal	.. 3
51	M/s Punjab General Manufacturers, Kaithal	.. 1
52	M/s Chandera Industries, Nakodar Road, Jullundur	.. 3
53	M/s Free India Surgical Works, Industrial Area, Jullundur	.. 4
54	M/s Standard Mechanical Works, Mandi Road, Jullundur	.. 2
55	M/s Kwaliti Industrial Works, 17-G, Industrial Area, Faridabad	.. 2.50
56	M/s Shamrock Industries, Mathura Road Far idabad	.. 4
57	M/s P & S (India) Corporation, Gurgaon	.. 6
58	M/s T. R. Metal Engineering Works, Rewari	.. 0.50
59	M/s Bushhing Schmitz Private Ltd., 18/6, Mathura Road, Faridabad	4

**Supply of Eye Glasses to a Legislator detenu in District Jail, Nabha 3124. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the names of the communist detenus who were supplied eye-glasses and dentures at Government expense on the recommendation of the Jail Medical Officers in the State ;

(b) whether it is a fact that a legislator detenu lodged in district Jail Nabha in 1965, was recommended change of eye glasses by the Eye Specialist and the Jail Medical Officer but he was not supplied with the glasses ; if so, the reasons for the same ?

**Shri Chand Ram :** (a) Name of the detenus who have been supplied with Eye glasses—

1. Shri Harkishan Singh Surjeet.
2. Shri Ram Kishan Bharolian.
3. Shri Ghuman Singh.

## [Welfare and Justice Minister]

4. Shri Balbir Singh.
5. Shri Hazara Singh Jassar
6. Shri Udhe Singh Keshav.
7. Shri Gandharv Sen.
8. Dr. Bhag Singh.
9. Pt. Vidya Dev Longowal.
10. Shri Partap Singh Dhanaula.
11. Shri Ganda Singh
12. Shri Gurnam Singh.
13. Shri Gurbax Singh Dakota.
14. Shri Bhajan Singh.
15. Shri Prem Chand Bhardwaj.

Names of the detenus who are being provided with Eye glasses.

1. Shri Hazura Singh.
2. Ishar Singh Sodhi.
3. Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A.

*Denture—*

1. Shri Ram Kishan Bharolian.
2. Shri Bhag Singh Sajjon.

(Repairing of denture done at Government expense).

(b) Shri Makhan Singh Tarsikka, M.L.A. was recommended by the Medical Officer, District Jail Nabha, for examination by the Eye Specialist of the Rajindra Hospital, Patiala. Shri Tarsikka was examined by the Eye Specialist as an Out-door patient. However, no final report was received by the Superintendent District Jail, Nabha about this examination. Shri Tarsikka was not therefore supplied with eye glasses.

**Villages electrified in 1965-66 in the State**

**3125. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the total number of villages electrified in the State, district-wise and the expenditure incurred thereon during the year 1965-66.

**Sardar Gurdial Singh Dhillon (i) 60.** (up to 31st December, 1965) Statement.

(ii) Rs 223,48, 014.

**Lists of Towns/Villages electrified during 1st April, 1965 to 31st December, in the State district-wise.**

1. Mohindergarh	...	..
2. Simla	...	7
3. Jullundur	...	1
4. Ambala	...	9
5. Ludhiana	..	2
6. Bhatinda	...	1
7. Karnal	...	10
8. Amritsar	...	5
9. Kangra	...	1
10. Hissar	...	4
11. Rohtak	..	3

12.	Hoshiarpur	...	11
13.	Gurdaspur	...	3
14.	Lahaul and Spiti	...	3
Total			60

### QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : There is a privilege motion by Shri Om Parkash Agnihotri. He may please read it out.

Shri Om Parkash Agnihotri : I have not got a copy of it.

Mr. Speaker : Then it reads—

“According to the standing order of the Government, officers of certain categories i. e. upto Deputy Secretary are entitled to stay at the Circuit House at Simla. But when the Members of the Assembly are on duty i. e. when they go there to attend a meeting, they are not permitted to stay there. This action of the Government by not permitting the members of the Assembly to stay in the Circuit House has adversely affected the superior position and prestige of the legislators. With a view to restore the Privilege of the Members, I move this motion”.

This motion is kept pending. I would like the Minister for Parliamentary Affairs to discuss the matter with me. After that I will give my ruling.

### ADJOURNMENT MOTIONS/CALL ATTENTION NOTICES

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कुछ एडजर्नमेंट मोशनज और काल एटेंशन मोशनज आई हैं। आप सब जानते हैं कि आज गवर्नर के अड्रेस पर बहस शुरू होगी और इस पर बहस 4 दिन चलेगी। इसके बाद बजट पर डिस्कशन 5, 6 दिन चलेगी। इसके बाद डिमांडज पर डिस्कशन होगी। इस तरह से तीन स्टेजिज पर डिस्कशन होगी। माननीय सदस्यों को अपने प्वायंट्स रेज करने के लिये 13, 15 दिन मिलेंगे और उस वक्त यह सब चीजें अपनी स्पीच में रैफर कर सकते हैं। इस लिये इस बिना पर एडजर्नमेंट मोशनज और काल एटेंशन मोशनज इस स्टेज पर डिस्अलाओ की हैं। लेकिन एक चीज और वाजह कर देना चाहता हूं कि अगर डिस्कशन के दौरान माननीय सदस्यो ने जो प्वायंट्स रेज किये और उन का जवाब गवर्नमेंट न दिया तो इन हालात में अगर माननीय सदस्य उस चीज के बारे में कोई मोशन चाहे, काल एटेंशन मोशन हो, या दूसरी कोई मोशन हो, देगा तो उस की इजाजत दे दूंगा।

(I have received a number of notices of Call Attention and adjournment motions. As the hon. Members are aware today, the discussion on Governor's Address will commence and will continue for four days. After that the Budget Estimates for 1966-67 will remain under discussion for five or six days. This will be followed by discussion on Demands for Grants. The hon. Members would, therefore, get 13 to 15 days for raising these points. They can refer these matters during the course of their speeches,

[Mr. Speaker]

So on this ground these adjournment and Call attention motions are disallowed at this stage. But I would like to make one thing clear and that is that if such matters even when brought to the notice of the Government during the discussions, were not adequately answered then in that case, if an hon. Member would give a notice of an adjournment or a call attention motion on that subject, I would duly consider it and allow it.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੇ ਅਜ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਫੂਡ ਕਰਾਇਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉਤੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Mr. Speaker : Do not compare the situation here with that of Kerala.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4, 5 ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਹੂਮ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ appoint ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)।

ਡਾ॰ ਕਲਵੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਨੇ ਹਾਊਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਯਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਕਰਤ ਅਹਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਪਰ ਹੁਮਾਰੇ ਕਹਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਏਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਆ ਥਾ। ਉਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਯਾ। ਉਸੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਆ। ਕਹ ਕੁਰਫਤ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁਆ। ਏਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਂ ਅਗਰ ਉਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰਿਅਲ ਬਨਾਯਾ ਗਯਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕੋ ਹੀ ਬਢਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਐਰ ਅਨਯ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਓਤਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਧਨ ਅਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪਹਲੇ ਹੀ ਉਸ ਕੋ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਖੋਂ ਰੁਪਯੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਕੇ ਫਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਦਿਯੇ, ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਯੇ ਐਰ ਜਾਯਾ ਕੀਯੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਕੁਝ

हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स ने अपने डिस्क्रिशनरी फंडज में से 50 हजार रुपये जो कि गरीब जनता की कमाई से टैक्स के द्वारा वसूल किए हैं, वह रुपये सरदार प्रताप सिंह कैरों के मैमोरियल पर खर्च किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार यह कोई अच्छी कंवेंशन लागू नहीं कर रही है। इस लिये यह मामला बहुत ही अहम है। और इस पर हाउस में डिस्कशन करने की इजाजत जरूर होनी चाहिए।

**Mr. Speaker :** please take your seat.

**चौधरी देवी लाल :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। आप ने जनरल प्रोसीजर के बारे में बताया और कहा कि यह मामला गवर्नर के एड्रेस में और बजट की डिस्कशन करते समय उठाया जा सकता है। स्पीकर साहिब, यह बहुत ही अहम सवाल है। इस सवाल का पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा सम्बन्ध है। स्पीकर साहिब, जैसा कि डाक्टर बलदेव प्रकाश ने फरमाया कि स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरों दास कमीशन के द्वारा कुरप्ट चीफ मिनिस्टर साबित हुए और उसे इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया। इस के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब, उस दास कमीशन की रिपोर्ट को गीता के बराबर का दर्जा देते रहे हो और उसे आज पंजाब का हीरो तसब्बर किया जा रहा हो तो वह चीज आपस में कैसे मेल खाती है। कुछ मंत्रियों ने अपने डिस्क्रिशनरी अमाउंटस में सरदार प्रताप सिंह कैरों के मैमोरियल के लिये रुपए दिए हैं। यह निहायत ही नावाजिब चीज है। इस तरह हर एम. एल. ए. मिनिस्टर बनने की कोशिश करेगा और कुरप्शन करने की कोशिश करेगा क्योंकि उस को पता है कि बाद में उस का भी मैमोरियल इसी ढंग से बन सकेगा। इस लिये ऐसी बात हरगज नहीं होनी चाहिए। यह बहुत-ही अहम मामला है और इस पर डिस्कशन करने की इजाजत हाउस में देनी चाहिए ताकि इस पर डिटेल्ज में डिस्कशन कर सके और सरकार को जनता के खून और पसीने से कमाए हुए पैसे नाजायज तौर पर खर्च करने से रोक सके।

**कामरेड राम प्यारा :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, कामरेड शमशेर सिंह जोश ने फरमाया है कि लोक सभा में श्री अध्यक्ष ने फूड सिच्युएशन पर एडजर्नमेंट मोशन पर डिस्कशन करने की इजाजत दी है जबकि वहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, बजट पर डिस्कशन, और डिमांडज पर भी डिस्कशन होगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे कहने पर और कोशिशों के बावजूद राष्ट्रपति ने सरदार प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध दास कमीशन नियुक्त किया और उस के द्वारा वह दोषी ठहराए गए। ऐसा कमीशन 18 साल की पिछली हिस्टरी में पहला है। हम ने कुरप्शन के चार्जज लगाए और वह साबित हुए। स्पीकर साहिब, इस सूबे में पहले ही सरदार प्रताप सिंह कैरों को डिफैंड करने के लिये काफी रुपया जाया किया गया और अब उसकी यादगार में एक मैमोरियल बनाया जा रहा है और वहां पर हमारी सरकार लोगों के पैसे को नाजायज तौर पर खर्च कर रही है। इस लिये यह मामला बहुत ही संगीन है। इस पर हाउस में डिस्कशन करने की इजाजत होनी चाहिए ताकि हम सरकार को इस बारे में खर्च करने के लिये मजबूर कर सकें।

**Mr. Speaker :** Please take your seat.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ—ਮਰਹੂਮ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਐਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਰਹੂਮ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਵਾਜ਼ਿਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਥੋਂ ਦੀ ਫੂਡ ਪਰਾਬਲਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਉਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਏਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 5, 6 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਕ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਐਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਇਡ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਿਜ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। (At this stage there were voices of Points of order and the Hon. Speaker called upon the Minister for Public Works to speak.)

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਇਤਨੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਬੜੀ ਇਨ ਐਫੀਸੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਰੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਫੜਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਂਕਰ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਆਸਾਸਾ ਦੇ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਂਕਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (Interruptions)

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਸਬ-ਜੂਡਿਸ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

(Interruptions and noise)

**Mr. Speaker :** Order please.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। (Interruptions, noise)

**Mr. Speaker :** Shri Tandon, Order please,

ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ

[ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ]

ਮਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਪਸਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼।

(I would expect from the hon. Members that whenever an hon. Member or a Minister is in possession of the House, they would refrain from making any attempt to interrupt him. The manner in which Shri Tandon and Sardar Lachhman Singh indulged in interruptions, was not proper. Every body gets an opportunity to have his say at the proper time. As to the Ministers, they are fully aware of what to say or what not to say and at what time. Now, therefore, it may be borne in mind that if one is interrupted, the others can retaliate. But by doing so, the order in the House can not be maintained nor can the proceedings be carried on smoothly. If the hon. Members are not interested in the smooth working of the House, it can be adjourned. (Interruption by Sardar Lachhman Singh Gill) Order please.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਵਾਉਣ ਲਗਾ ਸਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੁਹ ਹੈ। (I am already attentive.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਪਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਲ ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਸੀ.....

Mr. Speaker: You are making a lengthy speech.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੁਡੀਸਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੋਸ਼ੀ ਪਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆ ਹੈ **Kairon memorial plan announced . . .**

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ ਐਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੰਡਾ ਡਾਕੂ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿਤਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਉਸ ਨੇ ਲੁਟ ਲਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਡਾਕੂ ਵਾਂਗ ਸਲਾਘਾ ਹੈ। (**Voices of Shame, Shame from the Opposition. There was noise in the House and the hon. Speaker called upon the Minister for Public Works, Chaudhri Ranbir Singh to speak.**)

**Comrade Ram Piara :** I rise on a Point of Order, Sir.

**Public Works Minister :** I am not on a Point of Order, Sir. But I have a right to speak on any issue.

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਰਿਕਟਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਉ, ਸਪੀਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (**Addressing Com. Ram Piara**) (If the hon. Member insists on raising his point of order, I would allow him on the condition to strictly confine himself to the point of order and not make a speech. If he starts making a speech under the pretext of a point of order, he will have to stop, when I ask him to do so. I would permit him to raise only the relevant point of order, If any procedural matter is involved, then he is at liberty to raise a point of order but he will not be permitted to make a speech.)

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ :** ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੈਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ? (*Interruptions*)

**Mr. Speaker :** Chaudhri Ranbir Singh.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਬੱਸ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿਟੀ ਚਲੋ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? (*Cannot Sardar Lachhman Singh control himself ?*)

**ਲੋਕ ਕਰਮ ਮੰਤਰੀ (ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ) :** ਅਧ്യਕਸ਼ ਮਹੋਦਯ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤ੍ਰ ਮੇਂ ਵਿਚਾਰੀਂ ਕਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹ ਸਕਤਾ ਹੈ ਐਰ ਰਹਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਕੌੜੇ ਦੌਸਤ ਹੈਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਭੀ ਅਭੀ ਆਪ ਨੇ ਸੁਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਂ ਕੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਅਚੱਛੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤੋਂ ਕਹੀਂ।

**ਡਾ॰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਵਿਚਾਰੀਂ ਕੀ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ :** ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਆਪ ਸੇ ਉਮਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਹ ਸੇ ਇੰਟਰਪੁਟ ਕਰੋਂ। (*It was not expected of the hon. Dr. Baldev Parkash that he would interrupt like this.*)

**ਡਾ॰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਵਿਚਾਰੀਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੌੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੋ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਾ ਹੈ (ਵਿਧਨ)

**ਲੋਕ ਕਰਮ ਮੰਤਰੀ :** ਸਬ ਬਾਤੀਂ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ, ਆਪ ਸੁਨਨੇ ਕਾ ਹੌਸਲਾ ਰਖੋਂ। ਤੋ, ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਮਹੋਦਯ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਏਕ ਦਯਾਨਤਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਥਾ (ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸ਼ੇਮਸ਼ੇਮਕੀ ਆਵਾਜ਼ੋਂ) ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਮਹੋਦਯ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੇਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਯੋਂ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਤੋ ਅਪਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਰਖਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤ੍ਰ ਮੇਂ ਉਨ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਂ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਮੁਝੇ ਭੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਐਰ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਿਯੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਹ ਸਾਥੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਅਪਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈਂ।

**ਡਾ॰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ।

**ਲੋਕ ਕਰਮ ਮੰਤਰੀ :** ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਮਹੋਦਯ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਪਹਲੇ ਕਹਾ, ਜਹਾਂ ਤਕ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੁਝ ਭਾਈਯੋਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਝ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਥੇ। ਏਕ ਏਕ ਅਲਜ਼ਾਮ ਕੇ ਊਪਰ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਏ ਐਰ ਸਿਫੰ ਏਕ ਬਾਤ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੀਧੇਤੌਰ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਯਾ...

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧ੍ਯਕਸ਼ :** ਆਪ ਲੰਬੀ ਬਾਤੀਂ ਮੇਂ ਨ ਜਾਓਂ। ਬ੍ਰੀਫ ਸੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਐਰ ਸਪੀਚ ਨ ਕਰੋਂ।

(*He need not go into the details. He should state things briefly and not make a speech.*) (ਵਿਧਨ)

**ਲੋਕ ਕਰਮ ਮੰਤਰੀ :** ਅਧ੍ਯਕਸ਼ ਮਹੋਦਯ, ਯਦਿ ਆਪ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਬਾਤ ਕਹੂੰਗਾ। (ਵਿਧਨ)

**श्री अध्यक्ष :** ब्रीफली कहिये। (Please be brief.)

**मंत्री :** आप की आज्ञा से मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात सदन के सामने रखूंगा। दास कमिशन की रिपोर्ट का जिक्र किया गया।

**श्री अध्यक्ष :** देखिये इस वक्त न तो दास कमिशन रिपोर्ट के मैरिट्स पर बहस हो रही है और न ही ऐडजर्नमेंट मोशन पर बहस हो रही है। एक ऐडजर्नमेंट मोशन पर प्वायंट्स आफ आर्डर को ऐक्स्टेंड करते करते इस बात पर जो इधर से आबज़रवेशन्ज़ हुई सरदार प्रताप सिंह या दास कमिशन रिपोर्ट के बारे में उन का आपने अपने तरीके से जवाब दे दिया है। इस वक्त दास कमिशन या उसकी रिपोर्ट के मैरिट्स में जाने का औकेयन नहीं है। जो बात कही गई है उस के बारे में आप चाहें तो एक दो मिनट में कुछ कह लें।

(Please listen. At present neither the Dass Commission report is under discussion, nor is any adjournment motion being discussed. The points of order raised in connection with an adjournment motion were stretched to making observations on Sardar Partap Singh and Dass Commission Report by this side of the House and the hon. Minister has given a reply in his own way. Now this is not the occasion to go into the merits of the Dass Commission or its report. He may have his say in a minute or two on whatever has been said on this matter.)

**लोक कर्म मंत्री :** मैं थोड़े ही शब्दों में आप की इजाज़त से यह कहूंगा कि मैं यह मानता हूँ कि दास कमिशन रिपोर्ट सरदार प्रताप सिंह की इमानदारी का सबूत है। (विघ्न) (शोर)

स्पीकर साहिब, जहां तक डिस्क्रिशनरी फंड का ताल्लुक है मैं निवेदन करूंगा कि कैरों गांव में 8/2 को पंजाब के लाखों भाई इकट्ठे थे जिन्होंने यह खाहिश जाहिर की कि सरदार प्रताप सिंह की याद में कैरों के हायर सैकण्डरी स्कूल को कालिज बना दिया जाए। इस काम के लिये लोगों की तरफ से एक लाख रुपया देने का ऐलान भी दिया गया। (तालियां) उस समय मैंने भी इस स्कूल को सरदार प्रताप सिंह की याद में कालिज बनाने के लिये अपने डिस्क्रिशनरी फंड में से दस हजार रुपया देने का ऐलान किया था। (आपोजीशन की तरफ से आवाजें) शेम शेम। इस के अलावा अपनी जेब से भी मैंने 1100 रुपया देने का ऐलान किया था। (तालियां) और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जो कार्यवाही मैंने की वह सही है। (आपोजीशन की तरफ से आवाजें) गलत है।)

**श्री बलरामजी दास टंडन :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, प्वायंट आफ आर्डर यह है और यह वह बात है कि जिस पर सारी आपोजीशन ने स्ट्रैस अपौन किया है कि जो लोग इस काम में श्रद्धा रखते हों वह बेशक इस के लिये लाखों रुपया इकट्ठा करें, अपनी जेब से भी जो चाहें दें लेकिन सवाल यह है कि जिस पब्लिक फंड का कस्टोडियन मिनिस्टर साहिब को बनाया गया है (विघ्न) उस में से, कुरप्शन के मैमो-

[श्री बलराम जी दास टंडन]

रियल बनाने के लिये इजाजत नहीं दी जा सकती। यह हाउस इस काम के लिये रुपया नहीं दे सकता। यह अपनी जेब में से दे। (विघ्न)

**लोक कर्म मंत्री :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो माननीय सदस्य ने उस मैमोरियल को कुरप्शन की यादगार कहा है, मेरी प्रार्थना है कि वह शब्द इस कार्यवाही में से हटा दिये जाएं। (आपोजीशन की तरफ से शोर)।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। देखिए काल अटैनशन मोशन और ऐडजर्नमेंट मोशन के ऐडमिट होने या न होने के बारे में काफी बात चीत हुई है और सिवाए सरदार, गुरनाम सिंह के सभी ग्रुप लीडर्स ने अपनी बात कही। अब सरदार गुरनाम सिंह के बाद इस पर बहस नहीं होगी। ऐडमिट होने या न होने के बारे में जो आखिरी फैसला होगा वह मैं आप को बता दूंगा। (Order please. Quite a lot has been said about the admissibility or otherwise of the Call Attention Notice and the Adjournment Motion and excepting Sardar Gurnam Singh, all the group leaders have expressed their views on the subject. Now after Sardar Gurnam Singh has stated his view point, no further discussion on it will be allowed. As regards the final decision about its admissibility or otherwise, that I will convey to you.)

**चौधरी देवी लाल :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जो ऐडजर्नमेंट मोशन का सवाल है वह और भी जरूरी हो गया है। मैं आप की रूलिंग चाहता हूं। वजीर साहिब ने कहा कि उन्होंने दस हजार रुपया दिया और .....

**श्री अध्यक्ष :** रिपीट न करें। (Please avoid repetition.)

**चौधरी देवी लाल :** मैं आप की रूलिंग चाहता हूं। जहां तक 1100 रुपये का ताल्लुक है यह दें। प्रदेश कुरप्शन कमेटी चाहे जितना रुपया दे। मगर जहां तक सरकार के खजाने का ताल्लुक है उस में से नहीं दिया जाना चाहिए (विघ्न) इस बात पर ऐडजर्नमेंट मोशन ऐडमिट की जाए ताकि हम यह साबित कर सकें कि यह मिसयूज आफ पावर है या नहीं। (विघ्न)

**चौधरी नेत राम :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं इस मामले में आप की राय जानना चाहता हूं। पंजाब की जनता ने महसूस किया कि यहां पर सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है (विघ्न) पंजाब की जनता ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि यहां की कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है, केन्द्र सरकार ने दास कमिशन बैठाया। नतीजा यह हुआ कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार साबित हुई और तब यह नई सरकार बनी और यह सरकार आज उसी भ्रष्टाचार की यादगार बनाने के लिये सरकार का 50 हजार रुपया लगा रही है (आपोजीशन की तरफ से आवाजें : शेम, शेम) अब आप यह राय दें कि यह कांग्रेसी सरकार भ्रष्ट है या नहीं। (आपोजीशन की तरफ से तालियां)।

**मुख्य संसद सचिव :** ग्रान ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर मैं आप की रूलिंग इस बात पर चाहता हूं कि जो हाऊस का आध घंटा वक्त इस तरह जाया हुआ है (विधन) (शोर) लैट मी हैव माई से ।

**श्री अध्यक्ष :** आप कह रहे हैं कि आध घंटा हाऊस का वक्त जाया हुआ है तो इस में मिनिस्टर साहिब भी बोले हैं तो आप सोच लीजिए कि किस ने हाऊस का वक्त जाया किया है । (The hon. Chief Parliamentary Secretary has stated that half an hour of the House has been wasted. During this period some Ministers have also spoken. So he should think over as to who is responsible for this.)

**मुख्य संसद सचिव :** मैं तो, स्पीकर साहिब, आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या आप ने एडजरनमेंट मोशन को एडमिट कर लिया है जिस पर हाऊस का आध घंटा वक्त जाया हुआ है और दूसरा यह कि जिन मैम्बर साहिबान ने प्वाइन्ट आफ आर्डर किए हैं और इस प्रिविलिज को मिसयूज किया है क्योंकि आप के हुक्म के मुताबिक वह प्वाइन्ट आफ आर्डर न थे क्या ऐसे प्वायंट आफ आर्डर को एक्सपेंज कर दिया जाएगा ?

**श्री अध्यक्ष :** प्लीज टेक योअर सीट । यह मुनासिब नहीं कि आप हाऊस की जो प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं उन पर किसी तरह का रिफ्लेक्शन करें और कहें कि हाऊस का वक्त जाया हुआ है (The hon. Chief Parliamentary Secretary may please take his seat. It is not proper that he should cast reflection of any kind on the proceedings of the House which have already taken place and say that the time of the House has been wasted. (विरोधी दल की ओर से : शेम शेम) He may please withdraw these words.

**मुख्य संसद सचिव :** जनाब मेरी अर्ज यह है (विधन) (आवाजें-विदडरा फस्ट) ।

**Mr. Speaker:** Please withdraw those words first.

**मुख्य संसद सचिव :** आप मेरी अर्ज तो पहले सुन लीजिए । आप पहले रूलिंग दें कि क्या हाऊस का वक्त जाया हुआ है या नहीं और फिर मैं विदडरा करूंगा । और क्या मोशन आप ने एडमिट किया है या नहीं और अगर मोशन एडमिट नहीं किया तो हाऊस का वक्त जरूर जाया हुआ है मैं इस बात को पूरे जोर से कह सकता हूं । (विधन) (शोर)

**Shri Balramji Dass Tandon :** He is challenging your authority, Sir.

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज ।

श्री मंगल सैन, आप भी चेयर को चैलेंज करते हैं तो इन्होंने भी करना शुरू कर दिया है । लेकिन मैं गरग साहिब को बताना चाहता हूं कि जो प्रोसीडिंग्स हाऊस में हो जाएं

[श्री अध्यक्ष]

और जिन की स्पीकर इजाजत दे दे उस के बारे में यह कहना कि हाऊस का टाइम जाया हो गया है मुनासिब नहीं आप ने 'जो टाइम वेस्ट हुआ है' के लफ्ज [इस्तेमाल किये हैं उन्हें आप वापिस ले लें और हाऊस की किसी प्रोसीडिंग पर इस तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए।] ( Order please. Since Shri Mangal Sein challenges the Chair at times, he (the Chief Parliamentary Secretary) too has started doing so. But I would like to tell Shri Garg that it is not proper to say that the time of the House has been wasted on proceedings which have already taken place and which were permitted by the Speaker. He should withdraw the words used by him that the time of the House has been wasted. Any comments on the proceedings of the House should be avoided.)

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** जनाब, मैं ने जो हाऊस का टाइम जाया होने के लफ्ज कहे हैं उन्हें वापिस लेता हूं।

मेरी विनती यह है कि जहां तक प्वाइंट आफ आर्डर का ताल्लुक है इस को मिसयूज किया जाता है और इस तरह हाऊस का टाइम जाया होता है और हाऊस की कोई कारवाई नहीं चल सकती इस लिये जो प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं थे उन्हें डिसअलौ करना चाहिए, (विघ्न) (शोर)।

**डा० बलदेव प्रकाश :** आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी ने दो दफा इस हाऊस की इन्सलट की है पहली दफा यह कह कर कि हाऊस का टाइम जाया हुआ है हालांकि आप की इजाजत से हाऊस की प्रोसीडिंग चली थी और इस आगस्ट हाऊस में पब्लिक के नुमाइन्दों को अपनी फीलिंगज को हाऊस में रखने का हक होता है। इस तरह कह कर यह गुस्ताखी कर रहे हैं और दूसरा यह कह कर कि प्वाइन्ट आफ आर्डर में टाइम वेस्ट किया गया है और इस को मिसयूज किया गया है यह कह कर इन्होंने दूसरी बार फिर गुस्ताखी की है। प्वाइन्ट आफ आर्डर रोज़ करना तो मैम्बर साहिबान का एक प्रिविलिज है और कोई भी मैम्बर जब चाहे विवस्था प्रश्न पूछ सकता है यह एक ब्रेसिक और एलीमेंटरी नालेज है अगर चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब को इन बातों का भी पता नहीं तो इन्हें किस मैरिट की बिना पर पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी बनाया गया है? (विघ्न) तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रोसीडिंग आप की इजाजत से चली और जिस को आप ने रैलेवेंट करार दिया है उस के बारे में इन्होंने कहा है कि हाऊस का टाइम जाया हुआ है यह इन्होंने दूसरी गुस्ताखी की है। अगर इस तरह का एलीमेंट हाऊस में हो जिन्हें ऐसी बातों का भी ज्ञान न हो तो हाऊस का डीकोरम कैसे रह सकता है।

**Transport and Elections Minister :** Mr. Speaker, I am very sorry that there has been so much unnecessary debate over it and a lot of heat generated. I would request you to kindly see that the matter is dropped now. It may, however, be discussed on some other occasion. The Das Commission has

been referred to from the other side. So my colleague also spoke on that, otherwise we have no right to comment on it. Secondly, a point has also been raised about the schools. I may state that there are no Rules prohibiting the giving of discretionary grant to schools, no matter whether they are situated in village Kairon or somewhere else. Thirdly, I do admit that I was a great opponent of Sardar Partap Singh Kairon. But, now when he is no more, all controversies should end, and we should not bring in any politics. There is no doubt that he was murdered in broad day light. That act of violence must be condemned by one and all be they his friends or enemies. To say that a memorial for him should not be raised, is not proper.

**श्री जगन्नाथ :** आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। . . .

**श्री अध्यक्ष :** आप को अच्छी कनवेंशनज़ कायम करनी चाहिए। अगर कोई ग्रुप लीडर खड़ा हो तो उस को इन्ट्रूप्ट किया जाए तो इस तरह हाऊस का डेकोरम नहीं रहता।  
(The hon. Member should set up good conventions. If a group leader, who is in possession of the House, is interrupted, this detracts the dignity of the House.)

**श्री जगन्नाथ :** मुझे सब पता है जी मैं तो प्वायंट आफ आर्डर करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** आप को तो लैफ्ट और राइट हिट करने की और लूजली बातें करने की आदत है आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। (It has become a habit with the hon. Member to hit right and left and talk loosely. He should avoid this.)

**श्री जगन्नाथ :** आप भी कैरों के चमचे रहे हैं इसलिये आप ऐसा कहते हैं। (शोर)  
(विघ्न)।

**Mr. Speaker :** I do not recognise this.

**Chief Parliamentary Secretary :** These words may be expunged, Sir.

**Mr. Speaker :** No, let them remain. Will Shri Jagan Nath please withdraw these words ?

**श्री जगन्नाथ :** मैं यह लफ्ज़ वापिस लेता हूं। लेकिन मैंने टाइम जरूर लेना है।

**श्री अध्यक्ष :** टाइम किस को देना है और कब देना है यह मेरा राइट है।  
(It is my right to determine when and to whom time is to be given.)

**श्री जगन्नाथ :** मगर यह भी तो मेरा राइट है कि मुझे टाइम मिले।

**Mr Speaker :** All right. The hon. Member should speak strictly on a point of order. I will not allow him to go beyond that.

**श्री जगन्नाथ :** मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है, स्पीकर साहिब, कि आज यह कैरों साहिब का मैमोरियल बनाने लग पड़े हैं मगर कैरों साहिब की आखरी इच्छा की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 13 अप्रैल, 1964 की आप मेरी स्पीच देखें जिस में मैंने कहा था कि कैरों साहिब आपका मैमोरियल बनाऊंगा। इस के जवाब में उन्होंने कहा था कि पहले मैं तेरा मैमोरियल बनाऊंगा फिर देखा जायेगा। इसलिये मेरा कहना तो यही है कि जब तक उन की आखरी इच्छा पूरी ना हो यह मैमोरियल बनाया ही न जाये।

**लोक कर्म मंत्री :** स्पीकर साहिब, इनके मैमोरियल के लिये मैं अपनी जेब से 5/- रुपए देता हूँ। (हंसी)

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** The other Ministers should also follow suit.....

इन के साथ ही 5-5/- की कंट्रिब्यूशन को सारे मिनिस्टर्स को फालो करना चाहिये।

**परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री :** श्री जगन्नाथ मेरे तो पुराने दोस्त हैं। जितनी वह कंट्रिब्यूशन करेंगे उतनी मैं कर दूंगा।

**Sardar Gurnam Singh :** Mr. Speaker, Sir. I am a signatory ...

**चौधरी नेत राम :** मेरी प्रार्थना यह है कि सरदार गुरनाम सिंह जी की मांग तो पंजाबी सूबा की है। मगर वह भाषण अंग्रेजी में कर रहे हैं। इन्हें कहो कि वह पंजाबी में बोलें ताकि हमें भी कोई फायदा हो।

**Sardar Gurnam Singh :** Mr. Speaker, Sir, I am a signatory to this adjournment motion because it is based on a very fundamental principle. I need not go into the details of the things which are known to you, Sir, as also to the Hon. House that on a petition by the opposition Parties the President of India appointed a Commission to enquire into the corruption of the late Chief Minister. So far as his murder is concerned, we condemned it at the appropriate occasion and we condemn it again and we say that it is the duty of this Government to prosecute his murderers and take them to a successful prosecution. We are one with them. But as for his memorial to be raised out of the public fund tax payers' fund we strongly oppose it. The reasons are these. Sir, I am very sorry the Minister for Parliamentary Affairs made an effort to give a twist to mix it up with a school at Kairon. You, Sir, yourself were present in the meeting, as reported by the Press. I leave it to you to judge whether what he has stated here on the floor of the House are the correct things or wrong. But I give credit to Mr. Ranbir Singh who did admit that the money given out of his discretionary fund was for the raising of memorial to the late Mr. Partap Singh Kairon. I give him credit. But I am sorry for his presumptuousness where he tried to give his judgement over Mr. Das's Report. We are not concerned with this. We are concerned with two or three points. A commission of enquiry was appointed at the instance of Opposition Parties to go into the complaints. The Commission was no less a person than the retired Chief Justice of India, Mr. Justice Das. He gave certain findings and as a consequence of those findings the late Chief Minister was forced to resign by the Congress High Command and the Central Government. As a consequence of that he resigned. Well, the matter ended. As far as Mr. Kairon is concerned, we have forgotten these things and we wanted to forget them. But the internal politics of the Congress Party does not allow the matter to rest. There is a vocal section and names are given here which is being wooed by various groups of the Treasury Benches in order to please them and to win their votes. Here are the names of the Ministers who have announced the donation for the raising of the memorial.....

**Mr. Speaker :** Please be brief.

**Sardar Gurnam Singh :** I am coming to the vital question only. I have left it to the Hon. Speaker to see that because he was present there. The Chief Minister is reported to have said that Government have allocated Rs. 25,000 to the Agriculture University of Ludhiana for giving scholarships and stipends to research students to perpetuate Mr. Kairon's memory.

Similarly, Sardar Gurdial Singh Dhillon, Mr. Ranbir Singh, Mr. Kapur Singh, Mr. Ajmer Singh and Mr. Chand Ram, all Ministers of this Government, announced a donation of Rs. 50,000 out of their discretionary funds for raising a suitable memorial to the late Mr. Kairon.

(Voices from the Opposition : Shame).

It is not a question of Kairon school into the intricacies of which the Minister for Parliamentary Affairs wanted us to take. So, Sir, it is obvious that out of tax payers' money the Ministers of Punjab have announced to give Rs. 75,000 for raising memorial to Mr. Kairon. We feel that it is not raising of memorial. This Government is responsible for perpetuating corruption in this State. This is their responsibility. We wish, Sir, you had admitted the adjournment motion and I still request you to keep it pending and think over it and give us time to discuss this matter further. But we have no effective method at this time to dis-associate ourselves from this action of the Government except the one which we are going to follow without any disrespect to the Chair. We want to get away from the House for a little while to dis-associate ourselves from the Punjab Government's this questionable action in giving money for the memorial of Mr. Kairon. We therefore, Sir, without any disrespect to you, I again say 'without any disrespect to you', walk out of this House.

#### Walk-out

(At this stage all the Members of the opposition staged a walk-out).

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਬਦਕਸ਼ : ਮੇਰਾ ਐਡਜਨਸਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲ ਐਟਨਸ਼ਨਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਹੀ ਰੁਲਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪਹਲੇ ਥਾ। (My ruling regarding the Call Attention Notice and adjournment motions, which was given earlier, stands.)

#### GOVERNOR'S ADDRESS

(Copy laid on the Table of the House).

**Mr. Speaker :** In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I have to report that the Governor was pleased to address both the Houses of the State Legislature assembled together on the 14th February, 1966, under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

ਸਾਥੀਓ,

ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਜੋ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਹਰਦਿਲ-ਅਜੀਜ਼ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ-ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਸਨ। ਉੱਨੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਸਲੇ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੁਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਾਂਢੀ

ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤ੍ਰਾਣ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ-ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। (cheers)

2. ਸ੍ਰੀ ਨਰ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਡਗਿਲ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਕ ਨਿਧੜਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰੋਹੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ।

3. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਨਹਿਰੀ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਕ ਨੇ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੌਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛਾਤਾ-ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਰਖਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਲਗਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੁਰੱਅਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸਲਾਘਾ-ਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਲਗ ਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਣਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਖੀਵਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਤਿਲਫੁਲ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ।

4. ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤਸਵ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜਨਮਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

#### ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ

5. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੁਰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੌਢੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 66 ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 133 ਜ਼ਖਮੀ ; 17 ਆਦਮੀ ਲਾ-ਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ 14 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਛਾਤਾ-ਫੌਜੀ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰਨ ਲਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 172 ਛਾਤਾ-ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 136 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਵਲ-ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰਖਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਖਈ ਇਸ ਔਖੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਸ ਸਾਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ।

ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

**ਜਵਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ**

6. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਜਲ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮਾਣ-ਅਰਥੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ  $\frac{2}{3}$  ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 250 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤਕ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ-ਅਰਥੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਆਸੂਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਨਾਕਾਰਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਣ-ਅਰਥੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਲੜਕੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੇਵਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

**ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਭੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ**

7. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਲ ਵੀ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲਗ ਭਗ 50,000 ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਭਗ 5,000 ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਕਣਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 18 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਕਣਕ ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 45,000 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 26,000 ਤੋਂ ਵਧ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਲਗ ਭਗ 16,000 ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 8.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜੋੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ 'ਕੇਅਰ' (CARE) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰਮਨਕੂਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 195 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 201 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾਕਾਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਾਣ-ਅਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਘਟ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 1965 ਲਈ ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ, ਲਗ ਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਣ-ਅਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ ਦੇ ਭੇਂ-ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਉਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

8. ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਔੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔੜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਔੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਾਵੀ, ਰਿਆਇਤੀ ਨਿਰਖਾਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ, ਭੋਂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ-ਖੂਹਾਂ ਲਈ ਤਕਾਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਔੜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਿਸਾਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ-ਸ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1964-65 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਉਪਜ ਵਿਚ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਟਿਊਬਵੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ 11,000 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾ (N.E.S.) ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸ ਪਏ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਉਪਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਅਸਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1966-67 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦੇ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ। ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1965-66 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 4.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾ-ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 2.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਬੰਧੀ ਭਰਵੀਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ; ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਦਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 3,000 ਮਣ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ, 1965 ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਦੋਗਲਾ ਬਾਜ਼ਰਾ ਨੰ: 1 ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਟੇਲ-ਚੁੰਗ ਨੋਟਿਵ-1 ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਧਰੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਗਾਹੁਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

9. **ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ** ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗ ਭਗ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੁੱਧ-ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਲਗ ਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

10. **ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ** ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਪਜ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਸਤੇ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗ ਭਗ 3.40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ, 'ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਘਟੇ ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਪਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਾਂ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ, 35,000 ਟਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ 25,000 ਟਨ ਬਾਜਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 6,021 ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।

ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ-ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ-ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

11. **ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ** ਸਵੱਛ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਯੋਗ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ

ਸਬੰਧੀ ਰਪੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਕਫਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਯੋਗ ਰਾਜੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਪੋਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਪੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਪੋਟ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਪੋਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਲ (cell) ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਛ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ, ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਧੀਨ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ (Vigilance Cell) ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

12. **ਯੋਜਨਾ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਕਾਸ** ਤੀਜੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਕਾ ਲਾਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਕਾਰਣ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚ 231.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 245.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 110.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ

ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ-ਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਮਦਾਦ, ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, 1966-67 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1966-67 ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਰਕਮ ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ-ਬ-ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 1965-66 (64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 1966-67 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਮੁਨਾਸਬ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 'ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਭਰਵੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 100 ਟਨ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇਕ 'ਚਿਪਿੰਗ ਪਲਾਂਟ' (Chipping plant) ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਘਟਾਉਣ ਵਲ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ, 1965 ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਨਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰਪੋਟ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

13. **ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ** ਭੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀ-ਕਰਣ (Decentralisation) ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਲ 1964-65 ਵਿਚ 9 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ 13 ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲੂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਕਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਐਕਟ (Co-operative Act) ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਹਾੜੀ, ਰੇਤਲੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚਕਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ 10.26 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਚਕਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 1968 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

14. **ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ** ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔੜ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਲ ਗਿਣਤੀ 40,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12,000 ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਿਵਾਨੀ ਤਸੀਲ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿਰਕੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਰਵਾਣਾ-ਕਰਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬਰਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ-ਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਆਸ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਲਗਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਣ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ 3.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 1970-71 ਤਕ ਇਹ ਥੁੜ ਲਗ ਭਗ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, 1970 ਤਕ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

15. ਸਨਅਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਅਰਥਾਤ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਨਅਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 42.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ, 1965 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਾਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਜਿਸਤੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ (Excise) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟ/ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਡੈਮਰਿਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਣ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾ (Purchasing Organisation) ਨਾਲ ਵਧੇਰਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ, ਮੈਂ ਸਨਅਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:—

(1) ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਥਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਏਗੀ।

(2) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੂੰਜੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਡਲੀ ਲੋਹਾ (Pig Iron) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੀਓਰੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਇਰਨਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਸਤਰੋੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ 185 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋੜ-ਰਹਿਤ ਟੀਊਬਾਂ (Seamless Tubes) ਅਤੇ ਫੋਲਾਦੀ ਢਲਾਈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ, ਮਾਵਾ (Pulp) ਅਤੇ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੋਲਾਦੀ ਢਲਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਸੀਮਿੰਟ ਚਾਦਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਹੱਦ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਚਾਹ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ, ਅਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੇਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਸਿਲਕ ਧਾਗਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

16. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। 95 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 51 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1192 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,40,325 ਮੀਲ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਸਰਵਿਸਾਂ, ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਡੀਲਕਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਰਵਿਸ, ਲੰਮੇ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਅਬੋਹਰ ਸਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੀਕ

ਸਿੱਧੇ ਸਫਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ, 1965 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਵਿਉਂਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਸਕਲ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਪਰ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅੱਧ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਕ ਫਾਸਲਾ ਪੰਜ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਖੜੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 118 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ 98 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦਾ ਖਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਪਰ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਲੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

17. **ਸਹਿਕਾਰਤਾ** ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ (Co-operative movement) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ, 1965 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਅਧੀਨ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਅਬਾਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੱਜਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰਜ਼ਾ/ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਕਲਾਨਾ ਵਿਖੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲ, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

18. **ਸਿਖਿਆ** ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਫੰਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 6—11 ਸਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਗੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਪੋਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਪੋਟ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਗਜ਼ਟਿੱਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗ ਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

19. **ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ** ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 120 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਰੀਜਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 120 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਜਰਮਨ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਈ. ਐਮ.ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

20. **ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ** ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚੂਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 600 ਤੋਂ ਵਧ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ 1,200 ਬੋਤਲਾਂ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੈਨਾ ਲਈ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 10 ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 229 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 480 ਸਹਾਇਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸੀਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਵਧੀਆ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 26.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 45.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ (ੳ) ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਿਓਰੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, (ਅ) ਭਿਵਾਨੀ ਤਸੀਲ ਦੇ ਸੌਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ (ੲ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਭਿਵਾਨੀ ਤਸੀਲ ਦੀ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੱਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ (**Family Planning**) ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਕਮ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

21. **ਦਿਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ** ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 320 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 200 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੌਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਉਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ (**Village Roads Co-operative Development Scheme**) ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

22. **ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ** ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 150.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਖ ਰਖਦਿਆਂ ਘਟਾ ਕੇ 124.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 29 ਅਤੇ 30, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਸਟਲ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟਿਊਬ-ਵੈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਨਾ ਚੋ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਲ ਲਗਦੀ 400 ਏਕੜ ਭੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ 100 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, 17 ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡੀਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਟਰ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਥਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

23. **ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ** ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਮਕਰਨ ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਗਰਪਾਲਕਾਵਾਂ ਨੂੰ 4.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਗਰਪਾਲਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ-ਸੁਧਾਰ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (**Urban Local Bodies**) ਦਾ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ (**Urban Community Development Scheme**) ਅਧੀਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ (1) ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਾਇਆ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਇਆ ਪਾਬੰਦੀ ਐਕਟ, 1949 ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਯੁਕਤੀ ਪੂਰਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, (2) ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੁਝਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

24. **ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ** ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਣ-ਵਿਉਂਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗਾ

ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਵਿਉਂਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਐਕਟ, 1963' ਅਧੀਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਯਮਨਾ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁਲੂ, ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗਨੌਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਮਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਬਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਹਤਕ, ਜਗਾਧਰੀ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

25. **ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ** ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 113 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਆਵੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1962 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ 3.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਖਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਮਿਹਤਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੰਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਠਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਂਜ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਂ ਨਿਸਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜ ਤਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਅੰਕਣ (evaluation) ਲਈ ਇਕ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

26. ਸਾਬੀਓ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੌਂਪੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਉਪਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਔੜ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ—ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ, —ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰੇ ਸੰਕਟ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੁਰਮਗਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਉਦਮੀ, ਚੌਕਸ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਥਾਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ

ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਨਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਲ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦਰਾਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣ-ਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ, ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਗੇ।

ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ।

ਜੈ ਹਿੰਦ

#### Announcements by the Speaker

**Mr. Speaker :** (1) On the 4th November, 1965, Sarvshri Shamsheer Singh Josh, Gurcharan Singh, Gurbakhsh Singh and Babu Singh M.L.A.s., sought to raise a question of breach of Privilege regarding the publication of the "Expunged Proceedings of the meeting of the Punjab Vidhan Sabha held on the 2nd November, 1965", in the Daily 'Milap', the 'Partap' and the 'Pradeep', in their issues, dated the 3rd November, 1965. I referred this matter to the Press Gallery Committee for their views.

The Secretary, Press Gallery Committee, intimated that the correspondents of the Daily 'Milap' and the 'Pradeep' as also the Editor of the 'Partap', have expressed their regrets to me.

In view of the regrets expressed by the newspapers concerned, I have decided to drop the matter.

(2) On the 24th November, 1965, Comrade Ram Piara, M.L.A. sought to raise a question of privilege regarding the publication of the remarks made against him in the House by Sardar Jagjit Singh Gogoani, M.L.A. which were expunged from the proceedings of the meeting of the Punjab Vidhan Sabha held on the 22nd November, 1965, in the Daily 'Hind Samachar', Jullundur, in its issue, dated the 23rd November, 1965. The Deputy Speaker referred the matter to the Press Gallery Committee for their views.

The Secretary, Press Gallery Committee, —vide his letter, dated the 7th January, 1966, intimated—

"The Committee has to bring to the kind attention of the Speaker that Urdu Daily 'Hind Samachar' expressed its regret in its issue of November, 26, 1965. The cutting in original is being forwarded.

The Correspondent of the said paper stated before the President of the Committee that this error was unintentional. Soon after the incident took place in the House, the correspondent concerned filed his story on telephone. By the time the story had been sent to the Press at Jullundur, he came to know that the Honourable Deputy Speaker has expunged this part of the proceedings.

In view of regret expressed by the Editor and the circumstances explained by the representative of the paper, it is recommended that this matter too be dropped."

In the light of the views of the Press Gallery Committee and the publication of regrets expressed by the Editor in the issue of the 'Hind Samachar', Jullundur, dated the 26th November, 1965, I have decided to drop the matter.

(3) I have to inform the House that the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1965, was referred to the Regional Committees by the Vidhan Sabha at its meeting held on the 3rd November, 1965, with a direction to make a report by the 31st January, 1966. The Hindi Regional Committee could not finish its work within the prescribed period.

I was approached by the Chairman, Hindi Regional Committee to extend the time for the submission of the report upto the 28th February, 1966. As the House was not in session, I agreed to the said extension.

Now I am making a report to the House in the matter accordingly.

(4) I have also to inform the House that the Punjab Co-operative Societies (Second Amendment) Bill, 1965, was referred to the Regional Committees by the Vidhan Sabha at its meeting held on the 28th April, 1965, with a direction to make a report by the 30th September, 1965. The Hindi Regional Committee could not finish its work within the prescribed period.

I was approached by the Chairman, Hindi Regional Committee to extend the time for the submission of the report upto the 15th November, 1965. Later this time was got extended upto the 31st March, 1966. As the House was not in session, I agreed to the above extension.

Now, I am making a report to the House in the matter accordingly.

#### **Panel of Chairmen**

(5) Under rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairmen :—

1. Sardar Gurnam Singh.
2. Shri Ram Saran Chand Mital.
3. Pandit Chiranji Lal Sharma.
4. Shrimati Dr. Parkash Kaur.

#### **Announcement by the Secretary**

**Mr. Speaker :** Now, the Secretary will make an announcement.

**Secretary :** I beg to lay on the Table of the House a Statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during the Budget/Autumn Sessions, 1965, and which have since been assented to by the President/Government.

**Statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its Budget/Autumn Sessions 1965 and which have since been assented to by the President & Governor**

1. The Punjab Warehouses (Amendment) Bill, 1965.
2. The Punjab Cotton Ginning and Pressing Factories (Amendment) Bill, 1965.

3. The Punjab Town Improvement (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill, 1965.
4. The Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, 1965.
5. The East Punjab War Awards (Amendment) Bill, 1965.
6. The Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1965.
7. The Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill, 1965.
8. The Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965.
9. The Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965.
10. The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1965.

### Leave of Absence

The following letter has been received from Comrade Hardit Singh Bhathal, M.L.A. :—

“It is submitted that I have received the summoning letter for the Assembly Session which is to commence from 14th February, 1966. Owing to my detention, I would not be in a position to attend the Session. I, therefore, request the House through you to condone my absence from the Session or the meeting of any Committee of which I am a member so long as I am under detention.”

Has the hon. member the leave of absence asked for ?

*Voices : Yes, yes.*

*The leave was granted by the House*

### Papers Laid on the Table

**Revenue Minister (Sardar Harinder Singh Major) :** Sir, I beg to lay on the Table the Punjab Ordinances Nos. 1 and 2 of 1966.

I also beg to lay on the Table Orders Nos. 1-A and 2-A dated the 16th September, 1965, alongwith the Corrigendum No. 282/63-(2), dated 7th October, 1965 of the Delimitation Commission of India.

### LEGISLATIVE BUSINESS

#### (Presentation of Reports)

**ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ :** (ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ) ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ 1965 ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । (I beg to present the Report of the Punjabi Regional Committee on the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 1965.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਾਥ (ਸਭਾਪਤਿ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਕ ਸਮਿਤਿ) :** ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹੀਦਯ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਉਪਜ ਮਾਝੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ 1965 ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਕ ਸਮਿਤਿ ਕਰ ਕਾ ਪ੍ਰਤਿਵੇਦਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । (I beg to present the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 1965.)

**Reference of the Punjab Cattle Preservation Bill, 1964, to the Regional Committees**

**Shri Ram Partap Garg** (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Cattle Preservation Bill, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by 28th February, 1966.

**Mr. Speaker** : Motion moved—

That the Punjab Cattle Preservation Bill, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by 28th February, 1966.

**Mr. Speaker** : Question is—

That the Punjab Cattle Preservation Bill, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by 28th February, 1966.

*The motion was carried*

**DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS**

**Shri Ram Saran Chand Mital** (Narnaul) : Sir, I beg to move—

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

“That the members of the Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of the State Legislature assembled together on the 14th February, 1966.”

Sir, before I deal with the resolution which I have just moved, I would like to give expression to my feelings in regard to what happened the day before yesterday when the Governor came to address the Legislature. It was, for the first time, that the Punjab Legislature was addressed by a Punjabi as Governor, a non-controversial figure of saintly character devoting his time and energy to the service of the State and the Nation. But, most unfortunately, when he began to address the House, some friends of the Opposition tried to create disturbance. One Member of the Jan Sangh Group even questioned the validity of his appointment as acting Governor, although much time has since elapsed, one session has already passed and most of us have enjoyed his hospitality at parties at the Raj Bhavan. Then, Sir, the Communist Party and several Members of the Akali Party staged a walk-out. All these things were ugly scenes not befitting our Legislators. Besides being a slight to the constitutional Head of the State, I think we, as Legislators, feel humiliated by the enactment of such a scene of ugly demonstrations. Everybody knows that the Address, which the Governor reads, contains an account of the past performance of the Ministry and its future plans and policies. The Governor is not personally responsible for all that. He, as the Head of the State, has to read the Address. The entire function is a very solemn function held under the provisions of the Constitution. We are all under oath to observe the Constitution and the conventions properly in letter as well as in spirit. Yet I do not understand why such scenes are allowed to be enacted. The Constitutional experts, Speakers' conferences and various other bodies have deliberated over such affairs and have unanimously disapproved of this method. Ours

is a democracy and in a democracy Government is carried on by discussion. I can very well understand that they may not agree with the policies of the Government. I can also visualize that they may not approve of the future plans. They may have many things to criticise and vehemently criticize the past activities of the Government. That can be understood. To ventilate their feelings today is the appropriate and proper time. Here they can criticize the Government to their hearts' satisfaction, of course, within the constitutional decorum and propriety. But the things which they did day-before-yesterday in this Chamber are unbecoming and I would request you to devise ways and means to prevent such things in future at least.

Coming now, Sir, to the merits of the resolution, the year which is now just coming to a close, the financial year 1965-66, if anybody were to ask what were the outstanding events that occurred in this year, the answer would at least be, to my knowledge, it cannot be otherwise, that the outstanding events are the Indo-Pakistan conflict; the deaths of the most important great leaders and other important personalities of the country and, Sir, the failure of rains in Punjab giving rise to drought and famine conditions in the State—in some parts at least—and the terrible consequences of all these events. Naturally, Sir, the Governor's Address must be dominated by these outstanding events. Para 3 at page 2 of the Address reads—

“The past year has been a period of trial and tribulation. My Government was faced with an overwhelming and unprecedented situation when Pakistan launched aggressive military action against the territorial integrity of our country. Whereas our armed forces personnel enhanced their prestige by their many deeds of daring, courage and sacrifice, our people in Punjab—cultivators, traders, workmen and women everywhere—also exhibited rare qualities of resourcefulness, forbearance and fortitude and gave valuable assistance to the army and the police in many ways, and the public services of all categories played their role magnificently....”.

The Address, Sir, contains many details of the various activities of the Government. The public, the officials and all concerned during this Indo-Pakistan conflict—we call it a conflict because there was no formal declaration of war otherwise to all intents and purposes it was nothing short of a regular war and it was a terrible war—played their role magnificently. The consequences of this conflict were very serious. At least for the first time Punjab was involved in this conflict. Punjab became more or less a battle-field. Of course, there were other States, Jammu and Kashmir, Rajasthan and, to some extent, Gujrat also. But Jammu and Kashmir and Punjab had to bear the brunt of this war, and what the public did, what the Government did, what the officers did, what other sections of the population including the Opposition did, that has received admiration not only of the people of Punjab but of the entire country. Our great leaders have unequivocally appreciated our work, our performance. In 1962, Sir, there was Chinese aggression. At that time also we made huge preparations. Of course, at that time the late Sardar Partap Singh Kairon was at the head of the administration and the work done at that time served as a model and a pattern during this Indo-Pakistan conflict. At that time also the work of Punjabis was appreciated so much that the State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan set apart vast tracts of land for the Punjabi personnel of the Armed Forces and at all hands that work was much appreciated. This time the conditions were more serious and those at the helm of affairs in Punjab acquitted themselves very well. It was a joint co-operative

[Shri Ram Saran Chand Mital]

effort. I do not go into the details. They are well described in the Address and several pamphlets and booklets published by the State Government. I had an opportunity, Sir, to tour the Punjab right from my home town, Narnaul, up to Amritsar with Chaudhri Ranbir Singh. At Amritsar I found Sardar Gurdial Singh Dhillon at his job and Captain Rattan Singh as well. I crossed the Wagha border and went to the place where shelling was going on. [Sardar Gurnam Singh, a Member of the Panel of Chairmen in the Chair.]

Sir, I cannot forget and will never forget the enthusiasm I noticed at that time among the people from one corner of the State to the other corner of the State. A soldier of another State entering the sacred soil of Punjab, from Delhi right up to Amritsar, will never forget the enthusiasm hospitality and cordiality with which he was welcomed. There are many other things but I need not go into the detail.

Sir, war is undesirable. It brings destruction, loss of life and property but many a time it is a blessing in disguise as well. The State of Jammu and Kashmir is predominantly inhabited by Muslims and Pakistan tried to pose herself as a champion of the rights of the Muslims. But, Sir, it is a very pleasant and happy thing to note that the blood of the Muslims of Jammu and Kashmir and other States of India mingled with the blood of Hindus, Sikhs, Anglo-Indians, Parsies and other people inhabiting this Sub-continent for the defence of the motherland.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, the hon. Member is speaking on the Governor's Address and it was expected of him that he would throw some light on the future policies of the Government but he is talking of the war which is a dead past. I would, therefore, through you, Sir, request the hon. Member to enlighten as to what the Government is going to do in the future.

**Shri Ram Saran Chand Mittal :** Only my hon. friend should have patience and tolerance . . . . .

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** That of course we have.

**Shri Ram Saran Chand Mital :** Sir, what I was driving at was that the sacrifices that we have made will not go in vain. That is one view about this Address. I will also come to that part of the Address to which Pandit Chiranji Lal Sharma made a reference. Sir, the second outstanding event is the death of several leaders, Shri Lal Bahadur Shastri, Gen. Kulwant Singh, General Thimayya, Dr. Bhabha and Dr. Gadgil, our former Governor. The House has already passed Resolutions of condolence. But the places of Shri Lal Bahadur Shastri, Dr. Bhabha and the Generals cannot be filled up. That is our permanent loss.

The third outstanding event is the failure of the rain-fall and the creation of the drought conditions. Here I am referring to the words of the Governor himself—

“.....we are confronted with another grim problem caused by the failure of rains and the resultant drought. There has been a serious shortage of rain in the entire State, but the conditions are particularly bad in the districts of Hissar, Rohtak and Mohindergarh”.

Then of course the Government has made financial provisions to meet the famine conditions. At least about Mohindergarh district, the place where I come from, I can say that this famine appears almost every year in some parts of the district. I have been making repeated assertions on this point in this House and elsewhere. I have been requesting the Government to take some permanent measure so that we may not have repetition of such

conditions. Here in the Governor's Address there is some indication of what the Government is doing :—

“My Government has projected itself further too and constituted a Committee with the Financial Commissioner, Revenue as a Chairman, to prepare a plan for dealing with this problem on a permanent basis in the drought affected region of Hissar, Mohindergarh, Gurgaon and Rohtak Districts as well as the Una Sub-Division and Kandi area of Garhshankar.

Sir, the Committee no doubt would prepare its plan. The Financial Commissioner, Revenue, seems to be a good fellow but I would suggest that unless you provide the irrigation facilities there cannot be any permanent solution. Wherever there is a scope Government may extend the canals but in several parts of the drought affected regions, canals cannot be easily dug. For that purpose the Government must resort to energisation of tubewells and of pumping sets and they would not mind spending whatever is required. No question of scarcity of materials, no question of lack of finances. These things should not come in the way and I would suggest to the Government that they should start forthwith electrification beginning from the southern most part of this State, namely, Nangal Chaudhri Block right upto the northern most part of this State. Unless they spend a good deal of amount it set apart for that purpose forthwith without any loss of time and without even awaiting for the results of the Committee set up, these problems cannot easily be solved. I am sure, this is the Budget time, the Government must take notice of these things.

Sir, now I come to the other aspects of the Governor's Address. The hon. Member Pandit Chiranji Lal Sharma was very anxious to know about the future plans of the Government. There are two aspects of the future plans. For one we shall have to wait till the Budget Estimates are placed before the House and for the other it is obvious that we are being hit by drought, we are being hit by the consequence of the Indo-Pakistan conflict and naturally the Government must strain every nerve to normalise the economic conditions prevailing in the State. There is no escape from it. They must do it. The Address of the Governor makes a mention of it and about the future plans of the Government. I refer to page 8 of the Governor's Address. It reads—

“One piquant lesson which has been brought home significantly by the Emergency is that the economy of the country must become self-reliant at the earliest stage, specially in the matter of food production.....”

About food production it says—

“We have suitably expanded our programme for the supply of seeds, fertilizers, improved agricultural implements, plant-protection equipment and pesticides during the year.”

Then it further reads—

“.....Thus, we have taken measures which have contributed to the stabilisation of prices, availability of foodgrains in the State throughout the year and fulfilment of our onerous duty towards the deficit areas of the country.”

Then they are going to introduce statutory rationing in some towns after the arrival in the market of the next Rabi Crop.

Sir, I can very well understand that there may be some differences. I cannot also support that there are no loopholes. They are in this State and in the entire country as well. We are a surplus State in the matter of production of foodgrains. Foodgrains here are comparatively cheaper.

(Shri Ram Saran Chand Mittal)

But, just cross the Jamuna and you will find that the foodgrains there are more costly. But, after all Rome was not built in a day.

**Voice :** 18 years have since elapsed.

**Shri Ram Saran Chand Mittal :** There are always two aspects of every problem. We have Zonal System and if that is abolished, one section of our population will oppose it and the other will favour its continuance.

**Mr. Chairman** (Sardar Gurnam Singh) : Zonal System is being considered by your High Command.

**Shri Ram Saran Chand Mittal :** My submission is that whenever any reform is introduced, one section of the population is hit. When the crops come in the market after the harvesting season, prices go down. The poor producer suffers. At that time, Government comes to his aid. It makes purchases so that the price does not go down beyond a certain limit. And, then that stored grain is used for internal consumption and also sent to outside deficit States. So that thing happens. If the farmers sell all their produce well in time, they have to buy it at the time of their need. Then the prices go high. That you cannot easily avoid. It is a very very complex machinery. Unless all the sections of the population co-operate, unless the entire machinery is stirred, all this is inevitable. I accept that there are laxities in the administration. There are laxities in our character. And, it is not the fault of that administration or that Government alone. It is our own fault and it is the fault of all of us. We cannot blame the Government alone. *(Interruptions).*

What I feel is that so far as the future plans are concerned, the entire attention of the Government is now concentrated upon the restoration of the old normal conditions of our economic life. But, for that you cannot have a magician's wand. You cannot restore everything in a day. That takes time. There are certain limitations as well. We have to look to our financial resources. The Governor's Address gives a description of the Third and Fourth Five-Year Plans. You have made some savings. We have spent more than what we have. We have spent on defence. The figures are there. I need not go into them. The only point that I want to make out is that at this time the machinery of the Government is devoted to the restoration of the normal economic conditions. In industries, there is a loss of industrial output worth about Rs 15 crores of rupees. There are so many difficulties, All-India difficulties, foreign exchange difficulties and so on. About our future plans, details are given in the Address. I would not like to go into their details. About Industries, it is stated in the Address :

"The recent conflict with Pakistan severely strained our economy in another field as well, i.e., industries. It led to the contraction of credit facilities, dislocation of transport and shortage of raw materials. In consequence, the State suffered a loss of over Rs 15 crores in its industrial output. With a view to stabilising production and the growth of industries, several measures were taken promptly....."

You cannot expect all these things to happen in a day or overnight. This is along drawn out process.

*(Interruptions and noise in the House)*

**Mr. Chairman :** Order, Order, please.

**Shri Ram Saran Chand Mital :** I would now briefly refer to transport, teachers and students' contributions towards the Punjab Defence and Security Relief Fund and the Haryana Affairs. Regarding Transport, I am glad and I congratulate my friend, Sardar Gurdial Singh Dhillon, that he has introduced concession of free lifts to our school children.

*(Interruptions)*

I must, at the same time suggest that he should make it a point to see that every district headquarters has a very fine Bus Stand built at the cost of the Government. From this Bus Stand, bus routes should lead to all other important directions. For example from Narnaul to Alwar Jaipur and all other important places.

Then, Sir, the Governor has paid a rich tribute to the teachers, students and other departments for their substantial contributions to the Punjab Defence and Security Relief Fund. For this collection of funds, no doubt, huge efforts had to be made. But, in regard to the teachers, yesterday when I was reading some Paper in the Library, I found a news item which I wish to bring to the notice of the House and through you, Sir, to the State Government as well. It is published in 'Patriot' (Punjab edition, dated the 16th February, 1966. The news is from Ludhiana. I will read three or four lines of it—

"At a public meeting jointly organised by the Punjab Government Teachers' Union, the Pepsu Government Teacher's Union and the Subordinate Educational Services Teachers' Union under the Presidentship of Mr. Madan Gopal, President of the Government Teachers' Union, a resolution protesting against what they called forcible cuts being made in teachers' salaries in Punjab for buying gold was passed".

This may be an exaggeration. I do not know much about it. Of course, we have to accept donations for purchasing gold or towards the Punjab Defence and Security Relief Fund voluntarily from every section of the society including the Government employees and teachers in the schools. Teachers are proverbially poor. But I would suggest to the Government not to employ the teachers or the students for collection purposes. The teacher's job is very very sacred and to employ a teacher for collection purposes is not proper. That goes against his profession and by this we are reducing his status. I will confine myself to this much only that they may kindly pay attention to this news item appearing in the Press. But otherwise we are glad that contributions are pouring in from all quarters. Of course, good deal of progress has been made in various directions, spread of education, technical education and so on. But one point I do not find here, Girls' education, female education. I do not know whether any special efforts have been made to spread girls' education because in my district, in my tehsil, I find that hardly any improvement has been made for the spread of girls' education. That is very necessary, otherwise one section of the population remains backward.

Then, Sir, I come to the Haryana question. No doubt a Committee had been appointed to suggest measures for the development of Haryana and we are told, it has submitted its report as well and we quite feel that the only thing that the Governor has said in his Address is that the report of the Committee will receive consideration. The fact remains that the Committee submitted an interim report many months ago so that the Government could take action thereon there and then and in this budget session we expect . . . .

**Sardar Lachhman Singh Gill :** Are you in favour of Haryana Prant ?

**Shri Ram Saran Chand Mital :** I have submitted a memorandum to the Parliamentary Committee and I have appeared before it also. But the office of the Lok Sabha has directed that we should keep the memorandum secret as its disclosure would be breach of privilege of that august House. so whether I am in favour or against it, that question cannot

**Shri Ram Saran Chand Mittal**

be asked here. I have submitted my views as a witness before that Committee. So, my learned friend would not persuade me to commit a breach of privilege of that House.

**Sardar Lachhman Singh Gill** : I suppose you have already told it to your Mrs.

**Shri Ram Saran Chand Mital** : With regard to the Haryana business, I agree that they should have taken steps to implement the interim report of the Haryana Development Committee which was submitted to the Government several months ago and its commission I think, will be explained by the Government when they elaborate their own point.

**Mr. Chairman (Sardar Gurnam Singh)** : So, you withhold your thanks as far as Haryana question is concerned ?

**Shri Ram Saran Chand Mital** : Taking as a whole because they are giving relief for the famine conditions I am moving the resolution which stands in my name.....

**Pandit Chiranji Lal Sharma** : A specific question was put by the Chair whether you withhold your thanks so far as Haryana question is concerned. You have not replied to it.

**Shri Ram Saran Chand Mital** : No. About this affair I say, Sir, ..... (Interruptions).

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੋਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਹਲ ਮੁਹਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ।

**Shri Ram Saran Chand Mital** : I would request that I may be given 10 minutes extra which they, I will not say not wasted because that might create difficulty, took by repeated interruptions.....

ਪੰਡਿਤ ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੋ ਸਿਜਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਿਓ ਟਾਈਮ ਕਾਟ ਲੈਂ ।

**Mr. Chairman** : The hon. Member has taken 40 minutes. He may kindly try to wind up.

**Shri Ram Saran Chand Mital** : Sir, when I read the views of several legislatures on the Governor's Address in newspapers I came across one sentence that the Address was colourless. From whom it came, you know better.

**Pandit Chiranji Lal Sharma** : Not only colourless, but odourless also.

**Shri Ram Saran Chand Mital** : Sir, whose remarks that was, I leave it to you to find out and judge.....

**Mr. Chairman** : I know whose remark it was.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੈਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਲ ਹੈ ?

**Shri Ram Sara Chand Mital** : Now, Sir, I would read three sentences from the Tribune's comments dated the 16th February, 1966, from where it can be seen whether the Address is colourless or not. The first is—

“.....As a result, he (Governor) had something more to offer than the usual routine record of departmental achievements and a dull survey of the past year mostly featuring generalities.....”

The second is—

“.....As was but appropriate, the Governor devoted a part of his address to the State's war-hit economy and to the varied problems of reconstruction...”

The third is—

“.....Notable in the outline of the Ministry's policies is the determination” to continue translating democracy, secularism and justice for the development of the State”.

With these remarks I whole-heartedly agree. I deem it a favour done to me that I was allowed to move this resolution which I do most heartily.

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ (ਫਰੀਦਕੋਟ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ.....

ਚੀਫਰੀ ਫਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਲਿਕ : ਆਨ ਆਫ ਆਫ ਆਡਰ ਸਰ। ਗੁਜਾਰਿਸ਼ਾ ਧਰੁ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰੀ ਬੈਚਿਜ਼ ਪਰ ਇਸ ਕਕਤ 10 ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹੁਏ ਹੈਂ। ਇਸ ਜੇ ਧਰੁ ਯਾਹਿਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਸੋ ਗਕਰਨਰ ਆਡੇਸ ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਟ੍ਰੈਸਟ ਹੈ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਵੀ ਇਤਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉੱਨਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੈ ਇਸ ਆਈਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਥੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਹੈ (Hear, hear) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਮਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਆਨੈਸਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਘ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਰਿਆ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬਣਾ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਤਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਿਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਉਥੇ ਹਿੰਦ

[ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ]

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਸਾ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਭੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਨਵੀ ਅਤੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ੨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਸ਼ਾਬਾਸ਼) ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ।

(Mr. Speaker in the Chair.)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਫੌਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਕਾਕੀ ਤੇ ਇਕ ਕਾਕਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। (This is not a proper expression. The hon. Member is not sitting in his own house.)

ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ : ਇਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੌਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲਖ

ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਜਰਮਨ ਐਕਸਪਰਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਨਾ ਸਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਦੀ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੀਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਲਭੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਢੇਗੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਜ਼ ਦੇ ਭਾ ਗਿਰਨ ਵੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਜ ਕਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨਸ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨਾਜ ਵਧ ਉਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਵਧ ਉਗਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਮਾਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਣ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਘਟ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 49 ਤੋਂ 52 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਣਕ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਭਾ 60—65 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਭੇਜ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾ 100—ਤੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛੇ

[ਕਿਆਨੀ ਜ਼ੇਲ ਸਿੰਘ]

ਨਾ ਸੁਟਿਆ ਜਾਵੇ। (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਇਹ ਗੱਲ ਅਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਸਸਤੀ ਛੋਲੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਤੇ ਜੌਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਧੀ ਹੀ ਦੁਗਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਸਾਡੀ ਕਿ ਅਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਨਾਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਹ। ਦੇਗ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਸਦਾ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੇਗ ਫਤਹ ਭਾਵ ਤੇਗ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਮੁਕੇ ਅਤੇ ਤੇਗ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭਾ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵਧਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 1,100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੂਬ-ਵੈਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਉਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਫੀ ਸਦੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਖ ਵਿਚ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਜਨ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਖਾਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮੀਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਚੂਹੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ 6 ਕਰੋੜ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ 6 ਕਰੋੜ ਚੂਹੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 1966-67 ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਐਸੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਾਵੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਸੂਖ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ

[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]

ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੀਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੰਦ ਇਕ ਚਿਟਕਪੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ:** ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਰ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਚਿਟਕਪੜੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੱਦਰ ਪੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

**ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ :** ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਟਕਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ ਅੰਗ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਹਨ। (ਇੰਟਰਪੁਸ਼ਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਇਤ ਸਗੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਮਿਊਨਟੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਏਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਐਸ. ਡੀ. ਓਜ਼. ਅਤੇ 4 ਓਵਰਸੀਅਰਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ 10 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ

ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਣਕ ਕਢਣ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਗੇ ਕਣਕ ਕਢਦਿਆਂ ਬੜਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲੇਬਰ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਢ ਕਢੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ (ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ) । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੋਲੋ । ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਓ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ, 1.60 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਬਾਜਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭੁਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ੨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਟੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਭਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹਨ । ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹਨ । (ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ: 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹਨ) ਇਹ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹਨ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਏਸੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਏਸੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਹਾਂ । ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ । (ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਰਿਹੋ । ਵਜ਼ੀਰੀ

[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]

ਭੁਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ (ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ: ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ।) ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। (ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੇਖੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਵੇਖੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਇਕ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਤੋਲਣੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ)।

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ : ਆਜ ਏ ਪ੍ਰਾਧੰਟ ਆਫ ਆਡੀਟਰ, ਸੇਡਸ ਸੈਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਨਕੀ ਬੋਲਤੇ ਧੀਨਾ ਥੰਗਾ ਹੀ ਗਯਾ ਹੈ ਤੋ ਹੁਸ ਕਬ ਬੋਲੋਂ ਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। (Giani Ji may please wind up, He has reminded the hon. Member about it.)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਰਨ। ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਜ ਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਮੀਟਿੰਗ, ਈਟਿੰਗ, ਚੀਟਿੰਗ। ਮੀਟਿੰਗ, ਈਟਿੰਗ, ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ—ਇਕ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਗਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇ ਸੈੱਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚੁਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੌਕਸ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋ ਗਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ

ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਥੇ ਡਬਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਢੀ, ਡਬਲ ਸੜਕਾਂ ਕਢੀਆਂ । ਅਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਕ ਆ ਕੇ ਥਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨੀ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਪਤਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬੇਦਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਢਿਡ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਡੀਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ।  
(I find that out of all the longest speech has been made by the hon. Member.)

**ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਰੇ । ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਓਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਮੈਂ ਰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਪਰ ਏਰੀਆ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ । ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 13 ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੋਗਾ, ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50, 50 ; 60, 60 ਮੀਲ ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਬਠਿੰਡਾ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ ?

**ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ :** ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]

ਹੱਦ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਤਨੀ ਰਕਮ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜੇ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦਾ 23 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਸਨ ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੱਜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਜ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਹੋਇਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮਗਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ

ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਰੀਲੀਫ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ 1948 ਤਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1948 ਤਕ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰੋ। (The hon. Member Giani Zail Singh has been speaking for the last fifty minutes. He may please wind up in three minutes.)

**ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**Deputy Speaker :** Motion moved—

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

“That the members of the Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of the State Legislature assembled together on the 14th February, 1966.”

Some amendments to the Motion have been received from various honourable Members. These amendments will be deemed to have been read and moved and may be discussed alongwith the main motion.

1. **Pandit Mohan Lal Datta :**

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that no mention has been made—

(1) of the necessity of introducing prohibition in the State ;

(2) of Land Reforms which was essential for increasing agricultural production and bringing about social justice ;

**[Deputy Speaker]**

- (3) of rural industrialisation which was essential for rural development ;
- (4) of the unirrigated and drought-hit hilly areas of tehsil Una. Hamirpur equally with the other drought hit Districts as regards relief measures ;
- (5) of the steps to be taken to provide irrigation facilities to the hilly areas particularly tehsil Una."

**2. Principal Rala Ram :**

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret—

- (1) that the cent per cent hilly areas of Thana Hajipur (District Hoshiarpur) has been excluded from the purview of the Committee appointed under the Chairmanship of the Financial Commissioner (Revenue) to suggest permanent measures to tackle the drought problem in certain areas of the State, including Una Tehsil to which it is contiguous ;
- (2) that the Address make no mention of any steps intended to be taken to redress the imbalance in the matter of Tube-well connections which have not been given at all in areas like Mukerian and Hajipur Blocks so far ;
- (3) that no scheme for the upgrading of such Government primary middle schools where the Panchayats have put up the necessary buildings and are prepared to pay the cash amounts prescribed for the purpose has been outlined in the Address ;
- (4) that no indication has been given in the Address as to the period during which the Datarpur area water supply scheme and the Kumalie Devi area (Hajipur Block) water-supply scheme are to be implemented ; and
- (5) that no mention has been made in the Address of the spurs so badly needed to save villages, lying on the banks of River Beas on Mukerian-Mirthal side, from the depredations of floods in that River."

**3. Pandit Babu Dayal Sharma :**

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention is made for the revival of the Salt Industry of Gurgaon District and to give foremost priority to supply the electric power as promised by the Government in 1953 and supply fresh drinking water to all such villages and towns where there is salt water."

**4. Babu Ajit Kumar :**

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

- (1) for the cancellation of lease of Birla Brothers land ;
- (2) to protect the rights of Scheduled Castes employees specially serving in Punjab State Electricity Board, Agriculture University, Punjab University, Punjabi University and Kurukshetra University with regard to reservation in promotions ;
- (3) regarding allotment of all Government land to the landless people ; and
- (4) for the allocation of 1/4th of the yearly Budget for the uplift of the Scheduled Castes and other Backward Classes."

**5. Babu Bachan Singh :**

That in the motion the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

- (1) to check the growing unemployment in the State ;
- (2) of transforming of the present capitalistic social set up into socialistic pattern ; and
- (3) of the new excise policy set by the State Government."

6. Comrade Jangir Singh Joga :
7. Comrade Babu Singh Master :
8. Comrade Gurbakhsh Singh :
9. Comrade Bhan Singh Bhaura :

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that—

- (1) no promise has been held out to cancel lease of land to Birla Brothers in the sutlej Bed in deference to the public opinion ;
- (2) no mention has been made of acceding to popular demand for release of detenue ;
- (3) full cognizance has not been taken of the damage caused to the agriculture by prolonged drought and no measures have been announced for stepping up irrigation ;
- (4) no steps have been taken to meet the demands of government employees ;
- (5) no mention have been made to check the growing un-employment in the State ; and
- (6) no mention have been made regarding the allotment of surplus land as well as government lands to the tiller in order to increase the agricultural production.”

10. Dr. Baldev Parkash :
11. Shri Balramji Dass Tandon :
12. Shri Mangal Sein :
13. Shri Satya Dev :
14. Shri Fateh Chand Vij :

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that nothing has been said—

- (1) for allocating 60 per cent of the total Budget for the development of Haryana and Hilly areas ;
- (2) for abolishing the Food Zones to better the lot of farmers and to give a fillip to move production of foodgrains ;
- (3) regarding taking concrete steps to rehabilitate the War hit economy of the State ;
- (4) to fulfil the promises made by the Government of and on to grant ample loans for Industry and to give relief in taxation in border industry; and
- (5) to dissolve the deed made by the Government with Birlas to lease them 1000 acres of reclaimed land against the interest of petty farmers and landless Harijans.”

15. Comrade Shamsheer Singh Josh :

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that—

- (1) the Address makes no mention of any steps intended to be taken to provide irrigation by setting up Government tube-wells or from Bhakra Canal or by constructing Dams at the heads of rainy rivulets in Ambala and Hoshiarpur Districts. This matter assumes grave importance because 88 per cent areas of these districts are unirrigated ;
- (2) the Address takes no notice of strong public opinion against the Birla land lease and also fails to mention the reasons for imposition of section 144 around Assembly and Secretariat ;

[Deputy Speaker]

- (3) The Address fails to mention inordinate delay in distribution of rehabilitation loans amongst unemployed workers during Pakistan-India conflict and also fails to mention the failure of the Government to stop large-scale retrenchment of workers all over the State;
- (4) the Address fails to mention any steps taken to set up Hydel Power Plant at Rupar on Bhakra Canal; and
- (5) the Address fails to mention the reasons as to why Hilly area allowance is not given to Government employees of Rupar and Majri Blocks of Ambala District."

**16. Shri Roop Lal Mehta :**

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

- (1) regarding supply of electric material and not supply of electric connection to hundred of Tube-wells for short of material in entire Gurgaon District ;
- (2) regarding industrialisation of Palwal area for Co-operative Sugar or Spinning Mills which are proposed to be set up in other parts of the State ;
- (3) to provide better class of Buses to avoid frequent break down ; and
- (4) regarding removal of disparity of water rates of upper Agra Canal in Gurgaon District."

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਏਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ (ਤਾੜੀਆਂ) ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ (ਵਿਘਨ)। ਐਸੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗੇ ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜਿਜ਼ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ (ਹਾਸ) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਯਾਨਗੀ ਹੋਣ.....

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਂਡਮ। ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :

“ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ.....”

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ..... (ਸ਼ੋਰ) (ਬੈਠ ਜਾਉ, ਬੈਠ ਜਾਉ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ) .....

**Deputy Speaker :** If the hon. Member who is speaking does not give way, the Chief Parliamentary Secretary cannot speak.

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਫਰਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ..... (ਸ਼ੋਰ)

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ।  
(Addressing Shri Garg : The hon. Member Baboo Bachan Singh is referring to what has been given in the address. He is not saying anything of his own.)

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਉਸਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਨ ਜੋ ਬਾਬੂ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਇਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ (ਹਾਸਾ)

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਬਾਬੂ ਜੀ, ਜਿਥੇ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ।

(Addressing Baboo Bachan Singh. The hon. Member may

[Deputy Speaker]

mention the Governor by name while referring to the Ujjal Singh Committee otherwise he may be mentioned as Governor.)

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** If you kindly refer to address itself it is written thereon "Delivered by Sardar Ujjal Singh, the Governor of Punjab.....". Why should there be any objection to that? There is no bar.

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 14/15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.....

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਇਥੇ ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਲੋ ਮੱਲੀ ਦੋ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੁਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸੀਨ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਾਜ਼ਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਪਾਰਲਾਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਟਰਪ੍ਰੇਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਬ ਦਾ ਰਕੋਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਸੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਸਪਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Wedded to the Principles of democratic socialism, our Government shall make a determined effort..

**ਚੌਥਰੀ ਵੇਕੀ ਲਾਲ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਕਥਾ ਹਾਊਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਆਨ-ਰੇਕਲ ਮੈਂਬਰ ਮੁਖਯਸਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਪਛ ਸਕਤਾ ਹੈ? ਕਥਾ ਉਨ ਕੀ ਆਕਾਜ਼ ਕੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ?

**ਤਪਾਧਯਕਸ਼ਾ :** ਕਹਿ ਉਨ ਕੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕਲਿਕ ਉਨ ਕੀ ਸਪੀਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਸੁਨਾ ਰਹੇ ਹੈਂ।

(The hon. Member is not immitating but reading out certain excerpts from the Address)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੁਝ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ—

I was quoting, Madam,

“Our Government shall make a determined effort to make that social and economic order in which essential requirements of food, housing, education and health of our people are satisfied.....”

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੀਮਾਰ ਹਨ। ਰਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਦਮ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ—

ਬਹੁਤ ਸੌਰ ਸੁਨਤੇ ਥੇ ਪਹਿਲੂ ਮੇਂ ਦਿਲ ਕਾ,

ਜੋ ਚੀਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਤਰਾਏ ਖੂੰ ਕਾ ਨਿਕਲਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਨ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾ ਵਿਚ 63 ਲੱਖ ਟਨ, 66 ਲੱਖ ਟਨ, 70 ਲੱਖ ਟਨ, 74 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ। 1960-61 ਵਿਚ 63, 77,000 ਟਨ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 1961-62 ਵਿਚ 64,48,000 ਟਨ ਅਨਾਜ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

1962-63 ਵਿਚ 59,32,000 ਲੱਖ ਟਨ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ 1963-64 ਵਿਚ 57,32,000 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 69 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ :** 1964-65 ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਵੀ ਦਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਅਗਰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰ ਟਰੱਪਟ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਇੰ ਟਰੱਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਜ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀਰ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੋਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਟੱਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਦੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਰਿਡੀਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1964-65 ਦੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿਗਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

**ਤਪਾਘਖ਼ਾ :** ਆਪ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਇੰਟਰੂਪਟ ਨ ਕਰੋਂ। ਹਰ ਏਕ ਬਾਤ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। (The hon. Chief Parliamentary Secretary need not interrupt the hon. Member. It is not necessary to reply to every point)

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Can any Member of the House, even from the Treasury Benches, interfere like this, by asking an honourable Member to speak according to his wishes ?

**ਤਪਾਘਖ਼ਾ :** ਅਗਰ ਆਪ ਮੇਰੀ ਢਲਿੰਗ ਕੋ ਪਹਲੇ ਸੁਨ ਲੇਤੇ ਤੋ ਆਪ ਕੋ ਧਹ ਘਾਧੰਟ ਆਫ ਆਡੰਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਹਜ਼ੂਜ ਨ ਹੋਤੀ। ਮੈਂ ਨੇ ਪਹਲੇ ਕਹੁਦਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਕੋ ਇੰਟਰੂਪਸ਼ਨ ਇਨਕਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿਏ। (If the hon Member had cared to listen to my ruling, he would not have felt any necessity for raising this point of order. I have already stated that the Chief Parliamentary Secretary should avoid inviting any interruptions.)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਾਰਗੈਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ—

‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਪੋਟ ਅਧੀਨ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ

ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਾ ਅਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਨ 1962 ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਐਗਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਠੀਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੈਡੂਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸੰਨ 1963 ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਸੰਨ 1963 ਵਿਚ ਉਹ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਅਲੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਨਸਿਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਬਰਸਦਾ ਹੈ। ਅਕਲਮੰਦ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਿਲਬਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈਡਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ 1,72,000 k.w. ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਕੇ 70,000 k.w. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਉਹ ਘਾਟਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜਿਸ ਗਲ ਉਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜ ਅਨਐਂਪਲਾਏਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 19ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਮਾਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਂਟੀ ਛਾਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 28 ਫਰਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ

## [ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਅਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅੱਠ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਇਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਰੌਨਕ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਆਇਆ। ਰੌਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਗਨੌਰ ਵਿਚ ਟਿਊਬ ਕੰਪਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 32,000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਅਲੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲੱਗ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਗਰਿਪਸ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਸ ਹਨ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਿਪ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ—ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅੰਗੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ:—

“The unweighted general whole sale price Index Number (base October— December), 1949— 100 compiled on the basis of prices of 50 important commodities was 152.1 for the month of June, 1965 against 150.6 for the month of May, 1965. It was 4.1 points higher as compared to the corresponding month of the last year”.

ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ

ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਹੀ ਸੀ—ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 4.1 ਪ੍ਰਾਇੰਟ ਵਧ ਗਿਆ ਅੰਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ 160 ਪ੍ਰਾਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਨਾਲਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅੰਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਸੀਅਰਜ਼ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਇਕ ਹੈ ਅੰਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਹਿੰਗਾਈ 10 ਪ੍ਰਾਇੰਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਨਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਇਸ 1964-65 ਦੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 'ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਹਮਦਾਰ' ਕਰੈਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਿਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਉ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਨੇ ਭੁੰਜੇ ਸਿਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਲਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੂਮਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਖੋਮਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਿਰਲੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੀਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਥ ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ। ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਥਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਖੈਰਖਾਹ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੂਜ਼ਪਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਥਾਪਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਕੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿੰਬਰ ਬੇਦਰੇਗ ਕਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਗੇ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਗਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਇਸ ਲਈ 50 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰੀ, ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਥੂ ਖੈਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) ਇਥੇ ਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਰੌਨਕ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਨੌਰ ਵਿਚ 32,000 ਐਕਸੈਸ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਲੈਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਜਿਥੇ 12,000 ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਨ ਇਹ ਵਧਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 40,000 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਿੰਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਗਰ ਸੌ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਹੀ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਵਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹਨ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ

ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੇਲਣ ਤੇ ਕੋਹਲੂ ਪੁਟਵਾ ਦਿਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ ਦਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ 'ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ' ਦਾ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿਤਾ। ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਡ-ਲਿਸਟਾਂ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹਨ। ਅਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ-ਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਮਨਾਪੋਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਦੇ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੋਣ ਸਮਗਲਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟੀਅਰਜ਼ (ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ)

ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਬਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਹਵੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲੀ ਵਾਂਗ ਮਿਆਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਅਤੇ 98 ਪਸੇ ਫੀ ਮੀਲ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਹਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਰੂਟ ਅਤੇ ਕੁਲੂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

**Transport and Elections Minister :** We will do it according to schedule.

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਡੂਲ ਆਫ ਟਾਇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਇਮ ਸ਼ੈਡੂਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਵਿਘਨ)। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ।

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਕਾਇਮ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਟਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ 'ਏ' ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 'ਬੀ' ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਮਲੇਰ-ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੌਂਚੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੰਨਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖਲੀਫੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਇਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਥੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਡਗਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਉਗੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਤੁਹਾਥੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੀ (ਵਿਘਨ)

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਡਮ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਥੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਗਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ 51 ਮਿੰਟ ਲਏ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ 43 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਮਾਇੰਡ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ।

(Just as Giani Zail Singh took 51 minutes to speak, similarly Babu Bachan Singh has been speaking for the last 43 minutes. It is good that the hon. Minister has drawn my attention to this matter.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵਰਤੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵੇਸੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ

On such critical occasions in the course of our Independence, we cannot but remember and honour our debt to the Father of Nation, Gandhiji, who brought us our freedom and unity. ....

ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਦਿਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਤਾਮੀਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਤਾਮੀਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਮੁਲਕੀ ਅਸਲਾਹਾਤ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ-ਬੰਦੀ ਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਲਾਨੂਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 1964 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਤਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਬੱਤਲ ਦਾ ਰੇਟ 6 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਪੈਸੇ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 25 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਡ ਗੇਟ ਆਫ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਠੇਕੇ ਆਕਸ਼ਨ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਬਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਸਦੇ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਬਾਬੂ ਜੀ ਟਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਉ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ। (Addressing Baboo Bachan Singh) (The hon. Member has taken a lot of time. Hes hould now wind up and leave the subject of prohibition)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਨ ਆਫ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ । (The hon. Member can Speak.)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ-ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਨਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਤੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਗਗਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 42 ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਨ ਉਥੇ 19 ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ?

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਟਾਇਮ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ। (The hon. member has already taken so much time. He may kindly resume his seat)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। (ਵਿਘਨ)

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਨਾਉ।

(I am very sorry to say that when the Presiding Officer is standing, a senior member like the hon. Member, does not care to resume his seat but continue speaking. The hon. Member may please wind up.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਉ।

"Prohibition in the Congress Provinces is not going on in the spirit in which it was conceived..... Congress opinion is equally dormant. Congressmen do not seem to see that prohibition means new life for many millions. It means new and substantial accession of moral and material strength. They do not realise that honest prohibition gives a dignity and prestige to the Congress which perhaps no other single step can give. They do not see that prosecution of prohibition means identification with the masses and a resolute determination to refuse to have any thing to do with the drink revenue."

**Deputy Speaker :** The House stands adjourned till 9.30 A. M. tomorrow.

*(The House then adjourned till 9.30 A. M. on Thursday, the 17th February, 1966)*

1. The Government of India have received from the Government of Punjab a copy of the report of the Punjab Legislative Assembly for the year 1954-55.

2. The report contains a detailed account of the work of the Assembly during the year.

3. The report also contains a list of the members of the Assembly and a list of the members of the Council of Ministers.

4. The report is published in the Punjab Legislative Assembly Report for the year 1954-55.

**APPENDIX**  
TO  
**PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. 1, NO. 2, DATED THE**  
**16TH FEBRUARY, 1966**

**Upgraded Government Primary/Middle Schools in Ambala District**

**3086. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state:—

- (a) the number of Government Primary and Middle Schools upgraded to Middle and High Schools respectively during the year, 1965-66 to date in Amritsar District.
- (b) the number of class rooms in each of the said upgraded Middle and High Schools excluding the Headmaster's Office etc. ;
- (c) the area provided in each such school for play-grounds ;
- (d) the number of teaching posts sanctioned for each of the schools mentioned in part (a) above ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) and (d) Information already supplied.

(b) and (c) The requisite information is enclosed.

---

Serial No.	Name of School upgraded	(b) No. of class rooms in the school	(c) Area provided for play grounds
------------	-------------------------	---	---

---

**High Schools**

			Acres
1	Government High School, Ghariala	6	2
2	Government High School, Shahbazpur	5	4
3	Government High School, Lalpura	9	8
4	Government High School, Gaggo Bua	7	10
5	Government High School, Ekal Gudda	5	4
6	Government High School, Dial Bharang	2	10
7	Government High School, Bhindi Savadan	7	2
8	Government High School, Bachiwind	5	2

**Middle Schools**

1	Sakhira	5	4
---	---------	---	---

---

\*Please see page (2)120 of this Debates.

Serial No.	Name of School upgraded	(b) No. of class rooms in the Schools	(c) Area provided for play grounds
			Acres
2	Lauka	5	4
3	Jawanda Kalan	6	4
4	Bhalaipur Dogran	6	1
5	Buttar Kalan	2	7
6	Beas	8	1½
7	Jabbowal	8	3
8	Pakharpura	7	1
9	Gumanpura	1	4
10	Preet Nagar	8	1
11	Bath	4	4
12	Pandori Sidhwan	1	4
13	Panjwar	4	1
14	Tarsika	8	2
15	Bhura Kanah	6	6
16	Vain Poin	6	3

### Misuse of Loans under L.I.G.H. Scheme

**3059. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Capital and Housing be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Shri Brish Bhan, M.L.A., when he was Capital and Health Minister, sent to the Legislators of the State, D.O. letter No. 5601-4HG-62/23110, dated the 6th August, 1962, on the subject "Misuse of loans under the LIGH Scheme—Verification by M.L.As/M.L.C.s" ; if so, with what purpose and a copy of the same be laid on the Table of the House ;

(b) whether any more complaints had been receive by the Government against the loanees and against certain Legislators for wrong attestation/verification after 22nd July, 1960 ; if so, the number of such complaints together with the names of the loanees and of the Legislators against whom such complaints had been received ;

Original with:—

- (c) whether the Department concerned referred any case against any of the loanees and Legislators to the Police for registration; if so, the number and names of such Legislators together with the details of the action taken so far; if no action has been taken, the reasons therefor?

The answer to Assembly Question No. 3059 appearing in the list of Unstarred Questions on the 16th February, 1966 in the name of Comrade Ram Piara, M.L.A., is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

(Sd) — ,

Minister for Capital and Housing,  
Punjab.

To

The Secretary,  
Punjab Vidhan Sabha,  
Chandigarh.

U.O.No. 396-2Hg-66, dated Chandigarh the 15th February, 1966.

#### Misuse of Loans under L.I.G.H. Scheme

**3060. Comrade Ram Piara, :** Will the Minister for Capital and Housing be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the ex-P.W.D. Minister, Ch. Suraj Mal sent to the Legislators of the State, D.O. letter No. 5273-4HG-60/21879, dated the 22nd July, 1960, on the subject "Misuse of loans under the LIGH Scheme—Verification by M.L.As/ M.L.Cs", if so, with what purpose and a copy of the D.O. letter be laid on the Table of the House;
- (b) whether any complaints regarding wrong attestation or verification had been received by the Government; if so, the total number of the same together with the names of those in respect of whom such complaints had been received;
- (c) whether in respect of the wrong attestations or wrong verifications the Department referred any cases to the Police for registration against the loanees as well as Legislators; if so, the names of such loanees and the Legislators?

The answer to Assembly Question No. 3060 appearing in the list of Unstarred Questions on the 16th February, 1966 in the name of Comrade Ram Piara, M.L.A., is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

(Sd) — — ,

Minister for Capital and Housing,  
Punjab.

To

The Secretary,  
Punjab Vidhan Sabha,  
Chandigarh.

U.O. No. 396-2Hg-66, dated Chandigarh, the 15th February, 1966.

**Defaulting Loanees of Industries Department in District Karnal**

**3061. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the names of those loanees of the Industries Department who are defaulters in district Karnal together with the date of default in each case ;
- (b) whether any warrants for realising the amounts of loan as arrears of land revenue had been issued against any of the said defaulting loanees, if so, their names together with the date of issue of warrants in each case ;
- (c) the total amount outstanding against each of the said loanees as on 1st January, 1966 together with the amount of loan so far paid back by each ;
- (d) whether it is a fact that in the case of a number of defaulting loanees against whom warrants as mentioned in (b) above have been issued, the warrants are not being followed up by the Recovery Staff; if so, the reasons therefor ;
- (e) whether he is aware of the fact that some of the said loanees at Karnal disposed of their Industries for which loans were advanced and have not paid back anything to the Department till 1st January, 1966, if so, the names of such loanees together with the steps being taken for effecting the recoveries of the loan amounts due from them ?

**Subject.**—Defaulting loanees of Industries Department in district Karnal.

The answer to Unstarred Vidhan Sabha Question No. 3061 asked by Comrade Ram Piara, M.L.A., appearing in the list of questions for the 16th February, 1966, is not ready. The reply to this question will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

(Sd) . . . ,

Irrigation and Power Minister,  
for Chief Minister.

To

The Secretary,  
Punjab Vidhan Sabha,  
Chandigarh.

U.O. No. 16(AQ)-4CB-66, dated Chandigarh, the 15th February, 1966.

### Grievances Committee

**3088. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- the total number of meetings of the Grievances Committee held from the date it started functioning till the 15th January, 1966, in each district of the State, date-wise ;
- the number of their said meetings attended by the Superintendents of Police in each district, district-wise and date-wise ;
- whether it is a fact that some of the Superintendents of Police did not attend some of the meetings of the Grievances Committees held in their respective district, if so, their names together with the number of meetings, date-wise, not attended by each together with the reasons for non-attendance ;
- whether it is also a fact that some of the Superintendents of Police have been advised to attend the meetings of the said Committee unless some unavoidable duty binds them to be away from the headquarters on the day of the meetings ; if so, their names district-wise, together with the designation of the authority that advised the S.Ps in each case ;
- whether any of the S.Ps referred to in para (c) above were on leave or on duty elsewhere on the days of meetings ; if so, the details thereof date-wise and district-wise ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Number of meetings held district-wise and date-wise are as under :—

District	Number of meetings held	Dates
1	2	3
Amritsar	7	4-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Jullundur	8	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 5-10-65, 5-11-65, 5-12-65 and 5-1-66
Hoshiarpur	9	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Gurdaspur	8	5-5-65, 5-6-65, 6-7-65, 5-8-65, 1-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Ferozepur	9	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 5-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Kangra	8	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-11-65, 6-12-65, and 5-1-66
Kulu	8	5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 5-12-65 and 5-1-66

1	2	3
Ludhiana ..	9	7-5-65, 7-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65, and 5-1-66
Kapurthala ..	9	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 6-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Lahaul and Spiti ..	..	District Public Relations and Grievances Committee has not been considered necessary for this district and Punjab Tribes Advisory Council has approved of it
Patiala ..	10	5-4-65, 5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 5-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 5-12-65 and 5-1-66.
Bhatinda ..	9	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 5-9-65, 10-10-65, 5-11-65, 5-12-65 and 5-1-66
Mohindergarh ..	10	2-4-65, 5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Sangrur ..	10	5-4-65, 5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Ambala ..	9	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Rohtak ..	9	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66.
Hissar ..	8	5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Gurgaon ..	7	5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Karnal ..	9	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Simla ..	8	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65 and 6-12-65
(b) Number of meetings attended by the Superintendents of Police district-wise and date-wise are as under : —		
Amritsar ..	1	5-6-65
Jullundur ..	5	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-10-65 and 5-1-66
Hoshiarpur ..	8	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-12-65 and 5-1-66
Gurdaspur ..	6	5-5-65, 5-6-65, 1-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Ferozepur ..	4	5-6-65, 5-7-65, 6-9-65 and 5-1-66
Kangra ..	2	5-6-65 and 5-1-66
Kulu ..	6	5-6-65, 5-7-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65 and 6-12-65
Ludhiana ..	7	7-5-65, 7-6-65, 5-7-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65 and 6-12-65
Kapurthala ..	7	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65 and 5-1-66
Patiala ..	7	5-4-65, 5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65 and 6-12-65
Bhatinda ..	8	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 20-10-65, 5-11-65 and 6-11-65

1	2	3
Mohindergarh ..	6	5-5-65, 5-6-65, 5-8-65, 5-10-65, 5-11-65, 5-12-65
Sangrur ..	6	5-4-65, 5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 6-9-65, and 5-10-65
Ambala ..	9	5-5-65, 5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65, 6-12-65 and 5-1-66
Rohhtak ..	7	5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 6-12-65 and 5-1-66
Hissar ..	6	5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-11-65 and 5-12-65
Gurgaon ..	6	5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65 and 6-12-65
Karnal ...	4	5-5-65, 5-8-65, 6-9-65 and 5-1-66
Simla ..	7	5-6-65, 5-7-65, 5-8-65, 6-9-65, 5-10-65, 5-11-65 and 6-12-65

(c) Some of the Superintendents of Police of districts could not attend the meeting of the District Public Relations and Grievances Committee. Their names together with the meetings date-wise along with reasons for not attending the meetings are given below district-wise :—

District	Name of Superintendent of Police	Dates of meetings not attended together with reasons for not attending
1	2	3
Amritsar	Shri Sukhpal Singh, I.P.S.	5-6-65 S.P. was busy with important and urgent work. He deputed his D.S.P. to attend the meeting
	Shri S.S. Brar, I.P.S.	5-7-65 S.P. was busy with important and urgent work. He deputed his D.S.P. to attend the meeting
		5-8-65 Superintendent of Police was out of station for inspection of border area along with Shri K.S. Rustumji, Director-General, Border Security Force
		5-11-65 He went on duty to Jullundur Cantt in connection with the Punjab Police Sports meeting
		5-12-65 He went to Raja Sanshi in connection with the visit of Chief Minister of Orissa
		5-1-66 S.P. was busy with important and urgent work. He deputed his D.S.P. to attend the meeting
Jullundur	Shri Amar Singh, I.P.S.	5-8-65 S.P. was very busy with the maintaining of law and order situation in the City
		5-11-65 S.P. was busy with the visit of Union Home Minister

1	2	3
	5-12-65	S.P. was busy with the visit of Union Foreign Minister
Hoshiarpur	Shri I.J. Verma, I.P.S.	5-11-65 He was put on duty at Jullundur in connection with the Annual Sports, Athletic Meet of Police Department
Gurdaspur	Shri V.K. Kalia, I.P.S.	6-7-65 He was away from Headquarters in connection with Police arrangements due to the visit of Union Home Minister
	5-8-65	He was away from Headquarters in connection with the visit of Director-General, Border Armed Forces on the border
Ferozepur	Shri P.A. Rosha	5-5-65 S.P. was very busy with his work in connection with Kairon murder case
	6-8-65	S.S.P. was busy in meeting with D.I.G. of Police Border Range
	5-10-65	S.S.P. was busy with the visit of the Chief Minister, U.P. Government
	5-11-65	S.S.P. was busy in the meeting to discuss border security measures with Additional I.G., Police at Jullundur
	5-12-65	S.S.P. was busy with the meeting of SHOs meeting at Abohar
Kangra	Shri Avinash Chander, I.P.S.	5-5-65 S.P. was on leave on medical grounds
	Shri P.C. Wadhwa, I.P.S.	5-7-65 was busy with other important work
	5-8-65	Ditto
	6-9-65	was busy with National Emergency work
	5-11-65	S.P. was away to P.A.P. Headquarters on official duty with State Sports Athletics Meet
	6-12-65	S.P. was away on quarterly visit to T.B. Sanatorium, Tanda to see Police T.B. Patients
Kulu	Shri Joginder Singh I.P.S.,	5-8-65 S.P. was on duty outside Headquarters
	5-1-66	As D.C., Kulu was away from district Headquarters, he deputed District Inspector to participate in the meeting on his behalf
Ludhiana	Shri Harjit Singh, I.P.S.	5-8-65 S.P. was away at Halwara Aerodrome for security arrangements in connection with the visit of Union Food Minister
	5-1-66	S.P. was busy in discussion with D.I.G., Police Jullundur and Patiala in connection with the murder case of Karnail Singh of Gobindpur

1	2	3
Kapurthala	Shri Dalip Singh	6-11-65 } S.P. was on medical leave on these and } dates 9-12-65 }
Patiala	Shri Harjeet Singh, I.P.S.	5-10-65 S.P. was on leave 5-11-65 S.P. was away from headquarters in connection with Punjab Police Sports at Jullundur 5-1-66 S.P. was away from headquarters to Gobindgarh and Ludhiana with D.I.G., Patiala Range in connection with the investigation of murder case of Karnail Singh
Bhatinda	Shri C.K. Sawhney, I.P.S.	5-1-66 S.P. was to go to Police Training School, Phillaur for official work
Mahendergarh	Shri I.J.S. Sodhi, I.P.S.	2-4-65 He was away to Dadri in connection with the Inspection of D.I.G., Patiala Range Shri B.S. Dhaliwal, I.P.S.
		5-7-65 S.P. was indisposed 6-9-65 He was busy in Police arrangements due to Pakistani aggression
Sangrur	Shri M.S. Bawa, I.P.S.	5-8-65 S.P. was out of station in connection with the inspection of police station Julana 5-11-65 He acted as Time-keeper of Police Meet, Jullundur under orders of Additional Inspector-General of Police, Punjab 5-12-65 He was busy with the official work 5-1-66 He was at Jind in connection with Gurdwara dispute and dacoity case
Rohtak	Shri Bahal Singh Sandhu, I.P.S.	5-5-65 He was away from headquarters on and these days in connection with investiga- 5-11-65 tion of Partap Singh Kairon Murder Case
Hissar	Shri Maharaj Krishan Luthra, I.P.S.	5-10-65 He was out of headquarters in connection with the spot inspection of an important murder case 5-1-66 D.C. was away and the meeting was presided by S.D.M. Sirsa as such, it was attended by representative of S.P.
Gurgaon	Shri S.S. Palta, I.P.S.	5-1-66 S.P. was on leave
Karnal	Shri Brijinder Singh, I.P.S.	5-6-65 } S.P. was away from headquarters in 5-7-65 } connection with his of ficial duties of 5-10-65 } important nature 5-11-65 } 6-12-65 }
Simla	Shri K.S. Dhaliwal, I.P.S.	5-5-65 He was sick

(d) According to Government instructions district officers are required to be present in the meetings of the District Public Relations and Grievances Committees. They are required to attend these meetings themselves. No separate instructions specifically for Superintendents of Police were issued.

(e) Details in this respect have already been given in reply to part (c).

### **Awards for Gallantry, etc. to the Military Personnel in the recent Indo-Pak Conflict**

**3091. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total number of military personnel belonging to the Punjab district-wise, who have been awarded Param Vir Chakra, Maha Vir Chakra, Vir Chakra, etc., for displaying gallantry in the recent Indo-Pakistan Conflict, and to whom the State Government has given financial and other awards together with the details of such awards in each case ;
- (b) the total amount distributed by the Punjab Government amongst the relatives of the martyrs, wounded and missing military personnel of the state district-wise and month-wise, from the 1st September, 1965, to-date ;
- (c) the total number of visits paid by the Ministers, district-wise and month-wise, to condole with the war affected families.

**Shri Ram Kishan :** (a) A statement showing the number of military personnel belonging to Punjab who have been awarded gallantry awards in Indo-Pak Conflict is added as Annexure

“A”.

The Punjab Government scheme for the grant of awards to winners of new gallantry decorations” (Param Vir Chakra, Maha Vir Chakra and Vir Chakra) is enclosed as Annexure “B”.

Out of 54 awardees, sanctions have been issued in 23 cases for payment of cash rewards and the Deputy Commissioners have been authorised and requested to make them payments. The reason for delay is that the recipients are required to give an undertaking that they have not received payment of cash reward already (from other States) and an affidavit to the effect that they will be liable to refund the amount if it is found at a later stage that they had received the payment before. In a number of cases, concurrence of Finance Department is awaited, while in the remaining cases, reports are awaited from the Deputy Commissioners regarding the domicile of the decorees.

(b) The requisite information is given in Annexure “C”.

(c) The requisite information is given in Annexure “D”.

#### **ANNEXURE ‘A’**

**Statement showing the number of Military Personnel belonging to Punjab who have been awarded gallantry awards in Indo-Pak Conflict**

District	Paramvir Chakra	Mahavir Chakra	Vir Chakra
Amritsar	..	1	2
Jullundur	..	2	5
Hoshiarpur	..	1	3

District	Paramvir Chakra	Mahavir Chakra	Vir Chakra
Kangra	..	1	5
Ferozepur	..	4	2
Ludhiana	..	1	3
Rohtak	..	3	1
Gurdaspur	..	1	2
Ambala	..	..	5
Hissar	..	..	3
Gurgaon	..	..	1
Sangrur	..	..	3
Bhatinda	..	..	2
Mohindergarh	..	..	2
Karnal	..	..	1
Total	..	14	40

## ANNEXURE "B"

## Revised scheme for the grant of rewards to winners of new gallantry decoration by the Punjab Government

The Punjab Government have revised the scale of rewards for the New gallantry awards, namely, the Param Vir Chakra, the Maha Vir Chakra and the Vir Chakra, for the grant of rewards for the decorations recognised from 15th August, 1947.

## 2. Conditions :—

- (a) Rewards will be made to Punjabi Servicemen.
- (b) All ranks in the Army, Navy and the Air Force are eligible.
- (c) The recipients of gallantry awards will ordinarily be rewarded on the following scales :—

Name of decoration	Amount of reward
(i) Param Vir Chakra	.. Rs 10,000 plus Rs 500 annuity for 30 years, the annuity should be made applicable for the service-mens' life and the life of his widow (if the decoree has earned posthumously or if the decoree dies before his wife) or for 30 years which ever is longer
(ii) Maha Vir Chakra	.. Rs 7,500.
(iii) Vir Chakra	.. Rs 3,000.

These revised scales are applicable to the decorees of Congo, Nefa and Ladakh areas as well as all future decorees or gallantry award winners.

(d) A recipient of these gallantry awards shall be entitled to half the amount of the cash reward for the first fresh award or bar as the case may be, won subsequently, but the winning of any subsequent awards or bars shall not entitle him to any other reward.

(e) In case of posthumous awards, the persons eligible for the rewards will be the heirs in the following orders :—

- (i) Male lineal descendant of the deceased in the line of descent.
- (ii) Widow of the deceased, if she is not re-married.
- (iii) Unmarried daughters.
- (iv) Successor or successors nominated by the Punjab Government from among deceased's father, his mother, married daughter, his daughter's son, sister, his sister's son and the male agnate members of his family.

#### ANNEXURE "C"

Statement showing the ex gratia grants, etc., distributed amongst the relatives of Martyrs/missing military personnel from 1st September, 1966 to 31st January, 1966

District		September, 1965	October, 1965	November, 1965	December, 1965	January, 1966	Total
Kangra	..	..	1,000	45,750	36,250	9,000	92,000
Narnaul	..	6,000	15,000	16,250	2,500	500	40,250
Simla	..	..	500	..	..	500	1,000
Gurdaspur	..	2,500	23,000	23,000	4,000	3,000	55,500
Ludhiana	..	..	24,700	24,500	..	18,000	67,200
Rohtak	..	..	29,500	15,500	5,000	9,000	59,000
Sangrur	..	2,000	9,000	13,000	3,500	1,000	28,500
Ferozepur	..	..	12,000	10,600	7,060	500	30,160
Patiala	..	..	5,000	14,500	3,000	7,500	30,000
Jullundur	..	2,000	49,000	27,000	11,000	1,000	90,000
Hoshiarpur	..	..	43,500	24,000	15,520	13,620	96,640
Hissar	..	1,500	6,500	2,500	6,000	3,500	20,000
Bhatinda	..	..	15,000	5,000	1,000	2,000	23,000
Kulu	..	..	..	..	2,500	3,000	5,500
Karnal	..	1,000	22,250	5,000	2,500	2,000	32,750
Ambala	..	3,000	26,500	15,000	11,000	..	55,500
Amritsar	..	..	..	11,300	38,300	8,800	58,430
Lahaul and Spiti	..	..	..	..	..	..	..
Kapurthala	..	3,500	3,500	6,560	1,480	500	15,540
Gurgaon	..	..	..	28,500	..	..	28,500

xiii  
ANNEXURE 'D'

Month	Name of District	Total number of visits paid by Ministers (excluding Chief Parliamentary Secretary) to condole with the war affected families
S eptember, 1965	.. Amritsar ..	1
	.. Ambala ..	1
	.. Karnal ..	1
	.. Ferozepur ..	2
	.. Mohindergarh ..	1
O ctober, 1965	.. Jullundur ..	2
	.. Ludhiana ..	3
	.. Ferozepur ..	1
	.. Patiala ..	1
	.. Hoshiarpur ..	3
N ovement, 1965	.. Patiala ..	2
	.. Hoshiarpur ..	1
D ecember, 1965	.. Rohtak ..	5
	.. Hoshiarpur ..	1
J a nuary, 1966	.. Rohtak ..	2
	Total ..	27

**Agricultural and Seed Farms in the State**

**3098. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the total number of Agricultural and Seed Farms, separately, in the State at present ;
- (b) the amount spent on each of the said Farms including the expenditure incurred on (i) salaries and allowances of the staff, (ii) seeds and fertilizers and (iii) all other agricultural activities during the period from 1961-62 to 1965-66 (to-date), year wise ;
- (c) the amount of profit earned or loss incurred by each such Farm during the said period, year-wise ?

**Subject:—** Vidhan Sabha Question No. 3098 (Unstarred) regarding Agricultural and Seed Farms.

The answer to Vidhan Sabha Question No. 3098 appearing in the list of unstarred Question to be asked at the meeting of the Punjab Vidhan Sabha to be held on the 16th February, 1966, in the name of Comrade Ram Chandra, M.L.A., is not ready. The reply will be sent as soon as the necessary information is collected.

Sd/-  
Home and Development  
Minister, Punjab.

To

The Speaker,  
Punjab Vidhan Sabha,  
Chandigarh.

U.O. No. 879-Agr.II(X)-66/769, Chandigarh, dated 15th February, 1966.

### Drought in the State

**3113. Comrade Makhan Singh Tarsikka. :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

- (a) whether it is a fact that there was drought in the whole state in November, and December, 1965 and January, 1966, if so, the nature of the revenue report, if any, received in this connection by the Government, districtwise ;
- (b) the details of the steps being taken by the Government to give relief to the people tehsilwise and regionwise ;
- (c) whether he is aware of the fact that there is no work for the labourers in the Haryana area who are migrating to other areas in search of work ; if so, the steps proposed to be taken to check this migration ?

**Sardar Harinder Singh, Major :** (a) scarcity conditions due to failure of monsoons first arose in the districts of Rohtak, Hissar and Mahendragarh only. Later, because of the failure of early winter rains scarcity conditions developed all over the State. Results of the special girdawari conducted by Deputy Commissioners in the month of February, 1966 are given in the attached statement.

- (b) Particulars of relief sanctioned are given below :—
- (I) Remission of land revenue has been allowed in all areas affected by drought in the State on the following scale :—
  - (i) Where the damage was more than 50 percent Total remission
  - (ii) Where the damage was below 50 per cent but more than 25 per cent —75 per cent remission
- (II) Recovery of taccavi loans has been suspended till Rabi 1966 in such areas.
- (III) Relief work

<i>Hissar District</i>		<i>Amount sanctioned</i>	
<i>Item</i>		<i>Rs</i>	
(1) Earth work on roads	..	15,000,00	
(i) Bhiwani tahsil	..	6,82,000	
(ii) Hissar tahsil	..	5,40,000	
(iii) Hansi tahsil	..	1,20,000	
(iv) Sirsa tahsil	..	1,51,118	
Total	..	14,93,118	
(2) Digging of johars	..	5,00,000	
(i) Bhiwani tahsil	..	2,00,000	
(ii) Hissar tahsil	..	2,00,000	
(iii) Sirsa Tahsil	..	25,000	
(iv) Fatehabad tahsil	..	75,000	
Total	..	5,00,000	
(3) Lift Irrigation Schemes	..	Rs 48,58,000	
(i) Bhiwani tansil	..	2/3rd of this amount.	
(ii) Hissar, Hansi and Sirsa tahsils	..	1/3rd of this amount	

(4) Soil Conservation Works .. Rs 10,00,000

(i) Hissar tahsil .. Rs 5,00,000  
(ii) Bhiwani tahsil .. Rs 5,00,000

Total .. 10,00,000

(5) Water Supply Scheme .. Rs 8,50,000

(as share of villagers)

In Bhiwani tahsil only. This scheme will cost Rs 70.95 lacs and serve 62 villages of Bhiwani tahsil.

#### Rohtak District

<i>Item</i>	<i>Amount sanctioned</i>
(1) Local Relief Works in Jhajjar tahsil	.. Rs 5,00,000

#### Mahendragarh District

<i>Item</i>	<i>Amount sanctioned</i>
(1) Earth work on roads	.. Rs 6,25,000
(2) Local Relief Works	.. Rs 15,00,000

The above amounts are being utilized in Mahendragarh Sub-Division i.e., in Dadri and Mahendragarh tahsils.

#### Hoshiarpur District

(1) Relief Works .. Rs 10,00,000  
For Una tahsil and the Kandi area of Garhshanker tahsil.

#### (IV) OTHER RELIEF

##### Hissar District

<i>Item</i>	<i>Amount sanctioned</i>
(1) Subsidy for fodder	.. Rs 1,75,000
	Rs
(i) Bhiwani Tahsil	.. 1,25,000
(ii) Hissar tahsil	.. 50,000
Total	.. 1,75,000

(2) Taccavi loans for purchase of fodder and seed .. Rs 21,00,000

	<i>Fodder</i>	<i>Seed</i>
	Rs	Rs
(i) Bhiwani tahsil	.. 8,25,000	2,50,000
(ii) Hansi Tahsil	.. 2,00,000	
(iii) Hissar tahsil	.. 3,25,000	
(iv) Fatehabad tahsil	.. 3,00,000	
(v) Sirsa tahsil	.. 2,00,000	
Total	.. 18,50,000	2,50,000

(3) Highest priority to be given to village water supply scheme and rural electrification.

(4) Recruiting centre to be opened in Hissar District.

- (5) Fodder depots .. 35 fodder depots are functioning  
 (i) Bhiwani tahsil .. 29 where the fodder is sold at subsidi-  
 (ii) Hissar tahsil .. 6 zed rates

Total .. 35

- (6) Fair Price Shops .. 116 fair price shops are function-  
 ing

- (i) Bhiwani tahsil .. 61  
 (ii) Hansi tahsil .. 29  
 (iii) Hissar tahsil .. 10  
 (iv) Fatehabad tahsil .. 6  
 (v) Sirsa tahsil .. 10

Total .. 116

- (7) Amenities provided in Bhiwani tahsil

- (i) Dhotis .. 44  
 (ii) Shirts of Mazri cloth .. 25  
 (iii) Shirt Mazri .. 14  
 (iv) Sweet shirts .. 24  
 (v) Khes .. 46  
 (vi) Shirting cloth .. 98 pieces  
 (vii) Ribbed ves Cloth .. 71 pieces  
 (viii) Woollen jackets .. 32  
 (ix) Night pyjama suits .. 25  
 (x) Bed sneets .. 77  
 (xi) Woollen blankets .. 49  
 (xii) Vests cotton flanna-  
 lettees .. 52  
 (xiii) Mazri cloth .. 45 pieces

#### Rohtak District

- | <i>Item</i>   | <i>Amount sanctioned</i> |
|---|--------------------------|
| (1) Taccavi loans for purchase of fodder in Jhajjar Tahsil    | .. Rs 2, 50,000          |
| (2) Fair Price Shops have also been opned. in Jhajjar tahsil. |                          |

#### Mahendragarh District

- | <i>Item</i>                          | <i>Amount sanctioned</i> |
|--------------------------------------|--------------------------|
| (1) Taccavi for percolation wells .. | Rs 5,00,000              |
| (i) Mahendragarh tahsil ..           | Rs 1,75,000              |
| (ii) Dadri tahsil ..                 | Rs 3,25,000              |
| Total ..                             | Rs 5,00,000              |

#### Hoshiarpur District

- | <i>Item</i>                                       | <i>Amount sanctioned</i> |
|---|--------------------------|
|   | Rs                       |
| (1) Taccavi loans for fodder ..                   | 3,00,000                 |
| (2) Taccavi loans for seed ..                     | 1,00,000                 |
| Rs two lacs each for Garnshanker and Una Tahsils. |                          |
| (c) There is no such migration                    |                          |

## STATEMENT NO. I

Statement showing the damage caused to Rabi crops by drought in the State

Serial Name of No. district	No. of villages in the district	Name of Tahsil	Total No. of villages in the Tahsil	No. of villages where damage caused to crops is 25% to 49%	No. of villages where the age damage caused to crops is 50% to 74%	No. of villages where the age damage caused to crops is 75 %to 100 %	Total area affected in quintals	Produce damaged in quintals	Value in Rs	REMARKS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gurgaon ..	1,586	Palwal ..	197	181	8	4	4	2,187	6,561	3,28,050	
			Ballabgarh ..	206	43	88	75	—	31,312	93,936	46,96,800	
			Gurgaon ..	226	61	114	49	2	55,648	1,66,955	83,47,921	
			Nuh ..	289	247	24	14	4	8,413	25,239	12,61,950	
			Ferozepur Jhirka ..	242	132	96	14	..	21,113	63,339	31,66,950	
			Rewari ..	426	300	96	22	8	37,253	1,11,759	55,87,950	
			Total ..	1,586	964	426	178	18	1,55,926	4,67,789	2,33,89,621	
2	Rohtak ..	806	Rohtak ..	133	93	40	..	..	46,783	1,47,319	93,17,455	
			Gohana ..	123	37	86	..	..	77,509	2,62,483	1,67,64,179	
			Sonepat ..	241	202	35	4	..	30,080	1,03,287	66,68,261	
			Jhajjar ..	309	121	72	101	15	84,418	2,53,000	1,62,05,497	
			Total ..	806	453	233	105	15	2,38,790	7,66,089	4,89,55,329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
3	Ambala ..	2,696	Ambala ..	325	3	42	190	88	69,761	1,67,742	83,87,100
	Jagadhri ..			493	28	104	126	230	51,307	1,36,392	66,22,822
	Naraingarh ..			334	..	..	..	334	66,911	1,55,532	1,02,75,305
	Kharar ..			489	2	25	90	362	71,153	2,05,774	1,02,98,966
	Rupar ..			386	104	124	79	79	21,293	58,396	33,66,624
	Nalagarh ..			669	..	5	29	597	28,613	1,97,831	52,36,131
	Total ..			2,696	137	300	514	1,690	3,09,038	9,21,637	4,41,86,948
4	Karnal ..	1,427	Karnal ..	422	112	113	162	35	1,02,644	4,10,576	2,05,28,800
	Panipat ..			185	130	51	4	..	33,750	1,35,000	67,50,000
	Thanesar ..			429	248	170	11	..	38,773	1,55,092	77,54,600
	Kaithal ..			220	9	133	70	8	1,11,259	4,45,036	2,22,51,800
	Guhla ..			171	52	119	..	..	20,267	81,068	40,53,400
	Total ..			1,427	551	586	247	43	3,06,693	12,26,772	6,13,38,600
5	Simla ..	1,081	Kandaghat ..	1,052	24	..	241	811	16,053	36,644	21,67,616
	Simla ..			29	..	..	21	8	78	8	15,680
	Total ..			1,081	24	..	262	819	16,131	36,652	21,83,296
6	Sangrur ..	1,039	Sangrur ..	300	261	24	14	..	48,143	1,75,005	1,03,45,749
	Barnala ..			142	90	52	..	..	68,654	2,06,406	1,23,60,672
	Malerkotla ..			296	139	..	..	..	2,176	7,934	5,82,020

Area which remained unsown in acres 1,75,734.

Narwana ..	136	35	..	..	..	5,456	32,736	16,36,800
Jind ..	165	146	13	6	..	19,135	76,540	45,92,400
Total ..	1,039	671	89	20	..	1,43,564	4,98,621	2,95,17,641
7 Patiala ..	1,497	501	46	271	173	11	91,820	4,54,947
Nabha	272	272	..	..	..	3,238	15,310	9,32,320
Sarhind ..	298	262	26	10	..	17,583	60,899	35,59,449
Rajpura ..	426	20	91	163	152	1,49,191	4,72,615	1,72,77,481
Total ..	1,497	600	388	346	163	2,61,832	10,03,771	4,67,14,988
8 Bhatinda ..	694	275	275	..	..	2,11,853	1,05,926	52,96,300
Mansa ..	249	249	..	..	..	65,101	1,30,202	75,51,716
Faridkot	170	170	..	..	..	22,797	46,174	24,26,150
Total ..	694	694	..	..	..	2,99,751	2,82,302	1,52,74,166
9 Mohendergarh ..	559	222	..	111	83	28	55,873	3,45,782
Narnaul	156	..	..	..	6	150	35,795	1,43,180
Mahendergarh	181	..	..	..	62	119	93,371	4,35,602
Dadri ..	559	..	111	151	297	1,85,039	9,24,564	5,06,63,251
Total ..	559	..	111	151	297	1,85,039	9,24,564	5,06,63,251
10 Kapurthala..	701	585	257	..	..	..	6,144	12,288
Kapurthala..	116	97	..	..	..	..	1,015	2,030
Phagwara	701	354	..	..	..	..	7,159	14,318
Total ..	701	354	..	..	..	..	7,159	14,318
11 Ludhiana ..	1,004	489	..	..	..	118	10,091	30,273
Ludhiana ..	340	23	4	11	90	16,107	48,321	24,16,050
Samrala ..	340	23	4	11	90	16,107	48,321	24,16,050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jagraon ..	175	11	4	22	3	7,344	22,032	11,01,600	
			Total ..	1,004	34	8	33	211	33,542	1,00,626	50,31,300	
12	Ferozepore	1,567	Muktsar ..	237	112	..	..	..	51,488	25,744	15,44,640	
			Fazilka ..	315	315	..	..	..	46,500	17,915	10,84,775	
			Moga ..	181	72	..	..	..	9,791	4,895	2,69,252	
			Zira ..	363	117	150	60	10	71,898	1,43,796	71,89,800	
			Ferozepore	471	285	..	..	..	27,563	13,781	8,26,860	
			Total ..	1,567	901	150	60	10	2,07,240	2,06,131	1,69,15,327	
13	Jullundur ..	1,320	Jullundur ..	433	131	12	11	3	5,572	18,259	7,70,440	
			Nakodar ..	353	..	..	..	..	..	..	..	
			Phillaur ..	242	214	28	..	..	11,735	14,672	8,80,320	
			Nawanshahar	292	290	..	..	..	25,000	1,000	60,000	
			Total ..	1,320	635	40	11	3	42,307	33,931	17,10,760	
14	Amritsar	1,276	Ajnala ..	347	125	101	65	56	61,460	2,45,840	98,33,600	
			Amritsar ..	389	367	..	..	..	14,468	14,648	7,32,400	
			Tarn Taran	340	..	..	..	..	..	..	..	
			Patti ..	200	..	..	..	..	..	..	..	
			Total ..	1,276	492	101	65	56	75,928	2,60,488	1,05,66,000	
15	Hoshiarpur	2,204	Hoshiarpur	527	12	128	131	253	1,18,908	3,56,724	1,78,36,200	
			Una ..	532	..	..	63	469	94,549	2,83,647	17,01,882	
			Dasuya ..	649	141	172	81	241	1,08,174	2,59,971	1,68,98,115	

Garhshankar	496	103	56	90	247	1,07,306	1,03,001	51,98,900	
Total ..	2,204	256	356	365	1,210	4,28,937	10,03,343	4,16,35,097	
16 Kangra .. 651 Nurpur	195/847	..	..	..	847	56,609	91,214	46,09,546	Damage has been given in tikkas instead of villages
Hamirpur ..	64/1982	..	..	104	1,767	89,381	1,79,791	1,21,50,466	
Palampur	113/1151	1	2	485	636	52,831	1,43,298	1,01,69,110	
Dehra ..	145/1241	..	..	..	1,231	65,179	1,54,370	95,46,311	
Kangra ..	134/1029	189	194	52	525	24,546	1,19,192	77,55,912	
Total ..	651/6250	190	196	641	5,006	2,88,546	6,87,865	4,42,31,345	
17 Hissar .. 1,068 Bhiwani	208	2	5	21	180	1,82,609	1,74,523	1,13,43,995	Area unsown due to drought in acres—6,02,011
Hansi ..	138	52	44	28	14	67,834	4,52,819	3,15,07,715	
Hissar ..	218	99	48	37	34	60,100	2,96,346	1,48,17,300	
Fatehabad	179	9	86	73	11	1,17,266	3,75,642	2,42,33,092	
Sirsa ..	325	121	73	101	30	1,85,082	7,40,328	4,44,19,680	
Total ..	1,068	283	256	260	269	6,12,891	20,39,658	12,63,21,782	
18 Gurdaspur .. 1,617 Batala	495	74	269	120	27	73,144	292,576	1,09,71,600	No crop was sown in 5 villages of Batala tehsil and 3 villages of Gurdaspur Tehsil
Gurdaspur	699	4	62	174	456	1,37,932	6,25,873	3,04,98,808	
Pathankot ..	423	..	..	8	415	14,612	2,61,863	12,78,505	
Total ..	1,617	78	331	302	898	2,25,688	11,80,312	4,27,48,913	
19 Kulu .. 170 Kulu	83	..	49	34	..	14,809	41,539	24,07,318	
Sub-Tehsil—Banjar ..	44	21	23	..	..	4,607	10,984	7,04,521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub-Tehsil	Ani	..	16	5	11	..	..	4,160	10,164	6,52,722	
	Sub-Tehsil	Nirmand		27	3	24	..	..	5,222	11,919	7,98,139	
	Total	..		170	29	107	34	..	28,798	74,606	45,62,700	
20	Lahaul and Spiti	Nil										
	Grand Total			28,562	7,346	3,678	3,594	10,708	38,67,800	1,17,29,475	61,05,40,147	

### Admission in various Medical Colleges

**3114. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) the number ; names and home addresses of students, district-wise, admitted in the Medical Colleges at Ludhiana, Patiala, Rohtak and Amritsar in 1964-65 and 1965-66 sessions, separately;
- (b) the number , names and addresses of students recommended by the Government every year since 1962 for admission in the Medical Colleges at Ludhiana and at Srinagar, respectively?

*Subject.*—Admission in Various Medical Colleges.

The answer to Assembly Question No. 3114 appearing in the list of Unstarred Questions for the 16th February, 1966 in the name of Comrade Makhan Singh Tarsikka, M.L.A. is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.,

(Sd) . . . . ,  
Health Minister, Punjab.

To,  
Secretary,  
Punjab Vidhan Sabha,  
Chandigarh.

U.O. No. 1166-IHBIV-66, dated Chandigarh, the 15th February, 1966.

### Industrial Training Centres in Amritsar

**3118. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the location of each of the Industrial Training Centres functioning at present in Amritsar District?
- (b) the total number of persons trained in each of the said centres trade-wise and year-wise, since the inception of these Centres;
- (c) the number of those, referred to in part (b) above centre-wise, who started work in the Industry or trade in which they received training

*Subject :—*Unstarred Assembly Question No. 3118 Asked by Comrade Makhan Singh Tarsikka, M. L. A.

The answer to the Unstarred Assembly Question No. 3118, appearing in the list of Unstarred Questions on 16th February, 1966, in the name of Comrade Makhan Singh Tarsikka, M. L. A. is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

(Sd.) . . . . ,  
Chief Minister,  
Punjab.

To

The Secretary,  
Punjab Vidhan Sabha,  
Chandigarh.

U. O. No. 1552-51BII-66, dated Chandigarh, the 14th/15th February, 1966.

1552-51BII-66, dated Chandigarh, the 14th/15th February, 1966.

**Assessment of surplus area in village Sithana, tehsil Panipat, District Karnal**

**3126. Comrade Ram Piara:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- (a) the names of landowners of village Sithana, tehsil Panipat, district Karnal who owned more than 30 standard acres of land as on 1st April, 1949, together with the area of each which has been declared surplus;
- (b) the dates when the work of assessment of surplus areas was started and finalised in the said village.

**Sardar Harinder Singh Major :** (a) None.

(b) (i) 15th December, 1964.

(ii) 21st April, 1966. ..



**"C" 1966**

Published under the authority of the Punjab Vidhan Sabha and  
printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab, Chandigarh.

# Punjab Vidhan Sabha Debates

17th February, 1966

Vol. I—No. 3

OFFICIAL REPORT



## CONTENTS

Thursday, the 17th February, 1966

	<i>Page</i>
Starred Questions and Answers	(3)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	... (3)19
Unstarred Questions and Answers	... (3)50
Adjournment Motions /Call Attention Notices	... (3)146
Papers laid on the Table	...
Report of the Haryana Development Committee	... (3)149
Resolutions—	
<i>Re. Lease of Land to Birla Brothers (Withdrawn)</i>	... (3)150
<i>Re. Allocation of 60 per cent of the Budget for Haryana and Hilly Areas.</i>	... (3)167—194
Appendix	.. i—iv



*E R R A T A*  
TO  
PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 3,  
DATED THE 17TH FEBRUARY, 1966

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ	ਪ੍ਰਾਇੰਟ ਆਫ	(3)3	8 from below
interim	iterim	(3)4	11
thing	h ng	(3)4	12
ਜ਼ਰੂਰਤ	ਜ਼ਰਰਤ	(3)9	14
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰ	(3)9	27
grievances	greivances	(3)13	40
ਕੀ	ਕਿ	(3)15	23
ਏਰੀਆ	ਏਸੀਆ	(3)15	25
ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ	ਕਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ	(3)16	22
इन्स्टालमेंट्स	इंस्टालमेंट्स	(3)17	25
ਰਿਪੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ	ਰੀਪੀਜ਼ੈਂਸ਼ਨ	(3)17	36
Therefore	Therefor	(3)18	4
Rajpura	Rapura	(3)20	7
Kot Kapura	Kat Kapura	(3)21	18 from below
commi-	commit-	(3)21	Last but one
Chaudhri Rizaq Ram	Chaudhri Rizaq Rom	(3)23	4 from below
cases	cass	(3)27	5
Gazette	Gazettee	(3)27	25
lapsed	lapsed	(3)28	19
brick kiln	brick)	(3)29	9 from below
brick-field	brickr-field	(3)32	22

P. T. O.

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
Singh	{ S ngn [ Sng	{ (3)42 [ (3)64	5 from below 11
Partap Singh	Par ap S ngh	(3)43	17
son	so	(3)45	8 from below
amount	ammount	(3)46	7 from below
subsidy	sub dy	(3)47	1
12	82	(3)48	S. No. 12
above	ahove	(3)50	29
vouchsafed	vonchsafed	(3)51	5 from below
volunteer	volunter	(3)52	3
contributions	cntributins	(3)52	5 from below
पुलिस	पुसिल	(3)53	17
कसमनुर्सी	कसमनुर्बी	(3)55	8
है	ई	(3)55	11
हकूमत का	हकूमत	(3)55	15
आई	माई	(3)57	11
महूरुम	महरूप	(3)57	18
मकान	माकन	(3)57	23
नामजद	मादजद	(3)58	3
तर्कफेल	तर्कफेल	(3)58	8
Development	Devekopment	(3)60	15
loanees	loan	(3)64	2
applicants	application	(3)66	2
present	pesent	(3)72	6 from below
Varpal	Vapal	(3)75	10 from below
school at	school	(3)76	9
Amritsar	fflmritsar	(3)76	13 from below
conditions	contidions	(3)78	16

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
Panipat	Pauipat	(3)88	4
Ludhiana	Luuuhiana	(3)90	17
Niranjan Singh	B Niranjan Singh	(3)93	14
Governor	Goverhor	(3)96	7
Secretary's	Sectetary's	(3)97	16 from below
Under Winding	unde inding	(3)103	32
Sangrana	Sang ana	(3)108	17
Saquinwali	Sa quanwali	(3)113	10
production	roduction	(3)115	15
Brick	Birck	(3)117	4 from below
Harbhaj Singh	Harhbaj Singh	(3)127	S. No. 22, col. 2
being a	being	(3)128	S. No. 12. col. 4
authorities	authories	(3)139	last but one
ਮੈਮੋਰੀਅਲ	ਮੈਮੋਸੀਅਲ	(3)146	5 and 6 from below
Sardar Ajaib Singh	Sardar Ajab Singh	(3)152	25
ਮੈਂਬਰ ਦੀ	ਮੈਂਬਰ	(3)161	7
leave	ieave	(3)162	1
which	whlch	(3)164	10 from below
ਏਕਸਪਂਜ	ਏਕਸਪਂਚ	(3)167	21
इलैक्ट्रीफाईड	इलैक्रिटफाईड	(3)168	5 from below
ਸੇਂ ਨੇ	ਸੇਂ	(3)170	7
श्री बलरामजी दास	श्री बलारमजी दास	(3)172	20
टंडन	टंडन		
लाज़मी	लाज़नी	(3)172	21
फलड	फलड	(3)172	9 from below
मुसीबत	बु ीबत	(3)173	5
give	given	(3)173	26

P.T.O.

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
किसी	किस	(3)174	7
करूंगी	करूंग	(3)174	8 from below
हिंदू-	हिंदू-	(3)175	15
चात	चात	(3)177	last
दे सकते हैं	सकते हैं	(3)180	16
फी सदी	फीसवी	(3)182	15
हरियाणा	हरियाणा	(3)182	15
यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी	(3)187	9
श्री बलरामजी दास	श्री बलरामजी दास	(3)188	last
एशोरेंसिज	एशारेसिज	(3)189	21
डिस्प्लेड	डिस्पलेन्ज	(3)190	5 from below

S  
ii

v

# PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 17th February, 1966

*The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 9.30 A.M. of the Clock Mr. Speaker (Shri Harbans in the Chair.*

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### Report of the Haryana Development Committee

**\*8840. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether Government has received the report of the Haryana Development Committee ;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the recommendations made in the said Report have been accepted in toto or partially ;
- (c) whether any schemes based on the said recommendations have been incorporated in the Fourth Five-Year Plan for implementation in the first year of the said Plan, if so, the details of such schemes ?

**Sardar Ajmer Singh (Planning and Local Government Minister) :** (a) yes, on 27th January, 1966.

(b) and (c) The recommendations made by the Committee are under consideration.

**श्री मंगल सैन :** क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा डिवेलपमेंट कमिटी ने जो रिपोर्ट पेश की क्या उस की सिफारिशों को लागू करने के लिए इस सेशन में पेश किये जाने वाले बजट में जरूरी प्रबन्ध किये जाएंगे ?

**Minister :** Mr. Speaker, this question can only be answered after the Report has been thoroughly examined. The recommendations are being looked into by the Administrative Secretary and the Planning Secretary who have been directed to study and examine them. After that the matter will be put up before the Cabinet and a decision will be taken. The question of enforcement will arise only after that. We will not lose any time in taking the decision.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** May I ask the Planning Minister as to how long the Government will take to consider the report ?

**Minister :** I have already stated that no time will be lost but at the same time no dead line can be fixed.

**श्री मंगल सैन :** इन्होंने अभी कहा कि इस कमिटी पर गौर करने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रेटरी फिनांस सैक्रेटरी रैवन्यू सैक्रेटरी और गैरा की एक कमिटी बनाई जाएगी।

[श्री मंगल सैन]

मैं इन से डीफीनिटली यह बात पूछना चाहता हूँ कि उस कमेटी की सिफारिशात पर गौर कर के कब तक उन को चौथी प्लैन के अन्दर या इस बजट के अन्दर शामिल कर दिया जायगा ?

**Minister** . I have already answered this question.

**मुख्य मन्त्री** स्पीकर साहिब, हरियाणा डिवैलपमेंट कमेटी की सिफारिशात के बारे में जो ऐंग्जाइटी मੈम्बर साहिबान के अन्दर पाई जाती है उसे हम भी अच्छी तरह से महसूस करते हैं । गवर्नमेंट ने जब यह कमेटी बनाई थी तो इसी वजह से बनाई थी । इन साहिबान को इस बात का इल्म होजाना चाहिए कि सरकार की यह खाहिश है कि हरियाणा की डिवैलपमेंट की तरफ और इस की बैकवर्डनेस को दूर करने की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए । यह ध्यान दिया जा रहा है और आयादा भी दिया जायगा । हाउस को मालूम है कि अभी दो हफते पहले ही इस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आई है और हम इस को कन्सिडर कर रहे हैं । उस के बाद यह कैबिनेट के सामने आयेगी जिस ने यह कमेटी बनाई थी । हमारी खाहिश है कि इस के सारे पहलुओं पर गौर करके इस पर अमल किया जाए । मगर इस से पहले इस के सारे आसपैक्टस फिनांशल इम्प्लीकेशन्स दगैरह के बारे में देखने होंगे मगर मैं यह आप को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस नेक नियती से हम ने यह कमेटी ऐप्वायंट की थी उसी नेकनियती से इस पर जल्दी से जल्दी अमल भी करना चाहते हैं । आप यह बात देखें कि सारे हिन्दोस्तान में और अपने सूबे में भी किसी भी कमेटी के सिलसिले में इतनी तेजी से काम नहीं हुआ जितना इस के बारे में हुआ है । हम चाहते हैं कि हरियाणा की डिवैलपमेंट जल्द से जल्द हो और इस पर हम अपने रिसोसिज के मुताबिक जल्द से जल्द गौर करेंगे ।

**Shri Ram Saran Chand Mital** : May I know from the Government whether it is a fact that the Haryana Development Committee submitted an interim report long ago ; if so, when it was submitted and whether its recommendations were considered and further whether any of the recommendations of that interim report have been incorporated in the Budget which will be presented to this House in this Session ?

**Minister** : The interim report was considered and the decision was taken but without final report no steps could be taken to implement any thing.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ** : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਗ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗੇਗਾ ?

**ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਵਰੂਪ** : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ यह है कि हरियाणा डीवैलपमेंट कमेटी को कब अमल में लाया जायगा (विघ्न) उस की सिफारिशात को ?

**श्री अध्यक्ष** : यह सवाल भी आ चुका और जवाब भी आ चुका है । (This question has already been asked and reply given.)

**मुख्य मन्त्री :** चौधरी साहिब, हरियाणा डिवेलपमेंट कमिटी तो खरम हो गई उस पर क्या अमल होगा ।

**चौधरी राम स्वरूप :** मैं किलीयर नहीं कर सका या यह समझ नहीं सके ।

**श्री अध्यक्ष :** बाद में किलीयर कर लें । (The hon. Member may clarify later on.)

**कामरेड राम प्यारा :** मैं इन से यह पूछना चाहता हूँ कि इस कमिटी की रिपोर्ट को कब पब्लिक में लाया जाएगा और कब इस सदन की टेबल पर रखा जायगा ?

**Minister :** Yesterday I have already placed a copy of it on the Table of the House in the Legislative Council. We are not going to keep it back. It will be placed here if it is desired.

Sir, for the information of my hon. friends I would say that the Haryana Development Committee has made a report that certain percentage of budget allocation on the Plan schemes should be spent in the Haryana area or Hindi Region. Now for that purpose it is very necessary to find out as to how much, under the present allocation, is being spent by the various departments on the Hindi and the Punjabi Regions. This has to be found out first. Now there are two types of schemes breakable schemes and unbreakable schemes. In the case of breakable schemes, of course, we can find out sooner but in the case of unbreakable schemes it has to be worked out. So we have first to find out as to how much is actually being spent at present on the Hindi Region and the Punjabi Region and then the Government will take a decision keeping in view its financial resources and the recommendations of the Haryana Development Committee.

**Mr. Speaker :** I feel rather surprised that a document which is placed on the table of one House is not placed on the table of the other House and the Government is waiting for the demand from the hon. Members. I hope this House will not be treated in that way. I expect that a document which is placed on the table of one House is simultaneously placed on the table of the other House.

**Minister :** Sir, as I have already stated we are not keeping it back. It shall be placed today.

**Mr. Speaker :** But it should have been placed on the table of the House on the same day.

**श्री बलरामजी दास टंडन :** स्पीकर साहिब, मेरा प्वाइंट आप आर्डर है, इस के बारे में आप ने अभी फरमाया है कि यह रिपोर्ट जो पहले इस हाउस में नहीं रखी गई कौंसिल में रखे जाने के साथ साइमलटेनिसली यहां रखी जानी चाहिए थी । जिस दिन वहां पर रखी गई उसी दिन यहां पर रखी जानी चाहिए थी । ऐसा नहीं किया गया और यह एक बहुत सिरियस बात है और यह इस हाउस का प्वाइंट आफ प्रिविलिज है कि गवर्नमेंट के नुकतानिगाह से या मिनिस्टर साहिब के नुकता निगाह से यह जरूरी नहीं समझा गया कि इस हाउस में कापी ले की जाए । और इस बात को बैट किया गया कि इस हाउस के मेम्बर साहिबान इस बात की मांग करेंगे तो

[श्री बलरामजी दास टंडन]

इस को हाउस की टेबल पर ले किया जाए । और दूसरी तरफ इसको फैंक्टो कापी ले कर दी गई । मैं प्राप का इस प्वायंट आफ प्रिविलिज पर रूलिंग चाहता हूँ । इस के बारे में ऐक्शन लेना चाहिए ।

**Mr. Speaker :** I have already made my observations.

**Minister :** Sir, I have already said that it will be done to day.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, the hon. Minister for Planning and Local Government in reply to the supplementary question of the hon. Member Shri Ram Saran Chand Mital has said that the Government was waiting for the final Report of the Haryana Development Committee. May I ask him as to what was the utility of the interim Report ? What action has been taken on the interim Report and whether anything has been included in the Budget as a result of the recommendations of the Committee ?

**मुख्य मन्त्री :** मैंने आगे भी अर्ज किया है और अब फिर बजाह्त कर देना चाहता हूँ कि इतने गुस्से से काम नहीं चलेगा । अभी दो हफ्ते तो हुए नहीं रिपोर्ट को आए हुए । पिछले 17 और 18 साल के अन्दर कोई कमेटी नहीं बनी थी । अब इस की रिपोर्ट आई है इस लिए इतना उतावलापन इस में नहीं दिखाना चाहिए । इस बात को मद्देनजर रखा जा रहा है कि हमारे पास कितने रिसोर्सिज हैं और जहाँ तक चालू साल का ताल्लुक है अभी तक इस की प्लान को फाइनलाइज नहीं किया गया है । प्लानिंग कमिशन और गवर्नमेंट आफ इंडिया का नजरिया यह है कि जो नई प्लान बनाई जाए उस में एग्रीकलचर पावर और इरिगेशन और इन्डस्ट्री पर सब से ज्यादा जोर दिया जाए । मैं हाउस को यकीन दिलाता हूँ कि जो नया प्लान बनेगा उस में हरियाना के बारे में जो सिफारिशात की गई हैं उन को मद्देनजर रखा जाएगा । और एग्रीकलचर, पावर और इरिगेशन पर की सिफारिशात पर जितना ज्यादा हो सका असल दरामद करने की कोशिश की जाएगी और इस गवर्नमेंट की खाहिश है कि हरियाना की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए ।

**सरदार अजयिब सिंघ सैयू :** मुख मंत्री साहिब ने एह फरमाया है कि पिछले 18 सालों में कौड़ी डीवेलपमेंट नहीं कीती गयी अउर हाल में सरकार गौर कर रही है उन की इस दा एह हल ठीक नहीं कि हरिआणा पूरा बसा चिउा जावे उन नो एह आपनी डीवेलपमेंट आप कर लैए ?

**Mr. Speaker :** This supplementary question is not allowed.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, the hon. Chief Minister has been pleased to state that stress has to be laid on agricultural development and rural electrification. Shall we, Sir, take it that the Government will now look the development of Haryana because preference has to be given to agricultural development ?

**मुख्य मन्त्री :** मैंने ओवरलुक नहीं कहा बल्कि मैंने कहा है कि कन्सिडर किया जाएगा । हमारी गवर्नमेंट की यह जबरदस्त खाहिश है, पहले भी थी और आगंदा

भी रहेगी और कोशिश की जाएगी कि फोर्थ प्लान में इन बातों का पूरा खयाल रखा जाए ताकि हरियाना की पूरी तरह से डीवैलपमेंट हो सके ।

**कामरेड बाबू सिंघ मासटर :** आन ए पाइंट आफ आरडर, सर। अज बिरला डील बारे रैजोलिउशन है ते इस दे मूव करन वाले मैम्बर नुं इनुं ने जाण बुझ के मैम्बर क र दिता है ताकि उह इस रैजोलिउशन नुं मूव ना कर सके अते उस मैम्बर ते ज़ोर दिता जा रिहा है कि इस रैजोलिउशन नुं विदडर कर लवे । (विपन)

**Mr. Speaker** Please take no notice of it.

**सरदार तारा सिंघ लाइलपुरी :** मेरा पुआइंट आफ आरडर इह है कि इस उरुं तां इनुं केलें डीवैलपमेंट नहीं होनी । किउं रुपिया अते वकत जाइआ कर रहे हन ? किउं नहीं पंजाबी सूबा ते हरिआना पूंउ बणा दिंदे तां कि उह आपणे इलाकियां दी आप ही डीवैलपमेंट कर देण । फिर इस उरुं दीआं कमेटीआं बणाण दी कौदी लेंड नहीं रहेगी ।

**श्री सपीकर :** तुसीं जिहड़ा "वकत जाइआ" दा सषद वरतिआ है इस नुं वापस लउ । (The hon. Member may please withdraw the words 'waste of time' used by him.)

**सरदार तारा सिंघ लाइलपुरी :** मैं इस नुं वापस लैंदा हूं ।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरियाना की डिवैलपमेंट करने और कमेटी की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने के लिए कोई डैड लाइन फिक्स की जा सकती है कि उस तारीख तक सारी रिकमेन्डेशन्ज पर अमल दरामद हो जायग और सारी कारवाई कमप्लीट हो जाएगी ?

**मुख्य मन्त्री :** कोई डैड लाइन तो फिक्स नहीं की जा सकती लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जल्दी से जल्दी अमल किया जाएगा ।

**Shri Mohan Lal :** Sir, may I know from the hon. Chief Minister whether the interim Report of this Committee was submitted at the instance of or as desired by the Government or was it submitted sub moto by the Committee ?

**मुख्य मन्त्री :** यह गवर्नमेंट के कहने पर नहीं दी गई बल्कि अपने आप फिनाशल कमिशनर डिवैलपमेंट को दी गई और वही उसे एग्जामिन कर रहे हैं ।

**Shri Mohan Lal :** Sir, may I know if the interim Report of this Committee was at all considered by the Government.

**Chief Minister :** It is under the consideration of the Development Department.

**कामरेड राम प्यारा :** क्या चीफ मिनिस्टर या प्लानिंग मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि उन्होंने फरमाया है कि इन्टरिम रिपोर्ट को एग्जामिन किया गया तो क्या उस रिपोर्ट में जस्टीफिकेशन पाई कि प्लान में हरियाणा की डिवैलपमेंट के लिए प्रबन्ध किया जा ।

मुख्य मन्त्री । मैंने अर्ज किया है कि प्लान बनाते वक्त इन सिफारिशों को मद्देनजर रखा जाएगा ।

**Registration of a case against a Goldsmith in Jind  
District Sangrur**

**\*9167. Chaudhri Net Ram :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Police registered a case against a goldsmith on the recovery of about 1½ kilos of Gold from him in Jind, district Sangrur, during October, November, 1965 if so, the provisions of law under which it was registered ;
- (b) whether it is also a fact that the case referred to in part (a) above has since been withdrawn, if so the reasons for not handing over the said case to the Central Excise and Taxation Department ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes. Under Section 411 I.P.C.

(b) the case was cancelled by the local Police as it could not be established that the gold was stolen property. The gold was returned to the accused under orders of S.D.M., Jind. Hence the question of handing over the gold to the Central Excise and Taxation Department does not arise.

**चौधरी नेत राम :** मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि सोना जो बरामद हुआ क्या वह डिफेंस फंड या गोल्ड बांड की शक्ल में जमा करवाया गया है ?

**श्री अध्यक्ष :** वह वापस कर दिया गया है । (That has been returned.)

**चौधरी नेत राम :** यह बिलकुल गलत है । यह इस तरह चोरों को छोड़ना चाहते हैं । यह तहकीकात होनी चाहिए कि असल बाका क्या है ।

**कामरेड राम प्यारा :** मैं पूछना चाहता हूँ कि आया इस सोना के मुताबिक पुलिस ने इस बात की इन्क्वायरी की कि यह जो सोना था यह समगलर्ज से हासल हुआ या चोरों का था ? क्या इस बात की कोई वैरिफिकेशन भी की गई थी ?

**मन्त्री :** मैंने जवाब में कहा है कि सारी बात की वैरिफिकेशन के बाद एस.डी.एम. के आर्डर के मुताबिक सारी चीज हुई ।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आया इस के मुताबिक पुलिस ने कोई केस रजिस्टर किया । आया बाँर किसी पराईमेंरी इन्वैस्टीगेशन के रजिस्टर हुआ था ? जब केस रजिस्टर हो चुका था तो पुलिस ने विदड़ा क्यों किया । वह कौनसी इन्वैस्टीगेशन है जिस की वजह से विदरा हुआ ? क्या पुलिस बाँर किसी वजह के विदड़ा कर गई या पुलिस ने कोई कारवाई की ?

**मन्त्री :** इतनी डिटेल्ज तो मेरे पास नहीं हैं । जो पूछा गया था उस का जवाब मैंने दे ही दिया है ।

**चौधरी दल सिंह :** जिस शख्स से सोना बरामद किया गया क्या वह जेवरात की चोरी का पहले भी मुलजिम था ? जहां तक मेरे इल्म में है यह केस साबत नहीं हो सका ?

**श्री अध्यक्ष :** इसका इसकेस से कोई ताआल्लुक नहीं है । (This has nothing to do with this case.)

**महोदय गुरुचरन सिंह :** जिसने झूठी सिवाष्टि बरदाएी मी, बी पुलिस ने उस से धिलाह 182 का वेम रजिस्टर बीडा ?

**भंडारी :** इस से लघी मैनु नोटिस चाजीदा है ।

**Pandit Chiranjilal Sharma :** On a point of order, Sir. As and when any question is put to elicit information from the honourable Minister, he is pleased to say that he does not have the requisite information with him. In this case, a theft case has been registered against an individual and the complainant has not been taken to task for the malicious prosecution brought about by him. I would like to know, Sir, whether the Minister is not required to come prepared with all possible information keeping in view the nature of the question or rather anticipating the likely supplementaries to be put in the House ?

**Mr. Speaker :** I agree that the honourable Ministers should come prepared anticipating all the relevant supplementaries. But, sometime it does happen that they cannot anticipate all the possible questions. In that case, the only alternative is that either the supplementaries are postponed or the Members take the trouble to put separate questions.

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, मुझे निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह केस स्टेट पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की एक शाकिंग तसवीर है । एक आदमी पर केस रजिस्टर होता है वह अरैस्ट होता है मगर किसी वजह से वह रिहा हो जाता है । आखिर वह कौनसी वजह है जिस से रिहा होता है या जिस वजह से उसे यह इनकनवीनिएंस उठानी पड़ी ; केस किस दफा के तहत रजिस्टर किया गया । इसके मुताल्लिक specific information has been asked for by the hon. member but the Minister is not prepared to give it.)

**Minister :** I refute it.

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** इस बात का इन को पता होना चाहिए कि ऐसे कारण क्या थे जिन की वजह से केस रजिस्टर हुआ । आया कोई इनवैस्टीगेशन हुई ; अगर हुई तो क्या वजह थी कि केस विदडरा कर दिया गया । क्या कोर्ट ने डिसचार्ज किया ?

**Mr. Speaker :** Let me see to the Supplementaries first.

**कामरेड राम प्यारा :** क्या यह हकीकत है कि यह सोना एक स्टेशन से पकड़ा गया था और यह जेवरों की शकल में नहीं था बल्कि सलाखों के रूप में था ?

**Minister :** I will repeat the reply already given by me

“(a) Yes. U/S 411 I.P.C.

[Home and Development Minister]

(b) the case was cancelled by the local Police as it could not be established that the gold was stolen property. The gold was returned to the accused under orders of S.D.M., Jind. Hence the question of handing over the gold to the Central Excise and Taxation Department does not arise.',

**कामरेड राम प्यारा :** स्पीकर साहिब, मेरे सवाल का जवाब आना चाहिये कि 1½ कि.ग्रा जो सोना पकड़ा गया वह जेवरों की शकल में था या सलाखों की शकल में ?

**मन्त्री :** यह 124 तोले सोना था ।

**कामरेड राम प्यारा :** यह जेवरों में था या सलाखों में था या इंटों में था ? दूसरी बात यह कि उसकी रिहाई एस० डी० एम० से नहीं बल्कि सेशनज कोर्ट से मिल मिलाकर करवाई गई ।

**मन्त्री :** इसे एस. डी. एम. के आर्डरज से रिहा किया गया ।

**डाक्टर मंगल सैन :** क्या यह बात सच है कि जिस आदमी को रिहा किया गया उसे जींद रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था और उस के पास जेवर नहीं बल्कि सलाखें थीं ?

**मन्त्री :** यह सोना 124 तोले था और सारी तफसीलात पूछ कर बताई जा सकती हैं। अगर चाहे आप इस को पेंडिंग रख सकते हैं।

**डाक्टर मंगल सैन :** पेंडिंग रखो जी ।

**Mr. Speaker:** Order, order, please. All right, I postpone further supplementaries on this question. But, it may be better if the honourable Members, who want to put the supplementaries, send the nature of their questions to the honourable Minister so that he comes prepared. The next question by Shri Talib has been postponed.

**कामरेड जंगीत सिंह जोगा :** आन ए पुआइटि आद आरुहर सर । में अरज करंगा कि होम मनिस्टर ने गलत इन्फार्मेशन दी है । जे सोना हासल कीता गिआ उह एस. डी. ए. ने बांडज जे डीफेंस फंड की शकल में देवे जमुं करवाया । असीं चैलेंज करदे हं एस. डी. ए. की तहकीकात कीती जावे ।

**श्री सपीकर :** इह इन्फार्मेशन उनुं नुं दे दिउ ताकि जवाब तਿਆर करके आउठे । (This information may be sent to the hon. Minister, so that he may come prepared with the reply)

**डा० बलदेव प्रकाश :** जोगा जी ने होम मनिस्टर की रिपलाई को चैलेंज किया है वह कहते हैं कि सोना वापस नहीं हुआ बल्कि बांडज की शकल में जमा कराया है । अगर यह गलत बात हाऊस में आई है तो इसकी भी इन्क्वारी होनी चाहिए ।

**Starred Question No. 9198 (Postponed)**

**Mr. Speaker:** Question No. \*9198 is postponed. इह किउंकि चंडीगढ़ परापर नुं रीलेट करदा है । एस. लडी एस. दा जवाब दी जलदी आउठा चहीदा है ।

(Starred Question No. 9198 is postponed But since this question relates to Chandigarh proper, it should be answered early.)

**Search of the house of late Sardar Partap Singh Kairon**

**\*9199. Sardar Niranjana Singh Talib:** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether any enquiry has been held regarding the search and digging of the floors of the house of the Late Sardar Partap Singh Kairon in village Kairon made after his resignation from the Chief Ministership, if so, the result thereof, if no enquiry has been held, the reasons therefor?

**Sardar Darbara Singh:** Yes. A search was carried out but no such directions were issued by the Government. Subsequently an enquiry was held and it was found that the local Police was legally justified in undertaking the search and no irregularity was committed.

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਘੋਰਾ :** ਕਥਾ ਹੋਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਓਗੇ ਕਿ ਵਹਾਂ ਕੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਇਨਕਸ਼ੌਰੀ ਥੀ ਕਿ ਕੁਝ ਫੁਆਰਾ ਥੀ ਸੋਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕੇ ਸਕਾਨ ਮੇਂ ਦਫ਼ਾ ਫੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੁਹੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੇਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਏਥੇ ਅਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਐਸ. ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਜੇਟਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਏਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ । ਬਾਕੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਘੋਰਾ :** ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਥੀ । ਸਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਗਾਂ ਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਾ ਫੁਆਰਾ ਥੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੀ ਥੀ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸੋਨਾ ਦਫ਼ਾ ਫੁਆਰਾ ਥੀ ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਐਸ. ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਉਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ । ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਅਗੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

**Pandit Chiranjī Lal Sharma:** On a point of Order Sir. Mr. Speaker I have to submit that since Sardar Partap Singh Kairon is dead, it would be in the fitness of things if no more supplementaries are put on this question, which, in a way, concerns him.

**Mr. Speaker:** I think, the proper thing would be not to put any more supplementaries to this question.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਕੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਲ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੰਟੈਨਸ਼ਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਦੋ ਦਫਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਥੇ ਗਲਬਨ ਸ੍ਰੀ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗਹ ਤੇ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜੈਕਚਰਜ਼ ਹਨ।

### STARRED QUESTION NO. 9077 (POSTPONED)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਆਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਹ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਕਰਟੇਰਿਏਟ ਮੈਂ ਇੰਜੀਲੀ ਐਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਓ ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਰੁਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨ ਦੇਨਾ ਕਰਾ ਜਾਯਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੋ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਓ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਯਕਸ਼ : ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਇਸ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਹਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਕਤ ਪਰ ਆਨਾ ਚਾਹਿਓ। ਆਜ਼ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਏ ਹੈ। ਉਨਕਾ ਜਵਾਬ ਦਿਯਾ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਓ ਥਾ। ਉਨ ਕੋ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਹ ਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਸਟਪੋਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨ ਕਰੇ। ਅਬ ਇਸ ਕੋ ਲਿਓ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੇਸ਼ਨ ਬਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। (I am at one with the hon. Member that the replies to questions should be given in time. The questions standing in the names of sarvshri Talib and Amar Singh should have been answered today. There seems no reason in getting them postponed. I would request the Government to avoid such postponements. Now I will have to be strict for this purpose.)

ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨੇ ਰੁਲਿੰਗ ਦਿਯਾ ਥਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਵੈਸ਼ਨ ਕੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਰਟੇਰਿਏਟ ਸੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਯਕਸ਼ : ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਪ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਿਯਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰ ਮੈਂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਰੁਲਿੰਗ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਰੇਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਯਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਤ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਡਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੰਦਾ ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੈਕਰਟੇਰਿਏਟ ਸੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਯਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਨੇ ਕਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। (Addressing Chaudhri Amar Singh) Shri Tandon had raised a point of order in connection with hon. Members, question and on that I have given my ruling. It is no use repeating it. As regards the words he has attributed to me that no question, reply to which is available in the Secretariat, can be postponed I may point out that I never said that)

**Zailghar Building, Kapurthala**

**\*9011. Sardar Lakhi Singh Chaudhri:** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Government in their letter No. L.B-8(55)-62/40156, dated the 2nd November, 1964, directed that the Zailghar Building, Kapurthala, may be transferred to the Zila Parishad, Kapurthala;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the possession of the building has actually been made over to the said Parishad;
- (c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the date on which the possession was made over, if in the negative, the reasons for the delay and the approximate time by which the possession is likely to be handed over to the said Parishad?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes.

(b) No.

(c) The matter is still under correspondence with the Deputy Commissioner, Kapurthala, and the Secretary to Government, Punjab, P.W.D., B&R/PH Branches/Chief Engineer, Punjab, P.W.D., B&R Branch, Patiala. Acute shortage of Government residential accommodation at Kapurthala is the main reason of the Deputy Commissioner, Kapurthala, for not getting the Building, in question, vacated. It is not possible to give the approximate time, by which the possession of the Building will be handed over to the Zila Parishad, Kapurthala.

**ਸਰਦਾਰ ਲਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ :** ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਚੁੱਕੀ ਜੀ. ਏ. ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

---

**Representations from certain Officers**

**\*9093. Sardar Tarlochan Singh Rasti:** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the number and names of the S.D.O. Overseers/Sectional Officer seniority-wise working in the office of the Superintending Engineer, Panchayati Raj (Development and Panchayat Department), Chandigarh at present;
- (b) the date on which the persons referred to in part (a) above joined the service in the Panchayati Raj Wing together with their qualification and experience;
- (c) whether he himself and or the Deputy Development Minister or Government received any representation from any Overseer/Sectional Officer of Panchayati Raj during the period from 1st January, 1965 to 31st December, 1965 complaining against his supersession in the matter of promotion as S.D.O. Panchayati Raj, if so when and a copy of the representation be laid on the table;

[Sardar Tarlochan Singh Riasti]

- (d) the action, if any, so far taken or proposed to be taken on the said representation, if no action has yet been taken, the reasons therefor and the time by which it is likely to be taken;
- (e) whether any delay has occurred in putting up said representation at any level, if so, the reasons therefore and the action, if any taken by the Government against the person responsible for such delay?

**Sardar Darbara Singh:**(a) *Sub Divisional Officers**Overseer/Sectional Officers*

1. Shri Parkash Singh. S.D.O.(S)
2. Shri D.C. Talwar,  
S.D.O (Rural Housing)
- 3 Shri A. L Jaggi, S.D.O., (Elect.)

As per the tentative seniority list the overseers working in the office of Superintending Engineer, Panchayati Raj Circle in order of Seniority, are as under:—

1. Shri Mukhtiar Singh Overseer (R. Housing)
2. Shri K.K. Thapa
3. Shri Jaswant Singh
4. Shri Balbir Chand  
(Electrical)

(b) There is no such wing as the Panchayati Raj Wing. The date of joining of the S.D.O.s and Overseers/Sectional Officers Panchayati Raj Circle Office is given in each case:

**1. Shri Parkash Singh**

Date of joining Panchayati Raj  
Circle Office ..  
Qualifications and Experience

28th June, 1962.  
Matric, qualified Overseer, also passed Departmental examination, 20 years experience as D/Man and Circle Head D/Man Promoted as S.D.O. on 3rd July, 1964.

**2. Shri D.C. Talwar:**

Date of joining Panchayati Raj Circle 23rd February, 1962  
Qualification and Experience

Matric, qualified Overseer from Hewath School of Engineer, Lucknow; 15 years experience as Overseer. Promoted as SDO. on 25th February, 1965

**3. Shri A.L. Jaggi**

Date of joining Panchayati Raj Circle 5th December, 1965.  
Qualifications and experience

B.Sc. Electrical Engineer, on deputation from State Electricity Board.

**Overseers/Sectional Officers**

1. Shri Mukhtiar Singh, Overseer, Rural Housing joined Panchayati Raj Circle on 23rd February, 1962; Diploma Civil Engineering Ramgarhia

Polytechnic Phagwara. 6 years experience as Overseer.

2. Shri K.K. Thapar, Overseer, Rural Housing joined Panchayati Raj Circle, on 23rd February, 1962: Intermediate, Diploma Craftsmanship from Government of India; 6 years experience as Overseer.

3. Shri Jaswant Singh, Overseer, Rural Housing joined Panchayati Raj Circle, on 23rd February, 1962; 1½ years course in survey trade. 5 years experience as overseer.

4. Shri Balbir Chand, Overseer (Electrical). Qualified Overseer from the Punjab State Board of Technical Education; appointed on 1st January, 1966.

(c) Yes by the Home and Development Minister and the Deputy Minister for Development. A copy of the representation is put up on the Table.

(d) Representation since considered by Government and rejected.

(e) No delay has taken place at any level. The question of taking action against any person does not arise.

Please examine it thoroughly and send me the file with your comments.

S.E. Panchayati Raj

(Sd.) ...  
H. D. M.  
1,9.65.

To

The Hon'ble Home and Development Minister, Punjab, Chandigarh.

**Subject.**—Recruitment of Sub-Divisional Officer, Rural Housing Cell-Representation against.

Sir,

If the circumstances had run their normal course, I would not have encroached upon your valuable time in doing which I crave your indulgence on the one hand and beg your pardon on the other. Having failed in my efforts to seek redressal of my greivances from the concerned authority, i.e., the Superintending Engineer, Panchayati Raj, P.W. Circle, Punjab and Commissioner Agricultural Production and Rural Development and Secretary to Government Punjab, Development and Panchayat Department, I most respectfully beg to bring to your kind notice the following points :—

(a) That having qualified diploma in civil Engineering I joined duty as overseer in Rural Housing Cell on having been selected by the Subordinate Services Selection Board on 25th April, 1960 and I am still working there as such. I am the senior most and have worked to the entire satisfaction of my officers but without any future prospects of promotion.

(b) That the post of Sub-Divisional Officer, Rural Housing Cell vacant in first quarter of 1964 and I being the senior most applied to the S.E. (PRC) vide my representation dated the 16th May, 1964 for my promotion but to my ill luck my name was not considered by him, and the post was kept vacant till an Overseer of P.W.D. B & R Branch who was working with Zila Parishad Patiala (Foreign body) was posted as S.D.O. (R.H) and I was made to calm telling that a working S.D.O. has been transferred to the post. There was hardly any justification to post a man who is quite ignorant of the scheme as head to run it. That person himself admitted in his representation for transfer that he has no knowledge of the scheme.

(Home &amp; Development Minister)

- (c) That now a Zila Parishad (erstwhile District Board) Overseer whose services are yet to be provincialized and are not yet been considered by Government for his appointment even as Overseer in Government Service has been put in charge of the Rural Housing that also without any recommendation of the Public Service Commission. It is not only ultrawires of Government instructions, but is also harmful in the running of scheme besides being fatal to our careers. The Zila Parishad Overseers were not Government employees but without recommendation of their services are being treated as superior over us. This is again jeopardising the claims of the qualified and experienced officials already employed to run the scheme, which ends to mar for good, any chance of betterment while working in this department. Such an action is causing great frustration to the effected officials including the applicant.
- (d) That since long I along with my other colleagues was looking forward for this post, but the wrong policy adopted by the administration has only benefited the officials of the P.W.D. B & R Department and the Zila Parishad (erstwhile District Board) employees who are not even Government employees. These Zila Parishad employees are mostly those persons who could not get Government jobs and joined service in Zila Parishad (erstwhile District Board) and are now being tipped through back door.
- (e) That according to Government instructions the minimum experience required for promotion to the higher post is to be fixed by Government in consultation with Public Service Commission but no such minimum experience in respect of Rural Housing, which is entirely different to B & R, has been fixed so far. As such, the sweet will of the authorities prevails and the future of the persons already working in the execution of the scheme, is in wilderness.
- (f) That the Rural Housing Cell is a quite separate unit whose 50 per cent Estt. expenditure are met by Central Government and as such the seniority list of the Overseer of this unit is totally separate to Block Overseer and Zila Parishad overseers, but the promotions are being given to others at the cost of Overseers of Rural Housing.
- (g) That it would not be out of place to mention that a working Head Draftsman with an experience of only about 3 years has now been promoted as Assistant Design Engineer an equivalent post to that of Sub Divisional Officer in Rural Housing Wing Punjab Engineering College, Chandigarh due to the difference nature of the job to B & R working. In such circumstances I most respectfully request that the move to import officials from the P.W. B. & R. etc. to man the job in the Rural Housing may kindly be quashed and I may be promoted as S.D.O. Rural Housing as I am the seniormost Overseer in this section, for which I shall be highly grateful to your honour.

Thanking you,

Yours faithfully,  
(Sd). MUKHTIAR SINGH,  
Rural Housing Cell, Chandigarh.

### Tours of Grape Cultivators to other States

\*8828. Comrade Ram Chandra : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the total number of tours of grape cultivators organised by the Government in 1964-65 and in 1965-66 to other States;
- (b) the number of members of each such Touring party;
- (c) the expenses incurred on each such tour?

Sardar Darbara Singh : (a)

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| (i) 1964-65     | .. One               |
| (ii) 1965-66    | .. Nil               |
| (b) (i) 1964-65 | .. Fifty             |
| (ii) 1965-66    | .. Does not arise    |
| (c) (i) 1964-65 | .. Rs 9,071.10 Paise |
| (ii) 1965-66    | .. Does not arise    |

**कामरेड राम प्यारा :** मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन आदमियों को दौरा पर भेजा गया और हजारों रुपया खर्च किया गया क्या वह आदमी अंगूर कल्टीवेशन के एक्सपर्ट थे और क्या उनको कोई पुराना तजर्बु था ?

**मन्त्री :** यह आदमी जो भेजे जाते हैं वह यह काम देखने और सीखने के लिए भेजे जाते हैं ताकि यहां पर उसका फायदा उठाया जाए। आंध्र में यह इन्डस्ट्री काफी डिवैलपड है इस लिए वहां काम देखने के लिए आफ एंड आन टूर्ज होल्ड किए जाते हैं।

**श्री मंगल सैन :** क्या मन्त्री सहोदय बताएंगे कि यह जो ग्रेप पार्टी दौरा पर गई उस में सिर्फ वही आदमी गए जिन्होंने अंगूर लगाने थे या कुछ स्यासी सज्जन भी भेजे गए ?

**कामरेड राम प्यारा :** क्या बजीर साहिब ने कहा कि यह आदमी अंगूर की काश्त का काम देखने के लिए दौरा पर भेजे गए तो क्या उन की अपनी ज़मीनें इस किसम की थीं जहां अंगूर की खेती हो सकती थी और क्या एग्रीकल्चर या हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट्स की सिफारिश पर वह आदमी भेजे गए या बगैर सिफारिश के ही भेज दिए गए ?

**मन्त्री :** इन में दोनों चीजें हैं। जिन के पास अपनी ज़मीनें हैं वह भी सीख कर काश्त कर सकें और दूसरे प्रापेगंडा के लिए भी टूर कराए जाते हैं ताकि वह लोग वहां सारा काम देख और सीख कर यहां लोगों को उत्साह दें और बताएं कि कौन सी कमर्शल क्राप है जिस से काफी फायदा हो सकता है।

**श्री मंगल सैन :** यह जो टूरिंग पार्टी गई इसमें कौन कौन लोग गए थे ?

**मन्त्री :** यह बड़ी लम्बी चौड़ी लिस्ट है अगर कहेंगे तो टेबल पर ले कर दी जाएगी।

**सरदार लड्डमण सिंह गिल :** की इस टूरिंग मंडली विच इस हाउस दा ज़ां अपर हाउस दा वी कौड़ी मैम्बर गिआ सी अउ जेकर गिआ सी उां उह कौंड है ?

**मंडरी :** इह इस सवाल विच पुछिआ नहीं गिआ। जेकर लिस्ट मंगेगे उां दे देवांगे, उस विच सारिआं दे नाम आ जाणगे, उसीं वेध लैणा कौंड कौंड है।

**सरदार गुरचरण सिंह :** इह जे आदमी टूर करन गये सी कि उनुं ने एधे आके अंगूर दी कल्टीवेशन सुरु कीती है ज़ां सैर करके ही आ गये हन ?

**मंडरी :** उनुं दे आउठ तें बाअद काढी ऐसीआ गरेप कल्टीवेशन हेठ आइआ है।

### Office of Vice-Chancellor, Agricultural University, Ludhiana

**\*9012. Lt. Bhag Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the office of the Vice-Chancellor of the Agricultural University, Ludhiana, is located at Chandigarh; if so, the period for which it is likely to continue to function at Chandigarh;

(b) the extra expenditure incurred on this account, if any?

**Sardar Darbara Singh:** (a) Yes. The office of the Vice-Chancellor will move to Ludhiana within six months or so;

(b) Extra expenditure amounts of Rs 448.12 per month on account of Compensatory Allowance paid to the Staff stationed at Chandigarh in the Camp Office.

**ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ :** ਜਦੋਂ 1962 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਉਹ ਦਫਤਰ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਉਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਿਉਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੁੰਕਿ ਇਥੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਖਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਥੇ ਰਿਹਾ।

**ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ :** ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇਥੇ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੱਲਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਇਥੇ ਰਖਿਆ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਥੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਉਣ ਉਤੇ ਕਿਨਾ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਟੀ. ਏ. ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਕ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਪਿਆ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ।

#### **Setting up of a New Mandi in Hissar City**

**\*9075 Shri Hunna Mak:** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether Government proposes to set up a new Mandi near the Civil Hospital and T.B. Hospital in Hissar City;

- (b) whether it is a fact that the business community has raised an objection to the setting up of the Mandi in the vicinity of T.B. Hospital; if so, the details thereof;
- (c) whether it is a fact that in spite of the objection referred to in part (b) above, it is proposed to go ahead with the said scheme and the plots have been auctioned;
- (d) whether it is also a fact that purchasers of the said plots have served the Government with a notice under section 80 C.P.C. demanding refund of the instalment paid by them due to the unsuitability of the site of the said mandi;
- (e) if the reply to parts (c) and (d) above be in the affirmative, whether there is any proposal under the consideration of Government to scrap the scheme for setting up the said mandi, if not, the reasons therefor?

**Sardar Darbarn Singh:** (a) Yes.

(b) Yes; proximity of the T.B. Clinic was one of the grounds for raising the objection.

(c) Yes.

(d) Some notices have been served by the plot purchasers with a view to back out of the transaction. Refund of the bid money has not been claimed on the ground of unsuitability of the site.

(e) No; the medical authorities have no objection to the location of the mandi at the present site.

**श्री हुन्ना मल :** क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि अगर व्योपारियों ने दफा 80 सी. पी. सी. के अधीन दी हुई ईस्टालमेंट्स को वापिस लेने के नोटिस दिए हैं तो क्या वहां पर मंडी बनाने की योजना रहेगी ?

**मन्त्री :** कुछ व्योपारियों ने दफा 80 सी. पी. सी. के अधीन नोटिस दिए हैं कि प्रैजेंट लोकेशन पर मण्डी न बनाई जाए। वह बैंक आउट कर रहे हैं।

**श्री हुन्ना मल :** क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वहां पर टी. बी. क्लीनिक है और इस वजह से वह लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वहां पर मंडी न खोली जाए और क्या सरकार अभी तक उसी योजना पर कायम है ?

**मन्त्री :** वहां के व्योपारी इस बात से बैंक आउट करना चाहते हैं। लेकिन इस बात से यह मामला खत्म नहीं हो जाता। अगर वहां के व्योपारी अन्य कोई सूटेबल जगह सरकार को बताएं तो वहां पर मण्डी बनाने के लिए विचार करने के लिए तैयार हैं। उस में देखना पड़ेगा कि वहां पर मण्डी बनाने में कितना समय लगेगा। अगर व्योपारियों की इस बारे में रीप्रिजेंटेशन आएगी तो सोचा जाएगा। जहां तक व्योपारी टी. बी. क्लीनिक का बहाना बना रहे हैं, उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि हैल्थ डिपार्टमेंट ने वहां पर मण्डी बनाने के लिए कोई रुकावट नहीं डाली है।

(Regarding Starred Question No 9008)

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या नम्बर 9008 कैप्टन रतन सिंह से सम्बन्ध रखता है। आज उन के जवाब देने का दिन निश्चित नहीं है। इस के अलावा उन की मेरे पास रिकवैस्ट भी आई है कि वह एप्रोप्रियट दिन पर इस सवाल का जवाब देंगे। इसलिए इस को उस दिन के लिए पोस्टपोन किया जाता है। (Starred Question No. 9008 relates to Captain Rattan Singh. Normally he is not

[Mr. Speaker]

scheduled to reply to question today. Besides I have received a request from him that he would answer this question on the appropriate day. Therefor this question is postponed to that day.)

**Ban on the purchase of "Daily Hind Samachar" for Municipal Libraries in the State**

\*8841. Comrade Ram Chandra: Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that Government has issued a circular letter banning the purchase of the newspaper 'Hind Samachar' by the Municipal Committees for their Libraries;
- (b) the names of other newspapers, if any, similarly banned for Municipal Libraries;
- (c) whether the Government have received a representation from the Municipal Committee, Ludhiana that the ban referred to in part (a) above, on this Committee be lifted?

**Sardar Darbara Singh** (Home and Development Minister): (a) Yes.  
(b) The daily 'Prabhat', 'Jathedar' and the Monthly 'Sant Sippahi'.  
(c) Yes.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ : ਕਧਾ ਸਨ੍ਰੀ ਸਹੋਦਯ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਿਆ ਐਰ ਕਬ ਜਾਰੀ ਹੁਆ ?

ਸਨ੍ਰੀ : ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 1961 ਕੋ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਿਆ ਥਾ । ਉਸ ਮੈਂ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ—

"In view of the changed circumstances the ban on the purchase of 'Parbhat,' 'Jathedar' and the monthly 'Sant Sapahi' be lifted.

ਗ੍ਰਹ ਸਨ੍ਰੀ : ਇਸ ਸਾਮਲੇ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਕਾਂਸਿਡਰ ਕਿਆ । ਇਸੀ ਟਰਹੁ ਸੇ ਲੁਧਿਆਨਾ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 1965 ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਿਆ ਥਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦ ਕਮਿਊਨਲ ਬੋਸਿਜ਼ ਤੇ 'ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ', 'ਪਰਭਾਤ', 'ਜਥੇਦਾਰ' ਅਤੇ 'ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ' (ਮੰਥਲੀ ਰਸਾਲਾ) ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਉਣੇ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। (A matter relating to the Vidhan Sabha Secretariat need not be discussed here.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?

Mr. Speaker : Question Hour is over.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਪਰ ਐਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਨੀ ਚਾਹੀਏ ।

Mr. Speaker: More supplementaries can be asked on this question next time.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Executive officer, Municipal Committee Jind, district Sangrur

\*9182. **Chaudhri Inder Singh Malik:** Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state—

- (a) whether the post of Executive Officer, Municipal Committee Jind, district Sangrur was advertised; if so, the requisite qualifications for the said post as mentioned in the advertisement along with the date of the interview;
- (b) whether the selection of the candidate for the said post was made by competent authority; if so, the name of that authority, along with the names and qualifications of the candidates interviewed in this connection;
- (c) the name of the candidate selected for the said post stating his age, qualifications and experience, if any;
- (d) whether the candidate referred to in part (c) above fulfils all the requisite qualifications/conditions as advertised?

**Sardar Ajmer Singh:** A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) A number of posts of Executive Officers was advertised and the post of Executive Officer, Municipal Committee Jind, was one of them. The qualifications prescribed for the post were as under :—

- (1) *Compulsory*.—B.A. with local bodies experience in a responsible post for at least five years ;

OR

B.A., LL.B., with five years' experience as an advocate, sound knowledge of municipal administration, capacity to handle accounts and prepare budget etc.

- (2) *Preferential*.—Senior Local Self Government Diploma awarded by the All India Institute of Local Self Government, Bombay.

- (3) *Age*.—Between 30 and 40 years. The upper age limit relaxable in case of specially qualified and experienced candidates.

The candidates were interviewed on 5th October, 1965.

(b) The candidates were interviewed by the Planning and Local Government Minister in the presence of Secretary, Local Government Department. Their names and qualifications, in brief, as stated by them in their applications, are as follows :—

Serial No.	Name and address of the candidates	Date of birth	Age	Qualifications	Experience
Sarvshri—					
1	Jagwant Singh Doad, son of S. Uttam Singh Doad, Octroi Superintendent-cum-Lands Officer, Municipality Faridkot	14-10-34	30	Graduate with L.S.G. Diploma	Working as Octroi Supdt. since 17-8-57 with additional duties of Lands Officer, and experience of municipal administration.
2	Rabinder Karan Aggarwal, Secretary Notified Area Committee, Rajpura Township	January, 1935	30	Law Graduate attended lectures on municipal law and administration	Joined service of the Municipal Committee in the year 1961 and worked as Office Superintendent and Octroi Superintendent in the Municipal Committee, Ambala City.

[Planning &amp; Local Government Minister]

Serial No.	Name address of the candidate	Date of birth	Age	Qualifications	Experience
2—Concl'd				tion and passed one paper of the Accountants' Examination, held by Local Government Department	for three years. Now working as Secretary Notified Area Committee Rapura Township since May, 1963.
3	M.L. Agnihotri Advocate, Court-Auctioneer, Arya Samaj, Patiala	25-4-34	31	B.A., LL.B.	Practising at Patiala since 1957, working as Oath Commissioner, holding the posts of Court Auctioneer-cum-Local Commissioner, Legal Advisoi to Municipal Employee r Association, Patiala, s possessed knowledge of municipal law.
4	Bhagwant Singh Jain, Executive Officer, Municipal Committee, Rampura Phul	Not mentioned in the appli- cation		M.A., LL.B.	He was working as Exe- cutive Officer, Municipal Committee Ram-pura Phul and had also served Municipal Committee Nabha, Malerkotla Sangrur, Tarn Traran, and Barnala for 10 years.
5	Kewal Krishan Dalla, Secretary Municipal Committee, Nabha	4-3-33	32½	B.A. in Economics Political Science, English and Urdu as optional	Worked as Senior Clerk in the Rehabilitation Department of the erst- while Pepsu State, Joi- ned municipal service at Nabha n 1956 as Office Superintendent. He was promoted as Secretary, Municipal Committee, Nabha, in the year 1960.
6	Gurbachan Singh, Head Clerk, Municipal Committee, Tarn Taran	1-4-28	37	B.A. Gyan, qualified B. grade Muni- cipal Accountant L.C.G.D.	Joined as Octroi Moharrir in 1948 was working as Head Clerk in the office of the Municipal Committee, Tarn Taran since July, 1959.
7	Darshan Lal Aggarwal Secretary, Municipal Committee, Giddarbaha	..	32½	B.A., LSGD. passed three papers of Municipal Accountants Examination	Working as secretary Municipal Committee, Gidderbaha since Sep- tember, 1956.
8	Hans Raj Sachdeva, Accountant, Muni- cipal Committee, Patiala	20-4-27	38	B.A. Honours in Hindi (Prabhakar) Qualified A Grade Accountant	In the service of Local Bodies since 1944, served in Municipal Commit- tee, Abohar as Clerk Assistant Accountant and Tax Superintendent

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (3)21  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Serial No.	Name and address of the candidate	Date of birth	Age	Qualifications	Experience
8—	<i>Concld</i>				from 1944 to 1957, served in the District Board, Ferozepore, and Municipal Committee, Jagraon as Assistant Accountant and Head Clerk-cum-Accountant respectively from 1957 to 1959, serving as Accountant in Municipal Committee Patiala since December, 1959.
9	Prithi Pal Singh Bassalvi, Executive Officer, Municipal Committee, Patti	..	35	B.A., LL.B. qualified in proficiency in Law, passed special course in Income Tax Law	Practised as lawyer from January, 1959 to March, 1962, worked as Secretary, Municipal Committee, Malerkotla from March, 1962 to January, 1965 and now working as Executive Officer, Municipal Committee, Patti.
10	Sant Ram Singla, Advocate, Banerji House, Bahera Road, Patiala	20-1-34	31	B.A., LL.B. M.A. in Public Administration	Was working as Legal Practitioner for about last six year, as Local Commissioner for Patiala District since November, 1962, was appointed as Commissioner to administer oaths and affirmations to deponents for two years from March, 1964.
11	Amolak Ram Chopra, Advocate, Ludhiana	12-4-27	32½	M.A. (Economics) LL.B.	Practising as an Advocate at Ludhiana for the last five years.
12	Jagjit Singh, Advocate, 11-F/2019, Sector 23-C Chandigarh	13-7-40	25	B.A., LL.B.	Practising as Advocate since 1962.
13	Jagdish Prashad Sharma, 2/614, Gali No. 1 Nai Basti, Bhatinda	29-8-17	48	M.A. LL.B.	Practised as a lawyer for about 7 years and worked as a Legal Advisor to Municipal Committee, Kat Kapura for more than one year, worked as Secretary to the same-Committee from November, 1953 to July, 1959, worked as Executive Officer, Municipal Committee, Bhatinda from 21-7-59 to 20-7-1965.
14	Sita Ram Aggarwal, Secretary, Municipal Committee, Kot Kapura	1-1-31	34	B.A., L.S.G.D.	13½ years' experience of the Municipal Committee, Kot Kapura, worked as Sanitary Inspector and continued as such till 2-4-1962 when he was appointed as Secretary, Municipal Committee, Kot Kapura.

## [ Planning and Local Government Minister]

Serial No.	Name and address of the candidate	Date of birth	Age	Qualifications	Experience
15	Jiwan Parkash Passy, Advocate, District Courts, Anaj Mandi, Nabha Gate, Patiala	..	39	B.A. (Hons.) LL.B.	Prosecuting Sub Inspector for 2 years. Litigation Inspector and Assistant Custodian of Evacuee Property from 26-7-50 to 1956.
16	Lachman Das Gupta, Librarian, Municipal Committee, Kot Kapura	10-7-25	40	B.A.	Joined the Municipal Committee, Kot Kapura as Head Clerk in June, 1955, worked as Octroi Inspector in addition to his own duties, working as Librarian since July, 1960.
17	Surrinder Pal Kaura, 100 C Model Town, Patiala	..	30	M.A. in History, Political Science and Public Administration	Claimed to have 10 years. experience without stating its nature
18	P.C. Malhotra	..	42	B.A., LL.B.	Practising at Patiala for the last 13 years.
19	Manohar Lal, son of Jiwan Dass, Ward No. 13, House No. 4/476, Jind	..	24	M.A. Economics	..

(c) Shri Manohar Lal. At the time of his selection, he was 24 years old. He is M.A. in Economics.

(d) He was below the prescribed age and did not possess the experience as advertised. These qualifications were relaxed in his case as the Municipal Committee, Jind, had passed a unanimous resolution for his appointment to the post.

### Executive Officers in the Erstwhile Pepsu State Area and in the Erstwhile Punjab

**\*9183. Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state—

- whether it is a fact that there are two different agencies concerned with the appointment and dismissal of the Executive Officers of Municipal Committees in the State, i.e., one for the erstwhile Pepsu State area and the other for the rest of the Punjab; if so, the reasons for the same;
- whether Government intend to remove the said distinction; if so, the time by which it is likely to be removed;
- whether it is a fact that the Executive Officers posted in the erstwhile Pepsu State area are answerable to the Deputy Commissioners concerned whereas such officers posted in the rest of the Punjab are answerable to the Committees concerned?

**Sardar Ajmer Singh :** A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

### STATEMENT

(a) There are two Executive Officers Acts in force in this State, viz., (1) the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931 and (2) the Patiala Municipal (Executive Officers) Act 2003 BK. The Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931, applies to the erstwhile Punjab territory and the Patiala Municipal (Executive Officers) Act, 2003 BK, applies to the erstwhile Pepsu territory.

In the erstwhile Punjab territory, the Municipal Committee is required to appoint an Executive Officer, for a renewable term of 5 years, by a resolution to be passed by not less than 5/8th of the total number of members constituting the Committee for the time being, at a meeting convened for the purpose of appointing an Executive Officer, at which no other business may be transacted, within three months from the date of extension of the provisions of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931, to particular municipalities and obtain approval of Government, failing which State Government may appoint an Executive Officer for a renewable period not exceeding five years. On the other hand, in the erstwhile Pepsu territory, all appointments of Executive Officers are made by the State Government.

There is no provision regarding dismissal of an Executive Officer in either of the two aforesaid Acts. He can, however, be suspended or removed. According to the Act, applicable to the erstwhile Punjab territory, an Executive Officer may at any time be suspended or removed from office by the State Government and he shall be so suspended or removed if at a meeting of the Committee convened to consider the question of his suspension or removal not less than 5/8th of the total number of members constituting the Committee for the time being vote in favour of his suspension or removal. On the other hand in the erstwhile Pepsu territory, an Executive Officer may at any time be suspended or removed from office by the State Government suo moto on the recommendations of the Committee, if at its meeting convened to consider the question of his suspension or removal, not less than 5/8th of the total number of members constituting the Committee for the time being vote in favour of his suspension or removal.

(b) Yes. The Punjab Municipal Bill, 1963, has already been introduced in the State Legislature. With the enactment of this Bill, the Punjab Municipal Act, 1911 the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931 and the Patiala Municipal (Executive Officers) Act, 2003 B.K., will be repealed and the present institution of the Executive Officers will be replaced by the Punjab Service of Municipal Chief officers. This will bring about a uniformity and remove the distinction referred to in the entire State of Punjab comprising the territories of the erstwhile Punjab and Pepsu States.

(c) There is no such distinction.

### Land Acquired for Lassara Drain

**\*9071. Sardar Sampuran Singh Dhaula :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether compensation for the land acquired for the Lassara Drain has been paid to the farmers of villages Dhaula, Ghuns, Tapa and Draj (Tehsil Barnala) ;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor and the time by which the compensation is likely to be paid to the said farmers ;

(c) whether it is a fact that even after the acquisition of the said land, land revenue in respect thereof is being realized from the previous land owners ; if so, the reasons therefor ;

(d) whether the Government proposes to refund the land revenue so realized ?

**Chaudhri Rizaq Rom :** (a) No.

(b) (i) Paucity of funds and time taken in the completion of legal

formalities.  
(ii) By May, 1966.

[Irrigation and Power Minister]

(c) Yes. Since award for the compensation of land acquired has not been announced by the Land Acquisition Officer, and the mutation has yet to be entered and attested in favour of Government, the Revenue Department had to recover land revenue from the previous land owners.

(d) Yes. After the award is announced and mutation in favour of Government is attested. The land revenue will be either refunded or adjusted towards the land revenue payable by them for the future.

**Compensation to the Families of the Employees killed/injured  
during Indo-Pak Hostilities at Hussainiwala**

**\*9101. Comrade Gurbakhsh Singh, Comrade Babu Singh Master :** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that some employees of the Irrigation Department working at Hussainiwala were killed/injured during the recent Indo-Pak hostilities; if so the details of the special facilities and help, if any, provided to the injured and to the families of the deceased ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** Yes. Rs 1,500 as *ex-gratia* grant has been sanctioned to the widow of the deceased Sectional Officer. In addition free education of children up to the Higher Secondary has also been allowed.

Rupees 500 each as *ex-gratia* grant has also been sanctioned to two sectional Officers and one Head Jamadar who were injured.

**Hill Compensatory Allowance to Employees working at the Beas  
Dam Project**

**\*9112. Principal Rala Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the employees working at the Beas Dam Project are getting Hill Compensatory Allowance permissible to Government servants working in the hilly areas of the State ; if not, the reasons therefor ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** No. Due to grant of Project Concessions Hill Compensatory Allowance has not been granted.

**Casualty at the Pong Dam Site**

**\*9113. Principal Rala Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of casualties that have occurred at the Pong Dam Site so far and the amount of compensation, if any, sanctioned in each case ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** The total No. of casualties category-wise that have occurred at the Pong Dam Site up to 6th February, 1966 is :—

(i) Fatal Cases	..	31
(ii) Permanent disability cases	..	28
(iii) Minor injury cases	..	708

The amount of compensation sanctioned in each case is given in the enclosed appendix 'A', 'B' and 'C' respectively.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (3)25  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

APPENDIX 'A'

Statement showing names of workmen who met with fatal accidents on Beas Dam  
Unit No. II up to 6th February, 1966 and the amount sanctioned in each case

Serial No.	Name and Designation and Token No.	Amount sanctioned
	Saryshri—	Rs g
1	Gurdit Singh, C/man Spl. T. No. 166-H	.. 3,500.00
2	Dhani Ram Muckar, T. No. 452-B	.. 2,400.00
3	Asa Singh Crowbarman T. No. 54-F	.. 2,100.00
4	Charan Singh Driller T. No. 888-N	.. 7,000.00
5	Sudharam Paul, Welder, T. No. 426-H	.. 7,000.00
6	Dasondhi Ram, Driller, T. No. 144-B	.. 7,000.00
7	Charanji Lal, Mucker, T. No. 328-N	.. 4,200.00
8	Achhar Singh, Beldar, T.No. 354-L	.. 4,200.00
9	Grib Dass, Beldar T. No. 309-M	.. 3,600.00
10	Amar Singh, Driller, T.No. 196-C	.. 7,000.00
11	Shakit Chand, Beldar, T. No. 544-L	.. 3,600.00
12	Parkash Chand, Beldar, T. Mo. 420-C	.. 3,600.00
13	Roshan Lal, C/man T. No. 248-C	.. 7,000.00
14	Udam Singh, Driller, T. No. 573-Y	.. 6,000.00
15	Kehar Singh, Chargeman Misc. T. No. 62-H	.. 7,000.00
16	Faqir Singh, Chargeman Misc. T. No. 450-H	.. 7,000.00
17	Puran Chand Carpenter, T. No. 32-C	.. 7,000.00
18	Jagat Ram, Junior Mechanic, T. No. 164-L	.. 6,000.00
19	Balwant Singh, F.M. Special, T. No. 96-L	.. Compensation not admissible
20	Atma Ram, Beldar, T. No. 442-K	.. 4,800.00
21	Dip Chand, F.M. Misc. T. No. 331-H	.. 8,000.00
22	Bhunga Singh, T/Operator, T. No. 221-Y	.. 7,000.00
23	Rasila Ram, Beldar, T. No. 596-A	.. 4,800.00
24	Rattan Chand, Junior Driller, T. No. 781-Y	.. 6,000.00
25	Lal Singh, Beldar, T. No. 641-Y	.. 4,200.00
26	Baboo Ram Chowkidar, T.No. 337-K	.. 4,800.00
27	Daljit Singh, Bus Conductor, T. No. 85-N	.. Case under preparation
28	Lal Singh, Junior Tourn Operator, T. No. 173-N	.. Case under preparation
29	Tilak Raj Welder, T. No. 115-V	.. Case referred to L.R.
30	Punnu Ram, Beldar, T. No. 722-P	.. Case under preparation
31	Ishar Singh Beldar, T. No. 888-O	.. Ditto

[Minister for Irrigation and Power]

## APPENDIX 'B'

Statement showing names of workmen who met with accidents and suffered permanent disabilities as assessed by the P.M.O. and the amount of Compensation sanctioned in each case on Beas Dam Project Unit No. II

Serial No.	Name, Designation and Token No.	Amount sanctioned
	Sarvshri—	Rs
1	Mohinder Paul, Mechanic, T. No. 434-H	.. 245.00
2	Gian Singh, Greaser, T. No. 444-B	.. 2,058.00
3	Girdhan Lal, Junior Fitter, T. No. 901-A	.. 126.00
4	Nikku Ram, Beldar, T. No. 85-E	.. 2,016.00
5	Vidya Dhar, Chargeman Special, T.N.o 233-L	.. 560.00
6	Radhy Sham, Turner, T. No. 444-L	.. 2,520.00
7	Nikka Ram, Welder, T. No. 171-L	.. 2,100.00
8	Trilochan Singh, Mechanic, T. No. 312-L	.. 882.00
9	Hari Singh, Junior Driller, T. No. 255-N	.. 5,040.00
10	Mohnga Ram, Mason, T. No. 179-G	.. 3,920.00
11	Dalip Chand, Carpenter, T. No. 310-C	.. 1,764.00
12	Karam Chand, Beldar, T. No. 771-C	.. 1,293.00
13	Onkar Singh, Driller, T. No. 199-C	.. 392.00
14	Anant Ram, Crano Operator, T. No. 297-L	.. 490.00
15	Resham Chand, Driver, T. No. 712-C	.. 686.00
16	Partap Singh, Beldar, T. No. 428-C	.. 2,940.00
17	Kartar Singh, Driller, T. No. 186-C	.. 3,920.00
18	Paras Ram, Junior Fitter, T. No. 77-K	.. 504.00
19	Salig Ram, Mucker, T. No. 65-N	.. 2,352.00
20	Baldev Raj, Junior Driller, T. No. 793-Y	.. 2,520.00
21	Brij Lal Beldar, T. No. 127-G	.. 1,176.00
22	Lachmi Narain, Chargeman Misc. T. No. 76-H	.. 2,940.00
23	Kishori Lal Mucker, T. No. 690-C	.. 201.60
24	Mohinder Singh, Chargeman, Special, T. No. 98-C	.. 3,360.00
25	Hans Raj, Junior Driller, T. No. 124-Y	.. 1,344.00
26	Makholi Ram, Beldar, T. No. 44-C	.. 1,176.00
27	Ram Asra, Junior Driller, T. No. 647-Y	.. Case referred to L.R.
28	Karam Singh, Driller, T. No. 739-X/307-V	.. Case under preparation

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (3)27  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45  
ANNEXURE 'C'

**Statement showing minor accident cases occurred up to 6th February, 1966 on Beas Project Unit No. II**

708 cases. Special leave is granted under rule 8.146(2) of C.S.R. Vol. I Part I in temporary disability case.

**Construction of Houses in Talwara Township Periphery Area**

**\*9114. Principal Rala Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the rules that regulate the construction of private houses within the periphery of the Talwara Township ;
- (b) the number of plans so far submitted by private persons for sanction for the construction of residential or business premises in the said area and the number of cases in which necessary sanction has been accorded ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) A copy of rules is placed at the Table of the House.

(b) During—

1962-63	..	4 Nos.
1963-64	..	85 "
1964-65	..	14 "
1965-66	..	5 "

No permission has been granted by the Project Administration to any individual because under the periphery Control Act, the sanction has to be granted by the Deputy Commissioner, Hoshiarpur.

[Published in the Punjab Government Gazette, Legislative Supplement Ordinary, dated the 17th August, 1962]

**PART III**

**IRRIGATION DEPARTMENT**

**BEAS PROJECT ADMINISTRATION**

The 26th/28th June, 1962

**No. G.S.R.128/P.A.34/61/S.16/62.**—With reference to the Punjab Government, Irrigation Department, notification No. G.S.R.69/PA-34/61/S.16/1962, dated 2nd May, 1962 and in exercise of the powers conferred by section 16 of the Talwara Township (Periphery) Control Act, 1961 the Governor of Punjab is pleased to make the following rules, namely :—

**RULES**

**1. Short Title.**—These Rules may be called the Talwara Township (Periphery) Control Rules, 1962.

**2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Talwara Township (Periphery) Control Act, 1961 ;
- (b) "Applicant" means a person who makes an application to the Deputy Commissioner under sub-section (1) of section 6 of the Act ; and
- (c) "Form" means form appended to these Rules.

**3. Sections (2), 16(1) Manner of Publication of notification of controlled area.**—The notification under sub-section (2) of section 3 of the Act shall be displayed on the notice

[Minister for Irrigation and Power]

board outside the office of the Deputy Commissioner and all the Panchayat Houses and Patwar Khanas in the controlled area. A general proclamation shall also be made by beat of drum in all the villages situated in the controlled area and affected by the notification.

4. *Sections 6(1) and 16(2) (b) Form of application.*—(1) Every application referred to in sub-section 6 of the Act shall be in Form 'A'. It shall be submitted, in duplicate, duly signed by the applicant or his legally authorised agent or attorney and shall be accompanied by a site plan showing according to the revenue record, the situation of the land on which the proposed erection or re-erection of any building or excavation or extension of any excavation, or laying out of any means of access to a road, is desired. Where permission is sought for the erection or re-erection of any building application shall also be accompanied by a building plan of the proposed erection or re-erection.

(2) The Deputy Commissioner may decline to accept an application which is not made in accordance with the provisions of sub-rule (1).

5. *Sections 6(1), 16(1) and 16(2). (b) Fresh application to be made if previous permission lapse and form of plan.*—(1) If the building is not erected or re-erected or an excavation is not made or extended or an access to a road is not laid out within six months of the date of the permission, permission shall be deemed to have lapsed in respect of such portion of the building or excavation or layout which has not been completed and for that portion a fresh application shall have to be made under rule 4.

(2) The plan deposited under sub-section (1) of section 4 of the Act shall indicate clearly the name of each village situated in the controlled area and specify the nature of restrictions applicable to such area.

6. *Section 6(2) and 16(1). Procedure to be observed before passing order under section 6(2), section 16(2)(e). Principles for grant and refusal of permission.*—Before passing final orders under sub-section 2 of section 4 of the Act, the Deputy Commissioner shall forward the application alongwith the plan submitted under rule 4 to the General Manager, Beas Project for comments, if any.

7. (1) The Deputy Commissioner may take into consideration the following principles and conditions under which applications for permission to erect or re-erect any building or make or extend any excavation or layout any means of access may be granted or refused, namely :—

- (i) the proposal will not produce unhygienic conditions ;
- (ii) there exist adequate arrangements for disposal of sullage waste and rain run off ;
- (iii) the proposal will not interfere with any natural drainage ;
- (iv) the proposal will not interfere with any new development work proposed to be undertaken by the Government ;
- (v) the proposal will not mar the general landscape ;
- (vi) the proposed erection or re-erection of any building shall conform to the building bye-laws in force at that time ; and
- (vii) the proposal is not prejudicial to public interest.

(2) The Deputy Commissioner shall refuse to grant permission to the laying out of means of access to a road, if—

- (a) the width of the means of access proposed to be laid out exceeds twenty feet ;  
or
- (b) its construction prejudicially affects any grave-yard, cremation ground, place of Worship, cenotaph or Smadhi.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (3)29  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

8. *Section 6(3) and 16(1). Form of communication of order.*—The order passed by the Deputy Commissioner under sub-section (2) of section 6 of the Act shall be communicated to the applicant in Form 'B'.

9. *Section 6(7) and 16(1). Form of register.*—The register, required to be maintained under sub-section (7) of section 6 of the Act shall be in Form 'C'.

10. (1) Every person desiring to use any land for the purpose of a charcoal kiln, pottery kiln, lime kiln, brick kiln or a brick field shall make any application to the Deputy Commissioner in Form 'D' and shall furnish the following particulars :—

- (a) a complete description of the land in which the kiln is proposed to be established with the name of the revenue estate in which the land is situated and the field number according to the latest revenue records and maps ;
- (b) the number and nature of kilns which are proposed to be set up on the land and the location of each ;
- (c) the total period for which the land is expected to be in use ;
- (d) the total number of labourers likely to be employed at the kiln and the sanitary and house arrangements proposed to be made for them ; and
- (e) any other information which the Deputy Commissioner may require to be furnished.

(2) Before passing an order on any application the Deputy Commissioner may make or cause to be made such enquiry as he considers necessary.

(3) The Deputy Commissioner shall refuse to grant a licence :—

- (a) for the establishment of any kiln within a distance of one hundred yards from the outer boundary of any public road ; or
- (b) if the land on which it is proposed to establish the brick field is, in his opinion, in undue proximity to any inhabited site or any site which is likely to become inhabited ; or
- (c) for any other reasons which seem to him just and sufficient.

(4) Every licence granted under section 11 of the Act shall be in Form 'F'.

11. *Sections 11 and 16(2)(d). Renewal and revocation of licences.*—Every licence granted under section 11 shall be valid for a period of one year from the date of issue subject to renewal by the Deputy Commissioner, from time to time, for a further period of one year : Provided that the D.C. may at any time revoke the licence if the licence violates any of its conditions.

12. (1) The following fees shall be charged for licences issued under section 11 of the Act :—

(a) For the initial grant of licence for—

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| (i) a brick field including not more than one brick of standard size                | Rs 40 per year             |
| (ii) a charcoal kiln  | .. Rs 10 per year          |
| (iii) a pottery kiln  | .. Rs 50 per year          |
| (iv) a lime kiln  | .. Rs 25 per year          |
| (b) Additional fee payable for every additional kiln after the first                | Half the fees as (a) above |
| (c) Additional fee payable in respect of any brick kiln which exceeds standard size | Rs 20 per year             |

## [Minister for Irrigation and Power]

- (d) For the renewal of the same for each year of : Half the above fees  
renewal

*Explanations.*—For the purpose of this rule a “brick-kiln of standard size” means a brick-kiln containing not more than thirty-two chambers each capable of burning twenty-five thousand bricks at one loading.

- (2) The fees prescribed in sub-rule (1) shall be deposited in the Treasury Challan as a proof of such deposit.

Provided that if the grant or the renewal of the licence is refused half the fee paid by the applicant shall be refunded.

- (3) If an additional kiln is installed or any existing kiln is made to exceed the standard size during the period of validity of licence of an existing kiln, the additional fee shall cover the unexpired period of validity and fresh additional fee will be payable after the expiry of that period.

- (4) Application for the renewal of licence shall be made to the Deputy Commissioner not less than one month before the date of expiry of the licence. If the application for renewal is not made within the time prescribed above the fee for renewal of licence shall be the same as for a new licence.

## FORM ‘A’

(See rule 4)

**Application under sub-section (1) of section 6 of Talwara Township (Periphery)  
Control Act, 1961**

To

The Deputy Commissioner/

Sir,

I/We request for permission to—

- (i) erect or re-erect a building ;
- (ii) make or extend any excavation ;
- (iii) lay out means of access to a road in the controlled area.

2. The required particulars are given below :—

- (i) Name of the applicant (in block letters)
- (ii) Father's name.
- (iii) Village.
- (iv) Hadbast No.
- (v) Tehsil.
- (vi) Khasra No.
- (vii) Area.

Bounded by—

- East.
- West.
- North.
- South.

- (viii) Purpose for which the building/wall/road/excavation is to be used.

3. I enclose the following documents in duplicate ;—

- (a) Site plan showing therein the existing structure, if any, and also the situation of the land on which the proposed erection or re-erection or excavation or extension of any excavation or laying out of any means of access to a road, is desired.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (3)31  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(b) The building plan, elevation and sections.

Signature of applicant.

I solemnly affirm that the above particulars are correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of applicant.

ATTESTED

OATH COMMISSIONER OR  
MAGISTRATE, 1ST CLASS.

---

\*Strike out which is not required.

FORM 'B'

[See rule 6(1)]

Form for the grant or refusal of permission under section 6 (2) of Talwara Township  
(Periphery) Control Act, 1961

No.

From

Deputy Commissioner.

To

Shri/Sarvshri \_\_\_\_\_

Dated, \_\_\_\_\_ the \_\_\_\_\_.

MEMORANDUM—

Reference your application, dated \_\_\_\_\_ for permission to—

(a) erect or re-erect a building ;

(b) make or extend any excavation ;

(c) lay out means of access to a road ; in the controlled area of village \_\_\_\_\_,  
HadBast No. \_\_\_\_\_, tehsil \_\_\_\_\_,  
district \_\_\_\_\_, as indicated in the site plan submitted  
therewith.

2. Permission is hereby,—

(a) granted subject to the following conditions,—

(i)

(ii)

(iii)

(b) refused for the reasons,—

(i)

(ii)

3. A copy of site plan/building is returned duly approved/rejected.

Deputy Commissioner,

**FORM 'C'**

(See rule 7)

**Form of register to be maintained under sub-section (7) of section 6 of the Talwara Township (Periphery) Control Act, 1961**

- (1) Serial No.
- (2) Date of receipt.
- (3) Name and particular of the applicant.
- (4) Description of the land or site or building.
- (5) Village.
- (6) Tehsil and District.
- (7) Condition of property and its use on the date of notice under section 3(2).
- (8) Purpose for which permission is required.
- (9) Number and date of order.
- (10) Permission granted/refused with conditions/grounds of grant/refusal.
- (11) Orders in appeal if, any.
- (12) Remarks.

**FORM 'D'**

[See rule 8(1)]

**Application for licence to establish and operate a charcoal-kiln/pottery-kiln/brick-kiln/  
lime-kiln/or brickr-field**

To

The Deputy Commissioner,

Sir,

In pursuance of the provision of sub-section (1) of section (11) of the Talwara Township (Perihery) Control Act, 1961, I/we hereby apply for licence, under the said Act and the rules framed thereunder, to establish and operate a charcoal-kiln/pottery-kiln/brick-kiln/lime-kiln/brick-field, in the locality specified below.

2. A sum of Rs—————being fee for the licence desired, has been deposited by me in Treasury under the head—————and a receipted copy of the Treasury Challan is enclosed.

Yours faithfully,

(Signature of applicant).

(3)33

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Particulars (full name, parentage, etc.) and full address of the applicant

---

If the applicant is a company or firm or if the applicant proposes to operate the kiln/brick-field through an agent give the name (with full particulars and address) of the Managing Director, agent or other person who will be directly in-charge of the kiln/brick-field

---

Kiln/brick-field is proposed to be established

---

Revenue Estate	Field	(Khasra Nos. indicate whether the whole of each field will be included or part only)
Total		

---

Number of kilns proposed to be set up in the said area with the location and capacity of each

---

Depth of the excavation in case of brick-field

---

Period for which it is expected that the land will be in use for the kilns

---

Number of labourers likely to be employed and the arrangements proposed for their housing and sanction

---

(Signature of applicant).

**FORM 'E'**

[See rule 8(4)]

**Licence to establish and operate a charcoal-kiln/pottery-kiln/brick-kiln/lime-kiln/brick-field**

In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 11 of the Talwara Township (Periphery) Control Act, 1961, the licence is granted to \_\_\_\_\_ under the Talwara Township (Periphery) Control Act, 1961, to establish and operate a charcoal-kiln/pottery-kiln/lime-kiln/brick-kiln in the said land hereinafter described subject to the condition set forth on the reverse of this licence.

2. Unless renewed, this licence shall cease to be valid after one year from the date of issue.

Name of village.

Signature of the Deputy Commissioner

Khasra No.

Area.

**(REVERSE)***Conditions*

1. The holder of the licence shall—
  - (a) provide adequate and suitable accommodation for the labourers working at the kilns or the brick-fields.
  - (b) make arrangements for supply of wholesome water for drinking and other domestic purposes ;
  - (c) provide sufficient and suitable latrines and urinals for the labourers and adequate staff of sweepers, at a minimum rate of one for every hundred labourers to attend to conservancy arrangements ; and
  - (d) not begin the work in the brick-field until the above requirements have been complied with to the satisfaction of the Deputy Commissioner and a certificate to this effect obtained from him.
2. The holder of the licence shall not permit any person suffering from any contagious or infectious disease to enter or be present in the licensed kiln or brick-field.
3. No excavation shall be made in any kiln or part of the brick-field to a depth of more than five feet below the surface level whether for the removal of clay to be used for making bricks or for any other purposes.
4. The holder of the licence shall comply with all directions which may be given by the Deputy Commissioner in writing for the regulation of excavation and the provisions of proper drainage or with a view to ensuring that rain or flood water shall collect at one place or in the kiln or the brick-field instead of a number of places and on completion of operation shall remove all structure and level, dress and tidy the site to the satisfaction of the Deputy Commissioner.
5. The whole of the brick-field area shall be open at all times to inspection by the Deputy Commissioner or any official deputed by him for this purpose on his behalf.
6. The grant of licence is subject to the condition that a licence under the East Punjab Control of Brick Supplies Act, 1949, is obtained from the Industries Department.

**R. S. GILL,**  
Secretary to Government, Punjab,  
Irrigation Department.

---

**Height of the outlets on certain Canals in District Hissar**

**\*9171. Chaudhri Net Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether he received any complaint during the period from July, 1965 to September, 1965 to the effect that the height of the outlets on certain canals in district Hissar has been raised to such an extent that the water is not flowing through the said outlets due to low water-level in the canals ;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the action taken thereon so far and the result thereof ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Yes.

(b) Some of the outlets have been set right and the remaining are being adjusted.

**Draining out Rain/Flood Water from certain villages in tehsil and district  
Rohtak**

**\*9161. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of the Government for draining out rain and flood waters from villages Dhamarh, Larhote, Makrauli Kalan and Khurd ; in tehsil and district Rohtak ; if so, the time by which it is proposed to be implemented ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** Yes. These villages are to be served by Makrauli drain proposed to be constructed by voluntary labour but the outfall of this field drain is into Jassia drain. The work on Jassia drain was started but was stopped on account of stay orders received from the Punjab High Court. Alignment Plan and long section for Makrauli field drain will be supplied to Deputy Commissioner as soon as the outfall conditions permit.

**Morkhi Minor**

**\*9186. Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government has recieved any representation from the residents of village Gangoli and other villages in tehsil Jind in connection with the change of the head of the Morkhi Minor on the ground that the Minor is not getting from the present head full discharge of water ; if so, the details of the action taken thereon and the time by which the said head is likely to be changed ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** Yes. The matter is under investigation. It will be finalized shortly.

**Elections of Directors of Haryana Co-operative Sugar Mills,  
Rohtak**

**\*9005. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the elections of the Directors of the Haryana Co-operative Sugar Mills at Rohtak fixed for 16th January, 1966, have been postponed, if so, when and the reasons therefor ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** Yes, on 13th January, 1966, due to the mourning period connected with the sad demise of the Late Shri Lal Bahadur Shastri.

**Harijan Colony for Dharamkot, district Ferozepore**

**\*8888. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that a Harijan Colony was sanctioned by the State Government for Dharamkot, district Ferozepore ;
- (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the date on which the sanction for the said Harijan Colony was accorded and a copy of the relevant order be laid on the Table of the House ;
- (c) the total number of quarters approved for the said Colony ;
- (d) whether the Colony referred to in part (a) above has come into existence ; if so, the total number of quarters constructed therein and the time by which the remaining quarters are likely to be completed ?

**Shri Chand Ram ;** (a) Yes.

(b) 31st March, 1964. A statement is laid on the Table of the House.

(c) Fifteen.

(d) No. The sites already purchased are likely to be changed due to consolidation operation there.

## [Minister for Welfare and Justice]

Copy of Memo No. A/3/H-(5/62-64/10261, dated the 31st March, 1964, from the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, Punjab and to the address District Welfare Officer, Ferozepore.

**Subject.**—Construction of houses for Sweepers,—1963-64.

The Punjab Government,—*vide* their Memo No. 353-WGI-ASO-2-64, dated 25th March, 1964. have approved the following place (s) for construction of house colonies during—

Serial No.	Name of place	Tehsil	No. of houses
1	Dharamkot	.. Zira	.. 15

The list of beneficiaries as recommended by the District Ad hoc Committee copy enclosed is hereby approved. The amount of Rs 11,250 on account of subsidy for the construction of new houses—Rs 750 each is being drawn and remitted to you separately by means of R. T. Rs in the name of beneficiaries.

The following directions should be strictly complied with :—

After getting necessary agreement, surety bonds and receipt etc., the amount of R. T. Rs. should be deposited in the Central Co-operative Bank on behalf of the beneficiaries, in a joint account duly pledged to the Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, Punjab, in accordance with the terms of resolution sent,—*vide* endorsement No. A/1/Aud/A/21095, dated 30th July, 1967

(2) The account should be operated upon by the District Welfare Officer and representative Committee.

(3) The amount should be withdrawn from the bank in three instalments of Rs 140, Rs 400 and Rs 210 per beneficiary on receipt of release authority from this office which should be applied for well in time.

(4) Before allowing construction, it would be ensured that the beneficiaries hold undisputed of the sites.

(5) The houses should be built according to the standard design and in the form of a colony.

(6) The payees receipts should please be forwarded to this office for transmission to the Accountant-General, Punjab, Simla.

Please supervise the actual implementation of the scheme as heretofore and send the completion certificate in due course.

RECOMMENDATION FOR HOUSING SCHEMES FOR SWEEPERS, DISTRICT  
FEROZEPORE  
1963-64

Serial No.	Name and parentage	Caste	Village	Tehsil	Amount
1	Jasmer Singh, son of Sardara Singh	Balmiki	Dharamkot	Zira	Rs. 750
2	Mehar Singh, son of Dara Singh	Do	Do	Do	750

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (3)37  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

S. No.	Name and parentage	Case	Village	Tehsil	Amount
3	Inder Singh, son of Khaira Singh	Balmiki	Dharamkot	Zira	Rs. 750
4	Sarwan, son of Ishar	Do	Do	Do	750
5	Kehar Singh, son of Sardara Singh	Do	Do	Do	750
6	Darwara Singh, son of Badan Singh	Do	Do	Do	750
7	Jagga Singh, son of Chanda	Do	Do	Do	750
8	Fakir, son of Bachana	Do	Do	Do	750
9	Tirath Ram, son of Ishar Ram	Do	Do	Do	750
10	Teja, son of Chanda	Do	Do	Do	750
11	Ram Parkash, son of Waspkha Ram	Do	Do	Do	750
12	Telu Ram, son of Amin Chand	Do	Do	Do	750
13	Gindo, son of Jaila	Do	Do	Do	750
14	Rounki Ram, son of Soba Ram	Do	Do	Do	750
15	Smt. Nand Kaur, widow of Inder	Do	Do	Do	750
				Total	11,250

(Sd.) . . . .

District, Welfare of Scheduled Castes  
and Backward Classes, Punjab.

**Harijan Colony for Village Kanwan in Dharamkot Block, District Ferozepore**

**\*8889. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- (a) whether any Harijan Colony has been sanctioned for village Kanwan in Dharamkot Block of district Ferozepore ;
- (b) the date on which and the order under which sanction for the Colony referred to in part (a) above was accorded and a copy of the said order be laid on the Table of the House ;
- (c) the total number of quarters sanctioned for the said Colony and of those which have been constructed so far ;
- (d) the time by which the construction of the remaining quarters is likely to be completed ?

**Shri Chand Ram (a) No.**

**(b), (c) and (d) Does not arise.**

**Divisional Welfare Officers**

**\*8966. Lieut. Bhag Singh :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- (a) the number of Divisional Welfare Officers (Scheduled Castes) in the State at present ;
- (b) the difference in the scales of pay of the Divisional Welfare Officers and the District Welfare Officers (Scheduled Castes) ?

**Shri Chand Ram :** (a) and (b) There is no post of Divisional Welfare Officer (Scheduled Caste). However, there are Regional Welfare Officers in the scale of Rs 170—10—350 *plus* a special pay of Rs 20 per mensem. District Welfare Officers are also in the same scale. They are not allowed special pay.

Out of three Regional Welfare Officers one belongs to Scheduled Castes.

**Grants and Loans to Harijans in Jullundur and Hissar Districts**

**\*9078. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state the total amount of grants/loans given by the Harijan Welfare Department to the Harijans in Jullundur and Hissar Districts from July, 1964 to date for different purposes stating the name and address of each beneficiary/loanee together with the amount received by each ?

**Chaudhri Chand Ram :** A statement is laid on the Table of the House.

**NAME OF PERSONS SETTLED ON LAND IN DISTRICT HISSAR AFTER  
JULY, 1964 TODATE MENTIONING THE AMOUNT GIVEN TO EACH  
ONE OF THEM**

S erial No.	Name and parentage of the beneficiary	Address	Amount given	
			Land Subsidy	Houses/ Wells Subsidy
			Rs	
1	Shri Bhogal, son of Shoe Chand	V. and P. O. Bamla, tehsil Bhiwani	2,000	..
2	Shri Ramji Lal, son of Girdhari	V. and P. O. Bhiwani, tehsil Bhiwani	2,000	..
3	Shri Ram Saroop, son of Chhottu	V. and P. O. Bansawan, tehsil Bhiwani	2,000	..
4	Shri Samat Ram, son of Udmi Ram	V. and P. O. Bhatoli, tehsil Bhiwani	2,000	..
5	Shri Dewan Chand, son of Matu Ram	V. and P. O. Puranpur, tehsil Bhiwani	2,000	..
6	Shri Phul Singh, son of Chhottu	V. and P. O. Kheri, tehsil Hansi	2,000	..
7	Shri Ajit Singh, son of Bura Singh	V. and P. O. Balaili, tehsil Fatiabad	2,000	..

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (3)39  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Serial No.	Name and parentage of the beneficiary	Address	Amount given	
			Land Subsidy	Houses/wells Subsidy
			Rs	
8	Shri Shankar, son of Chander	V. and P. O. Kheddar, tehsil Hissar	2,000	..
9	Shri Munshi Ram, son of Nathu	V. and P. O. Hissar, tehsil Hissar	2,000	..
10	Shri Piyarelal, son of Budh Ram	V. and P. O. Mita Thal, tehsil Bhiwani	2,000	..
11	Shri Shanker, son of Amir Chand	V. and P. O. Mangali, tehsil Hissar	2,000	..
12	Shri Sampuran Singh, son of Kher Singh	V. and P. O. Jalansala, tehsil Sirsa	2,000	..
13	Shri Karnail Singh, son of Babal Singh	V. and P. O. Dabawali, tehsil Sirsa	2,000	..
14	Shri Lilu Ram, son of Neki Ram	V. and P. O. Dinod, tehsil Bhiwani	2,000	..
15	Shri Faqir Chand, son of Khaki Ram	V. and P. O. Bhiwani, tehsil Bhiwani	2,000	..
16	Shri Kishan Singh, son of Jhanda Singh	V. and P. O. Mohdpur Rohi, tehsil Fatiabad	2,000	..
17	Shri Chandgi Ram, son of Nanda Ram	V. and P. O. Bass, tehsil Hansi	2,000	..
18	Shri Nathu, son of Gugan	V. and P. O. Dahina, tehsil Hissar	2,000	..
19	Shri Sheo Chand, son of Nand Ram	V. and P. O. Fatiabad, tehsil Fatiabad	2,000	..
20	Shri Bhagwana, son of Manohar	V. and P. O. Nirauli Kalan, Hissar	2,000	..
21	Shri Bakhtawar, son of Gugan	V. and P. O. Bhagana, tehsil Hissar	2,000	..
22	Shri Moji Ram, son of Karam Chand	V. and P. O. Bhiwani, tehsil Bhiwani	2,000	..
23	Shri Risala, son of Kanhaya	V. and P. O. Maugali, tehsil Hissar	2,000	..
24	Shri Jug Lal, son of Khubi Ram	V. and P. O. Lehga, tehsil Bhiwani	2,000	..
25	Shri Baldeva, son of Sheo Ram	V. and P. O. Kharkra, tehsil Hansi	2,000	..

Serial No.	Name and parentage of the beneficiary	Address	Amount given	
			Land Subsidy	Houses/wells Subsidy
			Rs	
26	Shri Lachman, son of Mat Ram	V. and P. O. Jhandli, tehsil Fatiabad	2,000	..
27	Shri Ballu Ram, son of Maugla Ram	V. and P. O. Bhodia Khera, tehsil Fatiabad	2,000	..
28	Shri Man Chand, son of Shanker	V. and P. O. Hajhinpur, tehsil Hansi	2,000	..
29	Shri Jogi Ram, son of Amin Lal	V. and P. O. Majra, tehsil Hansi	2,000	..
30	Shri Lehri Singh, son of Piru Ram	V. and P. O. Khauda Khere, tehsil Hansi	2,000	..
31	Shri Banwari, son of Mula	V. and P. O. Khakhera, tehsil Hansi	2,000	..
32	Shri Mool Chand, son of Inderaj	V. and P. O. Jaokalan, tehsil Bhiwani	2,000	..
33	Shri Risala, son of Mansukh	V. and P. O. Sheikhpura, tehsil Hansi	2,000	..
34	Shri Maugla, son of Deva Ram	V. and P. O. Bodan, tehsil Fatiabad	2,000	..
35	Shri Budh Ram, son of Jee Ram	V. and P. O. Dabra, tehsil Hissar	2,000	..
36	Shri Joginder Singh	V. and P. O. Churri Bagauan, Tehsil	2,000	..
37	Shri Roop Chand, son of Chandgi Ram	V. and P. O. Bidnoi, tehsil Bhiwani	2,000	..
38	Shri Kishan Singh, son of Ghanda Singh	V. and P. O. Sayana, tehsil Fatiabad	2,000	..
39	Shri Bir Singh, son of Bhangala Singh	V. and P. O. Dabawali, tehsil Sirsa	2,000	..
40	Shri Baldev Singh, son of Molar	V. and P. O. Rakhi Shahpur	2,000	..
41	Shri Pala, son of Pokhar	V. and P. O. Bhiwani, tehsil Bhiwani	2,000	..
42	Shri Om Parkash, son of Matu Ram	V. and P. O. Lohani, tehsil	2,000	..
43	Shri Jugla, son of Shanker	V. and P. O. Bhiwani, tehsil Bhiwani	2,000	..
44	Shri Zila Singh, son of Rur Singh	V. and P. O. Dabawali, tehsil Sirsa	2,000	..

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (3)41  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Serial No.	Name and parentage of the beneficiary	Address	Amount given	
			Land Subsidy	Houses wells Subsidy
			Rs	
45	Shri Chhanoo Ram, son of Dosha Ram	V. and P. O. Sheiripura, tehsil Hansi	2,000	..
46	Shri Ajmer Singh, son of Jiroan Singh	V. and P. O. Lehri, tehsil Hissar	2,000	..
47	Shri Ganga Ram, son of Kanshi Ram	V. and P. O. Jammami, tehsil Fatiabad	2,000	..
48	Shri Gurdial Singh, son of Dittoo Singh	V. and P. O. Tigri ..	2,000	..
49	Shri Jawala Pershad ..	V. and P. O. Prem Nagar	2,000	..
50	Shri Nihala, son of Mehar Chand	V. and P. O. Kapro, tehsil Bhiwani	2,000	..
51	Shri Jai Karan, son of Jhanda	V. and P. O. Biran ..	2,000	..
52	Shri Bichha Ram, son of Hirdoo	V. and P. O. Prabhuwala, tehsil Hissar	2,000	..
53	Shri Phool Chand, son of Jogi Ram	V. and P. O. Prabhuwala, tehsil Hissar	2,000	..
54	Shri Santa Singh, son of Nanak Singh	V. and P. O. Fatiabad, tehsil Fatiabad	2,000	..
		Total	.. 1,08,000	..

LIST OF PERSONS WHO WERE GIVEN SUBSIDY UNDER HOUSING SCHEME  
AFTER JULY TO DATE DISTRICT HISSAR HOUSING FOR OTHER  
THAN THOSE ENGAGED ON UNCLEAN OCCUPATION

Serial No.	Name and parentage	Address	Amount given
			Rs
1	Nand Singh, son of Mohan Singh	V. and P. O. Rori, tehsil Sirsa	900
2	Prem Singh, son of Dalip Singh	Ditto ..	900
3	Mangtu Ram, son of Mangal Ram	V. and P. O. Vedwala, tehsil Sirsa	900
4	Lekhu Ram, son of Malla ..	V. and P. O. Saharwa, tehsil Hissar	900
5	Mange Ram, son of Turtia ..	Ditto ..	900
SWEEPERS HOUSES			
6	Mola Ram, son of Khubi ..	V. and P. O. Umra, tehsil Hansi	900
7	Sanbi, son of Hardwari ..	V. and P. O. Sheikhpura, tehsil Hansi	900

Serial No.	Name and parentage	Address	Amount given
8	Binarsi Das, son of Hardawari ..	V. and P. O. Hansi, tehsil Hansi	900
9	Ram phal, son of Risal Singh ..	V. and P. O. Mirachpur, tehsil Hansi	900
10	Surjan, son of Jawahara Ram ..	V. and P. O. Hissar ..	900
11	Mohan Lal, son of Mohar Singh	V. and P. O. Bhiwani, Ashok Colony	900
12	Kartar, son of Sadhoo Ram ..	V. and P. O. Halwas, tehsil Bhiwani	900
13	Puran Lal, son of Ramji Lal ..	Ditto ..	900
14	Panna Lal, son of Gulzari Lal ..	V. and P. O. Kalanwali, tehsil Sirsa	900
15	Changgi Ram, son of Thawaria	Ditto ..	900
16	Rajila, son of Chandgi Ram ..	V. and P. O. Mirachpur, tehsil Hansi	900
17	Rugha Ram, son of Kirpa ..	V. and P. O. Hissar ..	900
HOUSES FOR THOSE ENGAGED ON UNCLEAN OCCUPATION			
18	Madho, w/o Teka Ram ..	V. and P. O. Miranpur, tehsil Hansi	900
19	Darya Singh, son of Mehar Chand	V. and P. O. Kinar, tehsil Hansi	900
20	Parbhu, son of Pinni Ram ..	V. and P. O. Kani Kheri, tehsil Hansi	900
21	Ram Kishan, son of Lehari Singh	Ditto ..	900
22	Faqir Chand, son of Kurra Ram	V. and P. O. Hissar, tehsil Hissar	Rs 900
23	Atali Ram, son of Binigha Ram ..	Ditto ..	900
24	Phula Ram, son of Misra ..	Ditto ...	900
25	Abhey Ram, son of Khubi Ram	Ditto ..	900
26	Banwar Lal, son of Sohan Lal ..	V. and P. O. Mangal Jaharan, tehsil Hissar	900
27	Sucha Sngn, son of Lekh Ram ..	V. and P. O. Tohana, tehsil Hissar	900
28	Mangur Ram, son of Bakhtawar	V. and P. O. Hissar ..	900
VIMUKAT JATIS HOUSES			
29	Kartar Singh, son of Khem Singh	V. and P. O. Mohmadpur Rahi, Tehsil Fatiabad	900

Serial No.	Name and parentage	Address	Amount given
			Rs
30	Ram Singh, son of Anup Singh .. V and P.O. Mohamdpur Rohi, Tehsil Fatiabad	Ditto ..	900
31	Jai Singh, son of Fateh Singh ..	Ditto ..	900
32	Chet Singh, son of Hira Singh ..	Ditto ..	900
33	Parap Singh, son of Santa Singh	Ditto ..	900
34	Nand Lal, son of Shanker ..	Village Bran, P. O. Noongarh, tehsil Bhiwani	900
35	Nahia, w/o Nahar ..	Village Biran, P. O. Noongarh, tehsil Bhiwani	900
36	Shispal, son of Singh Ram ..	V. and P. O. Kairoo, tehsil Bhiwani	900
	Total		32,400

NAMES AND ADDRESSES OF PERSONS WHO WERE GIVEN INTEREST FREE LOAN AFTER JULY, 1964 TO DATE IN DISTRICT HISSAR

Serial No.	Name and parentage of the beneficiary	Address	Amount
			Rs
1	Kanhaya Lal, son of Kalu Ram ..	V. and P. O. Tigrana Gujran, tehsil Bhiwani	400
2	Karam Chand, son of Tola Ram	V. and P. O. Dhani Gopal, tehsil Faridabad	400
3	Parbhati, son of Gopal Ram ..	V. and P. O. Kherwala, tehsil Sirsa	450
4	Banwari, son of Budh Ram ..	V. and P. O. Singhnani, tehsil Bhiwani	450
5	Bajrang Lal, son of Mangtu Ram	V. and P. O. Bhiwani, tehsil Bhiwani	400
6	Jai Lal, son of Rura ..	V. and P. O. Hissar, tehsil Hissar	400
7	Mangat, son of Mai Ram ..	V. and P. O. Kanda Kheri, tehsil Hansi	400
8	Nathu, son of Kahnava ..	Telu, tehsil Hansi ..	350
9	Karnail, son of Hazara Singh ..	Rori, tehsil Sirsa ..	400
10	Bachan Singh, son of Babu Singh	Rori, tehsil Sirsa ..	400
11	Hari Singh, son of Gullo Singh ..	Rori, tehsil Sirsa ..	400
12	Har Chand, son of Baggar ..	Kanheri, tehsil Hissar ..	400
13	Karam Chand, son of Nandu ..	Hissar, tehsil Hissar ..	400
14	Chandgi, son of Buja Ram ..	Dhani Mirdad, tehsil Hissar ..	400

Serial No.	Name and parentage of the beneficiary	Address	Amount
15	Lal Chand, son of Tirkha Ram ..	Dhani Mirdad, Tehsil Hissar ..	Rs 400
16	Santa Ram, son of Ami Lal ..	Ladwa, tehsil Hissar ..	500
17	Nanku, son of Millo ..	Dhani Mirdad, tehsil Hissar ..	400
18	Chhotu, son of Harnam ..	Kanhere, tehsil Hissar ..	450
19	Dalip Ram, son of Kirpa Ram ..	Babuna, tehsil Fatiabad ..	500
20	Moola Ram, son of Shoeji Ram ..	Fatiabad, tehsil Fatiabad ..	500
21	Ram Saroop, son of Salig Ram ..	Bhiwani, tehsil Bhiwani ..	400
22	Badloo Ram, son of Karmoo Ram ..	Narnaud, tehsil Hansi ..	500
23	Chhottu, son of Sheo Nath ..	Thurana, tehsil Hansi ..	500
24	Asha Ram, son of Net Ram ..	Milkpur, tehsil Hansi ..	500
25	Sorte, son of Daya ..	Sheikhpur, tehsil Hansi ..	400
26	Har Chand, son of Deotia ..	Mirchpur, tehsil Hansi ..	500
27	Dhoop Singh, son of Moller ..	Raman, tehsil Hansi ..	500
28	Sangh Singh, son of Hazura Singh ..	Rori, tehsil Sirsa ..	400
29	Parbhat Chand, son of Talu Ram ..	Bhiwani, tehsil Bhiwani ..	500

**Recommendation and amount paid under Housing Scheme Vimukat Jatis, 1964-65, District Jullundur**

Serial No.	Name and Parentage	Caste	Village	Tehsil	Amount
1	2	3	4	5	6
1	Ferozo, son of Chanan Ram ..	Barar	Mehtpur	Nakodar	Rs 900
2	Chanan, son of Ghulauri ..	Do	Do	Do	900
3	Ram Lal, son of Chanan ..	Do	Do	Do	900
4	Buta Ram, son of Chanan Ram ..	Do	Do	Do	900
5	Rajoo, son of Chaman ..	Do	Do	Do	900
6	Lakhu, son of Kathu ..	Do	Do	Do	900
7	Sadhu Ram, son of Devia ..	Do	Do	Do	900
Total					6,300

**Amount paid under Housing Scheme for Scheduled Castes and other than those engaged on unclean occupation, 1964-65, Jullundur District**

Serial No.	Name and Parentage	Caste	Village	Tehsil	Amount
1	2	3	4	5	6
					Rs
1	Atma Ram, son of Buta	.. Balmiki	Fethepur	Phillaur	900
2	Aurjun, son of Lakhu	.. Do	Do	Do	900
3	Hasara, son of Udho	.. Do	Do	Do	900
4	Mushtak, son of Buta Ram	.. Do	Do	Do	900
5	Buta Ram, son of Mehnga Ram	Do	Do	Do	900
6	Mehnga, son of Fathu	.. Do	Do	Do	900
7	J agta, son of Rulia	.. Do	Do	Do	900
			Total		6,300

**Amount paid under Housing Scheme for Scheduled Castes engaged on unclean occupation, 1964-65, District Jullundur**

Serial No.	Name and Parentage	Caste	Village	Tehsil	Amount
1	2	3	4	5	6
					Rs
1	Banta Ram, son of Jawahar	.. Adharmi	Mithepur	Jullundur	900
2	Gokal, son of Sundhu	.. Do	Do	Do	900
3	Nama, son of Mihaan	.. Do	Do	Do	900
4	Karma, son of Kishan	.. Do	Do	Do	900
5	Ananta, son of Jawahar	.. Do	Do	Do	900
6	Kehara, so of Sukhdev	.. Do	Do	Do	900
7	Sadher, son of Mehama	.. Do	Do	Do	900
8	Daulati, son of Punam	.. Do	Do	Do	900
9	Daulti, son of Udhmi	.. Do	Do	Do	900
10	Thakar, son of Basanta	.. Do	Do	Do	900
11	Bhagto, son of Ghai	.. Do	Do	Do	900
12	Nand, son of Sunder	.. Do	Do	Do	900
			Total		10,800

(3)46

PUNJAB VIDHAN SABHA [17TH FEBRUARY, 1966

[Minister for Welfare and Justice]

**Recommendation and amount paid under Housing Scheme for Sweepers for the year 1964-65  
Jullundur District**

Serial No.	Name of Parentage	Caste	Village	Tehsil	Amount
1	2	3	4	5	6
1	Vidya Devi, w/o Faqir Chand	Balmiki	Basti Shiker	Jullundur	Rs 900
2	Jit, son of Sadhu	.. Do	Do	Do	900
3	Malawar, son of Bira Ram	.. Do	Do	Do	900
4	Lachman Das, son of Babu	.. Do	Do	Do	900
5	Vidya, w/o Piara Lal	.. Do	Do	Do	900
6	Debo, son of Rura	.. Do	Do	Do	900
7	Laji w/o Om Parkash	.. Do	Do	Do	900
8	Milkhi Ram, son of Mali	.. Do	Mihali Wala	Nakodar	900
9	Cheeri, son of Jiwan	.. Do	Malsian Road	Do	900
10	Basant Kaur, widdow of Lachman Singh	Do	Ditto	Do	900
11	Asso, widow of Mute	.. Do	Naurshal	Phillaur	900
12	Piara Lal, son of Durga Dass	.. Do	Do	Do	900
13	Dev Ram, son of Milkhi Ram	.. Do	Do	Do	900
14	Gian Chand, son of Lakha Ram	.. Do	Do	Do	900
15	Chandi Ram, son of Gulah	.. Do	Do	Do	900
16	Gian Chand, son of Mukand	.. Do	Basti Shekhan	Jullundur	900
Total					14,400

**Recommendations and ammount paid under House site Scheme other than those engaged on  
unclean occupation, 1964-65, Jullundur District**

Serial No.	Name and Parentage	Caste	Village	Tehsil	Amount
1	2	3	4	5	6
1	Amroo, widow of Daulat Ram	.. Adharmi	Ramgarh	Phillaur	Rs 200
2	Jagiro, widow of Gurmit	.. Do	Do	Do	200
Total					400

## Amount of Sub dy paid under water wells scheme 1964-65

Serial No.	Name of Village	Tehsil	Amount paid Rupees
1	2	3	4
1	Jandiali	.. N/Shehar	150
2	Jadla	.. Do	250
3	Reselpur	.. Do	150
4	Usman Pur	.. Do	300
5	Aur	.. Do	165
6	Lidhana Jhika	.. Do	150
7	Dhadula	.. Do	250
8	Bhin	.. Do	150
9	Barnala	.. Do	150
10	Bagura	.. Do	150
11	Dhogri	.. Jullundur	200
12	Badala	.. Do	300
13	Khurla	.. Do	150
14	Mevan	.. Do	500
15	Butan Pind	.. Do	175
16	Gohawai	.. Phillaur	200
17	Attai	.. Do	200
18	Sanurai	.. Do	200
19	Akalpur	.. Nakodar	180
20	Bajula	.. Do	200
21	Nawan Pind Khalewal	.. Do	200
22	Bakar Kalan	.. Do	500
23	Lahian	.. Do	130
Total			5,000

[Minister for Welfare and Justice]

## Amount paid under Scheme interest free loan 1964-65

Serial No.	Name and parentage	Caste	Village	purpose	Amount
1	2	3	4	5	6
					Rs
<b>Tehsil Jullundur</b>					
1	Bhupinder Singh, son of Harnam Singh	Majhebi Sikh	Sikh	Iron Industry	1,000
2	Gurditta Ram, son of Chuhar	Ad-Dharmi	Abadpura	Spare Parts Industry	1,000
3	Khushi, son of Chambe Ram	Balmiki	Basti Guzan	Iron work	1,000
4	Hardial Singh, son of Sohab Singh	Mahasha	Old Court	Wood Work	1,000
5	Som Datt, son of Genda Ram	Balmiki	Do	Cycle Parts	1,000
6	Hari Lal, son of Kanhiya Lal	Dhobi	Dhobi Mohala	Dry Cleaning	1,000
<b>Tehsil Nakodar</b>					
7	Ujaggat Chand, son of Mangat Ram	Balmiki	Lohian	Boot Making	500
8	Paras Ram, son of Mihan Ram	Ad-dharmi	Do	Shoe-Making	500
9	Mohinder, son of Amroo	Balmiki	Mer	Ban Making	400
10	Pritam Singh, son of Bhala Singh	Jhewan	Akalpur Malsian	Do	300
11	Ganda Ram, son of Jawaban Ram	Ad-dharmi	Sidwan	Leather Tanning	1,000
<b>Tehsil Phillaur</b>					
82	Chulna Ram, son of Phe-man	Adharmi	Talwan	Ban Making	300
13	Bakshi Ram, son of Gurditta Ram	Do	Phillaur	Do	300
14	Dalipa Ram, son of Attara Ram	Do	Ramgarh	Weaving	400
15	Mangha Ram, son of Udho Ram	Do	Nangal	Ban-Making	300
16	Gurdip Singh, son of Puran Singh	Mehra	Gursian	Pipe fitting	500
17	Faquir Chand, son of Kishan Ram	Adharmi	Khauda	Shoe-Making	800
<b>Tehsil N/Shehar</b>					
18	Sant Ram, son of Rulia Ram	Adharmi	Behram	Weaving	300

1	2	3	4	5	6
19	Sham Chand, son of Mela Ram	Adharmi	Behram	Ban Making	300
20	Gian Chand, son of Bhagwan Dass	Do	N/ Shehar	Boot Making	700
21	Gurmej, son of Dalipā	Do	Aur	Do	1,500
22	Milkhi Ram, son of Jawala Ram	Do	Chak Dana	Do	300
23	Ujjagai Ram, son of Karam Chand	Do	Kultham	Do	300
24	Swarna Ram, son of Schru Ram	Do	Ushman Pur	Do	300
25	Gabia, son of Counesha	Do	Raban	Ban-Making	300
				Total	15,300

**Amount paid to Harijan under House site Scheme other than Unclean, 1964 65**

Serial No.	Name and parentage	Caste	Address	Amount paid
1	Kartari, wife of Puran	.. Adharmi	Mehlon, Tehsil Nawanshehar	Rs 200
2	Shanti Devi, daughter of Amar Chand	Do	Village and Post office Talwan, Tehsil Phillaur	200
3	Resham son of Jagat Singh	.. Do	Village and Post office Gokkal, Tehsil Jullundur	200
4	Darshan, son of Jagat Singh	.. Do	Ditto	200
5	Chhajoo, son of Sadhoo Ram	.. Do	Basti Shekh, Tehsil Jullunuur	200
Total				.. 1,000

**Notice Received on 28th January. 1966**

**Memorial for appointment of Harijan as High Court Judge**

**\*9222 Chaudhri Ram Parkash :** Will the Minister for welfare and Justice be pleased to state whether it is a fact that the Harijan M.L.A submitted a joint Memorial to the Government for appointing a Harijan as High Court Judge, if so, the action taken thereon ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes, a joint representation, for the appointment of a Harijan as a Judge of the High Court, was received by Government from the Scheduled Caste M.L.As.

(b) The memorial was considered carefully by the Government in consultation with the Chief Justice of the Punjab High Court but the request of the M.L.As. could not be acceded to.

### UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

#### Smugglers of Amritsar District detained under the Defence of India Rules

**\*9228, Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the names of smugglers of the Amritsar District at present detained under the Defence of India Rules, with the names of the Jails in which they are lodged and the class given to each of them,

(b) whether the persons referred to in part (a) above have made any representations to the Government for their release, if so, copies thereof be laid on the Table of the House ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Requisite statement is laid on the Table of the House.

(b) Yes. Only 11 of them made representations to the Government for their release. Copies of their representations are laid on the Table of the House.

The Home Secretary,  
Punjab Government, Chandigarh.

**Subject.**—Prayer for release of Ajit Singh, son of Jawahar Singh of Village Burj, at present Detenu, District Jail, Amritsar.

SIR,

The above-named detenu Ajit Singh prays as follows :

1. That he was arrested under D.I.R. about 8/9 months back and he is being lodged in the District Jail, Amritsar.
2. That he has always remained well-wisher of the Government and is still the same.
3. That he contributed a lot of money in the National Defence Fund during the Chinese aggression and has been the helper of Police and Government officials in every respect.
4. That he belongs to a respectable family and owns a sufficient movable and immovable property but he was arrested on suspicion of his being involved in smuggling, which suspicion arose as a result of false information supplied to the Government due to party frictions, otherwise he has never done any smuggling.
5. That he was the elected Chairman of the Block Samiti Gandiwind during the year 1962 to 1965, and he has again been in Jail. He has also taken the oath of Chairmanship.
6. That he assures the Government that he would refrain from any activity in future, which the Government would feel to restrain him.

**\*Note:** Starred Question No. 9228 was treated as Unstarred Question.

Therefore, it is prayed that he may be released from detention and may be ordered to be set free.

Thanks and oblige.

Amritsar,  
23rd February, 1965.

Yours faithfully,  
(Sd) . . . .  
Ajit Singh, son of Shri Jawahar Singh,  
Village Burj, Detenu District Jail,  
Amritsar.

1. Copy forwarded to the Deputy Inspector General of Police, C.I.D., Punjab.
2. Copy to Senior Superintendent of Police, Amritsar.
3. A Copy for the Deputy Commissioner, Amritsar, for necessary action.

To

The Deputy Commissioner,  
Ferozepur District,  
Ferozepur.

SIR,

Most humbly and respectfully I beg to say that I have been ordered to be detained under Rule 30 (1) (b) of the Defence of India Rules,—vide orders of the Deputy Secretary to Government Punjab, dated 8th September, 1965.

I would like to bring it to your kind notice that I have never been associated with my anti-Social or anti-national activity and my order of detention has been issued on some wrong assumptions. My behaviour as a citizen of India has been quite exemplary and have never been a member of any political party.

I would request you to very kindly reconsider my case and recommend to the Government for reconsidering my order of detention and release me so that I may be able to serve my country as free citizen.

Thanking you.

Yours faithfully,  
Thumb Impression,  
(Sawarn Singh),  
son of Ujagar Singh,  
Now U/I confined in Sub-Jail,  
Karnal.

To

The Chief Secretary to Government,  
Punjab, Chandigarh.

*Subject.*—Appeal under Rule 30-B of the Defence of India Rules, 1962, for release of Manohar Lal, son of Shri Panna Lal Khatri, Katra Bhai Sant Singh, Police station 'D' Division, Amritsar arrested and detained under rule 30(1)(b) of the Defence of India Rules, 1962.

SIR,

The appellant prays as under :

That on 18th November, 1963 I was arrested under Defence of India Rules and at present I am confined in the District Jail, Sangrur.

2. That since I am behind the locks, I have always behaved properly and given no cause of any kind of complaint to the authorities which fact can be vouchsafed from them.

3. That this is my bad fortune that I have been held under D.I.R.

4. That my antecedents have been totally unblemished I had never taken part in any political party or in any other anti-social activities, much less the nefarious trade of smuggling.

[Home and Development Minister]

5. That on the other hand I had co-operated with the Government and helped it in the matter of volunteer/contributions towards the Defence efforts. I, myself had contributed about 100 grams of gold in the form of ornaments, which gold was given to Shri Jai Inder Singh, M.L.A., Punjab, who was deputed and responsible for collecting such funds on the eve of outbreak of hostilities between India and China. Also, I assisted and worked with the Sarafa Committee, Amritsar, and Sarvshri Jai Inder Singh, Bihari Lal Khanna, Gian Chand Kharbanda, Yog Nath and Baij Nath (brick Kiln owner) in collecting more than Rs. 20,000 as a humble contribution of the Sarafa Bazar.

6. That I have 5 children to feed with an old mother of more than 60 years. My father is already dead. I am the only male member in my family, with no other member to earn livelihood and who should look after them and cater for their education, nourishment and for their welfare. In my absence my entire family is starving, making not both ends meet, and facing extreme difficulties of life.

7. That I have been a law abiding citizen of Amritsar, which fact is corroborated by my submission made above in Para 5 of this petition, and there had been no cognizable offence against me before my arrest made under D.I.R.

8. That after the death of my brother-in-law (during my detention) my father-in-law, who is more than 70 years old, is in a precarious condition. He is in the Hospital, and the Medical Officer In-Charge of the V.J. Hospital, Amritsar is of the confirmed opinion that he shall have to undergo a major operation. The said Officer has given a certificate to this effect, which is enclosed herewith, duly countersigned by the Civil Surgeon (Chief Medical Officer) Amritsar, for your ready reference.

9. It is also important to mention that since my detention I have never been released even for a day.

10. Keeping in view and sympathetic consideration of my position explained above, it is requested that I may be released and if not at present, I may be released on Parole so that I could attend to my children and my father-in-law who is to undergo a big operation. God knows whether he would survive that operation or not.

Requesting for favourable consideration of my humble petition, I remain,

At present.—  
District Jail,  
Amritsar.

Yours obediently,  
MANOHAR LAL,  
Detenu, Kt. Bhai Sant Singh,  
St. Dalan, House No. 1088,  
Amritsar.

#### Affidavit

I, Manohar Lal, son of Shri Panna Lal Khatri, resident of House No. 1088, Street Dalalan, Kt. Bhai Sant Singh, Amritsar, now a detenu in district Jail, Sangrur, under D.I.R. do hereby solemnly declare and affirm as under :

1. That I was arrested on 18th November, 1963 under D.I.R. Orders of the district Magistrate, Amritsar.

2. That before my this kind of arrest there had been no case in the Police against me whatsoever.

3. That my career had been always unblemished, and I invariably behaved as a law abiding citizen of Amritsar.

4. That I have 5 children and an old mother of 60 years, who are all facing tremendous difficulties in my absence since there is no other male member in the family who can earn in my absence and feed them.

5. That I had co-operated with the Government and helped it in the matter of voluntary contributions towards the Defence of India, and that I had myself contributed 100 grams of gold, in the form of ornaments, to this Defence Fund, and had given this quantity of gold to Sardar Jai Inder Singh, M.L.A., Punjab., Gian Chand, Kharbanda, Yog Nath and Baij Nath, of Amritsar in collecting more than Rs. 20,000 towards the Defence Fund from the Sarafa Bazar.

6. That since I am behind the bars, I have never been released on parole even for a single day.

7. That my father-in-law who is 72 years old, is undergoing a major operation shortly.

Place : Sangrur.  
5th August, 1965.

MANOHAR LAL,  
Son of Shri Panna Lal,  
Deponent.

Verification.—It is hereby further declared on solemn affirmation that the statement made above is correct and nothing has been concealed or suppressed in it.

Dated : 5th August, 1965.

MANOHAR LAL,  
Deponent.

काबले ताजीम जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, चंडीगढ़, पंजाब ।

गुजारिश है कि मजहर अजीत सिंह साकनहाल चेयरमैन, ब्लाक समिति गंडीविंद, जिला अमृतसर, वल्द जत्थेदार जवाहर सिंह जी, सकना बुर्ज, थाना घरिडा, जिला अमृतसर, अर्सा 1½ साल से बिल्कुल बे-गुनाह नजरबन्द हूं। मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं ब्लाक का चेयरमैन होने की वजह से पुलिस की खामियों को नंगा करता था। मैंने कोई काम मुल्की मुफाद के खिलाफ नहीं किया। और हमारा दो पुश्त से सियासी रिकार्ड भी बहुत अच्छा है। मैं इस से पहले चुनाव में भी भारी अकसरियत से गंडीविंज ब्लाक का चेयरमैन मुन्तसिब हो गया था और अब मुझे नजरबन्द होते हुए भी भारी अकसरीयत से ब्लाक समिति गंडीविंड का चेयरमैन चुन लिया गया है। मेरे केस पर दोबारा गौर करके मुझे रिहा किया जाए।

अर्जी

(दस्तखत . . . . . ,

अजीत सिंह, वल्द जत्थेदार जवाहर सिंह जी,  
सकना बुर्ज, थाना घरिडा, जिला अमृतसर ।

बखिदमत जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, पंजाब चंडीगढ़ ।  
जनाबेआली,

गुजारिश है कि मजहर बी. ए. का फाइनल इम्तिहान पास करने के बाद किसी हसब लियाकत मुलाजमत की तलाश में था, उसी दौरान मेरे वालद श्री स्वर्ण सिंह को पुलिस तलाश करने लगी मगर वह मिल न सके। पुलिस ने मुझे सखती से दबाकर साथ चल कर अपने आप को गिरफ्तार कराने पर मजबूर किया। मगर मैंने इन्कार कर दिया। मेरे इस इन्कार पर पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार करके बाप की जगह जेल में भेज दिया। मैं अर्सा 1¼ साल से एक नजर-बन्द के तौर पर जेल में पड़ा हूं। मैंने अपनी तालिब इल्मी के जमाना या बाद किसी ऐसी कार्रवाई में दखल नहीं दिया जो मुल्की या कौमी मुफाद के खिलाफ हो। गिरफ्तार के पेशतर कभी पुलिस ने किसी जुर्म या इरतका बेजुर्म में गिरफ्तार नहीं किया था। मजहर एक प्रेजुएट और 23 साल उम्र नौजवानी में अपनी आंयदा जिंदगी को निभाने के ख. ब. ही ले रहा था, कि बदकिस्मती का शिकार बनकर एक नजरबन्द के तौर पर मायूस जिंदगी गुजारने पर

[Home and Development Minister]

मजबूर किया गया हूं। मेरी इत्तजा है कि मेरे केस पर गौर फरमा कर मेरी रिहाई का हुक्म सादर फरमाया जावे।

अर्जी

दस्तखत . . . . .

हरपाल सिंह, वल्द श्री स्वर्ण सिंह, कोठी नं. 17,  
टेलर रोड, अमृतसर, थाना सिविल लाईन,  
हाल करनाल सब-जेल 26 सितम्बर, 1965

दस्तखत अंग्रेजी,  
हरपाल सिंह।

जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, पंजाब चंडीगढ़।

जनाबेआली,

गुजारिण है कि मजहर अर्सा दो साल से नजरबन्दी की हालत में है। वाकियात यह है कि मैं दफ्तर डो. एम. साहिब, अमृतसर में पियन के तौर पर सरकारी मुलाजिम था। मजहर साबका ड्राइवर था और बाजाबाता लाइसेंस हासिल किए हुए था। मजहर अपनी वालदा की बीमारी की वजह से रुखसत पर था। वालदा की फौतीदगी पर मजहर चंद यौम ड्यूटी पर हाजिर न हो सका। आप का आर्डर 11803/डब्ल्यू, पी. एस. बी. मुबर्खा 25 सितम्बर, 1965 की तरफ दे दिया जाना है।

1. मजहर को जब कि मजहर गवर्नमेंट मुलाजिम पर हाजिर हो गया था बिला किमी जुर्म या इकतदामे जुर्म जेरदफा 30 डिफेंस आफ इंडिया एक्ट गिरफ्तार कर लिया है और ताहनूज जेल में है।

2. मजहर एक गवर्नमेंट कर्मचारी के नाते ड्यूटी पर हाजिर हो गया था। कभी किसी खिलाफे-कानून, खिलाफे डिफेंस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया और न ही अमनेआमा के लिए मुजिर साबित हुआ है।

3. मजहर बेगुनाह है, लहजा मेरे केस पर गौर फरमा कर मेरी रिहाई फरमाई जावे। एक कलील तन्खाहदार मुलाजिम हूं और खुद ही सारे खानदान की परविश का बोझ उठा रहा था। मेरा गांव अटारी से आगे बार्डर पर है। गांव जंग की वजह से खाली हो गए हैं। बच्चे और बोबी नामालूम कहां भटक रहे होंगे। रहम फरमा कर फोरी तोर पर रिहा किया जावे ताकि उन के दुख दर्द में शामिल हो कर अपने फर्ज को पूरा कर सकूं।  
26 सितम्बर, 1965।

अर्जी,

करनैल सिंह, वल्द रंगा सिंह साबका गर्दल दफ्तर,  
डिप्टी कमिशनर साहिब बहादुर, अमृतसर रुक्ना  
रोड़ावाल खुर्द तहसील तरनतारन, जिला अमृतसर

दस्तखत उर्दू

करनैल सिंह।

मोहतरिम जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, चंडीगढ़ ।

गुजरािश है कि मजहर 70, 72 साल की उम्र को पहुंच चुका है। गांव में लम्बदार है, साबका सरपंच है, उमररसीदा होने की वजह से बीनाई कमजोर है और चलने फिरने में बहुत तकलीफ महसूस करता है।

1. मौजूदा सरपंच देहखुद के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात खराब हैं और एक दूसरे के कत्ल होने में कई दफा चालान हो चुके हैं। कुंदन सिंह, सरपंच मजकूर ने पुलिस की इमदाद पर मजहर को नीचा दिखाने के लिए पुलिस के साथ साजिश करके नजरबन्द करा दिया है।

2. मजहर अर्सी एक साल साढ़े चार माह से जेल में सड़ रहा है। और कसमपुर्वी की हालत में रह रहा है।

3. मजहर का बाप अर्सी 20 यौम हुए फौत हो गया है और नरीना ताहाल इस कदर होशमन्द नहीं ई कि मौजूदा जंग में अफरा तफरी में हुए नुवसान में और नकल बहाली की तकलीफ को बर्दाश्त कर सके।

4. गांव बार्डर पर होने की वजह से जो हालात सुन रहा हूं वह इन्तहाई तकलीफ दे हैं।

5. मजहर हकूमत बफादार है। मजहर ने चीन के साथ जंग में हस्व तौफीक सौ रुपया फंड में दिया।

लहजा आप से इल्तजा है कि मजहर को मौजूदा हालात की वजह से फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि मजहर अपने बच्चों की तकलीफ में मदद कर सके। आप को दवा दंगा 26 सितम्बर, 1965।

अर्जी

संता सिंह, वल्द ठाकुर सिंह जट्ट, सकना  
हवेलियां बशमूला नशहरा ढाला, जिला अमृतसर  
हाल नजरबन्द सब जेल करनाल।

काबले ताजीम जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, चंडीगढ़ ।  
जनाबेअली

गुजरािश है कि मजहर काबल सिंह, वल्द सरदार जरनैल सिंह, सरपंच सकना भगतपुरा उर्क रांनोवाला, थाना जंडियालागुरु, जिला अमृतसर, साढ़े चार माह से बिल्कुल नाजायज और बेगुनाह नजरबन्द हूं। मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मेरे वालद साहिब ने पुलिस की रिश्वा मोक्या पर पकड़वाई थी। जिससे पुलिस वाले सख्त नाराज हो गए। मेरा कोई रिकार्ड थाना में खराब नहीं है। मैं इससे पहले चुनाव में भी सरपंच व मੈम्बर ब्लाक समिति, जंडियालागुरु था। मेरे केस पर हमदर्दना गौर फरमाया जावे।

मैं अर्सी 9 साल से बमकाम भगतपुरा में आबाद हूं और दोनों दफा वहां से सरपंच मुन्तखिब हुआ हूं लेकिन पुलिस ने मुझे मेरे आबाई गांव झटोल थाना घरिंडा का जाहिर

[Home and Development Minister]

करके वारंट लिए हैं। मेरी उम्र अब करीबन 25 साल है और अर्सी 9 साल से बमकाम भगतपुरा में मुस्तकिल रिहायश रखता हूँ। मेरे केस पर दोबारा गौर फरमाया जावे।

अर्जी

काबल सिंह, वल्द जरनैल सिंह, भगतपुरा,  
थाना जंदिवाला, जिला अमृतसर  
दस्तखत पंजाबी, काबल सिंह।

26 सितम्बर, 1965

बखिदमत जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, पंजाब चंडीगढ़।

श्रोमान् जो,

निवेदन है कि मैं कसबा खेमकरन का बाशिदा हूँ। मौजूदा जंग में इस कसबा को सब से ज्यादा नुकसान पहुँचा है। मेरी कोई औलाद-नरीना नहीं है। मेरा ससुर जो मेरी अदम मौजूदगी में घर की देखभाल कर रहा था, भी मौजूदा अफरा तफरी में कहीं गुम हो गया है। मेरी एक नाबालिग लड़की बा-उम्र तीन साल बमह अपनी वालदा के दरबदर भटक रही है। सपुराल मोजा रतते थे। वो भी दुश्मन के कब्जा में जा चुका है। मजहर म्युनिसिपल कमेट्री खेमकरन का म्युनिसिपल कमिशनर है। कभी किसी ऐसी कार्रवाई खिलाफे हकूमत हिरसा नहीं लिया। गवर्नमेंट और खासकर बरसरे इकतदार सियासी जमात का हामी रहा है। डिफेंस फण्ड में जंगे चीन में 500 रुपया दिया। किसी भी जरूरत के वक्त इम्दादे हकूमत से हाथ नहीं खँचा। मुझे पुलिस ने ज्ञाती दुश्मनी जो कि बदकिस्मती से उनकी सीनाजोरी और खिलाफ कानूनी मनमानी कार्रवाइयों की शिकायत करने पर पैदा हो गई थी, की दजह से नज़रबन्द करा दिया है।

मैं यह यकीन से कह सकता हूँ कि मैं ने कभी डिफेंस या अमनेआमा के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। मेरा कोई ऐसा आदमी बाहर नहीं है जो मेरी बीवी बच्चों को पनाह दे सके या नुकसान का अन्दाजा लगाकर क्लेम दाखल कर सके, लहजा आपसे दर्बास्त है कि आप मेहरबानी करके मेरी रिहाई पर गौर फरमायें। आपके इकवाल के लिए दवा करता हूँ।

अर्जी

तारा सिंह वल्द अमर सिंह जट्ट, म्युनिसिपल  
कमिशनर, खेमकरन, तहसील पट्टी, जिला  
अमृतसर।

निशान् अंगूठा

हाल नज़रबन्द, सब-जेल, करनाल।

बखिदमत जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, पंजाब चंडीगढ़

जनाबेआली

दरबास्त बराये नजरसानी बरहाई नजरबन्दी हुकम डब्ल्यू. डी. एस. बी. / 9169,  
मुबर्का 9 अगस्त, 1965, जेरेदका 30 डिफेंस आफ इंडिया एक्ट रूलज 1962।

गुजारिश है कि मैं पंजाब रोडवेज में बतौर एक ड्राइवर के ड्यूटी दे रहा था । मेरा सरकारी तौर पर पासपोर्ट बराये पाकिस्तान बना हुआ था । वो मुझे उसी वक्त मिलता था जब किस सरकारी ड्यूटी पर लाहौर जाना होता था । इस दौरान जो खिदमत मैंने महकमाना तौर पर की उनके इलावा इंटेलिजेंस महकमा के एक अफसर ने मुल्की खिदमत करने का जज्बा उभार कर कुछ करने को कहा, वो ड्यूटी मैंने जिस तौर पर दी, उसकी सराहना के सर्टिफिकेट तीन मेरे पास ताहाल है ।

(1) पुलिस अफसरों की जाती रकाबत की और धड़ेबन्दी होने पर मौजूदा आई. जी. पुलिस, पंजाब के खिलाफ असेम्बली में मामला उठाया गया जो कि मुझे सरकारी तौर पर मीटिंग होने की सूरत में अक्सर साथ जाना पड़ा, इस लिए मुझे चंद पुलिस अफसरों ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक एक हफ्तिना ब्यान दू जिसके लिए मैं राजी न हुआ । ब्यान मौजूदा आई. जी. साहिब और डी. गाई जी श्री रंजीत सिंह के खिलाफ था ।

(2) मैं आज जिस रुकावट और धड़ेबन्दी का शिकार हुआ हूँ, मैं मसलहतन यहां जिक्र करना मुनासिब ख्याल नहीं करता । इसलिए इन्साफ की खातर मैं यह दर्खास्त करता हूँ कि मुझे जबानी अर्ज करने का मौका दिया जाए ताकि मैं अपनी बे-गुनाही का सबूत दे सकूँ । मैं गरीब आदमी हूँ और सिवाये मुलाजमत के और कोई जगिया मुआश न था । मेरे बच्चे और औरत निहायत कस-मपुर्सी की हालत में रह रहे हैं । मेरी औलाद जो तंगदस्ती की हालत में तालीम से भी महरूप हो गई है, रहम करते हुए मुझे रिहा किया जाए । मजहर अर्सी पांच माह से नजर बन्दी की हालत में पड़ा है ।

अर्जी

फिद्बी दर्शन सिंह, वल्द परसा सिंह, असलामाबाद, अमृतसर शहर,  
दुर्गागली, माकन 306/13, हाल नजरबन्द जेल, करनाल ।

दस्तखत उर्दू

दर्शन सिंह

26-9-65

आली मर्तबा जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, पंजाब, चन्डीगढ़

जनाबेआली

गुजारिश है कि मेरा मक्खन सिंह बलटोहा, चचा जात भाई था जिसको पुलिस मुकाबला बना कर बमह तीन साथियों के मार दिया गया । पुलिस की इस ज्यादती के खिलाफ मैं हक्कामबाला को तारे दीं जिसके बाद यह मामला कांग्रेस पार्टी के चीदा चीदा ओहदेदारों और पुलिस के दरमियान वकारी सवाल खड़ा हो गया । चूँकि मैं अपने भाई की मौत के हक्क में और पुलिस के खिलाफ शहादतें कराना चाहता था जिसकी बिना पर पुलिस ने मेरे खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहा जिसकी शिकायत मैंने

[Home and Development Minister]

अनुरागन वाला को की बल्कि श्री गुरभगत सिंह मौजूदा, एस. एस. पी, अमृतसर का नाम मादज़द करके मैंने दरखास्तें दी कि मुझे अपनी जान का खतरा है, या कोई फर्जी मुकद्दमा खड़ा करा दिया जाएगा । मेरे यह चीज ख़ाब में भी न थी कि मुझे एक ऐसे बेबुनियाद इल्जाम में माखुज करके नजरबन्द कराया जायेगा जो मेरी जमीर के खिलाफ है ।

मैं सच्चाई और परमात्मा को मद्देनजर रख कर पूरे यकीन से कह देना चाहता हूँ कि अगर मैंने कभी देश और कौम के खिलाफ कोई फेल या तर्केफेल सोचा भी था या है तो मुझे बिला मुकद्दमा चलाये शारायेयाम पर गोली से उड़ा दिया जाये ताकि आयंदा आने वाली नसलें इस से सबक सीख लें और मुल्की मुफ़ाद के खिलाफ काम करने से मेरी हालत सुनकर डरें । मैं मरने से पहले बसीअत करूंगा कि मैं ये सजा खुद क़बूल कर रहा हूँ ।

अन्दरीं हालात मेरे खिलाफ दिये गये पुलिस के फर्जी व्यानात पर नजर करके इन्साफ की खातर गौर फरमाया जावे कि मजहर बेगुनाह अर्सा 6 माह से नजरबन्द जेल में सड़ रहा है । परमात्मा आपका रूतबा और बुलन्द करे ।

अर्जी

निशान अंगूठा ।

महेन्द्र सिंह, बल्द गज्जन सिंह, सकना बल्टोहा,  
थाना खास, जिला अमृतसर ।

हाल नजरबन्द सब-जेल, करनाल, 26-9-65 ।

बखिदमत जनाब गवर्नर साहिब बहादुर, चन्डीगढ़

गुजारिश है कि मजहर अपने गांव में सख्त धड़ाबन्दी होने की वजह से मसम्मियां जगतार सिंह साबको सरपंच से दुश्मनी थी, वो एक बारसूख आदमी थे । इत्फाक से वहां मसम्मियां श्री इन्दर जीत सिंह, डी. एस. पी. और जीत सिंह सब इन्स्पैक्टर, बल्टोहा ताइनात होकर आ गये जिनके साथ उनकी गहरी ठन गई ।

(1) मजहर के खिलाफ जब भी उन्हें उकसाया जाता वह कोई न कोई बहाना करके रेड कर देते हैं, मगर मुझ से कोई शैखिलाफ-कानून न मिली मगर तंग करने के लिए कई दिन तक मैं बिठाया जाता जिसकी वजह से मजहर ने उनके खिलाफ हक्काम बाला का तारें दीं, जिनके सबूत मेरे पास हैं ।

(2) अजीत सिंह, सब-इन्स्पैक्टर, बल्टोहा से तब्दील होकर सी. आई. डी. में लग गया और एक दिन अमृतसर मिलने पर मुझे धमकी दी कि तुम वहां मेरे खिलाफ दरखास्तें दिया करते थे, अब मैं जो चाहूं कर सकता हूँ । मजहर ने इनकसारी से कहा कि गरीब जुलम के खिलाफ आवाज उठा रहा था । आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ ।

(3) उस सरदार जीत सिंह ने एक अच्छी पोजीशन पर होने की वजह से जाती दुश्मनी पर नामालूम अन्दर ही अन्दर बया कारवाही की कि अचानक गिरफ्तार

करके जेल में नजरबन्द कर दिया गया हूँ। बाँडर पर गांव हैं सच से ज्यादा नुकसान इसी निवाह में हुआ है। बालबच्चे नामालूम कहां चले गए हैं और किस हालत में हैं। लहाजा रहम फरमाया जाये।

अर्जी

अजायब सिंह, बल्द भगत सिंह, जट्ट,  
सकना चीमा खुर्द, तहसील पट्टी, जिला  
अमृतसर।

निशाने अंगूठा।

### Kabulpur Khera Co-operative Society

3127. **Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Irrigation and Power with reference to the reply to Unstarred Question No. 2893 included in the list of questions for 11th October, 1965 be pleased to state—

- (a) whether the award of Rs 7,760.54 paise as indicated in part (c) of the said reply has since been referred to the Court for execution, if so, when, if not, the reasons therefor ;
- (b) the date when the said award was given, the date when the matter was referred to arbitrator and the name of the arbitrator ;
- (c) the date when the Kabulpur Khera Co-operative Society, district Karnal became a defaulter and the date when action for recoveries from this Society was initiated ;
- (d) whether any appeal either by the Kabulpur Khera Co-op-Society or by the District whole Sale Society has been filed against the said Award, if so, when by whom and with what result ?

**Chaudhri Rizaq Ram** : (a) Yes. On 1st February, 1966.

- (b) Part I On 25th May, 1964.  
Part II On 7th August, 1962  
Part III Shri Kashmira Singh, Inspector Co-operative Societies (Marketing) now promoted as Assistant Registrar, Co-operative Societies, Ferozepore.

(c) The District Wholesale Society, Karnal, did not specifically declare Kabul Khera Co-operative Society as a defaulter for the non-payment of Rs 5,857.25 as the price of sugar lifted by the latter on 31st August, 1957, but passed resolution for initiating action against the Kabul Khera Co-op. Society on 8th October, 1960. During this period the District Wholesale Society also adjusted a sum of Rs 543.20 which was due to the Kabul Khera Co-op. Society from it on account of commission.

(d) No.

### Loss of Movable/Immovable Property due to India-Pakistan Conflict

**3128. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the approximate loss of the movable and immovable property separately that accrued in the State during the recent India-Pakistan conflict, district-wise.

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** An assessment of the loss of the movable and immovable property has yet to be made by the Deputy Commissioners concerned, after the area occupied by Pakistan is completely cleared of mines and other dangerous objects and the persons concerned become available to the verifying Officers.

### Cases registered against an Ex-Sarpanch of Gram Panchayat of Udo Nangal, Tarsikka Block, district Amritsar

**3129. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

- (a) whether any case of mis-appropriation of the Panchayat funds and of destroying the Panchayat records was registered in Police Station Beas, district Amritsar on the order of the Deputy Commissioner, Amritsar against the Ex-Sarpanch of the Gram Panchayat, Udonangal, Tarsikka Block; if so, a copy of the orders be laid on the Table of the House ;
- (b) the date when the said case was registered and the details of the action so far taken ;
- (c) whether the challan in the said case has so far been put in the Court, if not, the reasons therefor ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) A case of mis-appropriation (F. I. R. No. 170/64 under section 410 I.P.C. P. S. Beas) was registered against an Ex-Sarpanch of village Udonangal. The Ex-Sarpanch lodged a report with the Police that the relevant record was lost on 26th March, 1964, on his way back from the office of B.D.O. No definite evidence regarding destruction of record by the Ex-Sarpanch could be available during investigation of case under section 409 I.P.C. A copy of the order of D. C., Amritsar, is enclosed.

(b) 28th July, 1964. The case is pending trial in Court.

(c) Yes.

**From Sardar Iqbal Singh, I. A. S., Deputy Commissioner, Amritsar, to the Senior Superintendent of Police, Amritsar, No. DAP/1667, dated the 14th/15th July, 1964**

**Subject.**—Transfer of charge of Gram Sabha Udonangal from the Ex-Sarpanch to the newly-elected Sarpanch.

**Memorandum :**

Reference correspondence resting with your Memo. No. 25614-C, dated the 11th June, 1964, on the subject cited above.

2. Brief history of this case is that Ex-Sarpanch Bahadur Singh, Udhonangal, P.S. Beas, avoided to hand over the charge of the Panchayat record to the new

Sarpanch Shri Gopal Singh in spite of clear orders and instructions. The matter had to be reported to the S. H. O., Beas for the transfer of the charge vide this office Memo. No. DA-3830, dated the 2nd/4th May, 1964. In your Memo. under reference it is said that according to the Sarpanch the relevant documents were lost and he got a report recorded in the daily diary of P. S. Jandiala. This report dated 26th March 1964, appears to have been lodged with S. H. O., Beas actually and it was stated there in that the Panchayat record was lost on his way back to home from B.D.O. and P. O.'s office. As against this on the proceeding day viz., 25th March, 1964 this very Sarpanch met A. S. I., Baj Singh and told him that he had already delivered the record in the office of the B. D. and P.O. Tarsikka, and this statement was made by him in the presence of Sarvshri Gopal Singh, Sarjit Singh, Members Panchayat and Jagdish Singh. It will be seen that the statements are contradictory and it is not difficult to see that the Sarpanch had deliberately denied to hand over the charge. There is every apprehension and likelihood that same amount has been embezzled by him.

3. In the circumstances stated above it seems necessary that the case be got registered through the S. H. O., Beas, against the Ex-Sarpanch and suitable action taken against him as well as for the transfer of record.

### **Magisterial Enquiry held against the Sarpanch of Gram Panchayat, Lola, district Amritsar**

**3130, Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

- (a) whether any magisterial enquiry was held against the Sarpanch of Gram Panchayat Lola, Tarsikka Block, district Amritsar, by Shri T. N. Gupta, Magistrate First Class Amritsar, for obtaining sugar permits for bogus marriages etc. in the year 1964-65; if so copies of all the reports made by the said Magistrate to the Deputy Commissioner, Amritsar, in this connection and the result thereof be laid on the Table of the House;
- (b) whether it is a fact that while the enquiry was going on against the said Sarpanch, the Chairman of the Panchayat Samiti ordered an enquiry into the matter with himself as the Enquiry Officer; if so, the details of this enquiry, if conducted/completed be laid on the Table (?)

**Sardar Darbara Singh :** (a) No. However, an enquiry was held by Shri T. N. Gupta, M. I. C., Amritsar, in to the cases of mis-utilization of sugar permits by some of the residents of village Lola.

(b) No.

### **Applications for loans for Tube-Wells/Pumping Sets made to Panchayat Samiti, Tarsikka, district Amritsar**

**3132. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the names of those who applied for loans for Tubewells and pumping sets to the Panchayat Samiti, Tarsikka, district Amritsar, during the years 1964-65 and 1965-66 to-date together with the dates when applications for the purpose were made in each case
- (b) the names of persons out of those mentioned in part (a) above who were actually given the said loans together with the dates of sanction of the loan and of actual disbursement in each case ?

**Sardar Darbara Singh** : The information regarding (a) and (b) is laid on the Table of the House.

Information regarding Assembly Question 3132

(a) 1964-65

Name and address of loanees	Purpose of loan
1. Shri Tara Singh, son of Dal Singh, village Madhepur	Tube well
2. Shri Teja Singh, son of Lachhman Singh, village Madhepur	Ditto
3. Shri Nand Singh, son of Kahan Singh etc. village Jodhan Nangri	Ditto
4. Shri Bahadur Singh, Hukam Singh, Rikhi Singh, sons of Bhagat Singh, village Jharunangal	Ditto
5. Shri Bishan Singh, Ajit Singh, Dalip Singh, sons of Jawala Singh, village Bhorshi Rajputan	Ditto
6. S. Ajaib Singh, son of Mula Singh, village Jabowal ..	Pumping set
7. S. Sudagar Singh, Sunder Singh, village Bhani Badeshan	Ditto
8. S. Chater Singh, son of Lal Singh, village Bhani Badeshan	Ditto
9. S. Puran Singh, son of Santa Singh, village Mehian Br.	Ditto
10. S. Ajaib Singh, Harbans Singh Mohinder Singh, sons of S. Hari Singh, village Neberwind	Tube well
11. S. Swaran Singh, Surat Singh, village Neberwind ..	Ditto
12. Balwant Singh, son of Jawala Singh, village Bhoe ..	Pumping set
13. Tara Singh, son of Jiwan Singh, village Ghanishampura	Ditto
14. Samund Singh, son of Ghasita Singh, village Banian ..	Ditto
15. S. Harnam Singh, son of Gursit Singh, village Bhorshi Raj	Ditto
16. Sucha Singh, son of Gurdit Singh, village Bhorshi Raj	Ditto
17. Dalip Singh, son of Lall Singh, village Tahrpura ..	Ditto
18. S. Surat Singh, son of Ishar Singh, village Dhulka ..	Ditto
19. S. Inder Singh, son of Hem Singh, village Banian ..	Ditto
20. S. Swaran Singh, son of Bela Singh, village Banian ..	Ditto
21. Arjan Singh, son of Sadhu Singh, village Mattewal ..	Ditto
22. Shri Bishan Singh, son of Sobha Singh, village Kaleka ...	Tube well
23. Shri Santa Singh, son of Buta Singh, village Ghanishampura	Ditto
24. S. Hakam Singh, son of Lahna Singh, vilage Bolla ..	Pumping set
25. S. Kesar Singh, son of Hem Singh, village Dhulka	Tube well

Name and adress of loanees	Purpose of loan
26. Puran Singh, son of Attar Singh, village Mehnian Br. . .	Pumping set
27. S. Bawa Singh, son of Chanda Singh, village Mehmoodpura	Tube well
28. S. Amra Singh, Kala Singh, Lachhman Singh, Mohan Singh, village Batike	Pumping set
29. S. Gurcharan Singh, son of Suraj Singh, village Mehsum-pura Kalan	Tube well
30. S. Santa Singh, son of Jhanda Singh, village Mehsumpura Kalan	Ditto
31. S. Harnam Singh, son of Santa Singh, village Gill . .	Tube well
32. S. Santa Singh, son of Bhola Singh, village Lolla . .	Pumping set
33. Harbhajan Singh, son of Surain Singh, village Lolla . .	Ditto
34. Mewa Singh, son of Nihal Singh, village Akalgarh . .	Tube well
35. S. Bhagat Singh, son of Sunder Singh, village Jaspal	Ditto
36. S. Hazara Singh, son of Jhanda Singh, village Mehsumpura	Ditto
37. S. Amar Singh, son of Maghar Singh, village Madhepur	Ditto
38. S. Jagir Singh, Pritam Singh, sons of Bela Singh . .	Tube well
39. S. Mohinder Singh, Sobha Singh, sons of Chanan Singh	Pumping set
40. S. Basant Singh, village Gill . .	Tube well
41. S. Gurmakh Singh, Mehr Singh, Kartar Singh, sons of Thakur Singh, village Rasulpur Kalan	Pumping set
42. S. Milkha Singh, Massa Singh, vilage Jharu Nangal . .	Tube well

## 1965-66

1. Shri Suwarn Singh, Gurbachan Singh . .	Tube well
2. Joginder Singh, village Saidolehl	Ditto
3. Lakha Singh, son of Inder Singh, village Kohala . .	Ditto
4. Thakar Singh, Tara Singh, vilage Kohala . .	Ditto
5. Buta Singh, son of Banta Singh, Kohala	Ditto
6. Suwarn Singh, Gurbachan Singh, Joginder Singh, village Saidolehl	Ditto
7. Vir Singh Charno, village Akalgarh . .	Ditto
8. Surjan Singh, Thakar Singh, village Rasulpur Kalan	Ditto
9. Bahadur Singh, son of Jawand Singh, village Dehriwala	Ditto
10. Pritam Singh, son of Harnam Singh, village Dehriwala	Ditto
11. Nidhan Singh, Khajan Singh, village Saidolehl	Ditto
12. Mohinder Singh, Narinder Singh, Bhup Singh, Kabir Singh, village Dhulka	Ditto

[Home and Development Minister]

Name and address of loan	Purpose of loan
13. Sadhu Singh, atma Singh, Piara Singh, village Kaler Bala Pain	Tube well
14. Jetha Singh, son of Ujagar Singh, village Akalgarh ..	Ditto
15. Sadha Singh, son of Desa Singh Bhorshi Rajputan ..	Ditto
16. Garib Singh, Piara Singh, village Jabowal ..	Ditto
17. Ralla Singh, son of Massa Singh, Jabowal ..	Ditto
18. Charan Singh, son of Arur Singh, village Jodha Nag ..	Pumping set
19. Sohan Singh, son of Kishan Singh, village Mallowal ..	Ditto
20. Prem Singh, son of Sunder Singh, village Kaleke	Ditto
21. Hazara Singh, son of Chatter Singh, village Kaleke ..	Ditto
22. Sadhu Singh, son of Harnam Singh, village Bagga ..	Ditto
23. Jeo, wife of Teja Singh, village Kohat wind Muslmana ..	Ditto
24. Jawahar Singh, son of Bishan Singh, village Mattewal	Ditto
25. Tara Singh, Harbhajan Singh, village Kalerbala Pain ..	Ditto
26. Surat Singh, son of Ujagar Singh etc. village Khidowali	Tube well
27. Surjit Singh, Guro, village Bagga ..	Ditto
28. Suba Singh, Jhanda Singh, village Khaira Bala Chak ..	Pumping set
29. Thakar Singh, Ajaib Singh, Karnail Singh, village Rasulpur Kalan	Ditto
30. Fauja Singh, son of Sunder Singh, village Jabowal ..	Ditto
31. Harnam Singh, son of Mula Singh, village Rasulpur Kalan	Tube well
32. Udham Singh, village Muchhal ..	Ditto
33. Ajit Singh, village Rasulpur Kalan ..	Pumping set
34. Sohan Singh, Santodh Singh, village Kohatsind Muslmana	Tube well
35. Hem Singh, son of Harnam Singh, village Bagga	Pumping set
36. Mohinder Singh, son of Bala Singh, Dhulka ..	Ditto
37. Karnail Singh, Pritam Singh, Ajit Singh, village Tanel ..	Tube well
38. Harnam Singh, son of Phula Singh, village Shahpur Khurd	Ditto
39. Pritam Singh, son of Gujar Singh, village Shahpur Khurd	Ditto
40. Lachhman Singh, village Kaleke ..	Ditto

All the applications for loan received up to November, 1965 have been granted loan and money disbursed. No application prior to this period is pending in this Office.

The applications received after November, 1965 are numerated below:

Name of applicants	Date of submission of applications	Purpose of loan
1. S. Tara Singh, son f Bahadur Singh, village Akalgarh	24-11-65	Tube well
2. S. Narain Singh, son of Wadhawa Singh, village Mahnian Brahmna	2-12-65	Pumping set
3. Udham Singh, son of Boota Singh, village Khidowali	2-12-65	Ditto
4. Bahadur Singh, son of Jiwan Singh, Malowal ..	6-12-65	Ditto
5. Atma Singh, Tara Singh, sons of Roor Singh ..	7-12-65	Ditto
6. S. Hazara Singh, Tara Singh, Surjan Singh, Piara Singh, Ajaib Singh Mehmoodpura	7-12-65	Ditto
7. Deva Singh, Dalip Singh, sons of Kesar Singh, Mallowal	15-12-65	Ditto
8. Narain Singh, Gurdit Singh, Thothian ..	15-12-65	Tube well
9. Mohan Singh, son of Hardit Singh, Akalgarh Dhapian	15-12-65	Ditto
10. Jiwan Singh, son of Sunder Singh, Rasulpur Kalan	17-12-65	Ditto
11. Tara Singh, son of Chanda Singh, Malowal ..	17-12-65	Pumping set
12. Gurdit Singh, son of Charat Singh, Malowal ..	17-12-65	Ditto
13. S. Shamir Singh, Dalip Singh, Puran Singh, Hardit Singh, Santa Singh, son of Santa Singh, Khidowali	18-12-65	Ditto
14. Sukhwant Singh, son of Sadhu Singh, Bhoewal ..	23-12-65	Ditto
15. Ujagar Singh, son of Kesar Singh, Bhoewal ..	23-12-65	Ditto
16. Bahadur Singh, son of Hakam Singh, Mahsumpur Kalan	29-12-65	Tube well
17. Kartar Singh, son of Wassan Singh, Mallowal ..	31-12-65	Ditto
18. Gujjar Singh, son of Lehna Singh, Ramdewali ..	4-1-66	Ditto
19. Arur Singh, son of Bhagat Singh Lolla ..	4-1-66	Ditto
20. Bakhshish Singh, son of Makhan Singh, Lolla ..	4-1-66	Pumping set
21. Harbans Singh, son of Ujagar Singh Bhoewal ..	4-1-66	Tube well
22. Jagir Singh, son of Chet Singh, Bhoewal ..	4-1-66	Ditto
23. Kartar Singh, son of Bishan Singh, Bhoewal ..	4-1-66	Ditto
24. Jiwan Singh, son of Natha Singh, Bhoewal ..	4-1-66	Ditto
25. Nazar Singh, son of Ruldha Singh, Boparai ..	4-1-66	Ditto
26. Inder Singh, son of Atar Singh, Bhoewal ..	4-1-66	Ditto

[Home and Development Minister]

Name of application	Date of submission of applications	Purpose of loan
27. S. Harbhajan Singh, son of Kharak Singh, village Bhorshi Brahmna	4-1-66	Pumping set
28. S. Balbir Singh, son of Karam Singh, Nibberwind	4-1-66	Tube well
29. S. Bhagwan Singh, son of Alla Singh, Khidowali ..	21-1-66	Ditto
30. S. Avtar Singh, Jaswant Singh, sons of Ishar Singh Malowal	27-1-66	Pumping set
31. S. Sumand Singh, son of Hakam Singh etc. Jabbowal	31-1-66	Tube well
32. Ranjit Singh, son of Kishan Singh, Sarai Bulara ..	31-1-66	Pumping set
33. Amar Nath, son of Mohan Singh. Tarsikka ..	2-2-66	Pumping set
34. S. Kehar Singh etc. Ram Dewali Musalmana ..	4-2-66	Tube well
35. S. Atma Singh, son of Mula Singh Shahpur Khurd	9-2-66	Ditto
36. S. Massa Singh, son of Punjab Singh Dhulka ..	9-2-66	Ditto
37. S. Hazara Singh, son of Ashar Singh, Saidolehl ..	10-2-66	Ditto
38. S. Sulakhan Singh, Wassan Singh, Makhan Singh son of Labh Singh, Saidolehl	10-2-66	Ditto
39. Sohan Singh, Mohan Singh, son of Kala Singh ..	10-2-66	Ditto

(b)

1964-65

Name and address of loanees	Date of disbursement	Purpose of loan
	1	2
		3
1. Tara Singh, son of Dal Singh, village Madhepur ..	12-1-65	Tube well
2. Teja Singh, son of Lachhman Singh, village Madhopur	12-1-65	Ditto
3. Nand Singh, son of Kahan Singh etc. village Jodhanangri	12-1-65	Ditto
4. Bahadur Singh, Hukam Singh, Rikhi Singh, sons of Bahgat Singh, village Jharunangal	13-1-65	Ditto
5. Bishan Singh, Ajit Singh, Dalip Singh, sons of Jawala Singh, village Bhorshi Rajputan	13-1-65	Ditto
6. S. Ajaib Singh, son of Mula Singh, village Jabowal	13-1-65	Pumping set
7. S. Sudagar Singh, Sunder Singh, village Bhani Badeshan	13-1-65	Ditto
8. S. Chattar Singh, son of Lal Singh, village Badeshan	13-1-65	Ditto

1	2	3
9. S. Puran Singh, son of Santa Singh, village Mehnian Br.	13-1-65	Pumping set
10. S. Ajaib Singh, Harbans Singh, Mohinder Singh, sons of Hari Singh, village Neberwind	14-1-65	Tube well
11. S. Swaran Singh, Surat Singh, village Niberwind ..	30-1-65	Ditto
12. Balwant Singh, son of Jawala Singh, village Bhoe	19-2-65	Pumping set Ditto
13. Tara Singh, son of Jiwan Singh, village Ghanishampura	19-2-65	
14. Samund Singh, son of Ghasita Singh, village Banian	19-2-65	Ditto
15. Harnam Singh, son of Gursit Singh, village Bhorshi Raj.	19-2-65	Ditto
16. Sucha Singh, son of Gurdit Singh, village Bhorshi Raj.	19-2-65	Ditto
17. Dalip Singh, son of Lall Singh, village Tahrpura ..	19-2-65	Ditto
18. Surat Singh, son of Ishar Singh, village Dhulka ..	19-2-65	Ditto
19. Inder Singh, son of Hem Singh, village Banian ..	19-2-65	Ditto
20. Swaran Singh, son of Bela Singh, village Banian ..	19-2-65	Ditto
21. Arjan Singh, son of Sadhu Singh, village Matewal ..	19-2-65	Ditto
22. Shri Bishan Singh, son of Sobha Singh, village Kaleke	19-2-65	Tube well
23. Santa Singh, son of Buta Singh, village Ghanishampura	19-2-65	Ditto
24. Hakam Singh, son of Lahna Singh, village Lolla ..	24-2-65	Pumping set
25. Kesar Singh, son of Hem Singh, village Dhulka ..	25-2-65	Tube well
26. Puran Singh, son of Attar Singh, village Mehnian Br.	27-2-65	Pumping set
27. S. Bawa Singh, son of Chanda Singh, village Mehmoodpura	4-3-65	Tube well
28. S. Amra Singh, Kala Singh, Lachhman Singh, Mohan Singh, village Batike	4-3-65	Pumping set
29. S. Gurcharan Singh, son of Suraj Singh, village Mehsumpura Kalan	4-3-65	Tube well
30. S. Santa Singh son of Jhanda Singh village Mehsumpura Kalan	4-3-65	Ditto
31. S. Harnam Singh son of Santa Singh, village Gill ..	5-3-65	Tube well
32. S. Santa Singh, son of Bhola Singh, village Lolla ..	5-3-65	Pumping set
33. Harbhajan Singh, son of Surain Singh, village Lolla	5-3-65	Ditto
34. Mewa Singh, son of Nihal Singh, village Akalgarh	8-3-65	Tube well
35. Bhagat Singh, son of Sunder Singh, village Jaspal	5-3-65	Ditto
36. Hazara Singh, son of Jhanda Singh, village Mehsumpura Kalan	8-3-65	Ditto

	1	2	3
37. Ama Singh, son of Maghar Singh, village Madhepur	8-3-65	Tube well	
38. Jagir Singh, Pritam Singh, sons of Bela Singh ..	15-3-65	Ditto	
39. S. Mohinder Singh, Sobha Singh, sons of Chanan Singh	22-3-65	Pumping set	
40. S. Basant Singh, village Gill ..	29-3-65	Tube well	
41. S. Gurmakh Singh, Mehr Singh, Kartar Singh, sons of Thakur Singh, village Rasulpur Kalan	29-3-65	Pumping set	
42. S. Milkha Singh, Massa Singh, village Jharu Nangal	31-3-65	Tube well	
<b>1965-66</b>			
1. Suwarn Singh, Gurbachan Singh, Joginder Singh, village Saidolehl	15-7-65	Tube well	
2. Lakha Singh, son of Inder Singh, village Kohala ..	15-7-65	Ditto	
3. Thakar Singh, Tara Singh, village Kohala ..	15-7-65	Ditto	
4. Buta Singh, son of Banta Singh, Kohala ..	15-7-65	Ditto	
5. Suwarn Singh, Gurbachan Singh, Hoginder Singh, Saidolehl	15-7-65	Ditto	
6. Vir Singh, Charno, village Akalgarh ..	19-7-65	Ditto	
7. Surjan Singh, Thakar Singh, village Rasulpur Kalan	30-7-65	Ditto	
8. Bahadur Singh, son of Jawand Singh, village Dehriwala	12-8-65	Ditto	
9. Pritam Singh, son of Harnam Singh, village Dehriwala	13-8-65	Ditto	
10. Nidhan Singh, Khajan Singh, village Saidolehl ..	28-8-65	Ditto	
11. Mohinder Singh, Narinder Singh, Bhup Singh, Kabir Singh, village Dhulka	28-8-65	Ditto	
12. Sadhu Singh, Atma Singh, Piara Singh, village Kaler Bala Pain	28-8-65	Ditto	
13. Jetha Singh, son of Ujagar Singh, village Akalgarh	7-9-65	Ditto	
14. Sadha Singh, son of Desa Singh, Bhorshi Rajputan	10-9-65	Ditto	
15. Garib Singh, Piara Singh, village Jabowal ..	10-9-65	Ditto	
16. Ralla Singh, son of Massa Singh, Jabowal ..	10-9-65	Ditto	
17. Charan Singh, son of Arur Singh, village Jodha Nag	16-9-65	Pumping set	
18. Sohan Singh, son of Kishan Singh, village Mallowal	16-9-65	Ditto	
19. Prem Singh, son of Sunder Singh, village Kaleke ..	16-9-65	Ditto	
20. Hazara Singh, son of Chattar Singh, village Kaleke	16-9-65	Ditto	
21. Sadhu Singh, son of Harnam Singh, village Baga	16-9-65	Ditto	

	1	2	3
22. Jeo, wife of Teja Singh, village Kohatwind Muslmana		16-9-65	Pumping set
23. Jawahar Singh, son of Bishan Singh, village Mattewal		16-9-65	Ditto
24. Tara Singh, Harbhjan Singh, village Kalerbala Pain		16-9-65	Ditto
25. Surat Singh, son of Ujagar Singh, etc. village Khidowali		22-9-65	Tube well
26. Surjit Singh, Guro, village Bagga ..		22-9-65	Ditto
27. Suba Singh, Jhanda Singh, village Khairbala Chak		24-9-65	Ditto
28. Thakar Singh, Ajaib Singh, Karnail Singh, village Rasulpur Kalan		25-9-65	Ditto
29. Fauja Singh, son of Sunder Singh, village Jabowal		25-9-65	Ditto
30. Harnam Singh, son of Mula Singh, village Rasulpur Kalan		18-10-65	Tube well
31. Udham Singh, village Muchal ..		15-11-65	Ditto
32. Ajit Singh, village Rasulpur Kalan ..		15-11-65	Pumping set
33. Sohan Singh, Santosh Singh, village Kohatsind Muslmana		17-11-65	Tube well
34. Hem Singh, son of Harnam Singh, village Bagga ..		17-11-65	Pumping set
35. Mohinder Singh, son of Bala Singh, Dhulka ..		1-12-65	Ditto
36. Karnail Singh, Pritam Singh, Ajit Singh, village Tanel		1-12-65	Tube well
37. Harnam Singh, son of Phulla Singh, village Shahpur Khurd		27-12-65	Ditto
38. Pritam Singh, son of Gujjar Singh, Shahpur Khurd		27-12-65	Ditto
39. Lachhman Singh, village Kaleke ..		3-1-66	Ditto

Date of sanction of loan cannot be given as all the loan applications have since been transferred to Revenue authorities.

### Combination of Subjects for Masters/Mistresses

**3133. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Government has fixed any combination of subjects for purposes of appointment of Masters and Mistresses in the Government Schools in the State ; if so, the details of such combinations with the grades of pay which they are entitled to get ?

**Shri Prabodh Chandra :** Yes. The details of such combination category-wise are :—

- Social Studies.*—(i) B.A. with any two out of four elective subjects, viz., History, Economics, Political Science and Geography ; Or  
 (ii) M.A. Part (I) in History/Economics/Political Science/Geography with any other of the remaining subjects in B.A., viz. History, Economics, Political Science, Geography ; Or  
 (iii) M.A. in Economics or History or Geography or Political Science.

[Education Minister]

**Mathematics.**—B.A. with Mathematics A & B Courses Or Physics and Mathematics A Course.

**Science.**—B.A./B.Sc. with any two of the following subjects viz., Physics, Chemistry, Botany, and Zoology ; Or Physics and Mathematics A Course, Or Physics and Geography.

They are entitled to pay as under in the grade of Rs 110/250 :—

- |  |   |
|--|---|
| (i) Trained Graduates                                | .. Regular pay in the grade                                       |
| (ii) Untrained Graduates (Science & Mathematics)     | Initial pay of the grade till they acquire training qualification |
| (iii) M.Sc.s   | .. Higher pay of Rs 200 per mensem in the grade                   |
| (iv) M.A.s I & II Class with training qualifications | Higher pay of Rs 150 per mensem in the grade                      |
| (v) M.A.s III Class with training qualifications     | Higher pay of Rs 126 per mensem in the grade                      |

**New Building for Government Higher Secondary School (for Boys), Jandiala Guru, District Amritsar**

**3134. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- whether the Government has so far arranged to provide a new building for the Government Higher Secondary School (for boys), Jandiala Guru, district Amritsar, in view of the over-crowding in the school, if so, the details of the steps so far taken in this behalf ;
- the total number of students in each class at present on the rolls of the said school, together with the names of the teachers at present working in the school and the qualifications of each ;
- whether it is a fact that land for the said school has been donated by the residents of Jandiala during the Consolidation operations ; if so, the area of the lands so given and the steps so far taken for the construction of the new building ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) No.

(b) The statements giving the requisite information are enclosed.

(c) Yes. Total area of the land is one acre, 4 kanals and 5 marlas.

At present there is no scheme for the construction of new buildings for schools.

**Government Higher Secondary School, Jandiala Guru (Amritsar)**

Class	Total on Roll
XIA	20
XIB	28
XIC	9
XA	53
XB	28
XC	27
IXA	36
IXB	39

Class	Total on Roll
IXC	43
IXD	32
IXE	33
VIII A	54
VIII B	26
VIII C	32
VIII D	37
VII A	41
VII B	35
VII C	33
VII D	56
VII E	37
VI A	42
VI B	46
VI C	31
VI D	34
VI E	36
VI F	32

## Staff Statement

Serial No.	Name of the Teacher	Qualifications	Designation
1	Shri Dina Nath, Principal	M.A., B.T., P.E.S. (II)	Principal
2	Shri Sukhdev Singh	M.A., B.T.	Lecturer
3	Shri Harbhajan Singh	M.A., M.Ed.	Do
4	Shri Waryam Singh	B.Sc., B.T. (M.Sc. Condense Course)	Master
5	Shri Joginder Singh Bawa	M.A., B.T.	Do
6	Shri Joginder Singh Randhawa	Ditto	Do
7	Shri Karamjit Singh	Ditto	Do
8	Shri Harnam Singh	Ditto	Do
9	Shri Harbinder Singh	Ditto	Do
10	Shri Gurdip Singh	B.Sc., B.T.	Do
11	Shri Sohan Singh	B.A., B.T.	Do
12	Shri Mohinder Paul	B.A., B.T.	Do
13	Shri Mangat Ram	B.Sc., B.T.	Do
14	Shri Surinder Mohan	B.A., B.T.	Do
15	Shri Ajit Singh	Ditto	Do
16	Shri Dalbir Singh	Ditto	Do
17	Shri Sudarshan Kumar	Ditto	Do
18	Shri Surrindra Kumar	B.A. (Diploma G. Sc.)	Do

[Education Minister]

Serial No.	Name of the Teacher	Qualifications	Designation
19	Shri Krishan Mohan Mehta	.. B.A., B.T.	.. Master
20	Shri Narinder Singh	.. Ditto	.. Do
21	Shri Mela Singh	.. Middle, S.V., S. T.	.. Teacher
22	Shri Ved Parkash	.. Matric, Giani, S.T.	.. Do
23	Shri Harbans Singh	.. B.A., B.Ed., S.V.	.. Do
24	Shri Inder Singh Prof.	.. M.A., Munshi Fazil, O.T.	.. Do
25	Shri Mitter Singh	.. Matric, O.T.	.. Do
26	Shri Sardari Lal	.. F.A. Munshi Fazil, S.V., O.T.	.. Do
27	Shri Dev Raj	.. Middle, Shastri	.. Do
28	Shri Budh Singh	.. P.T.I. Army, 1st Class	.. P.T.I.
29	Shri Kulwant Singh	.. Matric, S.T.	.. Teacher
30	Shri Baldev Raj	.. Matric	.. Drawing Teacher
31	Shri Tarlok Nath	.. B.A., J.B.T.	.. Do
32	Shri Gurcharan Dass	.. Ditto	.. Do
33	Shri Nihal Chand	.. F.A., Giani, J.B.T.	.. Do
34	Shri Rajinder Kumar	.. F.A., J.B.T.	.. Do
35	Shri Ranjit Singh	.. Matric, Drawing Master	.. Do
36	Shri Madan Lal	.. Ditto	.. Do
37	Shri Parshotam Dass	.. Matric, O.T.	.. Do
38	Shri Darbara Singh	.. F.A., J.B.T.	.. Do
39	Shri Kewal Krishan	.. Matric, J.B.T.	.. Do

### Recognised Privately-managed Middle and Higher Secondary Schools in Amritsar District

**3135. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the number and names of privately-managed Middle and Higher Secondary Schools in Amritsar District recognised by the Education Department as at present ;

(b) the details of fees or other funds being charged by the management of the above mentioned schools from the students at present, class-wise ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) The statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

(b) The statement giving the details of fees and other funds prescribed by the Department is laid on the Table of the House. Information is being collected in regard to the actual fees/funds being charged at present in the schools in question.

#### INFROMATION RELEVANT TO PART (A)

##### BOYS HIGHER SECONDARY SCHOOLS

1. B.K. Higher Secondary School, Amritsar.
2. D.A.V. Higher Secondary School, Amritsar.
3. Gian Ashram Higher Secondary School, Amritsar.
4. Hindu Sabha Higher Secondary School, Amritsar.
5. Khalsa Collegiate Higher Secondary School, Amritsar.
6. Parkash Ashram Higher Secondary School, Amritsar.
7. P.B.N. Higher Secondary School, Amritsar.
8. Ram Garhia Higher Secondary School, Amritsar.
9. S.D. Higher Secondary School, Amritsar.
10. S.G.R.D. Khalsa Higher Secondary School, Amritsar.
11. S.S.S.S. Khalsa Higher Secondary School, Amritsar.
12. Khalsa Higher Secondary School, Bir Baba Budha Sahib.
13. R.G.N. Khalsa Higher Secondary School, Fatehpur Rajputan.
14. S.G.G.S. Majha Khalsa Higher Secondary School, Kairon.
15. Khalsa Higher Secondary School, Nawan Pind.
16. D.A.V. Higher Secondary School, Patti (Amritsar).
17. G.G.S. Higher Secondary School, Sarhali.
18. S.G.A.D. Higher Secondary School, Tarn Taran.
19. S.G.A.D. Khalsa Higher Secondary School, Valtoha.
20. S.I.S. Trust Higher Secondary School, Verka.

##### GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOLS

21. Putlighar Higher Secondary School, Amritsar.
22. Ram Kanya Higher Secondary School, Amritsar.
23. Saint Marry Higher Scondary School, Amritsar.
24. S. Guru Nanak Higher Secondary School, Amritsar.
25. S. Guru Ram Dass Higher Secondary School, Amritsar.
26. Shahzada Nand Higher Secondary School, Amritsar.
27. Vedic Higher Secondary School, Amritsar.
28. Sarswati Higher Secondary School, Amritsar.

##### BOYS AND GIRLS MIDDLE SCHOOLS

1. Janta Middle School, Amritsar.
2. Marwari Middle School, Amritsar.
3. Partap Middle School, Amritsar.
4. Vedic Dharam Middle School, Amritsar.
5. Vanaik Nirshula Pathshala Shouri Nagar.
6. Bal Vidyala Middle School, Amritsar.
7. Daya Wandi Middle School, Amritsar.
8. Parkash Ashram Middle School, Amritsar.
9. Chheharte Middle School, Chheharta.
10. D.A.V. Middle School, Ramdas.
11. Puj Sohan Lal Jain Middle School, Amritsar.
12. Ajanta Middle School, Amritsar.
13. Nav Bharat Middle School, Amritsar.

[Education Minister]

## RELEVANT TO PART (b)

Statement showing the monthly rates of prescribed fees charged in Classes VI to XI of Higher Secondary Schools

Serial No.	Nature of fee	Rates of fees and the Classes in which charged									
		VI	VII	VIII	IX	X	XI				
		Rs P	Rs P	Rs P	Rs P	Rs P	Rs P				
1	Tuition Fee	..	3.00	4.50	4.50	7.00	8.00	9.00	Boys		
		..	1.50	2.25	2.25	4.00	5.00	6.00	Girls		
2	Magazine Fund	..	No subscription is charged. Magazine is started on no loss no profit basis.								
3	Audio-visual Aids Fund	..	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
4	Science Fund	..	..	..	..	1.00	1.50	1.50			
5	Medical Fee (Health Fund)	..	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25			
6	Amalgamated Fund	..	0.37	0.50	0.50	0.75	0.75	0.75	Boys		
7	Red Cross Fund	..	0.25 6 P to 12 P per month	0.25	0.25	0.37	0.37	0.37	Girls		
8	Commerce, Agriculture, Fine Arts, Home Science Fund	..	..	..	..	1.00	1.50	1.50			
9	Technical	..	..	..	..	1.50	2.00	2.00			
10	Domestic Science Funds (For Girls only)	..	0.25	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37			
11	General Science Breakage fees	..	..	..	..	0.25	0.25	0.25			
12	Cycle Fund	..	Rs 1 per mensem per student who keeps a cycle								
13	Divisional Guide Rally and Tournament Fund (Girls)	..	Re 0.12 paise per Student yearly from the students of Secondary Department								

**Government High Schools at Chhajalwadi and Varpal, District Amritsar**

**3136. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the total number of rooms in the Government High School, Chhajalwadi and Government High School, Varpal, tehsil and district Amritsar at present ;
- (b) the total number of students on rolls in each of the said schools in each class at present ;
- (c) whether any rooms of the said school buildings were declared unsafe by the P.W.D. during the years 1964 and 1965 ; if so, the steps, if any, taken to carry out the necessary repairs ;
- (d) the names and qualifications of Masters and Teachers at present working in the schools mentioned above with their home addresses ?

**Shri Prabodh Chandra :**

- (a) (i) Government High School, Chhajalwadi .. Eleven rooms
- (ii) Government High School, Varpal .. Six rooms plus one unroofed Hall
- (b) Statements giving the requisite information are enclosed.
- (c) No.
- (d) Statements giving the requisite information are enclosed . . .

**Statement showing total number of students on Roll in Government High School, Chhajalwadi, District Amritsar**

Total number of students is 580 as detailed below :—

<i>Name of Class</i>	<i>Number of students</i>
10th A	33
10th B	31
9th A	45
9th B	42
8th A	39
8th B	38
7th A	32
7th B	43
6th A	34
6th B	36
6th C	35
5th	29
4th	30
3rd	32
2nd	44
1st Primary	37
Total	580

**Statement showing total number of students on Rolls in Government High School, Varpal District Amritsar**

Total number of students is 316 as detailed below :—

<i>Name of Class</i>	<i>Number of students</i>
10th B	40
9th A	25
9th B	32
8th A	30
8th B	27

Name of Class	Number of Students
7th A	34
7th B	36
6th A	29
6th B	35
6th C	28
Total	316

**Names and Qualifications of Masters and Teachers at present working in the schools  
Government High School, Chhajalwadi, district Amritsar**

Serial No.	Name of the official	Qualifications	Home Address
1	Shri Santokh Singhi 11, Headmaster	B.A., B.T. D.P.E. Gill	Village Dadupur, post office Majiha, district Amritsar
2	Shri Jagir Singh, Master	B.Sc., B.T.	Village Tharoo Nangal, post office Rayya
3	Shri Swarn Chand Master	M.A., B.T.	Village and post office Sultanwind, district Amritsar
4	Shri Didar Singh, Master	B.A., B.T.	Village and post office Tangra, district Amritsar
5	Shri Sewa Singh, Master	B.A., B.Ed.	Village and post office Bhorchhi Rajputan (Amritsar)
6	Shri Kartar Singh, Master	B.A., B.Ed.	Village and post office Muchhal, district Amritsar
7	Shri Atma Ram, Master	M.A., B.T.	House No. 101, Gali Gujran Jandiala Guru, district, Amritsar
8	Shri Banarsi Dass, Master	B.A., B.T.	Village and post office Harsa China, district Amritsar
9	Shri Harhhajan Singh, Master	B.Sc., Diploma in Gen. Science	Village and post office Dairywala, district Amritsar
10	Shri Pritam Singh, Teacher	Matric, Gyani, O.T.	Village and post office Bhorchhi Rajputan, district Amritsar
11	Shri Puran Singh, P.T.I.	Ambala Mlt. Trd.	Village and post office Dherar (Amritsar)
12	Shri Nihal Chand, Teacher	Special Certificate Drawing	Village and post office Ahmedgarh district Sangrur
13	Shri Santokh Singh, Teacher	F.A., J.B.T.	Village Butari, post office Khalchian
14	Shri Hardyal Singh, Teacher	Matric, J.B.T.	Village and post office Tangra

Serial No.	Name of the official	Qualifications	Home Address
15	Shri Lachhman Dass	Matric	Village and post office Muchhal district Amritsar
16	Smt. Dalbir Kaur, Teacher	Matric, J.B.T.	Village and post office Chhajalwadi (Amritsar)
17	Shri Chanan Singh, Teacher	Matric, Gyani, O.T.	Village and post office Chang ally, district Patiala
18	Shri Sadhu Singh, N.C.C. Instructor	Mlt. Trd.	Village and post office Chhajalwadi
19	Shri Makhan Singh	Matric with Hindi	Village and post office Dairywala (Amritsar) (working on six months basis)
20	Shri Dilbagh Singh	Matric, J.B.T.	Village Umra Nangal, post office Rayya (Working on six months basis)

**Names and Qualifications of Masters and Teachers at present working in the school at Government High School, Varpal, with their home addresses**

Serial No.	Name of the official	Qualifications	Home Address
1	Shri Bansi Lal, Headmaster	B.A., B.T.	Village and post office Varpal (Amritsar)
2	Shri Manmohan Singh, Master	M.A., B.T.	Village and post office Gonalwar (Amritsar)
3	Shri Beshamber Dass, Master	M.A., B.Sc., B.T.	Nurdin Bazar, Tarn Taran
4	Shri Dalip Singh, Master	M.A., B.Ed.	Village and post office Gonalwar, Varpal (Amritsar)
5	Shri Surjit Singh, Master	M.A., B.T.	212, Daim Ganj, Amritsar
6	Shri Moti Ram, Master	B.A., B.T.	365 (X-3) Tara Singh Gali, Amritsar
7	Shri Mohan Lal, Master	B.A., B.T.	Village and post office Chaba
8	Shri Gurbachan Singh, Master	B.Sc.	Village and post office Balia (Amritsar)
9	Shri Gurcharan Singh	B.A., B.T.	village and post office Monalwar, Varpal (Amritsar)
10	Shri Khem Chand	O.T. Shastri	House No. 2409/10, Katra Dulo, Amritsar
11	Shri Puran Singh	O.T., Giani	Village and post office Monalwar Varpal (Amritsar)

[Education Minister]

- |    |                    |    |                |    |  |
|----|--------------------|----|----------------|----|--|
| 12 | Shri Sat Paul      | .. | B.A., S.V.     | .. | Village and post office Varpal               |
| 13 | Shri Harbans Singh | .. | Matric, P.T.I. | .. | Tangra (Amritsar)                            |
| 14 | Shri Gurdish Singh | .. | Middle         | .. | Village and post office Daburji (Amritsar)   |
| 15 | Shri Jagdish Singh | .. | Matric, J.B.T. | .. | House No. 1276/7, Gate Bhagtanwala, Amritsar |

### **Taking over National College, Sathiala, District Amritsar by Government**

**3137. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) whether the Government has taken over the National College, Sathiala, district Amritsar, if not, the reasons thereof ;
- (b) a copy of the detailed correspondence which took place between the Managing Committee of the said College and the Government in 1965-66, be laid on the Table of the House ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) No ; the terms and conditions are being finalised.

(b) The salient details of the correspondence are as under :—

- (i) The management approached Government that they had made up deficiencies in Boys Funds and had also put up additional buildings. They, therefore, desired that the College be taken over from the beginning of the financial year 1964-65. The Joint Director (Colleges) visited the College on 3rd April, 1965 so as to verify on the spot whether the conditions imposed on the Management for taking over their College had since been fulfilled. He reported that almost all works have been completed excepting a few which would be complete by the end of April, 1965. The question of taking over was examined by Government and certain additional information was called for from the Committee.
- (ii) In connection with the completion of certain buildings attached with this College, the Management requested for the release of 75 percent of the Endowment Fund which has been accepted by Government.
- (iii) The Management informed that formal function of handing over the College to Government will be held on the 16th August, 1965, which will be presided over by the Education Minister. They, therefore, desired that Government sanction to the taking over of this College be conveyed urgently.
- (iv) In order to settle certain outstanding items, a meeting between the Management and Officers of Education Department including a representative of the Finance Department was held on 28th September, 1965. In this meeting, the Management stressed for the retention of a piece of land measuring 7 acres. Since this demand was against their resolution dated 15th November, 1960 for donating the entire land it was not agreed to. However, to enable the Government to examine the genuineness of this demand, the Management were asked to supply details of the entire land based

on the revenue record and also details of the expenditure incurred by them on this college from the date when negotiations for the transfer of this College to Government were started along with details of Library equipment, etc. The Management have supplied the relevant information and have also expressed their willingness to transfer the entire land to Government. The question of finalising the matter is under examination of Government. | A

**Amount invested by Government in different Industries**

**3138. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount of capital invested by the Government in different industries in the public and private sectors separately during the First, Second and Third Five-Year Plan periods respectively in the State, districtwise and in the other States in the country separately ;

(b) the present proposals of the State Government for the investment of capital in different industries during the Fourth Plan period ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Statements I, II, III and IV containing the requisite information are attached.

(b) The Fourth Five-Year Plan has not yet been approved by the Planning Commission/Government of India.

**STATEMENT I**

**Abstract of Investment made by the Punjab Government Plan-wise in the Industrial Undertakings in the Public and Private Sectors in the Punjab State**

Plan period		Private sector	Public Sector	Total
		Rs	Rs	Rs
First Plan period	..	40,00,000	..	40,00,000
Second Plan period	..	12,00,000	..	12,00,000
Third Plan period	..	97,27,750	13,17,000	1,10,98,750
Total	..	1,49,27,750	13,71,000	1,62,98,750

[Chief Minister]

## STATEMENT II

Statement showing the investment by the Punjab Government in the Industrial Undertakings in the Private Sector in the State during the 1st, 2nd and 3rd Plan periods

Name of the District	Plan	Year of investment	Name of the Industrial Undertaking	Amount invested	
				4	5
					Rs
Ambala	.. II	1957-58	Shree Gopal Paper Mills Ltd., Jagadhri	..	10,00,000
	III	1961-62	Punjab Handloom Weavers Apex Coop. Society, Ltd., Chandigarh	..	50,000
	III	1961-62	Punjab State Industrial Coop. Federation Ltd., Chandigarh	..	50,000
	III	1962-63	Ditto		25,000
	III	1963-64	Ditto		25,000
Gurgaon	.. II	1958-59	Panch-Shila Industrial Coop. Society Ltd., Faridabad	..	2,00,000
	III	1962-63	Ditto		2,25,000
	III	1961-62	Usha Spinning and Weaving Mills Ltd.	..	2,38,600
	III	1964-65	} Ditto		17,61,400
	III	1965-66	} Ditto		
	III	1964-65 & 1965-66	} Usha Forgings and Stamping Ltd., Badarpur	..	4,28,700

		1964-65 and 1965-66	III		Sikands Ltd., New Delhi (Faridabad)	..	14,34,000
Jullundur	..	1962-63	III		Bhargava Camp, Ahinsuk Charam Production-cum-Sales Coop-. So- ciety, Ltd., Jullundur City	..	₹ 50,000
Kangra	..	1962-63	III		Bir Coop. Tea Factory, District Kangra	..	₹ 50,000
		1963-64	III		Ditto		₹ 50,000
		1962-63 and 1963-64	III		Kangra Tea Planters Supply and Marketing Industrial Co-operative Society, Palampur	..	1,00,000
Kapurthala	..	1954-55 (including investment made during 1946—51)	I		M/s Jagatjit Cotton Textile Mills Ltd., Phagwara	..	17,00,000
Ludhiana	..	1963-64	III		Hindustan No. 1 Combers Cooperative Society, Ludhiana	..	4,29,750
Patiala	..	1955-56	I		Hindustan Wire Products Ltd., Patiala	..	3,00,000
		1962-63	III		Industrial Cables Ltd., Rajpura	..	7,00,000
Rohtak	..	1962-63	III		Hindustan Dowidat Tools Ltd., Sonapat	..	1,71,500
		1963-64 and 1964-65	III		Bharat Steel Tubes, Ltd.	..	39,38,000
Sangrur	..	1955-56	I		Malwa Sugar Mills Ltd., Dhuri	..	20,00,000
					Total	..	1,49,27,750

[Chief Minister]

## STATEMENT III

Statement showing the investment made by the Punjab Government in the State Sponsored Industrial Projects in the Punjab State

Name of the District	Plan	Year of investment	Name of the State-sponsored Project	Amount invested	REMARKS
1	2	3	4	5	6
				Rs	
III		1963-64	Punjab Air Rifles Ltd., Chandigarh	10,71,000	The Air Rifles Factory Project has since been abandoned
III		1964-65	Punjab Seamless Tubes Ltd.	20,000	} Location of these projects has not yet been decided
III		1963-64	Punjab Steel and Alloy Castings Ltd.	2,80,000	
Total				13,71,000	

## STATEMENT IV

Statement showing the investment held by the Punjab Government in the Industrial undertakings in the private sector in the other States in India

Serial No.	Name of the State	Name of the Industrial Undertaking	Amount of investment	REMARKS
			Rs	
1	Maharashtra ..	Investment through Shamji-Karamsi, Bombay	9,04,509	These investments were made by the erstwhile Pepsu Government and were inherited by the Punjab Government at the time of merger
2	Do	Associated Cement Companies Ltd., Bombay	1,70,700	
3	Madras ..	Dalmia Cement (Bharat) Ltd. Dalmia Puram, Madras	82,750	
4	Mysore ..	Mysore Paper Mills Ltd., Bangalore	2,000	
5	Mysore ..	Krishan Rajindra Mills, Ltd., Mysore	10,000	
6	Rajasthan ..	Dholpur Glass Works Ltd., Dholpur	50,000	
7	Do	M/s Udai Bhan Industries Ltd., Dholpur	3,50,000	
	Total	..	85,69,959	

## Surplus Area and its Allotment

**3139. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :

- the area of surplus land in the State, district-wise as at present ;
- the steps taken by the Government to distribute the said surplus area amongst the Harijans, Backward Classes and tenants from 1960 onwards separately, district-wise and year-wise ?

**Sardar Harinder Singh Major :** (a) A statement is enclosed.

(b) Under the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 and Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955 surplus area is allotted to tenants on the reserved area of the landowners or those who are tenants of small landowners, irrespective of the fact whether they are harijans or otherwise. As such the question of taking steps to allot surplus land to harijans and backward classes alone does not arise. However, harijans numbering 12,037 have so far been allotted surplus area measuring 27,086 standard acres. Figures for allotment of surplus area to members of the backward classes are not available.

[Revenue Minister]

## STATEMENT

Serial No.	Name of District	Area declared surplus in standard acres
1	2	3
1	Hissar	.. 84,787
2	Rohtak	.. 20,085
3	Gurgaon	.. 12,190
4	Karnal	.. 46,149
5	Ambala	.. 11,816
6	Simla	.. 12
7	Kangra	.. 6399
8	Hoshiarpur	.. 4,322
9	Jullundur	.. 6,975
10	Ludhiana	.. 5,978
11	Ferozepore	.. 79,413
12	Amritsar	.. 22,894
13	Gurdaspur	.. 13,924
14	Kulu	.. ..
15	Lahaul and Spiti	.. 36
16	Patiala	.. 10,039
17	Sangrur	.. 26,537
18	Bhatinda	.. 14,459
19	Mohindergarh	.. 1,243
20	Kapurthala	.. 1,216
Total		.. 3,68,474

## Setting up a Paper Factory near Nangal

**3140. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has taken any final decision for installing a paper factory in the State near Nangal.

If so, the details of the said decision alongwith the blue print of the factory be laid on the table of the House.

**Shri Ram Kishan :** Yes. A newsprint mill with a daily capacity of 100 tonnes of newsprint is to be set up at Kiratpur by M/s. Shree Gopal Paper Mills Ltd. (a concern of M/s. Karam Chand Thapar & Bros.). They hold a licence from the Government of India, in collaboration with

M/s. Abitibi Power and Paper Company Ltd., of Canada. Details of the agreement regarding supply of pulpwood material at the agreed rate etc. for newsprint manufacture are being finalised.

**Permits issued for Stage Carriages**

**3143. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that the Government issued permits to the private transport companies in the State for stage carriages during the years 1964-65 and 1965-66 to date on 50:50 basis; if so, the detailed list thereof be laid on the Table of the House;
- (b) the details of mileage given to the private companies, company-wise under the said arrangement during the said period ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) and (b) Yes. A statement is laid on the Table of the House.

## [Transport and Elections Minister]

## List of Stage Carriages permits issued during the years 1964-65 and 1965-66 in favour of Private Transport Companies and mileage given company-wise

Serial No.	Name of Transport Company/ society	Name of route	Number of permits	Number of trips	Total mileage
AMBALA REGION					
1	The New Chenab Co-operative Transport Society Ltd., Ambala City	Yamuna Nagar - Derabassi via Kala Amb and Naraingarh Derabassi-Ambala	1	1	32
2	Universal Victory Bus Service (P) Ltd., Ambala City	Ambala-Jagadhri via Mullana Sadhaura-Naraingarh	1	1	70
3	Ambala Bus Syndicate (P) Ltd., Rupar	Ambala - Jagadhri via Mullana Chandigarh-Kurali via Siswan-Mullanpur-Gribdas Chandigarh-Pinjore extension upto Kalka	2 1 2	3 1 2	210 36 12
4	The Karnal Co-operative Transport Society Ltd., Karnal	Karnal-Sonepat	1	1	104
5	Indian Motor Transport Company Ltd., Karnal	Derabassi-Yamuna Nagar via Kala Amb-Naraingarh Thol-Jhansa-Pipli Karnal-Karsa extension upto Dhand (extension only) Jagadhri-Ranjitpura Abdulapur-Pawani	1 1 1 3 1	1 2 2 3 1	64 84 24 108 22
6	The Rohtak -Delhi Transport (P) Ltd., Rohtak	Delhi-Rewari via Manesar	1	1	108
7	The Rohtak - Gohana Bus Service (P) Ltd., Rohtak	Rohtak-Gohana extension upto Guru Kul-Khanpur (extension only) Gohana -Sonepat	1 1	1 1	12 50

8	Rohtak-Hissar Transport Company, Rohtak	Assandh-Jind	1	$\frac{1}{2}$	27
9	Rohtak-Hissar Transport Company (P) Ltd., Rohtak	Assandh-Jind	1	$1\frac{1}{2}$	81
10	Rohtak General Transport Co. (P) Ltd., Rohtak	Tosham-Sewani Rohtak-Narnaul	1	1	54
11	Satnam Transport Co. (P) Ltd., Rohtak	Bhiwani-Tosham-Sewani Gohana-Khera extension upto Bhambewa Gohana-Sonepat	1 1 1	$\frac{1}{2}$ 1 1	76 84 12
12	The Hissar District Transport Company, Hissar	Tosham-Behl Hissar-Tohana	1 1	1 1	56 92
13	The Hissar Nilibar Co-operative Transport Society Ltd., Hissar	Hissar-Loharu via Rodhan Hissar-Dharsul	1 1	1 1	100 68
14	Ganjibar Bus Service, Hansi	Barwala, Nehla Hansi-Khandakheri	1 1	1 1	30 44
15	Dabwali Transport Company (P) Ltd., Mandi, Dabwali	Dabwali-Kalanwali Sirsa-Sardulgarh extension upto Rori (extension only) Dabwali-Rori extension upto Sardulgarh (extension only)	1 1 1 1	1 1 1 1	42 12 12 12
16	Zamindara Bus and Transport Company (P) Ltd., Rohtak	Jhajjar-Dadri Jhajjar-Dadri via Birhor-Imlofa	1 1	$\frac{1}{2}$ 1	27 54
17	Modern Co-operative Transport Society Ltd., Gurgaon	Gurgaon-Palwal extension upto Rasulpur	1	1	14
18	Rohtak-Bhiwani Transport Company Group 'A', Rohtak	Rohtak-Narnaul	1	$\frac{1}{2}$	76
19	Rohtak-Bhiwani Transport Company Group 'C', Rohtak	Bhiwani-Behl-Jhumpa	1	$\frac{1}{2}$	50
20	Paris Bus Service Rohtak	Ditto Sirsa-Nohar	1 3	$\frac{1}{2}$ 3	50 222

(granted the share of Roadways without creating any vested rights as the Roadways was not interested to operate on Sirsa-Nohar route)

## [Transport and Elections Minister]

Serial No.	Name of Transport Company/Transport Society	Name of route	Number of permits	Number of trips	Total mileage
21	Haryana Co-operative Transport Ltd., Kaithal	Kaithal-Jind Kaithal-Paupat Kaithal-Assandh-Panipat-Gohana	1 1 1	1 1 1	100 100 150
		(All the permits issued in rehabilitation claim in favour of the Haryana Co-operative Transport Ltd., Kaithal)			
22	The Rohtak District Co-operative Transport Society Ltd., Rohtak	Rewari-Mohinderghar Delhi-Rewari via Manesar	1 1	1 1	68 108
23	Rohtak-Haryana Transporters (P) Ltd., Rohtak	Jhajjar-Dadri Sonapat-Bagpat	1 1	1 1	27 24
24	Sadhaura Transport Company (P) Ltd., Sadhaura	Yamanagar-Derabassi Ambala-Derabassi	1 1	1 1	32 34
25	The Tourist Co-operative Transport Society, Ltd., Ambala City	Sadhaura-Naraingarh	1	1	42
26	Hansi Co-operative Transport Society, Ltd.	Barwala-Jullana	1	1	94
27	Hansi Co-operative Transport Society Ltd., Hansi	Uchana-Narnaund	1	1	50
28	The Kharar-Satnam Co-operative Transport Society, Ltd., Kharar	Chandigarh-Kurali via Siswan -Mullanpur-Gribdas	1	1	30
		(The permit has been issued on four monthly basis the share of Punjab Roadways, without creating any vested rights)			
29	The Tehsil Sirsa-Dehat Co-operative Transport Society Ltd., Sirsa	Dabwali-Sadaul Shahar via Sangria	1	1	94
30	The Abohar Hanumangarh Co-operative Transport Society Ltd., Abohar	Hanumangarh-Dabwali via Sangria	1	1	94
31	The Nalagarh Dehat Co-operative Transport Society Ltd., Nalagarh	Nalagarh-Suna	1	1	36
32	Nankanasahib Transport Company (P) Ltd., Ludhiana	Delhi-Sonapat	3	3	168

Permits granted to newly-formed Co-operative Transport Societies under 15 per cent of 50:50 scheme)

33	Bhutan-Zafraabad Co-operative Transport Society Ltd., Sonapat	Gohana-Sonapat via Purkhas-Pgthala	1	1	82
34	The Shivalak Co-operative Transport Society Ltd., Bhagwanpura -Ambala	Surajpur-Mullah	1	1	18
JULLUNDUR REGION					
1	New Himalaya Transport Company (P) Ltd., Batala	Batala-Qadian	1	1	24
2	Sheikhpura Transport Company, Ludhiana	Ludhiana-Nawanshehr via Bohara	1	1½	96
3	Sewak Bus and Transport Company Ltd., Moga	Ludhiana-Moga	1	1	86
4	New Majha Co-operative Transport Society, Amritsar	Khem Karan-Ludhiana via Harike	1	½	117
5	Akal Transport Company Ltd., Ludhiana	Ditto	1	½	117
6	Dashmesh Transport Company Ltd., Ludhiana	Ludhiana-Hissar via Sangrur	2	1	292
7	Jullundur Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur	Jullundur-Pathankot	1	1	142
8	Pritam Bus Service Ltd., Jullundur	Ditto	1	1	142
9	The New Sutlej Transport Company Ltd., Jullundur	Ludhiana-Jandiala	1	1	54
10	Victor Public Hill Motor Transport Company Ltd., Hoshiarpur	Una-Daulatpur via Mubarkpur	1	1	62
11	Hoshiarpur Azad Transport Company Ltd., Hoshiarpur	Mukerian-Talwara-Daulatpur	1	1	60
12	Kartar Bus Service Ltd., Jullundur	Jullundur-Mehatpur	1	1	42
13	Hoshiarpur National Transporters Ltd., Hoshiarpur	Mukerian-Talwara	1	1	34

## [Transport and Elections Minister]

Serial No.	Name of Transport Company/Transport Society	Name of route	Number of permits	Number of trips	Total mileage
14	Karnal General Labour Co-operative Society, Karnal	Abohar-Sadhuwala	1	1	52
15	New Majha Transport Co-operative Society Ltd., Amritsar	Amritsar-Rasulpur via Gandiwind	1	1	44
16	New United Transport Company (P) Ltd., Amritsar	Amritsar-Qadian	1	1	72
17	New Midh Bhawara Transport Company, Batala	Batala-Dera Baba Nanak Batala-Fatehgarh-Churian	1 1	1 1	38 32
18	New Himalaya Transport Company Ltd., Batala	Gurdaspur-Dera Baba Nanak	1	1	50
19	New Piyaar Bus Service Ltd., Amritsar	Amritsar-Verowal	1	1	54
20	Hamirpur Transport Co-operative Society, Hamirpur	Nangal-Awa Devi via Patta Bhakra Bridge	1	1	160
21	Dashmesh Transport Company Ltd., Ludhiana	Ludhiana-Payal-Dhamot-Bhadewal	1	1	60
22	Shiwalik Transport Company Ltd., Hoshiarpur	Pong Dam-Dharamsala via Dola Dehra	1	1	124
		Hoshiarpur-Pong Dam via Kotla Jorbar	1	1	118
23	Moga Transport Company Ltd., Moga	Moga-Nihalsingwala	1	1	48
24	Sandhu Transport Company (P) Ltd., Amritsar	Fatehabad-Patti	1	1	46
25	District Transport Co-operative Society Ltd., Amritsar	Amritsar-Ajnala-Dehra Baba Nanak	1	1	70
26	Sandhu Transport Company, Amritsar	Tarn-Taran - Verowal Tarn-Taran-Ratta-Gudava-Patti	1 1	1 1	50 72
27	National Transport and General Company, Ludhiana	Ludhiana-Machhiwara via Kohral	1	1	44

28	Azad Nakodar Bus Service Ltd., Jullundur	Nakodar-Kapurthala	3	3	132
29	Kulu Transport Co-operative Society Ltd., Kulu	Hoshiarpur-Jawalamukhi-Khundian (purely temporary)	1	1	96
		Hoshiarpur-Nadauan-Dhaneta (purely temporary)	1	1	86
30	Hamirpur Transport Co-operative Society, Hamirpur	Jawalamukhi road -Jahu (purely temporary)	1	1	108
31	Sharnarth Transport Co-operative Society Ltd., Abohar	Abohar-Muktsar (Kucha) (purely temporary)	1	1	70
32	Dasmesh Transport Company Ltd., Ludhiana	Ludhiana-Dhamot-Bhadwal Bridge	1	1	60
33	Onkar Bus Service (P) Ltd., Jullundur	Hoshiarpur-Rupar	1	1	116
34	New Sutlej Transport Company	Jullundur-Jandiala extended up to Nurmehal Ludhiana-Jandiala via Goraya	1	1	46 54
35	Pritam Bus Service Ltd., Jullundur	Jullundur-Pathankot	2	2	284
36	Kulu Transport Co-operative Society Ltd., Kulu	Hoshiarpur -Patlander	2	1	168
37	National Transport Company Ltd., Amritsar	Ludhiana-Machhiwara via Kohar	2	2	88
38	Randhawa Transport Company Ltd., Amritsar	Amritsar-Mehta Fatehgarh-Churain-Ajnala	2 1	2 1	100 32
39	Shiwalik Transport Company Ltd., Hoshiarpur	Hoshiarpur-Hamirpur via Gagret	1	1	58
40	Victory Public Hill Motor Transport Company, Hoshiarpur	Ditto	1	1	58

**Detention of Communist Detenus**

**3144. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that the detention of all the communist detenus in the State jails whose arrests warrants were issued on the 24th December, 1964, was declared illegal by a Bench of the Punjab High Court on 10th December, 1965, if so, whether the said detenus were released accordingly ;
- (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the names of those with dates who were re-arrested, the reasons therefor and the jails in which they are now detained ;
- (c) whether the Government is prepared to pay the compensation for the period of detention which has been declared illegal, if not, a copy of the High Court Judgement be laid on the Table of the House ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) No. However, the detenus were ordered to be released on technical grounds.

(b) List of persons who were re-arrested with dates and names of Jails where they are now detained is enclosed. They have been detained with a view to preventing them from acting in a manner prejudicial to the Defence of India and Civil Defence.

(c) The question of compensation does not arise. A copy of the Judgement is enclosed.

**LIST OF PERSONS WHO WERE RE-ARRESTED WITH DATES AND NAMES  
OF JAILS WHERE THEY ARE NOW DETAINED**

Serial No.	Name of person	Name of Jail	Date of re-arrest
1	2	3	4
<b>Sarvshri—</b>			
1	Rachhpal Singh, son of Haveli Ram Bhatia	.. Sangrur	15-12-65
2	Chhatar Singh, son of Ganesh Lal	.. Patiala	11-12-65
3	Mange Ram Vats, son of Hazari Lal Brahmin	.. Sangrur	11-12-65
4	Raghubir Singh Jhakhar, son of Prit Singh	.. Nabha	15-12-65
5	Gian Singh, Pleader, son of Subh Ram	.. Sangrur	11-12-65
6	Ishar Singh, son of Prabhu Dayal Singh Sodhi	.. Hissar	11-12-65
7	Gurbax Singh Dakota, son of Waryam Singh	.. Sangrur	11-12-65
8	Mehar Singh Khanpai, son of Talsa Singh Ramdasia	Nabha	11-12-65
9	Prof. K.R. Palta, son of Shadi Lal	.. Hissar	11-12-65
10	Dr. Bhag Singh, Ex-M.L.A., son of Sunder Singh	.. Nabha	14-12-65
11	Chanan Singh Dhut, son of Basant Singh Dhut	.. Sangrur	11-12-65
12	Ram Kishan Bharolian, Ex-M.L.A., son of Munshi Ram	Patiala	11-12-65

Serial No.	Name of person	Name of Jail	Date of re-arrest
1	2	3	4
13	Bhag Singh Sajjan, son of Nihala	.. Sangrur	11-12-65
14	Harkishan Singh Surjit, son of Harnam Singh	.. Delhi	13-12-65
15	Kishori Lal Rattan, son of Raghubir Datt Sharma	Hissar	11-12-65
16	Gurcharan Singh Randhawa, son of Panna Singh	.. Patiala	11-12-65
17	Pt. Bakhshi Ram, son of Banjhu	.. Sangrur	15-12-65
18	Gurbax Singh Atta, son of Partap Singh	.. Patiala	11-12-65
19	Udhe singh Keshav, son of Bhura Singh	.. Nabha	21-12-65
20	Dharam Singh, son of Bulaka Singh	.. Do	21-12-65
21	Sarwan Singh Cheema, son of Banta Singh	.. Sangrur	11-12-65
22	Dhanpat Rai Nahar, son of Mehnga Ram	.. Nabha	11-12-65
23	Gandharav Sen, son of Bhagwan Dass	.. Do	11-12-65
24	Satwant Singh, son of B Niranjana Singh	.. Do	11-12-65
25	Rachhpal Singh, son of Bishan Singh	.. Do	11-12-65
26	Chanan Singh Brar, son of Zora Singh	.. Sangrur	11-12-65
27	Daya Singh Prem, son of Kalu	.. Do	11-12-65
28	Dalip Singh Tapiala, son of Janmeja Singh	.. Do	11-12-65
29	Fauja Singh Bhullar, son of Arur Singh	.. Do	11-12-65
30	Makhan Singh Tarsika, son of Gujjar Singh	.. Patiala	16-12-65
31	Hazura Singh, son of Harbans Singh	.. Hissar	11-12-65
32	Darshan Singh Jhabal, son of Bawa Singh	.. Sangrur	11-12-65
33	Hazara Singh Jassar, son of Lachhman Singh	.. Nabha	21-12-65
34	Kartar Singh Gujapir, son of Narain Singh	.. Hissar	11-12-65
35	Bishan Singh, son of Sawan Singh	.. Sangrur	11-12-65
36	Sulakhan Singh, son of Partap Singh	.. Hissar	11-12-65
37	Amarmmeet Singh, son of Chanan Singh	.. Do	11-12-65
38	Prem Chand Bhardwaj, son of Jai Sita Ram	.. Do	11-12-65
39	Bhim Singh Advocate, son of Dalip Singh	.. Do	11-12-65
40	Harnam Singh Chamak, son of Achhara Singh	Patiala	11-12-65
41	Hardit Singh Bhattal, M.L.A., son of Ram Singh	Do	11-12-65
42	Vidya Dev Longowal, son of Kanshi Ram	.. Nabha	11-12-65
43	Ghuman Singh Ugrahan, son of Pala Singh	.. Do	11-12-65
44	Partap Singh Dhanaula, son of Attar Singh	.. Do	11-12-65
45	Dalip Singh Bhatiwala, son of Narain Singh	.. Hissar	11-12-65
46	Janak Singh Bhattal, son of Hari Singh	.. Nabha	21-12-65
47	Ganda Singh, son of Harnam Singh		

## [Home and Development Minister]

1	2	3	4
48	Gajjan Singh Tandian, son of Bishan Singh	.. Nabha	15-12-65
49	Karnail Singh Phide, son of Sarwan Singh	.. Hissar	11-12-65
50	Ram Singh Harinau, son of Sawan Singh	.. Nabha	11-12-65
51	Gurnam Singh Sibbian son of Dal Singh	.. Do	11-12-65
52	Balbir Singh, son of Jhanda Singh	.. Do	11-12-65
53	Dharam Singh Kasui, son of Sohan Singh	.. Hissar	11-12-65
54	Satya Mandan, son of Rao Madho Singh	.. Sangrur	11-12-65
55	Ganpat Singh, son of Ram Jiwan Ahir	.. Hissar	15-12-65
56	Mangal Singh, son of Sub. Ram Singh	.. Sangrur	14-12-65
57	Bhajan Singh, son of Ram Singh	.. Do	22-12-65
58	Devki Nandan, son of Ram Sarup Brahman	.. Hissar	22-12-65
59	Kesar Singh, son of Mala Singh	.. Amritsar	20-1-66

## COPY OF JUDGMENT

## IN THE HIGH COURT FOR THE STATE OF PUNJAB AT CHANDIGARH

## CRIMINAL WRIT SIDE

## Criminal Writ case No. 6 of 1965

Com. Dalip Singh Tabiala, resident of Tabiapal, Amritsar, now at District Jail, Nabha .. Petitioner

- (1) The State of Punjab through the Secretary to the Government, Home Department, Chandigarh;
- (2) Deputy Secretary, Government of Punjab, Home Department, Chandigarh;
- (3) S. Darbara Singh, Home Minister, Punjab, Chandigarh;
- (4) Shri Gulzari Lal Nanda, Home Minister, Central Government, New Delhi;
- (5) Superintendent, District Jail, Nabha

... Respondents

Case referred by Hon'ble Mr. Justice H.R. Khanna, on 19th July, 1965, to a large bench for decision of the important question of law involved in the case, and the case was finally decided by a division bench consisting of Hon'ble the Chief Justice D. Falshaw and Hon'ble Mr. Justice H.R. Khanna, on 10th December, 1965.

Petition under section 491 of the Code of Criminal Procedure read with Article 226 of the Constitution of India praying that detention order against the petitioner under the Defence of India Rules be quashed.

Dated the 10th December, 1965.

## PRESENT:

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE D. FALSHAW AND  
HON'BLE MR. JUSTICE H.R. KHANNA.

*For the petitioner.*— M/s B.K. Garg, S.C. Aggarwal and A.S. Bains, Advocates.

*For the Respondents.*— Mr. L.D. Kaushal, Senior Deputy Advocate-General, with Mr. S.K. Aggarwal, Advocate.

Dated, the 19th July, 1965.

PRESENT:

HON'BLE MR. JUSTICE H.R. KHANNA

*For the Petitioner.*—Mr. Anand Sarup, Advocate, and Mr. A.S. Bains, Advocate.

*For the Respondents.*—Mr. L.D. Kaushal, Senior Deputy Advocate-General, Mr. P.R. Jain, Advocate.

*For the Respondent No. 3.*—Mr. V.P. Prasher, Advocate.

#### ORDER

The petitioners in the present and connected habeas corpus petitions are the members of the Communist Party of India who have been ordered to be detained under rule 30(1)(b) of the Defence of India Rules by the Punjab Government. One of the main grounds on which the detention has been assailed is that though the order for detention was made formally by the Punjab Government it was in pursuance of a directive issued by Shri Gulzari Lal Nanda, Union Home Minister, that the petitioners were ordered to be detained. It is contended that the State Government did not independently take its decision to detain the petitioners and merely carried out the behest of the Union Home Minister. This contention has been resisted on behalf of the respondents and it averred that the decision to detain the petitioners was taken by the State Government independently. As the matter is of some importance and arises in a large number of petitions I am of the view that to secure an authoritative pronouncement on the subject it should be decided by a large Bench. I accordingly direct that papers may be laid before my Lord the Chief Justice for referring the matter to a larger Bench.

19th July, 1965

(Sd) H.R. KHANNA,  
Judge.

#### ORDER OF THE DIVISION BENCH

Forty-eight petitions have been filed under section 491, Criminal Procedure Code, read with Article 226 of the Constitution by various individuals and one petition has been filed under section 491, Criminal Procedure Code, by R.P. Manchanda. All the petitioners have been ordered to be detained under Rule 30(1)(b) of the Defence of India Rules by orders of the Government of Punjab. The first 48 petitioners are apparently all members of the so-called Left Wing of the Communist Party of India which is generally supposed to be Pro-Chinese and the orders under which their detention was ordered were all dated the 29th of December, 1964. The orders are in identical terms and I cite that issued regarding Harkishan Singh Surjeet petitioner as an example :

“WHEREAS Shri Harkishan Singh Surjeet, son of Harnam Singh, resident of Bundhala, district Jullundur, is reported to be indulging in anti-national and pro-Chinese propaganda and as such his activities are prejudicial to the Defence of India and Civil Defence ;

AND WHEREAS the Governor of Punjab is satisfied in respect of the said Harkishan Singh Surjeet that with a view to preventing him from acting in a manner prejudicial to the Defence of India and Civil Defence it is necessary that the said Harkishan Singh Surjeet be detained ;

NOW, therefore, in pursuance of the provisions of rule 30(1)(b) of the Defence of India Rules, the Governor of Punjab hereby directs that the said Harkishan Singh Surjeet be detained at Rohtak in the District Jail and in matters relating to the maintenance, discipline.....the said Harkishan Singh Surjeet shall be governed by the Punjab Detenus Rules, 1950, as amended up to date.”

The signature is that of the Deputy Secretary to Government, Punjab, in the Home Department, but it is not disputed that the orders were issued in the name of the Governor by the Home Minister, Shri Darbara Singh.

In the case of R.P. Manchanda, the order is dated the 5th of April, 1965. It reads:

“WHEREAS Shri Ram Parkash Manchanda, son of Shri Attar Singh, Assistant, Officer of the Life Insurance Corporation of India, Chandigarh, is reported to be indulging in activities prejudicial to the maintenance of public safety and maintenance of public order and peaceful conditions ;

## [Home and Development Minister]

AND WHEREAS the Governor of Punjab is satisfied in respect of the said Shri Ram Parkash Manchanda that with a view to prevent him from acting in a manner prejudicial to the maintenance of public safety and public order it is necessary that the said Shri Ram Parkash Manchanda be detained;

NOW, therefore, in pursuance of the provisions of rule 30 (1)(b) of the Defence of India Rules, the Governor of Punjab hereby directs that the said Shri Ram Parkash Manchanda be detained at Ferozepur in the District Jail and in matters relating to maintenance, discipline.....the said Ram Parkash Manchanda shall be governed by the Punjab Detenus Rules, 1950, as amended up to date."

Again the signature on the order is that of the Deputy Secretary in the Home Department and again it is not disputed that the Home Minister was responsible for it.

The petitions of the Left Wing Communists have been referred to a larger Bench by my learned brother Khanna J. because of the importance of the point raised that although the orders for detention of the petitioners were formally made by the Punjab Government it was in pursuance of a directive issued by Shri Gulzari Lal Nanda, the Union Home Minister, and it was contended that the State Government did not independently take the decision to detain the petitioners. The petition of R. P. Manchanda was also referred by my learned brother because of the difficulty and importance of the point raised that the order was made by Shri Darbara Singh in his capacity as Home Minister and according to the Business of the Punjab Government Allegation Rules of 1961 there was no Home Department and so Shri Darbara Singh could not pass an order for the detention of the petitioner in his capacity as Home Minister. This point also arises in connection with the detention of the Left Wing Communists.

The point on which the reference to a larger Bench was though necessary in the petitions of the Left Wing Communists appears to have been settled by the recent decision of the Supreme Court in the writ petition filed by *K. Ananda Nambiar and another v. The Chief Secretary, Government of Madras and others*, Civil Writ No. 47 of 1965, decided on the 27th of October, 1965. In that case the order for the detention of the petitioners had apparently been passed by the Chief Minister of Madras and the argument was raised that the Chief Minister had not really satisfied himself regarding the justification for detention but had been unduly influenced by certain pronouncements of the Union Home Minister. The matter is dealt with the following passage in the judgement by Gajendragadkar C.J. who delivered the judgment of the Court:—

"Bedsides, it is urged that the Chief Minister of Madras passed these orders without satisfying himself that it was necessary to issue them. He was influenced by what the Union Home Minister had already decided in regard to the petitioners. It is not as a result of the satisfaction of the Chief Minister himself that the petitioners had been detained, the orders of detention have been passed against the petitioners solely because the Union Home Minister was satisfied that they should be detained. That, in substance, is the grievance made before us by Mr. Chatterjee against the validity of the impugned orders of the detention.

It appears that the Union Home Minister made certain statements in his broadcast to the nation from the All India Radio on January 1, 1965, and in reply to a debate on the Budget Demands of the Ministry of Home Affairs in the Lok Sabha on April 27, 1965. This is what the Union Home Minister is reported to have said in his broadcast:—

'As you are aware, a number of leaders and active workers of the Left Communist Party of India have been detained during the last three days. We have had to take this step for compelling reasons for the internal and external security of the country. It is painful to us to deprive any citizen of this free country of his liberty and it is only after the most careful thought that we have taken this action.

This very disagreeable decision was taken after giving the most serious thought to all (Sic) that he would be taking a serious risk with the external and internal security of the country if we did not act immediately.'

"This is what the Union Home Minister is reported to have said in the Lok Sabha; (It is a matter of regret to me that I have had to make myself responsible

for throwing into prison a fairly large number of citizens of this country. I look into the cases personally. I may say that it may be that some error may have occurred here and there ; that test has to be satisfied. We have to make sure that it is because of our clear appreciation of the activities which we may call pro-Chinese, disloyal activities, subversive activities, one way or another, that we have to resort to this kind of action. If on any person, any detenu on his part, it can be said that there was a mistake made, that he actually is not pro-Chinese and he is a loyal citizen of the country I personally am prepared to look into each case and again satisfy myself that no wrong has done or no injustice has been done.'

"For the purpose of dealing with the present petition, we are assuming that the petitioners can rely upon these two statements. The learned additional Solicitor General no doubt contended that these statements were not admissible and relevant and had not been duly proved. Besides, according to him, some of the statements produced were also inaccurate; even so, he was prepared to argue on the basis that the said statements can be considered by us, and so, we have not thought it necessary to decide the question about the relevance or admissibility or proof of these statements in the present proceedings.

In appreciating the effect of these two statements, it is necessary to refer to these statements made on affidavit by the Chief Minister of Madras and the Chief Secretary to the Government of Madras respectively. This is what the Chief Minister of Madras has stated on oath—

'Consequent upon the outbreak of hostilities between China and India and declaration of Emergency, it was necessary for the Government of India and the various states to watch carefully the movements and activities of those persons who either individually or as part of any group were acting or likely to act in a manner prejudicial to the safety of India and the maintenance of public order. The Communist Party of India was rift into two factions and the faction known as the Left Communist Party of India, which came to be known as the pro-Peking faction, had particularly to be watched. The question of detaining persons belonging to this faction and who were also active was engaging the attention of the Governments and was also discussed at the Chief Ministers' Conference. Our sources of intelligence continued to maintain a watch over the movements and activities of these individuals. The Communist Party of India being an All India organisation with a wide network, the question with a wide of detention had necessarily to be considered on a national level, so that a co-ordinated and concerted action may be taken. It was in this context that the Central Government communicated with the State Government.

I submit that I ordered the petitioners in the above petitions to be detained on the 29th December, 1964. The petitioners are also known to me and their detention was ordered on my personal satisfaction that it was necessary. My satisfaction was both on the general question as to the need for detaining persons like the petitioner and on the individual question namely whether the petitioner was one such whose detention was necessary.

The Chief Secretary's affidavit is on the same lines.

On these statements the question which falls to be decided is, is it shown by the petitioners that the impugned orders of detention were passed for an ulterior purpose, or that they have been passed by the Chief Minister of Madras without satisfying himself merely because the Union Home Minister thought that the petitioners should be detained. It is not disputed that if the Union Home Minister wanted to make an order detaining the petitioners he could have made the order himself. But the contention is that the orders in fact have been made by the Government of Madras and it is, therefore, necessary to consider whether the Chief Minister of Madras satisfied himself or not.

In dealing with these pleas we cannot ignore the fact that the question about detaining the petitioners formed part of a large question about the attitude which the Government of India and the State Government should adopt in respect of the activities of the party to which the petitioners belong. This party is known as the Left Communist Party of India

[Home and Development Minister]

which came to be known as the pro-Peking faction of the Communist Party. It is therefore not surprising that this larger issue should have been examined by the Union Home Minister alongwith the Chief Ministers of the State in India. The sources of intelligence available to the Government of India had given it the relevant information. Similarly the sources of information available to the Governments of different States had supplied to their respective States the relevant information about the political activities of the Left Communist Party of India. Having considered these reports, the Union Home Minister and the Chief Ministers came to certain decision in regard to the approach which should be adopted by them in respect of the Left Communist Party in view of the Emergency prevailing in the country. This general decision naturally had no direct relation to any particular individual as such. The decision in regard to the individual members of the Left Communist Party had inevitable to be left to the State Governments or the Union Government according to their discretion. It is conceded that the Union Government had in fact issued orders of detention against as many as 140 members of the Left Communist Party of India whereas different orders of detention have been passed by different State Governments against members of the Left Communist Party in their respective States. It is in the background of this position that the statements of the Union Home Minister as well as those of the Chief Minister of Madras have to be considered.

Thus considered, we do not see any justification for the assumption that the detention of the petitioners was ordered by the Chief Minister of Madras without considering the matter himself. Indeed, it is not denied that the Chief Minister knows both the petitioners and he has stated categorically that he examined the materials in relation to the activities of the petitioners and he was satisfied that it was necessary to detain them. We see no reason whatever why this clear and unambiguous statement made by the Chief Minister of Madras should not be treated as true. As the Chief Minister States in his affidavit, his satisfaction was both on the general question as to the need for detaining persons like the petitioners and on the individual question of each one of them. In this connection it is obvious that he was speaking for the Union Government and the State Governments as well, and when he spoke in the first person singular he was referring to cases with which he was concerned as the Union Home Minister and that would take in cases of persons whose detention has been ordered by the Union Government. There is therefore no inconsistency or conflict between the statements of the Union Home Minister and the affidavit of the Chief Minister of Madras. That being so, we are satisfied that there is no substance in the grievance made by Mr. Chatterjee that the impugned orders of detention passed against the petitioners were made either *mala fide* or without the proper satisfaction of the detaining authority."

In the present cases the affidavit of the Home Minister reads:—

"I, Darbara Singh, Home and Development Minister, Punjab Government, do hereby solemnly affirm and say as under:—

1. I say that I have been Minister in charge of Home portfolio of the Punjab Government since July 1964 and all matters relating to detenus are put up before me through proper channel with all relevant records and papers, *vide* item No. 4 (Misc.) Rules of Business, Vol. I, page 28. The papers relating to the detention of the detenu in the instant case were also out before me.
- (2) I have been read the petition and affidavit of Shri\_\_\_\_\_dated \_\_\_\_\_
- (3) I further say that I considered reports of intelligence and other material relating to the activities of Shri\_\_\_\_\_and as a result thereof I was satisfied that his activities were prejudicial to the defence of India and civil defence and that it was necessary to detain him with a view to preventing him from acting in any prejudicial manner.

- (4) I also say that the detention order against the detainee was passed by me after examining his individual case and the assertion that the same was passed at the instance of Shri Gulzari Lal Nanda, the Union Home Minister, is incorrect."

It seems to me that even if the statement made in the last sentence is not strictly accurate in the sense that there had actually been some consultations between the Central Government and the State Government as regards the attitude to be adopted towards the pro-Chinese Wing of the Communist Party of India as has been described in the judgement of the Supreme Court, I still do not see sufficient reason for not accepting the assurance of the Home Minister that the activities of each of the petitioners were considered before the decision was taken that it was necessary to detain him.

The next point which arises in all the cases is the power of the Home Minister of the State of Punjab to pass an order for detention under rules 3 of the Defence of India Rules. Our attention has been drawn to the Rules of Business of the Punjab Government, Part I, These are rules drawn up under clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution by the Governor. The rules read:—

- (2) The business of the Government shall be transacted in the Departments specified in the Schedule annexed, and shall be classified and distributed among those Departments as laid down therein.
- (3) The Governor shall, on the advice of the Chief Minister, allot among the Ministers the business of the Government by assigning one or more Department to the charge of a Minister ;

Provided that nothing in this rule shall prevent the assigning of one Department to the charge of more than one Minister.

- (4) Each Department of the Secretariat shall consist of the Secretary to the Government, Who shall be the official head of the Department, and of such other officers and servants subordinate to him as the State Government may determine ;

Provided that:—

- (a) more than one Department may be placed in charge of the same Secretary,
- (b) the work of a Department may be divided between two or more Secretaries."

Then follows the Schedule by which the business is allocated among the various named Departments which are 33 in number. Admittedly there is no Home Department or Department of Home Affairs among these Departments. However, at the time when these orders were passed by the Home Minister the distribution of work among the Council of Ministers was governed by a Gazette Extraordinary notification of the 7th of July, 1964 in which Shri Darbara Singh was described as Home and Development Minister and the portfolio allotted to him read—

- “(1) Home (including Integration).
- (2) Elections.
- (3) Community Development (including Panchayats, Panchayati Raj and Development of Hill Areas).
- (4) Agriculture.
- (5) Fisheries.
- (6) Animal Husbandry.
- (7) Dairying.
- (8) Co-operation.”

## [Home and Development Minister]

In the Home Ministers's affidavit the position was taken up that the Home portfolio consisted of Departments of which the Home Secretary was the official head. This, however, does not appear to be entirely correct since even in the distribution of work in the notification of the 7th of July, 1964 the Jails Department was allotted to the Chief Minister and at page 23 of part I of the Rules of Business the Jails Department is shown as being administered through the Home Secretary. Moreover ordinarily the Department of Law and Order would certainly appear to be included in the portfolio of the Home Minister and yet at page 26 of the Rules of Business it is stated that this Department is administered through the Chief Secretary. At the same time it would seem that orders for detention under the Defence of India Rules are not included in the heads of business in the Department of Law and Order. The only reference to detention is at item No. 33 which reads:—

“Preventive Detention Act, 1950 and Punjab Security of the State Act, 1951. including Advisory Board References relating to.”

The power to issue orders of detention under the Defence of India Rules is claimed to be part of the business of the Home Minister as falling in the so-called. Miscellaneous Department administered through the Home Secretary at page 28 where item No. 4 reads:

“Detenus, Security Prisoners and State Prisoners References relating to actual detention of.”

Although it would have been better if in the allotment of the Home Portfolio to a particular Minister the exact nature of the tasks allotted to him were more clearly defined by specifying the particulars Departments categorised in the Schedule, since according to rule 3 it is Departments, and not portfolios, which are to be allotted, there is no reason for not believing that in fact the Department of Law and Order and the Miscellaneous department administered through the Home Secretary fall within the scope of the Home Minister's portfolio. The question therefore is whether under the Departments allotted to him was included the power of detaining under the Defence of India Rules.

On one point there can be no doubt, namely that if the function of detaining for the reasons for which an order of detention has now been passed under the Defence of India Rules already existed in the Rule of Business there was no necessity for any fresh allocation among Ministers under Article 166(3) of the Constitution. This is settled by the following passage in the judgment of the Supreme Court in *Godavari Shamrao Parulekar and another v the State of Maharashtra and others*, A.I.R. 1964 Supreme Court 1128—

“The next argument is that there is no order of allocation made by the Governor or under Article 166 of the Defence of India Ordinance and the Rules framed thereunder and therefore the allocation of business by the Rules of Business which were enforced by an order of the Governor dated May, 1, 1960 would not be of any effect in allocating the subject of preventive detention arising under the Defence of India ordinance, Act and the Rules to the Minister and the Governor should have passed the order of detention himself. We are of opinion that there is no force in this contention. Allocation of business under Article 166(3) of the Constitution is not made with reference to particular laws which may be in force at that time the allocation is made; it is made with reference to be three lists of the Seventh Schedule to the constitution for the executive power of the Centre and the State together extends to matters with respect to which parliament and the Legislature of a State may make laws. Therefore, when allocation of business is made it is made with reference to the three lists in the seventh schedule and thus the allocation in the rules of business provides for all contingencies which may arise for the exercise of the executive power. Such allocation may be made even in advance of legislation made by Parliament makes to be available whenever parliament makes a legislation conferring, power on a state Government with respect to matters in list I of the seventh schedule. It was therefore in our opinion not necessary that there should have been an allocation made by the Governor under article 166(3) of the power to detain under the Defence of India Ordinance, Act and rules after they were passed, it will be enough if the allocation of the subject, to which the defence of India ordinance, act and rules refer has been made with reference to the three lists in the seventh

schedule and if such allocation already exists, it may be taken advantage of it and when laws are passed reference to the three lists in the Seventh Schedule and if such allocation already exists, it may be taken advantage of it and when laws are passed”.

In that case the detenus had been detained by the Minister in charge of the Home Department of the Maharashtra Government with a view to preventing them from acting in a manner prejudicial to the defence of India, the public safety and the maintenance of public order. The grounds thus fell under two heads, one relating to the public order of the State, for which the state could legislate under item (3) in the concurrent lists in the seventh schedule to the constitution, and the second relating to the defence of India, which was a matter falling in the first list in the seventh schedule, i.e. the Union list. However, section 40 of the defence of India Act permits the delegation of powers under the Act to the State Government even regarding matters on which the State Legislature is not competent to legislate. The rules of Business of the Maharashtra Government were examined and it was found that at item No. 7 in the business of the Home Department (Special) provision was made for preventive detention for reasons connected with the security of the State, the maintenance of public order and so on, while at the same time, in the rules of Business relating to the so-called General Administration Department, provision was made at item No. 44 for preventive detention for reasons connected with defence, foreign affairs or the security of India. In these circumstances the only question that arose was whether the Minister who passed the order of detention was in charge of both the Departments concerned, and when it was found that he was so in charge the detention order was upheld.

In my opinion, however, it cannot possibly be said that there was anything in the Punjab Government rules of Business which anticipated legislation by the Central Government enabling the state Government to detain persons under the Defence of India Rules such as existed in clear language in item No. 4 in the Central Administration Department of the Maharashtra Government. *Prima facie* the only function of detention provided for in the Punjab Rules of Business is detention under the Preventive Detention Act of 1952 or the Punjab Security of the State Act of 1951, which appears at item No. 33 in the business of the Department of law and order Administered by the Home Minister through the Chief Secretary. It seems to me to be straining the language beyond endurance to read into item No. 4 of the business of the miscellaneous Department administered through the Home Secretary any function of detaining under any Act. Indeed the plain meaning of the two items appears to me to be that matters relating to passing of orders of detention under the Preventive Detention Act and the Punjab Security of the State Act are to be dealt with by the Home Minister through the Chief Secretary, and that the other item to be dealt with by the Home Minister through the Home Secretary merely relates to the conditions of detention of persons already ordered to be detained either under the Preventive Detention Act or the Punjab Security of the State Act. When headings are drawn up as in the lists of departmental business contained in the schedule it is ordinary practice to put the main subject first and then details afterwards and . . . . and if item No. 4 in the Miscellaneous Departments business were put into ordinary English it would read, “References relating to actual detention of detenus, security prisoners and State Prisoners”. Here the words ‘security prisoners’ would evidently refer to prisoners detained under the (Central) Preventive Detention Act and the words ‘State Prisoners’ to persons detained under the Punjab Security of the State Act. In either case the subject is merely confined to administrative matters relating to the conditions of detention for any reason whatever can possibly be read into the words.

As a matter of fact it would not appear that the manner in which the functions relating to detention were set out in the Maharashtra Rules of Business was in anticipation intelligent or otherwise, of the delegation of powers to the State Government under the Defence of India Act and Rules. Section 3 of the Preventive Detention Act reads:—

“(1) The Central Government or the State Government may:—

- (a) if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to—
  - (i) the defence of India, the relations of India with foreign powers or the security of India
  - or
  - (ii) the security of the State or the maintenance of public order, or
  - (iii) the maintenance of supplies and services essential to the community.

## [Home and Development Minister]

It is necessary so to do make an order that such person be detained."

Thus the State Governments were already empowered under the Preventive Detention Act Section 3 (1) (a) (i) to detain on grounds contained in List I on which only the Central Government could legislate. Such being the case, it is unfortunate that when power to detain under the Defence of India Rules was delegated to the State Government item No. 33 in the business of the Department of Law and Order, Punjab Rules of Business conducted through the Chief Secretary was not amended so as to include such detention. Since merely the grounds of detention were mentioned in the functions of the different departments in the Maharashtra Rules of Business, and not particular Acts as here, no amendment of those rules became necessary when the power to detain under the Defence of India Rules was delegated to the Maharashtra Government.

It might perhaps have been argued that since detention on the grounds on which the present detentions have been ordered was already within the functions of the Home Minister whose portfolio included the Department of Law and Order, though only under the Preventive Detention Act, these detentions were not outside the scope of his functions. This argument would, however, have to be repelled on two grounds. In the first place this was not the position adopted on behalf of the respondents who took their stand on the position that additional powers of detention beyond those at item No. 33 were conferred by item No. 4 of the business done through the Home Secretary, point with which I have dealt above. At this stage no such new position could be adopted. In the second place, although these detentions might all have been ordered under the powers conferred by the Preventive Detention Act, in fact they were not, and they were specifically made under rule 30 of the Defence of India Rules. Nor can they now be deemed to have been made under the Preventive Detention Act, since the incidents of detention under this Act differ considerably from those of detention under rule 30. For instance in detentions under the Preventive Detention Act the detenu has to be supplied with a copy of the grounds of his detention so as to enable him to make a representation to the detaining authority, and the decisions of the courts have seen to it that these grounds have to be detailed and specific. The detenu also has to be allowed to have his case considered by an Advisory Board composed of responsible persons who can hear him personally and also call for further information from the Government. No such privileges and safeguards exist in the case of detention under the Defence of India Rules.

For these reasons I am of the opinion that the detention orders of the present petitioners are bad for the reasons that their detention could not be ordered by the Home Minister in exercise of the functions conferred on him by the Rules of Business of the Punjab Government. Although the detention of R.P. Manchanda has been ordered to prevent him from acting in manner prejudicial to the maintenance of public order, the same arguments apply in his case also.

Only one other point remains regarding the order of detention of Harkishen Singh Surjeet who it appears is ordinarily resident of this State ; but in December, 1964 when the decision to take general action against Pro-Chinese Communists was taken happened to be in the State of Kerala. Orders for his detention were passed both by the Governments of Kerala and of this State and he was actually arrested and detained under the orders of the Kerala State Government, but about three months later, after some consultation between the States and the Centre the order of the Kerala State Government was cancelled and Harkishan Singh Surjeet was transferred to this State and detained under the order passed by this Government. The argument was advanced that he ought to be released because the only effective order of detention that was passed by the Kerala Government had been cancelled, and the order of the Government of this State had been a nullity from the beginning because of the order of the Kerala Government. There does not appear to me to be any force in this argument since clearly all that happened was that two orders were passed one of which was superfluous, and now, all that has happened is that the order of this State has been made effective on his transfer here and the unnecessary order of the Kerala Government cancelled. His petition nevertheless is entitled to succeed on the ground set out above. The result is that I would accept the petitions of the Left Wing Communist detenus as well as of R.P. Manchanda and order their release.

10th December, 1965.

I agree.

Word:—6787

Cost:—Rs 17

True copy

Supervisor Copy Branch.

(Sd.).....  
D. FALSHAW,  
Chief Justice.

(Sd). H.R. KHANNA.  
Judge.

**Industrial Co-operative Societies in Amritsar District**

**3146. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names and addresses of the Industrial Co-operative Societies in Amritsar District, at present together with the details of industries being run by them ;

(b) the quantity of raw material allotted to them during the years 1964-65 in each case ?

**Chaudhri Rizaq Ram (Minister for Irrigation and Power) :** (a) and (b). The requisite information is enclosed.

**Industrial Co-operative Societies in Amritsar District**

(a)		(b)
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
1	The Raj Hosiery Production Co-operative Industrial Society, Ltd., Jandiala Guru (Amritsar)	Hosiery ..
2	The Majitha Handloom Production Co-operative Industrial Society, Ltd., Majitha	Handloom ..
3	The Majitha Deep Handloom Production Co-operative Industrial Society, Ltd., Majitha	Do ..
4	The Wadlala Viram Oil Production Co-operative Industrial Society, Ltd., village Wadala Viram, post office Majitha	Oil ..
5	The United Textile Production Co-operative Industrial Society, Ltd., village Bhoman, post office Majitha	Under binding up orders ..
6	The Dhing Nangal Weavers Production Co-operative Industrial Society, Ltd., village Dhing, post office Majitha	Weavers ..
7	The Verka Weavers Production Co-operative Industrial Society, Ltd., village post office Verka	Do ..
8	The Waryam Nangal Weavers Production-cum-Sale C.I.S., Ltd., Waryam Nangal, post office Kathu Nangal	Do ..
9	The Chavinda Devi Textile P.C.S., C.I.S., Ltd., Chavinda Devi, post office Kathu Nangal	Do ..
10	The Bhangali Janta Oil Production C.I.S., Ltd., Bhangali, post office Bhangali Kalan	Oil ..
11	The Majitha Ramdasian Shoe-makers Production C.I.S., Ltd., Majitha	Shoes ..

Serial No.	(a) Name and address of Industrial Co. operative Societies	(b) Industries being run by the societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
12	The Nangali Nowshera H/P of Rice Production-cum-Sale C.I.S., Ltd., Nangali Nowshera	H/P of rice	..
13	The Ajnala Ban-making Production C.I.S., Ltd., village post, office Ajnala	Ban-making	..
14	The Ajnala Oil Ghani Production C.I.S., Ltd., Ajnala	Oil	..
15	The Ajnala Brick Kiln Production C.I.S., Ltd.	Bricks	..
16	The Ajnala Iron Works Production C.I.S., Ltd.	Iron work	..
17	The Jagdev Kalan Weavers Production C.I.S., Ltd., Jagdev Kalan	Weavers	..
18	The Bal Bawa Weavers Production C.I.S., village, post office Bal Bawa	Do	..
19	The Jassar Weavers Production C.I.S., Ltd., village, post office Jassar	Do	..
20	The Jassar Oil Ghani Production C.I.S., Ltd., Jassar	Oil	..
21	The Jassar Brick Kiln Production C.I.S., Ltd., Jassar	Bricks	..
22	The Thoba Oil Production C.I.S., Ltd., Thoba	Oil	..
23	The Longomal Brick Kiln Production C.I.S., Ltd., Longomal	Bricks	..
24	The Suffian Leather Production C.I.S., Ltd., Suffian	Leather	..
25	The Suffian Oil Ghani Production C.I.S., Ltd.	Oil Ghani	..
26	The Sansara Kalan Brick Kiln Production C.I.S., Ltd., Sansara Kalan	Bricks	..
27	The Chogawan Weavers Production C.I.S., Ltd., Chogawan	Weavers	..
28	The Chogawan Oil and Soap Production C.I.S., Ltd., Chogawan	Oil and Soap	..
29	The Chogawan Oil Ghani Production C.I.S., Ltd., Chogawan	Oil	..
30	The Chogawan Agriculture Implement Production C.I.S., Ltd., Chogawan	Agriculture Implements	..
31	Chogawan Bombay Cycle Parts Production C.I.S.	Cycle parts	..

Serial No.	(a) Name and address of Industrial Co-operative Societies	(b) Industries being run by the societies	(c) Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
32	The Adarsh Handmade Paper Production C.I.S., Kanwar	Paper	..
33	The Kohali Weavers Production C.I.S., Ltd., Kohali	Weavers	..
34	The Madhoke Flaying and Tanning C.I.S., Ltd., Madhoke	Flaying and Tanning	..
35	The Vaniake Weavers C.I.S., Ltd., Vaniake	Weavers	..
36	The Bhindi Oh-lakh Oil and Soap Production C.I.S., Ltd., Bhindi	Oil and Soap	..
37	The Preet Nagar Oil Ghani Production C.I.S., Ltd., Preet Nagar	Oil	..
38	The Harsha China Oil Ghani Production C.I.S., Ltd., Harsha China	Do	..
39	Navjeevan Flaying and Tanning C.I.S., Ltd., Ajnala	Flaying and Tanning	..
40	The Harsha China Textile C.I.S., Ltd., Harsha China	Weavers	..
41	The Harsha China Leather Production C.I.S., Ltd.	Leather	..
42	The Khiala Kalan Brick Kiln C.I.S., Ltd., Khiala Kalan, Amritsar	Bricks	..
43	The Raja Sansi H/P of Rice C.I.S., Ltd., Raja Sansi	H/P of Rice	..
44	The Raja Sansi Carpet-makers C.I.S., Ltd.	Carpet	..
45	The Kamashe H/P of Rice C.I.S., Ltd., Kamashe	H/P of Rice	..
46	The Saidpur Gur and Khandsari C.I.S., Ltd., G/K Saidpur, post office Mehta		..
47	The Amritsar Oil and Soap Production C.I.S., Ltd.	Under winding up process	..
48	The Amritsar Mechanical Production C.I.S., Ltd., Amritsar, Ghee Mandi	Mechanical	..
49	The Amritsar Janta Radio Production C.I.S., Ltd., Hall Bazar, Amritsar	Radio	..
50	The Bharat Engineering Production C.I.S., Amritsar	Engineering	..

[Minister for Irrigation and power]

(a)		(b)
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies	Industries being run by the societies
		Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
51	The Amritsar Bharat Textile C.I.S., Ltd.	Under liquidation ..
52	The Amritsar Good Luck Mechanical Production C.I.S., Pathankot Road, Amritsar	Mechanical ..
53	The Hussainpur Oil Ghani Production C.I.S., Ltd., Amritsar	Oil ..
54	The Amritsar Punjab Education Films Production C.I.S., Ltd., Laurance Road, Amritsar	Films ..
55	The Punjab Textile P.C.S., C.I.S., Ltd., Ghee Mandi, Amritsar	Weavers ..
56	The Rose Textile Production C.I.S., Ltd., Kashmir Road, Amritsar	Do ..
57	The Amritsar Sohal Engineering C.I.S., Ltd., Kot Atma Singh, Amritsar	Engineering ..
58	The Vallah Oil Ghani C.I.S., Ltd., Vallah	Oil ..
59	The Mudhal Oil Ghani Production C.I.S., Ltd., Mudhal, post office Verka	Do ..
60	The Amritsar Oil and Soap Production C. I. S., Ltd.	Under winding up process ..
61	The Amritsar Small Enterparneur C.I.S. Ltd.	Ditto ..
62	The Sitara Weavers Production-cum-Sale C.I.S., Ltd., Chatiwind, Amritsar	Weavers ..
63	The Amritsar Jai Bharat Production C.I.S., Ltd. Inside Hall Gate, Amritsar	Leather ..
64	The Amritsar Allied Appliances C.I.S., Ltd.	Under winding up order ..
65	The Amritsar Brick Kiln Production C.I.S., Ltd., H. No. 216, Amritsar (Hussainpura)	Bricks ..
66	The Amritsar Janta Central Leather C.I.S., Ltd., Katra Sher Singh, Amritsar	Leather ..
67	The Amritsar K. Khadi and G.U. C.I.S., Ltd.	Under winding up orders ..
68	The Karampura Weavers C.I.S., Ltd., Karampura	Weavers ..
69	The Amritsar Leather Production C.I.S., Ltd., Katra Sher Singh, Amritsar	Leather ..

(a)			b
Serial No.	Name and address of industrial Co operative Societies	Industries being run by the Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
70	The Amritsar Ekta Handloom Production C.I.S., Ltd., near Chitra Talkies, Amritsar	Weavers	..
71	The Rattna Handloom Production C.I.S., Ltd., Partap Bazar, Amritsar	Do	..
72	The Punjab Weavers C.I.S., Ltd., Amritsar inside Khazana Gate	Do	..
73	The Amritsar Bharat Thathiar Production C.I.S., Ltd., Bazar Thathiaran, Amritsar	Utensils	..
74	The Saido Lehal Weavers C.I.S., Ltd., Saido Lehal	Weavers	..
75	The Chatiwind Lehal Oil C.I.S., Ltd., Chatiwind Lehal	Oil	..
76	The Seed Crushing and General C.I.S., Ltd., Rayyia	Seed Crushing	..
77	The Rana Handicraft and Dying P.C.S., C.I.S., Ltd., Katra Sher Singh, Amritsar	Handicraft	..
78	The Garib Tanning Production C.I.S., Ltd., Amritsar	Tanning	..
79	The Punjab Co-operative Leather Production C.I.S., Ltd., Katra Karam Singh, Amritsar	Leather	..
80	The Ravidas Tanning P.C.S., C.I.S., Ltd., Katra Sher Singh, Amritsar	Tanning	..
81	The Amritsar Delight Radio Production C.I.S., Ltd., Hall Bazar, Amritsar	Radio	..
82	The Shabe Rose Oil Production C.I.S., Ltd.	Under winding up orders	..
83	The Darbar Textile P.C.S., C.I.S., Ltd., Bhagtanwala Gate, Amritsar	Weavers	..
84	The Jwahar Textile Production C.I.S., Ltd., Gali Satto Wali, Amritsar	Do	..
85	The Sathiala Weavers P.C.S., C.I.S., Sathiala	Do	..
86	The Sathiala Leather P.C.S., C.I.S., Ltd., Sathiala	Leather	..
87	The Mehta Leather C.I.S., Ltd., Mehta	Do	..
88	The Butari Weavers C.I.S., Ltd., Butari	Weavers	..
89	The Butari Oil and Soap C.I.S., Ltd., Butari	Oil and Soap	..
90	The Bhilloval H/P of Rice R.C.S., C.I.S., Ltd., Bhilloval	H/P of Rice	..
91	The Mattewal Oil and Soap Production C.I.S., Ltd., Mattewal	Oil and soap	..

(a)			(b)
Serial No.	Name and address of industrial Co. operative Societies	Industries being run by the Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
92	The Kale-ke Rural Weavers C.I.S., Ltd., Kaleke	Weavers	..
93	The Punjab H/P of Rice P.C.S., C.I.S., Ltd., Chaurasti Attari, Amritsar	H/P of Rice	..
94	The Cycle and Motor Spare Parts C.I.S., Ltd., Sangarana Sahib, Amritsar	Cycle and motor parts	..
95	The Sangarana Textile Production C.I.S., Ltd., Sangiana Sahib, Amritsar	Weavers	..
96	The Amritsar Cutlery and Spare Parts C.I.S., Ltd., Katra Sufaid, Amritsar	Cutlery	..
97	The Janta Lime P.C.S., C.I.S., Ltd., Ram Bagh Gate, Amritsar	Lime	..
98	The Januja Soap P.C.S., C.I.S., Dhab Vasti Ram, Amritsar	Soap	..
99	The Amritsar Friends Screen and Printing C.I.S., Ltd., Bazar Karam Singh, Amritsar	Printing	..
100	The Amritsar General Manufacturing S.M., C.I.S., Bazar Kathiana, Amritsar	Do	..
101	The Kanwar Handloom P.C.S., C.I.S., Ltd., Jaura Pull, Amritsar	Weavers	..
102	The Amritsar National Handloom P.C.S., C.I.S., Katra Sufaid, Amritsar	Do	..
103	The Amritsar Navyug Harijan Engineering Production C.I.S., Ltd., Lahori Gate, Amritsar	Engineering	..
104	Amritsar Stationery P.C.S., C.I.S., Ltd., Chowk Baba Sahib, Amritsar	Stationery	..
105	The Modern Handicraft P.C.S., C.I.S., Ltd., Chowk Passian,	Handicraft	..
106	The Amritsar Sewak Oil P.C.S., C.I.S., Ltd., Dal Mandi	Oil	..
107	The Amritsar Indian Engineering P.C.S., C.I.S., Ltd., inside Chatiwind Gate, Amritsar	Engineering	..
108	The Hind Weavers C.I.S., Ltd., inside Hathi Gate, Amritsar	Weavers	..
109	The Navdeep Films Production C.I.S., Ltd., B-Block, outside Chatiwind Gate, Amritsar	Films	..
110	The Parbhat Slate P.C.S., C.I.S., Ltd., Bazar Loharan	Slate	..
111	The Parcha Bufan C.I.S., Ltd., village post office Varpal	Weavers	..

	(a)		(b)
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies	Industries being run by the societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
112	The Amritsar National Textile C.I.S., Ltd., Ghee Mandi, Amritsar	Weavers	
113	The Amritsar Textile C.I.S., Ltd., Chowk Bahian, Amritsar	Do	..
114	The Manawala Weavers C.I.S., Ltd., village post office Manawala	Do	..
115	The Kailash Handloom C.I.S., Ltd., Lakar Mandi, Amritsar	Do	..
116	Amritsar Popular Engineering C.I.S., Ltd., G.T. Road, Amritsar	Engineering	..
117	The Amritsar Swarankar Engineering P.C.S., C.I.S., Ltd., Ajit Nagar, Amritsar	Do	..
118	Amritsar Desi Jora -Makers C.I.S., Ltd., inside Sultanwind Gate, Amritsar	Shoes	..
119	The Mohinder Mechanical Engineering P.C.S., C.I.S., Ltd., Railway Road, Amritsar	Engineering	..
120	The Amritsar Friends and Cycle Spare Parts Electroplating C.I.S., Ltd., Kot Bhagat Singh, Amritsar	Cycle spare parts	..
121	The New Asia Engineering C.I.S., Ltd., 152-Karkhana Bazar, Amritsar	Engineering	600 Kgs. Copper 400 Kgs. Zinc
122	The Sultanwind Oil and Soap Production C.I.S., Ltd., Sultanwind	Oil and Soap	..
123	The Amritsar Dairy and Milk Production C.I.S., Ltd., New Rego Bridge	Milk Production	..
124	The Novelty Radio C.I.S., Ltd., Bazar Bikanarian, Amritsar	Radio	..
125	The Amritsar Wool Workers C.I.S., Ltd., 1478/76, Muni Chowk, Amritsar	W/works	..
126	The Rajindra Sports Production C.I.S., 76-B, Hall Gate, Amritsar	Sports	..
127	The Dashesh Engineering P.C.S., C.I.S., Ltd., Sultanwind Road, Amritsar	Engneeing	..
128	Tarjindra Mechanical Production C.I.S., Ltd., Khata Tirath Ghali Bhallian, Amritsar	Do	..
129	The Amritsar Stationery Printing C.I.S., Ltd., Bazar Mai Sewan, Amritsar	Stationery	..

(3)110

PUNJAB VIDHAN SABHA [17TH FEBRUARY, 1966  
[Minister for Irrigation and power ]

a			b
Serial No.	Name and address of industrial Co operative Societies	Industries being run by the Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
130	Amritsar Co-operative Industrial Bank, Ltd.	Under Liquidation	..
131	The Jandiala Industrial Estate Ltd., Jandiala Guru	Industrial	..
132	The Friends Utensil Production C.I.S., Ltd., Bazar Bhatrian, Jandiala Guru	Utensil	57.800 Kgs. Copper
133	The Vaishno Utensil Production C.I.S., Ltd., Bazar Phatriana, Jandiala Guru	Utensil	..
134	Jandiala Milap Weavers Production C.I.S., Ltd., Jandiala	Weavers	..
135	The Jandiala Weavers Production C.I.S., Jandiala	Do	..
136	The Bundala Weavers C.I.S., Ltd., Bundala	Do	..
137	The Oil and General P.C.S., Ltd., Gehri	Oil	..
138	The Modern Textile C.I.S., Ltd., Gehri	Weavers	..
139	The Parcha Bufan C.I.S., Ltd., Kot Khera	Do	..
140	The Jandiala Engineering C.I.S., Ltd., Jandiala	Engineering	..
141	Tarn Taran Sharma Weavers Production C.I.S., Ltd., New Bazar, Tarn Taran	Weavers	..
142	The Attari Ramdasian Shoe Makers Production C.I.S., Ltd., Attari	Shoes	..
143	The Attari Leather Workers C.I.S., Ltd., Attari	Leather	..
144	The Tarn Taran Harijan Leather C.I.S., Ltd., S.M. Muradpura Road, Tarn Taran	Do	..
145	The Tarn Taran Ramdasian Shoe Makers C.I.S., S.M. Muradpura Road, Tarn Taran	Do	..
146	The Jiobala Weavers C.I.S., Ltd., Jeobala	Weavers	..
147	The Kaka Kandiala Weavers C.I.S., Ltd., Kaka Kandiala	Do	..
148	The Tarn Taran Engineering works C.I.S., Ltd., Jandiala Road, Tarn Taran	Engineering	..
149	The Tarn Taran Chawla Cotton Ginning and General C.I.S., Ltd., Sarhali Road, Tarn Taran	Cotton	..
150	The Tarn Taran Weavers Production C.I.S., Ltd., Guru Bazar, Tarn Taran	Weavers	..

Serial No.	(a) Name and address of Industrial Co-operative Societies	(b) Industries being run by the Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
151	The Lauhka Schedule Caste Weavers Production C.I.S., Ltd., Lauhka	Weavers	..
152	The Lauhka Weavers C.I.S., Ltd., Lauhka	Do	..
153	The Lauhka Khalsa Weavers Production C.I.S., Ltd., Lauhka	Do	..
154	The Saquanwali G/K Production C.I.S., Ltd., Saquanwali	G/K	..
155	The Sarli Sericulture C.I.S., Ltd., Sarli	Sericulture	..
156	The Amarkot Weavers Production C.I.S., Ltd., Amarkot	Weavers	..
157	The Mari Kamboke Weavers C.I.S., Ltd., Mari Kamboke	Do	..
158	The Sandhu G/K C.I.S. Ltd., Mari Mega, District Amritsar	G/K	..
159	The Sur Singh Brick-Kiln C.I.S., Ltd., Sur Singh	Bricks	..
160	The Singpura Weavers S.M.C.I.S., Ltd., Singhpura	Weavers	..
161	The Bhikhiwind Flaying C.I.S., Ltd., Adda Bhikhiwind, district Amritsar	Flaying	..
162	The Bhikhiwind Adda Leather Production C.I.S., Ltd., Adda Bhikhiwind, Amritsar	Leather	..
163	Bhikhiwind Ramdasian C.I.S., Ltd.	.. Under winding up process	..
164	The Bhikhiwind Janta Oil Production C.I.S., Ltd., Bhikhiwind	Oil	..
165	The Bhikhiwind Ban-making C.I.S., Ltd., Bhikhiwind	Ban making	..
166	The Parcha Bufan C.I.S., Ltd., Khem Karan	Weavers	..
167	The Khem Karan Wool and Cotton Production C.I.S., Ltd., Khem Karan	Do	..
168	The Gharyala Shoe-makers C.I.S., Ltd.	.. Under winding up process	..
169	The Gharyala Brick-kiln Production C.I.S., Ltd., Gharyala	Bricks	..
170	The Dubli Flaying and Tanning Production C.I.S., Ltd., Dubli	Flaying and Tanning	..
171	The Sabran Ban-making Production C.I.S., Ltd., Sabran	Ban-making	..

(a)			(b)
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies	Industries being run by the Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
172	The Kirtowal Weavers C.I.S., Ltd., Kirtowal	Weavers	
173	The Mansrover Oil Production C.I.S., Ltd.	Under winding up process	..
174	The Patti Ramdasian Shoe-makers Production C.I.S., Patti	Soap	..
175	The Patti Leather C.I.S., Ltd.	Under winding up process	..
176	The Patti Soap P.C.S., C.I.S., Ltd., Patti	Soap	..
177	The Patti Aggarwal Oil and Soap Production, Patti	Oil and soap	..
178	The Patti Ramgarian Production C.Y.S., Ltd., Patti	Weavers	..
179	The Patti Janta Handloom Production C.I.S. Ltd., Patti	Do	..
180	The Patti Weavers Production C.I.S., Ltd., Patti	Do	..
181	The Patti Handicraft Embroidery Production C.I.S., Ltd.	Handicraft	..
182	The Iron and W/Work Production C.I.S., Ltd., Patti	W/Work	..
183	The Patti Oil Production C.I.S., Ltd., Patti	Oil	..
184	The Navyug H/Pof Rice Production C.I.S., Patti	H/Pounting	..
185	The Nagoke Brick-Kiln Production C.I.S., Ltd., Nagoke	Brick-Kiln	..
186	The Nagoke Weavers Production C.I.S., Ltd., Nagoke	Weavers	..
187	The Nathoke Ban-making Production C.I.S., Ltd., Nathoke	Ban-making	..
188	The Khadur Sahib Ravidas Shoe-making Production C.I.S., Ltd., Khadur Sahib	Shoes	..
189	The Verowal Brick-Kiln Production C.I.S., Ltd.	Under winding up process	..
190	The Verowal Ban-making Production C.I.S., Ltd., Verowal	Ban-making	..
191	The Verowal Flaying C.I.S., Ltd., Verowal	Flaying	..
192	The Sandeep Fibre Production C.I.S., Ltd., Jallabad	Fibre	..

(a)			(b)
Serial No	Name and address of Industrial Co-operative Societies	Industries being run by the Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
193	The Saquinwali G/K Production C.I.S., Sa quanwali	G/K	..
194	The Sohal Engineering Production C.I.S., Ltd., Sohal	Engineering	..
195	The Civil Lines Handloom Production C.I.S., Azad Nagar, Amritsar	Weavers	..
196	The Putlighar H/P of Rice Production C.I.S., Ltd., Putlighar	H/P of rice	..
197	The Haripura Weavers Production C.I.S., Haripura, post office Khalsa College	Weavers	..
198	The Meharpura Weavers C.I.S., Ltd., Gali No. 3, Keharpura, post office Khalsa College, Amritsar	Do	..
199	The Sharma Soap P.C.S., C.I.S., Ltd., Haripura, Amritsar	Soap	..
200	The Kotli Mian Khan, H/P Paddy and Pulses Production C.I.S. Ltd., Kotli Mian Khan	H/P	..
201	The Swastic Rubber Production C.I.S., Ltd., Ram Tirth Road, Amritsar	Rubber	..
202	The Dam Ganj Weavers, P.C.S, C.I.S., Ltd., Dam Ganj, Amritsar	Weavers	..
203	The Miran Kot Kalan Glue Production, C.I.S., Ltd., Mirankot	Glue	..
204	The New Bharat Handloom Production, C.I.S., Hathi Gate, Amritsar	Weavers	..
205	The Kala Ghanupur Textile Production, C.I.S., Ltd., Kala Ghanupur	Do	..
206	The National Engineering Production, C.I.S. Chhehartta	Engineering	..
207	The Shiwalik Textile Production, C.I.S. .. Ltd., Ward Nos. 6 and 7, Chhehartta	Weavers	..
208	The Amritsar Oil Production, C.I.S., Ltd., Putlighar	Oil	..
209	The Kala Ghanupur Brick-Kiln Production C.I.S., Kala Ghanupur	Bricks	..
210	The Khasa Guru Nanak Glass Production C.I.S., Ltd., Khasa	Glass	..

(a)		(b)	
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies	Industries being run by Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
211	The Kathanian Weavers Production, C.I.S., Ltd., Kathanian	Weavers	..
212	The Amritsar Model Powerlooms C.I.S., Ltd., near Khalsa College, Amritsar	Do	..
213	The Islamabad Powerloom Production, C.I.S. Ltd., Islamabad	Do	..
214	The Putlighar Handloom Production C.I.S., Ltd., Cementry Road, Amritsar	Do	..
215	Harijan-Boot-makers Production C.I.S. Ltd. Haveli Rur Singh near Telephone Exchange, Amritsar	Shoes	..
216	The Amritsar Bharat Oil and Soap Production C.I.S., Mandi Charanjahan inside Hathi Gate, Amritsar	Oil	..
217	The Joshi Soap, P.C.S. C.I.S., Ltd., Katra Moti Ram, Amritsar	Soap	..
218	The Bharat Handloom P.C.S., C.I.S., Katra Sher Singh	Weavers	..
219	Th Loharka Kalan Oil and Soap Production C.I.S., village and post office Loharka Kalan	Oil and Soap	..
220	The Amritsar Thathiar C.I.S. Ltd., Thatharian	Utensil	..
221	The Hind Watches Mechanical Production C.I.S. Hall Bazar, Amritsar	Watches	..
222	The Amritsar Bharat Handloom P.C.S., Amritsar	Weavers	..
223	The Hind Oil and Soap P.C.S., C.I.S., Ltd., inside Hakimnawala Gate, Amritsar	Oil	..
224	The Amritsar New Bharat Powerlooms Production C.I.S. Ltd., Hathi Gate, Amritsar	U.W.O. weavers	..
225	The Jyoti Handloom Production C.I.S., Ltd., Katra Sher Singh	Do	..
226	The Amritsar Handloom Production C.I.S., Ltd., Katra Sher Singh, Amritsar	Do	..
227	The Amritsar Textile Trancee .C.I.S., Ltd., Katra Bhagian	Do	..

Serial No.	(a) Name and address of Industrial Co-operative Societies	(b) Industries being run by the Societies	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
228	The Amritsar Harijan Shoe-makers Production C.I.S., Katra Sher Singh, Amritsar	Leather	..
229	The Amritsar Engineering P.C.S., C.I.S., Ltd. Hide Market Amritsar	Engineering	..
230	The Amritsar Nav Bharat Handloom P.C.S. C.I.S., Ltd., Goel Market, Amritsar	Weavers	..
231	The Amritsar Sports Goods Production P.C.S. C.I.S., Ltd., Katra Sher Singh, Amritsar	Sports goods	..
232	The Frontier Foot Wear C.I.S., Ltd., Katra Sher Singh	Shoes	..
233	The Amritsar Luxmi Engineering C.I.S., Ltd., Railway Road, Amritsar	Engineering	..
234	The New Bharat C.I.S., Ltd., 123-Hall Bazar, Amritsar	Do	..
235	Roop Handloom Production C.I.S., Ltd.	Under Winding up Process	..
236	The Russian Paints and Varnish Production C.I.S., Ltd., Khazana Gate, Amritsar	Paints	..
237	The Tarn Taran Janta W/works Production C.I.S., Ltd., Sarhali Road, Tarn Taran	W/works	..
238	The Tarn Taran Handloom Production C.S. C.I.S., Ltd., Sadar Bazar, Tarn Taran	Weavers	..
239	The Malian Vishkarma Fabrication Production C.I.S., Ltd., village and post office Malian	Fabrica	..
240	The Friends W/works Production C.I.S., Ltd., Sadar Bazar, Tarn Taran	W/works	..
241	The Kudgil Weavers Production C.I.S., Ltd., Kudgil	Weavers	..
242	The Tarn Taran Ideal Textile Production C.I.S., Ltd., Railway Road, Tarn Taran	Do	..
243	The Tarn Taran Leather Production C.I.S., Adda Bazar, Tarn Taran	Leather	..
244	The Tarn Taran Guru Arjan Dev W/work Production C.I.S., Ltd., Sirhali Road, Tarn Taran	W/works	..
245	The Nanksar weavers Production C. I. S Ltd,	Weavers	..

[Irrigation and power Minister]

(a)	(b)
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies Industries being run by Societies
	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
246	The Tarn Taran Textile Production C.I.S., Sirhali Road, Tarn Taran Weavers ..
247	The Tarn Taran Dye House C.I.S. Ltd., Tarn Taran Dye ..
248	The Manochahl Kalan Weaver C.I.S. Ltd., Manochahl Weavers ..
249	The Tarn Taran Rayon Textile Production C.I.S. Ltd., Railway Road, Tarn Taran Do ..
250	The Tarn Taran W/Works Production C.I.S. Adda Bazar, Tarn Taran W/Works ..
251	The Tarn Taran Radio P. C. S. C.I.S., Ltd., Main Road, Tarn Taran Radio ..
252	The Dande Harijan Leather Works Production C.I.S. Dande Leather ..
253	The Chabbal Kalan Weavers Production C.I.S., Chabbal Kalan Weavers :
254	The Dhotian Brick-Kiln Production C.I.S., Dhotian Bricks ..
255	The Doburji Backward Weavers Production C.I.S., Doburji Weavers ..
256	The Tarn Taran Handicraft P.C.S., C.I.S., Adda Nurdi, Tarn Taran Handicraft ..
257	The Bathal Bhaike Iron and W/Works Production C.I.S., village and post-office Bathal Bhaike I/S ..
258	The Marhana Flaying and tanning P.C.S., C.I.S., Marhana F/T ..
259	The Fatehabad Janta Sewak Oil Production, C.I.S., Fatehabad Oil ..
260	The Ruriwala Agr. Imp. Production C.I.S., Ruriwal Agr. Imp. ..
261	The Sarhali Kalan Oil expellers Production C.I.S. Sarhali Kalan Oil ..
262	The Chohla Sahib Leather Workers P.C.S., C.I.S., Ltd., Chohla Sahib Leather ..
263	The Chohla Sahib Shoe makers Production C.I.S. Ltd., Chohla Sahib Leather ..

(a)	(b)	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies Industries being run by Societies	
264	The Gharka Ban-making C.I.S. Ltd., Gharka Ban-making	..
265	The Nowshera Panuan Shoe-makers Production C.I.S. Ltd., Nowshera Panuan Leather	..
266	The Nowshera Panuan Leather C.I.S., Nowshera Panuan Do	..
267	The Tarn Taran Ghani Oil Production C.I.S., Oil mohalla Na aksar, Tarn Taran	..
268	The Tarn Taran Jain Bharat Textile Produc- Weavers tion C.I.S., Sarhali Road, Tarn Taran	..
269	The Dyal Shahabpura G/K Production C.I.S. G/K Ltd., Shahabpura	..
270	The Gurdev H/P of Peddy and Pulses Pro- H/P duction C.I.S., Dyal	..
271	The Palasour Oil and Soap P.C.S., C.I.S. Oil Ltd., Palasour	..
272	The Tarn Taran Ramgarhian W/Works Pro- W/Works duction C.I.S. Ltd., Sadar Bazar, Tarn Taran	..
273	The Tarn Taran Brick-Kiln Production Bricks C.I.S., Jandiala Road, Tarn Taran	..
274	The Tarn Taran Janta Textile P.C.S., Tarn Weavers Taran	..
275	The Fatehabad Ban-making Production Ban-making C.I.S., Fatehabad	..
276	The Manochahl H/P of rice of P.C.S. C.I.S., H/P Manochahl	..
277	The Fatehabad Agr. Imp. Production C.I.S., Agr. Imp. Fatehabad	..
278	The Chaudhriwala Flayers Production C.I.S., Flayers Chaudhriwala	..
279	The Kairon Brick-kiln C.I.S., Ltd., Kairon Bricks	..
280	The Dhotian Brick-kiln C.I.S., Ltd., Do Dhotian	..
281	The Chaudhriwala Birck-kiln Production Do C.I.S., Chaudhriwala	..
282	The Nav Parbhat Engineering and Agr. Imp. Engineering Production, Karion	..

## [Irrigation and power Minister]

(a)	(b)	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies Industries being run by the Societies.	
283	The Kairon Engineering Production C.I.S. Ltd., Kaion Engineering	..
284	The Dande Hrijan Leather Works C.I.S. Ltd., Dande Leather	..
285	The Manochahl Kalan Weavers P.C.S., C.I.S., Manochahl Weavers	..
286	Tarn Taran Progressive Leather P.C.S, C.I.S., Muradpura Road, Tarn Taran Leather	..
287	The District Industrial Co-operative Union Ltd., Amritsar ..	..
288	The Nangli Nowshera Textile Production C.I.S., Nangli Weavers	..
289	The Bhinder Adhermi Textile Production C.I.S., Bhinder Do	..
290	The Rayyia Agr. Imp. Production C.I.S. Ltd., Rayyia Agr. Imp.	..
291	The Janian Soap Production C.I.S. Ltd., Janian, post office, Jandiala Soap	..
292	The Darbar Surgical cotton Production C.I.S. Ltd., Tarn Taran Surgical Cotton	..
293	The Amritsar Furniture P.C.S., C.I.S., Amritsar Furniture	..
294	The Amritsar Hero Foundry Works Produc- tion C.I.S., Amritsar Engineering	..
295	The Majitha Kabir Weavers Production C.I.S., Ltd., Majitha Weavers	..
296	The Mattewal Engineering Production C.I.S., Ltd., Mattewal Engineering	..
297	The Baba Bukala Leather Production C.I.S., Baba Bakala Leather	..
298	The Chohla Sahib Flaying and Tanning Pro- duction C.I.S., Chohla Sahib Flaying I Tanning	..
299	The Mattewal Handloom Production C.I.S. Ltd., Matewal Weavers	..
300	The Amritsar friends Handloom C.I.S., Amritsar Do	..

(a)	(b)	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies Industries being run by the Societies	
301	The Mehta Chowk Agr. Imp. Production C.I.S. Ltd., Mehta Chowk	Agr. Imp. ..
302	The Tarn Taran Agr. Imp. Production C.I.S., Tarn Taran	Engineering ..
303	The Patti W/Works Production C.I.S., Ltd., Patti Ward No. 3	W/Work ..
304	The Chohla Sahib G/K Production Co-operative Industrial Society Ltd., Chohla Sahib	G/K ..
305	The Nijerpura Agr. Imp. Production Co-operative Industrial Society, Ltd. Nijerpura	Engineering ...
306	Guru Nanak H/P of Paddy and Pulses Production C.I.S. Ltd., Kaleke	H/P. ..
307	Bishkarma Engineering Production Co-operative Industrial Society Ltd., Amritsar	Engineering ..
308	Manakpur Handpounding of Rice C.I.S. Manakpur	H/P ..
309	The Jodhpur H/P of Rice Paddy and Pulses Production C.I.S. Ltd., Jodhpur, post office Tarn Taran	Do ..
310	The Jamarai Ghani Oil and Soap Production C.I.S. Ltd., Jamarai	Oil and Soap ...
311	The Majitha Road Women C.I.S. Ltd., Majitha Road	Tailoring and Embroidery (Handicraft) ..
312	The Kasail Women C.I.S. Ltd., village and post-office Kasail tehsil, Tarn Taran	Ditto ...
313	The Ajit Nagar Ladies C.I.S. Ltd., Ajit Nagar, Amritsar	Ditto ...
314	The Ajnala Women C.I.S. Ltd., Ajnala, tehsil Ajnala	Ditto ...
315	The Bhalla Women C.I.S. Ltd., Kucha Ram Garian, Amritsar	Ditto ..
316	The Chabal Women, P.C.S., C.I.S. Ltd., Chabal Tehsil Tarn Taran	Ditto ..
317	The Gehal Singh Women, C.I.S. Ltd., Tangra G.T. Road, tehsil Amritsar	Ditto ..

## [Irrigation and power Minister]

(a)	(b)	Quantity of Raw material allotted during 1964-65 and 1965-66
Serial No.	Name and address of Industrial Co-operative Societies	Industries being run by the Societies
318	The Batala Women C.I.S. Ltd., Batala, tehsil Amritsar	Tailoring and Embroidery ..
319	The Amritsar Preet Nagar Women C.I.S. Ltd., H. No. 1708, Lakar Mandi Amritsar	Ditto ..
320	The Ram Dass Women C.I.S. Ltd., Ram Dass, tehsil Anjala	Ditto ..
321	The Kathu Nangal Women C.I.S. Ltd., Kathu Nangal, tehsil Amritsar	Ditto ..
322	Gohalwar Women C.I.S. Ltd., Gohalwar, tehsil Tarn Taran	Ditto ..
323	The Amritsar Women, C.I.S. P.C.S. Ltd., Amritsar	(Handicraft) ..
324	The Lankha Women P.C.S. C.I.S., Ltd., Lankha, tehsil Tarn Taran	Ditto ..
325	The Matewal Women General P.C.S. C.I.S., Matewal (Amritsar)	Ditto ..
326	The Raja Sansi Mastt C.I.S., Ltd., Raja Sansi Tehsil, Amritsar	Ditto ..
327	The Bundla Ladies C.I.S. Ltd., Bundla, tehsil Amritsar	Ditto ..
328	The Sarhali Kalan Women P.C.S. C.I.S. Ltd., Sarhali Kalan, district Amritsar	Ditto ..
329	The New Modern Women C.I.S. Ltd., House No. 4106, Gali No.4, Kot Babu Deep Singh, Amritsar	Ditto ..
330	The Fatiabad Ladies P.C.S. C.I.S. Ltd., village and post office, Fatiabad	Ditto ..
331	The Kairon Women P.C.S. C.I.S., Ltd., Kairon, tehsil Tarn Taran	Ditto ..
332	The Lalpura Ladies C.I.S. Ltd., village and post-office Lalpura, tehsil Tarn Taran	Ditto ..
333	The Sahabpura Ladies C.I.S. Ltd., Sahabpura, post-office Tarh Taran	Ditto ..
334	The Valthoa Ladies C.I.S., Ltd., village and post office Valthoa, tehsil Sahabpura	Ditto ..
335	The Nirmal Mahila P.C.S. C.I.S., Chowk Lohgarh, Amritsar	Ditto ..
336	The Refugee Women Home Multipurpose Society Ltd., Pila Hospital, inside Hall Gate, Amritsar	Ditto ..
337	The Sital Women P.C.S. C.I.S. Ltd., Bazar Mai Siwan, Amritsar	Ditto

### Representations by the Drivers and Conductors of the Randhawa Bus Service, Amritsar

**3147. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the names of the drivers and conductors who represented to the Labour Officer or Conciliation Officer, Amritsar about, their difficulties and about the termination of their services by the Management of the Randhawa Bus Service, Amritsar, during the period 1964-65, 1965-66, to-date ;
- (b) the details of the action, if any, taken on the said representation in each case, stating the date of representation and the date of the decision taken in each case ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) and (b) No complaint was made to the Conciliation Officer, Amritsar, by any driver or conductor regarding termination of their services. A Demand Notice, dated 1st June, 1964 was, however, received from the Pathankot-Amritsar Transport Workers Union, Amritsar, served on the Management of Messers Randhawa Bus Service, Amritsar, which contained seven demands of general nature. The Union, however, failed to furnish the letter of authority in Form 'F' as required under rule 36 of the Industrial Dispute (Punjab) Rules, 1958. The Demand Notice was, accordingly, filed by the Conciliation Officer, Amritsar, on 2nd September, 1964. There is no Labour Officer at Amritsar.

### Drivers, Conductors and Workshop employees of the Punjab Roadways

**3148. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the number and names of drivers, conductors and the workshop employees of the Punjab Roadways whose services were terminated in the years 1964-65 and 1965-66 to date ; depot-wise, stating the cause of the termination of their services ;
- (b) the names of the officials out of those mentioned above who were re-instated by the Provincial Transport Controller, on appeal ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) A statement at Annexure I is laid on the Table of the House.

(b) A statement at Annexure II is laid on the Table of the House.

#### ANNEXURE I

#### Statement of officials whose services were terminated

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
1	2	3	4

#### PUNJAB ROADWAYS, CHANDIGARH

- |   |                          |            |   |
|---|--------------------------|------------|---|
| 1 | Shri Inderjit, Conductor | .. 1964-65 | For taking money from the Conductor for his personal use, which was objectionable |
|---|--------------------------|------------|---|

## [Minister for Transport and Elections]

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
			and embezzlement of Government revenue
2	Shri Manjit Singh, Conductor	.. 1964-65 (services not extended)	Services were not extended beyond 10th September, 1964 the date up to which his appointment was ; as he had not issued tickets to the passenger who posed himself to be an employee of an Indian Transport Company
3	Shri Karmjit Singh, Conductor	.. 1964-65	On account of misconduct
4	Shri Kashmir Singh, Conductor	.. 1964-65	Fraud case
5	Shri Mehar Singh, Conductor	.. 1964-65	Ditto
6	Shri Amri Chand, Conductor	.. 1964-65	Ditto
7	Shri Prithvi Raj, Driver	.. 1964-65	For taking money from the Conductor for his personal use which was objectionable and embezzlement of Government revenue
8	Shri Jai Singh, Driver	.. 1964-65	For causing an accident
1965-66			
1	Shri Joginder Singh, Conductor	.. 1965-66	Fraud case
2	Shri Amar Nath, Conductor	.. 1965-66	Misbehaviour with a passenger as well as issued ticket from Chandigarh-Ambala City instead of Chandigarh-Ambala Cantt. route for which the fare had been collected
3	Shri Ramesh Chander, Conductor	.. 1965-66	Fraud case
4	Shri Chhaja Singh, Conductor	.. 1965-66	Ditto
5	Shri Mohan Singh, Conductor	.. 1965-66	Ditto
6	Shri Hans Raj, Conductor	.. 1965-66	Ditto
PUNJAB ROADWAYS, AMBALA			
1964-65			
1	Shri Amar Singh, Driver	.. 1964-65	Wilful absence from duty
2	Shri Gian Chand, Driver	.. 1964-65	Accident
3	Shri Ajit Singh, Driver	.. 1964-65	Do
4	Shri Wishwa Mitter, Conductor	.. 1964-65	Case of fraud
5	Shri Rajinder Paul, Conductor	.. 1964-65	Ditto

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
1	2	3	4
6	Shri Jagat Ram, Conductor	.. 1964-65	Case of fraud
7	Shri Charan Singh, Conductor	.. 1964-65	Ditto
8	Shri Kitab Singh, Conductor	.. 1964-65	Ditto
9	Shri Jashmer Singh, Conductor	.. 1964-65	Ditto
10	Shri Malkiat Singh, Conductor	.. 1964-65	Ditto
11	Shri Surjit Singh, Conductor	.. 1964-65	Ditto
12	Shri Amar Nath, Conductor	.. 1964-65	Ditto
13	Shri Ajmer Singh, Cleaner	.. 1964-65	Unauthorisedly driving the bus
<b>1965-66</b>			
1	Shri Nachhattar Singh, Driver	.. 1965-66	Rash and negligent driving
2	Shri Rattan Lal, Driver	.. 1965-66	Accident
3	Shri Atma Singh, Driver	.. 1965-66	Public Complaint
4	Shri Prithi Singh, Conductor	.. 1965-66	Accident
5	Shri Hari Chand, Conductor	.. 1965-66	Case of fraud
6	Shri Gobind Lal, Conductor	.. 1965-66	Ditto
7	Shri Raunak Chand, Conductor	.. 1965-66	Ditto
8	Shri Ram Parkash, Conductor	.. 1965-66	Ditto
9	Shri Jiwan Ram, Conductor	.. 1965-66	Ditto
10	Shri Amar Singh, Conductor	.. 1965-66	Ditto
11	Shri Charan Dass, Conductor	.. 1965-66	Ditto
12	Shri Amarjit Singh, Conductor	.. 1965-66	Ditto
13	Shri Ajudhya Nath, Conductor	.. 1965-66	Ditto
14	Shri Rattan Lal, Conductor	.. 1965-66	Ditto
15	Shri Maluk Singh, Conductor	.. 1965-66	Public complaint
16	Shri Krishan Kant, Conductor	.. 1965-66	Case of fraud
17	Shri Inder Singh, Conductor	.. 1965-66	Ditto
18	Shri Bal Krishan, Helper	.. 1965-66	Wilful absence from duty
19	Shri Jasbir Singh, Assistant Black-smith	1965-66	For mischief in putting foreign part in vntury
20	Shri Dalbir Singh, Helper	.. 1965-66	Wilful absence from duty
21	Shri Lakhpat Rai, Helper	.. 1965-66	Ditto

## [Minister for Transport and Elections]

Serial No.	Name of designation	Year of termination	Cause of termination
1	2	3	4
<b>PUNJAB ROADWAYS, PATHANKOT</b>			
<b>1964-65</b>			
1	Shri Malhar Singh, Driver, 141	.. 1964-65	Terminated for not handling the vehicle properly causing loss to Government.
2	Shri Raj Kumar, Driver, 156	.. 1964-65	Terminated being a temporary hand.
3	Shri Lochan Singh, Driver, 162	.. 1964-65	Terminated on account of wilful absence from duty.
4	Shri Rattan Singh, Driver, 168	.. 1964-65	Terminated due to surrender of trips.
5	Shri Fauja Singh, Driver, 165	.. 1964-65	Ditto
6	Shri Mangal Dass, Driver, 150	.. 1964-65	Terminated for causing an accident.
7	Shri Kartar Singh, Driver, 150	.. 1964-65	Service discontinued being temporary hand.
8	Shri Sudarshan Kumar, Driver, T-4	1964-65	Service discontinued on account of wilful absence.
9	Shri Gian Singh, Driver, 58-A	.. 1964-65	Service discontinued being temporary hand,
10	Shri Jagga Masih, Driver	.. 1964-65	Services terminated on account of case of smuggling.
11	Shri Gurdev Singh, Driver, 100	.. 1964-65	Service discontinued on account of wilful absence.
12	Shri Sumitter Singh, Driver, 2	.. 1964-65	Services terminated on account of a case of smuggling.
13	Shri Rurh Chand, Driver	.. 1964-65	Service discontinued due to shortage of vehicles.
14	Shri Hans Raj, Driver	.. 1964-65	Service discontinued being a temporary hand.
15	Shri Basant Singh, Driver	.. 1964-65	Ditto
16	Shri Mehar Singh, Driver, 23	.. 1964-65	Ditto
17	Shri Surjit Singh, Driver, T-1	.. 1964-65	Ditto
18	Shri Mohan Singh, Driver, T-2	.. 1964-65	Ditto
19	Shri Darshan Singh, Driver, T-3	.. 1964-65	Ditto
20	Shri Raj Kumar, Driver	.. 1964-65	Ditto
21	Shri Gian Singh, Driver	.. 1964-65	Ditto

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
1	2	3	4
<b>1965-66</b>			
1	Shri Surjit Sinah, Driver, 133	1965-66	Service discontinued on account of wilful absence from duty.
2	Shri Darbara Singh, Driver, 79	1965-66	Services terminated being convicted by the Court.
3	Shri Harhajan Singh, Driver, 133	1965-66	Service discontinued due to causing an accident.
4	Shri Balkar Singh, Driver, 22	1965-66	Service discontinued on account of wilful absence from duty.
5	Shri Gurcharan Singh, Driver, 113	1965-66	Service discontinued for causing an accident.
6	Shri Singhar Singh, Driver, 203	1965-66	Service discontinued being a temporary hand.
7	Shri Inder Singh, Driver, 182	1965-66	Services terminated being a temporary hand.
8	Shri Lochan Singh, Driver, 162	1965-66	Service discontinued on account of wilful absence from duty.
9	Shri Sohan Singh, Driver, 140	1965-66	Ditto
<b>Workshop Staff 1964-65</b>			
1	Shri Sukhcharan Singh, Assistant Fitter, son of Shri Kartar Singh, District Sangrur	1964-65	Terminated on account of wilful absence from duty.
2	Shri Parshotam Singh, Cleaner, son of Shri Balwant Singh, H. No. 39, Kapurthala	1964-65	Ditto
3	Shri Raj Kumar, Assistant Carpenter, son of Shri Vir Bhan, Mohalla Orla, New Narain Mandi, Gurdaspur	1964-65	Ditto
4	Shri Kaka Ram, Radiator-repairer, Kali Mata Mandir, Gandhi Nagar, Pathankot	1964-65	Ditto
5	Shri Ajit Singh, Cleaner, son of Shri Karam Singh, village Fatehgarh Churian, Gurdaspur	1964-65	Ditto
6	Shri Gurbax Singh, Assistant Blacksmith, son of Shri Harnam Singh, Magu Mohalla Singh, Moga, tehsil, district Ferozepur	1964-65	Ditto
7	Shri Romesh Chander, Store-boy, son of Shri Kishan Chand, H. No. 222, Katholi Mohalla, Pathankot	1964-65	Ditto

## [Minister for Transport and Elections]

Serial No.	Name and Designation	Year of termination	Cause of termination
1	2	3	4
8	Shri Bal Krishan, Assistant Welder, son of Shri Daulat Ram, 37, Hide Market, Sharif Manzil, G.T. Road, Amritsar	1964-65	Terminated on account of wilful absence from duty.
9	Shri Sukhdev Raj	1964-65	Ditto
10	Shri Subhash Chand, Assistant Fitter, son of Shri Lakhsmi Narain, Fire Brigade, Sector 17, Chandigarh	1964-65	Ditto
11	Shri Narinder Mohan, Mechanic, Nehru Garden, Batala	1964-65	Ditto
<b>1965-66</b>			
1	Shri Kashmiri Lal, Fitter, son of Shri R.K. Patwar, House No. 41, Netaji Colony, Jullundur	1965-66	Terminated due to inefficiency.
2	Shri Ram Parkash, Painter, son of Shri Mani Ram, House No. 8901, Sharif Pura, Amritsar	1965-66	Terminated due to wilful absence from duty.
3	Shri Mohinder Paul, Washing-boy, son of Shri Lal Chand, Androon Bazar, Pathankot	1965-66	Ditto
4	Shri Ram Singh, Cleaner, son of Shri Shankar Singh, village Tinne, post office Jaman Khal, tehsil Garwal	1965-66	Ditto
5	Shri Krishan Singh, Washing-boy, son of Shri Munshi Ram, village Rajream, House No. 415, Pathankot	1965-66	Service discontinued being a temporary hand.
6	Shri Bhag Sinah, Washing-boy, son of Shri Dalip Singh, village Batala, tehsil and district Jullundur	1965-66	Service discontinued being temporary hand.
7	Shri Prem Shanker, son of Shri Mulkh Raj, 298, Model Town, Jullundur City	1965-66	Terminated on account of wilful absence from duty.

**Conductors Staff****1965-66**

1	Shri Virsa Singh, D/220	1965-66	Service discontinued on account of a case of fraud.
2	Shri Jagir Singh, C/102	1965-66	Ditto
3	Shri Sham Paul, C/234	1965-66	Ditto
4	Shri Jaskaran Singh, C/233	1965-66	Ditto
5	Shri Mohinder Singh, C. 236	1965-66	Ditto
6	Shri Jaswant Singh, C. 223	1965-66	Ditto

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
1	2	3	4
7	Shri Harbans Singh, C. 227	.. 1965-66	Services discontinued on account of a case of fraud.
8	Shri Amrik Singh, C. 230	.. 1965-66	Ditto
9	Shri Harbej Singh, C. 237	.. 1965-66	Ditto
10	Shri Diwan Chand, C. 183	.. 1965-66	Service discontinued being temporary hand.
11	Shri Grib Dass, C. 231	.. 1965-66	Ditto
12	Shri Hari Singh, C. 225	.. 1965-66	Ditto
13	Shri Malkiat Singh, C. 220	.. 1965-66	Ditto
14	Shri Amrik Singh, C. 140	.. 1965-66	Service discontinued on account of wilful absence from duty.
15	Shri Dedar Singh, C. 137	.. 1965-66	Service discontinued being a temporary hand.
16	Shri Sakattar Singh, C. 126	.. 1965-66	Service discontinued on account of wilful absence.
17	Shri Santokh Singh, C. 132	.. 1965-66	Service discontinued on account of case of fraud.
18	Shri Jagdish Chander, C. 220	.. 1965-66	Ditto
19	Shri Dilbag Singh, C. 236	.. 1965-66	Ditto
20	Shri Hem Raj, C. 32	.. 1965-66	Ditto
21	Shri Baldev Singh, C. 140	.. 1965-66	Ditto
22	Shri Harhbaj Singh, C. 109	.. 1965-66	Ditto
23	Shri Nagar Mal, C. 53	.. 1965-66	Ditto
24	Shri Kashmere Lal, C. 222	.. 1965-66	Ditto
25	Shri Ram Lubhaya, C. 245	.. 1965-66	Ditto
26	Shri Harbhajan Singh, C. 120	.. 1965-66	Ditto

## Conductors Staff

1964;65

1	Shri Mohan Singh, C. 182	.. 1964-65	Service discontinued being temporary hand.
2	Shri Harbhaj Singh, C. 105	.. 1964-65	Ditto
3	Shri Dalip Singh, C. 140	.. 1964-65	Ditto
4	Shri Sat Paul, C. 192	.. 1964-65	Ditto
5	Shri Surrender Singh, C. 160	.. 1964-65	Ditto

## [Minister for Transport and Elections]

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
6	Shri Onkar Singh, C. 200	.. 1964-65	Service discontinued being a temporary hand.
7	Shri Kamal Singh, C. 190	.. 1964-65	Service terminated on account of rude behaviour.
8	Shri Balkar Singh, C. 114	.. 1964-65	Service terminated on account of case of fraud.
9	Shri Ram Parkash, C. 170	.. 1964-65	Service terminated on account of case of fraud.
10	Shri Kartar Singh, C. 120	.. 1964-65	Ditto
11	Shri Kartar Singh, C. 120	.. 1964-65	Ditto
12	Shri Jai Dev Dhami, C. 88	.. 1964-65	Service discontinued being temporary hand.
13	Shri Ram Sarwan Singh, C.114	.. 1964-65	Service discontinued being a temporary hand.
14	Shri Amar Singh, C.38	.. 1964-65	On account of a case of fraud.
15	Shri Lakhmi Dass, C.4	1944-65	Being a temporary hand.
16	Shri Manchar Lal, C/T-4	.. 1964-65	Ditto
17	Shri Rajinder Parshad, C.T.-3	.. 1964-65	Ditto
18	Shri Satish Kumar, C.52	.. 1964-65	Ditto
19	Shri Darshan Singh, C.197	.. 1964-65	Ditto
20	Shri Surinder Kumar, C. 197	.. 1964-65	Ditto
21	Shri Karnail Singh, C.194	.. 1964-65	Ditto
22	Shri Harbans Lal, C. 192	.. 1964-65	Ditto
23	Shri Iqbal Singh, C. 160	.. 1964-65	On account of fraud case.
24	Shri Ramesh Chander C. 140	.. 1964-65	Ditto
25	Shri Surjit Singh, C.177	.. 1964-65	Ditto
26	Shri Ram Parkash, C 170	.. 1964-65	Ditto
27	Shri Ajit Singh, C.T.-4	.. 1964-65	Fraud Case
28	Shri Gurdip Singh, C. 184	.. 1964-65	Ditto
29	Shri Avtar Singh, C. 170	.. 1964-65	Ditto
30	Shri Sham Lal, C. 109	.. 1964-65	Ditto
31	Shri Chunk Lal, C. 188	.. 1964-65	Ditto
32	Shri Harcharan Dass, C. 104	.. 1964-65	Ditto
33	Shri Baldev Singh, C. 3	.. 1964-65	Ditto

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
34	Shri Ram Lal, C. 36	1964-65	Fraud Case
35	Shri Jaidev Singh, C.7	1964-65	Ditto
36	Shri Amir Chand, C. 108	1964-65	Ditto
37	Shri Lal Singh, C. 116	1964-65	Ditto
38	Shri Satish Kumar, C. 5	1964-65	Ditto
39	Shri Joga Ram, C. 9	1964-65	Ditto
40	Shri Shandi Lal, C. 29	1964-65	Ditto
41	Shri Rajinder Parshad, C/T-3	1964-65	Ditto
42	Shri Devinder Kumar, C.192	1964-65	Ditto
43	Shri Harbans Lal, C. 192	1964-65	Ditto
44	Shri Mukhan Singh, C.40	1964-65	Ditto
45	Shri Prem Kumar, C. 141	1964-65	Ditto
46	Shri Roop Lal, C. 116	1964-65	Ditto
47	Shri Mohinder Lal, C. 109	1964-65	Ditto
48	Shri Joginder Singh, C.120	1964-65	Ditto
49	Shri Ravinder Mohan, C/140	1964-65	Ditto
50	Shri Atma Singh, C/139	1964-65	Ditto
51	Shri Harjinder Singh, C/188	1964-65	Ditto
52	Shri Swaran Singh, C/188	1964-65	Ditto
53	Shri Jagdish Mitter, C/19	1964-65	Ditto
54	Shri Harbans Lal, C/75	1964-65	Ditto
55	Shri Manohar Lal, C/109	1964-65	Ditto
56	Shri Jagjit Saini, C/150.	1964-65	Ditto
57	Shri Kirpal Singh, C/102	1964-65	Ditto
58	Shri Nathu Ram, C/194	1964-65	Ditto
59	Shri Baldev Raj, C/167	1964-65	Ditto
60	Shri Avnash Kumar, C/46	1964-65	Ditto
61	Shri Bahadur Singh, C/138	1964-65	Ditto
62	Shri Harbhajan Singh, C/109	1964-65	Ditto
63	Shri Ram Mohan Rai, C/129	1964-65	Ditto

## Minister for Transport and Elections

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
64	Shri Bhag Singh, C/111	1964-65	Fraud case
65	Shri Ram Chander, C/194	1964-65	Ditto
66	Shri Gurdhian Singh, CD/207	1964-65	Ditto
67	Shri Swaran Chand, C/202	1964-65	Ditto
68	Shri Prem Kumar, C/171	1964-65	Ditto
69	Shri Surinder Pal, C/46	1964-65	Ditto

## PUNJAB ROADWAYS, JULLUNDUR

## Conductors

1	Shri Balwant Singh, AC-26	1964	Fraud
2	Shri Sukhdev Singh, AC-12	1964	Do
3	Shri Prithipal Singh, C/112	1964	Embezzlement
4	Shri Satnam Singh, C/22	1964	Fraud
5	Shri Sohani Lal, C/98	1964	Do
6	Shri Gurdip Singh, C/261	1964	Do
7	Shri Darshan Singh, AC/5	1964	Do
8	Shri Nirmal Singh, C/203	1964	Do
9	Shri Bharpoor Singh, C/237	1964	Do
10	Shri Malkiat Singh, C/165	1964	Do

## Drivers

1	Shri Amar Singh, D/201	1964	Accident
---	------------------------	------	----------

## Workshop Staff

Nil

## Conductors

1	Shri Ram Chand, C/266	1965	Fraud
2	Shri Swaran Dass, AC/53	1965	Do
3	Shri Darshan Singh, C/40	1965	Do
4	Shri Krishan Datt, AC/44	1965	Do
5	Shri Hari Singh, AC/26	1965	Do
6	Shri Hashmat Rai, C/100	1965	Do
7	Shri Satya Paul, AC-56	1965	Do
8	Shri Gulzar Singh, C/253	1965	Do

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Drivers**

1	Shri Gurbachan Singh, D/75	1965	Accident
2	Shri Gurpal Singh, D/98	1965	Do
3	Shri Swaran Singh, D/78	1965	Do

**Workshop Staff**

Nil

**PUNJAB ROADWAYS, GURGAON****Conductors**

1	Shri Ram Kumar, C/202	1964-65	Fraud
2	Shri Hari Kishan, C/255	1964-65	Do
3	Shri Kishan Lal, C/T-2	1964-65	Do
4	Shri Charanjit Sachdeva, C/277	1964-65	Do
5	Shri Ram Sarup, C/255	1964-65	Do
6	Shri Suraj Bhan, C/256	1964-65	Do
7	Shri Madan Lal, C/249	1964-65	Do
8	Shri Ishwar Singh, C/163	1964-65	Do
9	Shri Balwant Singh, C/277	1964-65	Do
10	Shri Rohtas Singh, C/97	1964-56	Do
11	Shri Kartar Singh, C/53	1964-65	Do
12	Shri Kharaiti Singh, C/226	1964-65	Do.
13	Shri Dharam Singh, C/268	1964-65	Do
14	Shri Teja Singh, C/184	1964-65	Do
15	Shri Rameshwar, C/101	1964-65	Do
16	Shri Virender Nath, C/196	1964-65	Do
17	Shri Jai Singh, C/230	1964-65	Do
18	Shri Dalip Singh, C/151	1964-65	Do
19	Shri Khem Chand, C/181	1964-65	Do
20	Shri Barkat Ali, C/256	1964-65	Do
21	Shri Ramji Lal, C/93	1964-65	Do
22	Shri Ghansham Dass, C/93	1964-65	Do
23	Shri Om Parkash, C/60	1964-65	Do
24	Shri Bakshi Singh, C/261	1964-65	Do

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
25	Shri Rameshwar, C/134	1964-65	Fraud
26	Shri Jarnail Singh, C/270	1964-65	Do
27	Shri Suraj Bhan, C/74	1964-65	Do
28	Shri Nawal Singh, C/139	1964-65	Do
29	Shri Manphul Singh, C/90	1964-65	
30	Shri Sube Singh, C/139	1964-65	Do
31	Shri Sita Ram, C/202	1964-65	Do
32	Shi Piara Singh, C/30	1964-65	Do
33	Shri Rameshwar Dass, C/263	1964-65	Do
34	Shri Chander Bhan, C/1	1964-65	Do
35	Shri Maha Singh, C/157	1964-65	Do
36	Shri Shiv Charan, C/147	1964-65	Do
37	Shri Gurmail Singh, C/210	1964-65	Do
38	Shri Sahib Singh, C/156	1964-65	Do
39	Shri Saminder Singh, C/96	1964-65	Do
40	Shri Rajbir Singh, C/181	1964-65	Do
41	Shri Sohan Lal, C/19	1964-65	Do
42	Shri Rattan Singh, C/179	1964-65	Do
43	Shri Rattan Singh, C/176	1964-65	Do
<b>Conductors</b>			
1	Shri Ram Partap, C/169	1965-66	Fraud
2	Shri Hari Mohan, C/96	1965-66	Do
3	Shri Manjit Singh, C/281	1965-66	Do
4	Shri Balbir Singh, C/250	1965-66	Do
5	Shri Ishwar Singh, C/294	1965-66	Do
6	Shri Sunder Singh, C/183	1965-66	Do
7	Shri Kashmiri Lal, C/284	1965-66	Do
8	Shri Ram Kumar, C/159	1965-66	Do
9	Shri Phul Chand, C/154	1965-66	Do
10	Shri Gir Raj Singh, C/176	1965-66	Do
11	Shri Kundan Lal, C/101	1965-66	Do

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
12	Shri Mukhtiar Singh, C/60	.. 1965-66	Absence from duty
13	Shri Ram Kumar, C/300	.. 1965-66	Ditto
14	Shri Raghbir Singh, C/138	.. 1965-66	Ditto
15	Shri Ram Kishan, C/306	.. 1965-66	Ditto
16	Shri Mukhtiar Singh, C/213	.. 1965-66	Ditto
17	Shri Ram Kumar, C/69	.. 1965-66	Ditto
18	Shri Jaswant Lal, C/38	.. 1965-66	Ditto
19	Shri Harbans Lal, C/103	.. 1965-66	Ditto
20	Shri Balbir Singh, C/160	1965-66	Case of fraud
21	Shri Bool Chand, C/138,	.. 1965-66	Ditto
22	Shri Mohar Singh, C/249	.. 1965-66	Ditto
23	Shri Dharam Singh, C/289	.. 1965-66	Ditto
24	Shri Narain Dass, C/80	.. 1965-66	Ditto
25	Shri Jai Kumar, C/298	.. 1965-66	Ditto
26	Shri Jai Dev, C/147.	.. 1965-66	Absence from duty
27	Shri Raghbir Singh, C/307	.. 1965-66	Case of fraud
28	Shi Ram Singh, C/273	.. 1965-66	Ditto
29	Shri Vahid Khan, C 160	.. 1965-66	Ditto
30	Shri Om Parkash, C/162	.. 1965-66	Ditto
31	Shri Jagdish Kumar, C/186	.. 1965-66	Ditto
32	Shri Puran Singh, C/93	.. 1965-66	Ditto
33	Shri Risal Singh, C/312	.. 1965-66	Ditto
34	Shri Om Parkash, C/37	.. 1965-66	Ditto
35	Shri Surat Singh. C/38	.. 1965-66	Ditto
36	Shri Raghbir Singh, C/153	.. 1965-66	Ditto
37	Shri Lekh Raj, C/102	.. 1965-66	Ditto
38	Shri Nafe Singh, C/138	.. 1965-66	Ditto
39	Shri Ram Partap, C/259	.. 1965-66	Ditto
40	Shri Jai Singh, C/202	.. 1965-66	Ditto
41	Shri Satibri Singh, C/38	.. 1965-66	Ditto
42	Shri Attar Singh, C/243	.. 1965-66	Ditto

## [Minister for Transport and Elections]

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
43	Shri Harke Ram, C/69	.. 1965-66	Negligence in duty
44	Shri Bhagirath Lal, C/49	.. 1965-66	Case of fraud
45	Shri Asa Ram, C/96	.. 1965-66	Ditto
46	Shri Hira Lal, C/50	.. 1965-66	Ditto
47	Shri Rameshwar Sunaria, C/321	.. 1965-66	Ditto
48	Shri Balbir Singh, C/57	.. 1965-66	Ditto
49	Shri Lal Chand, C/256	.. 1965-66	Ditto
50	Shri Sher Singh C/ 115	.. 1965-66	Ditto
51	Shri Tek Ram, C/24	.. 1965-66	Ditto
52	Shri Ram Chander, C/58	.. 1965-66	Ditto
53	Shri Mange Ram, C/296	.. 1965-66	Ditto
54	Shr. Parladh Singh, C/134	.. 1965-66	Ditto
55	Shri Tek Chand, C/92	1965-66	Ditto
56	Shri Ram Singh, C/308	.. 1965-66	Ditto
57	Shri Sardars Singh, C/148	.. 1965-66	Ditto
58	Shri Raminder Singh, C/17	1965-66	Case of fraud
59	Shri Sohan Lal, C/36	1965-66	Ditto
60	Shri Roshan Lal, C/273	1965-66	Ditto
61	Shri Om Parkash, C/311	1965-66	Ditto
62	Shri Nahar Singh, C/249	1965-66	Ditto
63	Shri Jai Narain, C/241	1965-66	Ditto
64	Shri Sant Raj, C/138	1965-66	Ditto
65	Shri Ram Parkash, C/151	1965-66	Ditto
66	Shri Sardari Lal, C/156	1965-66	Ditto
67	Shri Gian Singh, C/176	1965-66	Ditto

## WORKSHOP STAFF

1	Shri Suraj Bhan, Store-boy	1964-65	Absence from duty.
2	Shri Harphool Singh, R/Repairer	1964-65	Ditto
3	Shri Dhoop Singh, A/Fitter	1964-65	Ditto
4	Shri Rishal Singh, B/Smith	1964-65	Ditto
5	Shri Subhash Chander, A/Fitter	1964-65	Unauthorised driving of bus
6	Shri Sarmail, Cleaner	1964-65	Absent from duty.

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
------------	----------------------	---------------------	----------------------

7	Shri Ram Kishan, Cleaner	1964-65	Absence from duty.
8	Shri Om Parkash, A/Painter	1964-65	Ditto
9	Shri Bhagwan Dass, Welder	1964-65	Ditto

## WORKSHOP STAFF

1	Shri Sadhu Singh, Carpenter	1965-66	Absence from duty.
2	Shri Channan Singh, Cleaner	1965-66	Ditto
3	Shri Dharam Paul, B/Smith	1965-66	Ditto
4	Shri Darshan Singh, Selder	1965-66	Accident
5	Shri Varinder Kumar, A/Fitter	1965-66	Do
6	Shri Ram Paul Singh, Mechanic	1965-66	Do
7	Shri Jagdish Lal, Fitter	1965-66	Absence from duty.
8	Shri Ram Krishan, Cleaner	1965-66	Ditto
9	Shri Ramji Dass, Fitter	1965-66	Ditto
10	Shri Ramesh Chander, Helper	1965-66	Ditto
11	Shri Chaman Lal, Fitter	1965-66	Ditto
12	Shri Darshan Singh, Fitter	1965-66	Ditto
13	Shri Om Parkash, Cleaner	1965-66	Ditto
14	Shri Kidar Singh, A/Fitter	1965-66	Ditto
15	Shri Gopal Kishan, Cleaner	1965-66	Mis-conduct
16	Shri Nanak Chand, Cleaner	1965-66	Absence from duty.

## DRIVERS

1	Shri Sohri Lal, D/169	1964-65	Case of fraud.
2	Shri Khazan Singh, D/109	1964-65	Absence from duty.
3	Shri Hari Singh, D/208	1964-65	Ditto
4	Shri Hari Singh, D/219	1964-65	Ditto
5	Shri Hari Singh, D/270	1964-65	Fatal Accident
6	Shri Sadhu Singh, D/73	1964-65	Absence from duty
7	Shri Shiv Narain, D/287	1964-65	Ditto
8	Shri Faqir Chand, Driver	1964-65	Ditto
9	Shri Krishan Chand, D/39	1964-65	Ditto

## DRIVERS.

1	Shri Krishan Lal, D/208	1965-66	Accident case
2	Shri Hansraj Singh, D/233	1965-66	Inefficiency

## [Minister for Transport and Elections]

Seral No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
3	Shri Kundan Lal, D/281	1965-66	Absence from duty
4	Shri Gulzari Lal, D/62	1965-66	Ditto
5	Shri Harke Ram, D/169	1965-66	Inefficiency
6	Shri Ram Kumar, D/286	1965-66	Absence from duty
7	Shri Kashmir Singh, D/124	1965-66	Ditto
8	Shri Daulat Singh, D/175	1965-66	Case of accident
9	Shri Shiv Narain, D/175	1965-66	Ditto
10	Shri Natha Singh, D/131	1965-66	Ditto
11	Shri Gurtej Singh, D/3	1965-66	Absent from duty
12	Shri Kundan Singh, D/315	1965-66	Negligence in duty
13	Shri Prithvi Singh, D/307	1965-66	Absent from duty
14	Shri Jagjit Singh, D/213	1965-66	Ditto
15	Shri Kashmira Singh, D/320	1965-66	Dito
16	Shri Kehri Singh, D/163	1965-66	Accident case
17	Shri Dalip Singh, D/80	1965-66	Irregularities
18	Shri Om Parkash, D/303	1965-66	Absence from duty
19	Shri Ram Chander, D/231	1965-66	Ditto
20	Shri Ram Paul, D/70	1965-66	Ditto

## PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR

## WORKSHOP STAFF

1	Shri Rachhpal Singh, A/Fitter	1964-65	Damage to the Vehicle in Workshop
2	Shri Munshi Ram, Cleaner/24	1964-65	Wilful absence from duty
3	Shri Chaman Lal, Cleaner/23	1964-65	Ditto
4	Shri Darshan Singh, Cleaner/52	1964-65	Ditto
5	Shri Naranjan Singh, Cleaner/23	1964-65	Ditto
6	Shri Subhash Chander, Cleaner/26	1964-65	Ditto
7	Shri Ram Parkash, A/Painter	1964-65	Ditto
8	Shri Yash Pal Singh, Helper	1964-65	Ditto
9	Shri Gurnam Singh, A/Blacksmith	1964-65	Ditto
10	Shri Kasturi Lal, CL/27	1964-65	Ditto
11	Shri Vinod Kumar, Store-boy	1964-65	Medically unfit

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
12	Shri Kulwant Rai, Sweeper	1964-65	Works not satisfactory
13	Shri Gurdip Singh, CI/38	1964-65	Wilful absence from duty
14	Shri Kewal Krishan, Helper	1964-65	Ditto
15	Shri Kasturi Lal, A/Fitter	1964-65	Ditto
16	Shri Kashmir Singh, CI/47	1964-65	Ditto
17	Shri Balbir Singh, CI/30	1964-65	Ditto
18	Shri Dilbagh Singh, Fitter	1964-65	Ditto
19	Shri Dev Raj, Painter	1964-65	Ditto

## DRIVERS

1	Shri Dalip Singh, D/220	1964-65	Conviction by the court
2	Shri Puran Singh, D/153	1964-65	Found guilty on ground of theft of Spring Assembly
3	Shri Goverdhan Lal, D/254	1964-65	Wilful absence
4	Shri Iqbal Singh, D/244	1964-65	Ditto
5	Shri Piara Singh, D/R-284	1964-65	Refused to pick-up the trip
6	Shri Mohinder Singh, D/226	1964-65	Wilful absence from duty
7	Shri Niranjan Singh, D/115	1964-65	Ditto

## CONDUCTORS

1	Shri Darshan Singh, C/35	1964-65	Fraud case
2	Shri Ayudhia Nath, C/235	1964-65	Ditto
3	Shri Harjinder Singh, C/75	1964-65	Ditto
4	Shri Arjan Singh, C/172	1964-65	Ditto
5	Shri Pritam Singh, C/163	1964-65	Ditto
6	Shri Krishan Dev, C/22	1964-65	Wilful absence from duty
7	Shri Puran Chand, C/182	1964-65	Fraud Case
8	Shri Gian Singh, R/28	1964-65	Ditto
9	Shri Shiv Kumar, R/476	1964-65	Ditto
10	Shri Jaswant Singh, R/604	1964-65	Ditto
11	Shri Mukhtiar Singh, C/500	1964-65	Ditto
12	Shri Mukhtiar Singh, C/211	1964-65	Ditto
13	Shri Ajit Singh, R/532	1964-65	Ditto

## [Minister for Transport and Elections]

Serial No.	Name and designation	Year of termination	Cause of termination
------------	----------------------	---------------------	----------------------

14	Shri Sadhu Ram, C/214	1964-65	Fraud case
----	-----------------------	---------	------------

15	Shri Balwinder Singh, R/558	1964-65	Ditto
----	-----------------------------	---------	-------

## WORKSHOP STAFF

1	Shri Jagir Singh, CI/59	1965-66 1965	Wilful absence
---	-------------------------	-----------------	----------------

2	Shri Gurbachan Singh, A/Fitter	1965	Ditto
---	--------------------------------	------	-------

3	Shri Amar Singh, Sweeper	1965	Ditto
---	--------------------------	------	-------

4	Shri Ram Singh, Chowkidar	1965	Ditto
---	---------------------------	------	-------

5	Shri Lal Bahadur, Chowkidar	1965	Ditto
---	-----------------------------	------	-------

6	Shri Partap Singh, Chowkidar	1965	Ditto
---	------------------------------	------	-------

7	Shri Chander Bahadur, Chowkidar	1965	Ditto
---	---------------------------------	------	-------

8	Shri Sher Bahadur, Chowkidar	1965	Ditto
---	------------------------------	------	-------

9	Shri Jagdish Chander, CI/38	1965	Ditto
---	-----------------------------	------	-------

## DRIVERS

1	Shri Kishan Singh, D/89	1965-66	Conviction by the court
---	-------------------------	---------	-------------------------

2	Shri Amar Nath, R-318	1965-66	Terminated on the ground of fatal accident committed rashly and negligently
---	-----------------------	---------	---

## CONDUCTORS

1	Shri Ranjit Singh, R/140	1965-66	Fraud case
---	--------------------------	---------	------------

2	Shri Haqiqat Singh, R/181	1965-66	Ditto
---	---------------------------	---------	-------

3	Shri Ram Sarup, C/311	1965-66	Ditto
---	-----------------------	---------	-------

4	Shri Major Singh, R/744	1965-66	Wilful absence
---	-------------------------	---------	----------------

5	Shri Jagir Singh, C/274	1965-66	On the ground of fraud
---	-------------------------	---------	------------------------

6	Shri Kashmir Singh, C/271	1965-66	Ditto
---	---------------------------	---------	-------

7	Shri Madan Mohan, R/553	1965-66	Ditto
---	-------------------------	---------	-------

8	Shri Raghubir Singh, C/647	1965-66	Ditto
---	----------------------------	---------	-------

9	Shri Mohinder Partap Singh, R/448	1965-66	Ditto
---	-----------------------------------	---------	-------

10	Shri Baldev Raj, R/616	1965-66	Ditto
----	------------------------	---------	-------

11	Shri Satwant Singh, R/722	1965-66	Ditto
----	---------------------------	---------	-------

12	Shri Tilak Raj, R/329	1965-66	Wilful absence
----	-----------------------	---------	----------------

13	Shri Boor Singh, C/307	1965-66	Fraud case
----	------------------------	---------	------------

## ANNEXURE II

Statement showing the officials of the Punjab Roadways who were re-instated on appeal

Serial No.	Name and designation	Roadways	Date of re-instate-ment
1	Shri Inderjit Singh, Adda Conductor	Chandigarh	21-1-65
2	Shri Manjit Singh, Conductor	Chandigarh	20-1-66
3	Shri Karamjit Singh, Conductor	Chandigarh	26-8-65
4	Shri Kamal Singh, Conductor	Pathankot	22-5-65
5	Shri Balkar Singh, Conductor	Pathankot	5-4-65
6	Shri Sohan Lal, Conductor	Jullundur	23-8-65
7	Shri Darshan Singh, Conductor	Jullundur	23-8-65
8	Shri Aydhia Nath, Conductor	Amritsar	4-2-66
9	Shri Arjan Singh, Conductor	Amritsar	18-8-65
10	Shri Shiv Kumar, Conductor	Amritsar	5-1-66
11	Shri Baru Ram, Driver	Gurgaon	6-4-65
12	Shri Piara Singh, Conductor	Gurgaon	31-12-65
13	Shri Mam Chand, Conductor	Gurgaon	20-4-65

**Loss suffered by the Punjab Roadways due to thefts committed in the Roadways Workshops, etc.**

**3149. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

(a) the details of the loss suffered by the Punjab Roadways during the years from 1962 onwards to date due to thefts of motor parts from the Roadways Workshops and buses, depot-wise, stating the names of General Managers, Traffic Managers and Works Managers who were in position in each case during the said period at the respective depots ;

(b) whether it is fact that the Punjab Roadways suffered a loss of more than Rupees 10 lakhs due to the said thefts ; if so, whether these thefts were traced, if not ; the reasons therefor ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) A statement is enclosed.

(b) No, the total loss on these thefts comes to Rs 6,836.12 paise only. All cases of thefts were registered with the police authorities and in some cases articles were traced out.

## [Minister for Transport and Election]

## STATEMENT

Year	Depot	Officer incharge	Items of loss	Value
1962	Punjab Roadways, Jullundur	(1) Shri R.S. Sarkaria, General Manager (2) Shri R.N. Sawhney, Works Manager (3) Shri H.S. Randhawa, Traffic Manager	Four self-starters	Rs. n.p. [ 1,660.16
1963	Ditto	(1) Shri Saran Singh, General Manager (2) Shri H.S. Randhawa, Traffic Manager	Two batteries	251.66
1964	Ditto	(1) Shri Saran Singh, General Manager (2) Shri B.S. Khurana, Works Manager	One self-starter	633.87
1965	Ditto	(1) Shri Saran Singh, General Manager (2) Shri B.S. Khurana, Works Manager (3) Shri H.S. Randhawa, Traffic Manager	(i) Two self-starters (ii) 20 Litres of Mobiloil	796.46 27.60
1962	Punjab Roadways, Amritsar	..	..	..
1963	Ditto	(1) Shri R.N. Sawhney, General Manager (2) Shri R.N. Bhatia, Works Manager (3) Shri D.S. Kohli, Traffic Manager	(i) One old crank shaft	430.00
1964	Ditto	(1) Shri R.N. Sawhney, General Manager (2) Shri R.N. Bhatia, Works Manager	One old differential tube	100.00

1965	Ditto	(3) Shri D. S. Kohli, Traffic Manager	One old tube	20.00
		(1) Shri R. N. Sawhney, General Manager		
		(2) Shri R. N. Bhatia, Works Manager		
		(3) Shri D. S. Kohli Traffic Manager		
1962	Punjab Roadways, Ambala	..		
1963	Ditto	(1) Capt. Gurcharan Singh, General Manager	One Radiator	309.00
		(2) Shri J.N. Durani, Works Manager		
		(3) Shri Lal Singh, Traffic Manager		
1964	Punjab Roadways, Ambala	..	..	..
1965	Ditto	..	..	..
1962	Punjab Roadways, Gurgaon	..	..	..
1963	Ditto	..	..	..
1964	Ditto	(1) Shri M. R. Pahwa, General Manager	..	..
		(2) Shri Jagdish Chander, Traffic Manager	One Front wheel bearing	30.28
		(1) Shri B.S. Dewan, General Manager	Gun Metal Bushes	909.09
		(2) Shri Ram Saran, Works Manager		
		(3) Shri Jagdish Chander, Traffic Manager		
1962	Punjab Roadways, Pathankot	..	..	..
1963	Ditto	..	..	..
1964	Ditto	..	..	..

## [Minister for Transport and Election]

Year	Depot	Officer in charge	Items of loss	Value Rs nP
1965	Punjab Roadways Pathankot	(1) Shri R. S. Sarkaria, General Manager (2) Shri Bishan Singh, Works Manager (3) Shri G. S. Mahaya, Traffic Manager	Three Batteries	498.0
1962	Punjab Roadways, Chandigarh	..	..	..
1963	Ditto	(1) Shri Naunihal Singh, General Manager (2) Shri Dalip Singh, Traffic Manager	One self-starter	950.00
1964	Ditto	..	..	..
1965	Ditto	(1) Shri Naunihal Singh, General Manager (2) Shri J. N. Durani, Works Manager (3) Shri Dalip Singh, Traffic Manager	Two dynamos	220.00

**Visit to the Central Jail, Patiala by the Minister**

**3151. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) whether he visited the Central Jail, Patiala on the 7th January 1966, if so, the details of the concessions, if any, announced by him in the meeting held with the Jail inmates be laid on the Table ;

(b) whether the promise made and concessions announced by him have been fulfilled ; if not, the reasons therefor ?

**Shri Chand Ram :** (a) Yes. The details of concessions announced by the Minister are given below :—

(i) Remission to prisoners confined in Central Jail, Patiala at the scale of 5 days per month subject to the maximum of 60 days.

(ii) In case no report from the District authorities is received on Parole/Furlough cases of prisoners within the period of one month, the Government will dispose of such cases without waiting for it.

(b) As regards the concession mentioned at (a) (i) above, formal orders have since issued. The proposal as at (ii) above is under consideration of Government.

**Treatment of communications received from the Members of the Punjab Legislature**

**3152. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state whether he and the Chief Secretary have received any complaints from the Legislators of the State, regarding non-compliance with the instructions contained in circular No. 6116-Pol(2P)-64-16546, dated 22nd August, 1964, from the Chief Secretary to Government, Punjab, to all Heads of Departments, Commissioners of Divisions and the Deputy Commissioners in the State on the subject of treatment of communication received from the Members of the Punjab Legislature during the years 1964-65 and 1965-66 to-date ; if so, the details of the action so far taken thereon and the copies of these complaints be laid on the Table ?

**Shri Ram Kishan :** Yes Sir. Copies of the two letters are enclosed. Referring to the complaint, dated 7th August, 1965, further instructions have been issued for strict compliance. A copy of the instructions is also enclosed. Regarding the second complaint, issue of further instructions is under examination

**Copy of letter, dated 7th August, 1965, from Shri Hari Singh, M.L.C., Nehru Garden Road, Jullundur, to the Chief Minister, Punjab.**

I have to bring to your notice that instructions contained Chief Secretary's circular letter No. 6116-Pol(2p)64/16546, dated 22nd August, 1964, on the subject of Treatment of Communications from Members of Punjab Legislature are not being implemented by officers in general as far as my personal experience goes. The circular letter instructs officers to acknowledge letters from Legislators immediately and to send intimation of action taken within one month. In most of the cases when I addressed letters to officers, I did not receive even acknowledgement thereof far less intimation of action taken. I feel by and large officers are completely ignoring Government instructions on the subject.

I am herein under giving specific cases for your information, enquiry and necessary action :—

1. My letter, dated 23rd January, 1965 to the Commissioner, Jullundur, on the subject of grant of sanction to the donation of Rs 25,000 by Jullundur Municipal Committee to Desh Bhagat Yadgar Hall, Jullundur.

2. My letter, dated 9th June, 1965 to the Regional Transport Authority Jullundur on the subject of Bus service in Ilaqa bet of tehsil Garhshankar of district Hoshiarpur.

[Chief Minister]

3. Another letter of mine addressed to Regional Transport Authority, Jullundur, on 18th June, 1965 on the subject of Bus service from Garhshankar to Nairwan.

4. My letter to Secretary, Irrigation and Power of 29th May, 1965 on the subject of Shops Allotment Committee, Talwara.

5. My letter, dated 14th June, 1965 to District Education Officer, re. book grants to certain students of Government High School, Bhunga, district Hoshiarpur.

6. My letter, dated 9th June, 1965 to District Education Officer, Hoshiarpur, re-Pakhowal-Beehran Primary School, in tehsil Garhshankar.

7. My letter, dated 27th May, 1965 to the Superintendent of Police, Hoshiarpur, re-complaint of one Gurdial Singh of re-Inspur, police station Mahilpur :

8. My letter, dated 6th July, 1965 to the Inspector-General of Police re-complaint of Guran Ditta of village Ganga Chak of tehsil Dasuya, district Hoshiarpur.

I am not aware of the experience of other Legislators. I generally write to the Ministers. I have written to officers only on a few occasions. My experience is bitter, for they generally do not even acknowledge letters, despite repeated Government instructions on the subject.

May I expect that you will conduct enquiries as regards specific cases I have brought to your notice and oblige.

Copy of letter No. nil dated the 10th January, 1966 from Master Hari Singh, M.L.C. to the Chief Minister, Punjab.

I have the honour to write this letter to you to bring to your notice once again how the minds of officers of to-day still tend to move in the old grooves of bara sahibs of British period.

Some months back I had brought to your notice a number of concrete instances to show that officers did not even acknowledge letters from Legislators far less intimate the action taken in the matter. Thereby they disregarded the instructions of the Government issued from time to time on the subject. The matter was brought to the notice of the Government and the public through a number of interpellations in the Legislature in the last autumn session.

Now I have the honour to bring to your notice a couple of other instances of wrong attitude of district officials *vis a vis* communications from Legislators. As representatives of people, we have to bring to the notice of ministers certain public grievances, even complaints of individual citizen. They are generally sent by Ministers to district officials for enquiry and necessary action. There is a tendency among district officials to dispose of them in a routine manner as a complaint from such and such Legislators, while in fact it is not a complaint of the Legislator concerned. I had brought two such instances to the notice of Deputy Commissioner, Hoshiarpur, in a letter, dated 2nd December, 1965.

I have along with this to bring to your notice yet another instance of bureaucratic attitude of district officials towards communications from Legislators, if they at all reply to such communications, they are in the habit of calling them as applications from such and such a legislator. I am enclosing copies of recent letters written to me by Deputy Commissioner and Superintendent of Police, Hoshiarpur, dated 2nd December, 1965 in English and 3rd December, 1965 in Punjabi. I fail to understand how our communications are treated as applications by district officials and in what sense.

Such an attitude on the part of officials is derogatory to the dignity and self-respect of Legislators.

You may please correct me if my thinking on the subject is not correct. Else kindly take steps to correct the attitude of officers.

#### **Block Education Officers in Amritsar District**

3153. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the names and academic qualifications of the Block Education Officers working at present in Amritsar District with the headquarters of each ;

(b) the reasons for not fixing Tarsikka as the Headquarters of the Block Education Officer of Tarsikka ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) The requisite information is as under :—

Serial No.	Name of the Block Education Officer	Qualifications	Headquarter
1	Shrimati Harbans Kaur	.. B.A., B.T.	Tarn Taran II
2	Shri Jarnail Singh	.. B.A., B.T.	Khadur Sahib
3	<i>Vacant</i>	.. ..	Bhikhiwind
4	Shri Gurcharan Singh	.. M.A., B.T.	Chogawan-I
5	Shri Saudagar Singh	.. B.A., S.A.V.	Chogawan-II
6	Shri Amarjit Khanna	.. B.A., B.T.	Rayya
7	Shri Balbir Singh	.. B.A., B.T.	Patti
8	S. Sulakhan Singh	.. M.A., B.T.	Naushehra Panu- wan
9	Shri Bhagwant Singh	.. B.A., B.T.	Tarsikka at Rasulpur
10	Shrimati Nirmaljit Kaur	.. M.A., B.T.	Majitha
11	Shri Ajit Singh	.. B.A., B.T.	Ajnala-I
12	Shri Tarjit Singh	.. M.A., B.T.	Ajnala-II
13	Shri Santokh Singh	.. M.A., B.T.	Amritsar-I
14	Shrimati Amrit Kaur	.. B.A., B.T.	Amritsar-II
15	Shri Gian Singh	.. B.A., B.T.	Amritsar-III
16	Shrimati Vimla Aggarwal	.. B.A., B.T.	Amritsar-IV
17	Shri G. R. Dhawan	.. M.A., B.T.	Verka at Amritsar
18	Shrimati B. K. Singh	.. B.A., B.T.	Jandiala Guru
19	Shri Mukhtiar Singh	.. M.A., B.T.	Valtoha
20	Shri Satnam Singh	.. B.A., B.T.	Chola Sahib
21	Shri A. C. Sharma	.. B.A., B.T.	Gandiwind
22	Shrimati Bhagwant Kaur	.. B.A., B.T.	Tarn Taran-I

(b) Because of paucity of suitable accommodation.

## ADJOURNMENT MOTIONS/CALL ATTENTION NOTICES

**ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਲ ਸੇਨ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਝਲਿਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਆਪ ਨੇ ਕਲ ਫਰਮਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਂਡ੍ਰੇਸ 'ਤੇ ਆਰ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਪੱਤ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ੋਲ੍ਵ ਅਕਰੋਂਸ ਵੀ ਹੋ ਕੋਈ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਯਾ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ (ਵਿਧਨ) ਮੈਂ ਨੇ ਕਲ ਵੀ ਰੀਜ਼ੋਲ੍ਵ ਅਕਰੋਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ., ਰੋਹਤਕ, ਨੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ, ਕੰਨਾਲ ਕੋਪੀਟਾ ਆਰ ਉਸ ਦੀ ਗਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ । ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨ ਦੇਵੋ . . . . .

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਓ । ਜੋ ਜਨਰਲ ਡੀਸਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  
(The hon. Member may resume his seat. The general decision already taken on this subject stands.)

**ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਆਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਮੈਂ ਨੇ ਕਲ ਵੀ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਮਾਲਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਪਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨ ਦੇਵੇ ਆਰ ਸੀਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰੀਕੌਂਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ( I had stated yesterday also that if any matter raised by a Member during the course of his speech on the Budget etc. remained unanswered by Government, in that case if the hon. Member chose to give notice of the motion again, that will be duly considered.)

**ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਕ adjournment motion ਸੀ . . . . .

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਓ । (The hon. Member may take his seat.)

**ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ :** ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਗੰਨਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । . . . .

**Mr. Speaker :** No please.

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨਾਂ ਵਲ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਕੁਲ 50,000 ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਪਿਆ ਕੈਰੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਕੈਰੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਰਮੈਂਟ ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਫ ਕਰੇ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ

साहिब दसठ कि आइआ दिलें साहिब दरुसत हन जं चोपरी साहिब दरुसत हन ।  
रुपिआ सकूल लਈ दिता गिआ सी जं कि कैरें मैमोरीअल लਈ दिता गिआ सी । मै  
उहाडा वुलिंग चहुंदा हं कि जदें सकूल वी सरकारी नही है, की कौरी वजीर आपटे  
डिस्क्रिशनरी फंड विचें रुपिआ दे सकदा है .....

**श्री अध्यक्ष :** आपने अपनी बात कह ली है । आप बैठ जाइये । मिनिस्टर  
साहिबान ने अपना अपना बयान दिया है । आप कहते हैं कि वह कंट्रेडिक्टरी हैं ।  
मिनिस्टर साहिबान ने अपने अपने डिस्क्रिशनरी फंड में से रुपया दिया है  
किस परपज के लिए दिया है यह उन का अपना मामला है ।  
(The hon. Member has stated his point. Now he may  
resume his seat. The Ministers have given their own  
statements separately. The hon. Member says that  
these are contradictory. The Ministers have made con-  
tributions out of their discretionary funds. As to for  
what purpose, it is their concern.)

(सरदार लछमण सिंह की तरफ से विघ्न)

**सरदार लछमण सिंह गिल :** वह पब्लिक का रुपया है ।

**श्री अध्यक्ष :** किसी मिनिस्टर ने रुपया अपने डिस्क्रिशनरी फंड से किस काम  
के लिये दिया है यह उस का अपना काम है, अपना व्यू है । चौधरी रणबीर सिंह  
ने किस परपज के लिए दिया है या ठिलों साहिब ने किस परपज के लिये दिया है  
इस के बारे में उन्होंने अपने अपने विचार बता दिये हैं उस में कोई कंट्रेडिक्शन नहीं हो  
सकती । (It is the business of the Minister rather his own view  
to see for what purpose he gives money from his discre-  
tionary fund. Both Chaudhri Ranbir Singh and Sardar  
Gurdial Singh Dhillon have stated their points of view about  
the purpose for which they have contributed money.  
There can be, therefore, no contradiction in their state-  
ments.)

**श्री बलराम जी दास टंडन :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मेरा प्वायंट आफ  
आर्डर यह है कि कल आप नें इस के बारे में रूलिंग दिया है कि जहां तक बजट  
सेशन का ताल्लुक है गवर्नर के एड्रेस पर बहस करते वक़्त और बजट पर बहस करते  
वक़्त कोई काल अटेंशन मोशन और एडवर्नमेंट मोशन नहीं लाई जा सकती । जहां  
तक मैं समझता हूं हमारा हाउस लोक-सभा की रवायात की कापी करता है । इस  
के बारे में लोक सभा में पहले भी कई बार यह बात हो चुकी है .....

**श्री अध्यक्ष :** आप बैठिये ..... (The hon. Member may  
please resume his seat.)

**श्री बलरामजी दास टंडन :** आप मेरी बात तो सुन लीजिये .....

**श्री अध्यक्ष :** मैंने आप की बात समझ ली है । इसके बारे में कि लोक सभा ने एडजर्नमेंट मोशन एडमिट की है कल यहां पर सारी बात आ चुकी है । वह अब रीओपन नहीं हो सकती । कल मैंने खुली इजाजत दे दी थी । केंरल में जहां वह बात हुई उस की अपनी डीटेल्ज हैं, अपनी पोजीशन है। अगर आप चाहें तो मैं वेरियस ग्रुप्स आफ लीडरज के साथ चेम्बर में यह बात डिस्कस कर सकता हूं । यहां पर यह मामला अब खत्म हो जाना चाहिए । नाउ बुरी पास आन टू दी नेक्स्ट आटिस । (I quite follow the hon. Member. The matter that an adjournment motion has been admitted in the Lok Sabha has already been fully discussed yesterday. Now that cannot be reopened. Yesterday, the Members were allowed to express themselves freely on the subject. As to the motion about Kerala, it had its own details and typical position. If the hon. Members so desire, I can discuss this matter with the various group leaders in my Chamber. Now we pass on to the next item.)

**सरदार लडमन सिंह गिल :** सपीकर साहिब, आप ने कहा है कि मिनिस्टर साहिबान नुं एह राशीट है कि उह आपने डिमिशनरी फंड विचें जिस नुं राहुट रुपिया दे देत । उनुं दा एह निजी मामला है । मैं समझदा हूं कि रुपिया स्टेट दा है जिहड़ा उनुं दी डिमिशनल ते है । पबलिक दा रुपिया है अते उह बाकायदा आडिट हुंदा है । जिस रुपये दा आडिट हुंदा है अते जिहड़ा रुपिया डी० सी० दे धरु धरु हुंदा है उस नुं समझदा हूं कि हाउस चैक कर सकदा है । उस दी एह एह पाणी नुं वेध सकदा है कि उह जस्टिस तरीके नाल धरु हुंदा है कि नही । मैनुं तां शक पै गिया है कि एह इस रुपये नुं बरबाद कर देठगे (*Interruptions*)

**श्री मंगल सेन :** स्पीकर साहिब, आप नें बोलने पर पाबन्दी लगा रखी है ।

**श्री अध्यक्ष :** डाक्टर मंगल सेन, आप ऐसी बात न करें । (The hon. Member, Dr. Mangal Sein should avoid saying such things.)

**श्री बलरामजी दास टंडन :** आप मीटिंग बुला लें ।

**श्री अध्यक्ष :** मैं आज ही मीटिंग काल करूंगा । (I will certainly call a meeting today.)

(सरदार लडमन सिंह गिल की तरफ से विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** आप का हक है आप मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं । लेकिन जहां पर यह सवाल आता है कि किस मिनिस्टर ने किस परपज के लिए रुपया दिया इस नें कंटेडिक्शन वाली बात कोई नहीं है । वह जो बात कहते हैं वह ठीक है या गलत आप क्रिटिसाइज कर लें लेकिन उस में कंटेडिक्शन वाली कोई बात नहीं है । (It is the right of the hon. Members to criticise the Ministers. But when the question

arises as to which Minister gave the money and for what purpose he gave it, there appears to be no contradiction in it. The hon. Member may criticise as to what the hon. Ministers have stated but there is no question of any contradiction in these statements.

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਟਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੇ ਅਡ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ.....

**Mr. Speaker** Order please, order.

**ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਗਜਾਧ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਥੀ ਆਪ ਨ ਕਹ ਦਿਯਾ ਨਿ ਆਪ ਅਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ । ਏਕੁ ਤਰਫ਼ ਤੋ.....

(ਵਿਥਨ) .....ਏਕੁ ਤਰਫ਼ ਤੋ ਏਸ.ਏਲ.ਏਜ. ਖਾਨਾ ਖਾਏਂ ਐਰ ਫ਼ੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਹੋਸਟਲ ਮੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭੂਖੇ ਰਹੇਂ । ਧਹ ਕਹਾਂ ਕਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਲੋਗ ਤੋ ਖਾਨਾ ਖਾਏਂ ਐਰ ਬੱਚੇ ਭੂਖੇ ਰਹੇਂ .....

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ( Order please.)

### PAPERS LAID ON THE TABLE

**Planning and Local Government Minister (Sardar Ajmer Singh):** With your permission, Sir, I lay on the Table of the House a copy of the "Harayana Development Committee Final \*Report".

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਭੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ।

**ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਲ ਸੇਨ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਸ ਸਦਨ ਕੀ ਐਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀ ਭੀ ਧਹੀ ਰਿਕਾਯਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਭੀ ਹਾਊਸ ਕੀ ਮੇਜ਼ ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਖੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਯਾ ਕਿਸੀ ਵਿਸ਼ਯ ਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਰਖੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਤਸ ਕੀ ਕਾਪਿਯਾਂ ਮਾਨਨੀਯ ਸਦਸ੍ਯੋਂ ਕੋ ਬਾਟੀਂ ਜਾਤੀ ਹੈਂ । ਇਸ ਲਿਏ ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਫ਼ੁਕਮ ਕਰੇਂ ਕਿ ਹਮੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਾਪਿਯਾਂ ਬਾਂਟੀ ਜਾਏਂ ਤਾਕਿ ਹਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਅਛੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਂ । ਮੈਂ ਕਲ ਪੰਡਿਤ

\*Kept in the Library.

[श्री मंगल सैन]

श्री राम शर्मा को मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि इस रिपोर्ट की एक हजार कापियां छपवायी गई हैं। इस लिए, मैं आप से दोबारा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप हुक्म करें और माननीय मंत्री महोदय टेलीफोन करके इस रिपोर्ट की कापियां मंगवाएं और हमें डिस्ट्रीब्यूट कराएं।

श्री अध्यक्ष : प्रायर तो यही है कि इस रिपोर्ट की कापियां माननीय सदस्यों को बांटी जाएं, अगर कोई टेक्नीकल डिफिकल्टीज हों तो आप देख लें। आप ने अपर हाउस में कितनी कापियां बांटी हैं ? (What appears to be proper is that each Member should have been provided with a copy of this report. If there are any technical difficulties in their distribution that may be looked into by the hon. Minister. How many copies have been distributed to Members in the Upper House ?)

ਜੇਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕੋ ਕਾਪੀ ਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

## RESOLUTION

Regarding lease of land to Birla Brothers (withdrawn)

श्री रामधारी गौड़ (गोहाना) : स्पीकर साहिब, मेरा आज यह रेजोल्यूशन, जिस में मैंने मांग की है कि जो बिरला ब्रादर्स को ज़मीन सरकार ने दी है वह गरीब प्रादमियों को मिलनी चाहिये थी, यह जो जमीन दी गई है समाजवाद के खिलाफ है। जो आदमी खुद काशत करता है, खुद काम करता है उस को मौका मिलना चाहिये, जहाँ एक गुजिपति के जिस के पास ज़राए हैं, अपने साधनों से अच्छे बीज पैदा कराना चाहता है।

Mr. Speaker : Shri Ram Dhari Gaur. . . .

डाक्टर बलदेव प्रकाश : पहले उन को सूब तो कर लेने दीजिए।

श्री रामधारी गौड़ : मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : राम धारी गौड़, आप मेरे पास आए थे और कहा था कि आप इसे सूब नहीं करना चाहते। अगर आप इसे सूब नहीं करना चाहते तो आप स्पीच नहीं कर सकते। (interruption) Order please, order.

या तो आप सूब कीजिए या कहिए कि सूब नहीं करना चाहता। (Addressing Shri Ram Dhari Gaur) (The hon. Member had come to me stating that he had no mind to move the resolution. So if he does not want to move it, he cannot make a speech on it. (Interruption) Order please, order. Either he should move it or say that he does not want to move it.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਾਰੀ ਗੌਡ :** ਕਥੋਂਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਥੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਯਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਪਰ ਮਾਨ ਲਿਆ ਗਯਾ ਹੈ ਆਰ ਓਕ ਕੈਬਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ . . . . . ( *Interruption* )

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਰਾਮਧਾਰੀ ਗੌਡ, ਆਪ ਇਸੇ ਸੂਭ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਯਾ ਨਹੀਂ । (The hon. Member, Shri Ram Dhari Gaur, may please tell me whether he wants to move it or not).

**ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਾਰੀ ਗੌਡ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਥੋਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮਾਨ ਲੀ ਗਈ ਹੈ. . .

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਸਾਫ਼ ਬਤਾਓ ਕਿ ਆਪ ਸੂਭ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਯਾ ਨਹੀਂ ( *Interruption* ) । (The hon. Member should plainly state whether he wants to move it or not). ( *Interruption* )

**ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਾਰੀ ਗੌਡ :** ਕਥੋਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮਾਨ ਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਭ ਕੀਯਾ ਜਾਏ ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਇਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਥੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਚਿਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । 10 ਮਿੰਟ ਤਕ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੌਖਲਾ ਹੈ..... (ਸ਼ੋਰ) ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ( *Interruption* )

**Mr. Speaker :** Order please.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਧਾਰੀ ਗੌਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।

**Mr. Speaker :** Sardar Ajaib Singh Sandhu, will you please withdraw your words ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਦੇਖੀਏ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਧਾਰੀ ਗੌੜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । (Please listen, Shri Ram Dhari Gaur met me in my Chamber and said that he did not want to move it.)

ਕੁਲ ਸ਼ਾਸਕ : ਕਹਿ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਇਥੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ । (Order please. I told the the hon. Member Shri Ram Dhari Gaur that he could do so in two ways. Either he should absent himself from the House when his turn for moving the resolution came or he should state in the House that he had no intention for moving it. But when he started speaking without saying whether he wanted or did not want to move the resolution, then I asked him whether he wanted to move it or not.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਚ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ । ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (Interruption)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । It is a reflection on the Chair. (Addressing Sardar Ajab Singh Sandhu) (Order please, what the hon. Member has said, namely, that why I asked Shri Ramdhari Gaur whether he wanted to move it or not, is not proper. It is a reflection on the Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਦ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Will you please withdraw your words. It is a reflection on the Chair.

(At this stage there was uproar in the House.)

Mr. Speaker : Sardar Lachbman Singh: order please. Sardar Ajaib Singh Sandhu: will you please withdraw your words?

Chief Parliamentary Secretary : Withdraw your words.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ।

**Mr. Speaker :** Sardar Ajaib Singh, please withdraw your words.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦ-ਡਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ? (*Interruptions*).

**Mr. Speaker :** Will you please, withdraw your words or not?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਛ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਣ ਦਿਉਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਲਿਆਂ ਔਰ ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।.....

**Mr. Speaker:** Sardar Ajaib Singh, Order please. (*Interruptions, Noise*)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (*Noise*)

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜਾਧ : ਗੈਡ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੀ (*Interruptions*).

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਯਾਮ : ਜਬ ਤਕ ਕਹ ਸੇਂਬਰ ਫਾਰਸਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਗਾ, ਕਹ ਸੂਕਤ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ। This is in accordance with the rules. (So long as the Member concerned does not formally move the resolution, it cannot be deemed to have been moved. This is in accordance with the rules.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਕਾਰਡ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫਰੈਂਸ ਨਾ ਕਢੀਏ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ—ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ ਰੈੱਡ ਸਮਝ ਲਿਆ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ read and moved ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਸ ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ ਦਸੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ find out ਕਰ ਲਉ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ—ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਰੀਕਾਰਡ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਇਕ ਦੋ ਸੈਨਟੇਸਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ **because he might have changed his mind.** ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚੇਂਬਰ ਮੇਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹोंने कहा कि मैं अपने रज़ॉल्यूशन को मूव नहीं करना चाहता। मैं यह वहाँ कहूँगा। जब इन्होंने यह नहीं कहा तब मैंने पूछा कि आप इस को मूव करना चाहते हैं या नहीं। इस पर दस मिनट बोलने की बात नहीं है, दो तीन मिनट लगे होंगे।

ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਧਰ ਕਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ ਤਕ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਗਯਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਮੰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਬਿਨ ਰੈਂਡ ਏਂਡ ਸੂਝ ਸਮਝਾ ਜਾਏ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਂ ਤੋ ਏਸਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਗਰ ਮੇਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੇਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਮੇਂ ਕੀ ਡੀਮੰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਬਿਨ ਸੂਝ ਏਂਡ ਰੈਂਡ। ਆਜ਼ ਤਕ ਏਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। **(I think the hon. Member was not present in the House at that time. It is not a question of 10 minutes. The hon. Member concerned hardly spoke for two or three minutes and the record would be shown to Sardar Gurnam Singh. The Member had first told me that he would not be moving his resolution. But when he had uttered one or two sentences and still did not move his resolution then I asked him whether he wanted to move it or not because he might have changed his views. I repeat that when he came to my Chamber, he said that he would say in the House that he did not want to move the resolution. When he did not say that but started speaking, then I enquired of him whether he wanted to move it or not. So, there is no question of his speaking for ten minutes. He may have taken two or three minutes.)**

The other point which I would like to mention is that so far it has never been the practice that a main resolution could be deemed to have been read and moved. This is possible in the case of amendments but not in the case of a main resolution. It is never stated by the Chair that the main resolution should be deemed to have been read and moved. There has never been such a practice here.)

ਚੌਥਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ : ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। (ਵਿਧਨ)

ਮੇਰਾ ਬਯਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰ ਜੋ ਬਿਰਲਾ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਦੀ ਏਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਗੌਰ ਹੈ . . . . .

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ : ਆਪ ਬੈਠਿਓ। (ਵਿਧਨ) ਆਪ ਤੋ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਲਗੇ ਹੈਂ। (ਵਿਧਨ) ਧਰ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਪਰ ਕੁਝ ਨ ਕਹਿਓ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਹਨੀ ਹੋ ਤੋ ਕਹੋ। (ਵਿਧਨ) **(The hon. Member**

may resume his seat. (*Interruptions*) He has started speaking on the resolution. (*Interruptions*). This is not a point of order. He need not comment on the wording of the resolution, but if he has to say anything else, that he may do so. (*Interruptions*).

**ਚੌਥਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ :** ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਏਕ ਲਫਜ਼ ਭੀ ਭਰਾ ਉਥਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ । ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵਾਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਤੀਨ ਵਧਾ ਕਿਆ । ਤਬ ਆਪ ਨੇ ਸਦਾਕਲਤ ਕੀ (ਵਿਧਨ) ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਰ ਇਸ ਲਿਓ ਭਾਵਾਰਥ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ । ਯਹ ਬਾਤ ਕਾਰਯਵਾਹੀ ਮੇਂ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ । ਯਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ (ਵਿਧਨ) ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵਾਰਥ ਇਸਲਿਓ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯਹ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੰਜੀਪਤਿ ਕੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਯਹ ਗਲਤ ਵੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਬ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਭਾਵਾਰਥ ਕਿਆ ਤੋ ਕਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਯਾ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਸੰਗਾਏ ਹੂੰ । ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਯਹ ਲਫਜ਼ ਹੁਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ ਯਾ ਯਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ (ਵਿਧਨ) (ਭੋਰ)..... I have called for the proceedings. If any where these words have been used that "I want to move this" or "I am moving this resolution... (*Interruption*). Order please.)

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਮਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਤਕ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ..... (ਵਿਧਨ)

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਧਾਰੀ ਗੌੜ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਏ ) (ਵਿਧਨ)

**Mr Speaker :** The Chief Minister.

(ਵਿਧਨ)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਲਉ ਹੁਣ [ X X X X ]\* ਨੂੰ ਸੁਣੋ (ਵਿਧਨ)

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । (ਵਿਧਨ) You cannot make observations at any time you like. (There is a limit to everything. It is not proper for the hon. Member to make such remarks. I give him the last warning. The House is not at the mercy of the hon. Member. This is not desirable and it cannot be allowed. (*Interruption*) He cannot make observations at any time he likes),

\*Expunged as ordered by the Chair.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । [ X X X X ]\* ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ? (ਵਿਘਨ) ਇਹ [ X X X X ]\* ਹੈ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : [ X X X X ]\* (ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : [ X X X X ]\* (ਸ਼ੋਰ)  
[ X X X X X X X X ]\* (ਸ਼ੋਰ)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : [ X X X X ]\* (ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : [ X X X ]\* (ਸ਼ੋਰ)

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧ്യਕਸ਼ : ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਕੱਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਟਰਪੁਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ । ਅਗਰ ਏਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਨਟਰਪੁਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਰੀ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਇਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਟਰਪੁਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । (Every hon. Member or a Minister or the Chief Minister has a right to express his views here and no interruptions of any kind ought be made. This does not look proper. If one side of the House starts interruptions, the other side also arrogates itself to this right. I would, therefore, submit that there should be no interruption at all).

Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a Point of Order, Sir.

Mr. Speaker : If it is not a valid Point of Order, it will be taken as a misuse of that right.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸੁਣ ਲਵੋ । ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ [ X X X ]\* ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਛਮਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ । ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ । (ਵਿਘਨ) ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰੀਮ ਸਨ । (ਵਿਘਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਬੀ ਕਿਹਾ.....(ਵਿਘਨ) ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪੰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । (I did not want to say this. Sardar Lachhman Singh used the word Dharam Putra, Other things followed. (Interruption). Sardar Lachhman Singh uttered words of an extreme nature. (Interruption) He called him Birle da Bi (Interruption). All these utterances are expunged from the proceedings)

(Chaudhri Net Ram rose on a point of order)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਇੰਟਰਪੁਨ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰੈਸ਼ਨਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਐਕਸਪੰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । (ਵਿਘਨ) (Whatever interruptions were made and

\*Expunged as ordered by the chair,

expressions used after Sardar Lachhman Singh had uttered the word 'Dharam Putra' are expunged from the proceedings.)  
(ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟਡਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਪਈ) (ਸ਼ੋਰ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਇਨਟਰਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਰੀਕ੍ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣ ਦਿਉ ।  
(As already stated, all the interruptions made and expressions used after Sardar Lachhman Singh had uttered the words 'Dharam Putra' will stand expunged. I would now request the hon. Member to let the proceedings of the house be carried on smoothly).

11 a.m.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ [\*\*\*\*\*] ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ [\*\*\*\*\*] ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ । (ਸ਼ੋਰ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼, ਆਰਡਰ । ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ) (Order please, order. Even now Sardar Lachhman Singh Gill has said certain things which are not proper) (Interruptions) (Noise)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ [\*\*\*\*\*] ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । (ਵਿਘਨ)

Mr Speaker : Orde please, order.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ . . . . . । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ).

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਪ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

(Will Shri Gill keep quiet or not ?)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਚੁਪ ਹਾਂ ! (I obey you, Sir.)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਲਫਜ਼ 'ਧਰਮਪੁੱਤਰ' ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਤਾਪ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤ 'ਬੇਈਮਾਨ' ਰੀਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ । (After the use of the word 'Dharam Putra' by Sardar Lachhman Singh Gill, whatever has been said by him or Shri Ram Partap Garg or others including the word "Beiman" (Dishonest) will not be deemed to be part of the proceedings.)

\*Expunged as ordered by the chair.

**मुख्य मंत्री :** स्पीकर साहिब, पिछले दस पंद्रह मिनट में जो कुछ इस हाउस में हुआ है मैं इन्हें स्पीचिज़ तो नहीं कहता जिस किस्म का मुज़ाहरा हुआ है यह बड़ा दुखदायक है। मैं उन्हीं कायन्ज़ में जिन में कि उन्हीं ने कहा है कुछ नहीं कहना चाहता। उन्हीं कायन्ज़ में रीपे नहीं करना चाहता, जो कुछ कि सरदार लच्छमण सिंह गिल और दूसरे दोस्तों ने कहा है। मेरी ज़बरदस्त चाहिश है और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हाऊस की डिगनिटी मेनटेन हो और एक डिगनीफाइड तरीके से हाऊस की प्रोसीडिंगज़ को चलाया जाए। जहां तक ट्रेयरी बैंचों का ताल्लुक है वह आप को अनकुआलीफाइड स्पोर्ट देंगे। (प्रशंसा) और मैं यह चाहता हूं कि जो पार्लियमेंटरी रवायात हैं, उन पर सारे भाई पूरी तरह से अमल करें। यह एक रवायत है कि जब स्पीकर की तरफ से रूलिंग आ जाए तो उस को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आप ने एक रूलिंग दिया और श्री राम धारी गौड़ को अपना रैज़ोल्यूशन विदडरा करने की इज़ाज़त दे दी तो फिर इस रूलिंग को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था। अगर स्पीकर की रूलिंग को न माना जाए तो हाऊस की डिगनिटी नहीं रहती। इस के कारण हाऊस के बाहर प्रैस में और प्लेटफार्म पर लोग इस हाऊस के बारे में ठीक राए कायम नहीं करेंगे। इस लिये मैं सब मैम्बर साहिबान से अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हाऊस की कारवाई को आगे चलने दें।..... (विघ्न)

**चौधरी नेत राम :** यह किस तरह कह सकते हैं कि रैज़ोल्यूशन मूव नहीं किया.... आप इस तरह कैसे रोक सकते हैं..... (विघ्न) (शोर)।

**श्री अध्यक्ष :** आप बार बार हाऊस की प्रोसीडिंगज़ को आब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं।  
(The hon. Member is obstructing the proceedings time and again.)

**चौधरी नेत राम :** मैं तो यह अर्ज़ कर रहा था कि उन्हीं ने कहा था कि मैं रैज़ोल्यूशन मूव करता हूं और उस के आगे अपनी तकरीर शुरू कर दी थी तो फिर आप को क्या अधिकार है कि आप कहें कि रैज़ोल्यूशन मूव नहीं हुआ। इस तरह से हरिजनों को दी जाने वाली जमीन...  
... (विघ्न)।

**श्री अध्यक्ष :** आप हाऊस की प्रोसीडिंगज़ को आब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं।  
(The hon. Member is obstructing the proceedings of the House.) (Interruptions)

I order the hon. Member to withdraw from the House. He is obstructing the proceedings of the House.  
(Interruption by Chaudhri Net Ram)

**श्री अध्यक्ष :** आप हाऊस से बाहर चले जाएं। (The hon. Member may please withdraw from the House).

**चौधरी नेत राम :** आप किस तरह से रैज़ोल्यूशन को विदडरा करवा सकते हैं? सरकार पंडित रामधारी को दबा कर उस से इसको विदडरा कराना चाहती है। इस तरह यह जो ज़मीन हरिजनों और गरीब किसानों को दी जानी थी उसे यह बिरले को दे रहे हैं यह कैसे सहन किया जा सकता है।..... (विघ्न) (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप को पहले ही हुकम दिया जा चुका है कि आप हाउस से विदडरा करें। (He has already been ordered to leave the House.)

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर. . . .

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम आप हाउस से बाहर चले जाइए। विल यू प्लीज . . . .  
(Please withdraw from the House. Will you please. . . .)

सरदार लडमट सिंघ गिल : उमीं सपीकर साहिब, जेस विंच ना आउ। (शोर)

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी नेत राम : जनाब आप किस तरह मुझे बाहर जाने का हुकम दे रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा हो और उस पर से अगर हम परदा उठाना चाहें और सरकार की तरफ से किए गए भ्रष्टाचार का इस हाउस में जिक्र करें तो आप क्या इसे हाउस की डिगनिटी नहीं समझते। आप यह चाहते हैं कि सरकार इस तरह से गरीब किसान के हक पर छपा मारे और लोगों के जज्बात की कदर न करें। (विघ्न) क्या आप चाहते हैं कि सरकार बिरले की, आपर की या किसी और की हिमायत करे और इस रैजोल्यूशन को मूव न करने दे और इस रोके ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम बावजूद चेयर कै कहने के हाउस से बाहर नहीं जा रहे हैं, इसलिये मैंने मार्शल को हदायत की है कि वह जा कर इन्हें हाउस से बाहर जाने को कहे।  
(Since Chaudhri Net Ram has refused to withdraw from the House, despite the orders of the Chair, I have directed the Marshal to approach the Member and tell him to leave the House.)

(विरोधी पक्ष की ओर से : शोम शोम) ( इस समय मार्शल चौधरी नेत राम के पास आ कर खड़ा हो गया )। (शोर)

सरदार लडमट सिंघ गिल : ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੇਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ।

Mr. Speaker : Please take your seat. (Interruption)  
ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Please take your seat (Interuption). I have ordered Chaúdhri Net Ram to leave the House and he should go out.) (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦਫ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੁਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

**Mr. Speaker:** Order Please.

**ਚੌਥਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ :** ਕਧਾ ਧਹੁ ਸਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਲਾ ਕੀ ਯਮੀਨ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰ ਫ਼ਸ ਯਮੀਨ ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਥਾ ਤਸੇ ਤਸੇ ਮਹਰੂਮ ਕਿਆ ਗਯਾ ਹੈ ? ( X X X )\*

(ਵਿਘਨ)

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਆਪ, ਚੌਥਰੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ । ਮੈਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿਆ ਹੁਆ ਹੈ... (ਵਿਘਨ)। (Chaudhri Net Ram may withdraw from the House. I have already ordered him to do so.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** [ X X X ]\*

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਆਪ ਚੁਪ ਰਹਿਓ । ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । (Order please, he may keep quiet.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

(ਫ਼ਸ ਸਮਧ ਚੌਥਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਸਾਰਥਲ ਕੇ ਸਾਥ ਹਾਤਸ ਸੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ) ( ਸ਼ੋਰ )

**Mr. Speaker :** Sardar Lachhman Singh Gill is proving disorderly and is obstructing the proceedings of the House. I order him to withdraw from the House. (interruptions)

I order Sardar Lachhman Singh Gill to withdraw from the House. He is obstructing the proceedings of the House and is not obeying the Chair.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** Please withdraw from the House. ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । (Please withdraw from the House. I have perforce to send the Marshal).

(At this stage the Marshal was directed to go to Sardar Lachhman Singh Gill.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਭੇਜ ਦਿਉ ।

**Mr Speaker :** Please withdraw from the House.

(At this stage. Sardar Surjit Singh. Theri got up from his seat and sat in between Sardar Lachhman Singh Gill and the Marshal)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

**Mr. Speaker :** Mr. Gill, I again ask you to withdraw from the House, please.

\*Expunged as ordered by the Chair.

**Sardar Lachhman Singh Gill :** \* \* \*  
**Mr. Speaker :** Mr. Gill, I have ordered you to withdraw from the House. Please withdraw.

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਥੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ \* \* \* ਦੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿਦਫਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵੇਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। **Order please.** (ਵਿਘਨ) . . . .

(I never expected that with full knowledge of the whole position, Comrade Babu Singh would raise such a point of order. Not once but several times I have pulled up Chaudhri Net Ram, but every time, he has misused the point of order.) (Interruption)

**Order, please . . . .** (ਵਿਘਨ)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** [\* \* \*]\*

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼। ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਫਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੇਅਰ ਤੇ reflection ਹੈ। (Interruption) (Order please. Whatever the hon. Member, Sardar Lachhman Singh had said, he should withdraw it. This is a reflection on the Chair.) (Interruption)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਉ।

[\* \* \*]\*

**Mr. Speaker :** (Addressing Sardar Surjit Singh Theri) Please go to your seat.

**ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਐਡਜਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

**Mr. Speaker :** Please go to your seat.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ :** ਇਹੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਡਜਰਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਉ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧ്യਕਸ਼ :** क्योंकि मैम्बरज हाऊस की प्रोसीडिंगज़ को चलने नहीं देना चाहते, इस लिए मैं आध घंटा के लिए हाऊस को एडजर्न करता हूँ। **Sardar Lachhman Singh will not be allowed to enter the House when it re-assembles. (Since some Members of the House are obstructing the proceedings of the House, I adjourn it for half-an-hour. However, Sardar Lachhman Singh will not be allowed to enter the House when it re-assembles.)**

**Sadar Lachhman Singh Gill :** I will not leave, the House.  
(The House re-assembled at 11.45 A. M.)

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਏਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਿਰ ਕਢੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ)

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਢੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਢੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਂਰ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਕਿ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਏਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।

**Planning and Local Government Minister :** I endorse what the Leader of the Opposition has said. In the interest of smooth working of the House and in the interest of Parliamentary conventions it is very very proper on our part that we should not indulge in excited tempers. I request Sardar Lachhman Singh Gill to withdraw what he has said in order to restore peace and calmness in the House.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲਫਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। (Yes. I agree)

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 8/10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਏਥੇ ਦਫਾ 44 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਐਂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ। ਉਥੇ 10/15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ . . . (ਵਿਘਨ)

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਸਰੀਫ਼ ਰਖੋ। ਮੇਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ

ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰਮੁਨਾਸਬ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(The hon. Member, Shri Josh, may resume his seat. My difficulty is that according to Rules, unless a Member has formally moved a resolution, it cannot be deemed to have been moved. It would have been quite appropriate, if the hon. Member had without making any observation, stated only this that he did not want to move the resolution. It was not fair what he did. Anyhow since he did not formally move the resolution, it cannot be treated as having been moved.)

**ਆਵਾਜ਼ਾਂ :** ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਲੀਡਰਜ਼ ਦੀ ਗਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(The convention is that if the group leaders are consulted by the Chair, the whole position is considered to have come to the knowledge of the Members of the respective groups. I, therefore, think that full information of whatever transpired between me and the group leaders has reached them. As regards moving of the resolution, it can not be deemed to have been moved. But if the hon. Chief Minister wants to make any observations for the satisfaction of the House, that he can do.)

**ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪਰਕਾਸ਼ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਗਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦਫਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਭੱਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਆਨ-ਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਦਫਰਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੋਰੇਂਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਅਸੋਰੇਂਸ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਉ ਔਰ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਧਾਰੀ ਗੋਂਡ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋ ਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਪਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੁਨਾਚਿ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਮੂਵ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਧਾਰੀ ਗੌੜ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿਨਟ ਲਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੀਚ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਮਾਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਬਸਟਾਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਰ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪੇਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਰੂਲ 84 ਇਸਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਰਖ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। (The suggestion made by the hon. Member is quite appropriate that the speech should be commenced after the main resolution or the main motion has been formally moved. I think this is quite a reasonable suggestion and in future we will follow it and see that before formally moving a main substantive motion or a resolution the mover does not make his speech. So far as amendments are concerned, they belong to a separate category. If the same procedure is adopted in their case as well then keeping in view the large number in which their notices are received, the hon. Members can well imagine the long time that will be required to move them. Thus the time for speeches will be reduced and a large number of Members would be deprived of an opportunity to speak. As regards the demand for discussion on this subject in the House, I submit that if all the leaders of groups in the Opposition make a demand for this in writing, then I shall allow discussion under Rule 84. But in this connection I have to make this suggestion that it would be better if the discussion on this matter is held

after the Budget is passed or if all the Opposition groups agree, a non-official day may be allocated for this discussion after the passage of the Budget.)

**ਆਵਾਜ਼ਾਂ :** ਠੀਕ ਹੈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ਲ ਡੇ ਰਖ ਦਿਉ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ਲ ਡੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Very well. After deliberating the matter in the Business Advisory Committee, a non-official day will be earmarked for this purpose.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਹ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਧਰ ਹੈ ਕਿ 1965 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੀ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਕਹਾ ਥਾ. . . . . ਏਕ ਲਾਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਜਾਏਗੀ. . . .

**Mr. Speaker :** No speech. Please state your point of order only.

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਹ :** ਮੈਂ ਆਪ ਕਾ ਰੁਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਕਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਂਚ ਸਾਤ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਜਾਏਗਾ ?

**Mr. Speaker :** I have already given ruling in detail on this point. Please take your seat.

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਅਮਰ ਸਿੰਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂਪ ਲੀਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਤਕਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਸੁਨਾਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਂਫੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਏ ਅਤੇ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਿਏ ਕਿ ਵਹ ਕੀ ਸਪੀਚ ਹੈ. . . . .

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਬੈਠਿਏ, ਆਪਕੇ ਲੀਡਰ ਭੀ ਵਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਥੇ।

(The hon. Member may please resume his seat. His leader was also there in the Committee.)

**ਮੁਖੀ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਹੁਆ ਹੈ ਵਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰ ਜਿਨ ਖਿਆਲਾਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਉਸ ਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰਖਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਗੇ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮ ਇਸ ਹਾਊਸ ਕੀ ਕਾਰਜ-ਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਚਲਾਏਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸੇ ਹਾਊਸ ਕੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਮੈਂ ਧਰ ਸਮਝਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪਾਲੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨਸੇ ਵਹ ਇਤਫਾਕ ਨ ਕਰੇਂ ਕ੍ਰਿ-ਟੀਸਾਇਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਇਨ ਬੈਂਚਾਂ ਪਰ ਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨਕਾ ਭੀ ਜਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋ ਉਸ ਤਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਤਵਜ਼ੋਹ ਦਿਲਾਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਹਦ ਤਕ ਯਾਜ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਉਸ ਪਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਏਸਾ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਭੀ ਹਮੇਂ ਅਪਨੀ ਕੁਝ ਰਵਾਯਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿਏ, ਹਮੇਂ ਕਿਸੀ ਤਰਹ ਭੀ ਏਕਸਾਇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਏ, ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿਏ ਅਤੇ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹਿਏ। ਜੋ ਬਾਤ ਭੀ ਕੋਈ ਕਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਹ ਮੀਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਮ ਇਸੀ

[मुख्य मन्त्री]

तरह बातें करेंगे तो इस से हमें किसी को शोभा नहीं मिलने वाली है और सारे हिन्दुस्तान में हमारी बदनामी होगी। मैं आशा रखता हूँ मुस्लिम पार्टी के सारे लीडरज मेरे साथ इस बात पर सहमत होंगे कि हम सब मिल कर इस तरीके से हाउस की कार्यवाही चलाएं जिस से कि बाकी बातों की तरह हम इस बात में भी दूसरी स्टेज को लीड दे सकें। जहां तक इन बैचों का सम्बन्ध है मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी और अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसके लिये जो आप स्पीकर साहिब कार्यवाही करेंगे हम पूरी तरह से आपको स्पॉर्ट देंगे ( cheers ) चेयर पर जो भी बैठा हो उसका इज्जत मान करना और उसके रूलिंग को मानना चाहे वह किसी को अच्छा लगे या बुरा हम सब का फर्ज है और इसी तरह हाउस की डिगनिटी कायम रह सकती है और हाउस की कार्यवाही चल सकती है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले सेशन में इस बात का यहां चर्चा हुआ था और सेशन खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के मੈम्बर साहिबान और कांग्रेस पार्टी के हरिजन मੈम्बरान के डैपुटेशन मुझे मिले थे और उन्होंने ने कहा था कि सरकार को इस डीड के सम्बन्ध में दोबारा गौर करना चाहिए। उसके बाद फिर इस हाउस की एस्टीमेट्स कमेटी भी रोपड़ उस फार्म को देखने गई थी। मुझे पता नहीं उन्होंने ने उसके बारे में क्या रिपोर्ट दी है लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक गवर्नमेंट का सम्बन्ध है हमारे पास जो भी चीज चाह इस तरफ से आए या उस तरफ से आए गवर्नमेंट उसे प्रेस्टीज के पायंट आफ व्यू से नहीं देखेगी। जो बात भी पंजाब के लोगों के हित की होगी गवर्नमेंट उस पर गौर करने के लिये हमेशा तैयार है। मैं ने जैसा कि अर्ज किया पिछले सेशन के बाद कुछ दोस्त कांग्रेस पार्टी के डैपुटेशन के साथ मिले थे। कोई 1½ महीना हुआ उसके मुताबिक कैबिनेट ने उनकी बात पर गौर किया था और हम ने डिसाइड किया था कि इस बिरला ब्रदर्स के डीड को रिव्यू किया जाए। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं जनवरी के महीने में कई ट्रैजिक डैथज हुई जिनकी वजह से कैबिनेट की नारमल मीटिंगज नहीं हो सकीं। कल फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस में हम ने यह फैसला किया कि इस सारी चीज पर गौर करने के लिये एक कैबिनेट सब कमेटी मुकर्रर की जाए जो इस सारे सवाल के लीगल, फिनांशल और दूसरे सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे। यह सब कमेटी एक हफ्ता के अन्दर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को देगी और फिर कैबिनेट उस पर गौर करेगी। हम ने जो सब कमेटी बनाई है उसके मैम्बर यह हैं :

1. Sardar Darbara Singh, Home and Development Minister  
Chairman
2. Major Harinder Singh, Revenue Minister
3. Sardar Gurdial Singh Dhillon, Transport and Elections.  
Minister
4. Chaudhri Ranbir Singh, Public Works Minister
5. Sardar Ajmer Singh, Planning Minister
6. Chaudhri Chand Ram, Welfare Minister

12.05 p.m. स्पीकर साहिब, यह सब कमेटी इस विषय के सारे पहलुओं पर गौर करेगी और एक हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को पेश करेगी। इस के बाद उस रिपोर्ट पर कैबिनेट में डिटेल्ड में गौर होगा।

स्पीकर साहिब, जहां तक नान-ऑफिशल डे का सम्बन्ध है, मुझे भी इस बारे में 13, 14 वर्ष का तजर्बा है कि किस तरह से रैजोल्यूशन मूव होता है। जब रैजोल्यूशन मूव किया जाता है तो बाकायदा वह रैजोल्यूशन हाउस में पढ़ा जाता है और मूव किया जाता है। मैं रैजोल्यूशन की अमेंडमेंट्स के बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना कहना चाहता हू कि जिस तरह से रैजोल्यूशन मूव किया जाता है, उस तरह से यह रैजोल्यूशन मूव नहीं किया गया। मैं इस वक्त प्रोसीडिंग्स के अन्दर नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन जो कुछ हुआ वह काबले ऑफ सोस है। मैं आशा करता हूँ कि जिन जजबात को मैं ने इज़हार किया है उसके बारे में माननीय सदस्य विचार करेंगे और ठीक ढंग से कार्यवाही चलाने में मदद देने का भरसक प्रयत्न करेंगे। मैं लीडर ऑफ दी ऑपोजीशन को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से किसी भी शक्ल में किसी का अपमान नहीं किया जाएगा। किसी पर परसनल अटैक नहीं किया जाएगा। किसी पर गन्दगी उछालने की कोशिश नहीं की जाएगी जो कि किसी तरह से हाउस को और हमें शोभा नहीं देता। मैं आशा रखता हूँ कि आप की तरफ से भी इसी तरह का माहौल कायम रखने की कोशिश की जाएगी। जहां तक गवर्न-मैंट की पालिसी को क्रिटीसाइज़ करने का सम्बन्ध है, उस के बारे में आपको पूरा हक है लेकिन कायदे और ज़ाबते के अधीन ही क्रिटीसिज़्म होना चाहिए।

जहां तक स्पीकर साहिब की रूलिंग का सम्बन्ध है, हम उस रूलिंग को पसन्द करें या न करें, उस के बारे में हमारा फर्ज है कि हम उन के आर्डज़ को मानें और पालन करें। उस के बाद हमें किसी तरह से खड़े हो कर स्पीचें नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हाउस के माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे और इस पर अमल करेंगे।

स्पीकर साहिब, मैं अन्त में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो कुछ हाउस में तलखी के वक्त हुआ, वह हाउस की प्रोसीडिंग्स में से ऐक्सपेंच कर दिया जाए।

**बामरेड गुरबਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ :** ਆਠ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਰ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

### RESOLUTION

Regarding development of Hilly and Haryana areas of the State by earmarking 60 per cent of the Plan funds for them.

**Mr. Speaker .** Now we pass on to the next Resolution given notice of by Shri Balramji Dass Tandon.

**Shri Balramji Dass Tandon (Amritsar City, West) :** Sir, I beg to move that —

With a view to bring the hilly areas of the Punjab which are backward, at par with the adjoining areas of the State and the Haryana area at par with the rest of the State in the matter of development, this House recommends to the Government to make plan allocations in such a way that sixty per cent of the plan funds are earmarked for the said Haryana area and the hilly areas.

स्पीकर साहिब, यह बहुत ही अहम मसला है। यह मसला पंजाब के पहाड़ी और हरियाणा क्षेत्रों के लोगों से सम्बन्ध रखता है। इस के बारे में पंजाब की जनता और लैजिस्लेटर्स के जो विचार हैं, उन को सरकार नहीं समझ सकी हैं, और मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं की। आज तक कांग्रेस का राज रहा है। यह ठीक है कि इस

[ श्री बलरामजी दास टंडन ]

असं के दौरान मिनिस्ट्रीज बदलीं। मैं यह भी मानता हूँ कि वर्तमान मिनिस्टरी में नए चीफ मिनिस्टर और कुछ अन्य व्यक्ति भी नए मिनिस्टर बने और उन में कुछ पिछली मिनिस्टरी के मिनिस्टर भी शामिल हुए लेकिन एक बात ठीक है कि इस सरकार ने वहाँ के लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। यह सरकार इस मसले को ऐजेण्डा नहीं ले रही है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हकूमत लोगों के जज्बात की परवाह नहीं करती है।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा और पहाड़ी इलाकों की बेहतरी के लिये कोई कदम नहीं उठाए और नहीं उन की डिवैलपमेंट की तरफ ध्यान दिया। सरकार ने पंजाब की जनता के और लैजिस्लैटर्ज के जज्बात की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। मुझे यह भी पता नहीं कि सरकार उन की डिवैलपमेंट की तरफ कितनी देर तक ध्यान नहीं देगी। जब भी पंजाब के बारे में स्कीमें तैयार की जाती हैं, उस वक्त इन इलाकों के लिये प्रापर स्कीमें तैयार नहीं की जाती। वहाँ पर सड़कें बनाने के लिये, सिंचाई के साधनों के लिए और बिजली सप्लाई करने के बारे में स्कीमें बनाई नहीं जातीं जिस का नतीजा यह होता है कि यह इलाके जो पहले ही पिछड़े हुए थे, वह और पिछड़ गए हैं। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को किसी तरह नहीं निभाया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पहली कैबिनेट में और इस कैबिनेट में हरियाणा प्रान्त के व्यक्ति भी मिनिस्टर रहे। इनके पास बिजली तथा सिंचाई जैसे इम्पार्टेंट महकमे रहें लेकिन इन्होंने वहाँ के लोगों की हालत को सुधारने के लिये कोई कोशिश नहीं की। इनको चाहिए था कि कम से कम इन बातों को इन्साफ के साथ देखने की कोशिश तो करते। जो पिछड़े हुए इलाके अंग्रेजों के वक्त से आ रहे हैं वह अब भी जब कि हमारी अपनी गवर्नमेंट है, अपने वजीर हैं, नज़र अंदाज़ होते रहे। वह अब भी पिछड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यह बात हमारी गवर्नमेंट के लिये और वजीरों के लिये भी शोभा नहीं देती। जब हम डीवैलपमेंट की बात को देखते हैं तो सब से पहले इम्पार्टेंट सवाल सड़कों का आता है। बिजली का सवाल आता है, इरीगेशन का सवाल आता है, एजुकेशन का सवाल आता है और इस के इलावा दूसरे साधनों को देखने का भी सवाल आता है। हमने यह भी देखना है कि आयाजिन इलाकों में हर साल फलड्रज आते हैं सरकार ने उनको रोकने का क्या प्रबन्ध किया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हर साल ड्रायट होता है। हमारे प्रदेश के कुछ इलाके हर साल उस की नज़र होते हैं, एक साल भी खाली नहीं जाता तो यह भी देखना है कि हमारी सरकार ने इस मसले को हल करने का क्या इन्तज़ाम किया है। यह चन्द एक मसले हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। ग़रे सामने बिजली मन्त्री बैठे हैं। मैं कुछ बातें उन के गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ। वे बिजली के महकमे के काम को देखने की कोशिश करें। कितने अफसोस की बात है कि अमृतसर के जिले में जहाँ पर इलैक्ट्रीफिकेशन हुई वहाँ पर 80 परसेंट गांव में बिजली जा चुकी है। इस के मुकाबिले में हमारी सरकार हरियाणा को भी देखे तो मालूम होगा कि सारे हरियाणा के अन्दर केवल दस से पन्द्रह परसेंट तक गांव इलैक्ट्रिफाइड हुए हैं। जिन इलाकों में इलैक्ट्रीफिकेशन नहीं हुई और न ही उन में आज तक इरीगेशन का कोई मुनासिब इन्तज़ाम हुआ है उन इलाकों ने हमारे प्रदेश पंजाब को आज तक एग्रीकल्चर यील्ड दे कर किसी प्रकार की बेहतरी और बहबूदी में कोई एडिशन नहीं की, उन के बारे में यह बात कही जा सकती है। हमारे प्रदेश का सरमाया बढ़ाने के लिये उन की कुछ कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो

इलाके बैरन हैं, आज तक बजिन हैं अगर उन में बिजली दी जाती, ट्यूबवैल लगा कर और दूसरा प्रबन्ध कर के वहाँ पर कृषि के काम को बढ़ावा दिया जाता तो शायद आज जो हालात हैं वे न होते। आज हिन्दोस्तान की हकूमत को करोड़ों अरबों रुपयों का अन्न बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर पंजाब की वह सारी धरती जो आज तक बैरन पड़ी है अन्न को उपजाती तो करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा हमारा देश बचा सकता था। जो आज अरबों की गिनती में बाहर रुपया जाता है वह बहुत हद तक बचाया जा सकता था। और साथ ही हमारा पंजाब इस बात के लिये सिर ऊंचा कर सकता था। जिन इलाकों में कुछ पैदा नहीं होता उन की यील्ड क्या हो सकती है, इस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जो लोग एक्सपर्ट हैं वह इस के बारे में आंकड़े बता सकते हैं कि यहां पर कितनी यील्ड हो सकती है। स्पीकर साहिब इस के विपरीत हमारी आंखों के सामने उन इलाकों की तस्वीर आती है जो कि इलैक्ट्रीफाइड हैं और जहां पर कदम कदम पर ट्यूबवैल लगे हुए हैं, नहरें हैं। वहां पर पोर्जीशन यह है कि वाटर-लागिंग की भयंकर समस्या बनी हुई है। बिलकुल पहली बात के उल्ट वाटर लागिंग की समस्या सिर दर्द बन कर खड़ी है। वहां से फालतू पानी को निकालने के लिये नालियां खोदने के लिये और ड्रेनेज बनाने के लिये करोड़ों अरबों रुपयों की आवश्यकता है। एक तरफ तो पानी नहीं है, पीने के लिये पानी नहीं मिलता, खेती के लिये पानी नहीं मिलता और दूसरी तरफ पानी की ज्यादाती की वजह से ज़मीन मर रही है वहां पर पानी बहुत ज्यादा है। मैं सरकार को आप के द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि जब वह प्लानिंग करती है तो उस को चाहिए कि सारे प्रदेश को एक परिवार के रूप में देखें। जैसे एक पिता को देखना होता है कि उस के सारे बच्चों की हालत क्या है। वैसे ही हमारी सरकार को सब इलाकों की डिवैलपमेंट पर दृष्टि रखनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि परिवार में एक बच्चे के पास तो पैसा भी नहीं वह कोई व्यापार नहीं कर सकता, रोटी भी कमा कर नहीं खा सकता और दूसरे बच्चे के पास इतना रुपया है कि वह उस को व्यय करना नहीं जानता और फ़जूल धन को लुटा रहा है। उस को यह भी मालूम नहीं है कि धन का प्रयोग कैसे करना है। ठीक यही पोर्जीशन पंजाब सरकार के सामने है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर पानी मिलने का कुछ इन्तज़ाम नहीं है न लोगों के पीने के लिये और न ही खेती करने के लिये और इस के खिलाफ दूसरे इलाके हैं जहां पर पानी इतना ज्यादा है कि उस की ठीक तरह से यूटीलाइज़ेशन नहीं हो रही और वहां पर पानी की ज्यादाती के कारण उल्टा नुकसान हो रहा है। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है।

स्पीकर साहिब, इस के पश्चात् मैं हिल्ली एरियाज़ के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुझे अफ़सोस है कि हमारे प्रदेश के साथ लगने वाले हिमाचल प्रदेश के इलाके की डिवैलपमेंट को हमारी सरकार नहीं देखती। वहां पर हकूमत किस ढंग से काम कर रही है हमारी सरकार ने देखने की कोशिश नहीं की। वहां पर सरकार ने माइनर इरीगेशन के काम को डिवैलप करने के लिये और दूसरे ज़राए डिवैलप करने के लिये किस ढंग से काम किया है किस प्रकार उन्नति की है और उसके साथ लगने वाले हमारे पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार का काम हुआ है, अगर हम इस बात को देखें तो दोनों इलाके पहाड़ी होने के बावजूद भी ज़मीन आसमान का अन्तर है जब हम यह देखते हैं कि वहां पर बिजली की प्लानिंग किस प्रकार हुई है, माइनर इरीगेशन की प्लानिंग किस प्रकार से की गई है और हमारे प्रदेश में क्या काम हुआ है तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। वे बेचारे भीख मांग कर लाएं लेकिन फिर भी बिजली के मामले को देखें और माइनर इरीगेशन स्कीमज को देखें और उस के मुकाबिले में हम अपने ज़राए को देखें और अपनी

[श्री बलरामजी दास टंडन]

इंडिपेन्डेंट स्टेट को देखें तो हमारा शर्म से सिर झुक जाता है। यह तो बिजली का पहलू है। सड़कों के बारे में यह पोजीशन है कि मास्वाए रोहतक जिले के बाकी सब जिलों की हालत काबले रहम है। रोहतक में तो हो सकता है कि उस में सड़कों का स्टैंडर्ड इस लिये थोड़ा सा अच्छा हो कि मिनिस्टर साहिबान वहां के रहे हैं और उन्होंने ने वहां पर सड़कें बनवाने का प्रयत्न किया हो। लेकिन बाकी हरियाणा के जिलों में जाने का मुझे मौका मिला है, मैं कई बार महेन्द्रगढ़ के इलाके में गया हूं, मुझे हिसार के इलाके को देखने का अवसर मिला है, मैं गुड़गांव के कई इलाके देखे हैं, वहां पर बहुत से इम्पाटेंट इलाके भी पक्की सड़कों से मिले हुए नहीं हैं। यह शर्म का मकाम है कि हम इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे सके और ठीक एलोकेशन इस सम्बन्ध में नहीं कर सके। जिन स्टेप्स को लेने की आवश्यकता थी वे हम नहीं ले सके। प्लान बनते हैं तो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं उन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। बजट में सकीमें बन जाती हैं, प्लान बन जाते हैं। ब्यू प्रिंट में आते हैं लेकिन यहां तक उन को इम्प्लीमेंट करने का ताल्लुक है पता नहीं क्या कारण है कि अभी तक उन की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकी। अगर हम सड़कों के सम्बन्ध में अपनी स्टेट के हिल्ली एरियाज की हालत को देखें तो वहां की हालत इस से भी गई गुजरी है। वहां पर सिवाए एक सड़क के जो सैंटर से हो कर जाती और कुल्लू मनाली पहुंचती है और कोई पक्की सड़क नहीं है। कच्ची सड़कें बहुत ही नाकाफी हैं। पक्की सड़कें न होने के कारण वह इलाका चाहे शिमला है, चाहे कांगड़े का इलाका है और चाहे ऊना तहसील का इलाका है जिसे हम ने हिल्ली एरिया करार दिया है, बिल्कुल गई गुजरी हालत में है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस बात को देखे कि जितनी रकम ईयर मार्क होती है वह बजट के सफे बढ़ाने के लिये नहीं, कागज पर लिखे जाने के लिये नहीं होनी चाहिए, उस की इम्प्लीमेंटेशन मुनासिब ढंग से होनी चाहिए।

स्पीकर साहिब, जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है हम देखते हैं कि बड़े तम्गोदौ के बाद ले दे के एक मैडीकल कालिज वहां पर खुला है। (*Deputy Speaker in the Chair.*) उसकी प्राग्रैस क्या होती है, यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन अम्बाला से लेकर गुड़गांव तक सारे के सारे इलाके के अन्दर कोई भी इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। जो तीन इंजीनियरिंग कालेज हैं वह एक ही बैल्ट के अन्दर यानी चंडीगढ़, लुधियाना और पटियाला में हैं और मेरा ख्याल है कि यह तीनों कालेज कोई तीस चालीस मील के रेडियस के अन्दर अन्दर हैं। चाहिए तो यह था कि इन को फैला कर कायम किया जाता। इस प्रकार से प्लैनिंग करके ये कालेज खोलने चाहिए थे कि स्टूडेंट्स को छोटे से छोटा डिस्टेंस चलकर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलियत होती। लेकिन सरकार ने ऐसा किया है कि सिर्फ एक ही बैल्ट में उन को बना दिया है और इसका नतीजा यह है कि लोगों को दूर दूर से चलकर यहां पर आना पड़ेगा। शायद इतनी दूर दूर से बच्चे मुनासिब जरायों के बिना वहां पर पहुंच ही न सकें। चाहे वे बच्चे अच्छे नम्बर भी हासिल कर लें, और दाखिला भी प्राप्त कर लें लेकिन वह इसलिये वहां पढ़ाई करने में असफल रहेंगे क्योंकि उन के माता पिता की जेबें इस बात की इजाजत नहीं देती कि उन के बच्चे इतनी दूर से सफर करके आए और वहां पर जाएं। इसलिये सरकार को चाहिए था कि कम अज कम एक ऐसा कालेज वह वहां पर किसी सैंट्रल प्लेस पर खड़ा करती लेकिन वह भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं बल्कि वहां पर दूसरे कालेज भी खालने की कोशिश नहीं की। बड़े अफसोस की बात है कि जहां तक दूसरे

कालेजों का ताल्लुक है, उन की हालत ऐसी हुई है कि सारी ऊना तहसील के अन्दर, जो कि कितने ही मीलों के रकबे के अन्दर फैली हुई है, एक भी कालेज नहीं है। अगर सारे हिल एरिया को देखें तो शायद वहां पर सारे एक या दो कालेज होंगे और उन कालेजों में भी जो हालत है वह भी काबले ब्यान नहीं। इस तरफ तो एक एक जिले के अन्दर आठ आठ दस दस कालेज होंगे लेकिन उस तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिये... वह बच्चे जिन्होंने भविष्य में इस देश में और प्रदेश में एक बड़ा पार्ट प्ले करना है, जिन्होंने बड़े हो कर सरविस के अन्दर जाना है, जिन्होंने कल को इस देश की हकूमत अपने हाथों में लेनी है, जिन्होंने भविष्य को अपने हाथों में सम्भालना है... अफसोस के साथ कहना पड़ता है, डिप्टी स्पीकर साहिवा, कि इस बात की तरफ हमारी सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप परसैंटेज देखें कि इधर हमारे जालन्धर डिविजन के इलाके में स्कूलों और कालेजों की कितनी परसैंटेज है और उसके मुकाबिले हरियाणा के अन्दर कितनी है और हिली एरिया के अन्दर कितनी है, आज पर हंडरड कितने आदमी एजुकेशन ले रहे हैं, तो यकीनन एक बड़ा ही अफसोसनाक पहलू हमारी आंखों के सामने आएगा। आज हालत ऐसी है कि जिस को नतीजा के तौर पर आप सरविसिज के अन्दर देखें कि कितने हैडज आफ दी डिपार्टमेंट इन इलाकों के हैं, कितने सैक्रेटरीज टू दी गवर्नमेंट इन इलाकों में से हैं तो अफसोस से कहना पड़ता है कि हरियाणा और हिली एरियाज से आप को बहुत कम मिलेंगे और यह इसी वजह से है कि जो बैसिक चीजें उन के लिये चाहिए थीं, यानी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए था वह उन को मुहैया नहीं किया। जो जो साधन उन के लिये जुटाने चाहिए थे उन के लिये वह साधन सरकार ने मुहैया करने की कोशिश नहीं की और मैं नहीं समझता कि जब तक किसी इलाके के अन्दर एक जैसी ग़ोथ न हो तो उसके अन्दर डिसेसिटिफिकेशन पैदा न हो और क्यों न वह बोलने के लिये मजबूर हो जाएं। उनकी तरफ फौरी तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बड़ी अच्छी अच्छी और लच्छेदार तकरीरों से ही लोगों की तसल्ली नहीं हो सकती। जहां तक प्रैक्टिकल कदम उठाने का ताल्लुक है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस दिशा में एक भी कदम सरकार उठाने की तरफ ध्यान नहीं देती। मैं बड़ी मुअदबाना दरखास्त करूंगा कि सरकार को चाहिए कि पिछड़े हुए इलाकों को प्रगतिशील इलाकों के एंट पार लाने के लिये वह अपनी प्लैनिंग में तब्दीलियां करें।

इतना ही नहीं, दूसरे भी कुछ पहलू हैं। वह पहलू इन्डस्ट्री का पहलू है, जरायत का पहलू है और इसी तरह दूसरी जरूरतें हैं। सरकार को चाहिए कि इस सिलसिला में उस सारे इलाके का सर्वे कराए और देखे कि कहां पर क्या क्या कमी है और उस कमी को, उस जरूरत को पूरा किया जाए। इधर यहां पर भी फलडज आते रहे हैं। सरकार ने उसका प्रबन्ध किया। कोई ड्रेनेज का प्रबन्ध किया। किसी जगह पर बान्ध लगने की कोशिश की जिस से कि दरिया के साथ वाला इलाका जो कि इरोजन में आता था उसको रोका जाए। वह इलाका कुछ रिक्लेम हुआ और कुछ रिक्लेम हो रहा है। कुछ सड़कों को ऊंचा करना था, वह भी किया। कई एक जगहों पर आऊटलैट रखने थे वहां आऊट लैट भी रखे और उसका नतीजा और समटोटल जो निकलता है वह यह है कि इस इलाके के अन्दर आपको आज पलड्ड देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा के इलाके के पिछले आठ दस साल से, जब से हम इस असम्बली के अन्दर बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर साहिवा, कोई साल नहीं जाता जब कि करोड़ों रुपए की ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिर्फ इस कारण बरबाद न हो क्योंकि सरकार ने वहां

[श्री बलरामजी दस टंडन]

पर ऐन्टी फल्ट मैयर्ज के लिये मुनासिब प्रबन्ध नहीं किए हैं। उसके लिये सरकार को क्या पड़ता है? हर साल जो कर्जे दिए जाते हैं, उन को माफ करना पड़ता है। सरकार के इलाकों का रैविन्यू और आबयाना माफ करना पड़ता है। अगर पिछले आठ दस साल आदादोशुमार इक्ठ्ठे किए जाएं तो जितना रुपया इस तरह से सरकार को खर्च करना पड़ा, करना पड़ा अगर उसी सारे रुपए को मुनासिब वक्त पर ऐन्टी फल्ट मैयर्ज पर खर्च किया होता ऐसी स्थिति के पैदा होने की सम्भावना ही न होती।

**उपाध्यक्षा :** मैं हाउस को बताना चाहती हूँ कि आज सुबह यहाँ पर जो अनप्लैज़ैन्टनेस हुई थी, जैसा कि आप के सामने आया, वह सारा हिस्सा हाउस की प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाएगा। (I would like to tell the House that the portion of the proceedings relating to the unpleasantness caused in the House in the morning, of which the hon. Members are already aware will be expunged.)

**श्री मंगल सैन :** वह तो पहले ही तै हो चुका है। वह तो अब पुरानी बात हो गई है।

**उपाध्यक्षा :** मैं इसलिये दुबारा बताना चाहती थी कि ताकि इसमें किसी तरह की कोई गलतफहमी न रह जाए। जो कुछ हुआ वह कोई अच्छी बात नहीं हुई थी। (I wanted to repeat it to avoid any misunderstanding. It was not a good thing.)

**श्री मंगल सैन :** यू आर राईट, मैडम। (विघ्न)।

**श्री बलराम जी दास टंडन :** तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि लाजनीतौर पर इन बातों को रोकने के लिये सरकार को ऐन्टी फल्ट मैयर्ज लेने चाहिए, उसके लिये अगर सरकार लोन रेज करना पड़े तो लोन लिया जाए लेकिन हर साल जो करोड़ों रुपए की जरई पैदावार उस इलाके की जाया होती है वह जाया न हो और जो करोड़ों रुपए के तकावी कर्जे हर साल सरकार वहाँ पर ऐसी हालत में देती है वह भी न देने पड़ें। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यह शोभा की बात नहीं। यह कोई अच्छी गवर्नमेंट की निशानी नहीं कि कोई कदम न उठाया जाए और जो सूबे के एक हिस्से का हर साल इस कदर नुकसान होता है उसको न बचाया जाए। यह मुनासिब मालूम नहीं होता कि आठ दस साल से इसी तरह से हालात चलते रहें और हर साल लोग यह समझें कि हमारा किस हकूमत से वास्ता पड़ा है कि एक बार फल्ट आए, दूसरी बार फल्ट आए गर्जों कि बार बार फल्ट आए और अभी तक सरकार उन को रोकने के लिये मुनासिब इन्तजाम भी नहीं कर सकी। मैं समझता हूँ कि इस के ज्यादा कोई दूसरा अफसोसनाक पहलू हो नहीं सकता।

इस के अलावा सवाल ड्रौट का है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हर साल ड्रौट पड़ता है। कितने ही सालों से ऐसा होता आ रहा है। महेन्द्रगढ़ का इलाका है, जिला हिसार का कुछ इलाका है रोहतक के अन्दर झझर का इलाका है। ये इलाके ऐसे हैं जहाँ हर साल उन लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि सरकार ने इस दिशा में भी मुनासिब यत्न अभी तक नहीं किए। इस सम्बन्ध में भी मुझे यही कहना है कि जितनी मदद हर साल इस ड्रौट का मुकाबिला करने के लिये सरकार ने अब तक दी है अगर उसी रुपए

को लेकर सरकार ने कोई प्लैनिंग करके योजना बनाई होती, उस पर अमल किया होता तो आज हम को इस मुसीबत से हर साल दो चार न होना पड़ता। अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी दी होती, ट्यूबवैल्व दिए होते, माईनर इरीगेशन का काम किया होता तो शायद आज उन इलाकों में वैसे हालात न होते जैसे कि होते रहते हैं और आए साल होते रहते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से विचार करे, इस मुसीबत से निजात हासिल करने के लिये उपाय सोचे और सिर्फ सोचे ही नहीं बल्कि उन पर फौरी तौर पर अमल करे। बाकायदा तौर पर कोई प्लैनिंग होनी चाहिए। इस बात के लिये किसी अफसर को इन्चार्ज बनाया जाना चाहिए। काफी रुपया उस की डिस्पोजल पर देकर देखा जाए कि क्यों नहीं काम होता। इस तरह से ऐक्सपर्ट ओपीनियन ले और जो भी साधन हो सकते हैं सरकार को इस सम्बन्ध में अपनाने चाहिए। इस सिलसिले में जितने भी हमारे देश के अन्दर ऐक्सपर्ट्स हैं, जितने भी विद्वानों में ऐक्सपर्ट्स हैं उन से ऐक्सपर्ट ओपीनियन मिल सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इतना ही नहीं इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जिनको मैं आप के द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। आप जानती हैं कि महेन्द्रगढ़ के अन्दर मिनरलज है। वहां पर जिस तरह से हमारी हकूमत ने...

उपाध्यक्ष : मैं आप का ध्यान वक्त की तरफ दिलाना चाहती हूँ ताकि कहीं आप की जरूरी जरूरी बातें न रह जाएं। यह बड़ी मुबारक बात है कि आप हरियाणा और बैकवर्ड एरियाज की डिवैलपमेंट के बारे में कह रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा तीस मिनट तक बोल सकते हैं। 28 मिनट आप बोल चुके हैं। अब आप दो मिनटों में खत्म कीजिए। और दूसरों को भी इस विषय पर बोलने का मौका दीजिए।

(I would like to draw the attention of the hon. Member to the time at his disposal so that important points may not escape his mention. It is gratifying to note that he is discussing matters relating to the development of Haryana and backward areas. He can at the maximum speak for thirty minutes. He has already spoken for 28 minutes so he should wind up in two minutes and given an opportunity to others to speak on this subject.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं बस जी पांच मिनट में खत्म किए देता हूं। तो मैं कह रहा था कि इस हैड में वहां पर हर साल दस लाख रुपया मिलता था मगर कितने अफसोस की बात है कि आज 50 हजार रुपया मिल रहा है। मिनरलज से पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा है। जिन लोगों की इन के पास ऐपरोच है या जो इन के रिश्तेदार वगैरह हैं वह लीज पर लेकर फायदा उठाते हैं मगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। ज्यादा मिनरलज तो इस सूबे में है ही नहीं मगर जहां है भी उन को भी इग्नोर किया गया है।

यही नहीं जिला महेन्द्रगढ़ में 550 गांव और हैं और उन में से सिर्फ तीस में ही बिजली गई है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार का ध्यान कहां पर है। हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्र में तो यह हालत है कि बहुत सी जगहों पर पीने का पानी भी नहीं मिलता। जब यह हालत हो तो इस सरकार को अपनी सरकार कैसे कहा जा सकता है। हमारी मां

[श्री बलरामजी दास टंडन]

बहनों को सिरों पर घड़े उठा कर दस दस मील की दूरी से पानी उठा कर लाना पड़ता है। मगर यह लोग खामोश बैठे हैं। और सब से ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस बात की तरफ उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जो उन इलाकों के हैं और कभी न कभी इन गदियों पर विराजमान होते रहे हैं।

जहां तक इस कैबिनेट का ताल्लुक है मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के किस आदमी को कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया। यही वजह है कि जब यहां पर सवाल पूछा गया कि जो पंजाबी फौजी शहीद हुए हैं उन के घरों में कितने वजीर गए हैं तो पता चला कि जो वजीर जिस इलाके का है वह अपने ही इलाके के फौजी शहीदों से मिलने गया और कांगड़ा के शहीदों जो कि सब से ज्यादा हैं उन के बाल बच्चों को देखने कोई वजीर नहीं पहुंचा। यह अपनी जिम्मेदारी कितनी समझते हैं (विघ्न) हां आप कटोच जो कि जैनरल हैं के हां गए हैं मगर मैं तो शहीद जवानों की बात कर रहा हूँ। उन जवानों के घर इस मिनिस्टरी में से कोई नहीं गया। इन को उन से कोई हमदर्दी नहीं है क्योंकि उन का अपना कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं है। इस लिये कांगड़े के लिये भी मिनिस्टरी के अन्दर मुनासिब जगह होनी चाहिए।

**श्री जगन्नाथ :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। प्रस्ताव हरियाणा के बारे में है और बहस हो रही है कांगड़ा जिला पर। (विघ्न)

**श्री बलरामजी दास टंडन :** तो मेरी यह मोअदबाना गुज़ारिश है कि सारे इलाकों को बराबर का स्टेटस दिया जाना चाहिए। यह इलाका और हरियाणा का इलाका जब तक दूसरे इलाके के बराबर नहीं आ जाता तब तक बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा इन पर खर्च किया जाना चाहिए। प्लैनिंग इस तरीके से की जानी चाहिए। जब तक इन इलाकों को दूसरे इलाकों के बराबर नहीं खड़ा किया जाता तब तक वहां के लोगों के साथ इनसाफ नहीं होगा। इस नाइनसाफी को दूर करने की ओर सरकार पूरा पूरा ध्यान दे।

**Deputy Speaker :** Motion moved —

with a view to bring the hilly areas of the Punjab, which are backward, at par with the adjoining areas of the State and Haryana area at par with the rest of the State in the matter of development, this House recommends to the Government to make plan allocations in such a way that sixty percent of the plan funds are earmarked for the said Haryana area and the hilly areas.

मैं आप से दरखास्त करूँगा, कि मैम्बर साहिबान ज़रा समय का ध्यान रखें ताकि सब को बोलने का मौका मिल जाए। आप रूल 200 को पढ़ें तो आप देखेंगे कि अनलिमिटेड वक्त नहीं दिया जा सकता। मूवर आध घंटे तक बोल सकता है। ((विघ्न) अगर आप कहेंगे तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। जब मैं कोई बात कह रही हूँ तो आप को बीच में खड़े नहीं होना चाहिए। तो अच्छा यह होगा कि हम कोई टाइम लिमिट मुकरर कर लें। कोई बात पांच दस मिनट में भी कही जा सकती है और वही बात पचास मिनट में भी कही जा सकती है। हमारे पास एक घंटे से कुछ ही ज्यादा का समय और है तो यह बेहतर होगा अगर कोई टाइम लिमिट मुकरर कर दी जाए। (I would request the hon. Members to

be careful about the time so that all get an opportunity to speak. If they just refer to Rule No. 200, they will find that they cannot speak for an unlimited time. The mover can speak for half an hour. (*Interruption*). If they so desire, I can stand up. When I am making observations, the hon. Member should not interrupt unnecessarily. Anyhow, it would be better if we fix some time limit for speeches. One thing can be briefly stated in five or ten minutes and the same thing can be explained in fifty minutes. But the time at our disposal is hardly a little over one hour. So it would be proper if some time limit is fixed).

ਆਕਾਸ਼ : 15 ਮਿਨਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ।

ਤਸਾਹਬ : ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ । (This is good.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਕ I.C. S. ਅਫਸਰ ਬਰੇਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਦਿਹਾਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲਾਉ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜ ਇਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 1958 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਚ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤਕ ਚੁਪ ਕਰ ਗਏ। (ਵਿਘਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾ ਕਿਸੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੈਲਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਪਾਸ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸੀਟ ਕੈਬਿਨਿਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਸੀਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ; ਬਿਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਿਮਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਲਿੰਗਵਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਬੰਬਈ ਬਾਰੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਦ ਕੁਸ਼ਤੋਖੂਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਲੇ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਥੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਮਨਿਸਟਰ ਕਰ ਲਉ, ਇਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਹਰਿਆਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗਵਿਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਉ—ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਨਾ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੜਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਦ ਤਕ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 'ਫੈਕਟਸ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ, 1965'। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਟੈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਡ ਆਫਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਡੇ ਕਾਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫਿਗਰਜ਼ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ 18 ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ : ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 18 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਵਿਚੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 65 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ

ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਵਿਚ 85 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਤਖਮੀਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੀਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੀਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕੇਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵਾਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਿਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 60 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਬਜਟ ਲੈ ਲਉ ਜਾਂ 65 ਪਰਸੈਂਟ ਲੈ ਲਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ?

ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ 1957 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਛਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਪਰਸੈਂਟ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਨਾ ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਹਰਿਆਨਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਖਾਂ ਪੁੱਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (Interruption)। ਹਰਿਆਨਾ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਟਰੱਪਟ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਨੇਚੁਰਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ 18 ਜਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ [ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ] ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 60 ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਗਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਖਾਂ ਪੁੱਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰ ਪੰਜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨਰਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ

ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ।

**Deputy Minister Industries and Hill Areas (Shri Gian Chand):** On a Point of order, Madam. Are the Hindi and Punjabi areas foreign to each other ?

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ :** ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਹਰਿਆਨਾ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ । ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਕ ਲਾਭੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਜੇ ਹਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਵਾਏ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ । (ਹਾਸਾ) ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਨਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਠੋਸੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰੇ । ਇਹ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ । ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਉਸ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ । ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਅਪਣੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਇਕ ਪੈਸਾ' ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ (ਕੁਸ਼ਵਰ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਯਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਟੰਡਨ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁਆ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹ ਮਾਂਗ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਲ ਏਰਿਆਜ਼ ਆਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਉਨਕੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੀ ਇੰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾ 60 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਉਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰ ਖਰਚ ਕੀਆ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਇਸ ਕਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈ ਮਗਰ ਜੈਸੇ ਯਹਾ ਪਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਡਾਯਰੈਕਟਰੀ ਸਮੇਟੇਂ ਯਾ ਆਪ ਇਸਕੋ ਇਨਡਾਯਰੈਕਟਰੀ ਸਮੇਟੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋ ਅਪਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂਗ ਕੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਹੈ।

(At this stage the bells were rung for want of quorum).

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਹਿਲਲੀ ਏਰਿਆ ਕੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਲਿਏ ਚਾਰ ਹਿਸਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਂਟਦੀ ਹਾਂ। ਸਭਸੇ ਪਹਲੇ ਤੋ ਏਸੇ ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਕਮਾਨੇ ਕੇ ਸਾਧਨ ਦਿਏ ਜਾਏਂ ਜਿਨ ਕੋ ਏਸੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਉਨਕੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਨਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਸੇ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਜਹਾਂ ੨ ਪਰ ਸਭਕੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਉਨ ਇਲਾਕਾਂ ਕੋ ਸਭਕੇ ਦੀ ਜਾਏਂ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਉਨਕੇ ਲਿਏ ਇੰਕਵੈਸਟਿਸਟੀ ਕਾ ਭੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਏ।

ਇਸ ਕੇ ਬਾਦ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਲਿਏ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1962 ਮੈਂ ਏਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਨਾਯਾ ਥਾ ਆਰ ਉਸ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਲਲੀ ਏਰਿਆ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀ ਜਾਨੀ ਥੀ ਜਿਸ ਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਗ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਅਪਨੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਥੇ। ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕੋਟੀਂ ਆਰ ਪਰਮਿਟੀਂ ਕੀ ਮਾਂਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੋ ਯਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਿਲ ਏਰਿਆ ਕੇ ਬਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਾਰੀਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਜ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਉਨ ਕੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਂਗ ਥੀ ਕਿ ਹਮੇਂ ਬੂਲ ਯਾਰਨ ਕਾ ਕੋਟਾ ਦਿਯਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਹਮੇਂ ਜਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕਰ ਛੋਟ ਛੋਟੀ ਹੀਜ਼ਰੀ ਕਾ ਕਾਮ ਚਲਾ ਕਰ

[श्रीमती सरला देवी ]

अपनी रोटी कमा सकें । लेकिन हमारी पंजाब सरकार ने जवाब दिया कि जो टैक्सटाइल कमिशनर है वह नहीं मानता और कहता है कि 1962 से पहले जिन्होंने फैक्टरियां लगाई थीं उन को कोटा दिया जाता है । अब किसी किस्म का कोटा नई इन्डस्ट्री वालों को नहीं दिया जा सकता । इस लिए मैं कहती हूं कि जब तक किसी को रोटी नहीं दी जाती तब तक वह इकनॉमिकली कैसे तरक्की कर सकता है । इन्होंने सीमेंट फैक्टरी देने का वादा किया था हम आठ साल से सुनते आ रहे हैं कि समरोटी के इलाके में सीमेंट की फैक्टरी लग रही है मगर आज तक वहां पर कुछ भी नहीं किया गया । अब जब मैंने गवर्नर साहिब का एड्रेस पढ़ा तो उसमें कहीं झलक नहीं आई कि हिली एरिया की डिवैल्पमेंट के लिए पैसा रखा गया हो । इसी लिए हम जोर से आवाज उठाते हैं कि हमें हिमाचल के साथ जाने दो । हम पंजाब के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि जितने भी हमारे प्लैन बनते हैं वह चण्डीगढ़ से बनते हैं जिन का हमें कोई फायदा नहीं होता । सैंटर से पैसा आता है लेकिन यहां पर यह बिलकुल नहीं देखा जाता कि कांगड़ा जिले के अन्दर जो पानी की स्कीमें भेंजी जाए वह किस किस्म की होनी चाहिए । अगर यह हमें पानी देना चाहे तो दरिया से और खडों से पम्पिंग सैट लगाकर सकते हैं । लेकिन यह कहते हैं कि उन के ऊपर खर्चा बहुत आता है इस लिए वह सारी की सारी स्कीमें वहां की वहां धरी रह जाती है । चौधरी रिजक राम जी हमारे हमीरपुर में गए । वहां हमने उन का दौरा करवाया । हम ने उन से कहा कि जिला कांगड़ा ने जोगिन्दर नगर से बिजली दी भाखड़े से बिजली दी लेकिन कितने अफसोस की बात है कि बाहिर तो हम रोशनी देते हैं मगर हमारे घर में अन्धेरा है । उन्होंने हमें जवाब दिया कि यहां पर बिजली नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है । मैं पूछना चाहती हूं कि उन्होंने जो दूसरे देहातों में बिजली दी है क्या वहां पर कोई बड़ी बड़ी टैक्सटाइल मिलें चलती हैं । अगर हमें बिजली दे दी जाए तो हम खडों के अन्दर पम्पिंग सैट वगैरा लगा कर ऐग्रीकलचर को डिवैल्प कर सकते हैं और छोटी मोटी इन्डस्ट्रीज भी चालू कर सकते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा कुदरत ने वहां पर एक जंगलात की बड़ी भारी नेहमत दी हुई है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वह नेहमत छीन कर इस दायरे में बन्द कर दी गई है कि उन के प्राफिट का हिस्सा हमें नहीं मिलता । हमारी मांग बड़ी देर से चली आती है कि फौरैस्ट से जो 3-4 करोड़ का सालाना प्राफिट होता है उस में से हमें हिस्सा मिलना चाहिए ताकि हमारी डिवैल्पमेंट हो । हम ने कहा था कि वहां पर गन्दे बरोजे की फैक्टरी लगाई जाए लेकिन यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहिबा हमीरपुर से एक सड़क निकलती है उस सड़क के एक तरफ हिमाचल के घर है और दूसरी तरफ हमारे कांगड़े के । हिमाचल के घर में बिजली लगी हुई है और पानी के टैप लगे हैं लेकिन हमारे गांव में बिजली और पानी दोनों ही नहीं हैं । इसी तरह शिमला हिल्ज में शिमला को छोड़ कर बाकी सारे इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा । मैं सड़कों की मिसाल देती हूं । हमारे इलाके में ऊना-जाहू-हमीरपुर तक सड़क बनाने के लिए पहली पंच वर्षीय योजना में

प्रोवियन किया था मगर आजतीसरी पंच वर्षीय योजना खत्म हो रही है और वह सड़क वहां पर नहीं बन सकी । फिर नौकरियों को ले लीजिए इन में भी हमें कोई रियायत नहीं मिलती । इसी तरह जब इन्जिनियरिंग कालेजों और मैडीकल कालेजों में ऐडमिशनज होती हैं तो कहते हैं कि वहां हम मार्कस के हिसाब से लड़के दाखल करेंगे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, लड़ाई शुरू हुई और अब खत्म भी हो गई है मगर आज तक इस सरकार ने वहां एक पीपा भी मिट्टी के तेल का नहीं पहुंचाया । हमारे बच्चे 10/10 मील के फासले से पैदल पढ़ कर आते हैं और उन को रात को पढ़ने के लिए एक बोतल मिट्टी के तेल की नहीं मिलती । अब आप सोच सकते हैं कि वह बच्चे जिन्हें पढ़ने के लिए कोई सहुलत न मिले वह इंजीनियरिंग कालेजों में और मैडीकल कालेजों में कैसे कम्पीट कर सकते हैं । मैंने परसों चौधरी रणबीर सिंह जी से रीक्वैस्ट की थी कि वह जो सड़क पहली पंच वर्षीय योजना की अभी तक नहीं बनी उसे बनवाने के लिए आप वहां के चीफ इनजीनियर, एस. ई. या ऐक्स इ. ऐन. की मीटिंग रखें ताकि वह देख सकें कि वह सड़क कितनी तेजी से बननी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारे इलाके के अफसर क्योंकि सर्विस में नहीं हैं इस लिए उन का वहां क्या इन्ट्रैस्ट हो सकता है । फिर मैं हिल आलाऊंस की बात करती हूं । शिमला में जो अफसर हैं उन को 30 प्रतिशत हिल एलाऊंस दिया जाता है लेकिन कांगड़ा में इतनी मंहगाई के बावजूद भी वहां पर जो आफिशल्ज हैं उन्हें कम एलाऊंस मिलता है । मैं निवेदन करूंगी कि उन्हें भी 30 प्रतिशत के हिसाब से एलाऊंस दिया जाना चाहिए ताकि उन को वहां जा कर काम करने का कुछ इनसैनटिव हो । डिप्टी स्पीकर साहिबा मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि हमारे वहां बिल्कुल डिवलपमेंट नहीं हो रही । बिजली वाले मिनिस्टर ने तो साफ जवाब ही दे दिया है । इस लिए हमें शायद धरना मार कर ही बैठना पड़े । मैं यह खुले शब्दों में बता देना चाहती हूं कि अगर हमारी यही हालत ग्बनी है तो हमें हिमाचल के साथ जाने दो हम वहां चाहे भूखे रहें चाहे नंगे रहें हम वहां अपने पहाड़ी लोगों के साथ रह कर जैसे भी होगा अपना गुजारा करेंगे ।

श्री जगन्नाथ (तोशम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा पहले दो मੈम्बर साहिबान बोलें हैं । एक टंडन जी दूसरे जसटिस गुरनाम सिंह जी । अगर असलियत को देखा जाए तो उन दोनों को ही हरियाणा से कोई हमदर्दी नहीं है । बल्कि वह अपने सैल्फ इन्ट्रैस्ट की वजह से हरियाणा की सपोर्ट कर रहे थे । मैं पिछले पांच साल से देख रहा हूं कि हम ने कई दफा हरियाणा के लिए आवाज उठाई, वाक आउट किए लेकिन इन्होंने कभी हमारे साथ मिल कर आवाज नहीं उठाई और न कभी वाक आउट किया । आज ही इनके दिल में हरियाणा के लिए दर्द उठा है जो कहते हैं कि वहां की डिवलपमेंट होनी चाहिए । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनके दिल में हरियाणा के लिए कोई दर्द नहीं यहां तो इनका सैल्फ इन्ट्रैस्ट है इस लिए अब ऐसा कहते हैं क्योंकि यह जानते हैं कि अगर उन्होंने ने हरियाणा की डिवलपमेंट की बात

[श्री जगन्नाथ]

अब न की तो एक तरफ पंजाबी सूबा मांग रहे हैं दूसरे तरफ यह हरियाणा प्रांत बना लेंगे और यह बीच में रगड़े जाएंगे । वरना अगर यह बात न होती तो पहले से ही यह हमें स्पॉट करते और हमारी डिवलपमेंट के लिए हमारे साथ मिल कर आवाज उठाते । जस्टिस साहिब ने देशी विदेशी की बात कही । मैं आप को बताना चाहता हूं कि बाईबल में लिखा है :

“It is better to rule in hell than to serve in heaven”.

हमारी वही हालत है । चीफ मिनिस्टर जब कोई बने तो इस रिजन का, स्पीकर, चेयरमैन इनके रिजन का सैक्रेटेरियट में चले जाओ तो सारे अफसर सैक्रेटरी इनके रिजन के, हाई कोर्ट के जज इनके । सबारडीनेट सर्विसिज सीलैशन बोर्ड, पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर इनके रिजन के और हर सहूलियत इनके रिजन को ही मिलती है हरियाणा को देते क्या हो और इसमें देशी विदेशी की बात क्या है । टंडन साहिब को आज हरियाणा की डिवलपमेंट का ख़ाब आया है पहल कभी इन्हें यह दर्द नहीं उठा । कभी इन्होंने यह नहीं कहा कि अमृतसर में 90 फीसदी एरिया इरीगेटेड है लेकिन हरियाणा में क्यों 15 फीसदी है और अमृतसर में 75 फीसदी गांव में बिजली है लेकिन हरियाणा में पांच सात फीसदी गांव में भी नहीं होगी इसकी क्या वजह है और वहां की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते । यह तो अब इस लिए कहते हैं क्योंकि इसमें इन का सैल्फ इन्ट्रेस्ट है । मैं हर सेशन में देखता हूं कि मैम्बर साहिबान यहां फिगरज देते रहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि फिगरज देने से कुछ नहीं बनेगा जब तक आपके हाथ में डंडा नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं देंगे । डिप्टी स्पीकर साहिब, आपने भी रोहतक से इलैक्शन लड़ा और फिर जगाधरी से भी इलैक्शन लड़ा और आपने देखा कि वहां के अलाकों की क्या हालत है लेकिन आपने भी कभी हरियाणा के लिए आवाज नहीं उठाई । मैं तो कहता हूं कि यह लोग अब हरियाणा के लिए आवाज नहीं उठाते हैं सिर्फ अपने सैल्फ इन्ट्रेस्ट के लिए आवाज उठाते हैं । इस लिए मैं अर्ज करता हूं कि हम हरियाणा की डिवलपमेंट की फोकी बातें नहीं सुनना चाहते बल्कि इन्साफ चाहते हैं । हम हरियाणा डिवलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट नहीं चाहते बल्कि हम अपनी डिवलपमेंट खुद अपने हाथों से करना चाहते हैं चाहे हमारी डिवलपमेंट करने वाला वह आदमी चौधरी रिज्जक राम क रूप में आ जाए, चाहे रणबीर सिंह के रूप में आ जाए । जब तक यह पंजाबी के रिजन के लोग हमारे ऊपर बैठे रहेंगे हमारी कभी डिवलपमेंट नहीं हो सकेगी । यह तो हमारे ऊपर बुरी तरह छार हुआ है । खिलाड़ियों की ही बात देख लो । एशिया के अन्दर अगर हमारा लड़का गोल्ड मੈडल लेता है तो उसे सिपाही भरती करते हैं लेकिन इनका अनपढ़ आदमी भी डायरेक्टर बना दिया जाता है । आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमारी हरियाणा प्रान्त की मांग चल रही है और उनकी पंजाबी सूबा की चल रही है । उनकी चले या न चले लेकिन हरियाणा की मांग जरूर चलेगी । एक दिन हम लेकर रहेंगे चाहे हमें उसके लिए खून देना पड़े ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : इस सदन में प्रस्ताव आया है कि हरियाणा और पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए बजट का 60 फीसदी रुपया सुरक्षित रख कर वहां पर खर्च होना चाहिए । मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं ने जज साहिब, बहिन सरला देवी और श्री जगन्नाथ के विचारों को बड़े गौर से सुना है । कहा गया है कि इस ग्रुप के लोगों को हरियाणा की बात अब याद आई है । श्री जगन्नाथ जी अभी नए इस हाउस में आए हैं और इनको पता नहीं होगा कि 1958 में जब वह इस हाउस के मੈम्बर नहीं बने थे हमारे ग्रुप के ही एक आदमी श्री लाल चन्द सभरवाल ने जो आज के मुख्य मन्त्री को हरा कर आए थे बजट पर बोलते हुए कहा था कि बजट का 60 फीसदी रुपया हरियाणा की डिवैल्पमेंट के लिए खर्च होना चाहिए । इस बात की गवाही इस हाउस का रिकार्ड है और भाई जगन्नाथ जी उसे पढ़ लें । हम यही बात बार बार रीपीट करते आए हैं । जज साहिब ने बड़ी वकालत की कि इनका हाई कोर्ट में जज नहीं है एडवोकेट-जनरल नहीं है, सैक्रेटरीज नहीं हैं यह वही है वह नहीं है मन्त्रिमंडल में 80 लाख की आबादी के आधे पौने पड़े मिल कर कुल 6 वजीर हैं और यह भी कहा कि सिवाए ताकत के कोई बात नहीं हो सकती । मैं कहता हूं कि वह खुल कर सामने क्यों नहीं आते और साफ क्यों नहीं कहते कि सैल्फ डिटरमिनेशन चाहते हैं जैसा कि उन्होंने पहले लुधियाना में कहा था । मैं कहता हूं कि ऐसा कहना इललीगल है और भारत के विधान के मुताबिक ऐसा करने का किसी को भी अधिकार नहीं है कि हम हक खुद मुस्तारी चाहते हैं । यह बात इस लिए कही जा रही है क्योंकि यह मन्त्रिमंडल कमजोर और बुजदिलों का टोला है और इसी लिए यह पंजाब की फजा खराब हो रही है वरना किस की मजाल है कि भारत के विधान के खिलाफ जा कर ऐसी बात करे । मैं कहता हूं कि यह आग से खेलने वाली बात है । भाई जगन्नाथ जी तो उस वक्त स्कूल कालिज में ही होंगे जब हम पर पंजाबी ठोसी जाने लगी थी और जिसका चर्चा यह फिर करने लगे हैं और हम ने ही उस वक्त आवाज उठाई थी कि हम पंजाबी नहीं पढ़ना चाहते तो हम पर लाठियां बरसाई गईं, हम जेलों में गए और 6 महीने के अन्दर आठ जेलों का चक्कर लगाया था । आज फिर हम कह देना चाहते हैं कि यह जो लाबिडिंग चलती है और हाई कमांड या लो कमांड की बातें हो रही हैं यह हम नहीं होने देंगे । अगर एक आदमी के जल मरने की धमकी से पंजाब की सरकार और केन्द्र की सरकार का पसीना निकल सकता है तो हम भी वही हालात पैदा कर सकते हैं और पैदा करेंगे । यह जो यूनीलिगवल सूबे की बातें हो रही हैं हम इस चीज को आप कान खोल कर सुन लें हर्गिज बरदाशत नहीं करेंगे । जहां तक हमारी डिवैल्पमेंट की बात है मुझे दुख है कि हरियाणा से इलैक्ट हो कर आने वाले हरियाणा की डिवैल्पमेंट करने की बजाए पहले सच्चर साहिब का बिस्तर उठाते फिर और फिर कैरों साहिब के आगे पीछे फिरते रहे । एक ने तो साम्पला में यहां तक कह दिया कि मुझे तो आपकी शकल में अपने चाचा जी की तसवीर नज़र आ रही है । हरियाणा की नुमाइंदगी करने वालों ने इस सदन में अवाम की नुमाइंदगी करने की बजाए अपने परिवारों कुन्बों की नुमाइंदगी की, वरना क्या वजह है कि 18 साल के अर्सा में पानी बिजली भी हरियाणा को न दे सके । वक्त आने दो हम सब देख लेंगे । यह बाजू हमारे आजमाए हुए हैं । हम पर यह यूनीलिगवल ठोस कर देखो तो सही फिर देखना कौन आगे आने वाला है । उस वक्त हम ही आगे आएंगे और यह दूध पीने वाले

[श्री मंगल सेन]

मजनुं अन्दर बस जाएंगे। जब हम पंजाबी के खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे तो हमारी पीठ पर छुरे मारे जा रहे थे और अब वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। वक्त पर नज़र नहीं आएंगे। हमारा यह शुरू से कनक्वशन है कि पंजाब दो भाषाई प्रदेश है और इसमें दोनों भाषाएं बोली समझी जाती हैं। हम यह बात इनकी तरह बोट लेने के लिए और दोबारा चुन कर आने के लिए कह कर जनता को धोखा नहीं देना चाहते और.....

**Planning and Local Government Minister (Sardar Ajmer Singh) :** Madam, the discussion is going beyond the track,. In fact, this is purely a question of planning and spending the amount on various regions. I request you and, through you, to the hon. Members as well that they should not indulge in such like things. They should confine themselves to the scope of the resolution. The political issue will be decided outside. Why to say these things here ?

आवाजें : हाउस में कोरम नहीं है।

**उपाध्यक्ष :** अब अगर इसके बाद कोरम न हुआ तो मैं हाउस एडजर्न कर दूंगी वार बार घंटो नहीं बजाऊंगी। (If after sounding the bells the House fails to be in quorum I will adjourn it. I will not allow ringing the bells again and again.)

( *Quorum bells were sounded till the House was in quorum.* )

**श्री मंगल सैन :** मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि मैंने जो कुछ कहा वह इस रैजोल्यूशन के स्कोप से बाहिर है। यहां पर कुछ ऐसी बातें कही गई जिस से मैंने भी यह बात कही है। अन्यथा मैं समझता हूं कि यह बात इस रैजोल्यूशन के स्कोप के बाहिर है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है इस बारे में किसी की दो राएं नहीं हो सकती हैं। हमारी नेक चाहिश है कि वहां की बैकवर्डनेस को दूर किया जाए। जब कामरेड राम किशन हमारे मुख्य मन्त्री बने थे तो उस वक्त इन्होंने भाषण दिया था कि हम हरियाणा प्रान्त पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे और वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज स्थापित की जाएंग। वैसे तो इन का काम तो लम्बे लम्बे भाषण देना होता है और उस पर अमल कम ही करते हैं। इन्होंने कहा था कि दिल्ली के आस पास एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाई जाएगी। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और रोहतक के आस पास तथा सोनीपत में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। वहां पर 40 करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। लेकिन अगर यह बातें कहने तक ही रहें तो उस से जनता को कोई फायदा नहीं हो सकता है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ताकि वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, 1957 से आज तक कहते ही आ रहे हैं कि सरदार प्रताप सिंह कैरों कुरण्ट चीफ मिनिस्टर थे। हम तो सदाकत कहते आ रहे हैं लेकिन उस के चले या पैरोकार अब भी कहते हैं कि वह नेक इन्सान थे जबकि उन्हें दास कमीशन ने भी दोषी ठहराया था। अगर उस के पैरोपकार दिन को रात कहें तो यही समझा जा सकता है कि उन

की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है । मेरे कहने का मतलब यह है कि वह भी और हमारे मुख्य मन्त्री भी झूठे वायदे लोगों के साथ करते हैं । हमारी तो यही प्रार्थना है कि हरियाणा के इलाके में इंडस्ट्रीज स्थापित की जाएं ताकि वहां के लोगों की हालत सुधर सके । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि उन के पास काश्त करने के लिए इतनी जमीन नहीं है जिसके ऊपर वह गुजारा कर सकें । इस लिए उन की हालत को सुधारने के लिए वहां पर इंडस्ट्रीज स्थापित की जाएं । पहले तो कहा जाता है कि हम हरियाणा प्रान्त में इंडस्ट्रीज स्थापित करेंगे लेकिन जब इंडस्ट्रीज लगाने का मौका आता है तो इंडस्ट्रीज लुधियाना, जालन्धर या बटाला में लगाई जाती है । अगर सरकार ने यही पालिसी इख्तियार किये रखी तो हरियाणा के लोगों की हालत सुधर नहीं सकती । इस लिए सरकार को इस विषय में कानून बदलने चाहिए ताकि वहां के लोग इंडस्ट्रीज सैट अप कर सकें । हमारी सरकार की पालिसी यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पंजाब में इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए कहती है और वह उद्योगपति फरीदाबाद, बल्लभगढ़ या सोनीपत आदि शहरों में अपनी फैक्टरियां लगाते हैं और दिल्ली में बैठ बैठे मौज उड़ाते हैं । इस के अलावा हमारे सूबे के मन्त्री उनके पास जाते हैं और उनको वहां पर थैलियां भेंट की जाती हैं और यह लेकर आ जाते हैं । इन हालात में हरियाणा के लोगों को खुद इंडस्ट्रीज लगाने में कैसे प्रोत्साहन मिल सकता है । इस लिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि वहां के लोगों की हालत में सुधार हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं अब बिजली के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । अमृतसर जिले में जितनी बिजली दी गई है उतनी बिजली सारे हरियाणा के इलाके को दी गई है । इस से भली भान्ति अन्दाजा लगाया जा सकता है कि यह सरकार उन की बेहतरी के लिए क्या कुछ करना चाहती है और क्या कुछ कर रही है । हाउस में हरियाणा प्रान्त को एम. एल. एज. और कैबिनेट में मिनिस्टरज रीप्रीजेंट करते हैं और कर रहे हैं लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने भी इस इलाके की हालत को सुधारने के लिए कोई आवाज बुलन्द नहीं की । मुझे एक बात याद आ गई । 1958-62 तक हिसार जिले के एक एम. एल. ए. मन्त्री पद पर विराजमान रहे । वह पी. डब्ल्यू. डी. के मिनिस्टर थे । उन के समय में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोलने की स्कीम बनी । हम उस वक्त कहा करते थे कि यह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में खोलनी चाहिए क्योंकि वहां पर काफी जमीन है और वहां पर दफतर बनाया जा सकता है । वहां पर बहुत बड़ी फार्म है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । हमारे जोर देने के बावजूद यह यूनिवर्सिटी लुधियाना में खोली गई । मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर अभी तक चन्डीगढ़ में काम कर रहे हैं । इस का कारण यह है कि उन को लुधियाना का मौसम सूट नहीं करता । वहां पर उस के लिए एयर कंडीशन्ड कोठी तैयार नहीं हो सकी । इस लिए वह वहां पर नहीं गए । मैं अर्ज कर रहा था कि उस वक्त हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार में खोलने के लिए प्रयत्न करते रहे लेकिन बाद में वह प्रोपोजल टर्न डाउन हो गई थी । वह हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति इस समय हमारे साथ हां में हां नहीं मिलाता

[श्रीमंगल सेन]

था और वह भी इसी पक्ष में था कि वह यूनिवर्सिटी लुधियाना में खोली जाए लेकिन अब वही व्यक्ति एक अलैहदा सूबा बनाने के हक में है ।

उपाध्यक्ष महोदया, श्री जगन्नाथ को कुछ कंप्यूजन हो गई है लेकिन मैं हरियाणा इलाके की हालत के बारे में वर्णन करना चाहता हूं । श्री जगन्नाथ की कांस्टीच्युएंसी में कहत की हालत है । इस के इलावा हिसार जिले की भिवानी तहसील, रोहतक जिले की झरर तहसील और महेंद्रगढ़ जिले के अन्दर कहत पड़ा हुआ है । वहां पर पशुओं को तो दरकिनार वहां के लोगों को भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है । वहां के लोग पशुओं को पानी की किलत के कारण छोड़ते जा रहे हैं । पहले यहां पर डाक्टर गोपी चन्द भार्गव चीफ मिनिस्टर रहे और अब वह खादो बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं । उसके बाद श्री भीम सेन सचचर चीफ मिनिस्टर रहे और बाद में उन्हें लंका का हाई कमिशनर नियुक्त कर दिया है । तीसरे यहां पर स्वर्भीय सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर बने । उन्हें दास कमीशन ने दोषी ठहरा दिया और बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा लेकिन कुछ ही महीनों के बाद नालायक सुच्चा सिंह ने उन को मार दिया । इतने 18 साल के अर्से में हमारी कांग्रेस सरकार इस इलाके को पीने का पानी मुहैया न कर सकी । जब वहां की ऐसी हालत है तो वहां के लोग इन से बागी क्यों न हों । उपाध्यक्ष महोदया, मैं चौधरी रिजक राम का बहुत मान करता हूं । मेरे दिल में उन के लिए बहुत इज्जत है । उन्होंने हाउस में कहा था कि लोगों को ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कुनैक्शन जल्दी दिया करेंगे । वह कहते थे कि ट्यूबवैल्ज लोग लगाएं और उसके बाद ही बिजली के कुनैक्शन देंगे । लेकिन मुझे पता नहीं चला कि उन्हें बिजली कहां से मिलेगी जबकि वहां पर खम्बे नहीं लगाए गए । उन को मालूम ही है कि लोगों की हजारों की संख्या में दरबास्त ट्यूबवैल्ज के लिए, बिजली के कुनैक्शन के लिए बिजली के महकमें में पड़ी हुई हैं । वज्जोर साहिब का इस बारे में कई बार ध्यान दिलाया लेकिन वह अभी तक टस से मस नहीं हुए और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । लोगों की एड़ियां इस काम के लिए सफर करते घिस गई हैं लेकिन उन की तकलीफ को दूर नहीं किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष, महोदया, मैं एजुकेशन के बारे में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं । माननीय सदस्य श्री बलरामजी दास टंडन ने कहा कि हरियाणा प्रांत में एक मैडीकल कालिज खोला हुआ है । वहां पर जिस तरह से एक दूसरे के प्रति खींचा तानी हो रही है । वह हमारे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को भी मालूम है । इस के इलावा इस क्षेत्र में एक लूली लंगड़ी यूनिवर्सिटी खोली गई जिसका नाम कुशक्षेत्र यूनिवर्सिटी है ।

\*

\*

\*

\*

**मुख्य मन्त्री :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । आज हाउस में नान आफिशियल रैजोल्यूशन पर बहस हो रही है । इस रैजोल्यूशन का यूनिवर्सिटी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । गवर्नर साहिब यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं । इसलिए बहस में उन का नाम नहीं लाना चाहिए ।

**उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य हरियाणा की दिक्कतों के बारे में बयान करें । वह गवर्नर साहिब को डिस्कशन में न लाएं । आप वाइंड अप कीजिए । (The hon. Member should state the difficulties of Haryana and refrain from bringing the Governor into the discussion. He should wind up now.)

**श्री जगन्नाथ :** ग्रान ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। उपाध्यक्ष महोदया, यूनिवर्सिटीज के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है और वहां पर चांसलर का नाम और वाईस-चांसलर का नाम लिया जाता है। इसलिए यहां पर उन का नाम लेने से क्या हर्ज है ?

**योजना तथा स्थानिय शासन मंत्री :** जो कुछ माननीय सदस्य ने गवर्नर साहिब के बारे में कहा है, वह एक्सपंज कर दिया जाए।

**उपाध्यक्ष :** हां जी। ठीक है। वह एक्सपंज किया जाता है। वाइंड अप प्लीज।  
(Yes. That is expunged. The hon. Member may please wind up.)

**श्री मंगल सेन :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बड़े जिम्मेदार आदमी इंटरफीयरेंस कर रहे हैं। उस वाईस चांसलर को डिस्क्रेज कर रहे हैं ताकि वह काम सुचारू रूप से न कर सके। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदया, यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि चंडीगढ़ पर काफी खर्च हुआ और उस का लाभ हमें नहीं मिलेगा। इस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि हम भी उस का लाभ उठाएंगे। हम इस लाभ से कभी महरूम नहीं रहेंगे (घंटी) इसी तरह से पंजाब के किसानों ने भाखड़ा डैम को तैयार करने के लिए करोड़ों रुपए दिए और उस के हिसाब से हमारे हरियाणा के इलाके वाले लोग भी फायदा उठाएंगे क्योंकि इन्होंने भी इस काम के लिए रुपए टैक्स के रूप में दिए।

मेरे कहने का मतलब यह है कि पानी, बिजली, सड़कों, अस्पताल, तालीम और डिवेलपमेंट के सारे कामों में हमें पूरा हिस्सा मिलना चाहिये। जब तक हमारा इलाका डिवेलप नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। आनरेबल प्लानिंग मिनिस्टर साहिब बैठे हैं मैं आशा करता हूं कि हमारी जायज डीमांड को अवश्य मानेंगे ? इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

**कामरेड राम प्यारा (करनाल) :** डिप्टी स्पीकर साहिब, यह रेंजोल्यूशन हरियाणा की डिवेलपमेंट के लिये पंजाबी रिजन के मंबर की तरफ से आया है बड़ी अच्छी बात है। जहां तक किसी इलाके की डिवेलपमेंट का ताल्लुक है वहां एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, रोड्स, एजुकेशन, सैनीटेशन, सर्विसिज के साथ दूसरी सारी बातों को मद्देनजर रखा जाए तो तभी डिवेलपमेंट हो सकती है। जब तक इन चीजों की तकसीम गैरमुनसिफाना होती है मायूसी और फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है। अगर यहां पर हरियाणा के मंबरो ने मायूसी का इजहार किया, फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया या हिल्ली एरियाज के किसी मंबर ने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया तो हमें यह समझना चाहिये कि मुनसिफाना तकसीम नहीं की गई तभी यह बात कही गई है।

अगली बात यह है कि सरदार गुरनाम सिंह ने श्री बलरामजी दास टंडन को क्रिटीसाईज किया और श्री बलरामजी दास टंडन ने सरदार गुरनाम सिंह को क्रिटीसाईज किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने अपने मकसद को सामने रखते हुए ऐसा किया। जहां तक हकीकत का सवाल

[कामरेड राम प्यारा]

है, किसी इलाके को ऊपर उठाने का सवाल है, जहां तक किसी इलाके को डिवैलप करने का सवाल है हम उस हकीकत को भूल जाते हैं। हम ने अपने स्यासी अग्राज की खातिर कई दफा रैजोल्यूशन लाए हैं, कई दफा इस के खिलाफ बोले हैं। कई दफा हक में बोले हैं। अगर हकीकत को सामने रखें तो सोचना पड़ेगा कि हरियाणा की डिवैलपमेंट किस तरह से की जाए। जहां तक सरदार गुरनाम सिंह ने कहा कि डिवैलपमेंट स्यासी ताकत के बिना नहीं हो सकती, मैं उन से इत्फाक रखता हूं कि स्यासी ताकत के बगैर डिवैलपमेंट नहीं हो सकती। अगर हम यह समझें कि पंजाबी रिजन ने जो तरक्की की है वह स्यासी ताकत की बिना पर की है और गौर से देखा जाए तो स्टेट में अमृतसर और जालन्धर के जिले हकूमत करते हैं और होशियारपुर और फिरोजपुर वाले रोज यहां पर चीखते रहते हैं। अगर हिन्दी रिजन को देखा जाए तो मैं यह कहता हूं कि पंजाबी रिजन वालों का हिन्दी रिजन कालोनी है और हिन्दी रिजन में से भी रोहतक और गुड़गांव उस की कालोनी बन जाता है। हिन्दी रिजन को जो कुछ भी मिलता है वह सब रोहतक वाले ले जाते हैं और दूसरों को बहुत कम मिलता है। इस से यह बात साफ जाहिर है कि पंजाबी रिजन के मुकाबले में अगर स्यासी ताकत ले ली जाए तो सारा हिन्दी रिजन डिवैलप हो जाएगा या स्यासी ताकत की बिना पर सारा पंजाबी रिजन डिवैलप हुआ है यह ठीक नहीं है। यह तो डीपेंड करता है इस बात पर कि किसी इलाके में कितनी अवेकनिंग है, कितनी जागृति है कितना पोलीटीकल प्रेशर है और मुकाबिले में जस्टीफिकेशन के लिये हम कितना लड़ सकते हैं और पोलीटीकल प्रेशर को कितना रीजिस्ट कर सकते हैं। रीजेंट करने की जरूरत पड़े, एजीटेशन करने की जरूरत पड़े तो वह भी कितनी कर सकते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक हरियाणा के अनडिवैलप होने का ताल्लुक है श्री जगन्नाथ जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ, सर्विसिज के बारे में सैक्रेटेरियट में हाई कोर्ट में, और दूसरे तमाम ओहदों के बारे में जिक्र किया है। वे बिल्कुल जस्टीफाईड हैं, उन की ताईद करने की जरूरत है, ताईद ही नहीं बल्कि बड़े जोर से कहने की जरूरत है। क्योंकि पंजाबी रिजन वालों के पास कुछ ताकत थी उस के कारण उन्होंने जगह जगह पर नाजायज फायदा उठाया। मिसाल के तौर पर अमृतसर और गुरदासपुर से बहुत से आदमी ले जाकर करनाल में बैठा दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या करनाल के गरीब आदमी को जमीन नहीं चाहिये, क्या वहां पर लैंडलैस नहीं बसते, क्या वहां पर इजैक्टिड मुजारे नहीं हैं? लेकिन गुरदासपुर और अमृतसर वालों के पास जोर था उन्होंने जोर डाल कर फायदा उठा लिया। जब अमृतसर और गुरदासपुर के इजला में फलड्ज आए तो दोनों इजला के स्कूलों के बच्चों की फीस माफ कर दी गई। लेकिन रोहतक और करनाल में जब फलड्ज आए तो मैम्बर साहिबान इस हाउस में चीखते रहे लेकिन वहां के बच्चों की फीस नहीं माफ की गई। दोनों इलाकों में फलड्ज आते हैं लेकिन एक इलाके में तो फीस माफ की जाती है और दूसरे में नहीं की जाती। आज यहां पर बलरामजी दास टंडन बोलते हैं, सरदार गुरनाम सिंह बोलते हैं लेकिन मुझे याद है कि सरदार प्रताप सिंह के वक्त में किसी को खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जब भी यह उठते थे तो वह कहता था कि सरदार गुरनाम सिंह मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो यह चुप हो जाते थे। श्री बलरामजी दास को भबकी देता था तो वह चुप

हो जाते थे। मैं ने यहां पर आपोजीशन वालों पर इल्जाम लगाया था कि वह छाती पर हाथ रख कर कह दें कि क्या रात के बारह बजे जा कर वे अपना काम नहीं करवाते तो बहुत सारों को ऐसा कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। हम बोलते बहुत हैं लेकिन पोलिटीकल अग्राज के लिये। मैं कहता हूं कि पोलिटीकल अग्राज को छोड़ो और जस्टी-फिकेशन के पीछे पड़ो। अगर पंजाबी रिजन की मांग जायज है तो उस की ताईद करनी चाहिये और अगर हिन्दी रिजन वालों की मांग जायज है तो उस की ताईद करनी चाहिये। अगर बजट में तीस करोड़ पंजाबी रिजन वालों के लिये रखा जाता है और तीस करोड़ ही हिन्दी रिजन के लिये रखा जाता है तो गवर्नमेंट का फर्ज है और एम. एल. ए. साहिबान का फर्ज है कि हम देखें कि क्या कारण है कि हिन्दी रिजन में स्कीम्ज की एक्सीक्यूशन क्यों नहीं होती, उस की डिवलपमेंट क्यों नहीं होती। अगर पंजाबी रिजन वाले ही तरक्की करते जाते हैं और हिन्दी रिजन वालों की तरक्की नहीं होती तो गवर्नमेंट की सिनसेरीटी डाउटफुल है और डाउट करता हूं। आखिर क्या वजह है कि पंजाबी रिजन की सारी स्कीम्ज तो इम्प्लीमेंट हो जाती है लेकिन हिन्दी रिजन की नहीं होती, बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन होती है यहां तक कि रुपया लैप्स हो जाता है अगले साल फिर वही प्रोजेक्ट सामने आ जाता है और गवर्नमेंट बड़े फख्र से कहती है कि हम ने इतनी भारी रकम हरियाणा की डिवलपमेंट के लिये रखी है। लेकिन गवर्नमेंट को यह भी सोचना चाहिये कि कितनी दफा रुपया बजट में रखा हुआ लैप्स हुआ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि करनाल-काछवा रोड 1964 में मंजूर की गई थी पहले बजट में 20 हजार रुपया के करीब रकम रखी गई। वह लैप्स हो गई। दूसरी बार दस हजार रुपया रखा गया वह भी लैप्स हो गया फिर सतरह हजार रुपया मंजूर किया गया लेकिन रोड को मुकम्मल नहीं किया गया। इस लिये मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट जो एशारेसिज हरियाणा के बारे में देती है इस लिये नहीं देती कि इस की नीयत ठीक हो गई है बल्कि इस लिये कि हरियाणा में अवेकनिंग आ गई है। वह महसूस करते हैं कि उन्हें अपना हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट को झंझोड़ना शुरू किया है। गवर्नमेंट ने खतरा महसूस किया है इस लिये उस ने लिप सिम्पथी शुरू कर दी है। इसी तरह से करनाल में इन्दरी एस्केप पुल बनाने के लिये 1962 में तीस हजार रुपया मंजूर किया गया था लेकिन आज 1966 हो गया है और वह पुल अभी तक नहीं बना। क्या पंजाबी रिजन में भी ऐसी बातें होती हैं? क्या वहां पर भी कोई प्रोजेक्ट चार साल तक रुका रहा और नहीं बन सका। मैं यह बात नहीं मान सकता। जहां हम पंजाबी रिजन वालों से गिला करते हैं वहां पर मुझे हिन्दी रिजन वालों से भी गिला है क्योंकि अगर उन में रीजिस्ट करने की ताकत होती, फाईट करने की ताकत होती, हम इशारों पर न बैठ जाया करते, लालच में न आ जाते तो कभी भी इतनी दुर्गति न होती। इस लिये मैं समझता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हिन्दी रिजन की डिवलपमेंट होती हमें यह देखना होगा कि पंजाबी रिजन का कोई आदमी हरियाणा में इंडस्ट्री कायम न करे वहां पर उस को कोई कोटा न मिले। यह नाम तो लेते हैं हिन्दी रिजन को डिवलप करने का लेकिन होता क्या है कि अमृतसर के किसी अमीर आदमी को सोनीपत में इंडस्ट्री लगा देते हैं किसी को कोटा देते हैं। वह तो पंजाबी रिजन वालों की ही तरक्की होती है हिन्दी रिजन वालों की नहीं। पंडित मोहन लाल मिनिस्टर थे उन्होंने अपने जिले के आदमियों

[कामरेड राम प्यारा]

को करनाल में भट्ठे दे दिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा इलाका डिबैल्प नहीं होता। यह अपने आदमियों को ही डिबैल्प करते हैं। यह अंदर खाते उन से पत्तियां लेते हैं इन का उस बिजनेस में हिस्सा होता है। जब गवर्नमेंट किसी प्रकार की एशोरेंस देती है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पंजाबी रिजन से आदमी ला कर वहां पर बैठाने की जरूरत नहीं है बल्कि उसी इलाके के आदमियों की हालत में सुधार करने की जरूरत है। उसी इलाके के आदमियों को इंडस्ट्री मिलनी चाहिये। यह बात व भी इगनोर नहीं की जा सकती। जिस वक्त 1940 में कुछ लोग पोलिटिकल बिना पर जेल गए तो उस वक्त भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए। जो लोग बाहर थे उन्होंने खूब कमाई कर ली जिन का दस हजार रुपये का इसासा था उन्होंने एक लाख तक अपना इसासा बना लिया अगर यह खयाल किया जाए कि उस इसासे वाले का लड़का और मेरा लड़का दोनों एक ही तरह से कामयाब हो जायेंगे तो यह नामुमकिन बात है। यह तो हो सकता है कि अकलम और मेहनत में मेरा लड़का उस से आगे बढ़ जाए लेकिन ट्यूशन की फेसिलिटी बिजली के पंखे की, रेफ्रीजरेटर की और कूलर वगैरा की फेसिलिटीज जो एक के पास हैं वह दूसरे के पास नहीं हैं // एक वक्त था जब कि पंजाबी रिजन के एक हिस्से ने अंग्रेजों की मदद की थी इस लिये वह उनके राज्य में पूरी तरह से डिबैल्प हो गया और चूंकि 1857 में हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी इस कारण सजा के तौर पर अंग्रेजों ने उस इलाके के टुकड़े टुकड़े कर दिये। उस के टुकड़े करके उन इलाकों को अलग अलग कर दिया ताकि उन में फिर सिर उठाने की हिम्मत न रहे। आजादी के लिये लड़ाई लड़ने की उन को उस वक्त यह सजा मिली // तो मैं पूछता हूं कि क्या आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की सजा उनके लिये आज तक भी जारी रहेगी // पिछले दिनों तक हरियाणा में कुछ ऐसे गांव थे जहां पर डबल मालिया की सजा आज तक कायम रही थी। अठारह साल तक गवर्नमेंट भुली रही कि हिन्दी रिजन को सैटिस्फाई किया जाए उस को डिबैल्प किया जाए, उसे इंडस्ट्रियलाईज किया जाए, वहां पर ऐग्रीकल्चर को फरोग दिया जाए। अगर यह कहा जाए कि करनाल जिला में चावल पंजाब में सब से ज्यादा होता है तो मैं समझता हूं कि इस के लिये गवर्नमेंट का कोई क्रेडिट नहीं। जो लोग पाकिस्तान से उजड़ कर आए यह उन के परिश्रम का नतीजा है। उन को पैडी ग्राइंग का बहुत बड़ा तजरुबा था और इस के अलावा कुछ जमीन वाटर लाग्ड हो गई जिस की वजह से वहां पर पैडी की पैदावार ज्यादा होने लगी।

एक बात मैं हिन्दी रिजन के लैजिस्लेटर्ज और पालेटीशन्ज से कहूंगा कि वह इस बात को भूल जाते हैं कि उधर पाकिस्तान से आए हुए डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज भी हिन्दी रिजन में सैटल हुए हैं। जब वह इस रिजन की बात करते हैं तो इन डिस्प्लेन्ज पर्सन्ज को वह हरियाणा में नहीं गिनते। मैं कहूंगा कि जब वह यहां पर आकर सैटल हो चुके हैं तो वह भी हरियाणा के हैं। उन को भी इस धरती से उतना ही प्यार है जितना उन को है। उन के हक भी उतने ही हैं। इसलिए जब वह हिन्दी रिजन की बात करते हैं तो उसमें उन डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज को भी शामिल करके बात किया

करें जो कि यहां पर आकर सैटल हुए हैं । अगर वह ऐसा करेंगे तो उन की ताकत और भी ज्यादा हो सकती है और इस तरह से ज्यादा सख्ती के साथ, ज्यादा मजबूती के साथ मिनिस्टरी को, हकूमत को झकझोरा जा सकता है । हिन्दी रिजन की डिवैल्पमेंट कराने का यह भी एक बहुत बड़ा तरीका है । (घंटी )

एक बात कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बाबत आई । मैं इसे उस लाइट में नहीं और लाइट में लूंगा । वहां पर जो स्टूडेंट्स की एडमीशन है, मेरी इत्तलाह के मुताबिक अगर देखा जाए तो हिन्दी रिजन के सिर्फ दस परसेंट लड़के ही वहां पर पढ़ते हैं । बाकी बहुत से पंजाबी रिजन के ही हैं । वहां पर जो बड़े बड़े हाकिम बैठे हुए हैं वह हिन्दी रिजन के लड़कों को वहां पर दाखिल होने से डिस्क्रेज करते हैं और पंजाबी रिजन के लड़कों को एनकरेज करते हैं। कभी कहते हैं कि उन को स्पोर्ट्समैन होने के नाते ले लो । अगर स्पोर्ट्समैन के नाते उन को लेना है तो क्या पटियाला और जालन्धर में उन को नहीं लिया जा सकता ? यहां कुरुक्षेत्र में ही उन को क्यों दाखिला दिया जाता है ? हमें इस बात का गिला नहीं कि वह क्यों आगे न बढ़े । हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं। शिकायत सिर्फ इस बात की है कि जब वह आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं तो जो भी यूनिवर्सिटी है, जो इन्स्टीच्यूशंज हैं, जो सस्थाएं, जो स्कूल और कालेज हरियाणा में है चाहे वह पंजाबी रिजन के मुकाबिला में निहायत कम हैं -कम अर्ज कम वहां पर तो हरियाणा के लोगों के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिए । (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन इस के साथ ही साथ एक बात का और जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता और वह यह कि गवर्नमेंट के अपने रिकार्ड में है कि सारे जिला अमृतसर में इतने गांव इलैक्ट्रिफाई हो चुके हैं कि जितने सारे हरियाणा में नहीं हुई हैं । इस के अलावा आप इन्डस्ट्रीज को ले ले गर्जें कि किसी चीज को ले लें । हालत यह है कि उस इलाके में सड़कें बनाई गईं नहरें बनाई गई बिजली भी आ गई । अब हमारे सामने उस सम्बन्ध में जो बजट में आईटम आती है वह उन के मेनटेनेंस की बाबत आती है कि उस के लिए इतना रुपया हर साल दरकार है । मैं इस बात को मानता हूं कि जो जो डिवैल्पमेंट हो चुकी है, जो जो काम शुरू किए जा चुके हैं उनके लिए मेनटेनेंस की जरूरत है और उस पर लाजमी तौर पर रुपया खर्च होना ही चाहिए । अब उन चीजों की बाबत इस लिए लापरवाह नहीं होना चाहिए कि उन की मेनटेनेंस के लिए रुपया दरकार है । वह काम तो बदस्तूर चलना ही चाहिए लेकिन जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि उस के साथ ही साथ जो नया बजट बनना है उसमें जरूरी है कि इधर के इलाकों को इन्डस्ट्रीज के तौर पर कुछ न कुछ डिवैल्प किया जाए । अगर इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की तरफ से दी गई एश्योरेंसिज को देखा जाए तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वायदे तो एक के बाद एक बहुत किए गए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते । मैं इस बात को मानता हूं कि लुधियाना ने 1933 में कलकता में जा कर होजरी के सिलसिले में जापान के साथ मुकाबिला किया था ।

[कामरेड राम प्यारा]

इस बात का मैं उन को कैंडिड देता हूँ । मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जालन्धर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने सियालकोट का मुकाबिला कर लिया है । लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह उस तरफ के इलाकों ने तरक्की की है उसी तरह थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी दिया जाए ताकि यहां पर जो फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है वह न हो । अगर इस तरफ के लोगों के साथ इम्प्याजी सलूक होता है, अगर यहां पर फ्रस्ट्रेशन आती है तो उस का असर पंजाबी रिजन के लोगों पर भी पड़ सकता है । जो कैबिनेट के अन्दर हरियाणा के मिनिस्टर रहे हैं या जो इस वक्त हरियाना के इलाके से गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं उन पर इस बात की खास तौर पर जिम्मेवारी आती है और मैं कह सकता हूँ कि हरियाना के मिनिस्टर्स ने अपने आप को सन् 1957 से लेकर आज तक, जो हमारा तजर्बा है, इन दी इन्ट्रैस्ट आफ हरियाना बिल्कुल जस्टीफाई नहीं किया । इसलिए पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ ऐज सच तो बेशक इस इलाका की रीसैन्ट-मेंट कम होगी लेकिन इन मिनिस्टर्स के खिलाफ जो कि हरियाना के होते हुए भी उन के इन्ट्रैस्ट्स को सेफगार्ड नहीं कर पाए, उन के खिलाफ अज़हद शिकायत का मादा पाया जाता है । यहां तक कि जो जो महकमें उन के पास रहे हैं या हैं उन महकमों से मुताल्लिक भी उन्होंने अपने इस पिछड़े हुए इलाकों की तकालीफ को दूर करने की कोशिश नहीं की है । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर दोस्तों ने मुख्तलिफ ढंग से इस चीज़ को ऐक्स्प्लायट करने की कोशिश की है । मैं इसे ऐसे ढंग से ऐक्स्प्लायट करना पसन्द नहीं करता । किसी ने पंजाबी सूबा के नाम को लेकर स्यासी अगराज के मातहत बात की, किसी ने हिन्दी रिजन का नाम लेकर बात की । लेकिन मैं इन सभी बातों को छोड़ कर यही कहूंगा कि हर एक एरिये की डिवैलपमेंट इन दी इन्ट्रैस्ट आफ दी पीपल होनी चाहिए और यह आन दी बेसिज़ आफ जस्टीफिकेशन, राइट्स एंड प्रिविलेजिज़ होनी चाहिए । आप का शुक्रिया ।

उपाध्यक्षा : कामरेड जंगीर सिंह जोगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप उधर से ही बुला रही हैं । इधर से भी बुलाइए ।

उपाध्यक्षा : गौतम साहिब, आप बैठ जाइए । (The hon. Member Shri Gautam may resume his seat.)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : यह क्या बात है । आप इधर से भी बुलाइए ।

उपाध्यक्षा : श्री गौतम, मैं कहती हूँ कि आप बैठ जाइए । (Shri Gautam may please sit down. )

कामरेड जंगीर सिंह जोगा (उलवंडी साघे) : डिप्टी सपीकर साहिबा, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਤਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਵਧ ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ "ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀ" ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲ

ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਂਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਇਥੇ ਲਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲਗੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਥੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ 6.7 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 5.7 ਫੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 3.5 ਕਿਊਸੈਕਸ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.04 ਕਿਊਸੈਕਸ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਰੋਹਤਕ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 3.5 ਕਿਊਸੈਕਸ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।.....

(No Quorum)

उपाध्यक्षा : गर्ग साहिब, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप कोरम नहीं रख सकते, बार बार घंटी बजानी पड़ती है। (Addressing the Chief Parliamentary Secretary : Shri Garg I regret to find that you have failed to maintain a quorum in the House. I have to ring the bells time and again.) (Quorum Bells were rung and the quorum was complete.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਅਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਮਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। (ਵਿਘਨ) ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਰਖਦਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਬੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਣ ਪੈਪਸੂ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੜਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਰਾਏ ਦਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ.....

(Comrade Jangir Singh Joga was still on his legs when the House rose for the day.)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਦਨ ਸੋਮਵਾਰ, 21 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਜੇ ਤਕ ਸਥਗਿਤ  
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (The House stands adjourned till  
2:00 P. M. on Monday, the 21st February, 1966.)

(The House then adjourned till 2.00 p. m. on Monday the 21st February, 1966.)

THE FIRST FEDERAL, 1900-1901)

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8675 PVS.—384—19-8-66—C., P. & S., Pb., Chd.

## APPENDIX

TO

P. V. S. DEBATES, VOL. I, No. 3, DATED THE 17TH  
FEBRUARY, 1966.

### Audit of Accounts of Sugar Mills.

**3145. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the accounts of the Co-operative Sugar Mills in the State, for the year 1964-65, were checked and audited, if so, the details of profit and loss and the irregularities, if any, detected, mill-wise, be laid on the Table of the House ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** The accounts of the Co-operative Sugar Mills, Rohtak, Panipat, Bhogpur and Morinda have been audited, while the accounts of Nawanshahr and Batala Mills are under audit.

	Profit (+)/Loss (—)
Rohtak	+ 8, 76, 892. 26
Panipat	+ 23, 91, 426. 11
Bhogpur	—9, 22, 099. 22
Morinda	—56, 199. 26

The irregularities pointed out in the audit reports are of general nature and the items are large in number. To tabulate them will not be commensurate with the time and labour involved.

### MEMORANDUM SUBMITTED BY THE PUNJAB ROADWAYS WORKERS UNION

**3150. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state whether he received any Memorandum/Memoranda from the Punjab Roadways Workers Union during the year 1965-66 to date regarding their demands ; if so, the details of the action taken so far to meet their demands and a copy/copies of the Memorandum/Memoranda mentioned above be laid on the Table of the House ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :**

- (i) Yes.
- (ii) A statement is laid on the Table of the House.

## ACTION TAKEN ON THE MEMORANDUM, DATED 18th JUNE, 1966

### 1. Implementation of Transport Workers Act / Rules framed thereunder

(a) The Department has now proposed some amendments in these Rules in clauses 9 (Rest Rooms), 10 (Uniforms), (15 Daily) intervals for rest, 16 (spread over 17 (Split duty), 19 (Weekly rest), 20 (Compensatory Rest) 26 (Extra wages for overtime etc.). These amendments are against the interests of the workers, and should not be allowed to make.

The Motor Transport Workers' Act has been enforced in the Punjab Roadways with effect from 23rd January, 1965, subject to sections 15, 16, 17 & 19 about which relaxation is being sought from the Government in the Labour Department.

(b) The implementation of Canteen, Medical facilities, Rest Rooms, etc., in the Transport Workers Act, has been ignored in the Rules. Special Notification may kindly be issued for these facilities

Retiring rooms have been provided at most of the termini. Arrangements are being made to cover the remaining stations.

(c) Individual Control Book/Duty Cards may kindly be issued to the operational staff to record their duty hours, overtimes, etc., as agreed upon by the Deputy Transport Controller in the presence of the Deputy Labour Minister, on 22nd April, 1964, for providing the same within 4 weeks. Now 8 weeks are over nothing has been done.

Individual Control Books and Overtime Registers have since been introduced.

### 2. Implementation of Bonus Ordinance in the Public Sector

The recommendations of the Bonus Commission, 1964, Chapter XVIII, clause 18.8 (as contained on page 89 of the Report) may kindly be enforced in the Public Sector (run by the Department) since the Punjab Roadways fully comply with the three conditions prescribed in the report, namely:—

Government have sanctioned *ex gratia* grant at 4 per cent of wage bill, for the years 1964-65 & 1965-66 to all categories of employees including the supervisory staff but excluding the ministerial staff at Headquarters.

- (i) The establishment should be at least 6 years old.
- (ii) Margin of profit should be at least 20 per cent.
- (iii) It should be competing the private sector and should be running like that and the nature of service should be just as that of private Sector.

It may be submitted for your information that Shri Rizak Ram, the Hon'ble Labour Minister, in the Punjab Council announced on 30th April, 1965 that Punjab Government has recommended that this report of the Bonus Commission should be implemented on the Punjab Roadways Workers too.

### 3. National Wage Board for Transport Workers

The Wage Board for Transport Industry is much needed when the transport workers of the country are covered under one 'Motor Transport Workers Act of 1961'. Just as this Act of 1961 is applicable throughout the country on all transport workers, similarly there should be one National Wage Board for Transport Workers of the whole country and the wage rates should be uniform.

The question of establishment of National Wage Board for transport workers will be taken up after the emergency is over.

(a) It is also further brought to your kind notice, that the minimum wages of transport workers were fixed in 1948. Since then the prices of all the commodities have arisen considerably. No doubt after that it has been revised twice. But the grades have not been upgraded according to the present timings.

(b) Our minimum wages should be fixed according to the recommendations of the 15th Labour Conference.

(c) Minimum Wages Committee should be empowered to fix the upgrading pay scales in the industry.

(d) These wages should be linked with the cost of living index at Re 1 per point in its raise.

#### 4. Transport Tripartite Committee Decisions

With a view to solve the dispute in the Transport Industry in the State, the Punjab Government set up a **TRIPARTITE COMMITTEE**, in the year 1960. The decisions arrived at in the year 1961, these were applicable for 5 years, i.e., upto 1965. But it is a matter of great regret that we have been repeatedly requesting the authorities concerned to implement the above-said decisions upon us, and in spite of our hue and cry, this has not been done.

Most of the decisions of the Tripartite Committee have been implemented except the workers participation in the management. The Department is opposed to the participation and have candidly expressed view on this subject in the Committee's meeting.

It may be submitted that as per decisions arrived at in the 20th Indian Labour Conference, it was decided that the decisions arrived at by the Tripartite Committee in the different States will be made applicable in the private and public Sectors both equally.

#### 5. Fines

In certain cases operations staff are fined for no fault of theirs, and entirely on account of shortcomings of the irregularities and illegalities of the Department, like incomplete Registration Permits, back-lights, Speedometers not working, electric bell not in working order, First-aid Box incomplete, and other defects, etc. Operational staff is heavily fined and has to pay huge amount from personal pocket. It is, therefore, requested that such like challans may be defended by the Department and the fines should be paid at the spot by the Department.

Transport Secretary has been delegated powers to allow reimbursement of fines & upto Rs 25. Reimbursement cases are being dealt with very promptly.

#### 6. Stitching Charges of Uniforms

We are not getting stitching charges for our Uniforms anything, for the last several years. On 31st December, 1964 the Deputy Transport Controller (T&C) agreed in writing that one of the following conditions will be levied upon us:—

Stitching charges of uniforms are being paid according to the ceilings of costs fixed for various categories of uniforms.

- (a) Either we shall be paid according to the stitching charges rates as given to Pepsu Road Transport Corporation; or
- (b) The Department will enlist tailors for stitching Uniforms departmentally ; or
- (c) The rates which are prevailing in the Gandhi Vanita Ashram, will be given to us.

The learned Deputy Transport Controller promised that one of the above-said terms will be implemented upto 10th February, 1965, finally. But so far nothing has been done.

#### 7. Rest Rooms for Drivers/Conductors on Bus Stands

There is no facility provided at the Bus Stands for taking rest of the Drivers/Conductors during intervals of the trips. Separate room, with other facilities of electric fan, charpoy, and light, etc. may be arranged on all Bus Stands.

The position regarding provision of rest rooms for drivers/conductors has been explained in (b) above.

(b) Similarly, in workshops, where 200/300 staff work, there is no rest room provided at the workshop. It is requested that in all the workshops, rest rooms facilities as submitted in para (a) above may kindly be provided for the workshop staff.

(c) Canteen arrangements in the offices are unsatisfactory. These are mismanaged. Dirty commodities are provided at exorbitant rates as compared to the general market. There is not adequate furniture in most of the Canteens. It is requested that the Canteens should be run on Co-operative basis NO LOSS/NO PROFIT basis in the better interests of the health and pocket of the workers.

### 8. Travelling Allowance/Overtime/other Dues

The Travelling Allowance, Overtime arrears of pay and other dues of the workers should not be delayed for more than one month. Last month's arrears should be cleared by the 22nd of the next positively.

It has already been decided that payment of Travelling Allowance and overtime Allowance may be made by the 25th of the month following the incidents. The General Manager, Punjab Roadways have again been instructed to observe that date punctually.

### ACTION TAKEN ON THE MEMORANDUM DATED 17TH NOVEMBER, 1965

#### 1. Implementation of Transport Workers Act

This act was passed by the Parliament in 1961, while Rules thereunder were framed by the State Government in 1963. Although a period of about 2½ years is over, the provisions of these Rules have not been implemented in the Punjab Roadways, in spite of our repeated requests. The following items of these Rules may very kindly be implemented immediately:—

(a) Issue of Individual Control Book ;

(b) Payment of Washing Allowance to the Workshop Staff, and supply of Chappals;

(c) Calculation of overtime of the operational staff, under Section 17 of the Act.

(d) Providing Rest Rooms at various Headquarters for the operational staff, for rest and night stay at different stations.

(a) The position regarding Individual Control Books and Overtime Allowance Registers has been explained under item 1(c) of memorandum, dated 18th June, 1965.

(b) Instructions have already been issued for payment of Washing Allowance and supply of Chappals to the General Managers, Punjab Roadways. (c) Regarding section 17, a reference is being made to the Government in the Labour Department.

(d) Retiring rooms have been provided at most of the termini and arrangements are being made to cover the remaining stations.

#### II. Implementation of Bonus Commission Recommendations

On the basis of the recommendations of the Bonus Commission, the Government has framed "The payment of Bonus Act, 1965". The following provisions of this Act, may kindly be implemented in the Punjab Roadways:—

The position regarding payment of bonus has already been explained in item 2 of memorandum, dated 18th June, 1965.

(1) Section 20, *Vide* this Section, this Act has been made applicable in "Public Sector" (i.e. Punjab Roadways).

### III. Reimbursement of Fines

On 31st December, 1964, it was agreed by the Deputy Transport Controller (T & C), that upto 31st January, 1965, the reimbursement of fines will be started. Nothing has been done so far.

The position regarding reimbursement of 'fines' is the same as explained in item 5 of memorandum dated 18th June, 1965.

### IV. Uniforms

(a) Uniforms are not being supplied in time. Although winter season has already set in, no Uniform (warm) for the year 1965 has been provided.

(a) Uniforms in most cases have been supplied.

(b) Cashiers and Assistant Cashiers may kindly be supplied uniforms seasonwise, like Booking Clerks and Storekeepers, since the nature of duty is almost similar.

(b) The question regarding supply of uniforms to Cashiers Assistant Cashiers is under examination.

(c) Stitching charges may kindly be given as per agreement with the Deputy Transport Controller (T&C), dated 31st December, 1964.

(c) The position regarding stitching charges has been explained in item 6 of memorandum dated 18th June, 1965

(d) The price allowed for Jersey for workshop staff is Rs. 15 only which is too meagre. No Warm Jersey is available in the market for this amount. Its price may be fixed Rs. 25.

(d) In most cases Jerseys have been issued within the sanctioned dated amount.

### V. Penalty of Conductors for Loss of Tickets

(a) The Court of Shri R.S. Sood, Sub-Judge, 1st Class, Jullundur, in the case of Shri Prem Chand, Conductor Vs. Punjab State, ordered that penalty for loss of tickets may be fixed equivalent to the printing charges of the tickets and not on the value of the tickets. This decision may kindly be implemented in the Roadways.

The case regarding penalty on Conductors for loss of tickets is under consideration.

(b) Those Conductors who have instituted appeals before the P.T.C. against the heavy penalty imposed by the General Managers of Punjab Roadways, on this account, the recovery proceedings from their respective salaries may kindly be ordered to be stayed.

### VI. Difference of Pay to the Army Reservists

(a) Those Military Reservists who were called by the Army in 1962, during Chinese aggression, the difference of pay has not so far been paid to them by the Punjab Roadways, so far.

(a) In most of the cases difference in pay to army Reservists has been paid.

(b) All those Reservists were not given good work reward, and they have not been paid, although they were specially entitled to this reward because of their duties for the National Cause in the Army.

(b) The matter regarding cash rewards is under consideration.

### VII. Recovery of Leave Salaries on Medical Grounds of the Workshop Staff

The workshop Staff is governed by the employees State Insurance Corporation. Recoveries of leave salaries on Medical grounds in their cases may not be made. They may kindly be allowed the same benefits as heretofore.

The issue regarding payment during sick leave is under consideration.

### VIII. Payment of Night Allowance

To Trainees at Chandigarh during Training School, may kindly be made to them.

The issue regarding payment of Night Allowance is also under consideration.

### IX. Provident Fund Scheme

Contribution Provident Fund Scheme is applicable in our case, and under this Scheme, the employer is responsible to make deductions of Provident Fund from the salary of the employee who has put in 240 days' service in an establishment. This is not being done in the Punjab Roadways punctually, which may kindly be ordered.

(b) Provident Fund Accounts may kindly be got corrected from the Accountant Generals' Office, Simla, according to the actual contributions of the workers.

(a) In most of the cases provident fund deductions are being made. Others are being looked in.

(b) Instructions have been issued to all the General Managers, Punjab Roadways, to reconcile the provident fund accounts with the Accountant-General, in the company of the representative of the Union.

### X. Payment of Overtime / Travelling Allowance in Time

Overtime and Travelling Allowances are generally paid too late. Arrangements may kindly be made so that all such dues be paid to the workers by the 20th of the month.

The issue regarding payment of Overtime and Travelling Allowance has been explained in item 8 of memorandum, dated 18th June, 1965.

s prev  
etern  
looki

been  
eneral  
Road  
provi  
th the  
the  
ative

Next  
long  
long  
um,



RECEIVED  
PUNJAB VIDHAN SABHA  
LUDHIANA  
1954

**"C" 1966**

Published under the authority of the Punjab Vidhan Sabha and  
printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab, Chandigarh.

# Punjab Vidhan Sabha Debates

21st February, 1966

Vol. I—No. 4

## OFFICIAL REPORT



### CONTENTS

Monday, the 21st February, 1966

	PAGE
Starred Questions and Answers ..	(4)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45 ..	(4)20
Unstarred Questions and Answers ..	(4)53
Question of Privilege ..	(4)98
Announcement by the Speaker ..	(4)99
Papers laid on the Table ..	(4)99
Discussion on Governor's Address (Resumption) (not concl'd.)	(4)99—148

Price : Rs. 7.00 Paise.



**ERRATA**  
TO  
**PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 4,**  
**DATED THE 21ST FEBRUARY, 1966**

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
श्री बलरामजी दास टंडन	{ श्री बलरामजी दास टंडन	(4)6	11
	{ श्री बलरामजी दास टंडन	(4)17	1
	{ श्रीबलरामरजी दास टंडन	(4)18	13
Public	Public	(4)22	1
Minister	{ Minister	(4)32	1
	{ Minister	(4)36	1
land	and	(4)51	14
Comrade Hardit	Comrade Hardit	(4)58	1
Singh Bhathal	Siugh Bhathal		
sent	sets	(4)60	2
Singh	Signh	(4)60	25
District	Distict	(4)66	3
Jail	Jauil	(4)96	16 from below
Rules	ules	(4)99	2
Speaker	Speaket	(4)99	6
RESUMPTION	KESUMPTION	(4)99	19-20
ਪੱਤਰ	ਪੱਤਰ	(4)99	6 from below
ਕੁਰਪਟ	ਕਰਪਟ	(4)104	21
ਤਲਾਸ਼	ਤਲਾਸ਼	(4)105	11
ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ	ਖਸ਼ਗਵਾਰ	(4)105	18
ਮੁਜਰਮਾਨਾ	ਮਜਰਮਾਨਾ	(4)107	9
ਬੱਚੇ	ਬਚ	(4)108	3
ਮੁਰੰਮਤ	ਮੂਰੰਮਤ	(4)109	23
Chairmen,	Chairman	(4)109	8 from below
ਖੜ੍ਹੇ	ਖੜ੍ਹ	(4)110	20
ਮੈਜ਼ਦਗੀ	ਮੈਜ਼ਦਗੀ	(4)111	11
ਮੁਲਕ	ਮਲਕ	(4)111	6 from below

P. T. O.

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
ਗਵਨੰਮੋਟ	ਗਵਨਮੋਟ	(4) 115	1
ਸਕੂਲਾਂ	ਸਕਲਾਂ	(4) 129	4
ਭਲੈਂਕਟੀਫਾਈ	[ ਭਲੈਂਟੀਫਾਈ ਭਲੈਂਕਟੀਫਾਈ	(4) 130 (4) 131	last but one 1
ਰੋਸ਼ਨੀ	ਰੋਸ਼ਨੀ	(4) 130	last
ਸੀਕਾ	ਸੀਕਾ	(4) 131	4
ਚਾਹਿਓ	ਚਾਹਿਓ	(4) 131	10
ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ	ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ	(4) 131	12
ਯੂਰੀ	ਯੂਰੀ	(4) 133	4 from below
ਬੋਰਡ	ਬੋਰਡ	(4) 135	1
ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ	ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ	(4) 139	3
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ਕਰੋੜ 63 ਲਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੋ ਹਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਇਰੀਗੇ- ਟਿਡ ਹੈ ਉਹ 76 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ।	ਕਰੋੜ 63 ਲਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜੋ	(4) 139	4
ਇਕਲਾ	ਇਕਲਾ	(4) 140	4 from below
ਪੰਜਾਬ	ਪੰਜਾਬ	(4) 140	last but one
ਦੁਸ਼ਮਨ	ਦੁਸ਼ਮਨ	(4) 141	10
ਹੋਇਆ	ਹੋਇਆ	(4) 141	21
ਬੰਜਰ	ਬੰਜਰ	(4) 141	23
ਅੰਨ	ਅੰਨ	(4) 141	5 from below
ਰੋਲਾ	ਰੋਲਾ	(4) 144	2
ਮੰਗ	ਮੰਗ	(4) 146	18
Deputy Speaker	Deputy Speake	(4) 147	8 from below
ਤਰੱਕੀ	ਤਰੱਕੀ	(4) 148	2
Member	Member	(4) 148	4

# PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 21st February, 1966

*The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhavan, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 P. M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.*

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### Bonus for Punjab Roadways Employees

**\*8924. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state whether it is a fact that some decision has been taken by the Government to give some bonus to the employees of the Punjab Roadways ; if so, the rate at which it is proposed to be paid ; if no decision has yet been arrived at, the reasons therefor ?

**Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) :** The provisions of the payment of Bonus Act, 1965 do not apply to the Punjab Roadways employees, *vide* Section 32 (iv) of the Act.

**श्री बलरामजी दास टंडन :** क्या चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि जहां तक इस बोनस का ताल्लुक है पेंसू रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन ने यह बोनस देना शुरू कर दिया है है जब कि उसकी हालत पंजाब रोडवेज से अच्छी नहीं और उस को मुनाफा 50 हजार के दरम्यान रहता है, सिर्फ एक साल में 15 लाख हुआ था, और इस तरफ पंजाब रोडवेज का मुनाफा हर साल एक करोड़, सवा करोड़ और पौने दो करोड़ तक होता है तो पंजाब रोडवेज ने बोनस देना क्यों शुरू नहीं किया ?

**Chief Parliamentary Secretary :** Pepsu Road Transport Corporation is a statutory body. But the Punjab Roadways have introduced since 1959 an incentive scheme by which they give 1 per cent of the total profits for the good performance of the workers every year.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** On a point of Order, Sir.

**Mr. Speaker :** What is your point of Order ?

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, my point of Order is that none of the Ministers is present in the House. May I ask you, Sir, if there is some more important business than the sitting of this August House for the Ministers and particularly during the Question Hour ? The Government is answerable to this House and I will request you, Sir, to give a ruling whether the Ministers should be here to reply to the questions put by the Members of the House ?

**श्री बलरामजी दास टंडन :** आन एग्जायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, आपकी तरफ से इस हाउस के मੈम्बरों को एक सरकुलर दिया गया था कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 3 कलां

[श्री बलरामजी दास टंडन]

फलां दिन को यहां पर हाज़िर होंगे और सवालियों के जवाब देंगे और मेरा यह ख्याल है कि यह सारी बातें सरकार से और मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेयर्स से सलाह कर के तै हुई होंगी। तो जब मिनिस्टर साहिब ने आप एग्री किया है तो फिर क्या वजह है कि मिनिस्टर कनसन्ड हाज़िर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : जब यह रोस्टर बनाया गया था तो मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेयर्स से बात चीत करके दोनों हाउसों के सैक्रेटरीज़ ने तै किया था और यह ठीक है और मुनासिब है कि मिनिस्टर कनसन्ड अपने सवालियों के जवाब देने वाले हाउस में मौजूद हों लेकिन अगर मिनिस्टर मौजूद न हो तो मैं उन्हें कम्पैल नहीं कर सकता पर मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर कनसन्ड को हाज़िर होना चाहिए। They should attach due importance to this House. (When this roster was prepared it was done after due consultation with the Minister for Parliamentary Affairs by the secretariats of both the Houses. It is right and proper that the Ministers concerned should be present in the House on the day fixed for answering questions relating to their departments. But if the hon. Minister does not put in his appearance on that day, then I cannot compel him, but I do feel that the Ministers concerned should be present in the House.)

कामरेड सभसेर सिंघ जेस : सपीकर साहिब, मैं एह अरज करती चाहुंदा हूं कि साहूँ एह कन्वैन्शन बनावुनी चाहीदी है अउ उंस नुँ आबज़रव करना चाहीदा है कि जेकर किसे दिन सारी कैबिनेट ने ही ग़ौर-ग़ाज़र रहिना होवे उां बिज़नेस ओडवाधीजरी कमेटी नुँ दरबासत करके उंस दिन सेशन ही नहीं रक्खना चाहीदा। एह उरुां एह हाउस दी एह निरादरी है। अज ना एह चीड मनिस्टर साहिब हन, ना होम मनिस्टर, ना मनिस्टर फार पारलामेंटरी अफेअरज।

चीफ पारलामेंटरी सैक्रेटरी : जनाब सपीकर साहिब, पारलामेंटरी डेमेकरेसी दी एह कन्वैन्शन पहिलां ही है कि जेकर मनिस्टर ना होखे उां डिपटी मनिस्टर जां चीफ पारलामेंटरी सैक्रेटरी जवाब दे सकदे हन अउे लोक सभा विच वी एह उरुां हुंदा है।

There can be more important business somewhere else. Moreover, Sir, Ministers are present here.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि क्या यह ठीक है कि पंजाब सरकार तो पंजाब रोडवेज़ के इम्पलाइज़ को बोनस देना चाहती है लेकिन मरकजी सरकार के हुकम से इन्होंने बोनस देने से इन्कार किया है ?

मुख्य संसद सचिव : पंजाब रोडवेज़ में इन्सैनिटिव की स्कीम चालू है जिस के मुताबिक जिस एम्पलाई की परफार्मेंस अच्छी हो उस वरकर को मुनाफा का 1 परसेंट दिया जाता है।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मेरा सवाल तो यह है कि क्या यह ठीक है कि पंजाब सरकार तो बोनस देना चाहती है लेकिन सरकार के हुकम से इन्होंने बोनस देने से इन्कार किया है ?

**मुख्य संसद सचिव :** जी ऐसी तो कोई बात नहीं है।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** आन ए व्वायंट आफ आडर, सर। जनाब, मैं आप की मार्फत बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने खुद यमुना नगर में पंजाब गुड्रज कैरियर्स के स्वागती एड्रेस के जवाब में 14 फरवरी को बताया जिस का जिक्र मिलाप अखबार में आया है कि पंजाब सरकार तो बोनस देना चाहती है लेकिन सरकार के हुकम से इनकार किया गया है और माहरीन की एक कमेटी बिठाई जा रही है....

**Mr. Speaker :** The hon. Member was raising a point of Order and not putting a supplementary question.

**कामरेड शमशेर सिंह जोश :** सपीकर साहिब, चीफ पारलामेन्टरी सैक्रेटरी साहिब ने यह जवाब दिया है कि पंजाब रोडवेज के एम्प्लोयीज नुं इस लਈ बोनस नहीं दिया जा सकता कि पेंमेंट आफ बोनस ऐक्ट की कलान 32 विच जिरा उपाय है उस अनुसार यह नहीं दिया जा सकता। मैं उनुं का ध्यान पेंमेंट आफ बोनस ऐक्ट की सेक्शन 20 वल दिवांदा हां जिस अनुसार उनुं नुं उसी बोनस दे सकते हैं। इस विच दरज है—

If in any accounting year an establishment in public sector sells any goods produced or manufactured by it or renders any services in competition with an establishment in private sector, and the income from such sale of service or both is not less than twenty percent of the gross income of the establishment in public sector for that year.

**Mr. Speaker :** The hon. Member is raising a question relating to the interpretation of a provision of an Act. This is not a question of fact.

**Comrade Shamsher Singh Josh :** I am simply pointing out that the Government can under Section 20 of this Act give bonus to the Roadways employees. I, therefore, want to know why the Government is not giving bonus to 75,000 employees of the Punjab Roadways who have earned Rs 1.18 crores to the State this year ?

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** क्या चीफ पारलामेन्टरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि सैंटर के लेबर मिनिस्टर की तरफ से पंजाब सरकार को कोई लैटर मिला है जिस में कहा गया हो कि जहां पर बोनस एक्ट लागू न हो वहां पर एक्स ग्रेशिया दिया जा सकता है ?

**मुख्य संसद सचिव :** जनाब, इस के लिए तो नोटिस चाहिए, मेरे पास इस वक्त सारी कारसपान्डेंस मौजूद नहीं है।

**सरदार अजायब सिंह सैयू :** आन एं पुआर्डिट आफ आरडर, सर। मेरे उं पहिलां वी पुआर्डिट आफ आरडर उठाए गये हन कि अज सारे ही मनिस्टर साहिबान इस हाउस विचें गौर हाजर हन सिवाये श्री चंद राम जी दे उे उसी उनुं दे जवाब विच यह फरमाया सी कि उसी मनिस्टर नुं हाजर हन लਈ कंपेल नहीं कर सकते। फिर चीफ पारलामेन्टरी सैक्रेटरी ने यह दिसा सी कि पारलामेन्टरी रिवाइज

## [ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਿਸਟਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦਿਉ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨੀ। ਸਿਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (The hon. Member should avoid the habit of recapitulating what an other member has said and then advocating his point of view. He should straight away raise his point of order. While replying a question no one can anticipate all the supplementaries and therefore on this ground alone the question cannot be postponed.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਸਜੀ ਵਾਸ ਟਾਂਡਨ :** ਕਥਾ ਚੀਫ ਪਾਲਿਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਤਾਓ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਆਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਥਾ ਇਸ ਕੋ ਲੀਗਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਿਯੇ ਭੇਜਾ ਗਯਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਏ ਕਾਯਮ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਮਾ 20 ਪਰਸੈਂਟ ਸੇ ਜ਼ਯਾਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋ ਦਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?

**ਮੁਖਯ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ :** ਯਹੁ ਤੋ ਏਕੁ ਤਰਹੁ ਕੇ ਸੁਯੋਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਂ। ਇਨ ਸੇ ਕੋਈ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ?

**ਮੁਖਯ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ :** ਇਸ ਕਾ ਸਵਾਲ ਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਤਾਲਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਯਕਸ਼ :** ਕਥਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਦਿਯਾ ਗਯਾ ਹੈ ? (Whether any notice has been given in this connection ?)

**ਮੁਖਯ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ :** ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਫਰਵਰੀ, 1966 ਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਯਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਅਪਨੀ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਨੇ ਗ੍ਰੇਡਜ਼ ਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਭੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਯਹੁ ਧਰਾਂ ਪਰ ਗਲਤ ਕਯਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਯੁਕਤ : ਜਹਾਂ ਤਕ ਨੋਟਿਸ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਤੋ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਹ ਦਿਯਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈਂ । I shall look into the matter. (As regards the question of a notice, the Chief Parliamentary Secretary has already stated that no such notice has been given If the hon. Member thinks otherwise I shall look into the matter.

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੇਂ ਤਮਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਨੇ ਕਾ ਖਤਰਾ ਹੈ. . . . .

Mr. Speaker : Order please,

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, the hon. Chief Parliamentary Secretary has been pleased to state in reply to a question that no such notice was given and on the other hand as hon. Member of this House Shri Agnihotri has categorically stated that the notice was given on a certain date. You have been pleased to remark that you would look into the matter. Now, Sir, if the statement of the hon. Member Shri Agnihotri is correct, may I know what action will be taken against the Government.

Mr. Speaker : The hon. Member may please look to the rules. He is a senior Member.

Next Question by Shri Tandon please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ?

Mr. Speaker : No please, It is not postponed.

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਤ ਇਨਵਾਲਿਡ ਹੈ ਇਕ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਜੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕੁਅਸਚਨ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੀ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। It is a question of verification (The wheel will get jammed during the Question Hour. After this speeches on the Governor's Address only will commence. As regards notice, the Chief Parliamentary Secretary says

[Mr. Speaker]

that he has not been given. It is a question of verification now.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

**Mr. Speaker :** He is representing the Minister-in-charge. The Minister-in-charge is not there in his personal capacity.

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਾਲ ਅਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਚੇਅਰ ਦੀ ਰੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਕ ਸੇ ਝਯਾਦਾ ਦਫਾ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਯਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ ਵਾਲੀਂ ਕੋ ਬੀਨਸ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ.....

**Mr. Speaker :** All right, as a number of hon. Members are insisting, I am postponing this Question for further supplementaries.

#### Inadequate Accommodation at Punjab Roadways Bus Stand, Ludhiana

**\*8925. Shri Balramji Das Tandon :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state whether the fact regarding the inadequacy of accommodation at the Punjab Roadways, Bus Stand, Ludhiana, has been brought to the notice of the Transport Department or the Government : if so, the action, if any, taken or contemplated by the Government in this regard ?

**Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) :** (i) Yes.

(ii) A spacious site measuring approximately ten acres opposite Bharat Nagar near the Railway crossing on the junction of Ferozepur Railway Line and Link road has been selected and the Improvement Trust, Ludhiana, approached for early acquisition of the land. It is proposed to construct a General Bus Stand with all modern amenities at the new site.

ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਕਯਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜਗਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਏਕਵਾਯਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਯਾ ਕਹ ਭੀ ਏਸੀ ਗੁੰਜਾਨ ਆਕਾਦ ਜਗਹ ਹੈ ਜੈਸੀਕਿ ਅਬ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਕੇ ਲਿਏ ਹੈ ?

ਸੁਭਯ ਸੰਸਦ ਸਚਿਕ : ਇਸ ਕੇ ਲਿਏ ਜਨਾਬ 10 ਏਕਡ ਜ਼ਮੀਨ ਏਕਵਾਯਰ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡੁਾ ਸ਼ਹਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਤੀ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤਾ, ਜਯਦੀਕ ਜਗਹ ਪਰ ਹੀ ਰਖਾ ਜਾਏ ਗਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ : ਕੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह नया बस स्टैंड कब तक बना दिया जाएगा ?

मुख्य संसद सचिव : यह स्कीम एप्रूवल स्टेज पर है इस के मुताल्लिक जितनी जल्दी भी हो सका फैसला किया जाएगा ।

**Permits issued by the Provincial Transport Controller, etc**

\*8969, Comrade Ram Piara : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state —

- (a) the total number of permits for private carriers, public carriers and Passenger Buses with details thereof issued by the Provincial Transport Controller and/or by the Regional Transport Authorities in the State during the period from 7th July, 1964 upto-date together with the names of those individuals or Transport Societies and Undertakings including the Punjab Roadways in whose favour those were issued, date-wise ;
- (b) whether any permits were issued by the said authorities for tempos/scooter rickshaws/Motor Cycle rickshaws or any other conveyance used for carrying passengers during the above mentioned period ; if so, the names of those in whose favour these permits have been issued in each case ;
- (c) the criteria kept in view at the time of issue of permits mentioned in part (a) and (b) above ;
- (d) whether any applications were invited for the purpose ; if so, when and if not invited, the reasons for the same ;
- (e) whether any special consideration is shown to the political Sufferers or their dependents in the matter of issue of permits ;
- (f) if the reply to part (e) above be in the affirmative, the names of the Political sufferers or their dependents to whom such permits have been issued during the period mentioned in part (a) above ?

**Shri Ram Partap Garg** (Chief Parliamentary Secretary) : (a)(b) and (f) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. Information will, however, be supplied in any particular case, if sought.

(c), (d) and (e) : A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(c) 1. *Private Carriers*.—As provided in section (2)(22) of the Motor Vehicles Act.

2. *Public Carriers*.—There is liberal issue of public carriers permits for Punjab plains and the hill routes of Kangra and Hoshiarpur Districts excluding Pathankot—Manali route.

3. *Passenger buses*.—Permits are issued according to the needs of traffic after following procedure as prescribed under various provisions of Motor Vehicles Act.

4. *Tempos*.—These permits are sanctioned for operations within a radius of 5 miles to :—

- (i) Harijans ;
- (ii) Ex-servicemen ;
- (iii) Persons belonging to backward classes ;
- (iv) Refugees from Burma who are of Punjabi origin ;
- (v) People affected by floods ;
- (vi) Residents of villages in Tehsils on the Indo-Pakistan Border ;

5. *Scooter Rickshaws*.—Permits are given freely.

[Chief Parliamentary Secretary]

(d) Applications are dealt with as and when received.

(e) The extent has been indicated in (c) above.

**कामरेड राम प्यारा :** मेरा सप्लीमेंटरी यह है कि जैसा उन्होंने ने जवाब दिया है कि (a) और (b) की इन्फर्मेशन कुलैक्ट करने में टाइम लगता है मेरा तो सवाल ही सिर्फ इतना है कि अगर कोई कन्सिडरेशन पुलिटिकल सफरर्ज के लिये दिया जाता है तो वह कितना है। मगर सरकार जान बूझ कर डिले कर रही है जैसे उन्होंने ने कहा है *The time and labour involved will not be commensurate etc.*, क्या यह हकीकत है कि गवर्नमेंट ने उस की तकररी विदहोल्ड की है क्योंकि पुलिटिकल सफरर्ज में उसे इन्कलूड नहीं किया ?

**मुख्य संसद सचिव :** इसमें पुलिटिकल सफरर्ज भी हैं, हरिजन और एक्स सर्विस मैन और कुछ और कैटेगरीज़ हैं।

*(Interruptions and noise in the House)*

**सरदार लछमन सिंह गिल :** और कैटेगरीज़ क्या हैं ?

**Mr. Speaker** Order, Order. Let the reply be completed.

**कामरेड राम प्यारा :** मैं ने यह सवाल पुलिटिकल सफरर्ज के बारे में पूछा है, हरिजनों और दूसरों के बारे में नहीं पूछा। क्या चीफ पालियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि क्या यह हकीकत है कि गवर्नमेंट ने ऐसे आदमियों को परमिट दिए हैं जो पुलिटिकल सफरर्ज नहीं हैं, उन्हें मैलेशली फेवर करने के लिये ऐसा किया गया है ?

**मुख्य संसद सचिव :** कोई क्राइटीरिया फिक्स नहीं किया गया। अगर कोई स्पैसिफिक केस है तो नोटिस में लाएं, एग्जामिन कर लेंगे।

**सरदार गुरचरन सिंह :** मैं चीफ पारलीमेंटरी सैक्रेटरी साहिब ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ ਲਿਉ ਆਫ ੫੦-੫੦ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਈਟੀਰਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ ?

**Chief Parliamentary Secretary :** Mr. Speaker, Sir, if the hon. Member so desires, I will read out from the written reply —

- "1. *Private carriers.*—As provided in Section 2(22) of the Motor Vehicles Act.
2. *Public Carriers.*—There is a liberal issue of public carriers permits for Punjab plains and the hill routes of Kangra and Hoshiarpur districts excluding Pathankot-Manali route.
3. *Passenger buses.*—Permits are issued according to the needs of traffic after following the procedure as prescribed under various provisions of Motor Vehicles Act.
4. *Tempose.*—These permits are sanctioned for operations within a radius of five miles to—
  - (i) Harijans ;
  - (ii) Ex-servicemen ;

- (iii) Persons belonging to backward classes ;
- (iv) Refugees from Burma who are of Punjabi origin ;
- (v) People affected by floods ;
- (vi) Residents of villages in Tahsils on the Indo-Pakistan Border."

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ in lieu of 50:50 you have issued permits throughout the Punjab. ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ ?

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 50:50 ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

We are following the procedure as provided in the various provisions of the Motor Vehicles Act.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, may I know from the hon. Chief Parliamentary Secretary whether these permits are issued on the recommendations of the Regional Transport Authorities or direct by the Provincial Transport Controller ?

**ਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਚਿਕ :** ਧਨ ਕੌਨ ਸੇ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Mr. Speaker, I am sorry, the hon. Chief Parliamentary Secretary is putting a question to me. The question is before him. I am referring to part (a) of the question.

**ਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਚਿਕ :** ਇਟ ਇਜ ਏ ਕੇਸ ਕਵੈਸ਼ਨ। ਪੀ॰ ਟੀ॰ ਸੀ॰ ਕਾ ਏਕ ਏਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਹੁਆ ਥਾ ਤਸ ਕੇ ਸੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਏ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਏਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਪਾਕਰ ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਨ ਪਰਮਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇਂਦੀ ਹੈਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾ ਫਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਮੈਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਕੋਰੇਜ਼ ਪਰਮਿਟਸ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਹੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇਨਸਟਾਂਸ ਦਿਉ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਗਜ਼ਾਮਿੰਡ। (He has asked for a specific instance which will be examined.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪਰਮੈਂਟੇਜ ਹੈ ? ਜੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਐਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ?

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ।

**Comrade Kam Piara :** Mr. Speaker, Sir, in regard to Passenger Buses, it has been stated in the reply —

“Permits are issued according to the needs of traffic.....”

ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨੇ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨ ਸਾ ਕਾਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ? ਕੀ ਯਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਬਸੋਂ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਵਰਕਾਸਟੋਂ ਆਤੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਕੇ ਲਿਯੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿਏ ਜਾਤੇ ?

**ਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ :** ਜਬ ਕਿਸੀ ਈਲਾਕੇ ਸੇ ਰਿਪ੍ਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਈਸ਼ੂ ਕੀਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਕਸਾਮਿਨ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾ ਵਹਾਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿਯਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ :** ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ (ਸੀ) ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਟਿਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਲ ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਟਿਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਈਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

**ਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ :** ਜਨਾਬ, ਪੁਲਿਟਿਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛੀਸ਼ਨ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਈਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਵਹ ਬੋਨਾਫਾਇਡ ਪੁਲਿਟਿਕਲ ਸਫਰਰ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਮੇਂ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਫਿਕੇਟ ਈਸ਼ੂ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਲਿਸਟ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਂਡ ਹੈਂ ਤਾਂ ਹਮ ਈਕਸਾਮਿਨ ਕਰ ਲੈਂਗੇ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ 50 : 50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕ੍ਰੈਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ?

**ਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ :** ਇਸ ਕੇ ਲਿਯੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਈਕ ਬਾਤ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਲੇਜ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, may I know from the hon. Chief Parliamentary Secretary the definition of ‘Political Sufferer’ for the purpose of this question ?

**ਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ :** ਇਸ ਸਵਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਯਹ ਇਤਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਟਿਕਲ ਸਫਰਰ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾ ਫੁੰਗਾ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Mr. Speaker, Sir. I would like to know specifically from the hon. Chief Parliamentary Secretary as to who is a Political sufferer whether a person who has undergone imprisonment

against the Britishers or an Akali who has been to the Jail is a Political sufferer or not ? Who is a political sufferer for the purpose of this question ?

**मुख्य संसद सचिव :** जो आज़ादी की खातर लड़ा है, चाहे जन संघ का है, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, वह पुलिटिकल सफरर है।

**सरदार गुरचरन सिंघ :** की चीफ पारलीमेंटरी सैक्टररी साहिब दसठगे कि जिनू टरांसपोर्ट आपरेटरज ने आपली माਈलेज सैरेंडर कर दिती है उनू नू यट माਈलेज दे रूट परमिट दिते हन ? कुछ कंपनीआं अजिहीआं हन जिहज़ीआं यूनीअन दीआं मैंगर नही, उनू ने ज़िआदा माਈलेज दे रूट परमिट लये हन, जे डिज़रव नही करदीआं। इस दा की कारन है ?

**चीफ पारलीमेंटरी सैक्टररी :** कौसी औसा केस है तां नोटिस विच लियाउठ।

**सरदार गुरचरन सिंघ :** मालवा बस औंड समुंदरी टरांसपोर्ट कंपनी।

#### Bus Stand at Karnal

**\*3982. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Transport and Elections, with reference to the reply to Starred Question No. 5135 printed in the Debate, dated the 31st March, 1960, be pleased to state —

- whether the Bus Stand in Karnal was completed or was ready in the financial year 1960-61 as stated in Part (b) of the said reply; if the not, the reasons therefor ;
- the date when the construction of the said Bus Stand started together with the date when it was completed or is expected to be completed ;
- the total estimated cost of the said Bus Stand together with the expenditure incurred thereon upto-date ;
- whether the area of the said Bus Stand site remains 5.44 acres as indicated in part (a) of the said reply or has been increased or decreased together with the reasons therefor in each case ?

**Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) :** (a) (i) No. (ii) The possession of the land was not delivered.  
(b) (i) 7th October, 1964. (ii) Expected to be completed by 31st March, 1966.

(c) Rs 8,74,960 inclusive of the cost of land. The expenditure incurred so far as is Rs 3,81,360.

(d) The area of the site has been increased by 1.64 acres. The additional land was required for providing separate 'IN' and 'OUT' gates, shopping centre etc.

**कामरेड राम प्यारा :** Chief Parliamentary Secretary साहिब ने बताया है कि 31 मार्च, 1966 तक वह बस अड्डा बन जाएगा लेकिन साथ ही उन्होंने ने यह बताया है कि अब तक 3 लाख 81 हजार रुपया खर्च हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी का जो पांच लाख रुपया है वह सारा एक महीने में ही खर्च करना है या कि कुछ पेमेंट्स बाकी हैं जो करने वाली हैं।

**मुख्य संसद सचिव :** जितनी पेमेंट्स हो गई हैं उन की फिगर दी हैं। बाकी पेमेंट्स का सिलसिला तो काफी देर तक चलता रहता है।

**पण्डित चिरंजी लाल शर्मा :** करनाल का बस स्टैंड 1962 तक बनाने की स्कीम थी। मगर अब तक न बनने की क्या वजह है?

मुख्य सचिव : मैं अर्ज कर चुका हूँ कि पहले तो ज़मीन का possession नहीं मिला था, लेकिन जब possession मिल गया तो बाद में architect ने कहा कि 'in' and 'out' के लिये 1.64 एकड़ ज़मीन और चाहिए। खैर अब तो कम्पलीट होने वाला ही है।

कामरेड राम प्यारा : यह जो काम 1961-62 में खत्म होना था उस की बजाए 31 मार्च, 1966 को खत्म होगा। इस डीले की जिम्मेवार सेंट्रल गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट।

**Chief Parliamentary Secretary :** Sir, it is rather difficult to fix any responsibility in this connection.

### Bus Fare from Sirhind to Patiala

**\*9104. Dr. Baldev Parkash** (on behalf of Shri Om Parkash Agnihotri): Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state :

- (a) the bus fare being charged at present by the Pepsu Road Transport Corporation from Sirhind to Patiala ;
- (b) whether it is a fact that the fare referred to in part (a) above is higher by 30 paise than the rate charged by private companies on the said route ; if so, the reasons therefor ;
- (c) whether he has recently received any complaint regarding the charging of higher bus fare and also about other matters; if so, the action so far taken thereon ?

**Shri Ram Partap Garg** ( Chief Parliamentary Secretary ) : (a) Rs 1.20 plus Passenger Tax.

(b) (i) The Corporation fare is higher by 20 paise.

(ii) The Private Operators have the monopoly of operation on the shorter route connecting Sirhind with Patiala via Nandpur-Baran where they are charging 90 Paise as fare. Therefore, in order to attract passengers in their buses plying on the longer route via Rajpura, where they are competing with the Corporation, they are charging Re 1 as fare.

(c) Yes. Secretary, Regional Transport Authority, Patiala has been asked to eliminate disparity and to ensure uniformity. Now there is no disparity.

**श्री बलरामजी दास टंडन :** क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि जब यह डिसपैरिटी खत्म हो गई है तो अब नए रेट्स क्या फिक्स हुए हैं।

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** आठ पैसे फी मील हुआ है। 1.20 रुपए पर 30 पैसे पैसेंजर टैक्स होगा।

**श्री बलरामजी दास टंडन :** पहले जो फिक्स रेट्स से ज्यादा चार्ज करते रहे हैं उन के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया है ?

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** हमने मिनीमम और मक्सीमम 6 और 8 पैसे फिक्स किया हुआ था। तो शार्टर रूट पर वह आठ पैसे फी मील चार्ज करते रहे हैं और लॉन्गर रूट पर क्योंकि उन का कम्पीटीशन था कारपोरेशन के साथ इस लिए वहां पर 6 पैसे चार्ज करते थे। लेकिन हमने रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, पटियाला से कह कर डिसपैरिटी दूर करवा दी है।

ਸ੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਵਾਸ ਟੰਡਨ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਥਰ ਜੱਥੇ ਕਿ ਕੌਨੀ ਰੋਡ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੀਲ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕੀਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

**Chief Parliamentary Secretary :** Under section 43 of the Motor Vehicles Act, 1939, the Government have fixed minimum and maximum rates of bus fares per passenger per mile at 6 and 8 pies.

ਕਹਿ ਕੌਨੀ ਮੈਂ ਸੋਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੈਂ ਕਮ ਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।

**Nationalisation of Transport Routes by P.R.T.C., Patiala**

**\*9141. Comrade Bhan Singh Bhamra :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the P.R.T.C., Patiala, recently postponed nationalisation of Transport routes by one year ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that the nationalisation of the Malerkotla - Bhatinda route scheduled to be nationalised during the current year has been postponed ; if so, the reasons therefor ?

**Shri Ram Partap Garg ( Chief Parliamentary Secretary ) :** (a)

No.

(b) No. As required by law the scheme in respect of this route was published on 19th November, 1965 for inviting objections. A date for hearing these objections will now be fixed after which and subject to any modification if justified, it will be approved.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸੁਦਾ ਪਾਲੀਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤਕ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਕ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਪੈਪਸੂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹੋ ਪਾਲੀਸੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਨੋਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ : ਪੈਪਸੂ ਦੇ 2nd Five Year Plan ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪੰਨੇ 428 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

“By the year 1958-59, third year of the Second Plan, the Road Transport will be completely nationalized so far as the pucca routes are concerned.....”

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਅਸੀਂ ਇਕ ਫੇਜ਼ਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾ ਧਰ ਅਟਰੀਮੇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ : ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਪਸੂ ਕੋ ਅਨੁਵਰਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ 50:50 ਕਾ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ portable Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ.....

**Mr. Speaker :** Please withdraw your words.

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਲ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

**ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

### Construction of Bridge at Beas River

**\*8926. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the date when the work for the construction of another bridge and connecting roads at the Beas river was given together with the name of the contractor to whom it was given and the amount involved therein ;

(b) the time limit, if any, fixed for the completion of the said works and whether the same has been revised ; if so, the details thereof ;

(c) whether the Union Government is sharing the expenditure being incurred on the said works ; if so, to what extent ?

**Shri Ram Partap Garg ( Chief Parliamentary Secretary ) :** (a) and (b) The work of construction of the high level bridge over river Beas crossing G.T. Road in mile 250 has been allotted to various agencies. A statement showing the names of different agencies executing the work, amount of work and the original time limit and extension allowed, if any, is laid on the Table of the House.

(c) The entire scheme is being financed by the Government of India, Ministry of Transport ( Roads Wing.)

### STATEMENT

Various works in connection with the construction of a High Level Bridge over river Beas in mile 250 of G.T. Road allotted to different agencies

Serial No.	Name of Work	Name of contractor	Amount	Time limit
1	2	3	4	5
			Rs	
1	Main bridge over river Beas	M/s Gammon India Ltd., Bombay	79,50,000	36 months from the date of signing the agreement.
2	Approaches to Beas Bridge group I, RDO-1810 and diversion	Shri Satish Kumar, village and post office Raya, district Amritsar	2,00,000	Nine months from 14-11-63 and extended upto 30-4-65 Already completed.
3	Approaches to Beas Bridge, Group II, RD-1810-5810	M/s Nirmal Singh, Deva Singh, 165 Model Town, Jullundur	1,80,000	12 months from 23-11-63 extended 30-6-65, Already completed.

1	2	3	4	5
4	Approaches to Beas Bridge Group III, RD-5810—8800	M/s Srin Janta L & C Society	25,000	Six months from 11-10-63 extended upto 15-10-64. Already completed.
5	Approaches to Beas Bridge Group IV, RD 8800—12900	M/s Deva Singh-Nirmal Singh, 165 Model Town, Jullundur	2,35,000	11 months from 4-10-63 extended upto 3-5-65. Already completed.
6	Approaches to Beas Bridge Group V, RD-14900 to 19350	M/s Dhulka L & C Society	3,20,000	11 months from 11-10-63 extended upto 31-12-65. Completed upto dry portion.
7	Left Guide Bund	Shri Malik Ram Sethi, Ambala	8,00,000	12 months from 11-3-64 extended upto 15-2-66. Almost complete.
8	Right Guide Bund	Shri Malik Ram Sethi, Ambala	10,86,000	36 months from 15-1-1965
9	Collection of Stone wearing RD 5810-18350	Shri Malik Ram Sethi, Ambala	87,000	18 months from 5-1-1966
10	Providing pitching on Down stream side of left side approach of Beas Bridge	Shri Malik Ram Sethi, Ambala	1,60,000	15 months from 14-9-64 extended. Already completed.

श्री बलरामजी दास टंडन : यह जो लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक पार्ट या गुरुप 2, 3, 4, 5, के बारे में लिखा है कि **already completed** । क्या चीफ पार्लियामेंटरी सcretरी साहिब इसकी डिटेल्ज बताएंगे कि यह गुरुपस दया हैं ?

मुख्य संसद सचिव : इसके लिये नोटिस चाहिए ।

श्री बलराम जी दास टंडन : नोटिस तो दिया हुआ है , और क्या चाहिए ?

मुख्य संसद सचिव : आप सवाल को पढ़ें और उसके स्कोप से बाहर न जाएं । यह जो ग्रुप 2, 3, 4, 5 हैं **these are already completed**. अब आप क्या और जानना चाहते हैं ?

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से ग्रुपस हैं, उनकी क्या डिटेल्ज हैं और वह कौन सी रोडज हैं जिन के बारे आप कहते हैं आलरेडी कम्पलीटिड । हम वहां से रोड आते जाते हैं हमें तो कोई कम्पलीट नजर नहीं आई ।

**Chief Parliamentary Secretary :** Sir, earthwork on approaches to the bridge, stands completed except that the work cannot be carried out in the reaches near Guide Bund and abutments unless the Guide Bund and abutments are completed.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, जो वज़ीर साहिब इस महकमा के हैं वह इसका जवाब दें और अब इसे पोस्टपोन किया जाए क्योंकि इनकी तरफ से ठीक और सही जवाब नहीं आ रहा है। यह कहते हैं कि आलरेडी कम्पलीटिड लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी एप्रोच रोड कम्पलीट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर आपकी पुज़ीशन यह है कि जो उन्होंने ने जवाब दिया कि कम्पलीट हो गई वह ठीक नहीं है और वह रोड कम्पलीट नहीं है तो यह फ़ैक्टुअल मिस्टेक है। अगर आप फ़ैक्ट्स को चैलेंज करते हैं तो आप लिख कर दें। That can be looked into whether the facts given by him are correct or incorrect. (If the position taken up by the hon. Member is that the reply given by the Chief Parliamentary Secretary that the road is complete, is not correct and that the road is still incomplete then that is a factual mistake. If the hon. Member challenges the facts then he should do so in writing. That can be looked into whether the facts given by him are correct or incorrect.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं ने इन से यह पूछा था कि यह जो उन्होंने ने नम्बर 2, 3, 4, 5 एप्रोच रोडज बताई हैं कि कम्पलीट हैं वह कौन सी हैं, कहाँ पर हैं और उनकी डिटेल् बयान है। हम तो रोज़ वहाँ से गुज़रते हैं और हमें वहाँ एक भी सड़क नज़र नहीं आई जो कम्पलीट हो। जिनको यह कम्पलीट बताते हैं वह हैं कहाँ पर ?

सरदार लडभट सिंघ गिल : आन ए पुआर्टि आड आरडर, सर। इन्हें ने जे लिख के जवाब दित्ता उस दिच बिहा है कि सड़क मुक़मल है लेकिन गुट बिहा है कि गाड़ीड बंद नहीं बटिआ है। इसका मतलब है कि कौड़ी आदमी उधें क़रास नहीं कर सकदा। पुल बट गिआ गाड़ीड बंद बटिआ नहीं उं सड़क बिदे बट गिआ ? इन्हें दे जवाब उं उं कौड़ी गल नहीं बटिआ।

Chief Parliamentary Secretary : Sir, part (a) of the question reads—

“(a) the date when the work for the construction of another bridge and connecting roads at the Beas river was given together with the name of the contractor to whom it was given and the amount involved therein.

जनाब, इसके बारे में डिटेल् इन्फ़ॉर्मेशन ही हुई है कि कौनसा काम कौनसे ठेकेदार को कितनी मालियत का दिया गया है और. ....

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि कौन सा हिस्सा बन गया है और कौन सा अभी नहीं बना है। (The Chief Parliamentary Secretary may please state which part of the road has been completed and which still remains to be completed.)

मुख्य संसद सचिव : यह जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट हैं यह बन गए हैं। मेन ब्रिज जो है वह अभी नहीं बना है। 36 महीने का टाइम जब से काम शुरू हुआ है उसके बनाने के लिये दिया हुआ है यह बहुत बड़ा काम है 80 लाख के करीब का काम है।  
Collection of stone bearing No. 5810-18350 is not complete.

**श्री बलारम जी दास इंडन :** मेरा अग्रजैक्शन भी यही है कि जो लिस्ट टेबल पर रखी गई है उसे ही पढ़ कर सुनाया जा रहा है और जो बात मैं पूछता हूँ उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। जो आप पढ़ कर सुना रहे हैं वह तो मेरे पास भी है। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि जिनको आप आलरैडी कम्पलीट कहते हैं वह एप्रोच रोडज कौन सी हैं और कहां पर हैं। मेरा कहना यह है कि वहां एक भी पार्ट कम्पलीट नहीं है।

**Chief Parliamentary Secretary :** The approaches to Beas Bridge Group II, Group III, Group IV, Group V and the left Guide Bund have been completed. इस में साफ तौर पर दिया गया है। अगर आप नक्शा देखना चाहते हैं तो वह भी दिखाने के लिये तैयार है।

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। ट्रांसपोर्ट का महकमा सी. पी. एस. साहिब का नहीं है। मैं इस बात पर आपका रुलिंग चाहता हूँ कि जब हाउस में फुल दो मिनिस्टर बैठे हों तो क्या उनकी मौजूदगी में चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी को जवाब देना चाहिए। Why should not the hon Minister meet the House.

**Mr. Speaker :** It is not for the hon. Members to decide as to which of the Ministers should take responsibility of answering the questions. It is the Minister-in-charge and the Chief Parliamentary Secretary who have to decide whether the hon. Minister concerned should reply or another hon. Minister should be entrusted with this work, or the Chief Parliamentary Secretary should attend to this work.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, my point of Order was whether in the presence of a Minister, the Chief Parliamentary Secretary can supersede him in giving the answers.

**Mr. Speaker :** There is no question of superseding or otherwise.

**श्री फतेह चन्द विज :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। या तो मैम्बर साहिबान इतने मुश्किल सवाल न करें या फिर गगं साहिब को कहें कि वह इस सवाल को पोस्टपोन करें।

**मुख्य संसद सचिव :** मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ मैम्बरान को इर्रिलेवैंट सवाल करने की आदत है। जो एगजैक्ट सवाल है उसका एगजैक्ट जवाब देना चाहते हैं और दिया जा रहा है।

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** मैम्बर साहिबान को भी अफसोस है कि इस तरह हाउस का टाइम खराब होता है क्योंकि वह तैयार हो कर नहीं आए हैं। He has not been giving good performance.

**श्री अध्यक्ष :** कौन मैम्बर या मिनिस्टर हाउस का टाइम खराब करता है, जवाब ठीक आता है या नहीं, कोई सवाल रिलेवैंट है या irrelevant इन सब चीजों को मैंने डिफिनिट कर दिया है। यह चीज आप मुझे पर छोड़ दें। जहां कोई इर्रिलेवैंट होगा मैं रोक दूंगा। (Who wastes the time of the House, an hon. Member or a Minister, whether the reply given is correct

[Mr. Speaker]

or otherwise or whether a supplementary is relevant or irrelevant, all these things are to be determined by the Chair. The hon. Member may leave this to me. Whenever one is irrelevant I will pull him up.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मेन ब्रिज के बारे में उन्होंने बताया है कि 36 months from the date of agreement. लेकिन date of agreement नहीं बताई गई बाकी जब कि सब के बारे में डेट्स दी हुई हैं कि कब टाइम लिमिट खत्म होती है। मैं जानता चाहता हूँ कि इस की date of agreement क्या है ?

मुख्य संसद सचिव : अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है क्योंकि उस के बारे में लीगल रिमैबरेन्स जांच पड़ताल कर रहा है।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, । क्या कोई काम कोई एग्रीमेंट साइन होने से पहले सरकार शुरू करवा सकती है या नहीं चाहे उस में गवर्नमेंट को नुकसान या फायदा उठाना पड़े।

मुख्य संसद सचिव : जब टेंडर किसी का मंजूर हो जाता है तो काम अलाट हो जाता है और बाद में एग्रीमेंट साइन हो जाता है। इस तरह से काम शुरू हो ही जाता है

Mr. Speaker: Next question by Comrade Bhan Singh Bhaura.

सरदार लडमण सिंह गिल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । जिहड़ा प्रोजेक्ट चीफ पारलामेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने दिसा है मैं उस नुं चैलेंज करदा हं। किसे गैरमेंट either Central Government or a State Government in the whole of India विस किधरे वी एह प्रोजेक्ट नही है जिसे अग्रीमेंट साईन होण तें पयिला कंम चालू हो जांदा होवे । एह डेडलाइनली सरकार लयी क्रिमीनल गल है।

Mr. Speaker . Please take your seat.

सरदार लडमण सिंह गिल : मैं इस के बारे में आपका रूलिंग चाहूँदा हं।

श्री अध्यक्ष : यह गवर्नमेंट के लिए प्रापर है या नहीं कि एग्रीमेंट साइन होने से पहले किसी को काम दे दे । You can have your opinion. (The hon. Member can have his own opinion regarding whether it is proper or not for the Government to allot work to a party before getting the agreement signed.)

सरदार लडमण सिंह गिल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । चीफ पारलामेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने दिसा कि जिस पार्टी का कंटेन्टेन्ट का टैंडर

ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

**Mr. Speaker :** It is no point of order.

**ਸ਼੍ਰੀ ਆਮੋਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਿਨਹੋਤ੍ਰੀ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਾਮ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਦ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ । ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤਾਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਦ ਬਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਧਾਦ ਕਿਤਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ?

**Mr. Speaker :** It is no point of order.

**ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਗੋਤਮ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਾਮ ਕਿਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ?

**Mr. Speaker :** It is not a point of order.

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ :** ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਅਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਨੇ ਬਤਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਏ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਬਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਅਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਮ ਦੇ ਡਿਐਂਡ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

**Chief Parliamentary Secretary :** No.

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਅਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਪਾ ਕਰੇਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤਾਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਦ ਕਿਤਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ । ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਧਾਦ 5, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ । ਖੁਦਾ ਨ ਖਾਸਤਾ ਕਿਰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਏਮਰਜੈਂਸੀ ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਧਾਦ ਅਤੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮ ਕਦੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

**ਮੁਖੀ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ :** ਜਲਦੀ ਹੀ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿਤੀ ?

**Chief Parliamentary Secretary :** Separate Notice is required for this.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਨੋ" ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ .. ..

**Mr. Speaker :** Question Hour is over.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਈ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕੁਐਸ਼ਚਨ ਆਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। (The supplementaries on the previous question had not yet finished, when the Question Hour was over. Therefore his question could not be taken up.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**Mr. Speaker :** Please take your seat.

ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸਟੰਡਨ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਰ ਆਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

**Mr. Speaker :** Further supplementary questions can be asked next time.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ : ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਕਾਲ ਅਪੌਨ ਕੀਤਾ ਥਾ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਪਹਲੇ ਸਵਾਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਛਣੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਇੰਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਸਵਾਲ ਪਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਥੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਟੇਕ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। (Hon. Member's question was called upon, but the Members insisted upon making further interpellations on the previous question and their request for more supplementaries was allowed. So his question could not be taken up and the procedure laid down in this connection will be followed.)

#### WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

##### Patiala-Bhadson Road

**\*8931, Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether it is a fact that the Original alignment of the Patiala-Bhadson Road is now being changed ; if so, the reasons for the same ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** (1) Yes. The alignment is being changed at the starting point near Bhadson and between village Raimalmajri and Sadhnauli.

(2) The change is being made for the following reasons :—

(i) in order to prevent splitting of good agricultural land near village Bhadson ;

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4) 21  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

- (ii) the original approved alignment touched the outskirts of Bhadson town and covered the Agricultural Fertile land measuring 4.9 acres as against 0.91 acres only under the changed alignment.

---

**Roads constructed in the State**

**\*9125, Pandit Chiranji Lal Sharma:** Will the Minister for Public work be pleased to state the details of the roads constructed by the Government from April, 1962 to January, 1966 in the State, districtwise and the amount spent on each road alongwith the year of its construction.

**Chaudhri Ranbir Singh :** A statement is laid on the table of the House.

[Public Works Minister]

## Statement showing roads built from 1962 to 1966

Serial No.	Name of Road	Total length (Miles)	Length Metalled During				Total cost upto September, 1965 (Rs lacs)
			1962-63	1963-64	1964-65	1965-66 upto 30th September, 1965	
1	2	3	4	5	6	7	8
DISTRICT GURGAON							
1	Dharuhera-Shahjahanpur	..	15.75	Completed			18.50
2	Rewari-Pataudi	..	3.00	Completed			7.24
3	Gohana-Sikrawa	..	0.50	Completed			7.12
4	Bhadas-Sikrawa	..	0.50	Completed			7.84
5	Ferozepur Jhirka-Tijara	..	0.75	1.12	Completed		3.80
6	Chhajju Nagar-Rasulpur	..	2.25	Completed	Completed		2.19
7	Ferozepur Jhirka-Bhiwan Pahari	..	5.00	3.92	Completed		6.61
8	Village Lissan to Dahina Jastusana Road	..	..	..	0.75	1.25	0.79
9	Dahina-Jastusana	..	..	..	4.00	2.25	1.67
10	Gobindpuri-Nangal Mundi	..	..	..	5.75	0.25 Completed	0.09
11	Mamaria-Thatar to village Mayan	..	..	..	..	3.00 Completed	0.81
12	Rewari-Mohindergarh via Kaiuna	..	7.50	Completed	Completed		17.42

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)23  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45.

DISTRICT ROHTAK

1	Matenhale-Jharli Bahu Road	11.80	1.00	..	..	2.54
2	Chhara-Bahadurgarh	12.90	1.88	3.62	2.40	2.25
3	Gohana-Bhainswal	7.05	2.88	..	0.87	..
4	Gohana-Lakhan Majra	15.33	2.00	1.00	4.45	7.75
5	Mile 28 of G.T. Road to village Jatheri	..	2.20	2.20	Completed	1.09
6	Village Pipli Khara to G.T. Road	..	0.72	0.72	Completed	0.28
7	Gurgaon-Jhajjar Road	13.30	4.00	4.00	Completed	4.54
8	Mohindergarh-Kaina Lukhi-Nahar Road (in Rohtak District)	1.82	..	1.82	Completed	1.75
9	Ganaur-Shahpur Road, Section-Khubru Shahpur	4.46	..	..	0.96	2.00
10	Gohana-Jind	10.25	..	..	..	2.25
11	Sasrauli-Kaltwas	6.98	..	..	..	6.98
					Completed	2.24
12	Jhajjar-Subana	10.83	..	..	..	3.00
13	Jhajjar-Badli	8.44	..	..	..	1.70
14	Kosli-Gurian	4.60	..	..	..	4.60
					Completed	1.78

DISTRICT HISSAR

1	Link road connecting Tosham-Hissar Road to village Daiman	0.80	0.80	Completed	..	0.75
2	Barwala-Agroha mile 11 to 15.87	5.87	0.50	..	2.87	1.50
3	Pabra-Sarsaund	7.32	0.32	Completed	..	Completed
					..	7.28

## [Public Works Minister]

Serial No.	Name of Road	Total length (Miles)	Length Metalled During				Total cost up to September, 1965 (Rs lacs)
			1962-63	1963-64	1964-65	1965-66 up to 30th September, 1965	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Bhiwani Kheri to Garhi	..	2.33	2.67	Complete d		7.60
5	Balsmand-Bhadra	..	..	1.25	1.75	..	1.26
6	Link road to vi age Papso from Hansi Tosham Road	..	1.25	Completed			0.38
7	Bhaini Pal to Agricultural Farm, Hansi	..	1.31	Completed			1.25
8	Kalanwali-Rori Road	..	0.50	Completed			9.57
9	Ding to D.H.S. Road	..	0.12	0.13	Complete		2.74
10	Tohana-Ratia	..	1.00	1.22	Completed		21.10
11	Ottu-Rania	..	1.50	0.50	2.50	Completed	2.46
12	Dabwali-Chutala Road to Barang Khera	..	1.31	Completed d		..	0.67
13	Link road from village Kanehri to mile 40/1 of Hissar-Barwala-Tohana Road	0.38	0.38	Completed		..	0.35
14	Jhumpa Kalan-Bahal-Kairu Road	..	..	3.00	14.25	4.41	17.76
15	Tosham-Siwani Road	..	..	1.78	6.92	10.46	11.33
16	Rori-Sardulgarh	..	..	0.60	Complete		0.54
17	Sirsa-Ellanabad	..	..	..	2.00	1.75 +1.00	3.36

(4)25

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

18	Ludesar-Bhattu	..	15.19	..	2.25	1.19	Completed	15.14
19	Bhattu-Bhadra	..	8.63	..	..	1.00	0.75	1.92
20	Ratia-Rori	..	14.81	..	..	0.12	Completed	8.26
21	Barwala-Daulatpur	..	5.63	..	..	..	1.75	0.95
22	Tosham-Bahal	..	21.70	..	..	..	4.50	8.71
23	Manwal-Chichal Kotli	..	15.38	..	..	..	1.00	1.11
24	Rania-Chichal Kotli	..	6.40	..	..	..	3.00	2.20
25	Budhlada-Ratia	..	6.59	..	..	..	1.00	4.09
26	Link road, Mile 28 of Hissar-Tohana Road to Uklana-Mandi	..	3.24	..	..	..	1.00	0.79
DISTRICT KARNAL								
1	Panipat-Barsat Road	..	8.07	..	..	6.25	0.88	0.78
2	Assandh-Nikhuran	..	16.38	4.42	5.33	Completed	..	16.25
3	Village Rambato Indri-Ladwa Road	..	1.20	0.50	0.25	..	..	0.37
4	Kond-Munak Road	..	9.20	..	3.00	0.62	0.37	0.23
5	Chika-Tatiana Road	..	3.36	..	1.75	0.50	0.36 Completed	1.05
6	Pehowa-Dhand	..	6.18	..	3.00	3.18	Completed	3.79
7	Panipat-Sanauli	..	7.51	..	..	5.00	1.62	6.64
8	Pehowa-Gulah	..	16.80	7.00	Completed	..	..	10.35
9	Jhansa-Thol	..	5.45	1.00	..	2.00	..	3.20
DISTRICT AMBALA								
1	Kurali-Siswan	..	10.10	2.00	1.75	1.00	..	4.98

[Public Works Minister]

Serial No.	Name of Road	Total length (Miles)	Length Metalled during					Total cost up to September, 1965 (Rs lacs)
			1962-63	1963-64	1964-65	1965-66 up to 30th September, 1965	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Panjore-Nalagarh	..	23.00	4.25	5.00	8.00	Completed	20.36
3	Link road to Khanpur Garden Colony	..	1.03	1.03	Completed			0.57
4	Mubarikpur-Rangarh Road	..	3.10	3.00	0.10	Completed		3.08
5	Ambala-Jagadhri	..	24.40	2.90	0.50	Completed		14.71
6	Mohri-Kesri Road	..	3.90	1.75	0.15	Completed		3.12
7	Jagadhri Bye-pass	..	1.37	1.37	Completed	..		0.85
8	Chhajju-Majra-Raipur Rani, Mile 6—9	..	3.00	2.25	0.25	0.50	Completed	2.71
9	Mullanpur to Kurali-Siswan Road	..	3.50	..	..	0.75	0.50	0.93
10	Sadhaura-Bilaspur	..	7.44	..	..	0.69	Completed	5.08
11	Rangilpur-Mianpur	..	1.84	..	..	..	0.62	0.15
DISTRICT LUDHIANA								
1	G.T. Road Bye Pass, Ludhiana	..	5.38	0.13	Completed		..	5.30
2	Pail Ghurani-Dehlon, mile 7.58—13.23	..	5.70	..	..	4.70	0.75	3.00
3	Chokiman-Swadi-Bhundri	..	9.09	1.75	0.25	1.50	1.00	0.41
4	Machhiwara-Rahon	..	5.38	1.87	..	1.38	0.38	4.02
							Completed	

(4)27

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

5	Samrala-Chawa	..	6.66	0.75	0.25	0.62	0.75	3.46
6	Link to village Sangatpura from mile 34 of Ludhiana-Chandigarh Road	..	1.44	1.44	Completed		..	0.88
7	Khanna-Bhari-Kheri	..	8.01	2.62	1.50	1.64	1.25	4.23
8	Halwara-Pakhawal	..	3.85	1.73	1.37	0.75	Completed	2.40
9	Approach to Sidhwan Kalan	..	0.78	0.78	Copmleted		..	0.42
10	Sidhwan-Mahtpur	..	2.32	0.75	0.75	..	..	1.20
11	Approach to Bhaini Sahib from mile 14/1 of Ludhiana-Samrala Road	..	1.46	1.46	Completed		..	0.53
12	Sahnewal-Dehlon Raipur Gujjarwal Road— (i) Section Sahnewal-Dehlon and Gujjarwal-Pakhawal (ii) Section Raipur Gujjarwal	..	10.47	..	..	1.84	1.75 — — 1.25 —	2.32
13	Jagraon-Raikot Road to village Johran	..	3.46	..	1.25	..	1.00	4.61
DISTRICT FERROZEPUR								
1	Abohar-Usmankhera	..	19.42	2.50	3.67	Completed		16.27
2	Abohar-Sitogana-Dabwali	..	33.38	3.63	2.16	3.88	..	13.35
3	Usmankhera-Siri Manga Nagar (19.42—21.98)	..	2.56	..	2.56	Completed		2.32
4	Dipsingwala to mile 21/4 of F.F. Road	..	8.00	3.25	..	..	..	2.13
5	Zira-Dharamkot Road	..	14.60	0.25	0.75	1.50	2.00	6.67
6	Ferozepur-Dodh Road	..	9.00	1.50	2.00	0.50	2.00	0.89
7	Bagapurana-Nathana-Bhucho Road	..	12.00	2.00	2.75	..	..	5.57
8	Badni-Ramgarh (mile 14—25.12)	..	12.12	..	0.12	Completed		8.77
9	Mukatsar-Bhatinda	..	18.00	..	0.50	Completed		11.95

[Public Works Minister]

Serial No.	Name of Road	Total length (Miles)	Length Metalled During				1965-66 upto 30th September, 1965	Total cost upto September, 1965 (Rs lacs)
			1962-63	1963-64	1964-65	1965-66 upto 30th September, 1965		
1	2	3	4	5	6	7	8	
10	Mukatsar-Dodh, 0—12·60	..	12·60	..	2·00	7·25	4·72	
11	Approach to Wahike Police Post	..	7·87	..	4·25	1·50	0·41	
12	Amrikhas-Midha	..	3·12	..	0·88	1·50	0·22	
13	Dudhike to Chuhar Chak	..	2·00	..	1·00	1·00 Completed	0·99	
14	Ferozepur-Fazilka Road to Nurshah Police Picket	..	3·72	..	..	2·00	0·26	
15	Dhudke-Deodhar	..	3·00	..	..	1·00	0·82	
DISTRICT JULLUNDUR								
1	Nurmahal-Talwan	..	24·84	1·62	Completed		18·68	
2	Adampur-Bhogpur	..	9·58	2·00	Completed		8·70	
3	Approach to village Shankar	..	3·00	0·25	Completed		1·91	
4	Bye-Pass at Phillaur	..	1·88	..	0·15	1·50	10·62	
5	G.T. Road Bye-pass to Suranasi	..	3·83	..	..	1·00	1·50	
6	Mehtapur-Sidhwan Road, Mile 5—9	..	4·00	..	1·00	Completed	3·20	
7	Rahon-Machhiwara	..	5·85	..	0·25	0·75	1·40	
8	Chitti-Lambra	..	3·25	..	1·75	..	2·22	

(4)29

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

9	Bhogpur-Bholath, Section mile 0.00—2.75	..	2.75 ..	..	..	1.62	0.75	3.27
10	Nurmahal-Kot Badal Khan	..	3.20	..	..	3.20	Completed	1.75
11	Dosanjh Kalan G.T. Road	..	5.00	..	..	2.50	1.00	1.77
12	Ludhiana-Rahon-Jadla	..	15.00	..	..	2.00	..	4.05
13	Phagwara-Mahalpur, Section Paldi-Sadhwan (5.44—6.68)	..	3.24	..	..	3.24	Completed	3.18
DISTRICT HOSHIARPUR								
1	Anandpur-Ferry approach	..	2.63	2.13	0.25	Completed	..	0.22
2	Garhshankar-Nurpur	..	23.08	1.50	..	..	1.00 Completed	15.10
3	Dasuya-Miani	..	9.54	3.25	..	..	0.75	5.95
4	Hamirpur-Nadaun-Mubarikpur	..	11.83	1.00	1.50	..	..	10.91
5	Mahalpur-Jajon	..	8.50	..	0.50	Completed	..	5.04
6	Haryana-Dholbaha Road to village Janauri	..	0.73	0.73	Completed	..	..	0.53
7	Una-Aghar-Mandi, section in Hoshiarpur District	..	4.05	3.00	1.00	0.05	Completed	3.95
8	Mahalpur-Phagwara, Section Paldi-Sandhwan, 0.00—5.44	..	5.44	4.00	0.75	0.69	Completed	1.17
9	Churu-Amb	..	7.24	3.00	0.24	Completed	..	6.84
10	Bye-pass at Hoshiarpur	..	3.08	..	3.08	Completed	..	3.01
11	N.H. No. 1-A to village Zahura	..	1.52	..	..	0.50	1.00 Completed	1.48
12	Churu-Chowkminar	..	2.77	..	..	2.00	0.77 Completed	2.65
13	Nurpur-Abiana	..	7.06	..	..	..	0.25	2.53

[Public Works Minister]

Serial No.	Name of Road	Length Metalled During					Total length (Miles)	Total cost up to September, 1965 (Rs lacs)	
		1962-63	1963-64	1964-65	1965-66 up to 30th September, 1965			1965-66 up to 30th September, 1965	September, 1965 (Rs lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8		
DISTRICT AMRITSAR									
1	Chhabal-Attari	..	16.38	0.25	4.03	1.00	Completed	10.13	
2	Pati-Khemkarn up to Valtoha	..	11.30	5.50	4.30	Completed	..	8.73	
3	Amritsar-Taran Taran Road to Verpal	..	1.50	1.50	Completed	..	..	0.80	
4	Gandiwind approach	..	0.75	..	0.75	Completed	..	0.68	
5	Sheron-Dhotian	..	6.75	..	4.00	1.75	0.50	3.14	
6	Khem Karan-Gajjal	..	5.34	..	..	1.50	0.50	2.20	
7	Bachhiwind Town to Bachhiwind	..	0.83	..	..	0.83	Completed	0.78	
8	Manj-Kakkar	..	2.09	..	..	1.00	Completed	0.75	
9	Gaggomahal-Chaharpur	..	1.30	..	..	1.30	Completed	0.75	
10	Punga-Barlas	..	2.69	..	..	1.60	1.00 Completed	1.36	
11	Ajnala-Balharwal	..	4.30	..	..	..	2.55	2.03	
12	Ramdass-Kamalpur	..	3.70	..	..	..	2.00	1.08	
13	Village Tungpain to Amritsar-Pathankot Road	..	0.40	..	..	..	0.25	0.10	
DISTRICT GURDASPUR									
1	Fatehgarh Churian Town to Derababa Nanak (up to Mullowal)	..	9.80	6.75	0.25	1.80	Completed	5.79	

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)31  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

2	Gurdaspur to Kahnuwan	..	9.37	4.25	0.25	..	..	5.44
3	Gurdaspur-Pandori Mahantan	..	6.50	0.75	0.50	2.00	Completed	6.25
4	Pathankot-Shahpur Kandi	..	8.00	..	..	4.50	1.00	2.75
5	Kala Afgana-Veela Teja	..	3.33	0.50	1.75	0.33	Completed	1.97
6	Dina Nagar -Galri	..	7.90	2.00	3.65	2.25	Completed	3.38
7	G.P.O., Dalhousie to Bhakrota	..	1.88	..	0.50	0.75	0.63 Completed	4.12
8	Kalanaur-Bodhwadala	..	3.90	..	..	1.00	1.96	2.33
9	Kalanaur-Qila Lal Singh	..	9.41	..	..	4.75	1.25	5.04
10	Durangla-Shahpur	..	0.88	..	..	0.88	Completed	0.86
DISTRICT KANGRA								
1	Dehra-Jawalamukhi	..	7.32	3.75	0.75	Completed	..	8.57
2	Palampur-Thural Road	..	13.00	1.13	4.25	2.50	..	11.88
3	Bilaspur-Aghar-Hamirpur, Section Hamirpur-Bhota, 0.88 to 9.00	..	8.12	2.00	3.62	1.00	0.37	9.52
4	Approach to Jawalamukhi Mandir	..	0.20	0.20	Completed	..	..	1.02
5	Nadaun-Hamirpur	..	16.75	..	8.75	0.25	Completed	26.96
6	Holta-Chadhiar (up to Rajpura)	..	2.50	..	0.50	Completed	..	2.84
7	Chambi-Dharamsala	..	10.00	..	0.50	2.38	..	7.50
8	Ahju-Bir (Section Punjab Boundry to Bir)	..	1.55	..	1.55	Completed	..	1.45
9	Nadaun-Jawar	..	15.00	..	..	1.25	..	5.00
10	Nurpur-Fatehpur Dhameta	..	22.00	..	..	..	4.00	4.64
11	Una-Aghar-Mandi Road	..	39.71	..	..	..	7.25	30.26

## [Public Works Minister]

Serial No.	Name of Road	Total length (Miles)	Length Mentalled During					Total cost up to September, 1965 (Rs lacs)
			1962-63	1963-64	1964-65	1965-66 upto 30th September, 1965		
1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Kangra to Tanda Sanatorium	..	2.00	..	..	2.00 Completed	1.80	
13	Yol-Dadh	..	3.66	..	..	0.66	2.43	
14	Dharamsala-Yol	..	4.22	..	..	0.2	5.20	
DISTRICT KULU								
1	Left Bank Road Kulu to Manali (Jeepable Road)	..	25.00	2.50	6.75	1.25	0.25	5.90
2	Bhuntar-Mainkaran (Jeepable Road)	..	21.00	4.25	5.00	0.25	..	..
3	Manali-Kotli-Rahla	..	11.50	..	6.50	4.50	..	12.84
4	Raison-Manali Right Bank Road	..	16.00	..	16.00	Completed	..	11.17
5	Link Road from Hindustan-Tibet Road to Nirmand (Jeepable Road)	..	9.00	..	2.50	6.00	1.00	2.74
DISTRICT LAHAUL AND SPIT								
1	Gramphoo-Koksar (Truckable Road)	..	2.34	0.75	0.09	Completed	..	2.25
2	Koksar-Keylong (Truckable) Road	..	26.62	2.25	3.62	5.62	0.50	7.36
3	Tandi-Throat (Jeepable)	..	19.27	3.50	2.00	4.25	2.00	5.79
4	Batal-Kunzampass (jeepable road)	..	6.95	1.00	1.62	1.38	..	5.28

5	Khunzampass-Lossar (Jeepable Road)	..	11.95	..	..	9.00	..	13.72
6	Lossar-Kiato (Jeepable Road)	..	8.84	..	..	8.84	Completed	2.58
7	Kiato-Hull (Jeepable Road)	..	11.50	2.00	9.50	Completed		10.76
8	Hull to Rangrik Bridge (Jeepable Road)	..	11.55	..	10.30	Completed		11.40
9	Rangrik-Kibber (Jeepable Road)	..	9.78	..	..	0.10	3.75	4.59

Note.—Roads at serial Nos. 4 to 9 are also being widened to Truckable Road and the work is in progress.

#### DISTRICT SIMLA

1	Boileauganj-Tavi Road	..	0.54	..	..	0.54	Completed	0.93
2	Waknaghat-Sabathu Road (Motorable Road)	..	21.28	..	4.00	4.00	..	6.77
3	Totu-Badheri-Sabathu (Motorable Road)	..	22.60	..	4.50	6.00	2.00	13.17
4	Mamligh-Bill (Motorable Road)	..	4.41	..	2.00	1.00	1.00	3.70
5	Solan-Jaunaji-Kotla -Gaura (Motorable Road)	..	11.40	2.00	4.00	2.00	2.00	4.07

Note.—Roads at item Nos. 2 to 5 have since been completed as motorable roads, but ultimately these are to be metalled and black topped.

#### DISTRICT PATIALA

1	Pail-Ghurani-Dehlon in Patiala, 3.56—7.58	..	4.02	0.75	Completed	Completed	3.88
2	Approach to village Lal Kalan	..	0.87	0.75	0.12	Completed	0.40
3	Patiala-Bhadson	..	15.18	..	..	0.50	2.00
4	Patiala-Panjola-Chika, 0.75—14.65	..	13.80	..	4.00	0.50	..
5	Patiala-Sirhind	..	17.32	3.32	1.00	Completed	10.39
6	Bhawani arh-Samana—Section 4.00—12.73	..	9.73	1.37	2.00	2.36	..
7	Samana-Guhla	..	7.06	1.00	2.25	0.50	0.40

14.11

## [Public Works Minister]

Serial No.	Name of Road	Total length (Miles)	Length Metalled during				Total cost upto September, 1965 (Rs lacs)
			1962-63	1963-64	1964-65	1965-66 up to 30th September, 1965	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Link to village Chelala	..	..	..	1.12	0.25	0.9
9	Bye-Pass Rajpura	..	2.12	..	Completed	..	2.05
DISTRICT SANGRUR							
1	Sunam-Jakhal	..	23.02	6.75	2.00	1.75	15.80
2	Badber-Longowal	..	4.06	1.25	1.50	Completed	1.33
3	Bye-Pass at Malerkotla	..	2.03	1.50	Completed	..	2.55
4	Link to village Ram Rai	..	0.35	0.35	Completed	..	0.29
5	Uklana-Narwana	..	14.30	3.32	1.30	Completed	8.90
6	Jind-Pindu-Pindara	..	3.05	2.25	0.75	Completed	1.87
7	Kalait-Mataur	..	3.43	3.25	0.18	Completed	1.61
8	Jind-Rohtak	..	19.32	0.75	Completed	..	14.22
9	Pakhoke-Ramgarh	..	9.20	..	0.75	Completed	7.01
10	Link to village Haidar Nagar	..	1.67	1.67	Completed	..	0.56
11	Jind - Gohana	..	13.40	..	1.75	4.00	6.85
12	Link to Sunam from mile 41/6 of S.B.T.S. Road	..	0.49	..	0.49	Completed	0.47
13	Barnala-Sanghara	..	1.24	..	..	1.24 Completed	0.28

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)35  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

DISTRICT BHATINDA

1	Village Jassi to Bhatinda-Dabwali Road	..	0.30	..	..	0.30	0.13
2	Budhlada-Ratia	..	14.23	5.75	3.23	Completed	7.76
3	Budhlada-Jakha, 10.00—18.25	..	18.25	5.12	2.00	5.50	11.47
4	Bhatinda-Muktsar	..	11.20	0.60	Completed	2.00	6.70
5	Talwandi Sabo-Rori	..	12.75	4.00	..	2.00	6.61
6	Rampura Phool-Maur Road	..	14.10	0.10	Completed	..	13.10
7	Baghapurana-Nathana-Bhucho	..	16.00	2.50	0.50	..	7.27
8	Link Road to Lahra-Mohbatt Railway Station	..	1.43	1.00	..	..	0.41
9	Hari Singhwala-Sardulgarh	..	26.00	1.50	Completed	..	25.50
10	Bhikhi-Dhanaula	..	3.75	2.00	1.00	0.75	0.69
11	Rori-Sardulgarh	..	2.73	..	1.28	1.45	2.68
12	Talwandi Sabo-Rori	..	7.0	..	..	1.00	6.08
13	Muktsar-Dodh, 12.60—20.00	..	7.4	..	..	1.50	1.50
14	Ratia-Sardulgarh	..	7.56	0.50	0.21	..	2.35
15	Kheowali-Badala Gudda	..	8.32	..	..	..	1.67

DISTRICT KAPURTHALA

1	Degowal-Miani	..	2.98	2.00	Completed	2.42
2	Nadala-Begowal	..	8.50	1.25	5.00	Completed
3	hogpur-Bholath (Section file 2.75—8.30)	..	5.55	..	1.00	3.28

## [Public Works Minister]

Serial No.	Name of Road	Total length (Miles)	Length Metalled during				Total cost up to September, 1965 (Rs lacs)
			1962-63	1963-64	1964-65	1965-66 upto 30th September, 1965	
1	2	3	4	5	6	7	8
			DISTRICT MOHINDERGARH				
1	Kanina-Ateli	16.50	..	1.50	5.50	2.00	10.6
2	Mohindergarh-Satnali-Bhadra Jiri	34.09	..	..	2.00	7.75	12.57
3	Jetwar-Dalot	6.75	..	..	0.50	5.00	2.21
4	Dadri-Loharu in Mohindergarh	25.94	6.44	2.50	Completed	Completed	20.18
5	Mohindergarh-Kanina-Lukhi-Nahar	17.33	..	2.33	..	..	8.92
6	Narnaul-Nizampur	8.63	1.13	Completed	Completed	Completed	2.47
7	Rewari-Mohindergarh via Kanina	3.34	3.34	..	..	..	4.78
8	Dadri-Chirya Road	8.62	..	..	..	8.00	2.60
9	Village Ghosala to Dadri -Mohindergarh	0.59	..	..	..	0.59	0.16
10	Chapar-Atela Road	2.84	..	..	..	Completed 2.84	0.81
11	Faizabad-Seema-Kanina Road	17.91	..	..	..	Completed 4.00	4.47
12	Nizampur-Nangal Chowdhri	10.33	..	..	..	5.33	2.7
13	Nasibpur-Dharson	3.00	..	..	..	1.25	0.34
14	Narnaul-Kultajpur	3.94	..	..	..	1.50	1.24
15	Ateli Mandi-Narnaul-Rewari Road	0.38	..	..	..	0.38	0.08
		..	..	..	..	Completed	..

**Location of Courts functioning at different places at Sonapat**

**\*9127. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

- (a) whether he is aware of the fact that the courts in Sonapat are situated at two places and the distance between the two places is over a mile and the lawyers and the litigants experience great inconvenience on that score ;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether it is a fact that Government have received several representations from the Sonapat Bar Association for locating all the courts at one place at Sonapat ;
- (c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the date when the last representation in this connection was received and the action, if any, taken thereon ;
- (d) whether it is fact that the former Public Works Minister, and now Irrigation and Power Minister had written a note to the Department for location of the Courts at Sonapat at one place ; if so, the date when it was written and the action taken thereon ;
- (e) whether it is a fact that he also paid a visit to Sonapat at the request of the Bar Association and heard the grievances of the Bar Association personally in the Bar Room in December, 1965 ;
- (f) if the reply to part (e) above be in the affirmative, the details of the measures proposed to be adopted to consolidate the courts at one place and the name of the place where the new Court building is proposed to be constructed ;
- (g) whether any land has been acquired for the purpose ; if not, whether the Government propose to acquire it now ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** (a) Yes.

(b) The members of the Bar Association have been pointing out their difficulties off and on in this respect.

(c) The Bar Association represented to the Public Works Minister on his last visit to Sonapat on 20th December, 1965.

(d) Yes, on 19th May, 1965. The matter was under consideration when Emergency was declared and consequently ban was imposed by Government on the construction of new buildings.

(e) Yes.

(f) On account of emergency it has not been considered desirable to incur expenditure on new buildings. However, the suggestion to the effect that the S.D.M.'s new Court be located in a portion of his residential building and the existing S.D.M.'s Court building may be utilized for locating the Court of Sub-Judge is under examination in consultation with various departments.

(g) In view of the remarks against (f) above, question does not arise.

**Road from Dev Ban to Nagura in Tehsil Kaithal, District Karnal.**

**\*9244, Shrimati Prasanni Devi :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

- (a) whether there is any scheme under the consideration of the Government to construct a pucca road from Dev Ban to Nagura in tehsil Kaithal, district Karnal ;

[Shrimati Prasanni Devi]

- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the date by which the said Scheme is expected to be implemented ?

**Chaudhri Ranbir Singh :** (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

### Collection of Water Charges at Chandigarh

**\*9225. Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Minister for Capital and Housing be pleased to state—

- (a) the total number of private individuals or consumers of water in Chandigarh who are required to pay their water supply charges in cash to the Assistant Accounts Officer, Capital Project, Division 3, Chandigarh ;
- (b) whether it is a fact that all such consumers are required to pay their water supply charges bills at one place and at one counter only ;
- (c) whether it is a fact that the payment of such charges by money order, cheque or draft is not allowed ;
- (d) whether the Government is aware of the hardships of the water consumers in having to pay the water charges bills in cash at one counter after waiting in a queue for hours together ;
- (e) if the reply to part (d) above be in the affirmative, whether the Government proposes to redress the grievance of the Chandigarh public by allowing payment by money order or cheques or bank drafts ?

**Sardar Prem Singh Prem :** (a) 12,100 (including Government Servants living in private houses) ;

(b) No.

(c) No. Payments by money order and drafts except cheques, are allowed.

(d) Additional staff is deputed to assist the Cashiers as and when there is a rush. Besides, a period of 15 days is allowed to consumers for making payments from the date of presentation of the bills but the general tendency found among consumers is that they come to make payments on the last dates which creates rush.

(e) Payments by money orders and drafts, except cheques, are already accepted.

### Enquiries against Excise and Taxation Commissioners

**\*8899. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister with reference to the reply to Starred Question No. 8607 included in the list of questions for 18th October, 1965 be pleased to state—

- (a) whether the enquiries which were under investigation and were expected to be completed within two months, as stated in reply to parts (b) and (e) of the said question, have since been completed ; if so, when, if not, the reasons therefor ;
- (b) the result of enquiries or the details of the enquiries, if completed, be laid on the Table of the House ;
- (c) whether any action against the officers/officials, if found/held responsible for committing the irregularities, has since been taken ; if so, the details thereof and if not taken, the reasons therefor ;

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)39  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

- (d) whether any officials who were found to have been favoured or ignored due to the irregularities of certain officers, if proved, have been dealt with according to the findings of the Enquiry Officers ; if so, the details thereof ; if not dealt with accordingly, the reasons therefor ;
- (e) the names and designations of the officers to whom enquiries referred to in part (a) of the said reply were entrusted on tenth August, 1964 and 16th September, 1964 ?

**Shri Ram Kishan :** A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) No ; the reasons are that most of the relevant record has been taken back from the Special Inquiry Agency by the Administrative Department in connection with a threatened civil suit. Besides, the officer concerned remained on leave and certain points needing clarification at his end could not be dealt with. Further, on account of reduction in the staff of the Special Inquiry Agency with effect from 31st December, 1965 the officer who was investigating the enquiries has been transferred. The investigation had, therefore, to be entrusted to another officer who had to go through the voluminous record before going ahead with the investigation.

(b), (c) and (d) Does not arise in view of (a) above.

(e) It is not in the public interest to disclose the names and designations of the officers to whom enquiries were entrusted.

Report of Administrative Reforms Commission

**\*9139. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total expenses incurred so far on the members and the staff of the Administrative Reforms Commission as regards their salaries, allowances, travelling and halting allowances, etc., separately ;
- (b) whether the said Commission has submitted its final or any interim report so far ; if so, the main contents of the reports submitted be laid on the Table of the House ;
- (c) whether the said recommendations have been examined by the Government ; if so, the reaction of the Government over the said report and extent to which the recommendations have been implemented ; if the recommendations mentioned above have not been examined, the reasons therefor and the time by which the same are likely to be examined ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Members : Rs. 44,229.23  
Staff : Rs 1,40,122.84

(b) Not yet.

(c) Does not arise.

Jeep gifted to S.D.M., Malerkotla

**\*9142. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that a Seth gifted one jeep No. PNC 5001 to the S.D.M., Malerkotla, during the year 1963 ; if so, the conditions on which the said jeep was accepted by the latter ?

Shri Ram Kishan : No. Sir.

**Expenses incurred by Ministers on Cars, Electricity, Water Charges  
and Entertainment**

**\*9204. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount spent by the Government on each of the Ministers in respect of the following items during the year 1965 :—

- (i) car allowances, including the expenses incurred on the salaries of drivers, petrol and other incidental charges ;
- (ii) electric bills ;
- (iii) water bills ;
- (iv) entertainment of guests, etc. ?

**Comrade Ram Kishan :** (i), (ii) and (iii) A statement is laid on the Table of House  
(iv) Nil.

**STATEMENT**

Statement showing the information in respect of Starred Assembly Question No. 9204

Serial No.	Name and designation of the Minister	Expenditure incurred during the year 1965, in respect of car allowance including the salaries of drivers, Petrol and other incidental charges	Expenditure incurred during the year 1965, on the consumption of electricity at the residence of the Minister	Expenditure incurred during the year 1965, on the consumption of water at the residence of the Minister
1	2	3	4	5
		Rs	Rs	Rs
1	Com. Ram Kishan, Chief Minister	16,350.97	2,550.20	377.00
2	Shri Darbara Singh, H.D.M. ..	16,288.19	1,395.31	445.00
3	Shri Prabodh Chander, E.M. ..	12,982.89	1,430.64	303.00
4	Shri Kapur Singh, F.M. ..	12,156.57	1,329.32	303.00
5	Shri Gurdial Singh Dhillon, T.E.M.	7,102.49	533.86	297.00
6	Shri Ranbir Singh, P.W.M. ..	8,211.71	491.83	192.00
7	Shri Ajmer Singh, P.L.G.M. ¶ ..	7,828.25	575.76	144.70
8	Shri Harinder Singh, R.M. ¶ ..	11,374.32	2,204.61	347.00
9	Shri Rizak Ram, I.P.M. ..	10,931.09	1,260.25	320.30
10	Shri Prem Singh Prem, C.H.M. ..	5,612.09	410.61	249.00
11	Shri Chand Ram, W.J.M. ...	6,210.42	498.97	80.90

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)41  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45**

1	2	3	4	5
12	Smt. Om Prabha Jain, H.M. ..	6,094.33	364.01	148.90
13	Shri Sunder Singh, M.E.P.L. ..	9,064.60	677.17	168.00
14	Capt. Rattan Singh, M.A.H.A. ..	7,204.73	565.04	38.60
15	Smt. Chandravati, D.M.F.S. ..	6,142.51	411.19	66.00
16	Shri Gurmit Singh, D.M.D.I. ..	8,154.54	717.00	49.40
17	Shri Gian Chand Toto, D.M.I.H.	7,696.95	270.94	85.00

**Days spent by Ministers in the Capital, etc.**

**\*9205. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of days spent by each Minister (i) in Chandigarh, (ii) in the other parts of the State and (iii) outside the State during the year 1965 ?

**Shri Ram Kishan :** A statement is laid on the Table of the House.

**Statement showing the number of days spent by each Minister in Chandigarh, in the other parts of the State and outside the State during the year 1965**

Serial No.	Name of the Minister	Number of days spent by each Minister during the year 1965		
		In Chandi- garh	In other parts of the State	Outside the State
1	2	3	4	5
1	Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab	206	76½	82½
2	Shri Darbara Singh, Home and Development Minister	234½	75	55½
3	Shri Prabodh Chandra, Education Minister	254	91½	19½ (Upto Novem- ber, 1965)
4	Shri Kapur Singh, Finance Minister ..	237½	85½	42 (Upto Novem- ber, 1965)

[Chief Minister]

1	2	3	4	5
5	Shri Gurdial Singh Dhillon, Transport and Elections Minister	131	59	19 (Upto November 1965)
6	Chaudhri Ranbir Singh, Public Works Minister	78	97	34
7	Shri Ajmer Singh, Planning and Local Government Minister	117½	80½	11
8	Shri Harinder Singh, Revenue Minister ..	207	130	28
9	Ch. Rizaq Ram, Irrigation and Power Minister	253	73	39 (Upto 2nd December, 1965)
10	Shri Prem Singh Prem, Capital and Housing Minister	140	51	18
11	Shri Chand Ram, Welfare and Justice Minister	130½	90½	15
12	Shmt. Om Prabha Jain, Health Minister ..	115½	41½	52
13	Ch. Sunder Singh, Minister of State for Excise, Partition, Welfare and Labour	234	92½	38½
14	Captain Rattan Singh, Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture	104	98½	15½
15	Shmt. Chandravati, Deputy Minister, Food Supplies	123½	47	38½
16	Shri Gurmeet Singh, Deputy Minister, Development and Irrigation	121½	75½	12
17	Shri Gian Chand, Deputy Minister, Industries and Hilly Areas	12½	62½	18½

**Complaints received by Director of Public Grievances, Punjab, during 1965**

**\*9109. Dr. Baldev Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the detailed procedure, if any, laid down for the working of the Directorate of Public Grievances in the State ;
- (b) the total number of complaints received by the office of the Director of Public Grievances, in the year 1965 and the number of complaints out of those finally disposed of in 1965 ?

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)43  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

**Shri Ram Kishan :** (a) The Order of the Government Punjab, dated 25th October, 1965 on the working of Grievances Department is laid on the Table\* of the House.

(b) 208 complaints were received during 1965. Most of these complaints were of routine nature and were forwarded to proper quarters for disposal. Only 72 cases were taken up by the Director of Grievances with concerned authorities, out of which 33 were finally disposed of in 1965.

— — — — —  
**Starting intensive Rural Industrialisation Project in certain Blocks  
of tehsil Una, district Hoshiarpur**

**\*9094. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether the Government has received any representation for the starting of an Intensive Rural Industrialisation Project in the Gagret and Amb Blocks of tehsil Una, district Hoshiarpur, if so, the action, if any, taken thereon ;
- (b) whether the Government is aware of the fact that tehsil Una is a backward hilly area and needs intensive rural industrialisation with a view to provide adequate employment to the people of this area which, as at present cannot provide adequate means of livelihood for its entire population ;
- (c) whether the Government intend to start such Projects during the fourth Plan period ; if so, whether such a Project is likely to be started in tehsil Una ;
- (d) the details of other steps the Government propose to take to industrialise this backward hilly area ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes. Action will be taken as and when the State Government is asked to recommend new places for additional projects, by the Government of India.

(b) Yes.

(c) This is a centrally sponsored scheme and as such State Government cannot indicate whether Una will be selected during the Fourth Plan.

(d) A number of schemes already started in Una Tehsil are given in the attached statement which is laid on the Table of the House.

**STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE SCHEME ALREADY STARTED  
IN UNA TEHSIL.**

- (i) Rural Industrial Development Centre, Una.
- (ii) A Common Facility Workshop in Blacksmithy and Carpentry.
- (iii) A Bamboo Demonstration Party.
- (iv) A Weaving Demonstration Party.
- (v) A Rural Industrial Estate (under construction).

In addition to above loans and subsidies under the State Aid to Industries Act and all other facilities available to new industries all over the State such as technical know-how raw material quotas etc., are available to this area.

---

**\*Note.—Kept in the Library.**

### Proposal to set up a Pig Iron Plant in Hissar District

**\*9150. Shri Ram Saran Chand Mittal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Planning Commission has decided to abandon the plan to set up a Pig Iron Plant in Hissar District ; if so, the date when that decision was taken ;
- (b) whether for the utilisation of the iron ores of tehsil Narnaul, district Mahendergarh, the Government would permit or recommend to the Government of India to permit any other party to set up such a plant in Tehsil Narnaul ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Government have no knowledge. No such decision has so far been communicated.

(b) No. The proposal to set up a Pig Iron Plant in the Public Sector is based on the iron ore deposits of the Mahendergarh.

### Junior Industrial Schools in the State

**\*9218. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether he is aware of the fact that there is no Junior Industrial School for boys in the entire Amb Constituency which is a back ward hilly area ;
- (b) whether the Government propose to start such a school in the said area during the Fourth Five-Year Plan period in order to provide employment opportunities to the large number of unemployed people of the area ;
- (c) the number and the detail of such schools in the State, tehsil-wise ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes.

(b) and (c) No. In fact no such institution is functioning anywhere in the State.

### Supply of Kerosene Oil in Rural Areas of Hoshiarpur District

**\*9098. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the quantity of kerosene oil allocated and distributed to the people of the rural areas in Hoshiarpur District, block-wise during the period from September, 1965 to January, 1966 ;
- (b) the quantity allocated and distributed to the people of the towns in the said district during the said period ;
- (c) the quantity of kerosene oil allowed to each individual in the rural and urban areas separately ;
- (d) whether the supply of kerosene oil was made in each of the villages on the basis of the sanctioned quantity ;
- (e) the population of Gagret and Amb blocks in Hoshiarpur District and the quantity of kerosene oil which each such block was entitled to get on the basis of sanctioned

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)45  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45**

quantity to each individual and the actual quantity received by each block during the period referred to in part (a) above ;

- (f) whether he is aware of the fact that great difficulty is being experienced in the blocks referred to in part (a) above due to non-supply or inadequate supply of kerosene oil; if so, the steps the Government propose to take to remove the difficulty ?

**Shri Ram Kishan :** The reply is laid on the Table of the House.

(Regular allocation and distribution were started from 26th November, 1965. Hence figures are for the period from 26th November, 1965 to the 31st January, 1966).

(a) All told, 1,88,512 litres of kerosene was allocated for distribution in rural areas to the Co-operative Agencies. Out of this, the following stock was allocated and distributed in various blocks :—

Serial No.	Name of blocks	Allocation (in litres)	Distribution (in litres)
1	Mahlpur	4,878	4,878
2	Balachaur	6,246	6,246
3	Seroya	3,438	3,438
4	Garhshankar	4,518	4,518
5	Nurpur Bedi	4,734	4,734
6	Anandpur	29,200	29,200
7	Una	27,400	27,400
8	Garget	11,073	11,073
9	Amb	11,073	11,073
10	Hoshiarpur-I	13,602	13,602
11	Hoshiarpur-II	13,610	13,610
12	Banga	13,606	13,606
13	Tanda	1,386	1,386
14	Dasuya	6,804	6,804
15	Mukerian	3,044	3,044
16	Hajipur	3,040	3,040
	Total	1,57,652	1,57,652

The remaining stock of 30,860 litres was surrendered by the Co-operative Agency.

(b) Allocation .. 1,07,523 litres  
Distribution .. 1,38,383 litres

(Chief Minister)

The excess of 30,860 litres was diverted from rural areas to towns as surrendered by the Co-operative Agency.

- (c) Urban areas .. 4 litres per month per family.  
Rural areas .. One litre per month per family.

(d) No.

(e) Population of Amb and Garget Blocks is about fifty thousand each. According to the sanctioned scale each block was entitled to get 21,666 litres. As against this 11,073 litres were received by each Block from 26th November, 1965 to 31st January, 1966.

(f) Kerosene was in short supply in the wake of Indo-Pak hostilities. Now the supply position has improved considerably so much so that 30,860 litres were surrendered by the co-operative Agency recently. Government is taking action along the following lines :—

- (i) Close liaison is being kept with the Union Ministry of Petroleum and Chemicals for adequate allocations to the State ;
- (ii) Close liaison is being kept with the Oil Companies to ensure maximum movement of stocks against the allocations to the Hoshiarpur District.
- (iii) Distribution of kerosene will be continued on the sugar distribution cards to ensure equitable distribution.
- (iv) Deputy Commissioners have been asked to make available larger supplies of kerosene in the rural areas.

#### Complaint against Sub-Inspector, Civil Supplies, Dhatauli Barrier near Ghanaur, tehsil Sonapat

\*9128. Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether the Government/the Deputy Minister, Civil Supplies, received any complaint in April or May, 1965 from the residents of villages Shahpur Tanga, Kheri Tanga and Ghasoti etc. in tehsil Sonapat against the Sub-Inspector Civil Supplies, posted at Dhatauli Barrier near Ghanaur ; if so, the nature of the complaint so made ;
- (b) whether any such complaint was also forwarded to the Deputy Minister with a forwarding letter by any Legislator of Rohtak District ;
- (c) if the reply to parts (a) and (b) above be in affirmative, whether any enquiry was made into the said complaint ; if so, the action taken thereon ;
- (d) whether any complaint against the same official was also received by Deputy Commissioner, Rohtak District ;
- (e) whether it is fact that the D. S. P., Sonapat, personally went to Dhatauli Barrier to enquire into the complaint of falsely implicating a resident of village Shahpur Tanga in a case under the Essential Commodities Act ?
- (f) if the reply to part (e) above be in the affirmative, whether the said case registered against the resident of Shahpur Tanga was subsequently cancelled or sent untraced by P. S. Ghanaur, after the enquiry by the D. S. P., Sonapat ;
- (g) if the reply to part (f) above be in affirmative, whether any action was taken against the official concerned who was

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)47  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

responsible for getting a false case registered ; if so, what, and if no action has been taken, the reasons thereof ?

**Shri Ram Kishan :** (a) No complaint was received in April and May, 1965. However, the complaint was received in October, 1965 against Shri Ram Singh, Sub-Inspector, Food and Supplies, about his bad reputation/unnecessary harassment of villagers in connection with detection of smuggling case.

(b) Yes.

(c) Yes. The complaint against the Sub-Inspector, Food and Supplies was found to be baseless.

(d) Yes.

(e) Yes.

(f) Yes.

(g) Police investigation did not reveal any malafide on behalf of the Sub-Inspector, Food and Supplies, and therefore no action was taken against him.

**Wheat purchased/exported by Government in 1965**

**\*9151, Shri Ram Saran Chand Mittal :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total quantity of wheat produced in the State during the year 1965 ;

(b) the total quantity of wheat purchased and brought in the State in 1965 out of the wheat imported by the Government of India from the foreign countries ;

(c) the total quantity of wheat out of the wheat mentioned in parts (a) and (b) above separately which was consumed in the State in 1965 ;

(d) the total quantity of wheat produced in the State which was sent by the State Government or allowed to be sent by the Government to other States or places outside the Punjab in 1965 ;

(e) the price of wheat produced in the Punjab and of that imported from the foreign countries in 1965 ;

(f) whether the local wheat was costlier or cheaper than the foreign imported wheat; if so, the average differences between their prices

(g) whether it is a fact that the Punjab produced more wheat than it actually consumed in 1965 ;

(h) if the answer to part (g) above be in the affirmative, the reasons why the imported wheat or its atta is brought in the State and sold to the public by the Government through its Fair Price Shops instead of the local wheat ;

(i) whether it is a fact that by the introduction of statutory rationing in the Union territory of Delhi, the supply of local wheat to Delhi by Punjab has been reduced; if so, to what extent ?

**Shri Ram Kishan :** A statement is laid on the Table of the House.

[Chief Minister]

## STATEMENT

*Wheat purchased/ exported by Government in 1965*

- (a) About 33.99 lakh tonnes.
- (b) 1.58 lakh tonnes (1.40 lakh tonnes by the Roller Flour Mills in Punjab and about 18,000 tonnes by State Government.)
- (c) Information not available.
- (d) 1.59 lakh tonnes,
- (e) Average purchase price of country wheat (F.A.Q.) Rs 50.81 per quintal and of imported wheat, received from Government of India Rs 48.00 per quintal up to the middle of November, 1965, and Rs 50.00 per quintal, thereafter.
- (f) Yes, the country wheat was costlier by Rs 1.81 per quintal (excluding incidental charges).
- (g) Yes.
- (h) The Roller Flour Mills in the State are permitted by the Government of India to grind only imported wheat. The Mills are allotted their quotas of imported wheat by the Government of India. Wholemeal mill atta produced by the Mills is made use of and distributed through depots when the prices of country wheat go up in the open market. Some of the consumers then prefer imported wheat atta, as its price is lower than that of country wheat atta and consequently there is demand for this cheaper atta at the Fair Price Shops. The mills also produce fines like maida, and suji out of the imported wheat. The disposal of these products is regulated by the Government.
- (i) Yes, by about 20,000, 25,000 tonnes wheat per month on the average for the year.

**Requisitioning of a house at Amritsar**

**\*8932 Sardar Kulbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether it is fact that a house opposite to the residence of the the Deputy Commissioner, Amritsar, has recently been requisitioned ; if so, copies of two notices served for the purpose of requisitioning the said house be laid on the Table of the House
- (b) whether it is also a fact that the orders requisitioning the said house were served on persons other than the actual owners; if so, the reasons thereof ;
- (c) whether the said house before it was requisitioned, was under occupation; if so, whose ?

**Sardar Darbara Singh (Home and Development Minister) :** (a), (b), and (c) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

## STATEMENT

- (a) Yes. Copies of the notice, issued in this behalf as well as the requisitioning order are enclosed (Annexure I and II).
- (b) The requisitioning order was addressed to M/s Pran Nath Janki Dass, Maqbool Road, Amritsar. According to the Report of the district authorities neither of the ~~aforsaid~~ two persons was available at the house nor at the shop and, therefore, the requisitioning order was pasted on the door of the house.
- (c) The house, before it was requisitioned, was lying vacant.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)49  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

The owners of the house have filed a Writ Petition in the Punjab High Court which has been fixed for hearing for 8th March, 1966. As such the matter has been sub-judice.

ANNEXURE 1

Registered

FROM

The Additional District Magistrate,  
Amritsar.

To

M/s Pran Nath-Janki Dass,  
Maqbool Road.  
Opposite D.C.'s Bungalow,  
Amritsar  
No. RC/1029.

dated 28th December, 1965.

Memorandum

The property, details of which is given below is needed for the Defence of India and efficient conduct of Military and it is proposed to requisition the same. Since you are the owner of the property. you are hereby required to show cause within 10 days from the receipt of this notice as to why the said property should not be requisitioned.

*Schedule of the property*

House owned by M/s Pran Nath-Janki Dass, opposite D.C.'s bungalow, Maqbool, Road, Amritsar.

(Sd.) S. P. KALIA,  
Additional District Magistrate, Amritsar.

ANNEXURE II

No. RC-DFI-164/2,

dated 1st January, 1966.

Order.

Whereas, in my opinion, it is necessary and expedient so to do, for securing the defence of India and efficient conduct of Military operations, to requisition the property detailed in the schedule below :—

2. Now, therefore, in exercise of the powers under section 29 of the Defence of India Act, 1962, and the rules made thereunder as delegated by the Government of India-Notification No. CSR. 1716-dated the 13th December, 1962 read with Punjab Government No. 784 (2) IJ-62/54428 dated 21st December, 1962, I, Surinder Singh Bedi I.A.S., District Magistrate, Amritsar, having been satisfied that it is necessary and expedient so to do, do hereby requisition the said property for the period of emergency and six months thereafter, but not exceeding 10 years, from the date of possession, whichever is earlier, and hereby order M/s Pran Nath Janki Dass, Maqbool Road, Amritsar (opposite D.C.'s Bungalow), occupier and owner of the property to deliver possession thereof to the Military Estate Officer, Jullundur Circle, Jullundur Cantt, immediately after removing therefrom any furniture or other articles belonging to them. The owner shall intimate to me without delay subsequent change of ownership in respect of the whole or any part of the aforesaid property by furnishing full particulars of (a) the name of the owner (b) extent of his interest and (c) date of acquisition thereof.

3. The aforesaid Military Estate Officer, Jullundur Circle, Jullundur Cantt. who would be the occupier/allottee shall inform me at least, fifteen days in advance his intention to vacate the aforesaid premises.

**]Minister for Home and Development]**

No structural alterations shall be made by the owner or occupier to the said premises comprised in the aforesaid property without my written permission.

*Schedule of the property*

House owned by M/s Pran Nath Janki Dass opposite D.C's bungalow on the Maqbool Road, Amritsar.

(Sd.) S.S. BEDI,  
District Magistrate, Amritsar.

1. M/s Pran Nath-Janki Dass,  
opposite D.C.'s bungalow,  
Maqbool Road, Amritsar.

2. Military Estate Officer,  
Jullundur, Circle,  
Jullundur Cantt.

No. RC/DFI-164/3-4, dated 1st January, 1966

A copy is forwarded to the Tehsildar, Amritsar for service upon the owner/occupier and to deliver the possession of the house in question to the M.E.O. Jullundur, immediately on receipt of this order. He should arrange immediate transfer of the possession of the property to the Military Estate Officer Jullundur Circle Jullundur Cantt, and may obtain help if so required from the Senior Superintendent of Police, Amritsar.

2. Senior Superintendent of Police, Amritsar, for information and necessary action. Police help if applied for may please be afforded to the Tehsildar, Amritsar immediately.

(Sd.) S.S. BEDI,  
District Magistrate,  
Amritsar.

No. RC/FRI-164-5

Dated 1st January, 1966.

A copy is forwarded to the Commissioner for Home Affairs and Secretary to Government, Punjab, Home Department, Chandigarh, for information.

(Sd.) S.S. BEDI,  
District Magistrate, Amritsar.

**Grant of stipend from Chief Minister's Relief Fund**

**\*9067. Sardar Surjit Singh Theri :** Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether it is a fact that a stipend of Rs 75 has been granted to Shri Uma Shankar, son of Shri Mohan Lal Wasil Baqi Nawis, Palwal, resident of Village Khambi, District Gurgaon, from the Chief Minister's Relief Fund ;
- (b) whether the annual family income of Shri Mohan Lal Wasil Baqi Nawis including his pay, income from agricultural lands owned by him and his wife Shrimati Sheila Devi, was verified; if so, with what result ;
- (c) whether he obtained any recommendations with regard to the exceedingly poor circumstances of Shri Mohan Lal before granting the stipend referred to in part (a) above; if so, the names of the officials/publicmen who recommended the case;
- (d) whether he has recently received any complaint with regard to the grant of the said stipend; if so, the contents thereof ?

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (4)51  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes.

(b) Yes. No financial assistance to the student was remitted from the Chief Minister's Relief Fund, after the receipt of report from the Deputy Commissioner, Gurgaon, in regard to financial position of the family.

(c) Yes. Sarvshri Rup Lal Mehta and Khurshid Ahmed, MLAs recommended the case of the the student.

(d) Yes. Extract of the relevant portion of the communication is laid on the Table of the House.

*Extract from letter dated 15th January, 1966 from Chaudhri Harkishan, M.L.A.  
Palwal to Com. Ram Kishan, Chief Minister, Punjab.*

-----

You granted a stipend of Rs. 75 per month to Shri Uma Shankar son of said Mohan Lal and Shrimati Sheela Devi. He is a law student at the Punjab University Law Faculty. His father Shri Mohan Lal, W.B.N. Palwal, is getting Rs 180 per mensem as salary from Government, while income from the agricultural and is about Rs 6,00.0 per annum. Besides the said Uma Shankar is earning Rs 120 to 125 per month from the tuition work. These figures were disclosed by Shrimati Sheela Devi in a statement on oath before the S.D.O. Palwal in the course of an enquiry. This is undue favour and misuse of public money. A large number of poor and deserving cases of students who are getting technical education are ignored and this is the first instance when in spite of huge income of parents, a stipend of Rs 75 has been sanctioned to the student of non-technical trade.

-----

**Stipends Granted from the Chief Minister's Relief Fund  
Since 1964**

**9068, Sardar Surjit Singh Theri :** Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether there are any specific rules or instructions for granting stipend from the Chief Minister's Relief Fund, to the students of various courses and classes; if so, a copy of the same be placed on the Table of the House ;
- (b) the names and addresses of the students of the Law Classes who have been granted stipends from the said Fund and the details of the grounds on which these were granted in each case ;
- (c) the total number of applications received since 1964 from the students of Technical Trades for grant of stipends from the said Fund together with the number of such applicants who were granted stipends ?

**Shri Ram Kishan :** (a) No Each case is considered on merit.

(b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(c) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived therefrom. Hon'ble member is, however, welcome to visit Chief Minister's Secretariat for getting the information at personal level.

[Chief Minister]

## STATEMENT

Names and addresses of the Law students, who have been granted stipends	Grounds on which these were granted
1. Shri Rajesh Kumar Angi, son of late Shri Sada Nand Angi, village Wadha, tehsil Fazilka, district Ferozepur	The father of the student is dead and the bereaved family has no source of income. The student is promising. D.C. Ferozepur, also recommended grant of financial assistance
2. Shri Des Raj, House No. 3339, Sector 23-D, Chandigarh, of village Butana, post office Nilokheri, tehsil and district Karnal	The student comes of a very poor family of Haryana. His father died in his infancy. The family of the boy is in financial difficulties
3. Miss Balwant Kaur, daughter of Shri Sohan Singh, ex-M.L.A., Moga	This is a case of girl student belonging to Scheduled Castes with limited means.
4. Shri Uma Shankar Sharma, son of Shri Mohan Lal, Wasil Baki Navis, tehsil Office Palwal, district Gurgaon	Financial assistance in this case was sanctioned on the recommendations of two M.L.A.s

### Commendation Certificates given to Political Sufferers in Jullundur District

**\*9073. Shri Om Parkash Agnihotri :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- the total number of political sufferers at present in Jullundur District to whom Government has agreed to give "Commendation Certificates" in appreciation of the sacrifices made by them in the freedom struggle ;
- the total number of political sufferers of the said district who have already been awarded such certificates ;
- the time likely to be taken by the Government to give such certificates to the remaining political sufferers ?

**Chaudhri Ranbir Singh** (Public Works Minister) : (a) 626.

(b) 169.

(c) Commendation Certificates are under preparation and these will be distributed shortly after they are received.

### Haryana Development Committee

**\*9250. Dr. Baldev Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether Government has so far received the report of the Haryana Development Committee headed by Pt. Shri Ram Sharma ;
- the details of the total amount spent by the Government on the T.A. of its members so far ;
- the action proposed to be taken by Government thereon ?

**Sardar Ajmer Singh** (Planning and Local Government Minister) :

(a) Yes ; on 27th January, 1966.

(b) A sum of Rs 12,244.63 has been spent so far on T.A. of the Members of the Committee.

(c) The report of the Haryana Development Committee is under consideration with the Government.

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### Applicaions from certain Detenus in Nabha Jail

**3131. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state whether Government received any applications during the year 1965 from Shri Dhanpat Rai Nahar and Shri Dharam Singh, Karnal and Shri Ghuman Singh, all detenus in the Nabha Jail, for their medical treatment, etc. ; if so, the details thereof and of the action, if any, taken thereon be laid on the Table of the House ?

**Shri Chand Ram :** *Part (i).*—No.

*Part (ii).*—Question does not arise.

### Co-operative Agricultural Farming Societies

**3154. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names with addresses of the Co-operative Agricultural Farming Societies, district-wise, in the State at present ;

(b) the names of the societies out of those mentioned in part (a) above which were adjudged as first, second and third by the Department according to the work done by them district-wise (with their inspection report) during the last two years ;

(c) whether any of the said societies were visited by the Minister Incharge in 1965-66 ; if so, the nature of reports, if any, made by him in respect thereof ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) to (c) Time and labour involved in collecting this lengthy information will not be commensurate with the benefits to be derived therefrom.

### Judgement in a case challanned by Jandiala Police of Amritsar District during April, 1962

**3156. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some persons including women of village Ramana Chak who were arrested and challanned by the Jandiala Police in a Police encounter case during April, 1962, were honourably acquitted by the Sessions Judge on the ground that the case was false ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether after the said judgement any enquiry was initiated by the Government against the concerned Police Officer, who arrested and challanned the above-mentioned persons ; if so, the details of the said enquiry and if no enquiry has been initiated the reasons therefor ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) It is a fact that some persons including women of village Romana Chak were arrested and challanned for assaulting a party of Jandiala Police in April, 1962. It is, however, not a fact that the accused were acquitted by the Sessions Judge, on the ground that the case

[Minister for Home and Development]

was false. In fact the accused were acquitted in appeal on a legal technicality.

(b) Does not arise.

#### Enquiry against an ex-S.H.O. of Amritsar District

**3157. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether any enquiry was held against an ex-S.H.O. of Kotwali Amritsar by Shri Daryao Singh, D.S.P., C.I.D., Chandigarh, for framing a false case of recovery of about twenty Kilos opium from some persons of Amritsar City during the year 1965, if so, the details of this enquiry be laid on the Table ;
- (b) whether the said 20 Kilos opium has so far been deposited in the Government Malkhana ; if not, the reasons for not doing so ;
- (c) whether any case regarding the said recovery of opium was registered ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes. However, the matter is being looked into by the higher officials and as such the enquiry is not final as yet.

(b) No. Further reply is only possible when the matter as referred to at (a) is finalised.

(c) No case was registered pertaining to the alleged recovery of 20 Kilos of opium.

#### Property of Smugglers of Amritsar District detained under D.I.R.

**3158. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

- (a) whether the Police interrogated the smugglers of Amritsar District at present under detention under the D.I.R. in connection with the properties held by them ;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the details of properties held by each such smuggler before he took to smuggling and as at present as verified by the Amritsar Police after the said interrogation.

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes.

(b) The details of properties, held by each such smuggler before he took to smuggling and as at present as verified by the Amritsar Police are as under :—

Serial No.	Name of Detenue	Property held before taking to smuggling	Property held after taking to smuggling
1	Shri Mohan Singh, son of Udhm Singh, resident of Maluwal, Police station Gharinda	4 Kilas of land in the village and was a milk vendor	Rs 8,23,300 (Landed and other property including trucks etc).

Serial No.	Name of Detenue	Property held before taking to smuggling	Property held after taking to smuggling
2	Shri Santa Singh, alias Santa Bawa, son of Thakar Singh, resident of Havalian, Police station Gharinda	40 acres of land	Rs 1,98,000 (Landed and other property)
3	Shri Sarmukh Singhk, son of Surain Singh, resident of Malout, district Ferozepur at present Amritsar	20 acres of land	Rs 4,68,000 (Landed and other property)
4	Shri Ajit Singh, son of Jowahar Singh, resident of Burj, police station Gharinda	25 acres of land	Rs 7,25,000 (Landed and other property)
5	Shri Harpal Singh, son of Sowaran Singh, resident of Naushehra Dhalla police station Gharinda at present Taylor Road, Amritsar	20 acres of land	Rs 9,30,000 (Landed and other property)
6	Shri Niranjan Singh Akali, son of Sher Singh, resident of Bhagtanwala, Police station 'C' Division Amritsar	Nil. Milk Vendor	Rs 7,43,000 (Landed and other property)
7	Shri Sowaran Singh alias Swarna Shah, son of Wasson Singh, resident of Naushera Dhalla, police station Gharinda	Rs 20,000	Rs 4,56,000
8	Shri Manohar Lal son of Panna Lal Katra Bhai Sant Singh, Amritsar	Rs 10,000	Rs 35,000
9	Shri Karnail Singh, son of Ranga Singh, resident of Roranwala, police station Gharinda	Rs 1,000	Rs 27,000

Sarvshri Tara Singh *alias* Tara Pandit, son of Amar Singh, resident of Khem Karan and Teja Singh, son of Jowala Singh, resident of Kotli Korotana, police station Ajnala were also interrogated, but verification in respect of their properties held by them at present, have not been made by the Police. Tara Singh disclosed that he owned 15 heads of cattle and 30 tolas of gold. Teja Singh stated that he owned 80 kilas of land, one house and two buffaloes.

#### Examination of certain Detenues by Medical Specialists

**3159. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to lay on the Table of the House the details of the action taken on the reports of the medical specialists submitted regarding the ailments of Shri Hazur Singh Deo, Shri Kartar Singh Gujapeer, Both Detenus, Hissar Jail and Shri Hazara Singh, Jasar, Detenue, Nabha Jail, along with the medical reports ?

**Shri Chand Ram :** On the basis of reports of the Medical Specialist/ Medical Officer, Jail, Sarvshri Hazur Singh Deo, and Kartar Singh Gujapeer

[Minister for Welfare and Justice]

are being removed to the Medical College, Hospital, Rohtak/Civil Hospital, Hissar for operative treatment of eyes/ventral Hernia, respectively.

Shri Hazara Singh Jassar is not suffering from any ailment which may require treatment in the outside Hospital.

Copies of Medical reports in respect of these three detenus are at Annexure 'A'.

#### ANNEXURE A

Medical report on the health of communist detenu Hazura Singh :

"Communist detenu Hazura Singh attended Medical College, Rohtak, and has been advised operation of corneal opacity in the left eye and has also been advised glasses. So arrangements may be made to get him transferred to the place where the facility exists for eye operation. There is no eye specialist in the local Civil Hospital, Hissar".

Medical report on the health of communist detenu *Hazura Singh Jassar* :

"He is suffering from general debility and being given following treatment".

Tab. Vitman B. Complex.

Tab. Multi Vitaman One Tab. T.D.S.

Tab. Acid Acteyl.

Salislic one Tab. T.D.S.

Sheroo Feral Serol"

He has since been supplied with the spectacles at Government expense on medical advice.

Medical report on the health of communist detenu Kartar Singh Gujjapeer. "He is suffering from ventral Herina".

#### Loans given to Factories and Industrial Concerns in Amritsar District

**3160. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the factories and industrial concerns in Amritsar District, affected by the recent conflict with Pakistan, which have been given loans together with the amount of loan given to each ?

**Shri Ram Kishan :** It is not in public interest to disclose the names of the loanees as it adversely affects their business.

#### Representation from working Committee of the Erstwhile Pepsu Government Teachers' Union

**3161. Comrade Hardit Singh Bhathal :** Will the Minister for Education be pleased to state —

- (a) whether Government have received any representation from the Working Committee of the erstwhile Pepsu Government Teachers' Union requesting for the appointment of a Pay Commission to enhance their pay-scales ;
- (b) whether the said Working Committees also represented that in view of the financial position of the teachers, some interim relief be given to them till the Pay Commission referred to in part (a) above completes its report ;
- (c) whether the said Union has also represented that the collection of gold through the teachers be stopped ;
- (d) whether the said teachers have also requested the Government for exemption from the payment of professional tax and for the grant of village and house-rent allowances and free medical treatment ;
- (e) if the reply in parts (a) to (d) above be in the affirmative, the details of the action, if any, taken by the Government on the said demands of the teachers ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a), (b), (c), and (d), : No.  
(e) The question does not arise.

**Machines for giving warmth to Relieve pains in the Body in Rajindra Hospital, Patiala**

**3162. Comrade Hardit Singh Bhatla :** Will the Minister for Health be pleased to state —

- (a) whether there are any machines for diathermic treatment at present in the Rajindra Hospital, Patiala ; if so, their number and the number of those in working order ;
- (b) if none of the said machines is in working order, the reasons there for and whether any arrangements have been made to get them repaired or replaced and the time by which the said machines would start working after repairs or replacement ;
- (c) the daily average number of patients visiting the said Hospital for diathermic treatment ;
- (d) the average time in minutes for which a patient is given diathermic treatment ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** (a) Yes, Sir. There are two Diathermy Machines in Rajindra Hospital, Patiala, one for high frequency and the other for low frequency and both are in working order.

(b) Question does not arise.

(c) About thirty. This is the maximum capacity of the Machines. Overloading may cause fusing of machine coils.

(d) Time depends on many factors, viz :—

- (i) Disease and its severity and re-action of the Patient to treatment ;
- (ii) Sensitivity of the skin of the Patient ;
- (iii) Voltage of the current ;
- (iv) Machine of high or low frequency. So depending on these factors, the time ranges from 10—20 minutes daily for each patient.

**Prisoners undergoing Life Imprisonment in Punjab Jails**

**3163. Comrade Hardit Singh Bhatla :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state —

- (a) the total number of prisoners undergoing life imprisonment in the Punjab Jails at present together with their number in the Patiala, Ambala, Bhatinda and Ferozepur Jails, separately ;
- (b) the period of imprisonment after which the papers for the release of prisoners referred to in part (a) above are forwarded to the competent authorities ;
- (c) the number and names of Prisoners out of those mentioned in part (a) above whose charts for release have been sent to the authorities concerned ;
- (d) the date on which the chart for the release of each of the said life prisoners was sent ;
- (e) the maximum and minimum time taken in taking a decision on the kind of charts referred to in part (d) above ;
- (f) the number of prisoners in whose cases the final orders have been passed together with the number of cases on which decision has not been taken so far ;
- (g) whether there is any proposal under the consideration of the Government for expediting the cases of such prisoners who have served their terms of imprisonment according to the rules,

[Comrade Hardit Singh Bhathal]

and or to fix some particular time limit within which the competent authority might take a decision on the kinds of cases mentioned in (c) above ;

- (h) whether there is any proposal under the consideration of the Government to release the prisoners, decisions on whose cases are not taken by the competent authority within a prescribed period ?

**Shri Chand Ram :** A statement giving the requisite information is enclosed.

#### STATEMENT

(a) Total	..	2,712
Ferozepur	..	646
Patiala	..	756
Ambala	..	441
Bhatinda	..	33

b) Under Para 516-B of the Punjab Jail Manual the rolls of the life prisoners who were above 20 years of age at the time of Commission of offence are sent to Government for their premature release, when they have undergone 14 years sentence including remission.

As regards female prisoners and male prisoners who were under 20 years of age at the time of Commission of the offence, their rolls are forwarded to Government, for consideration for premature release, when they have undergone 10 years sentence including remission.

(c) and (d) Requisite information is given in the Statement at (ANNEXURE "A").

(e) Generally cases are decided within two to six months. But in cases where recommendations of the Village Panchayat and District Magistrate differ, the cases are referred to District Magistrates for fresh recommendations. In such cases, the period taken for final decision may be little longer.

(f) Cases decided- 67 ; cases not decided—186.

(g) and (h) No. The cases of prisoners as and when completed are disposed of expeditiously by Government.

#### ANNEXURE "A"

Name of the prisoner	Date on which roll sent
<b>Central Jail, Patiala</b>	
1. Shanghara Singh, son of Bhola Singh	.. 31st December, 1965
2. Mukhtiar Singh, son of Jhanda Singh	.. 28th September, 1965
3. Sappattar Singh, son of Nasib Singh	.. 18th October, 1965

Name of the prisoner	Date on which roll sent
<i>Central Jail Patiala—contd</i>	
4. Sohan Singh, son of Nidhan Singh	.. 22nd October, 1965
5. Jagir Singh, son of Pala Singh	.. 31st December, 1965
6. Nidhan Singh, son of Jawala Singh	6th September, 1965
7. Karnail Singh, son of Kehar Singh	.. 3rd November, 1965
8. Jagjit Singh, son of Dhanna Singh	: 16th November, 1965
9. Phulla, son of Shisha	.. 3rd November, 1965
10. Kauri <i>alias</i> Bakhtawar Singh, son of Hira Singh	.. 6th September, 1965
11. Pal Singh, son of Wadhawa Singh	.. 23rd September, 1965
12. Hassia, son of Kangu	.. 30th June, 1965
13. Kashmira Singh, son of Ganda Singh	.. 29th October, 1965
14. Bhartu, son of Badlu	.. 21st January, 1966
15. Kartar Singh, son of Kishan Singh	.. 2nd February, 1966
16. Santa Singh, son of Kaalan Singh	.. 2nd February, 1966
17. Ranjit Singh, son of Bhagwan Singh	.. 12th December, 1965
18. Sukhdev Singh, son of Mohinder Singh	.. 25th January, 1965
19. Dedar Singh, son of Kishan Singh	.. 2nd January, 1966
20. Shanti Sarup, son of Hukmia	.. 22nd January, 1966
21. Gujjar Singh, son of Kesar Singh	.. 7th October, 1964
22. Thambo, son of Sangri	.. 23rd November, 1965
23. Teja Singh, son of Bakhtawar Singh	.. 11th August, 1965
24. Nirranjan Singh, son of Sajan Singh	.. 25th September, 1965
25. Santa Singh, son of Narain Singh	.. 21st December, 1965
26. Kartar Singh, son of Bakhtawar Singh	.. 10th January, 1966
27. Gulab Singh, son of Kishan Singh	.. 20th January, 1966
28. Prem Chand, son of Budh Ram	5th October, 1965
29. Gurdial Singh, son of Harnam Singh	.. 23rd September, 1965
30. Gurbux Singh, son of Kirpal Singh	.. 25th January, 1966
31. Bhag Singh, son of Kehar Singh	.. 25th January, 1966
32. Karnail Singh, son of Sohan Singh	.. 25th January, 1966
33. Jagga Singh, son of Bahal Singh	.. 19th June, 1965
34. Gurdev Singh, son of Arjan Singh	.. 18th January, 1965

[Minister for Welfare and Justice]

Name of the prisoner	Date on which roll sets
<i>Central Jail Patiala—concl'd</i>	
35. Gulzar Singh, son of Buta Singh	.. 14th June, 1965
36. Modan Singh, son of Sarn Singh	.. 1st May, 1965
37. Gian Singh, son of Wadhawa Singh	.. 14th April, 1965
38. Massa, son of Rangoo	.. 17th May, 1964
39. Shawinder Singh, son of Shamir Singh	.. 9th September, 1965
40. Shankar, son of Kheta	.. 26th June, 1965
41. Piara Singh, son of Narain Singh	..
42. Mehanga Singh, son of Assa Singh	..
43. Mukhtiar Singh, son of Bhartu	..
44. Inder Singh, son of Mehanga Singh	.. Cases since decided
45. Ganga, son of Devi Dyal	..
46. Nanak Chand, son of Bagga Mal	..
47. Damodar, son of Mast Ram	..
48. Guram Singh son of Ishar Singh	..
49. Gulzar Singh, son of Lakha Singh	..
<b>District Jail, Bhatinda</b>	
50. Mara Singh, son of Sajjan Singh	.. 10th May, 1965
51. Mal Singh, son of Baghta Singh	.. 14th July, 1965
52. Pohla Singh son of Dalip Singh	.. 6th December, 1965
53. Kour Singh, son of Nikka Singh	.. 21st December, 1965
54. Balbir Singh, son of Budh Singh	.. 7th February, 1966
55. Hamir Singh, son of Kaku Singh	.. 10th February, 1966
<b>Central Jail, Ambala</b>	
56. Suchet Singh, son of Bachan Singh	.. 16th October, 1965
57. Gian Singh, son of Bakhtara Singh	.. 10th February, 1966
58. Om Parkash, son of Rura Mal	.. 10th February, 1966
59. Chanan Singh, son of Deva Singh	.. 22nd June, 1965
60. Prem Singh, son of Hira Singh	.. 26th November, 1965
61. Ruldu, son of Gattu	.. 12th November, 1965
62. Sabu, son of Lotan	.. 1st September, 1965
63. Naranjan Singh, son of Ghasita Singh	.. 18th November, 1965

Name of the prisoner	Date on which roll sent
<b>Central Jail, Ambala—contd.</b>	
64. Roshan Lal, son of Fakir Chand	.. 27th December, 1965
65. Virsa Singh, son of Gurdit Singh	.. 24th December, 1965
66. Shankira, son of Noria	.. 7th January, 1966
67. Piara Singh, son of Ujaggar Singh	.. 15th November, 1965
68. Basant Singh, son of Sawan Singh	.. 5th November, 1965
69. Kehar Singh, son of Bahadur Singh	.. 7th January, 1966
70. Bhajan Singh, son of Narain Singh	.. 27th December, 1965
71. Kuldip Raj, son of Ralla Ram	.. 15th January, 1966
72. Gian Singh, son of Dhanpat Ram	.. 1st June, 1965
73. Madan Singh, son of Birbal	.. 1st July, 1965
74. Tirlok Singh, son of Gulla Singh	.. 2nd August, 1965
75. Dara Singh, son of Baghel Singh	.. 15th November, 1965
76. Jarnail Singh, son of Sunder Singh	.. 6th July, 1965
77. Iqbal Singh, son of Narain Singh	.. 23rd April, 1965
78. Tara Singh, son of Ganda Singh	.. 3rd August, 1965
79. Arjan Kumar, son of Rikhi Ram	.. 6th November, 1965
80. Siri Ram, son of Rajji Lal	.. 17th June, 1965
81. Bakhshish Singh, son of Lakha Singh	.. 5th August, 1965
82. Krishan Lal, son of Shiv Ram	.. 18th October, 1965
83. Dhanna, son of Rana	.. 9th September, 1964
84. Hazara Singh, son of Mangal Singh	.. 17th June, 1965
85. Jagrup Singh, son of Jagjit Singh	.. 18th October, 1965
86. Rur Singh, son of Sardara Singh	.. 11th May, 1965
87. Krishan Lal, son of Piara Lal	.. 22nd January, 1966
88. Ram Narain, son of Har Lal	.. 7th August, 1965
89. Shori Lal, son of Budh Raj	} Cases since decided
90. Jhangi Ram, son of Nanu Ram	
91. Bali Singh, son of Sewa Singh	
92. Mehanga Singh, son of Narain Singh	
93. Utta Singh, son of Butta Singh	
94. Jagir Singh, son of Kahal Singh	

Name of prisoner	Date on which roll sent
<i>Central Jail Ambala—concl'd</i>	
95. Baru Sigh, son of Hattu,	cases since decided
96. Raj, son of Lakhan	
97. Balbir Singh, son of Surain Singh	
98. Jagdish , son of Harbux Singh	
99. Ram Pal, son of Labu Ram	
100. Bara Singh, son of Gehal Singh	
101. Balwant Singh, son of Bahal Singh	
102. Maghar Singh, son of Mangal Singh	
<b>District Jail, Jullundur</b>	
103. Sita Ram, son of Chhangin Ram	.. 27th September, 1965
104. Roshan Lal, son of Wadhawa Mal	.. 17th April, 1965
105. Khem Singh, son of Labha Singh	.. 21st January, 1966
106. Joginder Singh, son of Piara Singh	.. 14th February, 1966
107. Santokh Singh, son of Bakhshish Singh	.. 14th December, 1965
108. Chanan Singh, son of Bhag Singh	.. 28th December, 1964
109. Chintu, son of Punnu	.. 27th September, 1965
110. Gurmit Singh, son of Lachman Singh	.. 6th August, 1965
111. Naranjan Singh, son of Harnam Singh	.. 5th May, 1964
112. Avtar Singh, son of Narain Singh	.. 20th February, 1965
<b>Central Jail, Hissar</b>	
113. Joginder Singh, son of Nikka Singh	.. 17th September, 1964
114. Surjan Singh, son of Ballu	.. 20th October, 1964
115. Mange Singh, son of Mansa	23rd November, 1964
116. Dalip Singh, son of Hardam Singh	.. 26th December, 1964
117. Mange Singh, son of Nathu	.. 18th January, 1965
118. Mange , son of Bhura	.. 20th January, 1965
119. Lal Singh, son of Bhag Singh	.. 2nd January, 1965
120. Phul Chand, son of Suraj Bhan	.. 24th February, 1965
121. Lachhi Singh, son of Nathu	.. 9th April, 1965
122. Mansukh Singh, son of Manga Ram	.. 15th April, 1965

Name of prisoner	Date on which roll sent
<i>Central jail, Hissar—concl'd</i>	
123. Siri Chand, son of Manga Ram	.. 23rd April, 1965
124. Sita, son of Gujjar	.. 26th April, 1965
125. Siri Ram, son of Basti Ram	.. 24th May, 1965
126. Sada Singh, son of Chanda Singh	26th June, 1965
127. Tara Singh, son of Banta Singh	.. 23rd September, 1965
128. Ram Dhari, son of Lal Singh	.. 23rd September, 1965
129. Birbal, son of Bhagta	.. 23rd September, 1965
130. Joginder Singh, son of Mian Singh	.. 23rd September, 1965
131. Mal Singh, son of Gurdit Singh	.. 25h September, 1965
132. Chet Ram, son of Lal	.. 30th September, 1965
133. Mehar Chand, son of Manga Ram	.. 1st October, 1965
134. Avtar Singh, son of Kandhara Singh	.. 8th November, 1965
135. Bhajan Singh, son of Harnam, Singh	.. 16th October, 1965
136. Surinder Singh, son of Shamir Singh	.. 8th November, 1965
137. Jarnail Singh, son of Charan Singh	.. 17th November, 1965
138. Dulla Singh, son of Sardar Singh	.. 18th November, 1965
139. Mehanga Singh, son of Sampuran Singh	.. 22nd January, 1966
<b>District Jail, Ludhiana</b>	
140. Kalu Ram, son of Baru Mal	.. 14th September, 1963
141. Lambar Singh, son of Raja Singh	.. 16th January, 1965
142. Amar Singh, son of Deva Singh	.. 22nd December, 1965
143. Manohar Lal, son of Wazir Chand	.. 17th June, 1963
144. Kartar Singh, son of Sofa Singh	.. 26th October, 1965
145. Gajjan Singh, son of Mangat Singh	.. 20th May, 1965
146. Balbir Singh, son of Shiv Singh	.. 25th October, 1965
147. Gurbux Singh, son of Gulzar Singh	.. 22nd January, 1966
148. Joginder Singh, son of Bahadur Singh	.. 25th October, 1965
149. Sewa Singh, son of Chanda Singh	.. 25th October, 1965
150. Harnam Singh, son of Hazara Singh	.. 25th October, 1965
151. Ajaib Singh, son of Sardara Singh	.. 14th October, 1965
152. Ujjagar Singh, son of Pakhar Singh	.. 1st November, 1965

[Minister for Welfare and Justice]

Name of prisoner	Date on which roll sent
<i>District Jail, Ludhiana—concl'd</i>	
153. Sushil, wife of Gurcharan Singh	.. 8th July, 1965
154. Nirmal, wife of Sandha Singh	.. 14th December, 1965
<b>District Jail, Sangrur</b>	
155. Kartar Singh, son of Tota Singh	.. 3rd August, 1964
156. Nachhittar Singh, son of Pala Singh	.. 14th July, 1965
157. Dalip Singh, son of Kaka <i>alias</i> Harnam Singh	17th September, 1965
158. Inder Singh, son of Kehar Singh	.. 7th October, 1965
159. Kishan Chand, son of Karam Chand	.. 15th November, 1965
160. Kartar Singh, son of Kishan Singh	.. 16th December, 1965
161. Bant Singh, son of Santa Singh	.. 24th Decmeber, 1965
162. Gulla Singh, son of Ghuman Singh	.. 18th January, 1966
<b>Faridkot</b>	
163. Harbans Lal, son of Mohan Lal	.. 27th November, 1965
164. Prem Chand, son of Ganga Ram	.. 25th August, 1964
165. Jita, son of Makhan	.. 19th October, 1965
166. Sukhminder Singh, son of Hari Singh	.. 7th February, 1966
167. Mohinder Singh, son of Harnam Singh	.. 9th December, 1965
<b>Gurdaspur</b>	
168. Gurnam Singh, son of Bakhshish Singh	.. 6th January, 1966
169. Jagir Singh, son of Sudagar Singh	.. 5th January, 1966
<b>District Jail, Nabha</b>	
170. Rup , son of Kaka Ram	.. 22nd February, 1966
171. Rikhia, son of Khema	.. 5th June, 1965
172. Ujaggar Singh, son of Dan Singh	.. 20th November, 1965
173. Raghbir Singh, son of Bakhtawar Singh	.. 10th January, 1966
<b>District Jail, Rohatk</b>	
174. Ram Kishan, son of Jhandu	.. 7th October, 1965
175. Chain Singh, son of Bur Singh	.. 26th March, 1965
176. Madho Singh, son of Jai Singh	.. 10th July, 1966
177. Jogi Ram, son of Biru	.. 18th August, 1965

Name of prisoner	Date on which roll sent
<i>District Jail, Rohtak—concl'd</i>	
178. Parkash, son of Budhu	.. 10th June, 1965
179. Mangal Singh, son of Sunder Singh	.. 12th October, 1965
180. Manga Ram, son of Nikki	.. Decided
181. Mange Ram, son of Ram Mehar	.. 20th April, 1965
182. Rup Singh, son of Mam Chand	.. 4th February, 1965
183. Parhlad, son of Udhey	.. 15th July, 1965
<i>District Jail, Amritsar</i>	
184. Kartar Singh, son of Jagar Singh	.. 18th December, 1961
185. Charan Singh, son of Bishan Singh	.. 18th October, 1965
186. Bawa Singh, son of Jagat Singh	.. 26th October, 1962
187. Sajjan Singh, son of Mangal Singh	.. 10th December, 1962
188. Santokh Singh, son of Massa Singh	.. 17th August, 1965
189. Ghuni, son of Surkha	.. 24th December, 1964
190. Diwan Singh, son of Bishad Singh	.. 28th February, 1965
191. Sohan Singh, son of Bir Singh	.. 18th March, 1965
192. Joginder Singh son of Arjan Singh	.. 11st May, 1965
193. Bakhshish Singh son of Balwant Singh	.. 4th October, 1965
194. Darbara Singh, son of Ram Singh	.. 1st March, 1965
195. Santa Singh, son of Pal Singh	.. 2nd August, 1965
196. Mohinder Singh, son of Mohan Singh	.. 14th August, 1965
197. Chuhan Singh, son of Mulla Singh	.. 25th September, 1965
198. Natha Singh son of Hazara Singh	.. 6th October, 1965
199. Jit Singh son of Mangal Singh	.. 13th October, 1965
200. Jallu Singh son of Sunder Singh	.. 13th January, 1966
201. Pritam Singh son of Makhan Singh	.. 13th January, 1966
202. Jarnail Singh, son of Wadhawa Singh	.. 13th January, 1966
203. Jagga Singh, son of Bur Singh	.. 17th January, 1966
<i>District Jail, Hoshiarpur</i>	
204. Lotu, alias Parkash, son of Sanghu	.. 28th March, 1965
205. Sita Ram, son of Bhagwana	.. 22nd February, 1964

[Minister for Welfare and Justice]

Name of prisoner	Date on which roll sent
<i>Distict Jail Hoshiarpur—concl'd</i>	
206. Bishan Singh, son of Lachman Singh	.. 6th June, 1965
<b>Special Jail, Hissar</b>	
207. Siri Chand, son of Mam Chand	.. 16th October, 1965
208. Shanker, son of Harsukh	.. 22nd March, 1965
<b>Mohinder garh</b>	
209. Rameshwar, son of Kehar	.. 7th June, 1965
<b>Central Jail Ferozepur</b>	
210. Tulsi, son of Sidhu	.. 15th April, 1965
211. Sucha Singh, son of Khazan Singh	.. 8th December, 1965
212. Gurdev Singh, son of Arjan Singh	.. 20th January, 1966
213. Joginder Singh, son of Guddar Singh	18th October, 1965
214. Karam Singh, son of Bhagwan Singh	.. 8th December, 1965
215. Dalip Singh, son of Dasonda Singh	.. 3rd December, 1965
216. Piara Singh, son of Budh Singh	.. 1st February, 1966
217' Sher Sigh, son of Sunder Singh	.. 1st February, 1966
218. Nazar Singh, son of Hakim Singh	.. 29th November, 1965
219. Darshan Singh, son of Ravail Singh	.. 8th December, 1965
220. Sarwan Singh, son of Phuman Singh	.. 8th December 1965
221. Thakar Singh, son of Inder Singh	.. 8th December, 1965
222. Partap Singh, son of Thakar Singh	.. 2nd December, 1965
223. Jagir Singh, son of Ishar Singh	.. 21st November, 1965
224. Hira Lal, son of Nand Kisore	.. 29th June, 1964
225. Kashmira Singh, son of Tek Singh	.. 1st November, 1965
226. Zora Singh, son of Dharam Singh	.. 27th January, 1966
227. Faujab Singh, son of Uttam Singh	.. 20th August, 1965
228. Malloo Nath, son of Kesar Singh	.. 1st February, 1966
229. Guddar Singh, son of Guddar Singh	.. 16th November, 1965
230. Surat Singh, son of Budh Singh	.. 20th January, 1966
231. Sucha Singh, son of Sada Singh	.. 15th December, 1965
232. Bakshish Singh, son of Zora Singh	.. 15th December, 1965
233. Shamir Singh, son of Bhagat Singh	.. 17th December, 1965

Name of prisoner	Date on which roll sent
<i>Central Jail Ferozepur—concl'd</i>	
234. Labh Singh, son of Boor Singh	.. 25th September, 1965
235. Malla Singh, son of Rur Singh	.. 21st December, 1965
236. Sagar son of Harish Chander	.. 30th August, 1965
237. Ujagar Singh, son of Bachan Singh	.. 28th May, 1965
238. Lachhman Singh, son of Bhagat Singh	.. 14th August, 1965
239. Nihal Singh, son of Sajjan Singh	.. 5th January, 1966
240. Angrej Singh, son of Inder Singh	.. 19th February, 1965
241. Bishakha Singh, son of Manna Singh	.. 15th November, 1965
242. Gurbux Singh, son of Kesar Singh	.. 1st February, 1966
243. Niranjana Singh, son of Partap Singh	.. 4th January, 1964
244. Gajja Singh, son of Bhagat Singh	.. 11th October, 1965
245. Ajit Singh, son of Partap Singh	.. 27th January, 1966
246. Maghar Singh, son of Rulia Singh	.. 25th December, 1965
247. Nand Singh, son of Kaka Singh	.. 16th March, 1965
248. Godha Singh, son of Bachan Singh	.. 11th October, 1965.
249. Pritam Singh, son of Kapur Singh	.. 1st January, 1964
250. Wadha Singh, son of Manna Singh	.. 13th November, 1963
251. Santa Singh, son of Wadha Singh	.. 13th August, 1962
252. Resham Singh, son of Kartar Singh	.. 2nd December, 1965
253. Narain Singh, son of Bahagur Singh	.. 20th October, 1965

**Departmental enquiries against Shri Sajjan Singh, Ex-S.H.O.,  
Jandiala Guru, district Amritsar**

**3164. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether any departmental enquiries were initiated against Shri Sajjan Singh Ex-S.H.O Jandiala Guru, district Amritsar, during the year 1963-64, in Amritsar District and in 1964-65 and 1965-66 in Gurdaspur and Ferozepore districts ; if so, the details of each enquiry, the charges enquired into each case, the result thereof and the action taken thereon ;

(b) the details of the enquiries, if any, still pending against the said Ex-S.H.O. ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes. The details of the departmental enquiries initiated against Sub-Inspector Sajjan Singh during the year

[Minister for Home and Development]

1963-64 in Amritsar District are given in the statement laid on the Table of the House. The charges enquired into and the result thereof is also given in the said statement. No departmental enquiry against the said Sub Inspector was initiated in Gurdaspur and Ferozepur Districts in years 1964-65 and 1965-66.

(b) No enquiry is pending against him.

#### Statement

The following five departmental enquiries were initiated against S. I. Sajjan Singh formerly S. H. O., P. S. Jandiala, district Amritsar.

#### Departmental Enquiry No. I

He un-necessarily delayed the investigation of 11 cases of P. S. Jandiala. The charge was proved against him and for this misconduct, his one year's approved service was forfeited.

#### Departmental Enquiry No. II

He registered a false case under section 506 I. P. C., P. S. Jandiala against Shri Hukam Singh at the instance of Shri Sadhu Singh of Jandiala. He was held guilty of the charge and his 4 years' approved service was forfeited.

#### Departmental Enquiry No. III

He made discrepant statement before the Privileges Committee of the Punjab Vidhan Sabha regarding the incident of hand-cuffing of Shri Makhan Singh Tarsikka, M. L. A. and his detention in the lock-up of the P. S. Jandiala. The charge was not substantiated and he was, therefore, exonerated.

#### Departmental Enquiry No. IV

Stictures were passed against him by Shri Sant Singh, M. I. C., Amritsar in a case under section 9/1/78 Opium Act of P. S. Jandiala. He was not held guilty and was, therefore, exonerated.

#### Departmental Enquiry No. V

He failed to register a case under section 148/149 I. P. C., and under section 323 I. P. C., on a complaint of Shri Teja Singh of P. S., Jandiala. The charge was proved against him and his one year's approved service was forfeited.

#### Industrial Training Institute and Polytechnic Institutes

3166. Shri Om Parkash Agnihotri : Will the Minister for Education be pleased to state —

- (a) the total number of students in the Industrial Training Institutes and Polytechnic Institutes in the State, both private and public to whom loans were sanctioned during the year 1963-64 by the Technical Education Board for carrying on their studies ;
- (b) the dates when the instalments of the said loans were due to be paid to the said students and also the date when these were actually paid ;
- (c) whether it is a fact that the third instalment of the said loans due to the said students in their third year was not paid upto 31st January, 1966 ; if so, the reasons, if any, for this delay and the time by which the payment thereof is expected to be made ?

Shri Prabodh Chander (a) 1019 students in Polytechnics were advanced loans in 1963-64. The Industrial Training Institutes are under the control of the Industries Department and not Technical Education Department.

(b) Generally, loan is disbursed to the students after they have executed the loan deed and fulfilled other conditions as required under the Punjab Engineering Education Loan Rules.

It is not possible to give the actual date(s) of disbursement of loan to each student. The labour and Work involved in the collection of this information would be incommensurate with the possible benefit to be obtained.

(c) Some of the said students could not be paid their 3rd instalments upto 31st January, 1966 because proposals were received late from certain institutions. The amount of 3rd instalment in respect of such students has since been placed at the disposal of and remitted to the Heads of the Institutions concerned for disbursement.

#### Famine stricken areas in district Hissar

**3167. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

- (a) the number and names of the villages tehsilwise in Hissar District which are proposed to be declared as famine stricken area;
- (b) the total amount given as a relief measure after July, 1965 to-date in the famine stricken areas in the said district, tehsil-wise ;
- (c) the criteria adopted in distributing the amount referred to in part (b) above ?

**Sardar Harinder Singh Major :** (a) No area of district Hissar is to be declared as famine stricken area.

(b) The following amounts have been sanctioned by Government for relief works:—

	Rs
(i) Earthwork on roads	15,00,000
(a) Bhiwani Tahsil	6,82,000
(b) Hissar Tahsil	5,40,000
(c) Hansi Tahsil	1,20,000
(d) Sirsa Tahsil	1,51,118
<b>Total</b>	<b>14,93,118</b>
(ii) Digging of Johars	5,00,000
(a) Bhiwani Tahsil	2,00,000
(b) Hissar Tahsil	2,00,000
(c) Sirsa Tahsil	25,000
(d) Fatehabad Tahsil	75,000
<b>Total</b>	<b>5,00,000</b>
(iii) Lift Irrigation Schemes	48,58,000
(a) Bhiwani Tahsil	2/3 of this amount
(b) Hissar, Hansi and Sirsa Tahsils	1/3 of this amount
(iv) Soil Conservation Works	10,00,000
(a) Hissar	5,00,000
(b) Bhiwani	5,00,000
(v) Water Supply Scheme	8,50,000
(In Bhiwani Tahsil only)	(As share of villagers)

## [Revenue Minister]

Other relief measures sanctioned for, or given in Hissar District are given as below :

		Rs
(i) Remission of land revenue on the following scale:		2,08,845
(a) where the damage was more than 50 per cent	Total remission	
(b) where the damage was below 50 per cent but-75 per cent more than 25 percent	remission	
	Rs	
(a) Bhiwani Tahsil	..	1,17,354
(b) Hansi Tahsil	..	28,274
(c) Hissar Tahsil	..	32,980
(d) Sirsa Tahsil	..	30,237
Total	..	2,08,845
(ii) Suspension of recovery of taccavi loans till Rabi, 1966	Rs.	18,63,469
(a) Hissar	..	65,312
(b) Hansi	..	76,849
(c) Sirsa	..	2,42,772
(d) Bhiwani	..	14,78,536
Total	Rs.	18,63,469
(iii) Fodder and Seed taccavi	Rs.	19,50,000
	Fodder	Seed
	Rs	Rs
(a) Bhiwani	.. 6,75,000	2,50,000
(b) Hansi	.. 2,00,000	..
(c) Hissar	.. 3,25,000	..
(d) Fatehabad	.. 3,00,000	..
(e) Sirsa	.. 2,00,000	..
Total	.. 17,00,000	2,50,000
(iv) Subsidy for purchase of fodder	—	1,75,000
(a) Bhiwani	.. 1,25,000	
(b) Hissar	.. 50,000	
Total	.. 1,75,000	
(v) Fodder-Depots	..	35 fodder de-
(a) Bhiwani	.. 29	pots are
(b) Hissar	.. 6	functioning
Total	.. 35	where the
		fodder is
		sold at
		subsidized
		rates

(vi) Fair Price Shops	..	116	fair price shops are functioning
(a) Bhiwani	..	61	
(b) Hansi	..	29	
(c) Hissar	..	10	
(d) Fatehabad	..	6	
(e) Sirsa	..	10	
Total	..	116	

## (vii) Amenities provided in Bhiwani

## Tahsil:

(1) Dhotis	..	44	
(2) Shirts of Mazri Cloth	..	25	
(3) Shirts Mazri	..	14	
(4) Sweet Shirts	..	24	
(5) Khes	..	46	
(6) Shirting Cloth	..	98	pieces
(7) Rihhot Ves Cloth	..	71	pieces
(8) Woollen Jackets	..	32	
(9) Night Pyjama Suits	..	25	
(10) Bed Sheets	..	77	
(11) Woollen Blankets	..	49	
(12) Mazri Cloth	..	45	pieces
(13) Vests Cotten Flannatele	..	52	

(viii) Highest priority is to be given to village water supply scheme and rural electrification.

(ix) Recruiting centre to be opened in Hissar District.

(c) The Deputy Commissioner, Hissar, has allocated the amounts to various tahsils according to their requirements.

**A.S.Is. and S.Is. under suspension in the State**

**3168. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the number and names of A.S.Is. and S.Is. suspended on the charge of embezzlement in the State, district-wise, during the period from 1st July, 1965 to date ;

(b) the number and names of the said A.S.Is. and S.Is. who are under trial after their suspension in respect of the cases mentioned in part (a) above ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) No A.S.I. and S.I. was suspended on the charge of embezzlement during the period from 1st July, 1965 to-date .

(b) The question does not arise.

**Cases filed under section 107/151 before S.D.Ms (Civil) in Hissar and Amritsar Districts**

**3169. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the total number of cases filed before the Sub-Divisional Magistrates (Civil) in Hissar and Amritsar Districts, Sub-Division-wise, under sections 107/151 Criminal Procedure Code during the period from 1st April, 1965 to-date together with the number of persons bound down by each of the said Magistrates for apprehension of breach of peace ?

**Sardar Darbara Singh** : Total number of cases instituted under section 107/151 Criminal Procedure Code and the total number of persons bound down by the Sub-Divisional Magistrates in Amritsar and Hissar Districts from 1st April, 1965 to 11th February, 1966 are as under:

Sub-Divisions of district Amritsar		Cases filed		Persons bound down
Sub-Divisional	Magistrate, Amritsar	..	323	35
Sub-Divisional	Magistrate, Tarn Taran	..	157	70
Sub-Divisional	Magistrate, Patti	..	371	312
Sub-Divisional	Magistrate, Ajnala	..	349	236
Sub-Divisions of district Hissar:—				
Sub-Divisional	Magistrate, Hissar	..	197	98
Sub-Divisional	Magistrate, Hansi	..	188	48
Sub-Divisional	Magistrate, Bhiwani	..	266	40
Sub-Divisional	Magistrate, Fatehabad	..	380	52
Sub-Divisional	Magistrate, Sirsa	..	319	312

**District Public Relations and Grievances Committee, Amritsar**

**3172. Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the details of the complaints received by the District Public Relations and Grievances Committee, Amritsar District during the last six months, department-wise, and the action taken on each complaint ;

(b) lay copies of the proceedings of the said Committees during the said period on the Table of the House ?

**Shri Ram Kishan** : (a) No complaint was received directly by the Public Relations and Grievances Committee, Amritsar. Progress of removal of complaints of other departments was reviewed in the meetings of the Committee, the details of which are given in the proceedings of the meetings.

(b) During the past six months, four meetings of the District Public Relations and Grievances Committee were held on 5th November, 1965, 6th December, 1965, 5th January, 1966 and 8th February, 1966. Copies of the proceedings of these meetings are enclosed. No meetings were held during the months of September and October, 1965, due to emergency.

**Proceedings of the District Public Relations and Grievances Committee held on 5th November, 1965, under the Chairmanship of Shri Surinder Singh Bedi, I. A. S., Deputy Commissioner, Amritsar**

**Present :—**

- (1) Shri S. P. Kalia, I. A. S., Additional Deputy Commissioner, Amritsar.
- (2) Shri Shiv Singh, G. A. I, to D. C.
- (3) Miss P. Ahluwalia, P. C. S., G. A. II.
- (4) Shri Piara Lal S. D. O., (C) Ajnala.

- (5) Shri Ajit Singh Nagpal, S. D. O., (C) Ajnala.
- (6) Shri J. D. Gupta, I. A. S. S. D. O. (C), Amritsar.
- (7) Shri Gurdial Singh, S. O., (CH), Amritsar.
- (8) Shri B. S. Basur, District Food and Supplies Controller, Amritsar.
- (9) Shri Amir Singh, District Development and Panchayat Officer.
- (10) Shri Harcharan Singh, Secretary, Zila Parishad, Amritsar.
- (11) P. D. S. P., Amritsar.
- (12) Shri M. S. Brar, X.E.N. Majitha Division, U.B.D.C., Amritsar.
- (13) Shri H. R. Huria, X. E. N., B. & R., Amritsar.
- (14) Shri J. M. Mehta, X. E. N., Jandiala Division, U.B.D.C., Amritsar.
- (15) Shri A. K. Mehta, X. E. N., Amritsar Drainage Division.
- (16) Shri M. R. Sachdeva, X. E. N., Drainage Investigation Division.
- (17) Shri Kushal Dev, X. E. N., Electricity, Amritsar.
- (18) Shri Gurdas Mal, District Animal Husbandry Officer.
- (19) Shri R. N. Sawhney, General Manager, Punjab Roadways, Amritsar.
- (20) Shri Joginder Singh, Secretary, D.S.S. & A. Board, Amritsar.
- (21) Shri Hans Raj Khanna, Secretary Municipal Committee, Amritsar.
- (22) Shri Ved Bushan, D. P. R. O.
- (23) Shri Rajinder Singh, Divisional Forest Officer.
- (24) Shri L. R. Khosla, District Industries Officer, Amritsar.
- (25) Inspector, Co-operative Societies, Tarn Taran.
- (26) District Education Officer, Amritsar.
- (27) Tehsildars, Amritsar/Tarn Taran/Ajnala.
- (28) Deputy Chief Medical Officer, Amritsar.
- (29) President, Sadachar Samiti, Amritsar.
- (30) B. D. & P. Os., Taran Taran/Gandiwind/Ajnala/Patti/Jandiala/Valtoha Naushera Panuan/Chola Sahib, Verka/Majitha/Chugawan and Bhikhi wind.
- (31) Additional Excise and Taxation Officer, Amritsar.
- (32) Executive Officer, M. C., Taran Taran.
- (33) Field Publicity Officer, Amritsar.

Before proceedings of the meeting started the A. D. C., read out the letter, dated the 30th October, 1965, received from Director of Grievances, Punjab, Chandigarh and informed all the members that the instructions received from the Government regarding complaints should be dealt with strictly.

A copy of para No. 15 of the orders of the Punjab Government dated, the 25th October is being sent to all the officers of each department, so that they should proceed according to the instructions given in this paragraph.

[Chief Minister]

*District Food and supplies Officer.*—He informed the members that the supply of food in the city is satisfactory and wheat atta is being sold in the city at the rate of Rs 23 to Rs 25 per maund and the market rate of wheat is Rs 48 to Rs 55 per quintal. He also informed the members that the condition of sugar and cement in the city is satisfactory.

*Assistant Registrar Co-operative Societies, Amritsar.*—Some members informed the Deputy Commissioner, Amritsar, that the supply of sugar in the villages is most unsatisfactory and the military personnel who come on leave are not getting sugar regularly. The Deputy Commissioner directed the Officer concerned to remove this complaint.

*Secretary, D. S. S. and A. Board, Amritsar.*—He informed the members that the police is disturbing the military personnel who come on leave and the police make their searches with one pretext or the other. The Deputy Commissioner directed the Police Officer that he should issue instructions to the Police that they should refrain from doing this and if the Police want to make searches, they should at least do so in the presence of Sarpanches or Panches. The Secretary also informed that when the military personnel go back to duty after availing of their leave, their family members are harassed unnecessarily. The Deputy Commissioner brought this fact to the notice of the Police Officer and directed him that the Police should not act in a wrong way.

*S. S. P., Amritsar.*—Seventy-four complaints were received in the office of the Senior Superintendent of Police, Amritsar, out of them seventy-three complaints were found to have been rightly disposed of and one complaint was discussed in the meeting. This complaint was from Shrimati Prem Wati, servant of Shrimati Avtar Kaur, Head Teachress against Shri Mohan Singh Dhillon Advocate, regarding taking away of Shrimati Avtar Kaur forcibly.

The S. S. P. informed that this case is being investigated and in the next meeting a complete report regarding this complaint will be submitted.

*X. E. N., U.B.D.C., Jandiala Division.*—Only eleven complaints were received in this office and out of these eight were rightly disposed of and the hearing of three complaints was adjourned to next meeting.

*X. E. N., U. B. D. C., Majitha Division.*—Only six complaints were pending disposal in this department and the hearing of these complaints was adjourned to next meeting as the enquiry in these cases had not been finalised.

*Chief Medical Officer, Amritsar.*—Six complaints were pending disposal with this department. Out of these complaints, four were found to have been rightly disposed of and the hearing of the two complaints was adjourned to the next meeting.

*Secretary, Municipal Committee, Amritsar.*—Thirty-two complaints were pending disposal in this office. Out of these twenty-two complaints were rightly disposed of and the hearing of the fourteen complaints was adjourned to the next meeting as the enquiry on these complaints was not complete.

*District Education Officer.*—Six complaints which were pending with this department were postponed to the next meeting as the enquiry in these complaints was not finalised.

*Assistant Registrar, Co-operative Societies, Amritsar.*—Only six complaints were pending disposal with this department. Out of these four were found to have been rightly disposed of and the hearing of the two complaints was adjourned to the next meeting.

*District Excise and Taxation Officer.*—Four complaints were pending with this department and the hearing of these complaints was adjourned to the next meeting.

*District Industries Officer.*—Only four complaints were pending with this department. Out of these one was discussed and found to have been rightly disposed of. These complaints were kept pending for the next meeting.

*S. D. O. (C), Ajnala.*—In all thirty, two complaints were pending disposal with this department. Out of these ten were discussed and found to have been rightly disposed of. Twenty-two complaints were kept pending for the next hearing.

*S. D. O. (C), Amritsar.*—Fifteen complaints were pending with this department. Out of these five have been discussed and found to have been rightly disposed of and ten complaints were kept pending for the next meeting.

*Settlement Officer (CH), Amritsar.*—Eleven complaints were pending with this department have been adjourned to next hearing because the concerned Officer did not come to G. A. II for discussion.

*B. D. P. O. Majitha.*—Fifteen complaints were pending with this office. These complaints have been postponed to the next meeting because the officer concerned did not come to G. A. II for discussion.

*Chairman Improvement Trust.*—One complaint which was pending with this office and has been postponed to the next hearing. The officer concerned has been directed to dispose of this complaint immediately. This complaint is from Capta in Harinderpal Singh regarding Plot No. 167, Makbul Road, area Amritsar.

*B. D. and P. O. Tarn Taran.*—Only five complaints were pending disposal with the office. Out of these two were discussed and found to have been rightly disposed of. The hearing of these complaints was adjourned to the next meeting.

*District Food and Supplies Officer.*—Eleven complaints were pending disposal with this office. Out of these nine complaints were discussed and found to have been rightly disposed of.

*S. D. O. (C), Patti.*—Tehsildar Patti, Sub-Regional Employment Officer, District Agricultural Officer, Treasury Officer, Secretary Soldiers, Sailors and Airman's Board, B. D. P. O.s. Verka, Tarsika, Rayya Gandivind, Chola Sahib, Valtoha, Patti, Ajnala, Chaugawan, Jandiala, Naushera Panuan and Bhikhiwind.

No statement has been received from the above mentioned offices. The Deputy Commissioner, directed all the officers of the above mentioned offices to send their statements in time in future, so that proper action should be taken on them.

*General.*—The next meeting of the District Public Relations and Grievances Committee will take place on 6th December, 1965 at 10 A. M. in the Zila Parishad hall and all the officers have been directed to send their statements in time i. e., before the due date, on 26th November, 1965. The statements which were received late will not be entertained.

Sd. S. P. KALIA,  
for Deputy Commissioner,  
Amritsar

No. CEA/232/677, dated the 15th November, 1965.

A copy of the proceedings is forwarded to all Heads of departments and members of the Committee for information and necessary action.

Sd. S. P. KALIA,  
A.D.C.  
for Deputy Commissioner, Amritsar.

Proceedings of District Public Relations and Grievances Committee held on 6th December 1965 under the Chairmanship of Shri Surinder Singh Bedi, Deputy Commissioner, Amritsar.

*Present—*

1. G.A.I. and G.A.II to Deputy Commissioner, Amritsar.
2. S.D.O. (C), Amritsar.

[Chief Minister]

3. XEN Public Health Division, Majitha Division, Jandiala Division and State Electricity Board.
4. District Food and Supplies Controller.
5. P.D.S.P.
6. Traffic Manager, Punjab Roadways.
7. B.D.P.O. Verka, Jandiala, Rayya, Chola Sahib, Naushera Panuan
8. Tehsildars, Amritsar/Ajnala/Tarn Taran.
9. S.O. (Ch.)
10. Chairman, Zila Parishad
11. Shri Umrao Singh M.L.A.
12. S.D.O. Drains Investigation Division.
13. Trust Engineer, Improvement Trust.
14. Secretary, Municipal Committee, Amritsar.
15. Assistant Industries Officer.
16. Assistant Registrar, Co-operative Societies, Tarn Taran
17. District Animal Husbandary Officer, Amritsar.
18. S.D.O. , P.W.D., B and R
19. Secretary, D.S.S. and Airmens' Board.
20. Secretary, Zila Parishad.
21. Deputy Chief Medical Officer.
22. District Education Officer, Amritsar.

Before the start of the proceedings of the meeting, Shri Umro Singh, M.L.A., pointed out that there was no arrangement of Warabandi in Tehsil Patti, and the cultivators do not get water in time. He also said that the tube-well connections are not regularly given to the cultivators.

The Deputy Commissioner directed the XEN concerned to arrange for the supply of water to the cultivators immediately so that there should be no cause for Complaint from either side. Shri Umrao Singh also pointed out that sufficient transport facilities for going to village Gudda and Shahbazpur are not available to the public there and that more transport lorries should be made available for the facilities of the public. The Deputy Commissioner directed the Traffic Manager that he should look to their grievance immediately.

*District Food and Supplies Controller.*—The District Food and Supplies controller informed that the cement condition in the city is satisfactory. Some of the B.D.P.Os pointed out that villagers have to bring cement from the city, and they have to undergo a lot of expense and trouble. The D.C. directed that the cement supply should be made available in Blocks. The D.F.S.C. replied that if this media was adopted it would be greatly expensive to the Government. The D.C. directed the B.D.Os. that they should examine the the applications submitted for supply of cement and pass them on to the Controller and for making this arrangement the D.C. gave ten days time. It was desired that after the supply of cement to the villagers. If there was any balance that quota should be supplied to the urban population.

The Controller also said that the condition of sugar is satisfactory in the city. The D.C. asked the Assistant Registrar Co-operative Societies about the prevailing

condition of sugar in villages. Shri Umrao Singh, M.L.A. pointed out that sugar is not rightly distributed in villages and the public is facing great difficulty. The Assistant Registrar replied that Co-operative societies are not functioning in villages and for this reason the public from the villages have to get to adjoining villages for getting sugar. The Deputy Commissioner directed the Assistant Registrar to look into it and the societies which are not functioning should be regularised so that there should be no cause of grievance to the public in villages. The Deputy Commissioner also directed that where the societies were not functioning the arrangement for the supply of sugar should be handed over to the charge of panchayats so that rural people should get sugar in their villages.

The D.C. enquired about the supply of stamp papers. The Treasurer who attended on behalf of the Treasury Officer said that the supply of stamps is very meagre as the supply is not coming from the quarter concerned. The Treasurer also stated that Government have issued instructions that if any person was not getting stamp paper, he could deposit the required amount in the treasury and on an application he could get certificate from the Collector and in this way the need of public for stamps can be met with. The Treasurer also said that there was less number of the stamp vendors and that their number should be increased.

Some of the members pointed out that the stamp vendors leave their places without informing any body and on account of this public is put to inconvenience. The Treasurer replied that the Excise and Taxation Officer should be asked to have control over them.

Shri Umrao Singh, M.L.A. pointed out that when any officer visits villages, the general public is not informed before hand and that the officers should send tour programmes before visiting villages to tehsildars and Panchayat Samitis. In this connection the D.C. told Shri Hargurdial Singh that when he goes out for survey in villages he should inform the Panchayat Samitis.

G.A.II. read out the instructions received from the Government regarding the disposal of complaints and the Deputy Commissioner directed all the officers present in the meeting that they should abide by the instructions issued by the Government from time to time. The Deputy Commissioner also pointed out that Government have issued new instructions to deal with the complaints and according to these instructions every officer should act upon them. P.G.O. system should be enforced as per instructions of the Government and in future P.G.O. slips will be issued to the officers who will send their replies within forty-eight hours. In case the P.G.O. slip is not replied in time, D.C. will take notice of it.

*S.S.P. Amritsar*.—Sixty five complaints were pending disposal with this department. Out of these 54 complaints were discussed and found to have been rightly disposed of. Ten complaints were postponed for hearing of the next meeting. One complaint was discussed in the meeting. The Police Officer said that in the meeting the report on this complaint will be submitted.

*XEN U.B.D.C. Majitha Division*.—Only eight complaints were pending disposal with this department, out of them four complaints were discussed and found to have been rightly disposed of. Four complaints have been kept pending for the next meeting.

*S.D.O. Tarn Taran*.—Only 21 complaints were pending disposal with this office. Out of them ten were discussed and found to have been rightly disposed of. Eleven complaints have been kept pending for discussion in the next meeting.

*S.D.O. Patti*.—Seventy-two complaints were pending disposal with this office. Out of them 37 complaints were discussed and found to have been rightly disposed of. Thirty-five complaints have been kept pending for discussion in the next meeting.

*E.O. Municipal Committee, Amritsar*.—Thirty-two complaints were pending disposal with this office. Out of them twenty complaints were discussed and found to have been rightly disposed of. Eleven Complaints have been kept pending for discussion in the next meeting.

*District Education Officer*.—Five complaints were pending disposal with this office and the same have been adjourned for hearing in the next meeting as the enquiry in these cases was not finalised.

*Sub-Regional Employment Officer*.—Only one complaint is pending and that has been adjourned for hearing on the next meeting as the enquiry in this case has not been finalised.

[Chief Minister]

*Senior District Industries Officer.*—Only four complaints were sent to this department. Out of them one complaint was discussed and found to have been rightly disposed of. Three complaints have been kept pending for discussion in the next meeting because the enquiry in these cases has not been finalised.

*Assistant Registrar, Tarn Taran Co-operative Societies.*—Only one complaint was pending with this office and that was kept pending for discussion in the next meeting as the enquiry in this case was not complete.

*District Food and Supplies Controller.*—Only three complaints were sent to this office for report. Out of them two complaints were discussed and found to have been rightly disposed of. One complaint has been kept pending for discussion in the next meeting.

*Settlement Officer (CH), Amritsar.*—Eighteen complaints were sent to this office for report and those were kept pending for discussion in the next meeting as the officer concerned did not come to G.A. II. for discussion.

*D.D.P.O. Amritsar.*—Twenty complaints were sent to this office for report. Out of these nineteen complaints have been discussed and found to have been rightly disposed of. and one has been kept pending for discussion in the next hearing.

*B. D. and P. O. Rayya.* Only ten complaints were sent to this office for report. Out of these nine have been discussed and found to have been rightly disposed of. One complaint has been kept pending for hearing in the next meeting.

*X. E. N. Punjab State Electricity Board Tarn Tarn, Excise and Taxation Officer, District Public Relations Officer, Tehsildar Patti, Treasury Officer, all the B. D. & P. Os except Rayya, Secretary Soldiers and Airmen's Board.*

The statements from the above cited officers have not been received. The Deputy Commissioner directed these officers that they should send their statements in time so that action can be taken on them. The officers concerned who do not send their statements before due dates, their statements will not be entertained and the Government will be informed regarding their negligence.

The statements of the following offices have not been received in time and for this reason no action has been taken on their statement as these have been received after the due date. The officers concerned have been informed that they should send their statement by due date.

Chief Medical Officer, Amritsar.

S.D.O.(C), Ajnala.  
S.D.O.(C), Amritsar

*General.*—Next meeting of the District Public Relations and grievances Committee will take place on 5th January, 1966 at 10 A.M. in the Zila Parishad Hall, Amritsar and all the officers should send their statements before 24th December, 1965 and also come for discussion to G.A.II.

All S.D.Os and Tehsildars .. 27th December, 1965

All the XENs .. 28th December, 1965

Secretary M.C. and Chairman Improvement Trust  
D.P.S.C. 31st December, 1965

The remaining departments and S.S.Ps. office for 1st January, 1966

(Sd.) P.AHLUWALIA  
for Deputy Commissioner, Amritsar.

No 739/CEA

dated 14th December, 1965

A copy is forwarded to all the concerned departments and members of the committee for information and necessary action.

(Sd.) P. AHLUWALIA  
for Deputy Commissioner, Amritsar.

Proceedings of the meeting of the District Public Relations and Grievance Committee held on 5th January, 1966 under the Chairmanship of Shri Surinder Singh Bedi I.A.S., Deputy Commissioner, Amritsar.

Present—

1. P.G.O., Amritsar
2. S.D.Os (Civil) Tarn Taran, Patti, Ajnala and Amritsar.
3. Tehsildars Patti, Ajnala, Tarn Taran and Amritsar.
4. XENs, P.W.D., B.&R, Electricity, U.B.D.C, Majitha Division and Jandiala Division.
5. D.D.P.O., Amritsar.
6. B. D.P.Os. Ajnala, Bhikhiwind, Valtoha, Rayya, Gandiwind, Jandiala, Chola Sahib and Naushera Panuan,
7. Secretary, Zila Parishad.
8. E.O. M.C, Amritsar.
9. Secretary, D.S.S. & A. Board.
10. Settlement Officer (C./H.).
11. District Education Officer, Amritsar.
12. District Food and Supplies Controller.
13. D.S.P. Headquarters.
14. Shri V.S. Sodhi, Ex. Magistrate.
15. Chairman, Improvement Trust.
16. District Agricultural Officer, Amritsar.
17. District Animal Husbandary Officer, Amritsar.
18. Divisional Forest Officer, Amritsar.
19. Traffic Manager, Punjab Roadways.
20. Assistant Registrars, Co-operative Societies, Amritsar and Tarn Taran.
21. Shri Umrao Singh, M.L.A.
22. District Public Relations Officer :
23. Medical Superintendent, V.J. Hospital, Amritsar.
24. S.D.O. Drains Investigation.

*District Food and supplies Controller.*—The District Food and Supplies Controller informed the members that wheat atta is being sold in the market at the rate of Rs 24 to Rs 25 and the normal condition of the wheat atta is satisfactory. He also said that wheat is available in the market at the rate of Rs 54 to Rs 57 per quintal. He also pointed out that the sugar condition in the city is satisfactory.

*Shri Umrao Singh M.L.A.*—Shri Umrao Singh pointed out that the work of P.W.D. in the jurisdiction of Patti Sub, Division is not satisfactory, and that the officers of this department should take special interest to remove the grievances of the public in this sub-division. He also pointed out that the sugar condition in the jurisdiction

## [Chief Minister]

of Patti tehsil is unsatisfactory. The villagers of Makhi Kalan and Margindpura are not getting sugar for the last six months. The D.C. directed the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Tarn Taran to remove this difficulty of the Public immediately. Shri Umrao Singh also pointed out that transport facilities are not available to Cheema village, and now when bridges over the drains have been reconstructed, transport facilities should be provided to the villagers of Cheema. He also desired that one more bus should be made available for going to valtoha, so that people of the locality should get transport facilities. The Deputy Commissioner directed the Traffic Manager to look into it. The Traffic Manager replied that early arrangements will be made after surveying the area. Shri Umrao Singh further pointed out that military personnel stop the buses going to Mahmudpura and Cheema. The Deputy Commissioner directed the Traffic Manager to approach the military authorities in order to remove this difficulty of the public. Shri Umrao Singh also pointed out that military have acquired most of the land in gardens and have pitched up their tents there and that Government is not properly compensating the owners with the result that public has been put to a great loss. The Deputy Commissioner directed Shri Hargurdial Singh, Military Land Acquisition Officer to look into this matter. Shri Umrao Singh also pointed out that there is a complaint of the public that they are not getting proper relief. The Deputy Commissioner asked Shri V.S. Sodhi to see to this. Shri V.S. Sodhi also said that proper investigation will be made in this respect and there will be no complaint from the public about it in future. Shri Umrao Singh again pointed out that when the turn regarding compensation of Khasra Nos of this Halka comes, its list be either supplied to the Panchayat or to the Tehsildar, so that the public should know of it before hand. The Deputy Commissioner directed Shri Hargurdial Singh that when he will make a programme to serve this Halqa, he should sent the list of Khasra Nos to the Panchayat samities, so that the public should know it.

*S.S.P. Amritsar.*—In all 74 complaints were pending disposal with this department. Out of these 59 complaints were found to have been properly dealt with. Fifteen complaints were kept pending for the next meeting.

*XEN Majitha Division.*—Only six complaints were pending with this department. Out of these two complaints have been found to be properly dealt with, and four complaints were kept pending for the next meeting.

*S.D.O.(C), Amritsar.*—Fourteen complaints were pending with this office. Out of these ten complaints have been found to be properly dealt with and four complaints are still under enquiry.

*S.D.O.(C) Patti.*—Fifty-three complaints were pending disposal with this office. Out of these twenty complaints were found to have been properly dealt with. 33 complaints are still under enquiry.

*S.D.O.(C), Ajnala.*—Seventeen complaints were pending with this office. The enquiry in these complaints was not complete. These were, therefore, postponed for hearing to the next meeting.

*S.D.O.(C) Tarn Taran.*—Twenty complaints were pending disposal with this office. Out of these eight complaints were found to have been properly dealt with.

*Chairman, Improvement Trust.*—Only one complaint is pending disposal with this department. The inquiry into this complaint is incomplete. It has, therefore, been kept pending for the next meeting.

*Secretary, M.C., Amritsar.*—Only twenty complaints were pending disposal with this department. Out of these 17 complaints were found to have been properly dealt with and three complaints have been postponed to the next meeting.

*Chief Medical Officer.*—Three complaints were pending with this department and as the enquiry was not complete, therefore, these complaints have been postponed for hearing to the next meeting.

*District Education Officer.*—Three complaints were pending with this department and as these were still under enquiry, therefore, they were kept pending for the next meeting.

*A. R. Co-operative Societies, Amritsar*—Two complaints were pending with this department and these have been postponed for the next meeting.

*District Food and Supplies Controller, Amritsar*.—One complaint was pending with this department, and it has been postponed to the next meeting.

*D.D.P.O., Amritsar*.—Five complaints were pending disposal with this office. Out of these three were found to have been properly dealt with. Two complaints were postponed for hearing to the next meeting.

*General Manager, Punjab Roadways*.—Only one complaint was pending with this department and as the enquiry was incomplete, it has been adjourned to the next meeting.

*District Industries Officer*.—Only four complaints were pending disposal with this department. Out of these two were found to have been properly dealt with and two complaints have been kept pending for the next meeting.

*S.O., Consolidation of Holdings*.—Only one complaint was pending with this department and since the enquiry was not complete, it has been adjourned to the next meeting.

*B.D., and .PO. Choganwan*.—Only two complaints were pending disposal with this department.

District excise and Taxation officer/XEN, Punjab State Electricity Board, T.T. XEN Drainage Division, XEN Sutlej Canalisation Officer/Tehsildar, Patti, all B.D.P.O.s except Chogawan.

All the above-noted officers have not sent their statements and the Deputy Commissioner directed them to send the statement in the time in future.

*General*.—The next meeting of the District Public Relations and Grievances Committee will be held on 8th February, 1966 at 10 A.M. in the Zila Parishad Hall. All the officers are requested to send the statement in time. The discussion days are as under :

All S.D.O (C) and Tehsildar	.. 27th January, 1966
Municipal Committees/Chairman I/T and D.F.S.C.	28th January, 1966.
All remaining departments	29th January, 1966
S.S.P., Amritsar	31st January, 1966

**Proceedings of the meeting of the Public Relations and Grievances Committee, Amritsar held on 8th February, 1966 under the Chairmanship of Shri S.S. Bedi, I.A.S., Deputy Commissioner, Amritsar**

**Present.—**

General Assistant II to D.C.

Sub-Divisional Officer ( Civil), Ajnala.

District Food and Supplies Controller, Amritsar.

X.E.N., Punjab State Electricity Board, Amritsar.

X.E.N., U.B.D.C., Amritsar, Jandiala Division.

X.E.N., Drainage Investigation Division.

D.S.P. ( H.Qs), Amritsar.

Divisional Forest Officer.

Additional Excise and Taxation Officer.

Assistant Registrars, Co-operative Societies, Amritsar and Tarn Taran.

General Manager, Punjab Roadways, Amritsar.

D.A.O., D.I.O., D.A.H.O., D.E.O. and District Language Officer.

## [Chief Minister]

Chairman Improvement Trust, Amritsar.  
 Secretary, Zila Parishad, Amritsar.  
 Secretary, Municipal Committee, Amritsar.  
 Tehsildars, Amritsar, Ajnala, Patti and Tarn Taran.  
 Deputy Medical Officer, V.J. Hospital.  
 B.D. & P.Os., Rayya, Verka, Chogawan, Jandiala, Chola Sahib, Bhikhiwind, Valtoha and Gandiwind.  
 S.E.P.O., Majitha.  
 Assistants of the offices of S.D.Os(C), Amritsar and Patti.  
 Head Clerk of X.E.N., U.B.D.C., Majitha Division.

## Proceedings

*S.S.P., Amritsar.*—Ninety-seven complaints were sent to S.S.P., Amritsar for enquiry and report. Out of these, action taken on 55 complaints was considered adequate. The remaining 42 complaints were kept pending for the next meeting. Two complaints, one of Drug case and the other against A.S.I., Jaikarn Das were fully discussed in the meeting. The Drug case was ordered to be enquired into again and the second complaint was filed.

*Executive Engineer, U.B.D.C., Jandiala Division, Jandiala.*—There was one complaint sent for enquiry to this officer. The case was discussed and the Deputy Commissioner ordered to transfer the Patwari Canal from his present circle under intimation to this office.

*Executive Engineer, U.B.D.C., Majitha Division.*—There were seven complaints pending with this officer. Out of these action on one was considered appropriate and the remaining six complaints were kept pending to be considered at the time of next meeting.

*S.D.O. (C), Amritsar.*—Out of 13 complaints with this officer, action taken on three complaints was considered adequate and the remaining ten were kept pending for the next meeting.

*S.D.O. (C), Tarn Taran.*—There were in all 22 complaints with this officer. Nine complaints have been disposed of properly and the remaining 13 complaints have been kept for the next meeting.

*S.D.O.(C), Patti.*—There were 43 complaints pending with this officer. The action taken on 15 complaints was considered proper and the remaining 28 complaints will be discussed at the time of next meeting.

*S.D.O.(C), Ajnala.*—There are nine complaints pending with this officer and these will be taken up at the time of next meeting.

*General Manager, Punjab Roadways.*—Only two complaints are pending with this officer.

*Chief Medical Officer, Amritsar.*—Only one complaint is pending for disposal with this officer.

*Assistant Registrar, Co-operative Societies, Amritsar.*—Only one complaint is pending with this officer.

*District Food and Supplies Controller.*—Out of three complaints with this officer, action taken on one complaint has been considered appropriate and the remaining two have been kept for the next meeting.

*District Industries Officer, Amritsar.*—Five complaints are pending with this officer.

*S.O. (Ch.), Amritsar.*—Four complaints are still pending with this officer.

*District Education Officer.*—Six complaints are still pending with this officer.

*District Excise and Taxation Officer.*—There are nine complaints pending with this officer and these will be considered at the time of next meeting.

*Tehsildar (Ajnala).*—Only one complaint is pending with this officer.

*D.D. and P.O., Tarn Taran.*—There are three complaints pending with this officer.

*B.D. and P.O. Majitha.*—Thirteen complaints are pending with this officer.

**General.**—The next meeting of the Public Relations and Grievances Committee will be held on 5th March, 1966 and 10 a.m. in Zila Parishad Hall. All the officers are requested to send the statement regarding disposal of complaints to this office by the 25th February, 1966 and no statement will be entertained after that date. The officers are further required to attend the office of the Public Grievances Officer for discussion at the complaints as under:—

28th February, 1966	.. All S.D.Os ( Civil) and Tehsildars
1st March, 1966	Secretary, Municipal Committee, Chairman, Improvement Trust and D.F.Sc., Amritsar
2nd March, 1966	.. S.S.P. and all the remaining officers.

(Sd.) P. AHLUWALIA,  
for Deputy Commissioner.

#### Communist detained under the Defence of India Rules

**3173. Comrade Hardit Singh Bhathal :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

- (a) the total number of communists arrested and detained under the D.I.R. in the State as at present ;
- (b) the names of the detenus, the names of the jails where they are detained class-wise, the time since when they are under detention and the period so far spent under detention by each ;
- (c) the total number of detenus at present in Hoshiarpur Jail, class-wise together with the condition of their health ;
- (d) the names of detenus, if any, in the jails suffering from various diseases together with the names of their respective diseases and the details of the arrangements, if any, made for their treatment ;
- (e) whether Government/ authorities concerned have received any intimation from Comrade Ganda Singh of Sangrur one of the above-mentioned detenus, that his teeth are in a very bad condition due to pyorrhea and that no facilities have been provided for the treatment of his teeth ;
- (f) whether any representation was received by the officers concerned or a deputation met them in connection with the transfer of the said detenu to some other place where arrangements for the treatment of his disease exist ;
- (g) whether there is any proposal under the consideration of the Government to transfer the said detenu to some suitable jail for his treatment ; if so, the time by which he is likely to be transferred ; if not, the reasons therefor ?

**Shri Chand Ram :** Minister for Welfare and Justice (a) 59.

(b) A statement containing the requisite information is at Appendix 'A'.

(c) Only two non-communist detenus are at present detained in District Jail, Hoshiarpur. They are ' Ordinary Class' detenus. The general condition of their health is good.

(d) A statement containing the requisite information is at Appendix 'B'.

(e) While Shri Ganda Singh was detained in District Jail, Hoshiarpur, he had put in an application for treatment in the Rajindra Hospital, Patiala. The same was referred to the Chief Medical Officer, Hoshiarpur, by the Superintendent, District Jail, Hoshiarpur. The Dental Surgeon of the Civil Hospital, examined him and reported as under:

"He has been given good treatment here, so it is not necessary to transfer him to Patiala Jail."

(f) As stated above, against part (e) of the question, Shri Ganda Singh had put in a representation which was dealt with accordingly.

(g) Shri Ganda Singh has since been transferred from District Jail, Hoshiarpur, to District Jail, Nabha. Orders for treatment of his gum trouble in the Rajindra Hospital, Patiala, have been issued.

[Minister for Welfare and Justice]

## APPENDIX "A"

Serial No.	Name of the detenu	Class	Time since when under detention	Period spent so far under detention
CENTRAL JAIL, PATIALA				Y. M. D.
(B) 1	Shri Hardit Singh Bhathal..	Special	30th December, 1964 to 11th December, 1965 and 11th December, 1965 to date	1 2 6
2	Makhan Singh Tarsikka ..	Do	Ditto	1 2 6 He is at present on parole since 26th February, 1966
3	Chattar Singh ..	Ordinary	Ditto	1 2 6
4	Harnam Singh Chamak ..	Do	Ditto	1 2 6
5	Ram Kishan Bharolian ..	Do	Ditto	1 2 6
6	Gurcharan Singh ..	Do	Ditto	1 2 6
7	Gurbux Singh Atta ..	Do	Ditto	1 2 6
8	Sulakhan Singh ..	Do	Ditto	1 2 6
DISTRICT JAIL, NABHA				
1	Vidya Dev ..	Ordinary	30th December, 1964 to 11th December, 1965 and from 11th December, 1965 to date	1 2 6
2	Gajjan Singh, Tandian ..	Do	20th December, 1964 to 15th December, 1965 and from 15th December, 1965 to date	1 2 6
3	Raghbir Singh Jhakhar ..	Do	Ditto	1 2 6
4	Rachhpal Singh ..	Do	20th December, 1964 to 15th December, 1965 and from 10th December, 1965 to date	1 2 6
5	Dhanpat Rai Nahar ..	Do	Ditto	1 2 6
6	Gandharv Sain ..	Do	Ditto	1 2 6
7	Partap Singh Dhanaula ..	Do	Ditto	1 2 6

Serial No.	Name of the detenu	Class	Time since when under detention	Period spent so far under detention
				Y. M.D
8	Balbir Singh	.. Ordinary	Ditto	1 2 6
9	Ram Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
10	Satwant Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
11	Bhag Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
12	Janak Singh Bhathal	.. Do	30th December, 1964 to 21st December, 1965 and 21st December, 1965 to date	1 2 6
13	Hazara Singh Jassar	.. Do	Ditto	1 2 6
14	Dharam Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
15	Ude Singh Keshav	.. Do	Ditto	1 2 6
16	Ghuman Singh	.. Do	30th December, 1964 to 11th December, 1965 and 11th December, 1965 to date	1 2 6
17	Mehar Singh	.. Do	30th December, 1965 to 10th December, 1965 and from 10th December, 1965 to date	1 2 6
18	Ganda Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
19	Gurnam Singh	.. Do	Ditto	1 2 6

## DISTRICT JAIL, AMRITSAR

1	Kesar Singh	.. Ordinary	30th December, 1964 to 20th January, 1966 and from 20th January, 1966 to date	1 2 6
---	-------------	-------------	---	-------

## DISTRICT JAIL, SANGRUR

1	Chanan Singh Dhut	.. Ordinary	30th December, 1964 to 11th December, 1965 and from 11th December, 1965 to date	1 2 6
2	Rachhpal Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
3	Fauja Singh Bhullar	.. Do	Ditto	1 2 6
4	Satya Mandan	.. Do	Ditto	1 2 6
5	Chanan Singh Brar	.. Do	Ditto	1 2 6

[Minister for Welfare and Justice]

Serial No.	Name of the detenu	Class	Time since when under detention	Period so far spent under detention
				Y. M.D
6	Dalip Singh Tapiala	.. Ordinary	30th December, 1964 to 11th December, 1965 and from 11th December, 1965 to date	1 2 6
7	Gian Singh Pleader	.. Do	Ditto	1 2 6
8	Darshan Singh Jhabal	.. Do	Ditto	1 2 6
9	Gurbux Singh Dakota	.. Do	Ditto	1 2 6
10	Mange Ram Vats	.. Do	Ditto	1 2 6
11	Bhag Singh Sajjon	.. Do	Ditto	1 2 6
12	Daya Singh Prem	.. Do	Ditto	1 2 6
13	Mangal Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
14	Bakhshi Ram	.. Do	Ditto	1 2 6
15	Sarwan Singh Cheema	.. Do	Ditto	1 2 6
16	Bishan Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
17	Bhajan Singh	.. Do	Ditto	1 2 6

## CENTRAL JAIL, HISSAR

1	Prem Chand Bhardwaj	.. Ordinary	30th December, 1964 to 11th December, 1965 and 11th December, 1965 to date	1 2 6
2	Hazur Singh	.. Do	Ditto	1 2 6
3	K. R. Palta	.. Do	31st December, 1964 to 11th December, 1965 and 11th December, 1965 to date	1 2 5
4	Kishori Lal	.. Do	Ditto	1 2 5
5	Kartar Singh Gujapeer	.. Do	Ditto	1 2 5
6	Dharam Singh Kasni	.. Do	Ditto	1 2 5
7	Ishar Singh Sodhi	.. Do	Ditto	1 2 5
8	Amarmmeet Singh	.. Do	Ditto	1 2 5
9	Bhim Singh Advocate	.. Do	Ditto	1 2 5
10	Dalip Singh	.. Do	Ditto	1 2 5
11	Devki Nandan	.. Do	Ditto	1 2 5

1	2	3	4	5
12	Ganpat Singh	.. Ordinary	31st December, 1964 to 11th December, 1965 and from 11th December, 1965 to date	1 2 5
13	Karnail Singh Phide	.. Do	Ditto	1 2 5
CENTRAL JAIL, DELHI				
1	Harkishan Singh Surjeet	.. Ordinary	Ditto	1 2 5

## APPENDIX "B"

Serial No.	Name of the detenus	Disease from which suffering	Details of arrangements made for their treatment
------------	---------------------	------------------------------	--

## CENTRAL JAIL, PATIALA

1	Shri Hardit Singh Bhathal	Osteoarthritis Knees	He was examined by the Medical Specialist of the Rajindra Hospital, Patiala and is being given the treatment in Jail as advised
2	Shri Makhan Singh Tarsikka	Hiatus Hernia. Complained of pain in lower chest and upper abdomen	He was examined by the Specialist and is being given necessary treatment as advised
3	Shri Sulakhan Singh ..	Dental trouble	He is however on parole since 26.2.66. He is getting necessary treatment regularly
4	Ram Kishan Bharolian	..	His old denture and spectacles has been replaced by new one
5	Gurcharan Singh Randhawa	Pain in back and knees	He was examined by the Specialist and is being given necessary treatment as advised
6	Gurbux Singh Atta ..	Hypertension and ischameic heart and Nassal polypur and alergic rhinitis	He is under the treatment of Specialist of Rajindra Hospital, Patiala
7	Harnam Singh Chamak	Diabetes and Ischae-mic heart	Ditto

## DISTRICT JAIL, NABHA

1	Satwant Singh	.. 1. Old Injury knee 2. Arthritis 3. Dental trouble	He is being given the following treatment :— (1) Linament Terribinthinae application Elkosine Tab. Novalgin. Injection Vit. B. 1. and referred to Civil Hospital, Nabha for treatment
---	---------------	--	--

Serial No.	Name of the detenus	Disease from which suffering	Detail of arrangements made for their treatment
2	Dharam Singh	.. Acute conjunctivitis. Ipsomnia and absence of teeth	Terramycin Eye Ointment. Achromycin in old eye drops. Tab. Equianial recommended for denture
3	Dr. Bhag Singh	.. Enlarged Prostrate. Corn	Tab. Stilbisterol Alkasol. Advised operation. No. 20 Oz. 1 T.D.S. Acidacitic for application. Cornik
4	Dhanpat Rai Nahar	.. 1. Piles and Defective vision	Ung. Galic Mopio. Liquid parafin. Injection Streptopenicilin. Tab. Vit. B. Complex. Nepercainol. He is being sent to Rajindra Hospital, Patiala Examination by the Specialist for defective vision
5	Partap Singh Dhanaula	Dermatitis and Presbopia	Ung. Derm Equinal. Tab. B. Complex. Tab. Aspirin. Cup. Chloromycetin. Tab. Novalgin. He has been supplied with glasses
6	Balbir Singh	.. Presbopia	Glasses have been provided
7	Janak Singh	.. Bachache, Dental trouble and Acute Bronchitis	He has been recommended diathermy for 15 days and is to be examined by the Dental Surgeon, Nabha. He is being given No. 14
8	Ghuman Singh	.. Dermatitis. Presbopia and absence of teeth	Ung. Betnoyit. Dermoquinol. Ung. Tarsalon. Ung. Zinc. Boric Tab. Prednislone. Tab. Dilosyin. Glasses have been supplied. Referred to Skin Specialist of Rajindra Hospital, Patiala and has been recommended for denture at the same Hospital
9	Vidya Dev Longowal	.. I.V.P.D. and Peptic Ulcer. Acute Conjunctivitis	Hard Bed. Tab. Celusil. Nutrodona. Tab. Fersolate Referred to Medical Specialist of Rajindra Hospital for investigation. Terramycine Eye ointment. achromycin in oil eye drops
10	Ghanderv Sen	.. Dental trouble and defective vision	Scaling and Gum treatment. To be examined by the Eye Specialist of the Rajindra Hospital, Patiala
11	Ram Singh	.. Hypertension, Elergium Dermetatis and Piles	Tablets Surpina Injection P. Pencilline admitted in Rajindra Hospital for treatment

1	2	3	4
12	Rachhpal Singh	.. Defective vision	Ung. Detonovit. Ung. Nupre-can. Referred to Eye Specialist of Rajindra Hos-pital, Patiala
13	Raghbir Singh	.. Backache. Ch. Cons-tripation. Neu ralgia	Tab. Butacort. Tab. Vitamin B.1. Tab. Vitamin B. Com-plex. Enos. Fruit Salt. Tan. Saridon
14	Hazara Singh Jassar	.. G. Debality	Tab. Vitamin B Complex. Tab. Multi Vitamin.
15	Udhey Singh	.. Dyspepsia	Tab. Vitamin B. Complex.
16	Mehar Singh	.. Dyspepsia, Defective Vision. Multiplecar-ries	Becasuler. Recommended Glasses. Referred to Rajindra Hos-pital, Patiala for treatment
17	Gurnam Singh	.. Dyspepsia. Coryza. Dental trouble	Becasules. Tab. Medribon. Referred to Rajindra Hospi-tal, Patiala for Dental treat-ment (Scaling and Polishing)
18	Ganda Singh	.. Gingivitis	Referred to Rajindra Hospital, Patiala for treatment

## DISTRICT JAIL, AMRITSAR

1	Shri Kesar Singh	.. Mental patient	He is under the treatment of Dr. Vidya Sagar of the Punjab Mental Hospital, Amritsar
---	------------------	-------------------	--

## DISTRICT JAIL, SANGRUR

1	Dalip Singh Tapiala	.. Ch. Amboisis 2. Teeth	He is being treated by the Jail Medical Officer. The Artificial grinders are being arranged from the Ra jindra Hospital, Patiala
2	Shri Rachhpal Singh	.. 1. Ch. Conjunctivities 2. Visions	He is under the treatment of Jail Medical Officer. Already using Spectacles. Applied for change. Being arranged through the Eye Specialist
3	Shri Bakhshi Ram	.. External Piles	He is under treatment of the Jail Medical Officer
4	Shri Fauja Singh Bhullar	1. Post. Inf. Hepatitis 2. Visions	Tablets. Prednisolone Course. Vitazyme Elixir. Being re-ferred to Rajindra Hospital, Patiala, for further investiga-tions.  2. Requests for change of glasses, which are being arrang-ed through the local special-ist

[Minister for Welfare and Justice]

Serial No.	Name of the detenus	Disease from which suffering	Details of arrangements made for their treatment
5	Shri Satya Mandan ..	Ch. Dermatitis	Under treatment of the Jail Medical Officer
6	Shri Gian Singh ..	Ch. Para-Nasal Sinusitis	Under treatment of the Jail Medical Officer, and is being referred to E.N.T. Specialist of the Rajindra Hospital, Patiala
7	Shri Bhag Singh Sajjon	Ch. Stomatitis	Under treatment of the Jail Medical Officer
8	Shri Darshan Singh ..	Brachial Neuralgia 2. Pyroic Teeth	Under treatment of the Jail Medical Officer, and Dental Surgeon. He is being provided with artificial denture
9	Shri Gurbux Singh Dakota	Mild Ch. Sacral, Neuralgia	Under treatment of the Jail Medical Officer
10	Shri Mange Ram Vats	Ch. Dermatitis Hard of Hearing	Under treatment of Jail Medical Officer He is being provided with hearing aid machine
11	Shri Daya Singh Prem	Ch. Glaucoma Operated Gum Im- maturesenile Contract	Under the treatment of Eye Specialist
12	Sarwan Singh Cheema ..	Ch. Amboisis	Under treatment of the Jail Medical Officer
13	Bhajan Singh ..	Ch. Conjunctivitis	Ditto
14	Shri Chanan Singh Brar	Ch. Dermatitis	Ditto
15	Shri Bishan Singh ..	Ch. Amboisis	Ditto
CENTRAL JAIL, HISSAR			
1	Prem Chand Bhardwaj	Nauritis	He is being given treatment locally
2	Hazur Singh ..	Leucoma Crote Opacity Ey. C. Refraction	Treated in the Government Medical College, Rohtak by Specialists. Glasses have been provided
3	K. R. Palta ..	Old Injury Rt. Ankle Joint	Local treatment. Specialist treatment at Civil Hospital, Hissar.—X-Ray.
4	Pt. Kishori Lal ..	Ch. Bronchitis. Br. Asthama. Loose Artificial Denture	Local treatment. Case for Specialist treatment in the Rajindra Hospital, Patiala is under consideration
5	Kartar Singh Gujapir	P.M.	Local treatment

Serial No.	Name of the detenus	Disease from which suffering	Details of arrangements made for their treatment
6	Ishar Singh Sodhi	Refraction Check up Ventral Harnia	Treated in the Medical College, Hospital, Rohtak. Glasses have been provided to him
7	Bhim Singh, Advocate	Coryza	Under treatment of the Jail Medical Officer
8	Ganpat Singh	Debility. C. Anemia and Refraction	Under treatment of the Jail Medical Officer. He has been provided with glasses
9	Karnail Singh	Devalid Septum. C. Ch. Sinusitis	He is being referred to E.N.T. Specialist

## CENTRAL JAIL, DELHI

1	Shri H. S. Surjeet	Gastric Acidity. Osteo Arthritis Spine. Trachoma as per record shown by him Interproximal Carics	For Trachoma and for weakness of eyes, he has been provided with glasses. His case for Osteo Arthritis and Dental troubles for which he requires a radiological treatment in the Irwin Hospital is under consideration
---	--------------------	--	--

## Applications submitted by Detenus for Family Allowance

**3174. Comrade Hardit Singh Bhatia :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- the number and names of the detenus in the Punjab Jails who have applied for family allowances so far ;
- the number of applications of the said detenus which were rejected and of those accepted, respectively ;
- the number of applications out of those referred to in part (b) above which were received before and after the 11th November, 1965, separately ;
- the dates of submission of applications and rejection thereof together with the time since when the applicants have been under detention ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) 32. A list of names is placed on the Table of the House.

(b) 48 applications were received. Out of them 36 have been rejected and 12 are under consideration.

(c) and (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement showing the number of applications received before and after 11th November, 1965 and date of submission of applications and rejection together with dates of detention

Serial No.	Name of Detenu	No. of applications received before 11th after 11th November, November, 1965	No. of applications received	Date of submission of applications	Date of rejection of applications	Date of detention
1	2	3	4	5	6	7
1	Raghubir Singh Jharkhar	..	2	February/March, 65	Rejected	30-12-64
2	Ude Singh	..	1	30-1-65	7-4-65	30-12-64
3	Gian Singh	..	1	23-1-65	8-4-65	30-12-64
4	Dharam Singh	..	1	29-1-65	7-4-65	30-12-64
5	Ishar Singh	..	1	27-1-65	29-6-65	30-12-64
6	Gurbax Singh Atta	..	1	29-3-65	29-6-65	30-12-64
7	Mehar Singh Kanpni	..	2	23-1-65 20-7-65	31-1-66	30-12-64
8	K. R. Palta	..	1	27-1-65	6-5-65	30-12-64
9	Ram Kishan Bharolian	..	1	27-1-65 24-1-66	7-4-65 Under consideration	30-12-64
10	Chanan Singh Brar	..	1	..	..	30-12-64
11	Harkishan Singh Surjit	..	1	..	Under consideration	31-3-65

12	Gurcharan Singh Randhawa	...	1	1	23-3-65 24-1-66	26-4-65 Under considera- tion	30-12-64
13	Dhanpat Rai Nahar	..	1	1	18-1-65 5-1-66	Under considera- tion	30-12-64
14	Keser Singh	..	1	..	15-1-65	6-5-65	30-12-64
15	Rachhpal Singh	..	1	..	March, 1965	25-5-65	30-12-64
16	Bhajan Singh	...	2	2	29-1-65 12-7-65 11-11-65 23-11-65	29-3-65 11-8-65 14-2-66 14-2-66	30-12-64
17	Daya Singh Prem	...	1	..	..	Under considera- tion	30-12-64
18	Fauja Singh Bhullar	...	1	1	14-8-65 7-2-66	5-1-66 Under consider- tion	30-12-64
19	Darshan Singh Jhabal	...	2	..	25-1-65 12-5-65	8-4-65 7-6-65	3-1-65
20	Kartar Singh Mujaipir	...	1	1	1-2-65 17-12-65	6-5-65 10-2-66	30-12-64
21	Bishan Singh	..	1	..	1-3-65	27-5-65	24-1-65
22	Sul Khan Singh	...	1	1	27-1-65 21-1-66	24-4-65 Under considera- tion	20-1-65
23	Prem Chand Bhardwaj	...	2	1	10-2-65 24-3-65 28-12-65	29-3-65 21-4-65 Under considera- tion	30-12-64

[Minister for Home and Development]

Serial No.	Name of detenu	No. of applications received before 11th November, 1965	No. of applications received after 11th November, 1965	Date of submission of applications	Date of rejection of applications	Date of detention
1	2	3	4	5	6	7
24	Vidya Dev Longowal	..	1	26-1-65	24-3-65	30-12-64
25	Ghuman Singh	..	1	30-1-65	8-4-65	30-12-64
26	Dalip Singh Bhatiwala	..	..	27-1-66	Under consideration	27-4-65
27	Janak Singh Bhathal	..	1	30-1-65	29-3-65	30-12-64
28	Ganda Singh	..	1	February, 1965	29-4-65	30-12-64
29	Ram Singh Harinai	..	1	19-8-65	8-12-65	30-12-64
30	Dharam Singh Kasni	..	..	16-12-65 7-1-66	Under consideration	30-12-64
31	Devki Nandan	..	2	29-1-65 8-5-65	15-4-65 1-6-65	30-12-64
32	Satya Mandan	..	1	26-1-65	8-4-65	30-12-64

### Facilities of Water and Electricity provided in the Residential Quarter of Jail Warders

**3177. Comrade Hardit Singh Bhathal :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- (a) the names of the jails in the State where adequate facilities for the supply of water and electricity are available to the warders in their family and ordinary residential quarters ;
- (b) the nature of such facilities in detail, jail-wise ;
- (c) whether the said facilities of electricity and water, etc. are adequately provided in the Warders' quarters of the Central Jail, Patiala, if not, the reasons therefor ?

**Shri Chand Ram :** (a) and (b) Almost all the jails in the State have adequate arrangements for the supply of water to the warders in their family and ordinary residential quarters, but the position regarding the availability of electricity lighting arrangements in various jails is indicated below :—

(i) *Central Jail, Ambala.*—Both these facilities have been provided in warders quarters and single warder's line constructed after partition. These facilities however do not exist in old quarters where water is supplied through common water taps provided in front of the quarters. The number of such quarters is eight only.

(ii) *Central Jail, Ferozepore.*—Both these facilities exist in single warders' lines but there is no electricity in the family warders quarters and water is supplied through common water taps provided in front of the quarters.

(iii) *Central Jail, Hissar.*—Both these facilities exist in warders quarters and single warders line.

(iv) *Central Jail, Patiala.*—Adequate water supply arrangements have been made by providing common water taps in front of the warders quarters. The single warders lines have been provided with electricity and common bath-rooms. Out of 41, only 7 residential quarters have been provided with electricity. It is mentioned in this connection that management of Central Jail, Patiala was transferred to Punjab on integration of Pepsu in the year 1956. It has, therefore, not been possible to provide electricity in every quarter due to lean financial position. However, such facilities are provided in the newly constructed quarters in the state.

(v) *District Jail, Nabha.*—Both these facilities are available in single warders' line but there is no electricity in the family quarters and water is supplied through common water taps provided in front of the quarters.

(vi) *District Jail, Sangrur.*—Both these facilities are available in single warders' line. As regards family quarters, water is supplied through common hand pumps and electric installations have been made in all the family quarters but electric connections have been provided to those who have applied for the same.

(vii) *District Jail, Gurdaspur.*—Both these facilities are available in single warders' line but there is no electricity in warders' family quarters and water supply is made through hand pumps provided in front of the quarters.

(viii) *District Jail, Amritsar.*—Both these facilities are available in single warders' line and family quarters of the warders.

(ix) *District Jail, Jullundur.*—Electricity has been provided in family quarters and single warders' line. Water taps have been provided in single Warders' line and in certain residential quarters. In others, water-supply is made through common water taps provided in front of the quarters.

[Minister for Welfare and Justice]

(x) *District jail Rohtak*.—Electricity is available in single warders' lines and some family quarters. Water supply is made through common water taps.

(xi) *District Jail, Hoshiarpur*.—Both these facilities are available in Warders' line and family quarters.

(xii) *District Jail, Gurgaon*.—Both these facilities are available in single warders' line and water supply is made through common water taps in family quarters of warders. The estimates for installation of electric connections have been approved and will be taken in hand in April, 1966.

(xiii) *District Jail, Karnal*.—Both these facilities have been provided in single warders' line and family quarters of warders.

(xiv) *B.I. and J. Jail, Faridkot*.—Single warders line is electrified whereas there is no electricity in the family quarters. Water supply is made through common taps.

(xv) *Special Jail, Hissar*.—Both these facilities are available in warders line but there is no electricity in family quarters and water is supplied through common taps.

(xvi) *Sub-Jail, Kapurthala*.—Both these facilities are available in single warders line and family quarters.

(xvii) *Sub-Jail, Simla*.—Electricity has been provided in all the residential quarters and warders line but there is a common water tap for supplying water.

(xviii) *Special Jail, Dharamsala*.—Both these facilities are available in single warders line, but there is no electricity in warders family quarters and water supply is made through common water taps provided in front of the quarters.

(xix) *Sub-Jail, Muktsar*.—Both these facilities are available in single warders line. There are no family quarters.

(xx) *Sub-Jail, Rupar*

(xxi) *Sub-Jail, Moga*

(xxii) *Sub-Jail, Fazilka*

(xxiii) *Sub-Jail, Mansa*

(xxiv) *Sub-Jail, Patti*

} Both the facilities are available in single warders line. There are no family quarters at these Jails.

(xxv) *Sub-Jail, Bassi Pathanan*.—There is one hand pump for the supply of water to family quarters. Electricity has not been provided in warders line and their family quarters.

(xxvi) *Sub-Jail, Malerkotla*

(xxvii) *Sub-Jail, Dasuya*

(xxviii) *Sub-Jail, Sirsa*

} Both the facilities are available in single warders line and their family quarters.

(xxix) *Sub-Jail, Mohindergarh*.—Electricity is not available in warders family quarters whereas water taps are installed near them.

(xxx) *Sub-Jail, Barnala*.—Water supply is made through a water gang from a well. Electricity is available in single warders line only.

(xxxi) *District Jail, Bhatinda*.—Both the facilities are available in single warders line. As regards family quarters, water is supplied through water taps and electric installations have been made in all the family quarters but electric connections have been provided to those who have applied for the same.

(xxxii) *District Jail, Ludhiana* Both the facilities are available in single warders' line. As regards family quarters, water is supplied through common water taps and out of 20 quarters, 10 family quarters of warders are electrified and the remaining will be electrified in April, 1966.

(c) Requisite information is given at serial No. (iv) of reply to parts (a) and (b) of the question above.

**Uniforms for Jail warders**

**3178. Comrade Hardit Singh Bhathal :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- (a) the period after which jail warders are supplied cotton/woollen uniforms ;
- (b) whether these uniforms are supplied regularly in accordance with the rules ; if not, the names of the jails where warders have not been supplied with uniforms and the reasons therefor ;
- (c) whether the said uniforms have been supplied to all the warders of Patiala Central Jail, if not, the number of those who have not been supplied the uniforms ;
- (d) whether it is a fact that the quality of cloth of the new cotton and woollen uniforms supplied at present is inferior to the Khaki drill and woollen uniforms supplied previously; if so, the steps intended to be taken to improve the quality?

**Shri Chand Ram :** (a) The information is given as under:—

**(Male Warders)**

<i>Articles</i>	<i>Period</i>
(i) 1 Cotton drill suit	.. 2 years
(ii) 1 drill shirt	.. 2 years
(iii) 1 pugree	.. 1 year
(iv) 1 khaki twill shirt	.. 1 year
(v) 1 pair of shoes	.. 1 year
(vi) 1 kullah or muslin (4 yards and eleven inches)	.. 2 years
(vii) 1 tin polish	.. 1 year
(viii) Chevrons	.. 2 years
(ix) 1 pair cotton pattis	.. 1 year
(x) 1 woollen jersey	.. 3 years
(xi) 1 great coat	.. 4 years for sub-Jail Dharamsala and 7 years for all other jails
(xii) 1 set of buttons and letters	.. 5 years
(xiii) Waist belt	.. 10 years
(xiv) 1 whistle	.. Always

**Female Warders**

(i) 1 chaddar	.. 1 year
(ii) 1 pair pyjamas	.. 1 year
(iii) 1 cotton coat	.. 1 year
(iv) 1 pair of shoes	.. 1 year
(v) 1 woollen jersey	.. 3 years

**(Both Sexes)**

(1) 1 kit box	.. always
(ii) 1 charpoy	.. always

[Minister for Welfare and Justice]

(b) Yes. The uniforms are supplied regularly in all jails to all warders staff in accordance with rules, except Central Jail, Patiala, where 25 new entrants have not been issued great-coats and jersey, because these two items are out of stock.

(c) No. As stated in part (b) above.

(d) Yes. The Khadi uniform cloth is inferior to mill-made cloth. The matter for switchover from khadi cloth to mill-made cloth is under the consideration of Government.

### Sugar supplied to prisoners through Jail Canteens

**3179. Comrade Hardit Singh Bhathal :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the names of the jails in the State where sugar ration is fixed per prisoner and is supplied through the jail canteens ;

(b) the quantity of the ration allowed per prisoner ;

(c) whether the sugar ration system is in force in the Patiala Central Jail ; if not, the reasons therefor ?

**Shri Chand Ram :** (a) No sugar ration has been fixed for the prisoners in the jail. However, the sugar received by the jails from the District Food and Supplies Controllers, is utilized for preparation of tea in the jail canteens for supply to the prisoners. The surplus sugar, if any, is issued to the prisoners through the jail canteens. In the following jails sugar ration at the rate of one kilogram per prisoner per month has been fixed by the Super-intendents concerned and is distributed through jail canteens, as and when surplus sugar may be available :

1. Central Jail, Ferozepur.
2. Central Jail, Hissar.
3. District Jail, Sangrur
4. District Jail, Gurdaspur.
5. District Jail, Nabha.
6. District Jail, Amritsar.
7. District Jail, Rohtak.

(b) One kilogram of sugar per prisoner per month is allowed as in the case of free citizens, if the prisoners desire to purchase the same and the stocks are available.

(c) No. Only a limited quota of 80 kilograms of sugar per month is issued by the District Food and Supplies Controller. 35 kilograms of sugar is issued to sick prisoners on medical grounds. Tea is prepared in jail canteen with sugar for supply to the prisoners as per their demand.

### QUESTION OF PRIVILEGE

**Mr. Speaker :** There is a Privilege Motion by Shri Lachhman Singh Gill to the effect—

“that the Sergeant-at-arms was carrying a “Danda” in his hand when he went to remove Shri Net Ram, M.L.A. of S. S. Party from the House on February 17. This is a breach of the Privilege of Members of the House.”

I shall look into this matter before giving my ruling.

## ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

**Mr. Speaker :** Under Rule 293(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions for the Budget Session, 1966 of the Vidhan Sabha :—

- (1) Shrimati Shanno Devi, Deputy Speaker, —*Ex-officio* Chairman.
- (2) Baboo Bachan Singh
- (3) Shri Multan Singh
- (4) Shri Roop Singh Phul
- (5) Chaudhri Tayyab Hussain Khan.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**Chief Parliamentary Secretary :** Sir, I beg to lay on the Table—

1. Six notifications containing the amendments to the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, as required under Section 133 (3) of the Motor Vehicles Act, 1939; and
2. The Punjab Motor Vehicles Taxation (First Amendment) Rules, 1966, issued under section 13 read with section 15 of the Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924.

## DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS (KESUMPTION)

**Mr. Speaker :** The House will now resume discussion on the Governor's Address. There are a few more notices of amendments to the motion of thanks moved by Shri Ram Saran Chand Mital to the Address by the Governor. These amendments, with the permission of the House, will be treated as read and moved.

*The House agreed.*

**17. Shri Roop Lal Mehta :** That in the motion, the following be added at the end namely :—

“but regret—

- (1) that no mention has been made to provide village roads in backward area of Palwal and Ballabhgarh Tehsils ; and
- (2) that no assurance has been given to provide means to check unemployment.”

**18. Sardar Gurdarshan Singh :** That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that no mention has been made about the development of the erstwhile Pepsu area”.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਤਰ) : ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ । ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਾਲਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਇਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅਜਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕਾਮਰੇਡ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਅਵਲੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀ ਮਜ਼ਹਕਾਖੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ—

“Punjab is prepared to enforce prohibition provided other States take similar steps.”

ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨੌ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨਚੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੱਕ ਓਨਰਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਰਜ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੱਕ ਜਲ ਗਏ ਹਨ ਅਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਤਾਂ ਚਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ) ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕ ਸੰਦੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਨੀਪਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੈਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ.....(ਵਿਘਨ) (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼ੇਮ’ ‘ਸ਼ੇਮ’ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ) (ਵਿਘਨ)

**ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਹ ਰਹੇ ਹਨ (ਵਿਘਨ) **I insist that he should disclose his name (Interruption)**

**Mr. Speaker :** Order please, order. ‘ਝੂਠ’ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੋ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ 'ਝੂਠ' ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ.....

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ : ਫਿਰ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਦਭਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । (ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਿਨਹੋਤ੍ਰੀ : ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਧਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਹਾਊਸ ਕਾ ਮਹੀਲ ਖਰਾਬ ਹੁਆ ਥਾ ਤੋ ਉਸ ਸਮਧ ਭੀ ਚੀਫ ਪਾਲਿਯਾਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਕਾ ਕਾਫੀ ਹਿਸਸਾ ਥਾ ਆਰ ਆਜ ਭੀ ਵਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨ੍ਟ੍ਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ । ਇਸ ਸੇ ਮਾਹੀਲ ਖਰਾਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਰੋਕੋਂ.....

ਮੁਖਯ ਸੰਸਦ ਸਚਿਵ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਮੈਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਧਾ ਤੋ ਨਾਮ ਲੋ ਆਰ ਧਾ ਅਪਨੀ ਬਾਤ ਕੋ ਵਾਪਿਸ ਲੋ ( ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : \* \* \* \* \*  
(ਵਿਘਨ).....

(ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਘਨ)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ : \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

(ਵਿਘਨ)

**Mr. Speaker :** Mr. Garg, let me make it clear that any hon. Member, speaking during the General Discussion, has every right to criticise the Government in any manner he likes provided he uses parliamentary expression. You cannot force the hon. Member to speak in a particular manner. But if he uses any unparliamentary words, I can stop him and ask him to withdraw those words. It is for the Government to reply in any manner they like.

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਧਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪੋਯੀਸ਼ਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦੋ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਕੋ ਥੀਡੀ ਸੀ ਬਾਤ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਹਾਊਸ ਸੇ ਬਹਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਯਾ ਥਾ । ਆਜ ਜਬ ਕਿ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡੇ ਹੀ ਰੇਲੇਬੇਂਟ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਰ ਬਡੀ ਅਚਛੀ ਤਰਹ ਸੇ ਏਕ ਬਾਤ ਹਾਊਸ ਕੇ ਅਨਦਰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਪਾਲਿਯਾਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡੀਵੇ ਜਾ ਕਰ ਬਡੇ ਹੀ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਫੰਗ ਸੇ ਏਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਤੀਨ ਚਾਰ ਦਫਾ ਹਾਊਸ ਕੋ ਇਨ੍ਟ੍ਰਪਟ ਕਿਯਾ ਹੈ ਆਰ ਹਾਊਸ ਕੇ ਅਨਦਰ ਗਡਬਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪ ਕੀ ਰੁਲਿੰਗ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪੋਯੀਸ਼ਨ ਕੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੋਂ ਕੋ ਥੀਡੀ ਸੀ ਵਹਜ ਪਰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਤੋ ਕਧਾ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ. ਪਾਲਿਯਾਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਪੋਯੀਸ਼ਨ ਪਰ ਹੈ ਆਰ ਬਗੈਰ ਵਜਹ ਕੇ ਮੈਂਬਰੋਂ ਕੋ ਇਨ੍ਟ੍ਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ ਇਤਨੇ ਸੀਨਿਯਰ

\*Expunged as ordered by the Chair.

[ਡਾਕਟਰ ਕਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ]

ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਜੂਗ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪੁਟ ਕੀਆ ਹੈ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਬਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਸ਼੍ਰੀ-  
ਕੇਨਸ਼ਨ ਇਝ ਕੋਟਰ ਫੈਨ ਕਯੋਰ। ਇਸ ਲਿਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਧਰੁ ਬਤਾਓ ਕਿ ਆਪਨੇ ਆਜ  
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਕਯਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿਝਨ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ? \* \* \*  
\* \* \* (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : \* \* \*

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ  
ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਜਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ..... (Order  
please. I did not expect from Dr. Baldev Parkash that he  
would make a reference now to a past incident.)

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ : ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ [ \* \* \* ]

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ।.....  
ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰੋਲ, ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਜਰ  
ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗਲ  
ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਪੁਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਬੂ  
ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ  
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ (ਵਿਘਨ) (Let Shri Jagan Nath first  
say, what he likes to say..... Every thing has its own cause and effect on  
environment. So it is not proper to comment on incident which took  
place sometime back. Now what has happened is this. Shri Garg in-  
terrupted once or twice under the impression that the hon. Member Baboo  
Bachan Singh had spoken obliquely of a Minister. He insisted that the  
Member should disclose his name. I pulled him up saying that there was  
no need to put a question like that. (Interruption).

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,  
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਥੇ ਇਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ  
ਇਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ \*  
\* \* ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।

(ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ \*\*\*\*\*ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ \*\*\*ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ  
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ  
ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋਇਆ ਹੈ  
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ.....

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ  
ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ.....

\*Note.—Expunged as ordered by the Chair.

ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ : ਕੀ ਰੀਕੁਐਸਟ ਹੈ ਓ ਭੇਰੀ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੀਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਏਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਲਿਟੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋ ਏਡਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਓ ਭੇਰੀ।

This practice should be discouraged in order to maintain the decorum of the House. I rather feel ashamed.

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ : ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। (Has the hon. member used these words ? But I feel that what Pandit Chiranji Lal has pointed out and suggested is correct and proper. So whatever unpleasant words have been used by Shri Jagan Nath, Sardar Lachhman Singh, Sardar Gurcharan Singh and Sardar Harchand Singh against each other, will not form part of the proceedings.)

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੇਹੂਦਾ ਫੁੰਗ ਸੇ ਸੀ.ਪੀ. ਏਸ. ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਸਕਾ ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸਲਿਏ ਆਪ ਪਾਸ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਕੋ ਪਾਸ਼ਿਲ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਏ (ਲਾਫਟਰ)

ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਉਨ ਕਾ ਸਤਲਬ ਹੈ, ਆਪ ਇੰਪਾਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ...  
(Interruptions)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਇਹ ਪੈਪਰ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ : ਪੈਪਰ ਕਾ ਫੁਆ ਤੋ ਕਥਾ ਫੁਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਸ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹੀ ਇਸਕੋ ਭੀ ਕਹਨਾ ਚਾਹਿਏ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : The hon. Member Shri Jagan Nath is transgressing all limits of propriety.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਫਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇ (Interruptions) (I do not want that any unpleasant situation should arise. Shri Jagan Nath is going beyond the limits of propriety. Shri Garg has not used any unparliamentary words.)

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ : ਕਹੋ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : “ਬੂਠ” ਦਾ ਲਫਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ।.....ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈ..... (*Interruptions*)

**Mr. Speaker :** He did not use these words within my hearing.

The hon. Member Shri Jagan Nath has made certain observations which amount to reflection on the Chair. He should please withdraw those observations.

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜਾਥ : ਸੁਝੋ ਬਤਾਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਕੀ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਜਿਨਕੋ ਮੈਂ ਵਿਦਫ਼ਾ ਕਰਾਂ।

**Mr. Speaker :** Shri Jagan Nath has made certain observations which amount to reflection on the Chair. He should please withdraw those observations.

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜਾਥ : ਮੈਂ ਵਿਦਫ਼ਾ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਉਨਕੋ ਭੀ ਚੁਪ ਰਖਾ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ : ਏਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਆਦਤ ਉਥਰ ਭੀ ਆਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

(It appears as if this habit of the hon. Member has affected the other side of the House.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠੀਪਤ ਦੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਜ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੁਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਥੇ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵੀ ਕੁਰਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੁਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਮਿਸਟਰ ਬੋਰੋ ਦੀ ਇਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—ਇਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਛਿਆ, “ਸਾਹਮਨੇ ਵਾਲੀ ਦਲਦਲ ਦੀ ਤਹਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ?” ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ, ਠੋਸ ਹੈ।” ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਕਦਮ ਰਖਤੇ ਹੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕਾ ਘੋੜਾ ਕਮਰ ਤਕ ਦਲਦਲ ਮੈਂ ਧੰਸ ਗਿਆ ਤੋਂ ਮਸਾਫ਼ਰ ਨੇ ਪੁਛਾ, “ਤੁਮ ਨੇ ਤੋਂ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਦਲਦਲ ਕੀ ਤਹਿ ਠੋਸ ਹੈ,” ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆ “ਹਾਂ, ਇਸਕੀ ਤਹਿ ਠੋਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਇਸ ਕੇ ਆਧੇ ਦੂਰ ਤਕ ਭੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।” ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਸਕਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਰਸਕਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਪੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਤਕ ਤਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖਾ ਮਾਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾਕੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਪਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਤਹਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ (ਸਰਹੰਦ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਬਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲਕੁਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਇਕ ਦੂਜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨਾਗਹਾਨੀ, ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਅਮਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਇੰਤਹਾਈ ਸਰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ—ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਥੋਂ ਬੇਵਕਤ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਖਸ਼ਗਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨਾਗਹਾਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਤਕ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤੱਲਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਟੇ ਘਟ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਥੇ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟਾਪੂ ਹੈਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਗਿਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਜ ਵੀ ਇਕ ਸਿਪੋਰਟ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]

ਅਗਰ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਕਰਤਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ; ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਅਫਸੋਸ ਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ P.A.P. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਗਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਤਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਅਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਖਤਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਥੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਇਨਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਥੋਂ ਵਧ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ **subject to correction, figures** ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ ਹਾਈ ਅਫਸਰ 61 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਥੇ 124 ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਐਮ ਪੀਐਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਗੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ। ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਜਿਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਥੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 6-7 ਕਰੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਵੀ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਡੀਐਮ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੀਟ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਲ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤਵੱਜੁਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਮਖਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਬੀਐਮ ਡੀਐਮ ਉਐਮ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲ ਪੁਛ ਸਕੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਅਗਰ ਕੋਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ—ਉਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਥੇ ਬੀਐਮ ਡੀਐਮ ਉਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ

ਤੇ ਸੁਪਰਵੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਿਰਨ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਹੈਵੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਟਿਜ਼ੈਂਸੀ ਆਫ ਫੰਡਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨੀ ਥੁੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਵਲ ਤਵਜੋਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਫਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਫਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤਵਜੋਹ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਿਰਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਈਟਮਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੱਦੇ-ਮੱਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇਥੇ ਇਹ ਗਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 : 50 ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਮਰਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 16 ਜੁਲਾਈ, 1957 ਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਚਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਹਿਸੇ ਨਾਲ ਤਫਰਕੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਖ ਲੈ ਲਉ—ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਰਵਿਸਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਥੇ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਚਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬਸਾਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ। (ਵਿਘਨ)

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਚ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਸਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੌਤੀਲੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ 50 : 50 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਜੋ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਨ । ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਤਫਰਕਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪੌਟੈਨਸ਼ੀਲਟੀਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਮਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਟੈਨਸ਼ੀਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ ?

ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਕੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ? ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਰੂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਖੰਨਾ, ਸਰਹੰਦ ਅਤੇ ਖਰੜ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

**ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੋਪੀਬਲ :** ਆਨ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਡਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫ਼ਾਇਲ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਗੈਲਰੀ ਯਾ ਸਕਨਰ ਬੈਂਚ ਸੇਟ ਜਾ ਕਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਕਿਸ)

**ਸਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਵਾਲਾ :** ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਡਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਇਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ 1956 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਪਟਿਆਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੀ ਅਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦ ਵੀ ਲੰਘੋ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ? ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਗਲ ਇਕ ਮੁਅੱਜਜ਼ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਿਖ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸਿਖ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

**(At this stage Shri Ram Saran Chand Mital, a Member of the panel of Chairman occupied the Chair.)** ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਤਨੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਐਡਵਾਨਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ ਇਕ ਇਕ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਆਮ ਰੋਡ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਨੀ ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 20—22 ਮੀਲ ਏਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਿਤਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਟੁਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਮੁਕਣ ਦੇ ਵਿਚ

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]

ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਇਹ ਇਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਡੀਫੈਂਸ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਕਤ ਐਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਏਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲੋਂ ਦੁਰਾਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਦੁਸਰਾ ਟਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ । ਇਹ ਪਟੜੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬਸੀ-ਖਰੜ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਪੈਪਸੂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ **Patiala was one of the beautiful cities.**

ਪਰ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟਸ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਏਥੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਏਥੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਾਨ ਖੜ੍ਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ।

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਚ ਟਰੀਬੀਊਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਕਿ—

**“Rich tribute is due to all the teachers, students and officers of the Education Department for what for very substantial contributions to the Punjab Defence and Security Relief Fund.”**

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ । ਲੋਕ ਵਾਲੰਟੈਰੀਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਕ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਉਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ । ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਫੰਡਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਟਰੀਬੀਊਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੰਡਿਸਪਲਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮੈਂ ਪੈਪਸੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੀਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਂਟੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਏਥੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਾਹਰੀਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਐਡੀਕੁਏਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਲਫਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇੰਨਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਫੂਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦੁਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਓਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਗੇ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਥ ਅੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਹੇਠ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ:—

#### “More Donations for India

ROME, Feb. 20 (Reuter and AP).—Money donations from Italians in all walks of life poured in this week-end to help India in its present food crisis.”

ਮੇਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਨਾਜ਼ ਸੀ ਅਜ ਉਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ : ਸ਼ੇਮ-ਸ਼ੇਮ-ਸ਼ੇਮ.....

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸ਼ੇਮ ਟੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ.....

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮੁਲਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜ ਵੀ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬਰਫ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ੨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਓਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]

ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰਖੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਗੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰਖੋ ਲੇਕਿਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕਾਫੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਰਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਡਰੈੱਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਆਰਿਟੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਲ ਪੂਰੀ ਤਵਜ਼ੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ 2 ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਘੰਟੀ) ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਬਿਆਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਰਾਇਅਰਿਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 1970 ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। (ਘੰਟੀ)। ਕਿਉਂਕਿ ਓਧਰੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਘੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਐਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਲਫਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਰੀਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਧਰ ਤਵਜ਼ੁਹ ਦੇਣ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਮ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹਨ ਉਹ ਏਧਰ ਤਵਜ਼ੁਹ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਂਸ਼ੀਲਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਬਣਾਉਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਾਧਿਤ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਲ) : ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਏਕ ਬਾਰ ਰਖਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਓ ਆਪ ਕਰਕਾ ਦੇਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਾਏ। (I want to put this point before the House. The number of Members desirous of participation in the discussion is very large. The House may kindly direct as to what time limit of speeches may be fixed.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਰਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ

ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਾਪਤਿ : ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਆਜ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੁਝੇ ਤੋ ਕੋਈ ਏਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹੇਂਗੀ ਕਿ ਹਮੇ ਬੋਲਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। (If the House fixes the time limit today, well and good other wise I have no objection to the debate going as before. But then the hon. Members would complain that they did not get the time. )

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ : 15 ਮਿਨਟ ਕਰ ਦੇਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਮਹਤਾ (ਪਲਵਲ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਨ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹੋਦਯ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਭੀ ਇਸਕਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਖੜਾ ਹੁਆ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਯਹ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆਰ ਆਗੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਕੀ ਏਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਯਹ ਕਾਯਦਾ ਸਾ ਹੋ ਗਯਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਬ ਵਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹੋਦਯ ਕਾ ਏਡ੍ਰੈਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਪਰ ਦੋ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਕਰਕੇ ਅਪਨੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਬ ਬਨੀ ਤੋ ਇਸ ਕੇ ਬਨਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਹਮਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਬੇਦਿਲੀ ਛਾਈ। ਯਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜੰਗ ਹੁਈ। ਉਸ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹਦ ਕਾ ਸੂਬਾ ਹੋਨੇ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਇਸ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਨੀ। ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਆਰ ਤਨਦੇਹੀ ਸੇ ਅਪਨੇ ਮੋਰੇਲ ਕੋ ਅੱਚਾ ਰਖ ਕਰ ਪੂਰਾ ਸਹਯੋਗ ਦਿਯਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ, ਸਬ ਨੇ ਅਪਨਾ ਫਰਜ਼ ਮਕਕਦਸ ਸਮਝਾ ਆਰ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤਿ ਕੋ ਕਾਯਮ ਰਖਾ। ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਬਡੇ ਹੌਸਲੇ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਸੂਬੇ ਕੀ, ਇਸ ਸਰਹਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਯਮ ਰਖੀ। ਹਮਾਰੇ ਸਰਹਦ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਂ ਜਿਸ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਅਪਨੇ ਏਡ੍ਰੈਸ ਮੇਂ ਕੀਯਾ ਹੈ। ਜਬ ਭੀ ਕਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਸੰਕਟ ਕਾ ਸਮਥ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਇਜ਼ਲਾ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਤੀ ਹੈ। ਵੇ ਘਰ ਸੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨੇ ਜਰਾਏ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਟਰਕ ਆਨਰਜ਼, ਕੰਡਕਟਰਜ਼, ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਆਰ ਜੋ ੨ ਭੀ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਉਨਕੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀ। ਚਾਹੇ ਉਨਕੋ ਯਹ ਦੇਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕੇ ਵਕਤ ਕਾਮ ਕੀਯਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੀ ਉਨ੍ਹੇਂ ਮਿਲਨਾ ਹੈ ਵਹ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ। ਹਮਾਰੇ ਟਰਕ ਆਨਰਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਕੀਯਾ। ਹਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਕਾਫੀ ਇਮਦਾਦ ਲੀ ਗਈ। ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਆਰ ਕੰਡਕਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨਕੇ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਦਫਤਰੀ ਕਾਮ ਮੇਂ ਦੇਰੀ ਲਗ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵਹ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹਿਏਂ। ਯਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹਾਯਲ ਹੋਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਪਰ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹੇਂ ਦੇਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਜਬ ਤਕ ਏਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਟੋਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਯਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਨੀ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਉਸੇ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਮੈਂ ਯਹ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਯਾ 18 ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜੋ ਟਰਕੀ ਕੀ ਹੈ ਵਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕੇ ਰਾਜ ਮੇਂ 100 ਸਾਲ ਤਕ ਇਤਨੀ ਟਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਤਨੀ 18 ਸਾਲ ਮੇਂ ਹੁਈ ਹੈ।

[श्री रूप लाल महता]

कुछ इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा पसमांदा हैं और सरकार को उन की तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह भी समझते हैं कि सरकार को पिछड़े इलाके के साथ सहानुभूति होती है, लेकिन वह भाई एक राई का पहाड़ बना कर खड़ा करते हैं जिसमें पंजाब के कई दफतर खड़े हो गए और किसी का कुछ न बना। हर मंम्बर

4.00 p. m.

को इस के बारे में कुछ कहने का हक है। मैं उन भाईयों के साथ सहमत हूँ जो गवर्नमेण्ट का ध्यान खामियों को दूर कराने की तरफ दिलाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऐग्रीकल्चर का महकमाले लीजिए। इस महकमे के कर्मचारी बिलकुल नाअहल साबत हुए हैं क्यों कि कागजों पर वह बहुत कुछ दिखा देते हैं मगर अमली तौर पर कुछ होता नहीं दिखाई देता। उन की सुस्ती की वजह से जितनी भी जरूरती स्कीमें हैं वह पाया तकमील तक नहीं पहुंचतीं। अभी तक लोगों को इरीगेशन के पूरे साधन नहीं मिल पाए। आज हालत यह है कि ट्यूबवैलज के लिए लोगों को बिजली नहीं मिलती। जब दफतरों में जा कर पूछा जाता है तो जवाब दिया जाता है रां मंटीरियल औरै फंडज की शोर्टेज है। मिनिस्टर साहिब भी चिट्ठी लिख कर हमें भेज देते हैं। मैं जो भी मिनिस्टर कन्सर्न्ड हैं उन से निवेदन करता हूँ कि वह हमारी आवाज सुनें और हमारे इलाके में लोगों को ट्यूबवैलज के लिये बिजली देने की कृपा करें। गुड़गांव के जिले में हर सब डिविजन में कितने ही ट्यूबवैलज बिजली न मिलने की वजह से बेकार पड़े हैं। मुझे मालूम है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कौन से जिलों को बिजली देता है। हरियाणे को अंदर बिजली के मामले में गुड़गांव सब से पीछे है, पिछले सेशन में यहां एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि पलवल डिविजन में 217 दरखास्ते पेंडिंग हैं जिन को बिजली ट्यूबवैलज के लिये नहीं दी गई है। अब फिर पूछा कि कब दोगे तो कहते हैं कि सामान अबेजेबल नहीं है। न मालूम उन को कब बिजली मिलेगी। हमारी गवर्नमेण्ट को इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त गुड़गांव के जिले में कहत साली हैं। तहसील पलवल, बलभद्र, नूह और झिरका को यू.पी. की अपर आगरा कैनल से जो गन्ने की आबपाशी के लिए पानी मिलता है, उस का वाटर रेट 32 रुपए फी एकड़ के हिसाब से चार्ज किया जाता है जब कि इसके मुकाबले में पंजाब के दूसरे हिस्सों में तकरीबन आधा है। एक ही स्टेट के अन्दर डिसपैरिटी नहीं होनी चाहिए। पंजाब सरकार को यू.पी. सरकार से मिनिस्टरियल लेवल पर बात चीत करके वाटर रेट पंजाब के वाटर रेट के बराबर करवाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ऐसा करवाने में कामयाब नहीं हो सकती तो फिर उन लोगों को अपनी तरफ से कम्पनसेट करे।

इसके इलावा, चेयरमैन साहिब राज्य पाल साहिब ने सूबे में कोआप्रेटिव मिलज लगाने का जिक्र किया था। मैंने पहले भी कई बार सरकार का ध्यान दिलाया है कि गुड़गांव में स्पिनिंग वीविंग मिलज और शुगर मिलज लगानी चाहिए, चाहे कोआप्रेटिव सैक्टर में लगाई जाएं चाहे पब्लिक सैक्टर में लगाई जाएं। इसके इलावा, चेयरमैन साहिब, पिछले साल चौधरी रणबीर सिंह जी ने कहा था कि 1965 में गुड़गांव कैनल में पानी दे दिया जाएगा लेकिन अब सन् 1966 चल रहा है मगर वहां पानी नहीं

दिया गया, गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी गुड़गांव कैनल प्राजैक्ट को मुकम्मल करे ताकि वहां पर इरीगेशन हो सके । जहां तक ट्यूब वेलज का ताल्लुक है बेहतर होगा अगर गवर्नमेंट वहां पर अपने ट्यूब वेलज लगा कर खुद अपने खर्चे पर खाल और नालियां बना कर किसानों को इरीगेशन के लिए पानी दे जैसा कि यू० पी० की सरकार कई सालों से करती चली आ रही है । गवर्नमेंट ट्यूब-वेलज के लिए लोगों को जो कर्जे देती है उस का पूरा फायदा नहीं होता क्योंकि लोग उतना गहरा बोर नहीं करवा पाते और उन को बाद में किशतें लौटाने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है । अगर ट्यूब-वेल सरकारी होंगे तो वह ज्यादा गहरे खोदे जाएंगे और उन में से पानी भी ज्यादा निकलेगा । चेंबरमैन साहिब रिवाड़ी में, 18 एक्सप्लोरेटरी ट्यूब-वेलज लगाए गए थे जो कि चार साल तक बेकार पड़े रहे । अब जो मौजूदा एस० ई० है उसने उन को चालू करवाया है जिस से 1,200 एकड़ ज़मीन आबपाश हो रही है । विघन)

**चौधरी इन्दर सिंह मलिक :** सरदार लछमन सिंह जी ने उनको बोक कहा है । यह लफ्ज़ विदड़ा करवाने चाहिए ।

**श्री सभापति :** ऐसे लफ्ज़ किसी ने नहीं सुने हैं । (Nobody has heard such words.)

**श्री रूप लाल महता :** चेंबरमैन साहिब अब मैं सड़कों की बात करता हूँ । पलवल से मोहना तक सड़क इस साल बनाने का प्रोविज़न था लेकिन सरकार उसे इस साल नहीं बना पाई । वह सड़क न बनने की वजह से मोहना से पलवल जाने के लिए 13 मील का चक्कर काटना पड़ता है । इस लिए, मैं उमीद करूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी उस सड़क को बनाने की कोशिश करेगी ।

इस के इलावा गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में कहा था कि रोडवेज़ की वर्किंग बहुत एफीशेंट है । लेकिन जहां तक गुड़गांव का ताल्लुक है वहां पर पुरानी और बेकार बसें भेजी हुई हैं उन का जगह जगह ब्रेकडाउन होता है और लोगों को रास्ते में कई कई घण्टे खराब होना पड़ता है । वहां पर नई बसें भेजनी चाहिए । जब इस से आमदनी भी इतनी काफी होती है तो फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस को इम्प्रूव क्यों नहीं किया जाता ? आज के ज़माने में इस तरह की बसें चलाना निहायत ही अफसोसकी बात है । लोग तंग आ चुके हैं और वह मज़ाक के तौर पर पंजाब रोडवेज़ को पीपा रोडवेज़ कहते हैं क्योंकि बहुत बुरी हालत की बसें चलाई जा रही हैं । इण्जन इतने बोसीदा हैं और इतनी खड़ खड़ की आवाज़ आती है कि बस में कुछ सुनाई नहीं देता । वर्कशाप वाले पता नहीं क्यों उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और मैं तो समझता हूँ कि वर्कशाप वालों को कोई पूछने वाला नहीं और न उनकी कोई चैकिंग है । इस तरह की बातों का लोगों पर बहुत असर पड़ता है । सरकार चाहे कितने अच्छे काम करती है लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो उस से सरकार की बहुत बदनामी होती है । इस रोडवेज़ के सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि वहां लोगों को दिक्कत न हो और सरकार की भी बदनामी न हो ।

[श्री रूप लाल महता]

जहां तक मेरे हलका का सम्बन्ध है मैं उसके बारे में कह सकता हूं कि वहां पर कोई कहने बनाने योग्य डिवलपमेंट नहीं हुई है। हमारे बजट का अब यह आखरी साल जा रहा है। अब बजट में हमारे लिए क्या रखा है ? और हमारी डिवलपमेंट के लिए क्या स्कीमों रख रहे हैं ? वह तो बजट आने पर पता चलेगा लेकिन पिछले चार साल के तज्जुबे की बिना पर मैं कह सकता हूं कि मेरा हलका टोटली निगलैक्टिड हलका है। जिस तरह कि अंग्रेज के ज़माने में था उसी तरह है, कोई बताने लायक फर्क नहीं पड़ा है। मैं हैरान होता हूं कि वहां लोगों को क्या जवाब दूं। सिवाए इसके कि मैं सरकार की कमज़ोरियां और मुश्किलात बता कर लोगों को शान्त करूं कि मुश्किल हालात में कुछ चीजें बरदाश्त करें मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता .....

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਠ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਹਬ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

श्री चेयरमैन : उनकी मैमेरी अच्छी हो सकती है और वह जबानी याद रख सकते हैं। महता जी अब आप वाइंड अप करें। (His memory can be good and remember things by heart. Now the hon. Member, shri Mehta may kindly wind up.)

श्री रूप लाल महता : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस साल बड़ी खुशक साली पड़ी है और सरकार उसके लिए रीलीफ का काम कर रही है। मेरा जिला भी बहुत बुरी तरह खुशक साली की लपेट में आया हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां के लिए बजट में ज्यादा से ज्यादा रुपया रखे और वहां रीलीफ के काम शुरू करे ताकि इन बेरोजगारी के दिनों में उन लोगों को काम मिले। पलवल में 8/10 हजार रिफ्यूजी ऐसे बैठे हैं जिनकी कौमी तावत जाया जा रही है। उसे ठीक तौर पर यूटिलाइज़ करने की जरूरत है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि फरीदाबाद, बल्बगढ़ में काफी इन्डस्ट्री लगी है और उस इलाके को काफी फायदा हुआ है लेकिन होडल से पलवल तक का इलाका ऐसे ही बेरोजगार पड़ा है। उस इलाके को इन्डस्ट्रियल एरिया करार दिया जाए। इस तरह कारखाने लगाने वाले आगे आएंगे क्योंकि उन्हें वहां जमीन सस्ती मिलेगी और दूसरी चीजें मिलेगी। इस से सरकार को भी काफी फायदा होगा। मैं, चेयरमैन साहिब आपका मशकूर हूँ जो चन्द मिन्ट आपने मुझे बोलने के लिए दिए। यह सामने बैठे आपोजीशन के भाई बड़े बेसब्र थे क्योंकि यह नहीं चाहते थे कि सरकार के हक की बातें कही सुनी जाएं लेकिन जो हकीकत है वह छुप नहीं सकती। पिछले 18 साल में इस सरकार के वक्त में पंजाब आगे बढ़ा है और आगे बढ़ रहा है। यह ठीक है कि जहां खामियां हैं वह हम ने बतानी हैं और सरकार ने भी उन्हें दूर करना है लेकिन इसी सरकार ने पंजाब को आगे बढ़ाना है और ने नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਢੀਗਿਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਫੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :

“ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਜਿਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਕ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਵਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ.....”

ਮੇਰੇ ਇਸਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਇਕ-ਮੁਠ ਹੋਕੇ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕਿਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਖਰੀ ਸਫੇ ਤਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜ ਤਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਅਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜ ਤਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੁਸ਼ਾ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿਉ.....(ਵਿਘਨ)

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਉ.....

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਆਨ ਏ ਪਾਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੋਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ *status quo* ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਬੀਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਓਥੇ ਜਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ । ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬੀਨਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉ ।

**Mr. Chairman:** No Interruption.

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ?

**ਬੀਬੀ ਜੇਤ ਰਾਮ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਏਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਭਾਤਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਾਧਿ :** ਯਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਗਰ ਆਪ ਅਭਿਯੋਗ ਮੌਕੇ ਏਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇੀ ਜਾਏਗੀ । (This is no point of order. If in further, the hon. Member raises such a point of order, he will be debarred from raising points of order)

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** On a point of Order, Sir. Mr. Chairman, in view of the atmosphere of the House I want your Ruling that if some hon. Member of the House refuses to obey the Chair or tries to take law and procedure into his own hand, I wonder how in the absence of the Marshal there would be any control.

**Mr. Chairman :** The hon. Member is a practising lawyer of high repute and besides he has always been on the Panel of Chairmen. He knows that Marshal is not necessary always and therefore it is no point of Order. I rule it out.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਵਜ਼ੀਰ ਇਲੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 7 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਨਾ ਪਰਾਂਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪੀਸ਼ਵਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਸ਼ਵਲ ਮੀਨਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਨਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਸਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਗੈਰਮ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਸਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਡ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆਰ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨਜੀਯ ਸਦਸਯ ਅਪਨੀ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਕੋਈ ਅਨਰੇਕਲ ਮੈਂਬਰ ਤਸ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਕੋ ਕਹਸ ਮੈਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੈਂ ਨਜਰ ਅਨਦਾਜ਼ ਕਿਆ ਗਯਾ ਹੀ ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਾਪਤਿ :** ਧਨ ਆਪ ਕਾ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਬਾਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਡ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਕਾ ਸਮਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ, ਕਹ ਸਬ ਯੇਰੇ ਕਹਸ ਲਾਭੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ। (This is an irrelevant point of order. Any matters mentioned in the governor's address or those which find no place therein but are connected with the punjab, they can be discussed.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੈਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈਦਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਸੌ ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਯੋਧਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਏ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਿਖ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਵਾ ਲਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਠੀ ਛੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਡੀਫੈਂਸ ਅਕਾਡੇਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਝੁਜਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਿਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ **means of communications** ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਲਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਲਿਜ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਉਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਐਡ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ “ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਸੀ “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਲਾਟਸ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤਕ 30—40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਉਗਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਂ ਰਖਵਾਇਆ, ਅਜ ਬਿਰਲਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪੱਟੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੱਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿਫਤ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਡ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਬੜੀ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀ ਗਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 182 ਫੈਮੀਲੀਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਵਾਹੁਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ, ਦੋ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਘਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬਿਰਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। “ਜੈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਲਾਨਜ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ

## [ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਪਲਸ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਕਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਕੇ ਦਿਉ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11000 ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ 5000 ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਿਥੋਂ ਲਗਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਿਉ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 80, 90 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਪੜ-ਬੇਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੀ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਘਟ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਘਟ।

ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਧਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਧਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੈਬੀਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੋਰ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਯੋਗ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਲੇਕਿਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਪਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਇੰਤਜਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤਾਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ

ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਾਸ ਥਿਰੀ ਅਤੇ ਫੌਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸਨ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਜ ਤਕ ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵੇਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ੧੦ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ ਵਧਾਏ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਟਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਠੀਕ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਭੁਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। (ਘੰਟੀ)

ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਵੱਛ ਰਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੱਛ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲੇ—ਅੰਬਾਲਾ ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵੇਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿ ਉਥੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ.....

ਸ੍ਰੀ ਸਭਾਪਤੀ : ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। (The hon. Member should not refer to the case of Ambala Zila Parishad because it is pending in the High Court.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ 29 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਹੋਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਉਥੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਹ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

40 ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਈਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਈਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 44 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ।

ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ (ਖੰਨਾ—ਐਸ. ਸੀ.): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼: ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਤਰੁਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ: ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਪਾਲੇਟੀਸ਼ਨ ਦਾਰੋਲ ਆਪਣੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। "There is not to question why, there is but to do and die"। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ air tight ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੌਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Nobody can question his order ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਲਾਲਾ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅੰਰ ਪਾਲੇਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੈਰੀ ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਏ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ : ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕਾਨੋਮੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕਾਨੋਮੀ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਦਾਖਲਤ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਪਰਸਨਲ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਵਿਘਨ) ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਮਾਕਰੇਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲੇਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਿਆਣੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਨਰਸਿਸ਼, ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ, ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਐਸ. ਪੀ. ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ, ਈਮਾਨਦਾਰ, ਲਾਇਕ ਔਰ ਤਕੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲੀ, ਵਢੇਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ "ਤੋਬਾ, ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ" ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਸ ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤਨਾ ਤੂਫਾਨ ਉਠਿਆ (ਵਿਘਨ)। ਉਸ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ..... (ਵਿਘਨ) ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ....

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੱਗ ਪਹਿਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ.....(ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ : ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ adjourn ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ M.L.A. ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮਿੱਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ

[ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ]

**obedient servant** ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਉਸ **fully packed** ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਤੇ **demoralising effect** ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿਗ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਡੀਫੈਕਟਿਵ ਪਨੈਨਿਗ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਠ ਨੂੰ ਹਲਕਾਏ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਟਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਉਠ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹਿਸਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿਉ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਅਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** **On a point of order, Sir.** ਜਦ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

**ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ :** ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਸ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਨਿਸਟਰ ਪਾਸ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਉਟੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਉ। ਉਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 50—60 ਫੈਮੇਲੀਜ਼ ਇਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੋਸੀ ਅਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭੂਤ ਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲਉ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਉਥੋਂ ਤਾਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ **alternative** ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿਉ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਵਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (**At this stage, Mr. Speaker occupied the Chair**) ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ **Evaluation Committee for Harijan Welfare** appoint ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋਗੀ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ **Scheduled castes welfare Deptt** ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੌਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ੈਸਟ

ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਟ ਪਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਨਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ। ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਦੀ ਇਕ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਰਾਮ ਚੰਦ' ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 'ਰਾਮ ਚੰਦ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਗਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

**ਲਾਲਾ ਹਲਿਆ ਰਾਮ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਭਰਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਹਿ ਹਰਿਜਨ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਭਰਮੀਨ ਸਹਾਜਨ ਕੀ ਭਰਮੀਨ ਨ ਹੋ ਤੋ ਕਧਾ ਕਹਿ ਹਰਿਜਨ ਹੀ ਕਹਲਾਏਗਾ ?

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)

**ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਸਰ। ਏਕ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ। ਇਨ ਕਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੈਸਾ ਦਿਸਾਗ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਯਕਸ਼ :** ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋ ਨਹੀਂ ਇਨਕੀ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਰ (ਹੁੰਸੀ) ? (Has Captain Rattan Singh any objection to the expression used by the hon. Members) (Laughter)

**ਰਾਜਯ ਸਕੱਤਰੀ ( ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ) :** ਅਗਰ ਧਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈਂ ਤੀ ਸੁਝੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਸਕੱਤਰੀ ਬਨਨੇ ਸੋਂ ਕੀਓਂ ਏਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਹੁੰਸੀ)

**ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ :** ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਕੇਨਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣੇ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਵਧ ਉਗਾਉ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਕਪੈਸਟੀ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਕਮਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਕਪੈਸਟੀ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰ

[ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ]

ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲੀਵਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁਦ ਦਬਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ 5.00 P.M. ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਲਫਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਕ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਚ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵਧ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੈਨਾਲ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਖਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ, ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੜ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੁਕਦੀ ਰਹੀ। (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 10—12 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਦੀ, ਟਿਬਾ, ਖਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮਪੁਰੀ ਜੱਸੜਾਂ, ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਅਜਨਦੋ, ਦੁਗਰੀਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਮਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਟੂਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। (ਘੰਟੀ)

ਬਸ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਦੀਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ। ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਡਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ, a new type of man, a race of rulers and a breed of viceroys " ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-

नामिक पावर, पॉलिटिकल पावर अਤੇ सरविसां ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

**ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ (ਮੁਕੋਰਿਆਂ) :** ਅਧ୍ୟਕਸ਼ ਮਹੋਦਯ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਨੇ ਏਡਰੇਸ ਮੇਂ ਆਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕੋ ਟ੍ਰਿਬੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਨਾ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਾ ਫਜ਼ ਹੈ। ਆਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਫੰਗ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਕਿਆ ਆਰੀ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਖੋਯਾ ਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਸੇ ਹਮ ਕੋ ਦਿਲਾਯਾ ਹਮ ਕਮੀ ਆਰੀ ਇਸ ਰਿਯੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਤੇ। ਇਸ ਲਿਏ ਹਮਾਰੀ ਉਨ ਕੇ ਚਰਣਾਂ ਮੇਂ ਅਫ਼ਾਜ਼ਲੀ ਬਜਾ ਹੈ।

ਜਹਾਂ ਤਕ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਝਿਕ ਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀ ਮਾਹਨੁਭਾਵੀਂ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤ੍ਯੁ ਸੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਹਨੁਭੂਤਿ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਏਡਰੇਸ ਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾ ਏਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੇ ਤਸਲੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਆਰੀ ਜਨਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਧਾਈ ਕੀ ਪਾਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਪਰ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਕਾ ਫਜ਼ ਥਾ ਆਰੀ ਉਸਨੇ ਅਪਨੇ ਫਜ਼ ਕੋ ਨਿਭਾਯਾ ਵਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰੀ ਮੌਤ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਰੀ ਇਸ ਲਿਏ ਲਾ ਏਡ ਆਰਡਰ ਕੋ ਠੀਕ ਫੰਗ ਸੇ ਕਾਯਮ ਰਖਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਇਸ ਲਿਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਾਮ ਮੇਂ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਆਰੀ ਜਨਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਧਾਈ ਕੀ ਪਾਤ੍ਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਿਆ ਉਨ੍ਹੇਂ ਜਿਤਨੀ ਬਧਾਈ ਦੀ ਜਾਏ ਥੋਡੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜਨਤਾ ਹੋਨੇ ਕਾ ਸਬੂਤ ਦਿਯਾ ਆਰੀ ਯਹ ਸਿਫ਼ ਕਰ ਦਿਯਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਗ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮੁਲਕੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗ ਚਿੜ੍ਹ ਗਈ ਤੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮੇਂ ਗੜ੍ਹ ਬੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਰੀ ਵਹ ਮੁਲਕ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਗੜ੍ਹਬੜ੍ਹ ਸੇ ਪੂਰਾ ਫਾਯਦਾ ਉਠਾਏਗੇ ਵਹ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਮੇਂ ਜੋ ਰਵੈਯਾ ਜਨਤਾ ਕਾ ਥਾ ਉਸ ਸੇ ਉਨ ਮੁਲਕੋਂ ਕੇ ਮੁਹਾਂ ਪਰ ਚਪਤ ਲਗੀ। ਇਸ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ, ਟਿਆਗ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਆਰੀ ਬਲਿਦਾਨ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਏਕ ਸਰਾਹਨੀਯ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਮਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕਿਆ ਉਨਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਬਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੂੰ ਆਰੀ ਰੈਜ਼ੋਲਯੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਏ ਹੂੰ। ਉਨ ਕੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਸਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਯਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਏਡਰੇਸ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰੀ ਉਨ੍ਹੇਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਉਸ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ।

ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਕੇ ਕਈ ਕਾਮਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਯਹ ਜਾਨ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜੰਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ, ਆਰੀ ਜੋ ਡਿਸਏਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆਰੀ ਜੋ ਅਪਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਨੇ ਕੇ ਯੋਗਯ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੂੰ, ਉਨਕੀ ਇਸ਼ਦਾਦ ਕੇ ਲਿਏ, ਉਨਕੀ ਸਹਾਯਤਾ ਕੇ ਲਿਏ ਕਦਮ

[प्रिसीपल रला राम]

उठाए हैं । मैं समझता हूँ कि वह तसल्लीबख्श हैं और मैं इस बात पर अपनी सरकार को बधाई देता हूँ ।

जहाँ तक हमारे डिफेंस का ताल्लुक है प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है हमारी सरकार ने इस मसले को सही तौर पर हल किया है । इस का प्रबन्ध गवर्नमेंट करती है और इतना संकट होने के बावजूद पंजाब की जनता ने 4 करोड़ रुपया इक्ठ्ठा किया हालांकि पंजाब के ऊपर संकट का सब से ज्यादा भार था और पंजाब की इकानौमी शैटर हुई थी । इतना होने पर भी पंजाब की जनता ने डिफेंस के लिए 4 करोड़ रुपया इक्ठ्ठा किया । इस के लिए भी हमारी सरकार और पंजाब की जनता दोनों बधाई के पात्र हैं । और मैं अपने दिल से उन्हें बधाई देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, जो खुशकसाली वर्षा न होने के कारण हुई है इस का प्रभाव हम-हर तरफ देख रहे हैं और इस से अन्न संकट की भारी समस्या देश के सामने आ गई है । जैसा कि अभी अभी कहा गया है अखबारों के अन्दर खबर छपती है कि सहायता के लिए अन्य देशों में हमारे लिए चन्दा इक्ठ्ठा किया जा रहा है मैं यह समझता हूँ कि यह एक शर्म की बात है । लेकिन यह बात ठीक है कि एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है । अगर हम सहायता नहीं लेते तो लाखों करोड़ों इन्सानों को भुखमरी से कैसे बचाया जा सकता है । वह हमारी दया के पात्र हैं । लेकिन हमारे लिए दान पात्र खुले यह हमारे देश के लिए लज्जा की बात है । हमारी गवर्नमेंट को अपना प्लानिंग इस ढंग से करना चाहिए कि हमारी ज्यादा से ज्यादा तब्ज्जो एग््रीकलचर और जरायत की तरफ हो । यह खुशी की बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने 11,000 ट्यूबवैलों को एनर्जाईज करने का संकल्प किया था और गवर्नमेंट ने इस वक्त तक शायद 6 या 7 हजार को एनर्जाईज कर भी दिया है लेकिन आप के द्वारा, अध्यक्ष, महोदय, सिचाई मन्त्री तक यह बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो पालेसी आज कल फालो की जा रही है वह अधूरी है और जो प्लानिंग इस सम्बन्ध में है वह नाकस है । मसलन मैं अपने हलका की बात करता हूँ कि मेरे हलका में चावल बहुत पैदा होता है मुकेरियां में से कोई तीन चार लाख मन चावल हर साल बाहर भेजा जाता है । यह दरिया के किनारे का इलाका है इस में खास तौर पर ट्यूबवैल लगाने से ऊपज को दुगना किया जा सकता है । लोगों के बार बार अर्जियां भेजने के बावजूद वहां पर ट्यूबवैल के लिए कोई कुनैक्शन नहीं दिए जा रहे । अर्जियां महीनों तक की वहां पर ही पड़ी हैं । इसी तरह से हमारे दूसरे इलाका हाजीपुर ब्लाक की भी बहुत सी अर्जियां पड़ी हैं कोई ख्याल तक नहीं किया जा रहा । मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को ट्यूब वैलज कुनैक्शन की पालिसी को रैशनेलाईज करना चाहिए । ऐसा करके अनाज की उपज में काफी से ज्यादा इमदाद की जा सकती है । जहां तक दिहात को इलैट्रीफाई करने का सवाल है वहां हमें अपने इलाके के मुताल्लिक पोशनी न मिलने का गिला है । यह पालिसी भी इतनी इरैशनल है, हमारे हां बीसियों

ब्लॉक हैं जिन के अभी तक इलैक्ट्रीफाई नही किया गया हालांकि पंजाब के और जिलों में हजारों दिहात इलैक्ट्रीफाई किये जा चुके हैं । यह पालिसी जो अभी तक इस सम्बन्ध में सरकार ने एडाप्ट की है यह निहायत ही गलत है । मैं अपने इलाका का अगर दूसरे इलाकों जिलों से मुकाबला करूं तो हमारे हां नौका पर पानी न मिलने की वजह से पैदावार में 25 प्रतिशत का घाटा पड़ा है । सरकार को हमारे इलाका को कुनैक्शन देने का प्रबन्ध फोरी करना चाहिए ।

गवर्नर महोदय ने इस ऐड्रेस के अन्दर जिक्र किया है कि हायर सैकंडरी की तालीम को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक बिल आने वाला है । ऐसा बिल जिस के जरिये तालीम का ढांचा बेहतर बने । मैं समझता हूं जरूर आना चाहिए । इस के साथ ही मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक ऐग्जामिनेशन बोर्ड बनाने का सवाल है यह एक ऐसा काम है जो सरकार की बड़ी सोच विचार के बाद अपने हाथ में लेना चाहिए । ऐजुकेशन डिपार्टमेंट को यूनिवर्सिटी से यह काम अपने हाथ में इस ढंग से लेना चाहिए कि किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव हमारे तालीमी ढांचा पर न पड़े । खास तौर पर इन इम्तिहानात को डिपार्टमेंट बड़ी सोच विचार के बाद टेक ओवर करे ताकि हमारी तालीम का स्टैंडर्ड और बढ़े । मुझे यह कहने में भी कोई झिजक नहीं कि हमारी तालीम का म्यार ऊंचा उठने की बजाये नीचे को ही गया है । हमें इसको ऊंचा उठाने के साधन अपनाने चाहियें । इसी लिए मैं कहता हूं कि हमें सारे कदम बड़े सोच विचार के बाद उठाने चाहिए । इन इम्तिहानात से हमें 32 लाख रुपये की आमदन होती है । हमें जहां इतनी आमदन को संभालना है हमें इस बात को भी नज़र अन्दाज़ नहीं करना चाहिए कि हम ने तालीम के म्यार को भी ऊंचा ले जाना है । पंजाब यूनिवर्सिटी ने हिन्दोस्तान भर में तालीम का ऊंचा स्तर कायम करके नाम पैदा किया है, हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरफ बड़ी सोच विचार के साथ कदम उठाने चाहियें । एक तरफ हमने ऐजुकेशन बोर्ड कायम करके यह देखना है कि 32 लाख की इन्कम जो इम्तिहानात से होती है वह होनी चाहिए, दूसरी तरफ तालीम के स्टैंडर्ड को भी कायम रखना है । अगर यह किसी तरह से घटिया दर्जे का हो जाता है तो कुदरती तौर पर जो रैपूटेशन हमारी हिन्दुस्तान भर में आज तक बनी हुई है वह भी गिर जायेगी । आप को यह बात याद ही होगी कि जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त हमारे लड़कों को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जल्दी जल्दी दाखल ही नहीं करती थी । कहते थे कि यह तो सोशल सरविस का बी० ए० है । आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक आला म्यार कायम किया है और पूरे ध्यान से आगे कदम उठाया है । इस ऐड्रेस के अन्दर गवर्नर साहिब ने जिक्र किया है कि 25 लाख रुपए इस काम के लिए और स्पेयर किए गए हैं जिस के लिए यह सरकार बधाई की पात्र है । एक आनरेबल मेम्बर साहिब ने यह भी जिक्र किया कि ऐजुकेशन का स्तर बेहतर तो है मगर इतना काबले तारीफ नहीं । मैं उनके साथ इस पर बिल्कुल सहमत हूं ।

[प्रिसीपल रला राम]

हमें इस को और ऊंचा ले जाना है और यह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे टीचर्स की आर्थिक हालत अच्छी नहीं हो जाती । इसी तरह से प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए भी हमें सबसे पहले प्राइमरी टीचर्स की हालत बेहतर बनानी होगी । प्राइमरी एजुकेशन के अन्दर जहां तक सुपरवाइजरी स्टाफ का ताल्लुक है सुपरवीजन की हालत निहायत खस्ता है । प्राइमरी टीचर्स स्कूलों के अन्दर इतना काम नहीं करते जिस से तालीमी स्तर ऊंचा हो सके । इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि 25 लाख रुपये की जो प्रोवीयन रखी गई है वह निहायत नाकाफी है । प्राइमरी टीचर्स के लिए कम-से कम 100 रुपये महावार वेतन होना चाहिए । अगर हम उसको इससे कम देते हैं तो तालीम का मयार ऊंचा नहीं उठा सकते ।

ट्रांसपोर्ट के मुताल्लिक मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने महज 9 महीनों के अन्दर इस काम में एक करोड़ 18 लाख रुपये का प्राफिट दिखाया है । लेकिन इसके साथ मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि बहुत सा किराया का पैसा जो बसों में टिकटें बेचते वक्त हासिल होता है, चोरी होता है । मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं अक्सर बसों में सफर करता हूं, मेरे पास अपनी कोई कार नहीं है । बसिज की 33 प्रतिशत आमदन ड्राइवर और कन्डक्टर मिल कर चोरी करते हैं । पिछले दिनों मैं जब बस में आ रहा था हम कोई 10 आदमी बैठे थे, इन में से किसी को टिकट नहीं दिया गया । सिर्फ एक आदमी को दिया गया जो कि बूटिड-सूटिड था । सिर्फ एक आदमी को टिकट दिया जो नकटाई पहन कर बैठा था । उसे वह समझते थे कि गवर्नमेंट का आदमी होगा । हम लोग तो देहाती मालूम देते हैं । मुझे भी टिकट नहीं दिया । जब हम शाम को आए तो पता चला कि एक भी टिकट इशू नहीं किया गया । ट्रांसपोर्ट की 33 फी सदी आमदन उधर रह जाती है । यह महकमा बधाई का पात्र है । अगर हम यहां भी सेविंग करके मुनासब इंतजाम करें तो नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह जो वाबेला है ज्यादा टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए हम इस से निजात पायेंगे । तो उसके लिए मैं यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए महकमे की तबज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पंजाब की यहां जो निगरानी और सुपरविजन है वह की जाये और लीकेज आफ रैवेन्यू को रोकना चाहिये, इसकी बड़ी भारी जरूरत है । कम से कम 33 फी सदी मेरे अपने ऐस्टीमेट के अन्दर लीकेज होती है । जहां तक कुरप्पशन का ताल्लुक है हम सब फील करते हैं कि हम इस की वह राखी नहीं कर सके जो कि करनी चाहिए । इसकी राखी हम उस वक्त समझेंगे जबकि गली के अन्दर जो आदमी है, गांव का जो आदमी है वह यह कहे कि मेरा काम बिना पैसे लिए हो गया दफ्तर में या कचहरी में । वह स्थिति अभी तक नहीं आई । इसके लिये रैड-टेपिजम, लाल फीते के रूल को कंट्रोल करना होगा और बहुत ज्यादा स्टाफ जो दफ्तरों में है कम करना होगा । मैं दफ्तरों में बहुत दफ्ता नहीं जाता लेकिन जब कभी दफ्तरों में जाता हूं, किसी काम के लिए जाने का मौका मिला है तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने 25 फी सदी से ज्यादा अमला को निकम्मा आईडल बैठा हुआ देखा । यह चीज ज्यादा है । अगर हमारा अमला ज्यादा बढ़ जाता है तो काम की आऊटपुट कम हो जाती है । इस तरफ ध्यान दें । यह जो

कुरपशन है, भ्रष्टाचार है इसकी किसी हद तक पब्लिक भी जिम्मेदार है। पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आयद होती है। मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ, इन्होंने चौकसी समितियाँ, विजीलेंस कमेटियों बनाई हैं जो कि इसको रोकने का प्रयत्न करेगी। यह भी अच्छा और सराहनीय कदम है। लेकिन उस के लिये हम कामयाब तब होंगे जब हम सूबे में यह जो रैड टैपिज़म लाल फीत शाही है इसको रेशनेलाईज़ करेंगे ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति यह अनुभव करे कि मेरा काम अब दफतर के अंदर बिना पैसे दिये हो जाता है। वह स्थिति अभी बहुत दूर है। कुरपशन काफी है। इस लिये मैं यह समझता हूँ कि इस तरफ हमारे कदम बढ़ने चाहिए (घंटी)। रोड्ज़ एंड बिल्डिंग्ज़ पी. डबल्यू. डी. के महकमे के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक देहाती लिंक रोड्ज़ का प्रश्न है वे बनानी चाहिए। यह ठीक है बिल्डिंग्ज़ के काम को संकट की वजह से मुलतवी करना चाहिए, उस से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मेरा यह ख्याल है कि **We have spent more on brick and mortal than what we should have spent.** हम ने ईंट और सीमेंट पर ज्यादा खर्च किया है, कम करना चाहिए था। इस तरफ रोक थाम बिल्कुल सही है। लेकिन रोड्ज़, खास कर विलेज लिंक रोड्ज़ का जहाँ तक ताल्लुक है वह होनी चाहिए। इस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर महोदय के एड्रेस में इसका कोई जिक्र नहीं। मैं आशा करता हूँ और आप के जरिए मैं अपनी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। गांव की हालत को बेहतर बनाने के लिये और आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विलेज लिंक रोड्ज़ की तरफ ज्यादा ध्यान बिल्कुल जरूरी है ताकि पिछड़े हुए जो देहाती इलाके हैं वे भी आर्थिक उन्नति कर सकें।

जहाँ तक इस खुश्कसाली का ताल्लुक है एक बात मैं आप के जरिए कहना चाहता हूँ। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है। लेकिन उस का ज्यादा फायदा मैदानी इलाकों की फसलों को पहुंचेगा। मैं अपने इलाके में देखता हूँ जो ऊंची ज़मीनें हैं कितनी भी बारिश पड़े उन्हें कोई फायदा नहीं। वक्त पर बारिश पड़ी नहीं, ज़मीनें खाली पड़ी हैं। जो बीजा था पैदा नहीं हुआ। वहाँ पर एक तो सस्ते अनाज के डिपो हों। वह अभी वहाँ खोले जाने चाहिए, वह हालत वहाँ भी पैदा हो रही है। वहाँ लोगों के लिये सस्ते अनाज के डिपो खोले जाएं। इस की जरूरत है। उन के पास रोज़गार के बसीले नहीं रहेंगे। जो सड़कें बनानी हैं उन का खासा हिस्सा पहाड़ी इलाके में बनना चाहिए। कुछ सड़कें तो आगे ही सैंक्शन हुई हुई हैं। उस काम को जलदी शुरू करना चाहिए। यह फसलें तो बिल्कुल तबाह समझनी चाहिए। सड़कें बनाने से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और आगे के लिये उनकी ज्यादा आर्थिक उन्नति भी हो सकेगी। यह पहाड़ी इलाके में सड़कें बनाने का जो काम है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस पर ज्यादा खर्च होना चाहिए ताकि उन गरीब लोगों को जिन की फसलें बिल्कुल नहीं हो रहीं रोज़गार मिल सके। केवल माली इमदाद करने से सहायता नहीं होगी, रोज़गार मुहइया करना जरूरी है। इन सड़कों के काम से उन्हें बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आप का धन्यवाद करता हूँ।

कामटेड समझे सिंथ नैम (रेपज़): भाठजेठ सपीकर साहिब, सभ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਚਮ, ਕੁਟਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀਟਤਾ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਗਲ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਟਿਕਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਸੱਖਣਾ ਜਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ **it lacks direction, initiative and push**। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗਲਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

### [Deputy Speaker in the Chair]

ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਸਫਾ 11 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ **'clean responsive and efficient administration has been the aim of my Government'** ਤੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਇਹ ਕਲੀਨ, ਰੈਸਪਾਂਸਿਵ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨਕਲੀਨ, ਅਨਰੈਸਪਾਂਸਿਵ ਤੇ ਇਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁਛਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ **unclean irresponsive ਤੇ inefficient administration** ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ 30 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ, **Without calling any tenders, without holding any public auction, without negotiating with any other party except Birlas.** ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਔਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਕ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗੀ ਧਨਾਡ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਨੀਲਾਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਾ ਹੈ? ਉਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ

ਬੋਝ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਦਮ ਨਵਾਂ ਪੁਟਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ ਉਚਿਤ ਗਲ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾ-ਚਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਆਖਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਚਲੋ, ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿਖਤ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਵੇਂਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਉਸ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ੌਰ ਬਣਨ ਲਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ੌਰ ਫੇਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਕੁਰਪਟ ਹੈ ਉਹ ਅਜ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਔਰ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜੂਨ 1964 ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਨੌ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਰੋਂ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲੀਡਰ'। ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਲੈਚਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਕ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1707 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 81 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 50 ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਤਾਂਜੋ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵਜੇ ਬਾਂਸਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲ ਦਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਰਡ ਤੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਖਾਣ ਹੈ :—

‘The fox changes his skin but not his habits.’

ਲੂਮੜੀ ਆਪਣੀ ਖਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਸਰੂਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਲੀਡਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਨਕੁਲੂਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹੋ ਪਾਰਟੀ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਾ ਕਰੋ। (The hon. Member Shri Josh may criticise the Government in any manner he likes but not make a party propaganda)

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਆਪ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ, ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਏ ਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਖ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 1965 ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਵਿਚ ਆਵੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ

ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਅਰੈਂਸ ਅਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਨਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਲਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਓਸ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਅਲਾਊਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਫਾ ਡੀ. ਏ. ਵਧਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਲਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਰੇਡ ਵਧਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ 18 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ਪੇਡ ਸਖਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ, ਅਲਾਊਂਸ, ਡੀ. ਏ. ਵਧਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲੈਚਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ :

“The appointment of pay commission, particularly for lower grade Government employees in Punjab, the establishment of a directorate for training Government employees and a directorate of personnel welfare to look after their welfare are some of the important recommendations made by the Administrative Reforms Commission set up by the Punjab Government.....”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਜ਼, ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੋਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਪੇ ਸਕੇਲਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਤਨਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਗਰੇਡ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਜੋਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਵਾਲਾ ਜਿਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਟੀ. ਵਾਲਾ ਜਿਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਈ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਜ਼/ਮਾਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕ ਦੋ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕਲ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹਿਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। A great deal of resentment is prevailing among the teachers against this betrayal of the Punjab Government ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 60/65 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਲਈ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਸਟਰ, ਮਾਸਟਰਾਨੀ 5 ਰੁਪਾਮ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਜੋ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸੋਨਾ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਕੁਅਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦਭਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀ. ਐਲ. 480 ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਐਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲਿਆਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਲੇਕਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ, ਤੀਜੇ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਇਕ ਲਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਇਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ

ਕਰੋੜ 63 ਲਖ ਰੁਪਏ

ਵਿਚ ਜੋ

87 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨਇਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 47 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ ਅਤੇ 53 ਫੀ ਸਦੀ ਅਨਇਰੀਗੇਟਿਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੋਰ ਰਾਜਬਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਸੈਟਿਵ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਥੇ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਅਨ-ਜਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇਕ ਰਿਗ ਬੋਰਿੰਗ ਲਈ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਬੋਰਿੰਗ ਰਿਗ ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਿਗਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਲਈ ਇਕ ਰਿਗ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 11 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨਇਰੀਗੇਟਿਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਨਹਿਰ ਜਮਨ ਗਰਬੀ, ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਠੂੜ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਣੇ ਤਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧ ਸਕੇ। (ਘੰਟੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਖਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਲੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 22 ਰੁ : ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਖਾਦ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਲੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 18½ ਰੁਪਏ

[ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ]

ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 1.50 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ 2.25 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 0.75 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ either you take the Nangal Fertilizers Factory as State Undertaking and supply the fertilizers at "no profit no loss" basis, or you stop supply of cheap electricity to that Factory and earn dividends, or get subsidy worth one crore of rupees from the Central Government and supply fertilizers at cheap rate to the people

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਮਾਮਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 1948 ਵਿਚ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਿਊ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। 1953 ਵਿਚ States Reorganization Commission ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਮੌਰਚੇ ਲਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਸ਼ੂ ਦੋਬਾਰਾ ਉਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਲਿਆਮੈਂਟਰੀ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਗਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ nothing short of Punjabi Suba will be acceptable to the people of Punjab and, if the Government of India does not concede it, the people will not accept that verdict.

ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉਤੇ ਇਕਠਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕੁਹਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। (ਘੰਟੀ) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਘੰਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ

ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ (ਘਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਤ ਦੀ ਜੋ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਮੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਸੀ, ਬਚਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੁਢਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਉ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ

6.00 p.m. ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, 10, 10 ਜਾਂ 12, 12 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਉਪਰ **interest free** ਖਰਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ 2½ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ

**[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ]**

ਹੁਣ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਵਿਖਾ ਦਿਉ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੈਸ਼ ਵਿਖਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਫਿਰ 2,500 ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਰਲਾ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇ। ਪਰਸੋਂ ਰੇਡੀਉ ਵਿਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕੀ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਾਂ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। **(May I know if any Minister is taking notes of the proceedings about the Harijan Problem? The Harijan members are giving vent to their difficulties and the Government has to reply to these points. After all we have to solve their problem.)**

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲ ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋਬਾਰਾ ਇਹ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦੇ ਡੀਪੋ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 11,000 ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਗੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੇਸੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਤਕ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਊਬ-

ਵੈਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਾ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆਂ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਧਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 4,4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦੀ ਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਢਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਰੀਜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਉ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈਆਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਬਚਾ ਤਾਂ ਐਮ. ਏ. ਤਕ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਤਾਂ 4,000 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਲਵੇ ਪਰ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ 80, 90 ਜਾਂ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਰਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕਪੜੇ ਸਿਲਵਾ ਦਿਉ, ਸਾਡੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਥੇ 6 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਕਲਰਕ ਕਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਟ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ]

ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਹਰਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫ਼ਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਹਿਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਥੇ ਸੜਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਕਸ ਵਿਚ ਐਪਰੋਚ ਰੋਡਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਕ ਗਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਸੀਕਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਮੀਲ ਭਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਕ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਡਸਾਹ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਫੈਂਸ ਐਫਰਟਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਉਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ—ਜਦ ਲੋਕ ਜਾਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖੁਵਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ, ਛੰਬ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾਗ ਹੋਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਉੱਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਔਰ ਡਟਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਖੂਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਯਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੋਤਮ (ਉਨ੍ਹਾਂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1965 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਮੌਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਥੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ—ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕਮਾਰਕਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਕਮੈਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ—ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂ ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਉਥੇ ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਫੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦਾ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗਲ

[ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੋਤਮ]

ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਨਕ ਸਕੂਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,33,00,000 ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਡਰ, ਤਕਾਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ—ਮੁਬਾਰਕ ਗਲ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਲਈ 1,33,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਉਨਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫੂਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਫਿਸਿਟ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਮਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਉਨਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਡੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਹਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜ ਤਕ ਉਨਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਉਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲ ਉਨਾ ਦੇ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰ-ਸਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਉਨਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਰਾਗ ਤਲੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿਤਸਾਲੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਥਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ

**Deputy Speaker :** Please wind up now.

**Deputy Speake** : Please wind up

60, 49 2 4 9, 2- 8- 14- 16- 373 0153

[ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੋਤਮ]

ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕੀ 50 ਪੈਸੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤਸਰੀਫ਼ ਰਖੋ। (The hon. Member should resume his seat.)

ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੋਤਮ : ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਉ।

Deputy Speaker : No please.

ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੋਤਮ : 50 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

Deputy Speaker : No please.

ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ (ਹੁਸੀਰਪੁਰ, ਏਸ. ਸੀ.) : ਸਫ਼ਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇ ਏਡੰਸ ਪਰ ਤਬਸਰਾ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਸੈਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ..... (The hon. member was still on his legs when the House adjourned.)

ਤਪਾਧਿਕਸ਼ਾ : ਸਫ਼ਰ ਕਲ 9½ ਬਜੇ ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। (The House shall reassemble at 9.30 a. m. tomorrow.)

(The Sabha then adjourned till 9.30 a. m. on the 22nd February, 1966.)



**"C" 1966**

Published under the authority of the Punjab Vidhan Sabha and  
printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab, Chandigarh.

# Punjab Vidhan Sabha Debates

*22nd February, 1966*

**Vol. I—No. 5**

**OFFICIAL REPORT**



## CONTENTS

	PAGES
<i>Tuesday, the 22nd February, 1966</i>	
Starred Questions and Answers ..	(5)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45 ...	(5)19
Points of Order ..	(5)68
Questions of Privilege ..	(5)69
Call Attention Notice ..	(5)81
Papers laid on the Table ...	(5)85
Discussion on Governor's Address (Resumption) ..	(5)87
Personal Explanation by Sardar Gurnam Singh ..	(5)103
Resumption of Discussion on Governor's Address (Not Concl'd)	(5)104-121

[illegible]

# ERRATA

TO

*Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 5 dated the 22nd February, 1966.*

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ	ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ	(5)2	17
ਫਾਸੀ	ਫਾਸੀ	(5)2	20,34
ਹਵੇਗਾ	ਹਵੇਗਾ	(5)4	15
ਬਤੌਰ ਲੋਨ	ਬਤੌਰ ਲਾਨੇ ਲੋਨ	(5)5	10th from below
growers	gorwers	(5)7	3
ਰੀਆਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ	ਰੀਆਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ	(5)13	14, 20
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ	ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ	(5)13	3rd from below
ਭਨਕਮਪਲੀਟ	ਭਨਕਪਲੀਟ	(5)14	14
ਖੇਚਲ	ਖੇਚਨਲ	(5)14	19
ਆਪਣੇ	ਆਪਣੇ	(5)14	29
Deputy Minister	Deputy Ministwer	(5)14	32
Challan	Challans	(5)16	8
registered	regstered	(5)17	15
Amritsar	mritsar	(5)23	4th from below
in his	him in	(5)30	3
in	by	(5)34	2
out side the Constituency	by him	(5)34	3
tehsil	tesil	(5)35	5
library	ibrary	(5)37	8th from below
Panjwar	Panjwal	(5)38	7th from below
Karnal	Karna	(5)39	Last

P. T. O.

(ii)

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
Samrala	Samral	(5)41	15
Construction	Constuction	(5)48	15
district	distric	(5)49	2
school	schoo	(5)49	4
Gandhi	Gand	(5)51	13
Karan	Karam	(5)51	20
College	Co ege	(5)51	29
Ambala	Amba a	(5)51	Last
library	brary	(5)56	16th from below
Gujri	Gujr	(5)62	3rd from below
stayed	staged	(5)63	15
Development	Developmen	(5)64	1
पंडित	पंडति	(5)68	8th from below
Pandit Chiranji Lal Sharma	{ Pandit Chiranaji Lal Sharma	(5)82	13
	{ Pandit Chiaranji Lal Sharma	(5)86	6
पंडित चिरंजी लाल शर्मा	पंडित जिरंजी लाल शर्मा	(5)82	28
श्री	श्री	(5)88	1
जंगे	जंगे	(5)91	9
morning	morn ng	(5)95	25
बतदा	दावर	(5)95	Last
लुका	लुका	(5)95	Last
Deputy Speaker	Dputy Speaker	(5)106	Last but one
DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS	GOVERNOR'S ADDRESS	(5)117	Heading

Se  
ba

C

M  
s

## PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 22nd February, 1966

*The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 9.30 A.M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.*

### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

#### Supplementaries to Starred Question No. \*9167

**Mr. Speaker :** Supplementaries on Starred Question No. 9167 by Chaudhri Net Ram.

**Comrade Ram Piara :** Mr. Speaker, the Home and Development Minister is not present in the House. He is to reply to this question and he should reply because there is a lot of bungling.....

**Mr. Speaker :** Comrade Ram Piara do not make a speech. Your point has come.

**Mr. Garg,** is the Home Minister coming today or not ?

**Chief Parliamentary Secretary :** No, Sir.

**Mr. Speaker :** All right, supplementaries are postponed.

#### Supply of Canal water to the Government Seed Farms

**\*8861. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that the Government Seed Farms are supplied more canal water than that supplied to the other land-owners of the commanded area ; if so, the reasons therefor ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** Yes, to produce seed of superior quality and in sufficient quantities so that the same is made available to the cultivators to step up food production.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤਲੱਕਾ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਐਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

**ਸਕੱਤਰੀ :** ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਸੁਤਾਲਿਕ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਧਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਡਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨੇਟ ਨੇ ਸਨ 1963 ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਥਾ।  
It was a suggestion from the Agriculture Department and it was approved by the Cabinet.

**ਚੌਥਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਿਕ :** ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਧਰ ਜੋ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟਸ ਕੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਮੈਂ ਕਾਪ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ?

**\*Note.**—Starred Question No. 9167 and reply there to appear in P.V.S. Debate, Vol. I, No 3, dated the 17th February, 1966.

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਸੂਬੇ ਭਰ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਕਰਿੰਗ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੋ ਏਗਰੀਕਲ-ਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ?

**Mr. Speaker :** That matter relates to the Agriculture Department.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੋਅਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਧਰੁ ਭਾਤ ਕਵੈਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਗਰੀਕਲ ਪਾਨੀ ਕਯੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਯਾ ਜਾਤਾ । ਮੈਂ ਨੇ ਤੋ ਜੋ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਹਨ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਰਖੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਆਪ ਅਲਗ ਨੋਟਿਸ ਦੇਂ ਤੋ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਹੋਂ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਠਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਮੈਂ ਨੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਹਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਯਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਥਾ ਕਿ ਕਯੋਂਕਿ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਅਚਠਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿਏ ਧਰੁ ਡਯਾਲ ਥਾ ਕਿ ਪਾਨੀ ਕੀ ਕਮੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਹੋ । ਇਸ ਲਿਏ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਕੋ ਆਰ ਏਗ੍ਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਲੀ ਫਾਰਮਾਂ ਕੋ ਫਾਲਰੂ ਪਾਨੀ ਦੇਨੇ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਯਾ ਗਯਾ ਥਾ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ :** ਕਯਾ ਕਰਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਕੋ ਡਬਲ ਪਾਨੀ ਦਿਯਾ ਗਯਾ ਉਨ ਕੋ ਕਿਸੀ ਸਟੇਜ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਰਿਫਾਈ ਕੀਯਾ ਯਾ ਇਸ ਕਾਤ ਕੋ ਏਗ੍ਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਕਿ ਕਯਾਦਾ ਪਾਨੀ ਦੇਨੇ ਸੇ ਕੋਈ ਫਾਯਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਏਗ੍ਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕਾਯਾ ।

**ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਮੈਂਟ ਸੀਡ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਅਗਰ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਏਗੀ ਤੋ ਉਸਕੋ ਏਗ੍ਰੀਕਲ ਕਰ ਲਿਯਾ ਜਾਏਗਾ ।

**ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੁਗਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਯੀਲਡ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਠਾਲੋਂ ਵਧ ਹੈ ਤੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਮੈਂ ਨੇ ਪਹਲੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਯਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਕੀ ਕਰਿੰਗ ਆਰ ਮੇਨ-ਟੇਨੈਂਸ ਕਾ ਕਾਮ ਏਗ੍ਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਸਕੀਦ ਇਤਲਾਹ ਚਾਹਿਏ ਤੋ ਇਸ ਕੇ ਲਿਏ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਆਪ ਦੇ ਦੇਂ I will try to collect it.

**श्री अमर सिंह :** क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब सारी ही सीड फार्मों फेल हो गई हैं तो क्या कारण है कि बिरला को बीज तैयार करने के लिये सीड फार्म अलाट कर दी गई ?

**Mr. Speaker :** Not allowed.

**चौधरी राम सूर्य :** क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि ज्यादा पानी देने से भी बीज खराब हो जाते हैं तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं है कि बह देखे कि पानी ज्यादा दिया है जिस की वजह से बीज खराब हो गए हैं।

**Mr. Speaker :** Beyond the scope.

**सरदार गुरुचरन सिंह :** मैं वजीर साहिब से यह पूछना चाहता हूँ कि पंजाब ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਡ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

**ਸਰਕਾਰ :** ਮੈਂ ਨੇ ਪਹਲੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਲੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

#### Re-settlement of the Beas Dam Oustees

**\*9294. Thakur Mehar Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) whether Government has taken a final decision for the resettlement of the Beas Dam Oustees in Rajasthan; if so, the area of land being reserved for them for the purpose and the area of land proposed to be given to each family together with the financial aid proposed to be given to them to construct their houses and start agricultural operations;
- (b) the details of transport facilities, if any, proposed to be given to the oustees to enable them to take their families and belongings to the place of their resettlement?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Yes. It has been decided to resettle the Beas Dam Oustees in Bikaner Division of Rajasthan in the area commanded by Rajasthan Canal. An area of 3.25 lac acres of land has been reserved for the purpose of resettlement of Punjab and Himachal Pradesh Oustees by the Rajasthan Government. The extent of land that would be allotted to each eligible oustee family is under consideration of the Government. Rajasthan Government have agreed to advance a loan of Rs 2 000 per family to construct their houses. There is no proposal at present to give financial aid to the oustees for starting agricultural operations.

(b) Details of transport facilities proposed to be given to the oustees to enable them to take their families and belongings to the place(s) of their resettlement on the pattern as adopted on the Bhakra Project are given in the Annexure 'A'

#### ANNEXURE 'A'

(1) Railways/Bus fare (inclusive of incidental charges) per adult members Rs 25

(2) No fare to be paid for children below three years of age.

## [Minister for Irrigation and Power]

- (3) For children between three years and twelve years of age .. Half the rates proposed above.
- (4) Freight charges for all animals to be transported on wagon load basis. In addition incidental charges of rupees 15 per cattle of the category of buffalo, Cow, Ox and camel etc. For Sheep and goat the customs will be given rupees 2 for each.
- (5) In addition, the oustees are to be paid a rehabilitation grant of Rs 250 per family. However, an increase in rehabilitation grant is under consideration.

**ਲੇਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ :** ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਵੇਗਾ ?

**ਸਰਕਾਰ :** ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

**Shri Rup Singh 'Phul' :** Sir, may I know the approximate date by which the first batch of oustees will be taken from District Kangra for settlement in Rajasthan ?

**ਸਰਕਾਰ :** ਇਸ ਦੇ ਲਿਏ ਹੁਸ਼ੀਅਰੀ ਨਾਲ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨ ਕੌਨ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਏ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੇਨੇ ਪਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣੇ ਭੀ ਹੋਣਗੇ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ :** ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਭੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ?

**ਸਰਕਾਰ :** ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਮਾਂਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਚੋਰੇ ਗੈਰ ਹੈ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦੇ ਆਉਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (That question has already been answered.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨਿਹੋਤ੍ਰੀ :** ਕੀ ਇਨ ਆਉਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਿਏ ਕੋਈ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

**मुख्य मन्त्री :** यह एक ऐसा सवाल है जो कि सारे हाउस की दिलचस्पी का बायस बना हुआ है। जहां तक ब्यास डैम के आउस्टीज़ का सवाल है हमारी 3 बार इस मुआमले के मुताल्लिक बात चीत हो चुकी है। मार्च के आखरी हफता में जो मीटिंग हुई इस में यह फैसला किया गया कि इनको 3 लाख 25 हजार एकड़ जमीन दी जाय। फिलहाल दो खित्ते हैं एक 19,000 एकड़ का और दूसरा 70,000 एकड़ का जो कि दिये जाते हैं। यह जमीन सिर्फ उन दो आउस्टीज़ को ही दी जायेगी जो इस जमीन को पूरी तरह से डिवैल्प करना चाहते हैं। हम इन को पूरी सुविधाएं जो भी दे सकते हैं देने की कोशिश करेंगे। जब तक कि वह पूरी तरह बसाये नहीं जा सकते इनके लिये ट्रांसपोर्ट का भी सारे का सारा बन्दोबस्त किया जायेगा। गवर्नमेंट लेवल पर इस के लिये एक कमेटी बनी हुई है जो वर्क आऊट कर रही है।

**चौधरी नेत राम :** ब्यास डैम निर्माणकारियों को जो जमीन दी जायेगी वह बारांनी जमीन होगी या इस को नहरी पानी दिया जायेगा।

**मुख्य मन्त्री :** हमारी कोशिश तो यह है कि वह जमीन दी जाये जिसको कि नहरी पानी लगता हो। उनको अच्छी से अच्छी जमीन देने की कोशिश की जाएगी।

**श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम :** जैसा के पहले बताया गया है कि आउस्टीज़ को 2000 रु० फी फैमिली घर बनाने के लिये दिया जायेगा, इस जमाने में जब कि हर एक चीज़ महंगी है क्या यह दो हजार रुपये नाकाफी न होंगे ?

**मन्त्री :** 2,000 रु० का लोन तो मकान बनाने के लिये है और भी बहुत से कामों में अलग अलग सहूलतें दी जायेंगी।

**लैफ्टीनेंट ब्राग सिंघ :** मैं पुछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो वादिया 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਗਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਦਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਉਸਟੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

**Mr. Speaker :** There should be no reflection on the Rajasthan Government. The hon. Member should please put his supplementary question. There should be no comment on the Rajasthan Government.

Moreover this is not a supplementary question.

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** दो हजार रुपया जो बतौर लाने लोन दिया जायेगा क्या यह विद इंस्ट्रैस्ट है या विदआऊट इंस्ट्रैस्ट है ?

**मन्त्री :** यह इंस्ट्रैस्ट फरी लोन होगा।

**कामरेड ब्राग सिंघ डेरा :** ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰੈਂਡਮ ਆਪਣੀ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਆਉਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

**मन्त्री :** उन की बहुत सी डिमांडज़ थीं जिन में से कुछ को मान लिया गया है और कुछ पर गौर किया जा रहा है।

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि दो खित्तों में जमीन है जो दी जानी है। एक 70 हजार एकड़ की है और दूसरी 19 हजार एकड़ की। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सारी जमीन को पानी दिया जायगा ?

**मन्त्री :** पहले फेज में जो जमीन दी जायेगी यह इरीगेटिड रकबा होगा और दूसरे फेज में जो जमीन दी जानी है वह बाद में सैराब हो जायेगी। पानी तकरीबन सारी को लगेगा।

**श्री रूप लाल महता :** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि गुड़गांव जिले को जो नहर दी जानी है इस के लिये 1966 तक जो मुकम्मल करने का फैसला किया था आया यह उस के मुताबक मुकम्मल हो जायेगी ?

**मन्त्री :** शैड्यूल के मुताबिक 1966 तक यह कम्प्लीट हो जायेगी।

**श्री बाबू दयाल शर्मा :** यह नहर कौन कौन से इलाके को सैराब करेगी ?

**मन्त्री :** वैसे तो इस सारी जमीन से कोई 6,86,000 ऐकड़ जमीन सैराब होगी मगर इस में से कोई 1,65,000 ऐकड़ जमीन राजस्थान की है जो सैराब की जायेगी। बाकी 5 लाख से ऊपर गुड़गांव जिले की है जो सैराब की जायेगी।

### Gurgaon Canal Project

**\*9325. Shri Roop Lal Mehta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the time by which the Gurgaon Canal Project is likely to be completed ;
- (b) the source of water from where the said canal will be fed ;
- (c) whether any feeder has been completed to provide water for the said canal ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) By 1969-70 Subject to availability of funds.

(b) River Yamuna and river Beas after the completion of Beas Sutlej Link

(c) Yes Narwana Branch Karnal Link has been completed,

**Pandit Chiranjil Lal Sharma :** May I know Sir as to why the completion of this Project has been unnecessarily delayed ?

**मन्त्री :** शैड्यूल के मुताबिक काम चल रहा है। 1962 में एमरजेंसी की वजह से ड्राप कर दिया था। शैड्यूल के मुताबिक यह काम जून, 1966 में मुकम्मल होना चाहिए, वह हो रहा है।

**श्री बाबू दयाल शर्मा :** क्या गवर्नमेंट के नोटिस में है कि उस नहर पर जो मैटीरियल पड़ा था वह पिछले दिनों में दूसरी जगह भेज दिया गया है ?

**मन्त्री :** मैटीरियल के मुताबिक सैपेरेट नोटिस दे दें, पता कर दूंगा।

**चौधरी नेत राम :** क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन के खेतों में नहर का पानी नहीं लगा और फसलें नहीं हुई क्या उन किसानों को सहायता दी जाएगी ?

**श्री अध्यक्ष :** वह अलग सवाल है। (This is a separate question.)

### Rates charged for Water supplied for Sugarcane in District Gurgaon

**\*9328. Shri Roop Lal Mehta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the rates of canal water supplied from the Upper Agra Canal for Sugar-cane in Gurgaon District are

high as compared with the rates charged in the other areas of the State ;

(b) whether the Government proposes to compensate the growers of Gurgaon district on account of the difference in the water rates referred to in part (a) above ;

(c) whether the Government proposes to acquire rights over the Upper Agra Canal portion in the Punjab Area in order to provide facilities to the Punjab farmers and to save them from payment of high water rates ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Yes

(b) No

(c) The matter is being pursued with the Government of India and the U.P. Government.

**श्री रूप लाल महता :** सौ साल से पंजाब के किसान डबल आबयाना दे रहे हैं। इस डबल रेट को कम करने के लिये पंजाब सरकार क्या कर रही है ?

**मन्त्री :** जिला करनाल की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उन पर जो आबयाना है वह पंजाब के दूसरे हिस्सों की निसबत ज्यादा है। क्योंकि उन पर यू. पी. गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, इस लिये भी कुछ तसल्लीबख्श काम नहीं होता। हमने यूनियन मिनिस्ट्री की मारफत यह दरखास्त दी थी कि यह जो गुड़गांव जिले में आगरा कैनाल की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इनका कंट्रोल पंजाब सरकार को दे दिया जाए और ट्रांसफर कर दें। दो महीने हुए दिल्ली में मीटिंग हुई थी। उस में यू. पी. के इरीगेशन मिनिस्टर और सैंटर के मिनिस्टर थे और पंजाब की तरफ से भी नुमायंदा हाजर था। उस में दो तीन बातों पर डिस्कशन हुई। उस के बाद 3 इंजीनियर्स की एक कमेटी बनी है। सैंटर के वाटर एंड पावर कमीशन के चेयरमैन उस के चेयरमैन हैं, एक इंजनियर पंजाब का है और यू. पी. के चीफ इंजीनियर मैम्बर हैं। वह सारी पोजीशन को एग्जामिन कर रहे हैं। उस में प्रिंसीपली यह फैसला होना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटरीज गुड़गांव जिला में से गुजरती हैं, जो होल यू. पी. की जमीनों को सैराब करती हैं उनको छोड़ कर बाकी डिस्ट्रीब्यूटरीज का कंट्रोल पंजाब सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए। उनकी रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।

**श्री रूप लाल महता :** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस साल ड्राट में पानी की कमी हुई आगरा नहर का हम ने पानी लेना था, पंजाब सरकार ने कितने कदम उठाए हैं पानी दिलाने के लिए ?

**मन्त्री :** इस साल पानी की सप्लाई का सम्बन्ध ईस्टर्न कैनाल से था, आगरा कैनाल से था। पंजाब की नहरें जो वेस्टर्न जमना कैनाल से, दरियाए जमना से सर्व होती हैं उन की नार्मल रिक्वायरमेंट का चौथा पांचवां हिस्सा भी पानी नहीं था। वह हालात ऐसे थे जिन में पंजाब सरकार या यू. पी. की सरकार मदद नहीं कर सकती थी। ड्राट की वजह से, बारिश न होने की वजह से पानी कम था।

**श्री बाबू दयाल शर्मा :** क्या गवर्नमेंट यह बता सकती है कि इतना अरसा से यू. पी. गवर्नमेंट चौगना टैक्स वसूल कर रही है, हमारी गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए ?

**मन्त्री :** बार 2 इस सवाल को टेक अप किया है। यू. पी. सरकार इसको ट्रांसफर करने के लिये एग्रीएबल नहीं थी। दो दफा मीटिंग्स हो चुकी हैं। इस मामले को परसू करेंगे।

**चौधरी नेत राम :** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी जगहों पर भी जहाँ किसानों की फसलें खड़ी हैं नहरों में पानी नहीं और इस के नतीजा के तौर पर खुराक में भी कमी है क्या सरकार उन किसानों को अनाज पैदा करने की सुविधा देगी?

**श्री अध्यक्ष :** यह सवाल पैदा नहीं होता। (This question does not arise.)

**श्री बाबू दयाल शर्मा :** पंजाब सरकार ने यू. पी. सरकार को बार 2 यह बात पेश की ज्यादा रेट चार्ज करने की और उनके न मानने पर इन्होंने यूनियन सरकार को यह मामला कितनी बार पेश किया कि हमसे चौगना रेट चार्ज किया जा रहा है?

**मन्त्री :** डेढ़ साल में यह मामला दो तीन दफा टेक अप किया है। दो दफा मीटिंग्स हो चुकी हैं। इस को सीरियसली परसू कर रहे हैं। प्रिंसिपली कुछ बातें तैयार की गई हैं। जितनी गवर्नमेंट की शक्ति है या जो कुछ इस मामले में कर सकती है हम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं।

**श्री सागर राम गुप्ता :** मैं मिनिस्टर साहिब से जानना चाहता हूँ कि सारे पंजाब में मुख्तलिफ वाटर रेट्स हैं, नहर का मुख्तलिफ है, ट्यूबवैल का मुख्तलिफ है, इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

**Mr. Speaker :** Not allowed.

**श्री रूप लाल महता :** पिछले साल सारी फसलें बरबाद हुई। पंजाब सरकार के जरिए हमने लिखा कि हमारे किसानों को वाटर रेट में रिमिशन मिलनी चाहिए, जैसे इस का ससपेंशन हो जाती है, यू. पी. सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। क्या सरकार उन्हें कम्पेंसेट करेगी?

**मन्त्री :** कम्पेंसेट करने के मुताल्लिक तो कुछ नहीं कर रहे। पंजाब के सम्बन्ध में किसानों को जहाँ रिलीफ देते हैं पानी न मिलने की वजह से वहाँ यू. पी. गवर्नमेंट भी देगी। और भी सुझाव हैं जिन की बिना पर पंजाब सरकार ने यह मुनासब समझा कि उन नहरों का कंट्रोल पंजाब के अख्तियार में हो तो जैसे और इलाके में देते हैं गुड़गांव के इलाके को भी यह सहूलत दें।

**श्री बाबू दयाल शर्मा :** मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इतना जो उन्होंने एक्सेस रिसीव कर लिया है क्या गवर्नमेंट उसको रिफंड कराने के लिए कोई तजवीज कर रही है?

**मन्त्री :** वह यू. पी. गवर्नमेंट ने फैसला किया है। आगरा कैनाल पंजाब स्टेट में नहीं है। जो उन के रेट हैं वह सारी स्टेट में हैं। उसके रिफंड करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

#### Construction of Grid Station at Sultanpur (Kapurthala)

**\*8958. Sardar Balwant Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether the Punjab State Electricity Board has acquired any land for the construction of a Grid Station (Power Station) at

Sultanpur (Kapurthala), if so, the date of acquisition of the said land ;

- (b) the details of the scheme of the Board with regard to the construction of the above-mentioned Grid Station (Power Station) and the dates when its construction is likely to be started and completed ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Yes Sir. 19-9-1963.

(b) The Scheme envisages construction of 2 MVA/33/11 KV Sub-station at Sultanpur and 33 Kv line from Kapurthala to Sultanpur. The work is likely to be started in March, 1966 and completed in December, 1966.

**ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ :** ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਲੈਕਟਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ? ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ । 1963 ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

Do you normally take three years in such cases, or is Sultanpur a particular case where three years have been taken between the acquisition of land and the starting of the Project itself ?

**ਮਨਤਰੀ :** ਭੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕੇਸ ਕਾ ਤੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਆਗਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਬਤਾਓ । ਨਾਰਮਲੀ ਦੋ ਤੀਨ ਸਾਲ ਝਰੂਰ ਲਗ ਜਾਏ ਹੈ । ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੈਟੀਰਿਯਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਕਰਨੇ ਮੇਂ, ਫ਼ਰਸਰੀ ਬਾਥੇ ਹੈਂ, ਉਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।

**Sardar Balwant Singh :** May I know from the hon. Minister, if the Government is prepared to enquire into the causes of this long delay and fix responsibility on the Officer responsible for such a long delay ?

**ਮਨਤਰੀ :** ਕੈਸੇ ਡੀਲੇ ਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਯਹ ਥੀ ਕਿ ਸੈਟੀਰਿਯਲ ਬਾਹਿਰ ਸੇ ਲਾਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਫਨਡਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਭੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ।

**ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ :** ਕਯਾ ਮਨਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਬਤਾਓਗੇ ਕਿ ਸਿਤੰਬਰ, 1966 ਮੇਂ ਕਹ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਕਿਤਨੇ ਏਰਿਯਾ ਕੋ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ ?

**ਮਨਤਰੀ :** ਇਸ ਕੇ ਲਿਏ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹਿਏ ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

**ਮਨਤਰੀ :** ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਈ, 1963 ਮੇਂ ਦੇ ਦਿਯਾ ਗਯਾ ਥਾ ।

#### Applications from persons of Bhiwani Tehsil for granting old age pension

**\*9319. Shri Sagar Ram Gupta :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- (a) the names and addresses of the persons in Bhiwani Tehsil from whom applications for old age pension have so far been received by the Government together with the dates on which the same were received ;

[Shri Sagar Ram Gupta]

- (b) the names and addresses of the persons out of those mentioned in part (a) above, who have been sanctioned the said pensions together with the amount sanctioned in each case and the date when it was sanctioned ;
- (c) the period within which the remaining applications are likely to be disposed of ?

**Shri Chand Ram :** The requisite information is laid on the Table of the house.

(a)&(b) No separate Tehsil-wise record of the applications received has been maintained. The time and labour involved in the collection of the requisite data will not be commensurate with the benefit likely to be achieved. However, out of 295 persons, who have so far applied for pension from Hissar District, 143 persons have since been granted pension. The rate of pension in all the cases is Rs 15/- p.m. each.

(c) Efforts will be made to dispose of the remaining applications as early as possible, subject to availability of funds.

**श्री सागर राम गुप्ता :** क्या मंत्री महोदय बताएंगे ओल्ड एज पेंशन की दरखास्तों को डिस्पोज आफ करने के लिए क्या क्राइटीरिया फिक्स कर रखा है ?

**मन्त्री :** दरखास्तें जैसे जैसे आती हैं first come first served के हिसाब से डील की जाती हैं। इस के इलावा जिन का कोई बिलकुल वाली वारस न हो उन को प्रायरीटी दी जाती है।

**श्री बलराम जी दास टंडन :** जब कोई दरखास्त आती है तो उस के मंजूर होने के लिए और ऐप्लीकेंट को पेंशन मिलने के लिए कितना समय लगा जाता है ?

**मन्त्री :** जब ऐप्लीकेशन आती है तो उस की इनवैस्टीगेशन करवाई जाती है। लेकिन सवाल फण्डज का भी होता है। फण्डज हमारे पास इतने नहीं हैं कि सब डिज़रविंग केसिज़ में पेंशन दे सकें।

**श्री बलराम जी दास टंडन :** क्या ओल्ड एज पेंशन सब को बराबर दी जाती है ?

**मन्त्री :** हां जी, 15 रुपए माहवार दी जाती है।

**बाबू अजीत कुमार :** सपीकर साहिब, अपेलीकेशन फार्म विच एक ऐसी आपीटम है जिहड़ी मैजिस्ट्रेट कॉलें अटैच्ट करवाਉਣੀ पੈਂਦੀ है। (Interruption)

**श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या मैम्बर साहिब अपनी सीट से बोल रहे हैं या किसी दूसरी सीट से ?

**Mr. Speaker :** He has been allotted that seat at his own request.

**श्री बलराम जी दास टंडन :** उन्होंने स्पीकर साहिब अपनी सीट चेंज करवाने के लिए क्या वजह लिख कर दी थी ?

**बाबू अजीत कुमार :** मैं परसनल अक्सपलानेशन दे दिंदा हਾਂ। मैं एरिजनली रिपबलीकन पार्टी का मੈਂबर सी मगर अकाली पार्टी ढाल घुँटो असेसिएट मੈਂबर दे बँठदा सी। मगर एरिजनली मैं रिपबलीकन पार्टी नुं बोलेंग करदा हਾਂ इस करके उस दे बेसिस ते मैं रिक्जैस्ट कीती सी और सपीकर साहिब ने मैनुं एह सीट अलॉट कर दिती है।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ੇਟਿਡ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਕੋਲੋਂ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

**ਸਕੱਤਰੀ :** ਮੈਂ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਣਗੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

**ਸਕੱਤਰੀ :** ਸੁਝੇ ਅਫਸਰੀਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਸਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈਂ ਜਿਨਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਂ ਹਰਿਜਨ ਨਾਨ ਹਰਿਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ ਕੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਹੈਂ ਤਨਕੋ ਸਬ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਗੋਤਸ :** ਕਧਾ ਕਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਧਹ ਜੋ 15 ਰੁਪਏ ਸਾਹਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਧਾ ਇਸੇ ਕਢਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਯੋਰ ਗੈਰ ਹੈ ?

**ਸਕੱਤਰੀ :** ਮੈਂ ਪਹਲੇ ਭੀ ਅਯੋਂ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ It is a question of funds ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਪਹਲੇ ਹੀ ਕੋਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਈ ਹੁਈ ਹੈ ਜਿਨਸੇਂ ਸੇ ਸੁਭਿਕਲ ਸੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈਂ। ਕਾਕੀ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋਤੋ ਹਸ 15 ਰੁਪਏ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੈਂ।

**ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਹਨ.....(ਸ਼ੋਰ)

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਫੀਸਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਜ਼ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। (This House has accepted three Languages viz. English, Hindi and Punjabi for the conduct of its proceedings and the hon. Members can speak in all the three languages for expressing their views. As the Members are aware the Official Languages Bill has already been passed. It is, therefore, not desirable to raise a point of order like this time and again. The Members can speak in any of the three languages.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਤਵਜ਼ੁਹ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸ ਜੋ ਲੋਕ ਗਏ ਹਨ.....

**Mr. Speaker :** I am sorry, it is not a point of order. This question has nothing to do with the Parliamentary Committee to which the hon. Member is referring to.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ..... (ਵਿਘਨ).....ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(I have already given my ruling on this point. This House can conduct its proceedings in three languages and out of these, a Member or a Minister may speak in any language.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.....(ਸ਼ੋਰ).....

**ਸ਼੍ਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ ਕਿੱਤ :** ਕਜੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਈ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਾਫਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿਯੋਗੀ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਭਰਵਾਰ ਭਾਟੋਂ ਜਾਤ ਹੈਂ ਕਥਾ ਉਸ ਫੰਡ ਮੈਂ ਸੇ ਰੁਪਏ ਭਰਵਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲਿਏ ਤੈਧਾਰ ਹੈਂ?

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ :** ਇਹ ਜੋ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੰਡਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

**ਸਕੱਤਰੀ :** ਧਰਮ ਸਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨੇਟ ਦੇ ਪਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਕੂ ਦਯਾਲ ਰਾਮ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਥਾ ਧਰਮ ਆਨਰੇਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? (ਹੱਸੀ)

## Scales of Pay and status of Tehsil/District Welfare Officers

\*9265. **Shri Amar Singh** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to upgrade the Scales of pay/status of the Tehsil Welfare Officers and District Welfare Officers in the Welfare Department; if so, the approximate date by which the same is likely to be implemented ?

**Shri Chand Ram** : The proposal is under consideration of the Government.

**श्री अमर सिंह** : पिछले सेशन में भी यही बात कहते थे और अब फिर यही कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक यह अंडर कंसिडरेशन रहेगा ? क्या इसके लिए कोई कमेटी बगैरा बनाई है या वैसे ही सिम्पल कंसिडरेशन हो रही है ?

**मन्त्री** : यह मामला हम ने फिनांस डिपार्टमेंट के पास उठाया हुआ है और उनको बताया है कि यह जो डिपार्टमेंट्स की रीआगेनाईजेशन हो रही है उस से खर्च में कमी पड़ेगी लेकिन हम फिनांस वालों को अभी तक समझा नहीं पाए हैं और उन्होंने अभी तक ऐसी नहीं किया है। शायद जल्दी ही इस का फैसला हो जाएगा।

**श्री अमर सिंह** : मैं वजीर साहिब को बताना चाहता हूं कि तहसील वेलफेयर अफसर का स्टेटस ऐसा है कि वह खुद ही चपड़ासी है खुद ही क्लर्क और खुद ही टी. डब्ल्यू. ओ. है। क्या वह सहसूस नहीं करते कि उनके साथ ज्यादाती हो रही है ?

**मन्त्री** : मैंने अर्ज किया है कि यह जो सारे महकमा की रीआगेनाईजेशन हो रही है उसके साथ यह भी चीज लिंक है कि वहां चपड़ासी भी हो और तनखाह का ग्रेड भी ज्यादा हो तो यह अंडर कंसिडरेशन है।

**कामरेड डान सिंघ भैंरा** : की वजीर साहिब दसलगे कि गरेड वधाण लयी नो अकटिव कनसिडरेशन हो रही है उस नुं किउना वकत लगोगा अजे उं एह महकमा वी टैम्परेरी ही चल रिहा है।

**मन्त्री** : मैंने अर्ज किया है कि फिनांस वालों के पास यह मामला गया हुआ है।

**बाबू अजीत कुमार** : की वजीर साहिब दसलगे कि उहिमील ते डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसरों के गरेड आफ पे अपगरेड के नाल नाल उनों के स्टेटस नुं वी ने इस वकत कलरक नालों वी घॉले है अपगरेड करन लयी मंच रही है ?

**मन्त्री** : जहां तक डी. डब्ल्यू. ओ. का ताल्लुक है उनका स्टेटस बढ़ाने में दिक्कत नहीं है गरेड बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। टी. डब्ल्यू. ओ. के बारे में सोच रहे हैं। मैं ने अर्ज किया है कि यह सारा मामला इन्टरनिक्ड है।

**सरदार लॉधी सिंघ** : वजीर साहिब ने किहा है कि अफ. डी. पास एह अंडर कनसिडरेशन है। की इनुं दी रिसपॉन्सिबिलिटी जार्डिंट नही अजे की एह एह महकमे वलों जवाब दे रहे हन जं गौरमिंट वलों जवाब दे रहे हन ?

**Mr. Speaker** : He has stated the facts.

**श्री जगन्नाथ** : इन्होंने ने कहा है कि फिनांस डिपार्टमेंट उनके ग्रेड के बारे में सोच रहा है। मैं पूछना चाहता हूं फिनांस डिपार्टमेंट फाइनल अथॉरिटी है या कैबिनेट ?

**ਸਾਨੀ :** ਧਹ ਤੋ ਸੇਰੇ ਖ਼ਾਲ ਸੋਂ ਸਕ ਜਾਨਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਏਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੋ-  
ਜਲ ਬਨਾਤਾ ਹੈ ਐਰ ਏਨ. ਡੀ. ਤਨਕੀ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇਖਤਾ ਹੈ । ਦੋਨੋਂ ਕੀ  
ਕਨਕ੍ਰੈਂਸ ਕੇ ਬਾਦ ਹੀ ਸਕ ਕੁਝ ਹੋਤਾ ਹੈ ।

**Expenditure incurred on extradition of Sucha Singh**

**\*9231. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home and Develop-  
ment be pleased to state the total expenditure incurred by the  
State Govt. item-wise, on the extradition of Shri Sucha Singh, the alleged  
murderer of the late S. Partap Singh Kairon ?

**Sardar Gurmit Singh (Deputy Minister. Development, Irrigation  
and Power) :** It is not possible at this stage to give a complete picture of the  
expenditure incurred on the extradition of Shri Sucha Singh.

**ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਲ ਸੇਨ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨਨੀਧ ਤਪ ਸੰਗੀ ਨੇ ਸੇਰੇ ਸਵਾਲ  
ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿਨਟ ਸੋਚਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਜਵਾਬ ਦੇਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਧਾ । ਮੈਂ ਤਪ ਸੰਗੀ ਸਹੋਦਧ ਸੇ  
ਪੂਛਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਂ ਇੰਕਪਲੀਟ ਜਵਾਬ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮਧ ਤਨ ਕੇ ਪਾਸ ਸੌਜੂਦ  
ਹੈ, ਦੇਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਤੈਧਾਰ ਹੈਂ ।

**ਤਪਸੰਗੀ :** ਮੈਂ ਨੇ ਸਾਨਨੀਧ ਸਦਸਧ ਕੋ ਤਨ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਧਾ ਹੈ ਕਿ :  
that it is not possible at this stage to give a picture of the total expen-  
diture incurred by the Government.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਨਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ  
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?

**ਉਪ ਮੰਤਰੀ :** ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਫਾਰ-  
ਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ  
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ  
ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ?

**Deputy Minister :** I have already stated that it is not possible at this  
stage to give a picture of the expenditure incurred by the Government.

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ  
ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਉਹ ਵੀ  
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿਤਾ  
ਕੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ?

**Deputy Minister :** Necessary data is being collected from the con-  
cerned quarters. Therefore, it is not possible at this stage to give the total  
expenditure incurred by the Government.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** May I ask the hon. Deputy Minister  
as to whether efforts have been made to collect this information by the  
Government at all ?

**Deputy Minister :** Efforts are being made. Necessary data is being  
collected from the concerned quarters.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੇਨ :** ਤਪਸਨਕੀ ਸਹੋਦਯ ਤੋਂ ਹਮਾਰੀ ਤਸਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਏ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਚਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਅੱਥਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਕੀਤਨਾ ਖਰਚ ਆਯਾ ਹੈ ?

**ਮੁਖਯ ਮੰਤਰੀ :** ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਏਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇਪਾਲ ਮੈਂ ਗਏ। ਇਸ ਕੇ ਅਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਆਫਿਸਰ ਭੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਗਏ। ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਯਕਤੀਯੋਂ ਕੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਆਰ ਕੁਝ ਕੇ ਬਿਲਜ਼ ਅਭੀ ਆਨੇ ਕਾਕੀ ਹਨ। ਜਬ ਸਬ ਕੇ ਬਿਲਜ਼ ਆ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਸਾਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੋ ਭੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਕਹ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਰਖ ਦੀ ਜਾਏਗੀ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ : that necessary data is being collected. Till the Government collects the necessary data, kindly postpone the supplementaries on this Question.

**Mr. Speaker :** No, please.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ੨ ਮਹੀਨੇ, ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

**ਮੁਖਯ ਮੰਤਰੀ :** ਜਬ ਯਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਰਖਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਏਗੀ।

#### Cases against sons of the Late S. Partap Singh Kairon

**\*9232. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state:—

(a) the names of places in the State where cases against Sarvshri Surinder Singh and Gurinder Singh sons of the late Sardar Partap Singh Kairon, are being tried at present together with the charges on which and the provisions of law under which each is being tried ;

(b) the stages at which the cases referred in part (a) above are at present .

**Sardar Gurmit Singh :** (Deputy Minister, Development, Irrigation and Power) :

(a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

## [Deputy Minister Development Irrigation and Power]

## Statement of cases which are being tried against Sarvshri Surinder Singh and Gurinder Singh sons of late S. Partap Singh Kairon

Serial No.	Particulars of the case	Name of places where cases are being tried at present	Charges	Provision of law	Present stage
1	F.I.R. No. 37, dated 18th August, 1964, P.S. Chamkaur Sahib, District Ambala against Surinder Singh Kairon and others (Note : There are four challans in this case.)	i. Ambala (1 challan) ii. Jullundur (1 Challans) iii. Rupar (2 challans)	Alleged corruption and misappropriation of material in the construction Siswan Super passage by Capital Construction Co. owned by Shri Surinder Singh Kairon	409/420 I.P.C. and 5(2) of P.C. Act.	Pending in Court at prosecution stage
2	F.I.R. No. 131, dated 8th August, 1964 P.S. Sadar Ambala against Surinder Singh Kairon and others	Ambala	Alleged misuse of G. C. Sheets etc. controlled material (issued on permits) by M/s Cineramas a concern of Kairon	7 E.C. Act read with Section 5 of Iron and steel control order of 1956.	Pending in Court for appearance of accused
3	F.I.R. No. 495, dated 27th October, 1964, P.S. Sadar Amritsar against Gurinder Singh and others	Amritsar	Alleged misuse of G.C. Sheets obtained for Cold Storage by Shri Gurinder Singh Kairon	7 E.C. Act.	Some P.Ws have been examined and 23rd February, 1966 has been fixed for the remaining P.Ws. Prosecution witnesses are being examined
4	F.I.R. No. 149, dated 19th November, 1964 P.S. Jind, District Sangrur against Surinder Singh Kairon	Jind	Alleged cheating and fraud practised by Surinder Singh Kairon and his 'Mukhtiar' on villagers of V. Dhani inducing them to part with their money, but did not transfer the land to them	406/420 IPC	
5	F.I.R. No. 232, dated 27th October, 1964, P.S. 'A' Division Amritsar against Gurinder Singh and others	Amritsar	Alleged misuse of G.C. Sheets obtained on permit by Gurinder Singh Kairon for Cinema construction	7E.C.	Charges were framed against Shri Surinder Singh Kairon but Shri Mehtab Singh accused was discharged State filed revision against this order which was accepted. The case has been fixed for 23rd February, 1966.

..

**श्री मंगल सेन :** क्या उप मन्त्री महोदय अपने सवालों के पैड को देख करके बताने की कृपा करेंगे कि उन के बखलाफ कितने केसिज थे, अब उन के बखलाफ कितने केसिज रह गए हैं और कितने केसिज विदड़ा हो गए हैं ? उन केसिज को विदड़ा करने का क्या कारण है ?

**Deputy Minister :** In all 23 cases were registered against the late Chief Minister Sardar Partap Singh Kairon and other members of his family in the following districts :—

(1) Ambala	.. 7 cases
(2) Amritsar	.. 8 cases
(3) Jullundur	.. 1 case
(4) Patiala	.. 2 cases
(5) Gurgaon	.. 3 cases
(6) Sangrur	.. 1 case
(7) Ludhiana	.. 1 case

Of these 20 cases were registered against his sons namely Sarvshri Surinder Singh and Gurinder Singh. Out of the 23 cases 7 have been filed as untraced or cancelled while challans in respect of 5 cases have been put up in the Courts and the same are pending trial at different stages and accused in 1 case was discharged. Investigation in respect of the remaining cases is likely to be finalised shortly when the challans of these will also be put up in the court(s).

**श्री मंगल सेन :** उप मन्त्री ने जवाब देते हुए फरमाया कि उन के बखलाफ कुछ केसिज अनट्रेसड करार दिए गए हैं और कुछ विदड़ा कर लिए गए हैं। मैं उप मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सुरेन्द्र सिंह और गुरेन्द्र सिंह अनट्रेसड हो गए जिस की वजह से ऐसा ऐक्शन लेना पड़ा।

**Mr. Speaker :** Untraced is a technical term in the Criminal Law.

**श्री मंगल सेन :** स्पीकर साहिब, क्रिमीनल ला मैंने तो पढ़ा नहीं है लेकिन सुन जरूर रखा हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सुरेन्द्र सिंह कैरों और गुरेन्द्र सिंह कैरों जो कि एक्ज्यूजड है, अनट्रेसड हो गए हैं, जिन की वजह से यह ऐसे केसिज अनट्रेसड करार दिए गए हैं ?

**उपमन्त्री :** मैंने जो कुछ अनट्रेसड के बारे में कहा, शायद माननीय मेम्बर उस चीज को समझ नहीं सके। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि जिन केसिज में पूरी विटनेस नहीं मिलती तो उन को अनट्रेसड करके छोड़ दिया जाता है। बाकी केसिज की इन्वेस्टीगेशन हो रही है और उन में से पांच केसिज अदालत में चल रहे हैं।

**कामरेड राम प्यारा :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने जवाब देते हुए फरमाया कि जब केस अनट्रेसड करार दे दिया जाता है तो फिर उस का चालान

कामरेड राम प्यारा]

कोर्ट में पुट अप नहीं किया जाता तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा केस है जहाँ पर अनट्रेसड केस करार देने के बाद भी चालान कोर्ट में पेश किया गया ?

**उपमन्त्री :** जनरली अनट्रेसड केसिज का चालान दोबारा कोर्ट में पुट अप नहीं किया जाता ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** On a point of order, Sir. The hon. Deputy Minister has been pleased to state that in the case of untraced cases challans cannot be put up in the courts. May I ask the hon. Deputy Minister, through you, Sir, if instances are given to the Government to show that where the cases have been sent up as untraced, challans have been put up in the courts, what action the Government will take ?

**Mr. Speaker :** This is not a point of order. This may be a supplementary.

**उपमन्त्री :** मारजिनल केसिज में ऐसा हो सकता है । लेकिन जब केस अनट्रेसड हो जाता है और कुछ भी सबूत नहीं मिलता और जो सबूत मिलते हैं वह नाकाफी होते हैं तो इन हालात में वह केसिज कोर्ट में पेश नहीं किए जाते । मैंने पहले अर्ज की कि उन के खिलाफ पांच केसिज कोर्ट में चल रहे हैं ।

**कामरेड राम प्यारा :** पहले निशान सिंह के केस को अनट्रेसड करार दे दिया था । उसके बारे में मैंने लिखा पढ़ी की और डंडा भी चढ़ाया । उस के बाद उसका चालान पेश किया गया । क्या इन केसिज पर डंडा चढ़ाने के बाद चालान कोर्ट में पेश किए जाएंगे ?

**उपमन्त्री :** जहाँ तक निशान सिंह के केस के बारे में सवाल किया गया, उस के बारे में सवाल में कोई बात नहीं है । अगर माननीय सदस्य इस बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वह सैपरेट नोटिस दें । पता करके बताया जा सकता है ।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** क्या डिप्टी मन्त्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रूलज में किसी केस को अनट्रेसड करार देने के लिए कितनी लिमिट मुकर्रर है या जब जी में आए या जब चाहें तो उस को अनट्रेसड करार दे दिया जाता है ?

**उप मन्त्री :** आनरेबल मੈम्बर का सवाल मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं आया मैं आप के जरिये उन से कहूँगा कि अपना सवाल दोबारा दोहरा दें ?

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** स्पीकर साहिब, मैंने पूछा है कि किसी केस को पुलिस रूलज के मातहत अनट्रेसड डिक्लेयर करने के लिए दो साल चार साल या दस साल की अवधि गुजर जाने की आवश्यकता है या वैसे ही दस दिन, बीस दिन या तीस दिन के अंदर ही अनट्रेसड डिक्लेयर किया जा सकता है ?

**Mr. Speaker :** Question hour is over now.

*(Interruptions and Noise in the House)*

**Mr. Speaker :** There will be more supplementaries on this question.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

**Challans under section 107/151 Cr. P.C. put up in Courts during the years,  
1965 and 1966**

**\*9289. Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of challans under sections 107/151 Cr. P.C. put up in the courts in the State during the years, 1965 and 1966 to date ;

(b) whether the number of cases under aforesaid sections is also kept in view while judging the efficiency of a Station House Officer of a Police Station ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Total number of challans under sections 107/151 Cr. P.C. put in the Courts.

1965

1966 (up to 11th February,  
1966)

44579

4399

(b) Quality and not quantity of preventive work is one of the many things which are kept in view while judging the efficiency of a Station House Officer.

**Gun Licences issued/cancelled in district Karnal**

**\*9368. Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number of gun licences issued during the period from 1st January, 1965 to 31st December, 1965 in District Karnal ;

(b) the number of Gun licences cancelled during the said period in the said district and a list showing the names and addresses of the licence holders whose licences were cancelled, be laid on the Table.

**Sardar Darbara Singh :** (a) 223.

(b) Thirty-five. A list is placed on the Table of the House.

List showing the Name and Address of the Licence Holders whose licences were cancelled during the period from 1st January, 1965 to 31st December, 1965

Serial  
No.

Name of licence holder with complete Address

- 1 Shri Chain Singh, son of Bhikham Singh, Jat Sikh of village Rohar
- 2 Shri Kapur Singh, son of Tara Singh Jat Sikh of village Thari
- 3 Shri Pritam Singh, son of Dula Singh Jat Sikh of village Rukshera
- 4 Shri Ram Kela, son of Kali Ram Jat of village Kawartan
- 5 Shri Jit Singh, son of Gita Ram
- 6 Shri Pala Singh, son of Hakam Singh Jat Sikh of village Rasulpur
- 7 Shri Kartara, son of Bir Singh of village Rasulpur
- 8 Shri Chaman Singh, son of Munshi of village Rasulpur
- 9 Shri Virsa Singh, son of Shri Dewan Singh Jat of Sikh of village Mustgarh
- 10 Shri Piara Singh, son of Bhagga Singh of village Khorak
- 11 Shri Makhan Singh, son of Banta Singh of village Secuser

Serial No.	Name of Licence Holder with complete address
12	Shri Malik Singh, son of Ujjagar Singh
13	Shri Gurcharan Singh, son of Sunder Singh of village Sausala
14	Shri Taswir Singh, son of Avtar Singh Jat Sikh of village Urlana khurd
15	Shri Jogi Ram, son of Raja Ram Jat of village Dikadla
16	Shri Jai Ram Dass, son of Dhani Ram, Tiagi of village Hathawala
17	Shri Ram Dhari, son of Naki Ram, Mahajan of village Dikadla
18	Shri Jagan Nath, son of Jai Dayal of village Rasaula
19	Shri Raghbir Singh, son of Mangal Singh of village Hamidpur
20	Shri Kapur Singh, son of Visakha Singh, village Darar
21	Shri Karnail Singh, son of Visakha Singh, village Chanar Heri
22	Shri Hazura Singh, son of Nand Lal of village Bansa
23	Shri Shingara Singh, son of Basan Singh of village Balu
24	Shri Vissa Singh, son of Nihal Singh of village Singra
25	Shri Karam Singh, son of Lachman Arora Sikh of village Shahbad
26	Shri Banta Singh, son of Sawand Singh of village Singara
27	Shri Dalip Singh, son of Man Singh of village Bachgaon
28	Shri Sardara Singh, son of Wasawa Singh (Lambardar), village Ruksana
29	Shri Gurbux Singh, son of Narain Singh, village Kamheri
30	Shri Nihal Singh, son of Ram Singh of village Bir Mathana
31	Shri Man Singh, son of Mangal Singh of village Dabri
32	Shri Beli Ram of Model Town, Karnal
33	Shri Labha Singh, son of Narain Singh of Barsat
34	Shri Sahib Singh, son of Labha Singh of village Barsat
35	Shri Sadhu Ram, son of Balwant Singh, Agond

#### Discretionary Grant given by Ministers

**a8908. Shri RupSinghPhul :** Will the Home Minister for Home and Development be pleased to lay on the Table of the House a statement showing the amount of discretionary grants given by each Minister, Minister of State and Deputy Minister, district-wise, during the current financial year ?

**Sardar Darbara Singh :** The statement is laid on the table of the House.

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (5)21**  
**TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45**

**Statement showing the total amount given by each Minister/Minister of State/Deputy Minister and Chief Parliamentary Secretary, district-wise during the current Financial year i.e. 1st April, 1965 to 31st January, 1966.**

Name of District	Name of Minister, with designation	Total amount given by him
1	2	3
		Rs
Ambala	.. Comrade Ram Kishan, C.M.	.. 14,250
	Shri Darbara Singh, H.D.M.	.. 5,000
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 2,100
	Shri Kapoor Singh, F.M.	.. 4,500
	Shri Gurdial Singh, T.E.M.	.. 2,000
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 1,200
	Shri Ajmer Singh, P.L.G.M.	.. 1,000
	Shri Prem Singh Prem, C.H.M.	.. 6,000
	Smt. Om Prabha Jain, H.M.	.. 1,000
	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	.. 1,600
	Shri Rattan Singh, M.A.H.A.	.. 1,100
	Shri Gian Chand, D.M.I.H.	.. 3,350
	Total	.. 43,100
Simla	.. Comrade Ram Kishan, C.M.	.. 10,000
	Shri Kapoor Singh, F.M.	.. 750
	Shri Gian Chand, D.M.I.H.	.. 1,250
	Total	.. 12,000
Hissar	.. Shri Darbara Singh, H.D.M.	.. 3,500
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 10,500
	Shri Kapoor Singh, F.M.	.. 1,500
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 3,100
	Shri Rizk Ram, I.P.M.	.. 4,500
	Shri Chand Ram, W.J.M.	.. 3,100
	Smt. Om Prabha Jain, H.M.	.. 3,000
	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	.. 1,000
	Total	.. 30,200

## [Home and Development Minister]

Name of District	Name of Minister with designation	Total amount given by him
1	2	3
		Rs
Rohtak (Concl'd)	.. Comrade Ram Kishan, C.M.	.. 18,000
	Shri Darbara Singh, H.D.M.	.. 8,500
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 4,200
	Shri Gurdial Singh, T.E.M.	.. 5,000
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 27,700
	Shri Harinder Singh, R.M.	.. 17,000
	Shri Rizaq Ram, I.P.M.	.. 30,700
	Shri Chand Ram, W.J.M.	.. 36,500
	Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	.. 5,451
	Shmt. Chandra Vati, D.M.F.S.	.. 1,000
	Shri Gurmit Singh, D.M.D.I.	.. 500
	Total	.. 1,54,551
Karnal	.. Shri Darbara Singh, H.D.M.	.. 2,000
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 5,100
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 4,000
	Shri Ajmer Singh, P.L.G.M.	.. 1,000
	Shri Harinder Singh, R.M.	.. 3,500
	Shri Rizaq Ram, I.P.M.	.. 1,000
	Shri Prem Singh Prem, C.H.M.	.. 5,000
	Shri Chand Ram, W.J.M.	.. 1,250
	Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	.. 75,00
	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	.. 500
	Shri Gurmit Singh, D.M.D.I.	.. 500
	Total	.. 31,350
Gurgaon	.. Comrade Ram Kishan, C.M.	.. 5,000
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 2,100
	Shri Kapoor Singh, F.M.	.. 1,500
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 5,000

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (5)23  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Name of District	Name of Minister with designation	Total amount given by him
1	2	3
		Rs
Gurgaon (Concld)	.. Shri Harinder Singh, R.M.	.. 5,000
	Shri Rizaq Ram, I.P.M.	.. 5,000
	Shri Chand Ram, W.J.M.	.. 1,000
	Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	.. 800
	Shri Rattan Singh, M.A.H.A.	.. 500
	Total	.. 25,900
Hoshiarpur	.. Shri Darbara Singh, H.D.M.	.. 6,000
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 5,900
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 1,000
	Shri Ajmer Singh, P.L.G.M.	.. 1,000
	Shri Rizaq Ram, I.P.M.	.. 2,000
	Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	.. 5,000
	Shri Rattan Singh, M.A.H.A.	.. 10,500
	Shri Gurmit Singh, D.M.D.I.	.. 500
	Total	.. 31,900
Kangra	.. Comrade Ram Kishan, C.M.	.. 500
	Shri Darbara Singh, H.D.M.	.. 2,500
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 1,100
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 1,000
	Shri Harinder Singh, R.M.	.. 2,500
	Shri Rattan Singh, M.A.H.A.	.. 750
	Shri Gurmit Singh, D.M.D.I.	.. 1,000
	Shri Gian Chand, D.M.I.H.	.. 11,500
	Total	.. 20,850
mrtsar	.. Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 4,200
	Shri Kapoor Singh, F.M.	.. 3,200
	Shri Gurdial Singh, T.E.M.	.. 16,500
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 1,000

## [Home and Development Minister]

Name of District	Name of Minister with designation	Total amount given by him
1	2	3
		Rs
Amritsar (concl'd)	.. Shri Ajmer Singh, P.L.G.M.	.. 500
	Shri Harinder Singh, R.M.	.. 4,500
	Shri Chand Ram, W.J.M.	.. 7,100
	Total	.. 37,060
Jullundur	.. Comrade Ram Kishan, C.M.	.. 22,100
	Shri Darbara Singh, H.D.M.	.. 10,400
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 2,600
	Shri Kapoor Singh, F.M.	.. 8,000
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 1,000
	Shri Ajmer Singh, P.L.G.M.	.. 2,000
	Shri Prem Singh Prem, C.H.M.	.. 1,000
	Shri Chand Ram, W.J.M.	.. 1,000
	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	.. 2,000
	Shri Gurmit Singh, D.M.D.I.	.. 500
	Total	.. 50,600
Kulu	.. Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	.. 1,000
	Shri Gian Chand, D.M.I.H.	.. 1,600
	Total	.. 2,600
Ludhiana	.. Comrade Ram Kishan, C.M.	.. 10,402
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	.. 2,600
	Shri Kapoor Singh, F.M.	.. 6,000
	Shri Gurdial Singh, T.E.M.	.. 5,000
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	.. 7,000
	Shri Ajmer Singh, P.L.G.M.	.. 45,000
	Shri Harinder Singh, R.M.	.. 2,100
	Shri Rizaq Ram, I.P.M.	.. 10,000
	Shri Prem Singh Prem, C.H.M.	.. 5,500
	Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	.. 10,000

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (5)25  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Name of District	Name of Minister with designation	Total amount given by him
1	2	3
		Rs
Ludhiana ..	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	500
(concl'd)	Shri Rattan Singh, M.A.H.A.	2,500
	Shri Ram Partap Garg, C.P.S.	1,000
	Total	1,07,602
Gurdaspur ..	Shri Prabodh Chandra, E.M.	1,100
	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	22,500
	Total	23,600
Ferozepur ..	Comrade Ram Kishan, C.M.	2,000
	Shri Gurmit Singh, D.M.D.I.	6,000
	Total	8,000
Lahaul and Spiti ..	Comrade Ram Kishan, C.M.	5,000
Patiala ..	Shri Darbara Singh, H.D.M.	4,000
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	1,500
	Shri Ajmer Singh, P.L.G.M.	4,500
	Shri Harinder Singh, R.M.	5,000
	Shri Prem Singh Prem, C.H.M.	16,000
	Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	5,000
	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	500
	Shri Rattan Singh, M.A.H.A.	2,000
	Shri Ram Partap Garg, C.P.S.	12,500
	Total	51,000
Sangrur ..	Shri Darbara Singh, H.D.M.	5,000
	Shri Prabodh Chandra, E.M.	1,100
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	2,000
	Shri Prem Singh Prem, C.H.M.	1,000
	Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	500
	Total	9,600

## [Home and Development Minister]

Name of District	Name of Minister with designation	Total amount given by him
1	2	3
Bhatinda	Comrade Ram Kishan, C.M.	Rs 5,000
	Shri Rizaq Ram, I.P.M.	4,000
	Shri Prem Singh Prem, C.H.M.	1,000
	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	500
	Shri Rattan Singh, M.A.H.A.	1,000
	Smt. Chandra Vati, D.M.F.S.	500
	Shri Ram Partap Garg, C.P.S.	2,500
	Total	14,500
Mohindergarh	Comrade Ram Kishan, C.M.	5,500
	Shri Darbara Singh, H.D.M.	5,000
	Shri Ranbir Singh, P.W.M.	6,000
	Shri Rizaq Ram, I.P.M.	2,000
	Shmt. Om Prabha Jain, H.M.	4,000
	Shri Sunder Singh, M.E.P.L.	2,000
	Shri Rattan Singh, M.A.H.A.	1,500
	Smt. Chandrawati, D.M.F.S.	18,904
	Total	44,904
Kapurthala	Shri Darbara Singh, H.D.M.	3,000
	Total	3,000

## Discretionary grants distributed by Ministers

**\*8927. Sardar Balwant Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- the amount of discretionary grant placed at the disposal of each Minister (including himself), Minister of State and Deputy Minister during the current financial year ;
- the amount out of the said discretionary grant distributed so far by each Minister, Minister of State, Deputy Minister in his own constituency and outside separately, together with the purpose for which it was given in each case ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) & (b) Statement containing the information is placed on the table of the House.



## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and designation of the Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own Constituency	For the purpose	Amount given outside the Constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
Chief Minister—Contd.						
		Rs	Rs		Rs	
		3,402				For the construction of Auditorium in the premises of Guru Nanak Engineering College, Ludhiana
		2,000				For the construction of Dharamsala in village Partal, district Mohindergharh
		5,000				For repairs of Gemur Monestary, Lahaul and Spiti
		1,000				Construction of village Chaupal in village Nangal Kalan, district Rohtak
		2,000				For dispensary building and medicine for the Haryana Public High School, Gohana, district Rohtak
		500				For Istri Samelan Building which is under construction in the compound of Chamunda Devi Mandir near Dharamsala, district Kangra
		5,000				For the extension of Bharat Tek Girls High School, Rohtak

1,500	For the purchase of library books for the Library of Gandhi Vidya Mandir, Charkhi Dadri district Mohindergarh
5,000	For furniture for Sanik Rest house, Rohtak
2 000	For the construction of building of Balidan Samarak Stadium at Charkhi Dadri, district Mohindergarh
5,000	To meet the educational expenses of Kanya Gurukul Maha Vidyalaya, Dehradun (Through Deputy Commissioner, Ambala)
5 000	For the construction of a Hall in the Rana Padam Chand Sanatan Dharam Bhargava College, Simla
1 000	For the development of Janta High School, Mustafabad (Science and Drawing Instrument), district Ambala
5,000	For the development of village Bopania district Rohtak (Completion of School Building), village Bopania, district Rohtak
2,500	For Sanyukta Sadachar Samiti, Chandigarh. (i) For the up-keep of Provincial Office, i.e., the pay of establishment, postage on daily correspondence, etc.
7,000	For Malwa Training College, Ludhiana (Science Equipment, Library Bocks, cost of Building, etc.)
5,000	For Ice Skating Club, Simla, for allowing free skating and provision of skating material free of charge to the poor Children, Simla
5,100	For the building of Geeta Bhawan in Shivpuri, Jullundur City

[Home and Development Minister]

S. No.	Name and designation of the Minister	Amount placed at his disposal	Amount given him in own Constituency	For the purpose	Amount given outside the Constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
	Chief Minister 1—Concid.	Rs	Rs		Rs	
					2,000	For the purchase of manuscripts and ancient religious Paintings from Nepal, for Spituk Gompa, Ladakh
					5,000	For the opening of the Regional Music College by the Harballabh Sangeet Sabha, Jullundur City.
					3,000	For acquiring of land for the Third All-India Leader Volley Ball Tournament, Jullundur, through President, All-India Leader Volley Ball, Tournament, Industrial Town, Jullundur City
					2,000	For completion of the building for Nari Niketan, Nakodar Road, Jullundur
				Total ..	94,252	
2	Shri Darbara Singh, Home and Development Minister	60,000	Nil	..	500	For the construction of Family Planning Centre, Phagwara (Kapurthala)
					5,000	For the construction of building of Public Middle Girls School, Bhungrani (Hoshiarpur) *
					2,000	For the construction of Home Science Laboratory L. B. (L), Bharatri Higher Secondary School, Panipat (Karnal)
					2,000	For the construction of Khalsa College, Patiala

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (5)31  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

5,000	For the construction of School building Shri G. R. Sanatan Dharam High School, Sargodha (Ambala City)
2,000	For the extension of school building S. D. Higher Secondary and J. B. T. Institution, Sultanpur-Lodhi (Kapurthala)
5,500	For the construction of a School Building at Pipli Khera (Rohtak)
5,000	For Library and Science equipment of Gandhi College, Charkhi Dadri (Mohindergarh)
5,000	For the benefit and extension of Goshala Uchana Kalan (Sangrur)
3,000	For the extension of Gurukul Building, Bhainswal Kalan (Rohtak)
1,500	For the improvement of 'Nehru Park' to commemorate memories of Martyrs at Sirsa (Hissar)
500	For the extension of Phagwara Club Premises at Phagwara, district Kapurthala
2,000	For the construction of building, purchase of furniture, etc., S. S. Harbhagwan School, Samana, district Patiala
2,000	For the construction of Primary School, Golagarh, tehsil Bhiwani, district Hissar
500	For the development of Play Ground and purchase of Sports Goods, village Dharamsala, district Kangra
2,000	For the utilization by the Village Panchayat Larha Tappa Galori, district Kangra
1,000	For the completion of Panchayat Ghar of Village Panchayat, Jalwehra, district Hoshiarpur

## [Home and Development Minister]

S. No.	Name and designation of the Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own Constituency	For the purpose	Amount given out side the Constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
2- Concl'd.		Rs	Rs		Rs	
					2,000	For the development works of Village Panchayat, Jaja Kalan
					1,000	As a relief to the families of the victims of Gobind Sagar in Boat drowning accident
					5,000	As a relief measure to the welfare of P. A. P. personnel 15th Battalion
					400	As a relief measure to the welfare of P. A. P. of Personnel 3rd Battalion
					1,000	Repairs of drains of Gram Panchayat, Shahkot, tehsil Nakodar, district Jullundur
					1,000	For repairs of the Public Middle School, Nihalwal, Jalwehra, district Hoshiarpur
				Total	.. 54,900	
3	Shri Prabodh Chandra, Education Minister	60,000	...	..	1,500	Purchase of furniture for Gandhi Bal Bhawan, Rajpura, district Patiala
					2,100	Purchase of library books for Vaish College, Bhiwani, district Hissar

2,100	Purchase of library books for R. S. D. High School, Sirsa, district Hissar
2,100	Purchase of Hygiene Physiology and Science apparatus for Jain Girls High School, Rohtak
2,100	Construction of library building and stadium of Sanatan Dharam College (Lahore), Ambala Cantt.
1,100	Purchase of library books for Vidya Mandir the school for children, Dharamsala, district Kangra
2,100	Purchase of library books Dera Ghazi Khan Hindu Higher Secondary School, Palwal, district Gurgaon
2,100	Purchase of Science apparatus for P. G. S. D. Higher Secondary School, Hissar
2,100	For extension of building of Bharat Tek Girls High School, Rohtak
2,100	Construction of a School Building of P.C.S.D. Higher Secondary School, Hansi, district Hissar
2,100	Purchase of library books for Hindu College, Amritsar
2,100	Purchase of library books for Dyal Singh College, Karnal
1,100	Repairs to the building of A. S. High School for Girls, Mukerian, district Hoshiarpur
1,100	Repairs to the building of Gandhi Janta High School, Thathal, district Hoshiarpur
1,100	Repairs to the building of D.A.V. High School, Una, district Hoshiarpur

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given by his own Constituency	For the purpose	Amount given by him	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
Rs						
					2,100	Purchase of Apparatus Slides Models etc., for the Biology Department of National College Sirsa, district Hissar
					2,500	Construction of building of R. K. S. D. College, Kaithal, district Karnal
					1,100	Construction of building of J. M. Shri Kundan Kanya Mahavidya, Amhedgarh, district Sangrur
					1,500	For the purchase of library books for Devi Sahai S. D. Higher Secondary School, Jullundur City.
					2,100	Purchase of books for library of Vishveshvaranand Vedic Research Institute, Hoshiarpur.
					2,100	For the purchase of equipment of Gymnasium Sports material and library books for D.A.V. Multipurpose Higher Secondary School, Amritsar
					500	Purchase of Hindi Typewriters for the office of the Hindi Sahitya Sangham, Hoshiarpur.
					2,100	For the purchase of library books for new Higher Secondary School for Boys and Girls, Civil Lines, Ludhiana

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (5)35  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

500	For the promotion of sports activities by the Republic Day Cricket Tournament Committee, Ludhiana		
500	For installing of Hand Pump in village Tundla, tehsil Karnal.		
1,10	For cultural activities to be utilized by the dramatic club of D.A.V. College, Jullundur.		
101	Purchase of material for gymnasting Patiala (For gymnastic team which gave Demonstration at Lalru, Derra Bassi Block)		
1,100	Purchase of library books for Arya Mahila College, Dinanagar, District Gurdaspur.		
		Total	44,201
5,000	Construction of a room of the National High School Gakkhal Dhaliwal, district Jullundur		
1,500	For the construction of a building Guru Nanak College, Dabwali, district Hissar.		
1,500	For the construction of a room in the S.D. High School, Gurgaon.		
1,260	Purchase of two Hand Knitting machines, Sital College for Women, Amritsar.		
1,500	Construction of 2 school building village Khur Buter Dhardev Crossing, district Amritsar.		
1,500	Purchase of equipment for S.D. Industrial School for Girls, Ambala Cantt.		
750	For developing the Scouts Camping Site and purchase of equipment Subathu, district Simla		
1,500	For purchase of Science equipment for Sikh National College, Banga, district Jullundur.		

4 S. Kapoor Singh,  
Finance Minister

60,000

(Since F.M. is an M.L.C. the Question regarding his own Constituency and outside does not arise.)

Total

44,201

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given by him in his own Constituency	For the purpose	Amount given by him outside his Constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
4—concl'd		Rs	Rs		Rs	
					1,500	Purchase of General Equipment for Prem Sewa Samiti Industrial School for Girls, Yamuna Nagar, district Ambala
					1,500	Construction of a room in Desh Bhagat Higher Secondary School, Gobindpur, district Jullundur.
					500	For the construction of Panchayat Ghar, village Lalpura, district Amritsar.
					1,500	To be spent for carrying on Special Service activities such as eye operation camps, by All India Sewa Samiti, Ambala Cantt.
					1,500	For the purchase of science equipment Guru Nanak Khalsa College for Boys, Ludhiana.
					750	Construction of a room in the Primary School, Sidhwan Bet, district Ludhiana.
					1,000	For construction of a room Khalsa High School, Nathowal, district Ludhiana.

(5)37

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

500	Purchase of books for the school library of Higher Secondary Girls School, Dehra, district Ludhiana.				
1,000	For the construction of a Rural Stadium at village Saraba, district Ludhiana.				
500	For the construction of a Janjghar by Ravi Dass Sewak Sabha, district Ludhiana.				
15,000	For the development and improvement of Panchayat Agricultural Lands of Nasruli area, district Ludhiana.				
5,100	For construction of a room in Women College, Phagwara.				
5,000	For repair to the school damaged building Convent of Jesus and Mary, Ambala Cantt.				
750	For construction of a room in primary School Salempur, district Ludhiana.				
	<b>Total</b>			50,610	
5	S. Gurdial Singh Dhillon, T.E.M.	60,000	3,000	2,000	For equipment for the Mountaineering Association, Ambala
	Construction of a Urinal, bathroom, etc., for Girls Hostel of Guru Arjan Dev Khalsa Higher Secondary School, Tarn Taran and for the purchase of books on development and national integration for school library			1,000	Sanitation and pavements of streets Sasroli, district Rohtak
	For improvement of sanitation in the Harijan Colony, Chabhal (Amritsar)			3,000	Pavement of street and sanitation village Juddi, district Rohtak
	Construction of link road connecting primary Health Centre and the main road, Chabhal, district Amritsar			5,000	Construction of approach road to village Bagpur in Mangat Block, district Ludhiana
				1,000	Sanitation and pavement of streets village Maliawas, district Rohtak

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and Designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own Constituency	For the purpose	Amount given by him out side his Constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
		Rs	Rs			
			4,000	(a) Earth work, culverts and bridges, etc., in village road connecting zila Parishad Middle School and Veterinary Hospital with the Bus Stand on the metalled Road (Amritsar-Khem Karn) near Dr. Tulsi Dass's garden, village Panjwar Khurd		
		2,000		(b) For Earthwork on road connecting village Bhujranwala with the Middle School and Veterinary School at Panjwal Kalan		
		2,500		For the construction of New Wings in the existing building of Khalsa Higher Secondary School, Nawanshahr, district Amritsar		
Total		16,500		Total	12,000	

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (5)39  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

6	Cn. Ranbir Singh, Public Works Minister	60,000	700	(1) Desilting of village Pond (2) Installation of Hand pump in village school, village Ritoli, Kabulpur, district Rohtak	5,000	Towards the construction of Nehru Children School building at Charkhi Dadri, district Mohinder garh
			500	Construction of Harijan Chopal in village Nigana, district Rohtak	2,000	Installation of tube-well in the Gandhi Memorial Public High School, Nariana, district Karnal
			2,000	Repair of Gausshala building Khidwali, district Rohtak, damaged during 1962 Floods	5,000	For extension of building of Lajpat Rai Memorial College, Jagraon, district Ludhiana
					2,000	Construction of Nehru Vigyan Bhawan in Jat High School Jind, district Sangrur
					2,000	Extension of building of the Khalsa College for Women, Sidhwan Khurd, district Ludhiana
					5,000	for laying of Rao Tula Ram Park Rewari district Gurgaon
					1,000	For Hindi Sahitya Sangam Library, Hoshiarpur
					1,000	Construction of a dispensary building by the Panchayat Durug of village Cha-hiar, district Kangra
					1,200	Purchase of books for Gandhi Samarak Nidhi Library, Chandigarh, district Ambala
					1,000	Installation of Hand Pump for Harijan in village Faridpur, district Hissar
					2,000	Publication of books on Haryana culture by Kurukshetra University, Kurukshetra, district Karnal
Total				3,200		

## RS

[illegible]

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and Designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
		Rs	Rs		Rs	
					1,000	Construction of a well and pucca streets in Ram Dasia and Balmiki Mohalla, village Manakpura, district Patiala
					1,000	Construction of a village library Room, Kahma, tehsil Nawanshahr, district Jullundur
					1,000	Construction of a village library Room in village Sa-aikhas district and tehsil Jullundur
					1,000	Construction of a bridge over Katra Minor between Majre Nand Karan and village Saharda, tehsil Kaithal, district Karnal
					1,000	Repair to the building of Shri Guru Gobind Singh Khalsa College, Mahalpur, district Hoshiarpur
					1,000	For the construction of Common Room, for use of Harijan, village Kutani Kalan, tehsil Ludhiana
					1,000	Construction of a Village Library Room, village Jonewal, tehsil Ludhiana

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(5)43

1	Shri Harinder Singh, Revenue Minister	60,000	2,000	For construction of village lanes and pavements of village Lala Afgana, tehsil Ajnala	Total	1,000	Construction of bridge village Baliwal tehsil Ludhiana
						13,000	
						2,000	For repairs of Chopal in village Ahulana, district Rohtak
						2,000	For the construction of building of free eye operation Hospital, at Karnal
						2,100	For the construction of the Sargodha Khalsa Girls Higher Secondary School, Ludhiana
						5,000	For the construction of building of the Public High School Samana and the purchase of Science apparatus, etc, for this School Samana, district Patiala
						2,500	For the construction of a road in village Bagroli, tehsil Nurpur, district Kangra
						10,000	For the construction of building of All- India Jat Heroes Memorial College, Rohtak
						5,000	For the construction of building of Kanya Gurukul Khanpur, district Rohtak
						5,000	For the construction of building and purchase of furniture and equipment for the educational institution noted below under the management of Ahir Education Board, Rewari

Serial No.	Name and Designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
		Rs	Rs			Rs
						(i) Teachers Training College, Rewari (ii) Ahir Degree College, Rewari (iii) Rao Balbir Singh Higher Secondary School, Rewari
						500 For the construction of Balmikij Harijan Well of village Sarhada, district Karnal
						1,000 For constructing a bridge over the Kacha road near village Ghataur Radur Block, tehsil Thanesar, district Karnal
						1,000 For organising exhibition and Sports on the occasion of the visit of Mr. M.C. Chagla, Union Education Minister, in Gurdaspur
						1,500 For construction of pacca streets village Musimbal, tehsil Jagadhri, district Ambala
						2,500 Construction of pacca streets in village Lalpura, district Amritsar
						Total .. 40,100

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(5)45

1	Shri Rizaq Ram, I.P.M.	50,000	11,000	For the construction of Tika Ram Memorial Hall in the Girls High School, Nahra, district Rohtak	10,000	For the construction of cycle shed and a Resting Room for the parents of the students in the Malwa College, Bondli, tehsil Samrala, district Ludhiana
			1,000	For construction of Chopal by Harijan (Chamar) Mahla Majra, district Rohtak	2,000	Additions and alteration in Girls Higher Secondary School, Santokhgarh, tehsil Una, district Hoshiarpur
			1,000	For construction of chopal for Harijans Mohamadabad, district Rohtak	2,000	Construction of Seth Chhajju Ram Memorial in the Farm Commercial College, Hissar
			1,000	For construction of a pucca tank in village Mandori, district Rohtak		
			5,000	Construction of Drain and reclamation channel around village Nahri, district Rohtak	2,500	For Gaushala for purchase of fodder, etc., village Dhanana, district Hissar
			1,000	Construction of a well for Balmiki Harijans, Halalpur, district Rohtak	1,000	For construction of a village road village Peoda, district Karnal
			1,000	For construction of chopal for Harijan, village Thanakalan, district Rohtak	5,000	For construction of a hostel of Sarvodya High and J.B.T. School, Patli
			1,000	For construction of chopal and repairs of wells of Harijans, village Garhibala, district Rohtak		
			1,000	For construction of chopal for Harijans in village Halalpur, district Rohtak	1,000	Construction of a Dharamsala, village Kot Sukhia, district Bhatinda
			2,700	Construction of a bridge over Jatola Minor for the area of village Kawali, district Rohtak	2,000	Construction of a bridge over R.D. 48200, Dadri District, village Hindol, district Mohindergarh

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and Designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
		Rs	Rs			
		2,000	2,000	For meeting the expenditure of railway crossing, village Kheri Manajat, district Rohtak	2,000	Completion of Veterinary Dispensary in village Sadiq, district Bhatinda
					1,000	Construction of a co-operative store, village Kot Sukhia, district Bhatinda
					1,000	For construction of chopal for Harijan, (Chamars) village Rohit, district Rohtak
					1,000	For donation for Anathalaya for uniform and clothing, Sonapat, district Rohtak
					1,000	For construction of Veterinary Hospital in village Kablana, district Rohtak
				Total	31,500	
1	Shri Prem Singh Prem, C.H.M.	60,000	500	Repair of two wells situated in Harijan Basti, village Jaraut, district Patiala	1,000	Construction of additional rooms in Arya Higher Secondary School Narwana, district Sangrur
			500	Repair of Harijan well, village Barauli, tehsil Rajpura	1,000	Construction of a co-operative store building Misriwala, district Bhatinda
			500	Repair of village well, village Dehra, tehsil Rajpura	3,000	Construction of a Library Extension Building, M.L.N. College, Yamuna-Nagar, district Ambala

Total

Total

1

Shri Prem Singh Prem,  
C.H.M.

60,000

500

Repair of two wells situated in Harijan Basti, village Jaraut, district Patiala

1,000

Construction of additional rooms in Arya Higher Secondary School Narwana, district Sangrur

500

Repair of Harijan well, village Barauli, tehsil Rajpura

1,000

Construction of a co-operative store building Misriwala, district Bhatinda

500

Repair of village well, village Dehra, tehsil Rajpura

3,000

Construction of a Library Extension Building, M.L.N. College, Yamuna-Nagar, district Ambala

500	Construction of a pucca streets, village Kaur, tehsil Rajpura			
1,000	Construction of pucca streets in Hari- jan, Mohalla, in village Ghanaur, tehsil Rajpura	5,000	Construction of rooms in Hindu Higher Secondary School, Kaithal, district Karnal	
1,000	Construction of a Janighar, village Banwari, tehsil Rajpura	3,000	Purchase of books for the Child, enwin g of Dawar, ka Dass Library, Lajpaa Bhawan, Chandigarh	
500	Repair of Harijan well, village Chaugera tehsil Rajpura	1,500	Construction of a village Library Room village Dholran, district Ludhiana	
1,000	Construction of a pucca street in village Kalo Majra, tehsil Rajpura			
500	Construction of a Janighar for Hari- jans in village Alluan, tehsil Rajpura			
1,000	Construction of pucca streets in village Alluan, tehsil Rajpura	1,000	Construction of Village Library Room village Panj Gragan, district Ludhiana	
500	Construction of a Janighar in village Rurki, tehsil Rajpura	1,000	Construction of Village Library Room, Kotla (Bet), district Ludhiana	
500	Repair, tubewell in Harijan Colony, village Machhali, tehsil Rajpura	1,000	Construction of Village Library Room, village Sherpur, Bet, district Ludhiana	
1,000	Construction of Harijan Janighar, vil- lage Lalru, tehsil Rajpura	1,000	Construction of Village Library Room, village Hambowal, district Ludhiana	
500	Ditto			
1,000	Construction of pucca streets, village Kheri Gujran, tehsil Rajpura	1,000	Construction of building for Nari Niketan, Jullundur	
2,000	For the construction of pucca streets, village Ajrawar, tehsil Rajpura	2,000	Construction of a College Building of Lajpat Rai Memorial College, Jagraon, district Ludhiana	

Original with;  
Punjab Vidhan Sabha  
Digitized by;  
Panjab Digital Library

3,100	For installation of tube-well for common use in village Babbal Pur, district Hissar
5,000	Construction of well around the school at Panjwar so that it would cover the Harijan colony and village abadi from view by the teachers and visitors of the School Village Panjwar tehsil Tarn Taran, district Amritsar
250	For purpose of equipment for Feroze Gandhi Memorial, Bal Vikas Kendra Kaithal, district Karnal
10,000	For purchase of land for extension of the school building of Haryana Public High School, Gohana
5,000	For construction of Backward Classes Hostel, Rohtak
1,000	For construction of Harijan Dharamsala village Nuran Khera
5,000	For construction of building of Haryana Harijan Balmik Nath Ashram, Rohtak
500	For Plastering of building of chaupal Dhanak Community Mohalla Brahmna Wala, Rohtak
5,000	For construction of additional accommodation for Chhotu Ram Dharamsala, Rohtak
2,500	For construction of school building (Bharat Tek School), Rohtak
5,000	For construction of Rasta from village Kulasi to village Kanonda, district Rohtak

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and designation of Minister	Amount placed at his/her disposal	Amount given in his/her own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1		3	4	5	6	7
			Rs.			
						Rs.
						500
						For repair to chaupal, Dehry Mohalla, Chamaran, Rohtak
						1,000
						For construction of chaupal of Bhangis in Ram Lia Para, Rohtak
				Total	48,950	
12	Smt. Om Prabha Jain, H.M.	60,000	5,000	For the construction of Swimming Pool at Jat Higher Secondary School, Kaithal, district Karnal	5,000	For construction of additional accommodation in Ludhiana Maternity Hospital, Ludhiana
			5,000	For installation of water hand pump in the abadi of Nayak Rajputs, Peoda, tehsil Kaithal, district Karnal		
			500	For construction of "Chabutra" on Balmiki Harijan well in Mulla patti, village and post office Kelram, district Sangrur		
		Total	6,000*			3,100
						For completion of Babra Vyayamshala and Gowshala Ga-Karan Tirath, Rohtak

\*Note Statement Printed as Supplied by Government.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(5) 51

1,000	For purchase of furniture and equipment for Haryana Public High School Gohana, district Rohtak
1,000	For holding of eye operation camp by Prantiya Arya Vir Dal, Karnal
251	For purchase of library books by Shri Krishan Nav Yuvak Mandal, Bahadurgarh, district Rohtak
1,100	For completion of building of Janta Dharamarth Ayurvedic Aushadhalyr outside Gur Mandi, Sonapat, district Rohtak
4,000	For completion of water works in Gand Vidya Mandir, Charkhi Dadri, district Mohindergarh
800	For levelling of Nehru park and Community Centre, village Mahchana, tehsil and district Gurgaon
1,000	For extension of the building of Middle School, Mani Karam, district Kulu
5,000	Construction and purchase of equipment for S. Patel Memorial College; Rajpura, district Patiala
5,000	Construction of building of Malwa College Bondi, tehsil Samrala, district Ludhiana
	For boring of well in village Ramshehr, tehsil Nalagarh, district Ambala
1,000	For extension of building of Coege Agriculture Kaul, district Karnal
500	For re-roofing of Primary School. Kishanpura, tehsil Nalagarh, district Ambala

## [Home and Development Minister]

Sl. No.	Name and designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
12—concl'd						
		Rs		Rs		

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(5)53

1,000	For construction of Janjghar in village Gotran Lahri		
1,000	For construction of a Janjghar, village Hayati Chak		
1,000	For construction of Panchayat Ghar in village Sultanpur	1,000	Repairs of Harijan well in village Khar-khara, district Hissar
1,000	For construction of Janjghar in village Anial	500	For Panchayat School equipment village Minka Minki, tehsil Ambala, district Ambala
1,000	For construction of Janjghar in village Sharaf Chak	500	Construction of Janjghar for Harijan Rampura Phul, district Bhatinda
1,000	For construction of a Janjghar in village Saidipur		
2,000	For construction of Community Hall in village Khunda	500	Construction of a Janjghar, village Galwatti, tehsil Nabha, district Patiala
500	For drainage works in village Paniar		
500	For institute equipment and library in Paniar	2,000	For construction of building at Nari Niketan, Jullundur
500	For Drainage works in village Gandhian		
1,000	For construction of a Janjghar in village Nangal Bhur		
1,000	For construction of a Panchayat Ghar in village Gharota		

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and Designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
Rs						
13—concl.						
				For construction of Janjghar in village Kiri Kurd		
		Rs 1,000				
		500		For construction of Janjghar for Harijan in village Chakval		
		500		For construction of Janjghar in village Sharif Chak	500	Water-Supply Scheme and Sanitation Kanti, district Mahendragarh
		500		For construction of Janjghar for Harijans in village Dhup Sari Jaswal	500	For construction of a Community Hall for Harijans in village Baloon, district Gurdaspur
		500		For construction of a Janjghar for Harijans in village Pumma		
		1,000		For drainage work in village Parmanand		
Total		35,000	22,000		9,600	
14	Shri Rattan Singh, M.A. H.A.	35,000	1,000	For Harijan Janjghar at Kannra Bet, tehsil Gar Shanker district Hoshiarpur	1,000	For Lt. Karam Singh Memorial Library Baji-khana, district Bhatinda

2,000	For school at village Chandpur Roorkee, tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur	2,500	Construction of a building of Kanya Vidyalaya Sahnewal district Ludhiana
1,000	For construction of Janjighar for Harijans at village Kaulgarh, tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur	1,100	Construction of a school building Gram Panchayat Middle School village Radiala, district Ambala
1,000	For construction of building of Panchayat Ghar at village Bagowal (Balachaur Block), tehsil Garhshankar		
Total		500	For furniture and books for the reading room, village Khori, tehsil Rewari district Gurgaon
		2,000	For purchase of Agricultural implements for the Panchayat Farm, Rauni, N.E.S. Block Doraha, district Ludhiana
		750	Construction of a building of Panchayat Ghar, village Agojar, district Kangra
		1,500	For the purchase of Science equipments and library books for Shri AS.D. Higher Secondary School, Narnaul
		1,000	For Harijan Janjighar at village Malewal, tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur
		500	For construction of Shri Jambhoo Jit Temple Well, at village Malewal, tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur
		1,000	For Harijan Janjighar at village Bihala, tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and designation of the Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
14—concl'd		Rs	Rs		Rs	
					1,500	For construction of building of the Panchayat Ghar at village Chandiani Khurd (Saroa Block), tehsil Garshankar, district Hoshiarpur
					1,000	Purchase of furniture for the Agricultural Block of the Private School Shri Gobind Singh Khalsa Labana Higher Secondary School, village Miani Urmartanda tehsil Dasuya district Hoshiarpur
					1,000	For construction of the building of the Public High School, village Talwara tehsil Dasuya, district Hoshiarpur
					500	For library at village Bihala, tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur
				Total	15,850	
15	Smt. Chandra Wati, D.M.E.S.	25,000	3,000	For the construction of School Building Arya Nagar, Charakhi Dabri, district Mohindergarh	500	Construction of School Building, Misriwala, district Bhatinda
			3,000	For the construction of School Building, Jitpura	1,000	For the development of the village Dispensary/Street/Library books, etc., village Sahawas, district Rohtak
			2,000	For the construction of boundary wall and room, etc., of the School, Kakroli Sardaran	2,000	For the construction of well for Harijan of village Gopalwas (Mohindergarh)
			1,500	For the construction of School Building Bond	2,500	For the Development of Panchayat Ghar, Jant (Mohindergarh)
			1,404	For the construction of School Building, Dhan		

WRITTEN ANSWERS      STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(5)57

Total	600	For the uniform of poor Harijan students in Badhra	1,500	For the construction of well in village Khatod (Mohindergharh)
	2,000	For College Building and other equipment in Charahi Dadri	501	To help the women league in their activities and for the setting up of an Industrial School, Yamunanagar (Ambala)
	13,504		3,495	For the uniforms of poor Harijan students. Consolidated sanction for Rs 3,495 was issued for this purpose Nawan, Badrai, Bhalothia, Sureht Kalan, Surehti Jakhal, Siampura, Bassi, Satnali, Nangal, Gopalwas
		Total	11,496	
16 Shri Gurmit Singh, D.M. D.I.	500	For construction of Janighar for Harijans in Burjan (Burj Sidhwan) district Ferozepur	500	For building of Feroze Gandhi Memorial Balvikas Kendra, Kaithal, district Karnal
	500	For construction of Janighar for Harijans in Tar Khanwala, district Ferozepur	500	For the building of rooms for Karyā Gurukul, Khanpur, tehsil Gohana district Rohtak
	500	For construction of Janighar for Harijans in alamwala (Ferozepur)		
	500	For construction of Janighar for Harijans in Khane-ki-dhab, district Ferozepur	500	For the installation of a pipe of water for village Dhaneta, district Kangra
	500	For construction of Janighar for Harijans in village Mohallan, district Ferozepur		
	500	For construction of Janighar for Harijans in Karam Patti	300	For the construction of a building of Guru Har Rai Higher Secondary School, Dasuya Kalan, district Jullundur

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and designation of the Minister	Amount placed at his disposal	For the purpose	Amount given out- side the consti- tuency	For the purpose
Rs					
Rs					
500	For construction of Janjghar for Harijans in Sakan wali	500	For the construction of village Pat from Bajuri Tika to Village Hastar village Bajuri, district Kangra	500	
500	For construction of Janjghar for Harijans in Ghamiara Khera	500	For the construction of a building for the village dispensary, village Jalwehra, district Hoshiarpur	500	
500	For construction of Janjghar for Harijans, Deon-Khera	500			
500	For construction of Janjghar for Mazbi Sikhs in Danewala	500			
500	For construction of Diggi for water for Harijans in Rathrian	500			
Total		5,500			
Rs					
500	For construction of Janjghar for Mazhbi Sikhs, Nahar Hasti, Dina, district Ferozepur	500			
500	For construction of Lt. Jatinder Singh Shaheed Stadium at village Khara, district Bhatinda	500			
500	For construction of Library building opening in memory of Shaheed Lt. Gurdev Singh, village Bhikhi district Bhatinda	500			
2,500	For construction of rooms for Middle School, village Totu, district Simla	2,500			
Total		..		7,000	

16—concl'd

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(5)59

17 Shri Gian Chand, D.M., I.H.	25,000	1,250	For improvement of school, i.e., addition of room as well as improvement in the present building, Village Rogra, tehsil Kandaghat, district Simla	500	For improvement of Jawahar Sarai, village Bihang, district Kulu
				500	For purchase of dramatic equipment etc., of Kangra Kala Kendra, Chandigarh
				350	Improvement of Sanitary conditions, etc., of the village Mullana, district Ambala
				1,000	Construction of more rooms of Boarding House of H/S Ram Sharma, district Ambala
				500	For construction of roofs of School building Jagat Sukh, district Kulu
				100	For Development of folk dance and purchase of equipment and clothes village Kargen, district Kulu
				1,500	Construction of one mile Kacha road to link with main road, village Baranda, district Kangra
				750	Construction of Bauli, village Bajuri, district Kangra
				500	Construction of roof of Panchayatghar constructed by Gram Panchayat, Anheh, village Chadhar, district Kangra
				750	Construction of Bauli in Kut village Bhater Khurd, tehsil Hamipur, district Kangra
				2,000	Construction of building for Ayurvedic Dispensary, Chagriani (Tapa Dhanet), tehsil Hamipur, district Kangra
				500	Construction of rooms for school building, village Ani, district Kulu
Total : 1250					

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1	:	3	4	5	6	7
					Rs	
					100	Repair and maintenance of road, village Sa-otri, district Kangra
					100	Repair and maintenance of road, village Daulatpur, district Kangra
					200	Repair and maintenance of road, village Balal, district Kangra
					1,000	Repairs and Maintenance of road, village Sunhi, tehsil and district Kangra
					100	Repairs and maintenance of road, village Kandi, tehsil and district Kangra
					500	Purchase of dramatic equipment for Sewa Samiti Higher Secondary School, Idgah, Road, Ambala Cantt
					1,000	Construction of new room for Middle School, Slol, district Kangra.
					1,000	Construction of rooms for Primary School, Salol, district Kangra.
					500	Construction of Playground, village Chadhar, tehsil Palampur, district Kangra
					1,000	Construction of new room for Middle School, Bhatoli, Phakorian, tehsil Dehra, district Kangra
					1,000	Construction of room for the High School, village Lanj, district Kangra

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(5) 61

1,000	Construction of library-cum-reading room, village Rajhoon, tehsil Palampur, district Kangra				
1,000	Construction of more rooms for Middle School, village Bhatoli Kalan, district Ambala				
2,500	Purchase of books for the library of Vaish College, Rohtak				
100	Purchase of Music equipment for Drama Party through Panchayat Samiti, village Brow, district Kulu				
		Total	..	20,050	
1,000	For purchase of medicines and instruments, etc., for use in free eye operation and curing eye diseases, Jagraon, district Ludhiana				
1,500	For constructing Part of building of the Gandhi Higher Secondary School, Mansa, district Bhatinda				
1,000	For construction of a Portion of building of Middle School, Bir Hodla Kalan, district Bhatinda				
1,000	For construction of Panchghar, Shadipur Momian, district Patiala				
500	For purchase of National-cum-International basket ball matches at Patiala				
500	For celebration of 300th birth Anniversary of Shri Guru Gobind Singh by a convention of representative of various bodies, association at Patiala				
1,000	For construction of well village Bhahri, Patiala Block, district Patiala				
250	For development works of the Project on the Samadhi ground of Shri Anand Mani Ji Maharaj, Patiala				
300	For meeting Printing charges of booklet of patriotic songs being published by Anjuman-e-Tarqui-e-Urdu--Patiala,				
1,000	For furniture, etc., in School Rukmani Devi, Modi Dastkari, Patiala				
1,500	For construction of building of Bal-miki Dharam Sabha School, Patiala				

18 Shri Ram Partap Garg, 25,000  
C.P.S.

## [Home and Development Minister]

Serial No.	Name and designation of Minister	Amount placed at his disposal	Amount given in his own constituency	For the purpose	Amount given outside the constituency	For the purpose
1	2	3	4	5	6	7
		Rs	Rs			
		250	For purchase of mat for the school children of Balmiki Dharam Sabha, Lahori Gate, Patiala		2,100	For construction of room in Shri Krishan Kumar High School, Rajpura Town, district Patiala
		1,500	For construction of school building of Bhartiya Bal Vidyala (Lower-Middle School run by Shri Brahman Sabha), Patiala		2,100	For purchase of furniture and construction of building for Public Girls High School, Rajpura
		2,000	For construction of Dharam Shala of Harijan in Dhilu-ki-Majri, Patiala		500	For purchase of equipment in connection with National Library started by National, Bassi Pathanan
<b>Total</b>	...	<u>8,300</u>				
					1,000	For constructing portion of building of Sanatan Dharam Industrial School for Women, Ambala Cantt.
					1,100	For constructing in the village via Panchkulla, Rajpura, district Patiala
					2,100	For construction of building of Mata ,Gujr College, Fatehgarh, Sahib tehsil, Sirhind Patiala
	<b>Total</b>			..	<u>13,900</u>	

**Postponement of Elections to the Zila Parishads, Hissar and Ambala**

**\*9230. Shri Mangal Sein, :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the dates fixed for holding elections to the Zila Parishads, Hissar and Ambala, during the years 1965 and 1966 together with the number of times and the reasons for which the said elections were postponed in each case ?

**Sardar Darbara Singh :** The required information is placed on the Table of the House.

Statement showing the dates fixed for holding elections of Zila Parishads, Hissar and Ambala during the years 1965-66 together with the reasons for which the said elections were postponed in each case.

**Hissar District**

1. 8th August, 1965 .. The Programme had to be cancelled for want of election of Chairman/Vice-Chairman of Panchayat Samiti, Sirsa which was staged by the High Court.
2. 20th August, 1965 .. The election of Chairman/Vice-Chairman of Panchayat Samiti, Sirsa had not been completed upto the fixed date and hence the programme had to be postponed.
3. 25th November, 1965 .. A fresh postponement was necessitated in view of the Emergency and with a view to ensure that the attention of the people should continue to be focussed on war efforts.
4. 11th January, 1966 .. Sub-Divisional Officer (Civil) Hissar who was appointed as Presiding Officer for the co-option of members fixed for 27th December, 1965 was transferred on 24th December, 1965. It was apprehended that the holding of elections by the new Sub-Divisional Officer (Civil) would involve a legal irregularity as his predecessor was appointed a Presiding Officer by name and not by designation. Hence the postponement.
5. 31st January, 1966 .. Co-option of Zila Parishad Members fixed for 16th January, 1966 was postponed due to State mournings on account of the death of Prime Minister.

**Ambala District**

1. 30th October 1965 .. Cooption of Members was fixed for 18th October, 1965. One Member could not be served with the notice of co-option being not available. The meeting had to be cancelled to avoid any complication.
2. 10th November, 1965 .. The postponement was made in view of the Emergency and with a view to ensure that the attention of the people should continue to be focussed on war efforts.
3. 17th January, 1966 .. The programmes was revised due to mourning falling the death of the Prime Minister.
4. 31st January, 1966 .. The elections were postponed, keeping in view the prevailing atmosphere in the district.
5. 12th February, 1966 .. Elections stayed by the Punjab High Court on a writ petition.

### Re-adjustment of Territorial Boundaries of Community Development Blocks

**\*8909. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the Government propose to re-adjust the territorial boundaries of the Community Development Blocks in the State ; if so, the reasons therefor and the time by which the re-adjustment is likely to be finalised ?

**Sardar Darbara Singh :** Yes. Wherever difficulties are experienced by the public either as the result of the Block being not geographically compact or any other incongruity, Government consider territorial re-adjustments. However, no time limit has been fixed for this process of delimitation.

### Panchayats which have not given Land to Harijans in Hissar District

**\*9270. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the number and names of the Panchayats in the Hissar District, block-wise, which have not so far given 1/3rd of Panchayat land to the Harijans in auction together with the action, if any, taken by the Government against them ?

**Sardar Darbara Singh :** There is no Panchayat in Hissar District which has not taken action in accordance with Rules concerning leases of Shamilat lands to the members of the Scheduled Castes. As such, question of taking action against any Panchayat does not arise.

### Community Hall at Behr, Tehsil Dehra, District Kangra

**\*9291. Thakur Mehar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether the Community Hall building at Kotla Behr Tehsil, Dehra, District Kangra has been completed ; if not, when it is likely to be completed ;
- (b) the estimated cost of the Hall referred to in part (a) above ;
- (c) the amount paid by the Union Government, Punjab, Government, Panchayat Samiti of the area and the local people separately, for the said Hall ;
- (d) whether any complaint regarding embezzlement of funds meant for the said Hall was received by the Government and an enquiry held in the matter ; if so, the result of the enquiry and the action taken thereon ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) No. It depends upon the Construction Committee.

(b) Estimated cost of the Project is Rs 9,315.

(c) (i) Contribution by Union Government	..	Nil.
(ii) Contribution by State Government	..	Rs 7,035
(iii) Contribution by Samiti	..	Nil.
(iv) Contribution by Local people	..	The Contribution of Rs 2,280 is promised by the People.

(d) The amount of Rs 33.25, for which there was not a valid receipt is being recovered from the ex-Sarpanch, Shri Rattan Chand.

**Mexican Wheat Seed**

**\*8863. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that Government have supplied wheat seed imported from Mexico to some farmers in the State if so, at what rate ;
- (b) whether it is also a fact that the Government have now realised that this Mexican wheat seed does not successfully germinate in India or Punjab ;
- (c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether Government intend to compensate the farmers who have sown the said seed at the instance of the Government ;
- (d) whether the Government carried out experiments with the said seed to find out the extent of its germination before it was supplied to the farmers, if so, the result of these experiments ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) (i) Yes.

(ii) It was supplied at the following rates on the advice of the Government of India :—

(i) Sonaro 64 at Rs 62 per bag of 50 Kilogram.

(ii) Lerma Rojo at Rs 58 per bag of 45 Kilogram.

In addition to the above price actual transportation charges from Bombay shipping to the destination station have also been charged.

(b) No. The germination of Mexican Wheat Seed is very satisfactory throughout the State. In very few cases, however, some farmers could not get good germination because they did not follow the instructions given by the district staff to them.

(c) As the percentage of germination of seed is as high as 80 per cent to 90 per cent in all except a very few cases, the question of compensation does not arise.

(d) Germination was tested and found satisfactory.

**Subsidy to Farmers for having installed Tube-wells**

**\*8865. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the total number of farmers who have installed Tube-wells since the Government announcement to grant a subsidy for the purpose and the number out of those who have been sanctioned Rs 750 each as subsidy.

**Sardar Darbara Singh :** Upto 31st December, 1965, 2,188 farmers have installed tube-wells ; but so far no subsidy has been given. The subsidy will be allowed to the eligible loanes by way of waiving off recovery of appropriate amounts of the loans, after the rest of the loans have been repaid.

**Sheep Breeding Farms**

**\*8912. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the number and names of the Sheep Breeding Farms so far established in the State together with the expenditure incurred on each ?

**Captain Rattan Singh** (State Minister for Animal Husbandry and Agriculture) : Two Sheep Breeding Farms—the Sheep Breeding Farm-cum-Experimental Station at Hissar and the Sheep Breeding Farm at Sainj in

[ Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture]

Kulu Valley—have been established and expenditure of Rs 3.54 lacs and Rs 2.24 lacs respectively, has been incurred so far.

### Complaint against the Secretary, Market Committee, Uklana in Hissar District

**\*9269. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a complaint against the Secretary, Market Committee, Uklana, in Hissar District is pending with the Department for the last few months, if so, the action, if any, taken thereon ;

(b) the contents of the complaint be laid on the Table of the House ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) The complaint was received last month which is being examined by the Secretary, State Agricultural Marketing Board, Chandigarh.

(b) The contents of the complaint (Annexure 'A') are laid on the table of the House. Annexure 'B' is the gist of allegations.

#### ANNEXURE 'A'

**विषय:—**अवकाश चौधरी देवा सिंह, सचिव, मार्किट कमेटी, उकलाना ।

**यादि:—**आप के कार्यालय पत्र नं० 42595, दिनांक 29 दिसम्बर, 1965 के सम्बन्ध में ।

इस के बारे में आप को विवरण में सूचित करूं कि चौधरी देवा सिंह, सचिव, मार्किट कमेटी, उकलाना दफ्तर से दिनांक 7 दिसम्बर, 1965 गैर हाज़िर था । और उसका दिनांक 7 दिसम्बर, 1965 को लगभग 1.30 बजे तार हिसार से आया मिला कि मेरा अवकाश स्वीकार किया जावे और सचिव बिना हैडक्वार्टर अवकाश लिया इस से पहले दिन कहीं चला गया जब उसे यहां से अवकाश ले कर जाना चाहिये था और इस का अवकाश न मंजूर किया था और इस की सूचना आप इस कार्यालय पत्र नं० 783, दिनांक 15 दिसम्बर, 1965 को आप को भेजी जा चुकी है ।

2. द्वारा सचिव दिनांक 21 दिसम्बर, 1965 को बिना अवकाश मांगे और स्वीकार करवाये कहीं चला गया और फिर वह दिनांक 24 दिसम्बर, 1965 तक वापिस नहीं आया और इस का तार आप को पहले दिनांक 24 दिसम्बर, 1965 को भेज दिया है ।

3. यह कि मण्डी प्रबन्धक बरवाला सब-यार्ड श्री राम भज ने यह रिपोर्ट की है कि चौधरी देवा सिंह, सचिव, मार्किट कमेटी, उकलाना ने एक पोल गैस टांगने का था वह ब्रेच दिया है और वह पैसा खुद खा गया है ।

4. यह कि मण्डी प्रबन्धक श्री आनन्द प्रकाश ने भी रिपोर्ट की है कि श्री देवा सिंह, सचिव, कार्यालय के कागजों पर भी मिसाल के तौर पर कम्पौंड के केसों पर जो मैं/प्रधान/ करता हूं हस्ताक्षर नहीं करता और यह रिपोर्ट साथ में भेजी जाती है । और इस का रबैया बड़ा गलत है ।

5. आप को और सूचित करें कि साबका कमेटी उकलाना ने अपने प्रस्ताव नं० 3, दिनांक 31 अक्टूबर, 1963 को सर्व सम्मति से पास किया था कि चौधरी देवा सिंह, सचिव, का काम तत्सलीबद्ध नहीं है। और सारा काम बकाया में पड़ा रहता है। और इस की तबदीली होनी बहुत जरूरी है। जिस की नकल साथ में है।

6. श्री सेला राम चपड़ासी-कम-चौकीदार ने रिपोर्ट की है कि चौधरी देवा सिंह सचिव इस से दफ्तर के समय तथा दफ्तर के बाद भी उन का सारा काम यानी पानी भरवाना, लकड़ी पाड़ना तथा कपड़े धुलवाना आदि करवाता है। और इस को हर समय दबाता रहता है। और उस की रिपोर्ट साथ भेजी जा रही है।

7. यह कि इस सचिव का गांव चार-पांच मील की दूरी पर केवल है। और यह हर समय पार्टीबाजी में बड़ा जोर से हिस्सा लेता रहता है। कमेटी के काम में कोई दिलचस्पी नहीं लेता।

8. आप को आप के कार्यालय सरकुलर नं० 38 दिनांक 9 अगस्त, 1965 के सम्बन्ध में सूचित करें कि सचिव चौधरी देवा सिंह इस कमेटी में लगभग 13 वर्ष से ही काम कर रहा है परन्तु आप का सरकुलर यह कहता है कि तीन वर्ष के बाद सचिव की तबदीली कर दी जाती है।

अतः आप से प्रार्थना है कि इस को यहां से तबदील कर के इस के खिलाफ इन्क्वायरी की जावे और मुनासिब ऐक्शन लिया जावे।

(हस्ताक्षर) .....

प्रधान,

मार्किट कमेटी, उकलाना, जिला हिसार।

नं० ....., दिनांक

#### ANNEXURE 'B'

Brief contents of the complaint dated the 1st January, made by the Chairman Market Committee, Uklana, district Hissar against Shri Deva Singh, Secretary, Market Committee, Uklana

- (1) Shri Deva Singh, Secretary, Market Committee, Uklana, remained absent from office on 7th December, 1965. However, he applied for leave from Hissar telegraphically on 7th December, 1965 at 1.30 p.m. without obtaining permission to leave the station.
- (2) Shri Deva Singh, Secretary, Market Committee, Uklana, remained absent from office for the period from 21st December, 1965 to 24th December, 1965 without any leave. The matter was reported to the State Agricultural Marketing Board on 24th December, 1965 by the Chairman Market Committee, Uklana.
- (3) Shri Ram Bhaj of Mandi Uklana, has reported that the said Secretary has sold the Gas Pole of the Sub Yard. Barwala and thus he has embezzled the money of the Market Committee.

## [Minister for Home and Development]

- (4) Shri Anand Parkash, has complained that Shri Deva Singh, Secretary, Market Committee did not sign on the compound cases and his behaviour is bad.
- (5) The Market Committee, Uklana vide its resolution No. 3 of 31st December, 1963 resolved that the work of Shri Deva Singh, Secretary, Market Committee, Uklana, is not upto the mark and as such, his transfer is quite necessary.
- (6) Shri Sela Ram, Peon-cum-Chowkidar of the Market Committee, Uklana, has complained that Shri Deva Singh, Secretary, Market Committee, Uklana, uses his services for his personal domestic affairs.
- (7) Shri Deva Singh, Secretary, Market Committee, Uklana, takes part in party politics and he does not pay full attention to his office work.
- (8) Shri Deva Singh, Secretary, Market Committee has been working or posted to the Market Committee, Uklana, for the last 13 years but it is against the policy of the State Agricultural Marketing Board, because in its circular No. 38, dated the 6th August, 1965, it has been laid down that a Secretary of Market Committee after his stay at a particular station for 3 years should be transferred.

## Applications for providing Diesel Engines for running Tube-wells

\*9330. Shri Roop Lal Mehta : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the total number of applicants in the State who applied for permission to use diesel Engines for running Tube-wells and the number of applications finalized, so far ;
- (b) the number of applicants from Gurgaon District who have started diesel Engines Tube-wells in response to the Government's appeal for grow more food campaign ?

Sardar Darbara Singh : (a) The information is being collected and will be supplied in due course.

(b) 233.

## POINTS OF ORDER

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आप का रूलिंग इस मामले में चाहता हूँ कि अगर कोई मैनबर इस हाउस में कहे कि डंडा चढ़ाया, क्या आप इन शब्दों को हाउस में तस्लीम करते हो। (विघ्न)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। कामरेड राम प्यारा ने एक दफा नहीं बल्कि दूसरी बार रिपीट किया कि डंडा चढ़ाया। मैं आप की रूलिंग चाहत हूँ कि हाउस को भी इस बात का पता लगना चाहिये कि किस ने डंडा चढ़ाया, कहाँ डंडा चढ़ाया और कैसे डंडा चढ़ाया।

श्री अध्यक्ष : पंडित चिरंजी लाल, आप बहुत एक्सपीरिएन्सड मैनबर हैं। यह प्वायंट आफ आर्डर आप ने गवर्नमेंट पर नहीं किया, कामरेड राम प्यारा पर किया है। क्योंकि यह शब्द कामरेड राम प्यारा ने इस्तेमाल किये हैं कई बार लफ्ज़ अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं नोटिस नहीं लेता। मुनासिब बात यह है कि पार्लियामेंटरी शब्द इस्तेमाल किये जाएं।

यह डंडा चढ़ाने वाली बात अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वक्त से सभी इम्प्रूव कर जाएंगे इस लिये मैं नोटिस नहीं लेता। यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं रहता।

(The hon. Member Pandit Chiranji Lal is a very experienced Member. He has raised this point of order not against the Government but against Comrade Ram Piara because these words were used by the latter. Very often the expressions used are not happy but I take no notice of them. The proper thing is that only parliamentary expressions should be used. 'Danda Charhana', is not a desirable expression. I think with the passage of time all will improve in the use of good language. That is why sometimes I overlook such things. This is no longer a point of order.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : जनाब, मेरी गुजरिश है कि मैं आप का रूलिंग चाहता हूँ कि क्या 'डंडा चढ़ाना' शब्द पार्लियामेंटरी है ? अगर नहीं तो फिर इस को विदड़ा करने के लिये क्यों नहीं कहा जाता ?

### QUESTIONS OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : There are two privilege motions.

एक प्रिविलिज मोशन डाक्टर बलदेव प्रकाश, श्री टन्डन और भौरा जी की तरफ से आई है। यह एक ही चीज़ के बारे में है। मोशन यह है।

(There are two Privilege Motions ; One is by Dr. Baldev Prakash and Shri Balram Ji Das Tandon and the other is by Com. Bhan Singh Bhaura. Both the questions of Privilege relate to one and the same subject. The motion reads as under) :—

"That the arrest of Comrade Ram Piara, M.L.A., under Section 420 by the Government is a serious breach of privilege of this august House. The verification done by Comrade Ram Piara, as alleged, was done for being a member of this House and due respect should have been shown by the Government. If somebody gets the verification done from a member of this House by giving false information, such a drastic action against the member is wholly undesirable. The matter should be referred to the Committee of Privileges for action."

Shri Mangal Sein : Certainly.

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : स्पीकर साहिब, यह जो मोशन हाउस के सामने प्रिविलिज मोशन के रूप में मेरी, टन्डन साहिब और भौरा साहिब की तरफ से पेश हुई है, बहुत ही अहम है। हाउस के मੈबरों को दिन में सैकड़ों कागज़ों पर दस्तखत करने पड़ते हैं। आप भी हाउस के मੈबर रहे हैं, अब भी हैं, आप को तो शायद अटेस्टेशन न करने पड़ते हों, मੈबरों को सुबह से शाम तक किसी को शैड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट, किसी को इन्कम का सर्टिफिकेट, किसी को लड़का स्कूल में दाखल करवाने का सर्टिफिकेट, किसी की शादी आ गई है इस के लिये, किसी को मकान बनाने के लिये सीमेंट का सर्टिफिकेट चाहिये, किसी के लड़का हुआ है उस के लिये खांड चाहिये, इन सारे कागज़ात पर मੈबरान को दस्तखत

[डा० बलदेव प्रकाश]

करने पड़ते हैं। कई बार ऐसी बात हो जाती है। एक बार सरदार जय इन्द्र सिंह से किसी ने शादी की तस्दीक करवा ली। उस ने बाद में शादी पोस्टपोन कर दी। मान लें कि किसी के लड़के की शादी है, कोई मौत हो जाने की वजह से वह पोस्टपोन हो जाती है तो क्या जिस एम. एल. ए. ने दस्तखत किये थे उस को फांसी चढ़ा दिया जाएगा? या तो आप यह वेरीफिकेशन का मामला ही खत्म करवा दें। एम. एल. ए. से ऐसे सर्टिफिकेट न लिये जाया करें। एक मैनबर को कई तरह की वेरीफिकेशन करनी पड़ती है। जनता का स्टैंडर्ड ऐसा हो चुका है कि लोग आ कर गुमराह करते हैं। और कई दफा गलत वेरीफिकेशन हो जाती है। सैकड़ों दस्तखत करने होते हैं कोई एक आध गलत भी हो जाता है उस में एम. एल. ए. का क्या दोष है उस को चार सौ बीस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। (आपोजीशन की तरफ से शेम, शेम की आवाजें) इस से बढ़ कर इस आगस्ट हाउस की वेइज्जती और क्या हो सकती है? और फिर इस सरकार के हाथों जो कि डेमोक्रेसी के लिये अपने आप को कस्टोडियन समझती है। इस मामले को डैफिनिटली प्रिविलिज कमेटी को देना चाहिये। यह मामला तय होना चाहिये कि सरकार को आगे के लिये इस सम्बन्ध में क्या रवैया अपनाना होगा।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : स्पीकर साहिब, दो तीन आनरेबल मैनबर साहिबान की तरफ से प्रिविलिज मोशन आई है। यह एक ऐसा मामला है जिस में इस हाउस के सारे मैनबरान इनवाल्ड हैं। आज कल हालत यह है गवर्नमण्ट ऑफिशियल्स इन-क्लूडिंग मैजिस्ट्रेट हर जगह पर एम. एल. ए. की तस्दीक मांगते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम पूछते थे कि मास्टर जी टट्टी कर आएँ, मास्टर जी पेशाब कर आएँ, मास्टर जी कपड़े धो आएँ, उसी तरह से अब होता है कि कि अगर कपड़े भी धोने हों तो एम. एल. ए. के दस्तखत करवाए जाते हैं। आफिसर्ज कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। पटवारी से भी वेरीफिकेशन करवाई जाती है, गिरदावर से भी तस्दीक करवाई जाती है तहसीलदार भी करता है लेकिन जिम्मेदारी सब एक एम. एल. ए. पर डाली जाती है। मुझे 1959 की बात याद है जब सरदार प्रताप सिंह जी हमारे मुख्य मंत्री होते थे। वे जाती तौर पर...

**Mr. Speaker :** The hon. Member should not please refer to the case. He may discuss the matter in a general way.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, I am not referring to the case.

अच्छा जी, मेरा मतलब केवल यह है कि आलरेडी उन की निवाजशें होती रही है और अब इस राज में, कामरेड राम किशन के राज में एम. एल. ए. पर निवाजशें की जाएं जरूर कहीं न कहीं विडिक्टिव स्पिरिट काम कर रही है। एम. एल. ए. की इज्जत आप के हाथों सिक्योर होनी चाहिए लेकिन हालत यह है कि टैक्नेकैलिटीज की आड़ में 419, 420 में उन के जलूस निकाले जाते हैं हमारे लिए इस हाउस में बैठना लानत है।

श्री यश पाल (जालन्धर शहर) : स्पीकर साहिब, मैं समझता हूँ कि यह बहुत बुनियादी सवाल है। न सिर्फ इस हाउस के मैनबर्ज के लिये ही बल्कि डेमोक्रेसी के लिये भी। जब कभी कोई शख्स एम. एल. ए. के पास तस्दीक करवाने के लिये आता है तो सिवाए इस के कि उस की ज़बान पर एतबार किया जाए और कोई साधन वेरीफाई करने का नहीं

ਹੋਤਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਿਤਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਸ਼ਯਕਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਰ ਏਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਏਮ. ਏਲ. ਏ. ਜ਼ ਕੋ ਤਸ਼ਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਗ਼ਲ਼ਸ਼ ਦੀ ਗਾਏਂ ਭੈਂਸ਼ ਕੇ ਲਿਯੇਂ ਕਿਤਨਾ ਦਾਨਾ ਚਾਹਿਯੇ। ਅਬ ਏਕ ਏਮ. ਏਲ. ਏ. ਕੋ ਯਹ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਤਨੀ ਗਾਏਂ ਭੈਂਸ਼ੇਂ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਜਾਕਰ ਭੀ ਤਸ਼ਦੀਕ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਏ ਤੋ ਕਯਾ ਪਤਾ ਭੀ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਪਨੀ ਗਾਏਂ ਭੈਂਸ਼ ਹੈਂ ਯਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋਸੀ ਦੀ ਹੈਂ ਵਹ ਤੋ ਗੁਡ ਫੇਥ ਮੇਂ ਤਸ਼ਦੀਕ ਕਰ ਦੇਂਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਦਨੀ ਦੀ ਤਸ਼ਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈਂ। ਅਬ ਬਤਾਏਯੋ ਕਿ ਕਿਸੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਠੀਕ ਇਨਕਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਤਾ, ਏਕ ਏਮ. ਏਲ. ਏ. ਕੈਸੇ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸਹੀ ਆਸ਼ਦਨ ਹੈ। ਵਹ ਤੋ ਇਨ ਗੁਡ ਫੇਥ ਤਸ਼ਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਤਕ ਯਹ ਬਾਤ ਸ਼ਾਬਤ ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੀ ਏਮ. ਏਲ. ਏ. ਨੇ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕਰ ਬੇੜਮਾਨੀ ਸੇ ਕਾਮ ਲਿਯਾ ਤਸ਼ਦੀਕ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੋ ਉਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਯਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਨੀ ਚਾਹਿਯੇ। ਯਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਸੁਤਾਲਾ ਕੀਯਾ ਗਯਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਯਾ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਯੇ ਤਾਕਿ ਕਤਰੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਯਾ ਜਾਏ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਤਰ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ਼ ਮੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਐਨਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਐਪ੍ਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ.....

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਇਸ ਸਪੇਸ਼ਿਫਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰੋ। (The hon. Member, Baboo Bachan Singh need not refer to this case. It will not be desirable to do so because it is *Sub judice*, He may generally discuss the rights of the Members but he should not refer to this specific case.)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੋਵਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼, ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੂਰਲ ਏਗੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਪਾਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੈਸ ਆਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ; ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ):** ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪਰਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਨੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਇਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਮਾਕਰੇਸੀ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰੋਕ ਪਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਡੀਮਾਰੇਲਾਇਜ਼ਡ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਖਵਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਓ।

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਫਰਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਰੁਖ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲੀਸ ਇਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ on its own arrest ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਜਗਰਾਉਂ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ.ਜ਼ ਵਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤਦ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨਸਟੀਚੂਏਂਸੀ ਵਿਚ ਗਿਆ .....

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰੋ (The hon. Member need not refer to this particular case).

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਅਤੇ ਡਿਮੈਰਿਟਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇਥੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੂਏਂਸੀ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿਚ ਐਡਵਰਟਿਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਲੈੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਦੇ ਵਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦ ਨੀਅਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਪੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤਮਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਲੈੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਚੁਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਡਿਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਿਵੇਲੇਜਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਰਾਜ ਟਾਂਡਨ (ਅਸ੍ਰਮਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਸ਼ਚਿਮ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੀ ਬਿਨਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ ਸਭ ਦੀ ਅਚਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਏਕਾਧੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਏਕਾਧੀ ਦੋ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਰ ਅਨਜਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਨ ਕਰਦੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ

[श्री बलराम जी दास टंडन]

ने भी, जब कि वह मैम्बर थे पिछले दस बारह सालों में कोई रांग सर्टिफिकेशन कर दी हो। ऐसे केसिज निकल आए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह जो तस्दीक वगैरा का काम है यह मैम्बर साहिबान इन गुड फेथ करते हैं। हर रोज़ उन के सामने कितने तरह के कागज़ात आते हैं और अगर मैं मुबालगा नहीं करता तो दिन में उन्हें सौ सौ कागज़ों पर दस्तखत करने पड़ते हैं। इस लिये केवल इसी बिना पर मैम्बर पर चार सौ बीस का केस बनाना मैं समझता हूँ कि निहायत गुमराहकुन, गलत और निहायत गिरी हुई बात है। इस लिये मैं समझता हूँ कि यह मामला हाउस के प्रिविलेज का है कि अगर एक मैम्बर अपने लेजिस्लेटर होने की हैसियत से इन गुड फेथ कोई तस्दीक करता है तो उस को उस बिना पर अरैस्ट कर लिया जाए और उस पर चार सौ बीस का केस बनाया जाए। यह बात हाउस के प्रिविलेज के अग्रेस्ट है। लिहाजा यह मामला प्रिविलेजिज कमेटी को सौंपा जाना चाहिए ताकि इस की सभी पहलुओं से तहकीकात की जा सके और मुनासिब ऐक्शन लिया जा सके।

**श्री मंगल सेन :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहिब, मैं आप से इस बात पर रुलिंग चाहता हूँ कि आप ने बजा फरमाया है कि जैसे कि कन्वैन्शन चली आ रही है कि जो मामला पुलिस में चला जाए.....

**श्री अध्यक्ष :** क्या यह आप का प्वायंट आफ आर्डर है ? (Is this the point of order of the hon. Member ?)

**श्री मंगल सेन :** हां जी, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर ही बोल रहा हूँ और एक प्वायंट पर आप की रुलिंग चाहता हूँ। आज तक की कन्वैन्शंस के मुताबिक आप यही कहते हैं कि जो मामला सब जूडिस हो, पुलिस में चला जाए वह डिस्कस नहीं किया जा सकता। अब यह मामला ऐसा है कि आई. जी. पुलिस ने जानबूझ कर कामरेड राम प्यारा को गिरफ्तार करवाया है.... मैं इस बात पर आप से रोशनी चाहूंगा, आप की रुलिंग चाहूंगा.....

**Mr. Speaker :** Please take your seat. It is no Point of Order.

**कामरेड भान सिंह डोरा (पूरी ऐस. सी.):** सपीकर साहिब, मैं इस मॉशन विच दे गॉलं कहीआं सन। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, "to the best of my knowledge." ਜਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦਾ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਕੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕੇ।

**ਚੌਥਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਕਾ ਧਰੁ ਜੌ ਮਸਲਾ ਆਜ਼ ਹਾਤਸ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਆਯਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ ਕਹੂੰ ਕਿ ਜਨਤਨਤਰ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਮ. ਏਲ. ਏ. ਜਨਤਾ ਕਾ ਨੁਮਾਯੰਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਰ ਇਸ ਹੈਸਿਯਤ ਮੇਂ ਜਨਤਾ ਤਸ ਸੇ ਅਪਨਾ ਕਾਮ ਲੇਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਕਾ ਆਦਮੀ ਅਪਨੇ ਨੁਮਾਯੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆਤਾ ਹੈ ਆਰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਆਰ ਮੈਂ ਤਸ ਪਰ ਸਕਾਨ ਬਨਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ. . . .

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਯਕਸ਼ :** ਥੋੜੇ ਮੇਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਹੋ. . . (The hon. Member may please try to be brief.)

**ਚੌਥਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ :** ਵਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਸਕਾਨ ਬਨਾਨਾ ਹੈ ਆਰ ਏਮ. ਏਲ. ਏ. ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਯੋਂਕਿ ਵਹ ਜਨਤਾ ਕਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਆਰ ਤਨ ਕਾ ਨੁਮਾਯੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਤਸ ਕੋ ਅਪਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਂ ਲੇਤੀ ਹੈ, ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਂ ਲੇਤੀ ਹੈ, ਏਮ. ਏਲ. ਏ. ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਸਗਰ ਹੋਤਾ ਕਯਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਏਕ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਥਾ। ਵਹ ਅਪਨੇ ਸੁਖਾਲਿਫੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ. . . .

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਯਕਸ਼ :** ਧਰੁ ਆਪ ਕਯਾ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਲਗ ਗਏ ਹੈਂ। (The hon. Member has gone off the track. What has he started saying?)

**ਚੌਥਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ :** ਤਨਹੀਂ ਅਪਨੀ ਤਾਕਤ ਕੇ ਬਲਕੂਤੇ ਪਰ ਅਪਨੇ ਅਫਸਰੋਂ ਸੇ ਨਾਜਾਯਜ਼ ਕਾਮ ਕਰਵਾਏ, ਅਪਨੇ ਸੁਖਾਲਿਫੀ ਕੋ ਦਬਾਯਾ। ਧਰੁ ਜੌ ਰਾਮ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਧਰੁ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਾਧਰ ਆਰ ਨਾਅਰਹਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ (ਕਿਥਨ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ ਜੌ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੇ ਏਮ. ਏਲ. ਏ. ਹੈਂ ਅਗਰ ਵਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਇਸ ਕੇ ਅਫਸਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਤਠਾਤੇ ਹੈਂ ਤੋ ਤਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਨਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ):** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 420 ਬਣੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੌਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਲੀਸ ਅਫਸਰ ਮੈਲਿਸ ਕਰਕੇ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਸੀਉਂ ਦਫਾ ਕਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਪਬਲਿਕਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਲਿਸ ਜਾਂ ਮੋਟਿਵ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੇਫਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਸੇਫਗਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਗਰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੀਫ

## [ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਮਨਿਸਟਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਲਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੁਲਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਗਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕੁਲਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ।

ਹੁਣ ਚੁੰਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੇਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਦਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਰੀਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਕੌਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ (ਧਾਰੀਵਾਲ):** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਇਕ ਦਫਾ 197 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਗਜੇਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜੱਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫਾ 197 ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਉਸ ਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰੇ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਵੇ। (ਤਾੜੀਆਂ)

**ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸ਼ੋ ਦੇਵੀ (ਜਗਾਬਰੀ):** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ ਕਦ ਮੈਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਤੀ ਬੜਾ ਟਾਝ੍ਹਾ ਹੁਆ। 1940 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਸ ਲੋਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਂ ਥੇ। ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਬੜੀ ਖਾਰੀ ਏਂਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਥੀ। ਆਯਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕਹ ਏਂਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਪਾਰ ਮਛਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੋ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ। ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਥੀ ਕਿ ਸੁਝੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਆ ਜਾਏ। 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਬਰ ਉਸ ਏਂਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖਤੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਕਾਕਜੂਫ ਡੇਝ ਦਿਨ ਲਗ ਗਯਾ। ਜਬ ਤਕ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੋ ਝੁਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਲੇ ਲੀ ਗਏ ਸੁਝੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨ ਕੀਆ ਗਯਾ। ਆਜ ਕਦੇ ਦੁਖ ਸੋ ਕਹੁਨਾ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਏਸ. ਏਲ. ਏ. ਕਸ ਸੇ ਕਸ ਏਕ ਲਾਖ ਝਨਸਾਨੀ ਕਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਰ ਹੁਸ ਸਬ ਮੈਂਬਰ ਆਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਹਾਂ ਪਰ ਲੋਗੀ ਕੇ

प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। मैं आप की मारफत चीफ मिनिस्टर साहिब से बड़े अदब से कहूंगी कि यह एक बहुत बुरी बात है। इस तरह कामरेड राम प्यारा का गिरफ्तार किया जाना तमाम मੈम्बरों की हक्क है। (तालियां)

इतनी बड़ी बात हो जाए कि असैम्बली के एक आनरेबल मੈम्बर को पकड़ा जाए और सी. एम. साहिब को और होम मिनिस्टर साहिब को पता न हो। यहां पर किस्म किस्म की बातें आती हैं और इस तरह की बातों को हम लोग बरदाश्त नहीं करेंगे और किसी को भी बरदाश्त नहीं करनी चाहिए (प्रशंसा)

11.00 a.m.

**सरदार लडमट सिंघ गिल :** पर, घीघी जी, ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

**सरदार दिलबाग सिंघ (ਬੰਗਾ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਡੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤੇ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਨੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਟ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤੁਅਲਕਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

**मुख्य मन्त्री ( श्री राम किशन) :** स्पीकर साहिब, मुझे इस बात की ख़ुशी है कि आज इस हाउस में एम. एल. ए. के इख्तियारात और उनकी इज्जत का सवाल यहां पर उठाया गया है और यह सवाल अपोजीशन के मੈम्बरों की तरफ से उठाया गया है। मैं आपकी विसातत से स्पीकर साहिब, यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इस हाउस में इलैक्टिक रिप्रैजेंटेटिव का ताल्लुक है उनकी इज्जत और मान करना हमारा सब का फर्ज है और मैं तो खुद इस बात का और इस कायदा का कायल हूं और इसी जाबते को मानता हूं। कि मैं खुद भी एम. एल. ए. साहिबान की इज्जत करूं और इज्जत करवाऊं (प्रशंसा) मैं ने, स्पीकर साहिब, एक सर्कुलर जारी किया था कि किसी एम. एल. ए. या एम. एल. सी. या किसी एम. पी. के खिलाफ पंजाब में कार्रवाई तब तक न की जाए जब तक कि उस बात को मेरे नोटिस में न लाया जाए। लेकिन, स्पीकर साहिब, आपको याद होगा कि इस हाउस में अन्दर ही इन मੈम्बर साहिबान की तरफ से जिन्होंने ने आज बहस में हिस्सा लिया है मेरे ऊपर इस बात के अटैक किए गए थे कि यह सर्कुलर इस लिये जारी किया गया है कि सरकार किसी मੈम्बर को प्रोटेक्शन देना चाहती है। मैं स्पीकर साहिब, इस बात को मानता हूं कि कोई भी एम. एल. ए. कानून से बालातार नहीं हो सकता लेकिन सर्कुलर तो इस लिये जारी किया गया था कि कोई सरकार की अथॉरिटी या सरकारी मशीनरी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल न करे। कोई यह न समझे कि उसके खिलाफ

[ मुख्य मंत्री ]

किसी बुग्ज की वजह से या किसी के कहने पर वहां की डिस्ट्रिक्ट अथारिटी ने आवाज उठाने पर कोई कार्रवाई की है या कर रही है। तो जब इस तरह की बातें इस हाउस में कही गईं तो मैं ने चीफ सैक्रेटरी से कहा कि मेरे इस सर्कुलर से शायद यह समझा जा रहा है कि मैं सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में दखल दे रहा हूं। क्योंकि मैं किसी किस्म का दखल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देना चाहता, इस लिये इस सर्कुलर को मनसूख किया जाए। और आज हाउस यह चाहता है कि इस तरह का कोई प्रबन्ध होना चाहिए। एक वक्त में तो एक प्वायंट आफ व्यू से बात कर दी जाती है और दूसरे वक्त किसी और ही प्वायंट आफ व्यू को यहां पर पेश कर दिया जाता है। इस लिये अगर आज किसी चीज को ठीक समझा जाए तो कल भी उस चीज को ला के मुताबिक और कायदे के मुताबिक ठीक समझना होगा। जहां तक अपोजीशन के लीडर का सम्बन्ध है और दूसरे ग्रुप लीडर बैठे हैं उन के साथ हम भी बैठ कर इस बात पर गौर कर सकते हैं कि आया उस सर्कुलर को फिर से रिवाइव किया जाए और अगर उसको दोबारा जारी किया जाए तो किस शकल में जारी किया जाए। मैंने शुरू में ही कहा है कि जो भी एम. एल.एज. हैं या एम. एल.सीज. हैं और लोगों के इलेक्ट्रिक रिप्रेजेन्टेटिव हैं हमारा फर्ज है कि उनकी रिस्पैक्ट की जाए। मैंने पहली और दो फरवरी को जो डी.सीज. की कानफ्रेंस हुई थी उस में जो ऐंड्रैस दिया था उसको आप देखें मैंने उस ऐंड्रैस में एक पहरा इस बात को दिया है कि अपने इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज हैं वह मैम्बर साहिबान को पूरी रिस्पैक्ट दें। दूसरे, जहां पर कामरेड राम प्यारा का ताल्लुक है मैं इस केस को मंगवाऊंगा और इसको एग्जामिन करूंगा और अगर किसी पुलिस के कर्मचारी ने किसी मैलिस की वजह से इस बात को किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा फर्ज है। मैं इस बात का यकीन हाऊस को दिलाना चाहता हूं। तीसरी बात यह है कि इस हाऊस के चार मैम्बर साहिबान हैं जिन में से दो अपोजीशन के मैम्बरान में से भी हैं और दो इस तरफ के बेंचों पर बैठने वाले हैं जिन के बारे में पता चला है कि उन्होंने ने अपने इख्तियारात का नाजाइज इस्तेमाल किया है। उन्होंने मकानात के लिये कर्ज लिये लेकिन न तो पता है कि मकान कहां पर है, मकान की जमीन कहां पर ली गई और कुछ पता ही नहीं मालूम देता। मेरे नोटिस में यह फाइलें लाई गईं पर मैंने आज तक उन केसों के अन्दर कार्रवाई नहीं की। यहां पर एक आनरेडल मैम्बर ने जिस भाषा में मेरे मुतालिक बातें अभी कही हैं मैं उसी भाषा में जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन, स्पीकर साहिब, और लीडर आफ दी अपोजीशन को कानफीडेंस में ले सकता हूं कि किस तरह की बातें नोटिस में लाई गई हैं। सरकारी फंडज का नाजाइज इस्तेमाल किया गया है। और कर्ज लेकर पता नहीं क्या किया गया है। यह सब बातें हैं। इस तरफ तो आप मैम्बरान साहिबान कहते हैं कि सरकार का जो रुपया है इसको आप के पास अमानत रखा गया है और मुझे आपकी तरफ से ह्दायत की जाती है कि इस अमानत में ख्यानत न की जाए और मैं अपने फर्ज को पूरा करूं कि अमानत में ख्यानत न हो (प्रशंसा) मैं यह देखना चाहता हूं कि एक एक पैसे का जाइज इस्तेमाल हो। मुझे आप ने इस स्टेट का एक प्रथम सेवक बनाया है और मेरा फर्ज है कि मैं इस सारी चीज को देखूं। और अगर कहीं पर सरकार के पैसे का नाजाइज इस्तेमाल हो रहा हो तो आप ही गाइड करें कि क्या मैं कोई कार्रवाई ऐसे एम. एल. एज. के खिलाफ करूं या न करूं।

आवाजें : जरूर, जरूर।

**मुख्य मन्त्री :** मैं किसी मैम्बर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस तरह के केस में पास आए हैं कि जहाँ पर सैंकड़ों मन खांड का गवन हुआ। इस तरह की और भी कन्ट्रोल्ड आइटम्ज़ हैं, मैं ने इन केसों को रोक रखा है और डिस्ट्रिक्ट अथारेटीज़ को इस सम्बन्ध में इन्स्ट्रक्शन दी हैं कि किसी एम. एल. ए. या एम. एल. सी. के विरुद्ध कोई कार्रवाई मेरे नोटिस में लाने के बाद की जाए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप मैम्बरान ने यह सवाल उठाया है। आप जो भी फैसला पूरे सोच विचार के बाद यूनानीमसली करेंगे उस के मुताबिक ही मैं कार्रवाई करूंगा (प्रशंसा) इस लिये मैं आप से बड़े अदब के साथ और नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप की और मेरी इज्जत सांझी है और इस में किसी तरह के पालेटिकस का दखल नहीं। हमारा सब का फर्ज है कि हम आपस में हरेक की इज्जत करें। जब सरकार फण्डज अलाट करती है और उसकी वसूली का सवाल आता है तो कायदा और रूल के मुताबिक वसूली ना हो सके पता और जगह के बारे में भी जानकारी न मिल सके और फिर हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उस के सामने भी सवाल आए और फिर कैबिनेट में इस तरह की बात आए तो गौर जरूर करना पड़ता है कि कार्रवाई किस ढंग से की जाए। इस लिये मैं अदब से दरखास्त करूंगा कि इन तमाम पहलुओं पर पूरा विचार किया जाए और जो आप चाहेंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सब को यकीन दिलाता हूँ कि मैं सब मैम्बर साहिबान की रिस्पेक्ट करता हूँ और करनी चाहिए।

इस मुआमला पर जहाँ तक गवर्नमेंट का ऐक्शन लेने का ताल्लुक है हम अभी विचार कर रहे हैं। इस लिये कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पास अभी एक और रिपोर्ट चार एम. एल. एज. के खिलाफ आई है। मैं समझता हूँ कि बजाये इसके कि फरदर ऐक्शन लेने के लिये कोई कदम उठाए जाएं। मैं ने इंडीविजुअल्ज़ को कान्फीडेंशल लैटर लिखा है, इसलिये कि वह आखिर इलैक्टड मैम्बरज़ हैं लाखों को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कोई ऐसी बात न हो जाये जिस से उन का अपमान हो जाए। मैं ने उन एक दो मैम्बरान के खिलाफ भी ऐक्शन लेना मुनासिब ना समझा, हालांकि उन के मुताल्लिक वह बात तसदीक भी हो गई थी। यह सब कुछ होते हुए भी मैं ने उनको एक कान्फीडेंशल लैटर लिखा। मैं यह भी जानता हूँ कि अगर हम में से चन्द एक पर भी अगर कोई बुरी राय बनती है तो यह एक निहायत ही ना मुनासिब सी बात होगी और इसका नतीजा यह भी लाज़मी है कि हम कौल व फैल से जो हमारे जिम्मे डियूटीज़ हैं उन को सही तरीका से सरअंजाम नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट अथारेटीज़ में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर हमारा वकार ज्यादा से ज्यादा बढ़े तभी हम अपने फरायज़ अदा कर पाएंगे और रूज़ ऐंड रेगुलैशन्ज़ के मुताबिक इसको अमली जामा पहना सकेंगे। मगर मैं देखता हूँ कि इस रास्ता पर चलने से बहुत सी अड़चने पैदा होती नज़र आती हैं। यहाँ पर कामरेड राम प्यारा के केस का भी जिक्र आया। आप यकीन रखें मैं इस केस को मंगवाऊंगा अगर किसी ने इसको बुरे इरादे से शिकायत करवाई है तो उस को कड़ी सज़ा दी जाएगी। हम रूज़ के मुताबिक जस्टिस देने की हर हालत में कोशिश करेंगे। एम. एल. एज. को पूरी रिस्पेक्ट हो हम खुद ऐसा चाहते हैं। मगर असल रिस्पेक्ट इनके अपने कौलो फैल से ही होगी। लोगों को भी इन्हें विश्वास में लाना होगा कि यह इतने बड़े इलाका को रिप्रेजेंट करते हैं, उन की नुमायंदगी करते हैं इन की वैरीफीकेशन से अक्सर बहुत से काम होते हैं, कई दफा किसी मुआमले की इनसे गलत तसदीक भी हो सकती है। गवर्नमेंट के सामने ऐसे केसिज़ आए हैं जिन से जाहिर होता है कि इन्होंने अपने इख्तयारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया।

[मुख्य मन्त्री]

जब इस तरह की शिकायात आती है तो गवर्नमेंट को तहकीकात करनी ही पड़ती है। ऐसी बातों पर हमें भी दुख होता है। इन सब बातों को समझते हुए हमें चाहिए कि हम ऐसी रवायात को कायम करें जिस से सरकार का काम ऐफीशेंटली चले।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रिविलेज मोशन को अभी पेंडिंग रखता हू। इस मुआमले को मैं लीडर आफ दी हाउस से और वेरियस ग्रुप्स के लीडर्स से मिलकर हल करने की कोशिश करूंगा। अब तक की जो डिस्कशन इस मुआमले पर चली इसमें दो बातें इन्वाल्व्ड हैं। एक तो यह कि लैजिस्लेटर्स के कहां तक राइट्स हैं और अगर कोई ऐसी बात थोड़ी बहुत इधर उधर की हो भी जाए तो कहां तक उसे मैलाफाइड कहा जा सकता है, इस के मुताल्लिक अगर गवर्नमेंट कोई पालिसी एडाप्ट करे तो कहां तक करे? दूसरी बात है कोड आफ कंडक्ट की। पिछले दिनों मैं ने कोड आफ कंडक्ट के मुताल्लिक तो इस हाउस में भी जिक्र किया था कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिये यह तरीका अख्तियार किया जा सकता है कि कोई मੈम्बर इसके लिये इस हाउस में मੈम्बर्स का कोड आफ कंडक्ट बनाने के लिये प्रस्ताव ले आये जिस के जरिए से ऐसी कोई कमेटी बनाई जा सके या आप इस के लिये अख्तियारात मेरे पर ही छोड़ दें। मगर अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव वावजूद मेरे कहने के किया नहीं गया। इस बात को सब मानते हैं कि मੈम्बर्स के मुआमला में हर काम में नेक नीयती होनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हरसमैट हरगिज नहीं होनी चाहिए। यह बातें मैं ने आपके सामने इस लिये रखी हैं ताकि किसी न किसी नतीजा पर पहुंचा जा सके।

(For the time being, I keep this Privilege Motion pending. I shall try to resolve this matter in consultation with the Leader of the House and various group leaders. So far as the discussion raised on this matter is concerned, there are two things involved in it. One of them is the scope of rights of the Legislators and if any such like thing happens how far it can be termed as *malafide* and the policy which should be adopted by the Government in regard to that. The Second thing relates to Code of Conduct. Some time back, I referred to Code of Conduct in this House and suggested that if the Members so desire, any Member could move a motion for framing the Code of Conduct for Members of this House on the basis of which a committee may be formed or those powers may be delegated by you to me. But inspite of my submission no such motion has been brought forward. There are no two opinions about it that there should be a clear conscience about every matter relating to the Members and their should be absolutely no harassment by the Government. I have placed my points of view before you so that we may be able to arrive at some decision.)

श्रीमती ज़न्नो देवी : मैं आप की मारफत यह कहना चाहती हूं कि जो चार शख्स बेईमान साबत हो चुके हैं, सरकार उनको फोरन पकड़े।

कामरेड घासू सिंघ भासटर : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੁਧ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ .....

**ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਆਮਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ (*Interruption*) ਜਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿਉ।

This matter will be taken up by the House Committee. (The hon. Member is an experienced Member. This matter relates to the House Committee. Such small matters can not be resolved in the House. (*Interruptions*) This Committee has been constituted for this purpose. He should report this complaint to this committee—which will take up this matter.)

### CALL ATTENTION NOTICES

**ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਏਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਥੀ ਜਿਸ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮੀ ਏਕ ਹਰਿਜਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਾ ਗਏ ਹੈ। ਏਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ. . . .

**Mr Speaker :** Please . . . . . (*Interruptions*)

**ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਕੀ ਲਾਸ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗਈ. . . .

**Mr. Speaker :** The hon. Member may please take his seat.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Mr. Speaker, Sir, Shri Jagan Nath was saying something just now. From that I conclude that there was some murder in the custody of the police. . . . .

**Mr. Speaker :** May be.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Then, Sir, this is something very serious. If the matter is not *sub-judice*, if the case has not been registered and the man has been done away with in the police custody, then. . . . .

**Mr. Speaker :** The hon. Member may please take his seat.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** I will positively abide by your order, Sir. But. . . . .

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਨੇ ਪਹਲੇ ਭੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਏ ਥਾ ਅਭੀ ਤੋ ਗਵਰਨਰ ਕੇ ਏਡ੍ਰੈਸ ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਦ ਬਜਟ ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਰ ਭੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ ਪਰ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਮਲਾ ਕੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਏ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਐਰ ਬਾਤਾਂ ਮੇਂ ਭੀ ਇਸ ਮੁਆਮਲਾ ਕੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਏ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਏਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਂ ਕਾਲ ਏਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਯਾ ਏਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਕੋ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਜਾਤਾ। ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬ ਭੀ ਮੌਕਾ ਹੋ ਉਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਹ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਭੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਐਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਦ ਅਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੇ ਕਰ ਆਏਂਗੇ ਤੋ ਮੈਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਜਾਨੇ ਕੋ ਤੈਧਾਰ ਹੂੰ। ਜੋ ਕਾਲ ਏਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਅਬ ਭੀ ਆਈ ਹੈ ਵਹ ਏਡਮਿਟ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜ ਦੀ ਜਾਏਂਗੀ ਫਾਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ। (The hon. Members may please listen. I state dearlier also that the discussion of the Governor's Address was still going on and this would be followed by the general discussion of the Budget. Besides this, several Demands for Grants will be discussed. This matter can be referred to during these discussions. So, when reference to this matter is possible on such occasions, an Adjournment Motion or a Call Attention Motion

[Mr. Speaker]

is not permissible under the circumstances. The hon. Member may, therefore refer to this matter whenever he finds an opportunity to speak during the general discussion.

I also observed the other day that if the Government failed to reply to a point raised by an hon. Member during the general discussion, and if the latter gave fresh notice of the motion on that subject, I would consider it. However, I am prepared to go to this length that any Call Attention Notice received by me, though, it is not admitted, yet the same will be forwarded to Government for consideration.)

**Pandit Chiranaji Lal Sharma :** Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of Order. Mr. Speaker, you have been pleased to remark just now that the hon. Members have ample opportunity to give expression to their views on the Governor's Address and on the general discussion of the Budget. But, Sir, if there is a matter of urgent public importance and if a man is said to have been murdered in the Police Custody, how long shall we wait ? After all everybody....

**श्री अध्यक्ष :** अगर काल अटेंशन मोशन आ जाय और एडमिट हो जाए तो गवर्नमेंट का जवाब 10 दिन के बाद आएगा तो फिर क्या होगा ? (If the Call Attention Notice is received and admitted and Government's reply is also received after ten days, then how far will it serve the purpose ?)

**Pandit Chiranaji Lal Sharma :** Sir, when the allegations are initiated, why should not the case be registered against the official concerned ?

**Mr. Speaker :** I shall send a copy of this motion to Government.

**पंडित जिरंजी लाल शर्मा :** स्पीकर साहिब, यहां कल 50 आदमी हिसार ज़िले घे आए। जिस शख्स का लड़का कतल हुआ है वह अंधा है। आप काल अटेंशन एडमिट करें और गवर्नमेंट से पूछें।

**Mr. Speaker ;** I am sorry. The hon. Member should please resume his seat. I am prepared to discuss the matter with the various group leaders in the House.

**कामरेड राम प्यारा :** मिस्टर स्पीकर, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जजमेंट्स आई हुई हैं कि आदमी पुलिस की कस्टडी में मरा। प्रेशर डाल कर मामला दबाया गया। पुलिस कस्टडी में आदमी मरा है। इतनी दरखास्तें हैं। लोकल स्टाफ ने कुछ नहीं किया। हायर अथारिटीज इन्क्यूजिंग होम मिनिस्टर के नोटिस में कोई चीज आई जाती है, रिकार्ड में हैं, मगर कुछ नहीं होता। कतल वाला मामला गैर जरूरी समझते हैं। मैं ने सैंटर को लिखा। जसैंटरल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर लिखते हैं कि करनाल जिला में अनप्रेसीडेंट मरडज हैं। क्योंकि बजट तो पहली तारीख को पेश होगा इसलिये या एडजर्नमेंट मोशन और काल अटेंशन मोशन का होना जरूरी है ताकि गपुलिस और गवर्नमेंट का शस हो।

**Mr Speaker :** Please take your seat.

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । स्पीकर साहिब, यह जो हाउस के सामने मामला है यह बहुत ही संगीन है । वैसे तो आपका फरमाना बिल्कुल दुरुस्त है, गवर्नर के ऐड्रेस पर या बजट पर वह सब चल रही हो तब काल एटेंशन और एडजर्नमेंट मोशन आमतौर पर न आनी चाहिए और न एडमिट होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर साहिब, स्टेट के अन्दर कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो कि आमतौर पर न होने वाली हों, मोस्ट अनयुयल हो । अगर कोई ऐसी संगीन वारदात हो जाए और बजट डिस्कशन के दौरान हफ्ते के अन्दर उस का रेफ्रेंस हो जाए तो सैंकड़ों बातों का रेफ्रेंस होता है, मिनिस्टर जबाब नहीं दे सकते । उस बात को पूरा नहीं कर सकते । कम अज कम चालीस पचास मैम्बर गवर्नर ऐड्रेस पर बोलेंगे और उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को रखना है । वह कितनी ही समस्याओं को रखेंगे अगर मिनिस्टर जबाब देना चाहें तो एक एक लफज भी उनके बारे में नहीं बोल सकते । वह एक एक बात के बारे में जबाब नहीं दे सकते । यह संगीन मामला है । एक शहरी को रहने का हक है । यह फन्डामेंटल राइट है । उसको गवर्नमेंट या महकमा पुलिस की कस्टडी में मार दिया जाए और उसकी लाश भी न मिले और कह दिया जाए कि उस ने खुदकशी कर ली है तो यह ठीक नहीं । अगर खुदकशी कर ली है तो सरकार जिम्मेवार है । अगर पुलिस कस्टडी में खुदकशी की है तो सरकार जिम्मेवार है ।

**श्री अध्यक्ष :** क्या आप प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं ? (Is the hon. Member raising a point of order ?)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** मैं प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं । ऐसे मामले में आप को खास खयाल करना होगा । यह खयाल करना चाहिए कि यह पंजाब की जनता की भावना के विरुद्ध रूलिंग न हो । यह एक बहुत संगीन मामला है । इसको एडमिट करना चाहिए । एक्सपेशनल केसिज में सरकार को खेंचना चाहिए । इस लिये आप इसको एडमिट करें ।

**चौधरी नेत राम :** यह पुलिस के थाने में पुलिस ने कत्ल किया है । मेरी यह काल एटेंशन मोशन, है मैं इस के बारे में जानना चाहता हूं ।

**Sardar Gurnam Singh :** Mr. Speaker, Sir, Rule 73 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly reads :

"A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement....."

The question, Sir, is whether this allegation relates to a matter of urgent public importance. If the case is registered by the Police and is under investigation, then, Sir, you can say that the matter is being examined. But supposing a man dies in the Police custody, the case has not been registered and no investigation is going on, what is the remedy for those people to get that wrong undone ? Where do they go ? Do they wait for the Governor's Address ? Do they wait for the general discussion on the Budget ? It may be a question of that man's body. So many other things may be involved. You may, therefore, kindly say that this is a matter of urgent public importance and the Government may make a statement. If the

[Sardar Gurnam Singh]

Police has done no wrong, the Government can make a statement immediately. But if the matter is not under investigation and the case has not been registered when a murder has taken place in the Police custody, certainly it is a matter which requires the attention of the Government and the Government should be asked to make a statement (*Cheers.*)

(*At this stage, some hon. Members rose on points of order.*)

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरी यह काल अटैशन मोशन है। मैं इस के बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (*The hon Member may take his seat.*)

चौधरी नेत राम : मेरे पास उस के गवाह का एफीडेविट है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम आप बैठ जाएं। (*Chaudhri Net Ram may please resume his seat.*)

चौधरी नेत राम : आप मुझे प्वायंट आफ आर्डर रेज नहीं करने देते मेरा भी अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (*Order please.*)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मेरे पास सबूत मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम, आप बैठें। (*Chaudhri Net Ram, please sit down.*)

चौधरी नेत राम : मैं प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : देखिए ; अगर तो आज का सारा टाइम इस पर लेना चाहते हैं कि काल एटैन्शन या एडजर्नमेंट मोशन एडमिट होनी चाहिए या नहीं वह तो मुनासिब नहीं होगा कि इस तरह की डिस्कशन पर ही सारा टाइम जाया हो जाए। यह बात एडमिट होने वाली नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सारी पुजीशन रीकंसिडर हो जाए तो मुनासिब होगा कि ग्रुप लीडर्स के साथ बैठ कर इनफारमल बात चीत की जाए, यह हाउस में नहीं करना चाहिए। एक चीज मैं आप के नोटिस में लाऊँ कि बहुत सी बातें अरजेंट होती हैं जो नोटिस में आनी चाहिए। अगर काल एटैशन मोशन भी लाई जाए, एडमिट भी होने लग जाए तब भी आपको कहीं लिमिट फिक्स करनी होगी। लोक सभा में एक काल एटैन्शन मोशन एक दिन में एडमिट होती है। (एक आनरेबल मेम्बर : एक मेम्बर की तरफ से एक होती है) एक एडजर्नमेंट मोशन या एक काल एटैन्शन मोशन सिर्फ एक दिन के लिये एडमिट होती है। इस से ज्यादा लोक सभा में एडमिट नहीं होतीं। जितनी काल एटैन्शन मोशन आएं उस के बारे स्पीकर को फैसला करना होता है कि कौनसी टेक अप होगी और कौनसी नहीं। और यह कि कौन सी अर्जेंट है कौन सी बहुत जरूरी है। यह कि जो पहली काल एटैन्शन थी शायद वह ज्यादा जरूरी है लेकिन हो सकता है कि दूसरी काल एटैन्शन मोशन इतनी जरूरी न हो। अगर आप इन्डीविजुअल मेम्बर को इख्तियार देंगे कि जितनी चाहे काल एटैन्शन मोशन ले आए या तो इस का फैसला आप पर छोड़ूं या आप को स्पीकर पर छोड़ना होगा। मैं ग्रुप लीडर्स को बुला कर सारा मामला रीकंसिडर करने के लिये तैयार हूँ। उस में फैसला करने के बाद अगर कोई एडजर्नमेंट मोशन डिसएलाओ हुई तो उस पर यहां डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। अब काल एटैन्शन मोशन पर कोई बात नहीं होगी, सारा मामला रीकंसिडर होगा। (*The hon. Members may please listen. If they want to take up the whole time in discussing whether*

the Call Attention Notices or the Adjournment Motions should be admitted or not, then this would not be proper to waste time on such discussions. This is not going to be admitted. If they feel that the whole position in this regard be reconsidered, then it would be desirable that this matter be discussed informally with the group leaders but not in the House. I would like to point out one thing. There are certain matters of great urgency which require to be brought before the House. Even if Call Attention Notices are given and these are admitted, they will have to fix some limit to their number. In the Lok Sabha, only one Call Attention Motion is admitted in a day. (*Interruption*). One adjournment motion or a Call Attention Motion is admitted in a sitting. Nothing more than this is admitted in the Lok Sabha. The Speaker has to decide on receipt of the Call Attention Notices, whatever be their number, as to which of them are to be admitted and which to be disallowed, which is urgent and which still more urgent. It is possible that the first Call Attention Motion may be of more urgent importance than the second one which may not have the same urgency as the previous one. So if an individual Member is allowed to give any number of Call Attention Notices, then to whom should the right of decision be given to the Members or the Speaker? I am prepared to send for the group leaders to reconsider and discuss the whole matter. If after that decision, any Adjournment Call Attention motion is disallowed, it should not be discussed in the House. Now no more discussion on the admissibility of Call Attention Motions will be allowed. The whole matter will be reconsidered.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : स्पीकर साहिब मेरा भी काल अटेंशन नोटिस है ।

श्री अध्यक्ष : जो आज के है वह पैडिंग है (Notices received today are pending.)

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

**Mr. Speaker :** The next item is : "Papers to be Laid on the Table". Will the Minister concerned please lay the papers on the Table ?

(*No Minister rose at this stage*)

**Mr. Speaker :** I am so sorry. No Minister is attending. That is not proper. If no Minister will attend, I will adjourn the House.

**Voice from the Opposition :** Yes, yes, please.

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, आप इस लिए हमारी बात नहीं सुनते क्योंकि [आप सरकार के पक्ष में रहते हैं। आप को ऐसा स्पीकर नहीं रहना चाहिए।]

**Mr. Speaker :** I order you to withdraw from the House. You are obstructing the proceedings.

**चौधरी नेत राम :** स्पीकर साहिब, आप जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इस लिए मैं बतौर प्रोटैस्ट के हाउस से वाक आऊट करता हूँ।

**Mr. Speaker :** The honourable Member has proved disorderly. He has obstructed the proceedings of the House. He has made reflections on the Chair. My order will stand so that the consequences can follow.

**Pandit Chharanji Lal Sharma :** Sir, you were pleased to ask the honourable Minister to lay Papers on the Table of the House, but no body stood up to do so. That shows how indifferent the Government is.

**Mr. Speaker :** I am coming to that please.

**Pandit Chharanji Lal Sharma :** Sir, the honourable Ministers do not even turn up. Are they not indifferent to the proceedings of the House ?

**श्री अध्यक्ष :** चीफ मिनिस्टर साहिब मैं एम्फैटिकली अर्ज करना चाहता हूँ कि आप के मिनिस्टर और मैम्बर्स में से बावजूद मेरे काल अपौन करने के कोई नहीं उठता और न ही कोई हाऊस को अटैंड करता है। मैंने कहा था :

Will the Minister concerned please lay the papers on the Table ?

But No Minister rose to do that. अगर इस तरह से कोई अटैंड नहीं करेगा then I will adjourn the House. मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आनरेबल मिनिस्टर को इस तरह इन्डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आयंदा के लिये यह ठीक नहीं होगा। ( I would like to submit to the hon. Chief Minister emphatically that none of the Miniters or Members of his party rises despite my calling upon him nor does any of the former attend the House. I had called, "Will the Minister concerned please lay the papers on the Table". But none rose to do that. I, then, said that if no Minister would attend then I would adjourn the House. I would, therefore, like to tell the hon. Chief Minister that the Minister should not be so indifferent. It would not be proper if this thing is repeated in future.)

**मुख्य मन्त्री :** स्पीकर साहिब, मुझे अफसोस है इस बात का कि आप को किसी मिनिस्टर या किसी मैम्बर के खिलाफ ऐसी शिकायत हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आयंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आज का एजण्डा है इस में कही भी यह जिक्र नहीं कि किसी मिनिस्टर ने कोई पेपर ले करने हों।

**Mr. Speaker :** I think, you have been wrongly advised by the Chief Parliamentary Secretary. An addendum was issued in regard to the Papers to be laid on the Table of the House. It was also circulated to all concerned. I do not understand how and why it was not received by the honourable Ministers.

**Shri Ram Partap Garg :** The List of Business is before me. There is nothing in it about the Papers to be laid on the Table of the House.

**Mr. Speaker :** No, this is not correct. In addition to the formal List of Business, issued on the 19th February, 1966, an Addendum dated the 21st February, 1966, was also issued. It reads :

"After item "I. Questions", the following shall be inserted :—

"I-A. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE.

A Minister to lay on the Table the Defence of India (Punjab Special Tribunal) (First Amendment) Rules, 1965, issued under section 15 of the Defence of India Act, 1962."

**Chief Minister (Shri Ram Kishan) :** I am sorry for this. I hope this will not happen in future.

**Mr. Speaker :** In such circumstances, at least one Minister should get up and say that he is not in possession of the papers.

(Deputy Speaker in the Chair)

**Discussion on Governor's Address (Resumption)**

**श्री रूप सिंह फूल :** (हमीरपुर एस.सी.) : डिप्टी स्पीकर साहिब, गवर्नर के एड्रेस पर तज्जकरा करते हुए मैं अर्ज कर रहा था। पेशतर इस के कि कुछ अर्जें हाल करूं एक बात की कम से कम गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हमले के दौरान जिस फर्ज शनासी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने काम किया वह काबले तारीफ है। जिस शिद्दत के साथ इन्होंने उन बार्डर एरियाज में जा जा कर लड़ने वाले जवानों के हौसलों को बुलंद किया उस के लिये हमारी गवर्नमेंट मुबारिकबाद की मुस्तहिक है। यही कारण है कि चीफ मिनिस्टर साहिब की परसनल अपील पर न सिर्फ 50 लाख या एक करोड़ बल्कि चार करोड़ की रकमें डिफेंस और रिलीफ फण्ड की जमा हो गई। यह सबूत देती है चीफ मिनिस्टर और उस की हुकूमत की हरदिलअजीजी का। मुझे यकीन है कि वह रिलीफ जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक पहुंच जाएगा। मगर हरेक तसवीर के दो पहलू होते हैं; एक रोशन साईड होती है और एक डार्क साईड। यह सरकार सोशलजिज्म की तरफ जा रही है और लोगों को यकीन दिलाती है कि हमारा एक सोशलस्टिक निजाम कायम करना है। मगर मंजिल इस की किसी और तरफ आ रही है। हमारे कामरेड जी और बीबी शन्नो देवी जी दोनों जंगे आजादी के जरतूल रहे हैं। इन्होंने आजादी हासिल करने के लिये खास काम किए हैं और यह भी ठीक है कि जिस वक्त यह अवाम से खिताब करते थे तो कहा करते थे कि जब हमारा कांग्रेस का राज आएगा तो हम 12 साल के मुज्जारों को हकूक मारूसीयत देंगे मगर आज 18 साल आजादी को हो गए हैं। यही वह कामरेड हैं और इन्हीं की आज सरकार है लेकिन पंजाब में मुज्जारों की बेदखलियां धड़ाधड़ हो रही हैं। मेरी गुज्जारिश है कि कितने ही कानून बनाए गए जिनके नाम तो रखे गए सिक्थोरिटी आफ लैंड टैनियोर लेकिन दरहकीकत वह इनसिक्थोरिटी आफ लैंड टैन्योर साबित हुई और मुज्जारों को उन से कोई सिक्थोरिटी नहीं मिली। माल मंत्री साहिब आज यहां पर बैठे हुए हैं और मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह जमींदारों की हुकूमत है जो पिछली यूनियनिस्ट हुकूमत की पुरानी पालिसी के तहत चल रही है। अगर ऐसी बात नहीं तो फिर आज जो सैंकड़ों साल से आबाद मुज्जारों को बेदखल किया जा रहा है उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। इसके अलावा मैंने स्पीकर साहिब सरकार का शुक्रिया अदा करना है और वह इस तरह कि :

"मैं कैसे कहूं कि तेरा जलबा नहीं देखा,

देखा है इस तरह से कि गोया नहीं देखा।

[श्री रूप सिंह फूल]

कामरेड साहिब आप जा रहे हैं लेकिन मैं आपको जाने न दूंगा रोक लूंगा, । ज़रा सुनिए तो :

“ जिन्दगी के उदास गुलशन में  
फूल कुछ तो खिला दिए होते  
हम ने जब जिकरे दरद छेड़ा था  
काश तुम मुसकरा दिए होते ”

डिप्टी स्पीकर साहिब, अब मुझे कुछ पहाड़ी इलाके के बारे में अर्ज करना है। यह जो भाखड़ा डैम बना है और अब पौंग डैम बन रहा है यह कांगड़ा के पहाड़ी इलाका की बदौलत बन रहा है। 75 हजार के करीब आबादी पौंग डैम के बनने से और 30 हजार की आबादी भाखड़ा डैम के बनने से उजड़ी है। कांगड़ा की इतनी खिदमात के सिला में इन्होंने यह किया है कि भाखड़ा डैम यहां बना है वह कोसरियां गांव कांगड़ा से निकाल कर तहसील ऊना जिला होशियारपुर में दाखिल कर दिया है। जब पूछा गया तो कहा गया कि यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट आफ व्यू से किया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह जिला कांगड़ा के साथ सख्त बेइन्साफी की गई है। यह गांव वापिस कांगड़ा को दिया जाए। वह गांव जहां हमारे आबाओ अजदाद की हड्डियां हैं और जहां दुनियां का इतना बड़ा शाहकार तामीर हुआ है जिस से फैजयाब तो हरियाणा और राजस्थान हो रहे हैं लेकिन गांव भी हम से छीन लिया है ताकि कांगड़ा का नामोनिशान मिट जाए।

मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि तहसील हमीरपुर को गवर्नमेंट कालिज दे दिया है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक बात का मुझे ज़रूर दुख है कि धर्मशाला में जो पहले से गवर्नमेंट कालिज है वहां पर बावजूद इसके कि काफी अर्सा से बावेला कर रहे हैं ऐम. ए. की क्लास जारी नहीं की गई है। अगर ज्यादा नहीं तो दो तीन मजामीन की क्लासें ही जारी कर दी जातीं ताकि कांगड़ा वाले कह सकते कि उनकी सरकार हायर तालीम के साधन उनको दे रही है। मैं समझता हूं इस तरफ जल्दी ही कदम उठाए जाएंगे। चार साल हुए गवर्नर ने ऐड्रेस पढ़ा। गवर्नर साहिब के उस ऐड्रेस को मैंने पढ़ा और बड़ी खुशी हुई कि न्यूज़ प्रिंट फैक्टरी और सीमेंट फैक्टरी हमारे कांगड़ा में लगेगी। सीमेंट फैक्टरी का तो अभी तक बिसमअल्ला भी शुरू नहीं हुआ है पता नहीं किस वक्त ऐस्टीमेट्स मुकम्मल होंगे और कब तक वह फैक्टरी लगेगी लेकिन जहां तक न्यूज़ प्रिंट फैक्टरी का ताल्लुक है उस का पता चला है कि पहले मीरथल में लगनी शुरू हुई थी उसके बाद नंगल की बात चली और अब सुनते हैं कि कीरतपुर में। यह कांगड़ा के साथ सख्त बेइन्साफी है और हक तल्फी है। कितने अफसोस की बात है कि फैक्टरी के लिये खास माल तो आए जिला कांगड़ा के जंगलात से लेकिन उस फैक्टरी से फैजयाब हों कीरतपुर वाले। यह हमारे साथ बेइन्साफी है जो कभी बरदाश्त नहीं होगी। इस से लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया है और इसके खिलाफ कांगड़ा वाले आंदोलन करेंगे वहां लोगों में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है कि हम जंगलात जला देंगे अगर फैक्टरी कांगड़ा से बाहर लगाई गई। मेरा ख्याल है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और यह फैक्टरी कांगड़ा में लगाएगी।

यह जो अभी 2 पाकिस्तान के साथ जंग हुई है उस में यह नहीं कहता कि सिर्फ डोगरों ने ही बहादरी दिखाई है। उस जंग में सिखों, गुरुखों, राजपूतों, मराठों, जाटों सब ने शुजायत दिखाई है लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि :

“जब कभी होगी जरूरत या वक्ते इस्तहान,  
सब से पहले सूप मैदान में डोगरे होंगे रवां।”

और वेह डोगरे रवां होते रहे हैं और होते रहेंगे यह वही जिला कांगड़ा के हैं जिन्होंने न चायनीज एग्रेसन के वक्त जामें शहादत पिया और हिमालय की बरफानी चोटियों पर सब से ज्यादा बहादरी से लड़े। अगर जिला वार देखा जाए तो कांगड़ा के जवानों ने उस वक्त भी सब से ज्यादा कुर्बानी दी। इसके बदले में न हमारे चीफ मिनिस्टर की तरफ से और न किसी और वजीर की तरफ से यह भी न हो सका कि वहां जा कर किसी शहीद के परिवार को तसल्ली दे सकें। दौरों पर तो वहां जरूर गए लेकिन किसी शहीद के घर पर जा कर इन्होंने घर वालों की मातमपुरसी नहीं की। इस का मतलब है कि हमारी जो खिदमात हैं उनका इन पर कोई असर नहीं:—

हम तो मखसूस हैं तोपों की तिजारत के लिये  
हम तो मामूर हैं मरने की ज्यारत के लिये  
हम में काबलियत न अमारत न सिदारत के लिये।  
कौन पूछे है हमें आज वजारत के लिये।

फिर यही बस नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देखें पब्लिक सर्विस कमीशन में कांगड़ा और पहाड़ी इलाका वालों का कोई मैम्बर नहीं। बिजली बोर्ड बना है और बिजली हमारे कांगड़ा को बंदौलत बनती है लेकिन उस में हमारा कोई मैम्बर नहीं। पोस्टवार रिकंस्ट्रक्शन फण्ड जितने पहाड़ी इलाके यानी जिला कांगड़ा का ज्यादा हिस्सा है उसका आज तक जिला कांगड़ा का कोई मैम्बर नहीं बनाया गया। सुबार्डीनेट सर्विसज सिलैक्शन बोर्ड में हमारा कोई मैम्बर नहीं। फिर जहां तक राजनीतिक क्षेत्र का सम्बन्ध है उस में भी देख लें कि हमें बुरी तरह इगनोर किया हुआ है। राज्य सभा विधान परिषद् में जिला कांगड़ा की कोई नुमाइंदगी नहीं। वह जिला कांगड़ा जिसकी दौलत को अगर ऐक्सप्लायट किया जाए तो न सिर्फ पंजाब की बल्कि सारे हिन्दुस्तान की डिवैलपमेंट के साधन हो सकते हैं। हर मामले में इगनोर किया जाता है। अर्ज करता हूँ :

फैजे कुदरत के हैं भरपूर दफीने मुझ में,  
दौलतों के हैं धड़कते हुए सीने मुझ में,  
खूब कुदरत ने सजाए हैं करीने मुझ में,  
और इरफान पै पहुंचने के हैं जीने मुझ में ”

मगर इसके बावजूद:

“गुगल हाथों को मेरे चाके गरेबानी का  
दिल है मजरूह मेरा काविशे पिनहानी का  
हल निकालों तो कोई मेरी परेशानी का  
भूक का गुरबतो अफलास का अरियानी का ”

[श्री रूप सिंह फूल]

हमें दुख यही है कि वावजूद हमारी इतनी दौलत के हमें उस से महरूम रखा जाता है और वहां की तरक्की का कोई खयाल नहीं किया जाता। इसी लिये मेजर साहिब लोग कहते हैं :

“वरना हम और कोई हम में फनाह होता है  
लोग कहते हैं कि इस राज में क्या होता है।”

हमें अफसोस है कि हमारे घर से बिजली निकाल कर दूर दराज के इलाकों को फैजयाब किया जा रहा है और पड़ोस के हिमाचल प्रदेश के गांव गांव में चिरागां हैं लेकिन हमारे घरों में अंधेरा है। मैं एक और अर्ज करूँ कि हमारे कांगड़ा की जो सड़कें दूसरे प्लान में मुकम्मल होनी थीं उनका आज तक भी जब कि चौथा प्लान शुरू होने वाला है आधा हिस्सा मुकम्मल नहीं हो पाया है। ऊना अधड़ मंडी रोड, मुबारकपुर नदीन रोड वैसे की वैसे पड़ी है। पता नहीं कितने प्लान निकल जाएंगे लेकिन वहां की सड़कें मुकम्मल नहीं होंगी। फिर सोशललिज्म की बड़ी बातें होती हैं लेकिन चौथे और तीसरे दर्जे के मुलाजिमीन की तनख ह में इजाफा नहीं किया गया।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौकीदारों को अभी तक 20 रुपये महीना तनखाह दी जा रही है। इस के फोरेस्ट के गाड़ों की तनखाह भी बहुत कम है। जंगल के राखों को कुछ नहीं दिया जाता। वह अपना गुजारा इतनी थोड़ी रकम में कैसे कर सकते हैं। (घंटी) मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो पहले गरीब हैं, वह बहुत ही गरीब बनते जा रहे हैं सरकार उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या इस सरकार का यही सोशललिज्म का नारा है? मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि—

फूल पर रंगे बहार आया है कुछ बात नहीं,  
खार पर रंगे बहार आए तो कुछ बात बने।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कांग्रेस राज के 18 सालों के अन्दर पहाड़ी इलाके के साथ इम्तयाजी सलूक किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आयादा भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। हमारे पहाड़ी इलाका की डिवैल्पमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वह पहले ही बैकवर्ड इलाका है। अगर वहां पर कोई डिवैल्पमेंट न हुई तो वहां के लोग पहले से भी बहुत गरीब हो जाएंगे। यही कारण है कि हम हिमाचल प्रदेश के साथ मिलना चाहते हैं ताकि वहां हम अपनी किस्मत का ठीक तरह से फैसला कर सकें। इस लिये हमें हिमाचल प्रदेश में मिलने देना चाहिए। हमारे जिले की संस्कृति और भाषा तथा रिवाज हिमाचल प्रदेश के साथ मिलते हैं। हमारी बोली भी हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती जुलती है। हमारे जिले के लिये सरकार ने जो डिवैल्पमेंट का पैटर्न बनाया हुआ है, वह ठीक नहीं है। इससे हमारे जिले की डिवैल्पमेंट नहीं हो सकती है। हमारे साथ इम्तयाजी सलूक किया जा रहा है। इस लिये वहां की जनता और हम मजबूर हो कर हिमाचल प्रदेश के साथ मिलने के लिये तैयार हो गए हैं। जितना डिवैल्पमेंट के लिये मैदानी इलाकों के लिये सहुलत दी गई है उससे आधी भी सहुलतें कांगड़ा जिले को नहीं दी गई। हमारे साथ किसी भी स्टेज पर इंसफ नहीं हो रहा है। इसी कारन हमारे जिले के लोग हिमाचल प्रदेश के साथ मिलने के लिए उत्सुक हैं। मैं पंजाब के बारे में इतनी अर्ज करना चाहता हूँ कि—

छड़ो देवतियो बांह मेरी, मैं स्वर्ग लोक नहीं रहना।

इस भगतां दी धरती अन्दर मेरा नहीं ठिकाना।

मैं जाना हूँ दोजख अन्दर जित्थे वसदे मेरे वरगे छैल छबीले मुंडे,  
कोते जिन्हां माशूकां बदले मूंह छबियां दे खूंडे ।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम मजबूर हो कर हिमाचल प्रदेश के साथ मिलने के लिये उत्सुक हो गए हैं ताकि वहां पर हम अपनी किस्मत का फैसला कर सकें। हमारा इलाका पहले ही बहुत पसमांदा है और अगर सरकार ने हमारे जिले के लिये यही नीति अपनाई रखी तो हमारी हालत आगे से भी बदतर हो जाएगी।

गो बज्राहिर है खिजादीदा मेरा बागे वतन,  
पर तेरे पंजाब का है बाजुए शमशीर जन।  
कोई अगर दे हुकम तो वह जंो बहरोवर करे  
चीनो पाकिस्तान क्या सारे जहां को सर कर दे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब भी भारत पर कोई मुश्किल आती है तो जिले के लोग बहादुरी के लिये आगे आते हैं और देश की रक्षा करते हैं लेकिन जब भी वहां की डिवैलपमेंट की बात आती है तो हमें हर पहलू पर नज़र अन्दाज़ किया जाता है। आपको मालूम है कि हमारे जिले के सब से ज्यादा फौजी शहीद हुए। उन्होंने सब से ज्यादा कुरबानी की लेकिन उन की हालत को सुधारने के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

( सरदार हरचन्द सिंह द्वारा विघ्न )

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਠ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਕੋਹੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

श्री रूप सिंह फूल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार पहाड़ी इलाकों की परवाह नहीं करती। अगर कोई सैनिक स्कूल खोले जाते हैं तो नाभा, कपूरथला और कुंजपुरा में खोला जाता है यानि इस लिहाज़ से भी ज़िला कांगड़ा को नज़र अन्दाज़ किया गया है। हालांकि सब से ज्यादा लोग फौज में ज़िला कांगड़ा से भर्ती होते हैं। (घंटी) हमें हर लिहाज़ में सैकंडरी प्लेस दी जाती है। हमारे जिले में से कितने आई. ए. एस., आई. पी. एस. और आई. एफ. एस. और दूसरी बड़ी बड़ी पोस्टों में लिए गए हैं, इस के बारे में आप को भी मालूम है। हमारे इलाके में से बहुत ही कम लोगों को ऊपर उठने का मौका मिलता है। इस की वजह यह है कि पहाड़ी इलाका बहुत ही बैकवर्ड है और सरकार उस की हालत सुधारने के लिये कोई कदम नहीं उठाती है। इस लिये हम मजबूर हो कर हिमाचल प्रदेश के साथ मिलने के लिये तैयार हुए हैं ताकि वहां पर हम अपना उद्धार कर सकें।

ठाकुर मेहर सिंह: ( डेरा गोपी पुर ) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस के अन्दर गवर्नर साहिब के एड्रेस पर तीन दिन से बहस चल रही है। मैं भी अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मेरे इलाके में सिंचाई के साधन हैं। दरिया ब्यास से सिंचाई की अप लिफ्ट की स्कीमें बनाई जा सकती हैं लेकिन सरकार उस इलाके में कोई तवज्जोह नहीं दे रही है। इस

[ठाकुर मेहर सिंह]

के अलावा आप को मालूम है कि सरकार ने मैदानों की हालत सुधारने के लिये सिचाई स्कीमों के अग्रोन करोड़ों रुपये खर्च किए लेकिन इस पहलू पर हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है।

**बाबू बचन सिंह :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। कल और आज रूलिंग पार्टी की तरफ से 3 आनरेबल मैम्बर बोल चुके हैं। और आप ने अब रूलिंग पार्टी के तरफ के आनरेबल मैम्बर को काल अपोन कर लिया। इस तरह आपोजीशन की तरफ से कोई मैम्बर नहीं बोला। स्पीकर साहिब, के साथ फैसला हुआ था कि रूलिंग पार्टी की तरफ से दो मैम्बर बोलेंगे और आपोजीशन पार्टी की तरफ से एक मैम्बर बोलेगा। हम तो उसी फैसले पर कायम रहने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर यह इक्वेशन चेयर की तरफ से तोड़ी जाए तो कैसे काम चलेगा।

**उपाध्यक्षा :** नुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यह इक्वेशन चेयर की तरफ से बिल्कुल तोड़ी नहीं गई। बाबू जी ने भाषण करते हुए 1 घंटा 17 मिनट लिए। बाबू जी ने आपोजीशन की तरफ से सब से ज्यादा वक्त लिया और खुद इक्वेशन तोड़ते हैं। Please take your seat. Order Please. (I must say that this equation has not been upset by the Chair. The hon. Member Baboo Bachan Singh himself took one hour and seventeen minutes to complete his speech. In fact, from the Opposition side he took most of the time and broke the equation. He may please resume his seat.)

**बाबू बचन सिंह :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या यह इक्वेशन रखी जाएगी या तोड़ दी जाएगी ?

**उपाध्यक्षा :** बाबू जी, आप तो खुद इक्वेशन तोड़ते हैं ? आपोजीशन का सब से ज्यादा समय आप ही ले जाते हैं। अगर आप समझते तो पहले ही आप अपनी स्पीच खत्म कर देते ताकि आपोजीशन के आनरेबल मैम्बरों को वक्त मिल जाता। आप ने तो एक घंटा और 17 मिनट भाषण दिया। इस लिये रूलिंग पार्टी और आपोजीशन पार्टी को पहले ही वक्त के बारे में तय करना चाहिए। (The hon. Member, Baboo Bachan Singh, is himself responsible for breaking the equation and consuming the biggest share of the time of the Opposition. If he had felt so much, then he should have completed his speech earlier to enable other members of the Opposition to get some time to speak. He himself took one hour and seventeen minutes to deliver his speech. In view of this the Ruling Party and the Opposition Groups should settle before hand the time limit for speeches.)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। बाबू बचन सिंह को आप ने या कोई भी चेयर पर बैठा हो गा उस ने बोलने के लिये 1 घंटा 17 मिनट भाषण करने की इजाजत दी होगी। अगर नहीं तो क्या उस वक्त चेयर पर कोई भी मौजूद नहीं था। किसी को बन्द करना चेयर का काम है। यह काम आनरेबल मैम्बरों का नहीं है। अगर चेयर ने रैलेवेंसी को देखते हुए उन्हें बोलने की इजाजत दे रखी तो यह हमारा कसूर नहीं है।

**उपाध्यक्षा :** चेयर ने आधे दर्जन से अधिक बार उन्हें वाइंड अप करने के लिये घंटी बजाई उन्होंने चेयर की कोई परवाह नहीं की। वह खुद इक्वेशन को तोड़ते हैं। प्वायंट आफ आर्डर पर टाइम वेस्ट न किया जाए। Please take your seat. (The

Chair sounded the bell for more than half a dozen time reminding him to wind up his speech but he paid no heed to the Chair. It is he who breaks the equation. No time need to be wasted on raising points of order.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मै डम। पहले आप आनरेबल मੈम्बरों को ज्यादा वक्त दे देते हो और फिर दूसरे मੈम्बरों पर कुल्हाड़ा चला देते हैं। क्या यह वाजिब है ?

उपाध्यक्ष : यह पहले तय हो चुका है कि हर ग्रुप अपनी अपनी तरफ वालों से बोलने की

12.00 noon

लिस्ट भेज देगा। आप का नाम चौथे नम्बर पर है। चेयर ने तो यह देखना है कि हर एक को ठीक वक्त मिले। बाकी आप आपस में फैसला कर लें।

(It has already been settled that every group in the House would send a list of its members intending to speak, to the Chair. The name of the hon. Member stands fourth in that list. The Chair has to see that every Member gets the apportioned time. The other points may be settled by them mutually.)

ठाकुर मेहर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। गवर्नर जे एंड्रैस में कांगड़े का जिक्र किया गया है इस सम्बन्ध में मैं यह जिक्र करना चाहता हूँ कि जिला कांगड़ा के अन्दर बाहर से जितने भी कर्मचारी जाते हैं उन को सी. ए. साढ़े बारह फीस दी दिया जाता है लेकिन कांगड़े के रहने वालों को केवल छः फीस दी सी. ए. दिया जाता है हालांकि मंहगाई का असर दोनों पर एक जैसा होता है। अगर होशियारपुर का कोई आदमी कांगड़ा जिला के तीन मील भी अन्दर चला जाए तो उसे तो साढ़े बारह रुपये के हिसाब से सी. ए. मिलता है और कांगड़े का रहने वाला चाहे चालीस मील और आगे चला जाए तो भी उसे साढ़े छः पैसे के हिसाब से ही सी. ए. मिलेगा, यह कैसी निरपेक्षता है इस की हमें समझ नहीं आती। हर प्रकार से कांगड़े के साथ धक्का किया जाता है। जितने भी मंडीकल कालिज बनाए गए हैं, सारे के सारे प्लेन्ज में बनाए गए हैं, जितने इंजीनियरिंग कालिज बनाए गए हैं वह भी सब के सब प्लेन्ज में बनाए गए हैं, हमारे जिले की तरफ किसी की तवज्जोह नहीं गई। यहां तक कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट भी कोई नहीं है, कई बार मांग की गई है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ही बताएं कि हम कैसे दूसरे लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं जब कि हमारे यहां एजुकेशन की हालत यह है कि अगर हमारे किसी हाई स्कूल में से साइंस मास्टर तबदोल हो कर चला जाए तो नौ, दस महीने तक उस की जगह खाली पड़ी रहती है। साइंस का सब जैकट मौजूद रहता है लेकिन पढ़ाने वाला मास्टर नहीं मिलता। बच्चों का सारा साल जाया जाता है। भला वे बच्चे दूसरों के साथ किस तरह से कम्पीट कर सकते हैं जिन के स्कूलों में पूरा स्टाफ होता है ? इस बात की तरफ खास ध्यान दिया जाना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के बाद में सफा 25 पर आईटम 20 की तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूँ जिस में स्वास्थ्य और पीने के पानी की स्कीमों का जिक्र है। इस में लिखा है कि स्वास्थ्य और पीने के पानी की स्कीमों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। पीने के पानी की स्कीमों का जहां तक इम्प्लीमेंट करने का सवाल है इस में भी इम्तयाज़ी सलूक किया गया है। खरोटी में आज से 6, 7 साल पहले वाटर नैशनल स्प्लाइ स्कीम के मातहत एक छोटी सी स्कीम बनाई गई थी लेकिन अभी तक वहां पर रेज़रवायर भी नहीं बनाया गया। स्टोर टैंक

[ठाकुर मेहर सिंह]

ही नहीं बनाया गया लोग वहीं से कपड़े धोते हैं, वहीं से नहाते हैं और वहीं से मवेशियों को पानी पिलाते हैं और खुद भी वहीं से पानी पीते हैं। कई बार इस तरफ तबज्जोह दिलाई गई है लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। लोग प्यासे मरते हैं गंदा पानी पीते हैं पीने के लिये साफ पानी नहीं है। 1965-66 में चिसाई की स्कीमों का 70 फीसदी रुपया खर्च होने जा रहा है लेकिन जिला कांगड़ा को एक दमड़ी का फायदा नहीं हुआ। दो करोड़ बीस लाख रुपया ट्यूब वेलों पर खर्च किया जा रहा है लेकिन जिला कांगड़ा को उस में एक पैसा मिलने वाला नहीं है।

इस से आगे मैं स्वास्थ्य के मामले में गरली अस्पताल की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वहाँ पर एक पुराना अस्पताल है एक लाख रुपया लगा कर पब्लिक ने बिल्डिंग बना कर दी है लेकिन नौ साल का अर्सा हो गया है उस में कोई डाक्टर नहीं आया। दो साल हुए एक लेडी डाक्टर वहाँ पर आई थी लेकिन चार ही महीने के बाद उस को तबदील कर के पालम्, पुर भेज दिया गया। हमीरपुर-डेहरा कांस्टीच्यूसी में चार लाख की आबादी है लेकिन वहाँ पर किसी भी हस्पताल में कोई भी लेडी डाक्टर नहीं है। जब किसी औरत को बच्चा पैदा होना होता है तो उस सूरत में कोई मैडीकल ऐड नहीं मिलती। इसी तरह से पीर सलूई में एक हस्पताल पब्लिक ने 50 हजार रुपया लगा कर बनाया परन्तु पिछले 9 साल में उस में कोई लेडी डाक्टर नहीं लगाई गई। मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि कई अस्पतालों में तो डाक्टर भरे पड़े हैं, चंडीगढ़ में हस्पताल ओवर स्टाफ्ड हैं लेकिन हमारे देहाती इलाकों में लोगों ने अस्पताल बना कर दिये हैं फिर भी वहाँ पर डाक्टर नहीं भेजे जाते। इस का कुछ इलाज होना चाहिये।

इसी तरह से पीने के लिये पानी की भी मुश्किल है। जहाँ सिंचाई के लिये हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जाता वहाँ पर पीने के लिये पानी की स्कीमों में भी पूरा हिस्सा नहीं मिलता। सरवे हुआ है लेकिन कुछ अमल नहीं किया गया। जहाँ पर नल लगे हुए हैं वहाँ की भी नागुफ-ताबेह हालत है। जब कोई नल खराब हो जाता है तो ठीक करने वाला मिस्तररी भी कोई नहीं मिलता। नल टूटा पड़ा रहता है लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता। अब पता नहीं कि हमारी क्या पोजीशन है, हिमाचल में मिलाते हैं या क्या करते हैं लेकिन हमें तो आज से ही इग्नोर कर दिया गया है। बजट में हिस्सा देना तो दरकिनार किसी प्रकार का आश्वासन भी नहीं दिया गया कि आप के लिये यह कर दिया जाएगा। मैं आप के द्वारा यह प्रार्थना सरकार से करना चाहता हूँ कि पीने के पानी की स्कीमों पर पूरी तनदेही से गौर किया जाना चाहिये यह हिदायत जारी होनी चाहिये कि जिन स्कीमों के एस्टीमेट्स दिये गए हैं उन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिये।

एंड्रैस में बठिंडा, हिसार, रोहतक, गुड़गाँवा और तहसील ऊना का जिक्र आया है कि वे कहतजदा इलाके हैं। हमारे यहाँ भी मकई की फसल बिलकुल नहीं हुई। गंदम की फसल भी नहीं हुई। आप मुलाहिजा कर के देखें कि जिस आदमी ने दस मन या बीस मन बीज का डाला है उस का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ क्योंकि वर्षा नहीं हुई। अब अगर वर्षा हो भी जाए तो कुछ पैदा होने वाला नहीं है फसल तबाह हो चुकी है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई और हमारे इलाके को कहतजदा करार नहीं दिया। अब सरकार कहती है कि सस्ते अनाज के डिपो खोल दिये जाएंगे। लेकिन मैं यह पूछता हूँ कि जब जमींदार की फसल ही नहीं हुई उस के

पास पैसा कहां से आएगा, जब पैसा नहीं होगा तो वह सस्ता अनाज कैसे खरीद सकेगा। मकई की फसल के लिये बावेली किया गया था कि मामला माफ कर दिया जाए लेकिन सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। हमारे लोग तकावियां लेने के आदी नहीं हैं, वे लोग कज्जे लेने भी नहीं जानते, मुनासिब नहीं समझते इस लिये उन की इमदाद करना निहायत जरूरी है। जो सेमझदा इलाके हैं जब वहां पर सेम हो जाती है तो लाखों मन अनाज मुफ्त तकसीम कर दिया जाता है इसी तरह से हमारे इलाके में न मकई का दाना हुआ है और न गंदम का कोई दाना हुआ है इस लिये उन की इमदाद होनी चाहिये। वहां पर ज्यादा से ज्यादा काम जारी किये जाने चाहिये। उन के लिये रिजर्व जंगलात को खोल देना चाहिये ताकि वे लोग अपने मवेशियों के लिये चारा प्राप्त कर सकें। इस तरह से वे लोग अपने मवेशी बचा लेंगे। अब एक और नई पाबन्दी जलाने की लकड़ी पर भी लगा दी गई है। चूँकि पोस्टें कायम कर दी गई हैं। यह पोस्टें कुर्रेशन का सम्बा है। वहां से बिना परमिट के तो लोग रिश्वत दे कर कितनी ही लकड़ी निकाल कर ले जाते हैं लेकिन जो लोग रिश्वत नहीं देते उन को परमिट भी बिना रिश्वत लिये इशू नहीं किये जाते। जिन लोगों की अपनी मलकियत है वे लोग भी अपने दरख्त नहीं काट सकते। चूँकि वहां पर कहत पड़ा हुआ है खुशक साली है इस लिये उन लोगों को इजाजत होनी चाहिये ताकि वे अपने वृक्ष काट कर पत्ते पशुओं को डाल सकें और लकड़ी बेच कर अपना गुजारा कर सकें। महकमा जंगलात ने अंधेरगरदी मचा रखी है। उन को अपने दरख्त काटने की इजाजत होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।

**सरदार गुरबखश सिंह गुरदासपुरी :** डिपटी सपीकर साहिब, कॅरम वल वी पिआन कॅरें कि है नां नही। (Interruption)

**डिपटी सपीकर :** मेजर साहिब, मैनु अड्रेस नाल कहिणा पैँदा है कि ब्रावजुद एस गल दे कि अज सुबाह सपीकर साहिब ने वी काफी कृप किहा सी, जे टैजरी बेंचिस वल पिआन दिउि उं चेअर दे समेत कॅरम हिंदा है। जेकर कॅरम ना रिहा उं मैं हाउस नुं अडजर्न कर दवांगी। (Addressing Major Harinder Singh, Minister for Revenue) (I am constrained to remark that despite the fact that to-day in the morning the hon. Speaker had made certain emphatic observations in this connection things do not appear to have gone home and a glance at the Treasury Benches shows that the quorum is hardly complete even after including the Chair, If the House does not remain in quorum then I will adjourn it.)

**माल मंडरी (सरदार हरिंदर सिंह, मेजर) :** डिपटी सपीकर साहिब, जे हालात चल रहे हन उिउ उगाडे कॅलें हूपे रहे नही। मैनु उं उमीं जे हुकम दिउिगे उिनुं दी मैं पालना करांगा लेकिन जद हालात ही एस उरुं दे हो जात उं मैं की कर सकदा हं।

**अपोजीशन वलें कृप मानजोग मैंबर :** मेजर साहिब ने बिलकुल ठीक किहा है।

**डिपटी सपीकर :** मेरा वी एिग डरज है कि मैं एिग चीज उगाडे नॅटिस दिच ले आवं। (It is my duty also that I should bring this fact to the notice of the hon. Minister.)

**माल मंडरी :** डिपटी सपीकर साहिब, मैं वी गलत गल नहीं कहिंदा। सॅची गल दाकर हं, लुका के नहीं रक्खा।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर—पूर्व) :** डिप्टी स्पीकर साहिब, हाउस में गवर्नर साहिब के ऐंड्रैस पर बहस चल रही है। धन्यवाद का प्रस्ताव ट्रेजरी बैचिज़ की तरफ से पेश हुआ और उसका समर्थन भी हुआ। लेकिन यह तो एक फारमैलिटी ही रह गई है कि गवर्नर साहिब का धन्यवाद किया जाए कि उन्होंने यहां पर हाउस के अन्दर आकर हम को ऐंड्रैस किया है। वैसे अगर देखा जाए, तो इस ऐंड्रैस के अन्दर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, कोई सरकार के ऐसे नए कारनामे नहीं हैं जिन पर फ़ख्र किया जा सके। है क्या? वही रूटीन बातें कि सरकार ने यह किया वह किया और जो कुछ नहीं भी किया उसे भी इस के अन्दर बता दिया गया है। वैसे भी अगर इस के अन्दर यह लिखा हुआ हो कि सरकार फ़लां बात करेगी फ़लां बात करेगी और गवर्नर साहिब यहां पर आकर वह सबकुछ फरमा भी दें तो भी उसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि सन् 1962 में गवर्नर साहिब ने ऐंड्रैस में इस बात का एलान किया था कि पानीपत के अन्दर कागज़ की एक मिल लगाई जाएगी, पब्लिक सैक्टर में यह किया जाएगा, प्राइवेट सैक्टर में यह किया जाएगा किसी चीज़ के लिये आठ करोड़ रुपया रखा गया और किसी के लिये चार करोड़। लेकिन इसी हाउस के अन्दर उस मिल की बाबत हर साल सवाल पूछे जाते रहे कि वह कहां तक पहुंच पाई है। जवाब दिए गए कि इसके लिये लाईसेंस दिया गया है, ऐग्रीमेंट हुआ हुआ है। हर साल इसी सम्बन्ध में सवाल पर सवाल पूछे गए लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब, आप को मालूम ही है कि सन् 1965 में आकर यह जवाब दिया गया कि उस स्कीम को ही ख़त्म किया गया है। तो एक बार तो यहां पर गवर्नर साहिब का धन्यवाद किया जाए कि आप ने बहुत अच्छा किया जो फ़लां काम स्टेट में शुरू कर दिया या उसको शुरू करने की योजना बनाई है लेकिन उस के बाद ही अगले साल हम उन को कोसें कि वह स्कीम कहां गई, उसका क्या बना, उसे क्यों ख़त्म कर दिया गया तो फिर मैं समझता हूं कि इस ऐंड्रैस की कोई अहमियत नहीं रह जाती।

जहां तक सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, हालात यह हैं कि यहां पर एक टाप है वो एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन इन एकीशिएंसी इतनी ज्यादा है कि ब्यान नहीं किया जा सकता। जहां तक पालिसीज़ का मामला है सरकार में ही इतनी कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं चलता कि वह चाहती क्या है, क्या करती है और जो कहती है वह करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती। जहां तक को-आर्डिनेशन का सम्बन्ध है, मिनिस्ट्रों की आपस में को-आरडीनेशन नहीं, डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्रों के साथ को-आरडीनेशन नहीं, डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट्स के साथ को-आरडीनेशन नहीं और गवर्नर साहिब ने यहां पर यह कहा कि आपोजीशन गवर्नमेंट के साथ को-आपरेट करे क्योंकि आपोजीशन भी तो गवर्नमेंट का एक विंग ही है। मैं तो यह कहूंगा कि आपोजीशन की तरफ से को-आपरेशन का सवाल तो तब पैदा होता है जब कि खुद मिनिस्टर की मिनिस्टर के साथ डिपार्टमेंट की मिनिस्टर के साथ और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट के साथ को-आपरेशन हो एक दूसरे के काम में को-आरडीनेशन हो। फिर तो आपोजीशन की को-आपरेशन से देश का सूबे का फायदा हो सकता है लेकिन सवाल इस स्टेट के अन्दर यह है कि अगर एक मिनिस्टर एक काम करने का हुकम देता है तो दूसरा मिनिस्टर उसी की इम्प्लीमेंटेशन को अपने हुक्म के ज़रिए बन्द कर देता है। उसे कैंसल कर देता है। एक मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के लिये अपना नुक्तानिगाह रखता है और दूसरा मिनिस्टर उसकी बाबत दूसरा ही नुक्तानिगाह रखता

है। वह एक दूसरे के काम में अड़चन डलवाने की कोशिश करते हैं। जहां पर ऐसे हालात हों तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ही अन्दाज़ा लगाएं कि उस सूबा के अन्दर लोगों की क्या हालत होगी? वहां पर डैमोक्रेसी किस कदर पनपेगी. . . . वह डैमोक्रेसी जिस की बाबत खुद गवर्नर साहिब ने अपने ऐड्रेस में जिक्र किया है कि इस देश की हकूमत डैमोक्रेसी की इन्स्टी-च्यूशन पर चल रही है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, लोगों की इस वक्त क्या हालत है? लोग महंगाई के नीचे पिस रहे हैं। उन की बुनियादी आवश्यकताएं प्रतिदिन की जरूरतें भी पूरी नहीं हो रहीं, उन को सही इन्साफ नहीं मिल रहा, कहीं किसी केस की रिपोर्ट पुलिस के पास जाकर दर्ज करवानी हो तो उसको रजिस्टर नहीं किया जाता। एक तरफ तो लोगों की यह हालत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस गवर्नर साहिब के ऐड्रेस को पढ़ा जाए तो ऐसे मालूम होता है, ऐसा खूबसूरत नक्शा दिखाई देता है, ऐसी सुनहरी तस्वीर हमारे सामने आती है गोया सूबे के अन्दर सब अच्छा है, सब अच्छा है और कहीं पर कोई मुसीबत या मुश्किल लोगों को पेश नहीं आ रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक एक मसले को एक एक करके अब मैं हाउस के सामने रखूंगा।

जहां तक सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने का सम्बन्ध है, कुछ मिसालें हमारे सामने आईं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरम्यान कुछ दिन लड़ाई होती रही और उस लड़ाई के दरम्यान हमारे सूबा को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसके नतीजे के तौर पर यहां पर इन्डस्ट्री खत्म हो गई, बिज़नेस खत्म हो गई, एग्रीकल्चर को भारी नुकसान हुआ, जो फसलें खेतों के अन्दर खड़ी लहलहा रही थीं वह बरबाद हो गईं, सूख गईं और हमारी सरकार के मुख्य मंत्री और दूसरे मन्त्री हर रोज़ एक से एक नई स्टेटमेंट प्रैस में निकलवाते रहे। कहा जाता था कि कोई फिकर वाली बात नहीं है, आप को बैंकों की तरफ से सहूलियतें मिलेंगी, फलां महकमा की तरफ से यह सहूलियतें मिलेंगी, फलां महकमे की तरफ से यह सहूलियतें मिलेंगी। फलां महकमा यह काम करेगा, फलां महकमा यह काम करेगा, हम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मदद ले ली है। आप किसी प्रकार की कोई चिन्ता न करें। यह सब कुछ होता रहा लेकिन हालत यह है कि जितनी इस तरह की इन की तरफ से स्टेटमेंट्स आती थीं उतनी ही ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ती जाती थी। इन की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स देने के बाद, लगातार मीटिंगें करने के बाद भी कुछ न हो पाया। अमृतसर के अन्दर बैंकों के मैनेजर्स और एजेंट्स के साथ कई एक मीटिंगें की गईं। कभी इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अफसर वहां पर जाते थे तो कभी मिनिस्टर। कभी डायरेक्टर जाता था तो कभी डिप्टी डायरेक्टर। आज पंजाब का मिनिस्टर आ रहा है तो उसी शाम सेंटर का कोई मिनिस्टर। हालत यह थी कि वहां पर सुबाह से ले कर शाम तक कोई तीन, चार या पांच वो. आई.पी.जी. ही रोज़ जाते थे। लोगों के मसलों को सुना जाता था। यह पूछा जाता था कि उन की तकलीफ क्या है। लेकिन उस सब का नतीजा हुआ क्या? किसी भी नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिये एक नया पैसा भी खर्च नहीं हुआ। बार बार यह एलान किया गया कि सैलज टैक्स को वसूल करने की मयाद तीन महीने बढ़ा दी गई है। यहां पर हाउस के अन्दर और बाद हर रोज़ इस सम्बन्ध में पालिसी स्टेटमेंट्स दी जाती रहीं लेकिन अगर महकमा के अन्दर कोई शख्स जाकर कहता है कि गवर्नमेंट ने इस

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

मियाद को बढ़ा दिया है और तीन महीने बाद भी इस टैक्स को जमा करवाया जा सकता है तो डिपार्टमेंट का हेड कहता है कि हमारे पास तो इस किस्म की कोई इतलाह नहीं पहुंची, हम ने तो आप से नैस वसूल करने हैं और अगर नहीं दोगे तो जेल के अन्दर कर दिया जाएगा, गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस सूबा के अन्दर इस कदर कन्फ्यूजन हो और एक लैवल पर नहीं हर लैवल पर यही स्थिति बनी हुई हो और यहां पर जो बात सरकार की तरफ से एलानिया कही जाती हो तो उसको पूरा न किया जाए तो ऐसी हालत को क्या कहा जा सकता है इसे आप खुद महसूस कर सकती हैं। ऐक्साईज के सवाल पर, नशाबन्दी के सवाल पर मेरे साथी बाबू बचन सिंह जी ने बड़े विस्तार के साथ आप को ध्यान किया है। इसलिये मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एक तरफ तो सरकार यह एलान करती है कि वह सूबा के अन्दर प्रोहिबिशन लाना चाहती है क्योंकि नशाबन्दी करनी है, शराब पीना बुरी चीज है लेकिन दूसरी तरफ इन की जो नीति चलती है वह क्या है? ठेके दिए जाते हैं ज्यादा सेल के आधार पर तो आप अन्दाज़ा लगाएं कि जो ठेकेदार शराब की ज्यादा सेल करेगा वह लाजमी तौर पर उस के लिये अधिक से अधिक ऐडवर्टाइजमेंट करेगा लोगों को ज्यादा शराब पीने के लिये प्रेरणा करेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से सरकार के अपने कामों के अन्दर कन्फ्यूजन नहीं तो और क्या है? हर लैवल पर... चाहे वह इन्डस्ट्री का मसला हो, चाहे ऐक्साईज का सवाल हो, चाहे इकानोमी का मामला हो, चाहे ऐग्रीकल्चर और रीहैबिलिटेशन का सवाल हो यानि कोई भी मामला क्यों न हो प्राईसिज का मामला हो या कुरप्शन का हो एक बहुत भारी कन्फ्यूजन सरकार ने पैदा किया हुआ है।

**Sardar Gurnam Singh :** This is not confusion but this is dishonesty.

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** मैं सरदार गुरनाम सिंह जी के साथ बिकूल एग्री करता हूं कि यह एक बड़ी जबरदस्त डिसग्रानैस्टी है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप प्राईसिज के मसले को ही लें। हमारी सरकार इस सम्बन्ध में सदा से ही यह एलान करती आई है कि हम कीमतों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जमीन आसमान एक कर दिया और कहा गया कि हम ने यह किया है, वह किया है लेकिन फिर भी प्राईसिज कम नहीं हुई। और इस के लिये जिम्मेदार कौन है? मैं तो यह कहूंगा कि इस के लिये खुद सरकार जिम्मेदार है कि जो प्राइक्ट्स खुद सरकार के कन्ट्रोल में हैं, जो जो चीजें सरकार खुद बनाती है और जनता में बेचती है सरकार उन चीजों की प्राईस भी कन्ट्रोल नहीं कर सकी, उन चीजों को भी महंगे होने से नहीं रोक सकी। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि गलती अपनी और दोष दिया जाता है व्यापारियों को, इंडस्ट्रियलिस्टों को और छोटे छोटे दुकानदारों को। उन को डी.आई.आर. के अधीन जेलों के अन्दर भेजा जाता है। मैं समझता हूं कि उन को दोष देना बेकार का काम है जब कि सरकार के अपने यूनिट्स जो काम करते हैं, वह टाप प्राफिट कमाते हैं। मैं आप के सामने एक नहीं कई मिसालें रख सकता हूं। बिजली को देखें। सरकार कितनी महंगी बिजली देती है जबकि इस को बहुत सस्ती पड़ती है। फिर फर्टीलाइजर है। यह खेती के लिये कितना ज्यादा जरूरी है। अन्न की कमी के कारण आज यह देश सारी दुनियां में भिखारी बना हुआ है। दूसरे देश यह समझने लगे हैं कि हिन्दुस्तान तो एक भूखाना देश है। यहां तक कि इटली जैसा यतीम देश भी आज हमारे लिये नुमायशें लगा कर पैसा इक्कठा कर

रहा है। आर्टिस्टों ने चित्र बना कर दिये हैं उस पर टिकट लगा कर हिन्दुस्तान की भूखी जनता के नाम पर रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। यह हालत है हमारे देश की, यह इमेज है कि यहां के लोग भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं वहां पर सरकार उस फर्टिलाइजर को जो कि अन्न के पैदा करने के लिये इतना जरूरी है उस पर नफा कमा रही है। इस पर सरकार का क्या खर्च आता है। बिजली और पानी। मगर उसकी कीमत कितनी ज्यादा रखी हुई है। इस लिये एक बड़ी जरूरी बात मैं आप के नोटिस में लाना चाहता हूं। यह फर्टिलाइजर स्माल-स्केल इन्डस्ट्री के जरिये जगह जगह पैदा किया जा सकता है। आज अपने देश में फर्टिलाइजर सारी दुनियां से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। जापान जैसा देश जो कि इतना छोटा है उस ने इन्टेंसिव खेती के जरिये और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर के यहां के 3 प्रतिशत के मुकाबिले वहां पर 47 प्रतिशत फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है—अपनी प्रोड्यूस को बहुत बढ़ा लिया है। इस फर्टिलाइजर को स्माल-स्केल इन्डस्ट्री के जरिये पैदा किया जा सकता है। मेरे शहर के एक आदमी ने स्माल-स्केल इन्डस्ट्री वाले ने दरखास्त दी कि उसे स्माल-स्केल पर फर्टिलाइजर पैदा करने की इजाजत दी जाए। मगर उसे कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस की इजाजत नहीं देती। छोटे लोगों को इस लिये लाइसेंस नहीं दिया जाता क्योंकि लाइसेंस तो देने हैं बिरला और टाटा को और उन की मनापली बन जायगी। (तालियां) और यह इस लिये रखी जायगी ताकि फर्टिलाइजर की कीमत कम न हो। अगर यह छोटे पैमाने पर फर्टिलाइजर बनाने की इजाजत दें तो पंजाब में इन्टेंसिव फार्मिंग हो सकती है। और हिन्दुस्तान की जरूरतों को सिर्फ पंजाब ही पूरा कर सकता है। (तालियां) यहां का किसान मेहनती है, यहां का कारीगर होशियार है वह मेहनत करके कमी को दूर कर सकते हैं और इन को बाहर विदेशों में जा कर यहां की जनता की भुखमरी की तसवीर खींच कर पैसा मांगने की जरूरत न रहेगी मैं डिप्टी स्पीकर साहिब महंगाई की बात कर रहा था। रेलों का किराया सरकार के पास है, टैलीफून सरकार के पास हैं। क्या इन के किराये कम हुए हैं। इस के रेट्स पहले से एकदम दुगने कर दिये हैं। टैलीफून की जरूरत पड़ती है इन्डस्ट्री के लिये, ट्रेड के लिये, दुकानदार को और दूसरे लोगों को। अब रेट डबल कर दिये हैं सब को 15 पैसे देने पड़ेंगे। अब भला इन का इस में क्या खर्च बढ़ा है? फिर मिल्क प्राइड्स हैं जिन को अब सरकार ही बनाती है। लोगों के हाथों से यह काम सरकार ने छीन लिया है वह क्रीम नहीं बना सकते, मखन नहीं बना सकते, घी नहीं बना सकते। उनकी डेरीज बन्द हो गई हैं, कारोबार ठप हो गए हैं। सब कुछ अब सरकारी प्लांट्स में बन रहा है। आप हैरान होंगे कि बेरका में जो घी बनता था उस का दाम आठ रुपए से बढ़ा कर दस रुपए कर दिया गया है। तो इस महंगाई के लिये पंजाब का बनिया जिम्मेदार है जिस से यह काम छीन लिया गया है। सारा काम आप ने सम्भाल लिया, तो क्या जनता को इस से कोई राहत मिली, क्या आठ रुपये से भाव कम हो कर सात रुपये हो गया? मखन निकालना भी बन्द कर दिया और आज मखन का भाव साढ़े दस रुपये किलो है। यह महंगाई कौन कर रहा है? यह घी दूध की हालत उस देश में है जहां थी दूध की नदियां बहती थी। आज यहां पर योरूपियन देशों से कहीं ज्यादा यह महंगे हैं। यह चीजें महंगी इसलिये हो गई हैं कि इस काम को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। आज क्रीम वगैर बनाने के इजाजत दे दें तो आज यह सस्ती हो सकती है। ट्रांसपोर्ट सरकार के हाथ में है। क्या इस में किराये

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

कम हुए हैं? क्या रेलवे फेयर कम हुई हैं? क्या बिजली के रेट कम हुए हैं? यहां पर महंगाई सरकार की गलत नीतियों के कारण है। फूड जोन्ज बनाए हैं। यह भी गलत बात है। आज देश में खाने पीने की चीजों का अकाल है। कई सूबों में भुखमरी है। वहां पर गेहूं 70-80 रुपये मन बिक रहा है। मगर पंजाब में यह चीजें सड़ रही हैं। इसी हाउस में नवम्बर अक्टूबर के सेशन में मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दी जिसमें कहा गया था कि पंजाब की मंडियों में चने को घुन लग रहा है। चना ऐसा अनाज है जिसे दो महीने के बाद घुन लग जाता है। बाहर सरकार भेजने नहीं देती आप खरीद नहीं रही। तो मंडियों में बोरियों में पड़ा है, नुकसान हो रहा है। मुख्य मन्त्री ने कह दिया कि मैंने आर्डर कर दिये हैं कि चना खरीदा जाए मगर हालत वैसी की वैसी ही रही। पता नहीं इन के आर्डर किस फाईल में, किस रूटीन में, किस दफ्तर में, किस चक्कर में घूमते रहे। पंजाब से गेहूं बाहर नहीं जा सकता। यहां के किसान को गेहूं बहुत सस्ते भाव बेचना पड़ रहा है, वह बाहर नहीं ले जा सकता जहां पर गेहूं 70 रुपये मन बिक सकता है। ब्लैक मार्केट होती है, स्मगलिंग होती है मगर सरकार अपनी गलत नीति पर डटी रहेगी। हालांकि उससे देश को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। यह सिर्फ डागमाज है इन को खत्म करें और इस समस्या को हल करने की तरफ कदम उठाएं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं वार हिट इकौनोमी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस लड़ाई के कारण बहुत से लोग बेकार हुए, इंडस्ट्री खत्म हुई, व्यापार खत्म हुआ, खेतों के अन्दर कारोबार खत्म हुआ, कुछ काम काज इन्होंने खुद बन्द कर दिये आर्डीनेंस लगा कर, हलवाई यह काम नहीं कर सकते, ड्राट आ गया, बिजली कम हो गई, दुकानों का टाईम फिक्स हो गया, इंडस्ट्री क्रिपल हो गई। सरकार ने क्या किया टाल प्रामिजज किये जो कि पूरे न हो सके। चाहिये तो यह था कि सरकार कहती कि हमारे पास इतने पैसे हैं और हम इतनी मदद कर सकते हैं। अगर इतनी मदद से आप का काम चल सकता हो तो ठीक है वरना आप अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करें। मगर हमारी सरकार ने कहा कि आप फिक्र न करो हम आप की बेशुमार मदद करेंगे, हम ने करोड़ों रुपया सैंटर, एल. आई. सी और दूसरी जगह से लिया है आप जितनी मर्जी दरखास्त दें हम लोन देंगे। मगर हुआ यह कि दो लाख से ज्यादा लोन न दिया जा सका। लोगों ने हजारों ऐप्लीकेशन दी, अश्टाम खरीदे, वैरीफिकेशन करवाई और इस तरह से वार हिट होने के बावजूद दो तीन सौ खर्च किया हजारों आदमी चक्कर काटते रहे मगर हुआ कुछ नहीं। यह वादे तो जनता के साथ धोखा था। बाबू बचन सिंह जी ने ट्रकों का जिक्र किया था। मुझे पता है कि अमृतसर के ऐसे मालिक हैं जिन के ट्रक नष्ट हो गए हैं, बाम्बिंग में ब्लास्ट हो गए उन्होंने क्लेम दिये हैं मगर उन को अभी तक कुछ नहीं मिला। फिनांसियज को उन को किस्ते देनी पड़ रही हैं, सरकार क्लेम नहीं दे रही है। वह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में धक्के खाते फिर रहे हैं, कारोबार बन्द हो गया है, ट्रक रहा नहीं, उन का बुरा हाल है। सरकार ने इस तरह के वार हिट लोगों की हालत को सुधारने के लिये क्या किया है?

डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर साहिब ने अपने ऐड्रेस में कहा है कि उन की सरकार डेमो-क्रैटिक इन्स्टीच्यूशन को मान्यता दे रही है। और यह जो अभी सैंटर में चेंज हुई है वह डेमोक्रेसी

को वजह से ही हुई है और इस की महानता का सबूत है कि यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी के बारे में हमारे गवर्नर साहिब ने कहा है कि यह सरकार डेमोक्रेटिक इन्स्टीच्यूशन के मुताबिक चलाई जा रही है। और यहां पर यह भी कहा गया कि डेमोक्रेसी की वजह से ही था कि किस तरह स्मूथली सैंटर में चेंज आफ लीडरशिप हुई। हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इस में तो किसी को शक नहीं, पर दूसरी तरफ अपने हाथों से ही सरकार डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्ज को खत्म कर रही है। आज सूबा के अन्दर म्युनिसिपल कमेटियों को तोड़ा जा रहा है। कहीं पर सुपरसीड किया जा रहा है और चुनाव नहीं होने दिए जा रहे। आज अमृतसर की म्युनिसिपल कमेट्री की यह हालत है कि 15 साल से ज्यादा हो गए हैं चुनाव नहीं किए जा रहे। जब सवाल आता है तो ईश्वर ने इन की मदद कर दी कि लड़ाई आ गई लेकिन अब तो फौजें भी वापिस आ गई हैं और 26 फरवरी को वागा बार्डर तक का इलाका हम छोड़ कर आ जाएंगे और पाकिस्तानी भी अपनी जगहों पर वापिस चले जाएंगे। अब अमृतसर में चुनाव न करवाने की क्या वजह है? और मुझे यह डर है कि इन्होंने आइन्दा दो साल तक इस बात का नाम नहीं लेना। क्या डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्ज के मुताबिक जनता को अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह स्थानीय शासन में भाग लें। जिस ढंग से इस चुनाव को हर बार पोस्टपोन किया जा रहा है इस से डेमोक्रेटिक सिस्टम की तो कबर खोदी जा रही है। (घंटी)

मैं डिप्टी स्पीकर साहिब, एक दो प्वायंट और कहना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन के इनएफीशेन्सो के बारे में जिक्र करके अपना आखरी प्वायंट आप के पास रखूंगा जिस के लिए कि मैं यहां पर आया हूं और वह आखरी प्वायंट आज कल का बर्निंग टॉपिक है।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का तात्लुक है मैं इस के इनएफीशेन्ट होने की मिसाल देना चाहता हूं जिसको सुनकर आप भी हंसेंगी। मिनिस्ट्रों का यह हाल है कि इनकी कोई सुनता ही नहीं और न ही कोई इन के कहने पर अमल करता है। अमृतसर के एक आदमी को चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा कि तुम्हें प्रापर्टी टैक्स में छूट दी गई है और कोई पैनलटी नहीं ली जाएगी लेकिन उस को नोटिस आ गया कि पैनलटी दी जाए। उस आदमी ने वह नोटिस मुझे दिया और मैंने कहा कि मैं इसे चीफ मिनिस्टर साहिब के पास ले जाऊंगा। मैंने यहां पर वह कागज मुख्य मंत्री को दिखाया यह बहुत गर्म होने लगे कि यह कैसे हो सकता है। मैं अभी देखता हूं आप मेरे पास यह कागज रहने दें हालांकि मुझे उस आदमी ने हिदायत की थी कि देखना कहीं कागज गुम न हो जाए लेकिन फिर भी मैंने मुख्य मंत्री को वह कागज दे दिया। इन्होंने पता नहीं किसी को टैलीफोन किया किसी को झाड़ा लेकिन वह कागज गुम कर दिया। मैंने फिर भी मुख्य मंत्री की इज्जत बचाने के लिये उस आदमी को कह दिया कि मैंने दो चार बार अपने कागज जेब से निकाले थे तो आप का कागज कहीं मुझ से गुम हो गया है। और हो सकता है कि होस्टल के कमरे में ही रह गया हो। अब आप देखें हैरान होने वाली बात है कि तीन हफ्ते के बाद वही कागज पटियाला के कमिश्नर की तरफ से रजिस्टरी होकर उस आदमी को मिल जाता है और हुकम होता है कि तुम कहते हो कि तुम से पैनलटी न ली जाए इस लिये तुम 27 तारीख को पटियाला में पेश हो जाओ। (हंसी) वह कागज ले कर मेरे पास आया कि तुम तो कहते थे कि कागज गुम हो गया है लेकिन यह तो मेरे पास वापिस आ गया है। डिप्टी स्पीकर साहिब, यह हालत हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की है कि अफसर इन मिनिस्ट्रों का

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

कहा नहीं मानते। मैं तो हैरान हूँ कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की यह हालत हो वहाँ पर यह मिनिस्टर किस तरह कुर्सियों पर अपनी आत्मा को मार कर और दबा कर बैठते हैं और इन को इन गद्दियों का इतना लालच है कि इन्हें छोड़ भी नहीं सकते। (धंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने सिर्फ एक ही बात और अर्ज करनी है।

आज सूबा के अन्दर इस स्टेट की रिडिमार्केशन लिगविस्टिक बेसिज पर किए जाने का चर्चा चल रहा है। इस का यह हल नहीं कर सकते जब तक सर्वसम्मति न हो। और इस मामले को सरकार खुद उठा उठा कर पैचीदा बना रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपने आनरेबल फ्रैंड कामरेड शमशेर सिंह जोश से मुतफिक हूँ कि यह मसला आज का नहीं मुदत से पुराना है। 1947 से पहले का मसला है इस के बारे में मास्टर तारा सिंह ने कहा था कि :

“The Sikhs have as good a claim for an independent Sikh State as the Musalmans. The claim for a Muslim Pakistan should not be conceded to Musalmans without at the same time conceding the claim for an independent sovereign Sikh State to the Sikhs.”

**Sardar Gurnam Singh :** Does it relate to the prepartition demand ?

**डा. बलदेव प्रकाश :** यह उनका प्रीपार्टीशन का क्लेम था और इसके बाद आपटर पारटीशन यही क्लेम जारी रहा। और आज भी इसी बात की कोशिश की जा रही है। ओल्ड वाइन इन न्यू बाटलज रख कर पेश की जा रही है। आज पंजाब में इस तरह का कोई मसला नहीं है। यहाँ पर प्राब्लम लिगविस्टिक बेसिज पर सूबा बनाने की नहीं। यहाँ पर प्राब्लम है डिक्लेपमेंट का। कुरप्शन को दूर करने का मसला है। लेकिन यह पोलिटीकल सवाल बना कर और प्रस्टीज का सवाल बनाकर कम्यूनल डीमांड लिगविस्टिक बेसिज का नाम दे कर पंजाब की टांगे खींच रहे हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हैरान होता हूँ कि सरदार गुरनाम सिंह जैसे काबिल आदमी जो हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हों इस ख्याल से कि दोबारा भी इलैकशन में रिटर्न होना है और हम ने पालेटिक्स में रहना है प्रिन्सीपल को जानते हुए कि पंजाब में इस तरह की कोई प्राब्लम नहीं है कुछ कहें तो हैरानी होती है। उन्होंने कहा कि इलाका की तरक्की के लिये यह जरूरी है कि सैल्फ गवर्नमेंट हो (विघ्न) सैल्फ डीटर्मिनेशन हो (हंसी) जब अंग्रेज का वक्त था तो हम होम रूल मांगते थे। तो आज मैं इन से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज किसी अंग्रेज की हकूमत नहीं है किसी इस डिस्ट्रिक्ट को दूसरे के ऊपर हकूमत करने का सवाल नहीं है। फिर इन्होंने यह भी कहा कि जब तक किसी देश में विदेशी ताकत रही है उस इलाके की तरक्की नहीं हो सकी। क्या यहाँ पर किसी विदेशी की हकूमत आज है दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहिब के एड्रेस में कहा गया है कि डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन को हम ने आगे ले जाना है लेकिन किस ढंग से इस को लेजाया जाएगा वह यह नहीं कि किसी को थ्रो किया जाए या कोई कोअर्शन का तरीका इस्तेमाल किया जाए। और इन्हीं तरीकों से आज पंजाब की डीमार्केशन के बारे में बात चीत की जा रही है जो डेमोक्रेसी के असूलों के खिलाफ है। यह ढंग डेमोक्रेसी को आगे ले जाने वाले नहीं। मैं आनरेबल फ्रैंड श्री जोश से सहमत हूँ हालांकि उनका सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया से है और उन्होंने डेमोक्रेसी के ढंग से अपने आपको एडजस्ट करने की कोशिश की है लेकिन जिन

डिमोकैटिक कन्वੈन्शन्ज को सरदार गुरनाम सिंह जी कायम कराना चाहते हैं आप इस का अंदाजा लगाएँ। इन्होंने अपनी तक्रार में कहा था कि अगर इन के खयाल के मुताबिक लिगविस्टक स्टेट न बनाई गई तो पंजाब के अन्दर महाराष्ट्र और बम्बई की घटनाओं को दोहराया जाएगा अगर ऐसी बातें इतने काबल जज की तरफ से आएँ तो यह निहायत अफसोसनाक है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आखिर में मैं एक बात कह कर अपनी जगह ले लूंगा। वह यह कि हम ने इस बात का तहैया किया हुआ है कि पंजाब की डिवैलपमेंट को पंजाब के विकास की किसी हालत में भी रुकने नहीं देना। चाहे यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या पंजाबी रिजन की डिमांड की शकल में क्यों न हो। हम ने तो पंजाब का विकास करना है। चाहे हमारे लिये अलग फंड रख कर विकास क्यों न करना पड़े। लेकिन अगर कोई रिजनल नौइयत के आधार पर पंजाब के अन्दर फूट के बीज बोना चाहे, जिस तरह की धमकियाँ आज इस हाउस में सुनने को आईं हम इस चीज को हरगिज बरदाश्त नहीं करेंगे। इसके लिये चाहे हमें सबकुछ कुरबानियाँ क्यों न देने पड़ें।

#### PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR GURNAM SINGH

सरदार गुरनाम सिंह : on a point of personal explanation, Madam. डिप्टी स्पीकर साहिबा, एिषे हाउस ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲਫਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

उपाध्यक्ष : उन को तो बात पूरी कह लेने दो (Let him first complete his point.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : हमारी पार्टी सिस्टम से उनका क्या मतलब है ?

सरदार गुरनाम सिंह ; चਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂਸਤੋਖੂਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਨ ਸੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं ने यह नहीं कहा था। मैं ने तो यह कहा था कि अगर यहां भी ऐसे हालात हो गए तो मजबूर हो कर हमें अपनी बात सुनानी पड़ेगी...

उपाध्यक्ष : यह सुनने और सुनाने की आपस की बातें हैं यह हाउस में क्यों करते हैं आपस में ही कर लिया करें। (Why should anything relating to their views and counter views be brought in the House? They should settle such things mutually outside the House.)

## DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS (RESUMPTION) (Not Concluded.)

श्री अमर सिंह (नारनौंद एस.सी.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस के अन्दर कई दिनों से बहस चल रही है, बहुत से मੈम्बर इधर से बोले हैं और बहुत से उधर से बोले हैं। इससे पहले कि मैं अपने विचार गवर्नर के ऐड्रेस पर रखूं मैं सब से पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री एन वी. गैडगिल और श्री एच सी. भाभा और बहुत सी मायानाज़ हस्तियां जो इस मुल्क की खिदमत करते करते हम से जुदा हो गई मैं उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूं ।

इस के साथ ही मैं इस ऐड्रेस के चन्द एक जरूरी आईटम्ज़ के मुतअल्लिक अपने विचार आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है मैं पहले पुलिस डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को ही लेता हूं यह दिन बदिन बढ़ती जा रही है जितनी हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होती जा रही है उतने ही उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में तीन तो एडीशनल आई. जी. हैं जहां यू.पी. में एक भी नहीं जो कि इस से बड़ा सूबा है। वहां पर महज़ एक पी.टी.सी है मगर यहां पर दो एडीशनल पी.टी.सी. हैं। एक आदमी जिस के लिये जनरल मैनेजर की पोस्ट पहले क्रिएट की गई उस के लिये एक एडीशनल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट क्रिएट की गई एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा अगर हाई लैवल पर देखा जाए तो यह बढ़ता जा रहा है और लोअर लेवल पर इसकी छांटी होती चली जा रही है। आप देखें कि यह कहां का इन्साफ है कि एक एडीशनल पी.टी.सी. तो बढ़ाया जा रहा है मगर इस के साथ ही लोअर लेवल की 25 पोस्टें खत्म की जा रही हैं। इन गरीबों को अगर तरक्की देने का सवाल आये तो 5-6 महीने तक एक एक मेज़ पर केसिज़ पड़े रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर रिडकशन करनी भी है तो यह लोअर लेवल से नहीं होनी चाहिए बल्कि हायर लेवल से शुरू की जानी चाहिए। आप देखें कि पहले महज़ एक फाईनैशल कमिश्नर होता था मगर अब कई फाईनैशल कमिश्नर बना दिए गए हैं। मुझे तो इस मौके का यह शेर कहना पड़ता है :—

दुनिया के मुसाफिर खाने में महमान बदलते रहते हैं।

किस्सा तो वही देरोना है उनवान बदलते रहते हैं।

जिन बातों के लिये हम ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी आज वह सारे काम बिल्कुल वरअक्स किये जा रहे हैं। हिस्टरी शाहद है कि वाकई वरअक्स काम हो रहे हैं। आज इस राज्य में लैजिस्लेटर्ज़ की इज्जत नहीं न किसी को किसी कायदे कानून का डर है। अपनी मन मानियां की जाती हैं इस की एक जीती जागती मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह कि 14 तारीख को प्रेमु नाम का दिहाती जो कि ज़माना गांव का रहने वाला था पुलिस की कस्टडी में पीट पीट कर जान से मार दिया जाता है। इसी दिन इस को पुलिस ने ज्यूडीशल मैजिस्ट्रेट से रिमांड हासिल करके गिरफ्तार किया था रात को उसे इतना पीटा कि वह जान से मारा गया।

उपाध्यक्षा : इस पर एक काल एटेंशन था जो एडमिट नहीं हुआ आप वजट की डिस्कशन पर ले आए। (I think a call a ttention motion on this subject was

received but not admitted. The hon. Member may refer to that matter during the discussion on the Budget.)

श्री अमर सिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि वारसों ने उसकी लाश मांगी वह भी नहीं दी गई। इसी तरह से मेरे हलके में एक हरिजन लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा गया मगर मुझे बड़े दुख से यह बात कहनी पड़ती है कि पुलिस आज तक इस केस को ट्रेस भी नहीं कर सकी। जहां तक सर्विसिज में कुरप्शन का सवाल है डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि जैसे मुल्क दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है उसी तरह से कुरप्शन में भी बड़ी भारी तरक्की इस मुल्क ने की है। आज महकमा नहर के ओवरसीयर एस.डी.ओ. लोगों को नाजायज तंग करके धड़ाधड़ पैसा खा रहे हैं। जब हमारे बहादुर जरनैल बार्डर पर लड़ रहे थे उस वक्त इधर इन्स्पेक्टर, पटवारी, ओवरसीयर और एस.डी.ओ. रिश्वत बटोरने के मोर्चे पर लड़ रहे थे। मुल्क के हालात इस तरह के खराब हो गए हैं जो निहायत ही अफसोसनाक हैं। यह मालूम नहीं कि अब इस मुल्क का क्या अंजाम होगा।

ऐ कामरेड, पाजेब तेरी वे खत से नगमे गाती है,

गर रवा रहा यह महफल का अंजाम ना जाने क्या होगा।

हमारे इलाका में ऐजुकेशन की यह हालत है कि हांसी सब डिवीजन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के बराबर है वहां पर तो कालेज दे दिया गया मगर हमारे इलाका में जहां पर लोगों ने पैसा इक्ठ्ठा करके बिल्डिंग तामीर की और सरकार से कालेज की मांग की वहां कोई कालेज नहीं दिया गया। और इस बारे में कोई सुनवाई नहीं। जहां तक हाई स्कूलों का ताल्लुक है हमारे पांच छः हाई स्कूल पिछले साल अपग्रेड किए गए। किसी जगह भी हैडमास्टर नहीं। बार बार लिखने के बावजूद जवाब नहीं मिलता।

जहां तक शैड्यूल्ड कास्ट्स का ताल्लुक है गवर्नर साहिब के ऐड्रेस में सफा 25 पर कितनी खूबसूरती के साथ लिखा है :

“My Government is wedded to the ideal of justice, economic as well as social. It is, therefore, imperative that we pay special attention to the programme for the betterment of the economic and social conditions of the Scheduled Castes, Vimukt Jatis and other Backward Classes.”

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 1962 में यहां पर हरिजन कल्याण ट्रस्ट के नाम पर से इसी हाउस में एक बिल लाया गया और वह पास हुआ। उस के तहत 3 करोड़ 86 लाख रुपया इक्ठ्ठा किया गया। मैं आप के जरिए अपनी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इतनी खूबसूरती से यह लिखा गया है लेकिन उनके इकनामिक स्टेट्स को बैटर बनाने के लिये आज तक एक पैसा भी उस फंड में से जो हरिजनों को डिमारेलाइज करके, बदनाम करके इक्ठ्ठा किया गया, खर्च नहीं किया गया। हम बार बार सवाल पूछते हैं इनजस्टिस मिनिस्टर साहिब से, वेलफेयर मिनिस्टर साहिब से कि इस पैसे को खर्च किया जाए लेकिन जवाब में इत्तलाह मिलती है कि अन्डर कन्सिड्रेशन है। अब उस के बारे में छानबीन की जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चाहता हूं कि .... (विघ्न)

कंवर राम पाल सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मिनिस्टर फार इन जस्टिस कौन से मिनिस्टर हैं ? हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर फार इन जस्टिस नहीं है ।

उपाध्यक्ष : चौधरी अमर सिंह, आप और कितना समय बोलेंगे ? (May I know from Chaudhri Amar Singh as to how much more time he will take ?)

श्री अमर सिंह : जबहुकम मिलेगा मैं बैठ जाऊंगा । मैं यह अर्ज कर रहा था कि पिछली सरकार ने जो सरदार प्रताप सिंह कैरों की सरकार थी उसने यह टैक्स लगाया और यह 3 करोड़ 86 लाख रुपया इक्ठ्ठा हुआ । उसके बाद 1 करोड़ 14 लाख रुपया एडीशनल प्लानिंग कमिशन की तरफ से लेकर इसमें डालने का फैसला किया । यह 5 करोड़ रुपया बना कर हरिजनों की हालत सुधारने का फैसला हुआ । वह पैसा इक्ठ्ठा तो हो गया लेकिन खर्च का प्रंदाजा नहीं । जब हम हरिजन लैंजिसलेटर्ज, कामरेड साहिब या हरिजन मिनिस्टर साहिब से इस के बारे में कहते हैं तो वह कहते हैं कि स्कीमें बनाओ । मैं कहता हूँ कि वह रुपया उनकी रोटी पर खर्च करो । इस से उन्हें रोटी कमाने के योग्य बनाओ ताकि हरिजनों का स्टेट्स ऊंचा हो, स्कीमें उनके पास हैं, वह पैसा खर्च नहीं करना चाहते । एक लाख 25 हजार एकड़ जमीन सतलुज बेट की हरिजनों को देने के लिये पहली सरकार ने आन दी फ्लोर आफ दी हाउस वायदा किया था कि हम इस सारी जमीन को जो सतलुज बेट में रोपड़ के पास है हरिजन और लैंडलैस टेनेन्ट्स को देंगे । वह जमीन जो आदमी खेती करना नहीं जानता, जिसको यह नहीं पता कि गेहूँ का पौधा कितना बड़ा है और गेहूँ कितना पानी मांगता है 1,000 एकड़ जमीन पंजाब के हरिजनों और पंजाब के किसानों को बीज देने के लिये बिरला को दे दी गई है । हमारे साथ यह कितनी ज्यादाती हुई है । मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहिब और गवर्नमेंट इस बात पर विचार करें यह हमारे साथ नाइन्साफी है । इस डील को कैसल किया जाए । गरीब हरिजन और लैंडलैस टेनेन्ट्स को यह जमीन दी जाए । (घंटी)

Deputy Speaker : Shri Babu Dayal Sharma.

श्री बाबू दयाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, यह जो रैजोल्यूशन पेश किया गया है...

श्री अमर सिंह : मैं ने वाइंड अप नहीं किया ।

Deputy Speaker : I have called upon Shri Babu Dayal,

श्री अमर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम ।

Dputy Speaker : I do not allow any point of order.

श्री अमर सिंह : मेरा प्वायंट आफ आर्डर तो सुन लें ।

**Deputy Speaker :** I do not allow your point of order. Will you resume your seat ?

फिर आप कहते हैं कि बोलने का वक्त नहीं मिलता। (I do, not allow your point of order. Will you take your seat ? Then the hon. Members complain afterwards that they did not get time to speak.)

**श्री अमर सिंह :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर।

**Deputy Speaker :** Will you take your seat ?

**Chaudhri Darshan Singh :** Madam, on a point of order.....

**Deputy Speaker :** Please take your seat.

**Chaudhri Darshan Singh :** I can take my seat. I can obey your order but I have a point of order to raise.

**Deputy Speaker :** I do not allow your point of order.

मेजर साहिब, यह जितने प्वायंट आफ आर्डर होंगे मैं उतना वक्त काट लूंगी। (I do not allow his point of order. (Addressing the Minister for Revenue) I shall deduct the time taken up in raising points of order.)

**चौधरी दरशन सिंह :** मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।

**Deputy Speaker :** I never allowed you.

**Chaudhri Darshan Singh :** Point of order is a right of the Member and I demand it.

**Deputy Speaker :** This is the discretion of the Chair.

**Chaudhri Darshan Singh :** Point of order is not a discretion of the Chair. It is the right of the hon. Members. It is the right of every Member to raise a point of order.

**Deputy Speaker :** Chaudhri Darshan Singh, you are losing your time now.

**श्री अमर सिंह :** मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि हाउस में कई मैम्बर तो 40, 40 मिनट बोलते हैं जब यह फैसला हो गया है कि हर मैम्बर 15 मिनट बोलेगा तो मुझे इतना टाइम तो दिया जाए।

**उपाध्यक्षा :** चौधरी अमर सिंह, आप बैठेंगे या नहीं? (Will Chaudhri Amar Singh resume his seat or not?)

**श्री अमर सिंह :** मैं आपके आर्डर की कदर करता हूँ।

**श्री बाबू दयाल शर्मा :** (पटौदी) : यह रैजोल्यूशन गवर्नर साहिब को वधाई देने के लिये पेश किया गया है। मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जो कुछ उन्होंने आदेश दिया है वह सराहनीय है परन्तु.....

ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ।

ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ ਕੋਟ ਕਰੋ ਜਿਥੇ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗੀ। (I shall quote it.)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਦਯਾਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਮੈਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰ ਸੇਂਧ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ।

“but regret that no mention is made for the revival of the Salt Industry of Gurgaon District and to give for most priority to supply the electric power as promised by the Government in 1953 and supply fresh drinking water to all such villages and towns where there is salt water.”

ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਦਯਾਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਉਪਾਧਿਕਸ਼ਾ ਮਹੋਦਯ, ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਡਗਾਂਵ ਮੇਂ 1913 ਸੇ ਪਹਲੇ ਸਾਲਟ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਤੀ ਥੀ ਜਿਸ ਸੇ ਲਾਖੋਂ ਆਦਮਿਯੋਂ ਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਤਾ ਥਾ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਗੁਡਗਾਂਵ ਆਰਿ ਫਲੁਖਨਗਰ ਕਾ ਨਮਕ ਆਗਰਾ ਮੇਂ ਜਾ ਕਰ ਈਕਟੁਠਾ ਹੋਤਾ ਥਾ ਆਰਿ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਤਾ ਥਾ। 1913 ਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਏਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਂਬਰ ਲੇਕ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇਂ ਹੈ ਉਸਕਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਆਰਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਲਿਯੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਬਰ ਲੇਕ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਇਤਨਾ ਝਾੜਾ ਨਮਕ ਬਨੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਲਿਯੇ ਕਾਫੀ ਹੋਗਾ। ਪਹਲੇ ਜਗਹ ਜਗਹ ਨਮਕ ਬਨਤਾ ਥਾ।

1.00 P.M.

ਗੁਡਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲਾ ਮੇਂ ਫਲੁਖਨਗਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਰਿ ਕਈ ਆਰਿ ਗਾਂਵ ਹੈਂ ਜਹਾਂ ਪਰ ਨਮਕ ਬਨਤਾ ਥਾ। ਨੂਹ ਤਹਸੀਲ ਇਸੀ ਲਿਯੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥੀ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਨ ਨਮਕ ਬਨਤਾ ਥਾ ਜਿਸ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਤਾ ਥਾ ਮਗਰ ਸਾਂਬਰ ਲੇਕ ਕਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਹੋਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਗੁਡਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲੇ ਕੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਅਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਜੰਗ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ ਹੈਂ ਇਸ ਲਿਯੇ ਆਪ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਮਕ ਪਰ ਸੇ ਬਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਤਹਰੀਕ ਚਲਾਈ ਥੀ ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਪ ਆਰਿ ਹਮ ਜੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਦਮੀ ਕੈਂਦ ਹੁਏ ਥੇ ਆਰਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਆ ਥਾ ਕਿ ਵਹ ਨਮਕ ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਮਗਰ ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਅਪਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਡਗਾਂਵ ਕੀ ਸਾਲਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਰੀਵਾਇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਮਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਕੀ ਤਰਕਿਕੀਯੋਂ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਮਗਰ ਮੁਝੇ ਅਫਸੋਸ ਸੇ ਕਹਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਡਗਾਂਵ ਮੇਂ ਸਾਲਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਫਿਰ ਸੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ। ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਦੋ ਸਾਲ ਸੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਹਰੀਕ ਚਲੀ ਹੁਈ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਕੇ ਡਾਇਰਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਂ ਵਹ ਬਹੁਤ ਪੇਂਜ਼ਟੇਂਕਿੰਗ ਹੈਂ। ਵਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਯਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਸੇ ਚਾਲੂ ਹੋ। ਉਨ ਕੇ ਕਹਨੇ ਪਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਸੇ ਏਕ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਹੋਂਨੇ ਉਪਰ ਸੇ ਹੀ ਪਾਨੀ ਲੇ ਕਰ ਕਹ ਦਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੇਂ ਨਮਕ ਕਮ ਹੈ ਮਗਰ ਵਹਾਂ ਕੋ ਜੋ ਏਕਸਾਇਜ਼ ਏਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੇ ਮਹਕਮੇਂ ਕੋ ਸੁਪਰਿਨਟੇਂਡੇਂਟ ਹੈਂ ਉਨਹੋਂਨੇ ਯਹ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਗਰ ਸੇ ਇਸ ਕਾਮ ਮੇਂ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾਕਰ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਬਨਾ ਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਕੋ ਚਲਾਏ। ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰ ਸਿਰਫ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਯਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਵਹਾਂ ਕੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਹੈਂ ਪਛਿਤ

चिरंजी लाल शर्मा और दूसरे हरियाने के एम. एल. एज. और पण्डित श्री राम शर्मा ने सरकार को कई बार रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट को भेजे हैं कि वह इस की तरफ तवज्जो दे मगर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं दरखास्त करूंगा कि इस इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी रीवाइव किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1953 में जब मैं मੈम्बर बन कर आया था तो उस वक़्त हमारे मौजूदा गवर्नर साहिब वजीर होते थे। उस वक़्त उनकी स्पीच हुई थी। पंजाब में जब थल प्राजैक्ट और हवेली प्राजैक्ट से कितनी ही नहरें निकल चुकी थी तो सर छोटू राम ने कहा था कि हरियाणा को सैराब करने के लिये भाखड़ा डैम बनाया जाए। उस वक़्त सर सिकंदर हयात के जमाने में एजीटेशन भी चलाई गई कि यहां भाखड़ा डैम को लाओ नहीं तो गद्दीयां छोड़ कर बाहर चले जाओ। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि 1953 में सरदार उज्जल सिंह जी ने वादा किया था कि भाखड़ा बनने पर गुड़गांव के जिला को फोरमोस्ट प्रायोरटी दी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां पर जहां पर खम्बे लग थे वह यूँके नूँ ही पड़े हैं बिजली आज तक नहीं पहुँची उस वक़्त भाखड़ा की सिर्फ 23 करोड़ की स्कीम थी जो कि 200 करोड़ तक पहुँच चुकी है जिस में गुड़गांव के जिले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान में भाखड़ा डैम नहर पहुँच गया है जिस का कोई प्रोग्राम नहीं था मगर हमें वादा कर के भी कुछ नहीं दिया गया,। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अलक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो कन्सल्टेटिव कमेटी है उस का मुझे मੈम्बर बनाया हुआ है लेकिन देखता क्या हूँ कि कोई कुनैक्शन भी बगैर रिश्वत के नहीं दिया जाता। तरह तरह के बहाने किए जाते हैं, कहते हैं कि मैटीरियल नहीं है लेकिन दरियाफत करने के बाद पता लगा कि 9 करोड़ 90 लाख रुपये का सामान पड़ा खराब हो रहा है। मैंने पूछा कि बताओ क्यों सामान ऐसे पड़ा हुआ है लेकिन बहाना यह लगाया कि किसी का कंडक्टर नहीं किसी का कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि सामान पूरा खरोदना चाहिए ताकि काम में आ सके। फिर यह कहते थे कापर और जिंक के बगैर काम नहीं चलता। चुनावि हमारे इंडस्ट्री के डीपार्टमेंट ने नानफैरस गेटल पर बड़ी भारी पाबन्दी लगाई और उस का जो नतीजा हुआ वह हम देखते हैं जो पहले दिक्कत थी वही दिक्कत आज भी है। मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आज से 13 साल पहले जो जिला गुड़गांव को बिजली देने का वादा किया गया था वह पूरा किया जाए। तीसरी बात मैं यह करना चाहता हूँ कि जिला गुड़गांव में 450 गांव ऐसे हैं, फारुख नगर सुलतानपुर बगैरा और नूँ के इलाके में जहां से नमक निकलता था वहां पर मीठा पानी नहीं मिलता। गर्मियों के दिनों में जब किसानों के बयाह शादी के दिन होते हैं तो लोगों को खारा पानी पीने से हैजा हो जाता है। खेतों को पानी देना तो दरकिनार उनको पीने को पानी भी आप नहीं दे पाए। मैं गुज़ारिश करूंगा कि वहां कम से कम पीने का पानी जरूर मँहैया किया जाए। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत तरक्की की है मगर जो कमी रह गई है उस को पूरा करने की तरफ तवज्जो दी जाए

एक लार्ड ऐवरबरी ने कहा है

“When money is lost, nothing is lost, when health is lost something is lost and when character is lost, all is lost.”

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे बड़ा भारी दुख होता है यह कहते हुए कि हमारा चरित्र दिन बदिन गिरता जा रहा है। मेरी एक गुज़ारिश यह भी है कि यह सरकार कैरेक्टर डिवैलपमेंट की भी

[ श्री बाबू दयाल शर्मा ]

कोई स्कीम सोच कर बनाए क्योंकि कैरेक्टर गिरता जा रहा है। मुझे खुशी है कि डाक्टर बलदेव प्रकाश जी ने कुछ अच्छे प्वायंट्स दिए हैं। मिसाल के तौर पर कि प्रोहिबिशन जल्दी लागू की जानी चाहिए। मैं भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा करना निहायत जरूरी है वरना आप देखेंगे कि जहाँ पहले गांव में कोई शराब जानता नहीं था अब वहाँ शराब निकाली जाती है, पी जाती है, बेची जाती है और अफसरों तक वहाँ पीते हैं। आपोजीशन वाले नुक्ताचीनी तो बहुत करते हैं लेकिन यह नहीं देवते कि असल बीमारी क्या है। उन्होंने एक मिसाल दी लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि इसमें चीफ मिनिस्टर साहिब का क्या कसूर है। असल जो बीमारी है उसे तो वह टच नहीं करते। इधर उधर की मिसालें देते हैं। असली बीमारी यह है कि सरकारी मशीनरी की वही पुरानी जहनियत है और उसकी जहनियत को हम अभी बदल नहीं सके हैं। इसमें आपोजीशन हमारी बिल्कुल मदद नहीं करती है। हमने कभी आज तक बाहर पब्लिक में इन्हें यह कहते हुए नहीं सुना है कि रिश्वत लेने देना पाप है। मैं पूछता हूँ कि यह जो कुरप्शन कुरप्शन की रट लगाए रखते हैं इन्होंने ने कितने कुरप्ट लोगों को पकड़ाया है। मैं इन से पूछता हूँ कि बताएं कुरप्शन को कैसे रोका जा सकता है। महज बातें करने से तो यह बन्द नहीं होगी ऐसी मिसालें तो मैं भी कई दे सकता हूँ लेकिन सवाल यह है कि इसे बन्द कैसे किया जाए। मैं भी बताना चाहता हूँ कि कैसे 2 जुल्म होते हैं। खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिये यह जो लैंड ऐक्वीजिशन ऐक्ट पास किया गया था कि जो बंजर ज़मीनें हैं और जिन ज़मीनों में 6 फसल तक काश्त नहीं की गई उसे उसके मालिकों से ले कर मुज़ारों को दी जाएं ताकि वह उसे आबाद करके अनाज पैदा करें उस ऐक्ट की जिस तरह गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से मिट्टी पलीद की गई है वह मैं बताना चाहता हूँ। हमारे अलावलपुर में जितनी बंजर ज़मीन थी वह एक कुआप्रेटिव सोसायटी को मारफ़्त मुज़ारों को दे दी गई। होता क्या है कि 4 साल से जो मुज़ारा उसे काश्त कर रहा था उस से वह वापिस ले ली गई। एक कमिश्नर साहिब एक लैंड लार्ड के पास वहाँ जाते हैं और चाए पीते हैं बिसवेदार जिसकी ज़मीन थी वह लैंड लार्ड के घर जा कर मिलता है और कहता है कि साहिब गलती हो गई और पांच फसल की बजाए गलती से 6 फसल लिख दी गई इसलिये मेहरबानी करके हुकम कर दो कि गवर्नमेंट उस ज़मीन को छोड़ दे। ऊपर से कहे जाने पर पटवारी ने सारा रिकार्ड बदल दिया और जो ज़मीन कई साल से बंजर पड़ी थी उसके बारे लिख दिया कि यह ज़मीन बंजर नहीं है। इस तरह ज़मीन छोड़ दी गई। मैं नाम भी बता सकता हूँ लेकिन कमिश्नर साहिब का नाम लेना ठीक नहीं होगा। मैं ने उन से अर्ज किया कि साहिब आपने पैप्सू में तो रिश्वत नहीं ली अब यहाँ क्या हो रहा है। शोर पड़ा तो उसकी इनवायरी कराई गई। तो पता चला कि 6 फसल वाली बात ठीक थी और यह सब फ़ाड किया गया है। ऐस.डी. ओ. की ऐक्सपलानेशन हुई और फिर वह ज़मीन वापिस की गई। लेकिन आगे देखें कि उस गरीब मुज़ारे के साथ होता क्या है। इस ऐक्ट के मुताबिक जुडीशरी को इसमें दखल देने का हक नहीं है। लेकिन होता यह है कि उसी बिसवेदार से अपील करा दी जाती है और कहा जाता है कि इस में जुडीशरी को दखल देने का हक है क्योंकि तहसीलदार की तरफ से बाकायदा नोटिस नहीं इशू किया गया। तहसीलदार जो नोटिस देने वाला था अदालत में आ कर बयान दे देता है कि मैं ने नोटिस इशू नहीं किया। मैं इन दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ इस में चीफ मिनिस्टर का क्या कसूर है। इन्होंने जो मिसालें दी हैं मैं

ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਬਫਿਯਾ ਸਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਰਟਰੀ। ਧਰੁ ਕਸੂਰ ਤੀ ਹੁਸਾਰਾ ਆਰ ਆਪੋਯੀਸ਼ਨ ਕਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਹਰ ਪਫਿਕਰ ਮੇਂ ਜਾਕਰ ਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਕਤ ਦੇਨਾ, ਲੇਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਆਰ ਜੀ ਕੁਰਾਟ ਅਫਸਰ ਹੈਂ ਤੁਨ੍ਹੇਂ ਪਕੜਾਓ। ਤਕ ਧਰੁ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭੀਨਰੀ ਠੀਕ ਹੋਗੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੇ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕੋਈ ਫਾਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ।

**ਤਧਾਧਯਕਸ਼ਾ :** ਕਾਕੂ ਦਧਾਲ ਜੀ, ਅਕ ਆਪ ਕੈਠ ਜਾਓ। (The hon. Member Shri Babu Dayal may kindly now resume his seat.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ** (ਜਗਰਾਉਂ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੱਐਲਕਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ.....

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਆਨ ਨੇ ਪਾਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸੁਬਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਉਠਾਉ ਵਰਨਾ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ।

(The hon. Speaker has already said a lot today in this connection, The hon. Member need not raise such points as the whole time will be taken up in their discussion)

(Interruptions made by Chief Parliamentary Secretary)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਿਤਾਨੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਭੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੀ ਘਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ।

[ ਸਰਕਾਰ ਲਫ਼ਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ]

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜ ਹੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ  $3\frac{1}{2}$  ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4, 5 ਮੰਜ਼ਲੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਨਾਅਹਿਲ ਅਤੇ ਨਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਬਣ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਅਸੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੀ ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਂਵਾਂ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਝਿੜਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ

ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਤੀਲੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੈਸਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਇਕੋ ਦੁਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਫੈਮਿਲੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ।

**उपाध्यक्ष :** आनरेबल मेम्बर लेडी हेल्थ मिनिस्टर को हस्पताल में दाखल करने की बात तथा आपरेशन करने की बात न करें। (The hon. Member should avoid talking of the lady Health Minister falling ill and undergoing an operation.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨ ਆਫ ਮਾਸਿਜ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਅਫ਼ੂਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ (ਘੰਟੀ) (ਵਿਘਨ)।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 40 ਮਿਨਟ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹਾਲੇਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਯੂ. ਐਨ. ਧੋਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗਲ ਰੋਡੀਉ ਵਿਚ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲ ਸੁਣਕੇ 2½ ਘੰਟੇ ਤਕ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ

## [ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਕਨਸਰੰਡ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਅਹਿਲ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਇਆ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ 14, 15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅਨਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਅਨਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਲ 50 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਰਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਸ ਬਰਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਗਵਰਨਰ ਤੁਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. . . . (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :

\* \* \* \* \* (ਸ਼ੋਰ, ਵਿਘਨ) ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ . . . . (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। (When the hon. Member Sardar Lachhman Singh is going to speak, he should think a while as to what he is going to say. )

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਡ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਆਦਮੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ

\*Note.—Expunged as ordered by the Chair.

ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਪਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗਲ ਤੇ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਸਟੇਟ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਡੈਸਪਰੇਟ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਿਖ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਠੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। . . . .

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  
(No please. He may resume his seat. He has already taken a lot of time.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਕਤ ਕਟ ਲੈਣਾ .....

**Deputy Speaker :** Please.....

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

**Deputy Speaker :** Will you please take your seat no .?

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਮੈਂ ਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਹੈ; ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿਨਟ ਦੇ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਮੱਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਨਜ਼ਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

## [ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1938-39 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 96.93 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਂਕੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ 1 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਰੀਫਿਊਜੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਚ 42 ਫੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.....(ਵਿਘਨ) ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਉ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਲਿਖਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕਿਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਉ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਜਣ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਵਜਾਹਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਤੇ ਛਾਏ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਅੜਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਆਫੀਸ਼ਲਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੰਗ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਅੰਗ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਸ ਦਿੰਦੀ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਧਾਈ

ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.....

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** Will you please take your seat ? ਚੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਹੀ ਕਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। Please. (Will you please take your seat? The hon. Member does not listen to the Chair but continues to make his speech This is not proper.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ..... (Interruptions)

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜੀ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਨ 1966 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਛਣਾ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਣ ਸਮਝ ਲੈਣ ਔਰ ਫੇਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। (While referring to Ministers, the hon. Member talked of Mahatma Gandhi saying that they had failed to act upon his advice but in fact the hon. Member himself while talking of Sant Fateh Singh does not care to act upon whatever he says.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ।

**ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ

## [ਚੰਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਐਡਰੈਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਮਾਂਇਡ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਇੰਡੈਕਸ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਿਜ਼, ਬਲਿਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਡਰੈਸ 28 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਫਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਮਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (Thumping from the Opposition) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਕੁਝ ਸੈਲੀਅੰਟ ਫੀਚਰਜ਼ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਵਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਔਰ ਚੌਥੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 5½ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ 3,86,00,000 ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 1,14,00,000 ਰੁਪਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 5,00,00,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ' ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸਾ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 'ਮਰਸੀਆਖਾਨੀ' ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ? ਪਿਛਲੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਵੀ 28 ਸਫੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ 28 ਹੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਐਨਾ ਰੀਲੀਫ ਦਿਤਾ 50,000 ਅਪਰੂਟਿਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 11,000 ਟਿਊਬਵੇਲਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80,000 ਏਕੜ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬਪਾਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬਪਾਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਅਲਗ ਹੈ 80,000 ਏਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਘਟੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕਾਨਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਥੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਤਕਾਵੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਰ ਤਕ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਏ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਸੂਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਲਗ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਬਪਾਸੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਤਕ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਗੜੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੜੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਰੀਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰੀਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਾਏ, ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਉਜੜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੈਵੀਨੀਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੈਠਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 53 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੜਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ ਤਕਾਵੀਆਂ, ਸੀਡ ਤਕਾਵੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਉ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਕਾਵੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੜੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਕਾਵੀਆਂ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੀਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਸਰੀ ਗਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਆਸਾਂ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਅਮੀਰ ਹਨ " **they are cheats, they are dacoits**" ਇਹ ਜੋ ਇਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲੰਗੇਟ ਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਸੌ ਟੁਕ ਦਾ ਪਰਮਿਟ

**[ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]**

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 15—20 ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਘੰਟੀ) ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿਨਟ ਦਿਉ, ਸਿਰਫ 7 ਮਿਨਟ ਹੋਏ ਹਨ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲੈਕਮਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਜ ਉਠਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੀਕਿਊਰਿਟੀ ਲਈ ਗਰੀਬ ਬਚਿਆਂ ਤੋਂ 8—8 ਆਨੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਗੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗੇ ਹੀ ਲਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗਡੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨੂੰ ਖਿਚੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਛੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ। ਇਸ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਡਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਮੋਰ ਫੂਡ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਲਈ 750 ਰੁਪਏ subsidy ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹਥ ਰਖ ਕੇ ਦਸਣ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

**Deputy Speaker:** Please wind up.

**ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ :** ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗੇ 19 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੋ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਨਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ 22 ਫੀ ਸਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। (ਘੰਟੀ) ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਚੁਕੇ ਹੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਵਾਂਗਾ।

ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਕਨੂੰਨੀ ਇੰਤਹਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਗਲਾਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗਲਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਉ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਮੈਂਟਰੀ

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਫੇ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। (ਵਿਘਨ) ਤੀਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਨੇ ਕੌਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੀ ਦੇ ਦਿਉ। (ਘੰਟੀ) ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। (ਘੰਟੀ) ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬਾਪਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।

**ਬਭਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਹ ( ਪਾਲਮਪੁਰ ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਜ ਤੀਨ ਦਿਨ ਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਏਂਡ੍ਰੇਸ ਪਰ ਬਹੁਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬ ਸੇ ਪਹਲੇ ਅਪਨੇ ਏਂਡ੍ਰੇਸ ਮੇਂ ਸਵਰਗੀਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਾਲਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਦਨ ਕੀ ਬੇਕਬਤ ਸੈਂਤ ਸੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਕ ਕੋ ਗਹਰਾ ਸਦਮਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਸੁਲਕ ਤਨ ਕੀ ਬੇ ਲੈਸ ਕੁਰਬਾਨੀਯੋਂ ਕਾ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਤਰਫ ਸੇ ਭੀ ਤਨ ਕੋ ਅਫ਼ਾਜ਼ਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੇਂ ਫੌਜ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਰ ਜੋ ਕੀਰਤਾ ਤਨ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਸ ਕਾ ਭੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਸ ਕੇ ਸਾਥ ੨ ਤਸ ਰਾਜਯ ਕੀ ਸਿਵਿਲਿਯਨ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿੰਮਤ ਆਰ ਜਵਾਂਸਦੀ ਆਰ ਜਜ਼ਬਾਏ ਹੁਬਲਕਤਨੀ ਕਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆ ਹੈ ਤਸ ਕੀ ਭੀ ਦਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਝੇ ਯਹ ਕਹਤੇ ਹੂਏ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਨੇ ਤਸ ਲੜਾਈ ਮੇਂ ਜੋ ਕੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਆਰ ਜੋ ਸਬ ਸੇ ਜ਼ਯਾਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਤਸ ਪਰ ਹਮੇਂ ਬਜਾ ਤੌਰ ਪਰ ਨਾਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਸ ਲੜਾਈ ਮੇਂ ਸਬ ਸੇ ਜ਼ਯਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੂਏ ਹਨ ਆਰ ਸਬ ਸੇ ਜ਼ਯਾਦਾ ਤਮਗਾਜਾਤ ਤਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਤਸ ਮੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਏ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ੀ ਪੀਰ ਕੋ ਫਤੇਹ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਤਨ ਜਵਾਨੋਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਸੁਝੇ ਯਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੇ ਹੂਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸ ਕਾ ਫਾਤੇਹ ਭੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਕਾ ਹੀ ਏਕ ਕੀਰ ਹੈ ਆਰ ਤਸ ਕਾ ਸੇਹਰਾ ਜੈਨਰਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਹ ਕਟੋਚ ਕੇ ਸਿਰ ਬੰਧਾ ਹੈ. . . . .

(The hon. Member was still on his legs, when the House adjourned.)

2-30 p.m. | **उपाध्यक्षा :** सदन कल साढ़े नौ बजे फिर मिलेगा। (The House stands adjourned till 9-30 a.m., to-morrow.)  
(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 23rd February, 1966.)



000 000

**"C" 1966**

**Published under the authority of the Punjab Vidhan Sabha and  
printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab, Chandigarh.**

# PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES

23rd February, 1966

Vol. I—No. 6

## OFFICIAL REPORT

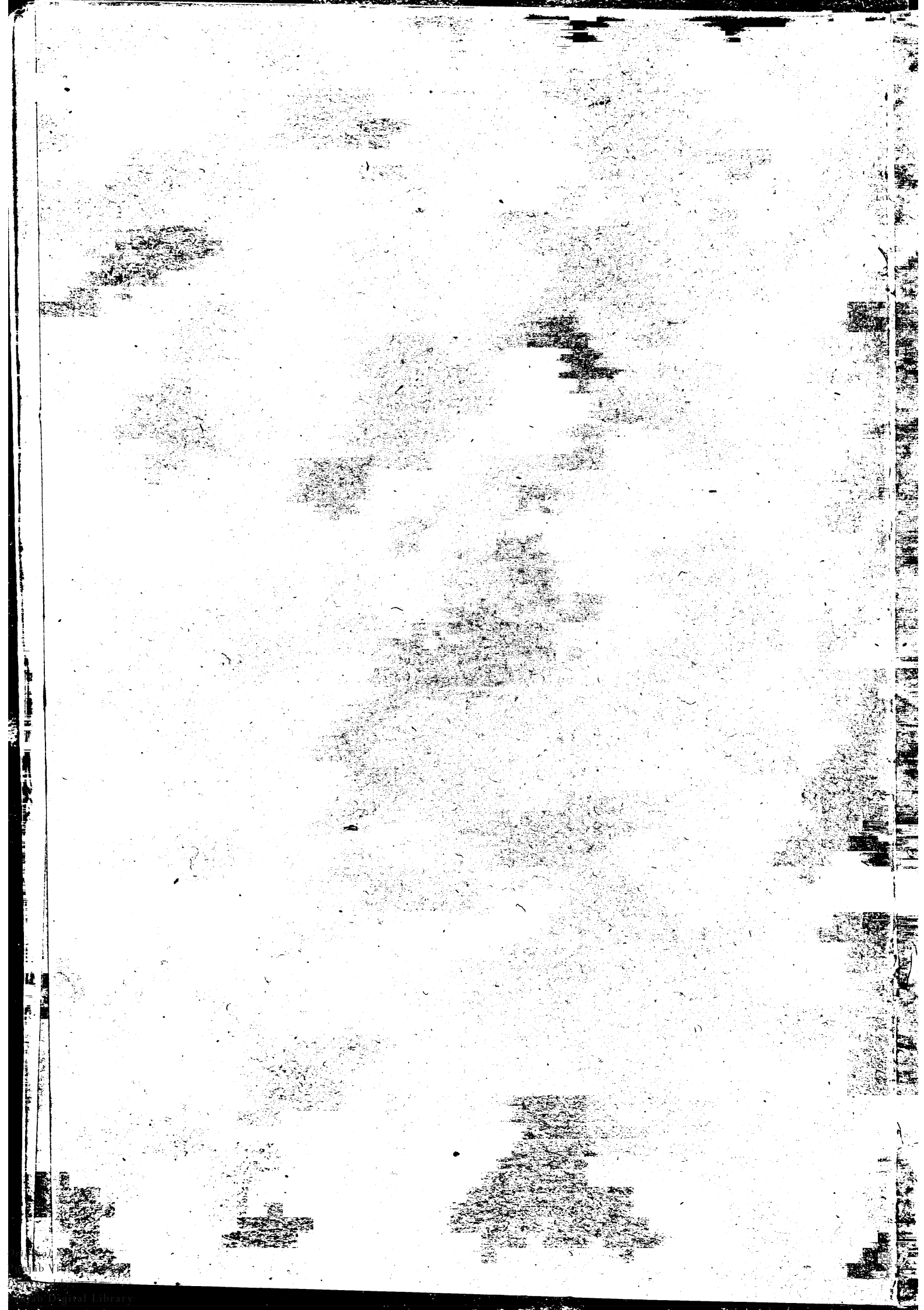


### CONTENTS

<i>Wednesday, the 23rd February, 1966</i>	PAGE
Unavoidable Absence of the Speaker ..	(6)1
Starred Questions and Answers ..	(6)1
Written Answer to Starred Question laid on the Table .. of the House under Rule 45	(6)39
Unstarred Questions and Answers ..	(6)39
Points of Order ..	(6)52
Adjournment Motion ..	(6)54
Discussion on Governor's Address (Resumption) ..	(6)57
Extension of Time ..	(6)108
Discussion on Governor's Address (Resumption) ..	(6)109—123
Appendix ..	(i)

Price ₹.20

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

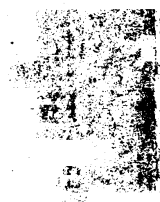


# ERRATA

to

**Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 6,  
dated the 23rd February, 1966.**

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
I have	have	(6) 14	40
Cities	Citie	(6) 15	27
anything	anythi	(6) 26	5
all	al	(6) 41	19 from below
down	dowh	(6) 41	16 from below
He was	advised to was	(6) 43	31
advised to continue	He continue	(6) 43	32
wool	woo	(6) 43	4 from below
State	tate	(6) 43	last
conversant	conversent	(6) 53	5 from below
Deputy Speaker	Deputy Spaker	(6) 54	1
Interruptions	Interrutions	(6) 56	19
ऐड्रेस	एड्रेस	(6) 57	9 from below
his	in his	(6) 67	15 from below
people and	and people	(6) 68	14
Governor's	Governor's	(6) 83	1
उपाध्यक्षा	उपध्यक्षा	(6) 83	29
का	क	(6) 90	20
chair	cahir	(6) 90	28
सरदार गुरदर्शन सिंह	सरदार गुरदशन सिंह	(6) 91	last
हमारी	हसारी	(6) 103	last
वगैरा	गैरा	(6) 104	last
2500	25000	(6) 107	4 from below
विजली	विसली	(6) 108	15
पंडित चिरंजी लाल शर्मा	पंडिन जिरंजी लाल शर्मा	(6) 109	6 from below
ड्राट	डाट	(6) 110	3 from below
तक	यक	(6) 113	3



Wednesday, the 23rd February, 1966

*The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh at 9.30 a.m. of the Clock.*

UNAVOIDABLE ABSENCE OF SPEAKER

**Secretary :** I have to inform the House that Mr. Speaker is unavoidably absent. The Deputy Speaker will, therefore, take the Chair.

[The Deputy Speaker occupied the Chair.]

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

FISH COLD STORAGE AT KAPURTHALA

**\*9008. Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether there is any fish cold storage at Kapurthala ;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether there was any condition imposed in the licence, issued for the purpose, to the effect that the licensee shall open a sale depot in Kapurthala ;
- (c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether any sale depot was actually opened by the said licensee and whether the same is functioning there, if not opened the reasons therefor?

**Captain Rattan Singh** (State Minister for Animal Husbandry and Agriculture) : (a) Yes.

(b) No licence is required to be issued.

(c) Question does not arise.

TRANSFERS OF TEACHERS FROM FEROZEPORE DISTRICT TO LUDHIANA DISTRICT

**\*8872. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the number of male and female teachers who applied for their transfers from district Ferozepore to district Ludhiana at the time of the general transfers in 1965 ;
- (b) the number of teachers out of those mentioned in part (a) above who were transferred to district Ludhiana ;
- (c) the number of teachers out of those mentioned in part (a) above whose applications were rejected together with the reasons therefor ;
- (d) the reasons for giving preference to the teachers mentioned in part (b) above over those mentioned in part (c) above ;
- (d) the number of applications of teachers out of these mentioned in part (c) above which were rejected by (i) the Block Education Officers (ii) the District Education Officer, Ferozepore (iii) the Circle Education Officer and (iv) the Director of Public Instruction, separately ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) (i) Men—46

(ii) Women—74

(b) (i) Men—17

(ii) Women—16

(c) (i) Men—29

(ii) Women—58

(a) Short stay.

(b) Non-availability of vacancies at the stations of their choice.

(d) (i) Longer stay at the station of posting.

(ii) Military cases.

(iii) Couple cases.

(iv) Wider choice of stations to which transfer was desired.

(e) (i) Block Education Officer .. Nil

(ii) District Education Officer .. Nil

(iii) Circle Education Officer (Men).. 29

(Women) .. 58

(iv) Director of Public Instruction,  
Punjab .. Nil

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਛ ਟਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਸਨ ?

**Minister :** If there is a demand from military personnel for the transfer of their wives, the Government's policy is to accommodate them as far as possible. But, in case there are more demands than the vacancies that are available, some of the requests have to be turned down.

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ :** ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਸਿਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

**Minister :** No such circular has been issued. Only important cases, or cases which need immediate attention, are to be attended to.

PERMISSION GRANTED TO TEACHERS IN LUDHIANA DISTRICT FOR APPEARING  
IN M. A. EXAMINATION HELD IN APRIL, 1965

**\*8873. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the total number of teachers in District Ludhiana who applied for permission to appear in the M.A. Examination held in April, 1965;
- (b) the number of teachers out of those mentioned in part (a) above who were given the required permission;
- (c) the number of teachers out of those mentioned in part (a) above who were refused the said permission;
- (d) the reasons for giving preference to the teachers mentioned in part (b) above over those mentioned in part (a) above ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) 128

(b) 119

(c) 9

(d) Permission was refused as their performance was poor.

**ਸ਼੍ਰੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨਿਹੋਤ੍ਰੀ :** ਕਥਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਕੋ ਐਮ. ਐ. ਕਾ ਐਂਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਉਨਕੋ ਜਿਨਕੀ ਪ੍ਰੋਫਰਮੈਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ? ਕਥਾ ਏਸੇ ਹਲਕੇ ਬਣੇ ਹੁਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨਕੀ ਪ੍ਰੋਫਰਮੈਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਗੀ ਉਨਕੋ ਐਮ. ਐ. ਕੇ ਐਂਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਐਂਪੀਯਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਿਯਾ ਜਾਏਗਾ !

**Minister :** Yes, here is a relevant portion of the circular which entitles the the teachers to appear for the M. A. :

“Permission should be granted only to those teachers including lecturers, who have put in at least two years’ service and whose performance has been good”.

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟਾਊਨ :** ਕਥਾ ਮਨੀ ਮਹੋਦਯ ਯਹ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਗੁਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਥਾ ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਲੇਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾ ਕਥਾ ਮਤਲਬ ਹੈ?

**Minister :** If their Confidential Reports are not satisfactory, then the performance is considered to be poor. If their results are much below the average, that too shows that the performance is poor. That is what the Government means by ‘performance’.

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ :** ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡੀ. ਐ. ਓ. ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਇਹ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ । 128 ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ 119 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਗੋਲਡ ਬਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਜ਼, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੋਟਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 5 ਜਾਂ 6 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 2 ਜਾਂ 3 ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਹਕ ਤਲਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ਼ਹ ਕਰਨ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 128 ਵਿਚੋਂ 119 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਲੀ 7% ਜਾਂ 8% ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲ ਤਵਜ਼ੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਲ ਤਵਜ਼ੁਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ?

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? (Does this question arise?)

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਮੈਡਮ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ।

#### SERVICE BOOKS OF TEACHERS IN CERTAIN EDUCATION CIRCLES IN LUDHIANA DISTRICT

**\*8874. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- the total number of teachers in Sudhar, Sidhwan Bet and Pakhowal Block Education Circles in Ludhiana District whose Service Books are not with their respective drawing and disbursing authorities at present;
- the whereabouts of the said service books together with the time since when the same are lying there ;
- the extent of loss suffered by each of the teachers referred to in part (a) above for want of his Service Book ;
- the action being taken against each of the officers who have withheld the said Service Books ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) 17

- A statement is laid on the Table of the House.
- Nil.
- Question does not arise.

## STATEMENT

Whereabouts of Service Books

Serial No.	Name of the teacher	Place of Posting	Whereabouts of Service Books
<b>Block Pakhowal</b>			
1.	Shri Atam Parkash	Government Primary School, Mansuran	Sent to Accountant General, Punjab, Simla on 13th February, 1966 with arrear bill.
2.	Shri Kapoor Singh	ditto	Sent to the Block Education Officer, Jagraon on 28th September, 1965 for completion.
3.	Shri Nirmal Singh	Government Primary School, Gondwal	Sent to the Block Education Officer, Mukandpur (Jullundur) on 16th August, 1965.
4.	Shri Malkiat Singh	Kaila	Sent to the Zila Parishad, Ludhiana on 16th September, 1965 with arrear bill.
5.	Shri Rajinder Singh	Nangal Khurd	Sent to the Accountant General, Punjab on 25th January, 1966.
6.	Shri Hardial Singh	Leel	Sent to the Accountant General, Punjab on 11th January, 1966.
7.	Smt. Surjit Kaur	Dhallian	Sent to the Accountant General, Punjab on 13th January, 1966.
<b>Block Sudhar</b>			
8.	Shri Chuhar Singh	Jhoran	Sent to the Accountant General, Punjab on 17th January, 1966.
9.	Shri Labh Singh	Rajoana	With Block Education Officer, Jagraon since 1st January, 1966.
10.	Shri Karam Singh	Tugal	The bill alongwith Service Book with observation of the Audit Department dated 22nd December, 1965 received back from the Director of Public Instruction, Punjab on 10th February, 1966. It remained under protracted correspondence.
11.	Smt. Sham Kaur	Hissowal	Sent to the Director of Public Instruction, Punjab, on 14th December, 1965 in connection with complaint against the Teacher regarding tampering of date of birth.

[Minister for Education]

Serial No.	Name of the teacher	Place of posting	Whereabouts of Service Books
<b>Block Sidhwan Bet</b>			
12.	Smt. Avtar Singh	Jandi	Sent to the Block Education Officer, Dehlon, on 1st September, 1966.
13.	Shri Malkiat Singh	Talwara	Still awaited from the District Education Officer, Ferozepore after their transfer on 1st September, 1965.
14.	Shri Gurcharan Singh	Kot Mana	Still awaited from the District Education Officer, Ferozepore after their transfer on 1st September, 1965.
15.	Shri Mukhtiar Singh	Fateh Garh Sibian	Service Book not received from the District Education Officer, Ferozepore after their transfer on 1st September, 1965.
16.	Smt. Sukhdev Kaur	Sidhwan Bet	Not yet constructed.
17.	Shri Bachan Singh	Gorsian Khan Mohd.	Awaited from the Block Education Officer, Khamanon on 1st September, 1965.

## TEACHERS WORKING IN MOBILE SOCIAL SQUADS

**\*9099. Comrade Babu Singh Master :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the teachers of the erstwhile Pepsu State in the Mobile Social Education Squads are still being paid the grade of Rs. 50—3—80 ;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether it is a fact that the said social Mobile Squad teachers were enjoying the same pay scales as other teachers in the Pepsu state ;
- (c) the reasons for which the Social Mobile Squad teachers have not been allowed the grade of Rs. 60—120 like the J. B. T. Teachers ;
- (d) the names of such Mobile Squad teachers with their present Place of posting who are still working in the Rs. 50—3—80 grade and the steps, if any, being taken to allow Rs. 60—175 grade to them ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) No. They are in the grade of Rs. 50—3—80/4—100 ;

- (b) The scale of teachers in the erstwhile Pepsu was the same;
- (c) The difference in grades is due to higher educational qualifications of J. B. T. teachers.
- (d) A list of Mobile Squad Teachers is laid on the Table of the House. The matter regarding revision of grade of Social Education Squad Teachers is under consideration.

## List of Mobile Squad Teachers

Serial No.	Name of the official	Place of posting
Sarvshri/Smt:—		
1.	Rattan Chand	Bachhod
2.	Lal Chand	Gulawala
3.	Gulzari Parshad	Nasibpur
4.	Madan Mohan Lal	Rasulpur
5.	Bahal Singh	Hathira
6.	Anand Sarup	Monindergarh
7.	Kamla Devi Bhatnagar	Mohindergarh
8.	Shanti Devi	Pali
9.	Sudarshan Kumari	Chharkhi

[ Minister for Education ]

Serial No.	Name of the official	Place of posting
	Sarvshri/Smt :—	
10.	Parmila Kumari	Dadri
11.	Santosh Bhatia	Talwandi
12.	Shanti Devi Mukhi	Nangal
13.	Krishna Kumari	Nautana
14.	Vidya Wati	Mohamdpur
15.	Sumitra Devi	Mandola
16.	Swaran Kanta	Akoda
17.	Vimal Sharma	Nangal (Harnathka)
18.	Janki Devi	Changroad
19.	Santosh Kumari	Santore
20.	Kaushalya Devi	Sarupgarh
21.	Savitri Devi Walla	Gulawala
22.	Kamaljeet Kaur	Pujam
23.	Shanti Devi Gupta	Mohindergarh
24.	Mohan Singh .	Dhilwan
25.	Kapur Chand	Razapur
26.	Harbhajan Singh	Godana
27.	Mohal Lal	Chakoki
28.	Gurbachan Singh	Mehtan
29.	Satya Vati	Dhilwan
30.	Harbans Kaur	Daburji
31.	Rajinder Sood	Brindpur
32.	Nirmal Devi	Bhulana
33.	Sat Pria Sharma	Khera Dora
34.	Satya Devi	Balair
35.	Tara Wanti	Aujla
36.	Sita Devi	Dwankhe
37.	Pushpa Devi	Khojewali
38.	Nirmal Kaur	Godana
39.	Sudesh Kumari	Bholath
40.	Sudesh Chopra	Kamranwan
41.	Santosh Kumari	Bhagwanpur
42.	Ravinder Kaur	Chaheru
43.	Parkash wati	Thakarki
44.	Shakuntla Devi	Mauli

Serial No.	Name of the official	Place of posting
Sarvshri/Smt :—		
45.	Shakuntla Gupta	Palahi
46.	Subhichha Devi	Khurrampur
47.	Amrit Kaur	Chachrari
48.	Indra Devi	Lakhpur
49.	Kamla Wati	Murar
50.	Satya Devi Puri	Nilo
51.	Sushila Devi	Mehmadpur
52.	Leela Devi	Jhallan
53.	Kamla Jand	Chuharpur
54.	Nirmal Joshi	Fatehpur
55.	Joginder Kaur Kang	Sheikhupur
56.	Shanti Jand	Gajju Majra
57.	Krishna Batta	Chana Khuti
58.	Sarla Gupta	Bhadpura
59.	Kamla Devi	Sadarpur
60.	Promila Devi	Sansarwa—1
61.	Balwant Kaur Sahni	Bibiipur
62.	Satwant Kaur	Khalifewalla
63.	Pushpa Devi	Chailala
64.	Shanti Sharma	Balpur
65.	Ajaib Kaur	Rorewalla
66.	Tara Kapur	Chaurwalla
67.	Parmahans Kaur	Jakhwali
68.	Narindar Kaur	Naraingarh
69.	Savitri Devi	Naulakha
70.	Sharan Kaur	Nalini
71.	Kuldeep Kaur	Nalina
72.	Amarjeet Kalra	Khorora
73.	Santosh Arora	Kharori
74.	Rajinder Kaur	Sarna
75.	Kesho Ram	Ambala Cantt.
76.	Sat Parkash	Patiala
77.	Surinder Kumar Bhatnagar	Bijalpur
78.	Hari Krishan Malhotra	Shermajra
79.	Jagdish Chand Attri	Khudi Kalan

[ Minister for Education ]

Serial No.	Name of the official	Place of posting
Sarvshri/Smt 1—		
80.	Darshan Kumar	Haibatpur
81.	Baisakhi Ram	Bhainikhurd
82.	Sukhdev Singh	Cheema
83.	Nathu Ram	Saleempura
84.	Hans Raj	Sehna
85.	Mohinder Kaur	Duggan
86.	Shanti Devi	Dhanula
87.	Mohinder Kaur	Bhadur Pore
88.	Jagdish Kaur	Dhuri Village
89.	Jasmer Kaur	Badbar
90.	Ram Piari	Mulalowal
91.	Kailash Devi	Barnala
92.	Sushila Devi	Rajo Majra
93.	Raj Kumari	Budhakan
94.	Santa Bhatnagar	Harigarh
95.	Bimla Devi	Mahal Kalan
96.	Kalwant Kaur	Jhaloor
97.	Versha Anand	Sekha
98.	Harbhajan Kaur	Dhanula
99.	Mukand Rani	Khudi Kalan
100.	Jagwant Kaur	Wazid-ka-Kalan
101.	Surjit Kaur	Bhadal Wadh
102.	Prem Lata	Cheema
103.	Moorti Devi	Pharwali
104.	Ranjit Kaur	Wazidke Khurd
105.	Balbir Kaur	Patti Sekhwan
106.	Maya Devi	Amla Singh Wala
107.	Naval Kishore	Khan Singh Wala
108.	Gurdial Singh	Rampura
109.	Hara Ram	Mehraj
110.	Krishan Kumar	Bhatinda
111.	Brij Lal	Jethu Ke
112.	Baldev Singh	Bhuchoo Kalan
113.	Gursewak Singh	Burj Gill

Serial No.	Name of the official	Place of posting
Sarvshri/Smt :—		
114.	Jaswanti Devi	Burj Gill
115.	Surjit Kaur	Khan Singh Wala
116.	Kamlesh Kanta	Phul
117.	Gurtej Kaur	Bhucho Kalan
118.	Swarn Kaur	Booger
119.	Rattan Kaur	Ganga
120.	Sushil Kaur	Chotian
121.	Raj Rani	Ram Pura
122.	Harwant Kaur	Kalooki
123.	Tejwant Kaur	Bhucho Mandi
124.	Yashoda Devi	Pitho
125.	Malkiat Kaur	Rampura Phul
126.	Narinder Kaur	Burt-Mansion
127.	Sumitra Devi	Dhule Wala
128.	Kanta Kumari	Faridkot
129.	Joginder Kaur	Bhatinda
130.	Harbans Kaur	Jalal
131.	Yashoda Devi	Poohli
132.	Kashulaya Devi	Dyalpura
133.	Lajya Wanti	Lehra Sondha
134.	Kalwant Kaur	Bhuchho Khurd
135.	Shilla Wanti	Mehraj
136.	Bimla Devi	Karar wala
137.	Basant Kaur	Dudwindi

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 1956 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਸਟਵਾਈਲ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਓਹੀ ਗਰੇਡ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸਟਵਾਈਲ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕੁਛ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਘਟ ਹਨ । ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੇਡ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਕਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ।

[ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਗੋਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਲਈ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੇਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਦੇਈਏ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : 1955 ਜਾਂ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਬਾਅਦ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

#### NURSERY TRAINED FEMALE TEACHERS

\*9102. Comrade Gurbakhsh Singh } (Put by Comrade Bhan Singh  
Comrade Babu Singh Master }  
Bhaura on their behalf) : Will the Minister for Education be pleased to state —

- (a) the total number with names of Nursery trained female teachers, with their present places of posting, who are being paid a fixed pay of Rs. 60/- since 19th December, 1963;
- (b) whether any representations have been received by the Government against the payment of this fixed grade; if so, a copy each of the same together with the details of the steps, if any, taken to allow, the said teachers the running grade of Rs. 60—175 be laid on the Table of the House ?

Shri Prabodh Chandra : (a)

- |   |   |
|---|---|
| (i) Total number of nursery<br>Trained female teachers. | II (excluding the Districts of<br>Ferozepore, Jullundur and<br>Gurdaspur from whom the<br>information is awaited).† |
|---|---|

- (ii) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

- (b) A copy each of the representations dated 13th June, 1964 and 4th June, 1965 and 30th November, 1965 made to the Government and the Director of Public Instruction, Punjab, respectively by one Smt. Janak Malhotra is laid on the Table of the House.

The Government have not taken any steps to grant running grade to such teachers unless they pass J. B. T. examination.

† Note : For additional information in respect of Starred Question No. 9102 please see Appendix to this Debate.

**Statement containing names of Nursery trained female teachers with their present places of posting**

(ii) Names of the Nursery trained teachers and their places of posting.

1. Smt. Surjit Kaur, Government Primary School, Dhandari Kalan (District Ludhiana).
2. Smt. Darshan Tuli, Government Primary School, Dashmesh Nagar (Ludhiana).
3. Smt. Shakuntla Devi, Government Middle School, Bhulla Rai (Kapurthala).
4. Smt. Amarjit Kaur, Government Middle School, Chachoki (Kapurthala).
5. Smt. Raj Kumari, Government Higher Secondary School, Hadiabad (Kapurthala).
6. Smt. Sita Kashap, Government Girls Higher Secondary School, Phagwara (Kapurthala).
7. Smt. Kamla Devi, Government High School, Sultanpur (Kapurthala).
8. Smt. Surjit Kaur, Government Primary School, Nihalgarh (Kapurthala).
9. Smt. Davinder Kaur, Government Primary School, Rampur Sunra, (Kapurthala).
10. Smt. Santosh Kumari, Government Middle School, Bhanoki (Kapurthala).
11. Smt. Janak Malhotra, Junior Model School, Civil Lines, Patiala.

The requisite information in respect of Ferozepore, Jullundur and Gurdaspur will be supplied later on.

Copy of application dated the 13-6-1964 from Smt. Janak Malhotra, Teacher, Government Primary School, Bhunarheri, Bhunarheri Block, Patiala to the Director of Public Instruction, Punjab and a copy to the Education Commissioner and Secretary to Government, Punjab Education Department, Chandigarh.

*Subject* :—Reinstatement of Shrimati Janak Malhotra.

Please refer to your Memo No. 2648-EWII-64/5/3-61-WII/2, dated the 21st March, 1964 on the subject cited above.

2. I am to point out that I was reinstated on the post of teacher in terms of your order No. 7148-EWDI-63/5/3-61, dated 7-6-63, but inspite of numerous letter reminders and personal calls made during this period of nearly one year, I have not been given the benefit of arrears of pay from the date of wrongful termination of my services in the year 1957 nor my pay, grade and seniority have been decided by you on the basis of my continous length of service. Since my total emoluments provisionally fixed at Rs. 100/- per month by the District Education Officer, Patiala pending decision are hardly sufficient to meet the present day high cost of living, I earnestly request you to kindly get the matter expedited on the issues pointed out above in the light of orders contained in Pepsu Government in Eaucation Department Patiala letter No. E/E9(526)-56, dated 23-10-1956.

Thanking you.

To

The Director of Public Instruction,  
Punjab Chandigarh.

*Subject* :—Fixation of pay running grade and payment of arrears of Mrs. Janak Malhotra, Teacher, Government Junior Model School, Civil Lines, Patiala.

Sir,

With reference to your Memo No. 673-G-EWI-II-64(2) dated 23-12-1964 to the address of the Principal, State College of Education, Patiala, with a copy endorsed to my wife Mrs. J. Malhotra by the Lady Supdt. Government Junior Model School, Patiala, I respectfully beg to submit as under:—

( Minister for Education )

- (1) That my wife Mrs. Janak Malhotra has been taken back into Government service in terms of your letter No. 7143-EW-II-63/5/3/61, dated 7-6-1963 and posted against a regular vacancy. It is crystal clear that for implementing the orders passed by erstwhile Pepsu Government in their U. O. No. ND/F-9(526)-56, dated 23-10-1956, Mrs. Janak Malhotra is entitled to the reinstatement benefits from the date of first entry into Government service. The word "taken back into service" means reinstatement and not re-employment (copy enclosed) as envisaged by you.
2. That my wife Mrs. Janak Malhotra passed the Intermediate Examination with full subjects in the year 1943. Subsequently, she attended nine months, training course of Association Montessori Internationals in the year 1957-58. The diploma awarded by Montessori Training Association has been recognised equivalent to the certificate awarded by Punjab Government Education Department to the trainees of Basic Training Schools (Government of India, Ministry of Education letter No. D-97/52-B, dated 28-1-1952 may be referred to (copy enclosed). In the light of this Mrs. Janak Malhotra is entitled to the running grade. It may further be pointed out that lady teachers already in employment with Montessori Diploma are enjoying the grade of Rs. 140—10—220.

In the light of position explained above, I request you to kindly sanction the benefit of running grade to Mrs. Janak Malhotra from the date of joining Government service. Her case for reinstatement from the year 1956 by allowing her the benefit of graded increments, payment of arrears etc. may kindly be examined and orders passed accordingly.

Yours faithfully,  
Sd/- H. K. Malhotra,  
Sirhandi Gate, Patiala.

4-6-1965.

Copy of an application, No. Nil, dated 30-11-65, from the (Mrs. Janak Malhotra) Teacher, Nursery Section, Government Junior Model School, Civil Lines, Patiala, to the Director of Public Instruction, Punjab, Chandigarh.

*Subject* :—Fixation of pay, running grade and payment of arrears of Mrs. Janak Malhotra, Teacher Government Junior Model School, Civil Lines, Patiala.

(Through Proper Channel)

Sir,

have come to know from a copy of your memo. No. 5762-EW-II-64(2) dated 13-8-1965 to the address of my husband Shri H. K. Malhotra (obtained from the office of District Education Officer, Patiala) that in order to earn the regular grade, I should appear in the J.B.T. Examination privately.

2. In this connection I may respectfully submit as under for your kind perusal and favourable consideration :—

- (a) I am a Montessori qualified teacher and the diploma awarded by the Association Montessori International has been recognised by the Punjab Government under article 179 of P. E. C. equivalent to the certificate granted for Teaching Basic Primary Schools. (copy of letter No. D 97/52-B-I dated 28-1-1952 from the Ministry of Education Government of India to the State Governments is enclosed). Thus the question of my taking up J. B. T. Examination as suggested by you hardly arises. Moreover the following Montessori trained teachers as indicated against each school have been placed in higher grades than even the B. A., B. Ed.s teachers.

Name of Teacher	Name of School	Grade enjoyed.
Mrs. S. Garg	Junior Model School, Pheel Khanna, Patiala.	Rs. 140/220
Miss. P. Inder Singh	Junior Model School Civil Lines, Patiala.	Rs. 140/220

There is thus no justification to deprive me of this running grade in the face of previous procedure and the recognition granted to Montessori Diploma by the State Government.

- (b) The orders passed in your memo No. 7148-EW-II-63/5/3/61 dated 7-6-1963 are crystal clear that I have been reinstated in terms of Pepsu Government, Education Department letter No. ND/F-9(526)-56 dated 23-10-1956. I am thus entitled to the payment of arrears of pay for the period from May, 1957 to August, 1963. The phrase 'taken-back' into service has wrongly been interpreted as fresh appointment and the office of District Education Officer, Patiala of its own accord has fixed my salary at Rs. 100 per month. I would request you to kindly afford me all the facilities eligible to a reinstated employee under this order, otherwise I shall be constrained to knock the doors of justice for redress of my grievances. I feel that my cause is just but I, have unnecessarily been deprived of my proper grade and pay, I, therefore, fervently request you kindly to re-examine the entire case and reconsider the decision taken by you in the light of facts stated by me at an early date.

Thanking you.

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਜਲਦੀ।

#### SHIFTING OF HIGHER SECONDARY SCHOOLS FROM THE VILLAGES TO THE CITIES IN THE STATE

**\*9221. Sardar Sampuran Singh Dhaura :** Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that the Government Higher Secondary Schools are being shifted from the villages to the cities in the State, if so, the reasons therefor?

**Shri Prabodh Chandra :** No. The rationalization of Higher Secondary Schools is, however, under consideration.

**ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ :** ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

**ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰੀਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਹਨ ਉਥੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੁਕ ਲਉ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਉ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ irrespective of the fact whether the demand is from a town, from a village or from a city. The case will be considered on merits and not on the basis of population of the area.

**ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ :** ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਉਥੇ 50/50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਰ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਏਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘਟ ਸੀ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਤਾਂ 2/3 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ।

**APPLICABILITY OF NEW PENSION RULES TO THE EMPLOYEES OF THE  
ERSTWHILE PEPSU STATE**

**\*9072. Sardar Sampuran Singh Dhaula :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that there is a condition that the employees of the erstwhile Pepsu State can avail of the benefits of the Family Pension Scheme only, if they opt for the new rules of the Punjab Government;
- (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the reasons why the said rules are not made applicable to such employees when they become automatically applicable to new employees on their entering employment without their having to opt for such rules;
- (c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to bring about a uniformity in the rules in the case of all of its employees?

**Sardar Kapur Singh :** (a) Yes, Sir,

- (b) The Punjab New Pension Rules and the Family Pension Scheme, 1964, cannot be made applicable automatically to such Pepsu employees, who opted to continue to be governed by the Erstwhile Pepsu Old/New Pension Rules, since it is not legally permissible.

(c) No, sir.

**ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ :** क्या यह बात उनके नोटिस में आई है कि पहले पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सरकुलर जारी हुआ और उसके मुताबिक पੈपसू वालों को फैमिली पेंशन मिलती रही लेकिन 7/8 महीने मिलने के बाद बिदड़ा कर ली गई ? इसका कारण क्या है ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । **That cannot be done, one cannot have both ways**

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟਾਡਨ :** ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਂਸੂ ਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਪੈਂਸੂ ਦੇ ਫੈਸਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਲਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕਤ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਉਹੋ ਸਨ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ *they are gaining by Pepsu Rules* ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ :** ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਉ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੂਲਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ?

**Finance Minister :** They must confine themselves to the contract they make.

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਹਿੱਚ, ਇਕ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੈ ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਇਹ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਇਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 1958 ਵਿਚ ਬਦਲੇ, 1961 ਵਿਚ ਬਦਲੇ, 1964 ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ !

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ :** ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਇਹ ਆਫ ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨਿਹੋਤ੍ਰੀ : ਕਥਾ ਧਰੁ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੂ ਕਾਲੋਂ ਕੋ ਜੋ ਫੈਸਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਹੀਨੋਂ ਤਕ ਦੀ ਗਈ ਤਸੇ ਰਿਫ਼ਠਡ ਕਰਨੇ ਕੇ ਕਾਰੇ ਮੈਂ ਆਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਏ ਐਰ ਕਥਾ ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਲਿਖਾ ਕਿ ਕਹੁ ਕਾਪਸ ਨ ਲੀ ਜਾਏ ?

ਮੰਤਰੀ : ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ । ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਬਦਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਰਾਈ ਰਾਈ ਕੋੜੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੱਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਪਸੂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ they would also ask for applying those rules to them. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ।

ਕਿੱਤ ਸੰਤੀ : ਮੈਂ ਪਹਲੇ ਅਜ਼ ਕੀ ਕਿ ਤੁਨ ਸੇ ਪਹਲੇ ਪੂਛਾ ਥਾ । ਤੁਨਕੇ ਕਹਨੇ ਕੇ ਸੁਤਾਬਿਕ ਹਸ ਨੇ ਏਕਸ਼ਨ ਲਿਆ । They will be governed by those rules.

#### AMOUNT OF LOANS GIVEN TO THE FILM PRODUCERS

\*9200 Sardar Niranjn Singh Talib : Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount of the loans given by the State Government to the film producers since the present Ministry came into office together with the number and name of the producers to whom loans were given and the amount given to each separately, for Hindi and Punjabi Films?

**Sardar Kapur Singh :** No loan to any film producer has been given by the State Government since the assumption of the office by the present Ministry.

**ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ :** ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ?

**ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ :** 1963 ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ । 1964 ਵਿਚ 2½% ਕਮੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਅਗਰ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

**ਮੰਤਰੀ :** ਅਗਰ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ (ਹਾਸਾ)

**ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ :** ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਹਕੀਕਤ ਫਿਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । That was a defence oriented picture. ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹਕੀਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਕਥਾ ਕਿਤ ਸੰਭੀ ਸਹੋਦਯ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਕੁਧਾ ਕਰੇਗੇ ਕਿ ਕਥਾ ਧਹੁ ਸਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਸ ਫਿਲਮ ਸੇ ਫੀਜੀਯੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਸੇ ਐਰ ਉਨਕੇ ਥਰੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਸੇ ਬਤਾਯਾ ਗਯਾ ਹੈ । ਕਥਾ ਧਹੁ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਤਸ ਫਿਲਮ ਕੇ ਦਿਖਾਨੇ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇ ਫੀਜ਼ ਸੇ ਭਰਤੀ ਹੋਨੇ ਸੇ ਤ੍ਰਸਾਹੁ ਕਸ ਹੀ ਹੁਆ ਹੈ ?

**ਸੰਤੀ :** ਧਹੁ ਤੀ ਸਾਨਨੀਯ ਸਦਸਯ ਕੀ ਅਪਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ।

**ਡਾਕਟਰ ਕਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਕਥਾ ਸਾਨਨੀਯ ਸੰਤੀ ਸਹੋਦਯ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਕੁਧਾ ਕਰੇਗੇ ਕਿ ਕਥਾ ਤਨ੍ਹੋਨੇ ਹਕੀਕਤ ਫਿਲਮ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਐਰ ਤਨ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਰਾਏ ਹੈ ?

**ਸੰਤੀ :** ਮੈਨੇ ਧਹੁ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲਿਕ ਤਨ੍ਹੋਨੇ ਜਵਾਨ ਫੰਡਜ਼ ਕੇ ਲਿਏ ਸੁਝੇ ਰਪਯਾ ਭੀ ਦਿਯਾ ।

## MARLA TAX ADVISORY COMMITTEE REPORT

**\*9105. Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether Government have received the report of the Marla Tax Advisory Committee constituted by it; if so, a copy thereof be placed on the Table of the House; if no report has so far been received from it, the reasons for the delay in its submission ?

**Sardar Harinder Singh Major (Minister for Revenue) :** Yes. It will be placed on the Table of the House after it has been considered by Government.

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਫਾਸ ਟੰਡਨ :** ਕਥਾ ਮਾਲ ਸਕੀ ਮਹੋਦਯ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਬ ਮਿਲੀ ਐਰਿਓਰ ਯਹੁ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕਿਤਨੇ ਅਸੋਂ ਸੋ ਹੈ ? ਕਥਾ ਇਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋ ਦੌਰਾਨ ਕਹੁ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਓਸ ਕੀ ਟੇਬਲ ਪਰ ਰਖੀ ਜਾਏਗੀ ਯਾ ਨਹੀਂ ।

**Minister :** Madam, the report was received by the Government on 9th April 1965. ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਕਰਾਪ ਅਪ ਹੋ ਗਏ । ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਲਿਕਟ, ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ । ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਦੇਰ ਲਗ ਗਈ ।

This matter is under consideration of the Government and decision will be taken in due course of time.

**ਸ਼੍ਰੀ ਆਮ ਸ਼ਕਾਸ਼ ਅਹਿਨਹੋਰੀ :** ਕਥਾ ਕਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਕ੍ਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਹੁ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਫੈਰੇਂਸ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕਬ ਸੋ ਹੈ ਐਰਿਓਰ ਕਥਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਕੋ ਕਾਫ਼ ਇਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋ ਦੌਰਾਨ ਹਾਓਸ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਪ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪ ਪਰਾਇਰਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਨਸੰਸਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਘਟ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਚ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ । ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

CHARTER OF DEMANDS SUBMITTED BY PUNJAB MENTAL HOSPITAL  
EMPLOYEES ASSOCIATION

\*9100. Comrade Gurbakhsh Singh }  
Comrade Babu Singh Master } : Will the Minister for  
Health be pleased to state.

- (a) whether it is fact that the Punjab Mental Hospital Employees Association submitted a charter of their demands to the Government in 1958;
- (b) whether it is also a fact that the then Labour Minister managed to get an agreement arrived at, if so, copies of the charter of demands and the agreement so arrived at be placed on the Table of the House ;
- (c) whether the authorities concerned have implemented the agreement mentioned in part (b) above; if not, the reasons therefore and the steps being taken to implement the same ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** (a) Yes.

- (b) No. However, a statement showing the demands and the extent up to which these have been accepted by the Health Department is laid on the Table of the House.
- (c) Question does not arise.

## STATEMENT SHOWING THE DEMANDS AND THE EXTENT UP TO WHICH THESE HAVE BEEN ACCEPTED

Demands.	Extent up to which the demands have been accepted
1	2
3	
I. Revision of pay-scales and Grades	The pay-scales of following categories of staff were revised as under w. e. f. 1-4-59 :—
	Attendants
	Rs 45—1—65
	Ward Supervisors
	Rs 45—2—75
	Overseer Garden
	Rs 50—3—80—4—100
	Sub-overseer.
	Rs 60—4—100/5—120
	Overseer Personnel
	Rs 60—4—80/5—120/5—175
2. Allowances	
City Allowance	} Not accepted.
Border Allowance	
Medical aid allowance	Not accepted. However, all medicines are supplied from the hospital as are usually admissible to all Government employees.
Quarter allowance	This has been sanctioned w. e. f. January, 1965 in view of a general decision of Government.
3. Holidays-weekly day off	Attendants, Sweepers, Supervisors and Sub-Overseers were given fortnightly day off w. e. f. 17-2-1959.

[Minister for Health]

## 4. Uniforms

The uniforms are being supplied within the sanctioned cost with free stitching.

## 5. Confirmation of the staff

The staff has been confirmed after 2 years of probation.

The cooks have been taken on regular establishment. But, a few members of the staff are still paid out of contingencies.

## 6. Free medical aid and a separate medical ward for the staff.

One of the doctors of the hospital has been named as Authorised Medical Attendant for the staff and all the requirements of medicines are supplied from hospital. Some ill members of the staff are looked after in the out-patients ward of the hospital if they do not choose to go to V. J. Hospital Amritsar. Separate Medical ward for the staff has not been accepted.

## 7. Duty shift of Sweepers and Attendants

Most of the Attendants and Sweepers work in 8 hourly shifts. A few are given broken duties, where absolutely necessary.

## 8. Promotion to upper Supervisory posts

Supervisors, Sub-overseers and Overseers are only appointed on promotion from the lower position in the Hospital.

## 9. The surrounding wall be made 18 feet high

This has not been accepted as the Hospital has not ~~to be made~~ into a Jail. All over the world, Mental Hospitals have given up the jail architecture. There is a closed ward with 9 feet high walls. Surrounding wall is 7 feet high.

## 10. Refreshment rooms, library and radio and educational and cultural benefits for children of the staff

A canteen has been opened in the Hospital.

## 11. Copies of hospital rules be provided to the staff

Not accepted. However, duties of new entrants are told verbally by the overseer personnel and hospital orders are communicated to the staff at roll call time and put on the notice board.

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਸੱਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਉਨ ਕੋ ਵਰਕਲੀ ਬਤਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਨਕੇ ਲਿਓ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਪਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਯੋਂਕਿ ਧਰ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਰਖਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਨ ਕੋ ਕਾਪਿਆਂ ਦੇਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਸੱਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਿਆ ਗਿਆ ਵਹ ਰੇਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ । ਧਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਟਕ ਕੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਆਈਂ ਐਂਡ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਅਪਨੀ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ । ਉਨ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਇਨਟਕ ਕੇ ਫਾਰਾ ਆਨੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜ ਦੀ ਗਈ ਐਂਡ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਨ ਲੀ । *Otherwise it was not a regular demand notice of the employees of the Mental Hospital.*

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ? ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰ ਕਰਨਗੇ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਉਪਾਧਿਕਸ਼ ਮਹੋਦਯਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਕੈਂਕਗ੍ਰਾਂਡ ਬੰਨ੍ਹਾ ਦੂੰ । ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨਿਯਨ ਥੀ, ਵਹ 1955 ਮੈਂ ਕਾਯਮ ਹੁੰਦੀ । ਵੈਸੇ ਵਹ ਕਾਯਦੇ ਕੇ ਸੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਨੀਂ । ਉਸ ਯੂਨਿਯਨ ਨੇ ਇਨਟਕ ਕੇ ਸਾਥ ਸੀਧਾ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾ ਲਿਆ । ਉਸ ਕੇ ਫਾਰਾ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰੇਗੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਥਾ । ਵਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਸੀਧਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਉਨ ਕੀ ਜਿਤਨੀ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਆਈ ਉਨ ਮੈਂ ਸੇ ਜਿਤਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੂਰ ਕਰ ਸਕਤੀ ਥੀ ਵਹ ਕਰ ਲੀ ।

ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਕੀ ਜੋ ਨੇਚਰ ਆਫ ਡਿਪੂਟੀ ਥੀ ਉਸ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰਖਤੇ ਹੁਏ ਜੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਥਾ ਵਹ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ :** ਕੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਸੱਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕਿਉਂ ਲਗਿਆ ?

**ਸ਼੍ਰੀ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪ ਜਾਨਤੀ ਹੈਂ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੁਆ ਥਾ, ਉਸ ਕੇ ਬਾਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਨ ਕੀ ਐਸੇਟ ਨਵੰਬਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ । *Then the case was processed in the Finance Department and it took some time to finalize the matter.*

उपाध्यक्षा : ओम प्रभा जी, यह कोई वैलिड जवाब नहीं है। इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई काम करना है तो वह ग्रेस से हो जाना चाहिए।  
(Addressing the Health Minister : This is no valid reply. The matter should not have been delayed so much. If anythi is to be done, it should be accomplished gracefully.)

**RULES FRAMED UNDER THE PUNJAB STATE LEGISLATURE OFFICERS, MINISTERS AND MEMBERS (MEDICAL FACILITIES) ACT, 1965.**

**\*9201 Sardar Niranjn Singh Talib** : Will the Minister for Health be pleased to state whether any rules have been framed under the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Act, 1965 and circulated to all the Medical authorities concerned in the State for necessary action; if so, the date when it was done; if the rules have not yet been framed, the reasons therefor ?

**Shrimati Om Prabha Jain** : Yes Sir. All Heads of Sub-Offices in the Punjab Health Department have been instructed on 7th February, 1966, to provide medical facilities to the Legislators and Members of their family on the pattern prescribed in the Punjab Services (Medical Attendance) Rules, 1940.

**डाक्टर बलदेव प्रकाश** : क्या मन्त्री साहिबा जानती हैं कि चंडीगढ़ मैडीकल इन्स्टीच्यूट में अभी तक इस बात पर अमल नहीं किया गया और मेम्बरान को अभी तक भी ट्रीटमेंट के लिए पे करना पड़ता है ?

**Minister** : I am not aware of any such thing. If the hon. Member draws my attention, I will look into it.

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ** : ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ?

**Minister** : I am not aware of any such thing. It was in the Press that some Association advised them like that.

**VERKA PLANT**

**\*9106. Dr. Baldev Parkash** : Will the Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state :—

- (a) whether the Government has recently enhanced the price of pure ghee produced by the Verka Milk Plant; if so, the reasons for doing so ;
- (b) whether it is a fact that the said Plant has been exempted from the Government order prohibiting the manufacture of cream or butter; if so, the reasons for giving this exemption together with the reasons for not giving such exemption to the private parties;
- (c) the price at which the butter produced at the said plant is sold ?

**Captain Rattan Singh :** (a) Yes ; to reduce the large difference between the price of ghee manufactured by the Government Milk Plant, Amritsar and ghee of other brands.

(b) Government Milk Plant, Amritsar has been geared primarily to meet the requirements of milk products, of the Armed Forces. A quantity of milk is also sold for liquid consumption to citizens of Amritsar. Butter and ghee are manufactured from only such milk as is found surplus to these requirements. Exemption for doing that has been allowed to save surplus milk from going waste. There is no ban on the manufacture of butter or ghee by the country process. But use of milk for preparation of cream etc., has not been allowed to private parties for securing the defence of India, Civil Defence and the maintenance and increase of supplies and services essential to the life of the community.

(c) Rs 9.50 per Kg.

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** क्या पशु पालन मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह फैक्ट नहीं है कि बेरका प्लांट के बने हुए घी की कीमत उन्होंने उस वक्त भी बढ़ाई थी जबकि मार्किट में घी की कीमत बहुत कम थी ?

**राज्य मंत्री :** मैं अर्ज करता हूं कि हिन्दुस्तान लीवर का जो अनिक घी है उस की कीमत 12 रु० तीन पैसे पर किलो ग्राम है, डायर मीकिन का बना हुआ घी 12 रुपये तीन पैसे पर किलो ..... (विघन).....(आवाजें)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । अर्ज यह है कि जब रेलेवेंट सवाल किया गया है तो उस का जवाब भी रेलेवेंट ही होना चाहिये । जब पंजाब में घी की कीमत पूछी गई है तो पंजाब की कीमत ही बतानी चाहिए न कि मद्रास की मार्किट की कीमत बताने लग जाएं । वहां पर तो दूध तीन रुपए किलो बिकता होगा । इन को पंजाब की कीमतें बतानी चाहिए ।

**उपाध्यक्षा :** उन को कहने तो दें । (Let him speak.)

**राज्य मन्त्री :** इन को पता ही नहीं है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं । मैं कहने जा रहा था कि पंजाब में जितने भी गुड ब्रांड घी बिकते हैं उन में से बेरका प्लांट का घी सब से सस्ता है ।

**श्री बलरामजी दास टंडन :** क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पंजाब बनने वाले और बिकने वाले स्टैंडर्ड के कौन से घी हैं जिस से बेरके के बने घी की कीमत कम है ?

**राज्य मन्त्री :** मुझे पंजाब का तो पता नहीं है । जो कुछ मैं कहना हूं वह तो आप सुन लें । The good brands of ghee are Shiva, M Vasudev, Anik, Shakti.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ :** ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਉ ਹੈ 17 ਕਿਲੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦ ਬਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 915 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ । It does not include sales tax etc. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਉ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘਿਉ ਸਸਤਾ ਹੈ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ :** ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਮਿਲਕ ਵੂਡ ਪਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘੀ ਦੇ ਭਾ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ?

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰਤਨ ਘਿਉ ਬਣਿਆ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਿਉ ਹੈ ।

**ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ?

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ :** ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ "ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ," ਟਕੇ ਸੇਰ ਭਾਜੀ ਟਕੇ ਸੇਰ ਖਾਜਾ" । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਧ ਅਤੇ ਕਣਕ ਇਕ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ?

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਣੀ ਸੀ ?

**ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਦੁਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਵਡਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਇਹ ਸਵਾਲ ਘਿਉ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦੁਧ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ । (This question relates to ghee and not milk.)

**ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਿਉ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕਰੀਮ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ?

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਘਿਉ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਕਰੀਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਿਉ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ ਬਿਜ :** ਕਥਾ ਮਨ੍ਹੀ ਸਹੀਦਯ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਕੁਧਾ ਕਰੇਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗੁੜਗਾਂਵ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂ ਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨ ਦੂਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਹਲੀ ਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਧਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਤੈਧਾਰ ਹੈਂ ਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਹ ਆ ਕੀਮਤ ਤਧਾ ਖੋਧਾ ਵਨਾ ਸਕੇ ?

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਧ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਕ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਦੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਡਿੰਗਰ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਘਿਉ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਲਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਉ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ?

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਜੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਸ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜੇ ਆਨ-ਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਾਂਗਾ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਫਾਸ ਟੰਡਨ :** ਮਨ੍ਹੀ ਸਹੀਦਯ ਨੇ ਪਾਰਟ 'ਸੀ' ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੇਂ ਬਤਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਖਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲਗ ਭਗ ਪੀਨੇਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਧਾ ਵਹ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਜਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਕਖਨ ਕੀ ਇਤਨੀ ਝਧਾਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਨਟ੍ਰੋਲਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਸਮੇਂ ਤੈਧਾਰ ਕ੍ਰਿਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕਖਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਇਤਨੀ ਝਧਾਦਾ ਕਧੋਂ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ?

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਣੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਢੇ ਨੌ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਖਣ ਲੋਕਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਮਖਣ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ।

**Deputy Speaker :** Comrade Joga.

**ਡਾਕਟਰ ਕਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਂਧੰਟ ਆਫ ਆਡੰਰ, ਮੈਡਮ ।

**ਤਪਾਧਧਕਸ਼ਾ :** ਡਾਕਟਰ ਕਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਭੀ ਕੁਏਸਚਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਧਾ । ਆਪ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਦ ਜੋ ਪ੍ਰਊਨਾ ਚਾਹੂੰ ਪ੍ਰਊ ਸਕਤੇ ਹੈਂ । (Addressing Dr. Baldev Parkash : The question has not finished yet. Let first Shri Joga speak and afterwards he can ask whatever he likes.)

**ਡਾਕਟਰ ਕਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਂਧੰਟ ਆਫ ਆਡੰਰ ਪਰ ਖਡਾ ਹੁਆ ਹੂੰ । ਪ੍ਰਾਂਧੰਟ ਆਫ ਆਡੰਰ ਧਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਮਨ੍ਹੀ ਸਹੀਦਯ ਨੇ ਹਾਤਸ ਕੋ ਰਾਂਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ । ਵੇਰਕਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕੋ ਮੈਨੇ ਏਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਦਸ ਦਫਾ ਦੇਖਾ ਹੈ । ਵਹਾਂ ਕੇ ਜੇਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੀਰ ਸੇ ਧਹ ਬਾਤ ਹਮਾਰੇ ਧਧਾਨ ਮੇਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਹਾਂ ਸਕਖਨ ਬਨਾਕਰ

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

हम इसे साल, दो साल, और तीन साल तक भी रख सकते हैं क्योंकि यहां का चेम्बर माइनस दस डिग्री टेम्परेचर का है और वहां पर आदमी एक मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता, जम जाता है और वहां पर पहाड़ का पहाड़ मक्खन पड़ा था। उसने यह भी कहा कि उस मक्खन को अगले साल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसका घी बना कर बेचा जा सकता है लेकिन यह कहते हैं कि मक्खन वहां पर रखा नहीं जा सकता। यह बिल्कुल रांग इनफरमेशन है और मिनिस्टर साहिब को इस बात पर चैलेंज करता हूं।

**उपाध्यक्ष :** डाक्टर बलदेव प्रकाश, आप एक बड़े पुराने पार्लियामेंटरियन हैं। जब मैंने जोगा साहिब को सप्लीमेंटरी के लिए काल अपान कर लिया। तो उन को कह लेने देते और यह प्वायंट आफ आर्डर बाद में हो सकता था। (The hon. Member Dr. Baldev Parkash is an experienced Parliamentarian. When I had called upon Comrade Joga to put a supplementary, he should have let him ask it and this point of order could have been raised afterwards.)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** इन्होंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल रांग इन्फरमेशन है। आप इस बात पर रलिंग दें। इस से पहले सरदार गुरदर्शन सिंह ने एक सवाल किया तो उसके जवाब में मिनिस्टर महोदय ने कहा कि उनको इस बारे पता नहीं है और यह कि वह वेरीफाई करके बताएंगे लेकिन जब मैंने एक बात को प्वायंट आउट किया तो उसकी बाबत एक ग़लत इन्फरमेशन हाउस को दी जा रही है।

**Deputy Speaker :** Captain Rattan Singh.

**राज्य मंत्री :** डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं उं एिग विग उी ठगीं वि हेतवा पलांट विच डैमिलिटीज ठगीं उठ। मैं उं मँधठ ठूँ घाउठ उधठ घाठे उी विग मी (Interuptions) मैं एिग ठगीं विग वि हेतवा पलांट विच माडे वेल नगा ठगीं।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** डिप्टी स्पीकर साहिब, आप रिकार्ड देखें कि क्या कहा है।

**उपाध्यक्ष :** आप ने कहा था कि मक्खन एक ऐसी चीज़ है जो कि खराब जल्दी हो जाती है और यह कि इसे बाहर नहीं रखा जा सकता। आप अपनी बात पर कायम रहें। (The hon. Minister of State had stated that butter gets rntrefied soon and cannot be kept in the open for long. He should stand by this Statement.)

**राज्य मंत्री :** मैं अपनी बात पर कायम हूँ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ :** ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਿਉ ਅਤੇ ਮਖੌਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਿਉ ਅਤੇ ਮਖੌਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ?

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ।

*(Interruptions)*

**Deputy Speaker :** Comrade Shamsheer Singh Josh.

**Shri Balramji Dass Tandon :** On a Point of Order, Madam.....

**Deputy Speaker :** No, please. I do not allow your Point of Order. I have already called upon Comrade Shamsheer Singh Josh.

**Shri Balramji Dass Tandon :** I have risen on a Point of Order. Point of Order will be there.

**Deputy Speaker :** No, I won't allow. No Point of Order can be raised during Supplementaries.

**Shri Balramji Dass Tandon :** The Point of Order can be raised at any time.

**Deputy Speaker :** No, not like this. Please take your seat. (*At this stage, Shri Tandon took his seat.*)

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਿਉ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਤਾ, ਜ਼ਰਾ ਨਾਭੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘਿਉ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘਿਉ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਿਉਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਭੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘਿਉ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? *(Interruptions)*

**Shri Balramji Dass Tandon :** All wrong information is being given.

**Dr. Baldev Parkash :** Madam, he said rather ten times that it is the cheapest. We Challenge that it is not so.

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਉ । (*Captain Sahib may please reply to the supplementary put by Comrade Shamsheer Singh Josh.*) *(Interruptions)*

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ । *((Interruptions))*

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਉ । (*Captain Rattan Singh may please withdraw his words.*)

**Minister of State :** If my remark has injured any honourable Member, I am prepared to take it back, but they should not shout.

**Deputy Speaker :** No trouble should be created for the Chair.

**श्री बलरामजी दास टंडन :** डिप्टी स्पीकर साहिब, पहले इनके लफ्ज़ वापस कराओ ।

**ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵਧਮ ਲੈ ਲਏ ਹਨ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਉ ।

**Voices :** Point of order.

**कामरेड राम प्यारा :** क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि पंजाब में घी की कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि पंजाब में पब्लिक को घी बनाने की इजाज़त नहीं है और पंजाब से दूध देहली ले जाने की इजाज़त है और वहां पर इस से घी बनाया और बेचा जा सकता है ताकि पंजाब में लोगों को घी ना मिले ?

**Deputy Speaker :** The Question Hour is over now, but the supplementaries will go on tomorrow.

**Minister of State :** Not tomorrow, Madam. I will reply to supplementaries on the day according to the grouping.

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** डिप्टी स्पीकर साहिब, इस पर कल ही स्प्लीमैटरीज़ रखें ।

**उपाध्यक्षा :** कैप्टन रतन सिंह, प्रिपेयर्ड रिप्लਾईज़ और सही रिप्लਾईज़ आनी चाहिए । (*Addressing Captain Rattan Singh*) : The hon. Minister of State may please see that well prepared and correct replies to questions are given.)

**कैप्टन रतन सिंह :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं ने जितनी रिप्लाइज़ दी हैं वह उस इनफरमेशन के मुताबिक सही दी हैं जो मेरे पास है और मैं तैयार होकर आया हूं । (विघ्न)

**श्री बलरामजी दास टंडन :** यह जो हाऊस में मिसलीडिंग रिप्लाइज़ दी गई हैं और उन्होंने जो जवाब कल भी देने हैं उस के लिए यह प्रिपेयर हो कर आए । क्या मिनिस्टर को हाऊस में इस तरह से मिसलीडिंग रिप्लाइ देने चाहिए ?

**उपाध्यक्षा :** कितना अच्छा हो अगर आप बात को सुन लिया करें । जब चेयर ने यह कह दिया कि सही रिप्लाइ आने चाहिए, स्प्लीमैटरीज़ विल बी ऐलाउड तो उस के बाद भी कोई बात पैदा होती है ? हर वक्त चेयर को गाईड करने की कोशिश की जाती है । यह ठीक नहीं है । (How desirable it would be if the hon. Member listens to the Chair attentively. When the Chair has observed that correct replies should be given and that more supplementaries will be allowed on this question, what more is left to be impressed upon ? Every time an attempt is made to guide the Chair. This is not proper.)

ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਗੁਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ (ਹਾਸ) ।

WRITTEN ANSWER TO STARRED QUESTION LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

COMPLAINTS AGAINST THE SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY  
TO ANIMALS, AMRITSAR

**\*9107. Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state—

- (a) whether any complaints against the working of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Amritsar, were received by the Deputy Commissioner, Amritsar, in the year 1965;
- (b) whether it is a fact that the Deputy Commissioner, Amritsar, had ordered an enquiry by an Sub-Divisional Officer (Civil) into the said complaints/allegations; if so, the result of the enquiry and the action, if any, taken on the findings?

**Capt. Rattan Singh :** (a) Yes.

(b) **First Part :** Yes.

**Second Part :** The matter is under examination.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

INSPECTORATE/CLERICAL STAFF IN THE OFFICE OF THE DISTRICT FOOD  
AND SUPPLIES OFFICER, CHANDIGARH

**3175. Sardar Trilochan Singh Riasti :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total number and names with designations of the Inspectorate and Clerical staff working at present in the office of the District Food and Supplies Officer, Chandigarh, together with the total number and names of those belonging to the Scheduled Castes/Backward Classes amongst them;
- (b) the dates since when each of the officials referred to in part (a) above has been working in the said office;
- (c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to transfer those officials mentioned in part (a) above who have stayed at Chandigarh for more than three years, if so, the details thereof, if none, the reasons thereof?

**Shri Ram Kishan :** (a) & (b) Inspectors 12 (including one Scheduled Caste), Sub-Inspectors 6 (including two Scheduled Caste), Clerk 1.

[Chief Minister]

A list showing names and dates of joining of each of the officials in the office of the District Food and Supplies Officer, Chandigarh, is enclosed.

(c) There is no such proposal at present under the consideration of the Government. The transfer of the staff is generally taken up during March/April.

List showing the particulars of the members of the staff working in the office of the District Food and Supplies Officer, Chandigarh

Sr. No.	Name	Designation	Date of Joining	Whether from Sch. Caste/ Backward Class
1.	Shri Tarlochan Singh	.. Inspector	15-9-1963	Scheduled caste
2.	Shri V. K. Bhasin	.. „	27-11-1963	Nil
3.	Shri Sukhlal Dass	.. „	30-5-1964	Nil
4.	Shri Fauja Singh	.. „	19-10-1964	Nil
5.	Shri Har Mohinder Singh	.. „	18-11-1964	Nil
6.	Shri Kuldip Singh	.. „	13-1-1965	Nil
7.	Shri P. C. Gupta	.. „	14-1-1965	Nil
8.	Shri D. S. Sodhi	.. „	21-1-1965	Nil
9.	Shri Pritpal Singh	.. „	29-7-1965	Nil
10.	Shri Ajaib Singh	.. „	18-1-1965	Nil
11.	Shri Inder Pal Mohan	.. „	4-2-1966	Nil
12.	Shri Suraj Bhan Sharma	.. „	8-5-1964	Nil
13.	Shri Munshi Ram	.. Sub-Inspector	3-2-1963	Nil
14.	Shri Tarsem Lal	.. „	29-11-1963	Scheduled Caste
15.	Shri Baksha Ram	.. „	23-5-1964	Do
16.	Shri Jaspal Singh Pradeshi	.. „	27-1-1965	Nil
17.	Shri Naib Singh	.. „	6-10-1964	Nil
18.	Shri Deep Chand Jain	.. „	15-7-1964	Nil
19.	Shri Parshanta Sarwol	.. Clerk	16-11-1965	Nil

INSPECTORATE/CLERICAL STAFF IN THE OFFICE OF GENERAL MANAGER,  
PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR

3176. **Sardar Trilochan Singh Riasti** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- the total number and names with designation of the Inspectorate and Clerical staff working at present in the office of the General Manager, Punjab Roadways, Amritsar, together with the total number and names of those belonging to the Scheduled Castes/Backward Classes amongst them;
- the dates since when each of the officials referred to in part (a) above has been working in the said office ;
- whether there is any proposal under the consideration of the Government to transfer those officials mentioned in part (a) above who have stayed at Amritsar for more than three years, if so, the details thereof; if none, the reasons therefor?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) The transfers are considered on merits of each case in March every year in consultation with the General Managers of the respective units of Roadways.

**List of Inspectorate/Clerical Staff working in Punjab Roadways, Amritsar**

Sr. No.	Name of official	Designation	Date of posting in P. R. Amritsar	Remarks
1	2	3	4	5
Inspectorate Staff	Total—48	(i) Scheduled Castes		3
		(ii) Backward Classes		1
Clerical Staff	Total—99	(i) Scheduled Castes		3
		(ii) Backward Classes		1

**INSPECTOR STAFF**

1.	Shri Daljit Singh	.. Chief Inspector	1-5-1963
2.	Shri Shiv Bhola	.. "	2-8-1965
3.	Shri Harbans Singh	.. Inspector	23-5-1964
4.	Shri Mohinder Singh	.. "	5-5-1965
5.	Shri Natha Ram	.. "	26-4-1962
6.	Shri Narinder Nath	.. "	27-4-1960
7.	Shri Mohan Lal	.. "	27-4-1960
8.	Shri Jagan Nath	.. "	1-4-1963
9.	Shri Puran Singh	.. "	5-8-1964
10.	Shri Guran Duvaya	.. "	16-5-1960
11.	Shri Jagjit Singh	.. "	12-12-1961
12.	Shri Puran Chand	.. "	17-5-1965
13.	Shri Gurcharan Singh	.. "	3-1-1966
14.	Shri Gurdial Singh	.. "	5-5-1963
15.	Shri Hari Chand	.. "	13-5-1965
16.	Shri Kishan Singh	.. "	28-4-1961
17.	Shri Karnail Singh	.. "	1-2-1965
18.	Shri Tarlok Chand	.. "	7-11-1963
19.	Shri Kundan Lal	.. "	7-11-1963
20.	Shri Padam Kumar	.. "	4-5-1963
21.	Shri Manohar Lal	.. "	7-5-1962
22.	Shri Badha Mohan	.. "	22-1-1961
23.	Shri Rashbir Singh	.. "	5-5-1962
24.	Shri Swaran Singh	.. "	7-5-1963
25.	Shri Sarup Singh	.. "	1-9-1960
26.	Shri Pritam Singh	.. "	30-4-1963
27.	Shri Shamsheer Bahadur	.. "	22-8-1952
28.	Shri Gulzar Singh	.. "	16-6-1960
29.	Shri Krishan Kumar	.. "	5-5-1962

## [Transport and Elections Minister]

Sr. No.	Name of Official	Designation	Date of posting in P. R., Amritsar	Remarks
1	2	3	4	5
INSPECTOR STAFF—CONCLD				
30.	Shri Piara Singh	.. Inspector	12-12-1961	
31.	Shri Raghbir Singh	.. ..	14-12-1961	
32.	Shri Taswir Singh	.. ..	1-5-1962	
33.	Shri Kishan Chand	.. ..	1-7-1965	
34.	Shri Surajan Singh	.. ..	19-9-1962	Backward Class
35.	Shri Harbans Lal	.. ..	1-9-1962	
36.	Shri Surjit Singh	.. ..	1-9-1962	
37.	Shri Jugal Kishore	.. ..	13-3-1963	
38.	Shri Kartar Singh	.. ..	1-7-1964	Scheduled Caste
39.	Shri Sagli Ram	.. ..	13-8-1964	
40.	Shri Ram Murti	.. ..	24-5-1964	
41.	Shri Jagdish Parkash	.. ..	1-11-1965	
42.	Shri Kharaiti Lal	.. ..	1-11-1965	
43.	Shri Arjan Singh	.. ..	5-6-1965	
44.	Shri Swaran Singh	.. ..	24-3-1965	Scheduled Caste
45.	Shri Mohan Singh	.. ..	13-12-1965	Scheduled Caste
46.	Shri Harbhajan Singh	.. ..	7-1-1966	
47.	Shri Raj Kumar	.. Welfare Inspector	29-3-1965	
48.	Shri Kundan Singh	.. Station Super-visor II	13-5-1965	
MINISTERIAL STAFF				
1.	Shri Tirlochan Singh	.. Resident Senior Auditor	31-5-1962	
2.	Shri Parkash Singh	.. Accountant	14-10-1964	
3.	Shri Tilak Raj	.. Store Purchase Assistant	21-8-1950	
4.	Shri Pritam Singh	.. Asstt. Accountant	23-11-1957	
5.	Shri Kewal Krishan	.. ..	1-8-1956	
6.	Shri Ved Parkash	.. ..	5-1-1960	
7.	Shri Madan Mohan	.. ..	27-5-1957	
8.	Shri Chaman Lal	.. ..	28-7-1959	
9.	Shri Sudershan Lal	.. ..	11-10-1958	
10.	Shri Bhajana	.. ..	16-3-1960	Scheduled Caste
11.	Shri Jagdish Chander	.. ..	1-6-1958	
12.	Shri Khushi Ram	.. ..	11-6-1958	
13.	Shri Harbans Singh	.. ..	15-4-1958	
14.	Shri Dev Dutt	.. Cashier	28-1-1960	
15.	Shri Dharam Paul	.. ..	11-3-1957	
16.	Shri Chhaju Ram	.. Stenographer	16-9-1960	
17.	Shri Prem Kumar	.. Steno-typist	14-3-1960	
18.	Shri Sardar Mish	.. ..	14-3-1960	
19.	Shri H. L. Marwaha	.. Junior Auditor	19-3-1949	

Sr. No.	Name of official	Designation	Date of posting in P. R., Amritsar	Remarks
1	2	3	4	5
MINISTERIAL STAFF—CONTD				
20.	Shri B. N. Slaia	.. Juniot Auditor	13-5-1965	
21.	Shri Naranjan Singh	.. ..	1-5-1962	
22.	Shri Om Parkash	.. Booking Clerk	4-7-1958	
23.	Shri Ram Kishan	.. ..	1-5-1960	
24.	Shri Ghasita Mal	.. ..	3-5-1960	
25.	Shri Harpal Singh	.. ..	1-8-1961	
26.	Shri Beant Singh	.. ..	5-11-1959	
27.	Shri Tilak Raj	.. ..	11-8-1957	
28.	Shri Darshan Singh	.. ..	1-1-1961	
29.	Shri Harbans Singh	.. ..	17-8-1961	
30.	Shri Pavitar Singh	.. ..	1-7-1964	
31.	Shri Om Parkash	.. Asstt. Cashier	12-5-1962	
32.	Shri Ram Paul	.. ..	1-5-1963	
33.	Shri Prem Kumar	.. ..	18-9-1959	
34.	Shri Gurdip Singh	.. ..	5-3-1964	
35.	Shri Mohan Lal	.. ..	27-4-1960	
36.	Shri Kewal Krishan	.. ..	17-2-1962	
37.	Shri Gurnam Singh	.. Diarist	1-2-1964	Scheduled Caste
38.	Shri Karam Singh	.. Tracer	10-9-1961	Backward Class
39.	Shri Gurdip Singh	.. Ledger-Keeper	1-5-1962	
40.	Shri Kishan Chand	.. ..	11-12-1963	
41.	Shri Bal Krishan,	.. Chief Store-keeper	24-5-1963	
42.	Shri Prem Parkash	.. Typist	1-1-1961	
43.	Shri Tara Chand	.. ..	3-10-1964	
44.	Shri N. K. Taneja	.. Superintendent	12-5-1965	
45.	Shri Bua Ditta Mal	.. Assistant	18-1-1954	
46.	Shri Mohan Lal	.. Store-keeper	1-5-1965	
47.	Shri Rohani Kumar	.. ..	1-1-1962	
48.	Shri Prem Nath	.. ..	26-10-1960	
49.	Shri Gopal Dass	.. Restorer	3-12-1959	
50.	Shri Balbir Singh	.. D. P. A.	1-9-1962	
51.	Shri Roshan Lal	.. ..	13-11-1959	
52.	Shri Raj Paul	.. ..	1-2-1964	
53.	Shri Raj Kumar	.. ..	18-6-1963	
54.	Shri Darshan Kumar	.. ..	14-3-1963	
55.	Shri Krishan Lal	.. ..	1-10-1964	
56.	Shri Kailash Chander	.. Asstt. Store-keeper	1-8-1963	
57.	Shri Madan Lal	.. ..	1-7-1964	
58.	Shri Roop Lal	.. Clerk	2-11-1965	
59.	Shri Inderjit Singh	.. ..	12-3-1963	
60.	Shri Gurcharan Singh	.. ..	14-3-1963	

## [Transport and Elections Minister]

Serial No.	Name of official	Designation	Date of posting in P. R., Amritsar	Remarks
1	2	3	4	5
MINISTERIAL STAFF—CONCLD				
61.	Shri Sham Lal	.. Clerk	15-2-1963	
62.	Shri Gurbax Singh	.. ..	18-5-1965	
63.	Shri Iqbal Singh	.. ..	15-2-1963	
64.	Shri Balbir Singh	.. ..	10-5-1962	
65.	Shri Balwant Rai	.. ..	15-7-1964	
66.	Shri Roshan Lal	.. ..	22-5-1964	
67.	Shri Gurmit Singh	.. ..	22-5-1964	
68.	Shri Sardara Singh	.. ..	22-5-1964	
69.	Shri Raj Paul	.. ..	20-1-1966	
70.	Shri Yash Karan	.. ..	29-8-1964	
71.	Shri Shushil Chander	.. ..	1-8-1964	
72.	Shri Rattan Singh	.. ..	1-1-1965	
73.	Shri Ravinder Kumar	.. ..	11-6-1961	
74.	Shri Kewal Krishan	.. ..	8-10-1959	
75.	Shri Madan Lal	.. ..	13-8-1962	
76.	Shri Darshan Kumar	.. ..	13-2-1963	
77.	Shri Kewal Krishan	.. ..	1-5-1962	
78.	Shri Manmohan Singh	.. ..	1-3-1963	
79.	Shri O. P. Gosain	.. ..	1-6-1960	
80.	Shri Balbir Singh	.. ..	1-9-1964	
81.	Shri Janak Raj	.. ..	11-6-1958	
82.	Shri Sham Sunder	.. ..	1-10-1950	
83.	Shri Bua Dutt	.. ..	15-2-1963	
84.	Shri Piara Lal	.. ..	23-9-1965	Scheduled Caste
85.	Shri Ram Saran	.. ..	24-2-1955	
86.	Shri Kulbir Singh	.. ..	13-10-1960	
87.	Shri Manohar Singh	.. ..	4-5-1962	
88.	Shri Shanti Narain	.. ..	11-12-1950	
89.	Shri Bharat Bhushan	.. ..	1-5-1960	
90.	Shri Mohar Singh	.. ..	1-1-1964	
91.	Shri Dev Raj	.. ..	11-5-1965	
92.	Shri Mohinder Singh	.. ..	13-8-1962	
93.	Shri Sat Paul Singh	.. ..	6-9-1963	
94.	Shri O. P. Trikha	.. Station Supervisor	27-9-1965	
95.	Shri Sham Sunder	.. Clerk	13-3-1962	
96.	Shri Lekh Raj	.. Station Supervisor	1-6-1965	
97.	Shri B. S. Sodhi	.. ..	1-5-1963	
98.	Shri Sohan Lal	.. ..	4-5-1962	
99.	Shri Gurbachan Singh	.. P. M. A.	11-4-1963	

## DISPUTE OF WORKERS OF GIRSON TEXTILE MILLS, LUDHIANA

**3183. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether any case of dispute of the workers of the Girson Textile Mills, Ferozepore Road, Ludhiana was decided by the Industrial Tribunal, in favour of the workers in July, 1961; if so, a copy of the final decision be laid on the table ;
- (b) whether the recovery certificate was issued by the Labour Commissioner in the matter mentioned in part (a) above; if not, the reasons therefor ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Yes, Copy of Award dated 12th June, 1961, published with notification No. 2857-VIII-DALAB-61/23033, dated the 14th July, 1961 is enclosed.

(b) Yes, two recovery certificates have been issued after the receipt of computation orders of the Labour Court, Rohtak, dated 21st January, 1965 and on the receipt of the claim applications of the workers concerned.

BEFORE SHRI GIRDHARI LAL CHOPRA, PRESIDING OFFICER,  
INDUSTRIAL TRIBUNAL PUNJAB, PATIALA

Reference No. 7 of 1961

BETWEEN

The workmen and the management of Messrs Girson Textile Mills, Ludhiana.

*Present.—*

Shri Mohinder Singh Grewal, for the workmen.  
Shri M. R. Mittal, for the management.

## A W A R D

This is a reference under Section 10 of the Industrial Dispute Act made by the Government by No. 6557-VIII-USLab-60/3189, dated the 3rd February, 1961, for determination of the following industrial dispute between the workmen and the management of Messrs Girson Textile Mills, Ludhiana.—

Whether the action of the management in laying off/not providing work/terminating the services of the workmen (as per list attached) with effect from 9th September, 1960 was justified and in order? if not, to what relief they are entitled ?

On notices having been issued to the parties, the Union representing the workmen stated that the Respondent Mills employed about 107 workers and that the management refused entry and work to all of them on 9th September, 1960 or at any time thereafter without giving any notice of lay off, retrenchment, closure, dismissal or termination of service. The conciliation proceedings having failed this reference was made in respect of 74 of those workmen (list attached with the reference) and they claim to be marked present since 9th September, 1960 and to be paid full back wages. The management made a short out of the whole affair and took up the only plea that the persons concerned were not its workmen, but each one of them was an independent contractor and therefore they were not entitled to any relief. Nothing as to what had actually happened on 9th September, 1960 and as to whether the persons concerned were layed off or refused to be provided work or whether their services were terminated was stated. The following issues arose out of the pleading—

1. Whether the persons mentioned in the list attached to the reference were not workmen but were individual contractors and, therefore, no question of their lay off etc. arises ?
2. Whether the action of management in laying off, not providing work or terminating the services of the workmen (as per list attached) with effect from 9th September, 1960 was justified and in order.
3. If issue No. 2 be decided in favour of the workmen to what relief they are entitled ?

## [Irrigation and Power Minister]

## Issue No. 1

In support of this issue the management examined Shri Balwant Singh and Shri Amrit Lal, its Supervisor and Accountant, respectively, who stated that the names of the persons concerned were not entered in the attendance register because they were independent contractors and were paid on piece-rate basis and that no time was fixed for their working in the Mills, they could come and go at any time they liked. They further stated that the Mills closed in September, 1960, and thereafter only the medical staff, the sweepers and the Chaukidars continued in service and all others stopped working. In rebuttal the Union examined as many as 14 of the workmen concerned who unanimously stated that they were regular employees of the Respondent, some being paid monthly salary and others on piece-rate basis, that they attended and worked at the Mills at fixed timings and their attendance was duly noted, they had to and did apply for to obtain leave if they, for any reason, could not attend, that they were all governed by the Provident Fund and the employees State Insurance Schemes and that they were refused to be given any work when they attended on the 9th September, 1960, and on any day thereafter. Some of them have further stated that they were on certain occasions charge-sheeted by the management. Almost every one of them has produced his gate pass and the Provident Fund and the Employees State Insurance †Shri Bakshish Rai-Inspector, Employees State Insurance Corporation, Ludhiana, has appeared and stated that he used to visit and inspect the Mills in his official capacity and that on inspection of the books and other documents of the Respondent and its working he had come to the conclusion that the work at the Mills was not done through contractors but by regular employees of the Respondent. Tarsem Lal, Upper Division Clerk of the office of the Regional Provident Fund Commissioner, Ambala produced the statement of Provident Fund contribution prepared and filed by the Respondent with the department and also a copy of the representation made by the respondent on 23rd December, 1959 to the effect that the persons working with it were not covered by the term 'employees' Fund Act, but were independent contractors. The representation was, however, rejected by the Registrar, Provident Fund Commissioner,—vide his order dated 21st April, 1960.

Certain matters having remained in the dark, after the parties had closed their respective cases, I examined Shri M. R. Mittal representative of the management as a court witness and also got a statement (Ext. R. 4) prepared and filed by the management giving the length of service of each of the concerned workmen and the mode of payment of wages to him. He states: all the persons concerned, excepting Tehal Singh (No. 6 in the list attached to the reference) and Nachhatar Singh (No. 51) worked with the respondent as its employees till 30th April, 1960. Nachhatar Singh had already left service on 8th September, 1959 and Tehal Singh on 7th October, 1959. The remaining 72 of them started working as independent contractors from 1st May, 1960, continued to work as such up to 9th September, 1960 when the respondent closed the Mills on account of certain disputes having arisen between the partners. No document was executed when the status of the persons concerned as workmen was changed to that of independent contractors; it was only by means of an oral agreement noted in the Attendance Register. The piece-rate workers continued working at the same rates and those who were paid on monthly basis (23 in number) were made piece-rated on term orally and individually settled with them. Wages paid to them were no longer entered in the wages register but on separate sheets taken out of that Register. Prior to 30th April, 1960 and also thereafter up to 9th September, 1960, the Mills worked all the 26 hours and in three shifts.

The allegation of there being an oral agreement between the workers and the management is nothing but an after-thought and has to be rejected. No mention of it was made in the written statement filed by the management or by either of its witnesses. No question in cross examination regarding the alleged oral agreement was put to any of the workmen examined on behalf of the Union. There is no proof of evidence to corroborate the statement of Mr. Mittal examined as a court witness. A representation had in fact been made much earlier, i. e., on 23rd December, 1959, that the persons working with the respondent were not its employees but were independent contractors and that representation was rejected by the Central Provident Fund Commissioner on 21st April, 1960. It does not stand to reason that if any agreement was arrived at between the parties within nine days of the said order that would not have been reduced to writing.

---

†Not legible in the reply supplied by the Government.

The case of the respondent that the persons concerned were not its workmen was not put forward at any stage of the conciliation proceedings. The relevant record of the proceedings was produced by Shri Tara Singh, Labour and Conciliation Officer, Ludhiana (A 2) and he stated that Mr. B. C. Nanda, who appeared before him as attorney of the management on 29th September, 1960, on the other hand, admitted that the workers will not be marked absent and will be considered presenting themselves for duty ever since 9th September, 1960. It is so recorded in his order dated 29th September, 1960 (Ext. A. 2/30).

A part from all this, the facts disclosed by Mr. M. R. Mittal or stated by management's two witnesses cannot be regarded as sufficient to conclude that the relationship of master and servant had ceased, to exist on 30th April, 1960 or at any time thereafter. Prior to 30th April, it is admitted that the relationship did exist. The well recognised Test in the matter is whether the employer has only the right to direct the employee what work he is to do or whether he has the further right to direct how the work is to be done. The relationship of master and servant imports the existence of power of the employer not only to direct what the servant is to do but also the manner in which the work is to be done. In case [of a contract for service the master can order or require what is to be done while in the case of a contract of service he can not only order or require what is to be done but also how it shall be done (vide 1957, I LJ 177 S.C.)

In view of all the facts of the case I have no hesitation to hold that the persons concerned were and continued to be the workmen of the Respondent and decide the issue against the management. The persons were to work inside the factory and at fixed hours. They had to submit applications and obtain leave for absenting themselves. The nature of the work done by them required a good deal of control and supervision by the management. The mere fact that they were piece-rated, even if that were so, cannot be regarded as a decisive factor.

#### Issues No. 2 and 3

The case for the management is that certain disputes had arisen between the partners of the concern in the beginning of September, 1960, and the Mills, therefore, had to be suddenly closed on 9th. The Union contests, though only half-heartedly, the *bona fides* of the closure, and some of the workmen doubted even the factum of closure, and stated that the Mills had started working as before. There is no evidence whatsoever that there was any reason, other than the one stated by Mr. Mittal, for closing the Mills on 9th September, 1960. There appears to have been no trouble between the employees and the management, for which the latter wanted to get rid of them. At the close of the argument I, without any previous notice to management, inspected the Mills accompanied by the representative of the parties and found that only 3 or 4 of the looms out of 72 and two out of the 14 winding machines were in working order. Three or four spinners and two winders were present and they stated to be doing some casual work. The impression which I gathered, and that was shared by the representatives of the Union as well, was that the Mills had for all intents and purposes remained closed for a long time, not improbably from 9th September, 1960. There being no reliable evidence to the contrary that case for the respondent has, therefore, to be accepted. But since it is not shown that the undertaking was closed down on account of any unavoidable circumstances beyond the control of the employer and the case is not proved to fall under the proviso to Section 25 (FFF) I (F), the compensation has to be calculated as provided by Section 25 (F) of the Act, as already observed the only reason stated for the closure is that disputes had arisen between the partners. What those disputes were and how that necessitated the closure of the concern is not stated. Even that fact was disclosed at the very last stage of the case by Mr. Mittal when he was called as a court witness. There is thus no evidence what so ever that the circumstances on account of which the undertaking was closed were unavoidable and beyond the control of the Respondent.

Out of the 74 workmen concerned in the reference Tahal Singh (No. 6) and Nachhatar Singh (51) had already left service of the respondent on 7th October, 1953 and 8th September, 1959, respectively. Nanu ram (27), Darshan Singh (23), Natha Singh (43), Bhag Singh (44), Des Raj (57), Baldev Raj (61) and Jagiwan Singh (70) do not appear to have been in continuous services of the Respondent for one year on 9th September, 1960. These seven and also Tahal Singh and Nachhatar

[Irrigation and Power Minister]

Singh, who already left service, are, therefore, not entitled to any compensation. The remaining 65 of the workmen mentioned in the list attached to reference are entitled to compensation, as provided by Section 25 (F) of the Act. They shall get one months wages in lieu of notice and also compensation equivalent to 15 days average pay of wages for every completed year of service or any part thereof in excess of six months. The payment shall be made within three months of the publication of the award.

I decide the issue and pass my award accordingly.

12th June, 1961

Sd/-Presiding Officer,  
Industrial Tribunal, Patiala.

DISPUTE OF WORKERS OF GIRSON MILLS, TEXTILE DEPARTMENT, LUDHIANA

**3184. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether any dispute of the workers of the Girson Mills Textile Department, G. T. Road, Miller Ganj, Ludhiana, for increasing the rates of their daily wages is pending with the Labour Commissioner, Punjab, if so, since when;
- (b) the reasons why no decision has so far been given in the said dispute ;
- (c) whether he is aware of the fact that the delay in taking a final decision in the said dispute has encouraged the owners of the said Mill to retrench their workers in large numbers; if so, the names of the workers who were retrenched by the Mill-owners since the pendency of the above-mentioned decision?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Yes, since 31st December, 1965.

(b) The failure report received from Conciliation Officer, Ludhiana on 31st December, 1965, was incomplete and necessitated a back reference. The Conciliation Officer, Ludhiana has not been so far able to send his final reply as he is busy in connection with the distribution of loans to Industrial Workers at Amritsar.

(c) There has been large scale retrenchment in this Mill after this dispute. The services of the following four workers have, however, been terminated on the dates mentioned against each but the same is not due to any alleged delay in finalising the dispute case:—

- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Shri Ram Charan   | .. 7-2-1966                          |
| 2. Shri Surjit Singh | .. 22-1-1966                         |
| 3. Shri Jagan Nath   | .. Not provided work since 17-1-1966 |
| 4. Shri Hukam Chand  | .. 18-1-1966                         |

HEART-ATTACK SUFFERED BY A DETENU ON 27TH JANUARY, 1966 IN THE  
PUNJAB HIGH COURT

**3185. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether it is fact that a detenu fainted with a severe heart attack on 27th January, 1966, in the High Court where he was present in connection with his writ petition ;

- (b) the medical report in regard to the said detenu submitted by the Medical Specialist at Chandigarh who examined him be laid on the Table of the House?

**Sardar Darbara Singh :** (a and b) Yes. A copy of letter No. P.M.O. (4)66/1562, dated 16th February, 1966 from the Principal Medical Officer Chandigarh about the action taken and the detailed report regarding the detenu's medical examination is enclosed.

Copy of letter No. P. M. O(4)66/1562, dated 16th February, 1966, from the Principal Medical Officer, Chandigarh, to Shri Tulsi Dutt, A.S.I., Sector 17, P. S. Chandigarh, and a copy forwarded to the Director, Health Services, Punjab, Chandigarh.

**Subject:—**Medical Legal Report of the detenu who fainted with heart-attack on 27th January, 1966 in the High Court, Punjab, Chandigarh.

Reference your letter dated 16th February, 1966, on the subject noted above.

2. On 27th January, 1966, at 2 p. m. I got a telephonic message from the Reader of Justice R.P. Khosla's Court that Shri Makhan Singh Tarsika, M.L.A. had got an heart-attack and I was asked to attend to him immediately in the High Court. I reached there immediately and found him lying on a bench in front of the court room of Justice R. P. Khosla. On examination I found that he was quite conscious, pulse was 100 per minute and blood pressure was 130/90. He gave the history of sinking sensation and pre-cardial discomfort. I gave him injection of pathedine 100 mg and shifted him immediately to the Hospital. He was kept in the hospital from 3 p. m. till next morning. On going into the detailed history I found that he was being investigated at Rajindera Hospital, Patiala. His electro-Cardiogram was taken immediately and he did not show any change from his previous Electro-Cardiogram. He was found to be suffering from coronary insufficiency.

advised to was already under the treatment of Dr. Amarjit Singh and was He continue the same treatment.

#### WOOL TOP QUOTA DRAWN BY THE MILL-OWNER OF KASHMERE WOOLLEN AND SPINNING MILLS, INDUSTRIAL AREA, LUDHIANA

**3186. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Mill-owner of the Kashmere Woollen and Spinning Mills, Industrial Area (A) Ludhiana, is getting wool top quota regularly every month; if so, how much and since when;
- (b) whether it is a fact that the said Mill-owner closed his mill about four months ago but he is still drawing his quota regularly; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken in the matter ?

**Shri Ram Kishan (Chief Minister) :** (a) and (b) Allotment of wool top quota is made by the Textile Commissioner, Bombay (Government of India), direct. This information is not, therefore, available with the State Government.

## REPRESENTATION FROM PUNJAB SUBORDINATE SERVICES FEDERATION

**3187. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has considered the representations recently submitted by the Punjab Subordinate Services Federation regarding the demands of the Government employees in the State; if so, a copy of the said representation together with the action, if any, taken or proposed to be taken thereon be laid on the Table of the House ?

**Shri Ram Kishan :** The Government have received many representations from the Subordinate Services Federation. In the absence of specific date of the representation, a copy of the same is not being enclosed. The various demands of the Federation are, however, under examination of the Government.

## FOOD PRODUCTION TARGETS

**3188. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the details of targets of food production achieved in the State during the year 1963-64, 1964-65 and 1965-66 with the details of special efforts made to achieve the same ;
- (b) the details of fertilizers distributed during the period mentioned above district-wise ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) The details of production of foodgrains and other commodities achieved in the State during the year 1963-64, 1964-65 are given below:—

Crop	(Figures in, 000 tons/bales)	
	1963-64	1964-65
Rice	529	662
Maize	798	776
Bajra	296	343
Jowar	48	51
Wheat	2,789	3,399
Barley	110	185
Gram	1,099	1,619
Other	75	74
Foodgrains (Total)	5,744	7,109
Sugarcane	879	1,115
Cotton	1,165	1,080
Oilseed	176	309

It is too early to assess the estimates of production of Kharif and Rabi crops for the year 1965-66 as the return of crop cutting experiments based on random sampling method undertaken by the field agency are still being received and the dates of release of the final forecasts for the Kharif crops starts from the 15th February onward. For the Rabi crops the crop-cutting experiments are yet to be planned and area figures are not yet available. The Agriculture Department is already making strenuous efforts to step up agricultural production and the following measures have been adopted in this direction.

#### **Fertilizers—**

(i) The quantity of nitrogenous and phosphatic fertilizers used during the year 1964-65 were 9,78,239 and 24,249 tons, as against, 1,63,083 tons and 14,372 tons during the year 1963-64, respectively. During the year 1965-66, it is estimated to consume about 325,000 and 25,000 ton of nitrogenous and Phosphatic fertilizers.

#### **Seeds—**

About 2.5 lakh maunds of wheat seed, 25,000 maunds of rice and 5,000 maunds of Hybrid maize seed was distributed during the year 1964-65 against 70,000 maunds of wheat, 16,000 maunds rice and 12,000 maunds of Hybrid Maize during the year 1963-64. During the year 1965-66, 3.25 lakh maunds of wheat and 25,000 maunds of rice seed have been distributed.

#### **Intensive Agricultural Area Programme—**

In addition to Intensive Agricultural District Programme Ludhiana, Intensive Agricultural Area programme on Cotton, Rice, Maize, Wheat and Groundnut have been undertaken in potential Blocks of the State. The coverage of the blocks during the year 1965-66 is as under—

#### *No. of Blocks*

Rice	..	30
Maize	..	4
Cotton	..	30
Wheat	..	15
Groundnut	..	5

#### **Wheat—**

(iii) It is the most important food crop of this State and constitutes about 50% of the net food production. A package programme on wheat was started during the year 1964-65 in 58 selected blocks of Amritsar, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jullundur, Kangra, Sangrur, Kapurthala, Bhatinda, Ferozepur, Karnal and Rohtak Districts covering an area of 5.80 lakh acres. All the area covered under package programme on cotton, rice and ground-nut was also included in this programme in order to utilize the staff for the whole year. This programme has been extended to 84

[Home and Development Minister]

blocks during the year 1965-66 on an area of 8.75 lakh acres. Approximately, 80,000 maunds of seed of improved varieties of wheat was supplied in these blocks last year out of the total quantity of 2.50 lakh maunds supplied departmentally throughout the State. A sum of Rs 15 lakh was advanced as short-term credit especially to the small farmers and tenants for the purchase of wheat seed. Intensive education campaigns were organised which included 17,400 crop production plans, 580 training camps to train in 34,000 farmers and 580 demonstration centres.

The area under wheat increased from 58.15 lakh acres during the year 1963-64 to about 60.28 lakh acres in 1964-65, and a record production of about 33 lakh tons, i.e., 5.11 lakh tons more than the previous record production of 27.89 lakh tons was obtained.

#### **Rice—**

(iv) The rice crop covers an area of about 13 lakh acres and is becoming another very important food crop of the State. The package programme on rice was started during the year 1964-65 in 22 selected blocks covering an area of 177,500 acres in the districts of Amritsar, Gurdaspur, Karnal, Hoshiarpur and Kangra. During the year 1965-66, this programme has been further extended to 30 blocks on an area of 312,000 acres under the package of improved practices. As a result of intensive campaign and the use of increased inputs like improved seeds, fertilizers, insecticides etc., the production of crop showed a remarkable increase. The crop has given a record production of 6.62 lakh tons of rice during the year 1964-65 as against the previous highest figure of 5.29 lakh tons during the year 1963-64. The average yield per acre reported last year was 21 maunds which is the highest obtained so far.

#### **Hybrid Maize—**

(vi) In order to popularise the use of hybrid maize seed, a scheme was introduced in 1961-62 in the districts of Karnal, Ambala, Patiala, Sangrur, Ludhiana, Jullundur, Ferozepur, Hoshiarpur, Kapurthala, Amritsar, Gurdaspur and Kangra, for the purpose of laying out demonstration plots etc. As a result of the efforts made under this scheme so far, the area under Hybrid Maize has risen to nearly 31,000 acres during the year 1964-65. About 5,000 maunds of seed of Hybrid maize was supplied.

#### **Minor Irrigation—**

(vii) 6,800 tube-wells were energized during 1964-65. The S. E. B. Planned to energize 7,000 tubewells during 1965-66. The State Government provided special funds to the S. E. B. to enable them to energize 11,000 tubewells.

Rs 200.52 lakhs were advanced as loan for minor irrigation during the year 1964-65. During the year 1965-66, the amount of loan provided for this purpose is Rs 198.80 lakhs.

(b) Details of fertilizers distributed during the years 1963-64, 1964-65 and 1965-66 (up to 30th November, 1965) are given in the enclosed statement.

## Statement showing district-wise consumption of fertilizers during 1963-64 and 1964-65.

Serial No.	District	Quantity distributed during 1963-64			Quantity distributed during 1964-65		
		Nitrogenous	Phosphatic		Nitrogen	Phosphate	
1.	Amritsar	14,604	785		18,534	1,404	
2.	Ambala	8,816	818		15,251	1,903	
3.	Ferozepur	31,232	787		45,490	1,348	
4.	Gurdaspur	7,105	341		12,228	817	
5.	Gurgaon	4,019	115		7,158	205	
6.	Hoshiarpur	9,468	812		16,278	1,357	
7.	Hissar	11,084	427		16,771	639	
8.	Jullundur	15,187	1,038		24,732	1,955	
9.	Kangra (Kulu)	2,088	91		4,897(402)	344(139)	
10.	Karnal	9,213	907		16,823	1,620	
11.	Ludhiana	16,082	5,661		27,388	7,761	
12.	Rohtak	7,351	300		13,280	320	
13.	Patiala	7,353	840		12,612	2,013	
14.	Bhatinda	13,411	405		19,288	620	
15.	Sangrur	10,599	485		18,483	1,107	
16.	Kapurthala	3,170	477		6,104	1,180	
17.	Mohindergarh	1,032	13		2,239	86	
18.	Kulu	269	66		71	26	
		1,63,083	14,372		2,78,629	24,249	

[Home and Development Minister]

District-wise Consumption of Fertilizers during 1965-66 up to 30th November,

Serial No.	District		Nitrogenous	Posphatic
1.	Amritsar	..	12,888	1,014
2.	Ambala	..	12,694	1,851
3.	Ferozepur	..	27,763	917
4.	Gurdaspur	..	8,677	616
5.	Gurgaon	..	5,950	143
6.	Hoshiarpur	..	12,968	1,002
7.	Hissar	..	10,780	184
8.	Jullundur	..	17,006	2,203
9.	Kangra	..	3,449	292
10.	Kulu	..	355	113
11.	Karnal	..	10,540	935
12.	Ludhiana	..	30,330	6,347
13.	Rohtak	..	10,179	167
14.	Patiala	..	9,316	1,454
15.	Bhatinda	..	12,063	529
16.	Sangrur	..	12,408	848
17.	Kapurthala	..	4,722	1,022
18.	Mohindergarh	..	891	27
19.	Simla	..	40	4
Total		..	2,02,949	19,668

#### PLYING ROADWAYS BUSES UP TO VILLAGE TARSIKKA PROPER IN AMRITSAR DISTRICT

**3189. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the reasons for not plying Roadways buses up to village Tarsikka proper in district Amritsar in spite of repeated demands made to the Government ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** Portion of route from Tarsikka proper to metalled road is unmotorable.

#### GENERAL MANAGER, PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR

**3190. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) whether an enquiry was held against the General Manager of Amritsar Roadways, for having a car of his friend got repaired by sending Roadways workshop employees in a private workshop daily for more than 15 days during the year 1964; if so, the details of the action taken against the General Manager, so far;

- (b) copies of the D. O. letters of S. S. P., Amritsar and his report to the higher authorities regarding the said enquiry be laid on the Table;
- (c) whether it is a fact that the State Authorities deputed the A. I. G., Traffic for holding the enquiry on the spot in the said case; if so, a copy of the report submitted by him be laid on the Table ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) Yes. The enquiry report has been received and the same is under examination for further necessary action.

(b) It would not be in public interest to lay the documents/report on the Table of the House.

(c) (i) Yes.

(ii) It would not be in public interest to lay copy of the report on the Table of the House

---

#### ENQUIRIES CONDUCTED BY THE KARNAL POLICE

**3192. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Home and Development with reference to the reply to Unstarred Question No. 3013 included in the list of Questions for 1st November, 1965, be pleased to state—

- (a) whether any more affidavit/affidavits from Shri Ram Sarup of Karnal in addition to the affidavit and application referred to in part (a) of the said reply has/have been received under Regd. cover by the D. I. G., Ambala Range; if so, when, and a copy each of the same be laid on the Table of the House;
- (b) whether after the receipt of the affidavit, if any, after 15th November, 1965, any enquiry either from Shri Ram Sarup or from the D. S. Police, Panipat, has been made, if so, the details thereof; if not made, the reasons for not doing so ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes. A copy of the affidavit dated 27th December, 1965 of one Ram Sarup of Karnal received in the office of the Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range on 31st December, 1965 is placed on the Table of the House.

(b) Yes. An enquiry regarding the contents of the affidavit dated 27th December, 1965 was got made through D. S. P., Panipat. During the enquiry, Ram Sarup author of the affidavit unequivocally stated that whatever statements he had already made were correct. Regarding this affidavit he stated that it was extorted from him by Comrade Ram Piara, M. L. A. and Lala Hari Ram of Karnal. A copy of Shri Ram Sarup's statement to the Enquiry Officer is laid on the Table of the House.

---

[ Home and Development Minister ]

## AFFIDAVIT

I, Ram Sarup son of L. Budh Ram, resident of.....  
House No. D-171, Nawab Chhatta, Karnal do hereby solemnly affirm/declare :—

- (1) That I know Shri Atal Bihari Mathur, Sub Inspector Police since 1948 when he was Lines Officer there and I was a Head Constable Police posted at Hissar.
- (2) That I know Shri Hari Ram son of L. Jhandu Mal as a respectable citizen of Karnal.
- (3) That a case of theft of register No. 11, History Sheet and Personal File from the records of P. S. City Karnal was registered and Shri Hari Ram aforesaid and one Budh Ram constable were suspected in the F. I. R.
- (4) That Shri Atal Bihari Mathur expecting me to ditto showed me as an informer implicating Shri Hari Ram and Budh Ram in the above case.
- (5) That I never passed on any information to him nor I have any such information.
- (6) That in order to save himself from a tight corner first prevailed upon me to say as he desired of me to say but when I did not agree to oblige him he threatened me with dire consequences.
- (7) That he then required of me to make a statement of choice before D. I. G., Ambala Range at pain of arrest in some untraced burglary case and I vomited out the tutored statement out of fear and apprehension of arrest.
- (8) That thereafter to supplement it, he got my signature on some document addressed to Shri Prem Kumar, D.S.P. Karnal which was cleverly finished at a space, leaving some of it to introduce a line or so and I signed it without knowing the contents of matter to be added.
- (9) That in fact I know nothing as to how the record, if at all, was stolen and Shri Hari Ram never talked to me of the affair.

Dated 27-12-1965.

*Deponent*—Ram Sarup.

Sd/-RAM SARUP.

I hereby solemnly declare and affirm that the above contents are true to the best of my knowledge and belief and that nothing in this respect has been concealed or withheld by me.

Sd/-RAM SARUP.

Ram Sarup—*Deponent*.

Verified at Karnal dated 27-12-1965.

Identified the deponent and he has signed in my presence.

Sd/-

DALIP SINGH  
Advocate.  
27-12-1965.

*Attested:*

Sd/-

M. I. C. Karnal.  
29-12-1965.

SIR,

I beg to state that I have seen my affidavit dated 27-12-1965 which bears my signatures. It was extorted from me by L. Hari Ram and Shri Ram Piara, M.L.A., Karnal under influence. In the month of December Shri Daryao Singh, D. S. P. C. I. D. had come for the investigation of theft of history sheet and personal file of Hari Ram from the P. S. City Karnal. As Hari Ram was apprehensive of his arrest, he and Shri Ram Piara approached me with the request that I should give an affidavit in order to devalue my previous statements given before the D. S. P. Karnal and D. I. G. Ambala Range. The allegations against S. H. O. City Karnal raised in the affidavit are totally incorrect. The statements already given before the D. S. P. and the D. I. G. Ambala Range are correct.

Sd/-RAM SARUP MALHOTRA.

Dated 7-2-1966.

Ram Sarup Malhotra s/o  
L. Budh Ram, House No. D—171  
Nawab Chhatta,  
Karnal.

Attested:

Sd/-Prem Kumar,  
D. S. P.  
7-2-1966.

## STEEL QUOTA TO KNITTING MACHINERY MANUFACTURERS IN LUDHIANA.

**3193. Comrade Makhan Singh Tarsikka:** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the manufacturers of knitting machinery in Ludhiana who are getting steel quota at present along with the quantity of quota allotted to each?

• **Shri Ram Kishan :**

Sl. No.	Name of the manufacturers of knitting machinery	Quota allotted during 1965-66 (B.P. Sheet)
1.	M/s Raj Mechanical Industries, Ludhiana	2.000 Metric Tons
2.	M/s Swarup Mechanical Works, Ludhiana	2.300 „
3.	M/s Bharat Machinery Works, Ludhiana	2.200 „
4.	M/s Sartaj Machinery Works, Ludhiana	9.758 „

## WOOL AND ART SILK QUOTA HOLDERS IN LUDHIANA

**3194. Comrade Makhan Singh Tarsikka:** Will the Chief Minister be pleased to state the names and addresses of those who are at present getting quotas of wool and art-silk in Ludhiana with the quantity of quota allotted to each and the criteria kept in view in allotting the said quota?

**Shri Ram Kishan:** There is no control over distribution of wool and art silk. The question of allotting quotas of these materials, therefore, does not arise.

PETITIONS RECEIVED BY THE DISTRICT CONCILIATION OFFICER, LUDHIANA

**\*3195. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the number, names and addresses of the workers from whom petitions were received by the District Conciliation Officer, Ludhiana, during the years 1964-65, and 1965-66, together with the result in each case;
- (b) the names and addresses of those whose petitions are still pending alongwith dates on which each of the applications was received and the reasons for its non-disposal so far ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Under the Industrial Disputes Act, a Conciliation Officer can take cognizance of Demand Notices by Trade Unions only and not individual workers.

The requisite information for petitions received by C. O. Ludhiana, is, therefore, nil.

- (b) Question does not arise in view of (a) above.

#### POINTS OF ORDER

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਂਡਮ । ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਐਂਸੋਅਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤਵੱਜ਼ੁਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕਾਂਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜ ਇਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ.....

**उपाध्यक्ष :** आप ने जो यह कहा है यह ठीक है, सुनासिब है । इस के मुतालिक स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं । अगर 9-10 दिन में न आए तो आप सवाल फिर खडा कर दें । (Whatever the hon. Member has said is right and proper. In this connection the hon. Speaker is having a talk with the Chief Minister. If no statements are received from the Government within nine or ten days, then the hon. Member may raise this point again.)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ "ਨਹੀਂ", ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ।" ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.. ..

**उपाध्यक्षा :** बाबू जी, रुज़ज़ की किताब मैं ने भी पढ़ी हुई है और आप ने भी पढ़ी हुई है । आप बहुत वक़्त ले चुके हैं । अब मेहरबानी करें और बाकी मैम्बरों को बोलने दें । I agree with you. (The hon. Member Baboo Bachan Singh has read the rules of procedure and so have I. He has already taken a lot of time. Now he may please allow other Members to speak. I agree with him.)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ.....

(At this stage Deputy Speaker was on her legs.)

**Deputy Speaker :** Baboo Bachan Singh Jee, will you take your seat ?

**Baboo Bachan Singh :** No, I will not take my seat. I am raising a point of Order and I must raise it.

**उपाध्यक्षा :** मैं खड़ी हूँ, आप बैठिये । (विघन) मैं ने यह कहा है कि यह किताब मैं ने भी पढ़ी हुई है, आप ने भी पढ़ी हुई है, अब गवर्नर के ऐड्रेस पर बहस चलने दें (विघन) आप तो पुराने और सियाने पार्लियामੈटेरियन हैं, आप को हाउस चलाने में मदद देनी चाहिये । It is no point of order. (Baboo Bachan Singh again rose to speak) अभी तो मैं खड़ी हूँ । देखिये यहां पर सप्लीमेंटरीज के वक़्त प्वायंट्स आफ आर्डर होते हैं, बहस के वक़्त प्वायंट्स आफ आर्डर होते हैं । इस में बहुत वक़्त लग जाता है, और बोलने वालों की हक़ तलफ़ी होती है । वरना आप को कौन रोकता है, आप सारा दिन यह प्वायंट्स आफ आर्डर रोज़ करें । (I am standing and therefore the hon. Member may resume his seat. (Interruption) I have said that I have read the Rules of procedure and he too is fully conversent with it. So he may let the discussion on Governor's Address proceed. (Interruption). He is an experienced parliamentarian of long standing. He should rather help in smoothly conducting the proceedings of the House. It is no point of order.

[Deputy Spaker]

I am still on my legs. Please listen. Here points of order are raised at the time of supplementaries and the same thing is done during the debate. This takes a lot of time and deprives the Members of their right to speak. Otherwise who prevents them from raising the points of order? They may go on for the whole day.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਜਦ ਤਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 'It is no point of order, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ। (ਵਿਘਨ) (I would in future hear the point of order raised by the hon. Member. Now he may please resume his seat.) (*Interruptions*)

#### ADJOURNMENT MOTION

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਂਡਮ। ਮੈਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.....

उपाध्यक्षा : अगर आप इसी तरह से प्वायंट्स आफ आर्डर रोज़ करते रहें तो इस में हाउस का बहुत बुरा लग जाता है, सैंबरों का नुकसान होता है। (If the hon. Members continue to raise points of order like this then this will consume considerable time of the House and that too at the cost of the hon. Members who would consequently suffer.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲਖ ਟਨ ਗੰਨਾ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਪੀੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਆਣਾ। (The hon. Member is aware that adjournment motions are seldom allowed during the Budget Session. The Governor's Address is under discussion and he can have ample opportunity to express himself fully on the subject. If anything is left, the motion can be brought in later on),

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ । (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।

उपाध्यक्षा : यह बहुत अहम मामला है, ठीक है । मैं ने कहा है कि आप बहस में इसे उठाइये । अगर इस तरह से यह हल न हो तो मैं आप के साथ हूँ । मगर इस तरह से इसे रेज़ करना सुनासिब नहीं । (विघन) (It is true that this is a matter of vital importance. What I have said is that the hon. Member may raise it during the debate. If still it remains unsolved, then I am with him to help him. But it is not proper to raise this matter in this way.) (Interruptions)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਦੀ ਮਿਲ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ । (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : आप ही हाउस के मੈम्बर नहीं । औरों को भी एड्रेस पर बोलने दें । (विघन) (Addressing Comrade Shamsheer Singh Josh : You are not the only Member of this House, let the other hon. Members also speak on the Address.) (Interruptions)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह हज़ारों किसानों का मसला है । पिछले साल उन को डी. आई. आर. के तहत गिरफ्तार किया जाता रहा है कि गन्ना नहीं देते । अब उनका गन्ना उठाया नहीं जा रहा । (विघन)

उपाध्यक्षा : आप मुझे अपनी सारी बात मेरे चैम्बर में बताइये । (विघन) (The hon. Member may explain the whole matter to me in my Chamber.) (Interruptions)

(A number of Members from the Opposition Benches rose to speak.)

Deputy Speaker : Sardar Gurnam Singh ji, I seek your help.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ : ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ । (ਵਿਘਨ) ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : हमारे इलाके के हज़ारों किसान गन्ना देने के लिये मारे मारे फिरते हैं । फिर सीजन चला जाना है । (विघन)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ : ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । *Inter-  
rptions.*)

*(A number of members from the opposition spoke simultaneously.)*

ਤਪਾਧਕਸ਼ਾ : ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ । ਆਪ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਝਾ ਦੋ । *(I cannot allow them to speak in this fashion. They should see me in my chamber and explain the whole position.) (Inter-  
ruption.)*

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਉ ਤੇ ਕਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿਨਸ ਕਰਾ ਦਿਉ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਟੋਕ ਅਪ ਕਰਨ ਵਿਚ । *(ਵਿਘਨ)*  
*(I do not approve of such like pressure tactics. I have already stated that they should first convince me as to its admissibility, then I, too, would join them in taking up this matter.) (Interruptions)*

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਸਟ । ਮੈਂ ਕਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ । *(ਵਿਘਨ)* *(The hon. Member has requested that discussion be allowed on this subject. But I have already said that I would like to be convinced first. I shall make observations about this tomorrow.) (Interruptions)*

## DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS

(Resumption)

**Deputy Speaker :** Bakhshi Partap Singh will resume his speech on the discussion on Governor's Address.

बख्शी प्रताप सिंह (पालमपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं पिछले कल कांगड़ा की वीर भूमि के डोगरा नौजवानों ने जो शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाए थे और जिन के जरिए बजा तौर पर सारे देश का गौरव बढ़ा है उनका जिक्र कर रहा था। मुझे इस बात की निहायत खुशी है कि पंजाब सरकार ने इस बात का पूरी तरह एहताम किया है। गवर्नर साहिब के भाषण में यह भी जिक्र है कि पंजाब सरकार ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने का फैसला किया है।

(इस समय सरदार गुरनाम सिंह, पैनल आफ चेयरमैन के एक सदस्य, ने कुर्सी संभाली)

फौजियों की बेहतरी और बहबूदी के लिए सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को यह काम सौंपा गया है कि साबिक फौजियों को रोजगार मुहैया किया जाए। चेयरमैन साहिब, फौजियों की इमदाद के लिए ग्रांटें मंजूर की गई हैं और दूसरी किस्म की इमदाद देना भी मंजूर किया है। इस के लिए पंजाब सरकार हमारी सब की मुबारिकबाद की मुस्तहिक है। लेकिन, चेयरमैन साहिब, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सिवल एडमिनिस्ट्रेशन ने इमदादी ग्रांटों की तकसीम के वक्त जो बदतरीन सबूत पेश किए हैं उन्हें देख कर सर शर्म से झुक जाता है। चेयरमैन साहिब, मेरे हलका नुमाइन्दगी के अन्दर यह ग्रांटें तकसीम करते वक्त एस. डी. ओ. (सिवल) पालमपुर, की तरफ से शाही फरमान जारी हुए जिन के मुताबिक शहीदों की नौजवान बेवा औरतों को देहात के मर्कजी मकामात पर सूर्य निकलते ही बुला लिया और सूर्य छिपने तक वहीं रखा गया। लेकिन, चेयरमैन साहिब, शाम तक वहां पर कोई सरकारी कर्मचारी एक्सप्रेशिया ग्रांट तकसीम करने के लिए नहीं आया। फिर रात के अन्धेरे में बी. डी. पी. ओ., बैजनाथ की मारफत ग्रांट तकसीम की गई। गवर्नर साहिब ने अपने एड्रेस में यह भी फरमाया है कि हमारी गवर्नमेंट अपनी बेहतरीन काबलियत के मुताबिक शहीदों के खानदानों की पूरी देख भाल करती रहेगी। लेकिन, चेयरमैन साहिब, सरकारी कर्मचारियों की जिस सेवा का नक्शा मैं ने अभी अभी इस सदन के सामने पेश किया है अगर इसी किस्म की सेवा होती रही तो फिर खुदा हाफिज़।

चेयरमैन साहिब, गवर्नर साहिब ने अपने एड्रेस में पंजाब की तरक्की और तामीर का जिक्र किया है लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पहाड़ी इलाका जात के बारे में गवर्नर साहिब के एड्रेस में सिर्फ एक ही फिकरा कलमबन्द है।

[बख्शी प्रताप सिंह]

“हिल ऐरियाज की माँग को पूरा करने के लिए हर साल अलग योजना बनाई जाती है।”

चेयरमैन साहिब, यह जो योजना का जिक्र किया गया है कि पहाड़ी इलाका-जात की तरक्की और जरूरियात को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसको इस पैमाने से नहीं नापा जा सकता। मैं ने पहले भी इस सदन में इस बात का जिक्र किया था कि अगर पहाड़ी इलाके की तरक्की को नापना है तो एक इवेलूएशन कमेटी मुकर्रर की जाए। वह देखे कि पहाड़ी इलाके में पर कैपिटल कितनी आमदन है, खेती बाड़ी के मैदान में कितनी तरक्की हुई है, सड़कों के मैदान में कितनी पुख्ता सड़कें बनाई गई हैं। यह देखे कि तालीम के मैदान में हालत कितनी सुधरी है, छोटी और बड़ी मुलाजमतों में कितना हिस्सा इनको मिला है, तब जा कर सही तौर पर पता लग सकता है कि तरक्की हुई है या नहीं। चेयरमैन साहिब, बड़े दुख से कहना पड़ता है, पहाड़ी इलाके की योजना, जिस का जिक्र गवर्नर साहिब ने किया है, उस को बनाने के लिए एक हिल ऐरिया एडवाइजरी कमेटी मुरततव की गई थी जो एक मुरदा बन कर रह गई है। आज कई महीनों से इसकी मीटिंग नहीं हुई और न ही इस की किसी भी सब-कमेटी की मीटिंग हुई है।

चेयरमैन साहिब, पहाड़ी इलाके की तरक्की के लिए सब से जरूरी बात जराए आमदोरफत पर निर्भर है और इनका अच्छा होना निहायत जरूरी है लेकिन जिला कांगड़ा में जराए आमदोरफत की हालत बहुत खराब है। कच्ची सड़कें जो देश आजाद होने पर लोगों ने अपनी हिम्मत और सरकार की मदद से तामीर की थीं उन सड़कों को आज तक पी. डब्ल्यू. डी. की तहवील में नहीं लिया गया और न ही इस के बारे में आज तक कोई इकदाम उठाए गए हैं। मैं किस किस सड़क का जिक्र करूं। मेरे हल्का नुमाइन्दगी पालमपुर में एक कच्ची सड़क भवारना से आलमपुर बरास्ता खैरा जाती है, वह तमाम इलाका फौजियों का गढ़ कहा जाता है। मैं, चेयरमैन साहिब, आपकी वसातत से अपनी सरकार पर जोर देना चाहता हूं कि जब सरकार ने इस बात का एलान किया है कि जिन इलाकों में फौजियों के परिवार आबाद हैं उनकी बहबूदी और तरक्की के लिए फौरी कदम उठाए जाएंगे और गवर्नर साहिब ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि फौजियों के इलाकों की तरक्की की तरफ ध्यान दिया जाएगा तो इस सड़क को जल्द से जल्द पी. डब्ल्यू. डी. की तहवील में लिए जाने का एलान किया जाए और जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। इस के साथ साथ पहाड़ी इलाके में जितनी सड़कें कच्ची हैं उन में से ज्यादा से ज्यादा पी. डब्ल्यू. डी. की तहवील में ले कर उनको पक्का करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रूपया मखसूस किया जाए। इसी में ही हमारे पहाड़ी इलाका की तरक्की का राज छिपा पड़ा है।

एजुकेशन : चेयरमैन साहिब, जहां तक तालीम का ताल्लुक है गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में जिक्र किया है कि सरकार न टीचरों की बहबूदी के लिए 25 लाख रुपया की रकम मखसूस की है। लेकिन इस से सिर्फ 32 हजार टीचरों को फायदा मिलेगा और 48 हजार टीचर मुंह देखते रह जाएंगे। चेयरमैन साहिब, यह खुशी की बात है कि इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर साहिब सदन में विराजमान हैं और गौर से मेरी इस बात को सुन रहे हैं। मैं उन से कहूंगा कि इस तरफ तवज्जो दें। टीचरों को कौम के मैमार कहा जाता है और वह कौम के निर्माता हैं इस लिए इस तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जानी जरूरी है और उनकी बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया रखा जाना चाहिए। जिला कांगड़ा की तालीम के मैदान में आज क्या हालत है ? इस वक्त ऊंची तालीम के बारे में मुकम्मल एक ही कालेज धर्मसाला में है और दूसरा कालेज सरकार की तरफ से हमीरपुर में खोला जा रहा है। इन दो कालेजों से जिला कांगड़ा की जरूरियात पूरी नहीं हो सकतीं। आप बखूबी जानते हैं कि हमारे साथ लगते इलाका हिमाचल में 7 या 8 कालेज हैं हालांकि कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल सपिति के रकबे के बराबर हिमाचल का रकबा है। इसलिए, चेयरमैन साहिब, मैं आपकी वसातत से अर्ज करना चाहता हूं कि पालमपुर का इलाका जिस ने हमेशा से लड़ाई में कुरबानियां देने में नाम पाया है, इस इलाके के बच्चों के लिए चौथी पांच साला पलैन के तहत कालिज खोला जाए ताकि वहां के इलाके के बच्चे तालीम हासल कर सकें। इस के अतिरिक्त जिला कांगड़ा के स्कूलों को अपग्रेड करते वक्त रुपया तथा बिलडिंगों की शर्तों से मुबर्क रखा जाए। वहां के लोग देश के लिए खून तो बहा सकते हैं लेकिन अपनी उन्नति के लिए धन देने में असमर्थ है। जिला कांगड़ा को तालीमी क्षेत्र में आगे लाने के लिए जरूरी है कि बगैर किसी शर्त के ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए जाएं। इस के अलावा इस इलाका की फौजी अहमीयत को मदेनजर रखते हुए जिला कांगड़ा में एक सैनिक स्कूल भी खोला जाए ताकि वहां के लोग अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में शिक्षा दिला कर और फौज में भरती करा कर देश की रक्षा करने के लिए भेज सकें।

चेयरमैन साहिब, मुझे यह बात भी कहनी पड़ती है कि पंजाब सरकार इस बात का डोल पीटती चली आ रही थी कि जिला कांगड़ा के अन्दर कागज का कारखाना लगाने लगी है मगर जब कारखाना लगाने की बारी आई तो यह कारखाना नंगल के नजदीक लगा दिया। इस तरह से हमारे जिला कांगड़ा में जंगलात तो चील के दरखतों से भरे पड़े हैं, जब गंदा बरोजा के कारखाने के खोलने का सवाल आया तो यह कारखाना गगरेट में खोला गया। अब आप ही बताएं कि इस से बड़ा अन्याय हमारे इलाके के साथ क्या हो सकता है। क्या हमारे इलाके के साथ अन्धेर गर्दी और जुल्म नहीं है ? अब सरकार कहती है कि हम जिला कांगड़ा के अन्दर सीमेंट की फैक्टरी लगाएंगे।

[बख्शी प्रताप सिंह]

ऐसा ऐलान किया गया है मगर हमें तो शक है कि जब वक्त आएगा तो किसी दूसरी जगह पर ही लगेगी, कांगड़ा जिला वैसे ही रह जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि इंडस्ट्री पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। जहां तक इस इलाके में इंडस्ट्री लगाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस इलाके में फास्ट की इतनी घनी पैदावार है कि जो भी इन से सम्बन्धित फैक्टरीज हैं वह वहां पर आसानी से लगाई जा सकती हैं।

**जंगलात :** कांगड़ा व कुल्लू तो जंगलात के घर कहे जा सकते हैं। लेकिन वहां के अग्राम को इस बारे में कोई खास सहायता नहीं दी जाती बल्कि कानून का शिकंजा उन्हें दिन व दिन बुरी तरह जकड़ रहा है। जंगलात की आमदन में तो हर साल इजाफा हो रहा है लेकिन वहां के लोगों को इस से कोई लाभ नहीं है। वन सरकार मलकीयत रकबाजात का सरकार दो तीन साल पहले यह फैसला कर चुकी है कि वहां पर दरख्तों की मलकीयत मालकान को दे दी जाए लेकिन वह अभी तक उन्हें नहीं दी गई। चहारम की वसूली में उन्हें बहुत दिक्कतें पेश आती हैं और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। गन्दा बरोजा की आमदन की चहारम उन्हें नहीं दी जाती। वन सरकार रकबाजात अभी तक पंचायतों को नहीं दिए गए। यह सरकार पर बदनुमा धब्बे हैं। जब तक यह नहीं धुलते और लोगों को सहायता नहीं मिलती और जंगलात की आमदन का नुमाया हिस्सा उनकी जेबों में नहीं जाता तब तक वह लोग सरकार से पूरी तरह नाला रहेगे। सरकार की शोभा तब ही बढ़ेगी जब वह महकमा जंगलात की तरफ से की जाने वाली सख्तियों व ज्यादातियों की पूरी तरह रोकथाम करेगी और लोगों को जंगलात की आमदन से ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएगी।

मेडीकल और हैल्थ की सर्विसिज के मुताल्लिक मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि वहां पर बहुत से हस्पताल खोले गए हैं। मगर इन का फायदा कोई नहीं है। जैसे पुजारी के बगैर कोई मंदिर हो इसी तरह से यह हस्पताल बगैर डाक्टरों के हैं। लोग दूर दराज से चल कर हस्पतालों में जाते हैं। मगर जब न कोई डाक्टर मिलता है, न कोई दवाई मिलती है और न कोई मरीजों के साथ अच्छा सलूक होता है तो वह निराश हो कर हस्पतालों से वापस लौटते हैं।

**श्री बलरामजी दास टंडन :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चैयरमैन साहिब, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि बोलने का टाइम लिमिट आध घंटा है या 15 मिनट है। आया इस में कोई तबदीली की गई है?

**Mr. Chairman :** No change please,

बख्शी प्रताप सिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे इलाके के अन्दर जो हस्पताल हैं, वहां पर ना कोई दवाई है और न ही डाक्टर हैं। वहां के लोग इलाज कराने के लिए घाटियों, खड्डों, नदी नालों को अबूर करके आते हैं लेकिन उन्हें दवाई न मिलने के कारण निराश हो कर वापस जाना पड़ता है।

चेयरमैन साहिब, इस के साथ ही मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पानी की खानी तो पहाड़ों से होती है लेकिन वहां के लोग पीने के पानी को भी तरसते हैं। चेयरमैन साहिब, इस साल वर्षा न होने की वजह से बहुत सारे इलाकाजात में लोगों को पीने के पानी की नायाबी की वजह से सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों ने अपने पशुओं को लेकर दरयाओं व खड्डों के किनारे डेरें डाले। सरकार हमेशा यह एलान करती चली आ रही है कि पहाड़ी इलाकाजात में पीने के पानी की सुविलयते मुहैया करने में भरसक प्रयत्न करेगी मगर जब इस काम के लिए रुपया बांटा जाता है तो इन इलाकों को नजर अन्दाज कर दिया जाता है। मैं आप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ज्यादा ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा रुपया इस काम के लिए प्रोवाइड करे।

चेयरमैन साहिब, गवर्नर साहिब ने अपने एड्रेस में सिचाई बिजली के सम्बन्ध में मैदानी इलाकाजात का ही जिक्र किया है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैलों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने की चर्चा की गई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। चेयरमैन साहिब, मैं आप के द्वारा सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकाजात में खेती व बागवानी की पैदावार को बढ़ाने के लिए आबपाशी के साधन मुहैया किए जाएं। वहां की कूहलों को सरकार अपनी तहवील में ले ले और उन के हैडज को पुखता करे ताकि बाकायदा पानी की खानी जारी रह सके। इस के अतिरिक्त जहां जहां वाटर लिफ्टिंग की स्कीमें कामयाब हो सकती हैं, उन्हें अमली शकल दी जाए।

चेयरमैन साहिब, इलैक्ट्रिसिटी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इलैक्ट्रिसिटी रोड जो आते आप को बड़ी सरकार समझे बैठा है, पहाड़ी इलाकाजात में बिजली दिए जाने के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में ज्यादा से ज्यादा रुपया इस काम के लिए खर्च किया जाए।

चेयरमैन साहिब, जहां तक ट्रांसपोर्ट के महकमे का सम्बन्ध है, पिछले साल की निस्वत इस साल कुछ बेहतरी हुई है लेकिन अब भी पंजाब रोडवेज की बहुत सी बसें ऐसी हैं जो रास्ते में दम तोड़ देती हैं। ऐसे हालात में मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहां पर पंजाब रोडवेज की मोटर

[बखशी प्रताप सिंह]

सर्विस चालू नहीं की गई, उस के बारे में ज़िला कांगड़ा की सिटीजन कौंसिल ने अपनी सिफारिशों भेजी थीं और जिन्हें पंजाब सरकार ने पूरी तरह से मान लिया था लेकिन वहाँ पर अभी तक पंजाब रोडवेज की बसें चलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए । हम चाहते हैं कि उन सड़कों पे जल्दी से जल्दी बसें चलाई जाएं और इस इलाके को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट की सहुलियतें दी जाएं और पहाड़ी इलाके के लिए एक अलग रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कायम की जाए ।

चेयरमैन साहिब, गवर्नर साहिब के एड्रेस में हिसार, रोहतक और महेन्द्रगढ़ के ज़िलों में बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ जाने से वहाँ के लोगों की सहुलियत के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए देने का जिक्र किया गया है । लेकिन, चेयरमैन साहिब, मैं आप की वसालत से सरकार को बताना चाहता हूँ कि ज़िला कांगड़ा में भी कहतसाली के हालात पैदा हो गए हैं । तमाम बारानी इलाकाजात की फसलें खुशक हो चुकी है । मवेशियों के चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है । इस तरफ सरकार को फौरी ध्यान देना चाहिए । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कांगड़ा ज़िला में खुशकसाली की ज़द में आए हुए और आने वाले इलाकों को भी दूसरे ज़िलों के मुताबिक ही सहुलतें दी जानी चाहिए । उन की दिक्कत को दूर करने के लिए उन को सस्ते भाव पर और ज्यादा से ज्यादा अनाज भेजा जाए ताकि वह भूख से न मरें ।

चेयरमैन साहिब, मैं अन्त में सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पहाड़ी इलाकाजात की तामीर व तरक्की की जो तस्वीरें इस हाउस में रखी जाती हैं, उन से आप देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ी इलाकों में अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई और हालात से तंग आ कर वह लोग इस हरे भरे पंजाब को खैरबाद कहने पर आमादा हो गए हैं । वह हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं । उन्होंने अपने दिलों की आवाज़ चंडीगढ़ और देहली के एबानों तक पहुंचा दी है कि उन्हें जल्द अज़ जल्द हिमाचल से मिला दिया जाए ताकि सुख और शान्ति का सांस ले सकें और तामीरी तरक्की के मैदान में आगे बढ़ सकें । चेयरमैन साहिब, आप का शुक्रिया अदा करके मैं अपनी सीट संभालता हूँ ।

सरदार गुरबख़्त सिंह गुरदासपुरी (पारीवाल) : चेअरमैन साहिब, पिछला साल इंग्रज़ियां, उँधलियां उे फसादां दा साल सी । आउठ वाला साल ओड़ उे षट पैदावार हँठ करके बड़ी निरासता दा साल है । मैं समझदा हं कि असल दिच एह भासठ मुबारकबाद दा हँकदार है जं नही केवल इस मिआर उँ सँचठा चाहीदा है, इस उरुं उँलिआ जाणा चाहीदा है कि आइआ एह साडे पिछले उँधलियां नुँ अगे वासते दूर करेगा जं नही अउे साडी इस निरासता

11.00 a.m.

ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਛਡਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਵਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਲਨ ਗਰਾਡ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਫੌਜੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛਡਿਆ ਤੇ ਦਸ ਦਸ ਮੀਲ ਅਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਔਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੌਖਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੁਹ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 195 ਆਦਮੀ ਮਰੇ, 201 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲਖੁਥਾ ਟਨ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਛਾ ਇਹ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੇਵਲ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਭੀਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਲਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਊਥ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਥ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹਾਂ ਯਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ]

ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

(Deputy Speaker in the Chair)

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 8 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜ਼ੁਹ ਦਿਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਖਲਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਫੈਂਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਲੈਨ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲਗੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰਾਈਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਟ ਹੈ। ਤੋਖਲਾ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦਸੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। 18 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ। ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟਰਕੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ 15 ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਕਦਮ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਡੀਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦਾ ਐਨਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਨਾ ਅਮਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਇਕ ਅਖਰ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਐਨਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਲਭਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਲਕਿ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪਾਲਸੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'Our agriculture Road to self-sufficiency.' ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

“They have suggested an appropriate land policy free from ideological considerations.”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਜ਼ੋਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿਉਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਉ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹੋਣ ਉਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਕ ਦੇਣ, ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 7% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਹ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਫਾ 10 ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਔਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 44 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 54 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਫੇਰ 60 ਰੁਪਏ ਕੰਜਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਕੇਵਲ 49-50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਿਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 76 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ 54 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਜੇ ਜਗਾਧਰੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਉ ਤਾਂ ਉਥੇ 86 ਰੁਪਏ ਭਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਉ ਤਾਂ 108 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਫਾ 13 ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਏਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਹਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਰੋਵਿੰਸ ਆਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਰਗਿਜ਼

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ]

ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਵਿੰਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਏਥੇ ਦਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ—

“Even today by ‘Swarajya’ I mean redistribution of India on fully autonomous linguistic basis”

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। (The hon. Member may please wind up.)

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ :** ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਏਥੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਵਿੰਸ ਆਨ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਏਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉ। ਸਿਰਫ 11% ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਧਰ ਇਕ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ 89 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਚਿਰ ਤਕ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵਰਿਨ ਸਟੇਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਵਰਿਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 65% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝਨਾਬ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਉ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ “sub-autonomous areas hall have to be carved out for the Sikhs”. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਿਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਅਟਾਨੋਮਸ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਵਾਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਲਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਝੂਠ ਲਈ ਮਰਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 89% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ । ਸੈਲਫ ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰਲਡ ਜੋਜ਼ਫ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "Self determination is the essence of democracy." ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ "it is the essence of independence." ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਅਗੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਟ ਬਰਿਟੇਨ ਇਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਔਰ ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ । ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਅਟਾਨੋਮਸ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਠੀਕ ਉਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ । (Sardar Gurbakhash Singh may please resume in his seat.)

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ :** ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ....

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ-ਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹੋ । (I shall shortly let the House know the time already taken by the Members party-wise.)

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸ਼ਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ.....

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । (The whole position about the time will come before the hon. Members.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਂਟਾ ਪੈਂਟਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਟਿੰਟਰਪਸ਼ਿਜ਼ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ? There should be no question of 15 minutes limit ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ।

ਡਾ॰ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਭਿ-ਭਾਸ਼ਣ ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਭਿ-ਭਾਸ਼ਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਸਵਰਗੀਯ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਬੇਵਕਤ ਮ੍ਰਿਤ੍ਯੁ ਪਰ ਸ਼ੋਕ ਕਾ ਝੁਜ਼ਹਾਰ ਕਿਆ ਹੈ । ਯਹ ਸ਼ੋਕ ਐਰ ਦੁਖ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਐਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਹੁਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤਿ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਸਹੀਨੇ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸੇ ਅਰਸੇ ਮੇਂ ਦੁਨਿਆ ਕੇ ਵਡੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੋ ਹਾਸਿਲ ਕਿਆ ਐਰ ਜਬ ਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸਮਭਾਲੀ ਜੂ ਜੂਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਗਯਾ ਜਨਤਾ ਕਾ ਪ੍ਧਾਰ ਉਨ ਕੇ ਲਿਏ ਵਧਤਾ ਗਯਾ ਐਰ ਜਨਤਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਿਆ । ਯਾ ਮੈਂ ਯਹ ਕਹੂੰ ਕਿ with the passage of time he got confidence of the and people people got confidence in him. ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਕੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਸਮਯ ਕੌਮ ਆਜ਼ਮਾਯਸ਼ ਮੇਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਯਹ ਹਮਾਰੀ ਅਗਨਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਜ਼ਮਾਯਸ਼ ਕੇ ਸਮਯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ, ਸਾਹਸ ਐਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੇ ਕਾਮ ਲਿਆ ਐਰ ਜਿਸ ਤਰਹ ਟਾਇਮਲੀ ਐਰ ਕ੍ਰਿਕ ਡੀਸੀਜਨਜ਼ ਲਿਏ ਐਰ ਉਨ੍ਹੇਂ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਆ ਉਸ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨਿਆਂ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ । ਇਨੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਵਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮ੍ਰਿਤ੍ਯੁ ਕੇ ਬਾਦ ਉਨ ਕਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਿਲ ਹੋ, ਉਨ ਕੀ ਸਤ੍ਰੀ ਕੇ ਲਿਏ ਮਕਾਨ ਨ ਹੋ, ਬੱਚ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨ ਹੋ, ਇਸ ਸੇ ਹਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਵਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਧਾਰਣ ਐਰ ਕਿਤਨੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਕੇ ਆਦਮੀ ਥੇ । ਉਨ ਕੀ ਸੈਂਕ੍ਰੀਫਾਇਸ ਐਰ ਸੈਲਫਲੈਂਸ ਜੀਵਨ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਆਜ ਕੀ ਦੁਨਿਆ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਰੰਟਸ ਪਰ ਕਾਮ ਕਿਆ । ਪਹਲਾ ਫਰੰਟ ਥਾ ਲੜਾਈ ਕਾ ਐਰ ਦੂਸਰਾ ਫਰੰਟ ਥਾ ਅਮਨ ਕਾ । ਵਾਰ ਫਰੰਟ ਪਰ ਜਿਸ ਤਾਕਤ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਦਲੇਰੀ ਐਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿਆ ਉਸ ਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾ 1962 ਕੇ ਚਾਯਨੀਜ਼ ਐਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਵਕਤ ਕਾ ਖੋਯਾ ਹੁਆ ਵਕਾਰ ਦੋਬਾਰਾ ਨ ਸਿਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਕਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਐਰ ਆਗੇ ਵਧਾਯਾ ਐਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਐਰ ਆਨ ਕੋ ਦੁਨਿਆਂ ਮੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕਿਆ । ਪੀਸ ਕੇ ਫਰੰਟ ਪਰ ਵਹ ਅਮਨ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਅਮਨ ਕੀ ਖੋਜ ਮੇਂ ਤਾਸ਼ਕਨਦ ਪਹੁੰਚੇ ਐਰ ਵਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਐਰ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾਂ ਕੋ ਪੀਸਫੁਲ ਨੈਗੋਸ਼ਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਹਲ ਕਿਆ ਐਰ ਉਨ੍ਹੇਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਨਾਤੇ ਹੀ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਕੀ ਆਹੁਤਿ ਦੀ । ਤਾਸ਼ਕਨਦ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦੁਨਿਆਂ ਕੀ ਹਿਸਟ੍ਰੀ ਮੇਂ ਸੁਨਹਰੀ ਹਰੁਫ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਜਾਏਗਾ ਐਰ ਯਹ ਭੀ ਲਿਖਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 'He pleaded peace and he died for peace.' ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਨੇ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਮੇਂ ਚੰਦ ਐਰ ਵਿਅਕਤੀਯਾਂ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤ੍ਯੁ ਪਰ ਭੀ ਸ਼ੋਕ ਐਰ ਦੁਖ ਕਾ ਝੁਜ਼ਹਾਰ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਯਾਂ ਦੀਂ । ਮੈਂ ਭੀ ਗਵਰਨਰ

साहिब के साथ उस दुःख और शोक में शामिल होता हूँ। गवर्नर साहिब ने अपने ऐंड्रेस के दूसरे सफे पर इण्डो-पाकिस्तान जंग में सैनिकों की दलेरी, बहादुरी और कुरबानी की सराहना की है जिन्होंने सिर पर कफन बाँध कर अपने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जाने न्योछावर की और वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने इस लिए अपनी जाने दी ताकि हम ज़िन्दा रह सकें। उन शहीदों के खून से मातृभूमी का ज़र्रा ज़र्रा रंगा हुआ है और इसी लिए अलामा इकबाल ने कहा था कि—

“खाके वतन का मुझ को  
हर ज़र्रा देवता है”

यही नहीं, हमारी पी. ए. पी. और दूसरी पुलिस, सिवल पापुलेशन, अफसरों, ट्रक-ड्राइवरों ने भी जिस तरह सपलाई लाइन को जारी रखा और जिस तरह सिवल पापुलेशन ने लड़ाई के मोरचों पर खुराक और असलाह पहुँचाया और ऐसे काम कर के जो शानदार रवायते लोगों ने कायम कीं उस की मिसाल दुनिया में ढूँढे नहीं मिल सकती। पैराट्रुपर्स को गिरफ्तार करने और उन्हें उन के मिशन में नाकामयाब करने के लिए इलाके के ज़मींदारों ने और इन सब ने मिल कर जो काम किया उस की गवर्नर साहिब ने सराहना की है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारिकबाद देता हूँ। मैं गवर्नर साहिब और उन की सरकार को इस लिए भी मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्होंने ने सोलजर्ज, सेलर्ज, एयरमैन और दूसरे लोगों को जिन्होंने देश की डिफेंस के लिए जाने दी और डिस्चार्ज हुए हैं उन्हें ऐक्स ग्रेशिया ग्रांट्स दो हजार से पांच हजार तक मुकर्रर की हैं और इस के साथ उन के बच्चों की तालीम का बन्दोबस्त करने के लिए 10 रुपये से लेकर 250 रुपये तक वज़ीफे दिए हैं। प्रिजनर्ज आफ वार के बच्चों के लिए भी ऐसी ही सहुलते दी हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे दो फ्रंट थे, एक सीमा की लड़ाई का और दूसरा फील्ड का। सीमा का फ्रंट तो बन्द है लेकिन फील्ड की लड़ाई जारी है। हमारे फील्ड के फ्रंट में बारिश न होने के कारण हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खुशकिस्मती से दो चार दिन हुए कुछ थोड़ी बारिश हुई है जिस से आशा है 10/15 फीसदी अनाज की पैदावार में बढ़ती हो जाएगी लेकिन पंजाब में मसल मशहूर है कि खेती ओह राणी जिस दे सिर ते पाणी। इस मिसाल से हमारी सरकार भी वाकिफ है इस लिए उन्होंने ने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए एक बड़ी भारी रकम रखी है। महेन्द्रगढ़, रोहतक, हिसार के जिलों, ऊना सब-डिवीजन और गढ़ शंकर के कंठी के इलाकों के लिए एक करोड़ 33 लाख रुपया रखा गया है जिस से वहाँ चारा, बीज, इरीगेशन, माइनर इरीगेशन, पम्पिंग सैट्स, परकोलेशन वेल्व, ट्यूब वेल्व वगैरा और सायल कन्ज़रवेशन का काम किया जाएगा। मैं सरकार से कहता चाहता हूँ कि होशियारपुर के इलाके का कंठी एरिया भी इस में शामिल करना चाहिए जिस की हालत इन से किसी तरह बेहतर नहीं है। इस गए साल सरकार ने 11 हजार ट्यूब वेल्व लगाने का टारगेट मुकर्रर किया लेकिन

(डा० बाल कृष्ण)

इस की रफतार किस कदर सुस्त रही वह किसी से छुपी हुई नहीं है । इसकी दो वजूहात हैं और इन की तरफ मैं सरकार की तबज्जुह दिलाना चाहता हूँ । पहली वजह यह है कि . . . . .

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** ग्रान ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । क्या चेयर किसी मिनिस्टर या पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी को डायस पर बुला कर उस से डिसकशन कर सकती है ?

**उपाध्यक्ष :** हां कर सकती है । (Yes. The Chair is competent to do so.)

**डा० बाल कृष्ण :** डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार ने जो 11 हजार ट्यूबवैल्व लगाने का टारगेट मुकर्रर किया, उस पर सरकार बहुत ही सुस्त रफतार से चल रही है । इस का कारण यह है कि सरकार के पास बोरिंग करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है । कई स्थानों पर बोरिंग एक्स्प्लोरेशन कामयाब भी नहीं होती जिस से गरीब किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है । मैं अपने ज़िला की एक मिसाल हाउस में रखना चाहता हूँ । एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन पर बोरिंग करवाई । वह बोरिंग करते हुए 350 फुट तक पाइप लाइन को ले गया लेकिन बोरिंग मुकम्मल न हो सकी । उस का नतीजा यह हुआ कि पाइप नीचे रह गई और वहीं पर सारा काम खत्म हो गया । अगर सरकार इस काम के लिए उत्सुक है तो सरकार को चाहिए कि वह इस काम को करने के लिए वार फुटिंग पर शुरू करे । यह कैसे हो सकता है ? सरकार खुद रिग्ज खरीदे । मैं समझता हूँ कि रिग काफी महंगी होती है लेकिन सरकार के लिए रिग्ज खरीदना मुश्किल बात नहीं है । मैं जानता हूँ कि सरकार के पैसे कई अन्य मशें पर व्यर्थ जाया हो रहे हैं लेकिन इस से तो सरकार को और जनता को लाभ होगा । सरकार को जल्दी ही रिग्ज खरीदने चाहिएँ । उन रिग्ज के द्वारा एक दिन के अन्दर ही ट्यूबवैल्व खोदे जा सकते हैं । उन रिग्ज को जमींदारों की ज़रूरत के मुताबिक जगह जगह पर पहुँचाया जा सकता है । इस तरह से लोगों को ट्यूबवैल्व खोद कर सरकार को देने चाहिएँ ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा कर सकें । डिप्टी स्पीकर साहिब, आवाजें कसनें से और ग्री मोर फूड के लिए शोर मचाने से खेती की उपज नहीं बढ़ सकती है । उस चीज़ के लिए सरकार को कोई न कोई कदम उठाने ही पड़ेंगे । मैं समझता हूँ कि हम इस टारगेट को प्रेक्टीकली तभी अचीव कर सकते हैं जब सरकार खुद रिग्ज खरीदे । मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार के लिए रिग्ज खरीदने कोई मुश्किल नहीं है । मुझे बतौर चेयरमैन, पी. ए. सी. के पता है कि सरकार का पैसा कई महकमों के अन्दर किस तरह से वेस्ट हो रहा है । स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा लगाया 'जय जवान, जय किसान' यह तभी पूरा हो सकता है जब सरकार पूरी तरह से अमल करे ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की एपेथी के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। उस के बारे में मुझे बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि उस बोर्ड की जमींदारों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा है? जिस समय यह बोर्ड बनाया गया था उस के आवजैक्ट्स क्या थे, उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। उस के तीन आवजैक्ट्स थे। वह थे—

- (1) To exercise economy ;
- (2) To increase efficiency ;
- (3) To avoid redtapism.

इकानोमी का हाल तो यह है कि यह बोर्ड शुरू से ही घाटे में जा रहा है। इस बारे में आगस्ट हैड जो इस बोर्ड का चेयरमैन है, जब भी उस को सवाल पूछा गया कि इस के अन्दर गबन क्यों हुआ और कैसे हुआ तो उस ने जवाब दिया कि यह बात मेरे नोटिस में नहीं आई। जब उस बोर्ड के चीफ इंजीनियर को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ने यह केस बोर्ड को काफी समय पहले भेज दिया था और उस के बाद हम ने दो तीन रिमाइंडर्ज भी दिए। मैं उन की एफीशेंसी के बारे में अर्ज कर रहा हूँ कि उस की हालत बहुत खराब हो चुकी है। मैं इस समय ज्यादा डिटेल्ज में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं पी. ए. सी. की रिपोर्ट मार्च के पहले हफ्ते में हाऊस में पेश कर रहा हूँ। इस वक्त वह कन्फी-डेंशल है। जब यह हाऊस में पेश हो जाएगी तो माननीय सदस्यों को पता लग जायेगा कि बोर्ड के अन्दर क्या कुछ हो रहा है।

**कुछ आवाजें :** क्या यह रिपोर्ट अब भी कन्फीडेंशल रह गई है ?

**डा० बाल कृष्ण :** मैं तो जनरल रिमार्क्स कर रहा हूँ। मैं किसी पर्टीकुलर बात पर कुछ नहीं कह रहा हूँ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहाँ तक एफीशेंसी का सम्बन्ध है, उस के बारे में आप को भी मालूम है कि हर रोज बिजली कितनी कितनी बार फेल होती है। जहाँ तक रैड टेपड्रजम की बात है, उस की भी माननीय सदस्यों को पूरी वाक्फायत है। लोगों ने ट्यूबवैल्ज खूदवा रखे हैं। मोटरें फिक्स करा रखी हैं लेकिन उन को बिजली के कुनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इस के अलावा ट्यूबवैल्ज के नज़दीक से 11 के. वी. लाइन जाती है लेकिन यह डिपार्टमेंट उन को कुनेक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई एम. एल. ए. उन के पास लोगों की आवाज़ को ले कर जाते हैं तो वह डिपार्टमेंट के अधिकारी कहते हैं कि माननीय सदस्य उन के डे टु डे के कामों में इंटरफीयरेंस करते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वह पब्लिक के सरवैट्स और एम. एल. एज. जनता के रिप्रीजेंटेटिव्स हैं। वह जनता के रिप्रीजेंटेटिव्स को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जब यह बात हम मिनिस्टर के नोटिस में लाते हैं तो कहते हैं कि बिजली बोर्ड अटानोमस है हम कुछ नहीं कर सकते। जब लोगों को कुनेक्शन नहीं मिलते तो किस तरह से ग्री मोर फूड हो सकती है ?

(घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने जमींदारों की दो चार मुश्किलात हाऊस में

[डा० बाल कृष्ण]

व्यान करनी हैं। इस लिए मुझे कुछ और टाइम दे दिया जाए। वैसे जब भी आप मुझे स्पीच बन्द करने के लिए हुकम देगी मैं उसी वक्त बैठ जाऊंगा।

**उपाध्यक्ष :** आप ने 10 मिन्ट स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्बन्ध में लगा दिए और अब आप जमींदारों के बारे में कहने के लिए टाइम मांग रहे हैं। Kindly wind up now. (The hon. Member has taken ten minutes on obituary reference to the late Shri Lal Bahadur Shastri and now he wants time for discussing matters relating to land tenures. He may Kindly wind up.)

**डा० बाल कृष्ण :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे दिल में उन के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस लिए जो कुछ मैंने कहा वह ही जरूरी था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने एक फ्लड्ज कंट्रोल का महकमा बनाया हुआ है। वहां पर सरकार का बेशुमार रुपया जाया हो रहा है। सरकार फ्लड्ज को कंट्रोल करने के लिए जो स्कीम बनाती है, वह सिस्टमैटेकली ठीक नहीं होतीं। जहां पर स्कीम लागू करनी चाहिए, वहां पर लागू नहीं होती और जहां पह लागू नहीं होनी चाहिए, वहां पर लागू कर दी जाती है जिस का नतीजा यह होता है कि जो जमीन अच्छी होती है वह भी खराब हो जाती है। इस तरह से हजारों एकड़ अच्छी जमीन जाया हो रही है। फ्लड्ज तो इन स्कीमों से कम नहीं हुए बल्कि उस से ज्यादा फ्लड्ज आए और नुकसान भी बेशुमार हुआ। इसी तरह से सरकार ने ड्रेनेज के लिए एक महकमा खोला हुआ है। उस का हैड जो है, वह तो डाक्टर है लेकिन उस को चीफ इंजीनियर का रैंक दिया हुआ है। मुझे पता चला है कि उस की टर्म खत्म हो रही है लेकिन सरकार उस को और एक्सटेंशन देने जा रही है। वह यह काम करता है कि ड्रेनेज के लिए चैनल तैयार करनी होती हैं। वह तो सीधी चैनल तैयार करते हैं जिस से अच्छी जमीन चैनल के जद में आ जाती है और वह नेचुरल फलो को छोड़ देते हैं। इस से अच्छी जमीन भी खराब हो जाती है। (कुछ आवाजें : उस का नाम क्या है?) मैं हाऊस में उस का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वह यहां पर अपने आप को डीफेंड नहीं कर सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बाबू बचन सिंह ने उज्जल सिंह कमेटी का हाउस में जिक्र किया था। मुझे और सरदार गुरनाम सिंह को उस कमेटी का मेम्बर होने का शर्फ हासिल है। हम ने सोचा कि कास्ट आफ प्रोडक्शन कम हो और वह कैसे हो सकती है। उस के लिए फर्टिलाइजर की कीमतों को सबसिडाइज किया जाए। उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि—

#### NEW PRICING AND DISTRIBUTION POLICY ON FERTILISERS

The Government of India has recently decided that all fertiliser plants licensed upto 31st March, 1967 will have, for a period of seven years from the start of commercial production, the freedom to fix price for their products and organize their own distribution thereof, subject to the condition that the Government will have the option to buy up to 30 per cent of their products at a negotiated price.....”.

(February, 1966—Fertiliser News)

तो इन हालात में कैसे कीमते कम हो सकती हैं। पिछले साल गुड़ की कीमत ज्यादा थी तो हमें कहा गया कि वह गन्ना मिल्ज वालों के दें। किसान खुद गन्ने को क्रश नहीं कर सकता है। (घंटी) जब गन्ने की कीमत 13 रुपए हो गई तो किसानों को कहा जाता है कि यह खुद गुड़ तैयार करें। अगर किसानों के इंटेस्ट को सरकार ने वाच नहीं करना है तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ सकती है। इस के अलावा जब गुड़ की कीमत घट गई तो सरकार किसानों से गन्ना लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमें कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना उगाओ और सरकार के कहने के मुताबिक हम ने ज्यादा से ज्यादा गन्ने की खेती करनी शुरू की लेकिन जब गन्ना खरीदने का वक्त आया तो सरकार ने गन्ना लेने से इन्कार कर दिया। मुझे यह सरकार की पालिसी समझ में नहीं आती है। फिर इस जोनल सिस्टम में क्या है? पंजाब में ज़मींदार ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करता है। हालांकि पंजाब की धरती राजस्थान से तीसरा हिस्सा है लेकिन यहां पर अनाज राजस्थान से दुगना पैदा होता है। होता क्या है? यहां पर तो गंदम 22 रुपये मन और राजस्थान में 33 रुपये मन मिलती है। ज़रा आगे चले जाइये तो गंदम चालीस रुपये मन बिकती है मैं पूछता हूं कि क्या यह जोनल सिस्टम ज़मींदारों का गला घोटने के लिये रखा हुआ है? इस को उड़ा देना चाहिये और ज़मींदारों को उन के अनाज की पूरी कीमत मिलनी चाहिये। आप का धन्यवाद।

(विघ्न)

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिब, पिछले दो दिन से यहां सदन में गवर्नर साहिब के एड्रेस पर विवाद हो रहा है। मैं इस एड्रेस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात से दुखी हूं कि मैंने इस 35,40 सफे के एड्रेस को कई बार पढ़ा है। इस में मज़दूरों के बारे में सरकार की क्या पालिसी है, उन्होंने क्या सैक्रेफाईसिज की है और सरकार उन के लिये क्या करना चाहती है कतई कोई जिक्र नहीं है। इस बात से यह जाहिर होता है कि हमारी सरकार मज़दूरों की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद किए हुए है। इस एड्रेस में इस बात का काफी जिक्र आया है कि जब भारत की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो उस में लोगों ने जो सेवाएं की, फौजियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दीं दूसरे लोगों का भी जिन का नुकसान हुआ उन को सरकार ने सब को मुआविजे दिये। लेकिन आप सुन कर हैरान होंगे कि मज़दूरों को जिन के काम खत्म हो गए, जो बार्डर से बेघर हो गए, उजड़ गए, उन को किसी किस्म की राहत हमारी सरकार ने नहीं दी। आप को याद होगा कि पिछले सेशन के दौरान हमारी सरकार ने यह एलान किया था कि मज़दूरों में 25 लाख रुपया तकसीम करने के लिए प्रोवाईड किया है। हाऊस को यह जान कर ताज्जुब होगा कि आज तक उस 25 लाख रुपये में से सिर्फ तीन लाख रुपया मज़दूरों में बांटा गया है। इस बात को कितने महीने हो चुके हैं, कितनी देर हो गई वार हिट इकानोमी को रीसैटल करते हुए लेकिन आज तक तीन लाख रुपया मज़दूरों में बांट

[श्री सागर राम गुप्ता]

पाए हैं और वह भी इस सेशन से कुल दस पन्द्रह दिन पहले बांटे गए हैं। जितने भी लेबर डीपार्टमेंट के अफसर पंजाब में थे उन सब को अमृतसर में ले जाकर बैठा दिया गया यह दिखाने के लिये कि हम मजदूरों को रुपया देना चाहते हैं। पहले तीन चार महीने सरकार सोई पड़ी रही। आप जानते हैं कि अगर दस दिन भी काम बंद हो जाए तो मजदूर भूखे मरने लगते हैं। जरूरत तो उस वक्त थी जबकि पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी। उस वक्त तमाम कारखाने बंद हो गए थे मजदूर भूखे मरने लगे थे। कोई यू० पी० चला गया, कोई बिहार चला गया और कोई बंगाल चला गया काम की तलाश में, रोटी की तलाश में। अब उन्होंने छः महीने के बाद 25 अफसरों को अमृतसर ले जा कर बैठा दिया और कह दिया कि इन में रुपये बांटो और वह भी तीन लाख रुपया बांट पाए। आप को सुन कर हैरानी होगी कि वार हिट लोगों में करोड़ों रुपये की ग्रांट्स बांटी गई हैं और मुआवजे दिए गए हैं लेकिन मजदूरों में लोन बांटे जा रहे हैं। आज हमारी सरकार दावे करती है कि हम सोशललिज्म लाना चाहते हैं, हम मजदूरों की इमदाद करना चाहते हैं गरीबों की सहायता करना चाहते हैं। पूंजीपतियों को, जिन के कारखाने बंद हो गए तरह तरह की सबसिडी दी जा रही है, ग्रांट्स दी जा रही है, फ्री इंट्रेस्ट लोन दिये जा रहे हैं और मजदूरों को, जिन के पास कोई आल्टरनेटिव एम्पलायमेंट नहीं जिन के पास कोई सेविंग्स नहीं है कि दुःख के वक्त गुजर कर सकें, आज 6 महीने के बाद दो दो सौ रुपया लोन दिया जा रहा है। आप मजाक देखिये जो हमारी सरकार मजदूरों के साथ कर रही है। पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त जो नुकसान मजदूरों का हुआ वह अभी तक उस से ही नहीं संभल पाए थे कि बिजली की कमी जो पंजाब में चल रही है उस की वजह से सारे पंजाब में हजारों मजदूर बेकार हो गए। जगह जगह पर ले आफ हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि पूंजीपति कारखानेदार मजदूरों को आम तौर पर परमानेंट नहीं होने देते। उन को कई सालों तक बदली वर्कर रखते हैं। चुनांचि अब ले आफ 75 फी सदी मजदूरों को कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा क्योंकि वे परमानेंट नहीं हैं, बदली वर्कर हैं। अगर सरकार वास्तविक तौर पर मजदूरों की सहायता करना चाहती है तो जो बात वह कहती है उस पर अमल करना चाहिये। जो एलान सरकार करती है उस पर उस को पूरी तरह से पाबंद रहना चाहिये। सरकार का यह फर्ज है कि मजदूरों के प्रति जो उस की जिम्मेदारियां हैं, समय समय पर जो उसने एलान किये हैं उन को पूरा करने की कोशिश करें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मजदूरों के साथ तरह तरह के अन्याय होते हैं। आप को याद होगा कि बजट सेशन में इस हाउस के अन्दर लेबर मनिस्टर ने यह विश्वास दिलाया था कि मंहगाई के आंकड़े जो गलत तौर पर सरकार के द्वारा निकाले जा रहे हैं उन को ठीक करने के लिये फौजी तौर पर एक कमेटी बनाई जाएगी और

उस की सिफारिशात आने पर सही आंकड़े निकालने शुरू कर देंगे । आप जानती हैं कि मजदूरों को जो महंगाई मिलती है अगर आंकड़े मुनासिब न हों, ठीक न हों जो कि मार्किट की कीमतों का उतार चढ़ाव ठीक जाहिर नहीं करते तो वह ठीक नहीं मिलती । मजदूरों के साथ अन्याय होता है । उन को मुनासिब महंगाई नहीं मिलती । डी० ए० के मामले में सरकार ने कमेटी बिठाई थी । आज तक उस ने कोई कार्यवाही नहीं की । अब सुना है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि वह कमेटी ही डीफैक्ट है और वह कोई और कमेटी बनाएंगे । पता नहीं है कि वह कब कमेटी बनाएंगे, कब वह विचार करेगी, कब ठीक आंकड़े दिये जाएंगे और कब मजदूरों को महंगाई मिलेगी । भगवान मालिक है मैं नहीं समझता कि कम से कम मजदूरों वाले मामले में सरकार की कोई अकल काम नहीं करती है । दिन रात प्रोडक्शन की रट लगाई जा रही है, लेकिन हमारी सरकार भूल गई है कि प्रोडक्शन में एक बहुत हद तक भागीदार मजदूर हैं । उन के प्रति हमारी सरकार ने यह रवैया अपना रखा है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप न इनवाईट करी ऐजीटेशन, आप न इनवाईट करी मजदूरों के रोष को । मजदूर जहां काम करते हैं वहां वे ऐजीटेशन करना भी जानते हैं । मैं नहीं चाहता कि ऐजेंसी के दौरान, जिन का फायदा कारखानेदार उठा रहे हैं और सरकार भी उठा रही है, मजदूर संस्थाओं को मजबूर किया जाए कि वह कोई ऐजीटेशन शुरू करें । मजदूरों का मसला खत्म करने से पहले मैं चंडीगढ़ के मजदूरों का जिक्र खासतौर पर करना चाहता हूं । आप जानते हैं कि चंडीगढ़ को बसाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये गए हैं और बहुत से मजदूर दिन रात काम करते रहे हैं । और आज भी कर रहे हैं ऐसा नहीं किया गया कि जिन मजदूरों ने लोगों के लिये मकान बनाए, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई बड़े बड़े भवन बनाए उन के लिए भी कोई शैल्टर बना दिया जाए । एक एक कमरा कुछ लोगों को दिया है । आप अंदाजा लगाइये कि कहां पर उस का कुन्वा रहे, कहां पर वह खुद रहे और अगर कोई आ जाए तो उस को कहां बैठाए । इस पर तुरा यह है कि उन की तनखाहें बहुत कम हैं । उन को वर्क चार्ज रखा जाता है, आठ आठ, दस दस साल तक टेम्परेरी रखा जाता है । वायदे बेशुमार किये जाते हैं लेकिन अमल नहीं किया जाता । मैं मिसाल पेश कर सकता हूं कि बाकायदा तौर पर, कानूनी तौर पर कैपिटल प्राजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मजदूर यूनियन्ज का समझौता हुआ है कुछ शरायत तय हुई ; नौकरी के बारे में कुछ शरायत तय की गई । लेकिन चीफ इंजीनियर कैपिटल प्रोजेक्ट, एस० ई० और एग्जिक्टिव इंजीनियर समझौते के पाबंद नहीं रहते । वह उन शरायत को लागू नहीं करते । मान जाते हैं, दस्तखत कर देते हैं लेकिन पाबंद नहीं रहते । जब हम लेबर डिपार्टमेंट से कहते हैं कि यह कानून को तोड़ने हैं इन का चलान करो तो फिर वहां पर लिहाज, आपसी भाई चारा अफसर अफसर का आपस में बीच बचाव और सारी बातें आ जाती हैं । डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि यह जो मजदूर हैं, जिन्होंने पंजाब की राजधानी को बनाया है और बना रहे हैं, इन की सहूलियात की तरफ भी पूरा पूरा ध्यान दिया जाए ।

[श्री सागर राम गुप्ता]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं कुछ अपनी कान्स्टीचुएँसी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। आप को मालूम है कि तहसील भिवानी में इस वक्त सख्त कहत पड़ा हुआ है और पिछले तीन चार सालों से कोई फसल वहाँ पर नहीं हो रही। अभी जो स्पेशल गिरदावरी सरकार ने वहाँ पर की उस के अन्दर सौ फी सदी खराबा रिपोर्ट में आया है। पिछले सत्रह अठारह साल तक हमारी सरकार इस इलाके के साथ स्टैपमदरली ट्रीटमेंट करती रही लेकिन खुशी की बात है कि अब इस दफा कुछ काम वहाँ पर शुरू किया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि काम शुरू करने में अभी तक बहुत सुस्ती चल रही है, (घंटी) बड़ी सुस्ती से वहाँ पर काम चल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर काम करने की रफतार को तेज किया जाए। इस के अलावा एक बात और वहाँ के इलाके के बारे में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ। सरकार की यह डिक्लेयर्ड पालिसी है कि जहाँ पर कोई इरीगेशन का साधन नहीं, जहाँ पर नहरें नहीं या कोई और तरीका सिंचाई का नहीं वहाँ पर ज्यादा ट्यूबवैलज को कून्केशनज दिए जाएं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भिवानी तहसील में कई कई महीनों तक ट्यूबवैलज वाले लोग मारे मारे फिरते हैं, हर तरीके की फारमैलिटीज को उन्होंने पूरा कर रखा है लेकिन फिर भी कई कई महीनों तक उनको बिजली के कून्केशनज नहीं मिल रहे। सरकार को चाहिए कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा प्रायरटी दे और वहाँ पर जल्दी से जल्दी ट्यूबवैलज लगाए जाएं जिस से कि लोगों को खेती करने में सुविधाएं मिलें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, तहसील भिवानी के बारे में एक बहुत जरूरी बात और रह गई है जिस का जिक्र किए बगैर मैं रह नहीं सकता और वह है कि जिला महेन्द्रगढ़ में सरकारी अधिकारियों को 75 फी सदी कम्पैन्सेटरी एलाऊंस मिल रहा है लेकिन तहसील भिवानी में नहीं मिल रहा। उस का नतीजा यह होता है कि वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते। अभी पिछले दिनों भिवानी में एक नया डिवीजन नहर कायम किया गया और वहाँ पर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा एक्स० ई० एन० पोस्ट किया गया लेकिन वहाँ पर कोई एक्स० ई० एन० जाना नहीं चाहता। नतीजा यह हुआ है कि वहाँ पर महीना डेढ़ महीना हो गया कोई काम शुरू ही नहीं किया जा सका। फ़ैमिन रिलीफ का काम खुद सरकार मानती है कि टाप प्रायरटी का काम है और काफी खर्चा करने के लिए सरकार वहाँ पर तजवीज कर रही है। इस लिए सरकार को चाहिए कि इस मामले कि तरफ फौरी तौर पर ध्यान दे और तहसील भिवानी में भी महेन्द्रगढ़ की तरह इस एलाऊंस को जारी किया जाए। (घंटी)

इस के अलावा एक और बात है....

उपाध्यक्षा : आप जैसे मेम्बर भी मेरी बात को न माने तो अच्छा मालूम नहीं देता । (It does not look proper if an hon. Member like him does not obey the Chair.)

श्री सागर राम गुप्ता : बस जी, खत्म ही करने जा रहा हूँ । सरकार ने भिवानी तहसील और दूसरे ड्राट अफैक्टिड एरियाज के बारे में कोई परमानेंट हल सोचने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की है जिस का चेयरमैन फाइनेन्शल कमिश्नर है । मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में पूरी तरह से और सही लाइन्ज पर काम किया जाए ताकि इस तरह की मुसीबत का सामना लोगों को आए साल न करना पड़े । इस के लिए मैं चाहूँगा कि इण्डस्ट्री की तरफ खास तौर पर ध्यान दिया जाए और भिवानी में पब्लिक सैक्टर में कोई इण्डस्ट्री कायम की जाए ताकि जो लोगों में अनएम्पलायमेंट की समस्या है वह भी किसी हद तक हल हो सके । जहां तक इण्डस्ट्री को फरोग देने का सम्बन्ध है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमें तो यह देख कर दुःख होता है कि वैसे तो सरकार ने तीन चार कारपोरेशनज बनाई हुई हैं और वहां पर कई सैक्टरीज, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरा लगाए हुए हैं मगर अगर ध्यान से देखा जाए तो वह सारे के सारे ही पंजाबी रिजन के हैं और हरियाणा का कोई नहीं । और शायद यही कारण है कि वह लोग हरियाणा में कोई इण्डस्ट्री कायम करने की बात नहीं करते । गनौर में एक सीमेंट्स ड्यूब फैक्टरी लगाने की स्कीम थी लेकिन अब सुना जा रहा है कि अब उसे भी खत्म करने की तजवीज है । इस लिए अपनी जगह पर बैठने से पहले मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन कारपोरेशनज में हरियाणा के लोगों को भी मुनासिब स्थान दिया जाए ताकि वहां पर इण्डस्ट्री की डिवैलपमेंट हो सके । आप का शुक्रिया ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज गवर्नर के एंड्रैस पर डिस्कशन का आखरी दिन है ।

कुछ आवाजें : आखिरी दिन नहीं, एक दिन और है । (विघ्न)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : तो शायद इस हकूमत के आखरी दिन आए हुए हैं ।

उपाध्यक्षा : आप इन के साथ न उलझिए । आप अपनी बात कीजिए । नो इन्ट्रूप्शंस प्लीज । (The hon. Member need not enter into controversy with him. He may proceed with his speech. No interruptions please.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : जैसा क्लरलैस, ओडरलैस और फीका सा गवर्नर एंड्रैस है ऐसे ही हमारी हकूमत के वज्जीरों ने इस सेशन में यहां हाजरी न देकर अपन आप को ऐसा होने का सबूत दे दिया है (आपोजीसन की तरफ से प्रशंसा) डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब से यह हाउस इस बार मीट किया है तब से ही हमारे बुजुरा साहिबान पता नहीं कहां जलवा अफरोज रहे हैं, उन्हें हम उन की सीट्स पर तो देखते नहीं रहे ।

मुख्य संसत् सचिव : वह अपने कमरों में बैठे हैं ।

कुछ आवाजें : गलत । वह यहां पर हाज़िर नहीं । देहली दौड़े फिरते हैं ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सी० पी० एस० ही सवालों के जवाब देता है । क्या वही हकूमत की नुमायन्दगी करता है । वज़ीर कहां दौड़े फिर रहे हैं ?

मुख्य संसत् सचिव : वह लोगों की खिदमत कर रहे हैं ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : यूँ क्यों नहीं कहते कि देहली में लोगों को टिकटें दिलाने के [लिए] गवर्नमेंट के खर्च पर दो दो सौ रुपया रोज़ खर्च कर रहे हैं और इसी वजह से वहां पर भागे भागे फिरते हैं ?

मुख्य संसत् सचिव : कोई नहीं जा रहा ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैंने अपनी आंखों से उन को वहां पर देखा है ।

मुख्य संसत् सचिव : यह गलत व्याप्ती है ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मेहरबानी करके सी० पी० एस० को कहें कि वह ज़रा सब्र और तहम्मल से काम लें ।

एक आवाज़ : इस को तो लागी बना कर भेजा गया है। यह तो मरासी है ।  
(विघ्न)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : यहां पर सी० पी० एस० सभी मनिस्ट्रों को सुपरसीड करने की कोशिश करता है और अब तक जो सवाल आए हैं तो in the presence of the Ministers the Chief Parliamentary Secretary usurps the powers of the Ministers.

मुख्य संसत् सचिव : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं आप से जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मनिस्टर हाउस में न बैठा हुआ हो तो क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी उस के सवालों का जवाब दे सकता है या नहीं ।

उपाध्यक्षा : आप अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं । (He can reply to questions relating to him.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह मेरा टाईम लिए जा रहे हैं । आप इस बात को नोट कर लीजिए  
(विघ्न)

मुख्य संसत् सचिव : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम ।

उपाध्यक्षा : मैंने अपनी रूलिंग दे दी है । (I have given my ruling.)

मुख्य संसद सचिव : मेरा प्वायंट आफ आर्डर दूसरा है । और वह यह है कि सी० पी० एस० के पास अमूमन कोई अपना पोर्टफोलियो नहीं होता । मैं आप से यह रूलिंग चाहता हूँ कि क्या वह किसी भी मिनिस्टर के सवालों का जवाब दे सकता है या नहीं ?

उपाध्यक्षा : यह प्वायंट देखने का है कि सब के जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता । मिस्टर चिरंजी लाल, आप चेयर को एंड्रेस करें और आपस में बात न करें। (This point requires examination whether the Chief Parliamentary Secretary can answer questions relating to all the Ministers. The hon. Member Shri Chiranji Lal may address the Chair and avoid mutual discussion.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैं तो, मैडम डिप्टी स्पीकर, आप को ही एंड्रेस कर रहा हूँ । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे देहात में डूम हुआ करें । डूम घूम घूम कर जजमान का ढोल पीटता रहता है और कुछ मांगता रहता है । हमारा सी० पी० एस० भी उसी डूम वाला पार्ट अदा कर रहा है (आपोजीशन की तरफ से तालियाँ)

उपाध्यक्षा : आप इन को कहेंगे और यह आपको कहेंगे और इसी तरह से बात बढ़ जाएगी । आप मेहरबानी कर के ऐसी बातों को एवायड करें । (If the hon. Member says something about him, the latter will also retaliate and this will result in aggravation of tension. The hon. Member should, therefore, avoid saying such things.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैडम डिप्टी स्पीकर, यह जो गवर्नर साहिब ने एंड्रेस पेश किया है इस पर काफी कुछ कहा जा चुका है । लेकिन अगर मैं गलती नहीं करता तो इन बैचिज की तरफ से—मेरा इशारा अपोजीशन के मैम्बर्स की तरफ है—हरियाणा के सवाल पर शायद अब तक कुछ नहीं कहा गया । इस एंड्रेस में भी इस की बाबत कुछ नहीं कहा गया हालांकि यह एक निहायत बरनिंग टापिक है और इस सम्बन्ध में हुकूमत की तरफ से भी जमीन आसमान एक किया जा रहा है और जिस के बारे में सारे वज़ीर देहली जा जा कर कदमी पैमायश कर रहे हैं । गवर्नर साहिब के एंड्रेस में इस का जिक्र तक नहीं आया ।

मुख्य संसद सचिव : इस का फैसला अभी पेंडिंग है । इस लिए इस में इस का जिक्र कैसे आ जाता ?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : जहां तक पेंडिंग का ताल्लुक है.....

(विघ्न)

Deputy Speaker : Order please. There should be no interruption in the House.

**Shri Mangal Sein :** Madam, he may be removed from the House.

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मेहरबानी कर के सी० पी० एस० का मुंह बन्द करें। यह मेरा टाईम यूँही ले रहा है।

**उपाध्यक्षा :** आर्डर प्लीज। अब कोई इन्टरप्शन नहीं होनी चाहिए।  
(Order please. Henceforth there should be no interruptions.)

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** हमें पता लगा है कि इस गवर्नमेंट की तरफ से पालियामेंटरी कमेटी के सामने एक बात रखी गई है कि पंजाब को बाई लिगुअल रखा जाए। मैं हकूमत से यह कहना चाहता हूँ कि अगर उन की यह बात पार न पड़ी, पंजाब को बाईलिगुअल न रखा गया, तो इस हकूमत को यहां सामने वाले बैचिज़ पर ज़िन्दा रहने का कोई हक नहीं और अगर हकूमत की रिप्रिज़ेंटेशन पर उन के नज़रिए को मंज़ूर न किया गया तो हकूमत को चाहिए कि इन बैचिज़ को खाली करके बाहर सैर करे।

**सरदार गुरचरण सिंह :** बैचिज़ तो अभी भी खाली पड़े हैं।

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक लैंग्वेज का सवाल है यह एक कंट्रोवर्शियल इशू है। इस के बारे में काफी कुछ कहा गया है।

12.00 noon

मैं इस के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा मगर चूंकि यह मेरे इलाके से भी ताल्लुक रखता है इस लिये मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि हरियाणा प्रांत किसी भी कीमत पर पंजाबी लैंग्वेज को बरदाश्त नहीं करेगा। (आपोजीशन की तरफ से तालियां) दूसरी बात यह कहूंगा कि अगर पंजाबी रिजन के किसी तबके को खुश करने के लिये हरियाणा प्रांत कि डिसमेम्बरमेंट की गई तो इस को भी हम बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेंगे। (विघ्न)

**Chief Parliamentary Secretary:** The honourable Member is not discussing the Governor's Address.

**Deputy Speaker :** Let the Chair perform her duties.

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** अफसोस की बात यह है कि सी० पी० एस० साहिब पांच साल तक पालियामेंट के मैम्बर रहे हैं, चार साल से यहां भी मैम्बर हैं। मगर इन को अभी तक पता नहीं है कि गवर्नर के ऐड्रेस की तारीफ क्या है, यह किस बला का नाम है। इन्हें तो सिवाए सरकार का ढोल पीटने के और किसी बात का पता नहीं है। (विघ्न)

**मुख्य संसत् सचिव :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम।

**उपाध्यक्षा :** यह तो ठीक नहीं अगर इसी तरह से प्वायंट्स आफ आर्डर चलते रहे। (This is not proper, if the points of order continue to be raised.) (Interruptions)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : उन्होंने कहा है कि गवर्नर का ऐड्रेस क्या होता है । मैं इन को बता दूँ (विघ्न) इस ऐड्रेस में सरकार की पालिसी डिसकस की जाती है, प्रोग्राम डिसकस किया जाता है । Madam, the Chief parliamentary Secretary does not know what the policy of the Government is. He makes bold to say that what I am referring to, is not in the Governor's Address. He should first read and then talk. I pity his innocence.

उपाध्यक्षा : मैं ने उन को कह दिया है कि चेयर का फंक्शन चेयर को करने दो । (I have asked him to let the Chair perform its function.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : सी० पी० एस० साहिब जो भी इन्टरप्शन करेंगे मैं उस का स्वागत करूँगा और बड़े खूबसूरत तरीके से उन को जवाब दूँगा, मैं वकील हूँ ।

Deputy Speaker : This is not a Court.

(Interruption)

Pandit Chiranji Lal Sharma : At page 13 of the Address, it is stated:

“....Another step taken in the direction of reducing this disparity was the setting up of a Committee in March, 1965, to make a study of the socio-economic conditions of the Haryana Region so as to recommend development measures for an accelerated and integrated growth of that region. The Committee submitted its final report on the 27th January this year, and the recommendations made by it will receive the careful consideration of the State Government.”

डिप्टी स्पीकर साहिब, आप देखें कि सारे इतने बड़े ऐड्रेस में हरियाणा प्रांत के लिये सिर्फ 6 लाइनें हैं उस कमेटी की रिपोर्ट के लिये जो कि हरियाणा के हिन्दू के लिये गीता का स्थान रखती है, हरियाणा के सिख के लिये ग्रन्थ है और हरियाणा के मुसलमान के लिये कुरान का हतबा रखती है । अभी तीन चार रोज़ हुए हैं हमारे प्लैनिंग मिनिस्टर साहिब ने कौंसिल में स्टेटमेंट दी थी कि इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन्ज़ हैं उनको चौथी प्लैन में इनकारपोरेट नहीं किया जायेगा, (विघ्न) पहले साल में हम उन को बजट अलाट नहीं कर सकते । जिन का मक्का और मदीना लुधियाने के अन्दर हो, जिन के मन्दिर और शिवाले अमृतसर या गुरदासपुर में हों वह इस रिपोर्ट के मुताबिक क्यों बजट अलाट करेंगे ? मगर मैं आप की विसातत से हकूमत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे सबरो तहम्मल का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, बहुत दिनों तक हमारा जनाज़ा चीफ पालियामेंट्रै सैक्रेटरी और इन के साथियों के कन्धों पर निकलता रहा है । (तालियां) (विघ्न)

**उपाध्यक्ष :** क्या यहां पर शादी विवाह हो रहे हैं ? (Are there any marriages being solemnised here ?) (Interruptions).

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** यह कहते हैं कि मेरी शादी हरियाणा में हुई है। तो जिस आदमी के दिल और दिमाग में अपने सुसराल का लिहाज नहीं है, वह पंजाब का क्या कल्याण करेगा ? जो अपने सगे बीवी बच्चों का नहीं है, साले और सुसर का नहीं है वह पंजाब के साथ क्या अच्छा सलूक करेगा। (आपोजीशन की ओर से तालियां) डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम यह चाहते थे कि मुतहिदा पंजाब के अन्दर प्रेम और प्यार की मुरली बजती रहे, बुगजो अनाद के नाकूस न फूके जाएं मगर हमारी हकूमत कोमप्रस्ती के नाम पर फिरकादारों की मदद कर रही है। हमें मजबूर हो कर आज वह नारा लगाना पड़ रहा है जो कि हम ने आठ दस साल पहले लगाना बन्द कर दिया था कि अगर कोई चीज हम पर हमारी मर्जी के खिलाफ ठोंसी जायेगी तो हम उसे बरदाश्त नहीं करगे। फैक्ट्स ऐंड फिगरज को देखें तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, रौंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सारे किस्से की यह हरियाणा कमेटी की रिपोर्ट एक मूंह बोलती तसवीर है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सर्विसिज में हमारा पांच फीसदी भी हिस्सा नहीं है। (आपोजीशन की तरफ से 'शेम शेम') फिर ऐजुकेशन की फिगरज को लें। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बड़े नाज नखरे से कहा जाता है कि हिन्दी रिजन के अन्दर है। इस का जरा नकशा मैं आप के सामने रखता हूं। पिछले साल हकूमत ने इस का वाइस चांसलर डाक्टरबूल चंद को मुकर्रर किया। श्री सूरज भान, जिस के खिलाफ कुछ ऐलीमेशनज थे, को वहां से निकाल कर हायर स्टेटस दिया....

**उपाध्यक्ष :** पंडित जी, किसी को बाई नेम रेफर न करें। (The hon. Member need not refer any body by name.)

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, परसनल अटैक भी नहीं कर रहा। आईएम स्टेटिंग फैक्ट्स। मैं ने यह नहीं कहा कि यह बात सच्ची या झूठी है। मैं ने तो यही कहा कि डा० बूल चंद को उस जगह पर लगाया गया

**Chief Parliamentary Secretary :** On a Point of Order, Madam. Can we discuss. . . .

**Deputy Speaker :** Every time I cannot allow you to raise a Point of Order.

**Chief Parliamentary Secretary :** That is very important. Can we discuss a person who is not present in the House ?

उपाध्यक्षा : मैं ने उन को कह दिया है। आप के कहने की ज़रूरत नहीं।  
(I have already told him. He need not point it out.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : श्री सूरज भान को पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दिया....

मुख्य संसत्-सचिव : फिर नाम ले रहे हैं। (विघ्न)

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Madam, I must name him. You cannot debar me from doing so. It is as a result of my right that I am doing this.

**Chief Parliamentary Secretary :** You cannot do this.

*(Interruptions and Noise in the House.)*

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Madam I seek asylum from you. You should gag his mouth. He must learn Parliamentary practice. He must know how to behave on the floor of the House. He should always be open to conviction.

उपाध्यक्षा : पंडित जी, आप चेयर को ऐड्रेस करें। उन की तरफ न ले जाएं। हरियाणा की बात करें। और मेहरबानी कर के किसी को नाम लेकर रेफर न करें।  
(The hon. Member Pandit Ji should address the Chair and not address him directly. He may speak about Haryana but should avoid reference to any body by name.)

श्री मंगल सेन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। (विघ्न) मैं आप की रूलिंग चाहता हूं। जब इस सदन में कोई मेम्बर बार बार आग्रह करता है, इन्टरप्ट करता है तो स्पीकर साहिब कहते हैं कि चूंकि वह हाउस की कार्यवाही चलने नहीं देते लिहाजा वह हाउस से बाहर चले जाएं।

मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब अपोजीशन की तरफ में एक आनरेबल मेम्बर बोल रहे हैं और रैलेवेंट और दरुस्त कह रहे हैं तो यह चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी एक अनाड़ी की तरह अपनी सीट से उठ उठ बैठते हैं। पता नहीं इन की सीट के नीचे सिपरिंग लगे हुए हैं, इन्हें रोक देना चाहिए। (हंसी)

उपाध्यक्षा : आप का यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। (This is no point of order.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : सी. पी. एस. तो क्या समुद्र का तूफान और आसमान की बिजली भी मेरे रास्ते में हायल नहीं हो सकती। (प्रशंसा)  
तो मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा अर्ज कर रहा था कि कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में डा० बूल चंद को वाइस-चांसलर मुकर्रर कर दिया गया।  
(विघ्न)

**उपाध्यक्ष :** आप को किसी का नाम नहीं लेना चाहिए । (The hon. Member should not refer to any body by name.)

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** आप मुझे बताएं कि वह कौन सा जाब्ता है और रूल है जिस के मुताबिक आप मुझे किसी का नाम लेने से रोक सकती हैं, मैं किसी पर कोई इलजाम नहीं लगा रहा । किसी अफसर का नाम लेना कोई गुनाह नहीं । I have a right to mention the name of an individual being appointed or who has been appointed on a post.

अगर मैं किसी का नाम नहीं लेता तो हाऊ कैन आई ब्रिंग होम दी फैक्ट्स ? डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं तो यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस नाम के खिलाफ साजिश की जा रही है । कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर मुकर्रर किया जाता है तो अब डैप्यूटेशन भेजे जा रहे हैं । पार्लियामेंट में भी इन के बारे में सवाल करवाया गया कि डा. बूल चंद को हटा दिया जाए । मैं आप की वसातत से बताना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी की क्या हालत है । यह हिन्दी रिजन में है और इसकी जो कोर्ट है आप जरा उस के बारे में देखें कि उस के 38 मैम्बर हैं और इन 38 में से सिर्फ 4 हरियाणा के रहने वाले हैं । इन में 12 गवर्नर की तरफ से नामीनेटिड मेम्बर हैं । इन में से सिर्फ एक चौधरी सूरज मल हरियाणा के हैं । यह तो हालत यूनिवर्सिटी की है । जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सिण्डिकेट है, इस के आगे एग्जैक्टिव कौंसल है इस में 18 या 20 मैम्बर हैं और एक भी हरियाणा का नहीं, इसी तरह ऐकेडैमिक कौंसल है इस में 23 मैम्बर हैं और इन 23 में से 17 हैड्ज आफ डिपार्टमेन्ट हैं इन में से एक आध हरियाणा प्रांत का है । टीचिंग स्टाफ में 135 प्रोफेसर हैं जिन में से सिर्फ 6 हरियाणा के हैं । फिर इस में 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार और 3 या 4 सुपरिन्टेण्डेंट हैं और एक भी हरियाणा का नहीं । मैं पंजाब की दूसरी यूनिवर्सिटियों का जिक्र नहीं कर रहा, उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहा हूं जो हिन्दी रिजन में लोकेटिड है । अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा यह हाल है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और पंजाबी यूनिवर्सिटी में तो हमारा टिकाना क्या होगा आप इस का अंदाजा लगा सकते हैं ।

This is an eye-wash हमारे घर में हम से यह सलूक किया जाता है तो दूसरे रिजन में हमारे साथ इन के सलूक की क्या हालत हो सकती है ? खुशी की बात है कि एजुकेशन मिनिस्टर साहिब इस वक्त इस हाऊस में कद्मुरंजा फरमा हो गए हैं और वह शायद इस बात का जवाब देंगे कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी लेवल पर सौतेली मां का सलूक क्यों किया जा रहा है । यह कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एक अटानोमस बाडी है और हम इस के काम को डिस्कस नहीं कर सकते । लेकिन अपने हकूक के लिए और जहां पर ज्यादाती की जा रही हो आवाज तो उठा सकते हैं ।

जब यहां पर कोई चीज हम लाने लगते हैं तो जवाब दिया जाता है कि हम कनसिडर कर रहे हैं। आप हरियाणा डिवैलपमेंट कमिशन की रिपोर्ट को ले ले, आज तक यही जवाब दिया जा रहा है कि इस को सरकार कनसिडर कर रही है। यह हकूमत खत्म हो जाएगी और इस को कनसिडर ही किया जाता रहेगा। यह मैं समझता हूं कि एक आई वाश है और अगर हरियाणा डिवैलपमेंट कमिशन की रिपोर्ट को किताब की शकल में पेश किया गया और इस पर कारवाई न की गई तो इस के नतायज खराब होंगे। हरियाणा के लोगों ने अपने हकूक के लिए पंजाब में और गली गली में लड़ना होगा। वह इस तरह का सलूक हरियाणा के साथ बरदाश्त नहीं करेंगे। जब हम हरियाणा के लोगों की आवाज को उठाते हैं तो हमें ट्रेटर्ज कहा जाता है और हमें गुलस्तां और बौसतां पढ़ने के लिए कहा जाता है। और दबी जबान में कहा जाता है कि न न ऐसा न करना, नहीं तो हिन्दुस्तान तबाह हो जाएगा। हमें देश द्रोही कहा जाता है जब हम यह कहते हैं कि हम पर पंजाबी लैंग्वेज को थ्रस्ट न किया जाए और हमें एपीथट दिए जाते हैं। आज यह तो हालत है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस में हकूमत का क्या कसूर है, यह तो आपस में ही टांगे खींचते हैं और इसी काम में लगे हुए हैं। इस के बारे में आप देखें कि पंजाब का प्रैस क्या कहता है, आप प्रस को छोड़िए गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है वह फरमाते हैं :

“....But progress in any State or country, in the ultimate analysis, must depend on the stability of its Government and the confidence it inspires in the public mind. For this, there must be full harmony and union in the functioning of the Government....”

He is giving sermons “there must be.....”

गवर्नर साहिब ने कहा है कि हारमनी नहीं है और कानफिडेस होने का संदेश दे रहे हैं। अब आप ही देख लें, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि यह हकूमत किस तरीके से चल रही है। इस का असर जहां लोगों पर पड़ता है वहां एडमिनिस्ट्रेशन पर भी पड़ता है। State of uncertainty and suspense prevails in the entire administration. Go to the Secretariat, और वहां पर छोटे से छोटा क्लर्क और बड़े से बड़ा अफसर जब भी कोई लैजिस्लेटर उन के पास चला जाएगा तो यही सवाल पूछेगा कि कौन मिनिस्टर रहेगा, यह या वह। अगर इस तरह की बातें हों तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या हरियाणा की हालत सुधर पाएगी unless there is stability in the Government. मैं ने गवर्नर साहिब को कोट किया है कि मिनिस्टरी में हारमनी नहीं है और मेरे ख्याल में हकूमत के पास इस बात का जवाब नहीं है।

(पंडित चिरंजी लाल शर्मा)

इस के इलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। आज 18 या 19 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं और फिर भी एग्रीकल्चर की क्या हालत है ? हम लोगों से मांगने पर तुल आए हैं और बाहर के मुल्कों को इमदाद देने के लिए कहा जा रहा है। यह बात उचित नहीं। आज एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट का नारा दिया जा रहा है और आल इण्डिया लैवल पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है। यहां पंजाब में भी इस का चर्चा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार ड्रामा कर रही है और बाकी जगहों का तो क्या कहा जाए, सीट आफ दी गवर्नमेंट चन्डीगढ़ में भी यह नाशरा दिया गया है और कहा यह गया है कि 4,000 एकड़ या बीघे जमीन को अन्डर कल्टीवेशन लाया जा रहा है और दरख्तों के नीचे फसलें उगाने का यत्न किया जा रहा है। पहले तो दरख्त लगाएंगे और फिर अब उनके नीचे ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं और कहा गया है कि इन के नीचे गेहूं बोया जा रहा है। मैं आप का ध्यान इस तरफ दिलाऊं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि यहां पर श्री एम. सी. छागला एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट आफ इण्डिया यहां पर तशरीफ लाए किसी रेली के सिलसिले में तो उनका स्वागत किया गया और गवर्नमेंट कालेज के लान पर एक साढ़े तीन एकड़ का लान तैयार करवाया गया जिस के लिए बताया गया है कि कलकत्ता से घास मंगवाया गया। और इस लान को तैयार करने पर 5 हजार रुपया खर्च किया गया।

क्षिशा मन्त्री : यह बिलकुल ग़लत है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : इस के बारे में फिगरज गवर्नमेंट कालेज के खाते में जरूर होंगी। उस लान पर घास उगाई गई। और सिर्फ 10 मिनट के लिए छागला साहिब वहां पर रहे। यह ठीक है कि छागला साहिब हमारे मुअज्जिज मेहमान थे और उनका स्वागत करना चाहिए था लेकिन इतनी रकम अगर किसी काम पर खर्च की गई तो उसे कायम रखना चाहिए था। अब कालेज वालों को यह कहा गया है कि इस लान में से घास को उथल दो और इस की जगह पर गंदम लगा दिया जाए। आप अंदाजा लगाएं कि साढ़े तीन एकड़ के प्लॉट पर कितनी गंदम हो सकेगी। क्या 5,000 की गंदम निकल जाएगी ? तो मैं यह कहता हूं कि this is a big hoax. It is a fraud. लोगों की आंखों में धूल डालने वाली चीज है कि हुक्म दे दिया कि कोठियों के लान्ज में गंदम बीज दी जाए। इस से एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट नहीं हो सकती।

फिर एग्रीकल्चर इन्स्पेक्टरों की गिनती को लीजिए, इस में कितना इजाफा हुआ है। मेरे अपने हल्का सोनीपत में, सोनीपत ब्लाक में 9 इन्स्पेक्टर हैं जहां कि पहले सारी तहसील में एक होता था।

और यह 9 के 9 ही यू. पी. के रहने वाले हैं और इस तरह से रह रहे हैं कि जैसे मेहमान होते हैं, रोटी खा ली और ठाठ से रहे। मैं यह समझता हूँ कि डिवलपमेंट के महकमा का भार और बोझ हमारे फंड्स पर है और नीचे काम करने वाले इस तरह से हैं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया।

पंजाब की जनता के कंधों पर बोझ है। इस लिए अगर डिवलपमेंट के सारे डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया जाए तो 10 करोड़ रुपये की रकम गवर्नमेंट को सेव हो जाएगी और बी. डी. अजी. और उनके साथ जीपों में चलने वाले कम्पैनियन खत्म किए जा सकते हैं।

इस लिये मैं कहूंगा कि डिवलपमेंट के नाम पर जो भार गवर्नमेंट ऐक्सेचकर पर डाला जा रहा है वह खत्म किया जाये।

एक दो बातें मैं मिल्क सप्लाय स्कीम और फूड प्राईसिज के मुताल्लिक भी आप की खिदमत में अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ।

इन्होंने ने फूड कराईसिज का नारा लगा कर मुलक में भुखमरी फैलाई हुई है। मेरे सोमवार शाम को 4-5 मेहमान आ गये। मैं ने जब उन के लिये खाना मांगा तो नहीं मिला, दूध मांगा तो वह भी नहीं मिला।

आखिर में उन को कुछ तो खिलाकर ही सुलाना था इस लिए मुझे फौरन बाज़ार जाना पड़ा और केला, संतरा वगैरा जो भी मारकेट से मिल सका उन्हें ला कर दिया। मैं पूछता हूँ आखिर इस सूबे में ऐसा क्यों है।

क्या हिंदुस्तान में कहीं और इस तरह की पाबंदी लगी हुई है ? अगर नहीं, तो यहां क्यों है ? मैं पूछता हूँ कि क्या हफते में एक बार रोटी न खाने से खुराक में इजाफा हो जायेगा।

क्या यह कोई भुक्खभरी का ड्रामा सटैज नहीं किया जा रहा महज अमरीका को दिखाने के लिये कि हम तो भाई भूखे मर रहे हैं, हमारी आप इमदाद करो।

मुलक को भिखारी शो करना, क्या इस तरह से इस मुलक की 46 करोड़ जनता को बैठे देखते हुये शर्म नहीं आयेगी। मैं कहता हूँ कि अगर आप को नहीं आती तो मुझे जरूर आती है।

आप मिल्क सप्लाय स्कीम को भी देख लीजिये। इस स्कीम के नाम पर इन्होंने ने सारे पंजाब के नाक में दम कर रखा है।

सोनीपत तक का दूध ले जा कर तो दिल्ली के हलवाई खोया निकाल सकते हैं मगर पंजाब के सारे हलवाई बेकार बैठे रहें तो कोई बात नहीं है। आज जब मिनिस्टर साहिब का ध्यान इधर दिलाया गया तो आप ने फिर कह दिया कि अभी दूध से पाबंदी उठाई नहीं जा सकती।

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

कैसी हालत हो गई है इस मुल्क को ? डिप्टी स्पीकर साहिब। आप भी 70 साल की हो गई हैं आप ही बतायें कि क्या आप ने कभी 28 रुपये मन गेहूं का भाव देखा था ? 24-25 रुपये मन कभी चना बिका था ? यह कहते हैं कि फूड प्राईसिज इस लिये कंट्रोल की हैं ताकि सब को अनाज मिल सके ।

आप ज़रा देहात में तो जा कर लोगों की हालत देखें जिन को एक वक्त भी पेट भर कर खाना नहीं मिलता । अगर यह हालत करनी थी तो फेयर प्राईस शाप्स पर इतना भारी खर्च करने की क्या ज़रूरत थी ? मार्च—अप्रैल में इन्होंने कहा था कि 7,000 Fair Price Shops have been opened by the Government. इस तरह की बेसलैस बातों के करने का क्या फायदा है, आप ज़रा प्रैक्टिकल तौर पर तो देखें कि खुराक की हालत इस मुल्क की क्या है । हम आज कहां से कहां पहुंच गये हैं ।

अगर इस सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन को लिया जाये, तो मैं यही कहूंगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मिज कमिशन की रिपोर्ट ही ले लीजिये कि उन्होंने ने इस के मुतालिक क्या कहा है ।

हनुमंथध्या की रिपोर्ट अगर आप ने पढ़ी हो तो उस में एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक लिखा है कि "The Punjab administration is paper-logged as the State is water-logged." अगर इनकी नीयत साफ थी तो जो रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मिज कमिटी के चयरमैन ने दी थी उस को प्रैक्टिस में लाते, मगर यहां तो इन्होंने एक छोटे से क्लर्क से लेकर सारे अमले को एक टायर सिस्टम में जकड़ रखा है । It is a large burden on the shoulders of Punjab. इस हकूमत का अगर कोई ध्यान है तो महज तीन बातों की तरफ है, वह है मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग की तरफ ।

अब आप ही बतायें, जब स्टेट के हालात ऐसे हों तो कैसे गवर्नर साहिब के ऐडरैस पर शुक्रिये का आया रैज़ोल्यूशन यहां पर पास किया जा सकता है ।

शिक्षा मंत्री: वैसे तो सारी डिबेट का जवाब चीफ मिनिस्टर साहिब देंगे । मैं एक मिनट में एक मामले पर हाउस की तवज्जो दिला कर क्लोयर कर देना चाहता हूं । मेरे फाज़ल दोस्त ने जो अभी अभी कलकत्ता से मंगवा कर घास लगाने की बात कही है इस से मुझे कुछ हैरानी सी हुई है ।

यह सरासर ग़लत ब्यानी से काम लिया गया है । वहां पर एक पैसा भी कहीं घास लगाने पर खर्च नहीं किया गया आप खुद चलकर देख सकते हैं । मैं इस बात को ओपनली चैलेंज करता हूं ।

जब हम इस आगस्ट हाउस में कोई एक बात भी ऐसी कर देते हैं जिस का वजन ही कोई न हो तो बाकी सारी बातों का भी कोई वजन नहीं रहता।

आप देखें यह कहते हैं 5,000 रु० कलकत्ता से घास मंगवाने पर खर्च किया। मैं कहता हूँ एक पैसा भी इस संबंध में वहां पर खर्च नहीं हुआ। अगर हो तो आप जो मरजी सजा तजवीज करें मैं भुगतने को तैयार हूँ।

**पंडित चिरंजी लाल :** मैं कहता हूँ कि घास तैयार करने के लिये लैंड तैयार की गई, घास मंगवाया गया जब श्री एम. सी. छागला आये थे। यह पता नहीं यह कलकत्ता से आया या कहीं और से मगर इतना जरूर है कि घास जरूर मंगवाया गया।

**शिक्षा मंत्री :** चलो ठीक है, अगर घास मंगवाया गया हो या इसके लिये लैंड भी तैयार की गई हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, वरना यह इस्तीफा दें।

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** पहले ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब आप को इस्तीफा दें, मैं भी आपको दे दूंगा। फिर आप जाकर मौका देख लें। एक बात के लिये एक तरीका है, मगर ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब हर बात में इस्तीफा की धमकी देते हैं। The Ministers are supposed to be broad-minded.

**उपाध्यक्ष :** अगर किसी बात पर दोनों में मतभेद है तो दोनों मौका पर जाकर और देखकर तसल्ली कर सकते हैं। इस तरह की बातों में आखिर हाउस का वक्त जाया क्यों किया जाये (If there is any difference of opinion between the Minister and the Member both of them should see things on the spot and satisfy themselves. After all, why should the time of the House be wasted like this?)

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** आप भी तसल्ली कर लें, मैं उनको भी झूठा नहीं मानता। मैं ने जो ऐलीमेशन्ज लगाये हैं आप उनकी इन्कवायरी करा कर पहले उसे रिफ्यूट करें।

**श्री मंगल सैन :** आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, मैडम। मैं आपका रुलिंग इस बात पर चाहता हूँ कि जब कि कोई ऐसा इशू इस हाउस में ऐसे इनवालवड हो जिस पर कि इस हाउस का एक आनरेबल मिनिस्टर इस्तीफा देने को कहे, यही नहीं बल्कि दूसरा मेम्बर भी इस्तीफा देने को तैयार हो तो ऐसे जंकचर पर इस हाउस की रोशनी के लिये आपका रुलिंग आना लाजमी है। मैं इस मामले पर आपकी गार्डिडैस चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष : बैठ जायें । वह आपको इस्तीफा भेज देंगे । (The hon. Member may resume his seat. He will send his resignation to him.) (Laughter.)

श्री मंगल सैन : मुझे मत भेजिये, अपने पास ही रखिये । (हंसी)

पंडित भगीरथ लाल : (पठानकोट) उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव गवर्नर महोदय के भाषण पर पेश किया गया है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

गवर्नर महोदय ने अपने इस भाषण में इस बात की खास तौर पर चर्चा की है कि पिछला वर्ष खास तौर पर संकट वर्ष था जो हमें गुज़ारना पड़ा है ।

इस भाषण में जहाँ उन्होंने ने उन नौजवानों का, उन शहीदों का, देश के ऊपर मरने वालों का, कुरबानी करने वालों का, देश के संकट में साथ देने वालों का, हर फिरके का जिस ने कि साथ दिया है, जिक्र किया है वहाँ इसके साथ चाहे कोई व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, ट्रक वाले हैं, सब ने अपना अपना हिस्सा उसमें डाला है, उनका भी जिक्र किया है ।

यह चीज हमारे देश की एकता का सबूत है । डिण्टी स्पीकर साहिब, मैं तो बिलकुल बार्डर पर रहने वाला हूँ । जिला गुरदासपुर में पठानकोट के पास हम ने खुद देखा, मुझे उन मोर्चों पर जाने तक का मौका मिला है । हम बार्डर पर रहने वालों ने जहाँ बंब पड़ रहे थे वहाँ जा कर अपनी सेवाएं देश के लिए अर्पण करने का यत्न किया ।

यह सारे देश के लिए एक हितकर, उत्साह-वर्धक और देश को आगे ले जाने वाली बात है जिसका जिक्र भाषण में आया है । इस लिये मैं उस भाषण में बताई गई बातों के बारे में कहना चाहता हूँ । डिण्टी स्पीकर साहिब, इसके साथ साथ गवर्नरमैट ने भी अपना पूरा यत्न लगा कर मदद की । हमें खुशी है कि गवर्नरमैट ने उन परिवारों को, जिन के आदमी शहीद हुए हैं, हर तरह से, हर ढंग से, हर योग्यता से उत्साहित करने का, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ देने का वायदा किया है । (At this stage Pandit Chiranji Lal Sharma, a Member of the Panel of Chairmen occupied the Chair.)  
चेयरमैन साहिब, आज देश बड़े कठिन मरहले से गुज़र रहा है । पंजाब ने कई करोड़ रुपया रक्षा फंड में दिया है । सोना दे कर अपना हिस्सा डाला है और बांड लिये हैं । इत्तफाक से हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब भी यहां बैठे हैं और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इत्तफाक से उनके पास है । मैं उनकी तवज्जो पठानकोट सब-डिवीजन की तरफ दिलाना चाहता हूँ । पठानकोट कोहिस्तान का इलाका है जहाँ से सारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और कुल्लू वगैरा के लिए सप्लाय होती है । पाकिस्तान ने पठानकोट पर अटैक करने के लिए पड़ी चोटी का जोर लगाया ।

वहां की लाईन काटने के लिए कोशिश की । हमारे बहादुरों ने बहादुरी से मुकाबला किया और पाकिस्तान मुंह की खा कर गया । पठानकोट में इस वक्त तक कोई इंडस्ट्रीयल एस्टेट नहीं बन सकी । (विष्ण)

अगर यह बोलेंगे तो ठीक नहीं । चेयरमैन साहिब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं ठीक बोल रहा हूं यह इंटरेस्ट करते हैं । पठानकोट सब-डिवीजन की खास बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया ।

उस पिछड़े हुए इलाका की तरफ ध्यान दिया जाए । उसके साथ नरोट जैमल सिंह हिल्ली ऐरिया भी उसके साथ लगता है । अगर वहां कोई इंडस्ट्री लग जाए तो उस से वह लोग जो बेरोजगार हैं, पिछड़े हुए हैं उन्हें उत्साह प्राप्त होगा, वह अपने जीवन के दिन अच्छी तरह गुजार सकेंगे । चेयरमैन साहिब, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं । वहां ट्रांसपोर्ट का काम बहुत भारी है ।

**सरदार संपूरन सिंह पौला :** आठ ए पुआर्ट आड आरडर, सर । चेअरमैन साहिब, मैं आप की तुलिंग चाहता हूं कि की हाउस के दो मेंबर हाउस विच अस-डीटे की गलत रथ के वापस लै सकदे हन ज्ञां नही ?

**Mr. Chairman :** How do you take it that it has been taken back. This has not been done.

**सरदार संपूरन सिंह पौला :** की हाउस विच आधी गलत वापस लै सकदे हन ज्ञां नही, मैं आप की तुलिंग चाहता हूं ।

**श्री सभापति :** जो आपने कहा है वह ठीक है । (Whatever the hon. Member has said is correct.)

**सरदार गुरदरशन सिंह :** आठ ए पुआर्ट आड आरडर, सर । हाउस विच चैलेंजिंगाजी होयी सी । ऐज्युकेशन मन्सटर साहिब ने 'उठ के असडीटा' लिख लिआ उे उहाडे केल ज्ञां सपीकर साहिब केल दैवे असडीटे पहुँच गये । अगर नही पहुँचे उां एह मामला की है ?

**श्री सभापति :** अगर मेरा अस्तीफा होता तो वह मेरी जेब में होता । आई एम परसनली कन्सरंड । आप डिप्टी स्पीकर से कहें । (If it were my own resignation, it would have been in my pocket. Since I am personally concerned in the matter, the hon. Member may enquire about it from the Deputy Speaker.)

**पंडित भगीरथ लाल :** पठानकोट तीन चीजों के लिए मशहूर है टिंबर, सप्लाई और ट्रांसपोर्ट । उस इलाका को इस संबंध में तमाम सुलतें मिलनी चाहिए ।

**सरदार गुरदशन सिंह :** मुस्कराते क्यों हैं ?

पंडित भगीरथ लाल : और रोज़? चेयरमैन साहिब, रोने वाले तो यह हैं मैं तो मुस्करा कर चलता हूँ। वहाँ ट्रान्सपोर्टों के साथ बड़ी भारी बेइन्साफी है। वह यह कि हिमाचल से यानी चम्बा से सीधे रूट जो है वह पठानकोट के हैं, लेकिन वे हिमाचल वालों के हैं। वहाँ के जो ट्रान्सपोर्टर्ज हैं उनके जम्मू जाने की कोई इजाजत नहीं है। ( *At this stage Deputy Speaker occupied the chair.*)

वह उधर नहीं जा सकते, अपनी हद में रह सकते हैं। हिमाचल की गाड़ियाँ सीधी पठानकोट पहुँचती हैं। वह सब जगह का स्टॉक ले सकते हैं। लेकिन जो पठानकोट के ट्रान्सपोर्टर्ज या गाड़ियाँ हैं वह हिमाचल में नहीं लाई जा सकती।

वह जम्मू तक स्टॉक को नहीं ले जा सकते। मैं पंजाब गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। इसी तरह से कुल्लू कारपोरेशन में है। पंजाब के, खासकर पठानकोट के ट्रान्सपोर्टर्ज के साथ बेइन्साफी है। मैं गवर्नमेंट की तबज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कुल्लू मनाली की जो कारपोरेशन है उस को हिमाचल का जो हमारा हिस्सा है उस के अंदर जाने की इजाजत नहीं। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिब, आप ने देखा नहीं, बीच में बातें होती रहीं।

उपाध्यक्ष : 5 मिनट में जो कहना है कह कर समाप्त करें। ( *The hon. Member may have his say within five minutes and then wind up.*)

पंडित भगीरथ लाल : मैं अपनी गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ने कण्ठी के एरिया में पीने के पानी का इन्तज़ाम किया है वहाँ पर नलके तो लगे हुए हैं और टाँकियाँ भी बनी हुई हैं लेकिन वहाँ पर जो इस महकमें के मुलाज़िम हैं वह इतनी कोहताई से काम करते हैं कि ठीक समय पर पानी नहीं मिलता। इस लिए इस लापरवाही की वजह से वहाँ के लोगों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सरकार इस बात की तरफ ध्यान ज़रूर दे ताकि लोगों को पूरा फ़ायदा पहुँच सके।

हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने एड्रेस में एक बड़ी भारी अपील की। उन्होंने ने कहा कि हमारा प्रान्त तभी तरक्की कर सकता है अगर यह एक हो कर रहे। अगर यह टुकड़े टुकड़े हो गया तो तरक्की नहीं कर सकेगा। (Noise)

(घबुआ सारीआं आवाज़ां : एह गलत बਿਆनी है, बिहड़े सढे उे लिखिआ होइआ है ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਗਲਤ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਫਾ ਦਸਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਦੱਸਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ।

ਪੰਡਿਤ ਮਹੀਰਥ ਲਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਪੇਜ 32 ਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਰਾਜ ਮੇਂ ਪ੍ਰਗਤਿ ਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੋ ਬਨਾਏ ਰਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਭੀ ਵਰਗੋਂ ਮੇਂ ਏਕਤਾ ਐਵਰ ਸਦ੍ਭਾਵਨਾ ਬਨੀ ਰਹੇ।" ਆਪ ਆਖ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿ ਧੰਨ ਕਯਾ ਹੈ। ਕਯਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ? ਕਯਾ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਏ?

(Interruptions)

Deputy Speaker : Please do not interrupt the hon. Member.

ਪੰਡਿਤ ਮਹੀਰਥ ਲਾਲ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਕੋ ਏਕ ਬਨਾਏ ਰਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਕ ਬਨ ਕਰ ਰਹੇਂ ਤਥੀ ਸੂਬਾ ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : Please resume your seat now.

ਪੰਡਿਤ ਮਹੀਰਥ ਲਾਲ : ਧੰਨ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਪਰ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੋ ਗਯਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਸਪਰਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੋ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Deputy Speaker : That is not your business Please resume your seat.

ਪੰਡਿਤ ਮਹੀਰਥ ਲਾਲ : ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਏਕ ਰਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਏ ਸਭ ਕੋ ਇਸੇ ਸਾਨਨਾ ਚਾਹਿਏ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ (ਫੂਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਲਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗਰੇਡ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ। ਇਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੂਣੇ ਦੂਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂ ਮਨਥਾਈਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨਲਜ਼ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਐਂਡ ਜਗਤਜੀਤ ਮਿਲ, ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 23 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਸੋਲਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1945 ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੇਡ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਗਰੇਡ ਅਜ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਇਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਸਕਵੈਡ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਰੀਲੀਫ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸਾਂ ਤੇ 1-4-1966 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28-2-66 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (The hon. Member may please pass on the papers to the Chair first. Permission for being laid on the Table will be given later on.)

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਦਸ-ਦਸ, ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਰਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਾਜੈਕਟਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ 10, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੈਂਸੀ ਨਾ ਬਣਾਉ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਫੂਡ ਪਰਾਈਸਿਜ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ "ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ" ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭੀ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫਾ ਖੋਰੀ ਤੇ ਨਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਕੇ ਪੰਪਿੰਗ-ਸੈਟਸ ਤੇ ਟਿਊਬ-ਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਤਕ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਲੌਨਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਬਲਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੇਸ ਮੈਚਿਊਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਮੈਚਿਊਰ ਹੋਏ ਹਨ (1) ਰਾਮ ਪੁਰਾ ਤੇ (2) ਫੂਲ ਬਲਾਕਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੇਸ ਮੈਚਿਊਰ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੂਡ ਪਰਾਬਲਮ ਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਊਸਿਕਸ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਗਾਬਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੀਲਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਨਾਹਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਸਗੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬ-ਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਰਾਜ ਵਰਗੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 80 ਟਿਊਬ-ਵੈਲਜ਼ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਪੰਨਾ 22 ਅਤੇ ਪੈਰਾ 11 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਨ, ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੀਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਰੀ ਕਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਹੈ ਇਸਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਘੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਪੈਪਰ ਦੀ ਉਨਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪੈਪਰ ਨਾਲ ਧਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਪੈਪਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣ ਲਉ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਫੂਲ ਨੇ ਕੋਈ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਲਾਬਤ-ਪੁਰ ਤਕ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਮਟੀ ਕਲਾਂ ਤਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਐਸ. ਈ. ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਡੀ. ਸੀ. ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਐਸ. ਪੀ. ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਐਸ. ਪੀ. ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦਫਾ 144 ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸੁਪਰਿਨਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੇ ਦੂਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਕੇ ਕੈਰੋਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸਨੂੰ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਥੇ ਗਈ ਜੋ ਕੁਰਪਟ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ (ਘੰਟੀ) ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਅਜ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਦ ਕੋਈ ਮਗਾਲਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਮਗ ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। (ਹਾਸਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉ। (ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ, ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਪਰਾਬਲਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਐਲ. 480 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਸਬ-ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਬ੍ਰਾਦਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1957-58 ਵਿਚ ਜਿਸ ਇਵੈਕੂਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ ਘਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੈਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬੈਨਾਮੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਬਿਰਲਾਜ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਘੰਟੀ) ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕੈਬੀਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲਾਜ ਦਾ ਡੀਡ ਵੇਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਲ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਕਾਫ਼ਤਸ਼ਾ : ਮੁਖ਼ਯ ਸੰਕੀ (Chief Minister)।

1.00 p.m.

(ਮੁਖ਼ਯ ਸੰਕੀ ਅਧਨੀ ਸਹੀਬ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਖੜੇ ਹੁਏ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਲ ਸੇਨ : ਆਨ ਏਕਸਾਇਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਸੈਡਸ।

**उपाध्यक्षा :** आप ने कितनी बार प्वायंट आफ आर्डर रेज करने हैं। (For how many times the hon. Member has to raise his points of order ?)

**श्री मंगल सेन :** उपाध्यक्षा महोदय, अगर मुझे हजार बार भी प्वायंट आफ आर्डर रेज करने की जरूरत पड़ी तो हजार बार ही प्वायंट आफ आर्डर रेज करूंगा।

(विघ्न)

**उपाध्यक्षा :** श्री मंगल सेन जी, आप अपने लफ्ज वापिस लें कि मुझे रुलज का पता नहीं है। (The hon. Member Shri Manga! Sein may please withdraw his words that I am ignorant of rules.)

**श्री मंगल सेन :** उपाध्यक्षा महोदय, मैंने यह लफ्ज बिल्कुल नहीं कहे। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि हमें जो एजेंडा इशू किया गया उस में लिखा हुआ है कि गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 5 दिन बहस होगी। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की स्पीच के बाद गवर्नर साहिब के एड्रेस पर बहस कन्कलूड समझी जाएगी या बाद में भी चलती रहेगी ?

**उपाध्यक्षा :** जब मुख्य मंत्री जबाब देने के लिए खड़े हो गए तो आप को समझ लेना चाहिए कि गवर्नर साहिब के एड्रेस पर बहस खत्म होगी या नहीं। (When the Chief Minister has arisen to reply the debate the hon. Member should understand whether the discussion on Governor's Address comes to an end or not.)

**बाबू बचन सिंह :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिब पहले हमें हाऊस के बिज़नेस के बारे में प्रोग्राम मिला। उस के बाद हमें रीवाइज़्ड प्रोग्राम जारी किया गया। मैंने खुद स्पीकर साहिब से बात की और उन्होंने मुझे बताया था कि गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 5 दिन बहस जारी रहेगी। प्रोग्राम में भी 5 दिन गवर्नर साहिब के एड्रेस में दिए गए हैं। इस लिए आप इस बारे में देख कर हमें अपना रूलिंग दे।

**उपाध्यक्षा :** मुख्य मंत्री जी को अपनी स्पीच करने दें और इसी बीच में मैं रिकार्ड देख लूंगी और अपना फैसला दे दूंगी। (Let the Chief Minister proceed with his speech and in the meantime I will consult the record and then give my decision on it.)

**कामरेड सभसेर सिंਘ ਜੋਸ਼ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰੁਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚੀਫ ਮਨੀਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਬਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। (ਸ਼ੋਰ)

उपाध्यक्षा : अगर जरूरत महसूस हुई तो वह उन सदस्यों के प्रश्नों के जवाब दोबारा दे देंगे। (If need be, the Chief Minister would again reply to the points raised by these members.)

(Noise)

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिब, आप ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की स्पीच के बाद भी बहस जारी रहेगी। ]

उपाध्यक्षा : मैं ने यह नहीं कहा। मैं ने कहा कि मुझे पहले रिकार्ड देखना है और उस के बाद फैसला दूंगी। (I have not said so. What I said was that I would first see the record and then give my finding.)

(Noise)

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : आप रिकार्ड देखेंगे और आपको पता चलेगा कि पहले गवर्नर साहिब के एड्रेस पर दो दिन बहस होती थी। उस के बाद तीन दिन बहस होनी शुरू हुई और अब गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 4 दिन बहस होती है। (शोर)

कुछ आवाजें : नहीं पहले 5 दिन बहस होती थी। (शोर)

उपाध्यक्षा : मैं ने रिवाइज्ड प्रोग्राम देखा है। उस में लिखा है कि गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 4 दिन बहस होगी। अब हाऊस की कार्यवाही उसी प्रोग्राम के मुताबिक होगी। (I have seen the revised programme of the sittings of the session. It indicates that Governor's Address would remain under discussion for four days. The House is to conduct its proceedings according to the programme.)

(Noise) (Interruption)

श्री मंगल सेन : आन ए प्रॉपर्ट आफ आर्डर, मैडम। . . . . .

उपाध्यक्षा : आप का नम्बर 2 पर था और पंडित चिरंजी लाल शर्मा का 4 पर था लेकिन आप के चीफ विहप ने पंडित चिरंजी लाल शर्मा को स्पीच करने के लिए कह दिया था। इस लिए उसे टाइम दिया गया। (The name of the hon. Member was at No. 2 while that of Pandit Chiranji Lal Sharma was at No. 4, but since their Chief Whip had requested to allow Pandit Chiranji Lal Sharma to speak, therefore he was given time accordingly.)

(Noise)

श्री मंगल सेन : आन ए प्रॉपर्ट आफ आर्डर, मैडम। कैसे हुआ, यह डिप्टी स्पीकर साहिब, आप आज चेयर पर विराजमान हैं। आप मुझे बोलने की इजाजत दें या न दें यह तो आप की भर्जी है। मेरी प्रार्थना यह है कि हमें जो रिवाइज्ड प्रोग्राम दिया गया, उस में गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 4 दिन बताए गए हैं लेकिन यह बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो नहीं हुई थी कि गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 4 दिन बहस होगी और न ही इस बारे में कोई मीटिंग कनवीन हुई। यह प्रोग्राम कैसे बदला गया ?

**उपाध्यक्षा :** मैं भी खुद बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग में मौजूद थी। वहाँ पर तो यही फैसला हुआ था। अगर मेरा वस चले तो मैं 10 दिन गवर्नर साहिब के एड्रेस पर निश्चित करूँ। लेकिन गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 4 दिन और बजट डिस्कशन पर 5 दिन मुकर्रर हुए थे। (I was myself present in the Business Advisory Committee. This was the decision which was taken there. If it were in my power, I would have fixed ten days for the discussion of the Governor's Address. But the fact remains that four days for discussing the Governor's Address and five days for the general discussion on the Budget were fixed.) (Noise)

**बाबू बचन सिंह :** आन एक्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पास पहले ओरिजिनल प्रोग्राम पहुँचा। उस के बाद रीवाइज़ड प्रोग्राम मिला। प्रोग्राम पहले के मुताबिक शिवरात्री के दिन भी गवर्नर साहिब के एड्रेस पर बहस होनी थी। अगर वह दिन गवर्नर साहिब के एड्रेस पर बहस करने के लिए मान लिया जाए तो उस से साफ़ ज़ाहिर है कि गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 5 दिन बहस होनी थी। अगर उस में कोई तबदीली हुई तो सवाल यह है कि वह बात कैसे तय की गई। इस लिए मेरी अर्ज यह है कि आया पहले प्रोग्राम के मुताबिक काम चलेगा या रीवाइज़ड प्रोग्राम के मुताबिक काम चलेगा ?

**उपाध्यक्षा :** मैं ने रीवाइज़ड प्रोग्राम देखा है। उस में गवर्नर साहिब के एड्रेस पर 4 दिन निश्चित किए गए हैं और उसी मुताबिक हाऊस की कार्यवाही चलेगी इस के अलावा बजट डिस्कशन पर बहस 5 दिन जारी रहेगी। (I have consulted the revised programme. It shows that four days have been fixed for discussing the Governor's Address and the proceedings of the House would be carried on accordingly.)

(Noise) (Interruption)

**ट्रांसपੋर्ट अਤੇ चੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਛੁਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਚੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜਨੈਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਰਖ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 23 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜਨੈਸ ਹਟਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹੋ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਵਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। (ਵਿਘਨ) ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਓ। (I may tell Sandhu Sahib that it is not proper on the part of any hon. Member to assume that he alone knows the rules and regulations. He should bear this in mind that the Chair is also conversant with the rules. This chapter may now be closed. (Interruption) Sardar Gurnam Singh was present in the Committee. He will clarify the position (Interruption) He may be enquired in this regard.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਛੁਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅਜ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There is no confusion. ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਵਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ)।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਉ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਉ। (ਵਿਘਨ) ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। (The hon. Member may please resume his seat. Sardar Gurnam Singh may kindly clarify the position. (Interruption) The hon. Member is a wise man. It is not desirable to behave in that manner.) (Interruption) (Noise)

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ :** ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ। “Modified tentative programme for the Budget Session ensuing from the 14th”

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ । (ਵਿਘਨ) ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਮਨਿਸਟਰ ਐਵੇਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਝਟ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ । ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗਏ ਰਖੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.....

**ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ :** ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਐਗ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ?

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ :** ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ । ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ । ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਕਤ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ । ਮੇਰਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ 10 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

'Copy forwarded to all Members of the Punjab Vidhan Sabha for information.'

2. This supersedes the programme issued on the 7th of February, 1966.'

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

**ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ :** To the best of my knowledge, ਚਾਰ ਹੀ ਦਿਨ ਰਖੇ ਥੇ ।

(ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਚੇਅਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ।)

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਬੈਠ ਜਾਉ, ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ । (The hon. Member Shri Gill is not well. He need not take the trouble of rising on a point of order. He may please sit down.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਬੀਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਉ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਂਸਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜ਼ੇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਬੀਚ ਆਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਵੇ । ਸਾਡੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯੀਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੁਲਿੰਗ ਦਿਉ ਤਿ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ।

डिप्टी स्पीकर : उमीं ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ । (The House runs the Government.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸੱਤ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर एड्रेस पर चार दिन की बहस के दौरान 26 के करीब स्पीकर ने अपने खयालात का इज़हार किया है । हो सकता है कि मैं हर भाई की हर एक बात का जवाब न दे सकूँ । लेकिन मुझे खुशी है कि हर भाई ने आपने विचार हाउस में रखे । इस बात का उन को हक है कि वे गवर्नमेंट को पबलीकली क्रिटिसाईज़ करें, गवर्नमेंट की पालिसी की नुक्ताचीनी करें । लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पबलिकली क्रिटिसाईज़ करते वक़्त हर एक भाई, खाह वे अपोज़ीशन के हों, खाह दूसरे हों, उन को पबलिक इंट्रेस्ट को ज़रूर सामने रखना चाहिये । यह पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी का बुनियादी असूल है, इस पर हमें पूरी तरह से अमल करना चाहिये । इस के साथ ही कुछ मੈम्बरान ने आपनी तकरीर करते हुए ऐसे डिस्टारटिड फ़ैक्ट्स पेश किए हैं कि बेहतर होता यदि वह सारी चीज़ की अच्छी तरह से तहकीकात कर लेते । मैं आप के द्वारा हाउस के मेम्बरान को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस जिस भाई ने जो जो भी बात कही है वह जिस जिस तवज्जो के मुस्तहक होगी उस को उसी के मुताबिक पूरी तवज्जो दी जाएगी ।

जो फ़ैक्ट्स उन्होंने दिये हैं उन के मुताबिक पता किया जाएगा और उन में से जो फ़ैक्ट्स ठीक निकलेंगे उन के सम्बन्ध में मैं उन मेम्बर साहिबान को कान्फ़ीडेंस में ले कर कारैस्पोंडेंस से उन उन चीज़ों को टेक अप करूंगा और उसके मुताबिक अगर उन की तसल्ली न हुई तो उन को पूरा हक है कि वह बजट सेशन में वह उन सारी चीज़ों को कह सकते हैं ।

कुछ मेम्बर साहिबान ने तकरीर करते हुए अपनी अपनी कान्स्टीचुएंसीज़ की बाबत कुछ बातों का ज़िक्र किया । वह तो जब बजट आ जाएगा तो उसके बाद भी वह उन उन बातों को कह सकते हैं इसलिए शायद मैं उन की कई चीज़ों में इस वक़्त न जाऊँ लेकिन जहां तक पालिसीज़ का सवाल है, उन्हीं की बाबत हमें इस वक़्त डिस्कशन करनी है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछला साल जो गुज़रा है यह पंजाब के लोगों के लिए मुसीबतों का तकलीफों का और कठिनाइयों का साल था लेकिन जिस बहादुरी और हिम्मत से पंजाब के लोगों ने अपना खून देकर, अपनी हिम्मत से मेहनत और परिश्रम के साथ कुरबानियां देकर इन सभी कठिनाइयों का मुकाबला किया है इस के लिए पंजाब की पुलिस, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब के किरती, पंजाब के गांव में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग, सभी हमारी मुबारिकबाद के और धन्यवाद के पात्र हैं । इस इन्डो-पाकिस्तान कान्फ़्लिक्ट के दौरान हिन्दुस्तान के जितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है उन में मैं समझता हूँ कि पच्चास फीसदी नौजवान पंजाब में से गए हैं और वह सारे के सारे हसारी मुबारिकबाद के हक्दार

[मुख्य मंत्री]

हैं और उन के परिवारों की देखभाल करना, उन के परिवारों की मदद करना हमारा अहम फर्ज है और यह बात पंजाब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पर ली है कि हम पूरी तरह से उनके परिवारों की मदद करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस कान्फ्लिक्ट के दौरान पंजाब को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पंजाब की ट्रेड तबाह हो गई, पंजाब के किसान को बड़े जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। बारिश नहीं हुई, ड्रोट से फसलों को पानी नहीं मिला और इस कारण फसलें तबाह हो गईं। लेकिन पंजाब के लोगों ने मेरी अपील पर जो कि मैंने 14 सितम्बर, 1965 को पंजाब के लोगों के नाम की थी कि पंजाब की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए, पंजाब के जवानों की बैलफेयर के लिए इन्तजाम किए जाएं, इन सभी मुसीबतों के बावजूद हाउस को यह जान कर खुशी होगी कि इस फंड में लोगों ने 3,95,83,844 रुपया दे दिया है और उस के लिए अभी भी पैसे आ रहे हैं। कल ही मुझे कॅनेडा से वहां को खालसा दीवान सोसाइटी की तरफ से पाँच हजार डालर आया है। इसलिए इस फंड में जिन भाई और बहनों ने हिस्सा दिया है वह सभी हमारी मुबारिकबाद के मुस्तहक हैं। इस सम्बन्ध में मैं हाउस को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस फंड का एक एक पैसा हमारे लिए एक सेकरंड अमानत है और इस का एक एक पैसा उन नौजवानों की बैलफेयर के लिए, पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए ही खर्च किया जाएगा। इस के साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी यह खाहिश है कि यहां पर पंजाब के अन्दर एक अड़ाई करोड़ रुपए का परमानेंट ट्रस्ट कायम कर दिया जाए जिस के जरिए पंजाब के उन नौजवानों के बच्चों की, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुरबानियां दी हैं, शिक्षा के लिए उन की विद्या के लिए परमानेंट तौर पर ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया जाए। गवर्नमेंटें आती हैं, चली जाती हैं, मिनिस्टर आते हैं और चले जाते हैं लेकिन जिन जवानों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किए हैं उन के काम हमेशा के लिए जिन्दा रहेंगे, उन का नाम हमेशा के लिए जिन्दा रहेगा और उसके लिए, जैसा मैंने अर्ज किया, कि हम कोई परमानेंट तौर पर काम करना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के अन्दर मैं आप के जरिए हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी किस्म का कोई पालेटिव्स नहीं आने दिया जाएगा। इस का प्रबन्ध करने के लिए इसमें इम्पार्टेंट आफिसर्ज होंगे, जिन में चीफ सैक्रेटरी होगा, होम सैक्रेटरी होगा, आई.जी. और वैस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर होंगे और इस तरह से और दो तीन अफसर होंगे जिन का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा। इस लिहाज से हम सोच रहे हैं कि एक परमानेंट फंड इस सिलसिले में कायम किया जाए। (प्रशंसा) डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बार के अन्दर आप ने देखा कई जवान डिसएबल्ड हो गए हैं और हम उन की पूरी तरह से सहायता करना, और उन के बाल बच्चों की देखभाल का प्रबन्ध करना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमने एक कमेटी बैठाई थी और आर्मी से इस सम्बन्ध में हम सारी फहरिस्त गैरा इकट्ठा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस तरीके से पूना के अन्दर कुईन

मेरी इन्स्टीचूट है उसी तरह से यहां पर टैक्निकल ऐजुकेशन दें और प्रबन्ध करें। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और उन्होंने सारा टूर करके एक मुकम्मल चीज हमारे सामने पेश की है। उस सिलसिले में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मार्फत हाऊस को कहना चाहता हूं कि हम उस के लिए पच्चास लाख रुपए से एक ऐसी इन्स्टीचूशन कायम करना चाहते हैं और उस के लिए पच्चीस लाख रुपया पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। हम कोशिश करेंगे कि कुछ रुपया पोस्ट वार रीकन्स्ट्रक्शन फंड में से, कुछ रुपया डिफेंस मिनिस्टरी से मिले ताकि जो जवान डिस-एबलड हुए हैं उन की पूरी तरह से देखभाल हो सके, उन के बच्चों की देखभाल हो सके, और उस सिलसिले में सारा प्रबन्ध किया जा सके। उन के लिए रोजगार का प्रबन्ध हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब के अन्दर जिन जिन जिलों से जवान शहीद हुए हैं उन की बाबत जिक्र करते हुए कुछ भाईयों ने यहां पर शिकायत की है कि वहां पर कई जगहों पर मिनिस्टर साहिबान नहीं पहुंचे। ठीक है। हमें वहां पर पहुंचना चाहिए था। एक एक जगह पर पहुंचना चाहिए था। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मार्फत मेम्बर साहिबान को अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने अपने सभी डिप्टी कमीशनर्स को इस बात की हिदायत की हुई थी कि जब जब भी वह ऐक्स ग्रेशिया ग्रांट दें तो वह खुद एक एक फैमिली के पास पहुंचें और उन के तई हमारी तरफ से उनके परिवारों को सिम्पथी जाहिर करें। जहां पर दूसरे जिलों के बहुत से लोग शहीद हुए, वहां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांगड़ा जिला ने हिन्दुस्तान की इज्जत और शान को कायम रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जवान देकर हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा किया है। (प्रशंसा) वहां के लोगों के सामने, राजपूतों के सामने हमारा सिर इज्जत के साथ झुकता है। इस मौके पर मैं दूसरे जिलों की सेवाओं को नज़र अन्दाज नहीं करना चाहता। लुधियाना जिला में भी हमारे बहुत से बहादुर जवानों ने अपने बलिदानों से अपना और सूबे का नाम रोशन किया है। एक से एक बढ़ कर है। किस किस का जिक्र करूं। जिला होशियारपुर, ऊना, दसूआ वगैरा सभी जगह के लोगों ने एक दूसरे से बढ़ कर कुरबानी की है। जालन्धर, अमृतसर, हिसार से लेकर अज्जर, रोहतक, करनाल, अम्बाला वगैरा ने इस जंग में हिस्सा लिया है। गांव गांव के लोगों ने, एक एक परिवार ने कुरबानी दी है और वे सारे पूरी तरह से हमारी तरफ से मुबारिकबाद के मुस्तहक हैं। मैं आप के जरिए हाऊस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम उन की जितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं करेंगे। जहां तक उन के मैमोरियल कायम करने का सवाल है, उन की याद मनाने का सवाल है वह सब कुछ जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। (प्रशंसा)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त हमारे सामने बड़े अहम सवाल आ गए हैं। सब से पहले सवाल हमारे सामने यह है कि इस इन्डो-पाक कान्फ्लिक्ट के अन्दर पच्चास हजारके करीब हमारे भाई और बहन, कोई आठ हजार के करीब परिवार उजड़े और बेकार हुए हैं। इसलिए इस वक्त सब से ज्यादा अहम सवाल हमारे

[ मुख्य मंत्री ]

सामने उन को इज्जत के साथ और मान के साथ अपनी अपनी जगहों पर बसाने का है। इस सम्बन्ध में मैं आप को और आप के द्वारा हाऊस को वताना चाहता हूँ कि मार्च के दूसरे हफ्ते में उन को बसाने का काम पूरे जोरों के साथ शुरू हो जाएगा। वैसे 28 फरवरी तक तो पूरी तरह से फोसिज की विद्वान्ता हो जाएगी लेकिन इक के बाद जरूरी है कि एक हफ्ते के अन्दर हमारी पुलिस और फौज उस सारी जगह की देखभाल कर ले ताकि कहीं कोई माईन्ज वगैरा न रह गई हों और इस तरह से कोई खतरे वाली बात न हो। तो इस तरह से इस सारे सिलसिले को देख लिया जाएगा और यह काम शुरू कर दिया जाएगा। वहां पर लोगों का कान्फिडेंस बढ़ाने के लिए पुलिस की चौकियां और रिजर्व पुलिस आगे से ज्यादा रखी जाएगी ताकि लोगों को डर न हो। इस के साथ ही साथ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक चीज और आप के जरिए हाऊस के सामने रखना चाहता हूँ। इन भाईयों को फिर से बसाने के सम्बन्ध में पंजाब गवर्नमेंट ने 1,04,99,650 रुपए की मंजूरी इस वक्त तक दी है जिस में से 55 लाख रुपए फरवरी की 15 तारीख तक डिसबर्स हो चुके हैं और बाकी का रुपया डिसबर्स हो रहा है। जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया का ताल्लुक है, इस वक्त तक उन की तरफ से कोई 1,92,45,000 रुपए की सैक्शन आ चुकी हुई है। इस में रोड्ज भी शामिल हैं जिन के लिए कोई चालीस लाख रुपया खर्च होने वाला है। जो लोकल बाडीज डिस्पलेस्ड हो गई थीं उन को रिहैबिलिटेड करने के लिए भी चार लाख और पैंतालीस हजार रुपए की सबसिडी इसी साल दी गई है और इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और लेबर का जहां तक ताल्लुक है उन के लिए भी लोन वगैरा देने के सिलसिले में मदद की गई जो कि एक करोड़ रुपए के करीब बनती है। तो इन सभी चीजों के बारे में सवाल हमारे सामने है कि किस तरह से इन भाईयों को बसाया जाए। और किस तरह से उन को अच्छी तरह से बसाया जाए। इस सिलसिले में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मार्फत हाऊस से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भाई और परिवार अपनी अपनी जगहों पर वापिस जाएंगे उन को अगली खरीफ की फसल तक, इस वक्त से लेकर अगस्त और सितम्बर के महीने तक पूरी तरह से उन की सबसिस्टेंस के लिए मीन्ज प्रोवाईड किए जाएंगे और यह तब तक किया जाएगा जब तक कि उन की फसल आ नहीं जाती। उन के गुजारे के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से उन की मदद करेगी। न सिर्फ यह, बल्कि उन के बच्चों की ऐजुकेशन के लिए, उन की शिक्षा के लिए पूरे प्रबन्ध किए जाएंगे और उन की फैमिलीज के साईज के मुताबिक उन की हम हर तरह से मदद करेंगे। (प्रशंसा) इस के अलावा यह भी अर्ज कर दूँ कि वहां पर जितने भी रूरल एरिया में या शहरी इलाके में लोग रहते थे और जिन के कच्चे या पक्के मकान थे जो गिर गए उन को बनाने के लिए और उन की मुरम्मत करने के लिए भी पूरा इन्तजाम किया जाएगा। उन को ग्रांट्स दी जाएंगी ताकि वह लोग अपने उन मकानों की मुरम्मत वगैरा करा सकें और नए मकान बना सकें। यही नहीं बल्कि वहां रूरल और शहरी के इलाकों में जिन की दुकानें थीं और जो कि अपनी दुकानों

को छोड़ कर चले गए थे उन को वह दुकानें मरम्मत करने के सम्बन्ध में भी मदद की जाएगी और उन को भी ग्रांट्स देंगे। इस के अलावा जो हमारे ऐग्रीकल्चरिस्ट भाई, ज़िमींदार भाई, जिन्होंने इस मौके पर एक महान् कुरबानी की है, उन के लिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मार्फत अर्ज करना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को ट्यूबवैल्व के लिये, परकोलेशन वैल्व के लिये, फर्टिलाइजर, सीड, ऐग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स, बैलों और ट्रैक्टर के लिये सबसिडी और लोनज दिये जाएंगे। (विध्वन) और उन की मदद की जायेगी। इस सारी चीज़ के लिये डिप्लेज अफसरों की कमेटी ने वर्क आऊट की है। पंजाब गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है और गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ भी इस बारे में खतोकिताबत जारी है। उनकी पूरी पूरी मदद की जायेगी। जो आर्टीज़न थे उन की भी हम पूरे जोर से मदद करेंगे। (तालियां) उन को सबसिडाइज्ड रेट्स पर अनाज देने के लिये दुकानें खोलेंगे। मैं अर्ज करूँ कि हर किस्म का जन्तुजाम, हैल्थ सेंटरों का हस्पतालों का पढ़ाई का वगैरह वगैरह किया जायेगा। हम ने हिन्द सरकार से दरखास्त की है कि बार्डर जिलों में ज़िमींदारों की फसलों की कम्पलसरी इन्शोरेंस कर देनी चाहिए और रैग्रीडेशनल लिमिटिंग की भी इन्शोरेंस की जानी चाहिए।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** On a Point of Order, Madam.

**Chief Minister :** I do not give way.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** We want to hear you, Sir, and therefore, request you to go a bit slow...

**Deputy Speaker :** Please sit down, when I am standing...

*(Interruptions and Noise)*

**Chief Minister :** Sitting of the House may be extended, Madam.

**Deputy Speaker :** I am not going to extend the time.

मुख्य मन्त्री : तो मैं अर्ज कर रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट इन लोगों की रीसैटलमेंट का पूरा पूरा इन्तज़ाम करेगी। हमारे अफसरों की कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, इस पर गौर कर रहे हैं और हिन्द सरकार से परसनल लेवल पर भी और खतोकिताबत के जरिये भी बात कर रहे हैं। इस काम को हम ने फर्स्ट प्रायटी दी है। चूंकि वक्त कम है मैं ज्यादा डिप्लेज में नहीं जाऊंगा।

यहां पर ऐग्रीकल्चर का जिक्र आया। हम इस बात को मानते हैं कि यह हमारे राज्य की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इस की जितनी भी मदद हम कर पाएंगे उतना ही हिन्दुस्तान मज़बूत होगा। पिछले 19 सालों के अन्दर हम 25,000 करोड़ रुपये का अनाज इम्पोर्ट कर चुके हैं। यह बहुत बड़ा बोझा है हिन्दुस्तान पर। इस लिए पैदावार को बढ़ाना बहुत जरूरी है। पंजाब को ग्रैनरी आफ इंडिया कहा जाता है। इस को ज्यादा से ज्यादा ताकत देनी चाहिये। इस लिए राज्य सरकार की यह

[ मुख्य मंत्री ]

नीति है कि इस को ज्यादा से ज्यादा तकवीयत दी जाए। जहां तक एग्रीकल्चरिस्ट की जिनस का ताल्लुक है हमारी यह राय है कि ज़िमींदार को अपनी उपज की मुनासिब कीमत मिलनी चाहिए। आप को मालूम है कि यहां पर एक प्राइस कमीशन और सरदार उज्जल सिंह कमेटी बैठी थी। उस के मुताबिक सब कुछ किया गया। मगर अब हालात बदल गए हैं। इस लिये हम ने परसनल लैवल पर भी और खतोकिताबत के जरिये भी यह कहा है कि पहली फिक्स की हुई कीमतें अब रिवाइज होनी चाहिए ताकि किसान को अपनी प्रोड्यूस की फेयर प्राइस मिले। दूसरी बात यह है कि हम ज़मींदार को कहते हैं कि वह आपनो प्रोड्यूस बढ़ाएं तो नैचुरली इस के लिये उस को साधन भी चाहिए। इस बारे में मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि मेरे पास वक्त नहीं बरना, मैं डिटेल् में जाता। पहली बात यह है कि इस साल हम ने जितना मैक्सीकन व्हीट का सीड बांटा है अगले मालो साल में इस से चालीस गुना ज्यादा बांटा जायेगा। (तालियां)

इसी सिलसिले में आपको मार्फत मैं हाऊस को यह बताना चाहता हूं कि इस साल पानी की कमी की वजह से बिसली की कमी हुई है। तो इस कमी का मुकाबला करने के लिये पंजाब सरकार सूबे में डीज़ल इंजन वाले पम्पिंग सैट लगाने का इन्तज़ाम कर रही है। हम हिन्द सरकार और दूसरे जराए से भी दस हजार डीज़ल इंजनों वाले पम्पिंग-सैट लगाना चाहते हैं। पांच हार्स पावर वाले इंजन को हम 50 फीसदी तक सबसिडाइज करेंगे। (तालियां) दस हार्स पावर वाले इंजन को हम साढ़े सैंतीस फीसदी तक सबसिडाइज करेंगे। इस बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह पम्पिंग सैट किसी मिडल मैन के जरिये नहीं, किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट के जरिये नहीं बेचे जाएंगे बल्कि सरकार ज़मींदारों को बराह रास्त नो-प्राफिट-नो लास बेसिज पर सप्लाई करेगी। (तालियां) मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पिछले सालों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा तीन लाख टन फर्टिलाइज़र बांटा गया था। आईदा साल के अन्दर हम बन्दोबस्त कर रहे हैं कि ज़मींदारों को . . . . (विघ्न) . . . .

**चौधरी देवी लाल :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। हम इनका जवाब तो सुनना चाहते हैं मगर टेप रिकार्ड नहीं सुनना चाह रहे।

#### EXTENSION OF TIME

**Chief Parliamentary Secretary:** Madam, I want to move a motion for extending the time of the House.

**Deputy Speaker:** No, I won't allow you. The Chair is not bound for this.

**Chief Parliamentary Secretary:** I have a right to move the motion, Madam, I beg to move—

That the sitting of the House be extended for half an hour.

**Deputy Speaker:** You should give this in writing.

**Chief Parliamentary Secretary:** I have already moved the motion.  
(Interruptions and Noise)

**Deputy Speaker:** Motion moved—

That the sitting of the House be extended for half an hour.

**Deputy Speaker:** Question is—

That the sitting of the House be extended for half an hour.

**Voices:** Yes.

**Voices:** No.

*(Interruptions and Noise)*

**Sardar Gurnam Singh:** Let us not waste any more time of the House. The Chief Parliamentary Secretary is un-necessarily intervening and interrupting. He is not allowing his Leader to continue his speech.

**Chief Parliamentary Secretary:** I am sorry to say that the Leader of the Opposition does not want the Deputy Speaker to give her ruling. Let her give her ruling.

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** We want to hear the Chief Minister. Let there be no interruptions from the Chief Parliamentary Secretary.

**ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ:** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਦਾ ਇਨਟਰਵੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਲਉ।  
(ਵਿਘਨ)

**Deputy Speaker:** The sitting is extended by half an hour.

#### DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS (RESUMPTION)

**ਕਾਮਰੇਡ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ:** ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਰੈਸ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੰਜਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜਾਡੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ:** ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

**ਪੰਡਿਤ ਜਿਰੰਤੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ:** ਜਨਾਬ ਪ੍ਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਸੇ।  
(ਹੱਸੀ)

**ਸੂਰ੍ਧ ਮਾਤ੍ਰੀ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਈਕੀਲੂਚਰ ਦੀ ਤਰਕਕੀ ਕੇ ਲਿਏ ਜੋ ਜੋ ਸਾਬਨ ਜਰੂਰੀ ਥੇ ਤਨ ਕੀ ਤਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਸੇ ਤਕੜੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਜ਼ੀਦ ਤਕੜੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰਜ਼ ਆਪ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਰਖਨਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਕਹਾਂ ਤਕ ਤਰਕਕੀ ਕੀ

[मुख्य मंत्री]

गई है। जहां तक हिन्दी रिजन का संबंध है 1964-65 में कुल 29 लाख 58 हजार 325 एकड़ जमीन का इरीगेटिड एरिया था और 1965-66 में हरियाणा के एरिया के अन्दर इस सरकार का ध्यान देने की वजह से यह एरिया 32 लाख 19 हजार 197 एकड़ इरीगेटिड हो गया है। इस का मतलब यह हुआ कि 2,60,872 एकड़ जमीन को ज्यादा पानी मिला है। सिर्फ यह ही नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के जरिए से हाउस को यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इरीगेशन का संबंध है और इस को तकवीयत देने के सिलसले में और एग्रीकल्चर के प्वायन्ट आफ व्यू से हरियाणा में काफी प्राबलम्ज थीं, जैसे कि वाटर-लॉगिंग की, जिस की तरफ कि ध्यान दिया गया। मैं यह नहीं कहता कि पंजाबी रिजन में ध्यान नहीं दिया गया लेकिन उस के बारे में मैं बाद में कहूंगा। हम ने पंजाबी रिजन की तरफ भी तवज्जो दी है। जहां तक हिन्दी रिजन का संबंध है मैं अर्ज करना चाहता हूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि वैस्टर्न जमना कैनल रोमाडलिंग प्राजैक्ट की दो स्कीमें थीं। इन में से एक पर 9 करोड़ 52 लाख रुपये का खर्च होना है इसमें से इस वक्त तक 3 करोड़ 82 लाख खर्च कर दिया है और इस से इरीगेटिड एरिया हो जाएगा 12,46,283 और हम इस सारी चीज पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसी तरह वैस्टर्न जमना कैनल के फीडरों पर 3.31 करोड़ का खर्च होना है इस में से इस वक्त तक 2.07 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी इस कैनल को मिल सके। इस प्राजैक्ट के दो हिस्से हैं—नरवाना करनाल लिंक और बरवाला लिंक। नरवाना करनाल लिंक सारे का सारा मुकम्मल हो गया है और बरवाला लिंक पर प्राग्रेस जारी है और आशा रखते हैं कि जिन इलाकों को पानी नहीं मिलता था वहां अब पानी ज्यादा मिलेगा। जहां अब 1.92 क्यू से कस पानी 1,000 एक्ड़ के लिए मिलता था अब 2.5 मिलेगा और फोर्थ प्लान के आखिर तक अगर फण्ड्स मिलते रहे और सारी स्कीम मुकम्मल हो गई तो फिरोजपुर और लुधियाने की तरह 3.5 क्यूसेक्स तक पानी हरियाणा के इलाके को मिला करेगा और यह हरियाणा की खुशहाली के लिए एक अहम कदम इस सरकार ने उठाया है, इसी तरह गुड़गावां कैनल प्राजैक्ट पर 8 करोड़ 31 लाख रुपया खर्च होना है और इस पर इस वक्त तक 3 करोड़ 67 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। इस प्राजैक्ट से कुल 3,43,605 एकड़ जमीन सेराब की जाएगी। और हम आशा रखते हैं कि हम इस प्राजैक्ट को 1969-70 तक मुकम्मल कर लेंगे।

इस के बाद, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज करूँ कि रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम से 1964-65 में 3,400 एकड़ जमीन को इरीगेट किया गया। इस की तरफ मज्जीद तवज्जो दी जा रही है। मैं इस के साथ ही डाट के मसले को लेना चाहता था लेकिन उसे बाद में लूंगा। फैमिन के बारे में जिला हिसार में 42 लाख रुपया खर्च किया गया है और माइनर को एक्सटेण्ड करने से कुल

33,315 एकड़ जमीन को मज़ीद को पानी मिलेगा। इन से एम्पलायमेंट भी मिलेगी और फूडग्रेन की पैदावार को भी तरक्की मिलेगी। इस तरफ पूरी तवज्जो दी जा रही है।

आप के जरिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हाउस की सेवा में यह बताना चाहता हूँ कि फ्लड कंट्रोल के बारे में मुख्तलिफ स्कीमों पर अमल किया जा रहा है। और इस के लिए एक कमेटी बनाई हुई है। जहाँ तक हरियाणा के इलाके का ताल्लुक है पिछले सात-आठ साल के अन्दर उतना काम नहीं हुआ जितना कि पछले डेढ़-दो साल के अन्दर हुआ है। और जहाँ पानी नहीं दिया जा सका या ज्यादा पानी आ जाने की वजह से धरती तबाह हो गई वहाँ इस सरकार के आने पर पूरी तवज्जो दी गई। और इस से करनाल, दिल्ली, रोहतक और गुड़गावाँ के इलाके में काफी तरक्की हुई है, और स्कीम पूरी हो चुकी है। धासा बांध पर जो रैगुलेटर था उस की जहाँ पहले कपेसिटी 450 क्यूसेक्स थी अब बढ़ कर 3,000 क्यूसेक्स हो गई है। और फ्लड को रोकने के लिए हमेशा का खतरा खत्म कर दिया गया है। पहले जहाँ कपेसिटी कम थी वहाँ अब दस गुना बढ़ गई है और इस की तरफ इस सरकार ने पूरी तवज्जो दे कर रोहतक के इलाके को फ्लड से बचाया है। इस इलाके को इस से फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने हमारे कहने पर इस बात को मनज़ूर कर लिया है कि 200 की बजाय 600 क्यूसेक्स पानी का डिस्चार्ज अपने इलाके में ले ले। इस से उस इलाके को फायदा होगा जहाँ आज कल नूध-उज्जाना ड्रेन है। इसी तरह, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मार्फत हाउस को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने घघर दरिया पर एक और साइफन बनाने की रज़ामंदी दे दी है। यह दूसरा साइफन आने वाले मानसून सीज़न से पहले तैयार हो जाएगा। इस साइफन पर कोई गेट्स नहीं होंगे। इस साइफन के मुकम्मल हो जाने से सरसा तहसील में घघर के आस पास के इलाके को फायदा होगा और इस इलाके की प्राबलम्ज हल हो जायेगी। मैं इस वक्त सारी तफसील में नहीं जाता। आप देखें कि हमने कितने इलाके को सैराव करने का प्रबन्ध किया है। वैसर्टन जमना कैनाल में पहले 2.15 क्यूसेक्स जहाँ पानी लगता था अब 2.75 लगेगा। इस से हमारी 9 लाख एकड़ ज्यादा जमीन को फायदा होगा। इस तरह दूसरी कैनाल में जहाँ 2.64 था वहाँ भी 2.75 कर दिया है इस से 105,000 एकड़ और जमीन सैराव हो सकेगी। इस के अलावा हमने 11,000 ट्यूब वेलज़ लगाने का भी प्रबन्ध किया है इन में से 7,000 के करीब अभी मुकम्मल हो चुके हैं, 31 मार्च तक इन की तादाद में और भी इज़ाफा हो जायेगा।

जहाँ तक कैटलवैल्यू का इस सूबे का ताल्लुक है इस की इम्प्रूवमेंट के लिये हमने तीन-चार स्कीमें बनाई हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस के लिये 32 लाख रुपया फारेन एक्सचेंज का मन्ज़ूर किया है। हमारा अंदाज़ा है कि इस साल के आखीर तक 4 करोड़ रुपया भी बनाने में कामयाब होंगे। इस के साथ ही हम 5

[मुख्य मंत्री]

करीमरीज और कायम करना चाहते हैं जो फोर्थ फाइव थ्रीएर प्लैन में पंजाब में कायम की जायेगी। हमें जैसे जैसे भी फारेन एक्सचेंज मिलता जायेगा हम वैसे ही इस काम को आगे ले जायेंगे।

इस के साथ ही मैं एक बात और जो कहनी चाहता हूं वह यह है कि यहां पर कांगड़ा के जब मेरे फाजल दोस्त बोले थे तो उन्होंने ने सब से बड़ी शिकायत यह की थी कि हमारे हां इतने फारैस्ट्स हैं मगर इन के मुतप्रल्लिक रा-मैटीरियल के कारखाने बाहर लगाये जा रहे हैं। इस के साथ ही उन्होंने ने जो जमीन फारैस्ट्स में इन की चली गई है जिस का चहारम वह देते हैं इस का भी जिक्र किया था। मैं यह बात यहां पर साफ कर देना चाहता हूं कि यह बात हम हरगिज नहीं चाहते कि किसी गरीब को किसी तरह का भी कोई नुकसान पहुंचे। हम ने फारैस्ट्स लैंड रूल्ज को बदलने के लिये उन को दोबारा कनसिडर करने के लिये एक कमेटी कायम करने का फैसला किया है। वह कमेटी जब मीट करेगी तो जंगलात के मुतप्रल्लिक जितने भी झगड़े हैं उन को सुलझाने की कोशिश करेगी। इस कमेटी का कांगड़ा के लोगों को पूरी तरह से फायदा पहुंचेगा। इस कमेटी के मैम्बर हैं:—

(1) सरदार दरबारा सिंह

(2) सरदार अजमेर सिंह

(3) चौधरी रिजक राम

(4) चौधरी चांद राम

(5) कैप्टन रतन सिंह

और श्री ज्ञान चंद हिल्ली ऐरिया (डिप्टी मिनिस्टर) इस सारी की सारी चीज को अपने हाथ में जलदी से जलदी लेकर इस काम को करेंगे।

मैं आप की मार्फत एक बात और यह भी कह देना चाहता हूं कि हम हरिजन कल्याण फंड को निहायत ठीक ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात मैं आप की मार्फत यहां पर कह देना चाहता हूं कि हम ने इस सिलसिले में 2,60,00,000 रुपये की जमीन इस फंड में से हरिजनों के लिये खरीद की है। हरिजनों को लैंड देने के सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने कमिटेम्मेंट्स की हैं गवर्नमेंट उन पर पूरी तरह से कायम हैं। मैं इस हाऊस में यह बात कह देना चाहता हूं कि हम ने 33,000 एकड़ जमीन हरिजनों को देने के लिये रिलीज करवा ली है ताकि इन को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। (तालियां) इस के साथ ही मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक हरिजनों को लैंड देने का सवाल है हरिजनों को 2,000 रुपये तक का जो भी लोन दिया जाएगा वह बगैर किसी शर्त के दिया जायेगा। इस के अलावा हम ने यह भी फैसला किया

है कि 20 की बजाये हिल्ली एरियाज की रूल डिबैल्पमेंट के लिये 30% बतौर सब-सिडी के दिया जायेगा। (तालियां)

जहां एक हमारी पंजाब की इंडस्ट्री का ताल्लुक है हम ने इस को डिबैल्प करने के लिये बहुत अहम सर्टेप लिये हैं। इतना वक्त नहीं है कि मैं इस की एक एक की डिटेल् में जाऊं। हम ने इंडस्ट्रियल प्वायंट आफ व्यू से कुछ प्रोजेक्ट्स जिन के लाइसेंस हमें मिल चुके हैं या जिन के लैटर आफ इंडेंट मिल चुके हैं पंजाब में खोलने का फैसला किया है। यह हैं Small Tools, Paper and Pulp, X-ray Equipments, Woollen yarn, Rayon waste yarn, Steel casting, Vanaspati, Food yeast and Brewers yeast, Asbestos, Cement sheets, Steel strips, Tractors, Soda Caustic, Typewriters, Nylon yarn, Chip Board and Cast Iron Rods यह इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं जिन के लाइसेंस हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिले हैं।.....

**श्री जगन्नाथ :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि आप इंडस्ट्री लगाने पर इतना जोर दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसी चीफ मिनिस्टर ने सोनीपत के अंदर एक साल में 40 करोड़ की इंडस्ट्री लगाने का वायदा किया था मगर अभी तक एक पैसा की नहीं लगी तो क्या ऐसे झूठे चीफ मिनिस्टर का भी आप के पास कोई इलाज है ?

**उपाध्यक्ष :** आप 'झूठ' शब्द पहले वापस लें। (The hon. Member may please withdraw the word 'झूठ' (Lie.)]

**श्री जगन्नाथ :** अच्छा जी, मैं झूठ की बजाये इसे गलत ब्यानी ही कहता हूं।

**मुख्य मंत्री :** मैं आप से अर्ज कर रहा था कि हम देखिये इंडस्ट्री को कितनी तेजी से आगे ले जा रहे हैं। 1964 तक हम ने 112 लाइसेंसिज दिये थे या इन के लैटर आफ इंडेंट इशू किये थे मगर अब यह जनवरी, 1963 से जून, 1964 तक 106 और इशू किये जा चुके हैं। जुलाई, 1964 तक 44 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किये थे मगर जनवरी, 1963 से जून, 1964 तक 4 और दिये जा चुके हैं। इस का मतलब है कि हम इंडस्ट्री की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। जितने लाइसेंसिज हैं इन पर हमारी 5,249 लाख रुपये की टोटल इनवैस्टमेंट होगी, 360 लाख रूपया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वाली इंडस्ट्रीज पर होगी टोटल 5,609 लाख की इनवैस्टमेंट होगी जिन की सारी डिटेल्ज़ में मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता क्योंकि वक्त काफी दरकार है। अगर आप हमारे इस काम को देखें तो पता चलेगा कि इस सारी चीज़ पर पूरी तवज्जो दी गई है।

2.00 p.m.

**डिप्टी मपीवर :** बामरेड मागिब. उमीं बिठा टापीम रेर लवेंगे ?  
(How much more time would the hon. Chief Minister require ?)

**मुख्य मंत्री :** 20 मिनट।

**डिप्टी स्पीकर :** मद्रा से दूने धउम वर सिउ। (He may kindly finish his speech by 2.15 p.m.)

**मुख्य मंत्री :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज कर रहा था कि हम ने इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन कायम करने का फैसला किया है और उस का कैपिटल 7 करोड़ रुपया होगा। 31 जनवरी 1966 को इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन रजिस्टर कर दी गई है। उस के लिए 19 लाख 50 हजार रुपया करंट फिनांशल ईयर में प्रोवाईड करेंगे और 50 लाख रुपया नैक्स्ट फिनांशल ईयर में प्रोवाईड किया जाएगा ताकि इस से ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और फोर्थ प्लैन में इस के लिए 6 करोड़ 50 लाख का प्रोवीजन होगा। मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी मारफत यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारी फिनांशल कारपोरेशन है उस को भी हम और तकवीयत दे रहे हैं ताकि वह प्राइवेट सेक्टर में कुछ मदद दे सके शेयर्ज में। उस के लिए हम फोर्थ प्लान में 2 करोड़ 12 लाख रुपया प्रोवाईड कर रहे हैं। और इस नए माली चालू साल में 35 लाख रुपया उस के लिए देगे। जिला हिसार में पिग आयरन प्राजैक्ट की हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई है। उस के लिए 185 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई है। उस की एक लाख टन की ऐनुअल कपैसिटी होगी। उस से फाउंडरी इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचेगा। उस की तरफ पूरी तरह से तवज्जो होगी। मैं आपकी मारफत हाऊस में यह भी बताना चाहता हूं कि हम सीमलैस स्टील ट्यूब्स मिल लगा रहे हैं जिस पर कोई 9 करोड़ की ज्यादा से ज्यादा इन्वैस्टमेंट होगी, जिस में फिनांशल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन से एक करोड़ 45 लाख रुपए इन्वैस्ट होगी। इस की 72,000 टन पर ऐनम प्रोडक्शन होगी। उस को बहुत जल्द बनाना है। स्टील कास्टिंग्स की 6,000 टन पर ऐनम प्रोडक्शन होगी। पावर टिलर्ज की एक प्लैन है।

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** क्या गनौर में लगाएंगे ?

**मुख्य मंत्री :** उस के लिए 2 करोड़ रुपए की इन्वैस्टमेंट होगी। उस में से इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन की तरफ से 50 लाख रुपया दिया जाएगा। उसकी 12,000 पावर टिलर्ज पर ऐनम की कैपसिटी होगी। गवर्नमेंट आफ इंडिया की इस फैक्टरी को सैट अप करने की मन्जूरी मिल गई है। सारे टाईप के पावर टिलर्ज वगैरा जो चाहिए उन की इन्वैस्टीगेशन हो रही है। यह जल्दी से जल्दी लगाई जाएगी। स्टील फौरजिंग्स के सिलसिले में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की इन्वैस्टमेंट होगी। उस से 9,000 टन पर ऐनम प्रोडक्शन होगी। कन्सलटेंट्स एंवायंट कर दिए हैं। मशीन टूल्स पर एक करोड़ रुपया इन्वैस्ट होगा। उस से मशीन टूल्स की कोई एक करोड़ 50 लाख रुपए की प्रोडक्शन होगी। उस को भी हमारा लाइसेंस वगैरा मिल गया है। हैवी इलेक्ट्रीकल पर 13 करोड़ रुपए की इन्वैस्टमेंट होगी। जो जो भी जरूरी चीजें हैं हम बनाते आ रहे हैं। हम सारी चीज पर तवज्जो दे रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के साथ साथ में हाउस में यह कहना

चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से योगोसलाविया गवर्नमेंट के साथ डीज़ल इंजन फैक्टरी कायम करने के लिए बात चीत हो रही है ताकि डीज़ल इंजन और पंप बनाए जा सकें। यह रूपी बेसिज़ पर होगा, खर्च कितना कर रहे हैं। हम 10,000 डीज़ल इंजन देने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक वेनीर फैक्टरी लगा रहे हैं ताकि सफेस मैटीरियल चिप बोर्डज़ और प्लाई वुड के लिए तैयार हो सकें। हम वह फैक्टरी फारेस्ट एरिया में लगाने की कोशिश करेंगे, हमारी डिस्कशन हो रही है। यू.एस. एस. आर., गवर्नमेंट के साथ बसीह पैमाने पर हमारे यहां शूज़ की प्रोडक्शन करने के लिए हम बसीह पैमाने पर फैक्टरी लगाना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इस से फाइदा हो सकता है जिन्होंने लड़ाई के दौरान मदद की।

**कामरेड बाबू सिंघ मासटर :** आन ए पुआर्टिंट आफ आरडर, मैडम । डिप्टी सपीकर साहिबा, मैं अरज करदा हूं कि काल अटेंशन अउं ऐडजर्नमेंट मोशनज़ इस वासते तूल आउट कर दितीआं गਈआं सन कि इस ऐडरस उं इंडीविजुअल कपेसटी विच जे मैम्बर बोलें हन उनुं दा जवाब चीफ मनिस्टर साहिब वउं दिता जायेगा । पर एह टेप रिकार्ड वरगा लिखती भासन दिता जा रिहा है। जिनुं गलं दा जवाब देना है उह दिता जाटा चाहीदा है ।

**डिप्टी सपीकर :** इनुं केल दरखासत कर दिती है कि जवाब दे दिओ ।  
(I have requested the Chief Minister to give a reply to those points.)

**सरदार लडमन सिंघ गिल :** इनुं ने चुडीके की फरमाइआ सी कि टर्बेक्टरों दा कारधाना लगा रहे हूं, गालबन मोगा उहिमील विच लगाउठा है ।

**चीफ पारलीमेंटरी सैक्टर :** पावर टिलर ।

**मुख्य मंत्री :** मैं तफसील में नहीं जाना चाहता ।

**चौधरी देवी लाल :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । सरदार बाबू सिंह ने जो कहा था उस पर रुलिंग चाहिए । एडजर्नमेंट मोशनज़ और काल अटेंशन मोशनज़ इस बेसिज़ पे रिजैक्ट की जाती हैं कि गवर्नर एड्रेस पर बीलते हुए जो बातें कही गई हैं यह उनका जवाब देंगे । उन का जवाब देना लाज़मी है या नहीं ।

**उपाध्यक्ष :** मैं ने कह दिया है, उन को दरखास्त कर दी है । (I have already stated that the Chief Minister has been requested to reply to those points.)

**कामरेड समसेर सिंघ जेस :** आन ए पुआर्टिंट आफ आरडर, मैडम । कैरें मैमोरीअल डंड लटी 75,000 रुपिया उनुं दी कैबीनिट दे मंत्रीआं ने दिता है, उस दे बारे चीफ मनिस्टर साहिब पुजीशन साफ कर देन ।

**Deputy Speaker :** You should wind up within five minutes.

**मुख्य मंत्री :** यहां हरियाणा के बारे में कहा गया, सवाल उठाया गया। मैं डिटेल् में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि उस में फैसला इस तरह से कर रहे हैं कि हरियाणा की इकनामिक डिवैलपमेंट के लिए एक अलहदा पोर्टफोलियो होगा जो एक मिनिस्टर के चार्ज में होगा। एक सीनियर अफसर को इस बात के लिए मुकर्रर किया जाएगा ताकि हरियाणा डिवैलपमेंट कमेटी की जो हमारे सामने रिपोर्ट आई है उस इलाका की डिवैलपमेंट हो। जो भी पंजाब के रिसोर्सिज हैं उन की तरफ फोरी ध्यान दे सकें, इस चीज पर तवज्जो दे सके। मैं आपकी मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि यहां बहुत से भाइयों ने, किसी ने पंजाबी सूबा के हक में, किसी ने हरियाणा के हक में कई तरह के यहां सवाल उठाए हैं और दिलचस्पी ली है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपकी मारफत हाऊस से कहना चाहता हूं कि यह सवाल अगर तकरीरों से हल होना होता तो कभी का हल हो गया होता। तकरीरों से यह सवाल हल होने वाला नहीं है। एक दूसरे से अनप्रेज्यूडिस्ड हो कर, एक दूसरे के जज्बात को समझते हुए, एक दूसरे के जज्बात की कदर करनी होगी। मैं मानता हूं कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए और कोशिश है। पंजाब के हिंदू जाट, पंजाब के सिख जाट, अहीर, डोगरे और राजपूतों ने हिंदूस्तान की आजादी को कायम रखने के लिए अपना खून किस तरह से बहाया है। उन्होंने शहीदियां दी हैं। इस मुहब्बत को कायम रखा जाए। इस सारी चीज को गवर्नमेंट आफ इंडिया ओपन माइंड से कनसिडर कर रही है। पिछले दिनों गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र शस्त्र आने पर जो इमोशनल इंटेंगेशन पैदा हुई है मैं आशा रखता हूं उसे पूरी तरह कायम रखा जाएगा। मेरी खाहिश है कि पंजाब की जो पंजाबी भाषा है इसे जितनी भी तकमील दी जा सके, दी जाए और जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उस को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। जहां तक हरियाणा के दोस्तों का ताल्लुक है उन के जज्बात का भी पूरा खयाल रखा जाएगा। हमारे पंजाब की इकानोमी जो है यह एक बार गैटर हो चुकी है इस नुक्ता निगाह से भी सोचेंगे पंजाब के दरियाओं का पानी, इन से निकाली गई पावर का सिस्टम और पंजाब की धरती हमें फाड़ नहीं सकती। आज सारे पंजाब के अंदर 88 करोड़ की लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जिस में से 58 करोड़ की हिन्दी रिजन में है और 30 करोड़ की पंजाबी रिजन में है। इसी तरह 5½ करोड़ की स्मालस्केल इंडस्ट्री हिन्दी रिजन के अंदर है और बाकी पंजाबी रिजन में है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह ब्यास, रावी और सतलुज जिन के पानी से हरियाणा को सैराब किया जाता है और जहाँ से बिजली मिलती है उस से वह कैसे अलहदा हो सकते हैं। तो डिवैलपमेंट के नुक्तानिगाह से आप को सारी चीज पर ठण्डे दिल से गौर करना होगा। हमें आपस में बैठ कर एक कोअप्रेटिव हल सोचना होगा और एक दूसरे के जज्बात की कदर करनी होगी। इस वक़्त 24 लाख एकड़ ज़मीन पंजाबी रिजन के अंदर और 11 लाख एकड़ हिन्दी रिजन के अंदर वाटर-लार्गिंग का

शिकार हो गई हुई है। इस लिए सब चीज को देखना होगा। हम अगर सारी बैकग्राउंड को देखें तो पता चलता है कि पंजाब के अंदर हिन्दू, सिख और मुसलमानों ने हिन्दुस्तान की हमेशा राहनुमाई की है। उस को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया एक ऐसा फैसला देगी जो सब को हर नुकसानिगाह से सूट करे। जहां तक हिल्ली एरिया का सम्बंध है, उन की डिवैलपमेंट और सेंटीमेंट्स का ताल्लुक है उन को भी मद्देनजर रख कर पंजाब की री-आग्रेशनाइजेशन का फैसला होगा। हमारे पंजाब के जितने इलैक्टिड रिप्रजेंटेटिवज हैं उन का एक एक लफज पंजाब में आग लगा सकता है और एक एक लफज पंजाब को प्यार के झुले झूला सकता है। इस लिए आप सब साहिबान का एक एक लफज ऐसा होना चाहिए जो पंजाब में मुहब्बत की रौ पैदा करे। हमें अपने गुरुओं ने जो प्यार का रास्ता दिखाया है, हमारे वेदों और ग्रंथों ने जो अमृतपान दिया है उन के ऊपर अमल करते हुए फैसले करने होंगे। हमारे सब दोस्त बैठे हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए मिल कर काम किया है। इस लिए अब जब हिन्दुस्तान की नई रूप रेखा बन रही है तो उस में यह नहीं होना चाहिए कि चौधरी देवी लाल एक तरफ बैठे और वह भाई जिन्होंने इकट्ठे गुरु के बाग में लाठियां खाईं वह इस समय पर डिवाइड हो जाएं। हम सब को मिल कर मुहब्बत और प्यार को कायम रखते हुए जो चीज जरूरी है वह करनी चाहिए। चौधरी सर छोटू राम आखीर तक इस बात के लिए लड़े कि मैं ने पंजाब के सब जाटों को एक जगह रखना है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम सर छोटू राम के नकशे कदम पर चलेंगे लेकिन जब अब अमली तौर पर उन की पैरवी करने का वक्त आता है तो उस में कुछ और सोचना ठीक नहीं। इस लिए सारे हालात को देखते हुए आगे चलना होगा।

इस के अलावा यहां पर गवर्नमेंट मुलाजमों के बारे में सवाल उठाया गया कि उन की तनखाहे बढ़ानी चाहिए। मुझे उन के साथ पूरी तरह से हमदर्दी है। लेकिन मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन की अगर आप सारी तफसील देखेंगे तो पोजीशन का पता चलेगा 11 दिसम्बर, 1956 को गवर्नमेंट सर्वेंट्स का नम्बर 1,29,295 था जो कि जून, 1958 को बढ़ कर 1,68,415 हुआ। उस के बाद 31 मार्च, 1962 को 2,46,669 हो गया। 1956 से ले कर 1964 तक 106 प्रतिशत के करीब गवर्नमेंट सर्वेंट्स की नफरी बढ़ी है। (विष्णु)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਠ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ,। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ (\* \* \* \*) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

\*Note: Expunged as ordered by the Chair.

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਉ। (If Sardar Gurcharan Singh has used these words, he may please withdraw them.)

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।

**ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

**ਮੁਲਕ ਮੰਤਰੀ :** ਜਹਾਂ ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਇਨਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਆਪ ਕੋ ਸਬ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿਡਿਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਪੈਂਸੂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਆਰ ਫ੍ਰਸਰੀ ਬਾਤਾਂ ਆਈ ਹੈਂ ਜਨਰਲ ਏਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਜਬ ਮੁਝੇ ਬਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤਨਕਾ ਜਕਾਕ ਫ੍ਰਾਂਗਾ। ਏਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕੀ ਮਾਰਫਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਭਾਈਓਂ ਸੇ, ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪੋ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤਿਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਏ ਆਰ ਇਸ ਕੋ ਆਗੇ ਬਢਾਏ। ਧਰੁ ਜੋ ਸਿਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਰਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤਸੇ ਸਾਰਾ ਹਾਤਸ ਇਨਤਫਾਕ ਰਾਏ ਸੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। (ਤਾਲਿਆਂ)

**ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ :** ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪਰ ਭੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲ ਦੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਨੇ ਕੌਂਸਿਲ ਸੇ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਕੇ ਪਹਲੇ ਸਾਲ ਸੇਂ ਤੋਂ ਵਹਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

**ਮੁਲਕ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋ ਸਟ੍ਰੇਨਜ਼ਰ ਰਖਤੇ ਹੁਏ ਜੋ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਝਰੂਰ ਕਰੇਗੇ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ :** ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦਿਉ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ :** ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਤਾਇਤੀ ਲੋਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸੂਚ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾ ਇਕੋ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ..... [ਸ਼ੋਰ].....

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੂਚ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?

[ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ।]

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ:** ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਦਨ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । (If the hon. Members continue doing like this, then I may make it clear to them that the sitting will last till this motion is put to the vote of the House.)

**ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ:** ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼:** ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

**ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ:** ਜੇਕਰ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

**Deputy Speaker :** Now, I will put the amendments to the vote of the House, one by one.

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that no mention has been made—

- (1) of the necessity of introducing prohibition in the State;
- (2) of Land Reforms which was essential for increasing agricultural production and bringing about social injustice;
- (3) of rural industrialisation which was essential for rural development;
- (4) of the unirrigated and drought hit hilly areas of Tehsil Una, Hamirpur equally with the other drought hit Districts as regards relief measures; and
- (5) of the steps to be taken to provide irrigation facilities to the hilly areas particularly Tehsil Una.”

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end namely,—

“but regret—

- (1) that the cent per cent hilly area of Thana Hajipur (District Hoshiarpur) has been excluded from the purview of the Committee appointed under the Chairmanship of the Financial Commissioner (Revenue) to suggest permanent measures to tackle the drought problem in certain areas of the State, including Una Tehsil to which it is contiguous;

[ Deputy Speaker ]

- (2) that the address makes no mention of any steps intended to be taken to redress the imbalance in the matter of Tube-well connections which have not been given at all in areas like Mukerian and Hajipur Blocks so far;
- (3) that no scheme for the upgrading of such Government primary middle schools where the Panchayats have put up the necessary buildings and are prepared to pay the cash amounts prescribed for the purpose has been outlined in the Address;
- (4) that no indication has been given in the Address as to the period during which the Datarpur area Water-Supply Scheme and the Kumahi Devi Area (Hajipur Block) Water-Supply Scheme are to be implemented; and
- (5) that no mention has been made in the Address of the spurs so badly needed to save villages, lying on the banks of River Beas on Mukerian-Mirthal side, from the depredations of floods in that River."

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—  
“but regret that no mention is made for the revival of the Salt Industry of Gurgaon District and to give fore-most priority to supply the electric power as promised by the Government in 1953 and supply fresh drinking water to all such villages and towns where there is salt water.”

*The motion was lost*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—  
“but regret that no mention has been made—

- (1) for the cancellation of lease of Birla Brothers land;
- (2) to protect the rights of Scheduled Castes employees specially serving in Punjab State Electricity Board, Agriculture University, Punjab University, Punjabi University and Kurukshetra University with regard to reservation in promotions;
- (3) regarding allotment of all Government land to the landless people; and
- (4) for the allocation of 1/4th of the yearly Budget for the uplift of the Scheduled Castes and other Backward Classes.”

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—  
“but regret that no mention has been made—

- (1) to check the growing unemployment in the State ;
- (2) of transforming of the present capitalistic social set up into socialistic pattern; and
- (3) of the new excise policy set by the State Government."

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that—

- (1) no promise has been held out to cancel lease of land to Birla Brothers in the Sutlej Bed in deference to the public opinion;
- (2) no mention has been made of acceding to popular demand for release of detenue;
- (3) full cognizance has not been taken of the damage caused to the agriculture by prolonged drought and no measures have been annouced for stepping up irrigation;
- (4) no steps have been taken indicated to meet the demands of the government employees;
- (5) no mention has been made to check the growing unemployment in the State; and
- (6) no mention has been made regarding the allotment of surplus land as well as government lands to the tiller in order to increase the agricultural production."

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that nothing has been said—

- (1) for allocating 60 per cent of the total Budget for the development of Haryana and Hilly areas;
- (2) for abolishing the Food Zones to better the lot of Farmers and to give a fillip to move production of foodgrains;
- (3) regarding taking concrete steps to rehabilitate the War hit economy of the State;
- (4) to fulfil the promises made by the Government of and on to grant ample loans for Industry and to give relief in taxation in border industry; and
- (5) to dissolve the deed made by the Government with Birlas to lease them 1,000 acres of reclaimed land against the interest of petty farmers and landless Harijans."

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that—

- (1) the Address makes no mention of any steps intended to be taken to provide irrigation by setting up Government tube-wells or from Bhakhra Canal or by constructing Dams at the heads of rainy rivulets in Ambala and Hoshiarpur Districts. This matter assumes grave importance because 88 % areas of these districts are un-irrigated;
- (2) the Address takes no notice of strong public opinion against the Birla land lease and also fails to mention the reasons for imposition of section 144 around Assembly and Secretariat;
- (3) the Address fails to mention inordinate delay in distribution of rehabilitation loans amongst unemployed workers during Pakistan-India conflict and also fails to mention the failure of the Government to stop large-scale retrenchment of workers all over the State;
- (4) the Address fails to mention any steps taken to set up Hydel Power Plant at Rupar on Bhakra Canal; and
- (5) the Address fails to mention the reasons as to why Hilly area allowance is not given to Government employees of Rupar and Majri Blocks of Ambala District.”

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that no mention has been made—

- (1) regarding supply of electric material and not supply of electric connection to hundred of Tube-wells for short of material in entire Gurgaon District;
- (2) regarding industrialisation of Palwal area for Co-operative Sugar or Spinning Mills which are proposed to be set up in other parts of the State;
- (3) to provide better class of Buses to avoid frequent break down; and
- (4) regarding removal of disparity of water rates of upper Agra Canal in Gurgaon District.”

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely—

“but regret—

- (1) that no mention has been made to provide village road in backward area of Palwal and Ballabgarh Tehsils; and
- (2) that no assurance has been given to provide means to check unemployment.”

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

“but regret that no mention has been made about the development of the erstwhile Pepsu area.”

*The motion was lost.*

**Deputy Speaker:** Question is—

That an Address be presented to the Governor in the following terms:—

“That the members of the Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of the State Legislature assembled together on the 14th February, 1966.”

(After ascertaining the votes of the Members by voices, Deputy Speaker said “I think the Ayes have it.” This opinion was challenged and division was claimed. Deputy Speaker after calling upon those Members who were for “Aye” and those who were for “No.”, respectively, to rise in their places and on a count having been taken, declared that the motion was carried.)

*The motion was declared carried.*

**Deputy Speaker:** The House stands adjourned till 11.00 a. m. tomorrow.

2.30 p. m.

(The Sabha then adjourned till 11 a. m. on Thursday, the 24th February, 1966.)



## APPENDIX

TO

**Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 6, dated the  
23rd February, 1966.**

*[For Starred Question No. 9102 and reply thereto please see page (6) 12 ante]*

Statement containing information required by parts (a) and (b) of Starred Vidhan Sabha Question No. 9102 regarding names of Nursery trained female teachers with their present places of posting in respect of Gurdaspur, Jullundur and Ferozepur districts.

**(a) Jullundur :**

Shrimati Raksha Khosla, Government Primary School,  
Bhaura.

Shrimati Kamla Devi, Government Higher Secondary  
School, Phillaur.

Shrimati Ramesh Kumari, Government Primary  
School, Thabalke.

**(b) Gurdaspur :**

Shrimati Sudesh Bakshi, Government High School,  
Kalanaur.

**(c) Ferozepur :**

Shrimati Surjit Kaur, Teacher, Government Middle  
School, Singhanwala.

Shrimati Shashi Bala, Teacher, Government Primary  
School, Fazilka No. 3.

Shrimati Gurbans Kaur, Teacher, Government Primary  
School, Phullanwala.

**(b) No representation was received from these teachers.**

---





© (1968)

Published under the Authority of the Punjab,  
Vidhan Sabha and Printed by the Controller,  
Printing & Stationery, Punjab, at the Govt. Press,  
Patiala.

# Punjab Vidhan Sabha Debates

24th February, 1966

Vol. I—No. 7

## OFFICIAL REPORT



### CONTENTS

Thursday, the 24th February, 1966

	PAGES
Absence of the Speaker	... (7)1
Starred Questions and Answers	.. (7)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	.. (7)21
Unstarred Questions and Answers	.. (7)59
Adjournment Motions	... (7)60
Statement by the Education Minister	.. (7)65
Papers laid on the Table	.. (7)65
Statement by the Transport and Elections Minister	.. (7)65
Resolution re. Development of Hilly Areas and the Hariana Area of the State	.. (7)66
Bill (Already introduced)— Punjab University (Amendment)— 1965	.. (7)87—94



**ERRATA**  
TO  
**PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I—No. 7,**  
**DATED THE 24TH FEBRUARY, 1966**

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
उपाध्यक्षा	*पाध्यक्ष	(7) 10	1
पालियामेंटरी	पालियानेंटरी	(7) 15	20
पंडित चिरंजी लाल शर्मा	पंडित चिरंजी लाल शर्मा	(7) 18	Last but one
Shri Balramji Dass Tandon	— Balramji Dass Tandon	(7) 20	2
Shri Ram Partap Garg	4, Ram Partap Garg	(7) 20	15
Kg.	Dg.	(7) 35	5 from below
vij	viz	(7) 36	7 and 3 from below
Comrade Bhan Singh Bhaura	Comrade Bhan Singh Baura	(7) 48	1
the	ihe	(7) 51	12 from below
reasons	rea ons	(7) 54	21
कामरेड राम चन्द्र	कामरेड राम चन्द्	(7) 69	10
मुल्क	मुलल्क	(7) 69	22
संस्थाएं	संस्थएं	(7) 73	18
ज़िले के	जिले की	(7) 73	21
speech	speach	(7) 76	11
टंडन	टडन	(7) 77	8
दो	ो	(7) 78	12
ट्यूबवैल	यूबवैल	(7) 85	23
रहम करें	रहम बरपा करें	(7) 85	Last but one
देशों	शों	(7) 86	10 from below
धेउत	धउत	(7) 90	25
ਉਠ੍ਹਾਂ	ਉਠ੍ਹ	(7) 91	5
Whether	hether	(7) 92	13 from below

ga

a  
f

## PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 24th February, 1966

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh at 11.00 a.m. of the clock.

### Absence of the Speaker

**Secretary:** I have to inform the House that Mr. Speaker is unavoidably absent at the present moment. The Deputy Speaker will, therefore, take the Chair.

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair).

### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS \*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 8924

**श्री बलरामजी दास टण्डन :** क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1961 में स्टेट कांग्रेस की जो कोऑर्डिनेशन और कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उस के अन्दर तै हुआ था कि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को बोनस दिया जाए या नहीं ?

**परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री :** मैं तो उस वक्त विधान सभा का स्पीकर था। उस वक्त पार्टी लैवल पर मीटिंग हुई होगी और उस मीटिंग को नान-आफीशल मीटिंग समझा जाना चाहिए। लेकिन इस के बारे में मैं सारी पोजीशन वाजेह कर दूँ। मैं किसी बात को छुपाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस में छुपाने वाली बात भी कोई नहीं है।

जब मैं ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बना तो उस के बाद ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की यूनियन के साथ कुछ बातें हुईं। उन बातों में बोनस का भी जिक्र आया था। मेरा निजी ख्याल है कि उन्हें बोनस दे देना चाहिए। इस विषय में दो बार मीटिंगें भी हुईं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि उनको बोनस देने में सरकार को कोई एतराज नहीं है। जब बोनस एक्ट को देखा तो वह एक्ट स्टेट अंडरटेकिंग पर एप्लाइ नहीं होता था। उस के बाद सारा केस एग्जामिन करवाया गया। मैं तो इस ख्याल का था कि इस केस को बहुत ही जल्दी डिसाइड किया जाए। पेमेंट आफ बोनस एक्ट, 1965 की धारा 32 की क्लॉज 4 है जिसने हमारे रास्ते में काफ़ी मुश्किलें पैदा की हैं। इस एक्ट के अंदर दो चीजें हैं। एक वह है जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बसें रन की जाती हैं, जैसा कि पंजाब रोडवेज है और दूसरी इंडीपेंडेंट है जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग बाडी है। वह अटानोमस बाडी है। वहां पर कम्पीटेशन है। जहां तक कारपोरेशन का सम्बन्ध है उस को मुसतसना करार दे सकते हैं। लेकिन जहां तक डिपार्टमेंट के द्वारा रन

\*Note:—Starred question No. 8924 and reply thereto appear in the Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. No. 4, dated 21st February, 1966.

[परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री]

की जाती है, वह इस ऐक्ट के रू में नहीं आता है। इस ऐक्ट की सैक्शन 32(4) और 20 लागू होती हैं। अगर आप चाहें तो सैक्शन 32(4) पढ़ देता हूँ:—

Section 32 (iv) of the Payment of Bonus Act, 1965, reads—

“Nothing in this Act shall apply to—

(iv) employees employed in an establishment engaged in any industry carried on by or under the authority of any department of the Central Government or a State Government or a local authority.”

इस के बारे में पोजीशन यह थी कि 1959 में फैसला किया गया था कि उन को 1 प्रतिशत इंसेंटिव ग्रंट के तौर पर दिया जाए। इस तरह 70 प्रतिशत स्टाफ को फायदा हुआ था। मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि उस वक्त यह बोनस ऐक्ट नहीं आया था लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने फैसला किया। इस तरह से हर साल उन को इनसेंटिव दिया गया। वह फिगर यह हैं:—

	रुपए
1960-61	.. 1 लाख
1961-62	.. 1,18 हजार
1962-63	.. 1,21 हजार और
1963-64	.. 1,15 हजार

लेकिन 1964-65 में कुछ ऐसी बात हो गई थी जिस से हम उन को इंसेंटिव नहीं दे सके। (विधन)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप को मालूम ही है कि मैं कभी भी इस हाउस में मिस नहीं होता लेकिन उस दिन, पार्लियामेंट की सूबे के बारे में एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, उन्होंने हमें टैलीग्राफिकली बुलाया था और वहां पर जाना भी जरूरी था। इसके सिवाए कोई रास्ता हमारे सामने नहीं था। अब मैं कारपोरेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। उन को इस ऐक्ट की धारा 20 लागू होती है।

The Pepsu Road Transport Corporation, have, however, paid interim bonus of Rs 1.54 lakhs to its employees for the year 1961-62.

1962-63 और 1963-64 में भी यही पोजीशन थी।

It has been advised that the employees of the Pepsu Road Transport Corporation, are covered by the Act, section 20 which reads as under:—

“20. Application of Act to establishments in public sector in certain cases:—

(1) If in any accounting year an establishment in public sector sells any goods produced or manufactured by it or renders any services in competition with an establishment in private sector, and the income from such sale or services or both is not less than twenty per cent of the gross income of the establishment in public sector for that year, then, the provisions of this Act shall apply in relation to such establishment in public sector as they apply in relation to a like establishment in private sector.

(2) An establishment in public sector to which this Act applies shall continue to be governed by this Act notwithstanding that in any subsequent accounting year its income from the sale of goods produced or manufactured by it or from services rendered or from both, in competition with an establishment in private sector, falls below twenty per cent of its gross income for that accounting year.”

इस के बारे में लीगल ओपीनियन ली गई। मेरा ख्याल था कि लीगल ओपीनियन डिपार्टमेंट को कवर करेगी लेकिन पता चला कि पंजाब रोडवेज एम्पलाइज सैक्शन 32(4) के नीचे और कारपोरेशन क्लाज 20 के नीचे कवर होते हैं। इस तरह से हमें बोनस देने में मुश्किल पेश आई। यह एकट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यह एकट पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने उन वर्कर्स को इन्सैंटिव देना है चाहे यह बोनस वगैरा की शकल में हो हम तो चाहते हैं कि वर्कर्स की तसल्ली हो जाए। अगर वह खुश हो जाएं तो हमें और ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है।

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। एक सवाल के जवाब में दस मिनट लग गए हैं, कुछ समय में नहीं आता कि किस तरह से काम चलेगा।

**उपाध्यक्ष :** मुझे आपने मौका ही नहीं दिया। मैं भी कहने ही वाली थी। टंडन साहिब को रूलज की कापी दे देते वे खुद ही पढ़ लेते।  
(The hon. Member did not give me the opportunity to speak. I was also going to point out this. If Shri Tandon had been provided with a copy of these rules he would have himself read them.)

**मंत्री :** डिप्टी स्पीकर साहिब, मैंने तो पहले पूछ लिया था कि अगर कहीं तो मैं पढ़ दूँ।

**श्री बलरमजी दास टण्डन :** क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने ने पठानकोट में बोलते हुए कहा था और पहले भी यह बात प्रेस के अन्दर आई थी कि स्टेट गवर्नमेंट की तो खाहिश देने की है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, इस में कहां तक सच्चाई है ?

**मंत्री :** हर अखबार अपनी मर्जी से खबर दे देती है। हमारे पास दस बारह अखबारें आती हैं और हर अखबार अपने ढंग से ही खबर देती है। मैंने तो पहले भी यह बात कही थी कि हमारी खाहिश है और यह बात हाउस के रिकार्ड पर भी आ चुकी है। लीगल ओपीनियन लेने के बाद हम परसनल लैवल पर बात को डिसाईड कर रहे हैं। इन्टैरिम अरेंजमेंट के तौर पर इन्सैंटिव दे रहे हैं। उसके बाद उन का जवाब आ जाने पर हम बोनस दे देंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** क्या मिनिस्टर साहिब बताएं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबर मिनिस्टरी की तरफ से पंजाब सरकार को कोई लैटर आई है कि जहां पर पब्लिक अंडरटेकिंग है यह एकट लागू नहीं होता वहां पर एक्सप्रेसिया के तौर पर इन्सैंटिव दे देना चाहिये।

**मंत्री :** उन्होंने ने मश्वरा दिया था और मैंने मान लिया है। लेकिन हम तो इन्सैंटिव दे ही रहे हैं।

*\*Supplementaries to Starred Question No. 8926.*

**श्री बलराम जी दास टण्डन :** ब्यास नदी पर पुल बनाने के सिलसिले में मन्त्री महोदय ने बताया है एप्रोच रोड नम्बर 1 भी मुकम्मल हो गई, रोड नम्बर 2 भी मुकम्मल हो गई रोड नम्बर 3 मुकम्मल हो गई और इसी तरह से रोड नम्बर चार भी मुकम्मल हो गई है। क्या तफसीलन वे बताएंगे कि कोन सी रोड्ज मुकम्मल हो गई हैं और उन का इस बात से क्या ताल्लुक है ?

**लोक कर्म मंत्री :** मुझे मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य ने कैसे समझ लिया है कि रोड्ज मुकम्मल हो गई हैं। जो काम उन को दिया गया था वह मुकम्मल हो गया है। उनकी जानकारी के लिये अर्ज कर दूं कि काम था मिट्टी डालने का। वह काम पूरा हो गया है इस से ज्यादा और कोई काम नहीं था।

**श्री बलरामजी दास टण्डन :** पहले दिन जवाब देते हुए चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी ने बताया था कि जो मेन ब्रिज है उस को कम्पलीट करने का तीन साल का एग्रीमेंट है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह एग्रीमेंट कब हुआ और तीन साल का अर्सा कब पूरा होता है ? इन दी मीन टाईम जो काम शुरू हुआ है उस की लीगल पोजीशन क्या है जो कि एग्रीमेंट होने से पहले हो चुका है ?

**मंत्री :** जहां तक पुल बनाने का ताल्लुक है वह एक कम्पनी को दिया गया है। काम के ठेके का रुपया 79 लाख 50 हजार बनता है। कूएं गालने व पीलपाए बनाने का काम लगभग 50 फीसदी पूरा हो चुका है। जहां तक एग्रीमेंट पर दस्तखत करने का ताल्लुक है कुछ शर्तें पत्र व्यवहार में सरकार ने मानी हुई हैं, कुछ ठेकेदार ने मानी हुई हैं। कानूनी तौर पर एग्रीमेंट की डीटेल्ज क्या होनी चाहिए उस के लिये एल.आर. (कानूनी मंशीर) के पास महकमा जाता है। जब कानूनी तौर पर सलाह मिल जाती है कि दस्तखत हों तो ठेकेदार से दस्तखत करवा लेते हैं। यह काम जो था यह तेजी से और वक्त के मुताबिक पूरा करना था। अगर हम एग्रीमेंट की इन्तज़ार करते रहते तो काम पूरा न हो पाता। जहां तक इस काम यानी कूएं गालने और पीलपाए (piers) बनाने के काम के मुकम्मल होने का ताल्लुक है वह जून, 1966 तक होगा। जब बरसात आ जाती है काम होना बन्द हो जाता है। बाकी काम बरसात के बाद होता है।

**श्रीमती सरला देवी शर्मा :** जब कभी ठेका दिया जाता है तो एग्रीमेंट पहले ही हो जाया करता है लेकिन इस केस में कौनसी कम्पलीकेशनज़ पैदा हो गई थीं कि एल. आर. के पास जाना पड़ा ?

**मंत्री :** यह तो माननीय सदस्या की सुचना है, मेरी नहीं है।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤਗੋ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਐਲ. ਆਰ. ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

**मंत्री :** दरअसल कूएं गालने और पीलपाए (piers) बनाने का काम 55 फीसदी पूरा हो चुका है। मैं अभी नहीं बता सकता कि कितना पैसा दिया जा चुका है। उस के लिये समय चाहिये। एक बात मैं कह सकता हूं कि जब ठेका मान लिया जाता है तो 1 फीसदी ठेकेदार

से अरनेस्ट मनी ले ली जाती है। उस के बाद जितना काम कर दिया जाता है अरनेस्ट मनी शामिल कर के उस का पांच फीसदी तक रखते जाते हैं।

**श्री फतेह चंद विज :** मन्त्री साहिब ने फरमाया है कि मिट्टी डाल दी गई है। मैं पूछता हूं कि मिट्टी डालने से उन का यह मतलब तो नहीं है कि जो काम उन्होंने ने वहां पर नाजायज किये हैं उन को खत्म कर दिया गया है?

**मन्त्री :** जैसे मानयोग सदस्य ने कहा ऐसी बात नहीं है। सड़कें बनाने के लिये पहले मिट्टी डालनी पड़ती है, मिट्टी को दबाना पड़ता है फिर ईटें डाली जाती हैं, तारकोल पड़ता है और फिर रोलर चलाया जाता है फिर जा कर सड़क मुकम्मल होती है।

( श्री बलरामजी दास टण्डन प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहते थे लेकिन चेयर द्वारा इजाजत नहीं दी जा रही थी। )

**श्री बलरामजी दास टण्डन :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। वह हमें मिसलीडिंग रिप्लाइज दे रहे हैं। आप मेरी बात को सुन लें।

**Deputy Speaker:** Mr. Tandon, I request you to please resume your seat.

**श्री बलराम जी दास टण्डन :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह मिसलीडिंग रिप्लाइज दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आधा काम हो गया है और मैं कहता हूं कि अभी तो कूएं ही आधे बने हैं और आधा ब्रिज कैसे बन गया।

**उपाध्यक्ष :** टण्डन साहिब, यह मुनासिब मालूम नहीं देता कि चेयर के मना करने के बावजूद आप इस तरह से खड़े हो कर अपनी बात कहते जाएं। यह मुनासिब नहीं।

(Addressing Shri Balramji Das Tandon) (It does not look proper for the hon. Member to rise time and again and in this way go on pressing his point in total disregard of the order of the Chair.) (Interruption)

You are an honourable Member of this august House and a known Parliamentarian. Please resume your seat.

**मन्त्री :** उपाध्यक्ष महोदया यह मानयोग सदस्य की समझ का फर्क है.... (शोर)

**उपाध्यक्ष :** मैं ने आप को काल अपान नहीं किया। आप बगैर मेरे कहे क्यों इस तरह से खड़े हो रहे हैं? इस का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं (विघ्न) आर्डर प्लीज। नैक्स्ट क्वेश्चन। (I have not called upon him. Why is he getting up without my permission? There is no need to reply to this question. (Interruption) Order please. Next question.)

#### Construction of approach and village roads in the State

\*8910. **Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the mileage of approach and village roads, separately, constructed during 1963-65, 1964-65 and 1965-66 (to-date) in the State, district-wise?

**Chaudhri Ranbir Singh:** A statement is placed on the Table.

**STATEMENT**

**Mileage of Approach and Village Road constructed during 1963-64, 1964-65 and 1965-66**

(Length in miles)

Serial	District	1963-64		1964-65		1965-66	
		Approach Road	Village Road	Approach Road	Village Road	Approach Road	Village Road
1	Ambala ..	0.15	..	..	..	..	..
2	Ludhiana ..	1.25	..	..	..	1.00	..
3	Sangrur ..	0.18	..	2.16	..	..	..
4	Simla ..	..	..	0.54	..	..	..
5	Ferozepur ..	..	..	1.00	..	1.00	..
6	Jullundur ..	1.75	..	5.70	..	2.25	..
7	Karnal ..	0.25	..	..	..	..	..
8	Patiala ..	..	0.12	..	..	..	..
9	Gurdaspur ..	2.25	..	2.33	..	..	..
10	Hoshiarpur ..	..	..	..	..	1.00	..
11	Bhatinda ..	..	..	..	..	0.30	..
12	Amritsar ..	..	..	..	..	0.25	..
Total ..		5.83	0.12	11.73	..	5.80	..

Total Approach Roads .. 23.36 Miles

Total Village Roads .. 0.12 Miles

**Shri Rup Singh Phul:** From the statement supplied to me, I find that in the matter of construction of approach and village roads during 1963-64, 1964-65 and 1965-66, the district of Kangra is conspicuous by its absence. May I know the reasons for the relegation of this district to such a position in this connection?

**मंत्री :** उपाध्यक्ष महोदया, यह जो पूछा गया है इसके लिये तो समय अपेक्षित है कि कांगड़ा क्यों उसमें नहीं आया। हाँ, एक बात कह सकता हूँ कि उसमें दो योजनाओं का जिक्र है। एक योजना पर काम तब चालू होता है जब लोग पच्चीस फीसदी हिस्सा दे देते हैं। हो सकता है कि पच्चीस फीसदी हिस्सा कांगड़ा वालों ने न दिया हो। दूसरी योजना पर कांगड़ा

में काम क्यों चालू नहीं हुआ उसके लिये मैं अफसोस ही कर सकता हूं और बाकी जवाब मेरे पास कोई नहीं ।

**श्री रूप सिंह फूल :** क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि इस लिहाज़ से कि ज़िला कांगड़ा की सारी स्टेट के अन्दर पर कैपिटल इन्कम लोएस्ट है, क्या सरकार उस ज़िला के लिये इस पच्चीस फीसदी की जो शर्त है उसे रीलेक्स करने के लिये तैयार है जहां तक कि विलेज रोडज़ और ऐप्रोच रोडज़ की कन्स्ट्रक्शन का ताल्लुक है ?

**मंत्री :** उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैं ने ज़िक्र किया इस सवाल में दो योजनाओं का ज़िक्र है। एक योजना के तहत हिस्सा लिया जाता है और दूसरी योजना के अनुसार सरकार सौ फीसदी काम खुद करती है। मैं ने इस से इनकार नहीं किया कि दूसरी योजना के तहत ज़िला कांगड़ा में काम नहीं होगा। दूसरी योजना के तहत काम हो सकता है लेकिन क्यों नहीं हुआ इसका जवाब मेरे पास इस वक्त नहीं है।

**पंडित लाल चन्द प्रार्थी :** क्या मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि ऐसी कोई इन्स्टांसिज़ आप के नोटिस में आई हैं जहां पर सड़क बनाने के लिये कहा गया हो और पच्चीस फीसदी रुपया लोगों ने न दिया हो ?

**मंत्री :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो एक ही बात कह सकता हूं। अगर यह पूछें कि उस ज़िला से कोई पैसा आया है या नहीं, वह तो मैं बता सकता हूं। इस के अलावा और कोई बात इस से पैदा नहीं होती।

**श्री अमर सिंह :** क्या लोक कर्म मन्त्री कृपा करके बताएंगे कि जो स्टेटमेंट हाउस में दी गई है उसमें डिस्ट्रिक्ट हिसार का कोई ज़िक्र है जब कि सारे सूबा की एप्रोच रोडज़ और विलेज रोडज़ की बाबत पूछा गया है। क्या यह बता सकते हैं कि हिसार जब कि कपूरथला से पांच गुना है वहां पर विलेज रोडज़ क्यों नहीं बनाई गई, इसका क्या कारण है ?

**मंत्री :** हो सकता है कि पिछले पांच सालों में वहां पर ज्यादा काम हो गया हो। बाकी मानयोग सदस्य अगर इस के बारे में अलग प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दे दिया जाएगा।

**उपाध्यक्षा :** आप को वेग जवाब नहीं देने चाहिए कि "हो सकता है" आप डेफ़ीनेट जवाब दें। हो सकता है तो हां कहें और अगर नहीं हो सकता तो साफ बता दें।  
(The hon. Minister should avoid replying vaguely. He should give a definite reply in the affirmative if this can be accomplished. If it is not possible he may straightaway say so.)

**मंत्री :** उपाध्यक्ष महोदया, सरकार की तरफ से जवाब देने की ज़िम्मेदारी मेरी है। जो जवाब मैं ने दिया है वह सही है। आप को अधिकार है कि अगर उसमें कोई ग़लती हो काट सकती है।

**उपाध्यक्षा :** यह मेरा काम है देखना कि जो सप्लीमेंटरी किया गया है वह सही किया गया कि नहीं या कि जो जवाब दिया गया है वह सही है कि नहीं। "हो सकता है" वाली बात मत कीजिए और साफ साफ जवाब दीजिए।

[उपाध्यक्षा]

(This is my job to see whether a supplementary is proper or otherwise also whether the reply given is correct or not. He should give a definite reply and avoid vagueness saying that it may be so.)

**मंत्री :** मैं जो जवाब दे सकता था वह दे दिया।

**डॉक्टर बलदेव प्रकाश :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। अभी अभी आनरेबल मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि सरकार की तरफ से जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है और यह कि हाउस के अन्दर जैसा चाहें जवाब दें। मैं आप से इस बात की रूनिंग चाहता हूँ कि सवाल की या जवाब की रैलेवेंसी को जज करना चेयर की अथारिटी है या कि नहीं। जब कोई इर्रे-लेवेंट जवाब दे रहा हो उस को रोकना चेयर की अथारिटी है या कि बूड बी हरियाणा प्रांत के बूड बी चीफ मिनिस्टर ने यह अथारिटी अपने पास रख ली है?

(इस समय सरदार लक्खी सिंह चौधरी अपनी सीट पर कुछ कहने के लिए उठे)

**सरदार गुरचरन सिंघ :** बहि जा उछे पैराटरूपर।

**टर्गसपेरेटर अउं चोन् मंत्री :** आन ऐ पुआइंट आफ आरडर, मैडम। मैडम सभर दों हद हों गਈ है। एह एंस उरुं दी "बूड बी चीफ मिनिस्टर" वगैरा दीआं गल्लं करके साठुं आपस विच झगड़ा रहे हन, लड़ा रहे हन; एह माझी गल्ल है। (Laughter)

**सरदार लक्ष्मी सिंघ चौधरी :** की वजीर साहिब दसठगे कि पिछले दों सालां विच नलंघर विच 7.95 मील सड़क बनी है और कपूरथले विच नही बनी। की एंस दा एह कारन है कि उधें दे मिनिस्टर बगुते हन?

**लोक कर्म मंत्री :** जवाब तो तथ्यों की बिना पर दिया जाता है और जो सच्चाई है वह मैं ने कह दी है।

**चौधरी डेवी लाल :** डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरा सप्लीमेंटरी सवाल पहले था लेकिन बीच में कुछ आपस में झगड़ा शुरू हो गया। आनरेबल मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया है कि पिछले पांच साल कपूरथला में ज्यादा खर्च हुआ है और हिसार में कम। क्या आप यह बताएंगे कि जब से आप मिनिस्टर बने हैं उसके बाद इधर ही ज्यादा खर्च हुआ है और क्या वह यह बताएंगे कि पिछले सालों में पंजाबी रिजन में जो सड़कों पर ज्यादा खर्च हुआ उस से इधर जो कमी रह गई है वह उस कमी को अपने अहद में पूरा कर देंगे?

**मंत्री :** कोशिश जरूर की जा रही है और की जाएगी।

**श्री फतेह चन्द बिज :** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो पंचायतें एप्रोच रोड्स के लिये या विलेज रोड्स के लिये लिख दें कि वह पच्चीस फीसदी रुपया देने के लिये तैयार है क्या उन की डिमांड पर वह गौर करेंगे और क्या वहां पर आप सड़कें बना देंगे?

**मंत्री :** जहां तक लिखने का ताल्लुक है उसके ऊपर तो कागजी कार्यवाही ही हो सकती है। अगर रुपया दाखिल कर देंगे तो अमली कार्यवाही हो सकती है।

#### Opening of New construction or Mechanical Divisions

\*8991. **Shri Rup Singh Phul:** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Government is considering any proposal to

open any new Construction or Mechanical Divisions or Sub-Divisions (B&R) in the State; if so, the number thereof and the names of the places where these are likely to be located?

**Chaudhri Ranbir Singh:** No such proposal is under consideration at present.

**श्री रूप सिंह फूल :** क्या वजीर साहिब के इल्म में यह बात है कि जिला कांगड़ा के लोगों ने एक अर्जदास्त भेजी जिस में कहा गया था कि रोड कंस्ट्रक्शन के काम को ऐक्सपीडाइट करने के लिये वहां पर मैकैनीकल डिवीज़न्ज़ जारी करना बहुत जरूरी है? क्या उस पर गौर किया गया है या नहीं?

**मंत्री :** सड़क बनाने के लिये जितनी कार्यवाही की आवश्यकता होगी महकमा उस कार्रवाई को जरूर करेगा।

**श्री रूप सिंह फूल :** क्या वजीर साहिब यह फरमाएंगे कि जब कभी भी कोई वजीर वहां पर जाता है तो कहता है कि कांगड़ा को हम स्वर्ग बना देंगे, और यह भी मैं जानता हूं कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिये, बार्डर रोड्ज़ कंस्ट्रक्शन के लिये उन के प्रोग्राम में काफ़ी अहमियत है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो स्वर्ग बनाने की बात है यह कब तक पूरी होगी, रोड कंस्ट्रक्शन का काम पूरा भी होगा या :

गिनते गिनते दिन जवानी के पूरे हुए,

जब बुढ़ापे में तुम्हारे शबाब आया तो क्या आया।

**मंत्री :** जिसे पंजाब का पहाड़ी इलाका कहा जाता है उसके लिये पिछले साल यानी सन् 1965-66 के बजट में जितनी धन राशि सड़क बनाने के लिये रखी गई थी उसके अलावा एक करोड़ रुपया और रखने का फैसला सरकार ने किया था ताकि पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाई जाए और उसके तहत काम जारी है।

**श्रीमती सरला देवी :** मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि इन्होंने जो एक करोड़ रुपये की ऐलोकेशन की है वह कैसे की है। ऊना से मंडी अथा रोड पहली प्लैन में बननी शुरू हुई है और उसी तरह से चली आ रही है। क्या यह काम इसी तरह से चलेगा और दस साल तक अगर वह इलाका हिमाचल में उस से पहले ही न मिल गया या उस काम को तेज़ करके उस को पूरा किया जाएगा?

**मंत्री :** इस के मुताबिक मैं इतना कह सकता हूं कि हिमाचल में मिलने से पहले ही ही इसे मुकम्मल कर दिया जाएगा।

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि श्री रूप सिंह जी ने अपने सप्लीमेंटरी में कहा था कि सरकार ने कांगड़ा को, हिल्ली एरिया को स्वर्ग बनाने का वायदा किया था। मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि आया स्वर्ग और नर्क बनाने का काम भी इन वजीरों के हाथ में है। (हंसी)

**उपाध्यक्ष :** अगर आप सिसियरली मेरी रूलिंग चाहते हैं तो वह यह है कि अगर आप सब मिल कर नेक नियती से चलेंगे तो जन्नत बनेगा नहीं तो जहन्नम बनेगा।  
(If the hon. Member sincerely wants my ruling, then I would say that if we all co-operate honestly to

[\*पाध्यक्ष]

work together, heavens will emerge, otherwise it will be a hell.) (विघ्न)

श्री रूप सिंह फूल : मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि. ....

उपाध्यक्ष : मैंने जब कह दिया है कि अगर सब मिल कर चलेंगे तो जन्नत बनेगी वरना जहन्नम बनेगा तो फिर अब क्या सवाल रह गया। (When I have already stated that working in full co-operation will bring about heavens and in its absence there will be hell, then, what further is left to be asked).

श्री रूप सिंह फूल : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आया इन का मतलब स्वर्ग बनाने से है या सुधारने से है ?

महोदय : वीरवार सांघ दसठगे कि बांगड़े नुं सदरग घनाउठ लਈ ऐक करेड रुपियां रधिया है, वी उह घहुउ मुहटा है ?

मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय मैं, ने तो कांगड़ा का नाम नहीं लिया, पहाड़ी इलाके का जिक्र किया था।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कांगड़ा और हिल्ली एरिया पर इस लिये मेहरबान है क्योंकि वह इलाका हिमाचल प्रदेश से मिलने जा रहा है ?

मंत्री : मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि इस बात से सरकार की नीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार इतना जरूर मानती है कि जो इलाके प्रदेश के पीछे रह गए हैं उन की ज्यादा से ज्यादा तरक्की की जाए।

#### Deputy Commissioner's Bungalow at Bharwain in District Hoshiarpur

**\*9219. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

- (a) whether the Government has considered the desirability of utilising the Deputy Commissioner's bungalow at Bharwain in Hoshiarpur district for better public purposes than maintaining it for a single officer exclusively ;
- (b) whether he is aware of the fact that there is a big Public Works Department, Rest House and two Zila Parishad Rest Houses at this place ;
- (c) the monthly maintenance charges of the Bungalow mentioned in part (a) above ;
- (d) whether it is a fact that there is a great lack of accommodation in the Government High School, Bharwain and whether the Panchayat of this area has represented to the Government requesting that the said Bungalow be given over for the purpose of school ; the

- (e) whether the Government propose to make it available to the school authorities for converting it into class-rooms after making suitable changes ?

**Chaudhri Ranbir Singh:** (a) The matter was considered by the Revenue Department and it was decided to continue *status quo*.

(b) There is one B Class Civil Rest House and another Zila Parishad Rest House at Bharwain.

(c) Rs. 206.

(d) There is, of course, scarcity of accommodation in the Government High School at Bharwain.

No representation for the use of D.C.s' residence as a part of the school has, however, been received from the Panchayat in the PWD, B&R Branch

(e) There is no such proposal at the present.

**पंडित मोहन लाल दत्त :** क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है या नहीं कि एक सरकारी अफसर के लिये जो कभी कभी ही वहां पर जा कर ठहरता है 206 रुपए माहवार खर्च करना फजूल खर्ची है या नहीं ?

**मंत्री :** माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ही लोक कर्म विभाग ने माल विभाग जिस से इस का ताल्लुक है उस के पास इन की खाहिशात भेजी थी। उन का फैसला यह है। अब फिर दोबारा लोक कर्म विभाग उस फैसले को बदलने के लिये उन को फिर से लिख सकता है।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर वहां पर साल में कितनी बार जाता है और सरकार को उस के वहां पर कितने दिन रहने के लिये यह खर्च बरदाश्त करना पड़ता है ?

**मंत्री :** इस सूचना के लिये तो समय अपेक्षित है।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** उन्होंने माना है कि वहां स्कूल के लिये अकामोडेशन कम है मगर अभी तक उन की तरफ से कोई रिकमैडेशन नहीं मिली। अगर इन को स्कूल अथारिटीज की तरफ से कोई इस बारे में रिकमैडेशन मिले तो क्या यह रैस्ट हाउस स्कूल को देने के लिये तैयार होंगे ?

**मंत्री :** अगर इस तरह का कोई विनय पत्र गांव या किसी और आदमी की तरफ से मिलेगा तो उस पर हमर्दाना गौर किया जायेगा।

**पंडित मोहन लाल दत्त :** क्या इन को इस बात का इल्म है कि उस स्कूल में बहुत असें से जगह की बहुत कमी चली आ रही है और हैडमास्टर की तरफ से यह मतालबा किया जाता रहा है कि यह बंगला बच्चों के बैठने के लिये स्कूल को दिया जाए ?

**शिक्षा मंत्री :** इस बारे में अर्ज है कि कई बार और जगह के मुतआल्लिक भी ऐसी रिकमैडेशनज आती हैं और सरकार जल्द से जल्द, कम से कम जितनी जगह की जरूरत हो उस को मुहैया करने की कोशिश करती है। इस के बारे में इतना अर्ज करता हूं कि और भी सरकार कोशिश कर रही है कि जितनी अकामोडेशन कम से कम जरूरी हो वह मुहैया की जाए।

**उपाध्यक्ष :** डिप्टी कमिश्नर साल में एक आध दफा ही वहां पर जाता होगा, यह इन को दिला ही दें। (The Deputy Commissioner hardly visits that

[उपाध्यक्षा]

place once or twice in a year. The hon. Minister may arrange for this accommodation.)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर उस बंगले में एक साल में आठ दिन से ज्यादा जा कर नहीं रहता और क्या यह भी फैक्ट नहीं है कि सरकार उस की मेंटेनेंस के लिये दो सौ रुपया माहवार खर्च कर रही है और उस बिल्डिंग के आठ कमरे खाली पड़े हैं ? क्या यह शोमफुल नहीं है कि एक तरफ तो सरकार इकानमी की बातें करती है और दूसरी तरफ इस तरह से फजूल खर्च कर रही है ?

**मंत्री :** माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर फिर से हमदर्दना गौर किया जाएगा ।

**पंडित मोहन लाल दत्त :** इन्होंने कहा है कि रैवेन्यू डिपार्टमेंट में सोच विचार करके यह फैसला किया है कि इस बंगले को डिप्टी कमिश्नर के लिये रखना है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ने यह फैसला किस दलील की बिना पर किया है ?

**मंत्री :** किन कारणों से माल विभाग ने यह राय बनाई है वह जानने के लिये समय अपेक्षित है ।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** क्या यह बताएंगे कि इस रैस्ट हाउस के अलावा वहाँ पर एक दूसरा रैस्ट हाउस भी है डिप्टी कमिश्नर के ठहरने के लिये ?

**मंत्री :** सदस्य तो सूचना दे रहे हैं, पूछ नहीं रहे ।

#### Expenditure incurred on Government Buildings Constructed in Chandigarh

**\*9058. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Capital & Housing be pleased to state —

- the total amount so far spent on the New Secretariat Building and on the Vidhan Bhawan together with the details of the expenditure, if any, incurred on their maintenance or repairs so far ;
- the total amount so far spent on the Sukhna Lake together with the amount so far incurred on its maintenance and repairs ;
- the total approximate amount so far spent on Government buildings in Chandigarh ;
- the total approximate amount spent in all on the development of Chandigarh, i.e., on construction of Government Buildings, Roads, Waterworks, Hospitals etc.etc. ;
- whether any estimate of the expenditure likely to be incurred annually on the maintenance of all Government buildings in Chandigarh has been worked out ; if so, how much is the same ; if no estimate has been formed, the reasons therefor ?

**Sardar Prem Singh Prem :** (a) Expenditure up to December, 1965, on construction is Rs. 1,34,32,194 and Rs 1,01,73,475 respectively and expenditure on maintenance & repairs Rs 20,27,265 and Rs 1,62, 963, respectively.

(b) Rs. 81,15,540 and Rs. 3,11,718 respectively up to December, 1965.

(c) Rs. 2.058.38 lakhs up to December, 1965.

(d) Rs 3,046.15 lakhs.

(e) Yes. Rs.24.66 lakhs per annum approximately.

**कामरेड राम प्यारा :** क्या कैपिटल मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि उन्होंने ने सैक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का खर्च 1 करोड़ 34 लाख बताया है और उसकी मेंटेनेंस का खर्च 20 लाख बताया है तो क्या यह मेंटेनेंस का खर्चा हर साल बढ़ता जाएगा या पहले सालों में ज्यादा हो रहा है?

**मंत्री :** जितना भी किसी बिल्डिंग की कन्स्ट्रक्शन पर खर्च आता है एकारडिंग टू कोड रूलज़ उस पर डेढ़ परसेंट मेंटेनेंस का खर्चा रखा जाता है जो कोई 22 लाख बनता है लेकिन असल खर्च 15.69 लाख हुआ है पहली प्लान में और दूसरी प्लान में कोई 27 लाख तो इस खर्च की कोड रूलज़ के मुताबिक इजाज़त है। जितने खर्चा की इजाज़त है उतना खर्चा हो नहीं रहा है।

**कामरेड राम प्यारा :** यह जो पार्ट (इ) है इसका जवाब दिया गया है कि एस्टीमेट्स बनाए गए हैं और हम सब का तजुर्बा है कि एस्टीमेट्स आम तौर पर ज्यादा बनाए जाते हैं। क्या यह हकीकत है कि मेंटेनेंस के खर्च को छुपाने के लिये एस्टीमेट्स ज्यादा बनाए गए हैं ?

**मंत्री :** नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात छुपाने के लिये नहीं की गई और अगर यह की जाती तो सही फिगरज़ आप को न बताई जातीं।

#### Chief Liaison Officer's Office at Delhi

**\*8934. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) the date since when the office of the Liaison Officer has been functioning at Delhi together with the date when the status of the said officer was raised to that of the Chief Liaison Officer;
- (b) the total monthly expenditure being incurred by the State Government on the said office at present together with its details;
- (c) the details of the functions assigned to the above-mentioned officer in general;
- (d) the details of the particular duties assigned to the said officer during the last year together with the details of those which were accomplished?

**Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary):** A statement embodying the desired information is laid on the Table of the House.

#### Statement

(a) It was decided in the beginning of the year 1961 that with effect from the 15th February, 1961 the Planning Commissioner, Punjab, will in addition to his other duties also function as Chief Liaison Officer for Punjab at Delhi with headquarters at Chandigarh. However, a full-fledged Chief Liaison Officer (since re-designated as Agent to Government Punjab) has been appointed in Commissioner's rank with effect from 25th June, 1961. The question of raising the status of the Liaison Officer to that of the Chief Liaison Officer, in these circumstances, does not arise.

(b) The expenditure being incurred by the State Government in the office of the Agent to Government, Punjab, varies from month to month because of its having been

[Chief Parliamentary Secretary]

set up independently quite recently. However, the figures of expenditure for the month of December, 1965, are given below:

	Rs
(i) Pay of the Agent	.. 3,000.00
(ii) TA/DA drawn by the Agent	.. 60.00
(iii) Pay of non-gazetted staff	.. 2,257.38
(iv) TA/DA drawn by staff	.. 941.10
(v) Rent for the office building	.. 2,668.00
(vi) Expenditure on contingencies	.. 14,773.37 ( This includes purchase of a car including transport charges from Calcutta and Registration Fee, etc)
Total	.. 23,699.85

(c) and (d) 1. To keep in touch with the Central Government and pass on useful information of prospective developments of importance to the State;

2. To follow up action initiated by the State where the usual process of reminding Delhi by letters on individual visits by officers is likely to lead to delay.

3. To represent officers of the State at important meetings, conferences and Committees at Delhi where the Agent would be competent to take their place with the help of a brief on the subject.

4. To keep the State Government informed of the visits of Foreign Technical Missions, representatives of International Organisations and Foreigners of importance whose direct contact may possibly help the industrial and economic development or other interests of the State.

5. To look after the interests generally of the State Government in so far as they are affected by activities in all fields of the Union Government and all-India Organisations with economic Social and similar non-political activities;

6. To act as Agent of the State Government in all miscellaneous matters where specifically instructed by the Government in any Department.

**श्री बलराम जी दास टण्डन :** क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि उन्होंने चीफ लाइज़न आफिसर दिल्ली का जो एक महीने का खर्च बताया है वह लगभग 24 हजार है तो इतना ज्यादा खर्च होने की क्या वजह है ?

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** यह खर्च दिसम्बर के महीने का था, उस में एक कार खरीदी गई थी इस लिये उस महीने का खर्च ज्यादा आया वैसे महीने का खर्च 14,773.37 आता है ।

**श्री बलरामजी दास टण्डन :** क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बातएंगे कि मैं ने सवाल के पार्ट ( डी ) के आदर पूछा था कि—

“the details of the particular duties assigned to the said officer during the last year together with the details of those which were accomplished”

तो इस पार्ट का जवाब देते हुए कोई इन्फरमेशन हाउस में ले नहीं दी गई इस की क्या वजह है ?

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** मैं ने इस का जवाब दे दिया है । अगर आप कहें तो पढ़ कर सुना देता हूं । आज कल जो एजेंट हैं और जो पहले चीफ लाइज़न आफिसर थे वह बहुत यूसफूल काम करते हैं । सरकार की तरफ से कई स्कीमें गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजी जाती हैं जिन्हें पास करवाना और उनको फालो आप करने का काम है जो यह करते हैं ।

**कामरेड राम प्यारा :** क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी बताएंगे कि गवर्नमेंट ने वरी रीसेंटली एन्टर्नमेंट के लिए कुछ खर्चा इस के लिए मुकर किया है ; अगर किया है तो इस की बैकग्राउंड क्या है ?

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** आप अगर इस के लिए अलहदा सवाल पूछें तो जवाब दे दूंगा ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** May I ask the hon. Chief Parliamentary Secretary if it is a fact that one of the senior-most officers of the State is the Chief Liaison Officer; if so, can't he be replaced by an officer of a junior status ?

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** वहां पर सीनियर मोस्ट आफीसर लगाने की खास वजह यह है कि उस ने गवर्नमेंट आफ इंडिया के सैक्रेटरीज के साथ बात चीत करनी होती है इस लिए वहां पर किसी जूनियर आफीसर का इतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता ।

**श्री बलराम जी दास टण्डन :** आप, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा क्वैश्चन मुलाहजा करें। इस में मैंने पूछा था कि

“the details of the functions assigned to the above-mentioned officer in general.”

तो इन्होंने जनरल ड्यूटी के बारे में बता दिया है और इस तरह सफेद हाथी बांध रखे हैं। मैं तो उस चीफ लाइजन आफीसर के बारे में पूछना चाहता हूं कि उस को क्या काम करने को दिया हुआ है ।

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** यह अच्छा मालूम नहीं देता कि इस तरह के शब्द एक सीनियरमोस्ट आफीसर के लिए यहां इस हाउस में इस्तेमाल किए जाएं। मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जो ड्यूटीज इस आफीसर को दी गई हैं इन्होंने वह बहुत ऐफिशिएंटली सरजाम दी हैं ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** May I ask the Chief Parliamentary Secretary if it is not a fact that Mr. R.P. Kapur, I.C.S. was posted as Chief Liaison Officer because the Government did not want to accommodate him on some responsible post at Chandigarh ?

**Chief Parliamentary Secretary :** No, no.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** I want a positive reply.

**शिक्षा मंत्री :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि यह जो इनसिनुएशन लगाई गई है इस की कोई बिना नहीं । और बिल्कुल गलत है। दूसरे सूबों में भी जो लाइजन आफीसर्ज दिल्ली में हैं वह सीनियर मोस्ट हैं ।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** इन्होंने जनरल ड्यूटी बताई है कि जो स्कीमें सरकार की तरफ से जाती हैं उन को परसू करना और सेंटर की सरकार से उन्हें मंजूर करवाना, लेकिन हम तो यह जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन कौन सी असाइनमेंट्स दी गई और किन किन को उन्होंने पूरा किया और कौन सी फाइनल स्टेज पर पहुंच गई। सरकार को इस का क्या लाभ हुआ और इस की अचीवमेंट्स क्या हैं ?

**उपाध्यक्ष :** श्री प्रबोध चन्द्र जी आप इस का जवाब दें। (Let Shri Prabodh Chandra reply to this.)

(At this stage the Chief Parliamentary Secretary rose to give a reply).

**Deputy Speaker :** I have called upon the Education Minister to reply to that question.

**शिक्षा मंत्री :** जहां तक स्पैसिफिक ड्यूटीज़ का ताल्लुक है कई तरह की स्कीमें सरकार की तरफ से भेजी जाती हैं, और करोड़ों रुपया की होती हैं, जैसे अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पंजाब में हैवी इंडस्ट्री आनी चाहिए। तो इस तरह की काफी स्कीमें हैं। इट इज़ ए मूविंग प्रोसेस। और उन्होंने सारा काम जितना दिया गया था किया है। और कई हालतों में तो उन्हें स्पेड वर्क भी करना पड़ता है। **It takes some time to complete the work.** पिछले 6 या 7 महीनों से 50 हजार रिफ्यूजीज़ को आबाद करने का मसला था। इस के बारे में रोज़ाना कई हिदायतें यहां से जाती रही हैं और फिर उन्हें कई घंटे रिहैबिलिटेशन मिनिस्टरी में जा कर काम करना पड़ता था। उन्होंने जो काम किया है अच्छा किया है।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** May I ask the hon. Education Minister if it is a fact that a sum of Rs. 10,000 has been placed at the disposal of the Chief Liaison Officer as entertainment allowance by the Government?

**शिक्षा मंत्री :** इस के लिये पहले आप नोटिस दें। अगर फ़ैक्चुअल बात होगी तो आप को बता दिया जायेगा।

**Sardar Gurnam Singh :** Madam, may I know if it is true that this officer is provided residential accommodation at Jorbagh and office elsewhere? May I also know whether he has been given a big amount as Entertainment Allowance?

**Minister for Education :** It is factually true that the residential accommodation for the officer is apart from the office. As regards Entertainment Allowance provided to him, I need notice. I can assure the hon. Member that we have nothing to hide. We will give the actual facts.

**Sardar Gurnam Singh :** Then, Madam, this question may be postponed. The Government may answer this when they have collected information.

**Minister for Education :** I will get the information and pass it on to the hon. Member. If he so desires, he can further pass it on to other hon. colleagues.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?

**Deputy Speaker :** Please be relevant.

(At this stage, Shri Balramji Das Tandon rose to put another supplementary question).

**Deputy Speaker :** There must be some limit on supplementary questions

**Sardar Gurnam Singh :** The hon. Member Sardar Gurcharan Singh is ignorant. That is another Branch in Delhi.

**श्री बलराम जी दास टण्डन :** क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि जैसे कि उन्होंने 2,665 रुपये माहवार किराये का खर्चा बताया है क्या यह आफिस कैनाल रैस्ट हाऊस में नहीं ले जाया जा सकता जिस से इस खर्चे की सेविंग हो जाये ?

**शिक्षा मंत्री :** हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कपूरथला एस्टेट मिल जाये तो हम आसानी से इस में इंतजाम कर सकेंगे। इस से यह सेविंग भी हो जायेगी।

### Travelling and Halting Allowances of the Ministers

**\*9402. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state the amounts of travelling and halting allowances, separately, drawn by each of the Ministers during the year 1965-66 ?

**Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) :** A statement showing travelling and halting allowance drawn separately by each Minister up to 31st December, 1965, is laid on the Table of the House.

Statement showing Halting and Travelling allowances drawn separately by each Minister

Serial No.	Name of Minister	Halting allowance	Travelling allowance	Total (upto 31st December, 1965)
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab	2,066.25	1,892.05	3,958.30
2	Shri Darbara Singh, Home and Development Minister, Punjab	1,612.50	595.75	2,208.25
3	Shri Prabodh Chandra, Education Minister, Punjab	1,228.10	430.00	1,658.10 (up to November, 1965. The details of December, 1965 not yet received)
4	Shri Kapur Singh, Finance Minister,, Punjab	1,473.75	2,190.75	3,664.50 (upto November, 1965 only. The details of December, 1965 not yet received)
5	Shri Gurdial Singh, Dhillon, Transport and Elections Minister, Punjab	1,128.75	1,840	2,968.75 (up to November, 1965 only. The details of December, 1965 not yet received).

## [Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	Name of visit	Halting allowance	Travelling allowance	Total [up to 31st December, 1965]
6	Ch. Ranbir Singh, Public Works Minister, Punjab	1,852.50	..	1852.50
7	Shri Ajmer Singh, Planning & Local Government Minister, Punjab	1,372.50	245.00	1,617.50
8	Shri Harinder Singh, Revenue Minister, Punjab	..	..	.. (No amount claimed)
9	Shri Rizk Ram, Irrigation and Power Minister, Punjab	1,372.50	830.20	2,202.70
10	Shri Prem Singh Prem, Capital and Housing Minister, Punjab	1,012.50	740.00	1,752.50
11	Shri Chand Ram, Welfare and Justice Minister, Punjab	1,582.50	69.70	1,652.20
12	Shrimati Om Prabha Jain, Health Minister	1,385.45	1,505.90	2,891.35

## Publicity Workers

**\*9134. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether it is a fact that the Government has recently decided to re-appoint Publicity Workers in the State ;
- if the reply to part (a) above be in the affirmative, the criteria for such appointments, the salary to be paid to such workers and the date by which such appointments are likely to be made alongwith the designation of the appointing authority ;
- whether any list of candidates selected for these posts has been finalised by the Government ?

**Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary)** (a) Yes.

(b) The Block Publicity Workers are required to possess background of rural life, flair for Public speaking and aptitude for social work. They are appointed by the Director, Public Relations, Punjab at a fixed monthly remuneration of Rs. 100 with the approval of Chief Parliamentary Secretary and Chief Minister, Punjab. These appointments are expected to be completed by the end of March, 1966.

(c) Block Publicity Workers in Amritsar, Gurdaspur, Ferozepore, Jullundur, Hoshiarpur, Ludhiana, Ambala and Mohindergarh Districts have since been appointed. Appointments for other districts are under consideration.

**पंडित चिरंजी लाल शर्मा :** क्या कुछ ऐसे जिले भी हैं जिन के लिये अभी आफिशल्ज एप्वायंट नहीं किये गये ?

**उपाध्यक्ष :** यह तो उन्होंने रिप्लाय में बता दिया है। (He has already mentioned about it in his reply.)

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Madam, may I know from the Chief Parliamentary Secretary the reasons for not finalizing the list for the remaining districts ?

**चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी :** जब हमारा पाकिस्तान से झगड़ा हुआ था तो उस वक्त हम ने बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स के डी. पी. पी. को ही हिदायत कर दी थी कि वह आप ही पब्लिसिटी वर्कज को एक्वायट कर दें। इसलिये यह एक्वायट किये गये थे।

**सरदार गुरचरन सिंह :** की ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਸਟੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 175 ਨਵੇਂ ਬਲਾਕਵਾਈਜ਼ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ। (The hon. Member is seeking and giving information at the same time.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ :** ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ?

(No reply was given)

**ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ :** ਜਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੀਰਿਐਂਸਡ ਵਰਕਜ਼ ਥੇ ਆਰ ਉਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਕਥਾ ਉਨ ਕੋ ਵੀ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ?

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਜੀ ਹਾਂ, ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ :** ਜਿਹੜੇ ਰੀ ਐਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਕਾ ਧਿਆਨ ਰਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ :** ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹਨ ?

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਉ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ।

**ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਕਥਾ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਯੋਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਆਫੀਸਲਜ਼ ਜਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕਰ ਉਨ੍ਹੇਂ ਹਟਾਯਾ ਗਯਾ ਥਾ, ਕਥਾ ਇਨ ਕੋ ਸੀਰਿਯਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗ ਜਾਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਵੀ ਫਿਰ ਲਗਾਯਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ?

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ :** ਇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਰਿਯਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਸਲਿਯੇ ਇਨ ਕੋ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

**Punjab Financial Corporation**

**\*8936. — Balramji Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state

- (a) the total amount of loans advanced by the Punjab Financial Corporation during the year 1965 together with its break up, industry-wise and district-wise ;
- (b) the amount of money advanced as loan, received back by the said Corporation during the year 1965, principal and interest both ;
- (c) the amount due back during the said period but not realized with reasons therefor ;
- (d) whether it is a fact that the Punjab Financial Corporation is running short of funds; if so, the details of the steps taken by the Government in this direction to meet the situation?

4, **Ram Partap Garg** (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Rs. 1,657,100.00 (i.e. from 1st of January, 1965 to 31st of December, 1965) Districtwise and industrywise statement is laid on the Table of the House.

(b) Rs. 56,86,423.74 as principal and Rs. 45, 78, 665.07 as interest.

(c) Rs. 12,91,517.80 as principal and Rs. 2,87,186.80 as interest. The main reason for these defaults is the Indo-Pakistan conflict.

(d) The Corporation has, so far, been meeting all genuine needs of the industry on the area of its jurisdiction. However, it cannot, on account of shyness in the capital markets, raise additional resources as easily as in the past. The Government is, however, alive to the situation and has assured the Corporation every assistance in its efforts to raise more funds. The State Government are themselves going to broaden the financial base of the Corporation during the Fourth Five Year Plan by contributing an amount of Rs. 2.00 crores.

**STATEMENT****PUNJAB FINANCIAL CORPORATION, CHANDIGARH**

Amount advanced during the year 1965 (i. e. from 1st of January, 1965 to 31st of December, 1965)

Serial No.	Name of the District	Amount advanced	Type of Industry
		Rs.	
1	Amritsar	.. 4,21,000.00	Woollen Textile
2	Ambala	.. 1,14,600.00	Steel Furniture
3	Gurgaon	.. 75,58,000.00	Motor parts, Steel Casting and forging and other miscellaneous industries
4	Hissar	.. 3,09,000.00	Cotton Ginning
5	Jullundur	.. 2,51,500.00	Electrical goods, Machine Tools and other miscellaneous industries.
6	Karnal	.. 8,58,000.00	Card Board, Cotton Yarn Spinning solvex Oils

(7)21

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45**

Serial No.	Name of the District	Amount advanced	Type of industry
7	Ludhiana	.. 47,85,600.00	Cotton Spinning Yarn Woollen Textile
8	Patiala	.. 4,82,500.00	Steel Casting
9	Rohtak	.. 23,000.00	Sanitary Ware
10	Delhi	.. 13,16,400.00	Hotel, Steel Re-Rolling and other Miscellaneous industries
11	Himachal Pradesh	.. 2,42,500.00	Woollen Textile.
12	Simla	.. 1,00,000.00	Food Malts
Total		.. 1,64,57,100.00	

**Deputy Speaker :** The Question Hour is over now. Supplementaries will be asked next time.

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON  
THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45**

**Land Acquired for Seamless Tube Factory at Ganaur, tehsil Sonapat**

**\*9133. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Government acquired land in Ganaur tehsil Sonapat in the year 1963-64, for the establishment of a seamless Tube Factory; if so, the area of land acquired for the purpose ;
- (b) whether it is a fact that the proposal to construct the said factory has since been dropped by the Government; if so, the reasons therefor ;
- (c) whether the land mentioned in part (a) above has since been released and the respective owners informed accordingly ;
- (d) whether there is any proposal under the consideration of the Government to start any other heavy Industry in place of the Seamless Tube Factory at Ganaur ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes ; 168.59 acres.  
(b) No. Does not arise.  
(c) and (d) Does not arise.

**Permits for G.P. Sheets (Imported) issued in the State**

**\*9145. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total number of permits for drawal of G.P. Sheets (imported) from M/s Amin Chand Peare Lal, Jullundur, which were

[Comrade Ram Piara]

- issued in the State district-wise by the Industries Department, to the Iron and Steel quota holders during the period from 1st December, 1963 to 15th February, 1964, together with the name of each quota holder and the quantity for which the permit was issued in his favour ;
- (b) whether it is a fact that some of the said permits were not honoured by M/s Amin Chand-Peara Lal, Jullundur, if so, the reasons therefor ;
  - (c) the total quantity of the G.P. Sheets imported by M/s Amin Chand-Peara Lal, Jullundur and intimated by them to the Punjab Government/Industries Department against which the Industries Department issued the said permits ;
  - (d) whether it is also a fact that the Director of Industries, Punjab, issued letter No. STC/1217/Misc/15773, dated 11th June, 1964 to the firm mentioned in part (c) above recommending the sale of 4 tons of G.P. sheets to Shri Dev Datt Vij of Karnal; if so, a copy of the same be laid on the table of the House ;
  - (e) whether any other letter was issued by the Department to the said firm recommending the sale/supply of sheets to the other quota holders, whose permits were not originally honoured by the said firm ; if so, the names of such quota holders and copies of the letters be laid on the Table of the House ;
  - (f) if the reply to part (e) above be in the negative, the reasons why the letter referred to in part (d) was sent by the Department ;
  - (g) whether it is further a fact that M/s Amin Chand-Peara Lal got the balance stock with them released from the Industries Department for sale in the open market at the time when the permits issued to the quota holders by the Industries Department were yet to be honoured ; if so, the quantity so released, the date when it was released and the reasons for releasing it.

**Shri Ram Kishan :** (a) 384. Information is placed on the Table of the House as annexure I.

(b) Yes. Originally a quantity of 1600 M.T. was allocated by Development Commissioner, Small Scale Industries, Government of India to Punjab. This was to be handled by M/s Amin Chand Payare Lal, the stock holders nominated by Government. Proportionate shares of this total quantity were earmarked for various districts and District Industries Officers were asked to issue permits accordingly. In anticipation of actual arrivals the D.I. Officer commenced issuing permits, which totalled to an aggregate quantity of 671.916 M.T. The actual arrivals of material were only 396.876 M.T. , and thus permits for the balance quantity could not be honoured.

(c) The total quantity imported by M/s Amin Chand-Payare Lal is 396.876 tons as per record in the Department of Industries. Intimations, from Stockists of arrival of 183.236 metric tons are available. The complete record of intimations which may have been received subsequently is not available. As already explained in reply to part (b), permits were issued not against intimation of actual arrivals with the stockists, but against the quantity allocated by Central Government.

(d) Yes. A copy of the said letter is placed at the Table of the House as annexure II.

(e) No.

(f) The letter was issued as the fabricated goods were to be supplied to Khadi Ashram, Karnal.

(g) No.

#### ANNEXURE—I

Statement showing the name of the parties (District-wise) together with the quantities for which the permits for G.P. Sheets (Imported) were issued in their Favour of the period from 1st December, 1963 to 15th February, 1964.

Serial No.	Name and address of the Party	Quantity of G.P. Sheets
1	2	3

#### DISTRICT AMBALA

- |  |          |
|--|----------|
| 1 M/s Iron and Steel Fabricators Association, Ambala Cantt             | .. 5.750 |
| 2 M/s Purshartha Iron and Steel Quota Holders Association, Ambala City | 5.460    |
| 3 M/s Capital Steel Quota Holders Association Indl. Area, Chandigarh   | 1.560    |
| 4 M/s Vishkarama Iron and Steel Quota Holders Association, Kurali      | 1.690    |
| 5 M/s Natial Engg. Co. Ambala City                                     | .. 2.000 |
| 6 M/s Jainco Industries, Spatu Road, Ambala City                       | .. 0.540 |

#### DISTRICT GURDASPUR (Batala)

- |  |            |
|--|------------|
| 1 M/s Mahajan Trunk Factory, Pathankot   | .. 1 M.T.  |
| 2 M/s Todar Mal-Durga Parshad, Pathankot                                       | .. 1 M.T.  |
| 3 M/s Kailash Trunk Factory, Pathankot   | .. 1 M.T.  |
| 4 M/s Dewan Chand-Kotu Mal, Pathankot  | .. 1 M.T.  |
| 5 M/s Sudarshan Steel Factory, Pathankot                                       | .. 1 M.T.  |
| 6 M/s Masoom National Industries, Pathankot                                    | .. 1 M.T.  |
| 7 M/s Gurdaspur Engg. Production (C&S), Coop. Industrial Society Lt. Gurdaspur | 2 M.T.     |
| 8 M/s Gurdaspur Iron and Steel Goods Mfg. Association, Gurdaspur               | 5 M.T.     |
| 9 M/s Northern India Engg. Association Batala                                  | .. 11 M.T. |
| 10 M/s Batala Manufacturers Association, Batala                                | .. 25 M.T. |

#### DISTRICT LUDHIANA

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 M/s Tilak Ram Chaudhry and Sons, Civil Lines, Ludhiana  | .. 2 M.T. |
| 2 M/s Sigma Steel Industries, Industrial Estate, Ludhiana | .. 2 M.T. |
| 3 M/s Mohinder Singh Manmohan Singh, Ludhiana             | 1 M.T.    |
| 4 M/s Chaman Singh Sunder Singh, Ludhiana                 | .. 1 M.T. |

[Chief Minister]

1	2	3
5	M/s. Manohar Metal Industries, Ludhiana	.. 1 M.T.
6	M/s. Nath Steel Manufacturers, Ludhiana	.. 1 M.T.
7	M/s. Sialkot Steel Works, Lakar Bazar, Ludhiana	.. 1.00 M.T.
8	M/s. Sadhu Ram Naurata Ram, Ludhiana	.. 1 M.T.
9	M/s. Hari Chand Mahal Chand, Lakkar Bazar, Ludhiana	.. 1.00 M.T.
10	M/s. Hamir Chand and Sons, Ludhiana	.. 1 M.T.
11	M/s. Gopal Dass Mangat Rai, Ludhiana	.. 1 M.T.
12	M/s. Lakra Metal Industries, Ludhiana	.. 1 M.T.
13	M/s. Cheap Iron Works, Takia Gujran, Ludhiana	.. 1 M.T.
*14	M/s. Sant Ram Krishan Lal, Khurd Moh. Ludhiana	.. 1 M.T.
15	M/s. Moonga Trunk Factory, Ludhiana	.. 1 M.T.
16	M/s. Gosain Labori Mal and Sons, Ludhiana	.. 1 M.T.
17	M/s. Nand Kishore Aggarwal, Gill Indl. Ludhiana	.. 1 M.T.
18	M/s. Guru Nanak Trunk Factory, Ludhiana	.. 1 M.T.
19	M/s. Chawla Trunk House, Ludhiana	.. 1 M.T.
20	M/s. Sheikhpura Mech. Works, Ludhiana	.. 1 M.T.
21	M/s. Arneja Industries, Ludhiana	.. 1 M.T.
22	M/s. Ram Metal Works, Ludhiana	.. 1 M.T.
23	M/s. Malak Chand Trunk Maker, Ludhiana	.. 1 M.T.
24	M/s. Faqir Chand, Nanak Chand, Ludhiana	.. 1 M.T.
25	M/s. Gopal Singh Vir Singh, Ludhiana	.. 1 M.T.
26	M/s. Narain Singh Raghu Singh, Ludhiana	.. 1 M.T.
27	M/s. M. Kartar Singh and Brothers, Bahadurgarh	.. 1 M.T.
28	M/s. Dhain Chand Parma Nand, Ludhiana	.. 1 M.T.
29	M/s. Pahwa Brothers, Mochpura Bazar, Ludhiana	.. 1 M.T.
30	M/s. Khurana Industrial Works, Ludhiana	.. 1 M.T.
31	M/s. Kesar Singh & Sons, Chandigarh Road Ludhiana	.. 1 M.T.
32	M/s. India Industry, Gill Road, Ludhiana	.. 1 M.T.
33	M/s. Sargodha Steel works Ludhiana	.. 1 M.T.
34	M/s. Lamba Trunk House, Ludhiana	.. 1 M.T.
35	M/s. Janta Trunk House, Ludhiana	.. 1 M.T.
36	M/s. Lyallpur Trunk House, Ludhiana	.. 1 M.T.
37	M/s. National Expeller workshop, Ludhiana	.. 1 M.T.
38	M/s. Telu Ram, Om Parkash, Ludhiana	.. 1 M.T.
39	M/s. Royal Manufacturing Co. Ludhiana	.. 1 M.T.
40	M/s. Goyal Loom Industries, Ludhiana	.. 1 M.T.
41	M/s. Swantantra Metal Works, Ludhiana	.. 1 M.T.
42	M/s. Jamna Dass Om Parkash, Ludhiana	.. 1 M.T.
43	Mistri Pritam Singh and Sons, Ludhiana	.. 1 M.T.
44	M/s. Kidar Nath Aggarwal & Company, Ludhiana	.. 1 M.T.
45	M/s. Kuldip Singh Lamba, Ludhiana	.. 1 M.T.
46	M/s. Jagraon Metal Industries Jagraon	.. 1 M.T.
47	M/s. Rakha Ram Hira Lal, Jagraon	.. 1 M.T.
48	M/s. Babu Ram Kidar Nath, Jagraon	.. 1 M.T.
49	M/s. Lal Singh and Sons Jagraon	.. 1 M.T.
50	M/s. Natha Singh & Company, Jagraon	.. 1 M.T.
51	M/s. Punjab Iron stores, Jagraon	.. 1 M.T.
52	M/s. Milkhi Ram Dev Raj, Jagraon	.. 1 M.T.
53	M/s. Sant Singh Registered Engineer, Jagraon	.. 1 M.T.
54	M/s. Gujranwala Trunk House, Jagraon	.. 1 M.T.
55	M/s. Bhola Nath Girdhari Lal, Jagraon	.. 1 M.T.
56	M/s. Nathu Ram Ramji Dass, Jagraon	.. 1 M.T.
57	M/s. Chanan Ram Sant Singh, Jagraon	.. 1 M.T.
58	M/s. Khushal Singh & Company, Jagraon	.. 1 M.T.
59	M/s. Ram Singh & Company, Jagraon	.. 1 M.T.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (7)25  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

1	2	3
60	M/s. Sat Parkash Singal Brothers, Samrala	.. 1 M.T.
61	M/s. Walaiti Ram Munshi Ram, Ludhiana	.. 1 M.T.
62	Parkash Chand, Ludhiana	.. 1 M.T.
63	M/s. Bharat Trunk House, G.T. Road, Khanna	.. 1 M.T.
64	M/s. Ram Lal Trunk Maker, Raikot	.. 1 M.T.
65	M/s. Janta Trunk House, G.T. Road, Khanna	.. 1 M.T.
66	M/s. Harcharan Dass Sat Dev, Ludhiana	.. 1 M.T.
67	M/s. Jindal Trunk House, Ludhiana	.. 1 M.T.
68	M/s. Buta Singh Avtar Singh, Ludhiana	.. 1 M.T.
69	M/s. Gurbax Singh Gopal Singh, Ludhiana	.. 1 M.T.
70	M/s. Malwa Trunk House, Ludhiana	.. 1 M.T.
71	M/s. Azad Trunk House, Ludhiana	.. 1 M.T.
72	M/s. Taluja Trunk Factory, Ludhiana	.. 1 M.T.
73	M/s. National Industries, Ludhiana	.. 1 M.T.
74	M/s. Jagpal Brothers Industry, Otalon	.. 1 M.T.
75	M/s. Balkrishan & Sons, Khud Moh., Ludhiana	.. 1 M.T.
76	M/s. Jagat Ram Gopal Dass, Ludhiana	1 M.T.
77	M/s. Aggarwal Metal Works, Ludhiana	.. 1 M.T.
78	M/s. Hindustan Industries, Ludhiana	.. 1 M.T.
79	M/s. Sharda Industries, Ludhiana	.. 1 M.T.
80	M/s. Sat Parkash Badri Nath, Ludhiana	.. 1 M.T.
81	M/s. P. Durga Dass & Sons, Purani Kotwali, Ludhiana	.. 1 M.T.
DISTRICT FEROZEPUR		
1	M/s. Punjab Trunk House, Ferozepur Cantt.	.. 0.250
2	M/s. Birla Sewing Machines, Ferozepur Cantt.	.. 0.250
3	M/s. Sareen Engineering Works, Ferozepur Cantt.	.. 0.250 M.T.
4	M/s. Durga Engineering Works, Ferozepur Cantt.	.. 0.250 M.T.
5	I.T.I., Ferozepur	.. 0.500 T.

[Chief Minister]

1	2	3
6	M/s. Raja Ram Kirpa Ram, Moga	.. 0.250 M.T.
7	M/s. Daulat Ram Prem Kumar, Moga	.. 0.250 M.T.
DISTRICT GURGAON		
1	M/s. Suresh Trunk Factory Gurdwara Road, Gurgaon	.. 1 M.T.
2	M/s. Khanna Industries, Gurdwara Road, Gurgaon	.. 1 M.T.
3	M/s. Anand Trunk Manufacturing Company, G. Road, Gurgaon	1 M.T.
4	M/s. Arjan Trunk House, Gurdawara Road, Gurgaon	.. 1 M.T.
5	M/s. New Model Trunk Factory, G. Road, Gurgaon	.. 1 M.T.
6	M/s. Subhash Trunk Factory, Gurd. Road, Gurgaon	.. 2 M.T.
7	M/s. The Executive Officer, Panchayat Samiti Khol at Rewari	.. 1 M.T.
8	M/s. The Executive Officer, Panchayat Samiti Hathin	.. 1 M.T.
9	M/s. The B. D. & P.O. Bawal	.. 1 M.T.
10	M/s. Azad Trunk Factory, Gurd. Road, Gurgaon	.. 0.6 M.T.
11	M/s. Ahuja Trunk House, G.T. Road, Palwal	.. 0.6 M.T.
12	M/s. Rashtriya Industries, Sohna	.. 0.6 M.T.
13	M/s. Jetha Nand Udhey Bhan, Sohna	.. 0.6 M.T.
14	M/s. The Executive Officer, Pachayat Samiti, Palwal	.. 438 K.G. 0.6 M.T.
DISTRICT JULLUNDUR		
1	M/s. New Model Industries, Kapurthala Road, Jullundur	.. 500 K.G.
2	M/s. Jullundur Trunk Balti, Association Chowk Panj Pir, Jullundur	1.250 K.G.
3	M/s. Doaba Industrialists Association Jullundur	.. 1.000 K.G.
4	M/s. Rahabilitated Industrialists Assocn., Adda Kapurthala, Jullundur	.. 1 M.T.
5	M/s. Jullundur Steel Fabricators Association, Chowk Sundan, Jullundur	.. 0.500 M.T.
6	M/s. Small Scale Industrialists Associantion, Mandi Road, Dhan Mohalla, Jullundu.	.. 0.750 M.T.
7	M/s. Cantonment Steel Quota Holders, Association., Jullundur Cantt.	0.250
8	M/s. Industrial Area Engineering Association, Jullundur	.. 1.000

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (7)27  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45**

1	2	3
9	M/s. Engineering Industries Association, T/Road, Jullundur	.. 1.000
10	M/s. Industrial Areas Development Assocn., Jullundur	.. 0.400
11	M/s. Industry Area Small Scale Fabricators Assocn., Jullundur	.. 0.250

**DISTRICT AMRITSAR**

1	M/s. The Amritsar Buckets, etc. Manufacturers Assoc., Amritsar	.. 6.000 M.T.
2	M/s. The Amritsar Buckets, etc. Manufacturers Assoc., Amritsar	.. 16.000 M.T.
3	M/s. The Amritsar Buckets, etc. Mfrs. Assoc., Amritsar	.. 15.000 M.T.
4	M/s. The Amritsar Small Scale Pumps and Spare Part Mfrs. Association, Amritsar	.. 1.300 M.T.
5	M/s. The Amritsar Small Scale Pumps and Spare Parts Mfrs. Association, Amritsar	.. 4.800 M.T.
6	M/s. The Amritsar Small Scale Pump and Spare Parts Mfrs. Association, Amritsar	.. 4.900 M.T.
7	M/s. Iron and Steel Small Scale Industries Association, Amritsar	.. 1.500 M.T.
8	M/s. Iron and Steel Small Scale Industries Association, Amritsar	.. 3.400 M.T.
9	M/s. Iron and Steel Small Scale Industries Association, Amritsar	.. 3.100 M.T.
10	M/s. Iron & Steel Mfrs. Association, Amritsar	.. 1.000 M.T.
11	M/s. Iron & Steel Mfrs. Association, Amritsar	.. 2.600 M.T.
12	M/s. Iron & Steel Mfrs. Association, Amritsar	.. 2.400 M.T.
13	The B.D. & P.O. Patti	.. 1.000 M.T.
14	M/s. Amritsar Small Scale Steel Quota Holders Association, Amritsar	4.000 M.T.
15	M/s. Amritsar Steel Fabricators Association, Amritsar	.. 10.000 M.T.
16	M/s. S.P.I. Quota Holder Association, Amritsar	.. 2.733 M.T.

**DISTRICT KARNAL (PANIPAT)**

1	M/s. Sangat Ram Steel Fabricator, Nilokheri	.. 2 M.T.
2	M/s. Hari Chand Steel Fabricator, Nilokheri	.. 2 M.T.
3	M/s. Maghina Trunk House, Panipat	.. 1 M.T.
4	M/s. Pharaya Lal-Jiwan Dass, Panipat	.. 2 M.T.
5	M/s. Ram Pyara Malm, Panipat	.. 2 M.T.
6	M/s. Chaman Lal-Khairati Lal, Panipat	.. 2 M.T.

[Chief Minister]

1	2	3
7	M/s. Vir Bhan-Aishi Lal, Panipat	.. 2. M.T.
8	M/s. Krishana Cooperative Industrial Society, Panipat	.. 2 M.T.
9	M/s. Hari Chand-Gulshan Rai, Panipat	.. 2 M.T.
10	M/s. Chanu Ram-Wazir Chand, Panipat	.. 2 M.T.
11	M/s. Krishnapura Iron Store, Panipat	.. 1 M.T.
12	M/s. Kundan Lal-Gita Ram, Panipat	.. 2 M.T.
13	M/s. Surinder Metal Industries, Panipat	.. 2 M.T.
14	M/s. Sobha Ram-Kishan Chand, Panipat	.. 1 M.T.
15	M/s. Basdeo Mal-Kashmiri Lal, Panipat	.. 2 M.T.
16	M/s. Sita Ram-Ram Sarup, Panipat	.. 2 M.T.
17	M/s. Bharat Trunk House, Panipat	.. 1 M.T.
18	M/s. Bhoj Raj-Jai Bhagwan, Panipat	.. 1 M.T.
19	M/s. Chandan Lal-Chatter Sain, Panipat	.. 1 M.T.
20	M/s. Banarsi Lal-Ashok Kumar, Panipat	.. 1 M.T.
21	M/s. Batra Steel Works, Panipat	.. 1 M.T.
22	M/s. Munshi Lal-Kewal Ram, Panipat	.. 1 M.T.
23	M/s. Chinot Trunk House, Karnal	.. 1 M.T.
24	M/s. Bharat Steel Works, Karnal	.. 1 M.T.
25	M/s. Zamindara Trunk House, Karnal	.. 1 M.T.
26	M/s. Girdhari Lal-Lal Chand, Karnal	.. 1 M.T.
27	M/s. Gujranwala Metal Works, Karnal	.. 2 M.T.
28	M/s. Lyallpur Steel Works, Karnal	.. 2 M.T.
29	M/s. Multani Trunk House, Karnal	.. 1 M.T.
30	M/s. Rashtrya Trunk House, Karnal	.. 1 M.T.
31	M/s. Chawala Trunk House, Karnal	.. 2 M.T.
32	M/s. Sujan Singh Steel Fabricator, Nilokheri	.. 1 M.T.
33	M/s. Kanshi Ram Steel Fabricator, Nilokheri	.. 2 M.T.
34	M/s. Jai Bharat Au son Industries, Karnal	.. 1 M.T.
35	M/s. Hans Trunk Hous Indri	.. 1 M.T.

(7)29

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

1	2	3
36	M/s. Ram Parshad Trunk House, Ladwa	.. 1 M.T.
37	M/s. Sharma Trunk House, Thanesar	.. 1 M.T.
38	M/s. Dharam Chand Steel Fabricator, Thanesar	.. 1 M.T.
39	M/s. National Manufacturers Traders, Kaithal	.. 2 M.T.
40	M/s. Mittal Iron Foundry, Samlkha	.. 4 M.T.
41	M/s. Aggarwal Iron Foundry, Samlkha	.. 4 M.T.
42	M/s. Devki Nandan Mittal, Samlkha	.. 1 M.T.
43	M/s. Nirankar Industries, Samlkha	.. 2 M.T.
44	M/s. Mohan Lal-Shiv Nath Rai, Samlkha	.. 2 M.T.
45	M/s. Tilak Raj Malhotra Trunk Maker, Nilokheri	.. 1 M.T.
46	M/s. American Industries, Samlakha	.. 2 M.T.
47	M/s. Chaman Lal, Steel Fabricator, Nilokheri	.. 1 M.T.
48	M/s. Satya Engineering Corporation, Panipat	.. 2 M.T.
49	M/s. Aggarwal Metal Industries, Kaithal	.. 4 M.T.
50	M/s. Telu Ram-Lekh Ram, Kaithal	.. 2 M.T.
51	M/s. Khurana Trunk House, Pehowa	.. 1 M.T.
52	M/s. Gupta Trunk House, Kaithal	.. 1 M.T.
53	M/s. B.L. Engineering Works, Kaithal	.. 1 M.T.
54	M/s. Janta Trunk House, Kaithal	.. 1
55	M/s. Jai Hind (I and S), Manufacturers, Kaithal	.. 1
56	M/s. Hari Chand-Dharam Chand, Kaithal	.. 1
57	M/s. Lal Chand-Lakhmi Chand, Kaithal	.. 1
58	M/s. Paul Trunk House, Assandh.	.. 1
59	M/s Nico Iron and Steel works, Kaithal	.. 1
60	M/s New India Tin Bucket and General Manufacturers, Kaithal	2
61	M/s Punjab General Manufacturers, Kaithal	.. 1
62	M/s Vishwakarma Industries, Kaithal	.. 4
63	M/s Kaithal Expeller Workshop Foundry, Kaithal	.. 1

[Chief Minister]

1	2	3
		M.T.
64	M/s Kaithal Wire Netting Production Coop ; Industrial Society Ltd., Kaithal.	1
65	M/s Lila Dhar-Karam Chand, Panipat	1
66	M/s Krishna Engg. Works, Railway Road, Panipat	3
67	M/s Deva Ram-Kishan Dutt, Panipat	1
68	M/s Ramesh Safe and Carding Works, Panipat	5
69	M/s Chinot Trunk House, Karnal	1
70	M/s Vishwakarma Engg. Works, Samalkhan.	2
71	M/s Ram Kishan Soni Steel Fabricator, Nilokheri	$\frac{1}{2}$
72	M/s Seema Indl. Corporation, V. Niawal.	$\frac{1}{2}$
73	M/s Asiatic Industries, Karnal	$\frac{1}{2}$
74	M/s True Tempo Auto Industries, Panipat	2
75	M/s Jai Hind Iron Foundry and Engg. works Samalkha	4
76	M/s Jai Bharat Hardware Co., Panipat	5
77	M/s Haryana Progressive Indl. Works, Panipat	5
78	M/s Hindustan Indl. Works, Panipat	5
79	M/s National Manufacturers and Traders, Kaithal	4
80	M/s Jai Bharat Auto Industries, Karnal	1
81	M/s Telu Ram-Lekh Ram, Kaithal	2
82	M/s Dev Dutt Vij, Karnal	4
83	M/s Jai Hind Iron and Steel Manufacturers, Kaithal	1
84	M/s Paul Trunk House, Assandh	1
85	M/s Vishwkarma Industries, Kaithal.	4
86	M/s Kaithal Exeller Workshop, Kaithal	1
87	M/s Kaithal Wire Netting Production Coop Indl. Society Ltd. Kaithal	1
88	M/s Lila Dhar Karam Chand, Panipat	1
89	M/s Dewa Ram Kishan Dutt, Panipat	1
90	M/s Vishwkarm Engg. Works, Samalkha	2

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (7)31  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

1	2	3
91	M/s Seema Indl. Corporation V. Niawal	1
92	M/s Ram Parshad Trunk House, Ladwa	1
93	M/s Guru Nanak Indl. Workshop, Ladwa	1
94	M/s German Production Coop ; Cycle Ind. Society Ltd., Karnal..	1
95	M/s Hukam Chand Balti Maker, Karnal	1
96	M/s Madan Metal works, Nilokheri.	1
97	M/s Batra Steel works, Panipat	1
98	M/s Raj Trunk Factory, Ladwa.	1
99	M/s Satya Engg ; Corporation, Panipat	1
100	M/s Mohan Lal-Sukhan Lal, Samalkha	2
101	M/s Balkishan Bhatia and Sons, Panipat	3
102	M/s Hargopal Bhati and Sons, Panipat	3
103	M/s Ravi Safe works, Panipat	3
104	M/s Mathra Dass Bhatia and Bros., Panipat	6
105	M/s Batra Steel works, Panipat	1
106	M/s Bhatia Engg. works, Panipat	2
107	M/s National Nail Industries, Nilokheri	1
108	M/s Chawala Trunk House, Karnal	2

DISTRICT ROHTAK

1	M/s Jain Trunk House, Rohtak	125 Kgms.
2	M/s Manohar Lal Trunk Manufacturer, Rohtak	160 Kgms.

DISTRICT PATIALA

1	M/s Pepsu Road Transport Corporation, Patiala	1.500 M.T.
2	M/s Thapar Institute of Engg. and Tech. Patiala	0.150
3	M/s Adarsh I, and St. Production Coop. Indl. Society Rajpura	8.000
4	M/s Bharat Indl. Coop. Society, Rajpura	10.000
5	M/s Himalayan Engg. Coop. Indl. Society, Rajpura	4.00
6	M/s Tulsi Ram-Pyare Lal Jain Patiala	2.000

[Chief Minister]

1	2	3
7	M/s Ashoka Steel Industries, Gobindgarh	.. 2,000
8	M/s Ahluwalia Trunk Factory, G. Garh	.. 2,000
9	M/s Bharat Trading Co. Patiala	.. 2,000
10	M/s Banny Traders, G. Garh	.. 4,00
11	M/s Bharat Industries, G. Garh	.. 2.00
12	M/s Chhaju Singh son of Runak Singh, Village and Post Office Bhandson Tehsil Nabha (District Patiala)	.. 4,000
13	M/s Mistri Dyal Chand, Township, Rajpura.	.. 2,000
14	M/s Durga Dass-Bant Ram Samana	.. 2,000
15	M/s Ganesh Trunk House, Rajpura Township	.. 2,000
16	M/s Gujranwala Steel Works, Patiala	.. 2,000
17	M/s Gupta Iron Stores, Banga	.. 2,000
18	M/s Gobind Ram Rajkumar, Lalru	.. 2,000
19	M/s G.R. Sewing Machine Co., Sirhind	.. 2,000
20	M/s Ganga Ram Madan Lal, Patiala	.. 2,000
21	M/s Hira Nand Hari Chand, Rajpura	.. 2,000
22	M/s Mistri Inder Singh Patiala	.. 2,000
23	M/s Mistri Durga Dass Patiala	.. 2,000
24	M/s Janta Trunk House, Rajpura Township	.. 2,000
25	M/s Jiwan La. Nathu Lal, Patiala	.. 2,000
26	M/s Janta Trunk Workshop, Patiala	.. 2,000
27	M/s Jai Industries, Gobindgarh	.. 6,000
28	M/s Jit Singh Amar Singh, Patiala	.. 2,000
29	M/s Jagir Singh Kulwant Singh, Gobindgarh	.. 2,000
30	M/s Sunrise Industries, Sirhind	.. 1,000
31	M/s Rup Chand Dharam Paul, Samana	.. 2,000
32	M/s Navyug Tradning Corporation Patiala	.. 10,000
33	M/s Malwa Toka Factory, Gobindgarh	.. 6,000
34	M/s Kay Jay Industries, Gobindgarh	.. 4,000

1

2

3

35	M/s Parma Nand-Indersain, Patiala	.. 2.000
36	M/s Megh Chand Jain & Sons, Patiala	.. 4.000
37	M/s Jarha Ram-Jeth Nand, Rajpura	.. 2.000
38	M/s Jai Dev-Loku Ram, Rajpura	.. 2.000
39	M/s Sindhi Trunk House, Rajpura	.. 2.000
40	M/s Salig Ram-Jiwan Lal, Patiala	.. 2.000
41	M/s Mangat Industries, Patiala	.. 9.000
42	M/s Mistri Waliti Ram, Patiala	.. 2.000
43	M/s Standard Electric Industries, Patiala	.. 4.000
44	M/s Ram Lal-Gopi Chand, Township Rajpura	.. 2.000
45	Works Manager, Pepsu Road Transport Corpn., Patiala	.. 1.000
46	M/s Beegee Switchgears (P) Ltd., Patiala	.. 5.000
47	M/s Asia Works (P) Ltd., Patiala	.. 5.000
48	M/s Rajpura Metal Industries, Rajpura	.. 7.000
49	M/s Sant Metal Industries, Patiala	.. 4.000
50	M/s Krishna Pipe and Iron Works, Rajpura Township	.. 2.000
51	M/s Manchanda Bros., Patiala	.. 4.000
52	M/s Norata Ram-Balkishan, Gobindgarh	.. 4.000
53	M/s Mohan Lal-Kewal Kishan, Patiala	.. 2.000 M.T.
54	M/s Patiala Trunk Factory, Patiala	.. 2.000
55	M/s Sardar Sons (Regd.), Patiala	.. 1.000
56	M/s Ujjagar Singh Jolly, Patiala	.. 2.000
57	M/s Tulsi Dass Blacksmith, Rajpura	.. 2.000
58	M/s Kartar Singh-Harbhajan Singh, Patiala	.. 4.000
59	M/s Banarsi Dass, Patiala	.. 2.000

#### DISTRICT HISSAR

1	M/s Kesho Ram-Rohan Lal, Sirsa	.. 0.250 M.T.
2	M/s Karyana Farm Machinery P.C.S., CIS, Ltd. Hansi	.. 0.250
3	M/s Bharat Trunk and Thread Ball Factory, Hansi	.. 0.250

[Chief Minister]

1	2	3
4	M/s Sujan Kumar-Dharam Pal, Sirsa	.. 0.250
5	M/s Narsing Dass-Ram Nath, Hissar	.. 0.860
6	M/s Karam Chand-Jagan Nath, Hissar	.. 0.500
7	M/s Chaudhry Trunk Factory, Bhiwani	.. 0.500
8	M/s Diwan Chand-Karam Chand, Hissar	0.500
DISTRICT MAHENDRAGARH (NARNAUL)		
1	M/s Arya Trunk Factory, Narnaul	.. 4 M.T.
DISTRICT HOSHIARPUR		
1	M/s Ohri Steel Works, Kashmere Bazar, Hoshiarpur	.. 1.916 M.T. (3 permits for 1.50, 0.200, 0.216 M. T.)
2	M/s Khalsa Engg. Works, Jullundur Road, Hoshiarpur	.. 1.000 M.T.
3	M/s Incharge Government Indl. Trg. Centre (Sheet Metal), Mahilpur	.. 1.000 M.T.
4	M/s Ishar Singh-Harbans Singh Purani Sabzi Mandi, Hoshiarpur	.. 1.930 M.T.
5	M/s Jaswant Singh & Sons, Kotwali Bazar, Hoshiarpur	.. 0.954 M.T.
DISTRICT BHATINDA		
1	Nil	
DISTRICT KANGRA AT DHARAMSALA		
1	M/s Sher Chand & Bros., V. and P.O. Bharoti	.. 0.200 M.T.
2	M/s Sarvjit and Iron Steel Works, Dharamsala	.. 0.200
DISTRICT SANGRUR (MALERKOTLA)		
1	Nil	
DISTRICT SIMLA		
1	M/s Sialkot Trunk House, Lower Bazar, Simla	.. 1M.T.
2	M/s Himachal Trunk House, Sanjauli (Simla)	.. 1 M.T.
DISTRICT ROHTAK (SONEPAT)		
1	M/s New Bharat Surgical I & E Industries, Indl. Area, Sonapat	1.500 M.T.
2	M/s Soorajmall Baijnath Industries (P) Ltd., Indl. Area, Sonapat	.. 0.750
3	M/s Lakshmi Metal Industries, Sonapat	.. 0.750
4	M/s Janta Iron and Steel Workers Co-op. Indl. Society Ltd., Sonapat	.. 1.000
5	M/s Hardeep Industries, Sonapat	.. 0.250

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (7)35  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

1	2	3
6	M/s Azad Steel Mfg. Industrial Co-op. Society, Sonapat	.. 0.500
7	M/s Ved Parkash-Ram Parkash, Sonapat	.. 0.500
8	M/s Sunrise Paint Industries, Sonapat	.. 0.500
9	M/s Adarsh Iron and Steel Works, Sonapat	.. 0.500
DISTRICT AMBALA (JAGADHRI)		
1	M/s Jagadhri Iron Works, Jagadhri	.. 922 Kgs.
2	M/s Mittal Metal Works, Jagadhri	.. 922
3	M/s Acme Steel Works, Y/Nagar	.. 464
4	M/s Parkash Steel Works, Y/Nagar	.. 464
5	M/s Batala Steel Industries, Y/Nagar	.. 464
6	M/s Durga Dass-Ved Parkash, Y/Nagar	.. 464
7	M/s Kharaiti Lal-Luxmi Chand, Buria	.. 464 Kg.
8	M/s Frontier Industries, Buaria	.. 464 Kg.
9	M/s Janta Steel Industries, Buria	.. 464 Kg.
10	M/s Damodar Dass & Sons, Buaria	.. 464 Kg.
11	M/s Suresh Chand & Sons, Buaria	.. 464 Kg.
12	M/s G.C. Jain and Co., Buria	.. 464 Kg.
13	M/s Atma Ram-Jassa, Ram Y/Nagar	.. 232 Kg.
14	M/s Ganpat Rai-Paras Ram, Jagadhri	.. 688 Kg.
15	M/s Milap Industries, Buria	.. 456 Kg.
16	The Principal, Industrial Training Institute, Yamunanagar	.. 218 Kg.
17	M/s Jindal Foundry and Engg. Works, Y/Nagar	.. 461 Kg.
18	M/s H.L. Chopra and Sons, Yamuna Nagar	.. 461 Kg.
DISTRICT KAPURTHALA—		
1	M/s Verma Trunk Works, Mandi Road, Phagwara	.. 300 Kg.
2	M/s Verma Trunk Works, Mandi Road, Phagwara	.. 500 Dg.
3	M/s Gupta Engg. Works, Kapurthala	.. 500 Kg.
4	M/s Gupta Engg. Works, Kapurthala	.. 500 Kg.
5	M/s Metro Engg. Works, Phagwara	.. 1.000 M.T.
6	M/s Santa Singh and Sons, Kalasinghian, District Kapurthala	.. 1.000 M.T.

(Chief Minister)

1	2	3
7	M/s Jamna Dass-Narain Dass, Kapurthala	.. 800 Kgs.
8	M/s Amin Chand-Bhagwan Dass, Kapurthala	.. 800 Kgs.
9	M/s Ganpat Rai Ganesh Dass, Kapurthala	.. 800 Kgs.
10	M/s Jolly Co., Industries, Dyalpur, district Kapurthala	.. 1.000 M.T.
11	M/s Walaiti Ram-Kashmiri Lal, Kapurthala	.. 800 Kgs.
12	M/s Vir Chand-Mangat Rai, Kapurthala	.. 800 Kgs.
13	M/s Sangdarshian Iron Works, Phagwara	.. 800 Kg.
14	M/s Masand Industries, Kapurthala	.. 1.500 M.T.
15	M/s Hira Singh,-Inder Singh, Phagwara	.. 1.000 M.T.
16	M/s Harish Kumar Ashok Kumar, Kapurthala	.. 800 Kg.
17	M/s Bhagwan Singh,-Ajit Singh, Phagwara	.. 800 Kg.
18	M/s Khalsa Trunk Works, Phagwara	.. 800 Kg.
19	M/s Thakar Singh, Niranjana Singh, Phagwara	.. 800 Kg.
20	M/s Kishan Singh & Sons, Phagwara	.. 800 Kg.
21	M/s Roada Mal-Kulwant Rai, Sultanpur	.. 800 Kg.
22	The Principal. Government Junior Technical School, Kapurthala	300 Kg.
23	M/s Saroop Singh, Harnam Singh, Phagwara	.. 1.000 M.T.
24	M/s Mehar Singh & Sons, Phagwara	.. 1.000 M.T.
25	M/s Jagan Nath,-Chaman Lal, Kapurthala	.. 1.000 M.T.

(b) The following permittees could not get supply against the above allotment —

1	Santa Singh & Sons, Village Kalasinghian, District Kapurthala	.. 1.000 M.T.
2	M/s Saroop Singh, Harnam Singh, Phagwara	.. 1.000 M.T.
3	M/s Mehar Singh & Bros. Phagwara	.. 1.000 M.T.
4	M/s Jagan Nath, Chaman Lal, Kapurthala	.. 1.000 M.T.

## ANNEXURE II

Copy of letter No. STL/1217/Misc./15772-J, dated 11th June, 1964, from the Director of Industries, Punjab, to M/s Amin Chand,-Pyare Lal, Tanda Road, Jullundur City.

**Subject.**—Release of imported G.P. Sheets.

You are requested to please release 4 tons of G.P. Sheets in favour of Shri Dev Dutt Viji, G.T. Road, Karnal against permit No. 33597, dated 13th January, 1964 issued by the District Industries Officer, Panipat against payment.

Endorsement No. STL/1217/Misc./15773-C, Dated 11th June, 1964.  
A copy is forwarded to —

- (i) Shri Dev Dutt Viji, G.T. Road, Karnal with a request to please arrange to lift the material from Jullundur against payment.
- (ii) District Industries Officer, Panipat with reference to his memo No. I&S/10016, dated 12th May, 1964. He is requested please to watch proper utilisation of material by Shri Dev Dutt Viji.

(Sd/-),  
Deputy Director (I.S.),  
for Director of Industries, Punjab.

**Purchase made by Controller /Additional Controller of Stores, Punjab  
from M/s Gian Chand Tirth Ram**

**\*9146. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister with reference to the reply to starred question No. 8532 included in the list of questions for 11th October, 1965, be pleased to state—

- (a) whether the enquiry which according to part (a) of the said reply was likely to be finalised shortly, has since been finalised; if so when and with what results; if not, the reasons therefor;
- (b) whether as a result of the said enquiry any action against any officer has been taken; if so, against whom; if no action has been taken, the reasons therefor;
- (c) whether as a result of the said enquiry, any case against any persons has been registered; if so, when, the provisions of law under which it has been registered and its present stage
- (d) the date when the enquiry referred to in part (a) above was started, the date when the complaint was received by the Chief Minister and the name of the Complainant?

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes, in the middle of December, 1965, but a further probe is being made on the basis of certain points raised by Comrade Ram Piara, M.L.A. in his meeting with the Home Secretary on the 31st January, 1966.

(b) and (c). No. This will depend on the final result of the enquiry.

(d) On the 23rd January, 1965. A complaint from Comrade Ram Piara, M.L.A., in the matter was received on the 21st July, 1964.

**Joint Directors in Directorate of Industries, Punjab**

**\*9175. Sardar Balwant Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total number of Joint Directors in the Directorate of Industries in the State at present together with the details of their functions, in each case;
- (b) the total number of sections in the said Directorate and the number of Gazetted Officers and non-Gazetted officials (excluding the field staff) working under each Joint Director;
- (c) whether each of the above-mentioned Joint Directors has been allotted equal/proportionate work?

**Shri Ram Kishan :** (a) Five. Other information is laid on the Table of the House as Appendix I.

(b) Excluding field staff, the Directorate of Industries has 35 Sections, 92 gazetted officers, 4 non-gazetted officers and 575 non-gazetted officials, including class IV employees. Other information is laid on the Table of the House as Appendix II.

(c) Yes.

**APPENDIX I**

**Statement showing the functions of Joint Directors of Industries.**

**1. Joint Director (Administration)**

**1. Administrative.**

Control of the Department as a whole, including Establishment, Budget and accounts. Inspections of the field office and Establishments.

**2. Joint Director (Industrial Procurement)**

1. Industrial Projects.
2. Large and Medium scale industries including licensing.
3. Study, collection and dissemination regarding Industrial Policy.
4. Information Bureau, including Committees and Exhibitions.
5. Statistics.
6. Survey, including economic enquiries.
7. Planning for future growth.
8. Liaison with Industry Government Departments and various Institutions, Boards and Committees, including Universities.
9. Evaluation.
10. Institutions  
(Other than Punjab, State Small Industries Corporation).
11. Plan work (Five-Year Plans).
12. Publicity and Public Relations work relating to orders from railways/Electricity Board/Post and Telegraphs/ Health, etc.
13. Co-ordination of Building Programme and acquisition of land.
14. The work relating to the Electricity Board/Planning and Development Board and Punjab Financial Corporation.
15. Protocol work.
16. Co-ordination of work relating to grant of loan to Large and Medium and Small Scale Industries in relation to the Punjab Financial Corporation.

**3. Joint Director (Small Industries)**

1. Procurement and Supplies.
2. Small Industries, including Powerlooms and Hosiery Industry.
3. Loan cases at State level, i.e., all loans granted under the Punjab State Aid to Industries Act, 1935.
4. Industrial Areas/Estates.
5. Work connected with State Orphanage Advisory Board.
6. Punjab State Small Industries Corporation.

**4. Joint Director (Village Industries)**

1. Industrial Co-operative.

2. Handicrafts.  
(Handicraft Centres, Emporia, Designs Institute Dyeing and Calico Demonstration Parties).
3. Handlooms (Handloom Schemes, Textile Organisation, including Marketing, Development and Designs Cell and Handloom Development Centres).
4. Khadi and Village Industries, Board.

5. Joint Director (Rural Projects)

1. Rural Projects.
2. Leather Industry, including Tanning Institute.
3. Sericulture.
4. Tea Industry.
5. Liaison with hill areas, including Lahaul and Spiti.
6. Agro-Industrial Corporation.
7. Defence orders.
8. Export Promotion.

APPENDIX II

Statement showing Sections and Staff under various Joint Directors.

Section	Gazetted Officers	Non-Gazetted Officials
1	2	3
<b>Joint Director (Administration)</b>		
1. Administration Section I	Assistant Director (Administration I)	(a) Head Assistants 3 (b) Assistant 17
2. Administration Section II	Assistant Director (Administration II)	(c) Clerks 51 (d) Stenographer 2
3. Administration Section III		(e) Steno-typist 1 (f) Daftries 3
4. Issue Reception and Watch and Ward		(g) Peons 24 (h) Machine men 2 (i) Restorer 1
5. Accounts and Cash Section	Accounts Officer (Administration)	(a) Head Assistant 1 (b) Assistants 4 (c) Accountant 1 (d) Cashier 1 (e) Clerks 7
6. Budget Section		(a) Head Assistant 1 (b) Caretaker 1 (c) Store Clerk 1 (d) Assistants 5 (e) Stenographer 1 (f) Clerks 5 (g) Drivers 3 (h) Peons 6 (i) Sweepers 6 (j) Chowkidar 2

[Chief Minister]

Section	Gazetted Officers	Non-Gazetted Officials
1	2	3
<b>Joint Director (IP)</b>		
1. Industrial Projects	Officers on Special Duty (IP)	(a) Assistants 1 (b) Steno 1 (c) Peons 1
2. Large and Medium Scale Industries Section	Assistant Director (IP)	(a) Head Assistant 1 (b) Assistants 2 (c) Clerks 3 (d) Steno-typist 1 (e) Peons 2
3. Planning Section	Deputy Director (Planning)	(a) Head Assistants 1 (b) Assistants 2 (c) Clerks 3 (d) Stenos 2 (e) Peons 2
4. Information Bureau	Assistant Director (IB)	(a) Assistants 2 (b) Librarian (Vacant) 1 (c) Clerks 5 (d) Peons 2
5. Statistics		(a) Research Assistant 1 (b) Assistants 2 (c) Steno 1 (d) Computer 1 (e) Clerks 1
6. Industrial Survey Section	(a) Deputy Director (Survey) (b) Research Assistant (Vacant) (c) Research Officer Chemical (d) Research Officer Production (e) Research Officer Mechanical	(a) Steno 3 (b) Clerks 3 (c) Peons 3
7. Liaison Agency New Delhi	(a) Liaison Officer (Industries)  (b) Assistant Liaison Officer	(a) Head Assistant 1 (b) Assistant/Accountants 1 (c) Steno 1  (a) Steno-typist 1 (b) Junior Steno-grapher 1 (c) Clerk 1 (d) Peons 3 (e) Driver 1 (d) Chowlidar-Cum-Mali 1

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (7)41  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Section	Gazetted Officers	Non-Gazetted Officials
1	2	3
<b>Joint Director (S.I.)</b>		
<i>Industrial Supplies—</i>		
1 E.C. (Steel) Section	(i) Deputy Director (S.I.)	(a) Superintendent 1
2 E.C. (Non-Steel) Section	(ii) Assistant Director (P.I.)	(b) Head Assistant 3
3 Non-ferrous Metals Section	(iii) Assistant Director (Steel)	(c) Industrial Supplies Officer 1 (d) Junior Inspector 1
4 Steel (indigenous) Section	(iv) Assistant Director (Prac.)	(e) Assistants 17 (f) Clerks 19 (g) Restorer 1
5 Coal, Pig Iron and Miscellaneous	(v) Development Officer (Miscellaneous) (Now posted in the field)	(h) Peons 8 (i) Steno to J.D.S.I. 1
6 Small Industries Section	(vi) Deputy Director (S.I.)	(j) Steno to D.D.I.S. 1
	(vii) Assistant Director (Textile)	(k) Steno-typist 3 (a) Superintendent 1 (b) Assistants 4 (c) Inspector Hosiery 1 (d) Clerks 3 (e) Peons 5
<i>7 Loan Section.—</i>		
Loan Advancements	(i) Deputy Director (Loan)	(a) Head Assistants 3
Loan Recovery-1	(ii) Assistant Director (Loan)	(b) Legal Assistants 1
Loan Recovery 2	(iii) Assistant Accounts Officer (Loan)	(c) Auditors 4 (d) Assistants 16 (e) Clerks 19 (f) Restorer 2 (g) Peons 6 (h) Steno grapher 1 (i) Steno-typist 2
8 Industrial Estates	(i) Deputy Director (I.E.)	(a) Head Assistant 1
	(ii) Assistant Director (I.E.)	(b) Assistants 4
	(iii) Development (M)...one	(c) Clerks 5 (d) Rent Collector 1 (e) Accountant 1 (f) Stenographer 1 (g) Steno-Typist 2

[Chief Minister]

Section	Gazetted Officers	Non-Gazetted Officials
1	2	3
		(h) Peons 4 (i) Chowkidar 1 (j) Mali 1 (v) Sweeper 1
<b>Joint Director (V.I.)</b>		
1 Industrial Co-operative Societies	(i) Deputy Registrar	(a) A.A.O., Industrial Co-operative 1
	(ii) Deputy Registrar (II)	(b) Head Assistant 3
	(iii) Tanning & Leather Expert	(c) Assistants 9
	(iv) Industrial Assistant Registrar	(d) Stenos 3
		(c) Clerks 6 (f) Peons 5
2 Handicrafts	(i) Deputy Director (H)	(a) Head Assistant 1
	(ii) Development Officer (P)	(b) Assistants 3
	(iii) Development Officer (H), Palampur	(c) Stenos 2
		(d) Steno-gtypist 1 (e) Clerks 2 (f) Peons 3
3 Handlooms	State Handloom Officer	(a) Assistants 2
		(b) Clerks 8 (c) Steno 1 (d) Peon 1
4 Village and Khadi Industries	Asstt. Director (V. I.) Part-time	(a) Assistant 1 (b) Clerk 1 (c) Restorer 1
<b>Joint Director (R. P.)</b>		
1 Rural Projects	(i) Deputy Director (HA)	(a) Head Assistant 1
	(ii) Deputy Director (RI)	(b) Assistants 11
	(iii) Asstt. Director (E)	(c) Stenographer 3
	(iv) Asstt. Director (VI) Part-time	(d) Steno-typist 0
	(v) Asstt. Director (RI)	(e) Clerks 9 (f) Driver 1 (g) Peons 7

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (7)43  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Section	Gazetted Officers	Non Gaetted Officials
1	2	3
	(vi) Carcass Leather and Marketing Officer	
	(vii) Development Officer (Leather)	
	(viii) Development Officer (H. A.)	
	(ix) Tea Development Officer	
2 Defence Production and Export Promotion Section	(i) Officer -on Special Duty (E)	(a) Export Promo- tion Officer 1
	(ii) Asstt. Director (S. I. I.)	(b) Head Assistant 1
	(iii) Asstt. Director (S. I. (II)	(c) Assistants 4
		(d) Steno-typist 3
		(e) Clerks 4
		(f) P.A. to Hony. Adviser 1
		(g) Stenographer to Hony. Adviser 1
		(h) Peons 3
		(i) Draftsman 1
		(j) Tracers 2
		(k) Chowkidar 1
		(l) Mali 1
<b>Posts in abeyance</b>		
	(i) Deputy Directors 3	
	(ii) Development Officer 3	
	(iii) Production-cum-mar- keting Officer 1	

**APPENDIX III**  
**Statement showing details of schemes and staff in Technical Director, Geological**  
**and Poultry Wings**

Section	Gazetted Officers	Non-gazetted Officers
<b>POULTRY WING</b>		
30. Poultry Section	Technical Expert                      One	Head Assistant                      1 Assistants                              2 Clerks                                    2 Stenos                                    2 Peons                                     3 Driver                                    1
<b>GEOLOGICAL WING</b>		
Geological Section	(a) State Geologist                      1 (b) Junior Geologists                    2 (c) Asstt. Mining Engineer              1 (d) Asstt. Drilling Engineer            1 (e) Asstt. Geologists                    8 (f) Asstt. Chemists                      2 (g) Drillers                                2	Technical Assistants                      5 Drilling Assistants                        4 Surveyors                                  3 Draftsman                                  2 Rigmen                                     8 Carpenter                                  1 Mechanic                                   2 Heavy Truck Drivers                      2 Drivers                                     3 Section Cutter                            1 Laboratory Asstt.                        1 Technical Bearers                        4 Laboratory Attendant                    1 Artists                                    1 Cleaners                                   2 Head Assistant                           1 Assistants                                1 Asstt. -cum-Accountant                   1 Store Clerk                                1 Store Assistant                           1 Store-keeper                              1 Stenographer                              2 Clerks                                     4 Chowkidar                                1 Peons                                      11 Statistical Asstt.                        1 Legal Assistant                           1 Steno-typist                              1 Driver                                     1
<b>TECHNICAL WING</b>		
Production Engineering	Technical Expert (P.E.) Technical Director Technical Expert (M.E.)	Head Asistants                      3 Assistants                              9 Clerks                                    5
Mechanical Engineering	Technical Expert (C.E.) Deputy Director (Tech.) Asstt. Director (P.I.P.)	Stenographers                        4 Junior Draftsman                        1 Steno-typist                              3
Pig Iron Plant Section	Assistant Director (Tech. I) Asstt. Director (Tech. II) Assistant Director (Tech. III)	Peons                                    9 P.A. to T.D.                            1 Driver                                    1
Chemical Engg.	Development Officer (Engg.) Development Officer (Black-smithy) Development Officer (Carpentry) Executive Officer (Trg.) Sub-Divisional Officer	Tech. Officer (Engg.)                      1

SCHEMES INITIATED/ABANDONED BY THE INDUSTRIES DEPARTMENT IN THE STATE

**\*9177. Sardar Balwant Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number and names of new schemes initiated by the Department of Industries in the State during the last two years ;
- (b) the number and names of the schemes which the said department closed/abandoned, during the said period and the reasons therefor ;
- (c) the budget estimates of the said department for the year 1963-64 and actual expenditure incurred by it in the year 1965-66 ?

**Shri Ram Kishan :** (a) 34. A list of such Schemes is laid on the Table of the House (Annexure 'A')

(b) 14. The requisite information is laid on the table of the House (Annexure 'B')

(c) Rs. 3,24,60,770. The actual expenditure incurred during the year 1965-66 upto the month of December amounted to Rs. 1,73,56,820.

ANNEXURE 'A'

List of new schemes started during the year 1963-64 and 1964-65

1. Scheme for the establishment of Public Sector Industrial Project Pig Iron Plant.
2. Scheme for the establishment of Public Sector Industrial Project-Steel Castings.
3. Scheme for the setting up of Air Rifles Factory.
4. Scheme for the setting up of Watch Factory.
5. Scheme for the Hide Flaying and Carcass Utilisation Centres.
6. Scheme for setting of Central Procurement Cell and participation in Exhibitions and shows by Government Emporia.
7. Scheme for processing of Khandasari Units.
8. Scheme for Training of Weavers.
9. Scheme for establishment centre for imparting training in pattern making.
10. Scheme for the extension and Promotion of Designs activities in the State.
11. Schemes for the establishment of a factory for the manufacture of tin containers in Kangra District.
12. Scheme for the purchase and maintenance of a station wagon for sericulture.
13. Scheme for training of candidates at the All-India Sericulture Training Institute, Mysore.
14. Government contribution towards loss sustained for participation in New York Fair.
15. Scheme for the payment of guaranteed amount for the loan from the Punjab National Bank to the Hosiery manufacturers of Ludhiana Bad debt losses.
16. Scheme for the Industrial Survey of the State Creation of Survey Cell.
17. Scheme for setting up of the Punjab Poultry Corpn.

[Chief Minister]

18. Scheme for the introduction of Production in Handicrafts Training Centre in Simla District by opening Doll Making Centre at Simla.

19. Scheme for the Central Design Organisation at Ludhiana.

20. Scheme for the Regional Research Laboratory at Chandigarh.

21. Scheme for the participation in share capital of Kangra Tea Planters Supply and Marketing Society Ltd.

22. Participation in share capital of the Co-operative Bir Tea Factory Ltd., Kangra.

23. Scheme for share capital loan to the Industrial Co-operative for purchasing shares of big Industrial Projects.

24. Scheme for granting loans to the Industrial Co-operatives at concessional rate of interest.

25. Share capital participation in the shares of Tea Marketing Society.

26. Grant of managerial subsidy to Industrial Co-operative Bank being set up at Jullundur.

27. Scheme for provision of irrigation and other improvements in the existing farms.

28. Establishment of Basic Mulberry Nursery cum Demonstration Farm, Nadaun.

29. Appointment of Additional Deputy Wool Controllers.

30. Continuance of staff sanctioned for the establishment of Public Sector Industrial Projects.

31. Supervisory, Inspection and Audit Staff for Reserve Bank of India for advancing credit facilities to Handloom Weavers.

32. Co-operative Spinning Mills.

33. Seamless Tube Mills.

34. Scheme for the establishment of Punjab Industrial Development Corporation Ltd.

#### ANNEXURE 'B'

**List indicating the names of the schemes closed or abandoned during the year 1963-64 and 1964-65**

1. *Scheme for the establishment of Public Sector Industrial Project—Air Rifle Manufacturing Plant.*—The scheme for setting up an Air Rifle Factory was abandoned in October, 1964 because the original estimates of capital outlay were increased 100 per cent by the company and the marketing of a continuous production of 1,80,000 rifles annually, as contemplated under the scheme was not considered to be feasible.

2. *Scheme for the establishment of Public Sector Industrial Project—Watch Factory.*—A provision of Rs 50,000 had been made in the Budget for 1963-64 for preliminary expenditure on a watch factory, but as no foreign collaboration for setting up the industry could be found, the scheme was not started.

3. *Scheme for the Re-organisation of Cottage Industries Museum Emporium, Chandigarh.*—The scheme was closed as the object of starting this scheme was achieved. This scheme was meant for decorating and furnishing of Chandigarh Emporium.

4. Scheme for the training-cum-production centre for bamboo goods at Dharampur.

5. Scheme for Stone and Marble Carving Training-cum-Production Centre, Narnaul.

6. *Scheme of production centre for Druggets at Panipat.*

The closure of these schemes is on the basis of review of these centres by the Department keeping in view their further scope.

7. *Scheme for the provision of Study Tour of Artisan members of the Industrial Co-operatives.*—The Members of the Co-operative Societies were allowed expenses of their touring to the extent of Rs. 100 which was given as subsidy to one member of the Co-operative unit. Since the poor artisan members were not in a position to bear expenditure of 50 per cent on long Railway and Road journeys, and there was not proper response hence dropped.

8. *Share Capital loans to the Industrial Co-operatives for purchasing shares of Big Industrial Projects.*

9. *Grant of Managerial Subsidy to Industrial Co-operative Bank being set up at Jullundur.*

10. *Scheme for granting loans to the Industrial Co-operative at concessional rate of interest.*

11. *Share Capital participation in the shares of Tea Marketing Society.*—In response to the State's Call for having in various schemes to provide funds for Flood Relief, the amount provided for the above schemes was surrendered for its utilisation towards flood relief schemes.

12. *Scheme for the establishment of a factory for the manufacturing of Tin containers in the Kangra District.*—The scheme was dropped, being uneconomical.

13. *Tapestry Training Centre.*—As the trainees already trained were to settle themselves in the trade by organising themselves into co-operative societies, it was decided by the Department to close the centre with effect from 1st June, 1963 when the 3rd batch of trainees was to complete their course.

14. *Licensing of Khandasari Units.*—The scheme was transferred to Cane Commissioner as he was declared licensing authority.

**Starting Industrial Training School in Amb Constituency of  
Hoshiarpur District**

**\*9220. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether he is aware of the fact that there is no certificate Industrial Training School in the Amb Constituency of Hoshiarpur District which is a backward hilly area ;
- (b) whether the Government intend to open at least one such school in this vast hilly area during the Fourth Plan period ;
- (c) the steps which the Government intend to take to impart training to women in some crafts during the Fourth Plan period in the said constituency ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes.

(b) There is no programme to open any new Industrial School in the State during the 4th Plan period.

(c) Two Industrial Schools for Girls, one each at Nangal and Hoshiarpur are already functioning.

**Stipends given to Students in the Industrial Training Institutes in the State**

**\*9376. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the rate at which stipends are given to the students studying in the Industrial Training Institutes in the State ;

[Comrade Bhan Singh Baura]

(b) the details of the special facilities, if any, being given to the Scheduled Castes students studying in the said Institutes ;

(c) the percentage of the students receiving the said stipends.

**Shri Ram Kishan :** (a) At Rs. 25 per mensem to 33 per cent of the trainees.

(b) 20 per cent of the seats and stipends are earmarked for the Scheduled Castes trainees.

(c) 20 per cent of the Scheduled Castes trainees are granted stipends out of the regular schemes and the rest are granted stipends under the Scheme "Removal of Untouchability" subject to availability of funds.

#### Expenditure Incurred on State Guests

**\*8935. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the persons with their status who were treated as State Guests in the year 1965 together with the expenditure incurred by the Government on each such guest ;

(b) the total expenditure incurred by the Government on the State Guests, year-wise, since 1960 up-to-date ?

**Shri Ram Kishan :** (a) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(b) A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

Statement showing the total expenditure incurred by the Government on the State Guests year-wise since 1960

		Rs	P
1960-61	..	78,526.	70
1961-62	..	77,612.	73
1962-63	..	64,603.	00
1963-64	..	74,451.	67
1964-65	..	1,47,972.	75
1965-66	..	56,701.	69
(from 1st April, 1965 to 31st December, 1965)			

#### Commissions Appointed by Government in the State

**\*9131. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Commissions appointed by the Government in the State during the period from June, 1964 upto January, 1966, the purpose for which these were appointed and the period of their appointment in each case ;

(b) the total amount so far spent on each such Commission separately ;

(c) the number of the said Commissions which have since submitted their Reports to the Government ?

**Shri Ram Kishan :** The required information is placed on the Table of the House.

ANNEXURE

(a) Serial No.	Name of the Commission	Purpose	Period of appointment
1	2	3	4
1	Administrative Reforms Commission	It was set up with a view to enquire into the various aspects of the administrative machinery in the State & to make recommendations to the Government to improve the procedure and methods of Government and to bring them in tune with the present day democratic set up	9th October, 1964 to 21st February, 1966
2	Commission of Inquiry	The District & Sessions Judge, Jullundur was appointed to enquire into the cause of death of Shri Parkash Chand, an undertrial prisoner in Civil Hospital, Jullundur	11th January, 1965 to 28th February, 1965
3	Commission of Inquiry	The District & Sessions Judge, Jullundur was appointed to enquire into the causes which led to the clashes between some groups of students and the Punjab Roadways staff at Jullundur and the sequence of events as they took place.	5th August, 1965 to 31st October, 1965
4	Punjab State Vigilance Commission	To enquire into the complaints of corruption against Government servants. The purpose is explained in details in Punjab Government Notification No. 1899-VI(I)-65/2437, dated the 8th March, 1965 (Appendix 'N')	August, 1965 to July, 1970
(b) (i)	Administrative Reforms Commission	..	Rs. 2,54,484.58
(ii)	Commission of Inquiry Jullundur	..	Rs. 4
(iii)	Commission of Inquiry Jullundur	..	Rs. 8.78P.
(iv)	Punjab State Vigilance Commission	..	Rs. 27,021.29
(c)	.....	3.	

APPENDIX N

(Extract from the Punjab Government Gazette (Extraordinary), dated the 9th March, 1965)

VIGILANCE DEPARTMENT  
Notification  
The 8th March, 1965

No. 1899-VI(I)-65/2437.—The Governor of Punjab is pleased to constitute the following Organisation for the purposes hereinafter appearing :—

1. The Organisation may be called the Punjab State Vigilance Commission (hereinafter referred to as the Commission).

[Chief Minister]

2. The Commission shall, unless otherwise directed by the State Government from time to time, be attached to the State Vigilance Department.

3. (1) The Commission shall have jurisdiction and powers in respect of the following matters namely:—

(A) To undertake any inquiry into any transaction in which a Government servant is suspected of having acted in a corrupt manner which may be referred to it by the State Government except a transaction relating to misconduct or misdemeanour of a Government servant not involving corruption.

(B) To undertake or cause an inquiry or investigation to be made into —

(i) any complaint of corruption and lack of integrity involving a Government servant which may be referred to it by the State Government ;

(ii) any other complaint or information specially entrusted to the Commission by the State Government in which a Government servant may or may not be involved.

(C) To call for reports, returns and statements from all departments of the State Government or undertakings so as to enable the Commission to bring about general liaison and co-ordination over the vigilance and anti-corruption work in such departments and undertakings.

(D) To take over under its direct control such complaints, information or cases for further action, namely :—

(i) to ask the Special Inquiry Agency to register a regular case and investigate it, or

(ii) to entrust the complaint, information or case for inquiry to the Special Inquiry Agency or to the Department or undertaking concerned, or

(iii) to hold itself an inquiry by taking evidence.

*Note I.*— The Commission may not be burdened with complaints against non-gazetted officials except when the complaint substantially involves a gazetted officer also.

*Note II.*—The Commission shall not take cognizance of anonymous and pseudonymous complaints unless referred to it by the State Government.

*Note III.*—The term “Government servant” does not include Ministers and non-officials such as members of Municipal Committees, Panchayats, Panchayat Samities, Zila Parishads or other local authorities, and office holders of Co-operative Societies and Universities.

(E) To advise the State Government in the matter of black-listing of any firm which might come to its adverse notice during an enquiry .

(2) In cases referred to in paragraph (D) (ii) above, the report of the inquiry shall be forwarded to the Commission so that on consideration of the report and relevant records it may advise the Department or undertaking concerned as to further action to be taken in the matter.

(3) In cases where the report of inquiry has been forwarded to the Commission by the Special Inquiry Agency, the Commission shall, while considering such report, obtain the comments of the Department or undertaking concerned.

(4) Where the Special Inquiry Agency considers that a prosecution should be launched and where prior sanction for such prosecution is required under any law for the time being in force, the Agency shall simultaneously send a copy of its report to the Department or undertaking concerned for any comments which it may wish to forward to the Commission.

(5) Where the authority competent to sanction such prosecution—

(a) is the State Government, the Commission will advise the Vigilance Department, after examining the case and considering any comments received from

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (7)51  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

the Department or undertaking concerned, whether or not prosecution should be sanctioned, whereafter the necessary order will be issued by the Vigilance Department in which the power to accord sanction shall vest; and

- (b) is an authority other than the State Government, and that authority does not propose to accord the sanction sought by the Special Inquiry Agency, the case shall be returned to the Commission and the aforesaid authority shall take further action after considering the advice of the Commission.

(6) The Commission may entrust an oral inquiry in any departmental proceedings, except in petty cases, to one of the Commissioners for Departmental Inquiries attached to the Commission.

(7) The Commissioner for Departmental Inquiries shall submit his report to the Commission and the Commission shall, after taking into consideration the comments of the Department or undertaking concerned and examining the report and such comments, forward the record of the report to the appropriate punishing authority with its advice as to further action to be taken in the matter.

(8) Where the Commission finds that discretionary powers in the discharge of his duties were exercised by a Government servant for improper or corrupt purposes, the Commission shall advise the Department or the undertaking concerned that suitable action be taken against the Government servant concerned; and if it appears to the Commission that any practice or procedure followed by the Department or undertaking is of such a nature that it affords scope for corruption or misconduct, the Commission may advise that such practice or procedure be appropriately altered or abandoned and the Commission may suggest the manner for doing so.

(9) The Commission may, at such intervals as it may consider necessary, initiate review of all practices and procedure of administration in so far as they relate to the maintenance of integrity in administration.

(10) The Commission may collect such statistics and other information as may be necessary.

(11) The Commission may obtain information about the action taken on its recommendations.

(12) The Commission shall submit to the State Government in the Vigilance Department monthly statements of all the inquiries made by it with all material particulars along with the details of the nature and scope of such inquiries, and return the Commission shall have the power to call for similar statements from the various Departments or undertakings of the State Government regarding inquiries conducted by them into complaints of corruption against Government servants.

(13) The Commission shall submit an annual report to the State Government in the Vigilance Department about its activities drawing particular attention to cases in which its advice has not been accepted or acted upon.

4. The Commission shall be provided with such staff, including such number of legal advisers and technical officers, as may be necessary for the proper discharge of its duties and responsibilities.

5. The head of the Commission shall—

- (a) be designated "Chairman, Punjab State Vigilance Commission";
- (b) be appointed by the Governor of Punjab by warrant under his hand and seal;
- (c) be removable in the same manner as the Chairman or Member of the State Public Service Commission;
- (d) hold office for a period of four years or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier;

Provided that the first head of the Commission shall hold office for a period of five years not withstanding his attaining the age of sixty-five years;

## [Chief Minister]

- (e) on ceasing to hold the office of the Chairman of the Commission, be ineligible for any other employment under the State Government or for holding any political or public office within the Punjab State for which purpose the Chairman of the Commission shall furnish a written undertaking to the State Government ;
- (f) for the present be of the status of the Chairman, State Public Service Commission, but in the exercise of his powers and functions not be subordinate to any Department of the State Government ; and
- (g) by convention be for the present given the same measure of independence and autonomy as the Chairman of the State Public Service Commission.

*Note.*—The Chairman of the Commission shall have the same place in the warrant of precedence which he held in accordance with his status prior to his appointment as such Chairman if the same was higher than that of the Chairman of Punjab State Public Service Commission.

6. Besides the Chairman, the State Government may appoint one or two other members of the Commission and the provisions contained in sub-paragraphs (d) and (e) of paragraph 5 shall apply to such member or members as they apply to the Chairman of the Commission.

7. The Secretary of the Vigilance Department, who shall be appointed by the State Government from amongst the Senior Secretaries to the Government, shall, in his *ex-officio* capacity act as an Associate Member of the Commission and shall serve as a link between the State Government and the Commission and shall be entitled to be consulted by the Commission in all important matters.

8. (1) In every department or undertaking of the State Government there shall be one Chief Vigilance Officer and a requisite number of Vigilance Officers who shall be appointed subject to the advice of the Commission. The Chief Vigilance Officer shall, as far as practicable, be an officer next in rank to the Secretary to the Government or the Head of the Department, as the case may be, and will work under his supervision. They will not be whole-time officers but will be nominated to do this work in addition to their normal duties. While an officer not approved by the Commission may not be appointed as a Vigilance Officer, the control over the working and conduct of these officers shall be exclusively that of the Secretary to the Government or the Head of the Department, as the case may be.

(2) The holding of inquiries, supervision over investigations drawing up of formal charge-sheets, compliance with procedural or legal requirements of these inquiries, consultation with the Commission and final disposal of cases shall be decentralised and will become the responsibility of the Department or undertakings concerned.

(3) The Special Inquiry Agency shall be an independent department, appointments to which shall be made on tenure basis subject to the concurrence of the Commission. The annual assessment of the work of the head of this Department will be made by the Secretary, Vigilance Department, as initiating authority and by the Chairman of the Commission as final reporting authority.

9. The investigating staff at present functioning under the Deputy Inspector-General of Police, Vigilance, shall be withdrawn from the Police Department and shall be constituted into a separate department with the officer of a rank of Deputy Inspector-General of Police as its head and shall be designated as "Special Inquiry Agency". The Deputy Inspector-General in charge of this Department will be designated as "Director" Special Inquiry Agency". The Officers of this Department shall continue to enjoy the powers of investigation vested in the Police Officers of the general police district as is the case at present and, if legally necessary, a fresh notification shall be issued for continued vesting of these powers in them. The Secretary to Government, Punjab, Vigilance Department, shall be the Administrative Secretary of this Department.

10. The Vigilance Department and its Secretaries counterpart as at present constituted shall be wound up and its staff of technicians and specialists as well as legal advisers shall be placed under the control of the Commission. This staff shall be available

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (7)53  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

at all times and on all occasions for consultation with, and giving opinions to, the officers of the Special Inquiry Agency and other departments in processing their cases.

11. The Commission shall take the initiative in prosecuting persons who are found to have made false complaints of corruption or lack of integrity against Government servants.

S. K. CHHIBBER,  
Secretary to Government, Punjab,  
Vigilance Department.

**Haryana Development Committee**

**\*9262. Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Haryana Development Committee submitted an interim report to the Government ; if so, the action, if any, taken to implement the recommendations contained in the said report and the amount spent by the Government on their implementation ;

(b) the time by which all the recommendations made in the said report are likely to be completely implemented ;

(c) whether the Government intend to publish the interim report for the information of the public, if so, when ;

(d) a copy of the interim report be laid on the Table of the House ?

**Sardar Ajmer Singh :** (Minister for Planning and Local Government) :

(a) & (b) Yes, Sir. The Haryana Development Committee has since submitted its final report also on 27th January, 1966. The recommendations of the Committee are under consideration with Government.

(c) No.

(d) A copy of the interim \*report is laid on the table of the House.

**Haryana Development Committee**

**\*9263. Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Haryana Development Committee has submitted its final report† to the Government ; if so, the date when it was submitted ;

(b) whether the Government propose to publish the said report and make it available to the Members of the State Legislature, if so, when ;

(c) the details of the recommendations made in the report of the said Committee which the Government proposes to implement, the time by which these are proposed to be implemented and the estimated amount to be spent thereon ?

**Sardar Ajmer Singh** (Minister for Planning and Local Government) :

(a) Yes; on 27th January, 1966.

(b) Copies of the final report of the Haryana Development Committee have already been made available to the members of the State Legislature.

(c) The report is under consideration of the Government.

---

†Note.—Interim Report of the Haryana Development Committee is kept in the Library.

**Recruitment of Draftsmen**

**\*9448. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether the Subordinate Services Selection Board invited applications for the recruitment of draftsmen during the period from 1st April, 1965 to 31st December, 1965 ;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the total number of applications received together with the number of candidates called for interview and the number of those who appeared for interview, respectively.

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes.

- (b) (i) 584
- (ii) 504
- (iii) 469

**Bus fares from Khanna to Ludhiana and Khanna to Chawa Pail**

**\*9154. Lieut. Bhag Singh :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state whether the Punjab Roadways charge from the passengers travelling by its buses different rates of fare from Khanna (district Ludhiana) to Ludhiana and Khanna (district Ludhiana) to Chawa Pail (district Ludhiana), if so, the amount of difference in each case and the reasons therefor ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (i) No.  
(ii) Does not arise.

**Loss suffered by Border Villages during the Recent Indo-Pak Conflict**

**\*9226. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the details of loss of life, household properties, cattle and crops which occurred because of the recent Indo-Pak hostilities in the villages in Amritsar, Ferozepore and Gurdaspur Districts during the period from September, 1965 to date village-wise and district-wise ;
- (b) the details of the help given by the Government in cash or kind to the affected people in Amritsar District, village-wise ;
- (c) the total number of men and women taken away by the Pakistani forces from the border villages of Amritsar District during the said conflict ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) The number of the civilians killed in Amritsar, Ferozepore and Gurdaspur Districts is reported to be 126, 38 and 6 respectively. As regards the losses of movable property and cattle, damage to crops and immovable property, etc., an assessment will be made as soon as the areas are vacated by the Pakistan or are declared by the Indian Army Authorities as accessible to the civilians.

(b) A statement is laid on the Table of the House. The village-wise break up of the details of the expenditure is not practical.

(c) 179.

Statement indicating the help given to uprooted persons in Amritsar District

	<i>Amount distributed in Amritsar District</i>
(i) <i>Ration in kind or cash—</i>	
(a) Wheat flour/wheat is being issued on the scale of 16 Kilograms per Adult and 10 kilograms per child per month	10,460 Quintals distributed
(b) Cash grant at the rate of Rs 18 and Rs 9 per adult and per child, p.m., for the purchase of Dal, Ghee, etc.	Rs 9,32,996
(ii) <i>Cash grant.</i> —An ex-gratia grant of Rs 17, Rs 16 and Rs 7 is being paid to each adult male, female and a child for the purchase of cloth for one suit of clothes. Amount sanctioned Rs 8.48 lacs	17,054
(iii) <i>Fodder subsidy.</i> —Fodder subsidy at the rate of Rs 00.50 per cattle per day is being issued for the cattle brought by the uprooted persons	5,546
(iv) <i>Subsidy for the cattle lost/killed.</i> —An ex-gratia grant of Rs 400 for bullock/camel, Rs 300 for a buffalow and Rs 2000 for a cow	1,24,900
(v) <i>For Houses damaged.</i> —An ex-gratia grant of Rs 2000 for pacca house and Rs 1,000 for kacha house	1,22,970
(vi) <i>Ex-gratia grant for killed, injured and disabled.</i> —An ex-gratia grant of Rs 1,500 paid to the families whose bread-winners had been killed, Rs 500 for injured persons and Rs 1,500 paid to the fully and permanently disabled civilians	1,65,950
(vii) <i>Ex-gratia grant for Military/Punjab Armed Police/Personnel killed. or injured.</i> —An ex-Gratia grant of Rs 5,000, Rs 3,000 and Rs 2,000 has been sanctioned in respect of the officers, J. C. Os, and other ranks killed or disabled respectively	35,740
(viii) <i>Providing (i) Quilts/Blankets (ii) Durrees.</i> —One Quilt/Blanket and Durree for each uprooted persons subject to a maximum of three per family	390 Blankets 11,757 Quilts. 7,997 Durries
(ix) Amount placed at the disposal of the Deputy Commissioner for advancing interest free loan for agricultural as well as business purposes	50,00,000
(x) Facilities of free education, supply of text-books and articles of stationery, free of cost, exempting the school going children from the payment of hostel fee and boarding charges	
(xi) Remission of land revenue and abiana, cess on commercial crops granted in an area falling within 10 miles of the International border and of all operational villages whether situate within this limit or beyond it. Recovery of Government dues such as taccavi loans stayed till further orders.	

Concessions given to Border Districts

\*9227. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the details of the concessions given to the border districts and war affected cities, so far, by the Government, district-wise ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Statements indicating the concessions given to the uprooted persons and the amount spent on various relief measures up to the 11th February, 1966 are laid on the Table of the House.

## [Transport and Election Minister]

## Statement indicating the concessions given to uprooted persons

(i) *Ration in kind or cash.*—(a) Wheat flour/wheat is being issued on the scale of 16 kilograms per adult and 10 kilograms per child per month.

(b) Cash grant at the rate of Rs 18 and Rs 9 per adult and per child per mensem for the purchase of Dal, Ghee, etc.

(ii) *Cash grant.*—An ex-gratia grant of Rs 17, Rs 16 and Rs 7 is being paid to each adult male, female, and a child for the purchase of cloth for one suit of clothes. Amount sanctioned Rs 8.48 lacs.

(iii) *Fodder subsidy.*—Fodder subsidy at the rate of Rs 00.50 per cattle per day is being issued for the cattle brought by the uprooted persons.

(iv) *Subsidy for the cattle killed/lost.*—Ex-gratia grant of Rs 400 for bullock/camel, Rs 300 for a buffalow and Rs 200 for a cow.

(v) *For Houses damaged.*—An ex-gratia grant of Rs 2,000 for pacca house and Rs 1,000 for kachha house.

(vi) *Ex-gratia grant for persons killed, injured and disabled.*—An ex-gratia grant of Rs 1,500 paid to the families whose bread-winners had been killed, Rs 500 for injured persons and Rs 1,500 paid to the fully and permanently disabled civilians.

(vii) *Ex-gratia grant for P.A.P./Military Personnel killed or injured.*—As per scale detailed below :—

*Military*—(i) Officers Rs 5,000 (ii) J. C. Os', Rs 3,000 (iii) Other ranks Rs 2,000.

*Punjab Armed Police*—

(i) Officers of the rank of Assistant Superintendent of Police and above Rs 5,000,

(ii) Deputy Superintendent of Police Rs 4,000,

(iii) Inspectors/Sub-Inspector/Assistant Sub-Inspectors, Rs 3,000.

(iv) Other ranks Rs 2,000.

(viii) *Providing* (i) *Quilts/Blankets*, (ii) *Durrees*.—One Quilt/Blanket and Durree for each uprooted persons above the age of 12 and one quilt/blanket and durree for two children between the age of 8 and 12 years.

(ix) Facilities of free education, supply of text-books and articles of stationery, free of cost, exempting the school going children from the payment of hostel fee and boarding charges. Amount sanctioned Rs 23,000.

(x) Remission of land revenue and abiana, cess on commercial crops granted in an area falling within 10 miles of the International Border in Amritsar and Ferozepore Districts and five miles in Gurdaspur District and of all Operational Villages whether situate within this limit or beyond it. Recovery of Government dues such as taccavi within 10 miles of the border stayed till further orders.

(xi) *Loans.*—(i) An amount of Rs 51 lakhs placed at the disposal of the Director of Industries, Punjab for advancing loans to Industrialists, in Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Kapurthala, Ludhiana and Jullundur.

(ii) An amount of Rs 10 lacs placed at the disposal of the Deputy Commissioners Amritsar, Gurdaspur and Ferozepore for advancing interest free loans to uprooted persons for agricultural and business purposes.

(iii) An amount of Rs 20 lacs placed at the disposal of the Labour Commissioner, Punjab, for advancing interest free loans to the unemployed Industrial Workers.

PROGRESS REPORT FOR THE PERIOD ENDING  
11-2-1966

BLOCK I—GENERAL

Distributed In

Serial No.	Item	Unit	Amritsar	Ferozepur	Gurdaspur	Other districts	Total	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persons registered	Number	29,799	18,766	1,459	101*	50,125	*Chandigarh campers 45,303
2	Families Registered	Do	4,779	3,517	266	28*	8,590	*Campers 890
3	Tents	Do	700	650	..	..	1,350	
4	Wheat	Quintals	14,544	9,892	720	43	25,199	
5	Milk Powder	Lbs.	29,652	14,685	2,746	..	47,083	
6	Quilts (i) Received	..	13,256	14,195	670	110	28,231	
	(ii) Distributed	Do	11,995	13,219	560	63	25,837	
7	Durries (i) Received	Do	11,182	11,298	420	110	23,000	
	(ii) Distributed	Do	8,993	7,197	420	72	16,682	
8	Blankets (i) Received	Do	936	500	27	..	1,463	
	(ii) Distributed	Do	390	436	27	..	853	

[Transport and Election Minister]

RELIEF INCLUDING EX-GRATIA GRANT S  
BLOCK II

Serial No.	Item for which cash grant given	Amount distributed in					REMARKS
		Amritsar	Ferozepore	Gurdaspur	Other Districts	Total	
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	
1	Ration (Ghee, Sugar, etc).	..	13,05,513	9,50,648	78,894	6,426	23,41,481
2	Grants for one set of clothing	..	1,11,426	1,88,358	12,004	1,378	3,13,166
3	Cattle fodder	..	5,546	19,255	..	..	24,801
4	Houses damaged	..	1,22,970	21,805	..	57,545	2,02,320
5	Cattle killed	..	1,14,900	8,175	..	4,330	1,37,405
6	Army men killed/injured/missing (ex-gratia grants)	..	35,740	32,960	49,000	6,78,400	7,96,170
7	Civilians including PAP/Home Guards killed/injured (ex-gratia grants)	..	1,65,950	42,750	2,000	37, 550*	2,48,250
							*Including 4 drivers of Karnal district killed while on military duty.
		18,72,045	12,63,950	1,41,898	7,85,699	40,63,593	

Approximate cost of wheat, quilts and durrees (items 4,6 and 7 Block I)

21,75,000

Total amount distributed as Relief including ex-gratia grants upto 31st October, 1965 .. 5,39,199 Rs.

62,38,593

### Villages electrified in Kangra District

**\*8911. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the number and names of the villages electrified during the current financial year (up to date) in district Kangra?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** One village Kandi.

### Persons registered as War Hit Persons in District Ferozepore

**\*9465. Sardar Kulbir Singh }**

**Chaudhri Satya Dev }** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to lay on the Table of the House a list of persons in district Ferozepore with their addresses who were registered as war hit persons but whose names were later removed from the list along with the reasons therefor ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** 321 families comprising 1,685 persons have been detected who were not previously residing in Pakistan occupied area. A scrutiny in regard to their claims is still being conducted and such persons will be weeded out only after the receipt of the report of scrutiny.

### Inclusion of certain villages in ten mile area of the Border

**\*9496. Sardar Kulbir Singh }**

**Chaudhri Satya Dev }** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

- (a) the names of the villages which applied for inclusion in the ten mile area of the border with Pakistan for remission of land revenue, abiana, etc. ;
- (b) the names of the villages referred to in part (a) above whose request was not accepted and the reasons therefor ?

**Sardar Gurdial Singh Dhillon :** (a) and (b). The concession of remission of land revenue and abiana extends to all villages situated within ten miles of the International Border in Ferozepore and Amritsar Districts. In case a part of the land of any village falls within the said limit the concession extends to the entire village.

As such the question of denying this concession to any village situated within 10 miles of the border does not arise. Nor is any village expected to seek this concession through an application.

### UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

**Enquiry held against Shri Jaswant Singh Grewal, D. S. P.**  
(now at Bassi Pathana, district Patiala)

**3180. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

- (a) whether an enquiry was initiated by the Department against Shri Jaswant Singh Grewal, D. S. P. (now at Bassi Pathana,

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

district Patiala) for implicating Members of this House in a false case of attempt to murder in 1962 ; if so, the result thereof and a copy of the charges etc. levelled against him and the findings of the enquiry be laid on the Table of the House ;

- (b) the names of the Officer who ordered the said enquiry and the name of those who actually enquired into the matter ?

**Sardar Darbara Singh** (Home and Development Minister) : (a) No.  
(b) Does not arise.

#### ADJOURNMENT MOTIONS

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕੁਅਰਸਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਚਰਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਗਰਾਮ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਲਰੈਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਡੀਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਦਭਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਿਡਨ ਗੋਲਡ ਕਢਣ ਲਈ ਸੀ। ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕਿਥੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟਰਾਂਗ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**उपाध्याय :** मैं ने कल भी कहा था कि बजट सेशन में बहस के लिए काफी वक़्त होता है अगर एडजर्नमेंट मोशनज़ न आएँ तो अच्छा है। जो बात आप ने कही है एजुकेशन मिनिस्टर साहिब ने कल उसका जवाब दे दिया था।  
(I had stated this yesterday also that since sufficient opportunities would be available during discussions in the Budget session for reference to such matters it would be better if no adjournment motion is given notice of. The matter referred to by the hon. Member has already been replied to by the Education Minister yesterday.)

**शिक्षा मंत्री :** मेरे इलम में ऐसी काफी शिकायतें आई हैं। मैं ने पहली शिकायत मिलते ही जनरल प्राजेक्ट हिदायत कर दी है कि किसी के साथ कोअर्शन यूज़ नहीं करनी है, किसी से पैसे न मांगो। किसी लड़के को नहीं कहना, किसी लड़के के बाप को नहीं कहना। अगर कोई अपनी मर्जी से दे तो ठीक है। एक टीचर 5 ग्राम सोना इकट्ठा कर सकता है तो करे। कोई कोअर्शन नहीं होनी चाहिए। इस हिदायत के बाद आप को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हफ़्ते के अन्दर अन्दर यह काम ख़त्म होने वाला है। 5 मार्च के करीब हम

इस को बन्द कर देंगे। कुछ लोगों ने कहा था कि हम हात्ते के अन्दर अन्दर जितना देना है दे देंगे।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** दूसरी एडजर्नमेंट मोशन मेरी तरफ से और बहुत से आपोजीशन के मैबरों की तरफ से है। कपूरथला के टीचर्स की स्ट्राइक के बारे में है जो कपूरथला कालिज में है। यह बहुत ग्रहम मामला है।

**उपाध्यक्षा :** टीचर्स ने स्ट्राइक की है तो ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब से मिल कर बात कर लें, एडजर्नमेंट मोशन का क्या सवाल है? (If the teachers have gone on a strike, then the hon. Member should discuss the matter with the Education Minister. How does the question of moving an adjournment motion arise?)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** स्टूडेंट्स की स्ट्राइक हो रही है। यह हाउस में एशोरेंस दें, इंकवायरी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ने सारे स्टाफ को तंग कर रखा है। वह उन को आदमी नहीं समझता। इस पर हाउस में डिस्कशन हो।

**शिक्षा मंत्री :** मेरा फाजिल दोस्त से आज ही सुबह चर्चा हुआ था और आज से चन्द दिन पहले उनका फ़ोन भी आया था कि कुछ टीचर्स मिलना चाहते हैं। मैं ने उस दिन वाजेह अलफाज़ में कहा था कि हम इस की इंकवायरी करने के लिये तैयार हैं। उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है। भूख हड़ताल के दबाव के नीचे गवर्नमेंट को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वे आज भूख हड़ताल छोड़ दें और वह चाहते हैं कि उन के साथ इस बात में इन्साफ़ हो हम हर कोई कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिस से तसल्ली हो। जब तक भूख हड़ताल है कोई कदम नहीं उठा सकते।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम। मेरी बात कपूरथले से ताल्लुक रखती है।

**उपाध्यक्षा :** ऐजुकेशन मिनिस्टर के सारी बात कहने के बाद कोई बात नहीं होती। (After the detailed statement by the Education Minister no further discussion on the matter will be allowed.)

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** वह क्लैरिफिकेशन करें। अगर वे स्ट्राइक खत्म कर दें तो क्या ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब ऐजुकेशन कमिशनर को इंकवायरी के लिए भेजने को तैयार हैं?

**उपाध्यक्षा :** उन से मिल कर कह लें ((He may meet the Minister and discuss the matter with him.))

**शिक्षा मंत्री :** मैं अफसर का नाम नहीं कह सकता। जिस अफसर पर आपकी तसल्ली होगी उसको भेज कर इंकवायरी करा लूंगा।

**सरदार अजायब सिंघ संधू :** आन ए पुआइंट आफ आर्डर, मैडम। मै, सरदार उतरा सिंघ लटिलपुरी, सरदार लढमट सिंघ गिल अउे घाकी 10 मैंगरां वलें दिक् औड जर्नलमेंट मॅसन् सिडी सी।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਕਰੋ। (Where is the necessity for raising a point of order for this purpose ? Let the hon. Member speak.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਗਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। (I have disallowed the motion. Let the hon. Member speak to me in my Chamber. If I am convinced, I will admit it.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਜ਼ਲਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਨੇ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ।

**Deputy Speaker :** Please resume your seat. I cannot allow you to speak on the Adjournment Motion.

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਪੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। (I have got this paper with me. I have read it) There must be some limit.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਇਹ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਰੈਮਿਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਹੀ ਦਿਓ। (It has been dis allowed. The remedy of this matter does not lie in giving notices of adjournment motions every day.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠ ਜਾਓ। (The hon. Member, Shri Sandhu may please take his seat.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ :** ਸੈਂਡਸ, ਆਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਇਸਕੋ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰੋਂ।

**ਉਪਾਧਿਕਾ :** ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ? ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਯੋਝਰ ਕੱਢੋ। (Who said that I had not seen the papers ? I never come to the House without studying them. The hon. Member may please withdraw his words.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥ :** ਮੈਂ ਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ।

**उपाध्यक्षा :** श्री जगन्नाथ, विद्वर! करें। (The hon. Member Shri Jagan Nath should withdraw his words.)

**श्री जगन्नाथ :** विद्वर! करता हूं।

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** आज से 2 दिन पहले इसी हाउस में एक एडजर्नमेंट मोशन पुलिस के किसी जुर्म और हैपनिंग के बारे में पेश हुई थी और उस पर हाउस के सैंटीमेंट क्या थे यह आप को पता लग गया है और आनरेबल स्पीकर साहिब ने उस एडजर्नमेंट मोशन को अभी तक पैडिंग रखा हुआ है। यह बात उसमें तै हुई थी कि अलग अलग ग्रुप्स के जो लीडर्ज हैं उन के साथ स्पीकर साहिब इस बात का फैसला करेंगे कि अगर ऐसी कोई अनयुजल बात होती है, स्टेट में असाधारण घटना हो जाती है जो बहुत ही अहमियत की है, जिसका जनता के जीवन से सीधा संबंध है, चाहे गवर्नर एड्रेस पर बहस हो रही है या बजट की जनरल डिस्कशन चल रही है उस पर गौर करेंगे और विचार करने के लिए मीटिंग करने के लिए रखा था। आज सरदार अजायब सिंह की तरफ से आई है। पहली एडजर्नमेंट मोशन यह थी कि एक आदमी को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है। इस दूसरी में यह है कि एक आदमी को जखमी कर दिया गया है। इस तरह की बातें स्टेट में हो रही हैं। ऐसी एडजर्नमेंट मोशन को रिजैक्ट करने से या अकामोडेट न करने से न जनता का भला होता है और न ही यह डेमोक्रेसी के फायदा में है। इस लिए आप इस को पैडिंग रखें और ग्रुप लीडर्ज के साथ डिसक्स करके फैसला करें कि ऐसे केसिज में क्या करना चाहिये ताकि प्रायंदा सूबे में ऐसी घटनाएं न रिपीट हों।

**उपाध्यक्षा :** अगर आनरेबल मैम्बर्ज मुझे सुनने की कोशिश करें तो प्वाइंट ऑफ आर्डर रेज करने की जरूरत नहीं हो सकती। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक दफा बैठ कर हमें इस बात को तय करना ही पड़ेगा। आज अगर स्पीकर साहिब न आए तो कल मैं आप से बैठ कर फैसला कर लूंगी। तमाम ग्रुप लीडर्ज के साथ बात करके गवर्नमेंट के नोटिस में लाया जाएगा कि प्रायंदा ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहियें (If the hon. Members just try to listen to me, then the necessity for raising points of order can be obviated. I quite agree that we shall have to decide this matter once for all. If to day, the hon. Speaker does not return, then tomorrow I shall discuss it with you and arrive at a decision. After consultations with all the group leaders, the Government will be approached with the request that in future repetition of such incidents should be avoided.)

**श्री बलराम जी दास टण्डन :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो इस का सैकण्ड पैरा है उसे आप पढ़ें तो कलेजा मूंह को आता है। उस आदमी को पकड़ कर ले जा कर 17 दिन तक उसे मारते रहे और फिर उस का 109 में चालान कर दिया। यह बूचड़ों का राज्य न हुआ तो और क्या हुआ? आप जैसे देश भक्त भी इस पर न सोचेंगे तो फिर और कौन सोचेगा?

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** On a point of Order, Madam. On an earlier occasion, an adjournment motion given notice of by another hon. Member of this House was kept pending on an assurance by the hon. Speaker. May I know if the adjournment motion given notice by about ten Members of this House yesterday has also been kept pending or a decision thereon has been given and rejected ?

**उपाध्यक्ष :** अगर आनरेबल मੈम्बर मुझे सुनने की कृपा किया करें तो बार बार उठने की ज़रूरत न पड़े। मैंने कहा है कि वह भी और यह भी ग्रुप लीडर्स के साथ डिसकस कर के इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि पुलिस किसी पर जुलम करे। (If the hon. Members please care to hear me then any need for rising again and again would not arise. I have stated that this and the other matter would be discussed with the Group Leaders and effort will be made not to allow the police to commit such atrocities.)

**कामरेड सभसेव सिंघ जेस :** आठ ए पुराईट आफ आरडर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसीं घुट ठीक कीता है कि इस मामले का नोटिस लिया है, लेकिन मैं अरज करती चाहूँदा हूँ कि एक आदमी नड्डतर सिंघ फड़िया सी। (*Interruption*)

**उपाध्यक्ष :** इस तरह से चेयर को फ्लाऊट करना मुनासिब बात नहीं जब कह दिया है कि पुलिस का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा तो फिर और प्वायंट आफ आर्डर करने का क्या फायदा। (It is not desirable to flout the Chair in this way. When I have already stated that the police would not be allowed to perpetrate atrocities, then what is use of raising such points of order.)

**सरदार कुलबीर सिंघ :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे 2 काल अटैन्शन नोटिस सन। उह ऐडमिट होए हन कि नहीं ?

**उपाध्यक्ष :** कल को टेक अप होंगे (They will be taken up tomorrow).

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने प्रैस वर्कर्स के बारे में काल अटैन्शन नोटिस दिया है। वह कल को हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि उन को चौधरी सुन्दर सिंह ने एंशोरेंस दी थी। (*Interruption*)

**उपाध्यक्ष :** आप का काल अटैन्शन नोटिस आया हुआ है। मैं सी. पी. एस. से दरखास्त करूँगी कि वह चौधरी सुन्दर सिंह से मिल कर आज ही इस बात को तय करें क्योंकि मामला बहुत लम्बा हो गया है। (The Call Attention Notice given by the hon. Member has been received. I would request the Chief Parliamentary Secretary to meet Chaudhri Sunder Singh today and settle the matter with him as it has already been prolonged.)

## STATEMENT BY THE EDUCATION MINISTER

**शिक्षा मंत्री (श्री प्रबोध चन्द्र) :** कल यहां पर मेरे एक फाजिल दोस्त ने कहा था कि पांच हजार रुपए का घास खरीदा गया । मेरे पास प्रिंसिपल साहिब का यह लैटर आया है, उन्होंने ने लिखा है—

“Reference your verbal query.

1. No Calcutta grass or any other grass was purchased at the time of Shri M. C. Chagla's visit to this College not even worth a paise. In fact the college has not purchased any grass in the last few years.”

This information has been received by me from the Principal of the College, duly signed by him.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Madam, my objection was that the hon. Education Minister got up yesterday abruptly to say that what I had said was wrong when I was saying that fact on the basis of some information. Since he is now making this statement after making an enquiry from the Principal of the College, I have nothing to say and the matter ends here.

**ਕਾਮਰੇਡ ਜ਼ੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। (ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਲੀਆਂ)

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**Welfare and Justice Minister (Chaudhri Chand Ram) :** Madam, I beg to lay on the Table the Defence of India (Punjab Special Tribunals) (First Amendment) Rules, 1965, issued under Section 15 of the Defence of India Act, 1962.

## STATEMENT BY THE TRANSPORT AND ELECTIONS MINISTER

**ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲੋਂ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹਾਈ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

The following procedure has been decided upon to prevent any risk to the civilian population returning to their homes in areas vacated by Pakistan :—

- (a) On the morning of the 26th February, the army accompanied by police representatives will locate on the ground the danger areas as communicated to it by the Pakistan Army.
- (b) The areas in question will be picqueted by the civil police.

[Transport and Elections Minister]

(c) The danger areas will then be cleared of all hazards by the army. Once this is done the police will be at liberty to lift their picquets.

(d) This will be followed by controlled re-entry of civilians into vacated territory under the direction and control of the local civilian authorities.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਥੇ ਖੂਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੌਲਿਊਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਸੀਕਿਊਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਵਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਉਥੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਹਾਦਸਾਤ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਸਤ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗ ਜਾਣਗੇ।

### Resolution re. Development of Hilly Areas and the Haryana Area of the State.

**Deputy Speaker :** Comrade Jangir Singh Joga who was in possession of the House, when it adjourned on the 17th February, 1966, will now resume his speech on the \*resolution.

**ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ):** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਨਹਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਮੋਹਨਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਉਖੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਖੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤ ਤੇ 2130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1.4 ਫੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ

\*Note : Previous discussion on the resolution moved by Shri Balramji Dass Tandon, that—

“With a view to bring the hilly areas of the Punjab which are backward, at par with the adjoining areas of the State and the Haryana area at par with the rest of the State in the matter of development, this House recommends to the Government to make plan allocations in such a way that sixty percent of the plan funds are earmarked for the said Haryana area and the Hilly areas.”

will be found in the P.V.S. Debate Vol. I, No. 3, dated 17-2-66.

ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਔਸਤ ਫੀ ਆਦਮੀ ਕਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਫੀ ਆਦਮੀ ਔਸਤ 149 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 135 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਦ ਹੇਠ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸਨਅਤ ਹੀ ਵਧ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾਕੇ ਕੁਲ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਨਅਤ ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸਨਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ 102 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਕ 516 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੈਨਲ ਆਫ ਰੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਅਟਾਮਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਪਾਸੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਵੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਮਦਰਾਸ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਉਥੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ ਏਕਾਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਤਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਏਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੁਟ ਪਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਟੀ-ਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਥੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਪੀਸਣ ਲਈ ਉਥੇ ਸਨਅਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਸਨਅਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਭਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਕਵਰਡ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ-ਮੈਂਟ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਲਹਿਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤ ਭੇਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**ਕਾਸਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦ (ਨੂਰਪੁਰ):** ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ ਕਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, उसे क्लਾउड करने की कोशिश की गई है। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं ताकि इस में कोई शक न रह जाय हम चाहते हैं कि पंजाब के अन्दर बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए और इसी प्रकार हम चाहते हैं कि यहां पर एटोमिक इनर्जी का कारखाना खोला जाए लेकिन ऐसा कोई भी कारखाना यहां पर खोला नहीं गया। मगर इस वक्त हमारे सामने यह सवाल है कि कांगड़ा और हरियाणा के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे कांगड़ा जिला के अन्दर जजबात पैदा हो गए हैं और कांगड़ा के लोग महसूस करते हैं कि हमारे साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है और जिस तरह हमें सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वह गुलामों से भी बदतर है। कांग्रेस का राज १६, १७ सालों से है। लेकिन जहां तक कांगड़ा जिला की डिबैलपमेंट का सवाल है, उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि उस की हालत को सुधारने के लिए कम ही ध्यान दिया है। इन चीजों को देखते हुए हमें मायूसी ही हुई है। चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुलक की सब से ज्यादा जरूरत यह है कि

We should have a good Government. We should have a just Government. We should have an honest Government. We should have a non-corruptible Government.

अगर यह चीज नहीं है तो लोगों को क्या कहा जा सकता है। मैं इस हाउस का मेम्बर 14-15 साल से लगातार चला आया हूं। यहां पर कहा जाता है कि कांगड़ा जिला के लिए फन फन स्कीमें बनाई गई लेकिन मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि कांगड़ा जिला की डिबैलपमेंट के लिए सही तौर पर कोई कदम नहीं उठाए गए और लोगों की हालत को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने जिला कांगड़ा की डिबैलपमेंट का ब्योरा जानने के लिए सवाल किया था। उस का जवाब सरकार की तरफ से आया कि पहली दो पंच वर्षीय योजनाओं के अन्दर कांगड़ा जिले में किसी तरह की इंडस्ट्रीज स्थापित या जारी करने का सवाल ही नहीं हुआ। वहां तीसरी पंच वर्षीय योजना के समय में कुछ स्कीमें बनाई गई लेकिन उन स्कीमों को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। सीमेंट की फैक्ट्री के बारे में कहा जाता रहा लेकिन उस का भी कुछ पता नहीं। इसी तरह से कांगड़ा जिला

[ कामरेड राम चन्द्र ]

के अन्दर कागज का कारखाना लगाने की बातें होती रहीं लेकिन बाद में शायद तंगल के नजदीक खोलने की बात हो रही है । वह कारखाना भी प्राइवेट सेक्टर में खोला जा रहा है । पहले तो हमें शिकायत है कि उसे जिला कांगड़ा से बाहर खोला जा रहा है क्योंकि सरकार पहले कुछ कहती है और जब खोलने की बात आती है तो कांगड़ा से बाहर खोल दिया जाता है । कांगड़ा जिला का रकबा लगभग 6 हजार चौरबरा मील है । कांगड़ा जिला एरिया की निम्नतम से सब से बड़ा जिला है । लेकिन उस की हालत को सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । तालीम के मामले को ही ले लीजिए । कांगड़ा इतना बड़ा जिला है लेकिन सारे जिले के अन्दर एक कालिज है । उस कालिज की हालत यह है कि वहां पर एम. एस. सी. की क्लासें भी जारी नहीं की जाती । कहा जाता है कि यह क्लासें वहां पर खोली नहीं जा सकती, एम. ए. तथा एम. एन्. सी. की क्लासें वहां पर खोली जाती हैं जहां पर यूनिवर्सिटी हो । अगर कांगड़ा के बच्चों ने एम. ए. या एम. एस. सी. की शिक्षा प्राप्त करनी हो तो उन्हें बाहर जा कर ही प्राप्त करनी पड़ती है । हम ने बार बार सरकार से प्रार्थना की कि वहां पर एम. एस. सी. ज्यूलोजी की क्लासें जारी करें लेकिन आज तक वहां पर यह क्लासें जारी नहीं कीं । हमें सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है कि निकट भविष्य में यह क्लासें वहां पर जारी कर दें । यही वजह है कि कांगड़ा के लोग समझ रहे हैं कि सरकार उन की डिबैल्पमेंट के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है । वह आवाज उठा रहे हैं कि हमें पंजाब से अलग कर दिया जाए और हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए ।

**सरदार अजयिब सिंह सैयू :** आन ए पुआइंट आफ आरडर, सर । अज बहूत अहिम मसला हाऊस के अंदर जेरे बहिम है लेकिन बहूत अडमस के नाल कहिणा पैदा है कि हाऊस के अंदर कौड़ी मनिस्टर मोजूद नही है, इस तें पता चलदा है कि गैरमिंट उनुं दी डीबैल्पमेंट घारे किंती हमदरदी रखदी है । चीफ पारलीमेंटरी सैक्रेटरी साहिब एिबे मोजूद हन । उह उं हमेसा एिबे हाऊस विच बैठे रहिंदे हन । उह उं सरकार नू रीपीजै ट नही कर सकदे । इस लई मै बेंनडी करदा हं कि किसे मनिस्टर नू हाऊस के अंदर काल कीडा जावे ।

**Mr. Chairman ( Pandit Chiranji Lal Sharma ) :** The Chief Parliamentary Secretary has been representing the Government on earlier occasions also.

**कामरेड राम चन्द्र :** चेयरमैन साहिब, कांगड़ा जिला की डिबैल्पमेंट के लिए कोई काम नहीं हो रहा है । कांगड़ा जिला के अन्दर सड़कें बहुत कम हैं । वहां पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है । बहुधा लोगों को पीने के लिए पानी 3, 4 मीलों से लाना पड़ता है । जो सरकार लोगों को पानी पीने के साधन मुहैया नहीं कर सकती है तो और वहां की बेहतरी क्या कर सकती है । अगर वहां पर हाल में बारिश न होती तो वहां के लोग सोच रहे थे कि वह अपने पशुओं को खुले

छोड़ दें क्योंकि वह उन को पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते थे और उन को घास भी नहीं दे सकते । जब वहां के लोगों को अपने पीने के पानी की समस्या है तो वह पशुओं को पीने का पानी कहां से ला सकते हैं । मैं यह कांगड़ा जिला के लोगों की आवाज हाउस में रख रहा हूं । वह समझते हैं कि उन की डिवैलपमेंट पंजाब के साथ रहने से नहीं हो सकती है । उन की यह मुतफिका और मुतहिदा राए है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया जाए । मैं उन की हाउस में नुमायंदगी करता हूं । इस समय सवाल उठ रहा है कि पंजाबी सूबा बनाया जाए । इस के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें उस से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन पहाड़ी इलाके के लोगों को हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया जाए । हमारा रहन सहन हमारे रीति रिवाज, हमारी विवाह शादियों के रसम रिवाज हिमाचल प्रदेश के साथ मिलते हैं । हमारी बोली भी एक ही है । हमें तो सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए उन से अलग कर रखा हुआ है । कांगड़ा जिले का कुछ इलाका-जैसा कि कुलू पंजाब के अन्दर है मगर कुलू और बैजनाथ के बीच हिमाचल प्रदेश का इलाका है । कुछ इलाका पंजाब का आता है और उस के बाद मंडी स्टेट आती है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ है और उस के आगे फिर पंजाब का इलाका आता है । यह अब नैचुरल हदबन्दी है । हमें तो सियासी मुफाद उठाने के लिए अलग कर रखा हुआ है । ताकि हम अपनी तरक्की के लिए और डिवैलपमेंट के लिए फुल प्रेशर सरकार पर न डाल सकें । आज यह कहा जाए कि कांगड़े के लिये कुछ ज्यादा रकम रखी जा रही है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे यकीन हो गया है पिछली तीन पांच साला प्लान्ज की इम्प्लीमेंटेशन को देख कर कि मौजूदा भाईचारा में रह कर कांगड़ा की डिवैलपमेंट नहीं हो सकती । इस की डिवैलपमेंट तभी हो सकती है अगर कांगड़े को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए, उस में कुलू को मिला दिया जाए और लाहोल स्पीती को भी मिला दिया जाए और इस पहाड़ी इलाके का एक फुल फलैज्ड पहाड़ी प्रदेश बना दिया जाए । (आपोजिशन की तरफ से तालियां) मैं जोश नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांगड़ा जिला फौजी खिदमात में अव्वल नम्बर पर रहा है । जब चीन के साथ लड़ाई हुई तो कांगड़े वालों ने जो कुरबानियां दीं और जो वे लोग शहीद हुए उन की तादाद टाप पर थी । अब भी जो लड़ाई पाकिस्तान से हुई तो कांगड़े के शहीद होने वालों ने हिन्दोस्तान भर में टाप किया है । हमें फखर है कि हम हिन्दोस्तान के बाशिन्दे हैं और हिन्दोस्तान की रक्षा की लड़ाई में लड़ते रहे हैं । लेकिन मैं यकीन दिला देना चाहता हूं कि अगर हमारे साथ इन्साफ न हुआ तो जो आदमी हिन्दोस्तान के दुश्मन से लड़ सकता है वह हिन्दोस्तान में अपने हकूक को हासिल करने के लिए भी लड़ सकता है । मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि नाराजगी का जजबा एम. एल. एज. में नहीं है, देहात में ज्यादा है । बल्कि देहात वाले हम पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि आप लोग ऐसे पंजाब के साथ क्यों रहते हो जहां पर हमारी तरक्की की कोशिश नहीं होती, उल्टी कोशिश होती है कि किसी तरह से पहाड़ के लोगों को आपस में लड़ा

[कामरेड राम चन्द्र ]

दिया जाए और जनता की तरक्की की तरफ कोई ध्यान, न दे सकें। मैं सचचर साहिब की इज्जत करता हूं। जितनी देर उन की हकूमत रही बड़ी अच्छी रही, उस हकूमत का अपना म्यार था, स्टैंडर्ड था। लेकिन उस वक़्त भी जब उन के साथ बातचीत होती तो वह कहते सब मैम्बर अपने अपने इलाके की डिवैलपमेंट के लिये स्कोम्प बना कर दे दो तो मैं ने उन से कहा कि आप क्या करते हैं। जहां पर पहले से ही कालिज हैं, स्कूल हैं, हस्पताल हैं और सड़कें हैं गोया कि हर प्रकार की तरक्की हुई है और इस के बरअक्स जहां पर कोई आदमी भी पढ़ा नहीं है कोई स्कूल नहीं है कोई कालिज नहीं है आप दोनों इलाकों के लोगों को कहते हैं कि स्कीमें बना कर दे दो यह क्या बात हुई, यह कहां का इन्साफ है ? चूंकि हमारा प्रेशर नहीं था इस लिये उन जैसा इन्साफ पसन्द आदमी भी कांगड़े की तरक्की न कर सका। केवल ऐसा कह देना कि दस स्कूल खोल दिये हैं भला उस से क्या बनता है। हमारा पहाड़ी इलाका है। रास्ते कटे-फटे हैं, आबादी भी ऐसी है कि स्कूलों की ज्यादा तादाद की जरूरत है, हस्पतालों की भी ज्यादा तादाद में जरूरत है और सड़कें भी ज्यादा तादाद में बनाने की जरूरत है। बाकी दुनिया से अलग होने की वजह से, रास्ते कटे फटे होने और दुश्वारगुजार होने के कारण बाकी दुनिया के बारे में पता नहीं लगता। अगर सड़कों के द्वारा बाकी मुल्क के साथ हमारे इलाके को जोड़ दिया जाए और हमारे इलाके को अन्दरूनी तौर पर भी आपस में सड़कों के जरिये से जोड़ दिया जाए तो भी फायदा होगा। एक तो दूसरों को देख कर हमारे लोगों को तरक्की करने का मौका मिलेगा और आपस में भी एक दूसरे से मिलेंगे तो शायद अपनी मांगों को बेहतर तौर पर और मुअस्सर तौर पर पेश कर सकेंगे। लेकिन इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं जानता हूं कि मेरे दोस्त कहेंगे कि अब हम सड़कें बना रहे हैं। मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि आप सड़कें वहां पर बना रहे हैं जहां पर आप को चीन ने मजबूर किया है। आप सड़कें वहां बना रहे हैं जहां पर आप को पाकिस्तान ने मजबूर किया है। हमारी जरूरियात को महसूस कर के सड़कें नहीं बनाई जा रहीं। जहां पर आप सड़कें बनाएंगे हम फिर भी सहयोग देंगे, पूरी तरह से कोआप्रेट करेंगे लेकिन इस से खास कांगड़े का भला नहीं होता है। कांगड़े के इंटर्नल इलाके में सड़कें बनाई जानी चाहियें। इस वक़्त तो कांगड़े को एक तरह की कालोनी बनाया जा रहा है। वहां पंजाब के तमाम लोग चले जाते हैं, वजीर जाते हैं, बड़े बड़े अफसर चले जाते हैं और वहां जा कर जमीनें खरीद लेते हैं। कुल्लू को भी नौ आबादी बनाने की कोशिश की गई है और इस के खिलाफ वहां पर आवाज़ उठाई जा रही है। वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर भेजे जाते हैं वे लोगों को दबा कर उन से जमीनें खरीद लेते हैं। अगर आप तहकीकात करें तो देखेंगे कि बाहर से तो लोग दबे हुए हैं लेकिन अन्दर उन के दिलों में गुस्से भरे हुए हैं। डेढ़ दो साल का अर्सा हुआ वहां पर कामरेड राम किशन जी गए थे। उन के सामने हम ने तमाम चीजें रखी थीं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी कमजोर है और यहां पर भी यही कहावत आयद होती है कि जिस की लाठी उसी की भैंस। जोर वाले की

बात पब्लिक में भी चलती है और गवर्नमेंट में भी चलती है । जोर वाले लोग हर जगह पर अपनी बात मनवा लेते हैं । हमारे लोग अभी तक न ज्यादा पढ़ सके हैं, न ज्यादा लिखना जानते हैं और न ही ज्यादा महफ़ज़ब हैं । इलाकों में रास्तों की दुशवारगुजारियों के कारण आसानी से एक दूसरे के साथ मिल भी नहीं सकते, सलाह मशिवरा भी नहीं कर सकते । इसी लिये मजमूई तरक्की के लिये अपने आप को इस तरह से आर्गेनाइज नहीं कर सके कि आवाज बुलंद कर के गवर्नमेंट को मुतासिर कर सकें । आज हम चाहे बेआवाज हैं लेकिन कल हम बेआवाज नहीं रहेंगे । जो मायूसी कांगड़े के और दूसरे पहाड़ी लोगों में है उस का अन्दाजा लगाना नामुमकिन है । इस मायूसी के नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे । हम देश के वफादार हैं, इस का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाना चाहिये । हम देश के दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने अब फैसला कर लिया है कि हम अपने हकूक के लिये भी लड़ेंगे । मुझे हैरानी होती है, आप कहते हैं कि यहां पर मैडिकल कालिज खोल दिया है, एक नया इन्स्टीच्यूट खोल दिया है और उस का एक्सपेंडिचर अनब्रेकेबल है । दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, एक डिविजीबल और दूसरा अनडिविजीबल । जब चन्डीगढ़ में कोई रिसर्च इन्स्टीच्यूट या मैडिकल इन्स्टीच्यूट खोलते हैं तो व्हते हैं कि उस का एक्सपेंडिचर अनब्रेकेबल है सारे के सारे पंजाब पर पड़ेगा और कांगड़े में जब कोई इन्स्टीच्यूट खोला जाता है तो कहा जाता है कि उस का खर्च ब्रेकेबल है । हम कहते हैं कि अनब्रेकेबल एक्सपेंडिचर वाली संस्थएं आप कांगड़े और नूरपूर में क्यों नहीं खोलते तो कोई सुनता नहीं है । तमाम एक्सपेंडिचर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है ।

पंजाब की वजारत क्या है ? वजारत में एक जिले की तीन नुमाइन्दे हैं, दूसरे दो चार जिलों के दो दो, नुमाइन्दे हैं, कुल 17 जिलों में से पांच जिलों के नुमाइन्दे पंजाब वजारत में हैं, बाकी जिलों की कोई नुमाइंदगी नहीं है । मैंने सवाल किया कि वजीर साहिबान के दौरे के मुताल्लिक बताया जाए कि हर जिले में कितना दौरा कर के आए हैं । सवाल के जवाब से जाहिर होता था कि वजीरों ने ज्यादा दौरे पहले अपने हल्कों में लगाए हैं और वक़्त बचा तो उन्होंने अपने जिले में दौरा किया अगर फिर भी कुछ वक़्त मिला तो वह बाकी के जिलों को दौरे के लिये दिया गया, क्या यह शर्म की बात नहीं है कि कांगड़ा जिला के लोगों ने लड़ाई में सब से ज्यादा कुरबानी की, सब से ज्यादा लोग वहां के शहीद हुए लेकिन उन के पसमांदगान से कोई वजीर हमदर्दी तक जाहिर करने के लिए नहीं जा सकता ? जब उन से पूछते हैं तो कहते हैं कि हम तो अपनी कांस्टीच्यूएंसी में दौरा करने के लिये जाते हैं जब इसी तरह से वजारत ने चलना है, इसी तरह से वजीरों ने दौरे करने हैं तो ऐसी सरकार पर हमारा क्या एतमाद हो सकता है ? ऐसी मिनिस्टरी में पब्लिक का कोई एतमाद नहीं हो सकता । जहां दूसरी जगहों पर कांगड़े वालों के साथ बेइन्साफी की जाती है वहां सर्विसिज में भी यही हाल है । चैयरमैन साहिब, कल मैं दिल्ली में था । वहां मैं एक मिनिस्टर को मिलने के लिये गया । वहां पर एक चपड़ासी

[कामरेड राम चन्द्र]

था वह कांगड़ा का रहने वाला था कांगड़े वालों के लिये दो इंडस्ट्रीज़ हैं, या तो चपड़ासी बना कर भेज देते हैं और या बरतन मांजने का काम देते हैं । और उन का कोई रोजगार नहीं है और न ही उन की किसी प्रकार की कोई तरक्की हुई है । वह चपड़ासी मुझ से कहने लगा कि कामरेड साहिब आप लोगों के एम.एल.ए. होने का क्या फायदा है । आप तकरीरें झाड़ जाते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी अच्छी है । हमारे गांव में तो कोई सड़क भी नहीं है । आप को अगले इलैक्शन में बताएंगे कि क्या भाव बिकती है ? आप लोग जबानी बातें कर जाते हैं लेकिन अपने इलाके को कोई मांग भी नहीं मनवा सके, आप को एम.एल.ए. बनवा कर भेजने का हमें क्या फायदा है ? तो अनपढ़ लोग भी यह महसूस कर रहे हैं । जब वे चण्डीगढ़ में आते हैं, जब वे दिल्ली जाते हैं और जब वह जालन्धर वगैरा जगहों पर जाते हैं तो देखते हैं कि हर जगह पर इतनी रोशनी है, इतनी तरक्की और इस कदर डिबैल्पमेंट हुई है और हो रही है तो वे हैरान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे यहां तो कुछ भी नहीं है । इसलिये वहां के लोगों में बिटरनैस भी है, ऐंगुइश भी है और वह इस बात के लिए बेताब है कि वक्त आ गया है कि हमें इस चीज के लिए लड़ना ही होगा । कहा यह जाता है कि अगर इस इलाके को हिमाचल के साथ मिला कर अलग स्टेट बना दिया गया तो यह यूनिट वायबल नहीं होगा, सैल्फ रिलायंट नहीं होगा, सैल्फ-सफीशेंट नहीं होगा । मैं तो यह समझता हूं कि यह एक बिल्कुल बोदी दलील है । खुद हिन्दुस्तान कहा सेल्फसफीशेंट है ? अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए सारी दुनिया से पैसा लिया जा रहा है और अगर देश के लिए दूसरे मुल्कों से पैसा ले सकते हैं तो क्या कांगड़ा के लिये उसमें से हिस्सा नहीं दिया जा सकता ? मुझे तो याद आता है कि एक स्थान पर एक महापुरुष ने लिखा है :—

“How long, How long, O’ Lord ? It is intolerable now.”

तो हमारी हालत भी अब नाकाबल बरदाश्त हो गई है । मुलाजमतों में भी हमारे पड़े लिखे आदमी नहीं लिए जाते ।

सरदार गुरचरण सिंह : तेग उठाओ, तेग ।

कामरेड राम चन्द्र : हमारे पड़े लिखे आदमियों को मुलाजमतों में कोई जगह नहीं दी जाती ।

Mr. Chairman : Will the hon. Member kindly try to wind up ?

कामरेड राम चन्द्र : मुझे तो, चैयरमैन साहिब, आप जिस वक्त हुदम देगे बैठ जाऊंगा । सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं । वजारत की बावत मैंने बताया कि हालांकि कांगड़ा जिला के सारे के सारे एम.एल.एज. कांग्रेसी है लेकिन उन में से किसी को वजारत में नहीं लिया गया । This conduct of the Ministers does not command confidence amongst the people of Kangra District.

मैं मानता हूं कि कांगड़ा के एम.एल.एज. बेशक चुप रहें क्योंकि अगर बोलेंगे तो शायद अगली इलैक्शनों में उन को टिकट न मिले और वह असेम्बली में न आ सकें लेकिन मैं इस मौके पर साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि कांगड़ा के लोग अब चुप नहीं रहेंगे । हालात अब नाकाबले बरदाश्त हो चुके हैं और सब्र की भी आखिर कोई हद होती है । हां, तो मैं सर्विसिज की बाबत अर्ज कर रहा था आप देखें कि पब्लिक सर्विस कमिशन में कांगड़ा की कोई नुमाइन्दगी नहीं है । जहां तक सबार्डीनेट सर्विसिज सिजेक्शन बोर्ड का ताल्लुक है उसमें भी कांगड़ा का कोई नुमाइन्दा नहीं है । आप कोई भी डिप्लोमैट का अदारा बताएं जहां पर कांगड़ा को कुछ नुमाइन्दगी मिली हुई हो । यही नहीं, बल्कि हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि जिला कांगड़ा में अफसर भी वह चुन चुन कर भेजे जाते हैं जिन को एक तरह से सजा देनी होती हो । जिन को सजा देनी हो उन को वहां पर तैनात किया जाता है और वह लोग आम तौर पर ऐसे आदमी होते हैं जो निहायत एग्रेसिव होते हैं, जो गलत बातें करते हैं और उन में अक्सर ऐसे आदमी होते हैं जो कि हर लिहाज से नाजायज बातें करते हैं । मौजूदा डिप्टी कमिशनर के मुताबिक मैं कहना चाहता हूं । वह न्यायशील नहीं और प्रयत्नशील भी नहीं है । इस से पहिले भी शिकायत की गई । बुजुरा साहिबान को भी कहा गया । मगर इस का उचित नोटिस नहीं लिया गया लड़ाई में हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से फेल हुई है । बेशक वह आई. ए. एस. अफसर है लेकिन इन आई. ए. एस. अफसरों को पता ही नहीं कि किस वक्त पर क्या करना है । लोग सिर्फ इस लिये नहीं लड़े कि कामरेड राम किशन की वहां पर उन के सामने तकरीरें जाती थीं या डिप्टी कमिशनर सरगर्म था , लोग इस लिये लड़े हैं क्योंकि उन को देश के लिए प्यार था और उन के दिल में वलवला यह था कि गवर्नमेंट चाहे कुछ करती है या नहीं करती लेकिन हरेक आदमी को देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति देनी है, देश के लिए उन्हें लड़ना है और मरना है । वह देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुरबान कर देने के लिए बेसब्र हो रहे थे । लेकिन वहां की ऐडमिनिस्ट्रेशन ने उन के साथ क्या किया ? मैंने नूरपूर के एस. डी. ओ. को कहा कि हमें गांव गांव जाकर लोगों के साथ बातचीत करके प्रोग्राम बनाना चाहिए । लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह अपनी जगह पर ही बैठा रहा । मैं बीस बाईस दिन, जितने दिन कि यह पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती रही, वहां पर रहा लेकिन एस. डी. ओ. की जुरत नहीं होती थी कि वह मेरे साथ चलता या मेरे साथ बात भी करता । लेकिन जब चन्दे की बात होती है तो लोगों से चन्दा जबरदस्ती इकट्ठा किया जाता है । यह शर्म की बात है कि जिस जिला ने सब से ज्यादा कुर्बानी दी हो, जिस जिला से सब से ज्यादा लोग शहीद हुए हों, जिस जिला ने फौज में सब से बड़ चढ़ कर भर्ती दी हो, उस जिला में चन्दा इकट्ठा करने के लिए दबाव डाला जाए ।

चेयरमैन साहिब, पिछली मरतबा चीफ मिनिस्टर साहिब जब धर्मशाला गए थे तो उन को बताया गया था कि वहां का एस. डी. ओ. एक बड़ दिमाग आदमी है ।

[कामरेड राम चन्द्र]

इसी तरह से देहरा और नूरपूर के एस. डी. ओ. निनकम्पू है । ठीक है कि आई. ए. एस. का इम्तिहान उन्होंने पास किया है लेकिन सिर्फ इम्तिहान पास करने से तो कोई अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन जाता . . . . .

श्री बलरामजी दास टंडन : यह निनकम्पू क्या है ? ( हंसी )

कामरेड राम चन्द्र : आप को सब कुछ पता है ( घंटी ) चेयरमैन साहिब, आप का हुक्म है तो मैं यहीं पर बस कर देता हूँ ।

Mr. Chairman (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Comrade Jee, I am bound by the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. Please see Rule 200 of these Rules, according to which no speech on a resolution shall ordinarily exceed fifteen minutes in duration. Therefore, please finish your speech.

कामरेड राम चन्द्र : बस अभी आधे मिनट में खत्म कर देता हूँ । लेकिन बैठने से पहले इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त जिला कांगड़ा के लोग हाईली डिस्सैटिस्फाइड हैं । जितने वह डिस्सैटिस्फाइड हैं शायद उतना कोई नहीं । जैसे तीसरी पांच साल प्लान में आप ने उस जिला के लिए कई चीजों को रखा था लेकिन उन को लागू बिल्कुल नहीं किया उसी तरह से कहा जा सकता है कि चौथे प्लान में भी हमारे जिले के साथ यही हालत होगी । अगर कुछ प्रोजेक्शन रखा भी गया तो उस पर अमल नहीं होगा । इस लिए कांगड़ा के लोग चाहते हैं कि हमें हिमाचल के साथ मिला दिया जाए ।

चौधरी राम सरूप (साम्पला) : चेयरमैन साहिब, सब से पहले तो मैं टंडन साहिब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यह जो रेजोल्यूशन मूव किया है, कम अज कम उन की सिम्पथी, लिप सिम्पथी तो है हमारे साथ . . . . .

श्री बलरामजी दास टण्डन : सिम्पथी से उठकर लिप सिम्पथी पर आ गए ?

चौधरी राम सरूप : सिम्पथी नहीं, यह तो लिप सिम्पथी ही है ।

(उपाध्यक्षा ने कुर्सी ग्रहण की।)

उन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश किया वह बहुत अच्छा है । वह मुझ से पछते हैं कि मैंने “लिप सिम्पथी” क्यों कहा है । उन्होंने जो कुछ कहा, वह तो मैंने पढ़ा नहीं लेकिन जो कुछ मुझे मालूम हुआ है, उन्होंने कहा है कि बजट में साठ फीसदी रूपया पहाड़ी और हरियाणा के इलाके के लिए रखा जाए । मैं कहता हूँ कि बजट तो सारा बन गया, कैबिनेट में पास हो गया और जो होना था वह तो सब कुछ हो गया और टंडन साहिब को अब होश आया कि इस तरह के रेजोल्यूशन को यहां पर हाउस में मूव किया जाए ताकि वह हमारे ऊपर एहसान कर सके । डिप्टी स्पीकर साहिब, गरीब आदमी हर एक का ममनून होता है । अगर मैं उन का इस के लिए शुक्रिया अदा करू तो कम अज कम वह यह तो नहीं कहेंगे कि हम नाशूकरे हैं । गरीब आदमी हरेक से दबता है और जो मैं उन का शुक्रिया

अदा करता हूं वह भी दब कर कर रहा हूं क्योंकि हम गरीब हैं और एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी हर आदमी की हमदर्दी हासिल करना चाहता है। उन को मालूम है कि गवर्नमेंट हरियाणा के साथ किस कदर बेइन्साफी करती आ रही है। ठीक है कि इसके लिए एक कमेटी मुर्कर हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है उस पर भी कोई अमल होने वाला नहीं है और न ही जो टंडन साहिब का रैजोल्यूशन है उस पर अमल होने वाला है। इस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि यह तो आऊट ऑफ डेट है क्योंकि, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, बजट वगैरा तो अगले साल का सब कुछ तैयार हो चुका हुआ है। अगर टंडन साहिब की वाकई हमारे साथ कोई हमदर्दी है और जैसा कि आप को मालूम है कि हमारे साथ किस हद तक बेइन्साफी हुई है तो उन्हें चाहिए कि वह खुले मैदान हमारा साथ दें। अभी अभी जिला कांगड़ा की तरफ से धमकी दी गई कि अगर हमारे साथ ऐसा सलूक जारी रहा तो हम कुछ न कुछ ऐजिटेशन करेंगे। उसी तरह से टंडन साहिब से, जिन्होंने इस रैजोल्यूशन को पेश करके हमारा शुक्रिया लिया है, कहेंगे कि गवर्नमेंट ने तो इस रैजोल्यूशन पर अमल करना नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा? हमें भी ऐजिटेशन शुरू करनी पड़ेगी। हम देखेंगे कि टंडन साहिब ने हमारे लिए यह रैजोल्यूशन पेश किया है वह जब हम ऐजिटेशन करेंगे, उस वक्त हमारा साथ देते हैं या नहीं देते। अगर वह उस वक्त भी हमारा साथ देते हैं तो हम उन का डबल शुक्रिया अदा करेंगे और अगर उस वक्त साथ नहीं देते तो बात साफ हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप को पता ही है कि डिमांडज मनवाने की बाबत गवर्नमेंट की पालिसी क्या है। उसकी सदा यही पालिसी रही है वह किसी को कोई चीज नहीं देती किसी की कोई बात नहीं मानती जब तक कि लोग उसके लिए ऐजिटेशन न करें। तकरीरें करने को तो सभी कर देंगे कि मैं यह हूं वह हूं, यह कर दूंगा वह कर दूंगा। लेकिन कमजोर आदमी की आवाज सुनता कौन है? उस पर यकीन कौन करता है? गवर्नमेंट को उसकी बात पर तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक कि वह ऐजिटेशन नहीं करेगा। वह समझते हैं कि इन को हम ने आज तक आजमाया हुआ है, यह धमकियां हो देते हैं, करते तो कुछ है नहीं। इस लिए हमारी बातों का कोई असर नहीं होता और असर तब तक नहीं होगा जब तक हम उन को पूरी तरह से अपनी मजबूती नहीं दिखा देते। और टंडन साहिब की बातों पर हम तब विश्वास करेंगे जब कि हम ऐजिटेशन शुरू करें और वह हमारा साथ देंगे।

श्री बलराम जी दास टण्डन : जरूर देंगे।

श्रीधरी राम सरूप : बड़ी मेहरबानी आपकी, डबल शुक्रिया। हां, तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि हरियाणा के साथ बड़ी बेइन्साफी हुई है। यहां पर मिनिस्टर और तो कोई मौजूद है नहीं सिवाय प्रबोध जी के.....

**उपाध्यक्ष :** आप के रोहतक के तो तीन वजीर हैं। क्या आप को भी शिकायत है ? (Three of his Ministers hail from Rohtak. Does the hon. Member also complain on this account ?)

**चौधरी राम सरूप :** किसी को कम होने की शिकायत है और किसी को ज्यादा होने की शिकायत है। क्या आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसी भी बात की है जिसकी बाबत किसी की शिकायत न हो ? इस बारे में हर आदमी की अलग अलग राय है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि यहां पर प्रबोध जी बैठे हुए हैं और मेरी अपनी राय उन की बाबत यह है कि वह इन्साफ पसन्द और दलील के कायल होने वाले हैं। इस लिये

1.00 p.m.

उन की खिश्मत में अर्ज करना चाहता हूं कि उन को हरियाणा और खास तौर पर रोहतक के लोगों की बात का पता है। आप भी वहां पर रह चुकी हैं। उन लोगों ने लाखों रुपये लगा कर स्कूल की बिल्डिंगें बनाई हैं और वह इन के पीछे पीछे फिरते हैं कि उन के प्राइमरी स्कूलों को मिडल कर दो, अगर मिडल स्कूल है तो हाई कर दो। वह खर्च देने के लिये तैयार हैं मगर उन की कोई सुनवाई नहीं होती। जब वह अपना पैसा खर्च कर के अपने स्कूल को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद इन की भी कुछ मजबूरियां हैं जो यह बयान कर चुके हैं। हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि एक साल का खर्च दे देते हैं और आगे खर्च नहीं होगा। इस लिये यह कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करने के बारे में पालिसी ही तबदील कर दी है और इनकी यह राय है कि आयादा बहुत एह्तियात से स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। अब पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। अगर आप ने इन्कार ही करना है तो भई कोई शर्त ही लगा कर करो। मगर यह तो कहते हैं कि अब तो पालिसी ही यह होगी कि अपग्रेड करते वक़्त कई बातों का लिहाज रखा जायेगा। मगर वह लोग तो सारी बातें पूरी करने के लिये तैयार हैं। अगर इस के बावजूद उन की दरखास्त न मानी जाए तो यह उन के साथ बेहद बेइन्साफी होगी। मुझे बड़ा दुख है कि यहां पर रोज मरती यह बातें होती हैं। इधर मेरे पास बैठे डा० बलदेव प्रकाश वगैरह कहते हैं कि क्या कहते हो कि हरियाणा को अलग कर दो, उधर पंजाबी सूबे वाले भी कहते हैं कि उन को अलग कर दो। हमें उन का तो पता नहीं मगर हम इन से नाता हैं और पंजाबी सूबे के इलाके में रहने वाले लोगों से भी नाता है। सिखों की यह शिकायत है कि जाकी की आबादी उन से इन्साफ नहीं कर रही है। तो इस हिसाब से मैं उन की मांग को जायज समझता हूं। अगर किसी कम्युनिटी के साथ बेइन्साफी होगी तो यह उस को हक है कि वह अलहदगी के लिये दावा करे। हम आप का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कांग्रेसियों या दूसरों न यह कहा कि हरियाणा वालों के साथ जुल्म हो रहा है। यह तभी बात आती है जब हमें अपना हक नहीं मिलता। एक बाप हो उसके दो बेटे हों। एक कमाता है मगर उस को तो रूखी रोटी मिले और दूसरा जो नहीं कमाता भी के साथ रोटी खाए तो पहले के लिये सिवाए अलहदा हो जाने के और कोई चारा नहीं है। हमें यह बात समझ नहीं आती कि जब आप हमारे साथ दावे ही करते हो, उन पर अमल नहीं करते तो आप हमें अपने पांव पर खड़े क्यों नहीं होने देते। आप

हमें अलहदा रह कर अपने इलाके की बहबूदी के लिये कोशिश तो करने दो। ऐसा करने भी नहीं देते और हमारी मदद भी नहीं करते। यह ठीक बात नहीं है। हम लाचार हैं। इस वक्त हरियाणा के लोगों के दिलों में यह ख्याल है कि पहले तो हमारी बात नहीं सुनी गई, अगर इस बार भी न सुनी गई तो हम मर मिटेंगे और जो कुछ भी वह कर सकेंगे करेंगे। (तालियां) आप देखें कि इस डिमांड के बारे में दो तरह के लोग हैं एक कांग्रेसी और एक गैर-कांग्रेसी। हरियाणा के कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी इस बात पर मूत्तफिक हैं कि हम सूबे को एक जबानी सूबा नहीं रहने देंगे, दो जबानी रखेंगे। दूसरे हम हरियाणा के टुकड़े नहीं होने देंगे। इन दोनों बातों के लिये वह सब कुछ करेंगे। अब यह बात जो बाहर सुनने में आ रही है वह यह है कि इस सूबे को एक जबान का सूबा बनाने की कोशिश हो रही है। यह हरियाणा वालों को तो कमजोर समझते हैं इस लिये उन की जायज मांगों को नहीं मानते। उन का इन को डर नहीं है। इधर सिखों को समझते हैं कि यह तो बड़े सयाने आदमी हैं यह भी शायद मान ही जाएं। कुछ हिस्सा हो सकता है संत वाला ग्रुप जो शायद इस को भी न मानें, दूसरे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यह सोचते हैं कि यह समझेंगे कि इन को अब कुछ तो दे ही रहे हैं। बाकी जो हरियाणा वाले हैं इन को तो हम हमेशा देखते ही रहे हैं। हो सकता है कि इन के आदमी सोचें कि चलो अच्छा किया, हम तो कमजोर थे, बहुत छोटे थे, चलो अब हमें बालग तो समझा जाने लगा है। मगर इस बात को इन को समझ लेना चाहिए कि इस बार हरियाणा वालों ने हर तरह की कुर्बानी देने का मन बना लिया हुआ है। आप जानते हैं कि इन लोगों ने इस लड़ाई में कितनी कुर्बानी दी है। एक तरफ तो आप मानते हैं कि यह लोग बड़े बहादुर हैं मगर दूसरी तरफ जब वह अपने हक मांगते हैं तो उन को कुछ नहीं देते कि यह तो कुछ नहीं कर सकते। यह कहां का इनसाफ है। अब वहां के कांग्रेस क्या और दूसरे क्या सभी मजबूर हो गए हैं। मैं जो कह रहा हूं वह लोगों की तरजमानी ही कर रहा हूं। वह कहते हैं कि हम मर मिटेंगे। मैंने ओम प्रभा जी का हवाला दिया कि वह एक जबान वाली और हरियाणा के टुकड़े होने की बात को नहीं मानेंगे। इस बारे में वह कहती हैं कि आपोजीशन के एम. एल. एज. को लड़ने की जरूरत नहीं है। इस बारे में कांग्रेस वाले ही निपट लेंगे। इधर सेटंडन साहिब भी हमसे हमदर्दी दिखाते हैं, रैजिस्ट्रेशन भी लाते हैं मगर यह सब देखेंगे कि यह ऐजीटेशन भी मैं हमारे साथ होते हैं या नहीं। (विघ्न) डा० बलदेव प्रकाश जी कहते हैं कि साथ देंगे। तो मैं समझता हूं कि यह सूरमा और बहादुर कहलाएंगे। और अगर साथ न दिया तो मैं क्या कहूं वह लफ्ज पालियामेंट्री नहीं है। (विघ्न) (आवाजें : जरूर देंगे) देखेंगे। (आवाज : आप न दौड़ जाएं) हमारा इलाका तो बैकवर्ड है। आप जानते हैं कि बैकवर्ड आदमी डरता है मगर जब हमें ऐसे बहादुर मिल जाए तो हमें डरने की क्या जरूरत है। (विघ्न) अब हम तंग आ चुके हैं डिपलोमेसी से। इधर चीफ मिनिस्टर साहिब भी कहते हैं कि घबराओ नहीं, हरियाणा को सारे हक मिलेंगे। हाई कमांड वाले भी ऐसी ही बातें कहते हैं। बातें तो कहते हैं मगर अमल नहीं करते। अगर यह अमल करें तो हमें बड़ी खूशी होगी और मैं अपने आप को झूठा साबित होता हुआ भी खुश समझूंगा अगर आप ने ऐजीटेशन में हमारा साथ दिया। यह बात साफ हो जानी चाहिए कि अगर हम लोगों पर गुरमुखी ठोसी गई, (एक आवाज : नहीं

[ਚੈਂਬਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ]

ਠੋਂਸੀ ਜਾਯਗੀ।) ਤੋ ਉਸਕੋ ਹਮ ਕਿਸੀ तरह से भी बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं होंगे। (विघ्न) मैं आप का यकीन करता हूँ मगर आप की तरफ कुछ आदमी हो सकते हैं जो ऐसा चाहें। (विघ्न)

**Deputy Speaker :** No interruptions please.

**ਚੈਂਬਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ :** ਹਮ ਨੇ ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਐਮ ਪ੍ਰਭਾ ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਉਸ ਪੈਂਡਰ ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਨਨੇ ਕੀ ਤੈਯਾਰ ਹੈਂ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਕੁਝ ਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਲਿਯੇ ਕੁਝ ਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਬਹਨ ਐਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਕੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨ ਹੋਗਾ ਕਿਯੋਂਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਰ ਉਨ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਉਸ ਕਾ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਲਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਅਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੋਟਿਵ ਨ ਥਾ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਤੀਨ ਚਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੇ ਜੋ ਦਾਵੇ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਹ ਜੋ ਦੋ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਨੇ ਪਹਲੇ ਬਤਾਈ ਹੈਂ ਹਮ ਇਨ ਕੋ ਕਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਨ ਮੈਂਸੇ ਕੁਝ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਨਤ ਅਲਗ ਬਨੇਂ। ਕੁਝ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਲਗ ਬਨੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਝ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਹਿਲਲੀ ਏਰਿਆ ਅਲਗ ਬਨੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਸੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਜੋ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਵਹ ਹਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਦਬਾਤੇ ਰਹੇਂ। ਇਤਨਾ ਕਹ ਕਰ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਕਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਯਾ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈਂ। (विघ्न)

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਮੈਂਡਮ। ਮੇਰੀ ਏਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਰ ਆਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਮ ਬੈਂਕ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਕੋ ਬੋਲਨੇ ਕਾ ਸੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਿਯੇ ਹਮੇਂ ਬੋਲਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਜਾਏ।

**उपाध्यक्षा :** आप के पार्टी विहप ने आप का नाम नहीं भेजा तो मैं क्या कर सकती थी। अब आप बैठिए आप की बात आ गई है। (The whip of his party has not sent up his name. What can I do then ? Now he may take his seat. His point has come.)

**ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਤ :** (ਅੰਬ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਟੈਂਡਨ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਪੇਸ਼ ਅਜ ਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਫਿਰ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਉਨਾ

ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਡੇਹਰਾਗੌਪੀ ਪੁਰ ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਸੀਲ ਉਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਗੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਸੀਲ ਉਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੀ ਤਸੀਲ ਉਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਿਹਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਕਰਕੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਕਾਂਗੜਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰਿਟੀ ਨੇ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜ਼ਾਰਿਟੀ ਮਿਨਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਖਸਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਲੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਜਾਂ ਤਸੀਲ ਉਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਭੁਖਾ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਮੈਨ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਹਥ ਪੈਰ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਲ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੋਦੇ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਰੌਲੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਿਉ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੀਪਬਲਿਕਾਂ

[ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ]

ਬਣ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪਰ ਸਟੇਟ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਘਟ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟ੍ਰੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਤਸਵੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਅਜ 16 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ-ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਏਥੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਏਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਇਕਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ ਇਕ ਇਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿਚ 20—20 ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ.....

**ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜਾਧ :** ਕਥਾ ਜ਼ਾਨੀ ਜੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲਿਥਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਬਨ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਥੰਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਸਨੀ ਸੀਟ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। (Let the hon Member take care of himself. He need not bother about the Chief Parliamentary Secretary.)

**ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ :** ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟਾਪੂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਏਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਗਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 274 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ 274 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਦੁਰਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ

ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲਕੇ ਤੱਕ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਕ ਰੋਡ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਾਰੀ ਲਾਲ ਕਰੀਨਾ (ਏਸ ਸੰ) : यह जो रैजोल्यूशन हिल एरियाज़ और हरियाणा की बैकवार्डनेस के मुतालिक चल रहा है . . . (विघ्न)

ਸ਼੍ਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ ਵਿਜ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, ਮੈਂਡਮ ।

जब आप ने पाटी वाईज़ बोलने वालों के नाम पुकारे थे तो उस उस वक्त बोलने वालों के नाम नहीं थे अब इनको कौनसी पार्टी की तरफ से बोलने की इजाज़त दी दी गई है

उपाध्यक्षा : आप बैठ जायें । यह मेरा अपना काम है । आप तशरीफ रखें ।  
(The hon Member may take his seat. This is my job to see to it.)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਾਰੀ ਲਾਲ : सब से पहले मैं टंडन साहिब का श्रुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हरियाणा के मुतालिक यह रैजोल्यूशन रखा है। मेरा ख्याल है कि पंजाबी रिजन वालों को हमारा अब खयाल आया है कि हरियाणा वाले बैकवर्ड हैं। इसमें कोई शक नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिब कि हरियाणा वालां से बड़ी देर से बेइन्साफी हो रही है। आप तो वखूबी जानती हैं कि हमारा इलाका महेन्द्रगढ़, कितना बैकवर्ड है। आज भी इतनी देर से आज़ादी हासिल हो जाने के बाद भी इस की क्या हालत है। जों आज़ादी के ज़माने में भी इस इलाके ने बड़ी बड़ी लड़ाईयां लड़ी है। 1857 में जब गदर हुआ था तो महेन्द्रगढ़ का इलाका सब से आगे था जिस का नतीजा यह हुआ था कि इस इलाके के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे। कुछ इलाका जींद स्टेट को, कुछ इलाका पटियाला स्टेट को, कुछ नाभा स्टेट को और कुछ अलवर को अंग्रेजों ने बांट दिया था। हम समझते थे कि इस मुल्क को जब आज़ादी मिलेगी तो हम भी सुख की सांस लेंगे। मगर आज़ादी आई को भी 18 साल के करीब हो गए हैं, महेन्द्रगढ़ के इलाके से वही सोतेली मां वाला सतूक किया जा रहा है। आप किसी भी चीज़ को क्यों नालें, हर बात में इस को पीछे धकेल रखा है। पंडित जी ने यहां पर बताया है कि पानी से पतली कोई चीज़ नहीं है आप देखें यह हरियाणा डिबैल्पमेंट कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है। इस के पेज 179 पर लिखा है कि हरियाणा के 8,500 गांवों में से 3,600 गांव ऐसे हैं जहां पर पीने को पानी भी नहीं मिलता। अब आप उस इलाका की डिबैल्पमेंट का ही अन्दाजा लगाएं जिस इलाके में कि पीने को पानी तक न मिलता हो। जहां पर लोगों को पीने का पानी तक न मिलता हो इस से और बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए और क्या हो सकती है। इस इलाके के लोगों के साथ हरियाणा के इलाके लोगों को रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारे साथ जगह जगह नाइन्साफी की जा रही है जो कि अब बरदाशत से बाहर है।

[श्री बनवारी लाल]

आप देखें कि इस इलाका को सैराब करने के लिये माईनर ईरीगेशन स्कीमात कोई तैयार नहीं की गई। एक सोना लिफ्ट स्कीम तैयार हुई जिस से 1.70 हजार एकड़ गुड़गांव और 1.15 हजार एकड़ महेन्द्रगढ़ के इलाके की जमीन सैराब होनी थी, मगर इस इलाके की डिवैल्पमेंट के लिये यह सरकार बजट अलाट करती है महज 1 लाख रुपया इस स्कीम के लिये। क्या कभी इस तरह स्कीमज कामयाब होती हैं? जितनी भी स्कीमज इस इलाके की डिवैल्पमेंट के लिये बनाई गई हैं वह सारी की सारी कागजी स्कीमज बन कर रह गई हैं। बड़ी बड़ी सड़कों को आप चाहे ले लें जो फर्स्ट फाईव-इयर प्लैन में बनाई जानी चाहिए थीं परन्तु वह सब कागजी स्कीम में बन कर रह जाती हैं। असेम्बली क्वैश्चन जब आता है तो यह कह देते हैं कि हम बहुत जल्दी यह काम शुरू कर रहे हैं मगर जब सेशन खत्म हो जाता है इस के साथ ही इन के सारे वायदे ही खत्म हो जाते हैं। पहले सरदार प्रताप सिंह की हकूमत आई तो यह कहते रहे कि हम हरियाणा की डिवैल्पमेंट करेंगे मगर अब कामरेड राम किशन कहते हैं कि मैं हिन्दी और पंजाबी रिजन की कोई तमीज नहीं रखूंगा, दोनों को डिवैल्प करूंगा। दो साल हो गए हैं इन से भी इस इलाके के लिये कुछ नहीं हुआ। आखिर इस इलाके में क्या कमी है जो यह अभी तक कोई स्कीम भी नहीं बना सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, रा-नैटिरियल महेन्द्रगढ़ के इलाके में मिलता है, लाईम स्टोन यहां मिलता है, लोहा यहां मिलता है। प्लैनिंग कमिशन की रिपोर्ट में यह सब कुछ दर्ज है। एक इलाके का हक काट कर दूसरे इलाके को बनाने के बहाने से सारा नुकसान हमारे इलाके पर पड़ता है। इस तरह की बातें अब बरदाश्त करने वाली नहीं हैं। हमें हर हालत में अपने हक मिलने चाहिए। इस हाउस में हम कोई 300 रु: माहवार लेने की गर्ज से तो नहीं आते। जब हम अपने इलाके के लोगों के हक की रक्षा ही नहीं कर सकते तो हमारा यहां बैठना फजूल है, यहां हमें आने का कोई हक नहीं है।

मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं और पहले भी कहा था कि एक बात गवर्नमेंट सोच ले, इस के बारे में महेन्द्रगढ़ के लोग कुरबानी दे सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि जब हरियाणा के लोग नेफा और लद्दाख में लड़ सकते हैं, चणूल के हवाई अड्डे को बचा सकते हैं, लड़ाई के डिफरेंट सैक्टर्ज में लड़ सकते हैं तो क्या वह अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते वह अपने हक के लिये लड़ेंगे और अपनी जान की बाजी लगाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब यह बरनिंग टॉपिक पंजाबी सूबा और हरियाणा का है। आप जानती हैं। (विध्वन)

सरदार गुरचरण सिंह: हरियाणा प्रांत के बारे में अपने विचार बता दें।

श्री बनवारी लाल: उसी पर आ रहा हूं। जब हम यह सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता, हरियाणा के जमींदार के नाम से पंजाबी रिजन का जमींदार, बनियों के नाम से वहां का बनिया तथा हरिजनों के नाम से वहां का हरिजन खा रहा है तो उस का इलाज यह किया जाए कि हमें अलहदा कर दो (विरोधी पक्ष की ओर से प्रशंसा) हम यह कहते हैं कि यह मांग हमें हरियाणा के लोगों को करनी चाहिए थी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पंजाबी सूबा की मांग की है। सैक्रेटेरिएट में देखें जाट का नाम ले कर हमारा हक्क ले जाते हैं। हरिजन के नाम से हमारा हक्क वहां के हरिजन ले जाते हैं और पंजाबी रिजन वाले हमारा

हक्क ले जाते हैं और शोड्यूल्ड कास्ट के नाम पर भी हमारा हक्क ले जाते हैं। अगर किसी तबके को इन्साफ नहीं मिलता तो उसे इनके साथ रहने का हक्क नहीं। (विरोधी पक्ष की ओर से प्रशंसा) या तो सरकार सीधे हाथों से मान जाए या फिर हमें लड़ कर अपना हक्क लेना होगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, देश की आजादी की लड़ाई तो आप ने भी लड़ी है। आजादी के लिये आप ने क्या नहीं किया? आप जेलों में गई और हम भी अपने हक्क के लिये जेलों में चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी के एम. एल. ए. ने लिख कर अपना अस्तीफा भेजा था। उन्होंने सोच कर भेजा है। हम चाहते हैं कि हम अलहदा हों, उन का पंजाबी सूबा बने या न बने, हमारा हरियाणा बने। (विरोधी पक्ष की ओर से प्रशंसा) फिर आप किसी कण्डीशन पर तो आएंगे। आज देश आजाद है। इस की नीति ऐसी है कि आप किसी चीज को बाई फोर्स नहीं करवा सकते, बाई परसुएशन करवा सकते हैं अगर ऐसा नहीं है तो यह आजादी नहीं यह तो डिक्टेटरशिप है। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि यह हमारे साथ नाइन्साफ होगी। इस लिये हम कहते हैं कि हमें अलहदा कर दो। यह चाहते हैं कि हम खत्म हो जाएं परन्तु हमारी अपनी मांग पूरी की जाए। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आप का धन्यवाद करता हूं।

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : आदरणीय उपाध्यक्षा महोदया, मैं आप के द्वारा प्राज हाउस में गैर सरकारी प्रस्ताव पर चल रही बहस में हिस्सा लेता हुआ कुछ अपने विचार रख रहा हूं। पंजाब के प्रांत में दो रिजन हैं, एक पंजाबी रिजन और एक हिन्दी रिजन। हिन्दी रिजन वाले अपनी बहबूदी के लिये कोशिश कर रहे हैं और पंजाबी रिजन वाले अपनी बहबूदी के लिये कोशिश कर रहे हैं। दोनों रिजनों में अपनी अलग अलग बोली है। अपनी बोली के साथ इन इलाकों ने तरक्की करनी है लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हैरान हूं कि आज 16 साल का अर्सा हो गया है अभी तक हिन्दी रिजन पिछड़ा हुआ रहा है। वहां कहत पड़ता रहा। जानवरों की कमी है। नहर का पानी न मिलने की वजह से बिजली की सप्लाई होकर जो यूब-वैल लगने चाहिए थे वह भी नहीं लग पाए। वह इलाका हर तरह से पिछड़ा रहा। चाहे वह आर्थिक मसला था, चाहे सरकारी मुलाजमों का, चाहे खेती बाड़ी, इण्डस्टरी, तालीम या कोई और मामला था वह सारे का सारा ताकतवर इलाके के लोग यानी पंजाबी इलाके के लोग अपने हाथों में लेते रहे और उसका फायदा उठाते रहे। उसका सबन हमारे सामने आज यह प्रस्ताव यह कह रहा है कि हरियाणा रिजन पिछड़ा हुआ इलाका है। पहाड़ी इलाका पिछड़ा हुआ है। हरियाणा पिछड़ा हुआ इलाका है इस लिये जरूरत है कि इस बीसवीं सदी में उस इलाके को मदद दी जाए। आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हरियाणा के लोगों ने आवाज उठाई है कि हम अपने आप को खुद मुख्तियार करें जिस तरह भारत की दूसरी स्टेटें अलग अलग सुबों में हुई हैं। हमारे पंजाबी रिजन के भाइयों का खयाल है कि यह पिछड़े हुए हैं, इनको 60 फी सदी रुपयों की इमदाद दी जाए। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर कोई मां से ज्यादा प्यार करती है तो वह डायन होती है। इस का मतलब साफ है कि पंजाबी रिजन के लोगों को खयाल है कि हरियाणा एरिया और हिल्ली एरिया जो पहाड़ी इलाका है वह पिछड़ा हुआ है और उन पर रहम बरपा करें। यह क्यों हो रहा है? यह इस लिये कि इस इलाके में इस प्रांत के अन्दर अपने देश के हिस्से के अन्दर दो बोलियां के लोग रहते हैं। एक पंजाबी

बोलते हैं और एक हिन्दी बोलते हैं। हिन्दी बोलने वाला वह इलाका है जिसको हरियाणा कहते हैं और पंजाबी बोलने वाला वह इलाका है जिसे आज आप पंजाबी रिजन के नाम से पुकारते हैं। आज वह लोग जो पंजाबी रिजन के अन्दर रहने हैं उस इलाके की, उस रिजन की यह अक्सरीयत चाहती है कि हमें अलग पंजाबी सूबा बना कर मौका दिया जाए ताकि हम तरक्की कर सकें क्योंकि आज तक उनको भी, जिस तरह से आज हिन्दी रिजन पिछड़ा हुआ है उसी तरह से जो अक्सरीयत में हैं उन्हें रियायतें नहीं दी जा रही हैं। सर्विसिज में नौकरियों में और दूसरी चीजों में रियायतें दी जा रही हैं, यह रियायतें दी जाती थीं, वह रियायतों से आखिरकार तंग आ गए। उस ढंग से तंग आ गए। उन्होंने ने ऐसा मन बनाया है कि क्यों न एक प्रांत बना कर इस भीख को छोड़ कर अपना हक्क हासिल करें और अपनी ताकत से अपनी सरकार को चलाएं और अपने इलाके के लोगों को तरक्की दिलाएं। आज जब हरियाणा के लोगों ने देखा कि हम भी ढूँढ़े हुए हैं, हम क्योंकि हमेशा पिछड़े हुए रहे जब कांग्रेस सरकार ने भा. देश में इस किस्म का ढंग इखितयार किया—आन्ध्रा प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात बनाया तो क्यों न हरियाणा के लोग अलग हो कर तरक्की करें। मैं मानता हूं, मैं पंडित मोहन लाल दत्त की राय की, उनके ख्याल की तारीफ करता हूं। मैं इस ख्याल का हूं कि अमीरों और गरीबों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह उसी तरह से रहेंगे। अमीरी और गरीबी इसी तरह से रहेगी। आज अगर हरियाणा प्रांत बन जाएगा तो हरियाणा के चौधरियों के हाथ में हकूमत जाएगी। गरीब किसान को कुछ नहीं मिलेगा। पंजाबी सूबे में गरीब सिक्ख को कुछ नहीं मिलेगा, अमीरों के हाथ में सब कुछ जाएगा। यह पापी कांग्रेस जो है यह हिन्दू और सिक्ख का नाम ले कर हिन्दी और पंजाबी का नाम ले कर आपस में लड़ती है। इस लानत से हम बच जाएंगे जब पंजाबी सूबा और दूसरा इलाका अलहदा अलहदा बन जाएगा। जब सिक्खों और हिन्दुओं में कोई झवाल पैदा होता है और वह अपने हकूक के लिये खड़े होते हैं तो यह फिरकाप्रस्त सरकार कहीं हिन्दी और पंजाबी का नाम ले कर मजदूर और किसानों की ऐजिटेशन को इस तरह की बताती है और कभी हिन्दू और सिक्ख का नाम ले कर ऐसा कहती है और इस किस्म की बात करती है कि हिन्दी स्टेट अलग स्टेट नहीं बननी है और पंजाबी रिजन अलग स्टेट बनने जा रही है। उनका मतलब है कि हिन्दू और सिक्ख आपस में लड़ते रहें और गरीबों का गला घुटता रहे और सरमाएदार नजाम पनपता रहे। कांग्रेस सरकार इस देश में जो लानत है वह बाहर के शों में नुमायश करती है और इस देश के नाच और गाने होते हैं। जो नुमायश में पैमे इक्ठे होते हैं वह इस देश के गरीबों को देती है। इस तरह से यह कांग्रेस सरकार इस देश को डबो रही है। इस सरकार का खातमा तभी हो सकेगा जब फिरकाप्रस्ती और भाषा की लड़ाई बन्द हो जाएगी। इस लिये मैं इस बात का हामी हूं कि पंजाबी रिजन में पंजाबी सूबा बनना चाहिए और हरियाणा का अलग प्रान्त बन जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिब, हरियाणे के लोगों को 1857 में सजा मिली थी क्योंकि इस मार्शल कोम ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। आज कल का मेरठ डिवीजन, आगरा डिवीजन, अम्बला डिवीजन और देहली का कुछ हिस्सा सारा उस वक्त हरियाणा डिवीजन था,

**उपाध्यक्ष:** चौधरी नेत राम जी, माईक आप के सामने है इस लिये इतने जोर से न बोलें। (Addressing Chaudhri Net Ram.) (The hon. Member

need not speak so loudly as the mike is before him.)

**चौधरी नेत राम :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस लिये जोर से बोलता हूँ कि शायद यह बहरी और अंधी सरकार इसी तरह से हमारी बुलंद आवाज़ को सुन ले। तो मैं बता रहा था कि जब यहां पर अंग्रेजों ने हकूमत कायम करनी चाही तो हरियाणा ने उन के खिलाफ लड़ाई की। जब अंग्रेज ताकत में आ गए तो उन्होंने सोचा कि इन को अलग अलग करने से ही हमारा भूत है।, चुनांचि उन्होंने एक भाषा वाले इलाके को तीन जगहों में बांट दिया ताकि वह आपस में लड़ते झगड़ते रहें और उन की हकूमत ताकत में रहे। ठीक उसी तरह यह कांग्रेस की सरकार फिरकाप्रस्ती का जहर फैलाती है और देश को फिरकाप्रस्ती की आग में डबो रही है। आप जानते हैं कि 1952 में अकाली पार्टी वाले कांग्रेस के साथ पूरा सहयोग देकर अपने आप को कांग्रेस में मद्गम करके बैठ गए थे लेकिन इस फिरकाप्रस्त कांग्रेस जमात ने उन्हें इस लिये बरदाशत नहीं किया कि अगर अकाली मेजारिटी में हो गए तो कहीं वह गद्दियों पर काबिज़ न हो जाएं। इस लिये इन्होंने आकालियों को फिर अलहदा होने पर मजबूर किया। इन्होंने सारे देश को लड़ाया। अगर यह चाहते हैं कि हरियाणा के लोग तरक्की करे तो उन को भीख न दें बल्कि उन्हें खुद मुख्तियार होने दें और उन्हें उनके हक्क दें। तब ही वह अपने पांव पर खड़े हो कर तरक्की कर सकेंगे। इस से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप का शुक्रिया अदा करके बैठता हूँ।

## BILL ALREADY INTRODUCED

### The Punjab University (Amendment) Bill, 1965.

**Giani Kartar Singh (Dasuya) :** Madam, I beg to move—

That the Punjab University (Amendment) Bill be referred to a Select Committee consisting of :—

1. The Education Minister,
2. Shri Ram Saran Chand Mital,
3. Sardar Gurnam Singh,
4. Comrade Shamsheer Singh Josh,
5. Shrimati Dr. Parkash Kaur,
6. Shri Amar Singh, and
7. My self (Giani Kartar Singh)

with a direction to make a report by the 28th February 1966.

**Deputy Speaker :** Motion moved—

That the Punjab University Amendment Bill be referred to a Select Committee consisting of :

1. The Education Minister,
2. Shri Ram Saran Chand Mital,

3. Sardar Gurnam Singh,
4. Comrade Shamsheer Singh Josh,
5. Shrimati Dr. Parkash Kaur,
6. Shri Amar Singh, and
7. Giani Kartar Singh

with a direction to make a report by the 28th February, 1966.

**प्रिंसिपल रला राम ( मुकेशियां ) :** उपाध्यक्षा महोदया, इस बात से किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी की वर्किंग में सुधार होना चाहिए और हर कोई इस बात से सहमत है कि उसमें सुधार की गुंजायश है लेकिन जो बिल ज्ञानी जी की तरफ से पेश किया गया है और जिसके बारे में प्रस्ताव किया गया है कि उसे सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाए उस से कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है । उसका बड़ा भारी कारण यह है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट उन बातों पर विचार कर रही है. . . . .

**उपाध्यक्षा:** गर्ग साहिब, किसी सीनियर मिनिस्टर को बुलाएं । यह हाउस है कोई मजाक नहीं है । चेयर को खाहमखाह कनफ्यूडन में पड़ना पड़ता है । अगर पांच मिनट के अन्दर कोई नहीं आएगा तो I will adjourned the House । (शोर)

(The Chief Parliamentary Secretary, Shri Garg may request some Senior Minister to attend the House. It is an august House and not a place to be made fun of. The Chair has unnecessarily to face confusion on this account. If no Minister comes to the House within five minutes. I will adjourned it.) (Uproar)

**प्रिंसिपल रला राम:** मैं अर्ज कर रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में एक माडल बिल बना रही है और अगलबन थोड़े समय के अन्दर अन्दर वह सारे राज्यों में सरकुलेट कर दिया जाएगा और वह सारे देश की यूनिवर्सिटियों के लिये एक माडल कांस्टीच्यूशन सुजेस्ट करेगा ताकि इस सम्बन्ध में सारे देश में यूनिफार्मिटी हो । इन हालात में मैं समझता हूं कि यह बिल अगर इस स्टेज पर प्रैस न किया जाए और इस वक्त इसे मुलतवी कर दिया जाए तो निहायत अच्छी बात होगी । रिफार्मज की जरूरत है और हम इस बात से इन्कार नहीं करते लेकिन वह सुधार इस तरीके से होना चाहिए जिस से हिन्दुस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में ताल मेल हो और उनकी एक जैसी वर्किंग हो । सुधार की जरूरत है और इसी जरूरत को अनुभव करते हुए ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक माडल बिल ला रही है जो सब राज्यों को सरकुलेट होगा । मैं समझता हूं कि उसकी रोशनी में हमारी सरकार जरूर कोई न कोई कम्प्रिहैन्सिव बिल लाएगी और जो नुकस हैं उन्हें दूर किया जाएगा और जिन सुधारों की आवश्यकता है उन्हें लाएगी । इस बिल में हो सकता है कि कई अच्छी बातें हों लेकिन मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर यह बिल अधूरा ही होगा और इस से विशेष लाभ नहीं होगा बल्कि कई नुकसान हो सकते हैं । इस लिये मैं समझता हूं कि इस वक्त इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का कोई फायदा नहीं होगा और हमें माडल बिल का इन्तज़ार करना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे राज्यों को सरकुलेट

ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਸਦੀ ਰੀਜ਼ਨੀ ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਏਕ ਕਮਿਸ਼ਨੈਰਿਸਕ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਕੋ ਸਾਮਨੇ ਲਾਏਗੀ। ਇਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕੋ ਸਾਥ ਸੋਂ ਕਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਜੋ ਬਿਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੀਮੈਂਚਰੀਓਰ ਐਂਡ ਅਨਜ਼ੈਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਸੋ ਸੋ ਇਨੇ ਜੁਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇ ਖਯਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਿਯੇ ਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸ ਤੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਡਲ ਬਿਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੁਖਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ 107 ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਸੀਮਤ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕਿਤਨਾ ਚਰਚਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸੋਧ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਇਕ ਇਕ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਡਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਨ ਲਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮਾਡਲ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਾਕਿਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਫਾ ਮੁਆਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਕਿਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ, ਪਰਭਾਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਏ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ 29 ਮੈਂਬਰ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ।

2.00 p.m.

**Mr. Speaker :** The hon. Member should not comment on this provision of the Bill.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਂਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ 107 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ 101 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੀਲੇਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪੈਟਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਿਊਰਲੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸੁਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇਗੀ।

**ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਹਾ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਿਤ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਟਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਸਬ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਭਿਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੀਫੈਕਟ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਸਬ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਰਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਥੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮੀਨੇਟਿਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਮੈਂਬਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਿਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਲੈਕਟਿਡ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ

[ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ]

ਬਿਲ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ । ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਬਿਲ ਇਹ ਲੈ ਆਉਣ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ । ਉਹ ਬਿਲ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਿਚ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਿਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ । ਚੂੰਕਿ ਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ।

**ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ :** 28 ਅਗਸਤ, 1966 ਤਕ ਮਿਆਦ ਮੰਗ ਲਵੋ ।

**ਅਧਯਕਸ਼ :** ਪੇਸ਼ਕਰ ਇਸ ਕੇ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਟਿੰਗ ਕੇ ਲਿਯੇ ਪੁਟ ਕਰੂੰ, ਜ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਾ ਏਯਾਨ ਰੂਲ 133 ਕੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 2 ਕੀ तरफ़ ਦਿਲਾਨਾ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ । ਜੋ ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਮੋਸ਼ਨ ਸੂਰ ਕਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਤਨ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਪਰ ਯਾਨ ਲੇਨਾ ਚਾਹਿਏ ਕਿ ਜਿਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਕਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਤੇ ਹੈਂ ਕਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪਰ ਸਰਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਤੈਯਾਰ ਹੈਂ । ਮੈਂ ਤਸਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪੂਲ ਲਿਯਾ ਹੋਗਾ । ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਨਾਮਾਂ ਮੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਪੈਨਲ ਆਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ । ਇਨ ਨਾਮਾਂ ਮੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਸਿਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪੈਨਲ ਆਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਂ । ਇਸ ਲਿਯੇ ਬੋਟ ਕਰਵਾਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਆਪ ਇਸ ਕੀ ਦੀਬਾਰਾ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਲੋ ।

(Before I put the motion to the vote of the House I would like to draw the attention of the hon. Member Giani Kartar Singh to Rule No. 133 [2]. It enjoins upon him that the mover shall as certain before moving his motion for reference of the Bill to the Select Committee whether the members proposed to be included by him in his motion are willing to serve on the Committee. I hope he must have secured their consent.)

The other thing is that the name of the Deputy Speaker or of a member of the Panel of Chairmen shall not be included in the motion. Out of these names, Sardar Gurnam Singh, Dr. Baldev Parkash and Mital Sahib, are already members of the panel of Chairmen. He may, therefore, reconsider the matter before the motion is voted upon.

**ਆਵਾਜ਼ੋ :** ਜ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੋ ।

**ਜ਼ਾਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ :** ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਤੀ ਮੈਂ ਅਖੀ ਨਾਮਾਂ ਮੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੀ ਅਗਯੇ ਹੁਕਤੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਂ, ਮੈਂ ਨਾਮਾਂ ਮੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦੂਗਾ ।

श्री अध्यक्ष : आप इन तीनों के नाम जरूरी चाहते हैं ? (Does the hon. Member Giani Kartar Singh want to retain the names of all the three gentlemen on the Select Committee ?)

ज्ञानी करतार सिंह : बड़े एक्सपीरिएन्स आदमी हैं, इन को रहने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इन्सिस्ट करते हैं तो मैं इजाजत दे देता हूँ।  
(If he insists to retain them, then I give my consent.)

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab University (Amendment) Bill be referred to a Select Committee Consisting of :

1. The Education Minister,
2. Shri Ram Saran Chand Mital,
3. Sardar Gurnam Singh,
4. Comrade Shamsheer Singh Josh,
5. Shrimati Dr. Parkash Kaur,
6. Shri Amar Singh, and
7. Giani Kartar Singh,

with a direction.....

श्री राम सरन चन्द मिश्रल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरी प्रार्थना है कि 28 फरवरी तक काम नहीं हो सकेगा महीना दो महीने के लिये तारीख एक्सटेंड कर दें।

Mr. Speaker : I cannot extend the time. The mover should agree to it.

Shri Ram Saran Chand Mital : Sir, the mover is agreeable. He says that the date be extended upto the 31st March, 1966.

श्री बलरामजी दास टण्डन : स्पीकर साहिब, मेरी प्रार्थना है कि इसमें हाउस के सभी ग्रुप्स के नुमाइंदों को रीप्रिजेंटेशन मिलनी चाहिए।

Mr. Speaker : This is not in my hand

श्री बलरामजी दास टण्डन : हम अमेन्डमेंट तो पुट कर सकते हैं। हम ने तो आप के द्वारा ही सूवर को रिक्लूएस्ट करनी है।

गिआनी करतार सिंह : मैं ऐग्री करदां हां जी, डाक्टर बलदेव प्रकाश दा नां रव लवें।

श्री सपीकर : मेरे पास कोई ऐग्रीड मॉशन आउट्री चाहीदी है।

(The hon. Member should put forth some agreed motion.)

**Voices :** It is agreed, Sir.

**Mr. Speaker :** Will the Select Committee consist of eight Members now as Dr. Baldev Parkash's name has been included ?

**Giani Kartar Singh and Some other Voices :** Yes.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Punjab University (Amendment) Bill be referred to a Select Committee consisting of

- (1) The Education Minister,
- (2) Shri Ram Saran Chand Mital,
- (3) Sardar Gurnam Singh,
- (4) Comrade Shamsheer Singh Josh,
- (5) Shrimati Dr. Parkash Kaur,
- (6) Shri Amar Singh,
- (7) Dr. Baldev Parkash, and
- (8) Giani Kartar Singh

with a direction to make a report by the 31st March, 1966.

After ascertaining the votes of the Members by Voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it. This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for 'Aye' and those who were for 'No', respectively, to rise in their places and on a count having been taken, declared that the motion was carried.

(When the count was being taken Shrimati Sarla Devi and Sardar Jagir Singh 'Dard' were not in their respective seats. On having been pointed out by the Opposition Benches, they went to their respective seats.

For the motion .....19

Against the motion .....18.)

*The motion was declared carried.*

*(Cheers from the Opposition Benches).*

2.23 p.m. *(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 25th February 1966.*



"C" (1966) Published under the authority of the Punjab Vidhan Sabha, and printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab, Chandigarh.

# Punjab Vidhan Sabha

## Debates

25th February, 1966

Vol. I—No. 8

OFFICIAL REPORT



### CONTENTS

Friday, the 25th February, 1966

	Page
Starred Questions and Answers ..	(8)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45 ..	(8)25
Unstarred Question and Answer ..	(8)37
Points of Order ..	(8)37
Question of Privilege ..	(8)37
Adjournment Motions/Call Attention Notices ..	(8)38
Announcement by the Speaker ..	(8)49
Adjournment Motions/Call Attention Notices (Resumption) ..	(8)49
Supplementary Estimates (Second Instalment), 1965-66 ..	(8)50
Presentation of the Report of the Estimates Committee on Supplementary Estimates ..	(8)50
Bill(s)—	
The Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment)—, 1965	(8)50
The Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Amendment—, 1965	(8)69—96

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੁਆਰਾ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਲਾਹੌਰ

ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

# ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 8,

DATED THE 25TH FEBRUARY, 1966

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
Shri	Shr	(8)1	19
शार्टेज	शर्टेज	(8)4	18
सुधारने	सधारने	(8)5	27
were	wre	(8)9	31
दरिया बुर्द	दर्या बुद	(8)11	1
President	Piesident	(8)19	13
श्रीमती सरला देवी	श्रीमती रला देवी	(8)23	1
QUESTIONS	QUESAIONS	(8)31	Heading
anything	any hing	(8)43	8th from below
Transport	T ansport	(8)55	18
Amendment	Amendmen	(8)66	10
Governor	Gov rnor	(8)75	2
मअठे	मअठे	(8)81	26
वाला	वाले	(8)92	4
कितना	कितन	(8)92	5
सेशन	सशन	(8)92	6
ठीक	ीक	(8)92	8
ढिल्लों	ि ल्लों	(8)92	14
पैटर्न	तैटर्न	(8)92	20
इन्कमटैक्स	इनकमटैक्ड	(8)92	27
कोआप्रेटिव	कुआ ेटिव	(8)93	14
Average	Avcrage	ii	6

# ਅੰਕ ੨੨

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਦਿਨ ੨੨ ਮਾਰਚ ੧੯੬੨

ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਨੰਬਰ	ਨਾਮ	ਨਿਰਵਾਚਨ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧	੧	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨	੨	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩	੩	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪	੪	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੫	੫	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੬	੬	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੭	੭	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੮	੮	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੯	੯	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੦	੧੦	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੧	੧੧	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੨	੧੨	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੩	੧੩	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੪	੧੪	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੫	੧੫	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੬	੧੬	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੭	੧੭	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੮	੧੮	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੧੯	੧੯	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੦	੨੦	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੧	੨੧	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੨	੨੨	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੩	੨੩	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੪	੨੪	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੫	੨੫	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੬	੨੬	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੭	੨੭	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੮	੨੮	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੨੯	੨੯	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੦	੩੦	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੧	੩੧	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੨	੩੨	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੩	੩੩	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੪	੩੪	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੫	੩੫	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੬	੩੬	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੭	੩੭	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੮	੩੮	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੩੯	੩੯	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੦	੪੦	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੧	੪੧	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੨	੪੨	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੩	੪੩	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੪	੪੪	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੫	੪੫	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੬	੪੬	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੭	੪੭	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੮	੪੮	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੪੯	੪੯	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ੫੦	੫੦	ਮੁਖੀ	ਮੁਖੀ

ਟੀ  
ਸੀ  
ਇਨ

92  
ma

ਕਿ  
ਸਾ  
ਕਿ

ਕਿ  
ਕਰ  
ਮੁਨ  
ਪਿ  
ਜਵ  
ਗਯਾ  
Se  
ad  
so  
cal  
Mi  
is  
or  
lik  
pre  
me  
ans  
on

(ਗਮ)

## PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 25th February, 1966

*The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.*

### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

#### Starred Questions Nos. 9167 and 9232

**Mr. Speaker :** Supplementaries to Starred Questions Nos. 9167 and 9232 are postponed as the Minister concerned is not present and he has made a request to this effect.

**श्री मंगल सेन :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, आपने फरमाया है कि मिनिस्टर साहिब यहां पर मौजूद नहीं हैं। मगर इस समय हाउस में तीन मिनिस्टर साहिबान मौजूद हैं, एक आधा एक पौना और काम चलाऊ वज़ीर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह जायंट रैस्पोंसेबिलिटी वाली बात खत्म हो गई है?

**श्री अध्यक्ष :** डा० मंगल सेन जी, मैं आप से और सब साहिबान से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप किसी मिनिस्टर को या मੈम्बर को ऐड्रेस करें तो बाकायदा पार्लियामेंट्री तरीके से करें। इस तरह से आधा या पौना मिनिस्टर कहना मुनासिब नहीं है (विघ्न) वही करें जो मुनासिब हो। क्वेश्चन आवर में तो एक ही घंटा है उसे जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लें। पिछली दफा जब यहां पर सप्लीमेंटरी सवाल आए थे तो यह रिक्वेस्ट की गई थी कि इन के जवाब सरदार दरबारा सिंह जी ही दें जो कि उस वक्त नहीं थे इस लिये उन को पोस्टपोन किया गया था। (I would request the hon. Member Shri Mangal Sein and other Members also that whenever they address an hon. Minister or a Member, they should do so in a proper parliamentary manner. It is not proper to call a Minister as half Minister or three-quarters Minister. (Interruptions). They should always do what is proper. We have only an hour at our disposal for oral answers. This may be utilised in any manner they like. Last time, when Sardar Darbara Singh was not present, it was demanded by the Members that supplementaries to questions standing in his name should be answered by him alone and the questions were postponed on that account.)

**श्री मंगल सेन :** वह कब तक दिल्ली रहेंगे ?

**सरदार नगजीत सिंह गोगोआठी :** असीं मैसठ दिੱਲੀ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਚਲੀਏ (ਹਾਸ)।

**Short Supply of Water in Canals**

**\*9233. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the reasons for the short supply of water in the canals in the year 1965-66 ;
- (b) whether Government has received any complaint or information to the effect that there is shortage of water in the various canals ; if so, the details of the remedial measures adopted by the Government in this connection ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Failure of monsoons and winter rains.

(b) Yes.

- (i) Programme for rotational running of various branches was framed for equitable distribution of available supplies.
- (ii) Maximum use was made of the Jagadhri Tubewells to augment supplies.
- (iii) A project for sinking of tube-wells in the Western Jamuna Tract for supplementing canal supplies has been taken in hand.
- (iv) Five Lift Irrigation Schemes from canals have been sanctioned in the famine affected areas to provide relief.
- (v) A number of Minor Irrigation Schemes planned to yield quick results have been taken in hand.
- (vi) About 11,000 private tube-wells are being electrified.
- (vii) All pumping sets of the Drainage Department were placed at the disposal of Agriculture Department for lifting water for irrigation from drains and depressions.

सरोवर साहिब, जो चौथा हिस्सा है उसमें जो 5 है उसकी बजाए 7 हो गई है। दो स्कीमज सैंकशन हो गई हैं।

**श्री मंगल सेन :** इन्होंने जवाब में यह बताया है कि इतनी स्कीमें सैंकशन हुई हैं, कहीं ट्यूबवैलज लगाए जा रहे हैं, इतनी स्कीमें पेश हुई हैं। मैं आप के द्वारा इन से यह पूछना चाहता हूँ कि जो इतना भयानक अकाल पड़ा हुआ है उस का सामना करने के लिये और खेतों को तुरन्त पानी पहुंचाने के लिये कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

**मंत्री :** इस बारे में जो स्कीमज हैं जैसे परकोलेशन वैलज लगाने के बारे में या जहाँ पर डिपेंडेंशन है वहाँ पर पानी उठाने के लिये पम्पिंग सेट्स लगाने और ट्यूबवैलज लगाने का काम पूरे जोर से चालू है। फेमिन वाले अलाकों में लिफ्ट इरीगेशन की स्कीमों पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। कैनाल इरीगेशन की स्कीमों पर भी काम चालू है। यह बात नहीं है कि मंजूर तो कर दी है मगर काम चालू न हुआ हो।

**श्री मंगल सेन :** आप ने बताया है कि ट्यूबवैलज चालू कर दिये हैं। जब आप ने देखा कि मौसम फेल हो गई है, भाखड़े में पानी नहीं है, डिफैक्टिव डिस्ट्रिब्यूशन हुई है तो आप बताएं कि आप ने पानी की कमी को पूरा करने के लिये तुरन्त कितने ट्यूबवैलज को बिजली दी ?

**मंत्री :** इस साल में 9-10 हजार के करीब ट्यूबवैलज इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं।

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कैनाल में जैसे कि वैस्टर्न जमुना कैनाल, सिरसा कैनाल में पानी रोटेशन से न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**ਸੰਤਰੀ :** ਏਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਮੇਂ ਹੋਤੀ ਵਹੁ ਬਤਾਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬਤਾ ਸਕੂੰਗਾ। ਹਰ ਏਕ ਕੰਨਾਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਿਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੇ ਪਾਨੀ ਦਿਤਾ ਜਾਨਾ ਥਾ ਉਸ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਤਾ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਹ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਪੂਰੀ ਕਰਵੀ ਜਾਏਗੀ।

**ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ :** ਕੀ ਮੇਜ਼ਦਾਰ ਦੋ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਿਦ ਸਾਫ਼ਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ?

**ਸੰਤਰੀ :** ਨਹੀਂ, ਇਨ ਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾ। ਥੋਡੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਕੇ ਲਿਯੇ 400-500 ਕੁਬੀਕਸ ਦੀ ਕਠੌਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ :** ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਔੜ ਲਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ?

**ਸੰਤਰੀ :** ਡਾਇਰਿਕਾਜ਼ ਕੋ ਜ਼ਯਾਦਾ ਸੇ ਜ਼ਯਾਦਾ ਫਸਟ ਪਾਏਟੀ ਦੇ ਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਨੇ ਦੀ ਹਿਦਾਯਾਤ ਕੀ ਗਈ ਹੈ।

**ਭੀ ਹੁਸ਼ਾ ਮਲ :** ਮੈਂ ਸੰਤਰੀ ਸਹੋਦਯ ਸੇ ਧਹ ਪੁਛਨਾ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੇ ਮਸਲੇ ਮੇਂ ਕੁਦਰਤ ਪਰ ਹੀ ਕਯੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਐਰ ਕੋਈ ਇਨਤਜ਼ਾਮ ਕਯੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਯੇ ਗਏ ?

**ਸੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਸੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਬੋ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਅਨੁਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਧਾ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਧਾ ਦਰਿਯਾਐਂ ਕੇ ਪਾਨੀ ਪਰ ਇਨਹਿਸਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨ ਹੋਗਾ। ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਏਸੇ ਥੇ ਕਿ ਜ਼ਯਾਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਐਰ ਫਲਡ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਵਜਹ ਸੇ ਧਹਾਂ ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਥੀ। ਧਹ ਖ਼ਯਾਲ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਡਰਾਟ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਏਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਏ ਹੂੰ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਲੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੈਂਚਰੀ ਮੇਂ ਕਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁਏ। ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਅਨੁਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਧਾ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਾਨੀ ਆਖਡਾ ਐਰ ਦੂਸਰੇ ਰੈਜ਼ਰਵਾਧਰਜ਼ ਸੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਨੀ ਅਨੁਡਰ ਗਰਾਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਰ ਉਸ ਕਾ ਫਾਧਦਾ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਕਦਾਮਾਤ ਕਿਯੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੂੰ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, the other day, the hon. Chief Minister while replying to the Debate on the Governor's Address stated that 7,000 Tubewells have been energised. The hon. Minister for Irrigation and Power in reply to one of the Supplementary Questions today has been pleased to state that about 9,000 or 10,000 Tubewells have been energised. Will he be pleased to state as to which of these two statements is correct ?

**ਸੰਤਰੀ :** ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਮਾਨ ਲੋ। ਜਿਸ ਸੇ ਆਪ ਜ਼ਯਾਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਂ ਸਕਦੇ ਹੂੰ ਵਹੀ ਮਾਨ ਲੋ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Mr. Speaker, Sir, the supplementary question that I have put cannot be smiled away. There is, Sir, a difference of 2,000 Tubewells.

**Minister for Education :** Sir, the two replies pertain to two different dates. The Government is not static. Everyday more than 150 tubewells are energised. So, the difference of 2,000 tubewells is due to difference in dates.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, will the hon. Minister for Education be pleased to state whether this difference of 2,000 tubewells was made up within a day or two because it is only the other day that the hon. Chief Minister was pleased to state that 7,000 tubewells have been energised ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्री :** स्पीकर साहिब, उन के पास पहले की फिगरें होंगी। यह अप टू डेट है जो हम ने अभी कल ही मंगाई है। सरकार के पास रोजाना तो इत्तलाह आती नहीं है। चूंकि यह कल ही दरियाफत किया था तो उन्होंने ने बताया कि 9-10 हजार एनरजाईज हो चुके हैं।

**बाबू बचन सिंह :** बी मनिस्टर साहिब दसठगे कि पहिलां जिरती बिजली दे मैटीरीअल दी स्टार्टेज सी जिस बाबे बाब बाब सिक्काइतां कीतीआं गयीआं अउं अहमतरां ने दी बिहा कि टयूबवैलज. नुं अँनरजाइज उां कर देयीऐ पर मैटीरीअल दी स्टार्टेज है उां की उँस स्टार्टेज नुं पुरा कर दिता गिआ है ?

**मंत्री :** यह दरस्त है कि शुरू शुरू में बिजली के सामान की कमी थी। मैटीरियल की शॉर्टेज थी और बोर्ड को इस बात का पता न था कि सरकार की तरफ से किस कदर रूपया मिलेगा लेकिन कोई दो महीनों के बाद ही उस शॉर्टेज को पूरा कर दिया गया और यह कमी सितम्बर और अक्टूबर में पूरी कर दी गई थी। लेकिन 10 हजार टयूबवैलज अब तक एनरजाइज कर दिए गए हैं। और इस वजह से अब फिर शॉर्टेज महसूस हो रही है जिस का इन्तजाम किया जा रहा है।

**कामरेड जंगीत सिंह जोगा :** बी दसठीर साहिब दसठगे कि मंगतुत जिले दीआं नहिरां दिच बाकी दे जिलिआं नालें पाठी बिउं षट दिता जांदा है अउं बी पैदावार नुं दपाउठ दी समसिआ नुं सागमटे रक्के एिनां नहिरां दिच पाठी जियादा देठ दा पूषप कीता जा रिहा है ?

**मंत्री :** इस के मुतालिक स्पीकर साहिब, एक कमेटी बनाई गई थी जिस में 3 आफिसर थे दो इन्जीनियर और एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। इस कमेटी ने रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ कैनल वाटर पर सोच विचार किया कि किन किन इलाकों में पानी की ज्यादा जरूरत है और पानी कम दिया जा रहा है और जहां पर पानी की कम जरूरत है वहां पर ज्यादा दिया जा रहा है तो उस को एडजस्ट कर दिया जाए और इस तरह से पानी को एडजस्ट किया जा रहा है।

**चौधरी नेत राम :** क्या माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि पानी की कमी की वजह से और पानी की तकसीम के ढंग के खराब होने के कारण जो नुकसान हुआ है और जहां पर रिश्कत अफसरों ने खाकर मोघा ऊंचा कर दिया और कहा जाता है कि जिस ने 1,000 रूपया दिया उसको पानी दिया गया और बाकी के राजबाहे के पानी को खराब किया गया तो क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस का क्या इन्तजाम किया गया है और जिन जिन अफसरों के खिलाफ शिकायतें आई कि उन्होंने ने अच्छे ढंग से पानी को तकसीम नहीं किया और रिश्कत ली

उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है और ठीक ढंग से पानी की सप्लाई को जारी करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

**मंत्री :** सवाल जो इतना लम्बा कर दिया गया है। वैसे जहां पर पानी कम मिलने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है उन को रिलीफ देने के बारे में रूल्ज बने हुए हैं और उन रूल्ज के मुताबिक रिमिशन आबियाना में लाजमी तौर पर दिया जाता है। बाकी ड्राट के बारे में तकावी मंजूर की गई है और इस के लिये स्पेशल गिरदावरी कराई गई थी, जहां पर कि पानी न मिलने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, ताकि रिमिशन दी जा सके और जहां तक शिकायतों का सवाल है जो पनसाल नवीसों के खिलाफ की गई और भी जहां पर किसी किस्म की गड़बड़ की गई और जो सरकार के नोटिस में आई है उन के खिलाफ एक्शन लिया गया।

**इंडित मोहन लाल दत्त :** क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएं कि हिल्ली एरिया में जहां पर जमीन सूखत है और बोरिंग के लिये सरकार के पास कोई रिग नहीं थी तो क्या बड़ा रिग मंगवाने का प्रबन्ध किया जाएगा ?

**पशु पालन तथा कृषि राज्य मंत्री :** रिग का इन्तजाम किया जा रहा है।

**श्री जगन्नाथ :** क्या मिनिस्टर साहिब बताएं कि मेरे हल्का पर तो इनकी ठन्डी नज़र है तो क्या लोहारू और भिवानी में, जो बैकवर्ड इलाका है, ट्यूबवैल्ज को प्रायरटी पर कुनैक्शन देने का प्रबन्ध किया गया है, अगर नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्री :** गवर्नमेंट की तरफ से इन्स्ट्रक्शन जारी है कि लोहारू और भिवानी का जो एरिड इलाका है उस में ट्यूबवैलों को टाप प्रायरटी पर एनरजाइज किया जाए। अगर आनरेबल मੈम्बर के पास कोई शिकायत हो तो सरकार के नोटिस में लाएं, जरूर ऐक्शन लिया जाएगा।

**श्री बनवारी लाल :** क्या मंत्री महोदय बताएं कि अभी अभी इन्होंने ने फरमाया है कि पम्पिंग सैट्स को एनरजाइज करने के लिये इन्स्ट्रक्शन जारी कर दी गई है तो वह इन्स्ट्रक्शन क्या हैं और कब जारी की गई ?

**मंत्री :** इन्स्ट्रक्शन यही जारी की गई है कि टाप प्रायरटी दी जाए।

**श्री फतेह चन्द विज :** क्या मिनिस्टर साहिब बताएं कि इस पंजाब सरकार के पापों की वजह से जो मुसीबत किसानों पर आई है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है या की गई है ?

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** May I, Sir, ask the Honourable Minister if the Government would consider the desirability of starting thermal plants to meet the shortage of supply of water for want of rains?

**राओ निहाल सिंह :** क्या मंत्री महोदय बताएं कि सरकार ने जो एलान किया था कि 750 रुपए की सबसिडी ट्यूब वैलों के लिये दी जाएगी तो इस पर कहां तक अमल किया गया है ?

**मंत्री :** आप अगर अलग नोटिस दें तो पता कर के बता दूंगा।

**वाभरेड जेगीश शिंथ जेगा :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਤੂਰੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ 1—8 ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ

[कामरेड संत्रीर सिंय नेंगा]

आषपाप्ती नूं दपान लਈ घिनली दी सपलाਈ नूं इस निछे दिच निआदा बरन लਈ पहिल कदमी करेगी ?

**मंत्री :** बिजली के बारे में पोजीशन यह है कि जिन गांवों में ट्यूब वेलों के लिये रिक्वेस्ट आई है उन के लिये बिजली दी जाएगी लेकिन जहां से ट्यूबवेलों के लिये कोई रिक्वेस्ट नहीं है वहां पर मुश्किल है, वैसे ड्राई एरियाज में प्रायरटी दी जा रही है।

#### Embezzlement in Talu Minor Extension Case

**\*9274. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total amount alleged to have been embezzled in the Talu Minor Extension case in Hissar District ;

(b) the action so far taken against the officials responsible in this respect ;

(c) a copy of the enquiry report, if held/completed in connection with the said case, be laid on the Table of the House ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Rs 18,995.00.

(b) Two Sectional Officers have been placed under suspension. Sub-Divisional Officer and Executive Engineer concerned have been charge sheeted and transferred.

(c) Inquiry is still in progress.

**श्री अमर सिंह :** क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह इन्क्वायरी किस के हवाले की गई और कब तक इसका फैसला हो जाएगा।

**मंत्री :** यह इन्क्वायरी एस.ई. ड्रेन्ज, श्री डिल्लों ने की और बाकी तो सारी मुकम्मल है लेकिन स्टेट बैंक से और पुलिस के डी. आई. जी., सी. आई. डी. की तरफ से कुछ इन्फरमेशन आनी बाकी है।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** क्या वजीर साहिब बताएंगे कि इस केस में 18 हजार से ऊपर का गबन किया गया तो क्या इस केस को पुलिस ने रजिस्टर किया, अगर नहीं किया तो क्या कारण है ?

**मंत्री :** इस में सोसाइटी को ओवरपेमेंट हुई थी उनका और भी काम था तो उस से पेमेंट कोई पांच छः हजार के करीब वसूल किया गया है। लेकिन इस केस को पुलिस के पास रजिस्टर नहीं किया गया।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** May I ask the honourable Minister as to why the case was not registered with the Police when it was a case of clear embezzlement of thousands of rupees ?

**मंत्री :** यह जो ओवरपेमेंट का कव्रेशन है इस की सारी डिटेल्ज में मैं नहीं जाना चाहता, क्या वजह थी कि ओवरपेमेंट की गई, इस का जवाब भी इन्क्वायरी के बाद ही देना मुनासिब होगा।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** Sir, I rise on a point of Order. Mr. Speaker, I had simply asked if it was a case of embezzlement of about Rs 18,000, why was a case for this embezzlement not registered ? But it has been stated that it was a case of overpayment. Does the overpayment not amount to embezzlement ? If not, why not ?

**Mr. Speaker :** It is no point of Order. It could be a supplementary question.

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** It may be treated as a supplementary question Sir.

**Mr. Speaker :** No, please, I am sorry.

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** क्या मिनिस्टर साहिब अब केस रजिस्टर कराने को तैयार हैं ?

**मंत्री :** चूँकि यह केस बहुत पुराना हो चुका है इस लिये अब इस को रजिस्टर करा कर अदालत में कामयाबी हासिल करना एक मुश्किल सी बात है ।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** इस ओवर पेमेंट होने का डिपार्टमेंट को कब पता लगा ? जो इन्कवायरी हो रही है यह कब तक कम्पलीट हो जाएगी ?

**मंत्री :** इस ओवर पेमेंट का 1965 में पता लगा था । यह इन्कवायरी अब कम्पलीट हो चुकी है सिर्फ डी. आई. जी ( सी. आई. डी. ) से इस के मुताल्लिक रिपोर्ट आनी बाकी है ।

**श्री अमर सिंह :** क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह एम्बैजलमेंट अक्जैक्टिव इंजीनियर के रैलेटिव को कंट्रैक्ट लेकर देने की वजह से तो नहीं हुआ ? या कोई और कारण है ?

**मंत्री :** स्पीकर साहिब, यह केस अभी क्योंकि फाईनेलाईज नहीं हुआ इस लिये इस की और ज्यादा डिटेल्स में जाना मुनासिब नहीं है ।

#### Compensation to Beas Dam Oustees

**\*9295. Thakur Mehar Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the details of the compensation proposed to be paid to the Beas Dam Oustees for their lands and houses to be submerged under the Dam water or to be acquired otherwise by the Government ;
- (b) the details of the concessions being offered to the oustees for employment in the Dam construction and other jobs at the Dam site ;
- (c) the total number of oustees referred to above already absorbed in such employment ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Compensation of land is assessed according to the provisions in the Land Acquisition Act, 1894. Classification of land as obtaining at present is taken into consideration. As regards compensation of houses, the same is worked out on the basis of rates as contained in P.W.D. Common Schedule of Rates applicable to Hilly Areas and Plains as the case may be.

(b) First preference for employment on construction of Beas Dam is given to workmen rendered surplus from Bhakra Dam and second preference to the oustees of Beas Project whose land has been—would be acquired by the Project Authorities. Workmen from other sources are only recruited when suitable candidates amongst Bhakra retrenchees and oustees are not available.

(c) So far 6,745 oustees have been offered employment on Beas Dam.

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** क्या वजीर साहिब बता सकते हैं कि ब्यास डैम में कितने परसेंट इम्प्लायमेंट फोर्थ, थर्ड ग्रेड और सुपरवाइजरी स्टाफ को दी गई है ?

**मन्त्री :** इसके लिये परसेंटेज कोई मुकर्रर नहीं है। भाखड़ा डैम का जितना भी रिट्रैचड स्टाफ अवैलेबल हो सका। उस सारे के सारे को एबजार्ब करने की कोशिश की गई है।

**श्रीमती सरला देवी :** वरकज की तरफ से जो रिप्रैजेंटेशन इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट को दिया गया था उस में कहा गया था कि जो पुराने वरकज को निकाल कर, सिफारिशी लोगों को भर्ती किया जा रहा है, इस पर सरकार की तरफ से क्या ऐक्शन लिया गया है ?

**मन्त्री :** इस शिकायत को रैप्रिजेंटिवज और जैनरल मैनेजर से आपस में डिस्कस करके रफा कर दिया गया है।

**Sardar Balwant Singh :** May I know the number of land-owners whose land has been acquired and whether all the land-owners have been paid full compensation for their land acquired ?

**मन्त्री :** टोटल एरिया जो एक्वायर होना है वह 72,208 एकड़ है, इसमें से 11,875.42 एकड़ एक्वायर हो चुका है। लैंड ओनर्ज की तादाद एक्चुअल तो इस वक्त दे नहीं सकता यह तकरीबन 27,000 या 30,000 के करीब लिखी हुई है।

**श्रीमती सरला देवी :** जो रिप्रैजेंटेशन आई इस के मुताबिक आफिसर्ज की क्या बात-चीत हुई। सारी लिस्ट के मुताबिक आया उन्हें रखा गया है या नहीं ?

**मन्त्री :** जो भी भाखड़ा डैम से हटाया गया है खास तौर पर उन चन्द लोगों को छोड़ कर जिन्होंने हमारे इनवीटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया बाकी सब को ब्यास डैम या इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड में एबजार्ब कर दिया गया है।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** जिन भाखड़ा डैम के रिट्रैचड एम्प्लाइज को पोंग डैम या ब्यास डैम पर लगाया गया है क्या उनकी पुरानी सर्विसज को भी साथ ही काऊंट किया गया है या नहीं ?

**मन्त्री :** उन की पिछली सर्विस के राईट्स को प्रिजर्व किया गया है।

**प्रिंसिपल रला राम :** क्या सरकारी आफिशियलज उन रिट्रैचड इम्प्लाइज को जिन को तलवाड़ा पोंग डैम या ब्यास डैम पर एबजार्ब किया जाता है परसनली जा कर चैक अप भी करते हैं ?

**मन्त्री :** इसके लिये बाकायदा इन्स्ट्रक्शन्ज हैं, उनको चैक अप भी किया जाता है।

**Payment of compensation for land covered by Chand Bhan and Bassian  
Outfall Drains to the land owners concerned in tehsil Moga,  
district Ferozepur**

**\*9350. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) whether compensation for the land covered by Chand Bhan and Bassian Outfall Drains has since been paid to the land owners of the villages in tehsil Moga, district Ferozepur ;

- (b) if the full compensation has not been paid to the landowners concerned, the reasons therefor ;
- (c) the total amount of compensation paid so far ;
- (d) the details of the amount of compensation not yet paid in each of the said villages ?

**Chaudhri Rizaq Ram** : (a) Yes, except for village Nangal.

(b) Time taken in the finalisation of award.

(c) Rs 3,58,052.25 P.

(d) *Village Nangal*.—Rs 21,873.

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ** : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਭਾਨ ਅਤੇ ਬਸੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਾਈਨੇ-ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕਿਤਨਾ ਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ?

**ਸੰਤਰੀ** : ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸੁਝੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗਰ ਅਖੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸੈਂਟ ਬਾਂਕੀ ਹੈ, ਤੀਜ ਲਾਖ ਦੀ ਪੇਸੈਂਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ** : ਕੀ ਸੈਦੋ, ਭਾਗੀਕੇ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਚੰਦ ਭਾਨ ਅਤੇ ਬਸੀਆਂ ਆਉਟਫਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

**ਸੰਤਰੀ** : ਜੰਗਲ ਕੇ ਅਲਾਕਾ ਸਭ ਕਾ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ** : ਬਸੀਆਂ ਆਉਟ ਫਾਲ ਡਰੇਨ ਸੈਦੋਕੇ ਭਾਗੀਕੇ ਬਗੈਰਾ ਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

**ਸੰਤਰੀ** : ਇਸ ਕੇ ਲਿਏ ਅਗਰ ਆਪ ਅਲਗ ਨੋਟਿਸ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

#### Bricks purchased by Ladwa Tube well Sub-Division, district Karnal

**\*9373. Sardar Piara Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :—

(a) whether the Ladwa Tubewell Sub-Division, district Karnal, purchased bricks from Shri Sunder Singh -Rattan Singh, Kiln owners from their kiln at village Ram Saran Majra about seven or eight years ago and that the bricks were allowed to remain at the site of the said kiln after making the payment of the price thereof, if so, the number of bricks belonging to the tubewell department which are still lying at the site of the kiln of the said firm ;

(b) whether the kiln-owners referred to in part (a) above have written to the said department for taking over the bricks or have the price thereof refunded ; if so, the action taken thereof ?

**Chaudhri Rizaq Ram** : (a) Yes, 5,94,630 pucca bricks were purchased in 1957-58 but now only 1,26,820 bricks are lying at kiln site.

(b) Yes, action is being taken to dispose of the surplus bricks.

**ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ** : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 7 ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭੱਠੇ ਤੇ ਬ੍ਰੌਰਮੈਂਟ ਦੀ 6 ਲਖ ਇੰਟ ਪਈ ਹੈ । ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ

[ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ]

ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਠਾਂ ਲੈ ਜਾਉ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਪਰ ਗੋਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਅਗਰ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੋਂ ਤੋਂ ਬਤਾ ਦੁੱਗਾ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਘੁਆਰਾ :** ਕਥਾ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਥਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਈਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਥੇ ਆਰ ਉਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਹੁਆ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਕਲਿੰਗ ਦੇ ਲਿਏ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਦ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਈਲਾਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਰ ਉਸੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਦ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਘੁਆਰਾ :** ਕਥਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਇਹ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਜਦ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰ ਟ੍ਰਿਕਲਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਰੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ? ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਕਲਿੰਗ ਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਲਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਏ ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ।

**Area eroded by Swan Nadi in tehsil Una, district Hoshiarpur**  
\*9377. **Shri Surinder Nath Gautam :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the total area in acres eroded by the Swan Nadi in Una tehsil, district Hoshiarpur ;
- (b) the details of the steps taken by the Government to stop such erosion and the result thereof ;
- (c) the total expenditure already incurred by the Government on the scheme formulated to stop such erosion with the details thereof and the time by which it is likely to be completed ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) No survey has been carried out. However, large area has been eroded due to river action.

(b) The following steps have been taken or formulated to give protection : —

- (1) Spurs have been constructed at Oel, Mubarakpur, Bhaira, Santokhgarh and Ahelgram to save these villages and their fertile land.
- (2) A scheme of canalizing Swan Nadi from the Una Bridge to its confluence with river Sutlej was sent to the Technical Committee but was deferred due to paucity of fund.
- (3) A scheme to canalize Swan Nadi Up-stream of Una Bridge upto Dharmasala-Hoshiarpur Road is under consideration.

(c) Total expenditure of Rs 583,000 has been incurred on works B(1). The cost of the Scheme at B(2) is Rs 38.2 lacs and the time by which it can be taken up and completed cannot be given due to paucity of funds.

**ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੋਤਮ :** ਕਥਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏਗੇ ਕਿ ਤਹਸੀਲ ਊਨਾ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡ ਹਿਲਡੀ ਏਰੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਆਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਜੋ 40 ਮੀਲ ਲੰਬੀ

और 3 मील चौड़ी है जिस से काफी जमीन दर्या बुद हो चुकी है इस के मुतालिक सर्वे कराने में गवर्नमेंट को क्या दिक्कत पेश आ रही है ?

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर ।

\* \* \* \*

Mr. Speaker : Please withdraw these words.

श्री जगन्नाथ : मैं विदङ्गा करता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : \* \* \* \*

श्री अध्यक्ष : आर्डर । जो कुछ श्री जगन्नाथ और श्री गौतम ने एक दूसरे के बारे में कहा है वह प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं होगा । (Order, please. Whatever remarks have been made by Shri Jagan Nath and Shri Gautam against each other, will not form part of the proceedings.)

मन्त्री : स्वां नदी की सर्वे करवाई जा चुकी है इस बात की कि कितना रकबा इरोज हो चुका है । इस के अलावा सर्वे नहीं हुई । उसके लिये स्कीम है कि स्वां नदी की इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, वह बनी हुई है । एक स्कीम पर काम चालू है । दूसरी स्कीम पर 30 लाख रुपया खर्च होना था । वह टेक्नीकल कमेटी में रखी गई थी लेकिन वहां से डिसेजिन डैफर कर दिया गया फंड्स की कमी की वजह से ।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े हुए इलाके में इस नदी ने हजारों एकड़ जमीन बरबाद कर दी है छोटे छोटे किसानों की । क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई ठोस कदम उठाने के लिये तैयार है जैसे कि पाइलट प्राजैक्ट के तौर पर लिया जाए और रुपया खर्च किया जाए ?

मन्त्री : यह 30 लाख रुपए की जो स्कीम है वह मन्जूर नहीं हुई । उसके बाद दूसरी स्कीम बनी है जिस पर 25 लाख रुपया खर्च होना है । वह टेक्नीकल कमेटी में ले जा रहे हैं । मन्जूर होने पर खर्च किया जाएगा ।

सरदार बलवंत सिंह : जिहड़ी एलुं ने मकीम घटाई है उस ची टोटल एस्टीमेट वासट बिंठी है ? आदिआ डेरष पलैन् विच एिग रुपिआ परोवाएीड कीडा है मदां नदी नुं चेनेलाएीज बरन दासडे जा नही ?

मन्त्री : उसकी एस्टीमेटिड कास्ट यह है कि एक स्कीम 30 लाख रुपये की है और दूसरी 25 लाख रुपये की है, फोर्थ प्लैन में किस कदर रुपया मिले वह कहना मुश्किल है ।

\*Note.—Expunged as ordered by the Chair.

**पंडित मोहन लाल दत्त :** यह काम बहुत बड़ा है। क्या सरकार इस सुझाव पर गौर करने के लिये तैयार है कि कुछ फंड पंचायतों और समितियों के सुपुर्द किए जाएं ताकि लोगों की सहायता से यह खर्च किया जाए ?

**मन्त्री :** बहुत अच्छा खयाल है, अगर पंचायतें और समितियां खुद काम करें तो कोशिश करनी चाहिए।

**Land acquired for widening Saraswati Drain in Pehowa Sub-Division, Karnal**

**\*9396. Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to—

(a) lay on the Table of the House a list containing names and full addresses of the land-owners whose lands have been acquired by the Government for widening the Saraswati Drain in the Pehowa Sub-Division, Karnal ;

(b) state whether the landowners referred to in part (a) above have been paid any compensation for the land acquired from them; if so, the number of such land-owners ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) The labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefit likely to accrue.

(b) No compensation has been paid so far.

**श्री उम प्रकाश अग्रनीहोतरी :** बी वजीर साहिब दसठ दी किरपा करनगे कि उनुं किसानों नुं कदें उक मुआवजा मिल जावेगा ?

**मन्त्री :** जो लैंड ओनर्स थे उन के अवार्डज अवेटिड हैं लैंड एकवीजीशन अफसर की तरफ से। उस के बाद फंडज मिलने पर कम्पेंसेशन की अदायगी की जाएगी।

**सरदार बलवंत सिंह :** जिहड़ा साड़ा ला है ऐकवीजीशन दा उस दे मुताबिक लैंड ऐक्वायर्ड करके ऐक्चुअल पेंसेशन लेट उं घाअद कंपेंसेशन देट लई बिउता दकटा होटा चाहीदा है।

**मन्त्री :** यह तो लैंड एकवीजीशन अफसर की ज्यूडीशियल प्रोसीडिंगज होती हैं। उस में न कोई किसी डिपार्टमेंट का ताल्लुक है और न ही कोई टाईम लिमिट होती है।

**चौधरी नेत राम :** जिन जमीन वालों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलना होता है उस के लिये कोई म्याद मुकर्रर होती है। अगर किसी कारण से उन को आज तक नहीं मिला तो कब तक मिल जाएगी ?

**मन्त्री :** नहीं जी, कोई म्याद नहीं होती।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** May I ask the hon. Irrigation and Power Minister as to when this land was acquired ?

**Minister :** In 1965.

**कामरेड राम प्यारा :** क्या इरीगेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इसी हाउस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी वकत यह ऐलान हुआ था कि जमीन एक्वायर होने के बाद छः महीना के अन्दर अन्दर कम्पेंसेशन दे दिया जाएगा।

**मन्त्री :** मुझे तो याद नहीं जी।

**Workers retrenched in Bhakra Dam Administration**

**\*9417. Shri Sarinder Nath Gautam :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the total number of workers retrenched upto 31st January, 1966 in the Bhakra Dam Administration, with the details thereof category-wise ;
- (b) whether all the retrenched workers referred to in part (a) above have been provided with alternative jobs on other projects ; if so, the details of such workers, category-wise upto-date, together with the names of the projects where they have been absorbed ;
- (c) whether there is any likelihood of further retrenchment of the workers in the Bhakra Dam Administration in 1966 ;
- (d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, the number of workers likely to be retrenched category-wise and the details of the scheme, if any, formulated to provide alternative jobs to such workers on other projects ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Since the beginning of Bhakra-Nangal Project 8,063 workers have been reduced upto 31st January, 1966, as per details given below, category-wise :

(i) Supervisory, Skilled and Semi-skilled	..	6,723
(ii) Unskilled	..	1,340
<b>Total</b>	..	<b>8,063</b>

(b) 5,325 workers were provided with alternative jobs on other projects, such as Beas Dam Project, Beas Sutlej Link Project, Hydrel Uhl Project, Punjab State Electricity Board etc. as per details given below:—

(i) Supervisory, Skilled and Semi-skilled	..	5,182
(ii) Unskilled	..	143
<b>Total</b>	..	<b>5,325</b>

Project-wise record is not available.

(c) Yes.

(d) The approximate number of workers proposed to be reduced from Bhakra-Nangal Project, category-wise during the year 1966, is as under:—

(i) Supervisory Staff	..	77
(ii) Skilled Staff	..	372
(iii) Semi-skilled Staff	..	58
(iv) Unskilled Staff	..	348
<b>Total</b>	..	<b>855</b>

All the surplus workmen are offered to the Beas Projects, Beas-Sutlej Link and Uhl Hydrel Project for employment, and such senior workmen, as can be absorbed are offered alternative employment on these Projects. Lists of such workmen as cannot be absorbed on these Projects are circulated to various prospective employers throughout India as per statement placed on the Table. Further, the names of the surplus

**[Irrigation and Power Minister]**

workmen are got registered in the Employment Exchange, Nangal Township which helps them to get jobs elsewhere. Only such workmen are retrenched as do not want to take up alternative jobs and who cannot be absorbed at any other place.

**STATEMENT.**

1. The Financial Commissioner, Planning and Secretary to Govt. Punjab Chandigarh.
2. The Director of Employment, Punjab, Chandigarh.
3. Dr. S. N. Channa, Director of Employment Exchanges, Govt. of India Ministry of Labour and Employment, New Delhi.
4. The General Manager, Beas Project, Talwara Township.
5. The Commander, General Reserve Engineering force, Centre, Roorkee.
6. The Chairman, Punjab State Electricity Board, Patiala.
7. The Director Construction Beas Dam Project. Talwara Township.
8. The Provincial Transport Controller. Punjab Chandigarh.
9. The Superintending Engineer, Beas Sutlej Link Mech. Circle, Nangal.
10. The Superintending Engineer, Uhl Constn. Circle, Palampur.
11. The Superintending Engineer, Beas Sutlej Link Civil Circle Mandi.
12. Director, Inspection and Control. Nangal.
13. Shri S. N. Agnihotri, Constn. Supdt. National Project Constn. Corp. Ltd. Durgapur (West Bengal)
14. The Manager, Heavy Electrical, Bhopal.
15. The Manager, Heavy Electrical Hardwar.
16. The Personnel Officer, Beas Dam Project. Talwara Town Ship
17. The Executive Engineer, Personnel, Beas Sutlej Link, Mandi (H. P.)
18. The Executive Engineer, Hydrel Uhl Constn. Division, Joginder Nagar.
19. The Executive Engineer, Ram Ganga Dam Division II Kalagarh (Bijnor) U. P.
20. All Executive Engineers, Dte of C and P Design, Nangal Township.
21. S. D. O. Retrenchment Compensation, Nangal Township.
22. District Employment Officer, Employment Exchange, Nangal.
23. General Manager, Punjab Roadways (1) Amritsar.
24. Ditto (2) Jullundur.
25. Ditto (3) Pathankot.
26. Ditto (4) Chandigarh.
27. Ditto (5) Ambala.
28. Ditto (6) Gurgaon.
29. Senior Personnel Officer, Fertilizer Corporation of India, Naya Nangal.
30. Chief Engineer, (Drainage) Irrigation Works, Pb. Chandigarh.
31. Chief Engineer, (Projects) Irrigation Works, Punjab Chandigarh.
32. Chief Engineer, Ram Ganga Project. (U. P.)
33. Chief Engineer, P. W. D. B. and R. Branch, Patiala.
34. Chief Engineer, and Secretary, P. W. D. Himachal Pradesh Simla.
35. Chairman, C. W. and P. C. New Delhi.
36. General Manager, and Chief Engineer, N. P. C. C. New Delhi.
37. General Manager, Northern Railway, New Delhi.
38. Shri M. K. Bhardwaj Labour Officer, Fertilizer Corporation of India Naya Nangal.

**श्री बलरामजी दास टंडन :** ग्रान ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, आप का हई वार रुजिंग प्राया है कि जवाब जब लम्बा हो तो टेबल पर रख देना चाहिए। इतना लम्बा जवाब जो मिनिस्टर साहिब अब पढ़ रहे हैं उस पर हम सप्लीमेंटरी कैसे कर सकते हैं?

**श्री अध्यक्ष :** आफिस की तरफ से मुझे मालूम हुआ है कि इस सवाल के जवाब की कापी टेबल पर रख दी गई है। मगर मੈम्बर साहिब ने उन को पढ़ने के लिये मजबूर किया था इस लिये वह पढ़ रहे हैं। (I understand from the office that a copy of the reply to this question has been laid on the Table. But the Member giving notice of the question compelled the hon. Minister to read out the reply, that is why the latter is reading it out.

**श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम :** वज़ीर साहिब ने बताया है कि 8,063 वर्कर्स रिट्रैच हुए हैं और उन में से 5,025 को आल्टरनेटिव जाबज दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बकाया जो वर्कर्स हैं उन को जाब क्यों नहीं दिए गए।

**Minister :** Out of this, 1,559 workmen did not get their registration cards renewed from the Employment Exchange. Probably they belonged to the neighbouring areas and did not like to go away elsewhere on jobs. 983 workmen failed to respond to the interview cards etc. issued by the Employment Exchange. 190 persons declined to accept the offer offered by the Employment Exchange. 1,669 workmen out of 4,380 retrenched have been reabsorbed on projects like Beas Dam etc. Only 7 workmen remained on the live register of the Employment Exchange, Nangal. One could not be provided with any alternative job as there was no requirement of his trade from anywhere.

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ?

**Mr Speaker :** He is also Chief whip.

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन वर्करों को भाखड़ा डैम से रिट्रैच किया गया और पौंग डैम पर लगाया गया है और जो रैगूलर एस्टैबलिशमेंट नहीं बल्कि वर्क चार्ज है और जिन्हें प्रोजेक्ट अलाउंस नहीं मिलता क्या उन को हिल अलाउंस दिया गया है?

**Minister :** Notice please.

**चौधरी नेत राम :** क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सरकार जब वर्कर्स की छांटी करती है तो पहले उन के लिये रोजगार की तलाश करके करती है या वैसे ही अन्धा धुन्ध छांटी कर देती है।

**मन्त्री :** जो आदमी रिट्रैच करने होते हैं उन की छः माह पहले ही लिस्ट लगा दी जाती है और वहां से फारग होने से पहले ही उन को दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** भाखड़े से रिट्रैच किए गए जिन वर्कज को अभी तक दूसरे काम पर नहीं लगाया जा सका क्या उन से सरकारी मकान खाली करवा लिए गए हैं या उन के पास ही हैं ?

**मन्त्री :** इस के लिये नोटिस चाहिए ।

**श्रीमती सरला देवी :** अगर गवर्नमेंट के नोटिस में ऐसे केसिज लाए जाएं कि रिट्रैच-मेंट के बाद सीनियर आदमियों को छोड़ कर जूनियर आदमियों को चार्ज-हैंड वगैरा लगाया गया तो क्या गवर्नमेंट उन जूनियर आदमियों को हटा कर सीनियर आदमियों को लगाने के लिये तैयार है ?

**मन्त्री :** अगर कोई ऐसा केस आप हमारे नोटिस में लाएंगे तो एग्जामिन कर लेंगे ।

**सरदार अजयिष सिंघ संधू :** की कौड़ी सरकार दा ओसा फैसला है कि जेदे रीट्रैचमेंट होवे उं सौडलड कासट वालिआं नुं ना कदिआ जावे । जे ओसा फैसला है उं डेर भाषडे विच उनुं नुं किउं रीट्रैच कीडा गिआ है ?

**मन्त्री :** भाखड़े के मुताल्लिक ऐसी कोई बात नहीं लेकिन जो दूसरे सरकारी महेकमें हैं उन के बारे में फैसला है कि जब तक वह रिक्वायर्ड नम्बर से ज्यादा न हों उन को रिट्रैच न किया जाए ।

**पंडित सुरेन्द्र नाथ गौतम :** क्या यह सही है कि यह जो वर्कज रिट्रैच किए जाते हैं उनके तनासब से अफसर बहुत कम रिट्रैच किए जाते हैं ?

**मन्त्री :** इस के लिये सैपेरेट नोटिस दें ।

#### Electricity generated in 1965 and 1966

**\*9236. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the quantum of electricity generated during 1965 and 1966 was lower than that generated during the years 1962, 1963 and 1964; if so, to what extent and whether the Government propose to instal thermal plants for generating electricity ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** 1965.—No.

1966.—Figures for the entire year cannot be given at this stage.

The rest of the question does not arise.

Thermal Diesel sets are under installation.

**श्री फतह चन्द विज :** जैसा कि इन्होंने बताया है कि बिजली की शारटेज है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि थर्मल प्लांट्स जहाँ जहाँ पहले पानीपत, जगाधरी वगैरा में चलते थे क्या उन्हें चलाने के लिए वह गौर कर रहे हैं ?

**मन्त्री :** जितने थर्मल प्लांट्स या जनरेटिंग सैट्स बोर्ड के हैं वह इस वक्त भी काम कर रहे हैं और आगे मज्जीद प्लांट्स लगाने के लिये फंडज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ?

**पंडित चिरजी लाल शर्मा :** पानीपत में जो थर्मल प्लांट था क्या उसने काम करना शुरू कर दिया है ?

**मन्त्री :** उसकी कुछ थोड़ी मशीनरी दूसरी जगह इस्तेमाल हो रही है । जो वर्किंग आर्डर में हैं वह चल रहे हैं ।

श्री फतेह चन्द बिज : यह जो थोड़ी मशीनरी कहते हैं बाहर भेजी गई है क्या वह मशीनरी मंगा कर उसे चालू कर देंगे ?

मन्त्री : यह तो आपकी सजेशन है जिस पर गौर किया जा सकता है ।

**Starred Questions o. 9497 and 9501**

**Mr. Speaker :** The hon. Minister concerned has applied for extension.

**Minimum Wages Committees**

✓ **\*9323. Shri Sagar Ram Gupta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

- (a) state the total number of Minimum Wages Committees appointed by the Government during the years 1964-65 ;
- (b) state the constitution of each of the said Committees together with the qualifications, experience and names of the members thereof and the industry for which each was appointed ;
- (c) state the criteria followed in allotting members to different Labour and Employers organisations ;
- (d) state the work so far done by each of the said Committee ;
- (e) lay copy of the reports submitted by the above-mentioned Committees or any of them together with the action, if any, taken thereon in each case ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) to (e) Necessary reply to the question is laid on the Table of the House.

## [Irrigation and Power Minister]

(a) Fifteen.

(b) The constitution of the Committees is given below :—

## (I) COMMITTEES CONSTITUTED BY GOVERNMENT IN 1964

Serial No.	Name of the Committee	Date of the constitution of the Committee	Names of Independent members	Names of Employers representatives	Names of Employees representatives
1	2	3	4	5	6
1	Employment in Private Presses	4-5-64	(1) Labour Commissioner, Punjab (Chairman) (2) Assistant Labour Commissioner, Punjab	(1) Shri Gian Chand Kharbanda, President, Master Printers Association, Hall Bazar, Amritsar. (2) Shri J.R. Berry, Prop. Berry Printing Works, Sadar Bazar, Ambala Cantt.	(1) Shri G.C. Bhalla, Organising Secretary, INTUC, Jullundur City. (2) Shri Rajeshwar Nath, Secretary, Hind Mazdoor Sabha, Ambala Cantt.
2	Employment in Agricultural Implementations, Machine Tools and General Engineering including cycle and Electric Goods Industry	6-8-64	(1) Labour Commissioner, Punjab (Chairman) (2) Shri A.P. Mayor, President Regd. Factory Owners Association C/o Watkins Mayors and Sons, Jullundur. (3) Shri S.S. Minhas, Manager, Asia Electric Co., Phagwara (4) Shri K.R. Sarin, President, Factors Association, Batala (5) Shri B.D. Kapur, General Manager, Atlas Cycle Industries Ltd., Sonapat	(1) Shri A.P. Mayor, President Regd. Factory Owners Association C/o Watkins Mayors and Sons, Jullundur. (2) Shri S.S. Minhas, Manager, Asia Electric Co., Phagwara (3) Shri K.R. Sarin, President, Factors Association, Batala (4) Shri B.D. Kapur, General Manager, Atlas Cycle Industries Ltd., Sonapat	(1) Shri Sat Pal Bhushan, Secretary INTUC, Putlighar, Amritsar. (2) Shri G.C. Bhalla, Organising Secretary, INTUC, Jullundur. (3) Shri Bhajan Singh, President, Ludhiana, Iron and Steel Workers Union, Miller Ganj, AITUC, Amritsar (4) Shri Parduman Singh, C/o AITUC, Amritsar.
3	Employment in Textile Industry	10-11-64	(1) Joint Labour Commissioner, Punjab (Chairman) (2) S. Attar Singh,	(1) Shri G.K. Nayar, Labour Secretary, Textile, Manufacturers Association, Amritsar (2) Seth Radha Krishan, Honorary	(1) Shri J.D. Bakshi, Secretary of INTUC, Ambala Cantt. (2) Shri Parduman Singh, General Secretary, AITUC, Amritsar

Labour Officer,  
Rohtak

(3) Shri A.S. Grover,  
State Hand Loom  
Officer, office of the  
Director of Industries,  
Chandigarh

General Secretary, The Punjab Textile  
Manufacturers Association, Katra  
Ahluwalia, Amritsar

(3) S. Inder Singh Uppal of Hemla  
Textile Mills, Coherentia

(3) Shri Rattan Singh Baghi, General  
Secretary, Amritsar Textile Labour  
Union (Regd.) Amritsar

(II) COMMITTEES CONSTITUTED BY GOVERNMENT IN 1965

- 1 Employment in  
Public Motor  
Transport  
12-3-65  
(1) Labour Commis-  
sioner, Punjab,  
(Chairman)  
(1) Provincial Transport Controller,  
Chandigarh  
(2) Shri B.K. Saini, Working Piesident  
Punjab Motor Union, Chandigarh  
(3) Shri Harbhajan Singh, Punjab Pub-  
lic (Goods) Carrier Union, Chandigarh
- 2 Employment in Cine-  
ma Industry  
22-3-65  
(1) Joint Labour Com-  
missioner, Punjab  
(Chairman)  
(2) Shri Ujagar Singh,  
M.L.A., Village and  
P.O. Jhabelwali, Dis-  
trict Ferozepore  
(1) Shri K.C. Nagia, Manager Chitra  
Talkies, Amritsar  
(2) Shri Sohan Lal Puri, President,  
East Punjab Motion Pictures Associa-  
tion, Railway Road, Jullundur  
(3) Shri Pran Nath Khanna, Manager,  
of M/s Parkash Talkies, Karnal  
(1) Shri J.D. Bakshi, Secretary, INTUC  
Ambala Cantt.  
(2) Shri Darshan Singh, General Secre-  
tary, Punjab Cinema Employees Union  
Amritsar  
(3) Shri Thakar Singh, President Pun-  
jab Cinema Employees Union,  
Jullundur
- 3 Employment in Oil  
Mills  
25-8-65  
(1) Labour Commis-  
sioner, Punjab  
(Chairman)  
(Chandigarh)  
(1) Shri Ram Baboo, Manager M/s  
Laxmi Oil Mills, Rohtak  
(2) Shri Gurditta Mal, Proprietor,  
Rama Oil Mills, Jullundur  
(3) Shri Sat Pal Mohindera, Secretary,  
Rosin and Turpentine Manufacturers  
Association, Hoshiarpur  
(1) Shri Sat Pal Bhushan, General  
Secretary, Mazdoor Council, INTUC  
Amritsar  
(2) Shri M.L. Didi, Vice-President  
Punjab, Trade Union Congress,  
AITUC, Ludhiana  
(3) Shri Ram Dass, General Secretary  
Rosin Labour Union, Hoshiarpur

## [Irrigation and Power Minister]

1	2	3	4	5	6
4	Employment in Textile Industry	26-3-65	(1) Labour Commissioner, Punjab (Chairman) (2) Shri N. Goswamy, Textile Officer, (Designs), Hussainpura, Amritsar (3) Shri S.P. Kumaria, Supdt. Quality Marketing Centre for Textile, Amritsar	(1) Shri S.C. Mahajan, President, Amritsar Scale Woollen Manufacturers' Association Ltd., Amritsar (2) Shri O.P. Aohi, C/o Aohi Textile Mills, Amritsar (3) Shri Dina Nath, Aggarwal, M.L.A., Ludhiana	(1) Shri Siri Kant, General Secretary, INTUC, Ludhiana (2) Shri Sat Pal Bhushan, C/o INTUC, Amritsar (3) Shri Madan Lal Didi, C/o AITUC Chandigarh
5	Employment in Ferrous Metal Rolling and Rolling Industry in Punjab	21-4-65	(1) Labour Commissioner, Punjab (Chairman)	(1) Shri Sat Pal, M.A. of M/s Amin Chand Payara Lal Tanda Road, Jullundur City (2) Shri Sohan Lal of M/s Ludhiana Iron and Steel Rolling Mills, Ludhiana (3) Shri Dharam Dev Sagar, C/o Rama Steel Rolling Mills, Gobindgarh	(1) Shri Tejinder Singh, General Secretary, Engineering Workers' Union, Patiala (AITUC) (2) Shri J.D. Bakshi, General Secretary, INTUC, Ambala Cantt.
6	Employment in Tannery and Leather Manufacturing	26-11-65	(1) Deputy Labour Commissioner, Punjab (Chairman) (2) Ch. Amar Singh, Advocate, Karnal	(1) Shri Hans Raj of M/s H.R. Mahajan and Sons, Jullundur (2) Shri P.R. Sondhi, C/o NIT, Kapurthala (3) Ch. Sunder Lal, Managing Director, Co-operative Industrial Leather (Tanning) society, Sonapat	(3) Shri G.C. Bhalla, General Secretary, Mazdoor Council, INTUC, Jullundur (1) Shri Gian Chand Mistry, NIT, Kapurthala (2) Shri Brij Lal, C/o Sports Industry Mazdoor Union, Jullundur (3) Shri Ram Kishan Azad, Secretary Labour and Const. Co-operative Society, Karnal
7	Employment in Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills	1-12-65	(1) Joint Labour Commissioner, Punjab (Chairman)	(1) Shri Raghu Nandan Bhatia, Guru Ram Dass Flour Mills, Amritsar	(1) Shri Tejinder Singh, General Secretary, Flour Mills Workers Union, Patiala (AITUC)

- (2) Shri M.D. Jain, Convener, District & Congress Committee, Rohtak  
(2) Shri Sham Singh, President, Rice Mills Association, Amritsar  
(3) Shri G.L. Relan, M/s Relan General Mills, Amargarh, Kaithal
- 1-12-65  
8 Employment in Shawl Weaving Estts. run on Power looms  
(1) Deputy Labour Commissioner, Punjab (Chairman)  
(2) Khan Abdul Gaffar Khan, M.L.A., Ambala  
(1) Shri Lakshmi Chand Aggarwal, The Lily Fabrics, Ludhiana  
(2) Shri R.K. Sehgal of M.H. Spinners, Batala Road, Amritsar  
(3) Shri Shiv Kumar Gupta, Paipat Woollen and General Mills, Kharar
- 1-12-65  
9 Employment in Contractors Estts. of the Punjab Forest Department  
(1) Deputy Labour Commissioner, Punjab (Chairman)  
(2) Bakshi Patrap Singh M.L.A.,  
(3) Shri E.S. Das, P.F.S.I. Deputy Chief Conservator of Forests Punjab, Chandigarh  
(1) Shri Anant Ram Sood, Forest Contractor  
(2) Shri Hazari Mal Kuthiala, Hoshiarpur  
(3) Shri Tachman Singh, Forest Contractor, Kalka
- 8-12-65  
10 Employment in Ayurvedic and Unani Pharmacies  
(1) Deputy Labour Commissioner, Punjab (Chairman)  
(2) Shri G.S. Sidhu, Professor of Bio-Chemistry, Agriculture University, Ludhiana  
(1) Shri Kirti Sharma, Principal Ayurvedic College, Patiala  
(2) Shri Nar Dev, C/o D.A.V. Pharmacy, Jullundur  
(3) Shri Madan Mohan, Proprietor, Pushkarna, Pharmacy, Amritsar  
(1) Shri Gauri Nandan Sharma, General Secretary, Vaid/Compounders Association, Simla  
(2) Shri Dev Raj Saini, C/o Punjab Ayurvedic Pharmacy Ladowali Road, Jullundur  
(3) Shri Sat Pal Bhushan, C/o INTUC, Amritsar
- 9-12-65  
11 Employment in Local Authority  
(1) Joint Labour Commissioner, Punjab, (Chairman)  
(2) Deputy Secretary to Government, Punjab Local Self Government  
(1) Shri Durga Dass Bhatia, President, Municipal Committee, Amritsar  
(2) Shri Sukhdev Khanna, Member, Municipal Committee, Patiala  
(3) Shri Phool Chand, Advocate and Municipal Commissioner, Sonapat  
(1) Shri J.D. Bakshi, President, Punjab Municipal Employees Federation, Ambala  
(2) Shri H.S. Bawa, General Secretary, Municipal Mazdoor Sabha, Amritsar  
(3) Shri Madan Lal Didi, C/o AITUC, Chandigarh
- (2) Shri G.C. Bhalla, Organising Secretary, INTUC, Jullundur  
(3) Shri Ram Karan President Sulej Flour Mills Workers Union, Ferozepore  
(1) Shri Om Parkash Mehta, AITUC, Ludhiana  
(2) Shri Sat Pal Bhushan, AITUC, Amritsar  
(3) Shri G.S. Joshi, INTUC, Yamuna Nagar  
(1) Shri Budhi Singh of Palampur  
(2) Shri Raghbir Singh Saur, Post Office, Lohaghat, Nalagarh  
(3) Shri P.L. Kachru, Labour Welfare Officer, Jammu and Kashmir Government, Pathankot

## [Irrigation and Power Minister]

1	2	3	4	5	6
12	Employment in Shawl Weaving in Handloom Estts.	9.12-65	Deputy Labour Commissioner, Punjab, (Chairman) (2) Shri Ram Parkash, M.L.A., Jagadhri	(1) Shri Ved Ram Thakar, President Bhuth Weaver, Co-operative Society, Kulu (2) Shri Madho Ram, President Thakur Handloom Production-cum-sale Co-op Society Industrial Kulu (3) Shri Jai Narain Goyal, Haryana, Woollen and General Mills, Panitlat	(1) Shri Raghbir Singh of Mazdoor Sabha, Panipat (2) Shri Lot Ram, Secretary M/s Badeh Weavers Co-operative Industrial Society Badah/Kulu (3) Shri Moti Ram, C/o Pangam Weaver Co-operative Society Raison (Kulu

(c) According to Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, each of the Committees, Sub Committees, and the Advisory Board are to consist of persons to be nominated by the appropriate Government representing employers and employees in the Scheduled employments, who shall be equal in number and independent persons not exceeding one-third of its total number of members; one of such independent persons is to be appointed the Chairman by the appropriate Government.

Before constituting a Committee, recommendations regarding the employers/employees' representatives are called from the Labour Officers in the State. Generally the employers' representatives are selected from the Employers' Associations representing the particular employment/important employers. Similarly the representatives of employees are selected from the different workers' organisations showing their affiliations with All India Body such as INTUC, AITUC, Hind Mazdoor Sabha and Independent Union etc.

(d) On the basis of the recommendations of the three Committees constituted during 1964, Government have fixed/revised minimum rates of wages in all the three employments. As regards the Committees constituted during 1965 recommendations of the Committees at Sr. Nos. 1 to 5 on the list at reply to part (b) above have been received. Minimum rates of wages in respect of the employments at Sr. Nos. 2 and 3 of the said list have been notified.

The Committees in respect of the remaining employments are still functioning.

(e) The time and labour involved in supplying the copies of the reports of the Minimum Wages Committees will not be commensurate with the possible benefit to be obtained. Reports from eight Minimum Wages Committees were received during 1964-65 out of which minimum wages have been fixed/revised on the basis of the reports of five Minimum Wages Committees. The remaining three reports are under consideration.

14

**श्रीमती सरला देवी :** मैं पूछना चाहती हूँ कि यह जो टेक्सटाइल मिनीमम वेजिज कमेटी 6 दफा बनाई गई और 6 दफा तोड़ी गई उसका क्या कारण है ?

**मन्त्री :** इसके लिये सैपरेट नोटिस दें ।

**Pandit Chiranji Lal Sharma :** In reply to the question of the hon. Lady Member Shrimati Sarla Devi, the hon. Minister has been pleased to state that he needs a separate notice. Sir, it is a very simple question. The question is as to what were the reasons for frequently changing the constitution of the Committee ?

**मन्त्री :** यह सवाल तो इससे पैदा नहीं होता । मैं तो इस फैक्ट को ही अभी नहीं मानता कि वह 6 दफा बनी और 6 दफा तोड़ी । इस के लिये नोटिस दें फिर पता कर लेंगे ।

**पंडित ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** मैं पूछना चाहता हूँ कि 1964 और 1965 के दौरान कितनी कमेटियां बनाई गई और क्या उनकी रिपोर्ट्स इम्पलीमेंट कर दी गई हैं या नहीं ?

**मन्त्री :** यह सारी इत्तलाह टेबल पर ले कर दी गई है ।

**पंडित ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बारे में जो रिपोर्ट दी गई है जिसके बारे में वर्कर्स मांग कर रहे हैं कि इम्पलीमेंट की जाए क्या उस पर कोई ऐक्शन लिया गया है और अगर लिया गया है तो क्या ?

**मन्त्री :** दिसम्बर में रिपोर्ट आई थी उस पर ऐक्शन ले रहे हैं ।

**Committee constituted to suggest changes in method of calculating working class cost of living indices**

**\*9322. Shri Sagar Ram Gupta** (put by Shrimati Sarla Devi on his behalf) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Government appointed a Committee to suggest changes and improvement in the method of calculating working class cost of living indices in the Punjab ; if so, the date when the said Committee was appointed and the names of its members ;
- (b) whether it is a fact that the said Committee has not yet started its work ; if so, the detailed reasons therefor ;
- (c) the time by which the said Committee is expected to submit its recommendations to the Government ?

**Chaudhri Rizak Ram :** (a) An Expert Committee to go into the working class cost of living index numbers was constituted,—vide Punjab Government Notification No. 3273-2LabI-65/8400, dated 5th April, 1965 with the following members :—

- (1) Secretary to Government, Punjab, Labour .. Chairman  
and Employment Departments
- (2) Labour Commissioner, Punjab .. Vice-Chairman
- (3) S. Gurdit Singh, Economic and Statistical .. Member  
Adviser, Punjab
- (4) Shri J. D. Khanna, Joint Director of Indus- .. Do  
tries, Punjab (Incharge, Statistics and  
Administration)
- (5) Shri J. S. Dhillon, Joint Economic and Sta- .. Secretary  
tistical Adviser, Punjab

**[Irrigation and Power Minister]**

(6) Shri Ram Sarup, Statistical Officer, Office  
of the Labour Commissioner, Punjab

.. Assistant  
Secretary

(b) Yes. After the constitution of the Committee, it was decided on the representations from the employers/workers representatives that this Expert Committee should be reconstituted giving representation thereon to the Economists and University Professors, etc. The matter is, accordingly, under consideration of Government.

(c) Question does not arise in view of the above.

**Houses constructed for Harijans in Tehsil Una, district Hoshiarpur**

**\*9380. Shri Surinder Nath Gautam :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state the total number of houses constructed for the Harijans by the Harijan Welfare Department in the Backward Hilly Areas of tehsil Una, district Hoshiarpur from January, 1965 to date with the total amount spent in each case?

**Shri Chand Ram :** Out of the four houses sanctioned during 1964-65 for tehsil Una, three have been completed after January, 1965 and subsidy of Rs. 1,200 each has since been paid to the three beneficiaries. The fourth house is still under construction and the beneficiary has been paid the first instalment amounting to Rs. 240.

**श्री अमर सिंह :** वजीर साहिब ने बताया है कि तहसील ऊना के बैकवर्ड हिल्ली एरिया में 1965 से लेकर अब तक सिर्फ चार मकान हरिजनों के लिये बने हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी ढंग से हरिजनों की डिवैलपमेंट होगी ?

**मन्त्री :** It is a question of funds. जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आने लगेंगे होते हैं उनके मुताबिक पापुलेशन बेसिस पर जिलावार और फिर आगे तहसीलवार तकसीम करते हैं और हर तहसील को प्रोपोरशनेटली बेनीफिट मिल जाता है।

**पंडित मोहन लाल दत्त :** क्या वजीर साहिब बताएंगे कि ऊना तहसील जो बैकवर्ड हिल्ली एरिया है और जहां हरिजनों की बुरी हालत है उनके घरों को बनाने के लिये कोई खास फंड मुकर्रर करने के लिये सरकार तैयार है ?

**मन्त्री :** स्पीकर साहिब, जहां हम मैदानी इलाके में 900 रुपया सबसिडी देते हैं वहां पहाड़ी इलाके में पहले ही 1,200 रुपया देते हैं। जहां तक तादाद का सवाल है मैं खुद इस हक में नहीं कि अनप्रोडक्टिव खर्च करें। फंड्स थोड़े हैं और हाउस फंड्स दिला दे तो और खर्च कर देंगे।

**पंडित सुरेन्द्र नाथ गौतम :** जो हरिजन बैकवर्ड हिल्ली एरिया में रहते हैं क्या सरकार उन्हें इस मामले में प्रायरीटी देने के लिये तैयार है ?

**मन्त्री :** मैं ने अर्ज किया है कि मैदानी इलाके के मुकाबले में हम पहले ही उन्हें ज्यादा सबसिडी देते हैं।

**लेडटीनेंट डाग सिंघ :** वी. वजीर साहिब दॅसलगे कि 1965 दिस में 3 घर बनावे गये हन एतुं घाते किस साल बजट अलॉटमेंट बीडी सी उ पेसे किस उतीध ठुं दिउं गये ?

**मन्त्री :** इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (8)25  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ :** ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਦਿਕਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਜਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਮੈਂ ਜੋ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਯਾ ਭਰਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਸੇ ਕਿਸੀ ਜਗਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

**ਸਾਨ੍ਹੀ :** ਇਸਕੇ ਲਿਯੇ ਨੋਟਿਸ ਦੋ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ :** ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਵਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡਜ਼ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਡਰਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਜ਼ ਤਹਿਸੀਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ।

**ਸਾਨ੍ਹੀ :** ਪਹਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਪਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਏਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਯਤ ਹੈ ਕਿ ਵਹ ਤਹਸੀਲਵਾਰ ਵੰਡੇ ।

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ?

**ਸਾਨ੍ਹੀ :** ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਏਸ਼ਜ਼ ਏਡ ਗਰਾਂਟਸ ਹੈ **Social and Economic advancement of the Harijans**, ਉਸਮੇਂ ਸਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸਦੀ ਬਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਮੇਂ ਸਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ।

**Mr. Speaker :** Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

**Payment of Haq-chuharam from the Income derived from Kutlehar Jagir Forests to the Panchayats**

**\*9498. Bakshi Partap Singh :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

- whether it is a fact that the Government decided on 26th October, 1961, to grant one-Fourth (Haq-Chuharam) of the income from Kutlehar Jagir Forests in district Kangra to the Panchayats ;
- if the reply to part (a) above is in the affirmative, the total income that accrued from the Kutlehar Jagir Forests during the years 1961-62, 1962-63, 1963-64 and 1964-65 ;
- whether one-fourth (Haq-Chuharam) of the income referred to in part (b) above was given to the Panchayats during the said period ; if not, the reasons therefor ?

**Shri Chand Ram :** (a) Yes.

	Rs.	P.
(b) 1961-62	..	40,432.04
1962-63	..	70,498.94
1963-64	..	65,128.12
1964-65	..	30,974.95

(c) No, because the matter regarding the payment to the Rakhas and Lambardars out of the share payable to the Panchayats is under consideration of the Government.

### Relief to the Families of those who died in an Encounter with the Pakistani-dropped Spies

**\*8842. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that Shri Faqir Singh, Nambardar, village Kalra, police station Adampur, died while in the company of local police, trying to catch the Pakistani-dropped spies in September, 1965 ;
- (b) the names of the other persons who also died in the said encounter and the date when this information reached the Government ;
- (c) the extent of relief so far given to the families of the deceased mentioned above in each case ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes. Shri Faqir Singh, Lambardar of village Kalra, police station, Adampur, district Jullundur, was in the company of the local Police when he died in trying to catch the Pakistani para-troopers in September, 1965.

(b) One Ram Parkash, Constable No. 823 of Hoshiarpur District also died in the same encounter. The information about this encounter and casualties was received by the Government on 8th September, 1965.

(c) A sum of Rs 1,500.00 has been given as ex gratia grant to the next of kin of Shri Faqir Singh deceased. The widow of late Constable Ram Parkash was given Rs 2,000 as relief and Rs 300.00 for funeral charges from the Police Welfare Fund. As the Constable had less than five years' service to his credit, his family was not entitled to family pension under the Family Pension Scheme, 1964. However, case for the grant of extraordinary pension to his family has been taken up. The Police Force of Hoshiarpur District also raised a sum of Rs 2,152.00 by contribution for the relief of Constable Ram Parkash's family.

### Action taken against the Bad Characters in the Border Areas for Looting the Property

**\*8850. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the details of the action taken by the Police to recover from the bad characters the property stolen or looted by them in the border areas of Punjab in the wake of the recent Pakistani aggression and the evacuation of Indian citizens from their houses ;
- (b) the details of the property so recovered ;
- (c) the total number of the said bad characters involved and the action taken against them ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) During the war, local Police was alerted to take special preventive measures by way of patrolling to safeguard the property of persons residing in the border area. The Police did their best to keep an eye over the activities of bad characters and to safeguard the property of the inhabitants of the War-affected border area. Where property was stolen during the war in the border area, immediate steps were taken to recover the same.

**WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE (8)27  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45**

(b) Stolen property worth Rs 8,487.50 was recovered. Details are given below :—

	Rs. P.
Cloth ..	6,287.50
Cattle ..	1,500.00
Sewing Machines ..	300.00
Cycle ..	75.00
Utensils ..	25.00
Ghee, Sugar, etc. ..	250.00
<b>Total ..</b>	<b>8,437.50</b>

(c) Sixteen accused were arrested for thefts detailed in (b) above.

**Complaint against S.H.O. Devinder Singh, Police Station Nihal Singhwala, District Ferozepur**

**\*8867. Sardar Gurcharan Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether he received any complaint against the S.H.O. Devinder Singh of P.S. Nihal Singhwala, district Ferozepur, in October or November, 1965 ; if so, the nature of the complaint and the action taken thereon so far ?

**Sardar Darbara Singh :** Yes. A complaint, dated 3rd November, 1965 was received by me on 4th November, 1965 from Shri Gurcharan Singh, M.L.A. It was alleged that Shri Devinder Singh, S.H.O., Police Station Nihal Singhwala, called one Charan Dass who was in possession of an illicit revolver, took Rs 1,000 from him as illegal gratification and let him go scot free and that the S.H.O. was trying to plant that revolver on somebody else. It was looked into by a Superintendent of Police but the allegations against the S.H.O. could not be substantiated.

**Case of Dacoity in Village Radhana, Tehsil and District Sangrur**

**\*9190. Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a dacoity was committed in the house of one Solhu of village Radhana, tehsil Jind, district Sangrur in the month of December, 1965 and an amount of Rs 35 thousand was taken away by the dacoits and that on that very day the D.I.G., Patiala, S. P., Sangrur and D.C., Sangrur along with a large police force were present in Jind in connection with the Gurdwara Sanatan Dharam Sabha dispute regarding a piece of land ;

(b) whether the said dacoity has been traced out, if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be traced ;

(c) whether any arrest has been made in connection with the said case, if so, the number of persons arrested or interrogated?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Yes. A dacoity was committed in the house of Shri Dehlu (not Sohlu), son of Shri Budhu Jat of village Radhana in which a cash and ornaments worth 30,300 were taken away. Case F.I.R. No. 169, dated 22nd December, 1965, under section 395/397, I.P.C., P.S., Jind was registered.

D.I.G., Patiala Range, S.P. Sangrur and D.C., Sangrur were camping at Jind on that day in connection with the dispute between Gurdwara and Sanatan Dharam Sabha over a piece of land.

**[Home and Development Minister]**

(b) No. The case is still under investigation. It is not possible to give any dead-line by which the case will be worked out, but every effort is being made to expedite it.

(c) No.

**Cases of Burglary in Jind and Panipat Sub-Divisions**

**\*9298. Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister of Home and Development be pleased to state the total number of cases of burglary registered at different police stations of Jind Sub-Division of district Sangrur and the Panipat Sub-Division of district Karal during the year 1965 together with the number of cases which have so far been traced and the number of cases in which the culprits were convicted ?

**Sardar Darbara Singh :**

	<i>Jind Sub- Division</i>	<i>Panipat Sub- Division</i>
(i) Number of burglary cases registered during the year 1965 ..	31	69
(ii) Number of cases traced ..	13	25
(iii) Number of cases in which culprits were convicted ..	5	14

**Licences for Pistols, etc., issued in District Ferozepore**

**\*9345. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the total number of new licences for pistols, revolvers and guns issued in District Ferozepore during the period from September to December, 1965 ;
- (b) the number of licences, if any, out of those mentioned in part (a) above issued for weapons which were originally illicit categorywise ;
- (c) whether the character of each applicant was verified before issuing him a licence ; if not, the number and category of cases wherein the said verification was not made and the reasons therefor ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) 1,075.

(b) 11.

(i) Revolvers/pistols ..	8
(ii) Gun ..	1
(iii) Rifles ..	2

(c) The character of each applicant was got verified before issuing the licence except in the case of following categories :—

(i) Persons who already held arms licences which had been issued after police verification ..	5
(ii) Persons personally known to the Deputy Commissioner ..	1
(iii) Government servants ..	2

**Development work done in Gram Panchayat Area of Kotla Ber, tehsil  
Dehra, district Kangra**

**\*9296. Thakur Mehar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the development work carried out in the Gram Panchayat area of Kotla Ber, tehsil Dehra, district Kangra, during the period from 1958 to 1965 ;
- (b) the total amount spent on the said work together with the amount out of it paid/contributed by (i) the Panchayat from its funds (ii) the Panchayat Samiti and the Government separately ;
- (c) whether the Panchayat activities were supervised and checked by the Panchayat Department during the said period ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) & (b) The information in the form of a statement is laid on the Table of the House :

(c) Yes.

## [Home and Development Minister]

## STATEMENT

*Total amount spent on the works*

Serial No.	Year	Development work carried out	Total amount spent on the works				REMARKS
			Government share	Panchayat Samiti contributions	Panchayat contributions	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1958	Purchase of furniture for Government High School, Kotla	300.00	..	..	300.00	
2		Repairs of Government Primary School, Kotla	75.00	..	..	75.00	
3		Repairs of Government Girls Primary School, Behr	75.00	..	..	75.00	
4	1959	Repairs of Girls Primary School, Kotla	100.00	..	..	100.00	
5		Repairs of Government Primary School, Bhadal	100.00	..	..	100.00	
6		Repairs of Government Girls Primary School, Jandaur	100.00	..	..	100.00	
7		Repairs of Girls Primary School, Kanpur	100.00	..	..	100.00	
8		Repairs of Girls Primary School, Jakhuni	100.00	..	..	100.00	
9		Repairs of Girls Primary School, Guraldhar	150.00	..	..	150.00	

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS  
LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(8)31

10	Purchase of furniture for Government Primary School, Jakhuni	75.00	..	..	75.00	
11	Purchase of furniture for Government Primary School, Guraldhar	75.00	..	..	75.00	
12	Construction and Repair of School, Kotla Behr, through Development Council	1,430.00	..	1,430.00*	2,860.00	*Public contributions through Panchayat
13	1960 Purchase of furniture for Government Dispensary, Kotla	200.00	..	100.00*	300.00	@ Ditto
14	Repairs of Kuhl Kasba	1,115.00	..	..	1,115.00	Handed over to Ram Rakha Dogra, Panch
15	Repairs of Girls Primary School, Kotla	110.00	..	..	110.00	
16	Repairs of Girls Primary School, Kanpur	110.00	..	..	110.00	
17	Repairs of Girls Primary School, Bhadal	110.00	..	..	110.00	
18	Repairs of Girls School, Guraldhar	110.00	..	..	110.00	
19	Repairs of Girls Primary School, Jandpur	110.00	..	..	110.00	
20	Repairs of Girls Primary School, Jakhuni	110.00	..	..	110.00	
21	1961 Construction of protection wall Girls Primary School, Kotla	360.00	..	348.78*	708.78	*Public contributions through Panchayats
22	Construction of Bouli at Kotla	830.00	..	@ 476.00	1,306.00	@ Ditto
23	Ditto	1,000.00	..	% 734.14	1,734.14	% Ditto
24	Construction of Community Hall, Kotla	7,035.00	..	..	6,391.70	(Spent out of total grant of 7,035)
25	Repairs of Girls Primary School, Kotla	100.00	..	..	100.00	
26	Repairs of Girls Primary School, Jakhuni	100.00	..	..	100.00	

[Home and Development Minister]

Serial No.	Year	Development work carried out	Total amount spent on the works				
			Government share	Panchayat Samiti contributions	Panchayat contributions	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
27		Celebration of Independence Day	10.00	..	..	10.00	..
28	1962	Repairs of Government Primary School, Kotla	100.00	..	..	100.00	—
29		Repair of Girls School, Jakhuni	100.00	..	..	100.00	
30	1963	Repair of Well Jakhuni	800.00	..	..	..	(Work yet to be started)
31		Construction of Bauli at Behr	1,100.00	..	..	..	Ditto
32		Construction of Bauli at Kotla	1,000.00	..	..	..	Ditto
33		Pavement of Streets of village Kotla	300.00	..	*104.75	404.75	*Public contributions through Panchayats
34		Repair of Girls Primary School, Jakhuni	96.00	..	..	96.00	
35		Repair of Girls Primary School Kasba Kotla	96.00	..	..	96.00	
36		Construction of Kuhl Kotla	4,244.00	..	..	..	—
37	1964	Construction of Well at Kotla	800.00	..	..	..	—
38		Handpump in Girls Primary School, Jakhuni	250.00	..	..	..	—

— Handed over to the Secretary  
Co-operative Society,  
Kotla. No account with  
Panchayat

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE  
TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

(8)33

39	Construction of Bund at Kotla	700.00	..	..	Work not started
40	1965 Repair of Government Primary Schools Kotla and Jakhuni	220.00	..	213.15	
41	Dramatic Club, Kotla	300.00	..	Purch	affected
42	Community Hall Kasba Kotla (construction)	..	3,000.00	..	Handed over to Ram Rakha Panch
43	Repair of Jakhuni Kuhl	1,733.00	..	..	Work not started
44	Repair of Kuhl Behr	1,600.00	..	..	Ditto
45	Construction of Girls Primary School, Kasba	1500.00	..	..	Ditto

### Provident Fund Contribution of Employees of Zila Parishads and Block Samitis

**\*9462. Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the rate at which the Provident Fund contribution is credited to the accounts of the employees of the Zila Parishads and the Block Samitis at present and the rate at which it was credited before the 4th September, 1965 ;
- (b) if the said rate were reduced after the 4th September, 1965 or near about, the reasons for such reduction ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) 6 per cent. The Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Provident Fund Rules, 1965, have been framed for the first time to take effect from 17th September, 1965. Before that the employees of District Boards absorbed by the Panchayat Samitis and Zila Parishads were also entitled to the benefit of Provident Fund contribution subject to a maximum of six per cent.

(b) Since the rules have been framed for the first time question of reduction of rate of contribution does not arise.

### Indo-German Package Scheme

**\*8843. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether it is a fact that an Indo-German Package Scheme applicable to the districts of Kangra and Kulu was rejected by the Union Government because of the fact that the Punjab Government failed to submit the scheme in time to the Union Government ; if so, the reasons why the Government failed to submit the scheme in time ?

**Sardar Darbara Singh :**

- Part I .. No.
- Part II .. Question does not arise.

### Food Production

**\*9234. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the quantity of foodgrains forecast to be produced in the current year together with the difference, if any, apprehended in the quantity of the said production this year as compared with that of the last ten years ?

**Sardar Darbara Singh :** The Total production of foodgrains in the State during 1965-66 is expected to be approximately 55 lakhs tons as compared to the production of 48 lakh tons in the years 1955-56, viz., the last ten year. The total production for the last ten years, viz., 1955-56 to 1965-66, is as under :—

Year	Production in '000 tons
1955-56	.. 4,800
1956-57	.. 5,453
1957-58	.. 5,266
1958-59	.. 6,142
1959-60	.. 5,555
1960-61	.. 6,148
1961-62	.. 6,203
1962-63	.. 5,700

LAI'D ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Year	Production in tons
1963-64	5,744
1964-65	7,109
1965-66	5,470
	(Estimated production)

The production figures for the year 1965-66 are only rough estimates and are not based on crop-cutting experiments. Shortfalls during 1965-66 are mainly due to severe draught and consequent short water supply to even canal irrigated areas. Recent emergency also affected the border areas. Fertilizers were also in short supply and were hardly 40 per cent of our total demand. Total demand was 6.01 lac tons and supply was about 2.38 lac tons upto 28th February, 1966.

**Cancellation of Lease of Land made in favour of Birlas**

**\*9343. Comrade Gurbakhash Singh, Dhaliwal :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Government proposes to cancel the lease of land in Rupar Tahsil made in favour of the Birlas;
- (b) if reply to part (a) above be in the affirmative, whether the Government is considering this question itself or at the instance of the Union Government or any organisation or individuals ;
- (c) whether the Government has received any memorandum from the political parties/public organisations in the State for the cancellation of the said lease ; if so the names of such political parties/public organisations, and the action, if any taken thereon ?

**Sardar Darbara Singh (a) No.**

**(b) Does not arise.**

**(c) Yes, the Government have received memoranda in this regard from the President, Peasants Action Committee, Parja Socialist Party, Punjab Branch, Jullundur, which are under consideration of the Government.**

**Diesel Tubewells in Tahsil Guhla**

**\*9393. Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether it is a fact that Government have announced that it would give a grant of Rs. 750 to every person who installs a diesel-run-tubewells in Guhla Tahsil ; if so, the number of owners of such Tubewells in the said tehsil, who have been given the said grant ?

**Sardar Darbara Singh :** Yes ; but only such recipients of loans for pumping sets/tubewells during the year 1964-65 or thereafter, as :—

- (a) are situated in non-electrified villages ;
- (b) instal new engines within one year of the receipt of loans ; and
- (c) use them for at least one year ;

Will be eligible for the grant of subsidy equal to 25 per cent of the cost of diesel engines, subject to a maximum of Rs. 750 . No subsidy has been allowed so far.

**Disposal of an Election Petition filed by Shri Om Parkash of Jind**

**\*9187. Chaudhri Inder Singh Malik :** Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state whether he is aware of the fact that an election petition by Shri Om Parkash of Jind against Shri Shamsher Jung, the elected Municipal Commissioner from Ward No. 4, was filed before the competent authority in July, 1964 and since then no date whatsoever has been fixed for its hearing, ; if so, the procedure proposed to be adopted by the Government for early decisions of election petitions while there are clear instructions that such petitions should be decided within six months ?

**Sardar Ajmer Singh : Part I.**—Yes, but hearings were fixed twice though service could not be effected. The delay has occurred due to frequent transfers of the officers appointed as Election Commission.

**Part II**—Does not arise.

**Municipal Committee Chheharta, district Amritsar**

**\*9455. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state—

- (a) whether the President, Municipal Committee, Chheharta, district Amritsar forwarded to the Government through the Deputy Commissioner, Amritsar on 26th February, 1965 a revised schedule of Professional tax adopted by the Chheharta Municipal Committee for publication in the Punjab Government Gazette, in accordance with the provisions of the Punjab Municipal Act, 1911;
- (b) if reply to part (a) above be in the affirmative, whether the said schedule has been published in the Gazette; if not the reasons for withholding publication of the same;
- (c) whether it is a fact that he discussed the above matter with the President of the said Committee on 5th January, 1966 at Chandigarh, and assured the latter that the said schedule would be published soon; if so, the reasons, if any, why it has not so far been published?

**Sardar Ajmer Singh:** (a) Yes;

(b) The requisite notification has already been issued for its publication in the official Gazette.

(c) Yes; the matter required further consideration at Government level which caused some delay in publication of the notification.

**Recommendations of Municipal Committee, Faridabad Town for restoration of Octroi Tariff in the Town**

**\*9464. Shri Roop Lal Mehta:** Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state whether the Government has received the recommendation of the Municipal Committee, Faridabad Town, for the restoration of the Octroi Tariff in Faridabad Town and for withdrawing the old concessions; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter; if no action has been taken, the reasons therefor?

**Sardar Ajmer Singh:** A proposal has been received from the Municipal Committee, Industrial Township, Faridabad, for the enhancement of rates of octroi in respect of a number of items of its octroi schedule. The matter is receiving consideration of Government.

## UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

**Survey to ascertain the presence of Flourine in Drinking Water in certain Areas of district Sangrur**

**3197. Sardar Ranjit Singh Nainewala, M.L.A. :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) whether any survey has been made to ascertain the presence of flourine in the drinking water in the Qanungoi Circles of Bhadaur, Mahal Kalan and Ahmadgarh of district Sangrur; if so, the extent of the area affected and the details of the scheme, if any, formulated for the supply of drinking water to the said area ?

**Shrimati Om Prabha Jain, :** (a) (i) Yes. About 250 water samples were collected from 44 villages/towns of Sangrur district (including Qanungoi Circles of Bhadaur, Mahal Kalan and Ahmadgarh).

(ii) The results obtained revealed that flourine in water was above 1 part per million in 24 villages only. No Scheme has so far been formulated for this area.

## POINTS OF ORDER

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਰ। ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਵੈਸ਼ਚਨ ਆਕਰ ਮੈਂ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰ ਫੂਏ, ਵਹ unstarred ਕਰਾਰ ਦਿਏ ਜਾਏਗੇ। (All those questions on the list, which could not be taken up in the House will be treated as unstarred questions.)

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਿਆਨ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੌਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ।.....

**Mr Speaker :** Please take your seat

## QUESTION OF PRIVILEGE

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨਿਹੋਤ੍ਰੀ ਨੇ ਏਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਸੰਡ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਕੋ ਕਈ ਬਾਰ ਕਹ ਚੁਕਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਮੇਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤੋ ਵਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾ ਈਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਕਾ ਜਵਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੇ ਬਾਦ ਆਪ ਕਾ ਜਵਾਬ ਆਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਜਵਾਬ ਹਾਊਸ ਕੀ ਮੇਜ ਪਰ ਰਖ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ।

(The hon. Member, Shri Om Parkash Agnihotri has given

[श्री अध्यक्ष]

notice of a Privilege Motion regarding the alleged wrong information supplied by the Minister concerned in reply to a question asked by Comrade Ram Chandra. In this connection I have told the House many a time that an alleged wrong reply given by a Minister in the House, cannot form the basis of a privilege motion. If the hon. Member considers the Minister's reply to be incorrect, then his view point will be conveyed to the Minister. After that the Minister's reply and the hon. Member's view would be placed on the Table of the House).

### ADJOURNMENT MOTIONS/CALL ATTENTION NOTICES

आज एक दो एडजर्नमेंट मोशनज़ और काल एटेंशन मोशनज़ आई हैं। उन के बारे में अभी तक प्रोसीजर तय नहीं हुआ है। आज इस बारे में बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है। वहां पर जो फैसला होगा उस के हिसाब से आगे कार्यवाही की जाएगी। यह एडजर्नमेंट मोशनज़ और काल एटेंशन मोशनज़ भी उसी फैसले के आधार पर कंसिडर की जाएंगी।

(Tod-day notices of one or two Adjournment and Call Attention Motions have been received. No procedure regarding their disposal has so far been settled. The Business Advisory Committee is meeting to-day in this connection. The disposal of such motions, will therefore be effected according to the decision taken there. The Adjournment and the Call Attention Motions set down for today will also be considered in the light of that decision.)

श्री ओस प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। कल यह मामला हाउस में टेक अप किया गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा ने चीफ पालियामेंटरी सेक्रेटरी को हुकम किया था कि वह चौधरी सुन्दर सिंह को कहें कि प्रैस एम्पलाइज़ को जो एंशोरेसिज़ दी थीं, उन के बारे में आगे कार्यवाही करें। यह बात कल की प्रोसीडिंग में भी आई। इस लिए मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप चौधरी सुन्दर सिंह को इस बारे में हाउस में स्टेटमेंट देने के लिए कहें।

कामरेड सभर सिंघ ज़ोस : आन द प्वायंट आफ आर्डर, सर। गवर्नमेंट परिस वरकरज़, चंडीगढ़ अंडे पटिआले ने एक दिन की सटराईक अज करदित्ती है। एह मामला कल वी हाउस दे अंदर लिआंदा गिआ सी। चेंपरी सुंदर सिंघ ने अज ए डिप्टी मनिस्टर डार लेबर अंड प्रिंटिंग अगसत, 1965 दिच एहनां करमचारीआं नुं क़ुअ अंशोरेसिज़ दितीआं सन लेकिन एहनां डे सरकार ने अमल नही कीता। एह कारन एह गंडीर मसला बट गिआ है। सानुं स़क है कि सरकार दा बजट वी वक़त डे डप ना सकेगा। एह डे नाल पेंसिशन हेंर वी कंपलीक्रेटिड हें सकेदी है। एह लदी मै सभदा हां कि एहनां दी मंगां ज़ादिज हन अंडे एहनां दी मंगां मिन लैटीआं चाहीदीआं हन।

**Mr Speaker :** please take your seat.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਕਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਬਿਲ ਉਤੇ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

**ਪਰਿਵਰਨਨ ਤਥਾ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਕੱਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਦਸਯ ਕੋ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਨ ਥਾ ਅਤੇ ਕਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ। ਮੁਝੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਾਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਟੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਨ ਥਾ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਥਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਕੋ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਆ। (ਹੱਸੀ) ਇਸ ਲਿਏ ਉਸ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਆਪ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਨ ਥਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁਆ। ਆਪ ਨੇ ਆਗੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਨੋਨ-ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹ ਚੁਕਾ ਹੋ ਤੋ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ। (ਹੱਸੀ) (The hon. Minister has said that yesterday being a non-official day, non-official business was conducted in the House. He further on stated that the non-official Bill was moved by a non-official Member. But once a Member has acted as a Minister, he earns the title of "Sarkaria".) (Laughter)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ?

**Mr. Speaker:** Please take your seat.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਛੋਟੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਆਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਪਾਰਲਿਯਾਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਯਰਜ਼ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਥੇ। ਉਨ੍ਹोंने यहां पर कहा था कि सरकार इस बिल की मुबਾਲफत करती है। ज्ञानी करतार सिंह ने हाउस में अपने व्यूज़ पेश किए। उस के बाद बिल के बारे में ਚੈਲੰਜ हुआ। मिनिस्टर साहिब ने खुद ही डिਵੀज़न कराने के लिए कहा। उसके बाद सरकार को डिਫੀਟ हुई। जब सरकार को डिਫੀਟ हो गई तो सरकार को मारेली भी फर्ज बनता है कि वह ट्रेज़री बैंचों पर रहने के काबिल नहीं है और उन्हें वज़ारत से ਰੀਜ਼ਾइन करना चाहिए। अब हाउस को इस सरकार पर एहतमाद नहीं रहा है। इस लिए इस सरकार को वोट ਆਫ ਕਾਂਫੀਡੈਂਸ लेना चाहिए। अन्यथा ज्ञानी करतार सिंह को अब टाइम ਫਿਕਸ करना चाहिए ताकि वह उस समय गवर्नਰ साहिब के पास जा कर ਆਥ ਲੇ और उस के बाद वह अपनी वज़ਾਰत बनाए और बाद में सरकार की कार्यवाही को चलाएं। (ਹੰਸੀ)

**ਜ਼ਿਲਾ ਮਨਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਥਾ ਕਿ ਯਹ ਬਾਤੋਂ ਲਾਈਟ ਸੂਝ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀਂ ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਰ ਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਕਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਯਾ ਗਯਾ ਆਰ ਕਹਾ ਗਯਾ ਕਿ ਹਮੇਂ ਰੀਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਦੇਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕੋ ਭੀ ਅਚਛੀ ਟਰਹ ਸੇ ਸਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਆਫਿਸ਼ਯਲ ਡੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਤੋ ਕਿਸੀ ਭੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਭੀ ਰੀਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਯਾ। ਸ਼ਾਨਨੀਯ ਸਦਸ਼੍ਯ ਦੁਨੀਯਾ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਯਹ ਬਾਤ ਯਾ ਮਿਸਾਲ ਬਤਾ ਦੇਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਭੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਨ-ਆਫਿਸ਼ਯਲ ਡੇ ਪਰ ਨਾਨ-ਆਫਿਸ਼ਯਲ ਬਿਲ ਪਰ ਡਿਫੀਟ ਹੋਨੇ ਪਰ ਰੀਜ਼ਾਇਨ ਕੀਯਾ ਹੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਭੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਕਾ ਕਾਂਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮ ਉਨ ਕੋ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਵਹ ਕਿਸੀ ਝੰਸ਼ੂ ਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲੇਂ ਆਰ ਉਨ੍ਹੇਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਝੰਸ਼ੂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਮੈਜਾਰਟੀ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਵੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹਨ..... (Interruptions)

**Mr. Speaker :** Order order.

**ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ( ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ—

“No outsider would be taken for apprenticeship if men having same qualifications are available from amongst the workers.”

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : Clear ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। (ਵਿਘਨ)

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਨਾਂਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ..... (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੈਰਮਿੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਰਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 45 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 43 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ rules, regulations ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ..... (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ hours ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ .....(ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਐਡ੍ਰੇਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਸੇ ਆਪ ਕਾ ਮੁੰਹ ਮਾਇੰਕ ਸੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਤਾ ਹੈ ਐਰਿ ਕਾਤ ਅਚਛੀ ਤਰਹ ਸੇ ਸੁਨਾਇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਆਪ ਸੁਭੇ ਐਡ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਐਰਿ ਅਪਨਾ ਮੁੰਹ ਮਾਇੰਕ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਰਖੋ।

(ਇਸ ਸਮਧ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਹ ਬੈਠ ਗਏ) (Noise)

ਦੇਖਿਯੇ, ਅਗਰ ਤੋ ਹਾਯਸ ਇਸ ਮੂਡ ਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਦੀ ਕਾਤ ਸੁਨਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਹਾਯਸ ਕੋ ਐਡਜਰਨ ਕਿਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਕੋ ਆਦਤ ਪੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਾਸਲੇ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੁਏ ਭੀ ਐਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਤੋਂ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਇਸੀ ਤਰਹ ਸੇ ਚਲਨਾ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਠੀਕ ਤਰਹ ਸੇ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀਂ। ਸਬ ਕੋ ਥੋਡਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਾਨਨਾ ਪੜੇਗਾ।

ਦੂਸਰੀ ਕਾਤ ਧਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ ਭੀ, ਆਗੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਭੀ ਐਕ ਕਨਵੇਨਸ਼ਨ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੇਂ ਫਾਲੋ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵਹ ਧਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਤੋ ਹਰ ਗ੍ਰੁਪ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਐਕ ਐਕ ਸਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ।  
(The hon. Minister Chaudhri Sunder Singh need not try to address any Member because while doing so, his face moves away from the mike and his voice is not heard properly. He may please address the Chair and keep his mouth before the mike.)

(At this time Chaudhri Sunder Singh took his seat) (Noise)

The hon. Members may please listen. If the House is not in a mood to hear any body, then it can be adjourned. It has become a habit with the Members on both the sides that they continue indulging in mutual talks even though they are seated at a sufficient distance. If they would behave like that then the proceedings of

[श्री अध्यक्ष]

the House cannot be carried on properly. All of us will have to conduct ourselves under some discipline.

The other thing is that I want to set up and follow a convention which is already in vogue in the Lok Sabha. That is when a statement is made by Government, then each group in the House will be entitled to ask a question on that.)

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, 6/7 दिन हो गए हैं एक आदमी मर गया था हांसी में। उस के लिये मैं ने मोशन दी थी। अब कल भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है लेकिन मेरी मोशन का फैसला नहीं हो रहा, . . . . . (विघ्न) पुलिस आदमी मार देती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप यह प्रिज्युम करते हैं कि अगर यह फैसला हो जाए कि काल अटेनशन मोशन एडमिट करनी है तो यह जरूर एडमिट हो जाएगी आप इस प्रिज्युम्पशन पर चलते हैं। मैं ने कहा था कि कि मीटिंग काल की हुई है उस में प्रोसीजर तय करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। (The hon. Member presumes, that if any decision regarding admisibility of Call Attention Motion is taken, then this particular motion must be admitted. This appears to be his presumption. What I said was that a meeting of the Business Advisory Committee has been called and whatever procedure in this connection is decided it will be acted upon).

सरदार अज्ञादिब सिंघ सैयू : उसां हुन फरमाਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁਪ ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

Mr. Speaker : He has completed his Statement.

सरदार अज्ञादिब सिंघ सैयू : नहीं जी।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि चौधरी साहिब ने जो स्टेटमेंट दिया है वह कोई स्टेटमेंट नहीं है। That does not amount to a statement even. उस का न कोई सिर है न कोई पैर। हाउस में अगर कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो उस में कोई स्पैसिफिक चीज़ आनी चाहिए। हमें उस की कापी मिलनी चाहिये ताकि हम उस को पढ़ कर सवाल पूछ सकें। उन की स्टेटमेंट का तो हाउस को कुछ पता नहीं लगा कि क्या बात उन्होंने मानी है और क्या नहीं मानी। बारह अगस्त और 14 नवम्बर

को जो उन्होंने स्पेसिफिक एशोरेस प्रेसमैन को दी थी उस पर स्टेटमेंट आनी चाहिये थी। तीनों बातों को क्यों नहीं माना गया, हम उस के बारे में स्पेसिफिक स्टेटमेंट चाहते थे . . . . .

**श्री अध्यक्ष :** कल डिप्टी स्पीकर साहिब ने आर्डर दिया कि मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट होगा। गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट थी कि स्टेटमेंट होगा आज आवाज उठाने पर मिनिस्टर साहिब ने स्टेटमेंट दिया है। वह अच्छी है या बुरी है, किलयर है या नहीं है यह बात दूसरी है। मैं फोर्स नहीं कर सकता कि वह परटीकुलर टाईप की स्टेटमेंट दें। (Yesterday, the Deputy Speaker had ruled that a statement on the subject should be given by a Minister. The Government made a commitment that a statement in this regard would be made. Today, when this point was again pressed, the hon. Minister made the requisite statement. Now whether this statement is good or bad, clear or otherwise, is a separate matter. I cannot force the Minister to give a particular type of statement.)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** आप ने फालो किया है।

**श्री अध्यक्ष :** मैं कमेंट नहीं कर सकता। स्टेटमेंट हाउस के सामने है। इट एज फार ही हाउस टू कनसिडर। ( I cannot make any comment. The statement is before the House. It is for the House to consider.)

(*Interruption*)

**श्री अध्यक्ष :** जब चौधरी सुन्दर सिंह बोलने लगते हैं तो बेतहाशा क्लैपिंग होने लगती है, बेतहाशा इन्ट्रप्शंस होने लगती है। ( When Chaudhri Sunder Singh rises to speak, lot of clapping is done and interruptions run galvare.)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** वह तो उन को ओवेशन मिलती है।

**श्री अध्यक्ष :** जब इस तरह क्लैपिंग और इन्ट्रप्शंस के दौरान वह कोई बात कह जाते हैं, अपने ढंग से कोई बात कह जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि यह तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। (When during clappings and interruptions like this he says anything in his own particular way, then the hon. Members complain that this is no statement.)

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** वह रिटन स्टेटमेंट दें।

**श्री अध्यक्ष :** मैं उन को नहीं कह सकता कि वह रिटन स्टेटमेंट ही दें। रिटन दें या ओरल यह उन की अपनी मर्जी है। (विघ्न) (I cannot compel him to make a written statement. It is up to him to make a written or an oral statement.)

(*Interruption*)

**Mr. Speaker:** It is for the hon. Minister concerned to make a choice whether he wants to make a written or oral statement. Now those hon. Members who are allowed to put questions may put the same.

**ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁਪ ਲੀਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

(Even from Congress benches, only one member will be allowed to put a question.)

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ।

**Mr. Speaker :** Please do not make comments and confine yourself to the point of order.

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੁਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੇਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਕਲ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ? (*Interruption*)

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਰਟਰੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਦਾ, ਕੇਸ ਸੈਕਰਟਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਡਾ ਹੈ?

ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਕ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਰੂਲਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ?

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਂ ਕੋ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਕੰਪੋਜਿਟੀ ਏਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਟੀਕਸ ਐਂਡ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਏਕ ਸੁਯੋਜਨ ਦੇਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇਧਾਂ ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂ ਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋ ਸਾਨਤਾ ਹੁੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਹਾਤਸ ਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਏਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਏਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਿਓ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਕੀ

इन्टरनल बातें हैं, मुनासिब होगा अगर उन को हाउस में न लाया जाए क्योंकि जो भी एक मिनिस्टर का फैसला होता है वह उसका अपना फैसला ही नहीं होता। यह चीज़ सारी की सारी ज़वायंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर होनी चाहिए वरना काफी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है जब एक मिनिस्टर यहां पर खड़ा हो कर यह कहता है कि मैं तो मानता हूं सैक्रेटरी नहीं मानता या यह कि मैं तो मानता हूं लेकिन फलां मिनिस्टर नहीं मानता है। उन को बताना चाहिए कि it is a decision of the Government or not. It will be better if Government comes to the House as a Government. (Thumping from the Opposition) (I would like to make a submission to Sardar Gurdial Singh Dhillon in his capacity as Minister for Parliamentary Affairs. Since long many a Minister has been individually telling the House that he was agreeable to a certain proposition and would like it to be implemented but the other Minister would not agree to it. I feel that in this House no Minister should speak in his individual capacity but on behalf of the Ministry as a whole and it would be proper that no internal talks on a difference of opinion subsisting between them on a certain matter should be ventilated in the House. The decision of a Minister does not reflect his own individual decision but that of the whole Ministry. The whole thing should be done on the basis of a joint responsibility, otherwise it creates confusion. When a Minister rises and says that he agrees with a certain proposal but a certain Secretary does not see eye to eye with him or a certain Minister did not countenance it, what he should tell the House, is whether it is a decision of the Government or not. It will be better if Government comes to the House as a Government.)..(Thumping from the opposition)

**Transport and Elections Minister:** Mr. Speaker, I am very sorry that so much misunderstanding has cropped up because of this....

**A voice:** Not understood.

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਮ ਟਰਮਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ—ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭਾਵਕ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ.....(ਵਿਘਨ)

(At this stage Sardar Gurbanta Singh rose on a Point of Order and the hon. Speaker asked him to do so after the Minister for Transport and Elections had finished his observation.)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ—ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਲੇਰੀਫੀ-ਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ( *Interruptions*)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਔਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਕ ਉਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੀ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਵੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

**Mr. Speaker :** Please do not make a speech

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਅਗਰ ਇਕ ਕਾਬਲ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਕੈਬੀਨਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਅਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਉ ਕੀ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅग्निहोत्री :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਐਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਐਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਧਰੁ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨੇ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਥੀ ਉਸ ਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਪਰ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 1965 ਆਰ 14 ਨਵੰਬਰ, 1965 ਕੋ ਤੀਨ ਐਂਥੋਰੋਸਿਜ਼ ਦੀਂ ਆਰ ਕਹਾ ਕਿ ਕਕਤ ਕੇ ਆਕਾਤ ਬਦਲਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ . . . . .

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕ :** ਆਪ ਸਪੀਚ ਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਐਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪਰ ਬੋਲੋ।

(The hon. Member need not make a speech. He may confine himself to his point of order.)

**ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅग्निहोत्री :** ਇਸ ਕੇ ਬਾਦ 22 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਏਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁई ਜਿਸ ਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਆਈ. ਏਨ. ਆਹੁ ਜਾ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਆਰ ਕਰਕੇਂ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿ ਸੀਯੂਥ ਥੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਂਥੋਰੋਸਿਜ਼ ਮੈਂ ਨੇ ਦੀ ਹੈਂ ਉਨ ਪਰ ਅਸਲ ਕਰਾਝਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਨ ਕੀ ਸੀਯੂਥੀ ਮੇਂ ਸੈਕਰਟਰੀ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਰ ਕਰਕੇਂ ਕੋ ਡਾਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਯਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਧਰੁ ਜਾਨਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਸੀਯੂਥੀ ਮੇਂ ਜੋ ਸੈਕਰਟਰੀ ਨੇ ਕਰਕੇਂ ਕੋ ਡਾਟਨਾ ਆਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਫਸ ਥਾ, ਕਥਾ ਧਰੁ ਠੀਕ ਹੈ ?

**ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ :** ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਇਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਫਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਉ ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ :** ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੈਮੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡੈਮੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । (*Interruptions*)

**ਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਨੜੀ :** ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਰਖਣੇ ਥੇ ਸਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 11.00 a.m. ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੇਂ ਚੁਪਾ ਹੈ ਯਹ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੇ ਗੁਜਰਾ ਹੋਗਾ । ਵਹ ਹੁਸ ਮੇਂ ਸ ਕਿਸੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਭੀ ਚਾਹੇ ਵਹ ਇਥਰ ਬੈਠੇ ਹੋਂ ਯਾ ਉਥਰ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਭੀ ਸ਼ੋਆ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਫਟ ਹਾਟਿਡ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਸਗਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਮਨੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ, ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਉਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਮਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਨਾਅਰਹਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ ਕੇ ਮੁੰਹ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਕਹੁੰਦੇ ਹੈਂ । ਹਮਾਰੇ ਮੁੰਹ ਮੇਂ ਭੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਆਰ ਹੁਸ ਭੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹ ਸਕਦੇ ਹੈਂ । ਸਗਰ ਯਹ ਅਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ । ਮੈਂ ਅੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋ ਹੁਸ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬੈਠਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਨਾ ਚਾਹਿਓ । ਅਗਰ ਇਨ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਤੀ ਤੋ ਡਿਫਰੇਂਸਿਜ਼ ਆਰ ਗੁਸ਼ਾ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੇ ਆਰ ਜ਼ਰਾਏ ਹੈਂ ਸਗਰ ਜ਼ਾਤਿਯਾਤ ਮੇਂ ਨ ਜਾਏਂ । ਕਿਸੀ ਕੇ ਲਿਯੇ ਏਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਸ਼ੋਆ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ । ਇਸ ਤਰਫ ਸੇ ਕਿਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਮਨੇ ਬੈਠਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੀ ਭਾਈ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜੋ ਉਨ ਕੇ ਪਰਸਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਂ । ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਸਾਮਲੇ ਮੇਂ ਅਗਰ ਯਹ ਚਾਹੇਂ ਤੋ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਹਾਂ ਪਰ ਏਕ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਂ ਤਾਕਿ ਕਿਸੀ ਤਰਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਯਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ।

**ਐਕਸਾਇਜ਼ ਪਰਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅਲਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੇਂਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਰਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ..... (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਆਪ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪਾਸ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ..... (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ..... (ਵਿਘਨ) ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁਬ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹਾਂ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਤਅਲਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿਚ ਦਸਾਂਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਾਂਗਾ । ਲੇਬਰਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ । **First I am labourer then anything else.** (ਗਲਿਯਾਂ )

**ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੈਬੀਨਟ ਵਿਚ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਗਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਭਾਏਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਇਧਰ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੇਚਿਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ।

With all the emphasis at my command I would like to give an assurance to the House that it is the policy of the Government meaning thereby the Ministry which will prevail and not the policy dictated by the Secretaries.

**ਡਾ॰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲ ਏਕ ਏਡਜਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਂ ਕਾਲਿਜ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੀ, ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਲਾਈ ਥੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਾਲ ਆਫ ਕਰ ਦੇਂ ਤੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਜੈਸਟ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ, ਮੈਂ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੁੰਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿਦਫ਼ਾ ਕਰ ਲੇਨੇ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਰ ਲਿਖਕਰ ਭੀ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਉਨ੍ਹੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿਦਫ਼ਾ ਕਰ ਲੀ ਹੈ ਉਸੀ ਟਰਹ ਸੇ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਇਨਕਵਾਧਰੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਏਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਲਾ ਦੇਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂ ਕਲ ਕਹਾ ਥਾ ਤੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਗਾ।

**ਸਿਖਾ ਮੰਤਰੀ :** ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਡਾ॰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਏਕ ਚਿਟ੍ਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਬਤਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਪਸ ਲੇ ਲੀ ਹੈ। ਧਹ ਸੁਬਹ ਮੁਝੇ ਮਿਲੇ ਥੇ। ਮੈਂ ਨੇ ਉਸੀ ਵਕਤ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹੋਂ ਅਨਕਨਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਾਪਸ ਲੇ ਲੀ ਹੈ ਅਰ ਹਾਲਤ ਨਾਮਲ ਹੈ ਤੋ ਫੈਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਵਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕਰ ਧਾ ਜਿਸ ਕੋ ਵਹ ਸਾਥ ਲੇ ਜਾਨਾ ਜਾਹੇਂ ਲੇ ਜਾ ਕਰ ਜੋ 2 ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਿਸਿਪਲ ਕੋ ਹੈਂ, ਸਟਾਫ ਕੋ ਹੈਂ ਧਾ ਜੋ ਅਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਧਤੋਂ ਹੈਂ ਉਨ ਸਬ ਕਾ ਜਾਧਯਾ ਲੇਂ ਅਰ ਜੋ ਹਲ ਵਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਕੋ ਮਾਨ ਲੇਗੀ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨਿਹੋਤ੍ਰੀ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਲੁਕੀ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗਏ ਥੇ ਅਰ ਸਬ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਜ਼ ਸੇ ਮਿਲੇ ਥੇ। ਉਨ੍ਹੋਂ ਵਯੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਏਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਂਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ ਕੋ ਆਧੰਦਾ ਹੈਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜਾਧਗਾ।  
**ਸਿਖਾ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੌਯੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕਰੁੰ। ਮੈਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਯੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬਤਾਏਂ ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਸੇ ਇਨਕਵਾਧਰੀ ਕਰਵਾ ਲੇਤੇ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹੋਂ ਕਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਸਿਪਲ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਧਯ ਸ਼ਿਕਾਧਤ ਥੀ ਅਰ ਉਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਨਾ ਚਾਹਿਏ ਤੋ ਉਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਧਗਾ ਅਰ ਅਗਰ ਧਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੋਂ ਕਾ ਕਸੂਰ ਥਾ ਅਰ ਉਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੋ ਉਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਏਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਧਗਾ।

I will accept in toto the report of the Enquiry Commission.

**Dr. Baldev Parkash:** In all fairness if anybody is found guilty he should be properly punished. But....

**Mr. Speaker:** It would be better if the hon. Member settles the matter after meeting the Education Minister.

**ਡਾ० ਕਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ :** ਹੁਸ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋ ਆਰ ਨ ਸਟਾਫ ਕੋ ਅਨਡਿਯੂ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਨੀ ਚਾਹਿਏ ।

**ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ । ਮੈਂ ਅਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਆਰ ਫ਼ਿਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਹੋਗੀ । ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਹੋਗਾ ਆਰ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ਿਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਜ਼ੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੇਗੀ । ਕਿਸੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਸੀਕਾ ਪਰ ਕਿਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇ ਅਨਡਿਯੂ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਸੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ਲ ਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੈਬੀਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ **within a week** ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ । ਅਜ ਉਸ ਗਲ ਨੂੰ ਅਠ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ।

#### ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

**Mr. Speaker:** I have to inform the House that an article published in the "Lalkar" Dharmasala dated the 5th January, 1966, under the caption "Kangra ke Baz Memberan Assembly par Lakhon Rupae Banare Ka Sansane Khez Ilzam" was recently brought to my notice. I have, after obtaining the views of the Press Gallery Committee, referred the matter to the Committee of Privileges for examination and Report under rule 285 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, as the said article appears to cast aspersions on the conduct of Members of this House representing Kangra District. The report is to be made within three months.

#### Adjournment Motions/Call Attention Notices (Resumption)

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ; ਇਹ ਦਸਣ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਡੀਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

**Mr. Speaker :** The hon. Member should please resume his seat. It is not for me to reply.

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੀ, ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਰਲਾ ਡੀਡ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ .....

**Mr. Speaker :** The hon. member should not please worry about it. It will be treated as an assurance.

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

**Mr. Speaker :** The hon. Member has had his say. It is for the Government to reply.

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਥੇ ਲਗ ਗਏ । ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਜ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਜ ਹੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਨ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।

### Supplementary Estimates (Second Instalment) 1965-66

**Minister for Finance, (Sardar Kapcor Singh):** Mr. Speaker, Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1965-66. This is an additional estimate of expenditure during the current year.

### Presentation of the Report of the Estimate Committees on Supplementary Estimates

**Sardar Bawlant Singh :** (Chairman, Estimates Committee): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1965-66.

### Bills

### The Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 1965

**Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Capt. Rattan Singh):** Sir, I beg to move —

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, as reported by the Regional Committees, be taken into consideration.

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ । (Addressing the Minister of State Captain Rattan Singh: I think a convention may be established, as it would be very proper that when a bill is moved for being taken into consideration, the aims and objects of the measure are explained to the members of the House.)

**ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ਵ ਬਿਲ ਮੈਂ ਇਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ

ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਫੀਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੁਣਾਉ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਨਟਰ-ਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਹਦੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਇਸ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

**Mr. Speaker :** Motion moved —

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill as reported by the Regional Committees, be taken into consideration,

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ** (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਕ ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ., ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨੇ ਵਖਰਾ ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਬਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਕਟ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਫੀਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਪੁਆਵਾਇੰਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਐਕਸ ਆਫੀਸੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਲਾਕਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ

**[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]**

ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸ ਆਫੀਸੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਫੀਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਮਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਣ। (**Deputy Speaker in the Chair**) ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

**ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਏਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸ਼ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਪਹੈਜਰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਡਾਈਸੈਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਏਥੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ :

We do not agree with the present amendment in the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 1965, in principle. We will oppose it in the Vidhan Sabha apart from other grounds, on the ground that nominated members should have no right of vote on any matter"

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਇਹ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਤਾਂ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਆਫੀਸੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ

ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਅਸੋਸੀਏਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡੀਊਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ਅਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਇੰਟਰੈਸਟਿਡ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਟੀ ਪਲੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਟੀ ਪਲੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਇਕ ਨਾਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਧੁਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਕਾਨਸਟੀਚੀਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਉਹ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਡੀ. ਓ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਜਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

**Minister for Transport and Elections:** Madam, I have to make a humble submission that whether there is any note of dissent or not and whether it is the Regional Committee Stage or the Vidhan Sabha stage, the scope of this Bill is very limited i.e. whether the official members should or should not have the right of vote. If it were a general amendment of the Principal Act, then anything could be said and this suggestion of my hon. Friend opposite could have been within the scope of the Bill, but not in the case of the present Bill where the scope is very limited.

**उपाध्यक्ष :** अब 11-30 बजे बिज़ीनेस एंडवाइज़री कमेटी की मीटिंग है। मैंनेल आफ चेंबरमैन में से कोई मैम्बर हाज़िर नहीं है अगर आप इजाज़त दें तो डाक्टर बाल कृष्ण को सभा की कार्रवाई चलाने के लिये कह दिया जाये। (The Business Advisory Committee is scheduled to meet

[उपाध्यक्षा]

at 11-30 a. m. Since out of the Panel of Chairmen, none is present now, and I want to go out, Dr. Bal Krishan may be determined by the Assembly to occupy the Chair in my absence, to conduct the proceedings of the House.)

**परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री :** मिनिस्टर्ज को एक ही वक्त में बहुत सारे काम अटेंड करने पड़ते हैं आप इधर कहती हैं कि मिनिस्टर्ज हाज़र नहीं रहते अब तीन चार कमे-टियां हो रही हैं आप कहती हैं इधर हाज़र हों, बिज़ीनेस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग है, एक कमेटी गवर्नर साहिब ने बुलाई है और भी कई हैं। चेंबर को चाहिये कि सारी बातों का ध्यान रखे।

**उपाध्यक्षा :** जिन हालात के अंदर मुझे जाना पड़ा है मैं ने बता दिया है। यह भी ठीक है एक ही वक्त इतनी मीटिंगज़ नहीं होना चाहिये। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो मैं नहीं जाती। (I have informed the House of the circumstances under which I have to leave the House. This is also right that so many meetings should not be held simultaneously. I would not go, if they think that my absence from the House is not proper.)

**बाबू बचन सिंह :** डिप्टी सपीकर साहिब, मैं यह अरज़ कर रहा हूँ कि इस गैरमैट ने अफसरों को नू कौंसल दी इलैक्शन विच वोट देना का हक दे के एक ऐसा कम कौता है जिस नाल डेमोक्रेसी की जिन्नी मिटी पलीद यह कर सकदे सन उर करन की कौंसल कीती है। अज इस ऐक्ट विच यह उरमीम लियाउठ लगे हन। रिजनल कमेटी विच सरदार दरबार सिंह इस बिल नू पासीलाट कर रहे सन। असीं उनुं की खिदमत विच अरज़ कीती हूँ कि आफीसल मैम्बरों नू राਈट आफ वोट ना दिओ तं यह परेगरेसिव मेज़र होवेगा। (इस समे डाक्टर बाल क्रिश्न चेअर ते आये) उसीं जिहड़ा यह हैपेजुसड अते हाव गारंटीड मेज़र लियांदा है कि इलैक्शन विच तं उनुं तें राਈट लै लओगे लेकिन डे टू डे कमों विच वोट करन का हक दिओगे यह डेमोक्रेटिक सेट अप के उलट है। लेकिन मैनुअल अफसेस है, कि जिस उरुं अज एके मुजाहिरा हो रहा है बिलकुल ऐसे उरुं रोज मुजाहरे हो रहे हन। यह मनिस्टर बिलकुल इनकंपीटेंट हन।

**ट्रांसपेरेंट अते चेन मंत्री :** बाबू जी, यह सेंटेंस हर वेले ला दिंदे हन, यह ठीक नहीं, यह बेमौका है।

**बाबू बचन सिंह :** मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक है। सैक्रेटरीटरीट वलें जो सलिप आ जांदा है जं यह कहें कि जिहड़ा पिछे हुकम उनुं नू आउंदा है यह तं हिज मास्टरज वआइस साबत हुंदे हन, होर कुछ नहीं। सवाल यह है कि अगर उनुं नू इलैक्शन विच गिंसा लैट तें महिगुम करन है, अगर यह चेअरमैन जं वआइस चेअरमैन खड़े नहीं हो सकदे, जिस उरुं ऐक्स आफीसिओ मैम्बरों नू राਈट आफ वोट नहीं तं मारकिट कमेटीओं विच राਈट आफ वोट किउं दिता जाये। मैनु

ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਸ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਪਰੈਜ਼ਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*[At this stage Dr. Bal Krishan, a member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair.]*

**Transport and Elections Minister :** I would request you, Mr. Chairman to ask the hon. Member to confine himself to the matter under discussion. How is Improvement Trust concerned with it ?

Babooji, I have all respect for you but I have the right to invite the attention of the Chair to it.

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਪੀਟੇਂਸੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕ ਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਹੈ।

**Transport and Elections Minister :** I would again request you to ask the hon. Member to be relevant.

**Mr. Chairman :** I would request the hon. Member to be relevant. Rule 132 of the Assembly Rules is absolutely clear on the point. If the hon. Member likes, I can read it out.

**Transport and Elections Minister :** He knows it well.

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਮਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਥ੍ਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਬਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।

**ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਟਰੀ :** ਜਬਰਨ ਥ੍ਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਇਹ ਨਾ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਗਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਿਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਥੇ ਐਨੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਸੁਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬੇਅਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਕਲ ਬੇਅਕਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਫੈਦ ਰੀਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਅਕਲ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਨਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਅਸੀਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ.....

**ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ :** ਬਾਬੂ ਜੀ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਦਸੋ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਸੋ।

(Addressing Babu Bachan Singh—the hon. member should not state the duties of the House, he should state only relevant points.)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੰਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਪ ਹੈਜ਼ਰਡ ਹੈ, ਹਾਫ ਹਾਰਟਿਡ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

**ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਛਾ ਨਾ ਚਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। It is not a decision of this Government. It is here since long.

**Mr. Chairman :** It is a make shift arrangement so to say.

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੈਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਫੈਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੇਰ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਭਜ ਨਠ ਛਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ, ਏਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ : ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਕਰ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਰਾਏ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਇਜ਼ਤ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਧ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ :** ਬਾਬੂ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਹਨ, ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਹਾਂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਥੈਲੇ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਥੈਲਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। **He is to serve and not to dominate.** ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਪਜ਼ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗੜਨ ਦਿਉ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਰਹੇਗਾ।

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕੰਪਰੋਮਿਸਵ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਟਨ ਬਿਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਔਰ ਉਤਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ (ਕਰਨਾਲ) :** ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਈ ਗਈ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

“This provision has often been criticised on the ground that the official members get involved in party politics in connection with the elections of Chairman and Vice-Chairman.”

ਤੋ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕੁਝ ਰਾਹੋਰਾਸਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਈਸ਼ੂ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1965 ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਰਾਜ਼ ਲਈ ਉਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗਜ਼ਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਉਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਅਗਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਰਮ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਮੈਜਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਰਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 19 ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 11 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਟਕਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਪਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਤਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਗਰਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ—

ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁਰਪਟ ਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਵਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੌਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੈਰੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ, 1965 ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਐਲ. ਆਰ. ਦੀ ਉਪੀਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਐਲ. ਆਰ. ਦੀ ਉਪੀਨੀਅਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਲ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

[ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ. ਆਰ. ਦੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਜ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਨਡੇਮੋਕਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਲ. ਆਰ. ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਨਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਰਾਇਪੁਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੇਟ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਅਧੂਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫੀਸਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਇਹ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਫੀਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਪਰਤਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਬਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰ ਆਲ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹਕ ਤੋਂ ਡਿਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਦਫਾ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੱਚ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਵਾਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਹੱਫਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ 'ਰਿਜਨ' ਵਿਚ ਜੋ ਐਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਲਰਜ਼

ਨੂੰ ਜੋ ਅਖਤਿਆਰ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐਸੀ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਲੈਕਟੇਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਗਜ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਰੇਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 12-00 noon ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਭੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਰਿਜਨ ਲਈ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

### ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਰੀਟੇਰਿਏਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਗਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੂਰਦ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਇਨਟਰੈਸਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਿਲ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਸਰ। ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) :** ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਨਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਟਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਪਜ਼ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਿਲ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਭੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ to suggest improvement in the functioning of the Agricultural Marketing Committees. ਉਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਰਾ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਮੈਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਵਾਜ਼ਿਬ ਅਤੇ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ

ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਮੀਡੀਏਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਭੀ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਭੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵੱਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਭੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਬਿਲ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲ ਜ਼ੋਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 28 ਸੂਜ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਕ ਕੰਪਰੀਹੈਨਸਿਵ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਲੀਗੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੰਡ ਦਾ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਰੁਪਿਆ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ

## [ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਖਰਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਲੀਫ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 60, 70 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਨੂੰ ਦਿਤਾ। 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਨੂੰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰੁਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਕਲਵਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕਲਵਰਟਸ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਬਲੀਗੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਿਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਉ। 15 ਵਿਚੋਂ 11 ਨਾਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੁਲ ਫਲੈਜ਼ਡ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਤਾਂ ਸਕੀਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:—

**The State Marketing Board should be abolished and in its place Directorate of Marketing should be established as a Government Department.**

ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਰਮ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਿਲ ਲਿਆਉ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਡਰਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਹੀ ਨਾਮਨਾ ਖਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਆਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੀਏ।

**ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ** (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਐਸ. ਸੀ.): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ

ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਲਿਆਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਈ ਜਾਣੀ ਚੀਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਲਜ਼ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਤੇਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਬੀ. ਡੀ. ਉ. ਅਤੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਡਾਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। **Half-hearted amendment** ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ **rush through** ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਪਰ ਅਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੇਲੇਵੈਂਟ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਗੁੱਜ਼ਰਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ। ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਐਨਾ ਕੰਪ੍ਰੀ ਹੈਂਨੇਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੋ . . . . (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ . . . . . ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਐਜ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਝਮੇਲਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

**Mr. Chairman :** (Dr. Bal Krishan) : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, as reported by the Regional Committee be taken into consideration.

*The motion was carried*

**Mr. Chairman :** Now the House will take up the Bill, clause by clause.

#### Clause 2

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਪਛਮ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਹਾਫ ਹਾਰਟਿਡ ਮੋਈਅਰ” ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਬਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲ ਰੀਮੈਂਬਰੈਂਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ, ਇਕ ਇਕ ਦਾ ਮੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਇਕ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਲੀਗਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਐਲ. ਆਰ. ਹੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲ. ਆਰ. ਹੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਅਹਿਮ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਸੈਮੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟ ਅਪ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੜਕ, ਕੋਈ ਕਲਵਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਡਾਇਰਕਟਲੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਫੈਂਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਉਤੇ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ

ਨੇ ਫੰਡ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡੀਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ, ਇਕ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਸ ਦਸ, ਵੀਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ, ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ 1962 ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਹਾਫ਼ਾਰਟਡ ਜਿਹਾ ਮੋਈਅਰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡੀਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੋਚੇਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮਨ੍ਹੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ** (ਧੂਰੀ—ਐਸ. ਸੀ.): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਟ ਆਫ ਡਿਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੋਚੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਐਸੋਚੇਸ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਐਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਵਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲ ਇਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਜ਼, ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼., ਬੀ. ਡੀ. ਓਜ਼, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਹਨ। ਗਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫੰਡਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ

## [ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ]

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵੇਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਜ਼ ਹੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੋ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਫੰਡਜ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਚੀਂਗੜਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫੰਡ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਦੇਣਾ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ।

**ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ** (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਐਸੋਰੇਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ .....

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਸੋਰੇਂਸਿਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

**ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਐਸੋਰੇਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਸੋਰੇਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਈ (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਐਸੋਰੇਂਸ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗਾ।

*[Shri Ram Saran Chand Mital, a member of the panel of Chairmen in the Chair]*

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਝੇ ਨਿਹਾਯਤ ਅਫਸੋਸ ਸੇ ਕਹਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ ਕੇ ਲਿਯੇ ਸੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਕੜੀ ਝੜਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ ਸੇ ਮੈਂ ਤਸਮੀਦ ਕਰਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਤ ਕੀ ਤੁਨ੍ਹੋਂਨੇ ਐਸੋਰੇਂਸ ਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਏਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਤਸਕੇ ਬਾ ਅਗਰ ਕੁਝੀ ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਧਹ ਨਹੀਂ ਕਹ ਸਕਤੇ ਕਿ ਧਹ ਬਾਤ ਫੁੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਲਾ ਕਿਲਧਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਨ੍ਹੋਂਨੇ ਤਸ ਕੋ ਪਹਲੇ ਸਾਨਾ ਐਸੋਰੇਂਸ ਆਈ ਕਿ ਹਸ ਤਸ ਕੋ ਸਾਨਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਤੈਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਨ ਫੁੜੀ ਤੋ ਕਹਾ ਕਿ ਹਸ ਖੁਦ ਲੇ ਕਰ ਆਏਂਗੇ। ਧਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਫੇਰ ਹੋਨੇ ਕਾ ਧਹ ਸਤਲਬ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਹ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਏ ਰੂਭ ਬਨੇ ਏ। ਤਸ ਸਾਮਲੇ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ਼ ਕਾ ਸਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਨਾ ਚਾਹਿਏ। ਅਗਰ ਏਕ ਬਾਤ ਆਪੋਭੀਸ਼ਨ ਕੇ ਬੈਂਚੋਂ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਧਹ ਖਰਾਬ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਧਹੀ ਜਬ ਤਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਧਹ ਅਚਠੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤਸ ਤਰਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਸੁਲਝੇ ਫੁਏ ਆਦਮੀ ਸੇ ਤਸਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਤੀ ਆ। (ਵਿਘਨ) ਅਗਰ ਤਸ ਕੋ ਆਪ ਧੋਖਾ ਕਹਤੇ ਹੈਂ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਾਫਗੋਏ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈਂ। ਤਸ ਲਿਯੇ ਸੇਰੀ ਤਨ ਸੇ ਸੁਅਫ਼ਬਾਨਾ ਫਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਧਹ ਤਸ ਬਾਤ ਕੀ ਐਸੋਰੇਂਸ ਤਸ ਤੀਸਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੇ ਕਕਤ ਦੇਂ ਕਿ ਤਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇ ਫੀਰਾਨ ਤਸ ਬਿਲ ਮੇਂ ਜੋ ਆਫਿਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋ ਔਰ ਕਾਮੀਂ ਕੀ ਤਰਹ ਸੇ ਤਸ ਮੇਂ ਆੀ ਕੋਟਿੰਗ ਰਾਇਟਸ ਸੇ ਡਿਪਰਾਇਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸੁਤਅਲਿਕ ਜੋ ਕਮੀ ਰਹ ਗਈ ਹੈ ਤਸ ਕੋ ਫੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਤਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਪਾਸ ਕਰੇਂਗੇ।

THE PUNJAB SUGARCANE (REGULATION OF PURCHASE AND (8)69  
SUPPLY) AMENDMENT, BILL

Mr. Chairman (Shri Ram Saran Chand Mital) : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

*The motion was carried*

CLAUSE 1

Mr. Chairman : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried*

TITLE

Mr. Chairman : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried*

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Capt. Rattan Singh) : Sir, I beg to move —

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill as reported by the Regional Committees, be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, as reported by the Regional Committees, be passed.

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab Agricultural produce Markets (Amendment) Bill, as reported by the Regional Committees, be passed.

*The motion was carried.*

The Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply ) Amendment  
\*Bill, 1965 (Resumption)

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and supply) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। उस वक्त वह बिल विदड़ा हो गया था, अब तो नए सिरे से पेश होगा।

श्री सभापति : यह गलत ख्याल है; वह पोस्टपोन किया गया था, इट वाज़ डैफर्ड।  
(This is not correct. The Bill was postponed. It was deferred.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मेरी दरखास्त है कि आप असेम्बली प्रोसीडिंग्स से बैरोफाई कर लें। इन्होंने कहा था कि इसे फार दी टाईम बीइंग विदड़ा करता हूं और री-कनसिडर कर के हाउस में पेश करूंगा।

\*Note : — The Bill was introduced on 2nd November, 1965

**श्री सभापति :** उस दिन मैं हाउस में मौजूद था और गालबन चेयर में था। मगर हाउस में ज़रूर था। इस की पहली डिसकशन हो चुकी है। इट वाज़ डैफ़र्ड। अब उस के आगे कार्यवाही चलेगी। (On that day I was present in the House and probably I was in the Chair. Anyhow, I was definitely present in the House. A full dressed discussion has already taken place on the Consideration Motion. The Bill was then deferred. Now the House would proceed with next stage of the Bill.)

**श्री बलरामजी दास टंडन :** बहस तो होने दें।

**श्री सभापति :** उस दिन सरदार दरबारा सिंह जी ने आते ही कहा था कि मैं इस को डैफ़र करने के लिये तैयार हूँ। गालबन उस दिन मैं चेयर में था; ऐनीवे, आई वाज़ इन दी हाउस। अब डिसकशन तो हो चुकी है.....

(When the Minister for Home and Development, Sardar Darbara Singh attended the House the other day he readily expressed his willingness to defer the Bill. Most probably I was in the Chair on that day. Anyway, I was present in the House. Now when the discussion has already taken place....)

**श्री बलरामजी दास टंडन :** डिसकशन कन्टीन्यू करेगी।

**ਕਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। (ਵਿਘਨ)

**श्री सभापति :** डिस्कशन हो गई है, सरदार दरबारा सिंह ने जवाब दे दिया है। (The discussion has taken place and Sardar Darbara Singh has replied to the debate.)

**Comrade Gurbax Singh Dhaliwal :** It was at the first reading stage.

**कामरेड राम प्यारा :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। उस वक्त सरदार दरबारा सिंह जी इस बिल पर बोल रहे थे, उन्होंने ने इस को डैफ़र किया था। उन्होंने ऐशोरेंस दी थी कि इस को कनसिडर करके लाएंगे। तो जब तक होम मिनिस्टर, ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर अपनी पोजीशन क्लीयर न कर कि उन्होंने क्या सोचा और उन की क्या राय है तब तक इस बिल को आगे चलना ही नहीं चाहिए। इस पर आप की रुलिंग चाहता हूँ।

**श्री सभापति :** हमारे हाउस की यह प्रैक्टिस रही है कि हमारी जो रोजाना की प्रोसीडिंज़ होती हैं इन का रोजाना एक बुलेटिन निकलता है। हर एक आनरेबल मैम्बर को उस की कापी जाती है। यह जो बुलेटिन है इस का नम्बर 14 है और इस की तारीख दो नवम्बर है।

है। उसमें चौथा आइटम है लैजिसलेटिव बिज़नेस जो इस तरह है : (This is a practice with our House that a daily bulletin giving the brief record of the proceedings is issued and a copy thereof is made available to every Member. The item No. 4 relating to the Legislative Business, in the bulletin No. 14 dated the 2nd November, 1965, indicates as follows—

#### IV LEGISLATIVE BUSINESS

##### The Punjab Sugarcane (Resolution of Purchase and Supply) Amendment Bill, 1966

“The Home Minister who was in possession of the house when it adjourned on the 1st November, 1965 resuming his speech on the motion that the Punjab Sugarcane (Regulation of purchase and Supply) Amendment Bill be taken into consideration at once spoke for 15 minutes. Further discussion on the Bill was deferred.”

(विघ्न)

श्री सभापति : आप देखें इस पर तकरीबन 17 मੈम्बर बोल चुके हैं और सरदार दरबारा सिंह जी ने इस का जवाब भी दिया था और अगले दिन भी चलना था। मगर नैक्स्ट डे उन्होंने ने कहा कि इसे डैफर कर रहा हूँ। (The hon. Members would see that no less than 17 Members spoke on the Bill. Sardar Darbara Singh replied to the debate also and the discussion was to continue the next day. But on the next day he announced that he would defer its further consideration). (Interruptions)

बाबू बचन सिंह : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि इस दिन पदरा बोलने वाले मੈम्बरों ने विद्वानों और अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया। इस बिल की प्रमुखता की बातों पर उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि इस बिल की प्रमुखता की बातों पर बोलने का मौका दिया जाय। (The hon. Members would see that no less than 17 Members spoke on the Bill. Sardar Darbara Singh replied to the debate also and the discussion was to continue the next day. But on the next day he announced that he would defer its further consideration). (Interruptions)

श्री सभापति : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि इस दिन पदरा बोलने वाले मੈम्बरों ने विद्वानों और अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया। इस बिल की प्रमुखता की बातों पर उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि इस बिल की प्रमुखता की बातों पर बोलने का मौका दिया जाय। (The hon. Members would see that no less than 17 Members spoke on the Bill. Sardar Darbara Singh replied to the debate also and the discussion was to continue the next day. But on the next day he announced that he would defer its further consideration). (Interruptions)

[ਜੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ]

Now, the hon. Minister is quite competent to come in the House and say or move that the Bill be taken into consideration.

**Comrade Bhan Singh Bhaura :** On what grounds ?

**Minister for Planning and Local Government :** Reasons he will give.

**ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ( ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰਨ ਚੰਦ ਸਿੱਤਲ ) :** ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਆਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਪਨੇ ਡਿਯਾਲਾਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੀਫ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ।  
(I am not yet giving my ruling on the point of order raised by Baboo Bachan Singh. If any other Member has to express his views on this matter, he may do so briefly so that I may be able to give my reply to all.)

**ਕਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ :—

“The amount involved for the year 1962—63 is Rs. 4.04, 550. The amount to be refunded for the year, 1963—64 and 1964—65 is not available.

ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਫਿਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਨਾਂਸਿਜ਼ ਇਨਵਾਲਿਡ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਕਨਕ੍ਰੀਟ ਗਲ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1963-64 ਅਤੇ 1964-65 ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਲਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 40 ਲਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਫਾਸ ਟੰਡਨ :** ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਅਪਨੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਆਖਿਰ ਮੌਕੇ ਕਹੇ ਸਨ ਆਰ ਜਿਨ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪਰ ਬਹਿਸ ਕੀ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂ ਕਿ ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਫਿਰ ਰਿਇਨਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

**Mr. Chairman (Shri Ram Saran Chand Mital) :** It has been observed by the hon. Member that the Bill has been reintroduced and if I, as now the Presiding Officer, admit that the Bill is reintroduced, complications will arise. So the position, as has been clearly stated in the agenda for today, is that discussion on this Bill was going on and the Minister concerned was giving a reply to the debate when at the last stage he requested the House to defer its consideration. Accordingly with the permission of the House, the consideration of the Bill was deferred. So now we are resuming that discussion and there is no question of reintroduction of the Bill.

Now the hon. Member from Ludhiana has observed that the Government should state reasons why it has been brought before the House when

its discussion was deferred. It is not obligatory on the part of the Government to make a statement. If they want to make a statement I do not come in their way. But if they do not want to do so, then I cannot compel them.

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸਟੰਡਨ : ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੀ ਖਾਂਡ ਦੀ ਏਕਸਪੋਰਟ ਫੁੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਫੁੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੂਫੇਕਚਰਜ਼ ਏਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਤ ਆਰ ਆਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਖਾਂਡ ਧਰਮ ਪਰ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗਈ ਵਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਲੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਆਰ ਜਿਤਨੀ ਏਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗਈ ਵਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਲੋਂ ਦੀ ਥੀ ਧਰਮ ਬਾਤ ਕਲਿਧਰ ਹੋ ਜਾਨੀ ਚਾਹਿਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਨਦਾ। ਆਪ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨਲ ਬਾਤ ਆ ਜਾਏ ਆਰ ਆਗੇ ਕਾਸ ਨ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੋ। (This is no point of order. The hon. Member can raise a point of order where it involves a constitutional point and further proceedings cannot take place.)

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਪੋਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਪੋਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਇਨ ਲਿਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਵੀ ਹੈ।

(Mr. Speaker in the Chair)

ਡਾਕਟਰ ਕਲਕੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਧਰਮ ਜੋ ਬਿਲ ਆਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਹੈ ਏਕ ਸਨੀ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਰੁਪਯਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਪਭੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈ ਕਿਆ ਥਾ। ਜੋ ਰੁਪਯਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇਨਵਾਲਿਡ ਹੈ The amount involved for the year 1962-63 is Rs 4,04,550. The amount to be refunded for the year 1963-64 and 1964-65 is not available.

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

जब तक एमंडमेंट का पता ही न हो कि 5 करोड़ है या 10 करोड़ है या सारा बजट ही पंजाब का जाने वाला है Unless we get the exact amount involved.....

**Mr. Speaker :** That is a question regarding merits of the Bill.

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** ठीक है, मगर यह तो एक फाईनैन्शियल बिल है, हमें पता ही नहीं कितना रुपया है। हम कैसे अपनी सहमती आप को दे दें।

**Mr. Speaker :** On this basis, it is for the hon. Members to vote it out or pass it

**डाक्टर बलदेव प्रकाश :** मैं स्पीकर साहिब, सब से पहले आप की इजाजत चाहता हूँ कि क्या इस तरह का इनकम्प्लीट बिल इस तरह से आना चाहिए। It is not in the proper form. It is not in proper shape. It should not, therefore, be allowed.

**Planning and Local Government Minister :** What I remember is the Government is going to take power under this Bill to refund, prospectively, as well as retrospectively the tax imposed on, and paid by, such factories under section 17 of the parent Act in respect of the cane purchased by them and utilized in manufacturing such quantities of sugar as are exported out of India. The money involved does not form part of the Bill. It is only a short Bill whereby the Government is taking power to refund the tax imposed on cane utilised for manufacturing sugar exported out of India after satisfying itself that the requisite quantity of sugar thus manufactured has been exported out of India. It does not suffer from any defect.

**Minister of State of Animal Husbandry and Agriculture :** Sir, this Bill was introduced during the last session. Today, only discussion thereon is being resumed. अब भी अगर देखा जाये जो खांडू हम ने एक्सपोर्ट की है उस पर जो सैस ली जानी थी उतनी ही वापिस करनी है और कोई ज्यादा सैस वापिस नहीं होगा।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** No direct talks please. ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲ ਪਰਾਪਰ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਪਲੇਨੇਟਰੀ ਫਾਈਨੈਨਸ਼ਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ . . .

(No direct talks please. The first thing is that as already stated by Captain Rattan Singh, this Bill is in the proper form. As to whether this Bill can be introduced or not, I think, if at all there was any objection, it could be raised at the introduction stage. As to the other thing that it

it should have been accompanied by a recommendation of the Governor as also the Explanatory financial Memorandum, I consider that . . . .)

**Dr. Baldev Prakash :** Incomplete memorandum.

**Mr. Speaker :** Technically, on this basis it cannot be thrown out. It is under discussion now. But in view of the points made out by certain hon. Members, it is for the Government to consider or, consider it.

ਪ੍ਰਸੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ Under this Bill the Government is taking power to refund prospectively or retrospectively tax on cane utilised for manufacturing sugar exported out of India after satisfying itself that the requisite quantity of sugar thus manufactured has been exported out of India.

ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਖੰਡ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 990 ਰੁਪਏ ਟਨ ਦੇ ਭਾਉ ਦੀ ਏਧਰ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਟਨ ਦੇ ਭਾਉ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

(At this stage Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal rose to speak).

**Mr. Speaker :** I am sorry. There has been protracted discussion. Moreover, the Minister has also replied to the discussion.

**Comrade Shamsheer Singh Josh :** He was explaining the circumstances under which the refund can be made...

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋਸ਼ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, 15—16 ਮੈਂਬਰਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। It is for the Government to decide whether to consider, reconsider or defer it. (The Hon. Member Comrade Josh perhaps does not recollect that discussion has already taken place on this Bill and 15 or 16 Members have also spoken on it. The reply to the discussion had also come from Sardar Darbara Singh. The discussion was, therefore closed as nothing more was left to be said on it. So it is for the Government to decide whether to consider, reconsider or defer it).

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ.....

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।

(This is correct that the hon. Minister had previously agreed to defer it.)

Now the Government has again come back after its consideration or reconsideration of the Bill. It is for it to consider, reconsider or defer it or whatever it is.

**Transport and Elections Minister :** We want to pass it today. Already it has been delayed.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of purchase and Supply) Amendment Bill be taken into consideration at once.

(After ascertaining the votes of the Members by voices Mr. Speaker said "I think Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for "Ayes" and those who were for "Noes" respectively to rise in their places and on a count having been taken, declared that the motion was carried.)

*The Motion was carried.*

**Mr. Speaker :** Now the House will consider the Bill clause by clause.

ਕਲਾਜ਼ ੨

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਖੰਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੈਸ ਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1953 ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 1953 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੇਨਗਰੋਅਰਜ਼, ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ।

1.00 p.m

**THE PUNJAB SUGARCANE (REGULATION OF PURCHASE AND (8)77  
SUPPLY) AMENDMENT, BILL**

**Statement of objects and Reasons of the Parent Act passed in 1953.**

“With the promulgation of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 with effect from the 8th May, 1952 the Regulation of Sugar Industry has become conclusively a central subject. The State Government are now only concerned with the supply of sugarcane to Sugar Factories. Moreover in view of the financial position of the State, the State Government are not in a position to provide adequate funds for extensive cane development work in the areas supplying cane to Sugar Factories, with the result that the factories are not getting cane of good quality. The Bill is being introduced in order to provide for a rational distribution of sugarcane to factories, for its development on organised scientific lines making adequate funds available after imposing a tax on sugarcane purchased by sugar Factories to protect the interest of the cane growers and of the Industry and to put the new Act permanently on the Statute Book”.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਲ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 1962 ਵਿਚ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸ਼ੁਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1962-63 ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1962-63 ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4,04,550 ਰੁਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1963-64, 1964-65 ਅਤੇ 1965-66 ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1962-63 ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ 4 ਲਖ ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ, ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਜਗਤਜੀਤ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ? 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਲੀਅਤ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਚਾਰ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਖੰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰਕੋਨ ਸੈਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਖਾ ਅਤੇ ਧਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1962 ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫਗਵਾੜੇ ਅਤੇ ਜਗਾਧਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰਸ ਘਟ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਖੰਡ ਘਟ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰੰਹ ਘਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਮਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਵੀ ਬੋਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸੇ ਹੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਰੜਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਗੰਨਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਰਿਸੀਪਲ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ

ਦਫ਼ਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ ਗੰਨੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਪਰੋਚ ਰੋਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਲਈ ਔਰ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਫਿਸਿਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਗਰ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਇਨਹਿਸਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈਸ ਲਾਏ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਲਖ ਟਨ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਏਥੇ ਨਾ ਬੰਬਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਜੂਟ ਮਿਲਜ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਪਰਾਫੀਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਏਥੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਪਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਕਪਾਹ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਗੰਨਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਕਬਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪਸ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਲਈ ਪਰਾਫੀਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਪਰਾਫੀਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਸਾਰਾ ਨਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜ਼ੌਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਣ ਔਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਕ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਪ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ੌਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਔਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਉ। ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕ ਧੋਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਟ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੁੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੂਹ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਭਿਖ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਫੰਡਜ਼ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਮਰਕਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਭਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਨ ਗਰੀਬ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਮਪਰੇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਟੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੁਲਹਾੜਾ ਚਲਾਣ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਛਾਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਲਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੰਡ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਈਸਿਕਲ, ਕਪੜੇ ਸੀਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪਖੇ, ਜ਼ਿਊਟ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹ, ਜੁਤੀਆਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਧਾੜ ਚਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਲਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ, ਸੇਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਲਖ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੇ ਲਖ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ

ਸਮਝਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਲਗਾਏਗਾ ਉਸਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਤਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਕਹੋ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਫਿਰੇ ਫੋਸੀ ਫੋਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੁਟਾਵੇ ਹੀਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁਖੇ ਮਰੀਏ, ਨੰਗੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੈ ਕਿ 750 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਪੋਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਿਆਨਤ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੋ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹਮਦਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

**ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਅਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ.....

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਉ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਿਵਲੀ.....

**ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲਵੋਗੇ? (How much more time will the hon. Member Baboo Bachan Singh take?)

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਅਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਉ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਕ ਗਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰੈਸਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਐਸਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ ਤਾਂ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਉ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਗਟ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਲ ਵਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਸੂਤਾ ਹੈ.....

**ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਲਖਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿਛੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲੁਟ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੀ ਬਦਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

**Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) :** Sir, enough discussion has taken place. Therefore, I beg to move—

That the question be now put.

**Voices from the Opposition :** We have still to speak.

**Mr. Speaker :** Let one more hon. Member from the Opposition side speak. Sardar Gurcharan Singh, please.

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ— **That the question be now put.**

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੰਗਾਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਚਲਾ ਸਕਣ । ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਉ । ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਫੀ ਸਦੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6½ ਫੀ ਸਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1½ ਆਨਾ ਫੀ ਮਣ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1½ ਆਨਾ ਫੀ ਮਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਆਨੇ ਫੀ ਮਣ ਸੈੱਸ ਲਾਈ ਗਈ । ਉਹ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਕਸ ਜਾਂ ਸੈਂਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਢਿਡ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਘਟ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਕਰਾਪਸ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਕਰਾਪਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 300 ਜਾਂ 400 ਮਣ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਭੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਰੇਟਸ ਵੀ, ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਰਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। (ਘੰਟੀ) (ਵਿਘਨ) ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸੈਂਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੀ ਬਦਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 4, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਦੀ ਭੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਖੁਦ ਪੀੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਹੇਠ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤਾਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸੈਂਸ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.....

**Mr. Speaker :** The hon. Member should be relevant.

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਲੱਡਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸ਼ਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1964-65 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੈਂਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੈਂਸ. ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੜ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ **without stoppage** ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਸੜਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਮਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਲਾਂ 15, 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨਾ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਗੁੜ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਅੜਚਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਰੇਅਰਜ਼ ਦਾ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਹਿਬੂਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**Mr. Speaker :** Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

CLAUSE 1 AND TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Clause one and the Title stand part of the Bill.

*The motion was carried.*

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Captain Rattan Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of purchase and supply) Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of purchase and supply) Amendment bill be passed.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਐਂਟੀ-ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਐਂਟੀ-ਜੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ-ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਡੈਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ—15 ਸਪੀਕਰ ਇਧਰੋਂ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਜ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਈਲਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਬੋਲੇ ਹਨ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ ਫਿਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਪ ਚੁਪਾਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਮਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੈਂਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੰਨੇ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਜ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਡੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 10-11 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਢਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.....

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ? (The hon. Member has gone off the track.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਉ.....

**Mr. Speaker :** Will you please try to be relevant ?

**Sardar Ajaib Singh Sandhu :** I am relevant.

**Mr. Speaker :** Please do not side track.

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੈਸ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਉ.....(ਵਿਘਨ) ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਆਂਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਕਰ ਦਿਉ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ" ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਟ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਫੌਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਐਂਟੀ-ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਐਂਟੀ-ਪੀਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ.....

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : You cannot speak like this. ਇਸ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ..... (Interruptions)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। (He has a right to speak. Let Comrade Josh have his say.)

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। Let him speak. (No. He has the right to speak. Let him speak.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਪਣੀ ਉਸ ਐਜ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ the East Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Bill ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਐਜ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਐਜ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। This government is throwing to the winds assurances after assurances, given in this House. ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਜ਼ੋਰੈਂਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਸੰਨ 1953 ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ.....

“The amount so realised is to be spent for improving the quality of sugarcane in the State I may also assure the House that the money thus realised from the cess would be spent.....”

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਅਜ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ or the question be now put. ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : Question ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ I am on my legs.

Mr. Speaker : You have missed the bus. When the Member is on his legs you cannot put the question.

Chief Parliamentary Secretary : Then, Sir, the sitting of the Sabha be extended by half-an-hour.

Mr. Speaker : What is the sense of the House ?

Voices : No.

Voices : Yes.

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸਨ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਬਿਲ ਹੈ; ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਿਜ਼ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਔਰ ਬਾਡੀ ਉਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣ—ਪੰਜ, ਸਤ, ਦਸ, ਮਿੰਟ ਜਿਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੋਲ ਲੈਣ। ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਫੇਰ ਦੋਬਾਰਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ।

Mr. Speaker : The sitting of the Sabha is extended by half-an hour.

Comrade Shamsheer Singh Josh : Sir, I was quoting from the speech of the then Finance Minister, Sardar Ujjal Singh—

“.....that the money thus realised from the cess would be spent on the improvement of sugarcane production in the State and will not be treated and spent as general revenues of the State”.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਐਸੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਸ ਹੈ; ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ “ਸੂਗਰ ਕੇਨ ਸੈਸ” ਇਕੋ ਹੀ ਸੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਮਣ ਪੱਕਾ ਗੰਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1½ ਆਨਾ ਮਣ ਸੂਗਰ ਕੇਨ ਸੈਸ ਦਾ ਢਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੇਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮਕਸੂਦ ਸਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤਨੇ

ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਕ ਆਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ; ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਨ ਸੈਸ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਮਿਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਕੇਨ ਗਰੇਚਿੰਗ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਣ ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੇਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਗੰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਰਜਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਗੰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਕਿਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਕੀ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਗੰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰੀਕਵਰੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ—ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰੀਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ; ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਆਂਗੇ ਤਦ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਸੰਨ 1962-63 ਵਿਚ ਜਾਂ 1963-64 ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿਉਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਨਾ ਵੀ ਦਿਉ ਤਦ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿਉਗੇ ਤਦ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਡ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।

**ਇਕ ਆਵਾਜ਼ :** ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਜੇ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਉ। ਕੇਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿੱਤਾ? ਇਹੋ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਕੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ—ਕੇਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ—ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਰਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਿਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 'appointed area' ਵਿਚ 10/15 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਸਤੇ ਭਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਟਵਾ ਲਵੇ। ਟੱਕਾਂ ਤੇ ਲਦ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ

2—00 p.m.

ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਟ ਨੂੰ ਇਨਸੈਨਟਿਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਢੋਲ ਪਿਟ ਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਗਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਨਵਾਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ।

**Chief Parliamentary Secretary :** Sir, I beg to move—

That question be now put.

**Voices :** No. No.

**Comrade Ram Piara :** Sir, We have a right to speak on the Bill.

**ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ?  
(Addressing Sardar Gurdial Singh Dhillon : Now that the sitting has been extended for half an hour, I think, there is no harm if one or two hon. Members are allowed to speak.)

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਈਡਰ ਇੰਟੈਂਸਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਉਂਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟਸ ਵਿਚ ਫੁਟਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਬਸਾਈਡੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਮਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਪੁਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੇਅਰ-ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਸੂਗਰ ਦੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜ ਸਕਾਂਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਬਾ ਕੇਸ ਲਉ । ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਉਂਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਜ਼ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** On a point of information, Sir, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲ ਨੇ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ।

**ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ :** ਇਸ ਮੇਜਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ੇਅਰ-ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ (ਕਰਨਾਲ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬ-ਜੈਕ੍ਸ ਏਂਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਮੇਂ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਕਾਈਡਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰੈਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ” ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਕੇ ਲਿਯੇ ਦਿਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵਕਤ ਕੇ ਲਿਯੇ । ਅਗਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਯੇ ਕਿ ਆਗੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਝਾੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ । ਪਹਲੇ ਤੋਂ ਧਰ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁਏ ਵਕਤ ਕੇ ਲਿਯੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਨੇ ਚਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ।

[कामरेड राम प्यारा]

दूसरी बात यह कि इस बिल पर पहली और दूसरी नवम्बर, 1965 को बहस हुई थी। फिर मिनिस्टर साहिब ने इस को डैफर किया क्योंकि हरेक मੈम्बर ने चाहे वह ट्रेयरी बैचिज पर बैठने वाले था या आपोजीशन के बैचिज पर बैठने वाला था इस की मुखालफित की थी। सबसे बड़ी एतराजवाली बात यह थी कि सरकार ने यह नहीं बताया कि इससे ऐक्सचेंजर पर कितन बोझ पड़ने वाला है। वह सेशन 24 नवम्बर तक रहा। 22-23 दिन तक सरकार फैसला नहीं कर सकी कि बिल को लाना है या नहीं या फिगर्ज देनी हैं या नहीं। अब आज 25 फरवरी है। इस मामले में या तो सरकार फेल हुई है कि वह फिगर्ज की कुलैक्ट नहीं कर सकी या फिर जान बूझकर बताना नहीं चाहती। इस तरह से या तो सरकार इन ऐफीशेंट है या फिर डिसऑनैस्ट है। इस में चायस इस की अपनी है यह जिसे चाहे इन में से चुन ले हम उसी से एग्री कर जाएंगे। जब यह एक मनी बिल है और इसे हम ने पास करना है तो यह हमारा हक और सरकार की यह ड्यूटी है कि यह हमें बताए कि इस में कितना रुपया इनवाल्ड है। जब सरकार यह नहीं बताती तो शक की गुंजायश है कि दाल में कुछ काला 2 है।

फिर मिनी साहिब ने कहा कि यह रुपया सिर्फ पुरी और थापर को ही नहीं मिलना बल्कि यह कोआपरेटिव मिलों को भी मिलेगा। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन अगर यह ठीक हो और इन तीनों कोआपरेटिव मिलों को उन दोनों से दसवां हिस्सा भी मदद मिलनी हो तो मैं इन को स्पॉन्सर करने के लिये तैयार हूँ। दरअसल यह सरमायादारों को ही मदद देना चाहते हैं अब यह पता नहीं कि इस के लिये इन पर प्रेशर सेंटर का है या उन सरमायादारों का जिसे रजिस्ट्रार करने का हिम्मत इन में नहीं है। स्पीकर साहिब, हम सोशलिस्ट पैटर्न की कमिटिड हैं जिस का मतलब तो यह बनता है कि अमीर पर टैक्स लगाएंगे और गरीब को रिलीफ देंगे। मगर हो यह रहा है कि जो 60/70 रुपए कमाता है उस पर तो टैक्स लग रहे हैं और जो लाखों कमाते हैं उन को इस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है। फोर्थ क्लास के मुलाजमों की रिट्रैक्मेंट की जा रही है, उन का अगर पांच रुपए तनखाह बढ़ाई जाती है तो वह नेशनल सर्विंग सर्टीफिकेट की शक्ल में दी जाती। उस से यह नहीं पूछा जाता कि तुम्हें रोटी गेहूं की मिलती है या मक्की की या मिलती भी है कि नहीं। मगर करोड़पतियों को रिलीफ दे रहे हैं जिन के मुतअल्लिक न जाने कितनी कमेटियां बैठें जिन्होंने यह रिपोर्ट की कि यह लाखों का इनकमटैक्स इवैड करते हैं, ऐसे आदमियों को रिलीफ दे कर यह कमिटिड पालिसी के बिल्कुल उलट चल रहे हैं। इस लिये हम इस की मुखालफित करते हैं। सरकार वाजे तौर पर बताए कि इस में कितना रुपया खर्च होगा और उस से कैसे फायदा होगा। हम भी चाहते हैं कि चीनी की एक्सपोर्ट बड़े और हमारा मुल्क फारेन ऐक्सचेंज कमाए, हमें डलर और स्टर्लिंग मिलें। जहां पर यह बात आती है कि यह डिवलप करना चाहती है इस इंडस्ट्री को तो अगर यह समझा दें कि यह किस तरह जस्टीफाईड है यह बिल लाने में तो मेरी तसल्ली हो जाएगी।

पानीपत शूगर मिल के लिये दो लाख रुपया सड़क बनाने के लिये पड़ा है। अर्सा हो गया है लेकिन इस दो लाख रुपया को कोई खर्च नहीं करता। लेकिन यह जो रुपया आप मन्जूर कर रहे हैं इस को दो हफ्तों के अन्दर अन्दर ही ले लिया जाएगा क्योंकि इस में उनका अपना निजी फायदा होता है। पुरी साहिब को इस तरफ तो फायदा पहुंचाया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ उन के जिम्मे सैस का रुपया निकलता था और उस को कई साल तक वसूल

नहीं किया गया। और न ही कोई सूद उस रकम पर लिया गया। जब कोई तकावी मन्जूर की जाती है और उस को एक खास वक्त के अन्दर दाखिल न किया जाए तो उस पे पीनल इन्ट्रेस्ट वसूल किया जाता है लेकिन इस तरफ बड़ा सरमायादार है और लाखों रुपया की वसूली नहीं की गई और वह इस रुपए को इस्तेमाल करता रहा। गवर्नमेंट ने इस की वसूली के लिये कुछ नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट हक बजानब है उन से पीनल इन्ट्रेस्ट चार्ज करने में। हमारी हालत तो यह है कि हमने जितना रुपया फारेन कन्ट्री से कर्ज लिया है उसकी किश्त भी हम अदा नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसैट्स नहीं और न इतना रैवेन्यू है कि हम रुपया वापिस कर सकें और किश्त को अदा करने के लिये हमें और कर्ज लेना पड़ेगा। किश्त हमारे पास नहीं, स्टेट के रैवेन्यू की हालत आपके सामने है और जितना हमारा फिनांस का रिजर्व स्टॉक था वह हम खा चुके हैं और दूसरी तरफ हम लाखों रुपया चन्द सरमायदारों को खुश करने के लिये दिए जा रहे हैं और इस लिये कि वह आने वाले इलैक्शन में इनके काम आएंगे। पर इन्हें यह बात भी सामने रखनी चाहिए कि अगर चन्द इन्डीविजुअल्स काम आ भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

एक बात सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों ने कुआप्रेटिव शूगर मिलों के बारे में कही कि यह इन्डिविजुअल हैं या पब्लिक के आदमी हैं। मैं इन से अर्ज करूँ कि अगर ऐसी बात होती तो दो सरमायदारों की मिलें क्यों हर साल मुनाफा निकालती हैं और दूसरी तरफ कोआप्रेटिव मिलों को क्या हालत है। क्या यह बता सकते हैं कि इन कोआप्रेटिव मिलों ने हर साल कितना मुनाफा निकाला है। पानीपत वाली मिल ने कुछ मुनाफा निकाला था; वह गवर्नमेंट की बकिंग से नहीं बल्कि इस लिये कि उन्हें मशीनरी सस्ती मिल गई थी। फिर एक और बात है कि अगर किसी मैनेजमेंट में कोई बात हो जाए तो उसका रिफ्लेक्शन होता है डिस्ट्रिब्यूटली काम किए जाने का लेकिन जब सरकार आप लाखों रुपए बगैर उस की डिटेल् बताए कि चन्द सरमायदारों को दे दे तो वह अपने इस एक्शन को किस तरह जस्टीफाई कर सकती है। आज जब बिल दूसरी बार इस हाउस में लाया गया है तो भी डिटेल्स नहीं बताई गई कि कितनी रकम दी जा रही है और यही कारण था जिसकी वजह से मिल को पिछली बार डेफर किया गया था इस लिये आखिर में मैं यह कहूँगा कि जब तक इस रकम की डिटेल् न दी जाए इस बिल को पास नहीं करना चाहिए।

ਪਸ਼ੂਪਾਲਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

(Interruption)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ

[ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ]

ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 'ਕੁਐਸਚਨ ਬੀ ਨਾਉ ਪੁਟ' ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁਪ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (The hon. Member should not have done like that. I have never wished that I should check any body from speaking. Even when the Chief Parliamentary Secretary Shri Garg moved a motion that the question be now put, I did not insist upon it so that more members may be able to speak on the Bill. Moreover, Comrade Josh of the Member's Group has already spoken. I allow only one member from a group to speak and have never restricted the discussion, therefore, the hon. Member should not insist on speaking.)

**ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ। ਬਿਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਵੈਸਚਨ ਬੀ ਨਾਉ ਪੁਟ' ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

**Mr. Speaker:** Please take your seat.

**ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਹੁਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਨੀ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

**Mr. Speaker:** Please take your seat.

**ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ (ਧੂਰੀ ਐਸ. ਸੀ.) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਖਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਗੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦ ਧੂਰੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੱਸਰ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਪੀੜ ਲੈਣ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੱਸਰ ਲਗਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ

ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ ਕਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਸ਼ਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਡੀਸਾਈ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡੀ. ਡੀ. ਪੂਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜੋ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨਾ ਉਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਮਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵੇਰ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਰ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 24 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਲਖ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਢੋਂਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲੀਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ।

**ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ :** ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਾਇੰਟ ਤਾਂ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਲੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਢੋਂਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲੀਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Amendment Bill be passed.

After ascertaining the vote of the Members present by voices, Mr. Speaker gave an opinion. The opinion was challenged. The bells were sounded. The question was put again and carried by a voice vote.

*The motion was declared carried.*

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 28th February, 1966.

*(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the  
28 February, 1966)*

28

## APPENDIX

to

P. V. S. Debates Vol. I—No. 8

*Dated the 25th February, 1966*

### KALLAR AND SALINE LAND IN QANUNGOIS OF CERTAIN VILLAGES IN DISTRICT SANGRUR

**3198. Sardar Ranjit Singh Nainewala :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

- (a) whether any survey has been made to ascertain the existence of Kallar and Saline in the Qanungoi Circles of Bhadaur, Mahal Kalan and Ahmadgarh of District Sangrur; if so, the extent of the areas affected thereby :
- (b) whether he is aware of the fact that a large portion of the cultivated area of villages Bhadaur, Mahal Kalan, Kasba and Mahali Kalan are affected by the existence of Kallar and Saline, if so, the scheme, if any formulated to eradicate Kallar and Saline from the lands of those villages.

**Chaudhri Rizaq Ram Irrigation and Power Minister:** (a) Yes. The damage due to Kallar and Salinity is not much in the Qanungois Circles of Bhadaur, Mahal Kalan and Ahmadgarh of District Sangrur.

(b) In view of the extent of damage being not much, in the villages Bhadaur, Mahal Kalan, Kasba and Maholi Kalan, no schemes have been formulated.

### Survey to ascertain the Water Table of Water logged Areas of District Sangrur

**3199. Sardar Ranjit Singh Nainewala :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any survey has been made to ascertain the water-tables of the water-logged areas of district Sangrur and that of the area of Bahadur, Shaina, Mahal-Kalan and Ahmadgarh Blocks; if so, the data of the water table so collected be laid on the Table of the House ?

**Chaudhari Rizaq Ram :** Yes, surveys to ascertain the water-tables of the waterlogged areas around 12 miles radius of Sangrur and Sunam cities of Sangrur district have only been carried out. Relevant data are attached. No survey of the area of Bhadaur, Shaina, Mahal Kalan and Ahmedgarh Blocks has been carried out.

(Enclosure to un-starred Assembly Question No. 3199)

## I

## SANGRUR PILOT ZONE

(Within 12 miles radius of Sangrur Town)

Average subsoil water depth based on 116 wells.

Serial No.	Month	Average water Depth	Serial No.	Month	Average water Depth
1	7/62	7.65'	21	3/64	6.80'
2	8/62	8.04'	22	4/64	7.25'
3	9/62	7.58'	23	5/64	7.41'
4	10/62	4.07'	24	6/64	7.80'
5	11/62	4.90'	25	7/64	4.60'
6	12/62	5.05'	26	8/64	3.20'
7	1/63	5.16'	27	9/64	3.00'
8	2/63	5.60'	28	10/64	3.50'
9	3/63	5.89'	29	11/64	4.10'
10	4/63	6.41'	30	12/64	4.20'
11	5/63	6.66'	31	1/65	4.75'
12	6/63	6.92'	32	2/65	4.76'
13	7/63	6.44'	33	3/65	5.07'
14	8/63	4.18'	34	4/65	5.46'
15	9/63	4.82'	35	5/65	5.83'
16	10/63	5.54'	36	6/65	6.00'
17	11/63	5.75'	37	7/65	5.25'
18	12/63	5.96'	38	8/65	3.50'
19	1/64	6.11'	39	9/65	Not Observed
20	2/64	6.29'	40	10/65	5.75'

## II

## SUNAM PILOT ZONE

(within 10 miles radius of Sunam Town)

Average Subsoil water depth based on 52 wells.

1	7/62	4.99'	11	5/63	4.92'
2	8/62	6.34'	12	6/63	6.41'
3	9/62	6.16'	13	7/63	6.67'
4	10/62	4.44'	14	8/63	6.08'
5	11/62	4.74'	15	9/63	5.34'
6	12/62	4.87'	16	10/63	5.93'
7	1/63	5.02'	17	11/63	5.93'
8	2/63	5.69'	18	12/63	5.95'
9	3/63	6.13'	19	1/64	5.58'
10	4/63	6.34'	20	2/64	6.38'

1	2	3	4	5	6
21	3/64	7.54'	31	1/65	5.14'
22	4/64	7.52'	32	2/65	5.25'
23	5/64	7.59'	33	3/65	5.55'
24	6/64	7.55'	34	4/65	5.73'
25	7/64	4.19'	35	5/65	6.92'
26	8/64	3.07'	36	6/65	6.08'
27	9/64	3.38'	37	7/65	4.65'
28	10/64	2.74'	38	8/65	4.47'
29	11/64	4.79'	39	9/65	Not observed
30	12/64	5.01'	40	10/65	5.27'



1951-52  
Punjab Vidhan Sabha  
Punjab Vidhan Sabha

**"C" 1966**

**Published under the authority of the Punjab Vidhan Sabha and  
printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab, Chandigarh.**

# Punjab Vidhan Sabha Debates

28th February, 1966

Vol. I—No. 9

## OFFICIAL REPORT



### CONTENTS

	<i>Page</i>
<i>Monday, the 28th February, 1966</i>	
Starred Questions and Answers ..	(9) 1
Unstarred Questions and Answers ..	(9) 28
Call Attention Notices ..	(9) 55
Message from the Governor ..	(9) 61
Points of Order ..	(9) 61
Papers laid on the Table ..	(9) 66
Bill(s)	
Extension of time for making the final Reports by the Regional Committees on :	
the Punjab Municipal Corporations—, 1963 ..	(9) 66
the Punjab Municipal—, 1963 ..	(9) 69
the Punjab Cattle Preservation—, 1964 ..	(9) 69
the Punjab Gram Panchayat (Amendment)—, 1965 ..	(9) 70
Supplementary Estimates (Second Instalment), 1965-66	
1. Discussion on the Estimates of the Expenditure charged on the revenues of the State ..	(9) 70—107
2. Voting of the Demands for Supplementary Grants Appendix ..	(i)—(viii)

Price: Rs. 5.75 Paise.



# ERRATA

To

*Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 9, dated the  
28th February, 1966*

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>
ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ	ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ	(9)28	1
		(9)68	9
Comrade Makhan Singh Tarsikka	Comrade Makhaan Singh Tarsikka	(9)28	20
12(3)	12 3)	(9)37	8
sureties	suretes	(9)44	3
investment	investiment	(9)45	26
relevant	relevent	(9)46	8 from below
commensurate	commensurat	(9)47	3 from below
specific	specifick	(9)47	Last but one
7.9	7.5	(9)48	12
ਹੁਕਮ	ਹੁਕਮ	(9)57	5
was	wa	(9)57	6 from below
investigation is	investigation	(9)57	5th from below
action is	action	(9)57	4 from below
ਐਡਜਨਸਟ	ਐਡਜਨਸਟ	(9)63	15
ਗੌਰਮਿਟ	ਗਰਮਿਟ	(9)64	3
ਦੇਵਗੀ	ਦੇਵਗੀ	(9)64	3
ਇਸ	ਇਲ	(9)64	11
ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲ	ਇੰਡੀਵਿਜ਼ ਅਲ	(9)67	3
ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ	ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ	(9)67	7
ਕਮੇਟੀ	ਕਮਟੀ	(9)67	7
ਕੰਪਰੀਹੈਨਸਿਵ	ਕੱਪਰੀਹੈਨਸਿਵ	(9)67	16
ਕੰਮ	ਕਮ	(9)67	last but one P.T.O.

<i>Read</i>	<i>For</i>	<i>Page</i>	<i>Line</i>	
ਕਰਨ	ਕਰਨਾ	(9)67	last	
ਕਾਸਰੇਡ ਰਾਸ ਪ੍ਧਾਰਾ	ਕਾਸਰਡ ਰਾਸ ਪ੍ਧਾਰਾ	(9)67	9	
ਮਿਉਨਿਸਪਲ	ਮਿਉਨਿਸਪਲ	(9)68	24	Th
that	tht	(9)71	13 from below	
ਮਹਿੰਗਾਈ	ਮਹਿੰਗਾਈ	(9)74	14	
ਮੁਤੱਲਿਕ	ਮੁਅਤਲਿਕ	(9)74	6	
ਭੱਤਾ	ਭੱਤਾ	(9)74	17	
ਭੱਤੇ	ਭੱਤੇ	(9)74	18	ਜਾਮਾ
ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ	(9)76	1	ਸ਼ੀਰ ਤ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ	ਦਾ ਕਾਨਦਾਰ	(9)76	3 from below	
ਸਾਡੇ	ਸਾਡ	(9)78	12 from below	ਕੀ ਹੈ ਕਿ
ਕਰੇ	ਕਰ	(9)78	last but one	ਪੈਸੇ ਹੈ
ਵੈਲਫੇਅਰ	ਲਵੈਫੇਅਰ	(9)79	16	ਟੇ ਜਹ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ	ਹੈ ਰਿਹਾਖ	(9)79	26	40 ਰੁਪ
ਬਚਣੀ	ਬੋਚਣੀ	(9)79	28	ਏ
ਫੈਸਲਾ	ਫੋਸਲਾ	(9)80	25	ਏਕਸ ਫੈ
2.44	244	(9)82	8 from below	ਜੀਟਿਸ ਸੋ
ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ	ਜਾਨਾ ਵਾਰਿਆਂ	(9)83	8	ਦਾ
the	thc	(9)86	10	ਸਾਇੰਸ ਕ
ਸਾਲ	ਲ	(9)90	14	ਅੰ
ਆਰਡਰ	ਆਸਡਰ	(9)92	8	ਜਾ ਕਿ ਹੋ
ਚਾਹੁੰਦੇ	ਚਾਂਦੇ	(9)93	8 from below	ਏ 60
ਤੋਂ	ਤੋਂ	(9)95	20	ਏ ਯਾ 3
ਮਨਜ਼ੂਰੀ	ਮੰਨਜ਼ਰੀ	(9)95	last but one	ਦਾ
ਪੰਜਾਬ	ਪਜਾਬ	(9)97	18	ਪੈਕਿੰਗ
ਗੋਅਰਜ਼	ਗੋਅਰਜ਼	(9)101	10	10 ਰੁਪਏ
Whether	Wnether	20		ਕੋਈ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	26		ਅੰ

# PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 28th February, 1966

*The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhavan, Sector I Chandigarh, at 2.00 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.*

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### Supplementaries to Starred Question No. 9106

**श्री बलरामजी दास टंडन :** मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि मैं हारलिव्स फैक्टरी, नाभा में घी की कीमत का पता करूंगा। क्या वह बताएंगे कि वहां के घी की क्या कीमत है और उसके मुकाबला में वेरका के घी की क्या कीमत है ?

**पशुपालन तथा कृषि राज्य मंत्री :** हारलिव्स फैक्टरी, नाभा की दो किस्म की घी की पैकिंग है। एक स्पेशल पैकिंग करते हैं। उसका 2 किलो का उन का रेट 17 रुपए 60 पैसे है और 4 किलो का 34 रुपए 60 पैसे है। उसकी अवेलबिलिटी कम है। उस का मार्किट रेट जहां उन के एजेंट्स रहते हैं वहां 2 किलो का 20 रुपए 34 पैसे है और 4 किलो का 40 रुपए है।

**श्री बलरामजी दास टंडन :** क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या उन के घी की एक्स फैक्टरी प्राइस 33 रुपए 25 पैसे है पर 4 किलो टिन ? क्या वह पेंटिड और प्रिंटिड टिन में सप्लाई करते हैं ?

**राज्य मंत्री :** जो इनफॉर्मेशन मेरे पास थी वह मैंने दे दी है। उन की एक्सफैक्टरी प्राइस का मुझे पता नहीं है, जो मार्किट रेट है वह बता दिया है।

**श्री फतेह चन्द विज :** क्या पशुपालन मन्त्री बताएंगे कि उस दिन उन्होंने फरमाया था कि वेरका और नाभा के घी के रेट एक जैसे हैं। आज उन्होंने 4 किलो की कीमत 34 रुपए 60 पैसे बताई है और मार्किट रेट 40 रुपए कह रहे हैं। उस दिन वाली बात ठीक है या आज वाली ?

**राज्य मंत्री :** उस दिन वाली बात भी ठीक है और आज वाली भी ठीक है। उसकी 2 पैकिंग है जो मार्किट में आती है। तो उसके मुताबिक 2 किलो हारलिव्स के घी की कीमत 20 रुपए 35 पैसे है। यह उनके स्पेशल पैकिंग की कीमत है। मेरी उस दिन वाली बात में कोई फर्क नहीं है।

**श्री बलरामजी दास टंडन :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जहां तक वेरका का ताल्लुक है वहां मिडल मैन नहीं है, वह प्राइवेट अदारा नहीं है। इसलिए मैंने यह बात

---

*Note—Starred Question No. 9106, along with its reply appears in the P.V.S. Debates Vol. I, No. 6, dated 23-2-1966.*

[ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ]

ਪ੍ਰਭੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਕਰ ਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਵਹਾਉਸ ਦੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮਦੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਹਾਉਸ ਦੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਮੈਨ ਰਖੇ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ : ਆਪ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਹ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕੈਸੇ ਬਨ ਗਯਾ ?  
(The hon. Member is asking a supplementary. How does this become a point of order ?)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਬਤਾਓਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ : ਜੋ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਉਨ ਦੇ ਪਾਸ ਥੀ ਵਹਾਉਸ ਨੇ ਦੇ ਦੀ ਹੈ।  
(Whatever information he possesses, he has imparted.)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਨਾਮਾ ਕਾ ਧੀ ਸਬ ਸੇ ਲਾਸਟ ਲੇਟੇ ਹੋ, ਤੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਨਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ ਦੀ ਏਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਬਨਿਸ਼ਕਤ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਯਹ ਇਸਟੇਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਯਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਧੀ ਦੀ ਏਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੀ ਉਸੀ ਆਧਾਰ ਪਰ ਲਾਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ?

ਰਾਜਯ ਮੰਤਰੀ : ਏਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾ ਕੋਈ ਸਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜ ਵੀ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਰੇਟ ਇਹ ਹਨ : ਇਕ ਕਿਲੋ ਗੋਪੀਕਾ ਘੀ ਦਾ ਟੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਲੋ ਅਨਿਕ 23 ਰੁਪਏ 69 ਪੈਸੇ, ਸ਼ਕਤੀ 22 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ, ਕਾਹਨ 24 ਰੁਪਏ 55 ਪੈਸੇ, ਮੋਹਣ ਘੀ 24 ਰੁਪਏ 55 ਪੈਸੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜਮਨਾ 23 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ, ਲਕਸ਼ਮੀ 22 ਰੁਪਏ, ਗੋਪੀਕਾ 20 ਰੁਪਏ 35 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਘੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਐਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸੇਲ ਰੇਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਸਰਦਾਰ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਖੁਦ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ ਵਿਜ : ਇਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੇਟ ਕੋਟ ਕੀਏ ਹਨ, ਕਯਾ ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏ ?

ਰਾਜਯ ਮੰਤਰੀ : ਉਨਕਾ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾ ਰੇਟ 40 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਾਰਾ ਭੀ 40 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਝੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਕੋ ਉਸ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗਾ, I will find out and take action.)

**Circular/order issued to District Excise and Taxation Officers regarding, payment of sales tax/property tax**

**\*9108. Dr. Baldev Parkash** (put by Shri Balramji Dass Tandon) : Will the Minister for Finance be pleased to state—

- (a) whether any circular/order was issued to the District Excise and Taxation Officers in the State in view of the assurance given by the Chief Minister to the effect that three months' extension would be allowed for payments of sales tax and property tax after the cease fire on the Indo-Pakistan Border which came into effect in September, 1965, if so, a copy of the said circular/order be placed on the Table of the House ;
- .. (b) whether any order was also issued to the District Officers not to enhance the assessment of property tax in respect of self-occupied houses situated in the border districts where no additions or alterations had been made during the last 5 years ; if so, a copy of the order so issued, be placed on the Table ?

**Sardar Kapoor Singh:** (a) (i) No general instructions to Excise and Taxation Officers in the State were issued but instructions were issued extending the date of deposit of sales tax and purchase tax for the quarter July—September, 1965 up to 31st December, 1965, by three months, in respect of the registered industrial units of the border districts of Ludhiana, Jullundur, Ferozepur Amritsar Gurdaspur and Kapurthala. A copy of the instructions is placed on the Table of the House.

(ii) No such instructions were issued in respect of Property Tax.

(b) No.

STATE

TELEGRAM

EXPRESS

ETAX LUDHIANA, JULLUNDUR, FEROZEPUR, GURDASPUR,  
AMRITSAR, KAPURTHALA

No. 8147-ET(III)65/1144 . Government desire that date for deposit of sales and purchase Tax for quarter July—September, 1965 by industrial units be extended by three months.

Secretary Taxation

Not to be telegraphed

Sd/-

Deputy Secretary, Excise and Taxation.

No. 8147-E&T (III)-65/9927

. Chandigarh, dated the 29th October, 1965

A copy by post, is forwarded to the Excise and Taxation Officers, Ludhiana, Jullundur, Ferozepur, Gurdaspur, Amritsar and Kapurthala, in confirmation.

Sd/-

Deputy Secretary, Excise and  
Taxation.

[Minister for Finance]

No.8147-E&amp;T III)-65/9930

Chandigarh, dated the 29th October, 1965

A copy, by post is forwarded to the Excise and Taxation Commissioner, Punjab, Patiala, for information, with reference to undersigned's telephonic talk with him.

Sd/-

Deputy Secretary, Excise and Taxation

IMMEDIATE

From

The Deputy Secretary to Government, Punjab,  
Excise and Taxation Department.

To

The Excise and Taxation Commissioner, Punjab,  
Patiala.

Memo No. 8767-ET(III)-65/10730  
Chandigarh, dated the 26th November, 1965

**Subject:—** Extension in time for deposit of sales and purchase Tax.

**Reference:—**Continuation of Punjab Government endorsement No. 8147-ET(III)-65/9930,  
dated the 29th October, 1965.

1. Government desire that the date of deposit of sales and purchase tax for the second quarter July-September, 1965 should be extended till the 31st December, 1965, in the case of Industrial Units only in the Districts of Ferozepur, Amritsar, Gurdaspur, Jullundur, Ludhiana and Kapurthala. Only these industrial units which are registered with the Industries Department will be eligible to avail of this concession up to 31st December, 1965.

2. Besides the date of deposit of sales and purchase Tax for the second quarter (July-September, 1965) should also be extended till 31st December, 1965 by the traders in the towns of Ferozepur, Fazilka and Dera Baba Nanak.

3. You are, therefore, requested to ensure that this concession is not mis-utilised by the authorities and the trade.

Sd/-

Deputy Secretary, Excise and Taxation.

**श्री बलरामजी दास टंडन:** क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि इस हाउस में एंशोरेंस दी गई थी कि सब डिपार्टमेंट्स को इंडस्ट्रकणन्ज भेजी जाएंगी कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स को सरकार ने बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर किया है, जो वारहिट ह, एक सरकुलर भेजा जाएगा प्रापर्टी टैक्स, परचेज टैक्स और सेलज टैक्स के बारे में ताकि उन को मौका मिले, राहत मिले कि टैक्स अभी जमा नहीं कराना, बाद में कराना है? उसके बारे में क्या हुआ?

**मन्त्री:** एंशोरेंस यह दी गई थी कि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि मनी मार्किट बहुत टाइट थी इसलिए मुनासब समझा गया कि जो सेलज टैक्स अदा करना था उन को 3 महीने की मोहलत दे दें ताकि 3 महीने के लिए वह उस सेलज टैक्स के पैसे को कारोबार

ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ I may classify। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਏਰਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਧਰਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹੀ ਥੀ, ਜੈਸੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮੇਂ ਸੈਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਥਾ ਅਪਨੇ ਆਡਜੈਕਸ਼ਨ ਪੁਟ ਡਨ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਇਸ ਲਿਏ ਉਨ੍ਹੇਂ ਸੋਹਲਤ ਦੇ ਦੀ ਗਈ, ਉਨ ਕਾ ਟਾਈਮ ਏਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਯਾ ਗਯਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਥੀ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਜੋ ਡਨ ਦੇ ਮਨ ਮੈਂ ਹੈ ਕਹਿ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਮੈਂ ਉਨ ਦਿਨਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਿਸਟੋਂ ਬਨ ਰਹੀ ਥੀ। ਇਟ ਕਾਜ਼ ਜਸਟ ਪਾਸੀਬਲ ਨਵੇਂ ਲਿਸਟੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਡਯਾਦਾ ਕਰ ਜਾਏ ਇਸ ਲਿਏ ਮੁਨਾਸਿਬ ਧਰਮ ਸਮਝਾ ਗਯਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਨੇ ਏਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੇ ਉਨ ਕੋ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿਯਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਏਪਲਾਈ ਨ ਕਰੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇ ਲਿਏ ਪੁਰਾਨੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਗੇਗੀ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਫਾਸ ਟਾਂਡਨ :** ਕਯਾ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਏਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਏਸ਼ੋਰੇਂਸ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਯਾ ਜਾਏ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਡਯੂ ਥਾ ਉਨ ਕੋ ਭੀ ਏਸੀ ਏਸ਼ੋਰੇਂਸ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਕਹਿ ਭੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਕਰਕਾ ਸਕਦੇ ਹੈਂ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰੀਟਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਗਏ ਐਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ **explanation call** ਕਰਾਂਗੇ ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਸੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਗੇ ਤਾਂ **enquiry shall be made** ਕਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

### Meeting held between the representatives of the Beoparis and the Government in December, 1965

**\*9527. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

- (a) whether the Finance Minister and the Excise/Sales Tax authorities were present at a meeting held at Chandigarh, in the first week of December, 1965, to discuss the problems of the trading community; if so, the names of the representatives of the Beoparis present at the said meeting;
- (b) whether any assurances were given by the Government to the representatives of the beoparies referred to in part (a) above in the said meeting; if so, the details thereof;
- (c) whether the assurances referred to in part (b) above envisage further amendment of the Punjab General Sales Tax Act, 1948, which was recently amended;

[Shri Fateh Chand Vij]

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, whether the Government proposes to bring another amending Bill in this respect, before the State Legislature during the Budget Session ?

**Sardar Kapoor Singh :** (a) Yes ; Shri Tulsi Dass Jaitwani, President, Punjab, Beopar Mandal and a few of his colleagues.

(b) A copy of the proceedings is placed on the Table of the House.

(c) and (d) The proceedings are under examination and legislation, wherever considered necessary, will be placed before the House.

**Proceedings of the meeting held at Governor's residence on 1st December 1965 at 12.15 P.M.**

**Present—**

1. His Excellency the Governor of Punjab.
2. Finance Minister, Punjab.
3. Excise and Taxation Commissioner, Punjab.
4. Deputy Secretary Excise and Taxation.
5. Representative of the Beopar Mandal.

The following decisions were taken:—

1. The powers of the Financial Commissioner for suo motu revision at any time, may be examined, there being no limitation for initiating such action.
2. Executive instructions be issued to the departmental authorities to decide all applications within a period of six months from the date of presentation.
3. The question of exempting dealers making small transactions, from the issuing of cash memoranda, be examined particularly, with regard to the Karyana dealers and Halwais etc. The representatives of the Beoparies may be consulted while drawing up the list of such dealers.
4. As regards the maintenance of day-to-day accounts it may not be made incumbent to prepare them at the end of the day itself, but they may be prepared within 48 hours of the transaction.
5. Copies of the assessment orders be supplied to the dealers within 30 days of the date of application i.e. within the same period which is prescribed for the payment of tax.
6. The question of prior payment of penalty before entertaining an appeal may be examined keeping in view the relevant provisions in the Acts of Delhi, U.P., Orissa etc.
7. Executive instructions be issued to the official incharge of barriers that no public carrier should be detained for more than three hours unless the driver fails to produce the requisite documents. All cases of longer delay may be reported to the Excise and Taxation Commissioner by the official incharge.
8. Finance Minister agreed, in principle, to the setting up of a tribunal preferably on the pattern of Maharashtra if possible. The details may be examined by the Department.

**ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵਿਜ :** ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

**ਸ੍ਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ ਵਿਜ :** ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਲਿਆਉਗੇ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਮ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

**Comrade Ram Piara:** The Finance Minister in reply to the question has stated that the matter is under consideration. I would like to know whether the same is being examined by the Cabinet or by the Excise and Taxation Department ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ ਮੀਮੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਾਂ ਰਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਧੌਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਉ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ :** ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਬਨੀਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹਨ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤਅਲੁਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਏਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ because the Act is going to be enforced from the first of April.

**ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਰਬੜ ਗੁਡਜ਼ ਹਨ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟੀਊਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਲਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਉਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਪ ਸਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ।

We are pulling on very nicely, this I can assure the hon. Member,

#### Tehsildars in the State

**\*8837. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- (a) the total number at present of Tehsildars working in the State together with the number of those who are permanent and of those who are likely to be confirmed among them ;

(b) the total number of substantive posts of Tehsildars at present against which confirmations are yet to be made ;

(c) the date when the last confirmation took place in the said cadre ?

**Sardar Harinder Singh Major :** (a) (i) Total Number of Tahsildars including those working on side line jobs-115.

(ii) Permanent 25, Likely to be confirmed 50.

(b) Fifty.

(c) 6th January, 1966.

**ਸ੍ਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ ਵਿਜ :** ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ 6 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਦੀ ਡੇਟ ਦਸੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1956 ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ ਸਨ । ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ 115 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ?

**Minister :** Sir, the cases are being looked into and a decision will be taken in due course of time.

**ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਫਾਸ ਟੰਡਨ :** ਕਥਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਕੋ ਪਰਮਾਨੈਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸੇ ਲਗ ਭਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਕ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਪਰ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਕੈਂਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਨੈਟ ਵੇਕੈਂਸੀ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਕੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਫਤੇਹ ਚੰਦ ਵਿਜ :** ਜੈਂਸਾਕਿ ਮੈਂ ਨੇ ਉਨਸੇ ਅਜ਼ ਕੀਯਾ ਥਾ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1956 ਦੇ ਤਨਕੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਕਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਥੀ, ਕਥਾ ਕਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕੇ ਬਾਦ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

### STARRED QUESTION NO. 8963

**ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ।

**ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਐਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਐਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ

ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਐਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਰੀਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਨ ਜੇਕਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਮਲੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ । ਨਾਰਮਲੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ( It has been observed from the requests for extension of times received from the Ministers that the extension asked for frequently exceeds fifteen days and sometimes it is for a month. According to the rules, the reply to a question must be supplied within fifteen days. But if the extension is in excess of 15 days then it creates a queer position. I have now framed a rule which will normally permit no extension of time and the reply, therefore, must come within 15 days. If at all any extension is given in a particular case, it will not exceed seven days. I am imparting this information to the House so that the various departments may come to know that they would no longer have to ask for a months extension and wait for that period. Normally, an extension of term will not exceed seven days.)

**ਮੰਤਰੀ :** ਆਪਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮਥੇ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਲੇਕਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਰਡ-ਸਟਿਕ ਐਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.....

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ (ਹਾਸਾ) ।

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ।

**Representation from Revenue Patwaris Union Punjabi Transcription  
Branch, Jullundur**

**\*9261. Shri Om Parkash Agnihotri :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Revenue Patwaris Union, Punjabi Transcription Branch, Jullundur sent a representation to the Deputy Commissioner Jullundur on the 14th January, 1966, requesting him to provide seating arrangement for them like other office employees ; if so a copy of the same alongwith the action taken thereon be laid on the Table of the House ;

(b) if no action has been taken in the matter, the reason therefor ?

**Sardar Harinder Singh Major:** (a) No.

(b) Question does not arise.

**ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ :** ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਫਾ ਸੈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਹਾਸ) ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ :** ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਐਸੀ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

**Complaint against the Revenue Officer, Tehsil Ajnala**

**\*9475. Sardar Kulbir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any complaint was received by the Deputy Commissioner, Amritsar, vide memorandum No. EA/BCIII/PF/3880, dated 21st September, 1963 from Shri Sajjan Singh Margindpuri against certain revenue officer of Ajnala tehsil for his having appeared as a Mukhtar Khas of his father-in-law before the Director, Consolidation of Holdings, Jullundur ; if so, a copy of the same be laid on the Table ;

(b) whether any enquiry was ordered into the complaint referred to in part (a) above ; if so, by whom and the name of the authority who conducted it ;

(c) whether the complainant was given an opportunity to substantiate his allegations, if so, the details of the procedure adopted by the enquiry officer for the purpose ;

(d) the result of the said enquiry and the details of action taken in the matter ?

**Sardar Harinder Singh Major :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No.

(d) The complaint was examined and it was found that there was nothing objectionable in the Naib-Tahsildar's appearing as Mukhtar Khas of his father-in-law before the Director of Consolidation, Punjab, Jullundur.

**ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫੇਸਾਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫੇਸਾਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।

**ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ :** ਬਗ਼ੈਰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

### Hospital at Una, District Hoshiarpur

**\*8892. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- whether he is aware of the fact that accommodation for in-door patients in the Hospital at Una, District Hoshiarpur, which has been declared an Eye Centre by the Government, is inadequate ;
- whether he is further aware of the fact that the said Hospital is not properly equipped with instruments required for eye operations ;
- whether Government received any representations for provincializing or improving the facilities in the said Hospital ; if so, the action taken or proposed to be taken in this behalf ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** (a) Yes, Sir. Though the present medical officer posted there and his two predecessors have been doing some eye work yet this hospital has not been declared as an eye centre.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. The matter is under correspondence with the Zila Parishad, Hoshiarpur and until they pass a resolution accepting the usual conditions, the hospital cannot be considered for provincialization.

### Private Practice by Teaching Staff of Government Medical Colleges in the State

**\*9223. Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- whether it is a fact that the members of the teaching staff of the State Medical Colleges at Rohtak, Patiala and Amritsar are

[Shri Ram Saran Chand Mital]

- allowed private practice and those of the Post-Graduate Medical Research Institute at Chandigarh are denied this privilege ; if so, the reasons for this differentiation ;
- (b) whether it is a fact that the members of the teaching staff of the State Medical Colleges do not like to join the Post Graduate Medical Research Institute at Chandigarh for fear of losing private practice ;
  - (c) whether he is aware of the fact that the private practice of the Medical teachers prevents the staff from devoting their full attention to their hospital work and causes heart burning among those who are not allowed this facility ;
  - (d) the steps, if any, proposed to be taken by the Government to introduce uniformity in the various medical educational and Post Graduate Institutions in the State ;
  - (e) whether it is a fact that some Principals of the State Medical Colleges were offered the post of Director, Medical Education and Research and they declined because of non-practice restrictions ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** (a) The teachers in the Medical Colleges employed in Clinical Departments and Pathology Department are allowed private practice in their respective specialities. The teachers in the non-clinical Departments are not allowed private practice but they are granted non-practising allowance in lieu thereof. The Registrars and Demonstrators in the State Medical Colleges are allowed neither private practice nor non-practising allowance.

This is a fact that all teaching posts in the Post Graduate Institute, Chandigarh, are non-practising. This is mainly due to the fact that the Post-Graduate Institute is basically a research institute and the medical officers employed therein could not be allowed to indulge in private practice. They have, however, been allowed higher scales of pay for the loss of their private practice.

(b) This is not a fact. A large number of doctors working in Post Graduate Institute are from the Medical Colleges.

(c) No such case has come to the notice of Government.

(d) No such proposal is under the consideration of Government.

(e) No.

#### Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine

**\*9422, Dr. Baldev Prakash (put by Shri Balramji Das Tandon) :** Will the Minister for Health be pleased to state the total number of meetings held by the Board of Ayurvedic and Unani system of Medicine in the State in the year 1965, together with the amount paid as T.A. to each of the members of the said Board ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** Three ; Rs 18.20 each to Shri Kartar Singh Babbar and Shri Parkash Nath Tewari.

#### Teachers working in Government Middle School, Sanghol, District Ludhiana

**\*8875. Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education be pleased to—

- (a) lay on the Table of the House a list of teachers working in the Government Middle School, Sanghol, district Ludhiana,

as on 28th February, 1965 together with the educational and departmental qualifications of each ;

- (b) state the number of teachers out of those mentioned in part (a) above who were working on a regular basis and on six monthly basis, separately ;
- (c) state whether the said teachers working on six monthly basis were appointed against vacant posts or against leave vacancies ;
- (d) state whether the posts mentioned in part (c) above were vacant posts, the time since when these were lying vacant together with the dates when regular persons were appointed against the same ?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) A list containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(b) (i) Number of teachers working on regular basis .. 7

(ii) Number of teachers working on six months basis .. 1

(c) The teacher who worked there on six months basis had been appointed against a regular vacancy.

(d) Yes. The vacancy was not filled up on regular basis from 11th May, 1964 to 30th April, 1965. The post was shifted from Government Middle School, Sanghol, with effect from 1st May, 1965. As such, the question of filling the same on regular basis does not arise.

**Statement containing information in respect of part (a)**

Serial No.	Name	Educational and professional qualifications
1	Smt. Balvinder Kaur	.. M.A., B.Ed.
2	Smt. Shanti Devi	.. Middle S.V.
3	Smt. Khushwant Kaur	.. Middle J.V.
4	Smt. Surjit Kaur	.. Middle J.V.
5	Smt. Kirpal Kaur	.. Matric J.B.T.
6	Smt. Pawan Sharma	.. Matric J.B.T.
7	Smt. Parkash Wari	.. Matric J.B.T.
8	Smt. Harbans Kaur	.. Matric Art & Craft, Giani trained.

**ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ :** ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

**Mr. Speaker :** This is not a supplementary.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਗੇ ਇਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਿਰਫ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। (It was said only in regard to motions.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

**Corruption charge against an official of District Education Officer's Office, Ludhiana**

\*8876. **Sardar Kultar Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the D.E.O., Ludhiana, caught a senior official of his office red-handed while taking one hundred rupees as bribe during the general transfers of the teachers effected in 1965; if so, the name and the designation of that official together with the action taken against him;

(b) if no action has been taken against the said official, the reasons therefor;

(c) the action, if any, being taken against the D.E.O., Ludhiana for shielding a corrupt official?

**Shri Prabodh Chandra:** (a) No.

(b) and (c) : In view of (a) above, the question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ਲ ਦੀ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੇਸ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਉਸ ਸੁਪਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 1½ ਘੰਟੇ ਤਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ : ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੀਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ

ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਘੁਆਰਾ :** ਕਥਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਨੇ ਦੀ ਕੁਪਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਖ਼ਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਟ ਕੀ ਜਾਏ ਐਸੇ ਸਦਾਕਤ ਭੀ ਹੋ ਤੋ ਏਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਕਵਾਇਰੀ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਤੈਧਾਰ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨਨੀਯ ਸਦਸਯ ਅਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਰ ਯਾ ਅਪਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਟਮ ਪਰ ਕ ਤਾਏਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਮੇਂ ਇੰਕਵਾਇਰੀ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਤੈਧਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਕਵਾਇਰੀ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਭੀ ਤੈਧਾਰ ਹੈ।

### Complaint against District Education Officer, Ludhiana

\*8877. **Sardar Kultar Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that some Legislators made a complaint to the Director of Public Instruction, Punjab, and the Minister for Education in the month of May or June, 1965 against the misbehaviour of the District Education Officer, Ludhiana;
- (b) whether any enquiry was made into the said complaint; if so, the results thereof, if no enquiry was made, the reasons therefor?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) No.  
(b) Does not arise.

### Basic Education in the State

\*8962. **Pandit Mohan Lal Datta:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of Government to re-orientate the pattern of Basic Education in schools so as to give it a dynamic agricultural and technical bias during the Fourth Five-Year Plan; if so, details thereof and the measures contemplated in this connection?

**Shri Prabodh Chandra:** Yes. The following programme is proposed to be undertaken during 1966-67—

No.

- |  |       |
|--|-------|
| (1) Starting of Agriculture Farms                                  | .. 10 |
| (2) Starting of Garden Plots                                       | .. 15 |
| (3) Introduction of Agriculture Groups in Secondary Schools        | 5     |
| (4) Introduction of Practical-Arts in Middle and Secondary Schools | 50    |

**ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇ-ਫਾਇਦਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇ-ਫਾਇਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

**कापरेड राम प्यारा :** क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐजूकेशन डिपार्टमेंट के अन्दर कोई ऐसी एजेंसी है जो इस चीज़ का रिकार्ड रखती हो कि बेसिक ऐजूकेशन हासिल करने वालों में अमुक व्यवित्यों ने लाभ उठाया है? अगर सरकार को पता लगा हो कि इस ऐजूकेशन का लोगों ने फायदा नहीं उठाया तो इस ऐजूकेशन को जारी रखने का क्या फायदा है ?

**मंत्री :** सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिस से माननीय सदस्य को यह इन्फर्मेशन दी जा सके। यह नहीं बताया जा सकता कि इस ऐजूकेशन से कितने आदिमियों ने प्रैक्टिकली फायदा उठाया है। मेरे लिए यह इन्फर्मेशन देने की काफी मुश्किल है।

**पंडित मोहन लाल दत्त :** क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि कई बेसिक ऐजूकेशन स्कूलों में एग्रीकल्चर का मज़मून बहुत अहम है लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए कुआँ का पानी मुहैया नहीं किया जाता है। क्या सरकार इस तकलीफ को दूर करने के लिये तयार है ?

**मंत्री :** वैसे तो जिन स्कूलों में एग्रीकल्चर का मज़मून रखा हुआ है वहां पर पानी का प्रबन्ध किया हुआ है। मगर माननीय सदस्य पहाड़ी इलाके की बात कह रहे हैं, उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर कुएँ नहीं खोदे जा सकते। इसलिए वहां पर पानी की मुश्किल का प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

**पंडित मोहन लाल दत्त :** मैं माननीय मंत्री की जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि जिस जगह के बारे में मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिला रहा हूं, वह स्कूल पहाड़ी पर नहीं है बल्कि मैदानों के इलाके में है। जब वहां की पंचायत कुएँ खोदने के लिए जमीन देने के लिए तैयार है तो क्या सरकार वहां पर कुआँ खोदने के लिए तैयार है ताकि वहां के विद्यार्थियों को अच्छी तरह से शिक्षा दी जा सके।

**Education Minister:** Sir, it is a suggestion for some action. If the honourable member brings a specific case to my notice, I will certainly have it looked into.

**Amount collected through students etc. towards National Defence Fund**

**\*9264. Shri Ram Saran Chand Mittal:** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the amount collected by the Government as donation towards the National Defence Fund or for other similar defence funds through the students and teachers of the Government academic institutions in the State, members of inspecting staff and the members of the Directorate of Public Instruction, Punjab, separately, since 1st April, 1965;
- (b) whether any instructions were issued by the Government, the Directorate of Public Instruction, or the Inspectors, to the Headmasters, Teachers and students regarding the mode of collection and the amount each individual was to collect; if so, a copy thereof be placed on the Table of the House;
- (c) whether the collection was made from the students themselves or through them from their guardians or the public;
- (d) whether the Government received any complaints or protests from the teachers or their representative bodies against the

employment of teachers and students for the purpose of collection;

- (e) whether the Government has appointed an Inspector of Schools for collecting gold and gold ornaments through teachers and students; if so, a copy of the instructions issued to him in this behalf be placed on the Table of the House;
- (f) whether any students have been asked to pay subscription or donation for other purposes also; if so, how much and for what other purposes;
- (g) the total amount collected in this manner and how it has been utilised?

**Shri Prabodh Chandra:** (a) Rs 65,56,706 in cash and kind. No separate details are available.

(b) A copy of the instructions is placed on the Table of the House.

(c) Yes; from students as well as from public and their guardians through them, to some extent.

(d) No.

(e) Yes; not for collection but for persuading them for investment.

A copy of instructions is placed on the Table of the House.

(f) Yes; for Teachers Welfare Fund on voluntary basis at the rate varying from 10 to 50 paise.

(g) No separate account of collections made from students alone has been maintained. About Rs 5 lakhs in all have been collected from all sources including students. No expenditure has been incurred out of it, so far..

### **NATIONAL EMERGENCY**

#### **TOP PRIORITY**

**FROM**

Shri J.D. Sharma, I.A.S.,  
Director of Public Instruction,  
Punjab.

**To**

ALL THE CIRCLE EDUCATION OFFICERS, DISTRICT EDUCATION OFFICERS, AND PRINCIPALS OF GOVERNMENT COLLEGES IN THE STATE/PRINCIPALS OF GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOLS, HEADMASTERS/HEADMISTRESSES OF GOVERNMENT HIGH SCHOOLS AND BLOCK EDUCATION OFFICERS IN THE STATE.

No. 12/7-65-OA-I(5)

Dated Chandigarh, the 9th September, 1965.

**Subject.**—National Emergency—Contribution towards “Defence Fund for Welfare of Soldiers”

**SIR/MADAM,**

I have the honour to state that it is strongly felt that in order to give proof of our zeal for raising the morale of our Armies, students and teachers working in the Educational Institutions should one and all contribute towards Defence Fund for the welfare of our brave soldiers defending the Motherland and facing the grave National Emergency. Although the contribution would be voluntary, I request that the students and the teachers should be approached appealing to their sense of patriotism to make, for the present, the contributions on the uniform scales indicated below so that accounting is simple and easy:—

(i) each student of Primary Classes

.. 25 Paise.

[Minister for Education]

- |   |                   |
|---|-------------------|
| (ii) each student of Middle , High and Higher Secondary classes | 50 Paise.         |
| (iii) College students  | Re 1 per student. |
| (iv) Staff in Schools and Colleges                              | one day's salary. |

2. The Heads of Institutions should maintain the record of donations received from the staff and students in a register and get the signatures of the individual donors in it to safeguard against the possibility of any mal-practices. A Committee consisting the Head of the Institution, two Senior Lecturers and two students should be immediately formed in each College while in the High /Higher Secondary Schools and Middle Schools the Committee should consist of the Head of the Institution. Two seniormost Teachers and two students besides a prominent member of Parents-Teacher Association, if available, to look after the work of collections and each Member should also, sign in the register maintained for the purpose in token of the correctness of the contributions received. The collections so made will be retained by the Head of the Institution concerned till further orders. In the case of Primary Schools, however, the Heads of Institutions would make collections in the presence of the Sarpanch or a representative deputed by the local Panchayat whose signatures shall be secured in the collection register which shall also be signed by the Head of the School. The total contribution shall then be passed on to the Block Education Officer for which receipt should be secured in the aforesaid register.

3. As already indicated all the collections thus made should be kept, till further orders, by the Principals and Headmasters of Colleges/Higher Secondary Schools/ High Schools. The collections made by the Middle Schools should be passed on to the District Education Officer under his signatures secured on the register. In the case of Primary schools, however, the collection should be kept by the Block Education Officer concerned who should take steps to visit each primary school within the shortest possible time and take charge of the collections against his signatures on the collection register.

4. Action on top priority basis should be taken in this case.

5. This circular has the broad authority of Government.

#### FOR DISTRICT EDUCATION OFFICERS ONLY

6. Copy each of these instructions should be sent to the private Higher Secondary, High and Middle Schools within your District for similar action. Fifty spare copies are enclosed for this purpose.

Yours faithfully,  
HARBANS SINGH,  
DEPUTY DIRECTOR (GENERAL ADMN).  
for Director of Public Instruction, Punjab

No. 12/7-65-OAI (5), dated 9th September, 1965

Copy is forwarded to the Principals of all Private Colleges, Private Higher Secondary, High and Middle Schools in the State for necessary action. Their co-operation in this common national cause is highly desirable and is solicited.

HARBANS SINGH,  
DEPUTY DIRECTOR (GENERAL ADMN.)  
for Director of Public Instruction, Punjab.

Prof. Balwant Singh,  
Joint Director (Schools).  
Punjab Education Department.

D.O. No.13/44-65-OAI,  
Dated, Chandigarh, the 22nd January, 1966.

Dear

The Minister of Education, Punjab has already addressed you for co-operation and assistance in the collection of Gold for investment in the National Defence Gold

Bonds, 1980 Blank application forms for the same have since been sent to you by the Directorate separately. Shri A.S. Shante, Circle Education Officer has been made Incharge of the Scheme so far as the Education Department is concerned.

I request that you may kindly give him full co-operation and assistance in the collection of gold in the investment of Gold Bonds as you have already done in connection with the collection of Defence and Security Relief Fund.

Yours sincerely,

(Sd.) ....

(BALWANT SINGH).

## NATIONAL EMERGENCY

### PRIOTIRY

#### **Punjab Education Department**

J.D. Sharma, I A S,  
Director of Public Instruction,  
Punjab.

D.O. No. DDSA-Stn-65  
Dated the 27th September, 1965.

**Subject:—COLLECTION OF PUNJAB DEFENCE AND SECURITY RELIEF FUND BY THE PUNJAB EDUCATION DEPARTMENT DISTRIBUTION OF RECEIPT BOOKS**

DEAR SIR/MADAM,

It has been decided that all the teaching personnel of the Punjab Education Department would make collections from the Public which would eventually be credited to the Punjab Defence and Security Relief Fund in lumpsum at the State level. Accordingly—Receipt Books are being sent to you through a special messenger. Please arrange to distribute them within twenty four hours of their delivery in your office so that the persons concerned start making collections immediately. The distribution of these receipt books should be made to various types of institutions broadly on the following scale:—

- |   |  |
|---|--|
| (i) Each Government College   | .. 25 copies.  |
| (ii) Each Government High/Higher Secondary School   | 15—20 copies, according to the number of teachers.   |
| (iii) Each Government Middle School   | .. 5—10 copies, according to the number of teachers. |
| iv) Each Block Education Officer  | .. 50 copies.  |
| (v) Balance to be kept in reserve for meeting special demand, on District Education Officers by the aforesaid institutions. |  |

An account of the Receipt Books should be kept against signatures of the heads of the institutions concerned and Block Education Officers. Detailed instructions regarding maintenance of accounts are, however, being issued separately.

2. You are requested to note that these collections are apart from the contribution of one day's salary to be made by each employee of the Department and the contribution to be realised from students regarding which instructions have already been issued—vide this office circular No. 10/7-65-OAI(5), dated the 9th September, 1965. These collections are to be made from the general public and particularly from the parents of the students studying in the various institutions. Even though collections on similar lines are being made by the District authorities, the parents of the students will, it is hoped, be agreeable to make contributions when approached by the teaching personnel. In a large number of cases, parents may not have been approached by the District authorities at all and this source needs to be tapped.

3. Proper account of all the Receipt Books and collections made is to be kept by you in accordance with the instructions and procedure being laid down separately.

**[Minister for Education]**

It may please be ensured that the Receipt Books are collected by you subsequently from the persons concerned and duly scrutinised with a view to checking that the total amount shown to have been collected in a Receipt Book tallies with the total amount deposited with you.

4. Detailed instructions for maintaining the account of this Fund and relevant record, remission of amount and periodical intimation of the amount collected and recognition of efforts of outstanding workers in this regard would follow.

5. Please acknowledge receipt of this letter.

Yours sincerely,

(Sd.)

(J.D. SHARMA).

Shri/Smt. \_\_\_\_\_  
District Education Officer,

End. No.

A copy is forwarded to the Principals of all Government Colleges and Circle Education Officers in the State (by name) for information and immediate necessary action. They should render the maximum possible co-operation in making collections towards the Fund.

(Sd.)

(J.D. Sharma,)

Director of Public Instruction, Punjab.

**Instructions for collection and maintenance of the accounts of contributions to the Punjab Defence and Security Relief Fund by the Education Department**

## **NATIONAL EMERGENCY**

### **TOP PRIORITY**

In view of the present National Emergency, it has been decided that the Education Department should make efforts to collect subscription for the Punjab Defence and Security Relief Fund from the public in general and parents of the students in particular by appealing to their sense of patriotism. The following detailed procedure for collection and upkeep of its accounts has been prescribed for strict compliance :—

#### **I. AUTHORISED AGENCIES FOR COLLECTION**

The following Officers of the Education Department have been authorised to raise subscription to the said Fund on behalf of Government :—

- (1) All Principals of Government Colleges.
- (2) All Circle/District Education Officers.
- (3) All Heads of Government High/Higher Secondary Schools.
- (4) All Block Education Officers.
- (5) Registrar, Establishment of the Directorate.

All these Officers will collect subscriptions themselves as well as through their staff viz., Professors, Lecturers, Masters/Mistresses and Teachers.

The Heads of High/Higher Secondary Schools may also collect subscription through reliable resourceful and senior students of their colleges and schools. For this purpose, a Committee consisting of two senior masters, two students and the Principal/Headmaster will be constituted. The students nominated by this Committee will collect subscription in sealed boxes issued by the Committee, Brooke Bond boxes would do,

Each box should be properly sewn with strong cloth and sealed at various places by two types of different seals. One seal should remain in the custody of the Head of the institution and the other with one senior member of the Committee. A proper record should be kept of the boxes issued to various students. The contents of each sealed box should be taken out by the Headmaster/Principal in the presence of the Committee members. The account of its contents should be kept in a separate register in the following form :

Serial No.	Date of opening box	Name of the students who made collection	Amount	Attested by the Principal/ Headmaster	Signature of Committee Members as witness
1	2	3	4	5	6

Rs

A regular receipt for the consolidated amount collected in each box should be issued by the Principal/Headmaster to the leader of the student-group, who collected the amount.

## II. RECEIPT BOOKS

Every D.E.O. will be supplied printed and numbered receipt Books containing twenty receipts. He will issue these Receipt Books to all authorised agencies mentioned above according to their demand and keep a detailed account of Receipt Books issued to various persons in the following form :—

Serial No.	Receipt Book No.	Date of issue	To whom issued	Signatures of the recipient	Attested by the Issuing Authority
1	2	3	4	5	6

Every authorised agency is required to countersign all the blank receipts in Receipt Book before bringing it into use in order to establish genuineness of the receipts. These authorised agencies will further issue one Receipt Book to each member of their teaching staff and a few resourceful, reliable Senior College students for collection of subscription. Each person receiving the blank Receipt Books will be required to count all the twenty receipts contained in it and record a count certificate of correctness on its fly leaf. The authorised agency will also keep detailed account of Receipt Books in the form mentioned above. Receipts Books to Middle School Headmasters will be supplied direct by the D.E.O. Primary School teachers will get Receipt Books from their respective Block Education Officers, through the Heads of the Centre Schools who will receive them from their respective Block Education Officers.

[Minister for Education]

## III. COLLECTIONS

No collection should be accepted without the issue of a regular receipt by the official receiving the subscription. No receipt should be issued for less than one rupee. A collective receipt exceeding one rupee may be issued in case a subscription of individual donor falls short of one rupee. Every official making collections shall hand over his collections on every Wednesday to the Officer from whom he received the Receipt Book and obtain a simple receipt in a separate note Book regarding deposit of the collection. As soon as his Receipt Book is completed, he/she should render the account of his collections to the officer concerned in the following form and also hand over counterfoils of Receipt Book to him/her for record.

Account of Receipt Book No. \_\_\_\_\_.

Date	Receipt No.	Amount
Collections		
		Rs
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
Total		

## Amount paid on

**Abstract**

..

Nil

**FORM 'A'**

**Receipt**  
**Book No.**

**Receipt  
Book No.**

*Receipt*  
*Book No.*

Date \_\_\_\_\_

**And so on**

**Total**

Name of the Collector

Name of Collector

Name of Collector

1

2

3

4

5

6

### Receipt-wise account of collections

**Receipt  
No.**

**Receipt  
Book No.**

Receipt  
Book No.

Receipt  
Book No.

**Total**

1.

**2.**

**3.**

[Minister for Education]

Receipt No.	Receipt Book No.	Receipt Book No.	Receipt Book No.	Total
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Total	..			
<i>Deduct—</i>				
amount received				
Balance	..			

The Primary School teachers will hand over their collections to centre teacher once in a week, on every Wednesday. Every Centre teacher will keep account of the amount received by him in the manner prescribed above and pass on the same to the concerned B.E.O., the next day for consolidation. All Professors, Lecturers, Masters, Teachers of Colleges and High, Higher Secondary Schools, will similarly render their accounts and collections to their respective Principals and Headmasters. The Headmasters of Middle Schools will render account of their collections direct to their D.E.Os. on every Wednesday.

All the authorised agencies will further communicate the amount collected by them weekly on Fridays to respective D.E.O. who will consolidate collections for the

*Statement of collections of D and S. Fund for the week ending  
(Wednesday)*

**These statements will further be consolidated in the Directorate on every Monday.**

Every D/D Officer of the Department who is a collecting agency will pass on his collections when their amount exceeds Rs 200 to the respective D.E.O. by drafts in favour of the D.E.O. All D.E.Os. will open Bank accounts with State or any other local Bank and deposit all type of receipts, viz., cash, cheques and drafts, etc. in the said account. Cheques and Draft received by any collecting agency should be in favour of the D.E.O. concerned only.

Every D.E.O. receiving Fund collections from various sources is to maintain a separate cash account in Form PFR-I and observe rules analogous to rules 2.2 to 2.7 of Punjab P.F.R. Vol. I, Part I. He should also maintain a Ledger Account in respect of every authorised agency for collection.

All authorised agencies who obtain Receipt Book from their respective D.E.Os. will return all counterfoils—used or unused—to them. They will also furnish detailed account of their collections on Form A and B mentioned above under para III-Collections. The D.E.O. will keep them in record after check.

The Account of all these collections will be open to inspection by an official authorised by the Department.

No expenditure is permissible to be incurred out of this Fund except bank charges incurred on obtaining bank drafts for remittance of collections from one place to another.

It may please be noted again that these collections are apart from the contribution of one day salary to be made by every employee of the Department and the contributions to be realised from students as per instructions contained in this office circular No. 10/7-65-OAI(5), dated 9th September, 1965.

*Recognition*

The services of officials who put in special efforts to collect maximum amount of contributions towards this fund will be recognised by Government by grant of appreciation letters and even with advance increments.

**Hostel Building for Government College, Narnaul**

**\*9265. Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the date when the Government College, Narnaul, started functioning ;
- (b) whether the said college has got its own building for hostel purposes ; if not ; the time by which one is likely to be constructed ;
- (c) the total number of college students of the said college at present in a rented building at Narnaul ?

**Shri Parbodh Chandra :** (a) From the Academic Session of 1954

(b) No, when the finances of the State will permit.

(c) 17

**Languages Department**

**\*9449. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the Languages Department which has been functioning for the last 9 years is still a temporary Department ; if so, the reasons for which it has not so far been made permanent ;
- (b) The time within which the said Department is likely to be made permanent ?

**Shri Prabodh Chandra :** The requisite information is laid on the Table of the House.

(a) Yes.

The Department of Languages came into existence as a result of integration of the Languages Department of the erstwhile Punjab and Punjabi Department of the erstwhile Pepsu, on merger of these two States on 1st November, 1956. The Punjabi Department of the erstwhile Pepsu was made permanent on the 11th August, 1956, whereas the Languages Department of the erstwhile Punjab remained temporary upto the date of merger. The question with regard to the character of the integrated Department whether temporary or permanent came on the surface, when the Finance Department, while examining the proposal of the Department for the conversion of five years old temporary posts into permanent ones, treated the Department as a temporary organisation in its advice dated 24th July,

1962, and desired that the case be taken to the Committee of Officers constituted for the purpose. The Chief Secretary was requested to advise whether the Department was to be treated as permanent or temporary. In reply on the 6th May, 1963 he informed that the Punjabi Department of the erstwhile Pepsu ceased to exist on the merger with the Languages Department of Punjab and, therefore, the integrated Department of Languages could not be treated as permanent, unless specifically declared as such by Government. The proposal remained pending due to the National emergency prevailing in the country, till the Officers, Committee again resumed its working in early, 1964, and after examining in its meeting held on 3rd August, 1965, agreed to recommend the proposal of the Administrative Department. The case is still pending for final decision.

(b) As early as possible.

**श्री फतेह चन्द बिज :** क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि इस महकमे को पक्का करने के लिये मामला 10 साल से लटक रहा है, इस के अलावा इस डिपार्टमेंट को पक्का करने के लिये एडवाइजरी कमेटी की भी रिपोर्ट आ चुकी है और इन चीजों को सामने रखते हुए यह डिपार्टमेंट कब तक पक्का कर दिया जाएगा ?

**Education Minister :** Sir, the whole matter is being looked into and an early decision will be taken.

**कामरेड राम प्यारा :** क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि किसी महकमा को पक्का करने के लिये सरकार ने क्या पालिसी बनाई हुई है ? कई डिपार्टमेंट्स के अन्दर 5 साल के अन्दर अन्दर एम्पलाइज पक्के कर दिए जाते हैं और कई डिपार्टमेंट्स के अन्दर 9 साल तक भी लोग पक्के नहीं किए जाते । इस की क्या वजह है ?

**मंत्री :** कई कर्मचारी प्लैंड स्कीमों के अन्दर काम करते हैं और कई नान-प्लैंड स्कीमों के अन्दर काम करते हैं । कई ऐसी स्कीमों हैं जहां पर सालहा साल कंटीन्युएंस की मंजूरी लेनी पड़ती है । इन के लिए कई अन्य जगहों से रुपया सरकार के पास आता है । जब तक वह डिपार्टमेंट्स हमें इन्हें पक्का करने के लिए कह नहीं देते तब तक इन को पक्का नहीं किया जा सकता ।

**श्री फतेह चन्द बिज :** क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि यह डिपार्टमेंट किस स्कीम के तहत चल रहा है ?

**मंत्री :** यह डिपार्टमेंट प्लैन और नान-प्लैन स्कीमों दोनों स्कीमों के अधीन आता है ।

**श्री फतेह चन्द बिज :** क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस डिपार्टमेंट को न पक्का करने की वजह यह है कि यह डिपार्टमेंट दोनों स्कीमों के अधीन चल रहा है ?

**मंत्री :** इस डिपार्टमेंट को नज़र अन्दाज़ नहीं किया गया । अगर आप इस के बारे में फिगरज़ देखें तो आप को पता चलेगा कि इस डिपार्टमेंट के खर्च में काफी इज़ाफा हुआ है । पहले इस डिपार्टमेंट को हिन्दी और पंजाबी भाषा को समृद्ध करने के लिये 3,500 रुपए दिए जाते थे लेकिन अब इस की राशि 12 लाख के लगभग है । इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि इस डिपार्टमेंट को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा रहा है ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਘੋਸ਼ :** ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸੇ ਕਰ ਕਰ 12 ਲਾਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤੀ ਭੀ ਮਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕੀ ਹੇਝੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਲੇ ਛੋੜ ਕਰ ਇਸ ਕਾ ਕਰ ਕਰ ਕਰ ਕੀ ਆਇ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਜਨਾਬ ਆਲੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਸ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁਟਦੀ ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ :** ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

**ਮੰਤਰੀ :** ਹਾਂ ਜੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਏਲਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### Grades of pay of employees of Government Ayurvedic/Allopathic Dispensaries.

**3191. Comrade Makhaan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) Whether it is a fact that the grades of pay of the employees of the Government Ayurvedic Dispensaries and the Allopathic Dispensaries in the State are different ; if so, the reasons therefor ;
- (b) the qualifications prescribed for the employees working in the Government Ayurvedic/Allopathic dispensaries at present alongwith their grades of pay and the nature of duties entrusted to each?

**Shrimati Om Prabha Jain :** (a) Yes ; due to different professional qualifications and duties.

(b) A statement containing the requisite information is enclosed.

**Statement Showing the categories of Medical Personnel employed in Allopathic/Ayurvedic Dispensaries, their qualifications and grades of pay, etc.**

***Allopathic Dispensaries***

Designation of the post	Qualifications	Grade of pay	Duties
1	2	3	4
1. Assistant Medical Officers	M.B., B.S. (Selection Grade)	Rs. 400—20—600	1. To control the administration of the Dispensary staff
Ditto	L.M.S.	150—10—200/15—275/15—380	2. Examination, diagnosis and treatment of patients attending the Dispensaries indoors as well as outdoors
Ditto	L.M.S. with F.Sc. (Medical Group) or its equivalent or higher qualifications	To start at Rs. 200 in the scale 3. of 150—10—200/15—275/15—380	3. To undertake the minor operation, emergencies, medicolegal work
			4. To correspond with the Chief Medical Officer and other higher officers where and when necessary
			5. To attend the history of both private and Public sector, etc.
2. Pharmacist	(a) Matric with Science (Physics or Chemistry)	75—5—100/5—125	1. Pharmacological work e.g., dispensing of mixtures and medicines, performing of injections and Dressing etc
	(b) Is a registered Pharmacist under section 30(a) or 31(e) of the Pharmacy Act, 1948	..	2. Clerical work regarding purchase of medicines. Verification and disposal of other routine work e.g., maintenance of

[Minister for Health]

Designation of the post	Qualifications	Grade of pay	Duties
1	2	3	4
	or under section 32 of the Act <i>ibid</i> provided that such persons :—		stock register in the Hospital/Dispensaries
	(i) Shall hold a degree or Diploma in Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or a Chemist and Druggist Diploma of a recognised University or Institution as the case may be or prescribed qualifications granted by an authority outside		3. Helping the Assistant Surgeon, in clerical work e.g. (a) Hospital admissions. (b) Hospital discharges. (c) Statistic work. (d) Routine correspondence (e) Contingent bills. (f) Diet bills (g) Preparation of monthly pay bill etc., etc.
	(ii) has passed an examination recognised as adequate by Government for compounders or Dispensers or Pharmacists		In actual practice a pharmacist apart from pharmacological work, is a general assistant to the Medical Officer
3. Dai	Trained Dai	32—1—42	To attend to the confinement cases.
<i>Ayurvedic Dispensaries</i>			
1. Vaidyas/Hakims	A diploma or Degree in Ayurveda 150—10—200/15—275/15—380 1. To control the administration of the or Unani Tibb of any recognised (five years) dispensary staff. University or Board of Indian 120—8—200/10—300 System of Medicine estab- (four years) lished by Law in India or 100—8—220/10—250 any teaching institution (three years) recognised by Government		2. Examination, diagnosis, and treatment of patients attending the dispensaries in outdoor 3. To correspond with the Chief Medical Officers and other higher officers where necessary.

4. To arrange and to disburse the salaries of dispensary staff.

5. To do all the clerical work of the Dispensary and maintaining of accounts of store and stock of the Dispensary.

To dispense with the prescribed medicine under the directions of Vaidya/Hakims Incharge

2. To do dressing and provide other facilities to the patients as directed by the Incharge.

3. To assist the Vaidya/Hakim in other multifarious duties of Dispensaries.

4. To maintain the accounts of medicines given to him for dispensing purposes and work out monthly balances thereof.

1. To attend to confinement cases.

2. Dispensers/Compounders      Qualified Unani or Ayurvedic      39—1—49  
compounder from any recognised  
Institution

Dai      Trained Dai      32—1—42

### Different grades of Pharmacy preparer and Ayurvedic/Unani Dispenser

**3200. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the grade of the Pharmacy Preparer in the Government Central Pharmacy, Patiala is higher than the grade of pay of an Ayurvedic/Unani Dispenser ; if so, the reasons therefor ;
- (b) whether it is also a fact that the qualifications prescribed for the post of Pharmacy Preparer are lower than those of an Ayurvedic/Unani Dispenser ; if so, the reasons for which grade/pay of the latter has not been revised ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** (a) Yes ; the posts are not identical.

(b) No ; the question does not arise .

### Timings of Ayurvedic/Unani and Allopathic Dispenser

**3201. Comrade Makhan Singh Tasikka :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that the working hours of the Ayurvedic/Unani dispensaries in the State are different from those of the Allopathic dispensaries ; if so, the reasons therefor ;
- (b) whether the Government has considered any proposal to introduce uniform timings in all the above mentioned dispensaries ; if so, the result thereof ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** (a) Yes. There was no Ayurvedic Directorate in Punjab before the integration of Pepsu and Punjab. The timings fixed by the Pepsu Directorate before integration were retained and are still continuing.

(b) The question of introducing uniform timings is being considered.

### Cases of workers received by Conciliation Officer, Ludhiana

**3202. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the particulars of the cases received by the Conciliation Officer, Ludhiana, from 1st January, 1965 to date through the Ludhiana Iron and Steel Workers' Union (Regd.) Millerganj, Ludhiana and the District Textile Workers' Union (Regd.) Millerganj, Ludhiana ;

(b) the dates when each of the cases referred to in part (a) above was received by the said Officer, the dates when each of the cases was decided and the decision in each case ;

(c) whether it is a fact that more than 150 cases of workers regarding the minimum wages disputes relating to March, 1965, are still pending with the above-mentioned Conciliation Officer, if so, the reasons thereof ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) & (b) Statements showing the requisite information are laid on the table of the House.

(c) There are 81 (and not 150) dispute cases of workers containing *inter alia* demand regarding minimum wages, pending with the Conciliation Officer, Ludhiana. Out of these the workmen of 24 factories disassociated themselves from the dispute or left service after having received their dues in full and final settlement. The parties were persuaded to refer the remaining 57 cases for voluntary arbitration. A final reply from the

union in this connection was received by the Conciliation Officer, Ludhiana, on 3rd January, 1966. The Conciliation Officer, Ludhiana remained on duty at Amritsar in connection with the disbursement of loan to industrial workers from 3rd January, 1966 onward almost continuously. As such he could not submit his final report.

## [Minister for Irrigation &amp; Power]

## Statement showing the particulars of the demand notices served through Ludhiana Iron and Steel Workers Union Ludhiana

Serial No.	Name of factory	Date of receipt of the demand notice	Date of disposal by Conciliation Officer	Recommendations of the Conciliation Officer	REMARKS
1	2	3	4	5	6
1	M/s Ludhiana Steel Rolling Mills, Ludhiana	14-1-65	24th February, 1965	Settled under section 12 (3)	
2	M/s Sital Metal Industries, Ludhiana	15-1-65	Report sent <i>vide</i> No. 3012, dated 27th March, 1965 the case	Recommended for rejection of	
3	M/s Bhoudhey Electric Engineering Co., Ludhiana	1-1-65	18th January, 1965	Settled under section 18(1)	
4	M/s Kailash Industry, Ludhiana	26-2-65	<i>Vide</i> No. 2915, dated 15th March, 1965	Recommended for rejection of the case	
5	M/s Deluxe Engineer Works, Ludhiana	15-4-65	10th May, 1965	Settled under section 12 (3)	
6	M/s P.K. Traders, Ludhiana	15-5-65	11th June, 1965	Referred for voluntary arbitration	
7	M/s Pretty Cycle Industry, Ludhiana	15-5-65	19th May, 1965	Withdrawn by the workmen	
8	M/s Sudarshan Engineering Works, Ludhiana	20-5-65	Report sent <i>vide</i> No. 3308, dated 5th June, 1965	Recommended for rejection	
9	M/s P. K. Traders, Ludhiana	4-6-65	11th June, 1965	Referred for voluntary arbitration	
10	M/s Sital Metal Industries, Ludhiana	14-6-65	2nd July, 1965	Settled under section 12(3)	
11	M/s Ganesh Engineering Corporation, Ludhiana	12-10-65	21st October, 1965	Ditto	

12	M/s Deluxe Engineering Works, Ludhiana	16-11-65	30th November, 1965	Ditto	..
13	M/s Jiwan Engineering Works, Ludhiana	19-11-65	21st December, 1965	Ditto	The Concilia- tion Officer, has been on duty for loan distribution at Amritsar since 3rd January, 1966 almost continuously.
14	M/s T. R. Chopra & Sons, Ludhiana	2-2-66	Pending	Pending	..

[Minister for Irrigation &amp; Power]

## Statement showing the particulars of demand notices served through District Textile Workers Union Miller Ganj Ludhiana

Serial No.	Name of the Factory	Date of receipt of demand notice	Date of decision	Recommendations of the Conciliation Officers	REMARKS
1	2	3	4	5	6
1	M/s Oswal Woollen Mills, No. 3, Ludhiana	18-1-65	Report sent to Labour Commissioner, vide No. 2735, dated 13th February, 1965	Recommended for rejection of the case	..
2	M/s Oswal Woollen Mills, No. 3, (Weaving Khata), Ludhiana	18-2-65	Vide No. 2987, dated 25th March, 1965	Ditto	..
3	M/s Owsal Woollen Mills, No. 3, (Spinning Khata,) Ludhiana	24-2-65	Vide No. 2986, dated 25th March, 1965	Ditto	..
4	M/s Kabir Dyeing, Ludhiana	2-3-65	22-3-65	Settled under section 12(3)	..
5	M/s International Woollen Mills, Ludhiana	6-3-65	7th April, 1965	Ditto	..
6	M/s Indian Shoddy Mills, Ludhiana	19-3-65	Vide No. 3311, dated 2nd February, 1965	Recommended for rejection of the case	..
7	M/s Gulshan Textile Mills, Ludhiana	19-3-65	Vide No. 3272, dated 20th May, 1965	Ditto	..
8	M/s Jaipal Weaving Factory, Ludhiana	22-3-65	Vide No. 3145, dated 20th April, 1965	Withdrawn by the workmen	..
9	M/s Parbhat Woollen Mills, Ludhiana	27-4-65	Vide No. 3310, dated 2nd June, 1965	Recommended for rejection of the case	..

10	M/s B. S. Textile, Ludhiana	..	27-4-65	<i>Vide</i> No. 3614, dated 3rd August, 1965	Ditto	..
11	M/s Gulshan Textile, Ludhiana	..	29-5-65	10th June, 1965	Settled under section 18(1)	..
12	M/s Swadeshi Karyala, Ludhiana	..	20-5-65	<i>Vide</i> No. 3309, dated 2nd June, 1965	Recommended for rejection of the case	..
13	M/s Kabir Dyeing, Ludhiana	..	8-6-65	<i>Vide</i> No. 3553, dated 24th July, 1965	Ditto	..
14	M/s Rajput Store, Ludhiana	..	14-6-65	28th July, 1965	Settled under section 12 (3)	..
15	M/s Ram Lal and Sons, Ludhiana	..	14-6-65	28th July, 1965	Ditto	..
16	M/s Girson Mills, Ludhiana	..	25-6-65	<i>Vide</i> No. 3558, dated 28th July, 1965	Recommended for rejection of the case	..
17	M/s Jawahar Textile, Ludhiana	..	25-8-65	<i>Vide</i> No. 3845, dated 10th September, 1965	withdrawn	..
18	M/s Sat Pal-Madan Lal, Weaving Factory, Ludhiana	..	16-9-65	<i>Vide</i> No. 3904, dated 24th September, 1965	Do	..
19	M/s Sethi Textile Mills, Ludhiana	..	10-9-65	<i>Vide</i> No. 4027, dated 20th October, 1965	Recommended for reference of the case	..
20	M/s Girson Mills, Textile Department, Ludhiana	..	13-10-65	<i>Vide</i> No. 4301, dated 24th December, 1965	Ditto	..
21	M/s Style Knitting Works, Ludhiana	..	1-11-65	13th December, 1965	Settled under section 12 (3)	..
22	M/s Cashmere Woollen Mills, Ludhiana	..	10-11-65	<i>Vide</i> No. 2, and dated 3rd January, 1966	Recommended for reference of the case	..
23	M/s Girson Mills Textile Department, Ludhiana	..	16-11-65	<i>Vide</i> No. 4303, dated 24th December, 1965	Recommended for reference	..
24	Ditto	..	22-11-65	<i>Vide</i> No. 4302, dated 24th December, 1965	Ditto	..
25	M/s Behari Textile, Ludhiana	..	6-12-65	Pending	..	The Conciliation Officer,

## [Minister for Irrigation &amp; Power]

Serial No.	Name of the Factory	Date of receipt of demand notice	Date of decision	Recommendations of the Conciliation Officers	REMARKS
1	2	3	4	5	6
26	M/s International Woollen Mills, Ludhiana	27-12-65	Pending		has been on duty for loan distribution at Amritsar since 3rd January, 1966 almost continuously
					Ditto

**Pay Scales of Radiographers working in different Hospitals**

**3203. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Health be pleased to state—

- (a) whether it is a fact that there are differences in the pay scales of the Radiographers working in the Rajindra Hospital, Patiala, the Medical Education and Research Institute, Chandigarh and the V. J. Hospital, Amritsar ; if so, the reasons therefor ;
- (b) the names, addresses and qualifications of the Radiographers at present working in the Hospitals mentioned above together with their pay scales in each case ;
- (c) the dates when each of the persons referred to in part (b) above first took charge of his post in the Hospital/Institute mentioned above ?

**Shrimati Om Prabha Jain :** (a) There is no difference between the pay scales of Radiographers working at Rajindra Hospital, Patiala and V. J. Hospital, Amritsar. However a post of Senior Radiographer in the scale of Rs 150—10—250 exists at V. J. Hospital, Amritsar. There is no post of Radiographer at the Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Chandigarh. However, posts of Senior /Junior Technicians (Radiology) and Senior /Junior X-Ray Technicians (Radiology) exist in this institution.

(b) & (c) A statement is attached herewith.

---

**Particulars of Radiographers working at Rajendra Hospital, Patiala**

Serial No.	Name	Address	Qualifications	Pay Scales	Date of join
1	2	3	4	5	6
				Rs	
1	Shri Khushi Ram Kapur	C/o Shri Chet Ram Kacha Patiala, Patiala	Matric with Science and Trained Radiographer	70—4—90/5—120	1-8-
2	Shri Suresh Kumar	C/o Shri Kirpa Ram, Kapurthala	Ditto	Ditto	30-6-
3	Shri Nirmal Bhatnagar	C/o Shri Bhagwan Sarup, 'B' Tank, Patiala	Ditto	Ditto	4-11-
4	Shri Vidya Sagar Sharma	C/o Shri Jagan Nath, Chatta Nanu Mal, Patiala	Ditto	Ditto	8-6-
5	Shri Mohan Lal Gupta	C/o Village and Post office Duddni, Tehsil Sunam, District Sangrur	Ditto	Ditto	1-5-6
6	Shri Baldev Singh	C. No. 843, Mohalla Khassian, Patiala	Ditto	Ditto	7-4-6
7	Shri Naubat Rai	House No. 243/8, Sirhindi Gate, Patiala	Ditto	Ditto	25-11-6
8	Shri Bishamber Nath	House No. 2460, Sachdeva Street, Fazilka	Ditto	Ditto	1-5-65
9	Shri Gurmail Singh	H/16, Rajindra Hospital, Patiala	Ditto	Ditto	6-12-63
10	Shri Raj Kumar Jain	C/o Shri Balraj Jain, Chatta Nanu Mal, Patiala	Ditto	Ditto	26-11-64
11	Shri Chaman Lal Jain	C/o Shri Keora Ram Jain, Chatta Nanu Mal, Patiala	Ditto	Ditto	

**Particulars of Radiographers working at V.J. Hospital, Amritsar**

Serial No.	Name	Address	Qualifications	Pay Scales	Date of Joining
1	2	3	4	5	6
Rs					
1	Shri Harbans Singh	X-Ray Department, V.J. Hospital, Amritsar	Matric with Science and Trained Radiographer	70-4-90/5-120	21-7-55
2	Shri Harnam Singh	Ditto	Ditto	Ditto	11-10-65
3	Shri M.K. Joshi	Senior Radiographer, V.J. Hospital, Amritsar	Ditto	150-10-250	1-8-34 (Promoted as Senior Radiographer with effect from 15th June, 1965)

## **Quota Holders of Wool Top and Art Silk in Amritsar District.**

**3204. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state the names and addresses of those who are getting quotas of wool tops and art silk in Amritsar district at present, together with the quantity thereof being given in each case ?

**Shri Ram Kishan :** There being no price/distribution control on art silk the question of its quota does not arise. The quota of wool tops is allotted to the units concerned by the Textile Commissioner, Bombay (Government of India) direct and the State Government have no information in this regard.

## **Implementation of Recommendations made by the Police Commission**

**3205. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the details of the recommendations of the Police Commission regarding —
  - (i) Gazetted Police officers ;
  - (ii) Inspectors, Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors of Police ;
  - (iii) Head Constables and Constables ;
- (b) the reasons for which the recommendations made regarding the Sub-Inspectors of Police have not so far been implemented ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) and (b) The Punjab Police Commission Report is a big and comprehensive Report involving administrative and financial implications. The recommendations are being examined one by one. It is not in the public interest to disclose the details of the various recommendations made in the Report at this stage.

## **Detenus Released on Parole**

**3207. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- (a) the names of the detenus detained under the Defence of India Rules in the State who applied for their release on parole jail wise during the period from the 1st December, 1965 to date, together with the dates of their applications, jail wise ;
- (b) the details of the reasons given by each detenus in his application such as attending marriages or other ceremonies etc. and the dates when such ceremonies were to take place ;
- (c) the names of the detenus out of those mentioned in part (a) above who were released on parole ;
- (d) the dates on which each of them was given information regarding the grant of paroles together with the details of the sureties demanded from each ;
- (e) the names of those who actually availed of parole and the dates on which they went on parole ?

**Sardar Darbara Singh :** (a—e) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

## Statement showing information in reply to part (a) to (e)

Serial No.	Name of detenu who applied for parole	Name of Jail	Date of submission of application	Date of receipt of application	Reasons for parole	Date of ceremony	Name of those who were released	Date of intimation	Details of sureties	Name of those who actually went on parole	Date on which went on parole
1	Kartar Singh	Hissar	27-1-66	29-1-66	To attend death ceremonies of his father-in-law	6-2-66	Kartar Singh	4-2-66	Two sureties of 10,000 each	Kartar Singh	5-2-66
2	Prem Chand Bhardwaj	Do	1-2-66	8-2-66	To attend to domestic affairs				Under consideration with the Government		
3	Harkishan Singh Surjit (His request for extension of parole on grounds ailment was, however, rejected)	Delhi	2-1-66	4-1-66	To attend marriage of his sister's daughter	29/30-1-66	Harkishan Singh	22-1-66	Two sureties of 10,000 each	Harkishan Singh	28-1-66
4	Vidya Dev Longowal Nabha		17-12-65	23-12-65	To attend marriage of his niece	16-1-66	..	13-1-66	Ditto	He refused to avail the parole that he will not be able to furnish sureties bonds in time	7-2-66
5	Chanan Singh Dhut	Sangrur	27-1-66	27-1-66	To attend marriage of his son	13-2-66	Chanan Singh	4-12-66	Ditto	Chanan Singh	7-2-66
6	Rachhpal Singh	Do	5-1-66	10-1-66	For participation in the election of Vice President of M.C., Hissar				It was not considered necessary by Government to allow him to participate in the election and as such it was rejected and necessary intimation was sent on 22nd November, 1966		

[Home Minister]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Satya Mandan	Sangrur	28-1-66	1-2-66	For illness of his wife	..	Granted parole by Government on 21st February, 1966	Gian Singh	31-12-65	Ditto	Gian Singh	5-1-66
8	Gian Singh	Do	30-12-65	31-12-65	In connection with death ceremony of his mother	..						
9	Dalip Singh	Do	19/20-1-66	20-1-66	In connection with death of his father	..	Granted parole by Government on 21st January, 1966					
10	Makhan Singh Tarsikka	Patiala	7-1-66	10-1-66	In connection with his illness	..		Makhan Singh	15-2-66	Do	Makhan Singh	25-2-66
11	Gurbax Singh	Do	6-1-66 7-1-66 13-1-66 11-2-66	14-1-66 17-1-66 29-1-66 15-2-66	In connection with marriage of his brother's daughter			Not released				

**Establishment of Heavy Industry in Punjab**

**3209. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether the Government sent any memoranda to the Union Government during the year 1965-66 for the establishment of some Heavy Industry in the State ; if so, the contents thereof ;
- (b) whether the Government have achieved any success in this respect ; if so, to what extent and the details thereof ; if there has been no success, the details of the replies received from the Union Government be placed on the Table of the House ?

**Shri Ram Kishan :** (a) Yes. A copy of D.O. No. LMI/21/Misc/5381-A, dated the 9th February, 1965 to the then Prime Minister of India is laid on the Table of the House.

(b) Yes. We have been assure that Punjab will get its due share so far as the location of central public sector projects is concerned.

*Copy of D.O. No. LMI/21/Misc/5381-A, dated the 9th February, 1965, from Shri Ram Kishan, to Shri Lal Bahadur Shastri, Prime Minister, Government of India, New Delhi*

You will kindly excuse me for bringing to your notice the fact that there is a widely-held feeling of grievance in this State that the principle of balance regional development is not being adequately observed in determining the location of new central industrial projects in the country. It is felt that the Punjab State has been allocated disproportionately meagre share out of the centrally sponsored industrial projects. During the period of the first three Plans, the total financial outlay on these projects aggregated to about Rs 2,130 crores. As against this the Punjab was allotted only two projects with the total capital investment of about Rs 30 crores which constituted only 1.4 per cent of the total investment. Even out of these two projects, one namely the Nangal Fertilizer Factory is more a liability than an asset to the State. This factory is intensively power based and takes away a good portion of the power produced at Bhakra, thereby thwarting new industries from coming up in the State and in its turn it neither gives any large scale employment nor generates any new or ancillary industrial growth.

2. It is sometimes argued that investment in Steel Plants, which must necessarily be located in close proximity to iron-ore and coal deposits, should not be reckoned while calculating the share of central investments in various regions. You will kindly agree that this logic is entirely fallacious and at several forums it has been conceded at the highest level that location of central projects should be so selected, that as far as possible an equitable share of the central investment in public sector projects, should fall to the share of various States; and that the areas where deposits of iron-ore, coal or oil do not occur, should receive other central projects which do not need to be located necessarily near such deposits. Consequently it is only fair to expect that States like Punjab which cannot get Steel Plants or oil refineries, should get projects like Heavy Electricals, Compressors Plants and the like, so as to raise the central capital spending to an equitable size.

3. During the period of the first three plans, the State's industrial growth even in the private sector has been hampered owing mostly to the situation obtaining as a consequence of partition. Thus, with inadequate allocations out of the public sector projects and slow growth rate in the private sector, the State has continued to remain industrially very backward and the State's economy continues to be heavily based on agriculture. Nearly 47 per cent of the net output and 66 per cent of employment is accounted for by agriculture and allied activities. The contribution of industry is only about 11 per cent on output and 9.3 per cent in employment. The percentage of indus-

[Chief Minister]

trial employment in the organised sector in the State comes to only about 0.6 as against over 2 per cent in West Bengal, 1.97 in Maharashtra and 1.72 in Gujrat, Our *per capita* industrial investment also stands at the low level of Rs 42.51 as compared to Rs 153.54 in West Bengal and Rs 170.54 in Maharashtra.

4. The Fourth Plan period is likely to be of decisive importance in determining the prospects of industrial progress in this State and failure to build up a sufficiently strong industrial base during this period might perpetuate the State's backwardness in this sphere almost for ever. Our existing industrial economy is dominated by small scale industries, which in the future will be able to survive not independently but only as ancillary to large scale and heavy industries.

5. We have made detailed representations, supported by facts and figures, some time back to Government of India, for the location of three new projects in the State viz., heavy electricals, ball bearings and air compressors and heavy pumps. We have abundance of engineering skills and an ambitious programme of power generation. We also feel that for sound development of agriculture the three projects already suggested by us a few more will need to be located in this region. We cannot hope to be able to persuade private sector to establish heavy engineering projects in the State and feel that unless we got an equitable share of central public sector projects, our entire programme of development of agriculture, rural electrification and small scale industries will become lopsided and weak.

6. From the papers recently circulated to the members of the Sub-Committee on Industry and Power of the National Development Council, it appears that location of a large number of central projects, is yet to be decided. We strongly feel that various considerations involved in deciding locations are as favourable to us as they can be said to be in case of most of the other States. With an ambitious hydroelectric programme coming up in Punjab, you will kindly agree that we are not in any way worse off than, for example, Hardwar in U.P., in the matter of location of a future Heavy Electrical Project.

7. I understand that in connection with locating the proposed Compressors and Pumps Plant with Soviet collaboration, our claim seems to have been ruled out even without a visit by the Technical team of visiting experts.

I am sorry to have taken your time by writing to you at some length, but I would have done less than justice to our case if I had not brought to your personal notice our feelings of being persistently ignored in the matter of location of Central Projects. I am enclosing a statement listing the projects location for which is yet to be decided and for which we are as well placed as any other State. I shall be most grateful for your kindly asking for a sympathetic examination of our claims being made.

I am also addressing Shri T.N. Singh, Union Minister for Industry on this subject.

With kindest personal regards,

### Research for Industrial Development in the State

**3210. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government, after having studied the relevant data in detail, appointed any experts or specialists or any adhoc Committee to carry on research for the industrial development of Punjab during the period from 1952-to date ; if so, the detailed particulars thereof and the nature of recommendations made by such body to the Government ;

(b) if the answer to part(a) above be in negative, the reasons therefor ?

**Shri Ram Kishan :** (a) A techno-economic Survey of Punjab including that for industrial development was got conducted by the National Council of Applied Economic Research, New Delhi in the year 1959-60 with a view to planning out strategy and programme of industrial development during the Third Five-Year Plan. Similarly for the Fourth Plan period also, the services of this very agency have been secured for advice on industrial planning. A copy of the Techno-economic survey of Punjab has already been supplied to the Vidhan Sabha Library. The report of the Council for Fourth Plan Industrial programmes is being finalised and copy thereof will also be supplied to the Vidhan Sabha Library when printed.

(b) In view of the reply to part (a) above, the question of giving any reasons therefor does not arise.

#### **Expenditure incurred on Package Programme launched in district Ludhiana**

**3214. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the details of the expenditure so far incurred by the Government on the Package Programme launched in district Ludhiana in connection with Agriculture together with the details of the benefits that have accrued there from, year-wise ;

(b) whether the agriculture Department or the officer incharge of the Package Programme Incharge has submitted any review report to the Government in connection with the said programme for the year 1964 or 1965 ; if so, a copy of the same be placed on the Table of the House ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Part I :—

(Rs. in lacs)			
1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
1.60	6.29	8.61	8.60
1964-65	1965-66	(estimated)	
9.22	12.72		

**Part II.**—The production of food grains and cash crops has considerably increased. The details are given in a statement laid on the Table of the House.

(b) Part I. : Yes.

**Part II :** The document is too lengthy and it is considered that the time and labour to be spent in supplying copies thereof will not be commensurate with the benefits to be derived therefrom. However, any specific information needed can be supplied.

Statement referred to in part (a) of the reply

Name of crops.	Total production in lakh maunds					Remarks
	1960-61	61-62	62-63	63-64	64-65	
1. Food Crops.						
Maize	12.4	20.7	14.4	25.0	18.9	The production of gram decreased due to the decrease in the unirrigated area on account of droughts etc.
Wheat	33.6	44.4	45.1	65.3	78.4	
Gram	4.5	5.3	4.2	3.7	4.2	
Wheat + Gram	19.1	22.3	19.9	18.2	21.4	
	71.6	92.7	81.6	112.2	122.9	
2. Cash Crops						
Cotton	5.6	6.0	3.6	7.5	5.5	The production during 1962-63 decreased due to drought and locust attack during Sept. 62.
Groundnut	6.7	8.3	8.6	15.2	21.4	
	12.3	14.3	12.2	23.1	26.9	

### Development of Co-operative Farming in the State

**3215. Comrade Makhan Singh Tarsikka ;** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

- the details of the targets fixed by the Government for the development of co-operative farming in the State during the last three Five-Year Plans together with the extent upto which those targets have been achieved so far ;
- the details of the plans formulated by the Government to encourage people in this direction in each of the said Plans and the extent to which these have been accomplished ;
- the details of the amounts spent on Co-operative Farming during the period mentioned in part (a) above during each plan period ;
- the details of special steps, if any, proposed to be taken by the Government with regard to Co-operative Farming during the Fourth Five Year Plan and the total amount to be spent thereon under this plan together with the details of the expenditure earmarked for the purpose under various heads ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** The requisite information is furnished as under seriatim :—

(a)

Plans	<i>Targets fixed</i>		<i>Targets achieved</i>		
	Physical (Societies)	Financial (Rs in lacs)	Physical (Socie- ties)	Financial (Rs in lacs)	
Ist Plan	..	..	..	..	
IIInd Plan	..	350	9.10	403	6.79 (187 societies assisted)
IIIrd Plan	..	600	67.51	777	60.59 (541 societies assisted)
Total	..	950	76.61	1,057	67.38 (728 societies assisted)

(b) (i) In the First Five Year Plan—Nil.

(c) (ii) Financial assistance to the extent of Rs 4,000 detailed as under, was provided for a co-operative farming society during a single year in the 2nd Five-Year Plan :—

(i) Managerial subsidy	..	1,200
(ii) Godown subsidy	..	1,000
(iii) Subsidy for purchase of machinery	..	1,000
(iv) Subsidy for fertilizers	..	800
Total	..	4,000

(iii) In the Third Five Year Plan, the quantum of financial assistance, details of which are given below, has been raised to Rs 12,200 per society :—

(i) Managerial subsidy	..	1,200 over 3 years.
(ii) Godown assistance	..	5,000(25 per cent subsidy 75 per cent loans).
(iii) Share capital	..	2,000 on matching basis
(iv) Medium term loan	..	4,000
		12,200

## [Minister for Irrigation and Power]

Further-more instructions have been issued by the Punjab State Electricity Board that while giving electric connections for tube-wells preference may be given to the cooperative farming societies.

(c) 1st Plan	.. Nil
II Plan	.. Rs 6.79 lacs.
IIIrd Plan	.. Rs 60.59 lacs.

(d) During the period of Fourth Five-Year Plan, it is proposed to give financial assistance to 125 cooperative farming societies to the extent of Rs 14.97 lacs giving each society the following assistance : —

(i) Managerial subsidy	.. Rs 1,200 over 3 years.
(ii) Godown assistance	.. Rs 5,000 (25 per cent subsidy 75 percent loan)
(iii) Share capital	.. Rs 2,000 on matching basis
(iv) Medium term loan	.. Rs 4,000

**Paper Factory Near Nangal**

**3216. Comrade Makhan Singh Tarsikka:** Will the Chief Minister be pleased to state—

- the details of the Paper Factory proposed to be set up near Nangal;
- whether the proposed factory is being set up in public sector; if not, the reasons therefor;
- whether the said factory is being set up in private sector; if so the details of the agreement, if any, signed by the Government with some firm be placed on the Table of the House?

**Shri Ram Kishan :** (a) A newsprint mill with a daily capacity of 100 tonnes of newsprint is to be set up at Kiratpur by M/s Shree Gopal Paper Mills Ltd. (a Concern of M/s Karam Chand Thapar & Bros) who hold a licence from the Government of India, in collaboration with M/s Abitibi-Power and Paper Co. Ltd. of Canada. The total cost of the project is estimated at Rs 10 crores. According to the tentative programme drawn up by the licencees, the factory is expected to start production by the end of 1969.

(b) No. There is no bar to such an industry being set up in the private sector. Since a private party was willing to set up this project it was not considered necessary to take it up in the public sector.

(c) Yes. No. agreement has yet been executed with the licensees. Details of the agreement are being finalised.

**Industrial development of the State in the Fourth Five Year Plan Period**

**3217. Comrade Makhan Singh Tarsikka:** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the special steps proposed to be taken during the Fourth Five Year Plan period for the industrial development of the State together with the details of the particular industries which are likely to be set up under the said Plan?

**Shri Ram Kishan:** The industries in the un-organised sector, i.e. small scale sector, would be developed through provision of facilities regarding built-up factory accommodation, developed land, training, management and marketing, preparatory and processing facilities, finance and research. In this sector of industries, it is difficult to give details of the particular industries but broadly preference would be given to the development of defence-oriented industries, agro-industries, export-oriented industries, and ancillary industries.

2. In the large scale sector, there would be a three dimensional policy i.e. (i) pressing Punjab's claim for allocation of more central projects (ii) institutionalisation of enterprise and (iii) provision of incentives to entrepreneurs for establishment of such industries. For the objective at (ii) above, an Industrial Development Corporation has been set up with an authorised capital of Rs. seven crores. The industries which are tentatively proposed to be taken up by the Corporation are seamless steel tubes, steel castings, steel forgings, power tillers, machine tools, heavy electricals and oscilloscopes. It is further proposed to establish a Pig Iron Plant with a capacity of one lakh tons per annum and a Coke Oven Plant and textile mills in the State Cooperative Sectors. The incentives which would be provided at the 15 focal points include provision of land on no-profit no-loss basis price of which will be recoverable in easy instalments, provision of finance and capital, Special Concession to power based industries, refund of sales tax on raw materials purchased by industry and on its finished products, and grant of subsidy for undertaking feasibility studies, etc. The particular industries which would be established at the Focal Points cannot be indicated at this stage as the prospective entrepreneurs would be free to select prospective industries of their own choice.

**Taccavi Loans given in Tehsil Narwana, district Sangrur.**

**\*3218. Shri Fakiria:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- (a) the amount sanctioned for advancing as taccavi loans during the year 1955-56 in tehsil Narwana, district Sangrur, together with the number of persons who have been given such taccavi loans ;
- (b) the amount of loans advanced to the Harijans out of the said amount ?

**Sardar Harinder Singh Majra** (a) & (b) A statement is laid on Table of the House.

**Statement**

Kind of loan	Amount disbursed during the year	No. of persons who have been disbursed this loan	Amount disbursed to Harijans	
			Number of persons	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Rs			
1. Seed, fodder & Cattle ..	10,000	50	22	6,050
	*3,000			
2. House Repair rural ..	1,000	1	1	1,000
3. Tubewell ..	48,000	8	..	..
4. Percolation wells ..	13,000	7	1	2,000
	75,000	66	24	9,050

\*The amount of Rs 3,000 has been placed with the Tehsildar Narwana recently and this amount is being disbursed by him.

**Complaints received from the Residents of village Tellewal, district Sangrur, against a Canal Patwari**

**3219. Comrade Gurbakhsh Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether the authorities of the Bhatinda division and the Ludhiana Circle of the Canal Department have received certain representations from (i) the residents of village Tellewal tehsil Barnala, district Sangrur against Sardar Gur Dev Singh, Canal Patwari of Bhotna area in the month of December, 1965 or January, 1966 (ii) the village Panchayat of the residents of village Chungan, tehsil Barnala, district Sangrur against the Patwari mentioned above, during the month of December, 1965 or January/February, 1966 in which they have alleged that the said Patwari has recommended, realisation of abiana on unjust basis after doing wrong girdawaris?
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the number of such representations received and a copy of each of them be laid on the table of the House with the details of the action if any, taken thereon;
- (c) whether it is a fact that the 'Khitoni' being used for the realisation of abiana has neither been checked or approved by any prescribed authority;
- (d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, whether the realisation of the said wrongly assessed abiana has been stopped; if not, the reasons therefor;
- (e) whether any enquiry has been held by some higher authority in this connection, if so, when and by whom;
- (f) whether the result of the enquiry have been conveyed to the complainants?

**Chaudhri Rizaq Ram:** (a) Yes.

(b) These applications are with the field staff for check in the field, which are being obtained and will be supplied.

(c) No.

(d) Question does not arise.

(e) The enquiry is being made by Deputy Collector and the Sub-Divisional Officer-in-charge.

(f) In view of (e) above, question does not arise.

**Complaints from Residents of village Dhurkot Rans in Tehsil, Moga, district Ferozepore.**

**3220. Comrade Gurbakhsh Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the number of residents of village Dhurkot Ransin, tehsil Moga, district Ferozepore, who have sent representations to the authorities of the Bhatinda division of the Canal Department during the year 1965 and January, 1966 alleging that wrong and unjust abiana has been recommended to be realised from them;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the names of the complainants, the dates when the said representations were received by the Department and the details of the action, if any, taken thereon;
- (c) whether the results of the enquiry have been intimated to the complainants?

**Chaudhri Rizaq Ram:** (a) Nine applications were received. Total number of persons mentioned in all the applications is 12.

(b) Name of complainant	Date of receipt of application	Action taken by the Department
1. Shri Ghamund Singh, son of Shri Ishar Singh and Banta Singh, son of Bishan Singh	May, 1965	It was rejected as the irrigation done was mixed one from canal and as well as from well. The assessment was correct.
2. Shri Lal Singh, son of Shri Kartar Singh	May, 1965	Ditto
3. Shri Bhadur Singh, son of Shri Mit Singh	May, 1965	Ditto
4. Shri Kartar Singh, son of Shri Waryam Singh	May, 1965	Application was found to be incorrect. It was in fact for remission due to failure of crop which was time-barred and hence rejected.
5. Sarvshri Dalip Singh and Bachittar Singh, sons of Bakhtawar Singh	May, 1965	On investigation, area was found to be actually irrigated by canal water and hence rejected.
6. Shri Kartar Singh	.. May, 1965	The application was wrongly submitted and withdrawn by the applicant subsequently. Area was actually found to be canal irrigated.
7. Shri Paul Singh, son of Shri Santa Singh	May, 1965	6.50 acres area out of total of 12.50 acres under dispute, was actually found to be canal irrigated and rest 6 acres was irrigated by well and for which approval has since been accorded by the Divisional Canal Officer for remission of abiana.
8. Sarvshri Jita Singh and Paula Singh sons of Mehar Singh	September, 1965	On investigation, area was found to be canal irrigated, hence rejected.
9. Shri Kaka Singh, son of Shri Mehar Singh	December, 1965	The contents of this application tally with those of S. No. 8 above and has been rejected.

#### **Arrears of T.A. of J.B.T. Teachers of district Gurdaspur**

**3221. Comrade Gurbakhsh Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state—

- (a) the total amount of arrears of T.A. due to J.B.T. Teachers of district Gurdaspur for the year 1961 together with the names of the said teachers and the amount of T.A. due in each case;
- (b) whether any teacher out of those mentioned in part (a) above has requested the department in writing to expedite the payment of his arrears of T.A. for the year 1961; if so, when and the details of the action, if any, taken thereon?

**Shri Prabodh Chandra:** (a) There is only one case in respect of Shri Lal Singh, J.B.T. teacher, Government Primary School, Khoje-ki-Chack on account of his transfer from District Ferozepore in 1961. The amount of T.A. claim is about Rs 70.

(b) Yes. The date on which he represented will be intimated later on. The original T.A. bill was lost in transit and the teacher was asked by the District Education Officer, Gurdaspur to submit a duplicate claim. A duplicate bill has since been sent by the Teacher which has been returned to him for removing certain defects and furnishing some documents for taking further action.

**Arrears of Pay of Ex-teachers in district Ferozepore**

**3222. Comrade Gurbakhsh Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the number of teachers in district Ferozepore whose arrears of pay are still outstanding while their services have been terminated by the Government ;

(b) the names of the said teachers and the amount due to them together with the dates when their services were terminated;

(c) the reasons for the non-payment of their arrears of pay?

**Shri Prabodh Chandra :** (a) Information regarding 10 cases has been received so far and the rest is being collected.

(b) The information regarding these ten cases is as under:

<i>Name</i>	<i>Date of termination of service</i>
(1) Shri Chaman Lal	.. Ist May, 1963
(2) Shri Kirpal Singh	.. 28th February, 1963
(3) Shri Ajit Singh	.. 28th July, 1963
(4) Shri Phul Chand	.. 2nd February, 1963
(5) Shri Ravinder Nath	.. Ist February, 1963
(6) Shri Harbans Singh	.. 18th November, 1963
(7) Shri Joginder Singh	.. 19th December, 1963
(8) Shri Hardit Singh	.. 15th December, 1963
(9) Shri Guru Dutt	.. 19th December, 1963
(10) Shri Lal Singh	.. 19th December, 1963

The information regarding the amount due, if any, in these cases and the remaining ones is under collection and will be supplied when received from the field.

(c) The reasons are being ascertained and will be intimated to the Hon'ble Member in due course.

**Protected Hand Teachers in district Ferozepore**

**3224. Comrade Gurbakhsh Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the number of "protected hand teachers" working in district Ferozepore at the time of the provincialization of the District Board Schools ;

(b) the number of teachers out of those mentioned in part (a) above whose services have been regularised ;

(c) whether all the said teachers have received payment of their arrears of pay and annual increments ;

(d) the number and names of the teachers out of those mentioned above whose cases are still pending and who have not received

- payment of their arrears and annual increments together with the names of the schools where they are working at present ;
- (e) the time by which the teachers referred to in part (d) above are likely to receive payment of their arrears of pay and annual increments ;
- (f) whether any of the said teachers has recently sent any representations against certain injustice done to him ; if so, the name of that teacher together with the date of submission of his representation and the details of the action, if any, taken thereon

**Shri Prabodh Chandra** : (a) 87.

(b) 87.

(c) to (f) Information is being collected. It will be supplied shortly.

#### Posts of J.B.T Teachers in Jullundur District

**3225. Comrade Gurbakhsh Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state the total number of sanctioned posts of J.B.T. Teachers ( Men only) in Jullundur Division, in 1959, 1960, 1961, 1962 1963 and 1964 ?

**Shri Prabodh Chandra** :

1959	..	10,216
1960	..	10,252
1961	..	10,315
1962	..	12,655
1963	..	14,035
1964	..	14,628

#### CALL ATTENTION NOTICES

**Mr. Speaker** : Now we pass on to the next item and take up the Call Attention Notices. Call Attention Notice No. 12 stands in the name of Shri Om Parkash Agnihotri.

**Shri Om Parkash Agnihotri (Phagwara)** : Sir, I beg to draw the attention of the Government towards the fact that in accordance with a circular issued by the Education Department a compulsory building fund is being charged at the rates of rupee 1 each from primary class students, rupees 2 each from middle class students and rupees 4 each from High class students during the year 1965-66. It has resulted in a great unrest amongst the public in general and the parents of the students in particular. Therefore, the realisation of this compulsory building fund should be stopped in the border and famine-stricken districts forthwith keeping in view the following points :

- (1) Industrial workers, farmers, petty shopkeepers and traders have received a great set-back during Indo-Pakistan conflict.

Thousands of industrial workers were thrown out of employment in these districts for a considerable period, the business remained at a standstill resulting in deterioration of financial condition of the people.

- (2) Defence Fund has already been realised from the parents of the students in the border and flood stricken districts.
- (3) This fund is breaking the back-bone of the people in these hard days when even the necessities of life are not available.

**शिक्षा मंत्री (श्री प्रबोध चन्द्र) :** जनाब आली, यह बिल्डिंग फंड लड़कों से लेने का मतलब यह था कि इस वक्त तकरीबन 90 फी सदी ऐसे स्कूल हैं कि जिन में या तो बहुत कम जगह बच्चों के बैठने के लिये है या बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में कई स्कूल इस लिये पहले बन्द हो जाते थे कि वहां पर धूप में बच्चे नहीं बैठ सकते थे। कई स्कूल वर्षा के कारण भी पहले बन्द हो जाते थे। बच्चों को स्कूल में बैठने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। जब सारा जायजा लिया गया तो पता लगा कि अगर बच्चों के बैठने के लिये मुनासिब जगह बनानी है तो बीस से पच्चीस करोड़ रुपये की जरूरत होगी, मुरम्मत करने के लिये भी और नई इमारत बनाने के लिये भी। गवर्नमेंट के ज़राए से यह बिल्कुल नामुमकिन था कि इतना रुपया या इस का कुछ हिस्सा भी बिल्डिंग फंड के लिये निकाल सकती। इस लिये गवर्नमेंट ने फैसला किया कि प्राइमरी के बच्चों से एक साल में एक रुपया, मिडल वालों से दो रुपये साल के और हाई और हायर सैकंडरी वाले बच्चों से तीन या चार रुपये साल के ले लिये जाएं। जिन इलाकों में मुश्किल पड़ती थी उन के लिये फैसला किया गया कि यह रकम चार किश्तों में ले ली जाए। तीन या चार महीने के बाद तीन आने या चार आने देना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर बच्चों को धूप, बारिश और अंधेरी से बचाना हो तो सरकार के पास इस के अलावा कोई और इलाज नहीं था। यह फैसला बड़ी सोच विचार के बाद किया गया था। यह भी फैसला किया गया कि 80 फीसदी फंड वहीं पर खर्च किये जाएं जहां से वे इकट्ठे किये जाएं, उसी इलाके के स्कूल बनाने पर खर्च किये जाएं जहां से वह इकट्ठा होता है। स्पीकर साहिब, कई साथी ऐसे हैं कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी काम करे उस को क्वांटिफाई करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं हाउस को कि बाईएंड लार्ज कोई शिकायत नहीं आई। एक दो एप्लीकेशन आई थीं और वहां से इकट्ठे रुपये लेने की बजाए यह फैसला किया गया है क्वार्टरली ले लिये जाएं ताकि उन को किसी प्रकार की तकलीफ न हो।

**श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री :** स्पीकर साहिब, मैं ने यह डिमांड की है कि बार्डर इजला के लोगों का बहुत तकलीफ हुई है। बच्चों को पहले डी फैंस फंड देना पड़ा है, मैं जानना चाहता हूं कि यह फंड कम्पलसरी है या अपनी मर्जी से देना है। अगर कम्पलसरी है तो क्या यह बात ठीक नहीं है कि जब बच्चों से फीस ली जाती है तो उन को मजबूर किया जाता है कि पहले बिल्डिंग फंड दो बाद में फीस ली जाएगी।

**मंत्री :** स्पीकर साहिब, आप ने इजाजत दे दी है। मैं ने फैकचुअल पोजीशन वाज़ेह कर दी है। बिल्डिंग फंड देना हर एक के लिये जरूरी है। प्राइमरी और मिडल क्लास के बच्चों की कोई फीस नहीं है और 25 लाख से कुछ ज्यादा बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ हाई क्लासिज़ और कालिजों से फीस ली जाती है। जो मां बाप हाई क्लासिज़ और कालिज की फीस दे सकते हैं, उन को तीन आने या चार आने महीने के ज्यादा खर्च करने पड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस से हम बच्चों को बैठने के लिये अच्छी जगह दे सकेंगे, वे अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। इसी लिये मुनासिब समझा गया कि अगर थोड़ी सी सख्ती भी हो तो फंड ले लिया जाए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी काफी हिस्सा इस काम में डालेगी।

(श्री बलरामजी दास टंडन बोलना चाहते थे ।)

**श्री फतह चन्द विज :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। एजुकेशन मिनिस्टर साहिब ने यह फरमाया है कि कुछ साथी मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। यह अल्फाज इनकी शान के शायं नहीं हैं। इस लिये या तो इन को विद्वान करने के लिये कहा जाए नहीं तो आप से रिक्रुएस्ट है कि इन को कार्यवाही से हफ्ता कर दिया जाए।

**श्री अध्यक्ष :** देखिये, मैं यह बात साफ कर दूँ। हमने मिल कर फैसला किया है कि एक दिन में दो मोशनज़ आया करेंगी। इस से ज्यादा हाउस में मोशनज़ नहीं आया करेंगी। हां, अगर कोई बहुत एक्सट्रीम इम्पाटेंस की है तो तीसरी मोशन भी आ सकती है। लेकिन जो पैडिंग हैं मैं उनको आज डिस्पोज आफ करना चाहता हूँ।

दूसरी बात, लोक सभा की जो प्रक्टिस हम फालो करेंगे वह यह है कि काल अटेनशन के जो सिगनेटरीज़ हों वह एक सवाल कर सकते हैं। (The hon. Members may please listen. We had unanimously decided that in future only two such motions would be taken up daily in the House and this number will not be exceeded in any case. Of course, if there is any other motion of extreme importance then in that case a third motion can be taken up. But as regards the pending motions, I want to dispose them of today.)

The other thing which we would like to follow, in accordance with the practice obtaining in the Lok Sabha is that each of the signatories to the Call Attention Motion would be entitled to put one question after the Minister had made a statement.)

**श्री बलरामजी दास टंडन :** अगर आप की इजाज़त हो तो . . . . .

**Mr. Speaker :** No, please.

Next Call Attention Notice No. 16 stands in the name of Sardar Gurcharan Singh.

(Nobody got up to raise the Call Attention)

**Mr. Speaker :** Next Call Attention Notice No. 17 stands in the name of Sarvshri Net Ram, Jagan Nath, Tek Ram and Inder Singh Malik.

**Chaudhri Inder Singh Malik (Safidon) :** Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact, namely, Shri Prabhu, son of Shri Har Chand of village Dhamana, tehsil Hansi, has been murdered by the police in Police Lock-up Hansi on 14th/15th February, 1966 night, Prabhu was under the Police remand for a week. Even the dead body of Prabhu was not given to his father after the post-mortem, after his repeated request. All these circumstances show that the death of Prabhu was due to police atrocities, but the police made a story that he had committed suicide. So, special enquiry and new investigation needed by a special agency. This is a heinous crime and the immediate action needed.

**मुख्य संसद सचिव (श्री रामप्रताप गर्ग) :** स्पीकर साहिब, पोजीशन यह है कि प्रभु जी कि एक प्रोक्लेम्ड औफेंडर था 4 फरवरी, 1966 को अरैस्ट किया गया था। उस के बाद

[मुख्य संसद सचिव]

14 फरवरी, 1966 को इडेंटिफिकेशन पेरेंड हुई और फिर उस का रीमांड ले लिया गया।

15 तारीख को सुबह सात बजे के करीब उस के साथ एक अंडर ट्रायल लखा सिंह था जो उसी जगह पर सोया हुआ था। सात बजे सुबह उसने एक आवाज सुनी कि कोई चीज धम्म से नीचे गिरी और उसने देखा कि परभू एक्यूज्ड जो था, उसने गले में धोती डाली हुई थी और उसने सुएसाईड कमिट की हुई थी। उसने शोर मचाया। फौरन उसी वक्त जो पुलिस के आदमी वहां पर मौजूद थे वह वहां पर इकट्ठे हो गए जिनमें परस राम, शिवचरण ए. एस. आई., कान्स्टेबल प्रभात सिंह, माम चन्द असिस्टेंट क्लर्क वगैरा उस तरफ दौड़े। एक स्वीपर भी उस वक्त वहां था और वह भी उस तरफ दौड़ा हुआ गया। इस तरह से वह लोग वहां पर इकट्ठे हुए। फौरन ही डाक्टर को बुलाया गया। डाक्टर रंजीत सिंह वहां पहुंचा और उसने डिक्लेयर किया कि सुएसाईड करके उसकी डैथ हुई है। डी. सी. ने फौरन एक एन्क्वायरी अंडर सैक्शन 176 सी. आर. पी. सी का आर्डर दिया। एक एस. डी. एम. को उस एन्क्वायरी पर लगाया गया। एस. डी. एम. ने सारे फैक्ट्स ऐंजामिन किए और लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा। उसके घर वालों ने उसकी बाड़ी को लेने से इन्कार कर दिया और उसकी बाड़ी को क्रिमेशन के लिए म्युनिसिपल कमिटी को भेज दिया गया। बाकी इन्क्वायरी चल रही है। यह केस अंडर एन्क्वायरी है।

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** जो स्टोरी पुलिस ने बनाई है वह बिल्कुल झूठ बनाई है। उसने मुईसाइड कोई नहीं की। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। (He has given the statement.)

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐंजैक्टिव से यह इन्क्वायरी क्यों कराई, जूडीशल मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं करवाई ?

**Chief Parliamentary Secretary :** It is under enquiry.

**Sardar Lachhman Singh Gill :** Is it judicial or executive enquiry ?

**मुख्य संसद सचिव :** मैंने बताया है कि इन्क्वायरी चल रही है।

**Sardar Gurnam Singh :** He has not replied.

**Mr. Speaker :** If he does not reply, I cannot force him.

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** स्पीकर साहिब, मेरा जवाब नहीं आया। (विघ्न)

**मुख्य संसद सचिव :** जूडीशल इन्क्वायरी है।

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** आन एप्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं आया। एस. डी. एम. ऐंजैक्टिव का हिस्सा है, वह जूडीशरी का नहीं है। उसकी लाश भी उसके वालदेन को नहीं दी गई। क्या म्युनिसिपल कमिटी उसकी वालदेन थी ? (शोर)

**श्री अध्यक्ष :** उन्होंने बताया है कि उसकी लाश को म्युनिसिपल कमिटी को दे दिया गया था क्योंकि उन्होंने उसे लेने से इन्कार कर दिया था। (The Chief Parliamentary Secretary has stated that the dead body was handed over to the Municipal Committee as the parents of the deceased had refused to take it.)

**श्री अमर सिंह :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मैं इस बात पर आप की रुलिंग चाहता हूँ कि हाउस में बिन्कुल गलत बयानी की गई है क्योंकि वहाँ पर कहानी कुछ और ही है।

**श्री अध्यक्ष :** आप वह कहानी मुझे लिखकर भेज दें। (The hon. Member may send me the details in writing.)

**श्री अमर सिंह :** मैंने लिख कर भेजी हुई है आपको।

**श्री अध्यक्ष :** गवर्नमेंट का बयान तो आज आया है। आपने कैसे लिखकर पहले ही भेज दी ? (The statement has been made by the Government to-day. How could the hon. Member intimate to me the whole position in writing?)

**श्री अमर सिंह :** मैंने आपको लिखकर भेजी हुई है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। आप बैठिए। (Order please. The hon. Member may please resume his seat.)

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर.....

**श्री अध्यक्ष :** यह प्रापर नहीं। आप मेहरबानी करके अपनी जगह पर बैठिए। (This is not proper. The hon. Member may please take his seat.)

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** स्पीकर साहिब, मामला बढ़ गया है। एक तरफ तो कहते हैं कि इन्क्वायरी हो रही है और साथ ही पहिले कहा कि इन्क्वायरी की। यह दो अलग अलग बातें हैं।

**Mr. Speaker :** Order please.

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक :** उन्होंने कहा है कि इन्क्वायरी हो गई है।

**Mr. Speaker :** He says it is in progress.

**Sardar Gurnam Singh :** If it is in progress, how does he say it was 'suicide' ? He cannot say that.

**मुख्य संसद सचिव :** वह तो पोस्ट मार्टम से पहिले की ही रिपोर्ट थी। (विघ्न)

**Mr. Speaker :** Order please. Next motion is by Comrade Bhan Singh Bhaura.

(The hon. Member was not present.)

**Mr. Speaker :** The next motion (No. 22) is by Sardar Kulbir Singh.

**Chaudhri Amar Singh :** On a point of Order, Sir.....

**Mr. Speaker :** Please take your seat.

**सरदार कुलबीर सिंह :** स्पीकर साहिब, मैं एक्साईज एंड टैक्सेशन के महकमे के वजीर का ध्यान एक बहुत जरूरी पब्लिक इम्पारटेंट के मामले की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो कि इस तरह है :

[सरदार कुलबीर सिंह]

फारम ए.ई.टी.ओ. बस्सी पठानां, जिला पटियाला, ने गुरुद्वारा के नाम पर लोगों से फंड इकट्ठा किया। जो लोग चन्दा न दे सकते थे उन से जबरदस्ती वसूली की जाती रही। जो लोग किसी वजह से चन्दा न दे सके उन पर टैक्स पहले से दुमना कर दिया। इस के अलावा, हर एक टैक्स देने वाले से जो काम वह करता था माल रिश्त में लिया जाता था। अगर कोई सिलाई की मशीन बनाता है तो उससे मुफ्त मशीनें ली गई। कोई पेमेंट नहीं की। इसी तरह एक दिन जी. आर. सीविंग मशीन कम्पनी, सरहिन्द, में आ कर सिलाई मशीन तलब की गई और एक हफ्ता इस्तेमाल के लिए कार मांगी। फर्म के मालिक ने इनकार कर दिया जिस पर पेशी के दिन 5000 रुपए टैक्स लगा दिया।

इन सब शिकायतों की इन्क्वायरी टैक्सेशन कमिशनर, पटियाला डिवीजन, ने की। इस बीच में ए. ई. टी. ओ. ने श्री जै किशन डाक्टर और श्री हरि किशन लाल एडवोकेट को साथ लेकर इन्क्वायरी से बचने के लिए सुलह करने जी. आर. सीविंग मशीन कम्पनी के मालिक के पास आया और तस्लीम किया कि मैंने गुरुद्वारे के नाम पर आप से जबरदस्ती चन्दा लिया है। सिलाई की दो मशीनें मुफ्त (विदाउट पेमेंट) व एक हफ्ते के लिए इस्तेमाल करने के लिए कार मांगी और न देने पर जो गालियां दीं उन के लिए माफी दी जावे। इन सब बातों का टेप रिकार्ड मौजूद है। इन्क्वायरी आफिसर को तमाम टेप रिकार्ड सुनाया गया और आफिसर ने कहा कि बहुत ही जबरदस्त सबूत है लेकिन हैरतनगी की बात है कि इन्क्वायरी कहां दब गई या उसका क्या नतीजा निकला। सरकार को इस खुले स्कैंडल पर कड़ी कार्रवाई फौरन करनी चाहिए।

नोट : ये टेप रिकार्ड पंजाब सरकार के वजीर को भी सुनाए जा चुके हैं।

विੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਇਹ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਈ. ਟੀ. ਓ., ਬੱਸੀ ਪਠਾਨਾਂ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀ. ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ। ਉਹ ਸੀ. ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਫ. ਸੀ. ਡੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਅਪਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਿ **enquiry should be made immediately. Meanwhile** ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ **under section 504 of the Penal Code** ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ **still, let us have some departmental enquiry** ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿਤਾ

upon the facts of this case ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫੇਰ ਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਉ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਅਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਲੈਤੋਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ । ਫਿਰ ਵੀ

3.00 p.m. | ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । But still we are enquiring from him. It shall be gone into thoroughly.

Mr. Speaker : Now we pass on to the next item.

### Message from the Governor

Mr. Speaker : I have received D. O. Letter No. 2105, dated the 24th February, 1966, from Sardar Ujjal Singh, Governor, Punjab, which reads as follows :

"I am in receipt of your demi-official letter No. 21-LA-66/9921, dated the 23rd February, 1966, together with a copy of the Motion of Thanks passed by the Punjab Vidhan Sabha on the 23rd February, 1966, for the Address I delivered to both the Houses on the 14th February, 1966.

I am grateful to the Punjab Vidhan Sabha for their Motion of Thanks".

### POINT OF ORDER

ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੱਡਨ : -ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਨਦਰ ਸਿੰਹ ਨੇ ਆਜ ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਥੀ . . . . .

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਯਕਸ਼ : ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਓ । (The hon. Member may please resume his seat.)

(ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੱਡਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਵਿਧਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਯਕਸ਼ : ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੇ ਕੀਆ ਹੈ ਮੈਂ उसी के मुताबिक चल रहा हूँ । ਜੋ ਕਾਲ ਐਟਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵਹੀ ਲਾ ਰਹਾ ਹੂੰ । (I am following the procedure laid by the House. I have taken up only those call attention notices which have been admitted.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ , ਸਰ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿਉਗੇ ? (Will the hon. Member not allow the proceedings to be conducted?)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਲ ਅਟੈਨ-ਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਅਗੇ ਇਕ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਾਮਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ.....

**Mr. Speaker :** Not here, please.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼, ਆਪ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ? (Will Comrade Josh please take his seat or not?)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਕਸ਼ : ਜੋ Call Attention Notices ਮੈਂ ਨੇਂ ਏਡਮਿਟ ਕੀਏ ਹਨ ਵਹੀਂ ਧਹਾਂ ਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਐਂਡ ਜੋ ਏਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਕਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। (Only those Call Attention Notices have been taken up here which have been admitted by me.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਪਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (At this stage Comrade Shamsher Singh Josh staged a walked out.)

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਕਸ਼ : ਸੁਝੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਜੂੜ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ ਯੂਪ ਲੀਡਰਜ਼ ਨੇ ਜੰਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਏਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਭਿਯਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਧਹ ਤਰੀਕਾ ਅਭਿਯਾਨ ਕੀਧਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸਿਫ ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਟੇਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਏਡਮਿਟ ਕੀਧਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਨੇ ਧਹਾਂ ਪਰ ਧਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਧਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਦੋ ਏਡਮਿਟ ਕੀ ਜਾਏਂ ਐਂਡ ਆਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਅਹਮੀਯਤ ਰਖਤਾ ਹੋ ਤੋ ਤੀਨ ਕਰ ਲੀ ਜਾਏਂ। ਇਤ ਕੇ ਕਾਕਜੂੜ ਆਗਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼ ਧਹ ਸਮਝਤੇ ਥੇ ਕਿ ਤਨ ਕੀ ਕਾਲ ਅਟੇਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਏਡਮਿਟ ਹੋਨੀ ਚਾਹਿਏ ਥੀ ਤੋ ਤਨ ਕੋ ਕਜਾਏ ਧਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਨੇ ਕੇ ਹਾਤਸ ਮੈਂ ਧਹ ਸਲਾ ਤਠਾਨਾ ਚਾਹਿਏ ਥਾ ਐਂਡ ਹਾਤਸ ਕੀ ਸਜੀਂ ਪਰ ਓਡ ਦੇਨਾ ਚਾਹਿਏ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਧੀਂਕਿ ਸਿਫ ਕਹ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਧਹ ਜ਼ਰੂਰ ਏਡਮਿਟ ਹੋਨੀ ਚਾਹਿਏ, ਇਸ ਤਰਹ ਸੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ

चल सकता (I am constrained to observe that despite the fact that in this connection a liberal policy based on the unanimous decision taken by all the group leaders in the House is being followed Comrade Josh has adopted this way of protest. Although in the Lok Sabha only one Call Attention Motion is admitted yet here we have decided that normally two motions may be admitted and in case a matter was of vital importance, the third one may also be admitted. If inspite of this Comrade Josh thinks that his call attention motion must be admitted then instead of adopting this method of walking out he should have raised the matter in the House and left it to its decision. But since he alone thinks that it must have been admitted, the business of the House cannot be carried on like this.)

सरदार गुरनाम सिंह : उन की क्या काल अटेनशन नोटिस थी या एजर्नमेंट मोशन थी ?

श्री अध्यक्ष : आईएम सारी। उन की एडजर्नमेंट मोशन थी। (I am sorry. This was an Adjournment Motion.)

श्री बलरामजी दास टण्डन : स्पीकर साहिब, आप ने यह जो फैसला किया है क्या यह काल अटेनशन नोटिसिज के बारे में है या एडजर्नमेंट मोशनज के बारे में है ?

श्री अध्यक्ष : यह फैसला काल अटेनशन नोटिसिज के बारे में है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कामरेड जोश ने यह तरीका अख्तयार करके रिफ्लैक्शन करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस के लिये वाक आऊट करने की जरूरत पड़े। जो फैसला ग्रुप लीडरज ने कर लिया हो उस पर अमल होना ही चाहिए। मैं अमीद करता हूँ कि आयरंदा के लिए हाऊस इस फैसले पर अमल करने की कोशिश करेगा। (This decision relates to the Call Attention Notices. I was submitting that by adopting this way of protest, Comrade Josh had attempted to cast a reflection on the Chair. But I think that it was not such a matter as required a walk out. Any decision taken by the group leaders must be implemented. I hope that in future, the House will make an endeavour to act upon this decision.)

शिक्षा मंत्री (श्री प्रबोध चंद्र) : स्पीकर साहिब, आप के कहने के बावजूद इस बारे में यहां पर एक ऐसा नज़रिया दिया गया है जिस से एक गलतफहमी पैदा हो सकती है क्योंकि उन्होंने कहा है कि 75 हजार रुपया पंजाब मिनिस्टरी की तरफ से दिया गया है। मैं आप की इजाज़त से यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि यह सारा रुपया मिनिस्टरी की तरफ से नहीं दिया गया बल्कि कुछ मिनिस्टरों ने अपने 2 डिस्केशनरी फण्डज में से जितना जितना मुनासब समझा इस मतलब के लिये दिया है। The Ministry as Government has not paid anything for this memorial.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਆਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿਟ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ 3 ਜਾਂ 4 ਦਫਾ ਦਿਲਾਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ ਰੁਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਐਲਾਉ ਹੋ ਗਈ ਐਂਰ ਆਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੈਰੀ ਆਉਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗੌਰਮਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਲ ਲਈ ਕੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ.....

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨੇ ਧੁਰ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਧਰਾਂ ਪਰ ਕਿਸੀ ਕਾਲ ਅਟੇਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਕੇ ਯਰਿਏ ਰੇਯ ਕਿਆ ਗਯਾ ਹੋ ਐਂਰ ਉਸ ਕਾ ਜਵਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਟਰਫ ਸੇ ਨ ਆਏ ਤੋ ਉਸ ਕਾਲ ਅਟੇਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇ ਰੀ ਕਾਨਸਿਡਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਯੇ ਤੈਧਾਰ ਹੁੰਗਾ । ਧੁਰ ਚੀਯ ਮੈਂ ਨੇ ਕਾਲ ਅਟੇਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਿਯ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਥੀ ਐਂਰ ਏਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਯ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਥੀ । ਏਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਯ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੋ ਧੁਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਧੁਰ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਅਹਮੀਯਤ ਰਖਨੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹੋਗੀ ਤੋ ਧੁਰ ਏਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਕੇ ਏਡ੍ਰੈਸ ਪਰ ਧੁਰ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋ ਧੁਰ ਏਸੇ ਮਾਮਲੇ ਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਜਵਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਟਰਫ ਸੇ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਮਾਮਲਾ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਟਰਫ ਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਧਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਸ ਕੀ ਟਰਫ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਧੁਰ ਕਿਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਤੋ ਧੁਰ ਏਕ ਅਲਗ ਬਾਤ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਧੁਰਾਂ ਪਰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । (The other day I stated that in case a point sought to be raised through a Call Attention Notice, remained unanswered by Government, when referred to during the general discussions, then I would be prepared to reconsider that Call Attention Notice. But I must make it clear that I said so in relation to Call Attention Notices alone and not to Adjournment Motions. As regards the Adjournment Motions the practice is that if it relates to specific matter of public importance, then it is admitted. But generally during the discussion on Governor's Address, all such matters can be discussed and replied to by the Government. But if in connection with a certain matter, the Government fails to give a reply or the reply given by the Government is not acceptable to an hon. Member, then this is quite a different thing. However, I think a lot of discussion has taken place regarding this matter.)

**Sardar Gurnam Singh :** Sir, if you refer to the record you will find that one of the reasons given by you for rejecting the Adjournment Motions is that we will have ample opportunities to speak on the matter during the

general discussion. Now, Sir, you have been pleased to say that you did not say so.

**Mr. Speaker :** I said it with regard to the Call Attention Notices and not with regard to the Adjournment Motions.

**श्री बलरामजी दास टंडन :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि इन दिनों बहुत सी काल अटेंशन नोटिसिज़ और एडजर्नमेंट मोशनज़ सिर्फ इस लिये रिजैक्ट होती रही है क्योंकि उन दिनों गवर्नर के एड्रेस पर डिसकशन हो रही थी और इन के बारे में मैम्बर साहिबान को डिसकस करने का मौका मिल सकता था। और अगर इस के बारे में यहां पर कुछ कहा जाएगा तो उस का जवाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। इस बारे में कई मैम्बरों की तरफ से जिक्र किये जाने के बावजूद भी मिनिस्टरी की तरफ से इस का कोई जवाब नहीं दिया गया और इस की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई तो . . . . .

**श्री अध्यक्ष :** 17 तारीख के बाद मैंने सारी काल अटेंशन मोशनज़ पेंडिंग रखी थीं, पेंडिंग दी डिसेयन आफ दी ग्रुप लीडर्ज़। उससे पहले का मुझे मालूम नहीं। (After the 17th February I had kept all the Call attention Notices pending till the decision of the group leaders. I am not aware of any other notices earlier to that).

**कामरेड राम प्यारा :** आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जहां तक आप ने पार्लियामेंट के प्रोसीजर का हवाला दिया है वह ठीक है, आप का राईट है। लेकिन यहां पर वाज्जे तौर पर एक मिनिस्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से हम दे रहे हैं। दूसरे ने कहा कि हम स्कूल के लिये दे रहे हैं मैमोरियल के लिये नहीं दे रहे। उस वक्त मैंने प्वायंट रेज़ किया था। बाद में एक मिनिस्टर ने कहा कि वह अपने डिस्क्रिशनरी फंड में से दे रहे हैं। तो यह बात इसी तरह बीच में रह गई। यह बात सरकार साफ करे। हम यह नहीं कहते कि आप मोशन ऐक्सेप्ट करें मगर सरकार यह बात जरूर साफ करे कि यह किस तरह दिया जा रहा है। अभी दास कमिशन की किताब कायम है। इस तरह से लोगों के खून पसीने की कमाई . . . (विघ्न)।

**श्री अध्यक्ष :** आप की बात आ गई, आप बैठें। (The hon. Member may take his seat. This point has come.)

**कामरेड राम प्यारा :** गवर्नमेंट को आप हुक्म दें कि वह यह बात क्लियर करे, हम यह नहीं कहते कि आप मोशन ऐडमिट करें।

**Mr. Speaker :** The hon. Minister for Education has made the position clear.

**मरदान लल्लमट सिंघ गिल :** बी जी ?

**श्री मपीवर :** उसीं सुटिआ ठही ? (Has he not heard about it?)

**मरदान लल्लमट सिंघ गिल :** ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਂਟਿੰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

**Minister for Education :** It was no taunting. I stated the factual position. The amount has not been given on behalf of the Punjab Government or collectively on behalf of the Ministry. The individual Ministers

[Minister for Education]

have paid money out of their respective discretionary fund. The Punjab Ministry has nothing to do with it.

**ਕਾਸਰੇਡ ਰਾਮ ਘੋਰੀ :** ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਯੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝੀਆਂ ਨੇ ਅਪਨੇ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਫੰਡ ਮੇਂ ਸੇ ਦਿਯਾ ਹੈ। ਹਸ ਧਹ ਪ੍ਰਭਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਕਧਾ ਕਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਧਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਧਹ ਪੈਸਾ ਅਪਨੀ ਜੇਬ ਸੇ ਦਿਯਾ ਹੈ ?

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲਜ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ?

**Mr. Speaker :** It is lying pending.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ.....

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰਖੋ। ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲਜ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਵਿਲਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਪ੍ਰਿਵਿਲਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰਖੋ। (Let the hon. Member have a little patience. His earlier Question of Privilege was referred to the Committee of Privileges. The matter has been reported by it. (Interruption) The decision taken by the Committee will come before him in the shape of its report. He need not be impatient.)

### Papers Laid on the Table

**Minister for Health (Shrimati Om Prabha Jain) :** Sir, I beg to lay on the Table the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Rules, 1966, as required under section 2(2) of the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Act, 1965.

### BILLS

(Extension of time for making the Final Reports by the Regional Committees)

THE PUNJAB MUNICIPAL CORPORATIONS BILL, 1963

**Minister for Planning and Local Government (Sardar Ajmer Singh) :** Sir, I beg to move—

That the time fixed for the presentation of the Final Reports of the Regional Committees on the Punjab Municipal Corporations Bill, be further extended up to the 31st August, 1966.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the time fixed for the presentation of the Final Reports of the Regional Committees on the Punjab Municipal Corporations Bill, be further extended up to the 31st August, 1966.

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਜਗਰਾਉਂ) :** ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਣਾ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ :** ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ ਅਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। It is for the Regional Committee ਉਸ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। (It is not a matter relating to an individual. It is for the Regional Committee to decide. He is also a Member of that Committee.)

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :** ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਐਸੋਰੈਂਸਿਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ, 10 ਸਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵਜ਼ੁਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਬਿਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਕੱਪਰੀਹੈਨਸਿਵ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਦਲੇ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਡੀਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਾਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਵਿਘਨ) ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਇੰਦਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ, **usurp** ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕ ਹੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ।

**ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਐਸ.ਸੀ.) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]

ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਲ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

**ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ :** ਧਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। (This motion relates to the Municipal Corporations Bill, while the hon. Members are referring to the other Bill which is Punjab Municipal Bill.)

**ਕਾਮਰਾਡ ਰਾਮ ਘਾਟਾ (ਕਰਨਾਲ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੈਂਬਰ 1963 ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਰ ਏਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਇਸ ਕੋ ਤਕ ਸੇ ਲੇ ਕਰ ਅਬ ਤਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਲਟਕਾਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾ ਵਕਤ ਆਰ ਰੁਪਯਾ ਜਾਯਾ ਕਿਆ ਗਯਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਹਾਊਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇ ਪੂਛਤਾਓ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇ ਏਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਂਗਤੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਝੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਸੇ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਲਾਏ ਥੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੋ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਸਗਰ ਏਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਗਯਾ। ਇਸ ਤਰਹ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਟ ਅਪ ਕੋ ਇੰਜਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ ਸਟੇਟ ਕੇ ਰੈਕੋਰਡ ਪਰ ਬੋਲ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਧਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਟੈਕਸ ਕਾ ਰੁਪਯਾ ਜਾਯਾ ਨ ਹੋ ਆਰ ਇਸ ਸੇ ਇਤਨੀ ਫੇਰ ਨ ਕੀ ਜਾਏ।

**ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ) :** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿਲ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇੰਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਵਕਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬਿਲ

ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ । ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਵੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਕ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਧਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਅਧੀਆਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ 30 ਜੂਨ, 1966 ਤਕ ਦਾ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਪਾਸੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

**Mr. Speaker :** Question is—

That the time fixed for the presentation of the Final Report of the Regional Committees on the Punjab Municipal Corporations Bill, be further extended upto 31st August, 1966.

*The motion was carried.*

### The Punjab Municipal Bill, 1963

**Planning and Local Government Minister (Sardar Ajmer Singh) :** Sir, I beg to move—

That the time fixed for the presentation of the Final Reports of the Regional Committees on the Punjab Municipal Bill, be further extended upto 31st August, 1966.

**Mr. Speaker .** Motion moved—

That the time fixed for the presentation of the Final Reports of the Regional Committees on the Punjab Municipal Bill, be further extended upto 31st August, 1966.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the time fixed for the presentation of the Final Reports of the Regional Committees on the Punjab Municipal Bill, be further extended upto 31st August, 1966.

*The motion was carried.*

### The Punjab Cattle Preservation Bill, 1964

**Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Captain Rattan Singh) :** Sir, I beg to move—

That the time fixed for the presentation of the Reports of the Regional Committees on the Punjab Cattle Preservation Bill, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be extended upto the 15th March, 1966.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the time fixed for the presentation of the Reports of the Regional Committees on the Punjab Cattle Preservation Bill, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be extended upto the 15th March, 1966.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the time fixed for the presentation of the Reports of the Regional Committees on the Punjab Cattle Preservation Bill, as amended by the Punjab Vidhan Parishad, be extended upto the 15th March, 1966.

*The motion was carried.*

### **The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill 1965**

**Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Captain Rattan Singh) :** Sir, I beg to move—

That the time fixed for the presentation of the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, be further extended upto the 30th June, 1966.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the time fixed for the presentation of the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, be further extended upto the 30th June, 1966.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the time fixed for the presentation of the Report of the Hindi Regional Committee on the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, be further extended upto the 30th June, 1966.

*The motion was carried*

### **Supplementary Estimates (Second Instalment) 1965-66**

#### **1. Discussion on the Estimates of the expenditure charged on the revenues of the State**

**Mr. Speaker :** If any hon. Member wants to raise discussion on the charged items, he may do so.

*(No hon. member rose to speak)*

#### **2. Voting of the Demands for Supplementary Grants.**

**Mr. Speaker :** In order to save time of the House and keeping in view the past practice, all the under mentioned Demands for Supplementary Grants will be deemed to have been read and moved. All the cut motions given notice of by the hon. Members, will also be deemed to have been read and moved. The members, while raising discussion, may please indicate the Demands on which they wish to speak, so that the Ministers concerned may also keep a note of them.

The guillotine will be applied at 6.00 p.m.

**Demand No. 1.**—that a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,41,780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 12—Sales Tax.

**Demand No. 2.**—that a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,10,040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1966, in respect of 22—Jails.

*Demand No. 3.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,55,79,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 28—Education.

*Demand No. 4.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 14,89,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 30—Public Health.

*Demand No. 5.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,45,580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 42—Multipurpose River Schemes.

*Demand No. 6.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 22,49,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 43—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

*Demand No. 7.*—That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,52,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of Charges on Irrigation Establishment.

*Demand No. 8.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 21,05,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 50—Public Works.

*Demand No. 9.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,42,280 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 70—Forests.

*Demand No. 10.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 57,36,110 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 71—Miscellaneous.

*Demand No. 11.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 91,58,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 78-A-Expenditure connected with National Emergency.

*Demand No. 12.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,92,26,790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

*Demand No. 13.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 62,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 120—Payment of Commuted value of Pension.

*Demand No. 14.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,63,56,560 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 124—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

*Demand No. 15.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 17,56,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of Loans to Local Funds—Private Parties, etc., and Loans to Government Servants.

*Demand No. 16.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 31—Agriculture.

*Demand No. 17.*—That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 103—Capital Outlay on Public Works.

## CUT MOTIONS

## DEMAND NO. 3

(28—Education)

## 1. Principal Rala Ram :

That the demand be reduced by Re. 1.

## DEMAND NO. 7

(Charges on Irrigation Establishment)

## 2. Principal Rala Ram :

That the demand be reduced by Re. 1.

**कामरेड राम चंद** (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, मेरा खयाल तो था कि बजट की जनरल बहस के वक्त बोलूँ लेकिन इस वक्त मेरी कानशंस प्रिक कर रही है इस लिये खड़ा हो गया हूँ। इस सम्बन्ध में दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि सरदार प्रताप सिंह की यादगार के लिये जो रुपया मन्त्रियों ने दिया है वह कानून विरुद्ध है..... (विघ्न) ।

**श्री अध्यक्ष** : आप किस डिमांड पर बोलना चाहते हैं ? (Which Demand, the hon. Member wants to discuss ?)

**कामरेड राम चंद** : मेरी अर्ज यह है कि वैसे कोई पर्टिकुलर डिमांड तो नहीं है। मैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि बजट की बहस में Omission और Commission दोनों बहस में आ सकते हैं। यह जो डिस्क्रिप्शनरी ग्रांटें हैं इस को एक ऐसे आदमी की यादगार बनाने पर खर्च किया जा रहा है जो कुरप्ट साबित हुआ। (विरोधी पक्ष की ओर से शेम शेम) और यह मिसयूज आफ दी मनी है। दूसरी अर्ज मैं यह करना चाहता हूँ कि हम एक बार discretionary grants की मंजूरी दे चुके हैं। उन का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं उसका विरोध करना चाहता हूँ।

**श्री अध्यक्ष** : इस में तो इस डिमांड का जिक्र नहीं है। आप कल के बाद बजट की आम बहस में इन बातों पर बोल सकते हैं। इस वक्त तो पर्टिकुलर डिमांड पर ही बोल सकते हैं। (There is no mention of this demand in the supplementary Demands. The hon. Member can discuss these general matters during the discussion on the Budget. At present he can speak on a particular demand only.)

**सरदार बलवीर सिंह** (ढीरोलपुर) : सपीकर साहिब, मैं इस सप्लीमेंटरी डिमांड के मेमबर नैड 9—लैंड रैवेन्यू, ग्रांट नं: 1 के सभ्य विरुद्ध कुछ बोलना चाहता हूँ।

ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਕਮਾਂ ਡੀਕ੍ਰੀਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਹੋਈ । ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੁਰਪਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਕ੍ਰੀਟਲ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਗਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਿਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਆਇਆ ਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਗਣਾ ਦੁਗਣਾ ਖਰਚਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਾਪਰ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵਜੋ ਦਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ ਪੇਜ 39, ਮੇਜਰ ਹੈਡ ਲੌਨਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ, ਆਈਟਮ ਨੰ: 3 ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੂਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਫਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਥੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਦਰਦੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਵਧ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਾਪਸ

[ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਹਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ: 5 ਹੈ ਜੇਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਅਤਲਿਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਚ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ। ਤਅਲੋਕ ਹੈ ਪਰ ਡੀਫੈਂਸ ਪਰਪਜ਼ਜ਼ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair.)*

ਇਕ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਥੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀ. ਏ., ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਘਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਊਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ** (ਜਾਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ: 14 ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ ਇਕ ਦੋ ਸੁਝਾਉ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੂਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗਰੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਸ ਇਕ ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ

ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਰਾਸ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ., ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਘਟ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਉ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ 47 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਮੀਲ ਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 67 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਯੂ ਪੀ. ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਊ ਤਾਂ 87 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 87 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ। ਅੱਜ ਕਲ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹੁ ਪੀੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਸਾਰੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ 11 ਆਨੇ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਪੀੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁੜ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36/37 ਰੁਪਏ ਮਣ ਗੁੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 27 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਗੁੜ ਕਢ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਦਾ ਭਾਉ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਮਾਦ ਪੀੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਭੋਗਪੁਰ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਦਿਉ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਟਰੇਡ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇ। ਬਸ ਏਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।

**ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਪੱਟੀ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਖੇਮਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀਰ ਬਾਰਡਰ ਤਕ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਹਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕੀ ਅਤੇ ਇੱਛੋਗਿਲ ਚਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਈ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵਿਚ 25, 25 ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਪਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤੇ ਔਰ ਆਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਢੋਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਮਿੰਘ]

ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12/13 ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੇਈ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਏਥੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਉਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਅਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛੁਪ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਕਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਫੋਰਸਿਲ ਨਹਿਰ ਖੋਦੀ ਸੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹਿਰ ਏਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਖੋਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕਢਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡੀਫੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੋਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕਢਣ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕਾਨਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਧਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ

ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰਤੋਕੀ ਖੇਮਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਸਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਹਿਸਟਾਰਿਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜ ਹੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਥੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਈਏ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਵਿਚ ਰੋਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁਧ ਪਿਆਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਉਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲੀਸੀ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚ ਮੁਚ ਉਸ ਉਜੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸਦੀ ਖਬਰ ਲਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਉ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

ਸਫਾ 33 ਤੇ ਜੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਜੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ..... (ਵਿਘਨ) ਉਥੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਫੂਡ ਪਰਾਬਲਮ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਕੜਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ, 1964 ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਰਾ ਕੇ ਵਖਾਇਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਪੁਲ ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਫਰਲਾਂਗ ਪਿਛਾਂ ਸੜਕ ਕਟ ਕੇ ਉਸ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਨੌਟ

**[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]**

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਧ ਸੈਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਤ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਕ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜਾਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਨਾਲ 15/20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਧ ਸੈਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਢ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘਟ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਪੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰ: 12 ਤੇ 14 ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰਖੀ ਹੈ। ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10/15 ਸਾਲ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਮਾਇੰਡਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਪਰ ਤੰਗੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨਾ ਬਿਜਵਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾ ਵਾਰ ਵਧਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਅਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਗੰਨਾ ਹੀ ਕਰੱਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੜ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਚੰਦੇ, ਭਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧ

ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਥ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਫਰਟੇ-ਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਉਥੇ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਉਹੋ ਭਾਉ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਉਹੋ ਰਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੰਬਈ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਲ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਖਾਦ ਲੈ ਜਾਕੇ ਉਸ ਭਾਉ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਭਾਉ ਇਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 'ਕੋਲੋਂ' ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਉ ਤੇ ਐਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਖਾਦ ਪਾਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 14/15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਵਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਉ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਐਟ ਪਾਰ ਰਖ ਰਹੇ ਹੋ । ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਲ ਵਢ ਕੇ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਗਾਲ, ਬੰਬਈ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਵੈਫੇਅਰ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਭੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਈਟਮ ਨੰ. 12 ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਆ ਹੈ ਰਿਹਾਖ । ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸੀ । ਉਹ ਠੇਕਾ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਐਮ. ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਐਕਸ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਬੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਫੈਂਕੇ ਅਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਇਹ ਗਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 85 ਫੀ ਸਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ):** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਮਾਊਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ—

“....As the amount was too meagre to cover all the categories of teaching personnel, it was decided in consultation with the representatives of teachers in the Punjab Legislative Council as also the accredited representatives of the teachers Unions in the State, to extend the financial benefit to those teachers who had put in five years or more service on 1st March, 1965. Similarly, the benefit and to Masters/Mistresses who had put in two years or more service on 1st March, 1965. Accordingly, a supplementary demand for Rs. 25 lakhs is presented.”

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਫੋਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਐਮ. ਐਲ. ਸੀਜ਼. ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। 48 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਇਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ. ਟੀ. ਜਾਂ ਬੀ. ਐਡ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਐਮ. ਐਲ. ਸੀਜ਼ ਭੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ਼ ਭੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 15 ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਟ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਵਿਚ ਅਮਾਉਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2½ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ 16, 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ **Class 1V** ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲਜ਼ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੇ-ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡਜ਼ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਨੂਮੰਨਬੈਯਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ **Pay Commission for low-paid Government Employees** ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਲੋ-ਪੇਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਬੜੀ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ-ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਡਵਿਲ ਜੈਸਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਇੰਟੈਰਿਮ ਇਨਕ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੌਕੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਹੋਰ ਨਾਜ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਉ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਇੰਟੈਰਿਮ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਲਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਨੂੰਮੰਥੋਯਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ-ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਗੇ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀਫੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡੀਊਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਅਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐਲ. 480 ਸਕੀਮ ... ਮਾਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਠੂਠੇ ਰਖੇ ਜਾਣ ਕਿ ਭੁਖੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨ ਵਿਚ ਸੈਲਫ-ਸਫੀਸੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਰੀਲਾਇੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਐਮੋਨੀਆ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਦ 17 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18.50 ਪਰ ਬੈਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ-ਖਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 244 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਲੰਸ-ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਧੋਲਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ 'ਨੋ-ਪ੍ਰਾਫਿਟ, ਨੋ ਲਾਸ' ਦੀ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਟਾਂਸ਼ਲ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨੋ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ' ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗਲ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਉਵਰ ਕਰ ਲਵੇ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਨੋ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ' ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈਗ ਵੀ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੈਗ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੌਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕ ਉਗਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਨਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਿਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਰਡ ਆਰਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਵਿਚ ਸੈਲਫ ਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਰਖ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਸਸਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 43 ਫੀ ਸਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, 57 ਫੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 57 ਫੀ ਸਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਨਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੌਨਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਨ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਲਈ ਲੌਨ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਊਬ-ਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੌਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖੂਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੌਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ 7 $\frac{3}{4}$  ਫੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੌਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 3 ਫੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 $\frac{3}{4}$  ਫੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੌਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰਲ ਲੌਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਾਏ ਕਰਦੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਭਾ ਤੋਂ ਘਟ ਭਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਟੈਰਿਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਅਰਨੈਸ ਐਲਾਉਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਸਸਤੇ ਭਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਅਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੰਗਾ, ਨਰੋਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

**कामरेड राम प्यारा (करनाल) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो ऐजुकेशन की डिमांड नम्बर 3 है, इसमें हम से कोई डेढ़ करोड़ के करीब रुपया मांगा जा रहा है। इसमें दो तीन आर्टिस्ट बड़ी इम्पारटेंट हैं। काफी रुपया मांगा गया है। अपग्रेडिंग आफ प्राइमरी स्कूलज़ इनटू मिडल और मिडल स्कूलज़ इनटू हाई स्टैंडर्ड के सम्बन्ध में कोई बत्तीस लाख रुपए की मांग की गई है। इस के अलावा एवार्ड आफ मैरिट स्कालरशिप टू स्टूडेंट्स के लिये भी रुपया मांगा गया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह दोनों आर्टिस्ट अच्छी हैं जिन की मैं तारीफ करता हूं। लेकिन मेरे अन्दाज़े के मुताबिक यह जो डिस्ट्रिब्यूशन है यह बिल्कुल अनफेअर है। वह इस लिये कि मिडल स्कूल से हाई स्कूल तो इस लिये होगा क्योंकि आबादी बढ़ रही है जिस से तालीम की मांग बढ़ती जा रही है। जब मिडल से हाई स्कूल हो जाएगा तो वहां पर लाज़मी तौर पर एकामोडेशन की ज़रूरत होगी, कमरों की ज़रूरत होगी, बिल्डिंग की ज़रूरत होगी और उन के लिये हमारे पास पैसा नहीं है और ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब ने कुएश्चन आवर में खुद ही फरमाया है कि एक एक रुपया, दो दो रुपये, तीन तीन और चार चार रुपये मुख्तलिफ तरह से स्टूडेंट्स से हम बिल्डिंग फंड के लिये ले रहे हैं ताकि उस रुपए से स्कूलों की बिल्डिंग बन सके या उन की मुरम्मत की जा सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक तरफ तो हम ने यह कदम उठाया कि फीसें मुआफ कर दीं। जो बड़े बड़े बिग बिज़नसमैन हैं, बिज़नेस मैगनेट्स हैं, जो बड़े बड़े बिग इनकम टैक्स पेयर हैं, हाई सेलरीड पर्सन्ज़ वगैरा हैं जो कि अंग्रेज़ों के वक़्त बड़ी बड़ी फीसें दिया करते थे उन के बच्चों के लिये हम ने यक कलम फीस मुआफ कर दी। यानि जो पांच, पांच सौ, सात सात सौ, हजार, दो, तीन चार और पांच पांच हजार रुपये माहवार तनखाह पाने वाले लोग हैं उन के बच्चों के लिये फीस मुआफ कर दी, और दूसरी तरफ एक एक, दो दो और तीन तीन रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से हम किन से यह फंड लेते हैं? उन से जो चपड़ासी के बच्चे हैं, क्लास फोर एम्पलाईज़ के बच्चे हैं, बेलदार के बच्चे हैं। उन से पैसे लेकर हम रिलीफ किन को देना चाहते हैं? उन को जिन की तनखाहें बहुत बड़ी २ हैं। बिल्डिंग की मुरम्मत के लिये और उन को बनाने के लिये रुपया उन लोगों से लिया जाएगा जो कि महां गरीब हैं हालांकि हमारी गवर्नमेंट कमिटिड तो इस बात के लिये है कि जो दे सकते हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला जाए और जो नहीं दे सकते उन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। लेकिन यहां तो बात बिल्कुल उलटी की गई है। इस के साथ साथ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स के सफा 17 पर सैनिक स्कूल के लिये स्कालरशिप्स की बाबत यह बताया गया है कि जिन वालदेन की तनखाह दो सौ रुपये तक है उन के बच्चों को पूरा यानि 1500 रुपया सालाना स्कालरशिप मिलेगा, जिन की दो सौ से लेकर चार सौ रुपये माहवार तनखाह है उन के बच्चों को 1125 रुपए सालाना वज़ीफा मिलेगा, जिन की चार सौ से छः सौ रुपया माहवार है उन के बच्चों को 750 रुपए सालाना मिलेगा और जिनकी तनखाह छः सौ एक से लेकर एक हजार रुपए माहवार तक है उन के बच्चों को 375 रुपए सालाना वज़ीफा मिलेगा। यानि जो लोग एक एक हजार रुपया माहवार पाते हैं उन के तई भी हमारी गवर्नमेंट इतनी मेहरबान है और वह इस लिये कि सैनिक स्कूल में उन के बच्चे जाएं। सैनिक स्कूल में बच्चे जा रहे हैं अपने मैरिट पर लेकिन हमारी मेहरबानी उन के ऊपर है जो एक एक हजार रुपया माहवार पाते हैं। और बिन

लोगों से वह चन्दा वसूल होगा ? किन लोगों से वह रुपया वसूल होगा ? उन से जिन की आमदन चालीस, पचास, साठ, सत्तर और पचहत्तर रुपये माहवार है। यह हजार हजार वालों को जो 375 रुपए दिए जाएंगे यह लाजमी तौर पर गरीब के ऊपर बोझ बनता है—तब बनता है जब कि उन से एक एक रुपया वसूल किया जाए। इस लिये, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज करूँ कि यह एक बहुत अनफेअर डिस्ट्रिब्यूशन है। इसे हमें कुछ अमेंड करना चाहिए। जो गरीब है उस की फीस बिल्कुल माफ हो और अगर दो चार सौ रुपया माहवार लेने वाले लोगों के बच्चों का वजीफा बढ़ा भी दिया जाए तो मैं उसे स्पोर्ट करूँगा लेकिन यह बात ठीक मालूम नहीं देती कि एक तरफ तो एक एक हजार रुपया माहवार पाने वालों को वजीफा दिया जाए और दूसरी तरफ गरीब लोगों पर इस तरह एक एक रुपया, दो दो और तीन तीन रुपया का बोझ डाला जाए। इस लिये मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि वह इस सम्बन्ध में अपनी पालिसी को रिवाइज करे।

ठीक है कि हम ने कान्स्टीच्यूशन के मुताबिक ऐजुकेशन को कुछ हद तक फ्री किया हुआ है। लेकिन जो रूरल पापुलेशन है वहाँ पर पांच से लेकर चौदह साल की उम्र के सिर्फ पच्चास या साठ फीसदी बच्चे ही स्कूल जाते हैं। क्यों ? इस लिये कि वह निहायत गरीब है। वह वहाँ पर बच्चों को स्कूलों में भेज नहीं सकते। इसी तरह से ही अर्बन एरियाज में 70 से 75 फीसदी बच्चे ही स्कूलों में जाते हैं। पच्चीस फीसदी के लगभग बच्चे अर्बन एरियाज में भी स्कूल नहीं जाते क्योंकि उन के वालदेन बहुत गरीब होते हैं। वह उन को स्कूलों में भेजना एफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैजोरिटी आफ दैम यह सोचते हैं कि जब तक उन के बच्चे मजदूरी न करेंगे, चने न बेचेंगे, रिक्शा न चलायेंगे तब तक उन की रोटी का काम नहीं चल सकता। इस लिये यह निहायत ही अनफेअर और अनबैलैन्ड डिस्ट्रिब्यूशन है जिस की तरफ मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक किसी की मदद करने का सवाल है, मैं मानता हूँ और इस बात को एप्रेशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट को उन की जरूर मदद करनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगली बात मेजर हैड 56 से सम्बन्ध रखती है। यह एविएशन डिपार्टमेंट के मुताल्लिक है। लैंड एक्वीजीशन कुलैक्टर ने 3,04,826 रुपये का एवार्ड दिया। जिन की जमीन थी उन्होंने अपील कर दी और अपील पर एवार्ड की रकम सात लाख रुपए ज्यादा बढ़ गई। अगर हम इस सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स को पढ़ें तो कोई सफा खाली नहीं रह जाता जहाँ पर कि गवर्नमेंट के खिलाफ डिग्री की एमाउंट का जिक्र न हुआ हो। अगर हम थोड़ा सा भी ज्यादा कंट्रोल रखें तो हमारा जो मुफ्त में टाइम जाया होता है वह भी बच जाए और जो रुपया फजूल जाया जाता है वह भी न जाए। कहां तो तीन लाख रुपया और कहां दस लाख रुपया। फिर आप हाईकोर्ट में गए तो कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। इस का यही कारण है कि हमारी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वह बहुत बिक है और अगर कंट्रोल बिक न होता तो जो रुपया स्टेट के रैवेन्यू का इस तरह से जाया होता है वह न होता। बहुत सारा रुपया बच सकता है। अगर हम पूरी तरह से ध्यान दें तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से हमारा कुछ न कुछ रुपया बच सकता है और हालात में इम्प्रूवमेंट हो सकती है।

[कामरेड राम प्यारा]

एक और बड़ी इम्पारटेंट आईटम है। यह डिमांड नम्बर 12 है। सरदार गुरचरन सिंह जी ने कुछ इस की तरफ इशारा भी किया है और मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है कि जो मिस्टर महाजन है उस ठेकेदार ने न सिर्फ पत्थर ही नहीं डाला बल्कि जो गवर्नमेंट की तरफ से तारकन्ट्रोल रेट पर उसे मिली थी उसने उसका भी बहुत सारा हिस्सा बलैक मार्किट में बेचा। विजिलेंस के जिम्मे इस की इन्क्वायरी हुई। मेरी इत्तलाह के मुताबिक विजिलेंस वालों ने अपनी इन्क्वायरी में एक फिकरा बड़ा ही शानदार लिखा है जिस की बाबत मैं विजिलेंस वालों को तो क्रेडिट देता हूँ लेकिन गवर्नमेंट को उस के लिये डिसक्रेडिट ही करूंगा क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मिस्टर महाजन का जो कान्डकट था वह ऐसा था कि **He has corrupted the whole of the department of the whole of the circle** क्यों? उस में एक्स. ई. ऐन. भी सस्पेंड हुआ, एस. डी. ओ. सस्पेंड हुआ, ओवर-सियर सस्पेंड हुआ और दो क्लर्क भी सस्पेंड हुए। और उसका नतीजा क्या हुआ? उस के पीछे जो मास्टर माइंड वह ठेकेदार था उसको किसी ने नहीं पूछा। सरदार गुरचरन सिंह जी ने इल्जाम लगाया है कि जो साबका होम मिनिस्टर पंडित मोहन लाल हैं, उसे उन्होंने शील्ड किया। मैं सरदार गुरचरन सिंह जी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने उसको शील्ड किया है तो अपनी फीस लिए बगैर शील्ड नहीं किया होगा। (आपोजीशन की तरफ से प्रशंसा) मैं तो सरकार से यह डिमांड करूंगा कि न सिर्फ उस ठेकेदार, बल्कि उस शील्ड करने वाले साबका होम मिनिस्टर के खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए, और इसके बाद उन की प्रासीक्यूशन होनी चाहिए (आपोजीशन की तरफ से प्रशंसा)। इस लिये कि जब हम किसी गुनाह को पकड़ते हैं मगर उसको मुनासिब सज़ा नहीं देते तो ग्राम तौर पर उस का असर यह होता है कि जो ऐसे ही और आदमी हैं उन को टेम्पटेशन मिलता है और वह समझते हैं कि जब किसी गुनाहगार को हम नहीं पकड़ते तो उन को शैह मिल जाती है और अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है तो वह गवर्नमेंट के सामने इस तरह से प्रेसीडेंट्स को रखेगा। इस से बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात और कोई नहीं हो सकती, चाहे यह पंडित मोहन लाल साबिका होम मिनिस्टर की तरफ से प्रोटेक्शन देने की वजह से हुई है या श्री महाजन ने की है, क्योंकि इस से हिन्दुस्तान को बहुत बड़ा घाटा पड़ा है क्योंकि वहां जो स्पर बनाया जाना था वह नहीं बनाया गया और उस के न बनने की वजह से दरिया ने अपना रुख इधर मोड़ लिया और दरिया का इस तरह से रुख मुड़ने की वजह से हिन्दुस्तान की बहुत सी ज़मीन पाकिस्तान की तरफ चली गई। अगर यह स्पर बना लिया जाता तो वह ज़मीन जो कि इस तरह से पाकिस्तान को चली गई थी वह न जाती और हमारे देश को घाटा न पड़ता। इस लिये मैं कहता हूँ कि इस तरह से सिर्फ कुर्रप्शन ही नहीं हुई बल्कि श्री महाजन ने और पंडित मोहन लाल, साबिका होम मिनिस्टर ने एक एंटी नेशनल काम किया है। इस लिये गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इस बारे में इनकुआयरी करवाए और इस के लिये जिस किसी के जिम्मे भी कसूर हो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उस की प्रासीक्यूशन होनी चाहिए। यह प्रासीक्यूशन सिर्फ इस लिये ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस में कुर्रप्शन इनवाल्व्ड है लेकिन इस लिये होनी चाहिए

क्योंकि इस तरह से हमारे देश को नुक्सान पहुंचाया गया है। हम ऐसा गुनाह कभी भी मुआफ नहीं कर सकते।

तो इस लिये मैं कहता हूं कि इस गवर्नमेंट के सामने जब बड़े २ आदमियों का सवाल आता है तो उन के लिये यह एक प्रोसीजर मान लेती है और जब गरीब आदमियों का सवाल आता है तब उन के लिये यह नहीं मानती। इसे अपनी इस पालेसी को बदलना चाहिए। अभी यहां पर फर्टीलाइजर की डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल उठाया गया था जिस का जिक्र कामरेड जोश ने अपनी तकरीर में किया था। क्योंकि वह कम्युनिस्ट है तो उन के मुंह से जाट का लफ्ज इस बारे में निकला था जो कि मैं समझता हूं कि उन्हें नहीं बहना चाहिए था मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि जमीन पर किसी खास तबका की मनाफली नहीं है। मैं तो उन की तकसीम दो तरह के लोगों में करता हूं यानी एक वह जो बड़े बड़े जमींदार हैं और एक वह जो छोटे २ रकबों के मालिक हैं। इस तरह से मैं उन की तकसीम इकनामिक बेसिज पर किया करता हूं क्योंकि मेरे पास आम तौर पर जो लोग आते हैं वह छोटे २ रकबों के मालिक होते हैं और जो बड़े २ रकबों के मालिक होते हैं उन की तरफ से जो गैर-कानूनी चीजों की जाती हैं वह मैं आम तौर पर गवर्नमेंट के नोटिस में लाता रहता हूं। इसी लिए मैंने जिला फिरोजपुर के एक बहुत बड़े जमींदार की फैमली को पकड़वाया है जिस की २१६ एकड़ जमीन सरप्लस निकलती थी लेकिन वह अपने असरोरसूख की वजह से यूटेलाइज नहीं होने दे रहा था क्योंकि वह खुद डिप्टी कमिशनर था, फिर उस का एक भाई डिप्टी कमिशनर था, एक भाई उस का हाईकोर्ट का जज है और एक भाई उस का वहां के जिला परीषद का चेयरमैन है। इस तरह से वह अपने असरोरसूख से अपनी सारी सरप्लस जमीन दबाए बैठे थे, मैं ने उन से वह निकलवाई है। इस के इलावा २२० एकड़ और जमीन जो और सरप्लस निकलनी चाहिए थी और नहीं निकली हुई थी वह निकलवाई है क्योंकि उन्होंने सिक्वोरिटी आफ लैण्ड टैन्थोर एक्ट के रूल ८ के तहत एक ज्वायंट कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पर उस रकबा की एग्जेंपशन ले रखी हुई थी हालांकि उनकी वह सोसायटी रजिस्टर नहीं हुई थी। **That was a fraud with the Government** मैं इस लिये जमींदारों की तकसीम दो हिस्सों में किया करता हूं। इसी तरह से मैं ने जिला करनाल के एक बड़े जमींदार की कोई दो ढाई लाख रुपए की मालियत की जमीन का एवार्ड कौन्सिल करवाया है। इस लिये मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि वह अपनी इस पालेसी को रीवाईज करे ताकि जिस अनफेयर और अन इकनामिक बेसिज पर इस का काम चल रहा है उसमें तबदीली आए और हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाईटी जो हम यहां कायम करने का फैसला कर चुके हैं उस की तरफ दो चार कदम उठा सकें। इतना कह कर मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप ने मुझे बोलने का मौका दिया है।

**चौधरी इन्द्र सिंह मलिक (सफीदों) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज यहां सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर बहस जारी है, इस लिये मैं आप की विसातत से फाइनैस मिनिस्टर साहिब से कहना चाहता हूं कि जो हर साल लाखों रुपये डिप्लेट एमाउंट की शबल में गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं इस को रोकने का इंतजाम करें क्योंकि यह एक खाहमखाह का बोझ

[चौधरी इन्दर सिंह मलिक]

सरकारी खजाने पर पड़ता है। इस का कारण यह है कि जो गवर्नमेंट का एल. आर. का डिपार्टमेंट है वह बड़ा नाअहल है क्योंकि जब गवर्नमेंट का कोई एम्पलाई या कोई और गवर्नमेंट को नोटिस देता है तो केस जब इस की राए के लिये जाता है तो इस डिपार्टमेंट की तरफ से कह दिया जाता है कि केस को कनटैस्ट किया जाए और कनटैस्ट यह कोर्ट में जाकर कर नहीं सकते। इस का नतीजा यह होता है कि कोर्ट खर्चा समेत गवर्नमेंट के खिलाफ डिगरी कर देती है। इस तरह से लाखों रुपये हर साल गवर्नमेंट को डिफ्रीटल एमाउंट के तौर पर देने पड़ते हैं। इन स्पलीमेंटरी डिमांड्स के अन्दर 70 हजार की एक रकम दर्ज है जो गवर्नमेंट को एक श्री गुप्ता को देनी पड़ी है। मैं समझता हूँ कि इस डिफ्रीटल एमाउंट को एवाएड करने के लिये जरूरी है कि गवर्नमेंट का जो एल. आर. का डिपार्टमेंट है वह तेजी से और ज्यादा होशियारी से काम करे। कई दफा ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स में कई सरकारी मुलाजमों को डिसमिस कर दिया जाता है और जो एथारेटी उन्हें डिसमिस करती है उस को ऐसा करने का अख्तियार हासिल नहीं होता हालांकि उस ने ऐसा एल. आर. की सलाह पर किया होता है। इस तरह से जब वह कोर्ट में जाते हैं तो वह फैसला सेट एसाइड कर दिया जाता है जिस करके गवर्नमेंट को बहुत रुपया उन्हें तनखाहें आदि की शकल में देना पड़ता है। इस तरह से सरकारी खजाने पर खाहमखाह का बोझा डाला जाता है। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

इसी तरह से, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हर साल हम देखते हैं कि जो जमीनें गवर्नमेंट एक्वायर करती हैं उन की कीमतों के जो एवार्ड दिये जाते हैं वह बहुत कम दिये जाते हैं हालांकि उन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इस का नतीजा यह होता है कि जिन जमींदारों की जमीनें यह एक्वायर करती हैं वह कोर्ट में अपील दायर कर देते हैं और कोर्ट उन के हक में ज्यादा कीमत का एवार्ड दे देती है। इस लिये मैं कहूंगा कि जमीनों की कीमतों का एवार्ड देने वाली एथारेटी को जो जमीन एक्वायर की जाए उस के आस पास की जमीनों की कीमतों को ध्यान में रख कर ठीक कीमत का एवार्ड देना चाहिए ताकि उन लोगों को मुनासिब कीमत अपनी जमीन की मिल सके। इस तरह से लाखों रुपये जो हर साल गवर्नमेंट को बाद में ज्यादा देने पड़ते हैं वह बच जायेंगे जिस तरह से 14 लाख रुपया जो गवर्नमेंट ने हिन्दुस्तान मशीन टूलज फैक्टरी के लिये जमीन एक्वायर की थी उस का देना पड़ा था। वह रकम बचाई जा सकती थी अगर पहले से ही सही कीमत लगाई जाती। इस लिये मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि जहां डिफ्रीटल एमाउंट को कम करने की जरूरत है वहां एवार्डों के कम देने से जो इस पर दोबारा खर्चा पड़ता है उस को बचाने की जरूरत है। इस से एक तो गवर्नमेंट का खर्च बच जाएगा दूसरा गरीब जमींदारों को जो कोर्ट में जाने के लिये सरदरदी करनी पड़ती है और खर्च करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा।

फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन डिमांड्स में वेस्ट्रन जमुना कैनाल के लिये एक मांग आई है जिस में जींद डिस्ट्रीब्यूटरी को रीमाडल करने का जिक्र है, यानी मुखी माइनर, सरफाबाद माइनर, माट माइनर और अबलपुर माइनर बनाए जा रहे हैं। कई सालों से इन पर काम लगातार चल रहा है लेकिन यह अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए। जमीन में नाले खोद

दिए गए हैं लेकिन उन के अन्दर अभी तक पानी नहीं दिया गया। यह सारी की सारी माइनर्ज खाली पड़ी हुई हैं। जिन जमींदारों से इन के लिये जमीन ली गई थी उन को उस की कीमत अभी तक नहीं दी गई। न तो जमींदार उन जमीनों में खेती ही कर सकते हैं और न ही उन्हें खेती करने के लिये पानी ही दिया जा रहा है जिस की वजह से वह बड़े दुखी हो गए हैं। फिर जो मुखी माइनर है उस पर जो हैड बनाया गया है वह नाकिस बना है क्योंकि उस पर पानी चढ़ता ही नहीं। सिंचाई विभाग के डिप्टी मिनिस्टर उस हैड को देखने के लिये गए भी थे। उन्होंने भी देखा कि यह हैड नाकिस बना है और उन्होंने वहां पूछा भी था कि इस हैड को किस इन्जीनियर ने बनाया है। अभी तक उस को ठीक नहीं किया गया। फिर यह सारा काम एक साल के अन्दर खत्म किया जाना था लेकिन अब दो साल हो गए हैं मुकम्मल नहीं हुआ। उधर जो बेचारे जमींदार हैं वह पानी के लिये तरस रहे हैं। अब तो वह सारा इलाका वैसे ही ड्राट एफैक्टिड है। फिर जो नहरें पहले की बनी हुई हैं उन के अन्दर भी पानी नहीं है। उन की हालत आज यह है कि सारे महीना में सिर्फ 6 दिन उन में पानी छोड़ा जाता है और इस का नतीजा यह हो रहा है कि जो छोटे २ खाले हैं या माइनर्ज हैं उन के अन्दर तो पानी पहुंचता ही नहीं। इस के नतीजे के तौर पर वहां के जमींदारों को सारे महीना में एक दिन भी पानी नहीं मिलता लेकिन उन से आबयाना सारे साल के लिये ले लिया जाता है। यह उन के साथ बड़ी बेइन्साफी हो रही है। चाहिए तो यह कि जिस फसल के लिये उन लोगों को पानी दिया जाए सिर्फ उसी के लिये आबयाना उन से चार्ज किया जाए लेकिन यह उन से सारे साल के लिये चार्ज कर लेते हैं। इस लिये मैं फिनांस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि नहरी पानी को डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से की जाए जिस तरह से बिजली की की जाती है यानी मीटर के हिसाब से पानी दिया जाए। जिस तरह से बिजली के मीटर लगे हुए होते हैं और जितनी बिजली कोई इस्तेमाल करता है उतना उस से चार्ज किया जाता है इसी तरह से नहरी पानी का किया जाए। जितना पानी एक जमींदार को दिया जाता है, उसे उतना ही आबयाना देना पड़े। यह न हो कि आबयाना उस से ज्यादा लिया जाए और पानी कम दिया जाए। इस से जमींदार को नुकसान होता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानते हैं कि जमींदार जो है वह देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वह खुशहाल है तो देश भी खुशहाल होगा। अगर वह दुखी है तो देश भी दुखी होगा। इसी लिए शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा लगाया था। आप ने देखा कि पाकिस्तान के साथ इस लड़ाई में पंजाब के और बाकी देश के किसानों ने किस तरह से उस का सामना किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इस तरह से हम ने अपने वकार पर चीन के साथ लड़ाई में आए धब्बे को भी धो डाला। मगर इसी किसान के साथ खाद देते वक्त, पानी देते वक्त, बीज और अच्छे औजार देते वक्त बुरा बर्ताव किया जाता है। खाद की कीमत कम होनी चाहिए मगर यहां पर इस के उल्ट 16 रुपये से बढ़ा कर साढ़े 18 रुपये कर दी गई है और फिर इस में भी अफसर देते 12 थैले हैं और साल के बाद कीमत मांगते हैं, 22 थैलों की। उस बेचारे को इस तरह से दुगना पैसा देना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट किसान को सारी सहुलतें देती है तब ही वह ज्यादा अनाज पैदा कर

[चौधरी इन्दर सिंह मलिक]

सकता है। आप देखें कि सरकार किसान के साथ कैसे डिस्क्रिमीनेशन करती है। स्टेट फार्मज को इन से दुगना पानी दिया जाता है। आप जानते हैं कि जो रजिस्टर्ड ग्रीनर है वह इन के कहने पर अच्छे बीज पैदा करता है और लोगों को यह सप्लाई होते हैं। उस को और दूसरे किसानों को खाद की सप्लाई नो प्राफिट और नौ लास बेसिज पर 8-10 रुपये थैला के हिसाब से होनी चाहिए। बीज वक्त पर मिलना चाहिये। होता यह है कि जिस वक्त जमींदार फसल बो चुकता है तो सरकार के पास बीज आता है। बाज दफा ट्रेडर नाकस बीज मिला देते हैं जिस से जमींदार का नुकसान हो जाता है। किसान और देश की तरक्की के लिये यह बातें खत्म होनी चाहिए और किसान को पूरी २ सहूलते वक्त पर मिलनी चाहिए। तभी वह ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है और जो हमारा रुपया दूसरे देशों को जाता है और हमें जो शर्म उठानी पड़ती है उस को वह मिटा सकता है। मगर शर्त यह है कि उस को पूरी २ सहूलते मिलें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं कुछ ऐजुकेशन की मद के बारे में गुजारिश करना चाहता हूं। इस साल इस मद में 158 स्कूल अपग्रेड किये गये हैं। मैं वजीर साहिब को इस के लिये मुबारकबाद देता हूं। आप को पता है कि कई सालों से यह स्कूल अपग्रेड नहीं किये जा रहे थे। यह मामला यूंही खटाई में पड़ा था। मगर उन्होंने जुरअत की और देहात के इन स्कूलों को अपग्रेड किया। यह बात ठीक है कि पैसे लिये मगर यहां पर तो लोगों ने पैसे भी जमा करा रखे थे मगर पहली हुकूमतों ने उन को अपग्रेड नहीं किया। जिस एम.एल.ए. ने कहा उसी का स्कूल अपग्रेड हो गया। मैं इन को इस के लिये मुबारकबाद देता हूं। मगर इतना जरूर कहूंगा कि अभी इन स्कूलों में पूरा स्टाफ और सार्यस का सामान नहीं पहुंचा है। इन से दरखास्त है कि इस तरफ तवज्जुह देकर उन को पूरा स्टाफ और सामान भिजवाएं। इन लफ्जों के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

**शिक्षा मन्त्री (श्री प्रबोध चन्द्र) :** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक ऐजुकेशन का ताल्लुक है 8 मदों के तहत रुपया मांगा गया है। उन में से एक है 27,90,500 रु० की। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पानसर्ड स्कीम है जिस के तहत स्कूलों को साइंस का सामान मुहैया किया जाना है ताकि उन का मियार ऊंचा हो सके यह रुपया हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से मिलना है। चूंकि इस का प्रोवियन हम पहले नहीं कर पाए इस लिये सप्लीमेंट्री डिमांड के जरिए मांगा है। जब यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से मिलेगा तो रीइम्बर्स कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।

दूसरी डिमांड है अपग्रेडिंग आफ स्कूलज के बारे में। मुझे खुशी है कि मेरे मोहतरिम दोस्तों ने इस बारे में कुछ अच्छे लफ्ज कहे हैं कि सरकार ने पहली दफा बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया है। करीब 150 से ऊपर मिडल स्कूलों को हाई बनाया गया है, 350 प्राइमरी स्कूलों को मिडल बनाया गया है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिस का रुपया जमा किया गया हो और उस को अपग्रेड न किया गया हो। और पहली दफा इस बात को कतई नजरअन्दाज किया गया है कि किस इलाके में ज्यादा सयासी दबाव डाला गया। बल्कि इस बात का ख्याल रखा गया कि कम से कम हर हलके को एक स्कूल दे दिया जाए और यह पहली बार है

कि पिछड़े इलाकों को उन के हिस्से से ज्यादा स्कूल दिये गये ताकि उन का घाटा पूरा किया जाए। मलिक इन्द्र सिंह ने कहा कि टीचर्ज और सामान की कमी है जो कि पूरी होनी चाहिए। यह मुनासिब शिकायत है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह कमी दूर की जाए। मगर मुश्किल यह है कि हमारे पास इस वक्त साइंस टीचर्ज की बहुत कमी है। और कई तरह के वजीफे देने के बावजूद हम काफी टीचर्ज को ट्रेड नहीं कर सकें। (विघ्न) हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन 90-93 फीसदी स्कूलों में 95 फीसदी जरूरी स्टाफ पहुंच गया है। कुछ कमी है वह भी जल्दी पूरी हो जायगी।

एक दोस्त ने कहा कि एक तरफ तो स्कूल बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों से एक २ या दो २ रुपया बिल्डिंग फंड के तौर पर लिया जा रहा है। मैं अर्ज करूं कि वह फंड सिर्फ उन स्कूलों के बच्चों से ही लिया जा रहा है जिनकी इमारतें पुरानी है और जिन की मुरम्मत की जरूरत है या जो बच्चों के बैठने के लिये पूरी नहीं हैं। बाकी जहां पर स्कूल बनते हैं वह पंचायतों या दूसरी लोकल बाडीज से पैसा लेते हैं।

यह भी गिला किया गया है कि हम ने अमीर बच्चों की फीस माफ कर दी है और हम उन को वजीफे दे रहे हैं और कि हम गरीब बच्चों पर बोझ डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बात किसी गलत फहमी की वजह से कही गई है। बदकिस्मती यह है कि जो फैसला पहिले किया गया वह काफी जजबाती बातों को सामने रख कर किया गया। मैं मानता हूं कि हमारी ऐप्रोच गलत थी। 14 साल के हजारों बच्चों की फीस माफ... (विघ्न) आप जरा देर से आए हैं। उन्होंने दूसरे स्कूलों का जिक्र किया था। उस में करीब 25 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जिन की फीस माफ है। और उन में से 4-5 लाख के करीब ऐसे होंगे जिन के मां बाप अपने बच्चों की फीस दे सकते होंगे। मैंने इस तरफ यूनियन ऐजुकेशन मिनिस्टर की तवज्जुह दिलाई थी मगर उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की कि जब तक कन्स्टीट्यूशन को बदला न जाए तब यह तबदीली नहीं कर सकते। जहां तक सैनिक स्कूलों का संबंध है अगर आप लिस्ट को देखें तो पता चल सकता है कि किस रेशो से वजीफे दिये जा रहे हैं। और आप को यकीन हो सकता है कि कहां पर गरीबों के 100 बच्चों को वजीफा का फायदा होता है वहां पर अमीरों के बच्चों की परसेन्टेज 7 या 10 है। और फिर यह ख्याल करना भी गलत है कि जो 800 या 900 रुपया लेते हैं वह अपने बच्चों को सैनिक स्कूलों में भेज कर 200 या 250 रुपया माहवार का खर्च बर्दाश्त कर सकें। आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस के पांच बच्चे हों चाहे वह 800 या 900 रुपया माहवार तनखाह पाता हो कैसे 200 या 250 रुपया अपने बच्चे की फीस अदा कर सकता है। आप को तो पंजाब सरकार को दाद देनी चाहिए कि हमारे सूबा में बाकी के सूबों में से सब से ज्यादा सैनिक स्कूल हैं और पंजाब के बच्चे हिन्दुस्तान के दूसरे स्कूलों में भी तालीम पा रहे हैं। और जहां तक रेशो का सम्बन्ध है मिल्टरी आफिसर्ज में पंजाब के बच्चों की जिन्होंने हमारे सैनिक स्कूलों में तालीम हासिल की है सब से ज्यादा है।

[शिक्षा मन्त्री]

इस के आगे हरिजन बच्चों के लिये 20 लाख रुपया की रकम मांगी गई है। यह हमारी खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती कि हरिजन भाईयों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी जितनी भी अलाटमेंट होती है वह आखिर में आकर गलत हो जाती है। अगर 40 लाख रुपया रखा जाता है तो 50 लाख तक खर्च हो जाता है। इस की वजह यह है कि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। कहां हम 12 और 14 लाख की आबादी से चल थे और अब 60 लाख तक पहुंच गई है। (विघ्न)

बाबू अजीत कुमार : डिप्टी सपीकर साहिब, आन ए पुआर्डिट आफ आसडर

\* \* \* \* \*

डिप्टी सपीकर : उसीं बिना मेरी इजाज़त उ बोल रहे हैं। इतना लंबा पुआर्डिट आफ आरडर नहीं हो सकदा। (The hon. Member is speaking without my permission. The point of order cannot be so long.)

शिक्षा मन्त्री : मैं, डिप्टी स्पीकर साहिब, सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहा था कि हरिजन बच्चों के लिये 20 लाख की रकम मांगी गई है। इस मद में सिर्फ हरिजन बच्चों को वज़ीफे देने की बात थी और मुझे यह बात कहने में ज़रा भी झिजक नहीं कि हरिजन बच्चों की गिनती आऊट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ रही है। या तो हरिजनों के बच्चे एजुकेशन माइंडिड बन रहे हैं या इन की गिनती बढ़ गई है। (विघ्न)

बाबू अजीत कुमार : आन ए पुआर्डिट आफ आरडर, मैडम।

Deputy Speaker: Please take your seat.

बाबू अजीत कुमार : आन ए पुआर्डिट आफ कलैरीफिकेशन, मैडम।

Deputy Speaker: Please take your seat.

बाबू अजीत कुमार : \* \* \* \* \*

डिप्टी सपीकर : उहाँ उं मै-इजाज़त नहीं सी दिउी बोलल लछी। इह जे कुछ श्री अजीत कुमार ने बिना इजाज़त दे किहा है प्प्रोसीडिंग्स दा पारट नहीं होवेगा। (I did not permit the hon. Member to speak. whatever Shri Ajit Kumar has said, will not form part of the proceedings.)

शिक्षा मन्त्री : इस में दो चार बिरादरियों और शामिल की गई है जैस कि कमबो हैं लेकिन उनकी तादाद सिर्फ 5 परसेंटेज से ज्यादा नहीं।

इसके इलावा 12 लाख रुपया की रकम गुरु गोबिन्द सिंह ट्राई सेन्टेनरी सैली-ब्रेशन्ज़ के लिये दिए गए हैं। हमें अफसोस है कि सरकार इस नेक काम के लिये और ज्यादा रकम न दे सकी। अगर और ज्यादा रकम हम दे सकते तो हमें खुशी होती। और इस बात पर तो किसी को भी एतराज़ नहीं है।

\*Note. Expunged as ordered by the Chair.

एक बात श्री राम प्यारा और सरदार गुरचरण सिंह ने कुर्रप्शन के बारे में कही। जब पहली बार इन्होंने मेरे नोटिस में यह बात लाई तो उसी वक्त हम ने फौरी तवज्जो दी और इरिगेशन मिनिस्टर साहिब को भी कहा और सी. एम. साहिब को भी बताया गया और उसी दिन इन्क्वायरी शुरू कर दी गई। एक बात मैं साफ कर दूँ कि इस मौजूदा रीजिम में कोई भी कम्प्लेंट किसी के खिलाफ कुर्रप्शन की आए तो उस की पूरी तरह से जांच होगी और चाहे कितना भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो इस बात पर सख्ती से अमल किया जाएगा कि अगर कम्प्लेंट सही है तो एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट किसी आदमी के सियासी दबाव में और किसी और ढंग से ऐसे केसों को छोड़ेगी नहीं जहां कि कुर्रप्शन की गई हो। (प्रशंसा)

यही 5 या 6 मई तालीम के बारे में थीं। जहां तक टीचरों को 25 लाख रुपया की सहूलियतें देने के बारे में सम्बन्ध है कुछ एतराज उठाए गए हैं कि सरकारी टीचरों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में टीचरों की यूनियनों को कहा है कि वह डी. पी. आई. और महकमा तालीम के दूसरे अफसरों के पास बैठ कर जिस तरह भी चाहें बात कर लें कि किस ढंग से रुपया दिया जाए। हम किसी किस्म की कोई एक्स्पेंशन नहीं चाहते। हम तो कैटेगरीवाइज देना चाहते हैं। हो सकता है कि कैटेगरी बनाते वक्त कोई एक आध रह गया हो लेकिन जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उन में पिक्क एंड चूज नहीं किया गया है और इस बात की कोशिश नहीं की गई कि 'ए' को या 'बी' को या 'सी' को मिले। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और यही डिप्टी स्पीकर साहिब, हल था जिस से ज्यादा से ज्यादा टीचरों को फायदा हो सकता था इन लपजों के साथ आप का शुक्रिया अदा करता हूँ।

**चौधरी राम सूरप :** मैं यह बात पूछना चाहता हूँ कि जो आप ने एम. एस. सी. के टीचर न मिलने के लिये कनडैन्स कोर्स शुरू किए हैं और बाद में बन्द कर दिए हैं तो जो लड़के दाखिल हुए थे वह न तो एम. ए. ही रहे और न एम. एस. सी. बने, इस की क्या वजह है और इस के बारे में क्या किया जा रहा है?

5.00 p.m.

**शिक्षा मन्त्री :** यह बात जेरे गौर है और सोच रहे हैं।

मैंं घाघू जी ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਂ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਹੈ ਕੋਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ. ਕੰਡੈਂਸਡ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ?

**ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਕਤ

ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
(The hon Members need not waste the time of each other while seeking information. Every Member can have his say at his turn.)

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** On a point of order Madam. ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਕਾਇਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੈ?

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਬਾਬੂ ਜੀ, ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)  
(Every thing is there where the hon Member, Baboo Bachan Singh is present. (Laughter))

**ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਜਗਰਾਉਂ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ. 7—8 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 8 ਨੰ. ਹੈ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਅਤੇ 7 ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਅਤੇ 6 ਹੈ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ. 6 ਵੱਲ ਆਪਦੀ ਤਵਜੋ ਫੇਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬੰਦ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਟੁਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਲਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਹਨ ਇਹ ਕਰਿਮੀਨਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਜ਼ ਐਮਬੈਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚ ਕਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਮ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਾ ਨੀਵਾਂ ਲੈਵਲ ਦੇਖੇ ਐਟ ਏ ਸਟਰੈਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਯਰੀ ਬੈਚਿਜ਼ ਦੇ ਚੰਦ ਇਕ

ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸੂਰਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ 10 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਡਰੇਨ ਬਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਕ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਭਾਨ ਡਰੇਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਿਮਨਲ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਜੇ ਇਧਰ ਖੁਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲੀਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰਿਜਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਤਾਂ ਬਰਿਜ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਰਿਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਬਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਏਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਰਿਜਜ਼ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਿਜਜ਼ ਨਾਲ ਘਟ ਡੋਂ ਘਟ 20 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਇਹ ਸਭ ਠਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰਬਾਨੀ ਹੈ)। ਇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੁਝ ਠਕੇਦਾਰ ਮੋਹਰਬਾਨ ਹਨ। ਬਰਿਜਜ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਰ ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਿਜਜ਼ ਟੁਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਐਮਬੈਜਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਜਰਮ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਠਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਐਕਸਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਰਿਜਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਪੂਰ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਪੂਰ ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਨਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 100, 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਅਕਸ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਕਿਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 1963-64 ਦੇ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜ 1966 ਦੇ ਵਿਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ

## [ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]

ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਊਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਡਿਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਡਿਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਲਫਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਪਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੈਲਿਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫੈਲਾਏ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਸਵਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਅਦਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਏਨਾ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ. ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਏਨੇ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਦ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਖਾ ਕੇ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਦੁਗਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਪਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਦ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

**ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ):** ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਹੇਠ 9 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਤੇ ਤਹਿਤ ਡੀਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਮਗਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ, ਬਗੈਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਔਰ ਐਂਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਵਲ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦੁਖਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਆਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦੋ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ 50/60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਤੀਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.....

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸੀਂ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? **Does the hon. Member attest the affidavits or not of those whom he is referring to ?**

**ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ :** ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ

**ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ :** ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਲ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੈ।

**ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ :** ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਸ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕਿਥੋਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮੰਗ ਤਾਂ 75 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਪਰ 25 ਲਖ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਲਖ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਟਸ ਨੂੰ 75 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਐਨੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਕਾਰ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਇਸਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ (ਘੰਟੀ) ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਉ। (Now he may resume his seat.)

**ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ :** ਮੈਂ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦੋ ਹਫਤੇ ਰਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਟ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ 8 ਬਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਜੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਜਗਮਗਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਟ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਚਲਾਣ ਲਈ ਦਿਤੀ

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਘੰਟੀ)। ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿਚ ਬੈਠਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਉ ਤਾਂਕਿ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਜਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਲਈ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਖਰਚ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਏ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਐਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੋ ਖਰਚ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 3, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਭੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟੇਕ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਰੇਨ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਮੀਲ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੇਨਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ 3, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਈ ਵੇਰ ਕੋੜਾ ਘੁਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ

[ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ]

ਕਮਾਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਸਪਲਾਈਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਲਡਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਟ ਦੇ ਚੁਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੈਨਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੈਂਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜ਼ਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜੈਸ਼ਨਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਵਿਘਨ) ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਅਦ ਭੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਜਾ ਵੱਡੀ ਕੰਸਰਨਜ਼ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਗਰ-ਕੇਨ ਦੇ ਭਾਉਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ-ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਦ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਉਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੇ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਗਰਕੇਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਉਥੋਂ ਵੀ ਗੁੜ ਆਇਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚੋਂ ਗੁੜ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਗੰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੀੜ ਸਕਣ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੂਗਰ ਮਿਲ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਦੋਹੇ, ਮੁਤਫਿਕ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅਜ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਟੁਟ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਕੇਲਾ ਉਹੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰੋਅਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ.....

**ਆਵਾਜ਼ਾਂ :** ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ।

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੈਂਸਡ ਰਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਮੁਲ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ.....

**ਆਵਾਜ਼ :** ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਮੇਰੀ ਤਵਜੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਲ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਧਾਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡੀ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ.....

**ਇਕ ਆਵਾਜ਼ :** ਮਕੱਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਨੂੰ ਮਕੱਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ (*Interruptions*) ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਰਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਂਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ।

(ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ)।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। (The hon. Member Sardar Har-chand Singh should first obtain the premission and then stand. He rises of his own accord.)

**ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ :** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੰਦੇ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਘਨ (ਸ਼ੋਰ)

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Legal or illegal let me try it ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ rice ਤੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.....

**ਇਕ ਅਵਾਜ਼ :** ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ?

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਇਹ ਫਰਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਦਸਣ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮਿਟ ਹਰ ਇਕ ਮਸਲੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗੌਰਮਿਟ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪਲਾਇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

**ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ :** ਗੁੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਅਜ ਘਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇਕ ਗੌਰਮਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.....

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਈਏ ? (ਹਾਸਾ)

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੌਰਮਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗੌਰਮਿਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡੀਊਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਗੌਰਮਿਟ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।

**ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ :** On a point of information. ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਡਿਊਚਾ ਭਾਅ ਹੈ, ਯੂ0 ਪੀ0 ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਤਿਗਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਅ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਅ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ 40 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਫਰਟੇ-

ਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਉਹੋ ਭਾਅ ਅਤੇ ਜਿਥੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਭਾਅ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ?

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ :** ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ।

**Deputy Speaker :** Will you please take your seat

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ :** ਅਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਜੀ ?

**Deputy Speaker** Please take your seat. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਉ।  
(The hon. Member may please take his seat, Let the hon. Minister first have his say.)

**ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ :** ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੋਹ ਬਾਰੇ.....

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਫੇਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। (Let the hon. Minister first complete his speech. Then I will permit him to speak.)

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈਏ (*Interruption*)

**Deputy Speaker:** Order please,

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ **irregularity** ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੀ ਐਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਐਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਰ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜੀਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਲਗਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਲੈ ਲਈ (ਵਿਘਨ) ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅੰਰ ਦੂਸਰਾ ਦੋ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੌ ਏਕੜ ਖਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਵਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 40 ਜਾਂ 50 ਰੁਪੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਥੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ—ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ—ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਥਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਹਰ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ? ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਕੁਲੈਕਟਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਹਨ ਅੰਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

**ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ :** ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (The time at the disposal of the hon. Minister is over)

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਰਖਾਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੀਏ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

**ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ :** ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

**ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ :** ਤਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਨੂਮਨਬੈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨੂਮਨਬੈਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ

ਪਾਸੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ : ਹਨੂਮਨਬੈਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਦ ਕਰੋਗੇ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਅਮਲ ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ..... (Interruption)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗਿਲੋਟੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਪੁਛ ਲੈਣਾ (Let Comrade Gurbakhsh Singh enquire about them at some other time because now it is the time for the guillotine)

(At this time Comrade Gurbakhsh Singh rose in his seat to say something but his voice was drowned in interruptions.)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਫੇਰ ਪੁਛ ਲੈਣਾ। (He may get this clarification at some other time)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ..... (Interruption)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਗਿਲੋਟੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। (Order please. Now it is time to apply the guillotine.)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : It is 6.00 P.M. now. I will apply guillotine and put the Demands one by one to the vote of the House.

#### DEMAND NO. 1

Deputy Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,41,780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 12—SALES TAX.

*The motion was carried.*

#### DEMAND NO. 2

Deputy Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 9,10,040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 22—JAILS.

*The motion was carried.*

**Deputy Speaker :** I think, all the remaining Demands should be put together to the vote of the House.

**Voices :** Yes, yes, please.

**Deputy Speaker :** Question is—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,55,79,760 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 28—EDUCATION.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 14,89,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 30—PUBLIC HEALTH.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,45,580 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 42—MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 22,49,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment, for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 43—IRRIGATION NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL).

That the Supplementary sum not exceeding Rs 25,52,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENT.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 21,05,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 50—PUBLIC WORKS.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 3,42,280 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 70—FORESTS.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 57,36,110 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 71—MISCELLANEOUS.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 91,58,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 78-A—EXPENDITURE CONNECTED WITH NATIONAL EMERGENCY.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,92,26,790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 99—CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL).

That a Supplementary sum not exceeding Rs 62,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 120—PAYMENT OF COMMUTED VALUE OF PENSION.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 2,63,56,560 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 124—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF GOVERNMENT TRADING.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 17,56,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of LOANS TO LOCAL FUNDS—PRIVATE PARTIES, ETC., AND LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 31—AGRICULTURE.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1966, in respect of 103—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS.

*The motions were carried.*

**Deputy Speaker :** The House now stands adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday.

*(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 1st March, 1966.)*



**APPENDIX**  
**TO PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOLUME 1,**  
**NO. 9, DATED THE 28TH FEBRUARY, 1966**

**JOINT SENIORITY LIST OF OFFICERS/OFFICIALS IN THE  
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT**

**3206. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to —

- (a) lay on the Table of the House a joint seniority list of Class I, II and III Officers/Officials of the Animal Husbandry Department in the State showing their dates of birth and the dates of their joining the service in each case ;
- (b) state whether Government has received representations from any of the above-mentioned employees regarding their super-sessions during the year 1964-65 and 1965-66 ; if so, the details thereof ?

**Captain Rattan Singh :** (a) & (b). The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

**Industrial Development of Amritsar**

**3211. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government received during January/February, 1966, a memorandum from any industrialist of Amritsar regarding the Industrial development of Amritsar, if so, the details thereof and the details of the action taken thereon be laid on the Table of the House ?

**Shri Ram Kishan :** No. Representations received from the paints manufacturers and the rubber manufacturers were however sent to the Government of India with a request to help them in solving their problems.

2. The representatives of Art-Silk Weaving Industry of Amritsar asked the Industries Department to contact the producers of art-silk yarn and to arrange supplies at Ex-Mill rates. A team of officers consisting of the Industries and Supplies Commissioner, the Director of Industries and the Managing Director, Punjab State Small Industries Corporation, were able to secure through the Man-made Fibres Association an offer from the spinners to supply two lakh Kilograms. Art-Silk Yarn at Rs 6.80 per lb. against their ex-mill rate of Rs 6.86 per lb. But the Industry at Amritsar did not avail of this offer on the plea that according to them, yarn was available in the market at lower rates. This position has however been belied by the rising rates in the market which have already gone above Rs 7.00 per lb.

**Agricultural Development in the State**

**3212. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

- (a) the details of the targets fixed for the agricultural development of the State in the last three five-year plans and the extent to which these targets have been achieved together with the details of their review reports ;
- (b) the details of the expenditure incurred on the development of Agriculture in the State as mentioned in part (a) above to-

gether with the details of the benefits that have accrued to the State ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) The targets fixed for the Agricultural Production during the First, Second and Third Plans period alongwith the achievements made thereunder are given below :—

### Physical Targets and achievements

(Figures in '000' tons/bales)

Commodity	1st Plan		2nd Plan		3rd Plan	
	Targets	Achievements	Targets	Achievements	Targets	Achievements up to 1964-65
Foodgrains ..	4,071	4,800	5,941	6,148	7,850	7,109
Oilseeds ..	115	150	185	206	300	309
Sugarcane ..	517	533	780	908	900	1,115
Cotton ..	540	533	1,050	802	1,200	1,080

In the above table, the achievements under the 3rd Plan are up to the year 1964-65. As regards production for 1965-66 the last year of the 3rd Plan, it may be stated that it is too early to make assessment of the production of Kharif and Rabi crops for the final year of the 3rd Plan, as the returns of crop cutting experiments based on random sampling method undertaken by the field agency are still being received and the dates of release of the final forecasts for the Kharif crops start from the 15th February onwards. For the Rabi crops, the crop cutting experiments are not yet available.

Details of the received reports are given at Annexure.

(b) The details of the outlays and expenditure incurred during the same periods mentioned in part (a) above are as under :—

### Financial aspects

(Rs in lakhs)

Period	Outlay	Expenditure
First Plan	.. 604.39	611.59
Second Plan	.. 571.24	465.10
Third Plan	.. 1,567.00	1,904.74 (anticipated)

The outlay and expenditure relate to sub-heads Agricultural Production, Minor Irrigation and Soil Conservation on Agricultural Lands.

Details of the benefits that accrued to the State are given at Annexure.

## ANNEXURE

## Agricultural Development

Agriculture contributes a major share of the National income, The role that agriculture plays in the economic development of our country, therefore, needs no emphasis. Agriculture, not only provides the food requirements of the country, but also the raw material for a number of industries. The surplus arising in the agricultural sector is an important source for earning foreign exchange. Moreover, the development of agriculture is very essential for the much needed economic progress in the rural sector. Over 70 per cent of the population being dependent on agriculture, the improvement in their living standards can be achieved only when agricultural productivity is raised appreciably.

The total population of the State according to 1961 census is 2,03,06,812 out of which 79.9 per cent are ruralites and depend directly or indirectly on agriculture for their livelihood.

The total area of the State is 30238,000 acres and according to broad land/uses, it may be classified as follows :—

		(Area in 000 acres)
		year 1963-64
(i) Forests	..	900
(ii) Not available for cultivation	..	8,149
(iii) Other uncultivable land excluding fallow land	..	1,270 928 (includes culturable waste)
(iv) Fallow lands	..	1,187
(v) Net area sown	..	18,803
(vi) Total cropped area	..	24,085

There are 2.98 million agricultural holdings out of these 2.5 million holdings are of 10 acres or less and cover 6.9 million acres of cultivated area, 0.84 million holdings are above 10 acres and cover 12.3 million acres i.e., about 2/3rd of the total cultivated area.

## Review of First and Second Five Year Plan

The First Five Year Plan accorded a place of distinction to programmes for agricultural production throughout the country seeking to raise the standard of living of the masses of the people, specially in the rural areas. The total first plan provision for the Punjab and Pepsu State together was Rs 604.39 lakhs, against which the actual expenditure was Rs 611.59 lakhs. The details of the benefits realised against the targets fixed for the various agricultural commodities for the first plan were as follows :—

Commodity	Unit	Base year	Target	Production
Foodgrains	.. 000 tons	3,437	4,071	4,800
Cotton	.. 000 bales	310	540	533
Sugarcane (Gur)	.. 000 tones	440	517	533
Oilseeds	.. 000 tons	110	115	150

Second Five-Year Plan also laid great emphasis on increasing agricultural production specially, foodgrains. The total outlay in the second Five Year Plan in the agricultural sector was Rs 571.24 lakhs against which, Rs 465.10 lakhs were spent. The target fixed for the re-organised Punjab State and achievement for the second plan are as under :—

Commodity	Unit	Base year	Target Production	
Foodgrains	.. 000 tons	4,800	5,941	6,148
Cotton	000 bales	533	1,050	802
Sugarcane (Gur)	.. 000 tons	533	780	998
Oilseed	.. 000 tons	150	185	206

#### Benefits accrued

It may be seen that during the period 1950-51 to 1960-61, the production of foodgrains increased by about 76 per cent, that cotton increased by 260 per cent, that of sugarcane by 225 per cent and that of oilseeds increased by about 137 per cent.

The agricultural production by the end of the Second Plan was 76.55 per cent higher than in 1950-51, compared to the country as a whole where the production in the same period increased by 46.34 per cent.

#### Progress during the 3rd Plan

During the Third Plan period, the original financial outlay on Agricultural Production was of the order of Rs 8.73 crores against this the anticipated expenditure is expected at Rs 11.09 crores. The outlay on minor irrigation was Rs 6.48 crores and the expenditure is expected at Rs 7.03 crores.

No attention was paid to the Soil Conservation Programme during the First two Five Year Plans. A beginning has been made in Third Plan and a total anticipated expenditure of Rs 0.92 lakhs will be spent on this programme by this Department.

The agricultural production targets fixed for the Third Plan and achievements upto 1964-65 are given below :—

(Thousand tones/bales)

Commodity	Targets 3rd Plan	Production up to 1964-65
Foodgrains	.. 7,850	7,109
Oilseeds	.. 300	309
Sugarcane	.. 900	1,115
Cotton	.. 1,200	1,080

In the above table, the achievement under 3rd Plan is up to the end of 1964-65. As regards production for 1965-66 the last year of 3rd Plan it may be stated that it is too early to make assessment of the production of kharif and Rabi crops for the final year of the Third Plan as the returns of crop cutting experiments based on random sampling method under taken by the field agency are still being received and the dates of release of the final forecasts for the kharif crops starts from 15th February, onwards. For the Rabi crops, the crop cutting experiments are not yet available.

### Development of Agriculture in the State

**3213. Comrade Makhan Singh Tarsikka :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the details of the programme chalked out by the Government for the development of agriculture in the State under the following heads in the Fourth Five-Year Plan :—

(1) Food Grains ; (2) Cotton (including American cotton) ; (3) Sugarcane; (4) Rice ; (5) Fruits ; (6) Vegetables; etc.

(b) whether the Government have requested the Union Government to take certain special measures and to provide special funds to the State during the Fourth Five-Year Plan so as to enable it to increase the production of foodgrains ; if so, the details thereof ?

**Sardar Darbara Singh :** (a) Details of the programme of production of (1) foodgrains, (2) cotton, (3) sugarcane, (4) rice, (5) fruits, and (6) vegetables, etc., chalked out during the Fourth Five-Year Plan are given below :—

Commodity	Units	Targets fixed for the Fourth Plan
Foodgrains	.. '000 tons	8,950
Cotton	.. '000 bales	1,500
Sugarcane (gur)	.. '000 tons	1,450
Rice	.. '000 tons	1,025
Fruits	.. acres (Addl.)	80,000
Vegetables	.. Do	50,000

(b) To increase the production of foodgrains the State Government have placed special emphasis on the adoption of the following measures :—

(1) Supply of improved seeds.

(2) Increased use of Fertilizers and Pesticides.

(3) Assured supply of Irrigation Facilities.

(4) Soil Conservation measures on Agricultural Lands.

The comparative figures of financial outlay for the 3rd and 4th Five-Year Plans under the sub-head "Agricultural Production Minor Irrigation and Soil Conservation" is as under :—

		Third Plan Outlay (likely expenditure) (Rs in crores)	Fourth Plan Outlay (Rupees in crores)
(i) Agricultural Production	...	11.09	19.5
(ii) Minor Irrigation	...	7.03	20.0
(iii) Soil Conservation on Agricultural lands		0.92	9.38

The figures for the Fourth Five-Year Plan are tentative.

It will thus be seen that the increase under Minor Irrigation and Soil Conservation is an important and of special feature meant to increase Agricultural Production.

**Election of the Managing Committee of the Takhanwadh Cooperative Agricultural Society Ltd., Takhanwadh, tehsil Moga, district Ferozepore**

**3223. Comrade Gurbakhsh Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the election of the Managing Committee of the Takhanwadh Cooperative Agricultural Society Ltd., Takhanwadh (tehsil Moga), district Ferozepore was held on 23rd May, 1965 ;

(b) whether it is also a fact that a member of the said Society lodged a complaint against the said election or sent a representation to the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Moga, if so, the date when the said representation/complaint was received by the said Assistant Registrar, and the date on which he looked into the matter and ordered an enquiry ;

(c) whether it is also a fact that it was established in the said enquiry that the Secretary of the said Society made alterations in the proceedings of the meeting held on the 14th May, 1965 ;

(d) whether it is also a fact that the said Assistant Registrar, set aside the election referred to in part (a) above ;

(e) if the replies to parts (a), (b) and (c) and (d) above are in the affirmative, whether the responsibility for making alterations in the proceedings of the meetings has been fixed on some person ; if so, on whom and the details of the action, if any, taken against him ; if it has not been fixed so far the reasons therefor ;

(f) a copy of the complaint/representation mentioned in part (b) above be laid on the Table of the House ?

**Chaudhri Rizaq Ram :** (a) Yes.

(b) Yes. A complaint was received in the Office of Assistant Registrar, Cooperative Societies, Moga, on 27th May, 1965. He ordered for an enquiry on the same day, i.e., 27th May, 1965. The report after enquiry was received by the Assistant Registrar on 7th June, 1965.

(c) The enquiry officer had expressed the doubt that the agenda, for holding the general meeting of the society, fixed for 23rd May, 1965, was written in the resolution dated 14th May, 1965 and it was changed to 8th May, 1965. The enquiry Officer apprehended that the Secretary of the Society was responsible to effect this alteration.

(d) Yes.

(e) On the basis of the above-mentioned report, the Assistant Registrar, Moga, set aside the elections of the Managing Committee held on 23rd May, 1965 and ordered for fresh elections. The Secretary of the Society was apprehended to have made the alteration and accordingly Managing Committee of the society was advised to take necessary action against the Secretary who is the employee of the Society itself.

On a further enquiry, made by Inspector, Moga-I, on 18th January, 1956, as to who is actually responsible for making alteration in the resolution dated 8th May, 1965, it has been reported that the Managing Committee did not agree with the findings of the Enquiry Officer submitting the report to the Assistant Registrar, on 7th June, 1965 on the same subject relating to the change of date from 14th May, 1965 to 8th May, 1965. Accordingly the Managing Committee is not inclined to take any action against the Secretary for the alleged change of date from 14th May, 1965 to 8th May, 1965.

In view of the fact that the Managing Committee of the Society did not agree that there is any change in the date from 14th May, 1965 to 8th May, 1965 in the proceeding book of the society, no action could be taken against the Secretary of the society. However, the matter is still under consideration of the Government.

(f) Copies of complaints, dated 23rd May, 1965 and 12th July, 1965 are attached herewith.

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ,

ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਮੋਗਾ।

ਵਿਸ਼ਾ : ਦੀ ਤਖਾਣਵਧ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ  
ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਡੀਟਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ।

ਮੁਖ ਮਨ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 23 ਮਈ, 1965 ਨੂੰ ਦੀ ਤਖਾਣਵਧ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਆਮ ਅਜਲਾਸ ਸ੍ਰ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਡੀਟਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਦਿਆ। ਕਾਪੀਆਂ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਕਿਸ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ।

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ,  
(ਦਸਖਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਖਾਣਵਧ  
ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ  
ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਤਹਿਸੀਲ  
ਮੋਗਾ।)

ਮਿਤੀ 23 ਮਈ, 1965

ਤਸਦੀਕ

ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ,

ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ,

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਮੋਗਾ।

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ,  
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਮੋਗਾ।

ਵਿਸ਼ਾ: ਦੀ ਤਖਾਣ ਵਧ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ,  
ਤਖਾਣਵਧ ਦੀ ਚੋਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਸ ਤਖਾਣਵਧ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 23 ਮਈ, 1965 ਦੀ ਚੋਣ  
ਰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਜਾਇਜ਼  
ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸ ਨਿਮੂਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਘਰ ਕਰਾਈ  
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ,

ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ,

ਮੈਂਬਰ,

ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਸ  
ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਤਖਾਣਵਧ

ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ, 1965

ਤਸਦੀਕ

ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ

ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ,

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਮੋਗਾ।



8497  
11

**"C" 1966**

Published under the authority of the Punjab Vidhan Sabha and  
printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab, Chandigarh.

**Chief Reporter**  
**Punjab Vidhan Sabha**  
**Chandigarh**

a  
rh.





